

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

प्रतियोगी राजनीति विज्ञान

(प्रथम खण्ड)

(POLITICAL SCIENCE, VOL. I)

(भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए)

डॉ. जी. पी. नेमा

अध्यायः दशः अष्टमः

एकद्विती विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग अध्यक्ष बनना

डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर

BT

डॉ. डी. सी. शिपाडी

इम ए, एल एल एम, डी पी एम इण्ड आर आर, डी टी एल ए

की वी धन , अतः सौ आठ एक रुप पौ (बु की) , पौ रुप दौ

डिप्टी कमिश्नर, भोपाळ, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार

कॉलेज बुक डिपो

झयपुर

प्रतियोगी राजनीति विज्ञान

(Political Science Vol. I)

•

हॉ जी पी नेमा

बॉ डी सी विमर्दी

© PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publishers. No part of this book may be reproduced / translated by any means without written permission of the publishers. This book is sold subject to Jaipur jurisdiction only. Due care and diligence has been taken while editing and printing the book, neither the authors nor the publishers / distributors of the book hold any responsibility for any mistake.

Published by: College Book Depot, 83 Tripolia Bazar, Jaipur 2

Type-setting by: Sudha Computers, Jaipur 16

Printed at: Laxmi Printers, Jaipur

प्राक्कथन

‘राजनीति विज्ञान’ सामाजिक विज्ञानों में महत्वपूर्ण विषय होने के साथ-साथ लोकप्रिय विषय भी है। आज के ‘वैश्वीकरण’ और ‘अन्तर्राष्ट्रीयतावाद’ तथा ‘एक विश्व’ की कल्पना में इस विषय को शीर्ष स्थान प्राप्त है और इसीलिए घर, परिवार, आंगन, चौखट, चौराहे और बाजारों में पान वालों और थड़ी-ठेले वालों के इर्द-गिर्द लोग राजनीति के चर्चित विषयों पर चर्चा करते हुए मिल जावेंगे। आज के समाज की यह स्थिति राजनीति विज्ञान की लोकप्रियता का ज्वलंत उदाहरण है।

इतना ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एवं राज्यों की राज्य-स्तरीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राजनीति विज्ञान परीक्षार्थियों का चहेता विषय है तथा अधिकांश परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में विषय चुनते समय ‘राजनीति विज्ञान’ को प्राथमिकता देते हैं।

इस रुझान को देखते हुए प्रस्तुत पुस्तक आई. ए. एस. तथा विभिन्न राज्य सेवा प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लाभार्थ लिखी गई है। पुस्तक में विषय के प्रथम प्रश्न पत्र ‘राजनीतिक सिद्धान्त तथा भारतीय राजनीति’ का विवेचन किया गया है।

पुस्तक के प्रारम्भ में, पाठ्यक्रम के खण्ड ‘क’ से सम्बन्धित विभिन्न अध्याय दिए गए हैं जिनमें राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन के उपागम, राज्य के सिद्धान्त, राज्य प्रभुसत्ता, प्रजातंत्र तथा मानव अधिकार, राजनीतिक संस्कृति के सिद्धान्त, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त, राजनीतिक विचारधाराएँ, शक्ति तथा आधिपत्य के सिद्धान्त, भारतीय राजनीतिक विचार एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की व्याख्या है।

खण्ड ‘ख’ से सम्बन्धित ‘भारतीय सरकार एवं राजनीति’ के विभिन्न अध्यायों में भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का स्वरूप एवं राजनीति, भारत

के राष्ट्रवादी आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक आयाम, सांविधानिक विकास के क्रम में ब्रिटिश शासन के समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाएँ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ, सिद्धान्त तथा व्यवहार में भारत की कार्यपालिका प्रणाली, भारत में संसद तथा संसदीय समितियों की भूमिका तथा कार्य, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, देश में कार्यरत विभिन्न सांविधानिक संस्थाएँ और आयोग, राजनीतिक दल व्यवस्था एवं दवाव समूह, भारतीय राजनीति में वर्ग, आयोजन तथा आर्थिक विकास एवं पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है। पुस्तक में प्रामाणिक एवं अधुनातन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। आशा है पुस्तक प्रतियोगी परीक्षार्थियों तथा राजनीति विज्ञान के सामान्य पाठकों एवं इस विषय में अध्ययनरत शिक्षार्थियों के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी सिद्ध होगी।

हम उन सभी देशी-विदेशी पुस्तकों के लेखकों-प्रकाशकों, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों, भारत सरकार के विभिन्न प्रकाशनों एवं उन सभी सहयोगियों के आभारी हैं जिनका इस पुस्तक में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग लिया गया है। श्री प्रकाश नारायण नाटाणी सर्वाधिक वधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने अधिक परिश्रम से पाण्डुलिपि तैयार की है और हमें पूर्ण संतोषप्रद सामग्री संयोजित करके दी है।

पुस्तक के प्रकाशक श्री पी. सी. जैन का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पुस्तक को सुन्दर साज-सज्जा के साथ शीघ्र प्रकाशित करने का प्रयास किया है। आशा है, यह पुस्तक विषय के विद्वानों एवं प्रतियोगी पाठकों को पसन्द आवेगी।

लेखकद्वय

अनुक्रमणिका

1. राजनीतिक सिद्धान्त : अध्ययन के उपागम 1
(Approaches to the Study of Political Theory)
राजनीति विज्ञान का अर्थ (1) राजनीति विज्ञान की परिभाषा (2) राजनीति विज्ञान की प्रकृति (5)
राजनीति विज्ञान का क्षेत्र (7) राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक सिद्धान्त में
भेद (10) राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन के उपागम (11) परम्परागत उपागम (11)
आदर्शमूलक या मानवीय तथा दार्शनिक उपागम (11) ऐतिहासिक उपागम (12) व्यवहारवादी
या आनुभविक उपागम (13) उत्तर व्यवहारवादी उपागम (16) अन्तर्विषयी उपागम (17)
'अन्तर्विषयी उपागम' हेतु अन्य समाजशास्त्रीय विषयों का राजनीति विज्ञान से सह सम्बन्ध (18)
राजनीति विज्ञान : एक विज्ञान के रूप में मान्यता (19)
2. राज्य के सिद्धान्त 21
(Theories of State)
संविदानुलक या सामाजिक संविदा का सिद्धान्त (21) उदारवादी सिद्धान्त (23) नव
उदारवाद (24) मार्क्सवादी एवं साम्यवादी सिद्धान्त (25) उपनिवेशोत्तर (26)
3. राज्य प्रभुता 27
(State Sovereignty)
सम्प्रभुता का अर्थ और उसकी परिभाषा (27) सम्प्रभुता की विशेषताएँ (28) सम्प्रभुता के विभिन्न
रूप (29) आस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धान्त (31) सम्प्रभुता का बहुलवादी या अनेकतावादी
सिद्धान्त (33) मार्क्सवादी सिद्धान्त (37)
4. श्रमजन्त तत्वा मानव अधिकार 38
(Democracy and Human Rights)
प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त : प्राचीन तथा समकालीन (38) मानव अधिकार के सिद्धान्त
मानव-अधिकारों का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य (43) मानव अधिकारों का उदारवादी परिप्रेक्ष्य (44)
संयुक्त राष्ट्रसंघ और मानव अधिकार (45) न्याय के सिद्धान्त (46) भारतीय संविधान में
राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की व्यवस्था (47) न्याय के सार्वभौमिक एवं स्थिर
आधार तत्त्व (49) कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधन (49) समानता (49) समानता तथा
स्वतन्त्रता का सम्बन्ध (51) नये सामाजिक आन्दोलन (51) संघर्ष एवं सुधार (52) क्रान्ति (52)
राजनीतिक बाध्यता (54) नये सामाजिक आन्दोलन (54) कुछ प्रमुख विचारधाराएँ (55)
5. राजनीतिक संस्कृति के सिद्धान्त 57
(Theories of Political Culture)
द्वितीय विश्व के देशों में संस्कृति तथा राजनीति (63) भारत की राजनीतिक संस्कृति (64)
6. राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त 65
(Theories of Political Economy)
अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त : प्राचीन तथा समकालीन (65)

13. राष्ट्रवादी आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक आयाम ... 224
(Social-Economic Dimensions of the Nationalist Movement)
साम्प्रदायिक समस्या तथा विभाजन की मांग (224) मुस्लिम साम्प्रदायिकता (228) हिन्दू साम्प्रदायिकता (231) पिछड़ी जाति के आन्दोलन, ट्रेड यूनियन तथा किसान आन्दोलन, नागरिक अधिकार आन्दोलन (232)
14. संवैधानिक विकास : ब्रिटिश शासन में महत्वपूर्ण घटनाएँ ... 235
(Landmarks in Constitutional Development during British Rule)
क्रिप्स मिशन (238) भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 (239)
15. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ ... 243
(Salient Features of the Indian Constitution)
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दार्शनिक मान्यताएँ (243) प्रस्तावना (243) मूल अधिकार और कर्तव्य (246) संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार (248) समानता का अधिकार (248) स्वतन्त्रता का अधिकार (251) मौलिक अधिकार : एक समीक्षा (259) मौलिक कर्तव्य (259) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त (261) निर्देशक सिद्धान्त : संविधानिक भावधान (261) निर्देशक तत्वों की आलोचना (265) निर्देशक तत्वों की उपलब्धियाँ (266) भारतीय संघवाद : सघ और उसका राज्य-क्षेत्र (267) भारतीय संघवाद की प्रकृति : सिद्धान्त और व्यवहार में क्या भारत एक संघ है ? (267) संविधान की व्यवस्थाएँ (271) जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्था (279) आयोजना में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध (279) क्या राज्यों की स्थिति 'नगोपालिकाओं' जैसी है ? (280) केन्द्र-राज्य विवाद के मुख्य कारण (281) केन्द्र राज्य भागदों को दूर करने के सुझाव (282) राज्य स्वायत्तता की ठोड़ी मांग (283) व्यवहार में सहकारी संघवाद (284) संसदीय प्रणाली (286) लोकसभा का अध्यक्ष (289) संसद की शक्तियाँ एवं कृत्य (292) दोनों सदनों के परस्पर सम्बन्ध (293) भारतीय संसद की सर्वोच्चता (295) संसद की कार्यप्रणाली (296) संसदीय समितियाँ (297) संशोधन प्रक्रिया (303)
16. सिद्धान्त तथा व्यवहार में कार्यपालिका प्रणाली ... 306
(The Executive System in Theory and Practice)
राष्ट्रपति (306) राष्ट्रपति की शक्तियाँ (310) राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ (312) राष्ट्रपति की संविधानिक स्थिति (316) राष्ट्रपतियों का आचरणगत पक्ष (319) उपराष्ट्रपति (319) प्रधानमंत्री (321) प्रधानमंत्री के अधिकार और उत्तरदायित्व (323) प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति (330) मन्त्रि परिषद् (331) राज्यपाल (335) राज्यपाल की शक्तियाँ (337) राज्यपाल की स्व-विवेकीय शक्तियाँ (339) केन्द्रीय अधिकारों के रूप में भूमिका (339) राज्यपाल की भूमिका : गिरती छवि (340) मुख्यमंत्री तथा राज्य मन्त्रिपरिषद् (341) मन्त्रिपरिषद् (343) राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्ध (344) नौकरशाही (344)
17. संसद तथा संसदीय समितियों की भूमिका तथा कार्य ... 345
(Role and Function of the Parliament and Parliamentary Committee)
पारम्परिक सम्बन्ध के आधार (345) संसदीय नियन्त्रण (345) सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन (348) वित्त पर संसदीय नियन्त्रण : लोक लेखा समिति तथा अनुदान समिति (349)
18. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ... 354
(The Supreme Court and the High Courts)
उच्चतम न्यायालय (354) उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार (355) भारत में न्यायिक पुनरावलोकन (360) न्यायापालिका की स्वतन्त्रता (362) उच्च न्यायालय (363) अधीनस्थ न्यायालय (364) व्यवस्थापिका न्यायापालिका सम्बन्ध (364) जनहित याचिका (367)

19. **संवैधानिक संस्थाएँ/आयोग** 368
(Statutory Institutions/Commission)
संघ लोक सेवा आयोग (368) निर्वाचन आयोग (370) भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (375) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (376) राष्ट्रीय महिला आयोग (378) पिछड़ा वर्ग आयोग (380) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (380)
20. **राजनीतिक दल व्यवस्था एवं दबाव समूह** 382
(Political Party System & Pressure Groups)
दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार (382) भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ (384) समग्र रूप से भारतीय दल प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ (387) वर्तमान में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल (388) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (389) भारतीय जनता पार्टी (390) भारतीय साम्यवादी दल (393) भारतीय मार्क्सवादी दल (मार्क्सवादी) (395) जनता दल (395) जनता दल (समाजवादी) (397) विखण्डन तथा क्षेत्रीयकरण (398) भारत में विपक्ष की भूमिका (406) दबाव समूह (408) दबाव-समूह और राजनीतिक कार्य-व्यवहार अथवा दबाव-समूहों की तकनीक (408) दबाव-समूह का महत्व (410) भारत में दबाव-समूह : विकास और विशेषताएँ (411) भारत में दबाव-समूहों के विभिन्न प्रकार और उनका प्रभाव (411) भारत में दबाव-समूहों की प्रकृति, भूमिका, विशेषताएँ और पारचात्य हित-संगठनों में उनकी भिन्नता (415) भारत में दबाव-समूह की भूमिका (416) मिली-जुली सरकारों की राजनीति का स्वरूप (417) निर्वाचन व्यवहार की प्रवृत्तियाँ (417)
21. **भारतीय राजनीति में वर्ग** 420
(Class in Indian Politics)
भारत की राजनीति में जाति एवं सजातीयता (420) भारत की राजनीति में वर्ग (425) साम्प्रदायिकता की राजनीति (425) क्षेत्रवाद (427) पिछड़ा वर्ग तथा दलित आन्दोलन (431) लिंग न्याय हेतु संघर्ष (432) लैंगिक समानता : एक ज्वलन्त प्रश्न (437)
22. **आयोजन तथा आर्थिक विकास** 440
(Planning and Economic Development)
योजना आयोग और सरकार का सम्बन्ध (444) आर्थिक नियोजन की चुनौतियों के सन्दर्भ में प्रशासनिक सुधार (445) राष्ट्रीय विकास परिषद् (447) उदात्तकरण के युग में योजना एवं आर्थिक सुधारों के राजनीतिक आयाम (449)
23. **आधार स्तर पर प्रजातन्त्र** 455
(Democracy on Grassroots)
पंचायती राज व्यवस्था (455) 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (457) पंचायती राज की प्रमुख समस्याएँ (466) पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सुझाव (467) ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं पर राज्य नियन्त्रण (468) नगर शासन (470) महानगर (470) नगर निगम (470) 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 (474) नगरपालिका (475) अधिसूचित क्षेत्र, समितियाँ एवं नगर क्षेत्र समितियाँ (479) इन्फ्रामेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट एवं छावनी बोर्ड (479) भारत में नगरीय स्वशासन की प्रमुख समस्याएँ (481) भारत में नगरीय स्थानीय प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव (482) नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियन्त्रण (484) आधार स्तर के आन्दोलन तथा महिलाओं को अधिकार देना (488)

राजनीतिक सिद्धान्त : अध्ययन के उपागम

(Approaches to the Study of Political Theory)

"सुसंस्कृत मानव प्राणियों में देखा होता है, किन्तु अब यह जानने एवं व्यापक को स्वीकार नहीं करता तो वह निरुत्पन्न प्राणी बन जाता है। यदि कोई मानव सभ्य में रहने योग्य नहीं होता अथवा जो स्वयं को अल्पविकसित मानकर सभ्य की अपेक्षा नहीं रखता, वह या तो एक पशु है अथवा देवता।" —आस्तु

आस्तु (Aristotle) का यह कथन इस बात का परिचायक है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज में रहकर ही उसका विकास सम्भव है। समाज से मानव-जीवा के विभिन्न पक्ष तथा—सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक आदि सभी प्रभावित एवं विकसित होते हैं। इन्हीं विभिन्न पक्षों के अध्ययन के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विज्ञान-विज्ञानों का प्रादुर्भाव हुआ है। राजनीति विज्ञान में मनुष्य समाज में रहते हुए राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है। राज्य एक राजनीतिक सत्ता है जिसके छठ मनुष्य के राजनीतिक सम्बन्धों का सुचारु रूप से संचालन होता है, अतः राजनीति विज्ञान अध्ययन का मुख्य विषय बन जाता है। राजनीति विज्ञान को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है।

राजनीति विज्ञान का अर्थ

(Meaning of Political Science)

राजनीति विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द 'पोलिस' से हुई है तथा 'पोलिटिक्स' शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान् आस्तु ने किया। ग्रीक-शब्द 'राष्ट्र-राज्यों' के विकास के साथ-साथ 'राजनीति विज्ञान' का विकास होता गया तथा राजनीति विज्ञान राज्य से सम्बन्धित विषयों का विज्ञान कहा जाने लगा।

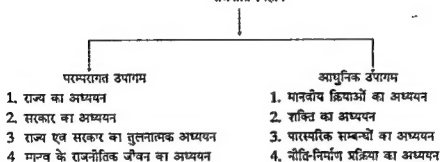
राजनीति विज्ञान को केवल राज्य के अध्ययन तक ही सीमित रखने की राकीर्ण सत्कल्पना बाद में विकसित हुई जो परम्परा के रूप में अनेक वर्षों तक प्रचलित रही। आस्तु ने इस सम्यर्थ में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था। के. आर्. बम्बवाल के अनुसार, "आस्तु ने राजनीति शास्त्र को 'मूल विज्ञान' की भक्षा दी और उसमें न केवल राजनीतिक समस्या, राज्य या नगर को शामिल किया वरन् उसमें परिवार, समाज एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की, जो समाजशास्त्र नीतिशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आती हैं, को शामिल किया। आस्तु द्वारा ऐसा लिखना स्वभाविक था, क्योंकि उसके समय में यूनानी नगर-राज्य व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के पहलू से सम्बन्ध रखते थे और उस समय राज्य और समाज में विभाजन रेखा नहीं थी। राजनीति विज्ञान का विकास अन्य सामाजिक विज्ञानों की भाँति राज्य के विशेष विज्ञान या राज्य सरकार के विज्ञान के रूप में होता गया।"

राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, जिसके अन्तर्गत मानव समाज के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन होता है। मनुष्य द्वारा निर्मित अनेक संगठन होते हैं जैसे—परिवार, कुल, जाति, सभ्यता, धार्मिक तथा राज्य अन्तर्देशीय संगठन आदि, किन्तु संसार में मनुष्य जिस एक संगठन के अंतर्गत रहते हैं वह संगठन है—राज्य। राज्य आधुनिक युग में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण संगठन है। 'राज्य' नामक इसी संगठन का मुख्य रूप से अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान की यह सकल्पना ग्रीक-शब्दों विकसित होती गई तथा इसने अब अधिक व्यापक रूप धारण कर लिया है। आई. जे. मैन के मतानुसार, "यद्यपि राज्य को राजनीति विज्ञान का अब भी मुख्य विषय माना जाता है, तथापि वर्तमान में राजनीतिक व्यवहार शासक और शासितों को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तथ्यों पर अधिक बल दिया जाने लगा है।"

राजनीति विज्ञान की परिभाषा (Definition of Political Science)

राजनीति विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यह विषय मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के विषय में विभिन्न मत हैं। विद्वानों ने इसे अपने-अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। यह मतभेद इन विद्वानों द्वारा विभिन्न पक्षों पर विशेष बल देने के कारण उत्पन्न हुआ है। कोई विद्वान् राज्य पर अधिक बल देता है तो अन्य विद्वान् सरकार अथवा राज्य एवं सरकार दोनों पर अथवा व्यक्ति के राजनीतिक जीवन या उससे सम्बद्ध समस्याओं अथवा शक्ति या नीति-निर्माण प्रक्रिया पर बल देते हैं। इस प्रकार परिभाषा की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, उस पर देशकाल का प्रभाव पड़ा है। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हम निम्नांकित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—

राजनीति विज्ञान



उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित है—

(क) परम्परागत उपागम (Traditional Approach)

1. राज्य का अध्ययन

गार्नर (Garner) के अनुसार, “राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरम्भ और अंत राज्य है।”

ब्लुन्श्ली (Bluntschli) के अनुसार, “राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका सम्बन्ध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं? उनका आवश्यक रूप क्या है? उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है?”

गूडनो (Goodnow) के अनुसार, “राजनीति विज्ञान राज्य नामक संगठन की व्याख्या उसके स्थिर एवं गत्यात्मक दोनों रूपों में करता है।”

एक्टन (Acton) के अनुसार, “राजनीति विज्ञान राज्य एवं उसके विकास के लिये अपरिहार्य दशाओं से सम्बन्धित है।”

गेरियर तथा जकारिया (Garies & Zacharia) के अनुसार, “राजनीति विज्ञान एक व्यवस्थित रूप से ठन आधारभूत सिद्धान्तों का अध्ययन करता है जिसके अनुसार राज्य समग्र दृष्टि से संगठित होता है तथा प्रभुसत्ता का उपयोग किया जाता है।”

स्पष्ट है इन परिभाषाओं में राज्य को ही राजनीति विज्ञान का केन्द्र बिन्दु मान कर अधिक महत्व दिया गया है और सरकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये परिभाषाएँ एकांगी कही जाती हैं, क्योंकि राज्य के साथ इनमें अन्य सम्बद्ध पक्षों को पूर्णतः उपेक्षा की गई है।

2. सरकार का अध्ययन

सीले (Secley) के अनुसार, “राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसन्धान करता है जिस प्रकार सम्पत्ति-शास्त्र सम्पत्ति का, जीवशास्त्र जीव का, बीजगणित अकों का तथा ज्यामितिशास्त्र स्थान एवं परिमाण का।”

लीकोक (Leacock) के अनुसार, “राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है।”

एच जे जेम्स के अनुसार, “राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, किन्तु राज्य में सरकार भी अन्तर्निहित है। सरकार राज्य के उद्देश्य को पूरा करने का यंत्र है। वह राज्य को मूर्त रूप प्रदान करता है।”

क्रोसे (Crocce) के अनुसार "रूपरेखा की अपेक्षा जो वास्तविकता की खोज में है उनके लिये राज्य सरकार के अधिकृत कुछ नहीं है। सरकार ये ही उसे पूर्ण रूप प्राप्त होता है।"

इस प्रकार राज्य अपूर्ण संस्था है सरकार उसे पूर्ण रूप प्रदान करती है अतः सरकार का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय होना चाहिए। यह मत भी एकांगी है क्योंकि इसके अनुसार राज्य एवं अन्य मानवीय तत्वों की अपेक्षा की गई है।

3 राज्य एवं सरकार का तुलनात्मक अध्ययन

पॉल जैनेट (Paul Janet) के अनुसार, "सामाजिक विज्ञानों का वह अंग जो राज्य और सरकार के सिद्धान्तों का विवेचन करता है राजनीति विज्ञान है।"

डिमॉक (Dimock) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान राज्य और उसके कानूक शासन सरकार से सम्बन्धित होता है।"

गिल्क्रिस्ट (Gulchrust) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य एवं सरकार की सामान्य समस्याएँ होती हैं।"

गैटिल (Gattel) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के उन संगठनों से सम्बन्धित है जो राजनीतिक इच्छाओं और सरकार एवं उनके कार्यों का निर्माण करते हैं।"

इन परिभाषाओं में राज्य और सरकार के अध्ययन पर विशेष बल देते हुए प्रथम एवं द्वितीय प्रकार की परिभाषाओं में समन्वय स्थापित किया गया है।

4 मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन

लार्स्की (Laski) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों में मानव-जीवन का अध्ययन है।"

हरमन हैलेट (Herman Hallet) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान के सम्पूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव सम्बन्धी आधारभूत मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है।"

विलोबी (Willoughby) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान संगठन की दृष्टि से समाज का अध्ययन है जिसमें समाज व्यवस्थित और प्रगतिशील जीवन व्यतीत करता है।"

इन परिभाषाओं में मानवीय परा को महत्व दे कर, उपरोक्त सभी प्रकार की परिभाषाओं के एकांगी दृष्टिकोण के दोषों के निराकरण का प्रयास किया गया है। राजनीति विज्ञान में राज्य एवं सरकार का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएँ मानव-जीवन को प्रभावित करती हैं।

(ख) आधुनिक उपागम (Modern Approach)

पारम्परगत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने के लिये अपनाया जाता रहा, किन्तु बीसवीं शताब्दी में इसके विकट असंतोष व्यक्त किया जाने लगा जो अमेरी विद्वान् ग्राहम वाल्टस (Graham Wallace) की 1908 में प्रकाशित पुस्तक 'राजनीति में मानव स्वभाव' (Human Nature in Politics) तथा अमेरिकी विद्वान् आर्थर बेन्टले (Arther Bentlay) की पुस्तक 'शासन की प्रक्रिया' (The Process of Government) में प्रखर रूप से प्रकट हुआ। वाल्टस ने कहा है— "राजनीति विज्ञान का अध्ययन अभी तक असंतोषजनक दृश्य में है। राजनीति के सभी विद्यार्थी राजनीतिक संस्थाओं की विवेचना करते हैं, किन्तु मानव के विशेषण की अपेक्षा करते हैं।" आर्थर का मत था कि "हमें एक प्राणहीन राजनीति विज्ञान मिला है क्योंकि उसमें प्रशासनिक संस्थाओं की केवल बाह्य विशेषताओं की औपचारिक व्याख्या ही मिलती है।"

प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) के पश्चात् अमेरिकी विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नवीन दृष्टि से कर पुनः परिभाषित किया जाने लगा। ये परिभाषाएँ विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न पक्षों पर बल देकर की गई जो अधिक व्यापक एवं व्यापकवादी हैं। राजनीति विज्ञान के इस आधुनिक उपागम पर 'व्यवहारवादी' (Behaviouristic) आन्दोलन का विशेष प्रभाव पड़ा। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने इस तथ्य पर बल दिया कि वर्तमान युग में समस्त मानव जीवन ने एक इकाई का रूप ग्रहण कर लिया है अतः इसमें व्यवहारवाद की विशेषताएँ संक्षेप में जोड़ी जाती हैं। मानव-जीवन के विविध पक्षों—राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि को एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। अतः राजनीति विज्ञान को केवल राजनीतिक क्रियाकराणों के अध्ययन तक सीमित न कर, उसमें मानव-जीवन के अन्य पक्षों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। यह समन्वयक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन में 'अन्तःअनुशासनात्मक उपागम' (Inter Disciplinary Approach) को अपनाये जाने पर बल देता है।

इस आधुनिक ढागम के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा में उन साधनों और प्रक्रियाओं को महत्व दिया गया जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएँ कार्य करती हैं, जैसे—'शक्ति', 'प्रभाव', 'सत्ता', 'निष्पत्ति', 'निर्णय', 'मूल्य' आदि। आधुनिक ढागम के अनुसार परिभाषाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. मानवीय क्रियाओं का अध्ययन

क्विन्सी राइट (Quincy Wright) के अनुसार "राजनीति एक ऐसी कला है जो एक वर्ग के हितों को सिद्ध हेतु अन्य वर्ग के विरोध में लोगों को प्रभावित तथा नियंत्रित करती है।"

कैलिने (Caline) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान नियंत्रित समाज में उन कार्यों का अध्ययन करता है जो नियंत्रण में प्रयुक्त होते हैं।"

पीटर मार्केल (Peter Markel) के अनुसार, "राजनीति का महत्व इस तथ्य में निहित है कि समाज में मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता के आधार पर राजनीतिक ढागों से स्वयं का भाग कैसे निर्मित करता है।"

स्टीफन वासबी (Stephen Wasby) के अनुसार, "राजनीतिक वैज्ञानिक मुद्दों को खोज में राज्य के पाँच बड़े तत्वों को कुछ करता है, वही राजनीति विज्ञान है।"

इन परिभाषाओं में समग्रित समाज में मानवीय क्रियाओं के अध्ययन को राजनीति विज्ञान माना गया है तथा मत्स्यगत तत्वों की उपेक्षा की गई है।

2. शक्ति का अध्ययन

लॉसवेल एव कैपलान (Lasswell and Kaplan) के अनुसार, "एक अनुपपन्न विज्ञान के रूप में राजनीतिक विज्ञान शक्ति (Power) की रूप-रचना और उपयोग का अध्ययन है।"

हार्मन हेनर के अनुसार, "आज का राजनीति विज्ञान मुख्यतः राजनीतिक शक्ति की प्रकृति, स्रोत एवं विस्तार का समझा पर विचार करता है।"

उल्मर (Ulmer) के अनुसार, "सभी सामाजिक विज्ञानों में शक्ति की धारणा से इतना सम्बन्धित कोई नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान।"

हुस्जर एव स्टीवेन्सन (Huszar and Stevenson) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ध्येय मुख्यतः मनुष्यों तथा राज्यों में शक्ति सम्बन्ध है।"

रॉबसन (Robson) के अनुसार, "शक्ति एक ऐसा आधारभूत विचार है जो राजनीति विज्ञान के सभी पक्षों को एक सूत्र में आवद्ध कर लेता है।"

इनके आदीनिक मतों पर वेबर, रसेल, वाटकिन, मैकडवेल, मॉन्टगो आदि विद्वानों ने भी राजनीति विज्ञान की शक्ति का अध्ययन बताया है। इनके अनुसार 'शक्ति' (Power) का अर्थ 'सैनिक शक्ति' नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व है। ये परिभाषाएँ सही हैं, क्योंकि शक्ति राजनीति विज्ञान के चरों (Variables) में से एक है, किन्तु एकमात्र नहीं।

3. सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन

रॉबर्ट ए. डाल (Robert A. Dahl) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान समग्रित मानव समाज की व्यवस्था में विद्यमान राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है।"

की (Key) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान शक्ति और शक्ति के प्रभुत्व एवं अधिपत्या के मानवीय सम्बन्धों का अध्ययन करता है।"

बर्ट्रैंड (Bertrand) के अनुसार, "शक्ति सम्बन्धों से होने वाले व्यक्तियों के मध्य स्थायी सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है।"

ये परिभाषाएँ भी सही हैं, क्योंकि ये राज्य, सरकार एवं अन्य राजनीतिक सम्बन्धों की उपेक्षा करती हैं।

4. नीति-निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन

डेविड ईस्टन (David Easton) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिनके अनुसार समाज के निचे मूल्यों का अधिकृत रूप से आवंटन किया जाता है।"

लुईस फ्रीमैन (Luice Freeman) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध व्यक्ति में व्यक्ति एवं व्यक्ति के विस्तार में है।"

नीति-निर्माण प्रक्रिया (Decision Making Process) केवल राजनीति विज्ञान में ही नहीं, अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण है। नीति-निर्माण में मूल्यों का निर्धारण विशेष महत्व रखता है। ईस्टन के अनुसार नीति का तात्पर्य समाज के उन निर्णयों एवं क्रियाकलापों से है जिनसे सामाजिक मूल्यों का निर्धारण होता है। अधिसत्ता द्वारा निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है। समाज के सदस्यों में व्यक्ति के कार्यकलापों का प्रभाव देखा जाता है अतः डेविड ईस्टन ने नीति, अधिसत्ता एवं समाज के अध्ययन को राजनीति विज्ञान के लिये आवश्यक समझकर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, किन्तु ईस्टन की विचारधारा में कुछ कमीयाँ हैं जैसे—राजनीतिक-अराजनीतिक में भेद करने, समाज पर नीति-निर्धारण के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा निर्णय-प्रक्रिया के व्यक्तिपरक (Subjective) होने की कठिनाईयाँ।

राजनीति विज्ञान की परम्परागत एवं आधुनिक उपागमों में समन्वयकारी परिभाषा

परम्परागत एवं आधुनिक उपागमों में उचित समन्वय स्थापित करने हेतु उन्हीं पिर्नाक और स्मिथ (Pennock and Smith) का प्रयास प्रशंसनीय है। इनके अनुसार, "राजनीति विज्ञान समाज के उन सभी प्रभावों, संस्थाओं तथा संगठनात्मक रूपों से सम्बन्धित होता है जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना और संचालन अपने सदस्यों के सामूहिक कार्यों के सम्पादन तथा उनके मतपेदों का समाधान करने के लिये सर्वाधिक अंतर्बोधित (Inclusive) और अन्तिम (Latest) माना जाता है।"

डॉ. इकबाल नाउपण ने पिर्नाक एवं स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा को सर्वथा ठीक बतलाते हुए कहा है कि "राजनीति विज्ञान उन कार्यकलापों का अध्ययन करता है, जिनका सम्बन्ध उसके जीवन के राजनीतिक राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं आदि पक्षों से होता है। यह महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के जीवन का राजनीतिक पहलू उनके अन्य पक्षों से और अन्य पक्षों से राजनीतिक पहलू को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।"

राजनीति विज्ञान की प्रकृति (Nature of Political Science)

राजनीति विज्ञान नामकरण से यथार्थ होता है। इस विषय को विज्ञान माना जाता है किन्तु इस प्रश्न पर काफी विवाद है। "क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है?" विद्वानों का एक वर्ग इसे विज्ञान की श्रेणी में रखता है तथा दूसरा क्लास में। एक तीसरा वर्ग है जो इसे प्राकृतिक विज्ञान न मानकर सामाजिक विज्ञान कहता है। हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि इसे किस सीमा तक विज्ञान कहा जा सकता है। पानु इसके पूर्व विभिन्न मतों का संक्षेप में उल्लेख कर राजनीति विज्ञान की प्रकृति सम्बन्धी मतपेद स्पष्ट करने चाहिये। जर्मन विद्वान् हाजेनबर्ग, रेनहोफर, ट्रोडस्के, वॉन मोहल आदि का यह दृढ़ मान्यता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। आस्तू ने इसे जहाँ "सर्वोच्च विज्ञान माना है, वहीं बर्नार्ड शॉ ने "मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान" कहा है। बोर्दी, हॉम्स, मर्टेस्म्यू, ब्राइस, ब्राशेरी, हरमन फाइनर, लास्की आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान स्वीकार किया है, लेकिन बकल, कापे, मर्टेस्म्यू, वियर्ड मोन्का, बर्क, ब्रोगन आदि विद्वानों की मान्यता है कि इसे विज्ञान कहना उचित नहीं है।

वियर्ड का मत है कि "राजनीति का विज्ञान बनना न तो वांछनीय है और न ही सम्भव।" कैटलिन का कथन है "अभी तक कोई ऐसा बस्तु नहीं है जिसको किसी मान्य अर्थ में राजनीति विज्ञान कहा जा सके।" मोन्का के अनुसार, "हम यह नहीं सोचते कि राजनीति विज्ञान ने अपनी वर्तमान दशाओं में अब तक वास्तविक रूप में वैज्ञानिक रणगण पर प्रवेश कर लिया है।" मोन्का के अनुसार, "राजनीति का विज्ञान से सीधा सम्बन्ध असमर्थिक और सदिग्ध है।" विद्वानों का तीसरा वर्ग इसे सीमित अर्थ में विज्ञान मानने को सहमत है। सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि "राजनीति के विज्ञान होने का अस्तित्व उसी अर्थ में और उसी सीमा तक है जैसे नैतिक विज्ञान का अस्तित्व है।"

विज्ञान क्या है?—अमेरिकन दिकशनरी के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो तथ्यों को व्यवस्थित रूप में एकत्रित करती है और सामान्य नियमों को खोज निकालने का प्रयत्न करती है। विज्ञान में प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन का कार्य कर अन्त में भविष्यवाणी की जाती है। चेम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार "वह ज्ञान जो परीक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली-भाँति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धान्त में समाहित हो, विज्ञान कहलाता है।" अनेक विज्ञान अपने अन्वेषण के विषय तथा एवं सामग्री के सम्बन्ध में दो प्रक्रियाएँ करती हैं—एक में कारण और दूसरे में प्रभावों का वर्णन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है।

कला क्या है?—कला ऐसा ज्ञान होता है जिसका उद्देश्य मानव-जीवन को सुन्दर बनाना होता है। एक विद्वान् का कथन है—"सत्यम् शिवम् और सुन्दरम् की साधना कला है।" कला का उद्देश्य अतीत के जीवन का चित्रण करते हुए भविष्य के लिये मार्गदर्शन करना तथा उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना करना होता है।

राजनीति विज्ञान, विज्ञान नहीं है—राजनीति विज्ञान को निम्न कारणों से विज्ञान नहीं माना जाता है—

(1) सर्वमान्य तथ्यों का अभाव—विज्ञान में तथ्यों पर मतभेद पाई जाती है, जैसे—गुरुत्वाकर्षण का नियम एवं $H_2 + O \rightarrow H_2O$ अर्थात् दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन मिलने पर पानी बन जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के सभी नियमों एवं तथ्यों पर विद्वानों में गहरा मतभेद विद्यमान है।

(2) प्रयोग एवं परीक्षण का अभाव—विज्ञान में प्रयोग एवं परीक्षण किया जाना आवश्यक है, लेकिन राजनीति विज्ञान में मानव से सम्बन्धित अध्ययन किये जाने के कारण न तो नमूना (Sample) हो लिया जा सकता है और न ही किसी सिद्धान्त का प्रयोग बार-बार किया जा सकता है। ब्राड्स (Bryce) ने लिखा है कि “भौतिक विज्ञानों में एक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बार-बार प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु राजनीति में एक प्रयोग बार-बार नहीं दोहराया जा सकता है, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएँ पुनः पैदा नहीं की जा सकती, जैसे—कोई एक ही नदी में पुनः नहीं गिर सकता।” मानव-प्रकृति की भिन्नता तथा परिस्थितियों की विविधता के कारण सिद्धान्त भी बदलते रहते हैं। मानवीय स्वभाव, विवेक, इच्छा, व्यवहार आदि सभी में भिन्नताएँ पाई जाती हैं।

(3) कार्य-कारण सम्बन्धों का अभाव—विज्ञान में निश्चित कारण और परिणाम निकलता है। जैसे—कोई वस्तु ऊपर से पड़े तो नीचे गिरेगी, लेकिन राजनीति विज्ञान में किसी निश्चित घटना के निश्चित कारण नहीं होते।

(4) भविष्यवाणी का अभाव—पदार्थ विज्ञान के अध्ययन के आधार पर निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रयोग एवं परीक्षण सम्भव है। राजनीति विज्ञान में किसी भी रूप में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

(5) मानवीय स्वभाव की परिवर्तनशीलता—राजनीति विज्ञान में ही नहीं वरन् सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिकता का महत्वपूर्ण बाधक तत्व मानवीय स्वभाव की परिवर्तनशीलता है। इसीलिए इसमें प्रयोग, परीक्षण, कार्य-कारण सम्बन्ध, भविष्यवाणी आदि सम्भव नहीं है।

(6) आत्मपरकता—राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अध्ययनकर्ता आत्मपरक दृष्टिकोण रखता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में अनुसंधानकर्ता का दृष्टिकोण वस्तुपरक होता है।

(7) वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अभाव—विज्ञान का अध्ययन वस्तुनिष्ठ (Objective) ढंग से किया जाता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन आत्मनिष्ठ (Subjective) ढंग से होता है, क्योंकि इसमें मानव तटस्थ नहीं रह सकता। पदार्थ के अध्ययन में अनुसन्धान का अपना व्यक्तिगत एवं मूल्य कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन राजनीति विज्ञान को अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत दृष्टिकोण, शिक्षा, सामाजिक बालाकरण आदि प्रभावित कर सकते हैं।

(8) राजनीति विज्ञान के अर्थ एवं नामकरण पर मतभेद—राजनीति विज्ञान के अर्थ और नामकरण पर ही राजनीति विज्ञान के विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। यह कहा जाता है कि इसकी ठन्डी ही परिभाषाएँ हैं, जिनके विषय के विद्वान्। विषय को सम्बोधित करने के लिए ‘राजनीति शास्त्र’, ‘राजनीति दर्शन’, ‘राजनीति विज्ञान’ आदि नामों का प्रयोग किया जाता है।

विद्वान् मानते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। कान्टे (Comte) का मत है कि “राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धान्तों एवं निष्कर्षों के सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिनके आधार पर भविष्य के लिए सही निष्कर्ष निकाले जा सकें।” बर्क ने ध्यात्मिक रूप में कहा है कि “जिस प्रकार हम सौन्दर्य विज्ञान को विज्ञान की सजा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता।”

राजनीति विज्ञान, विज्ञान के रूप में (Political Science as a Science)

राजनीति विज्ञान को तथा सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान नहीं माना जा सकता, लेकिन आरस्तू, बोर्दा, हॉब्स, मॉटस्की, लेविम, ब्लरल्टी, जैतनेक गार्नर जैसे विद्वान् इसे सामाजिक विज्ञान स्वीकार करते हैं। सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि “जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है, उसी धार में और उसी तरह अथवा उसी सीमा तक राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है।” ब्राड्स ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हुए कहा है कि “राजनीति विज्ञान उसी अर्थ में विज्ञान है जिस अर्थ में ऋतु विज्ञान है।” ये विद्वान् अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं—

(1) सर्वमान्य तथ्य—राजनीति विज्ञान में अनेक तथ्य ऐसे हैं, जिन पर विद्वानों में एकमत है, जैसे—प्रशासन शासन अन्य शासनों से श्रेष्ठ है, न्यायाधीश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति निष्पक्ष निकाय द्वारा हो आदि। इस प्रकार राजनीति शास्त्र में बहुत से सर्वमान्य तथ्यों का विकास हो चुका है। मुनरो ने ठीक कहा है कि “आज बहुत से राजनीतिक विद्वान् जिन्हें हम संयोग या मानव प्रयास की उपज समझते हैं, वास्तविक राजनीतिक नियम के रूप में हैं।” लॉर्ड ब्राड्स के मतानुसार, “मानव-प्रकृति की प्रवृत्तियों में एकसूत्रता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा एक ही प्रकार से कार्य करता है।”

(2) प्रयोग का परीक्षण सम्बन्ध—राजनीति विज्ञान में प्रयोग एवं परीक्षण प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सम्भव नहीं है, लेकिन राजनीति विज्ञान में अपनी तरह से प्रयोग एवं परीक्षण होते रहते हैं। गार्नर ने लिखा है कि "प्रत्येक नये कानून का निर्माण संस्था की स्थापना और प्रत्येक नीति का प्रारम्भ इस दृष्टि से एक प्रयोग ही होता है कि यह उस समय तक आस्थाधी या प्रस्ताव रूप में समझा जाता है जब तक परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता सिद्ध न कर दें।" पर्यवेक्षण के आधार पर राजनीति शास्त्र में अनेक निष्कर्ष निकलते हैं। मॉटिस्वु ने 'Spirit of Laws' और बाइस ने 'Modern Democracy' नामक पुस्तक की रचना पर्यवेक्षण के आधार पर की है।

(3) कार्य-कारण सम्बन्ध सम्बन्ध—साधु राजनीति विज्ञान में कार्य-कारण सम्बन्धों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकती, लेकिन विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन के बाद कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अरस्तू ने अपने महान ग्रन्थ 'पॉलिटिक्स' में घटनाओं के सामान्य और विशिष्ट कारण दिए हैं और विश्व की अधिकतर घटनाओं के पीछे ये कारण विद्यमान रहे हैं—राज्य की शक्ति पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का कार्य-क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए। सोक्रेटज शासन में जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहती है यदि सभी निष्कर्ष कार्य-कारण पद्धति से निकलते हैं। गार्नर के अनुसार, "प्रत्येक नये कानून का निर्माण, नई संस्था की स्थापना और नई बात का प्रारम्भ एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक यह अस्थायी समझा जाता है जब तक परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता सिद्ध न कर दें।"

(4) ध्वनिध्वानी सम्बन्ध—प्रकृति विज्ञान और मौसम विज्ञान की ध्वनिध्वानी कभी-कभी गलत निकल जाती है, फिर भी उन्हें विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। अतः राजनीति विज्ञान की ध्वनिध्वानी भी कभी गलत निकल जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे विज्ञान नहीं मानें। डॉ. हरमन फाइजर ने लिखा है, "हम निरपेक्षपूर्वक ध्वनिध्वानी नहीं कर सकते, परन्तु सम्भावनाएँ तो व्यक्त कर सकते हैं।" इसलिए लॉर्ड बाइस ने राजनीति विज्ञान की तुलना अन्तर्ध्वनि विज्ञान जैसे अधिकसित तथा अपूर्ण विज्ञान से की है।

(5) क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विषय—राजनीति विज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित हो चुका है। इसमें राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं के विचारों आदि का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है।

अतः राजनीति विज्ञान को एक आदर्शात्मक विज्ञान कहा जा सकता है।

राजनीति विज्ञान कला के रूप में (Political Science as an Art)

राजनीति विज्ञान को सभी विद्वान कला स्वीकार करते हैं, फिर चाहे बकल जैसे विद्वान इसे पिछड़ी हुई कला के रूप में ही स्वीकार करते हों। अलफ्रेडो ने लिखा है, "राजनीति विज्ञान विज्ञान की अपेक्षा एक कला अधिक है। इसका काम राज्य के सम्बन्धों में व्यावहारिक पथ-प्रदर्शन करना है।" कला के माध्यम से किसी भी वस्तु को सुन्दरतम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान कला है, क्योंकि राज्य प्रत्यक्ष में है, कल्याणकारी है और मानवीय जीवन को सुन्दर बनाने का प्रयास भी करता है।

राजनीति विज्ञान सर्वोच्च जीवन तथा किसी ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप देने की एक श्रेष्ठ कला है। राजनीति विज्ञान मनुष्य द्वारा उत्पन्न ज्ञान को राज्य के निर्माण में सहायता है। राजनीति विज्ञान द्वारा हम मानव के राजनीतिक जीवन का सुन्दर चित्रण कर सकते हैं।

निष्कर्ष—इस प्रकार राजनीति विज्ञान वास्तुतः कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में आता है। यह मानना निराधार है कि राजनीति विज्ञान मात्र कला की श्रेणी में आता है, क्योंकि विज्ञान एवं कला में कोई अन्तर्विरोधी नहीं होता। विलियम श्रमिंगर के अनुसार, "विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है।" हेडलिन राजनीति विज्ञान को 'कला, दर्शन और विज्ञान' तीनों मानता है। शास्वेल के मतानुसार, "राजनीति विज्ञान, कला, विज्ञान और दर्शन का एक संगम है।"

राजनीति विज्ञान का क्षेत्र

(Scope of Political Science)

परिभाषा की भाँति राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी लेखकों ने विभिन्न रूपों में चित्रित किया है। उदाहरणार्थ, अलफ्रेडो के अनुसार, "राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध राज्य के आधारों से है, अतः यह उसकी आवश्यक प्रकृति, विभिन्न स्वरूपों, अभिव्यक्तियों एवं उसके विकास का अध्ययन करता है।" गार्नर के अनुसार, "राजनीति शास्त्र का विषय-क्षेत्र तीन भागों में विभाजित है—प्रथम, राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति का अनुसंधान, द्वितीय, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और उनके इतिहास तथा रूपों की चोखण एवं तृतीय, उपर्युक्त खोज तथा चोखण के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का प्रस्तावना अनुमान सगणना।" हेडलिन पोस्तक के अनुसार, "राजनीति विज्ञान के दो भाग होते हैं—सैद्धांतिक राजनीति

विज्ञान और व्यावहारिक राजनीति विज्ञान। प्रथम भाग में राज्य के मूल तत्वों, सिद्धान्तों और आदर्शों पर विचार किया जाता है जबकि दूसरे भाग में उन साधनों का विवेचन होता है जिनके द्वारा राज्य अपनी शक्ति को अभिव्यक्त और प्रयुक्त करता है।" गिलक्राइस्ट ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के सम्बन्ध में तीन तत्वों पर बल दिया है—“(i) राज्य का वर्तमान स्वरूप (ii) राज्य का ऐतिहासिक स्वरूप एवं (iii) राज्य का भविष्य स्वरूप।” वितोरी ने माना है कि “राजनीति विज्ञान तीन बातों पर विचार करता है—राज्य, प्रशासन तथा विधि।”

राजनीति विज्ञान की क्षेत्र सम्बन्धी परिभाषाओं से हमारे समक्ष तीन विचारधाराएँ आती हैं—(1) इस विचारधारा के अनुसार केवल राज्य (2) केवल सरकार और (3) राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन। किन्तु यह ध्यान रखने योग्य है कि परिभाषा की भौतिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम मानव-तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकते अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन-क्षेत्र में राज्य, सरकार एवं मनुष्य तीनों ही आते हैं।

राज्य का अध्ययन—राजनीति विज्ञान राज्य का सर्वांगीण और सर्वकारिक अध्ययन है। इसमें राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य का वर्तमान स्वरूप, संगठन, अर्थव्यवस्था, दहरेय, कार्यक्षेत्र आदि शामिल हैं। राज्य के स्वरूप के अन्तर्गत राज्यत्व, प्रजातन्त्र आदि सरकारी चीजों का विवेचन आ जाता है। सरकार के संगठन की दृष्टि से विभिन्न अंगों और उनसे सम्बन्धित सिद्धान्तों का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से व्यक्तित्ववाद, समाजवाद, गाँधीवादी आदि विभिन्न सिद्धान्त राजनीति विज्ञान का विषय हैं। इस प्रकार देश का कुशल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, कृत्रिम, सन्धि-समझौते, विस्फोट आदि से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राज्य के तात्कालिक स्वरूप और संगठन में मनुष्य को स्थापित नहीं होता अतः प्रारम्भ से ही वह आदर्श राज्य का स्वप्न लेता रहा है। प्लेटो, आस्तू, मूर आदि ने आदर्श राज्य का चित्रण किया है।

सरकार का अध्ययन—सरकार वह उपकरण है जो राज्य के स्वरूप को क्रियात्मक अभिव्यक्ति करता है। राज्य अनूर्तु वस्तु है और सरकार उसका मूर्त रूप, अतः सरकार के अध्ययन के अभाव में राज्य का अध्ययन कोई महत्व नहीं रखता। राजनीति विज्ञान में सरकार के विभिन्न अंगों, उनके संगठन, कार्यक्षेत्र, उन अंगों के पारस्परिक सम्बन्ध, राजनैतिक दल, जनमत, स्थानीय शासन तथा दबाव-ग्रुपों (Pressure Groups) का विवेचन भी किया जाता है।

मनुष्य का अध्ययन—राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत मनुष्य के अधिकारों, राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों, मनुष्य तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के वे क्रिया-कलाप, जिनका सम्बन्ध राज्य और शासन से है, इस विषय को अध्ययन सम्पन्न है। राज्य मानव प्रगति का सूचक है। राजनीति विज्ञान में परिवर्तन, विचार, सामाजिक एवं बौद्धिक वातावरण आदि का क्रम भी ध्यान में रचना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं सम्बन्धों का अध्ययन—राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के सर्वांगीण अध्ययन के साथ-साथ मानव-तत्व और अपुनिक वातावरण का अध्ययन करता है। एन्सक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेन्ट ने अपने ‘Political Science’ नामक लेख में राजनीति विज्ञान की प्रतिपाद समस्या का विवेचन करते हुए लिखा है कि “आज राजनीति विज्ञान में प्रधानतः राजनैतिक शक्ति की पूर्ति, उसके दृढ़ीकरण और वितरण की समस्या एवं इन प्रक्रियाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा भौतिक, जलवायु, सम्बन्धी, जनैय, पद्धतिक, आर्थिक, सैनिक, नैतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय वातावरण और कानून के अनुसार जनशक्ति राज्य-सम्पादा का स्वरूप धारण करती है। इसमें महत्वपूर्ण राजनैतिक समुदायों, विशेषकर राजनैतिक दलों के संगठन और कार्य का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है।”

सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र सभ के युनेस्को (UNESCO) के एक सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर विचार किया गया था। युनेस्को के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय-क्षेत्र निम्नलिखित प्रमुख चार शाखाओं में विभाजित माना गया है—

(1) राजनैतिक सिद्धान्त (Political Theory) में राजनैतिक विचारों का इतिहास तथा राजनैतिक सिद्धान्त सम्मिलित हैं।

(2) राजनैतिक संस्थाएँ (Political Institutions) में संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रदेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनैतिक संस्थाएँ सम्मिलित हैं।

(3) राजनैतिक दल (Political Parties) में राजनैतिक दलों, समुदाय, जनमत, दबाव समूह, सरकार एवं प्रशासन में जनता के योगदान आदि का अध्ययन निहित है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations) में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्मिलित हैं।

राजनीति विज्ञान की परिभाषा एवं क्षेत्र के परम्परागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अन्तर

(1) परम्परागत दृष्टिकोण मूल्यों पर आधारित है तथा उसमें व्यक्तिनिष्ठता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्यों की उपेक्षा की जाती है और यह वस्तुनिष्ठ है। (2) परम्परागत दृष्टिकोण आदर्शात्मक है, किन्तु आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी है। (3) परम्परागत दृष्टिकोण में राजनीतिक समस्याओं पर बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में व्यक्तियों के व्यवहार पर बल दिया जाता है। (4) आधुनिक दृष्टिकोण अन्तर्विषयी उपागम (Inter-Disciplinary Approach) अपनाता है, जबकि परम्परागत दृष्टिकोण राजनीतिक अध्ययन तक सीमित है। (5) आधुनिक एवं परम्परागत दृष्टिकोण क्रमशः प्रक्रियाओं एवं संरचनाओं पर बल देते हैं। (6) परम्परागत दृष्टिकोण कल्पना पर आधारित है, किन्तु आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है।

रोलॉ पिटोड एवं डेविड मिग का मत है कि—“ये दोनों विचारधाराएँ राजनीति विज्ञान की विषय-वस्तु के दो पहलू मात्र हैं।”

नाम विभेद (Terminological Distinctions)

राजनीति विज्ञान के नामकरण पर प्रचलित मतभेद हैं। इसे राजनीति (Politics), राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy) तथा राजनीति विज्ञान (Political Science) आदि नामों में पुकारा गया है। राजनीति विज्ञान ही सर्व मान्य है तथापि यह देखना आवश्यक है कि विभिन्न नामों के अर्थ में क्या अन्तर है और इस विज्ञान को राजनीति विज्ञान ही क्यों कहा जाये।

राजनीति (Politics)

प्राचीन काल में ‘राजनीति’ शब्द का प्रचलन था। अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम ‘राजनीति’ (Politics) रखा था। प्राचीन यूनान के निवासियों के लिए राजनीति अर्थात् नगर-राज्य का वैज्ञानिक अर्थ राज्य एवं शासन का विज्ञान था और इस शब्द से राजनीति विज्ञान के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों का बोध होता था। यद्यपि मैल्लिनेक, होल्जन्डोरफ, मिर्जविक आदि कुछ आधुनिक लेखकों ने भी ‘राजनीति’ नाम प्रयुक्त किया है, तथापि इस शब्द का प्रयोग केवल व्यावहारिक राजनीति के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है—शासन सम्बन्धी नीति, चुनाव-प्रशासन आदि का अध्ययन। राजनीति शब्द में शासकी, लोक-प्रोद्, दलीय संगठन, नेतृत्व आदि की भावना निहित है, संगठित अध्ययन का साथ नहीं है। प्रचलित रूप में हम राजनीतिज्ञ उस व्यक्ति को कहते हैं जो शासन की तत्कालीन समस्याओं में विशेष रुचि प्रकट करता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राजनीति विज्ञान का ज्ञाता हो अतः राजनीति (Politics) में प्रशासकीय क्रियाओं का वर्णन किया जाता है जबकि राजनीति विज्ञान (Political Science) उस सम्पूर्ण विषय का नाम है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार और मनुष्यों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन विभिन्न पहलुओं के अन्तर्गत किया जाता है।

कतिपय लेखक राजनीति को दो भागों में बाँटते हैं—सैद्धान्तिक राजनीति (Theoretical Politics) और अनुप्रयुक्त राजनीति (Applied Politics) में विभाजित करने के पक्ष में हैं। फ्रेड्रिक पोलक (Fredrick Pollack) ने राजनीति शब्द का व्यापक प्रयोग करते हुए इसका वर्गीकरण निम्नांकित प्रकार से किया है—

सैद्धान्तिक राजनीति	व्यावहारिक राजनीति
(क) राज्य सिद्धान्त (राज्य के मूल तत्त्व, गुण, धर्म, उत्पत्ति एवं आदर्श आदि की व्याख्या तथा विवेचना)।	(क) राज्य का व्यावहारिक तथा वास्तविक रूप और शासन व्यवस्था का अध्ययन।
(ख) सरकार के सिद्धान्त (शासन सम्बन्धी समस्याओं, विभाग व्यवस्था, विधि, राज्य-कार आदि के सिद्धान्तों का अध्ययन)।	(ख) शासन के वास्तविक और व्यावहारिक रूप का अध्ययन, सरकार की कार्य-प्रणाली का वर्णन और विवेचन।
(ग) विधि निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्त (कानून की उत्पत्ति, उद्देश्य, विकास आदि की व्याख्या)।	(ग) विधि और विधि निर्माण प्रणाली, अदालतें आदि।
(घ) कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धान्त।	(घ) व्यक्तिगत रूप में राज्य का सिद्धान्त (कूटनीति, शांति, युद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध)।

राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy)

कतिपय विद्वान् राजनीति को 'राजनीतिक दर्शन' कहते हैं, किन्तु प्रो. गिलक्राइस्ट के अनुसार, "राजनीतिक दर्शन शब्द बहुत सकुचित है।" उनके मत में राजनीतिक दर्शन सम्पूर्ण राजनीति नहीं है तथा केवल राज्य की प्रकृति के मूलभूत सिद्धान्तों, नागरिकता, कर्तव्य और अधिकारों के सैद्धान्तिक पक्ष पर राजनीतिक आदर्शों से सम्बन्ध रखता है। इस मान्यता को स्वीकार करने पर जो विषय सामग्री राजनीति विज्ञान की है, वह राजनीतिक दर्शन के अन्तर्गत नहीं आती। गिलक्राइस्ट के अनुसार, "राजनीतिक दर्शन एक दृष्टि से राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर राजनीति विज्ञान आधारित है। राजनीतिक दर्शन को बहुत-सी ऐसी सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है जो उसे राजनीति शास्त्र से प्राप्त होती है अतः इन दोनों में विभाजन नहीं किया जा सकता, परन्तु आधुनिक प्रथा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट है, जबकि राजनीतिक दर्शन के अर्थ में वह स्पष्टता नहीं आ पाई है।" जे. एच. हैलोवेल (J H Hellowell) के अनुसार, "राजनीतिक दर्शन की दृष्टिकोणीयता इसमें नहीं है कि दृष्टि कैसे घटित होते हैं जितनी इसमें कि राजनीति में क्या घटित होता है और क्यों?" सिजविक के अनुसार, "राजनीति शास्त्र का सम्बन्ध मुख्यतः कुछ मनोवैज्ञानिक आधारों पर पारस्परिक सम्बन्धों की उभय व्यवस्था के निर्माण करने से है जो सभ्य मानव के समाज में होना चाहिए।" राज्य का कार्यक्षेत्र क्या हो, इस विषय पर जो विचारक मनन करते और निष्कर्ष निकालते आये हैं, वे राजनीतिक दर्शन के सिद्धान्त कहे जाते हैं। व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद आदि इसी श्रेणी में आते हैं।

राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में अन्तर है, परन्तु इस विभेद को स्पष्ट करना कठिन है। वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान अधिक व्यापक है और इसका अर्थ सुनिश्चित बन चुका है, इसलिए राज्य सम्बन्धी अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहना उचित है।

राजनीति विज्ञान (Political Science)

राजनीति अथवा राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा 'राजनीति विज्ञान' शब्द अधिक उपयुक्त है। इससे राज्य सम्बन्धी सभी पहलु के ज्ञान का बोध होता है। इसमें सैद्धान्तिक और व्यावहारिक राजनीति दोनों ही सम्मिलित हैं। सैद्धान्तिक पक्ष से इसका सम्बन्ध राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य आदि से है जबकि व्यावहारिक पक्ष से इसका सम्बन्ध राजनीतिक समस्याओं के संगठन तथा उनके हलों से है। डॉ. इचबाल नायपग के अनुसार, "राजनीति शास्त्र शब्द के अधिग्रहण में एक ऐसी व्यापकता एवं सुनिश्चितता है जो राजनीतिक दर्शन में नहीं पाई जाती, इसलिए राज्य सम्बन्धी कार्यों के अध्ययन को राजनीति शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान कहना उचित समझते हैं।"

राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक सिद्धान्त में भेद

(Distinction between Political Science, Political Philosophy & Political Theory)

'राजनीति शास्त्र' अथवा 'राजनीतिक विज्ञान' के नामकरण पर पर्याप्त मतभेद हैं। समाज विज्ञानों में राजनीतिक विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जिसकी कोई निश्चित एवं स्पष्ट रचना नहीं है। इसकी रचना की विविधता, अनिश्चितता एवं अस्पष्टता के कारण इस विषय को समझने में अनेक प्राथम्य उत्पन्न हुई हैं। जेलेनिक के अनुसार, "ऐसा कोई विज्ञान नहीं जिसे एक अन्की रचना की इतनी आवश्यकता हो जितनी कि राजनीति विज्ञान को इसकी रचना ऐसी है जो निश्चित व्यक्तियों को भी समझ में नहीं आती। इन नामपदों का सही अर्थ जाने बिना यह निश्चित करना कठिन है कि 'राजनीति विज्ञान' को कौनसा नाम देना उपयुक्त होगा? अतः इन नामपदों की व्याख्या कर उनका 'राजनीति विज्ञान' से भेद स्पष्ट करना उचित है।

कतिपय विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय राजनीतिक विचारकों के उन सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाता है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं और समस्याओं की समझने में सहायक होते हैं। ये विद्वान् इस विषय को 'राजनीतिक सिद्धान्त' के नाम से पुकारते हैं। उनका मत है कि यह विषय राजनीतिक जीवन के तथ्यों का अध्ययन न कर उनके अपर पर सामान्य नियमों के निर्धारण का प्रयत्न करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक बुद्धिमा की खोज करना है। इनका दृक है कि यह विषय महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों का विवेचन सत्यान्वेषण की दृष्टि से करता है और हमारे समक्ष ऐसे नैतिक मूल्यों तथा मान्यताओं को प्रस्तुत करता है जिनके आधार पर हम समाज के राजनीतिक कार्यों एवं बर्तव्यों का निर्णय कर उनका समझना एवं विवेचना का मूल्यकन कर सकते हैं अतः यह विषय 'राजनीतिक सिद्धान्त' के नाम से पुकारा जाता चाहिए, किन्तु 'राजनीतिक सिद्धान्त' की समीक्षा करते हुए कम्पे (Comte) का कथन है कि 'राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उनकी अध्ययन विधियों, सिद्धान्तों एवं निष्कर्षों के सम्बन्ध में एकाग्र नहीं हैं। इसने विज्ञान की निरालता का अर्थ है। इसने उन तथ्यों का अर्थ है कि उनके आधार पर मध्यम के निरपेक्ष निष्कर्ष निकाले जा सकें।' एस. एन. डूबे के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक दर्शन से तत्काल भिन्न है। दर्शन मूल्यों

से सम्बन्धित आधारभूत समस्याओं की विवेचना करता है। उसके अन्तर्गत विभिन्न मूल्यात्मक सिद्धान्तों के मध्य तार्किक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। उसके सिद्धान्तों अथवा निष्कर्षों का सम्बन्ध वास्तविक तथ्यों अथवा घटनाओं से नहीं होता। सिद्धान्त की प्रकृति इससे भिन्न होती है। वास्तविक घटनाओं अथवा तथ्यों के विश्लेषण से जो सामान्यीकरण (सामान्य नियम) निकलते जाते हैं, सिद्धान्त कहलाते हैं। किसी सिद्धान्त का अनुभव के आधार पर अथवा वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। उन सिद्धान्तों के आधार पर घटनाओं के सम्बन्ध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। किसी सिद्धान्त को सिद्ध अथवा असिद्ध किया जा सकता है, किन्तु किसी दार्शनिक सिद्धान्त का परीक्षण नहीं किया जा सकता। उसे या तो स्वीकार कर लिया जाये अथवा त्याग दिया जाये।"

अतः गिस्त्राइट के अनुसार, "विवेक तथा प्रयोग के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है।" अधिकांश विद्वान् इस विषय के लिए "राजनीति विज्ञान" शब्द को ही सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं।

राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन के उपागम

(Approaches to the Study of Political Theory)

बहुत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों का मतभेद है। इसी मत-भिन्नता के कारण इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों या उपागमों (Approaches) का अनुसरण एवं समर्थन विभिन्न प्रकार से प्रयोजित किया है। आगस्ट कांटे, मिल, व्हाली, हाइन्, टनसेन्ड आदि विद्वानों का प्रयास हम दिशा में उल्लेखनीय रहा है। इन अध्ययन-उपागमों को क्रमिक विद्वान् दो भागों में विभाजित करते हैं—(1) आगमनात्मक उपागम (Inductive Approach) तथा (2) निगमनात्मक या आदर्शमूलक उपागम (Deductive or Normative Approach) जबकि अन्य विद्वान् इन्हें दो पृथक् वर्गों में विभक्त करते हैं—(1) परम्परागत (Traditional), (2) आधुनिक (Modern) या समकालीन (Contemporary)।

परम्परागत उपागम

(Traditional Approaches)

परम्परागत प्रमुख उपागम हैं—दार्शनिक, कानूनी, अवलोकनात्मक, ऐतिहासिक एवं प्रयोगात्मक। परम्परावादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के संस्थात्मक पहलु पर बल दिया जाता है, आधुनिक अध्ययन उपागम में मानव-व्यवहार को महत्व दिया जाता है। आधुनिक उपागमों में प्रमुख हैं—(1) मनोवैज्ञानिक (Psychological) उपागम, (2) मानवीय या आदर्शमूलक (Normative) उपागम, (3) संरचनात्मक प्रक्रियात्मक (Structural Functional) उपागम तथा (4) व्यवहारावादी (Behavioural) उपागम। डॉ. इन्गल्स नारायण के अनुसार—“राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है तथापि यह शैक्षणिक विज्ञानों की तरह सुनिश्चित विज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक स्वरूप की यह अनिश्चितता उसकी अध्ययन पद्धतियों में भी पाई जाती है।”

1. आदर्शमूलक या मानवीय तथा दार्शनिक उपागम

(Normative or Humanistic & Philosophical Approach)

अर्थ एवं व्याख्या

आदर्शमूलक उपागम को मानवीय तथा दार्शनिक उपागम भी कहा जाता है। पद्धति या विधि की दृष्टि से इसे निगमनात्मक उपागम (Deductive Approach) माना जाता है। निगमनात्मक उपागम में सामान्य सिद्धान्तों या मान्यताओं के सत्य होने की कल्पना पूर्व में की कर स्वीकृत की जाती है और पृथक् विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयुक्त कर निष्कर्ष निकलते जाते हैं, अतः इस उपागम में हम सामान्य सिद्धान्त से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं।

इसमें तर्क एवं कल्पना का अधिक आश्रय लिया जाता है। इसमें पूर्व मान्यताओं को सत्य मानकर विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं पर ठोस साक्ष्य का अपने मानकों (Norms) का औचित्य सिद्ध किया जाता है जैसे—राज्य की आदर्श कल्पना कर उसे वर्तमान राज्य के संदर्भ में उचित सिद्ध करना। इस उपागम के अनुसरण करने वालों में प्लेटो, बॉथस मूर, रूसो, मिल, सिजबिक, वेडर, बोसकि आदि प्रमुख हैं। प्लेटो की 'रिपब्लिक' (Republic) तथा थॉमस मूर की 'यूटोपिया' (Utopia) राजनीति विज्ञान के आदर्शमूलक उपागम के उदाहरण हैं। प्लेटो ने एक काल्पनिक आदर्श राज्य की और थॉमस मूर ने स्वर्गिक राज्य का चित्रण कर ठोस आदर्श माना है। इस उपागम का अनुप्रयोग 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी के उपनिवेशवादवादी एवं आदर्शवादी विचारकों ने किया था। आधुनिक युग में रूसो, काण्ट, हीगल, मीन, अरविन्द आदि दार्शनिकों ने इस उपागम का अनुसरण किया है। आदर्शमूलक उपागम में जीवन की वास्तविकता की पूर्ण उपेक्षा की जाती है। इससे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में नैतिकता का सम्बन्ध हो जाता है। इस उपागम पर सर्वाधिक आग्रह सिजबिक तथा सेट ने किया है। सिजबिक के अनुसार, "राजनीति विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य आदर्शों को निर्धारित करना

और भविष्य के लिये मार्गदर्शन करना है।" सेट के अनुसार, "जीवन की सामान्य क्रियाओं में व्यस्त लोगों के लिए प्लेटो एक उतम निदान है।"

आदर्शमूलक उपागम के लाभ (Merits of Normative Approach)

यह विवेक एवं तर्क पर आधारित होने के कारण बुद्धि को विकसित करता है। इसमें वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं पर पूर्व कल्पित मान्यताओं को सत्य मानकर प्रयुक्त किया जाता है तथा इन संस्थाओं के दोष बताये जाते हैं तथा उनके निराकरण प्रस्तुत किये जाते हैं। यह कार्य तर्क और विवेक पर आधारित होता है जिससे बुद्धि विकसित होती है। दूसरे वर्तमान राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाओं में इस उपागम से नैतिकता का समावेश होता है, क्योंकि कल्पित आदर्श नैतिक होते हैं।

आदर्शमूलक उपागम के दोष, त्रुटियाँ एवं परिसीमारें

(Demerits, Errors and Limitations of Normative Approach)

इस उपागम का त्रुटि यह है कि इसमें प्रयुक्त पूर्व धारणाएँ एवं आदर्श काल्पनिक होते हैं और उनका व्यावहारिक जीवन से कम सम्बन्ध होता है, इसलिए सीले और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस उपागम को अशुद्ध और त्याज्य माना है। लास्की के अनुसार, "किसी भी प्रकार की पूर्ण में कल्पित राजनीति आगे चल कर अवश्य ही भग हो जाती है, क्योंकि उसका आरम्भ ही सुविचारित नहीं होता।" ब्लरानी के अनुसार, "यह उपागम केवल कल्पना पर आधारित है जिसका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं।" प्लेटो की राज्य की कल्पना या थॉमस मूर की स्वर्गिक कल्पना व्यवहारवादी नहीं हैं, अतः आदर्शमूलक उपागम के प्रयोग में इसकी परिसीमारों के कारण गलत निष्कर्ष निकलने की आशंका रहती है। आदर्शों के प्रयोग से निष्कर्ष व्यावहारिक तथ्यों के विपरीत निकल जाते हैं जिसके कारण इस उपागम की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। इस उपागम में मूल्यों का आश्रय लिया जाता है जिसके कारण दृष्ट्यता एवं वस्तुनिष्ठता के अभाव में इसमें वैज्ञानिकता नहीं आ पाती। आत्मपरक (Subjective) दृष्टिकोण के कारण यह निष्पक्ष उपागम नहीं है।

आदर्शवादी उपागम की त्रुटियों का निराकरण

इसका उपयोग अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ किया जाना चाहिए। व्यवहारवादी उपागम के साथ इसका सीमित प्रयोग अपेक्षित है। इस उपागम से वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में आदर्शों, मूल्यों एवं सद्ब्यवहार का समावेश तभी हो सकता है जब वर्तमान तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाये। समुचित अनुप्रयोग द्वारा आदर्शवादी उपागम राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविकता की पुनर्रचना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

2. ऐतिहासिक उपागम

(Historical Approach)

अर्थ एवं व्याख्या

सर फ्रेडरिक पोलक ने ऐतिहासिक उपागम का अर्थ एवं व्याख्या करते हुए कहा है—“ऐतिहासिक उपागम में यह खोज की जाती है कि संस्थाओं का क्या रूप रहा है एवं उनका क्या रूप बनता जा रहा है और इस प्रयास में वह संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप की व्याख्या करने की अपेक्षा यह अधिक ध्यान रखती है कि उनका भूतकालीन स्वरूप क्या था तथा वर्तमान स्वरूप कैसे निर्मित हुआ?” यह कथन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के रूप में ऐतिहासिक उपागम को अपनाने का औचित्य प्रकट करता है। राजनीति विज्ञान में इसका विवेचन किया जाता है कि राज्य क्या था, वह क्या है और क्या होगा? इस दृष्टि से वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के विवेचन हेतु अतीत का अध्ययन करना अपरिहार्य हो जाता है, अन्यथा इस उपागम का प्रयोग वर्तमान की तुलना भविष्य से करने हेतु किया जाना वांछनीय है।

गिल्क्राइस्ट के अनुसार, “इतिहास न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है बल्कि यह भविष्य के पथ-प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष प्राप्त करने में भी सहायक होता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राजनीति विज्ञान की आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रक्रियाएँ कार्य करती हैं।” यह कथन ऐतिहासिक उपागम का समर्थन करता है। लास्की (Laski) ने तो यहाँ तक कहा है कि—“सम्पूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है।” अतीत की घटनाएँ असम्बद्ध रूप से घटित नहीं होती, बल्कि अनवरत चलने वाली अटूट शृंखला के रूप में घटित होती हैं जिनके आधार पर भविष्य के पथ-प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जिम्मर्न (Zimmern) के अनुसार, “यह पूत का संपर्क है जो मनुष्यों और समाजों को वर्तमान कार्यों के लिए तैयार करता है। वर्तमान भौतिक चिन्ताओं और जटिल समस्याओं के कारण तनावपूर्ण होता जायेगा, पूत से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता बढ़ती जायेगी।” इस प्रकार राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक अध्ययन से अतीत के प्रकाश में वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है तथा जटिल समस्याओं के समाधान की प्रेरणा प्राप्त होती है। ओकशॉट के अनुसार, “ऐतिहासिक अध्ययन से रहित राजनीतिक शिक्षा अपूर्ण रहती है।” ऐतिहासिक उपागम से राजनीति

विज्ञान का परम्परा प्राचीन रही है। आसू इस उपागम का महत्व समझता था। तास्की, मैकिगवेली, माण्टेस्स्यू, होयल, कार्न मावर्, वेबर, कॉटे, हार्वर्ट स्पेन्सर, मॉर्गन आदि विद्वानों ने भी इस उपागम का अपने दृष्टिकोण से उपयोग किया है। आधुनिक युग में ऐतिहासिक उपागम के अनुयायी बोको, सेविघे, हेनरी मैन्, सीले, गिस्तकादृष्ट, प्रोमैन् आदि प्रमुख हैं। सेट ने इस उपागम के लाभ बताते हुए कहा है—“ऐतिहासिक उपागम से हमारा मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है, हमारे परिदृश्य (Perspective) में सुधार होता है और पटनओं के प्रति हमारी प्रवृत्ति ऐतिहासिक बनती है।”

ऐतिहासिक उपागम की परिसीमाएँ

(Limitations of Historical Approach)

ऐतिहासिक उपागम की परिसीमाएँ निम्नलिखित प्रकार से हैं—

(1) ऐतिहासिक उपागम के अनुप्रयोग में तत्कालीन परिस्थितियों एवं अल्पवर्तकों की भावनाओं से प्रभावित होकर अशुद्ध राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सीले के अनुसार, “इस अध्ययन-उपागम में ‘हम जैसा चाहते हैं’ उसके प्रकाश में प्रत्येक ‘जो है’ उसकी समझने और समझने का प्रयत्न करने लगते हैं।” (2) इस उपागम में उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता। सिजविक के अनुसार, “इतिहास यह निर्णय नहीं कर सकता कि राजनीतिक जीवन में क्या अच्छा तथा क्या बुरा है और क्या उचित अनुचित है? यह निर्णय करना दर्शन का काम है।” (3) इतिहास हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साधनों की खोजने में अधिक सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि अतीत का वर्तमान से सम्बन्ध का सही ज्ञान हमें नहीं हो पाता। (4) यह उपागम तर्कसम्पन्न रूप से प्रयुक्त होने में ही उपयोगी हो सकता है। इतिहास द्वारा राजनीतिक तथ्यों का संकलन मात्र होता है, किन्तु इनसे राजनीतिक निष्कर्ष तब तथ्यों की ठीक और विवेक की कमीटी पर परत कर ही निकाले जा सकते हैं। (5) व्यावहारिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक युग की कठिनाइयाँ और समस्याएँ भिन्न होती हैं। (6) इसके अनुकरण से नियतिवादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है और हम सामाजिक विकास के अपरिवर्तनीय नियमों के समूह स्वयं को असहाय समझने लगते हैं। (7) आत्यन्तिक रूप में इस उपागम के अनुसार से ‘अतीत में खोजें’ की आशाका बनी रहती है जिससे कूटिवादिता की सर्वोच्च भावना विकसित होती है। (8) इस उपागम के विकास की प्रक्रिया का मूल्योत्पन्न नहीं हो पाता। बार्कर का मत है कि “इस उपागम से विकास की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, किन्तु परिणाम का मूल्योत्पन्न नहीं हो पाता। ‘क्या था’ और ‘कैसे हो गया’ इसका अभिलेख मिल जाता है किन्तु ‘क्या होना चाहिए’ इसका ज्ञान नहीं हो पाता।”

ऐतिहासिक उपागम के प्रयोग में सावधानियाँ

(Precautions in the Use of Historical Approach)

(1) ऐतिहासिक पटनओं की अनौत एव वर्तमान की बाह्य समानताओं को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। कपरी समानताएँ एवं सादृश्य (Superficial Resemblance and Parallels) से भ्रम उत्पन्न होने की आशंका रहती है, जैसे—रूस एवं चीन की साम्यवादी क्रांति की समानता से उनके अन्तर का ज्ञान नहीं होता। (2) इस उपागम की मान्यता है कि वर्तमान अतीत का परिणाम है तथा भविष्य वर्तमान का, किन्तु यह केवल सापेक्ष (Relative) सत्य है क्योंकि कभी-कभी अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की पटनएँ असम्बद्ध हो सकती हैं अतः प्राकृतिक विज्ञान की भाँति इस उपागम में सामान्यीकरण अर्थात् नियम निर्धारण द्वारा भविष्य कथन किया जाना संभव नहीं होता, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। (3) कूटिवादिता के दोष से बचने हेतु निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। (4) नियतिवादी होने से सावधानी रखनी चाहिए। इस दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना नितांत वांछनीय है। (5) इस उपागम के प्रयोग में असावधानी से कभी-कभी झूठी आशयवादिता उत्पन्न हो जाती है अथवा निराशयवादिता उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है, अतः ऐसी मनोदशा से बचना चाहिए। (6) राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सर्वत्र इस उपागम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सिजविक के अनुसार, “यदि यह नहीं सोचना कि व्यावहारिक राजनीति की समस्याओं का सही हल ज्ञात करने में ऐतिहासिक उपागम का प्राथमिक प्रयोग होना चाहिए”, अतः इस उपागम का प्रयोग विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए।

3. व्यवहारवादी या आनुभविक उपागम

(Behavioural or Empirical Approach)

व्यवहारवाद का अर्थ (Meaning of Behaviouralism)

व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण का एक विश्लेष उपागम है। इसे द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसकी उत्पत्ति प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व ग्राहम वालास,

बैटसे आदि द्वारा की गई। 1908 में प्रकाशित ग्रन्थ बर्नस की पुस्तक 'Human Nature in Politics' तथा आयर बैटसे की पुस्तक 'The Process of Govt.' में राजनीति विज्ञान के परम्परागत अध्ययन ढांगों का विशेष हुआ है। 1925 से अमेरिका का रिचमोंड विश्वविद्यालय 'नॉल्स मेरिस' के प्रयास में व्यवहारवादी आन्दोलन का केंद्र बन गया। यह ढांग राजनीति विज्ञान के सन्दर्भ में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। 'राजनीतिक व्यवहार' के अध्ययन से यह राजनीति उसकी सगुणताओं, प्रतिक्रियाओं आदि के सम्बन्ध में सत्यार्थपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्याएँ और परिणाम तथा उनकी सक्रियता पर प्रभाव पड़ने विवेचित करना चाहता है। व्यवहारवादी अनुभववादी एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिगत मूल्यों, मानवीय विचारों, कल्पनाओं आदि का विवेचन नहीं है। इस दृष्टि से यह परम्परावादियों के विपरीत विरुद्ध है। डेविड ईस्टन के अनुसार, "व्यवहारवादी परम्परागत दृष्टिकोण के प्रति मात्र व्यवहारवादी विरोध नहीं है बल्कि यह एक व्यावहारिक क्रान्ति है।" रॉबर्ट ए. डहल के अनुसार, "व्यवहारवादी क्रान्ति परम्परागत राजनीति विज्ञान की उपन्यासों के प्रति असंतोष का परिणाम है। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है।" असलु व्यवहारवाद के अर्थ में सभी दृष्टिकोण समान नहीं हैं। कदरिय विद्वानों के अनुसार, यह एक मनोदशा या मनवृत्ति (Mood) है जो दूसरे अन्य विद्वानों की दृष्टि से इसके अन्तर्निहित विचार, सिद्धान्त और कार्यविधियाँ हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध और 1960 के बीच में व्यवहारवाद के साथ ही यह ढांग एक दूनोटी, एक अभिनवकरण और सुधार आन्दोलन के रूप में माना जाता रहा है। इसके अनुयायियों ने इसे एक अनुभववादी विज्ञान (Empirical Science) बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। डहल (Dahl) के अनुसार, "व्यवहारवादी मार्ग की प्रमुख पहचान तत्काल सिद्ध किए जाने वाले उद्देश्य का स्वरूप है और वह है वैज्ञानिकता।" डॉ. इक्वेल नारयण के अनुसार, "व्यवहारवाद का प्रयोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक पद्धति (Method) के रूप में भी किया गया और एक मार्ग (Approach), दृष्टिकोण या रीति के रूप में भी किया गया है तथा इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपपत्ति उनमें है कि इसमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप दिया जाने में सफलता मिली है।—व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति का प्रयोग अब इतना व्यापक एवं उच्च स्तर पर होने लगा है कि व्यवहारवाद पद्धति से बढ़कर अब एक मार्ग (Approach) बन गया है एवं व्यवहार के अन्तर्गत नई अध्ययन पद्धतियाँ विकसित हो गई हैं जिनमें सर्वेक्षण-सर्वेक्षण-पद्धति (Survey Research Method), वैयक्तिक समस्या-अध्ययन पद्धति (Case Study Method) एवं अवलोकन पद्धति (Observation Method) प्रमुख हैं।" अतः व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का लक्ष्यपूर्ण ढांग स्वीकार कर लिया गया है जिससे राजनीति विज्ञान ही नहीं समस्त सामाजिक विज्ञान समृद्ध और विकसित हो रहे हैं। अतएव यह ढांग समस्त परम्परागत अध्ययन-ढांगों के विरुद्ध एक क्रान्ति के रूप में विकसित हुआ है।

व्यवहारवादी ढांग की प्रमुख विशेषताएँ

(Main Features of Behavioural Approach)

व्यवहारवादी ढांग की विशेषताएँ डेविड ईस्टन ने अपने लेख 'व्यवहारवाद का प्रचलित अर्थ' (The Current Meaning of Behaviouralism) में बताई हैं—

- (1) नियमन (Regularisation)—व्यवहारवादियों की मान्यता है कि कुछ व्यक्तियों में मनुष्य कुछ निश्चित विधि से व्यवहार करता है जिसका नियमन कर उन्हें व्याख्या या परिणाम कथन देना सिद्धान्तों के रूप में प्रकट किया जा सकता है। इन व्यवहारों के सामान्य तथ्यों की खोजकर सामान्यीकरण किया जा सकता है।
- (2) सत्यापन (Verification)—इस ढांग द्वारा सगृहीत तथ्यों का सत्यापन पुनः जाँचकर किया जा सकता है।
- (3) तकनीक का प्रयोग (Use of Techniques)—तथ्यों को सूत्र बन हेतु विभिन्न तकनीकों, जैसे—प्रश्नवली, परीक्षण, सहसंयोजक-परिणाम, विश्लेषण विवेचना आदि का प्रयोग किया जाता है।
- (4) परिमाणिकरण (Quantification)—सांख्यिकी (Statistics) का प्रयोग कर सूचक तथ्यों का परिमाणिकरण किया जाता है जिससे दो या अधिक चरों (Variables) का परस्पर सम्बन्ध खोजा जाता है जिसमें निष्कर्ष अधिक स्पष्ट निकाले जा सकते हैं।
- (5) मूल्य-निर्धारण (Value Determination)—पद्धति व्यवहारवादी ढांग में मूल्यों से उच्च दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तदर्थ नैतिक मूल्यों का अनुपयोग मानवधर्म से किया जाता है।
- (6) व्यवस्थान (Systemisation)—सगृहीत तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है जिससे सामान्य सिद्धान्तों एवं निष्कर्षों का निर्माण किया जा सके।
- (7) वैज्ञानिक प्रकृति (Scientific Nature)—व्यवहारवादी अध्ययन का यह आशय रहता है कि वह वैज्ञानिक हो। उसमें साधनों की ओर 'मन-व्यवहार' का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

(8) समग्रता (Integration)—इस उपागम में मानव-व्यवहार को समग्र मानकर उसका एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। समग्रता के कारण ही मानव-व्यवहार में मौलिक एकरता पाई जाती है।

इन विशेषताओं को व्यवहारवादी उपागम के आधारभूत सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह उपागम वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बल देता है। यह अन्तर्विषयी अनुसन्धान (Inter-Disciplinary Research) को प्रोत्साहित करता है। इसमें संशोधकों की अपेक्षा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह उपागम तुलनात्मक अध्ययन को उपयोगी मानता है। व्यवहारवादी उपागम का वैज्ञानिक अनुसन्धान के निष्कर्षों के आधार पर निरन्तर परीक्षा किया जा रहा है। इस उपागम से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, फलतः उसके वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है तथा सिद्धान्त-निर्माण को महत्वपूर्ण माना गया है। किर्क पैट्रिक (Kirk Patrick) के अनुसार, "व्यवहारवादी उपागम वर्तमान परिस्थितियों में स्वीकार्य है। अब ऐसा नहीं रह गया है जिसका मतवाह्य अर्थ लगा लिया जाय, अतः यह शब्द निश्चित हो चला है और राजनीतिक जीवन के अध्ययन हेतु इस उपागम में समाविष्ट पूर्व धारणाओं, क्रियाविधियों, तकनीकों और संरक्षणों को पहचानना सम्भव है।"

व्यवहारवाद की सीमाएँ (Limitations of Behaviouralism)

(1) राजनीतिक पदार्थ की उपेक्षा—व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान बताने के प्रयास में विषय के राजनीतिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। व्यवहारवाद का यह तर्क कि अनुभवजन्यता के द्वारा राजनीतिक घटनाओं को सरलता से समझा जा सकता है, सही नहीं है। प्रायः सभी वर्तमान राजनीतिक व्यवहारवादी अध्ययन राजनीति विज्ञान के वास्तविक मूल्यों को स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। उपयुक्त सिद्धान्त मानव की मौलिक आवश्यकताओं की व्याख्या करता है। मिथ्या राजनीति का लक्ष्य वैयक्तिक हितों को बढ़ावा देता है। व्यवहारवाद का सम्बन्ध मिथ्या राजनीति से है क्योंकि मूल्य-निरपेक्षता विज्ञान के अध्ययन में बाधनीय नहीं है।

(2) अपूर्ण विश्लेषण पद्धति—राजनीति विज्ञान में शोध का सत्य 'क्या है' का पता लगाकर 'क्या होना चाहिए' को बताना है। यह पद्धति जीवन के पहलु का विश्लेषण करती है। व्यवहारवाद केवल 'क्या है' का अध्ययन करता है, 'क्या होना चाहिए' के प्रश्न का उत्तर नहीं देता। वास्तविकता का चित्रण करना अनुचित नहीं है, किन्तु केवल मानसिकता को सामने लाकर रद्द देना तथा उसके निराकरण के लिए कोई उपाय न बताना एक सैद्धान्तिक त्रुटि है।

(3) विशेषाभास से परिपूर्ण—व्यवहारवाद के सिद्धान्त एवं व्यवहार में विशेषाभास पाया जाता है। व्यवहारवादी एक ओर मूल्य-निरपेक्ष होने का दावा करते हैं तथा दूसरी ओर प्रमुख व्यवहारवादी जैसे—डब्लू तथा लिप्सेट मूल्यों पर बल देते हैं। अमेरिका की प्रजातांत्रिक सरकार सबसे अच्छी सरकार है जैसे मूल्य आधारित विचार विधार्थियों के लिए संकेत उत्पन्न कर देते हैं। सच हो यह है कि राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषणकर्ता मूल्य-निरपेक्ष होकर घटनाओं का विश्लेषण करे यह सम्भव नहीं है। राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते समय मूल्य-निरपेक्ष होगा, यह अनुचित धारणा है।

(4) राजनीतिक क्रियाओं की व्याख्या करने में असफल—व्यवहारवादी साहित्य राजनीतिक क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता। वे सभी क्रियाएँ राजनीतिक हैं जिनका उद्देश्य समान की आवश्यकताओं को पूरा करना है। व्यवहारवादी साहित्य इन क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता। अधिकांश व्यवहारवादी व्यक्तियों की स्वाधीन प्रवृत्तियों एवं उन क्रियाओं की व्याख्या करते हैं जिनका उद्देश्य वैयक्तिक हितों का पोषण है, जो मिथ्या राजनीतिक क्रियाएँ हैं। जनवल्याण राजनीति का प्रमुख सत्य है, किन्तु व्यवहारवाद इसकी उपेक्षा करता है।

(5) उत्तर प्रजातन्त्र के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण—लियोट्टरस का यह है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण उत्तर प्रजातन्त्र के प्रति पक्षपातपूर्ण है। लियोट्ट का मत है कि "व्यवहारवादी मान्यताओं को मान लेने से अच्छे समान की श्रेष्ठता का प्रश्न जो हम सदियों से उठाते आये हैं, समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्यवहारवादियों के अनुसार, अमेरिका ने यह प्राप्त कर लिया है जो दूसरे देश नहीं प्राप्त कर सके। उनके विचार से अमेरिकी जनतन्त्र सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था है।"

(6) तकनीक पर अत्यधिक बल—तकनीक पर अत्यधिक बल देने से विषम-यस्तु की उपेक्षा होती है।

(7) कार्यात्मक अध्ययन—क्रियचयन के अनुसार, "इसकी वैज्ञानिकता की धुन का परिणाम राजनीति से बचने के रूप में निकला है।"

(8) नीति-निर्धारण में असफल—मूल्यों की उपेक्षा से यह उपागम राजनीतिक नीति-निर्धारण में सहायक नहीं होता।

व्यवहारवाद एक पूर्ण पद्धति न होकर अन्य पद्धतियों की भाँति जीवन के सभी पक्षों का विश्लेषण न कर केवल एक ही पक्ष का विश्लेषण करता है।

उत्तर-व्यवहारवादी उपागम की विशेषताएँ

(Characteristics of Post Behavioural Approach)

(1) अध्ययन की तकनीकों की विषय वस्तु (Subject Matter) को अधिक महत्व—व्यवहारवादी उपागम में अध्ययन की तकनीक पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसी कारण व्यवहारवादी उपागम में तकनीक का अपेक्षा अध्ययन की विषय-वस्तु को प्रमुखता दी जाती है। एम. एन. दुबे का अनुसार, "उत्तर व्यवहारवादी तकनीक की अपेक्षा विषय-वस्तु को अधिक महत्व दी है।" इस दृष्टि में वे एक का परिचायक दूसरा आवश्यक हो उसे तकनीक को छोड़ जा सकता है। तकनीक वैज्ञानिक हो अपना न हो, अन्यथा यह आवश्यक है कि अनुसंधान का विषय सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक और उपयोगी होना चाहिए।"

(2) सामाजिक परिवर्तन पर बल (Stress over Social Change)—व्यवहारवाद परम्परा के साथ जुड़ गया था लेकिन उत्तर-व्यवहारवादियों को मान्यता है कि सामाजिक संरचना तथा विकासात्मकता के आधार पर सामाजिक परिवर्तन एवं परिवर्तनशीलता को अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन को गति एवं दिशा प्रदान की जाती चाहिए।

(3) मूल्यों के प्रति जागरूकता (Awareness of Values)—उत्तर व्यवहारवादी उपागम मूल्यों के प्रति जागरूकता रखता है। इसका अर्थ सामाजिक मूल्यों के साथ वैज्ञानिक परिवर्तन तथा उनके पहलू किये जाने पर रखा है क्योंकि मूल्य मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में सहायक रहते हैं।

(4) मनीषियों का दायित्व (Responsibility of the Scholars)—उत्तर व्यवहारवाद में इस दृष्टि पर जोर दिया जाता है कि मनीषी का दायित्व वैज्ञानिकों को अपना यह दायित्व स्पष्ट करना चाहिए कि वे अपने काम की क्रियाशील बनने और उसे कार्यरूप में परिणत करने में सहायक हैं।

(5) परिस्थितियों के औचित्य को दृष्टिगत रखना (To keep in view the Justifiability of Circumstances)—उत्तर-व्यवहारवादी उपागम में अनुसंधान का यह दायित्व बनता है कि राजनीति में व्यक्त भ्रष्टाचार को ठोकर न कर उस प्रकट करते हुए परिस्थितियों का औचित्य एवं अनौचित्य का निर्धारण कर, राजनीति को उचित दिशा प्रदान करें।

(6) तथ्यों की प्रासंगिकता का विमर्श (Relevance of the Facts)—अन्वेषण या अध्ययन के तथ्यों को वर्णन करने तक सीमित न रखकर उत्तर-व्यवहारवादी उपागम इन तथ्यों की प्रासंगिकता दर्शाने को भी अपना दायित्व समझता है।

(7) समन्वयवादी दृष्टिकोण (Attitude for Synthesis)—राजनीति विज्ञान के अति परम्परावादी तथा अति वैज्ञानिक अध्ययन-उपागमों में परस्पर समन्वय का प्रदान उत्तर-व्यवहारवादी उपागम करता है। वैज्ञानिकता के साथ राजनीतिक मूल्यों का सम्बन्ध ही अध्ययन की पूर्णता दे सकता है।

5 अन्तर्विषयी उपागम

(Inter Disciplinary Approach)

अन्तर्विषयी उपागम का अर्थ एवं महत्व

(Meaning and Significance of Inter Disciplinary Approach)

'अन्तर्विषयी' उपागम अथवा 'अन्तर-अनुशासनात्मक उपागम (Inter Disciplinary Approach) का अर्थ राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में यह है कि राजनीति विज्ञान अन्य अधिकांश विषयों से घनिष्ठतः सम्बंधित है अतः इन विषयों से सम्बन्ध (Correlate) कर इसका अध्ययन करना चाहिए। यह धारणा आधुनिक काल में अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। कार्ल के अनुसार, "हम दूसरे सहायक विज्ञानों का यथार्थ अध्ययन किये बिना राजनीति विज्ञान एवं राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीकी प्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते, जिस प्रकार गणित के बिना यात्र विज्ञान और रसायनशास्त्र के बिना जीव विज्ञान का। राजनीति विज्ञान ऐसा समाज विज्ञान नहीं है जो व्यवस्थित सामाजिक जीवन में व्यक्ति का अध्ययन करता है। अन्य समाज विज्ञान भी व्यक्ति का अध्ययन करता है नीतिशास्त्र मानव की नैतिकता, आचरण और व्यवहार के औचित्य और अनौचित्य का अध्ययन करता है इतिहास भूगोलीय घटनाओं सम्पत्ता और संस्कृति के विकास का अध्ययन करता है मनोविज्ञान मानव के मनोवेगों, राजन प्रवृत्तियों और भावनाओं का अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञानों के अध्ययन के बिना किया जा सकता है उसका अध्ययन अन्य समाजशास्त्रों के संदर्भ में पूर्ण माना जा सकता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का यह उपागम अन्तर्विषयी उपागम की सही पहलू करता है। राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि सामाजिक विज्ञान मानव-समाज के

अध्ययन से सम्बन्धित होते हैं और राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। योग्य एवं सत्याज का मत है कि—“राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिये अन्य विद्वानों अथवा इन की अन्य शाखाओं की मद्दत आवश्यक है।” सिजविक के अनुसार “यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह अत्यन्त लाभदायक होगा कि हम उस विज्ञान का अन्य विद्वानों या विषयों से सम्बन्ध मालूम करें और यह जानने का प्रयास करें कि उस विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है और स्वयं उसने अन्य विषयों को क्या दिया है?” ये कथन राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों में अंतर्निर्भरता, अंतर्सम्बन्ध तथा उनके परस्पर आदान-प्रदान की अन्तर्गत प्रक्रिया को प्रकट करते हैं एवं राजनीति विज्ञान के अध्ययन के ‘अन्तर्विषयी उपागम’ की महत्ता सिद्ध करते हैं।

अन्तर्विषयी उपागम का विकास (Development of Inter-Disciplinary Approach)

प्लेटो (Plato) का ‘रिपब्लिक’ (Republic) यद्यपि राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है, तथापि वह न्यायशास्त्र, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, शिक्षा, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पर लिखी गई रचना भी है। आरम्भ (Aristotle) की रचना ‘पोलिटिक्स’ (Politics) में राजनीति विज्ञान के विवेचन के साथ-साथ अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के सहसम्बन्ध को भी प्रकट किया गया है। कौटिल्य का ‘अर्थशास्त्र’ राजनीति के अतिरिक्त न्याय, कर नीति, प्रशासन, समाज आदि विभिन्न सामाजिक पक्षों का विवेचन प्रस्तुत करता है, अतः प्राचीन काल से ही राजनीतिक उपागम का रूढ़ि-शून्य विकास होता आया है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के राजनीतिक दर्शन में आर्थिक व्यवस्था को आधार माना गया है। आधुनिक काल में व्यवहारवादी आन्दोलन का प्रादुर्भाव प्रथम विश्वयुद्ध के बाद हुआ जिसने जीवन को सम्पूर्ण इकाई मानते हुए पूर्ण ज्ञान और विषयों की एक-दूसरे की अन्तर्निर्भरता पर बल दिया है।

अन्तर्विषयी उपागम का प्रभाव (Impact of Inter-Disciplinary Approach)

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जिस व्यवहारवादी आन्दोलन का उदय हुआ और जिसने युद्धोत्तरकाल (1945 के बाद) तथा हाल ही के वर्षों में एक व्यापक क्रान्ति का रूप ग्रहण कर लिया है, उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि मानव का सामाजिक जीवन एक सम्पूर्ण इकाई है और जीवन के विभिन्न पक्षों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, फलतः वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत ‘अन्तर-अनुशासनात्मक’ (Inter-Disciplinary Approach) पर अधिक बल दिया जाता है और परिणामस्वरूप इन की जिन नवीन शाखाओं का उदय हुआ है, उनमें प्रमुख हैं—राजनीतिक समाजशास्त्र (Political Sociology), राजनीतिक मनोविज्ञान (Political Psychology), राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political Economics) आदि। सभी अन्तरांगीय क्षेत्र में स्थापित ‘समाज विज्ञान और शोध परिषद’ (The Social Science & Research Council) की समीक्षा विज्ञानों का एक इकाई के रूप में गठन कर रही है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है, उन्होंने राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों से घनिष्टता को और अधिक बढ़ा दिया है। यह कथन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के समस्त उपागमों में नवीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय उपागम के रूप में ‘अन्तर्विषयी या अन्तर-अनुशासनात्मक उपागम’ को महत्वपूर्ण मानता है।

‘अन्तर्विषयी उपागम’ हेतु अन्य समाजशास्त्रीय विषयों का राजनीति विज्ञान से सह-सम्बन्ध

(Correlation of Other Social Sciences with Political Science for Inter-Disciplinary Approach)

1. समाजशास्त्र (Sociology)

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध अन्तर्विषयी उपागम हेतु उपयोगी है। दोनों में बहुमूल्य सामग्री का आदान-प्रदान होता है और दोनों अंतर्निर्भर एवं अंतर्सम्बन्धित हैं। गिडिंग्स के अनुसार, “जिन लोगों ने समाजशास्त्र के आदि सिद्धान्तों को नहीं समझा है, उनके लिये राजनीति शास्त्र पढ़ना उतना प्रकार निष्फल होगा, जिस प्रकार न्यूटन के नियमों को न जानने वाले को ज्योतिष पढ़ना।” गिडिंग्स के अनुसार, “समाजशास्त्र राज्य के संगठन के सम्बन्ध में जनकरी के लिये राजनीति विज्ञान पर निर्भर रहता है। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का बड़ा प्रयोग है। समाजशास्त्र द्वारा सामाजिक जीवन के जिन तथ्यों और नियमों का अध्ययन तथा प्रतिपत्ति किया जाता है, उन्हें राजनीति विज्ञान प्रायः ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है।” कैटलिन के अनुसार, “राजनीति और समाजशास्त्र अलग हैं और वास्तव में ये दोनों एक ही तस्वीर के दो पक्ष हैं।”

2. इतिहास (History)

इतिहास एवं राजनीति विज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध इन विज्ञानों के कथनों से प्रकट होता है—

सीले (Seeley) के अनुसार, “राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है तथा इतिहास राजनीति विज्ञान का मूल है।”

ब्राइस (Bryce) के अनुसार "राजनीति विज्ञान इतिहास एवं राजनीति के बीच की कड़ी है और वह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। यह इतिहास से अपनी सामग्री प्राप्त करता है और राजनीति में उस सामग्री का उपयोग करता है।"

बर्गस (Burgess) के अनुसार "यदि राजनीति विज्ञान और इतिहास का सम्बन्ध तोड़ दिया जाये तो उनमें से अगर एक स्रोत नहीं तो पण अवशेष हो जायेगा और दूसरा कुदे का ढेर मात्र रह जायेगा।"

3. भूगोल (Geography)

बोदी (Bodin) के अनुसार "विविध प्रकार की भौगोलिक स्थिति के लिये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है।"

ब्राइस (Bryce) के अनुसार "किसी भी देश में भौतिक परिस्थितियाँ और उद्योगधकार में प्राप्ता होने वाली समस्याएँ उस राष्ट्र की राजनीतिक समस्याओं को इस प्रकार प्रभावित करती हैं कि उस राष्ट्र के शासन को एक विशेष प्रकार का परिणाम हो जाता है।"

4. अर्थशास्त्र (Economics)

अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध 18वीं शताब्दी में ही स्वीकार किया जाने लगा, जब राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र का अंग समझा जाता था। वैटिल्वे के 'अर्थशास्त्र' में इन दोनों विषयों का सामंजस्य ईसा पूर्व की शताब्दियों में प्रतिष्ठित हो चुका था। बी. एन. अवामी का मत है, "अर्थशास्त्र जीवन के साधन प्रदान करता है जो राजनीति विज्ञान उन साधनों के उचित उपयोग की शिक्षा प्रदान करता है।" आरम्भ में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की शाखा माना है। प्राचीन यूनान में उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political Economy) के नाम से पुकारा जाता था। बिबर्ड (Beard) के अनुसार "अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक तथा आत्मपराक बनकर रह जाता है। राजनीति को समझना तथा पूर्ण ज्ञान के साथ निर्णय करना तभी संभव है जबकि अर्थ से सम्बन्धित प्रकरणों पर गंभीरता से विचार किया जाये।" आर्थर मार्बर्ग के अनुसार "किसी युग में सामाजिक जीवन के स्वरूप का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियाँ ही करती हैं।"

5. मनोविज्ञान (Psychology)

वाटसन (Watson) के अनुसार "मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है।" इस कथन से मनाविज्ञान का राजनीति विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध उजागर होता है। ब्राइस के अनुसार "राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं।" बार्कर (Barker) के मतानुसार "मनुष्य के चारों के अन्तर्गत होने वाली समस्याओं के निराकरण में मनोविज्ञान का प्रयोग करना हो गया है। हमारे पूर्वज पहले जीव विज्ञान की दृष्टि से राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते थे किन्तु अब मनोविज्ञान की दृष्टि से राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते हैं, अतः राजनीति विज्ञान का अध्ययन मनाविज्ञान से सम्बन्धित कर 'अन्तर्विषयी उपागम' के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना उपयुक्त रहता है।"

6. लोक प्रशासन (Public Administration)

बीसवीं शताब्दी में लोक प्रशासन एक पृथक् समाज विज्ञान के रूप में अस्तित्व में आया। लोक प्रशासन एक ऐसा समाज विज्ञान है जो राज्य द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन से संबद्ध प्रक्रिया का अध्ययन करता है। प्रो. विल्सन के अनुसार "यद्यपि यह सत्य है कि राजनीति प्रशासन के लिये भूमि का क्षेत्र प्रस्तुत करती है तथापि इन दोनों विषयों के प्रतिपाद्य विषय पृथक्-पृथक् हैं तथा उन्हें परस्पर मिश्रित करने की श्रुति नहीं की जानी चाहिए।" अतः अन्तर्विषयी अध्ययन उपागम अपनाने समय इन दोनों विषयों का परस्पर स्वाभाविक सम्बन्ध ही किया जाना आवश्यक है जिससे कि उनका पृथक् अस्तित्व बना रहे और वे परस्पर एक-दूसरे का संवर्धन करते रहें।

7. अन्य सामाजिक विज्ञान (Other Social Sciences)

उपरोक्त समाज विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे—नैतिकशास्त्र (Ethics), विधिशास्त्र (Law), मानव-विज्ञान या नृविज्ञान (Anthropology), साहित्य (Literature), शिक्षा (Education) आदि से भी राजनीति विज्ञान का सहसम्बन्ध उनके अध्ययन हेतु अन्तर्विषयी उपागम के अनुप्रयोग की सहायताएँ उपयुक्त करती हैं।

राजनीति विज्ञान : एक विज्ञान के रूप में मान्यता

(Political Science : Recognition as a Science)

राजनीति विज्ञान को विज्ञान इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी एक निश्चित शास्त्रीय अध्ययन पद्धति है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक कार्य-कलापों का अध्ययन निम्न दृष्टि से किया जाता है सभी प्रकार के तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है, उस ज्ञान को एकरूपता के साथ नियमबद्ध करने का प्रयास राजनीति के विद्वानों द्वारा किया जाता है। लॉर्ड

ब्राइस (Bryce) ने अमेरिका की राजनीति विज्ञान परिषद के अध्यक्ष पद से बान्ते हुए कहा था कि—“राजनीति प्रौढ विज्ञान के समान हा एक विज्ञान है। वह इस अर्थ में विज्ञान है कि मनुष्य का प्रवृत्तियों में एकरूपता और निश्चितता होता है जिससे हम मनुष्य के कार्यों से सम्बन्धित नियम बना सकते हैं। जिन कारणों से मनुष्य अनेक परिस्थितियों में एक कार्य इस समय करता है, उन्हीं परिस्थितियों में नियमानुसार उसने वही कार्य भूतकाल में भी किया होगा। कारणों की एकरूपता के कारण हमें अपेक्षा सम्बन्ध निरूपणा जा सकता है उनका नियमित ढंग से जमा कर उनका अध्ययन किया जा सकता है और यह परिणाम निकाला जा सकता है कि उन कार्यों को करने में सहायक प्रवृत्तियाँ साधारणतया ऐसी हैं।”

राजनीति का एक विज्ञान मानने वालों के प्रमुख तर्क हैं—

(1) विज्ञान का शाब्दिक राजनीति विज्ञान या व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का अर्थ है। राज्य, सरकार तथा उसके स्वरूपों का अध्ययन और राजनीतिक विचारधाराएँ राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित रहती हैं। (2) अवलोकन एवं पराष्ण राजनीति विज्ञान में उन्नत विज्ञानों का भौति होना सम्भव है। विश्व की प्रयत्नशीलता में समान के साथ राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं। प्रत्येक नवोन कमून, राति, मस्या आदि सरकार के स्वरूप में किया गया नवोन प्रयोग हा है। यद्यपि पूर्ण विज्ञानों का भौति राजनीतिक पराष्ण नहीं किया जा सकत, तद्यपि वे प्रयोग के रूप में हा है। (3) व्यापक-कारण सम्बन्ध का यद्यपि राजनीति विज्ञान में अन्य धनात्मक विज्ञानों का भौति निधारण नहीं किया जाता, तद्यपि व्यापक-कारण मूल्य का खात्र में राजनीति विज्ञान को खोज करता है। (4) मानव-स्वभाव के कारण यद्यपि मानव के राजनीतिक व्यवहार में परिवर्तन हात रहत हैं और उनमें जड वस्तु को भौति व्यावहारिक एकरूपता नहीं होता, तद्यपि कुछ राजनीतिक नियम एस है जिनमें एकरूपता पाई जाता है। (5) भविष्यवाणी का क्षमता यद्यपि राजनीति विज्ञान में अन्य विज्ञानों को भौति न हा, तद्यपि वह राजनीतिक भविष्यवाणीया अदवा सम्भवनाएँ तो व्यक्त करता हा है। डा. फाइनर (Finer) के अनुसार, “हम निश्चय रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते, किन्तु सम्भवनाएँ हा व्यक्त कर हा सकत हैं।”

राज्य के सिद्धान्त (Theories of State)

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में राजनीति विज्ञान में अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं। प्रमुख सिद्धान्तों की जानकारी इस प्रकार है।

१. सविदामूलक या सामाजिक समझौता का सिद्धान्त (The Contractual or The Social Contract Theory)

राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता सिद्धान्त ने राजनीति विज्ञान को गभीर रूप से प्रभावित किया है। डॉ. इकबाल नावायण के अनुसार, "सामाजिक समझौते का सिद्धान्त मुख्यतः राज्य की उत्पत्ति से सम्बन्धित सिद्धान्त है। इसका प्रयोग राज्य के स्वरूप, प्रयोजन एवं उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिये किया गया है।" राज्य की उत्पत्ति के साथ शासक और शासित के सम्बन्धों की विवेचना के लिए इस सिद्धान्त का व्यापक प्रयोग हुआ है। मूल रूप में यह सिद्धान्त राज्य के दैवी दृष्टिकोण के विरुद्ध एक सामाजिक प्रतिक्रिया थी। इसके प्रतिपादक यह सिद्ध करना चाहते थे कि राज्य का ज्ञात कोई अप्रत्यक्ष सत्ता न होकर उनकी अनुपत्ति है जिन पर राज्य अपनी सार्वभौमिकता (Sovereignty) का प्रयोग करता है।

समझौता सिद्धान्त की व्याख्या

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य ईशवीय (Divine) रचना तथा स्वाभाविक (Natural) सत्ता न होकर एक कृत्रिम (Artificial) संस्था है जिसका जन्म व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के फलस्वरूप हुआ है। मनुष्य ने अपनी चिन्ताओं से मुक्त होने के लिए, जान-बूझकर स्वेच्छिक रूप से राज्य को स्थापित किया है। राज्य के अस्तित्व से पहले मनुष्य प्राकृतिक (Natural) अर्थात् अराजनीतिक (Non Political) अवस्था में रहता था और इस अवस्था की अनुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए ही उन्होंने राज्य का निर्माण किया। समझौते द्वारा सभ्य समाज अर्थात् राज्य का जन्म हुआ। इन तत्वों को निम्नांकित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

(क) प्राकृतिक अवस्था (Stage of Nature)—सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना से पूर्व का जो काल था, वह प्राकृतिक अवस्था का था। प्राकृतिक अवस्था के सम्बन्ध में समझौता सिद्धान्त के प्रतिपादक प्रायः एकमत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं था। प्रत्येक मनुष्य एक-दूसरे का शत्रु था। यह 'अन्यकारपूर्ण और कष्टपूर्ण' स्थिति थी। 'जिसकी ताकती उसकी पैस' (Might is Right) वाली कहावत चरितार्थ होती थी। यह अवस्था निरन्तर युद्ध की अवस्था थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जीवन हर समय संकट में रहता था। अतः मनुष्य का जीवन एकाकी पार्श्विक और पतित था। दूसरी ओर, कुछ विचारकों का मत है कि प्राकृतिक अवस्था 'आदर्श', सलता और परमसुख की अवस्था थी जिसमें लोग स्वर्गिक आनन्द का उपयोग करते थे। इन विचारकों के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था ज्ञानि ५वाँ मैत्री पूर्ण थी। यह मानव जीवन का स्वर्णिम काल था। प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं था और न ही मानव निर्मित 'किसी कानून का अस्तित्व था। मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का नियमन अस्पष्ट प्राकृतिक नियमों (Natural Laws) द्वारा होता था। डॉ. इकबाल नावायण के अनुसार, "मनुष्य का यह जीवन यस्तुतः अच्छा था अथवा बुरा इस पर लेखकों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह अवस्था आदर्श एवं सुखदायक थी और उस समय आनन्द ही आनन्द था। अन्य विचारकों का मत है कि यह अवस्था अनुविधाजनक एवं असह्य थी, परन्तु यह सब स्वीकार करते हैं कि मनुष्यों ने इस समस्या को छोड़ दिया और आपस में समझौता करके राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जीवन व्यतीत करना अनुविधाजनक होने लगा था।"

(ख) समझौता (Contract)—प्राकृतिक अवस्था के अन्त में अनेक असुविधाएँ पैदा हो गईं और मनुष्य ने समझौते द्वारा राज्य की स्थापना की। समझौता क्यों हुआ और समझौते की प्रकृति क्या थी, इन स्थितियों पर विचारकों में मतभेद है। हॉब्स के अनुसार, मनुष्य ने जीवन की रक्षा के लिए लॉक के अनुसार, मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए और स्मिथ के अनुसार, मनुष्य ने समझौता कर राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। कुछ विचारकों के अनुसार समझौता केवल एक हुआ और इसी में समाज और राज्य दोनों की एक साथ स्थापना हुई, परन्तु अन्य विचारकों के अनुसार समझौते दो हुए जिनमें एक से समाज और दूसरे से सरकार की स्थापना हुई। जो विचारक सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं, उनके मतानुसार यह समझौता व्यक्तिगतों ने अन्त में एक-दूसरे से किया। ऐसा था कोई पक्ष नहीं था लेकिन जो विचारक सरकारी समझौते में विश्वास करते हैं उनके अनुसार, इस समझौते में एक पक्ष में जनता थी और दूसरे पक्ष में थर्ड मस्तबूत या क्विन्स अथवा कुछ व्यक्ति थे।

(ग) नागरिक समाज (Civil Society)—समझौते के फलस्वरूप प्राकृतिक अवस्था का अन्त हो गया और राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। मानव समाज एक राज्य का जन्म हुआ। इस अवस्था में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार एवं प्राकृतिक कानून हमेशा के लिए समाप्त हो गए और उनका स्थान मनुष्य के न्यायिक अधिकारों तथा राज्यों के कानूनों ने प्राप्त कर लिया।

समझौते के स्वरूप का विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार लोगों को अपने समस्त अधिकार त्यागने पड़े दो अन्य विद्वानों के विचारों में लोगों को कुछ अधिकारों का परित्याग करना पड़ा। कुछ विद्वानों के विचार से एक समझौता हुआ जबकि दूसरों के अनुसार दो समझौते हुए लेकिन इस बात से सभी सहमत हैं कि लोगों को सुरक्षा प्राप्त हुई और समझौते द्वारा राज्य का निर्माण हो गया। समझौता सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति किसी संविदा या समझौते से हुई, मानव के सामाजिक स्वभाव रक्षित या ईसा द्वारा नहीं।

समझौता सिद्धान्त की आलोचना

(Criticism of Social Contract Theory)

17वीं एवं 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता सिद्धान्त बहुत ही लोकप्रिय हुआ और राजनीतिक विचारों का मुख्य विषय बना रहा। हुकर (Hooker), मिल्टन (Milton), ग्रेमियस (Grotius), वुल्फ (Wolf), कान्ट (Kant), ब्लैकस्टोन (Blackstone), स्पिनोसा (Spinoza) आदि विचारकों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है, परन्तु 18वीं शताब्दी के अन्त के और 19वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारकों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। ह्यूम (Hume), जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham), ब्लान्सली (Bluntschli), बर्क (Burke), ऑस्टिन (Austin), ग्रीन (Green), पोलक (Polak) आदि लेखकों ने इस सिद्धान्त पर अनेक प्रहार किये। ह्यूम ने कहा कि यह सिद्धान्त ऐतिहासिक दृष्टियों के साथ मेल नहीं खाता। बेन्थम के अनुसार, "मैं मौलिक अनुकूल्य को अधिकारों के साथ विवादा करता हूँ और मैं इसे उन लोगों के समर्थन के लिए छोड़ता हूँ जो यह सोचते हैं कि उन्हें इससे अवसरकता है।" सर हेनरी डेन के अनुसार, "हॉब्स ने समाज और सरकार की उत्पत्ति का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, उससे बढ़कर अर्थहीन बात और कुछ नहीं हो सकती।" ब्लान्सली ने इस सिद्धान्त को "बयबक भूल" बतलाया है। ग्रीन इसे एक कल्पना (Fiction) के रूप में देखते हैं। वुल्फ के अनुसार, "यह सिद्धान्त सरल है।" इस प्रकार राजनीति शास्त्र के अनेक विद्वानों ने इसे एक निष्कर्ष, निरर्थक और सरल सिद्धान्त सिद्ध करने की चेष्टा की है।

आलोचकों के प्रहार से राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामाजिक समझौता सिद्धान्त निरास्त हो चुका है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस सिद्धान्त को बान्धनिक, अनैतिहासिक, दार्शनिक दृष्टिकोण से असत्य तथा कानूनी दृष्टिकोण से व्यर्थ एवं अकारण कहा गया है।

समझौता सिद्धान्त का औचित्य अथवा मूल्यांकन

(Justification and Evaluation of Contractual Theory)

यद्यपि समझौता सिद्धान्त की प्रत्येक दृष्टि से आलोचना की गई है, तथापि यह सर्वथा महत्वहीन नहीं है। यह सिद्धान्त सहमति और अनुमति की राज्य का आधार मानता है, रक्षित अथवा राजस्व की अधिग्रहण इच्छा को नहीं। इसीलिए मनुष्य का कथना है कि "इसने राज्य को मनुष्यी सत्ता बढकर निकला राजस्व का विशेष विषय है और प्रजातन्त्रीय शासन के विकास में योग दिया है।" दूसरे, इस सिद्धान्त द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धी आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के विकास में सहयोग मिला है। यदि हॉब्स (Hobbes) के विचारों के आधार पर ऑस्टिन के कानूनी प्रमुख सिद्धान्त के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली है तो स्मिथ की सामान्य इच्छा (General Will) द्वारा लोक-सामन्वय के विचारों को अमूर्त बना दिया। इस सिद्धान्त ने व्यावहारिक राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। टीमो-

इस सिद्धान्त ने दैवी अधिकारों के सिद्धान्त को समाप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस तथ्य पर बल दिया गया है कि राज्य ईश्वरीय इच्छा का फल नहीं है बल्कि इसके निर्माण में मानवीय शक्ति का हाथ है। चौथे इस सिद्धान्त के परिणामस्वरूप इतिहास में अनेक उथल-पुथल और सामाजिक ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रामझोता सिद्धान्त के आधार पर ही 1689 में ब्रिटिश जनता ने राजा जेम्स द्वितीय को गद्दी से उतार दिया था, 1776 में अमेरिका में क्रांतिकारियों के विद्रोह एक सहर टूट गई थी। इस सिद्धान्त ने गत दो शताब्दियों में विश्व इतिहास में भारी बदलावों को एक नयी दिशा प्रदान की है और मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण हाथ बैठाया है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त अप्रामाण्य रहा है।

2 उदारवादी सिद्धान्त (Liberal Theory)

इस सिद्धान्त के प्रवर्तकों में जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और हारबर्ट स्पेंसर के नाम प्रमुख हैं। यह सिद्धान्त 19वीं शताब्दी में लोकप्रियता के चरम पर था। इस सिद्धान्त को अदस्तक्षेप या 'लैसज़ फैर' (Laissez Faire) का सिद्धान्त भी कहा जाता है जिसका अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह जो चाहे कर सके।

उदारवादी या व्यक्तिवादी सिद्धान्त की व्याख्या

उदारवाद एवं व्यक्तिवाद पर्यायवाची माने जाते रहे हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य एक आवश्यक दुर्गुण है और मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी जीव है। प्राकृतिक नियम के अनुसार सबसे पहले वह अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है अतः मानव में सही मार्ग-दर्शन के लिए यद्यपि यह बाह्यीय नहीं, पर आवश्यक जरूरत है कि राज्य का काम रखा जाए। राज्य मानव की अपराधी एवं पारिवारिक प्रवृत्तियों पर एक आवश्यक नियंत्रण है। गार्नर के अनुसार, "व्यक्तिवादियों की यह मान्यता है कि राज्य का अस्तित्व अपराधों की उपस्थिति पर ही आधारित है अतः राज्य का प्रमुख कर्तव्य रक्षा और अपराधों को रोकना ही जाता है न कि विकास और उन्नति।"

व्यक्तिवादी राज्य के कार्यक्षेत्र पर शोक लगाना चाहता है। राज्य के कार्य एवं कानून नागरिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है अतः राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जाना चाहिए। फ्रीमैन (Freeman) के अनुसार, सबसे अच्छी सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। थॉमस हिल ग्रीन के अनुसार, राज्य का कार्य केवल पुलिस कार्य सम्पन्न करना अपराधियों को पकड़ना और सजायागारों पर कठोरतापूर्वक अमल करवाना नहीं है, अपितु राज्य की दयार्थक व्यक्तिगतों के लिये उनकी बौद्धिक तथा नैतिक प्रवृत्तियों में जो कुछ संश्लेषण है, उसे प्राप्त करने का सपना अवसर प्रदान करना है। व्यक्तिवादी राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते। वे केवल राज्य के कार्यों को कम कर देने के पक्ष में हैं ताकि व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिससे वहाँ के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो। राज्य का कार्य नकारात्मक (Negative) है और यह यह है कि व्यक्ति की प्राकृतिक उन्नति के मार्ग में जो बाधाएँ हो उनको हटा दे (To hinder the hindrances)। मानव की भलाई करना अथवा उसकी उन्नति का प्रवर्धन करना राज्य का कार्य नहीं है। राज्य की मूल रूप से एक पुलिस राज्य होना चाहिए। व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य को समाज में शांति और व्यवस्था (Law and Order) देना की बाड़ी आक्रमणों से रक्षा (Defence) तथा नागरिकों के ज्ञान और माल की रक्षा (Protection) करनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज, वापसातय और अनाथालय, अस्पताल इत्यादि छोटाना राज्य का कार्य नहीं है।

व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सभी उदारवादी अथवा व्यक्तिवादी एकमत नहीं हैं। हारबर्ट स्पेंसर ने राज्य के तीन कार्य सुनाए हैं—(1) व्यक्ति की बाहरी शक्तों से रक्षा करना। (2) व्यक्ति की आंतरिक शक्तों से रक्षा करना (3) विधिवत सम्पादित संपत्तियों का पालन करवाना।

कुछ व्यक्तिवादी राज्य को कुछ अन्य कार्य सौंपने को सहमत हैं। गितलब्रिड्ज के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य हैं—(1) राज्य एवं नागरिकों की बाह्य आक्रमण से रक्षा। (2) नागरिकों की आपसी सुरक्षा अर्थात् व्यक्तियों को शारीरिक शक्ति आदि से बचाना। (3) सम्पत्ति की सुरक्षा एवं शक्ति से रक्षा करना। (4) व्यक्तियों की संपत्तियों को भग्न करने वालों से रक्षा करना। (5) अपाहिणों एवं अशक्तों की रक्षा करना। (6) संक्रामक रोगों को रोकना और उनके फैल जाने पर व्यक्तियों की समुचित सहायता करना। अतिस दो कार्यों को सब व्यक्तिवादी स्वीकार नहीं करते।

व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Laissez Faire Theory)

(1) राज्य व्यक्ति के लिए अहितकर नहीं है। राज्य समाज के हितों की पूर्ति करता है अतः समाज के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है। गार्नर के अनुसार, "आज के जटिल एवं साम्य जीवन में राज्य का कार्य व्यक्तियों को केवल

दबाना नहीं है और न केवल ठनका नियेपालक नियमन करना है। राज्य का मूल्य दबावपूर्ण दण्ड की अपेक्षा बहुत अधिक है। वह सार्वजनिक भलाई का सम्मान कायम करता है, उसे प्रोत्साहित करता है और कार्यान्वित करता है।"

(2) व्यक्तिवाद का आर्थिक दृष्टिकोण औद्योगिक युग में सही नहीं माना जा सकता। व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था पूँजीवाद को जन्म देती है जिसमें मजदूरों की भलाई नहीं हो सकती। गिल्क्राइस्ट के अनुसार, व्यक्तिवाद आधुनिक जीवन की जटिलताओं के लिए पूर्णतः अनुपयोगी सिद्ध हुआ है।

(3) यह सिद्धान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हेतु सहयोग के स्थान पर सपर्य का समर्थन करता है। यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व है और दूसरे व्यक्तियों से उसका सम्बन्ध नहीं है, पर यह धारणा निर्मूल है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति का हित समाज या राज्य के हित से अलग नहीं है।

(4) स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ हस्तक्षेप का अभाव नहीं, अपितु उन व्यवस्थाओं का होना है जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का अधिकारिक विकास सम्भव हो सके। स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ वांछनीय तथा लाभकारी कार्य करने की सुविधाएँ हैं। सरकार अपने कार्यों द्वारा हमें विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करती है। आवश्यक प्रतिद्वन्द्व के अभाव में वास्तविक स्वतन्त्रता का अस्तित्व नहीं रह सकता।

(5) समाज में व्यक्ति समाज रूप से समर्थ योग्य धनी एवं शक्तिशाली नहीं होते। यदि राज्य निर्धनता की समस्या से और गुणों से प्राप्त सभ्य आदर्शों की रक्षा न करे तो समाज में अन्याय एवं अराजकता का बोलबाला हो जाए।

(6) व्यक्तिवादी यह नहीं धतलाने है कि जीवन-समय के लिए किसे सबसे उपयुक्त प्राणी मान्य ज्ञान, सर्वाधिक धनी बुद्धिमान या शक्तिशाली को? फिर ये इस पर मौन है कि समाज में बच्चों, रिक्तों तथा बीमारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए क्योंकि ये लोग स्वभावतः दूसरों के आक्रमणों से अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते।

(7) प्राणीशास्त्र के अनुसार जीवन-समय के नियम मनुष्यों पर पूर्णतया लागू नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य पशु न होकर एक विवेकशील और नैतिक प्राणी है।

(8) आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद शोषण का प्रथम देता है और उपभोक्तृओं के हितों के दमन में सहायता करता है। व्यक्तिवादियों का आर्थिक सिद्धान्त के परिणामस्वरूप लोग भूखों मरते हैं, मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है और सफाई तथा स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं होती।

(9) व्यक्तिवादी स्वभाव से मनुष्य को स्वार्थी मानते हैं, परन्तु यह अस्वाभाविक तर्क है। मनुष्य में त्याग तथा समाज सेवा की भावना होती है।

(10) व्यक्तिवादी राज्य तथा सरकार में भेद नहीं करते।

(11) व्यक्तिवादियों का यह कहना है कि व्यक्ति स्वयं अपने हित को सबसे अधिक समझता है, किन्तु मादक पदार्थों का सेवन करने वाले तथा व्यक्तिगरी अपने हित को चिन्ता नहीं करते। इन पर राज्य का नियन्त्रण होना वांछनीय है।

व्यक्तिवादी सिद्धान्त आज लगभग मृतप्राय हो चुका है, किन्तु इसके गुण आज समाजवादी युग में कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। गिल्क्राइस्ट के अनुसार, "आत्म-विश्वास बढ़ाने में अनावश्यक सरकारी विरोध बढ़ाने में, व्यक्ति को समाज का अमूल्य अंग बनाने में व्यक्तिवादी सिद्धान्त ने आधुनिक विचारधारा पर अमला असित प्रभाव डाला है।" हस्तक्षेप सम्बन्धी कानूनों को निरस्त करने में इस सिद्धान्त का महत्वपूर्ण योगदान है। बीसवीं शताब्दी में बढ़ते हुए अधिनायकवाद ने आज व्यक्ति की स्वतन्त्रता को समाप्त कर उसे राजनीतिक दसला के जंगल में घसीटने का प्रयास किया है। साम्यवाद, फासीवाद, नازیवाद जैसी तानाशाही प्रवृत्तियों के विरोधस्वरूप राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति पुनः अग्रद्वार ले रहा है। सर्वाधिकारवाद (Totalitarianism) के विरुद्ध व्यक्ति की यह प्रतिक्रिया आधुनिक व्यक्तिवाद (Modern Individualism) कहलाती है।

3. नव-उदारवाद

(Neo-Liberalism)

सन्धे समय तक उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची माना जाता रहा, किन्तु अब इसे पूर्ण सत्य नहीं माना जाता। अब यह माना जाता है कि व्यक्तिवाद उदारवाद का अन्तिम अंग है, किन्तु दोनों एक नहीं हैं। सेबाइन ने लिखा है कि लगभग 1830 तक उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई विरोध भेद नहीं था क्योंकि उस समय तक ये दोनों विचारधाराएँ व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी थीं, लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई। प्रोन जैसी उदारवादियों के द्वारा सकारणक स्वतन्त्रता पर जोर देने से समाज के सभी सदस्यों के कल्याण और विकास के लिए राज्य के द्वारा समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाने लगी। इसके साथ माना जाने लगा कि यदि जनकल्याण के सत्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के जीवन में राज्य द्वारा हस्तक्षेप करना या व्यक्तियों के जीवन पर नियन्त्रण रखा जाना आवश्यक है तो राज्य के द्वारा ऐसा किया जा सकता है।

नव-उदात्तावाद को लोकतन्त्र का नाम दे दिया जाता है, किन्तु यह निमित्त जर्म में ही मही है। आधुनिक लोकतन्त्र बहुसंख्यक वर्ग की रक्षा में विश्वास करता है जबकि नव-उदात्तावाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति अधिक जागरूक है। इस प्रकार नव-उदात्तावाद लोकतन्त्र से अधिक हो जाता है। उदात्तावाद परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है तथा व्यक्तिवाद और लोकतन्त्र भी इसमें शामिल है। इसके मूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं—1 इतिहास तथा परम्पराओं का विरोध 2 मानवीय स्वतन्त्रता की धारणा में विश्वास 3 मानवीय विवेक में आस्था 4 व्यक्ति साम्य तथा समान और राज्य साम्य 5 व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास 6 धर्मनिरपेक्षता में विश्वास 7 समान और राज्य को कृत्रिम संगठन मानना 8 शासकीय स्वेच्छागतिता का विरोध 9 कानून की प्रधानता में विश्वास 10 अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व शक्ति में विश्वास एवं 11 लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन।

4 मार्क्सवादी एवं साम्यवादी सिद्धान्त (Marxian & Communist Theory)

मार्क्सवादी सिद्धान्त मार्क्स के अनुयायियों अर्थात् सम्प्रदायियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धान्त के समर्थक एंजल्स (Engels), लेनिन (Lenin), स्टालिन (Stalin) मार्गो (Mao) आदि साम्यवादी नेताओं ने इसका विकास किया। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणापत्र (Communist Manifesto) में कहा था—“राज्य सम्पूर्ण बुर्जुआ वर्ग के सामान्य उद्देश्यों का प्रवक्ता करने के लिये उसकी कार्यकारिणी समिति है।” मार्क्सवादियों साम्यवादियों के लिये राज्य सामान्य हितों का पोषक नहीं अतः यह व्यक्ति के विकास में सहायक नहीं। इसके लिए राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका उद्देश्य बुर्जुआ वर्ग के हितों को रक्षा करने हेतु हुआ है। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स (1818-1883) तथा फ्रेडरिक एंजल्स (1820-1895) नामक दो दार्शनिक विचारकों ने एक क्रान्तिकारी विचारधारा का प्रवर्तन किया जो मार्क्सवाद के नाम से लोकप्रिय हुई। यह विचारधारा क्रान्तिकारी थी। रूस, चीन आदि देशों में इस विचारधारा के आधार पर क्रान्तियाँ हुईं और वहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई।

मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति

एम् एर दुबे के अनुसार “मार्क्स का राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अपना पृष्ठ सिद्धान्त है। वह अगस्त के मत से सहमत नहीं है कि राज्य एक प्राकृतिक सभ्यता है और न वह यह मानता है कि राज्य की रचना ईश्वर ने की थी। वह डॉक्टर लोक, क्रूसो आदि द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सभ्यता सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं करता है। यद्यपि मार्क्स के सिद्धान्त में शक्ति का महत्व है तथापि राज्य की उत्पत्ति के शक्ति-सिद्धान्त को वह उस रूप में नहीं मानता जिस रूप में अन्य विद्वानों ने उसका प्रतिपादन किया है। वह विकासवादी सिद्धान्त से सहमत नहीं है। वह यह मानता है कि राज्य का जो स्वरूप आज देखने को मिलता है वह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है किन्तु राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवादी सिद्धान्त को वह स्वीकार नहीं करता।” मार्क्स के अनुसार आदिमानव समाज राज्यविहीन था, न कोई शासक था न शासित, इसलिये उस आदिमानव की समाज-व्यवस्था को मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था कहा है। कालान्तर में आदिम सामाजिक व्यवस्था का विघटन होने लगा, फसल उत्पादन के तरीकों के विकास ने शोषण को सम्भव बना दिया। इस प्रकार समाज में वर्ग-भेद उत्पन्न हो गया। बुद्धि वर्ग-भेद और वर्ग-शासन ने राज्य को जन्म दिया, इसलिये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त को मार्क्सवादी वर्ग सिद्धान्त भी कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग के शोषण से हुई है।

मार्क्सवादी-साम्यवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य की प्रकृति के स्वरूप के लक्षण हैं—(i) राज्य बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। (ii) राज्य वर्गसमर्थक का परिणाम है। (iii) राज्य शोषण का यंत्र है। (iv) राज्य शक्ति और हिंसा पर आधारित है। (v) राज्य स्थायी संस्था नहीं है वह अस्थायी संस्था है। (vi) साम्यवादी व्यवस्था में राज्य का धीरे धीरे सफ हो जाएगा।

राज्य का उद्देश्य—राज्य की ऐतिहासिक भूमिका के आधार पर मार्क्स और एंजल्स की यह अवधारणा बनी कि “राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है। इसका उद्देश्य सभी वर्गों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना नहीं है। पूरे इतिहास में वर्ग-शोषण को कायम रखना ही उसकी भूमिका रही है।” लोकतन्त्र के विषय में मार्क्स का दृष्टिकोण अनुकूल था। यह लोकतन्त्र की व्यवस्था को सामन्ती युग की निरकुश राजतन्त्रीय व्यवस्था से अलग समझता था। 19वीं शताब्दी में मार्क्स ने यूरोप के उन सभी राजनीतिक समर्थों का सम्पर्क किया और सर्वद्वारा वर्ग के निरकुश राजतन्त्र को उन्मूलित करने एवं प्रजातन्त्र की स्थापना करने का आह्वान किया किन्तु मार्क्स की यह धारणा थी कि केवल लोकतन्त्र की स्थापना से ही शोषण विहीन समाज की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके लिये यह आवश्यक है कि मजदूर वर्ग राज्य को पूँजीपतियों के हाथों से छीनकर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर ले।

मार्क्सवादी सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Marxian Theory)—राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धान्त की आलोचना विद्वानों ने निम्नांकित प्रकार से की है—

(1) राज्यविहीन समाज की अवधारणा केवल भ्रम है—राज्यविहीन समाज की स्थापना का आदर्श एव वर्गहीन तथा शोषणमुक्त समाज का निर्माण कोरी कल्पना है, क्योंकि साम्यवादी देशों में शोषण, भ्रष्टाचार, वर्ग-भेद आदि पूर्णतया विन्युत नहीं हो सका है। मनुष्य को नियंत्रित एवं अनुशासित रखने हेतु राज्य की सत्ता की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। वर्तमान में रूस एव पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी व्यवस्था की विफलता इसका प्रमाण है कि साम्यवादी अधिनायकत्व से लोग सन्तुष्ट नहीं थे।

(2) राज्य एक नैतिक सस्या है, वर्गीय संस्था नहीं—मार्क्स की यह अवधारणा कि “राज्य कुछ अल्पसंख्यकों या बुर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा करता है और सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है” एक मिथ्या एव आधारहीन विचार है। वस्तुतः राज्य एक नैतिक सस्या है जो सभी व्यक्तियों के विकास में सहायक होती है।

(3) राज्य स्थायी है, अस्थायी नहीं—मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार यह मानना कि अधिनायकत्व एक सक्रमणकालीन व्यवस्था है और शीघ्र ही राज्य का तोप होकर वर्गहीन समाज की स्थापना हो जायेगी, कोरी कल्पना है। रूस का उदाहरण साक्षी है कि वहाँ 1917 से अब तक राज्य का तोप नहीं हुआ बल्कि साम्यवादी व्यवस्था का ही तोप हो गया है।

(4) मार्क्सवादियों द्वारा मार्क्सवाद का परित्याग—स्वयं कट्टर मार्क्सवादियों ने भी मार्क्सवाद का परित्याग कर दिया है। मार्क्सवाद की यह कल्पना केवल भ्रम रही है कि समस्त विश्व में साम्यवादी व्यवस्था कायम होने के बाद साम्यवादी देशों में अधिनायकवादी राज्य समाप्त हो जायेगा। साम्यवाद का नेतृत्व करने वाले देश रूस ने भी साम्यवाद का परित्याग कर ‘ग्लामोस्ट’ व ‘पेरिस्त्रोयका’ की गोर्बाचोव की नीति अपनाई है।

(5) सामाजिक परिवर्तन क्रान्ति द्वारा न होकर संवैधानिक परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है—साम्यवादियों की यह धारणा मिथ्या निकली कि सामाजिक परिवर्तन केवल क्रान्ति द्वारा ही संभव है, बल्कि अनेक लोकतांत्रिक देशों में संवैधानिक साधनों से भी परिवर्तन हुए हैं। संवैधानिक परिवर्तन अधिक स्थायी होते हैं और क्रान्तिमूलक परिवर्तन अस्थायी।

(6) राज्य केवल बुर्जुआ वर्गों का ही नहीं जनसाधारण (सर्वहारा) का भी हो सकता है—मार्क्सवादी सिद्धान्त की यह धारणा निर्मूल है कि राज्य केवल अल्पसंख्यक सुविधाभोगी बुर्जुआ वर्गों का हित साधन करता है, जनसाधारण का नहीं। विश्व के प्रजातांत्रिक राज्यों के कार्यों और उपलब्धियों से मार्क्स की यह धारणा मिथ्या सिद्ध होती है, क्योंकि राज्य यदि कुछ सुविधाभोगी वर्गों के द्वारा जनसाधारण के शोषण में योग देता है, तो यह कृषि उद्योगशिला, व्यापार-व्यवसाय, कला, साहित्य आदि के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के कार्य कर जनसाधारण का हित-साधन भी करता है।

5. उपनिवेशोत्तर

(Post Colonial)

जो देश उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के अधीन रहने के बाद स्वतन्त्र हुए, वे सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। परम्परागत मार्क्सवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासशील देशों में राज्य की भूमिका का विवरण नहीं मिलता, फिर भी समकालीन मार्क्सवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत इन देशों की राजनीति पर विचार किया जाता है। विकासशील देशों में एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के अलावा लेटिन अमेरिका के वे देश भी शामिल हैं जो इनसे बहुत पहले स्वाधीन हो गए थे, परन्तु पूँजीवादी देशों के दबाव के कारण अब तक अपना विकास नहीं कर पाये थे। इन्हें ‘ताँसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। विकासशील देशों में साधारणतया पूँजीवादी ढंग के औद्योगिक विकास का प्रयत्न किया जाता है, अतः इनमें स्थानीय पूँजीपति वर्ग कामगार वर्ग का शोषण करता है। दूसरी ओर, विश्व के विकसित राष्ट्र विद्यमान देशों के पूँजीपति वर्ग के साथ मिलकर अपने शोषण का तन्त्र बनाए रखते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियाँ, सैनिक सहायता या तकनीकी सहायता के बदले में प्राप्त होने वाली रियायतें विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवादी शोषण के आधुनिक प्रमुख उदाहरण हैं। अतः मार्क्सवाद के अनुसार विकासशील देशों की शोषित राष्ट्रों के नाते विश्व के सर्वहारा वर्ग के साथ मिलकर पूँजीवाद के विरुद्ध लड़ाई सहनी चाहिए।

राज्य सम्प्रभुता (State Sovereignty)

'सम्प्रभुता' अथवा 'प्रभुता' अंग्रेजी शब्द 'Sovereignty' का हिन्दी पर्याय है। यह शब्द अपने मूल रूप 'सुपरेमस' (Supremus) से बना है जिसका अर्थ है—श्रेष्ठ या सबसे ऊपर। इसका तात्पर्य राज्य की परम-शक्ति अथवा सम्प्रभुता से है। यह सम्प्रभुता राज्य का प्राण है। यह राज्य का ऐसा विशेषगुण है जिसे इसके आधार पर राज्य को अनेक समुदायों से पृथक् किया जाता है।

सम्प्रभुता का अर्थ और उसकी परिभाषा (Meaning and Definition of Sovereignty)

'सम्प्रभुता' राज्य की सर्वोच्च इच्छा-शक्ति का पर्याय है। राज्य के सभी व्यक्ति और सामग्री इसके अधीन होते हैं। यह किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होता। सम्प्रभुता बाह्य तथा आंतरिक दोनों पक्षों की दृष्टि से सर्वोपरि होती है। स्ट्रॉय के मतानुसार, "जब इस शब्द का प्रयोग राज्य के साथ किया जाता है तो इसका एक विशेष अर्थ बनाने वाली सर्वोपरि शक्ति से होता है।" सम्प्रभुता को ठीक प्रकार से समझने के लिए इसके दोनों स्वरूपों आंतरिक सम्प्रभुता (Internal Sovereignty) एवं बाह्य सम्प्रभुता (External Sovereignty) को भेदी-भाँति समझ लेना चाहिए। आंतरिक सम्प्रभुता से तात्पर्य है कि आंतरिक रूप से राज्य परम श्रेष्ठ है। इसके अधीनस्थ प्रदेशों में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों के लिए इसके आदेश सर्वथा मान्य हैं। राज्य के समूची नागरिकों और संगठनों पर राज्य की निर्वाण सत्ता होती है। राज्य के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों को राज्य की इच्छा के अधीन रहना पड़ता है। राज्य के अन्तर्गत ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जो राज्य का अपनी आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर सके, अतः आंतरिक क्षेत्र में राज्य सर्वोपरि होता है। यद्यपि के अनुसार, "प्रत्येक पूर्ण स्वतन्त्र राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय होता है जिसे कानून के रूप में सामूहिक इच्छा का निर्माण करने और उसे क्रियान्वित करने की सर्वोच्च सत्ता अर्थात् आज्ञा देने और उसे पालन कराने की अंतिम शक्ति प्राप्त होती है।" आंतरिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता के सम्पन्न बाहरी क्षेत्र में राज्य को स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। बाह्य कार्य-क्षेत्र की दृष्टि से सम्प्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य के बाहर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस पर वह आश्रित हो अर्थात् राज्य को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे सम्बन्ध स्थापित करे—चाहे वह मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखे चाहे युद्ध की घोषणा करे और चाहे हरस्य नीति का अनुसरण करे। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और सन्धियों का राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जानना उस राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। लास्की के अनुसार, "आधुनिक राज्य प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य होता है अतः वह अन्य राष्ट्रों के समक्ष स्वतन्त्र होता है। वह अपनी तद्विषयक इच्छा को इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि उस पर किसी बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।"

आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न होने पर ही सम्प्रभुता का सृजन होता है। होल्डरन के अनुसार, "राज्य द्वारा शासन करने की सर्वोच्च कानूनन शक्ति सम्प्रभुता है।" नैथेन के अनुसार, "राज्य के सब

- 1 Strong, C. F. Modern Political Constitutions, p. 7
- 2 Garner, J. W. Introduction to Political Science
- 3 Lauski A Grammar of Politics.
- 4 Sohm An Introduction of Politics.

जिसे वैधानिक रूप से अग्रिम आदेश देने की शक्ति प्राप्त हो। गार्नर के अनुसार, "कानूनी सम्प्रभु वह शक्ति है जो राज्य के उच्चतम आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर सके, वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों का नैतिकता के सिद्धांतों का तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके।"¹ कानूनी सम्प्रभु के पास असीम शक्ति होती है और उसकी आज्ञा ही कानून होती है। वकील इसी प्रकार की सम्प्रभुता में सम्बन्ध रखते हैं। कानूनी सम्प्रभुता नैतिक-सिद्धांत और जनमत द्वारा सीमित नहीं की जा सकती। कानूनी सम्प्रभुता के आदेश कानून कहलाते हैं और न्यायालय उन्हीं का अनुकरण करते हैं। रिचो (Ritchie) के अनुसार, "वैध-प्रभु कानूनी रूप में वकील का सम्प्रभु है और वह एक ऐसा कानूनी सम्प्रभु है जिसके परे वकील और न्यायालय देखने से इनकार करते हैं। ब्रिटेन में पार्लियामेंट तथा उन्हीं दोनों मिलकर कानूनी सम्प्रभु है। कानूनी दृष्टि से पार्लियामेंट की शक्ति असंमिता है।" डायसी के अनुसार, "ब्रिटिश पार्लियामेंट कानूनी रूप से एक बच्चे को बालिग घोषित कर सकती है, मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति को धरदोह का अपराधी ठहरा सकती है, किसी अवैध बच्चे को वैध करार दे सकती है और यदि उचित समझे तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही भाषले में अपना न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है।"²

(3) राजनीतिक सम्प्रभुता (Political Sovereignty)—वर्तमान में कानूनी सम्प्रभुता एवं राजनीतिक सम्प्रभुता में अन्तर किया जाता है। कानूनी सम्प्रभुता सैद्धांतिक रूप में असंमिता हो सकती है, पर वास्तविक रूप में प्रायः ऐसा नहीं पाया जाता। कानूनी सम्प्रभुता निश्चित होती है। कानूनी सम्प्रभु ही कानून की आँखों में सर्वशक्तिमान है, परन्तु विल्सन के अनुसार, "इस सर्वोच्च शक्ति का व्यवहार में कभी प्रयोग नहीं होता।"³ डायसी के अनुसार, "कानूनी सम्प्रभु के पीछे एक दूसरा सम्प्रभु होता है जिसके सम्मुख कानूनी सम्प्रभु को झुकना पड़ता है।"⁴ यह शक्ति ही राजनीतिक सम्प्रभु है।

गार्नर के अनुसार, "वर्षापि कानूनी सम्प्रभु के पीछे एक अन्य शक्ति रहती है जो कानूनी दायरे पर अग्रान्त असंगठित और कानूनी आज्ञा के रूप में राज्य की इच्छा को प्रदर्शित करने में चले ही असमर्थ हो, तथापि उसके पास ऐसी शक्ति होती है जिसके शासन-आदेशों को व्यवहार में कानूनी सम्प्रभु शिरोधार्य करता है और जिसकी इच्छा ही राज्य में सर्वत्र मान्य होती है। सम्पूर्ण जनता राजनीतिक सम्प्रभुता की सृष्टि करती है।" यह सम्भव है कि कानूनी सम्प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता में मतभेद उत्पन्न हो जाए, किन्तु इन दोनों के संघर्ष में कानूनी सम्प्रभु की मला ही मान्य होगी, इसलिए कानूनी सम्प्रभु की सत्ता सर्वप्रथम है। राजनीतिक सम्प्रभु के आदेशों की उच्चता के बावजूद न्यायालय केवल कानूनी सम्प्रभु के आदेशों को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक विचारक सम्प्रभुता की अवस्थिति को ही स्वीकार नहीं करते। मैटिल की मान्यता है कि, "कानूनी सम्प्रभु के पीछे किसी राजनीतिक सम्प्रभु की खोज का प्रयत्न ही सम्प्रभुता की सम्पूर्ण धारणा को नष्ट कर देता है और वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की एक सूची बनकर रह जाती है।"⁵ कुछ लेखक राजनीतिक सम्प्रभुता को अनिश्चित मानते हैं। लॉक के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति जिस छा सम्प्रभुता की वैधानिक धारणा की ठोस निश्चयता को लाँघता है, उसी समय सब कुछ अस्पष्ट हो जाय है। आधुनिक राज्य में व्यक्तियों का एक विरोध समूह जो कानून और विधान सम्बन्धी असंमिता अधिकारों से सुसज्जित रहता है एक निश्चित और जानने योग्य समूह है। विरोध व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह जिसकी इच्छा वास्तव में सर्वोच्च होती है विरुद्ध करने पर एक अस्पष्ट जटिलता में विलीन होता है।"⁶

राजनीतिक सम्प्रभु वह शक्ति है जो कानूनी सम्प्रभु का स्वरूप बदल सकता है। दीर्घकाल तक उसकी इच्छा मान्य होती है, अतः कानूनी सम्प्रभु के अतिरिक्त भी एक राजनीतिक सम्प्रभु सभी राज्यों में सदैव होता है। सिद्धांत के अनुसार, "एक अर्थ में किसी भी देश की जनता की राजनीतिक शक्ति का अतिम आश्रय-स्थल कहा जा सकता है।"⁷ लास्की के कथनानुसार, "राज्य की इच्छा वास्तव में सत्कार की इच्छा है, क्योंकि जिन नागरिकों पर वह शासन करती है वे उस इच्छा को स्वीकारते हैं। प्रत्येक सरकार की उन लोगों के निर्णय की ध्वज में रहना चाहिये जो उनके कार्यों के परिणामों को सहन करेंगे, अतः जनता की इच्छा एक ऐसी शक्ति है जिसके विरुद्ध अग्रित नहीं हो सकती।"⁸

(4) लोकप्रिय या जनप्रिय प्रभुता (Popular Sovereignty)—लोकप्रिय या जनप्रिय प्रभुता का विकास 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में हुआ। इसका जन्म राजाओं के दैवी अधिकार के विरुद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप दैवी

1. Garner : Political Science & Govt.

2. Dicey, J : German Philosophy and Politics.

3. Wilson : The Elements of Modern Politics.

4. Dicey, J : German Philosophy and Politics.

5. Gould : Introduction to Political Science.

6. Leacock : Elements of Political Science.

7. Sidgwick : Elements of Politics.

8. Laas : A Grammar of Politics.

एक निश्चित मानव-श्रेष्ठ अथवा समूह (Determinate Human Superior) होता है। किसी अनिश्चयात्मक समूह को सम्प्रभु नहीं कहा जा सकता। (3) यह निश्चित मानव-श्रेष्ठ किसी अन्य उच्चाधिकारी की आज्ञा का पालन नहीं करता। इसकी इच्छा का सभी लोगों द्वारा पालन किया जाता है। सम्प्रभु की आज्ञाएं अन्यायपूर्ण और अविचारपूर्ण होने पर भी वैध होती हैं और उनका विरोध नहीं किया जा सकता। (4) सम्प्रभु की आज्ञा का समाज पूर्ण रूप से अनुपालन करता है, फलतः यह अनुपालन न होकर एक आदत के रूप में होता है। थोड़े समय के लिए यदि किसी के हाथ में आज्ञा प्रदान करने की शक्ति आ जाए तो उसे सम्प्रभु नहीं कहा जा सकता। (5) सम्प्रभु के आदेशों को कानून होते हैं। इसके बिना किसी कानून का अस्तित्व नहीं रह सकता। सम्प्रभु की आज्ञा नहीं मानने वाले को दण्ड दिया जाता है। (6) सम्प्रभुता अविभाज्य होती है। उसका विभाजन करने का मतलब उसे समाप्त करना है। सम्प्रभुता निरपेक्ष होती है, उस पर मीमांसा नहीं होती।

ऑस्टिन ने सम्प्रभुता को निश्चित, स्वेच्छाचारी, स्थायी, सर्वव्यापी, असंश्लेषित और अविभाज्य माना है। उसका सम्प्रभुता-सिद्धान्त एक थकील के दृष्टिकोण का द्योतक है।

ऑस्टिन के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Austin's Theory of Sovereignty)

ऑस्टिन के सम्प्रभुता और विधि सम्बन्धी सिद्धान्तों की बहुत तीव्र आलोचना निम्नांकित बिन्दुओं पर हुई—

(1) समाज में निश्चित जनश्रेष्ठ को खोजना कठिन है—सर हेनरी मैन के अनुसार इतिहास में शासकों का कोई ऐसा उद्धारण नहीं मिलता जिसे ऑस्टिन का 'निश्चयात्मक सम्प्रभु' कहा जा सके। गणराज्य भी अनेक नैतिक प्रभावों, जनता की परम्पराओं और परम्परागत कानूनों से प्रभावित अथवा प्रतिबंधित होते थे। परम्पराएं और ऐति-रिवाज युगों के विकास का परिणाम होते हैं जिन्हें किसी भी निश्चयनात्मक व्यक्ति या 'निवाय' द्वारा बनाया नहीं जा सकता।

(2) आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं होता—आज जिस सम्प्रभुता में विश्वास किया जाता है वह ऑस्टिन के 'निश्चयात्मक सम्प्रभु' की धारणा से मेल नहीं खाती। संघात्मक राज्यों में यह पता लगाना असम्भव है कि निश्चयात्मक प्रभुसत्ता कहाँ स्थित है? यदि अमेरिका के संविधान में संशोधन करने वाले निकाय को सम्प्रभु माना जाए तो यह गलत होगा, क्योंकि वह 'निश्चयात्मक' नहीं होगा है। अमेरिकी संविधान में तो ऑस्टिन के 'निश्चयात्मक सम्प्रभु' की खोज निकालने का प्रयास एक अर्थहीन प्रयास ही है, क्योंकि वहाँ न तो कौनिस सर्वोच्च है न कार्यपालिका, न न्यायपालिका और न संविधान ही।

(3) सम्प्रभुता असंश्लेषित नहीं—ऑस्टिन ने अपने सिद्धान्त में पूर्ण रूप से अनुराग और वैधानिक दृष्टिकोण अनन्यता है तथा सम्प्रभुता के दारिद्र्यिक पक्षों की उपेक्षा की है। यह विचारणीय है कि यदि सम्प्रभु की आज्ञाओं का पालन केवल 'आदतन' किया जाता है तो उसे असंश्लेषित मानना अत्यधिक होगा।

(4) कानून सम्प्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता—उसके अनुसार कानून सम्प्रभु का आदेश मात्र है। साक्ष्यों का आरोप है कि कानून को केवल 'आदेश मात्र' मानना दो न्यायवैलोक्य के लिए 'बल की खाल खींचना' है। प्रत्येक समाज में ऐति-रिवाजों का महत्व होता है जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्राचीन राज्यों में सामाजिक प्रदाय और परम्पराएँ ही कानून का कान बनती थीं। यदि हम ब्रिटिश बर्मन्सों की स्थिति को देखें तो पढ़ें कि वकील सैलमन्टिन दृष्टि से संसद में गया था उसे परिचित किया जा सकता है और इसका उत्तर मोजा जा सकता है, तबले व्यङ्ग्य में सम्प्रभु द्वारा अधिष्ठाता बर्मन्सता को स्वयं की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना नहीं बदला जा सकता।

(5) सम्प्रभु कानूनों का निर्माता नहीं—वर्तमान अनुसंधानों ने यह निश्चित कर दिया है कि सम्प्रभु कानूनों का निर्माता नहीं होता। कानून सामाजिक आवश्यकता की अभिव्यक्ति होते हैं। जेम्स ह्यूम्स एवं लॉको का दर्ज़ है कि राज्य कानून नहीं बनाता, वरन् कानून ही राज्य को बनाता है।

(6) शक्ति को अत्यधिक महत्व—कानून की अवज्ञा करने वाले को दण्डित किए जाने की बात कहकर ऑस्टिन ने शक्ति के दत्व पर अधिक बल दिया है, पर वास्तविकता यह है कि हम कानून का पालन दण्ड के दप से नहीं, बल्कि कानून के अनुरूप व्यवहार करने की इच्छा से करते हैं।

(7) सम्प्रभुता अविभाज्य नहीं—ऑस्टिन ने सम्प्रभुता को अविभाज्य माना है। लॉर्ड इस मत से सहमत नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कार्य का विभजन किया जाता है। ऐसे विभाजन के बिना कोई भी सरकार प्रभावशाली बन नहीं सके। सरकार के दोन प्रमुख अंग हैं—कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इन प्रकार राज्य में केवल एक ही सम्प्रभु मानने की अपेक्षा दोन सम्प्रभु मानने होगे। दूसरे, प्रत्येक अंग अनेक इकाइयों में विभक्त बन होता है। सरकार के ये दोन अंग एक-दूसरे से इन्ने पृथक् और स्वतंत्र होते हैं कि बिना एक-दूसरे

एकलवादी सम्प्रभुता सिद्धान्त।¹ द्यूष्वी की दृष्टि से सम्प्रभुता का सिद्धान्त कपोल-कल्पित, निस्सार और मूल्यहीन है, अतः उसे लोक-नियमों के साहित्य से निकाल फेंकना ही अधिक श्रेयस्कर है। सम्प्रभु राज्य मर चुका है अथवा अपनी मौत की अंतिम घड़ियों गिन रहा है। लिण्डसे ने कहा है कि "यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्प्रभुता के सिद्धान्त का अन्त हो चुका है।"²

सात्त्विक बहुसत्तावाद के प्रमुख समर्थक थे। उनका कहना है कि "सम्प्रभुता के वैध सिद्धान्त को राजनीतिक दर्शन के लिए कानूनी बनाना असम्भव है।"³ वे मानते हैं कि "यदि सम्प्रभुता की सम्पूर्ण अवधारणा का अंत कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए एक स्थायी लाभ होगा।" क्रेब के अनुसार, "सम्प्रभुता के सिद्धान्त को राजनीतिक दर्शन से निकाल देना चाहिए।" मैटिल के अनुसार, "अनेकवादी इससे इनकार करते हैं कि राज्य असाधारण संगठन है। उनका मत है कि अन्य समुदाय समान रूप से महत्वपूर्ण और स्वाभाविक हैं। समुदाय अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिए उसी प्रकार सम्प्रभु है, जिस प्रकार राज्य अपने उद्देश्य के लिए है। वे इस तथ्य पर बल देते हैं कि राज्य अपनी सीमाओं में कुछ समूहों के विरुद्ध अपनी इच्छा को सक्रिय रूप नहीं दे सकता। वे इससे इनकार करते हैं कि राजा द्वारा बल-प्रयोग का अधिकार उसे किसी प्रकार का कोई श्रेष्ठतर अधिकार प्रदान करता है। वे सब समूहों के समान अधिकारों पर समान बल देते हैं, जो अपने सदस्यों की वफादारी के पात्र हैं और जो समाज में बहुमूल्य कार्य सम्पादन करते हैं, फलस्वरूप सम्प्रभुता बहुत से समुदायों में विभाज्य होनी चाहिए। यह अविभाज्य इकाई नहीं है और राज्य को सर्वोच्च या असीमित नहीं माना जा सकता।"⁴ इस प्रकार बहुसत्तावादियों ने अपने तर्कों का आक्रमण प्रभुता के एकल सिद्धान्त पर किया है। उनका कहना है कि वर्तमान राज्य जटिल है और अपने कार्य-भार से दबा जा रहा है। इस दबाव के कारण राज्य के कार्यों में ढील आती जा रही है। आर्थिक कार्य करने से राज्य की कार्यकुशलता दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है, अतः कार्यकुशलता लाने के लिए एक विकेंद्रीकृत राज्य आवश्यक है। थार्ड के अनुसार वर्तमान राज्यों में ऐसा लगता है जैसे केन्द्र को पछापा हो गया हो और शीर्ष बिन्दुओं पर रक्तहीनता महसूस होती हो। मैकडवर् ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सर्वसाधारण का अर्थ है; अयोग्यता और असामर्थ्य।⁵

बहुसत्तावादी द्वारा एकलवाद पर आक्रमण का विवेचन निम्नांकित प्रकार से किया जा सकता है—

1. विभिन्न संघों (संगठनों) का दृष्टिकोण

बहुसत्तावादी विचारों का जन्म मध्य युग में हुआ, जबकि यूरोपीय व्यापारियों और शिल्पियों के स्वरासी संघों को आत्यधिक अधिकार प्राप्त थे, धीरे-धीरे राजतन्त्र के उदय के साथ इन संघों का लोप हो गया। बहुसत्तावाद के प्रारम्भिक विचारक गर्क (Gierke) तथा मैटलैण्ड (Maitland) थे जिन्होंने मध्यकालीन युग में इस सिद्धान्त का सूत्रपात किया। उनके अनुसार समाज में जो विभिन्न समुदाय पाए जाते हैं, वे मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं। समुदायों का अपना व्यक्तित्व होता है। कानूनों के निर्माण में इन समुदायों का अपना योग होता है। प्रत्येक समुदाय की अपनी एक इच्छा होती है तथा उनकी अपनी सामूहिक चेतना होती है। वे राज्य में होते हुए भी राज्य से स्वतन्त्र होते हैं। यद्यपि ये दोनों लेखक राज्य की धारण प्रभुता को नहीं मानते, तथापि उसकी ठीकतर वैधानिक स्थिति को स्वीकार करते हैं। वे समाज के अन्तर्गत संघों के सहयोग के लिए एक संघोजक के रूप में राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं।

दुर्खीम (Durkheim) प्राचीन व्यावसायिक संघों की पुनर्जीवित करना चाहता था। उसके अनुसार व्यावसायिक संघों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए और उन्हें आर्थिक नियन्त्रण का स्रोत माना जाए। मैकडवर् ने अपनी पुस्तक 'The Modern State' में बहुसत्तावाद का समर्थन किया है। उसके अनुसार समाज के अनेक संघों में से राज्य एक सभ्य है, यद्यपि उसके कर्तव्य कुछ विशिष्ट प्रकार के हैं। संघ राज्य की भाँति समाज के लिए स्वाभाविक है, अतः राज्य को उनका निर्माण करने वाला नहीं माना जा सकता। मैकडवर् के अनुसार, "आज विशाल सभ्यारं न राज्य का भाग है और न उसकी प्रजा मात्र। वे अपने स्वयं के अधिकार के आधार पर विकसित होती हैं। वे अधिकारों का प्रयोग उसी प्रकार करती हैं जिस प्रकार राज्य स्वयं करता है। व्यावसायिक संघ के सदस्य राज्य की अपेक्षा अपने व्यावसायिक संघों के प्रति अधिक भक्ति प्रदर्शित करते हैं। वित्त और उद्योग, वाणिज्य और कृषि जैसे संघ स्वयं को राज्य के दास न समझकर उसके मालिक बनने की चेष्टा में रहते हैं, अतः राज्य को चाहिए कि सांस्कृतिक संगठनों में अपने अधिकारों को कायम रखते हुए गैर-राजनीतिक संगठनों में से एक स्थान अपने लिए प्राप्त कर ले।"⁶

2 अन्तर्राष्ट्रियता तथा राज्य

बहुसत्तावादियों के अनुसार राज्य का एकत्व और निकुञ्ज-सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता का मूल कारण है। संसार के सभी राष्ट्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं। उनके आर्थिक हित एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। इतना होते हुए भी प्रत्येक राज्य को अपनी-अपनी सम्प्रभुता पर गर्व है। इसी सम्प्रभुता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े और विश्वयुद्ध होते हैं। कठिनाई का मुख्य कारण यह है कि दुनियाँ में कोई ऐसी सार्वभौम प्रभुत्व सम्पन्न शक्ता नहीं है जो इन प्रश्नों का समाधान कर सके। केवल एक ही उपाय है कि राष्ट्रीय राज्यों की सम्प्रभुता का उन्मूलन कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, विश्व-शान्ति कायम नहीं हो सकती और सम्बन्धित राष्ट्र संधि की वही दशा हो सकती है जो राष्ट्र संधि की हुई थी।

3 कानूनी दृष्टिकोण

ह्यूम्स और क्रैब ने बहुसत्तावाद को कानूनी दृष्टि से देखा। ह्यूम्स के अनुसार कानून राज्य से स्वतन्त्र और राज्य की अपेक्षा अधिक ध्यातक है। कानूनी सम्प्रभु को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इसका निर्णय वर्तमान में कानून द्वारा किया जाता है। राज्य का कर्तव्य इन कानूनों को बल देना है। सच तो यह है कि कानून राज्य को संगठित करते हैं न कि राज्य कानून को। इसी तरह कानून राज्य को सीमित करता है राज्य कानून को नहीं, अतः इन लेखकों की मान्यता है कि राज्य के अधिकारों पर बल न देकर कर्तव्यों पर बल दिया जाना चाहिए। राज्य राजनीतिक शक्ति के रूप में एक कानूनी यंत्र है। वह कानून की सीमाओं में रहता है और कानून को स्थायी रखने के लिए ही वह जीवित रहता है। इसका उद्देश्य आज्ञा देना न होकर सेवा करना है। इसकी विरोधता सम्प्रभुता में निहित न होकर जनहित में है।

बहुलवाद की आलोचना (Criticism of Pluralistic Theory)

(1) सम्प्रभुता का विभाजन उसके नष्ट करना है। राज्य से प्रभुत्व-शक्ति को छीनकर बहुलवादी चाहते हैं कि राज्य समुदायों के मध्य सहयोग और संतुलन रखने का कार्य करे। यह परम्परा विरोधी दृष्टिकोण है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति को छीन लेने में बाद यह किस प्रकार सम्भव हो सकेगा कि राज्य विभिन्न समुदायों के मध्य सहयोग और संतुलन स्थापित करे। बहुसत्तावादियों के पास इसका कोई निश्चित सार्थक उत्तर नहीं है।

(2) बहुलवादी सम्प्रभुता के एकावकाटी सिद्धान्त को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए हैं। डीगल और उसके कुछ अनुयायियों को छोड़कर सम्प्रभुता के परम्परागत सिद्धान्त के समर्थकों में से किसी ने राज्य को निकुरा नहीं बतलाया है। डेदाहरणार्थ—बोर्दो, होम्स, बेन्थम आदि विचारकों का विशेष करना अनैतिक नहीं है लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य की सम्प्रभुता सीमित और तात्कालिक है। गैटिल के अनुसार राज्य अपना कर्तव्य स्वीकार कर सकता है अपने कार्यों पर स्वयं बंधन लगा सकता है और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दे सकता है। यह सारा कार्य वह अपनी कानूनी सम्प्रभुता का परित्याग किए बिना कर सकता है।¹ अद्वैतवादियों या एकत्ववादियों का इतना कहना है कि जब राज्य किसी निश्चित क्षेत्र में कानूनी सत्ता स्थापित करता है तो उस क्षेत्र में वह अन्य सब सामाजिक सत्तों से श्रेष्ठ और उच्च होता है। डॉ. आशीर्वाद के अनुसार, “अद्वैतवादी राजु जिस पर बहुलवादी प्रहार करते हैं बहुत हद तक एक कल्पनात्मक जीव है।”²

(3) बहुसत्तावाद के विरोधियों का कहना है कि राज्य की सम्प्रभुता के बिना समाज का कार्य नहीं चल सकता। सम्प्रभु राज्य के बिना समुदाय संघर्षरत हो जायेंगे। बहुलवाद का अतिरिक्त परिणाम अराजकतावाद में होगा। सम्प्रभुता का विभाजन हो जाने से वह नष्ट हो जाएगी और समाज में अशान्ति तथा अव्यवस्था के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहेगा। इस स्थिति से समाज के समस्त व्यक्तियों और सत्तों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्राकृतिक अवस्था की दशा सौट आयेगी। इस तरह समाज और विकास को पीछे धकेलने की स्थिति पैदा हो जाएगी, अतः यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की सम्प्रभुता अविभाज्य और अखण्ड रहे। राज्य ही अपनी सम्प्रभुता के बल पर विभिन्न समुदायों के पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से या शक्ति द्वारा सुलझा सकता है तथा उनके अनुचित कार्यों पर नियन्त्रण रख सकता है।

(4) बहुलवादी सर्व-शक्तिमान् राज्य का विशेष करते हुए अंत में राज्य की सर्वोपरिता स्वीकार कर लेते हैं। कोकर का कहना है कि बहुलवादी सभी आवश्यक सत्तों को पूर्ण समनता की स्थिति प्रदान करने की इच्छा रखते हुए परिश्रमशील

1 Maciver The Modern State

2 Chelvi : Introduction to Political Science

3 Ashirvatham : Political Theory

राज्य को प्रथम स्थान देने के लिए विचार हो जाते हैं। गिरफ्तारी और मेटलैण्ड संघों को वास्तविक व्यक्तिगत प्रदान करते हुए भी यह स्वीकार करते हैं कि राज्य अन्य सामाजिक संस्थाओं से ऊपर सर्वोच्च समूह है। पालकाक्षर सभी संघों और संस्थाओं को राज्य के अधीनस्थ मानते हैं।

(5) नैतिकता, शक्ति-विचार आदि से सम्बन्धित आपत्तियों का राज्य की सम्प्रभुता से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये आपत्तियाँ शासन की स्वेच्छाचरिता के विरुद्ध हैं। राज्य और शासन के सम्बन्ध में शक्ति में बढ़कर ये आपत्तियाँ उठाई गई हैं।

(6) बहुलवादियों का यह विचार प्रामाणिक है कि समाज के विभिन्न संघ एक समानांतर देखा पर चलते हैं, उनके कार्य-क्षेत्र अलग हैं, उनमें एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वे एक-दूसरे के अधिकारों और कर्तव्यों का अतिक्रमण करते हैं। सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू एक-दूसरे से सम्बन्धित है। उदाहरणार्थ, सभी आर्थिक पक्षों का राजनीतिक पहलू होगा और सभी राजनीतिक पक्षों का आर्थिक पहलू।

(7) बहुलवादियों का कानूनी दृष्टिकोण प्रामाणिक है। यद्यपि उनका कहना ठीक है कि कानून का स्रोत तथा उसकी वैधता राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, तथापि वे यहाँ अद्वैतवादी विचारधारा को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। अद्वैतवादी या एकत्ववादी यह स्वीकार करते हैं कि कानून के विभिन्न स्रोत हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें वैधानिक मान्यता अभी प्राप्त हो सकती है जब वे राज्य द्वारा स्वीकृत कर लिए जाएँ। एकत्ववादी कानून के औपचारिक तत्त्वों पर विशेष ध्यान देते हैं जबकि बहुलवादी इन्हें स्वीकार नहीं करते। एकत्ववादियों के अनुसार कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है जिसे न्यायालय लागू करते हैं, लेकिन बहुलवाद कानून के लिए इस विधानी मान्यता को आवश्यक नहीं समझते। डॉ. इब्राल नारपण के अनुसार, "बहुसंयुक्तवादी विचारधारा के अनुसार कानूनी दृष्टिकोण से राज्य की स्थिति अन्त्यता की नहीं है और उसकी सम्प्रभुता को अन्त्य एवं अविभाजनीय नहीं माना जा सकता।"

(8) यदि बहुलवादियों के मतानुसार समाज में विभिन्न संस्थाओं में प्रभुसत्ता को बाँट दिया जाए तो वे इतनी शक्तिशाली हो जाएँगी कि राज्य या अन्य कोई शक्ति उन्हें अपने नियन्त्रण में नहीं ले सकेगी जिससे अनेक गम्भीर समस्याएँ पैदा हो जाएँगी। यदि समाज में विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सम्प्रभुता प्रदान कर दी जाए तो इससे समाज विघटन की ओर अग्रसर होगा तथा संस्थाओं में पारस्परिक विवाद बढ़ जाएँगे।

(9) अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर बहुलवादियों द्वारा सम्प्रभुता के सिद्धान्त का विरोध सही नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय आधार, व्यवहार और कानूनों का आदर करना चाहिए, लेकिन इन सीमाओं को कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है और राज्य कानून के रूप में इनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि जनमत अथवा नैतिकता के दबाव से राज्य उनका पालन करता है तो ऐसा वह स्वेच्छा से करता है और इससे उसकी सम्प्रभुता खण्डित नहीं होती। यदि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों या कानूनों अथवा नियमों या संधियों का विरोध करने की ठान ले तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राज्य को ऐसा करने से रोक सके।

बहुलवादी विचारधारा का अधिकार और महत्व

(Justification and Importance of Pluralistic Theory)

इस निष्कर्ष पर पहुँचने पर कि राज्य-प्रभुत्व का परम्परावादी सिद्धान्त सही है, बहुलवादी विचारधारा के महत्व को स्वीकार करना पड़ता है। बहुलवादी विचारधारा ने व्यक्ति और समुदाय का महत्व दर्शाकर एक उपकार किया है। राज्य को शक्ति को सीमित करके तथा कानून की शक्ति पर बल देकर उन्होंने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है जो प्रभुत्व को आलोचना नहीं है, बल्कि राजनीतिक संगठन का एक स्वतंत्र सिद्धान्त है। यद्यपि राज्य के प्रभुत्व पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं हो सके, तथापि उसे नैतिक मर्यादों का पालन अवश्य करना चाहिए। बहुलवादी सिद्धान्त का इसमें पर्याप्त बल है कि राज्य के प्रभुत्व सिद्धान्त का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहिष्कार होना चाहिए। इस क्षेत्र में उसने नुर्गु और तन्मयसदा के अतिरिक्त अन्य कोई सुधार नहीं किया। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और विचारधाराओं के साथ धनमानी करने के कारण मानवता की विनाशक युद्धों का मुख देखना पड़ा है। मिस फोलेट के अनुसार, "बहुलवादी वर्तमान राज्य की सर्वोच्चता के अधिकार को नष्ट करते हैं। वे संघों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करने एवं अपने कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में स्वायत्तता देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे स्थानीय जीवन को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में हैं।" मैरिसम एवं बार्न्स के अनुसार, "बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य की सम्प्रभुता के सिद्धान्त का त्याग किया गया है और न ही इसका त्याग किया जा सकता है।"

3. मार्क्सवादी सिद्धान्त

(Marxist Theory)

मार्क्स का विश्वास था कि जैसे ही पूँजीपति वर्ग पूरे तरह नष्ट हो जाएगा, राज्य विनष्ट हो जाएगा और ऐसा समाज पैदा होगा जिसमें न तो राज्य होगा और न कोई वर्ग। ऐसे समाज में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देगा और अपनी आवश्यकतानुसार पाएगा। मार्क्स का यह विश्वास था कि इस सामाजिक स्थिति में पैदा हुआ नया इन्सान इवांशवादिक एवं स्वतः स्फूर्त रूप से समाज के सामान्य हित के अनुरूप अपने हित दान सकेगा।

ऐसी स्थिति में मार्क्स राज्य की प्रभुत्व सत्ता को समाप्त कर, समस्त पूर्ण समाज को स्थापना करना चाहता था। उसके राजनीतिक दर्शन में प्रभुसत्ता की धारणा का महत्व गौण नजर आता है।

4. सार्वभौमीकरण तथा राज्य

(Globalisation and the State)

घातान्तर, विचार व्याप्त एवं संचार के साधनों के कारण सात विश्व एक हो गया है। विज्ञान की प्रगति के कारण हुए इस परिवर्तन से राज्यों की सम्प्रभुता और सीमाओं के सम्बन्ध में नई अवधारणा जन्म लेने लगी है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का भी किसी देश से महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहता है। आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन द्वारा किए जा रहे वैश्वीकरण आदि कारण एक देश के हित दूसरे देश से संयुक्त होते जा रहे हैं। यद्यपि संसार के सभी राष्ट्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं, तथापि प्रत्येक राज्य को अपनी सम्प्रभुता पर गर्व है। इस गर्व पूर्ण सम्प्रभुता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़े और विश्वयुद्ध होते हैं, परन्तु अभी तक विश्व में ऐसी कोई सार्वभौम सत्ता नहीं है जो इन परेशानियों से विश्व को राहत दिला सके। एक ही उपाय है कि राज्यों की सम्प्रभुता का दमन कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा विश्व में शान्ति स्थापित होने में कठिनाई होगी। कभी तो ऐसा साबित है कि कहीं संयुक्त राष्ट्र सच की दशा राष्ट्र सच जैसी न हो जाए। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के महान समर्थक सास्की के अनुसार राज्य बाध प्रभुसत्ता पर रोक लगाना आवश्यक है। वस्तुतः सार्वभौमीकरण हो जाने के कारण एक सुसंगठित, एकीकृत और प्रभावशाली विश्व संगठन की नितान्त आवश्यकता है।

□□□

प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकार

(Democracy and Human Rights)

प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त : प्राचीन तथा समकालीन

(Democratic Theory : Classical and Contemporary)

आधुनिक युग 'प्रजातन्त्र का युग' है। विश्व के अधिकांश देश प्रजातन्त्र के समर्थक होने में गैरव अनुभव करते हैं फिर चाहे वे पूँजीवादी हों या साम्यवादी। यूनेस्को की लोकतन्त्र पर विरोधों की एक समिति ने कहा था कि—“आज इतिहास में पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि कहीं भी लोकतन्त्र विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है। लोग अपने विरोधियों पर लोकतन्त्र का रजु होने का आरोप लगाते हैं, किन्तु जिन समस्याओं का वे स्वयं समर्थन करते हैं उन्हें वे पूर्णतः लोकतन्त्रिक मानते हैं।” प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही 'प्रजातन्त्र' विश्व के राज्यों में व्यापक स्तर पर ग्रहण करता गया है और आज शासन का यह स्वरूप विश्व-व्यापी बन चुका है।

प्रजातन्त्र का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Democracy)

प्रजातन्त्र की परिभाषा भिन्न प्रकार से की गई है। अब्राहम लिंकन ने प्रजातन्त्र को सरकार का ऐसा रूप माना है जिसमें शासन 'जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा' होता है। सीले के अनुसार, 'प्रजातन्त्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रत्येक का योगदान होता है' (Democracy is a Govt. in which everyone has a share.) ब्राड्स के कथनानुसार, "हेरोडोटस के समय से ही जनतन्त्र का अर्थ उस शासन-प्रणाली से समझा जाता है जिसमें राज्य की प्रशासनिक शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथ में न होकर, सम्पूर्ण समाज के हाथ में होती है।" गर्नर के कथनानुसार, "जनतन्त्र सरकार का वह रूप है जिसका निर्माण तथा प्रचलन इस सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है कि कम से कम प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो किसी अपराध में दण्डित होने के कारण या किसी देश में निराश्रित के कारण अयोग्य न समझा जाता हो, उन व्यक्तियों का चुनाव करने की शक्ति प्राप्त होगी जिनके द्वारा वे कामन बनकर जाते हैं जो नागरिकों को प्रशासित करते हैं। प्रत्येक नागरिक की निर्वासक के रूप में समान आवाज होगी।"

प्रजातन्त्र में शासन जनता की स्वीकृति से चलता है। इसमें शासक-वर्ग सारे देश की जनता का प्रतिनिधि होता है किन्तु 'जनता' शब्द का अर्थ निश्चित और स्पष्ट नहीं है। ब्राड्स ने योग्य नागरिकों के बहुमत की प्रत्यक्ष इच्छा को प्रजातन्त्र का आधार माना है। प्रजातन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को मतदान की स्वतन्त्रता दी जाती है। यह निश्चित नहीं रहता कि उसके मत को मान्यता मिलेगी अथवा नहीं। प्रजातन्त्र में बहुमत को दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रथम, यह कि अल्पसंख्यकों की अनेका उन्माद मत सही होने की सम्भावना रहती है। बहुमत की रुढ़ि अल्पमत की अनेका अधिक होती है। प्रशासन की सञ्चालना का मापदण्ड जन-कल्याण माना जाता है। मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास को पूर्ण अवसर प्रदान करने की व्यवस्था ही शासन का श्रेष्ठ रूप समझी जाती है। प्रजातन्त्रिक शासन सर्वसम्मति से संचालित नहीं होता, उसमें लोगों के अलग-अलग विचार और विचार होते हैं। इन विचारों तथा विचारों के बीच सफल होने के बाद वास्तविक सत्य प्रकट होता है। समानता के सिद्धान्त पर आधारित लोकतन्त्रिक समाज में सभी व्यक्ति एक समान होते हैं तथा किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता।

प्रजातन्त्र का व्यापक अर्थ—विभिन्न देशों और कालों में प्रजातन्त्र के विभिन्न पक्षों पर बत दिया जाता रहा है अतः इसका अर्थ समझने के लिए इसके शासनिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य स्वरूपों को समझना आवश्यक है।

1. प्रजातन्त्र का शासनिक पक्ष—हर्नरा के अनुसार "लोकतन्त्र राज्य संचालन का वह [] जिसमें प्रमुख शक्ति सन्धि रूप से जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन सम्बन्धी मामलों पर अन्तः अन्तिम निर्णय

रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासनसूत्र स्थापित किया जाये।" प्रजातन्त्र, शासनिक दृष्टि से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इसमें जनता अपनी सत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रत्यक्ष पद्धति में स्वतन्त्र और अप्रत्यक्ष पद्धति में निर्वाचन पद्धति द्वारा जनता शासन का संचालन करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रजातन्त्र का प्रत्यक्ष रूप विराट् राज्यों में सम्भव नहीं रहा है। प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक देश में सम्पूर्ण जनता प्रत्यक्षतः शासन कार्य में भाग नहीं ले पाती। स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष और प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र का सम्मिश्रण किया गया है। राज्यों के विराट् आकार के कारण सभी देशों में प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।

2. प्रजातन्त्र का राजनीतिक एवं सामाजिक पहलू—राजनीतिक दृष्टि से प्रजातन्त्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग का अधिकार जनसंख्या के बहुसंख्यक भाग को होता है, अतः इस व्यवस्था में राजसत्ता पर किसी एक वर्ग का अधिकार न होकर शासन कार्य बहुमत द्वारा संचालित किया जाता है और कानून सभी लागू किए जाते हैं जो सामान्य जनमत के अनुकूल होते हैं, परन्तु लोकतन्त्र एक शासन प्रणाली ही नहीं है, यह एक ढाँचाकोटि का सामाजिक आदर्श भी है। सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतन्त्र समस्त व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करता है। लोकतन्त्रात्मक समाज में वस्त्र, रंग, धर्म, बंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जिस समाज में भेदभाव सुआधुत तथा शिष्टों को पुर्णों की अपेक्षा निम्न समझा जाता हो उसे लोकतन्त्रात्मक शासन नहीं कहा जा सकता।

3. प्रजातन्त्र का नैतिक पहलू—लोकतन्त्र व्यापक अर्थ में एक नैतिक आदर्श और मानसिक दृष्टिकोण है। जेफरसन (Jefferson) के अनुसार "लोकतन्त्रात्मक शासन का आधार यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपना शासन अपने-आप करने की और औसत नागरिक में सामाजिक हित की दृष्टि से शासकों को चुनने की योग्यता होती है।" लोकतन्त्र जनसाधारण की गरिमा में विश्वास रखता है। दार्शनिक काण्ट (Kant) के अनुसार "इस प्रकार कम को कि मानवता के साथ प्रत्येक मामले में छोड़े वह तुम्हारे व्यक्तित्व की बात हो अपना दूसरे की, व्यक्ति का व्यक्तित्व सदैव सम्पन्न रहे, संचन नहीं।"

4. प्रजातन्त्र का आर्थिक पहलू—राजनीतिक जनतन्त्र की सफलता आर्थिक प्रजातन्त्र पर निर्भर है। आर्थिक प्रजातन्त्र समाजता का पर्यायवाची है। समाज में जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक प्रजातन्त्र वास्तविक रूप में सफल नहीं हो सकता। जब तक राजनीतिक अधिकारों के साथ आर्थिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक प्रजातन्त्र का सफल होना संदेहास्पद है। इसे परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि प्रजातन्त्र एक विशेष प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धान्त है, एक विरोध प्रकार की मनोवृत्ति है, एक आर्थिक आदर्श है।

प्रजातन्त्र के भेद (Types of Democracy)

(क) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र—जब व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष रूप में सार्वजनिक विषयों पर अपना मत प्रकट करे तो ऐसे शासन को प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र कहते हैं। यूनान के नगर राज्यों का प्रजातन्त्र शुद्ध अथवा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र था, सभी स्वतन्त्र व्यक्ति आम सभाओं में एकत्रित होते और उन्हें कार्यान्वित करते, सन्दर्भों से मिलते और जूरियों के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार के लोकतन्त्र का पुनर्जन्म मध्य युग में इटली के नगर राज्यों में हुआ था। स्विट्जरलैण्ड के फोरैस्ट कंटन्स (Forest Cantons) में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र था और वर्तमान में भी है। 18वीं शताब्दी में रूसो ऐसे शासन का प्रबल समर्थक था। यह अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र को पसन्द नहीं करता था, किन्तु आधुनिक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को लागू करने के मार्ग की कठिनाइयों को वह महसूस करता था। उसके कहना था कि शुद्ध लोकतन्त्र के लिए अनेक बातों की आवश्यकता है और इनका एक साथ प्राप्त होना कठिन है। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक आवश्यकताएँ हैं—(1) एक छोटा राज्य जिसके नागरिक आसानी से एक जगह एकत्रित हो सकें और जिसमें प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिकों को आसानी से पहचान सके, (2) व्यवहार की एकदम सादगी, (3) पट, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति में पर्याप्त समानता, (4) बहुत कम वित्तासप्रियता या वित्तासहीनता।

(ख) अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र—आजकल प्रत्येक देश में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र का प्रचलन है। इसके अनुसार वास्तविक शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाता है। जे. एस. मिल के अनुसार "अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सम्पूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन-सत्ता का प्रयोग चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा करता है।" राज्य की इच्छा का निर्माण सर्वसाधारण प्रत्यक्षतः नहीं करते, बल्कि वे अपनी इच्छा अपने प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त करते हैं जिसका एक निश्चित अवधि के बाद निर्वाचन होता है और सर्वसाधारण

इन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा देश का शासन करते हैं। इस प्रकार कानूनों का निर्माण जन-प्रतिनिधियों द्वारा होता है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र इस विचार पर आधारित है कि जनता के सभी सदस्य राजधानी में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते, किन्तु वे अपने प्रतिनिधियों के रूप में उपस्थित माने जा सकते हैं। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र में सना जनता में हो निवास करती है। इसमें शासन और शासितों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है और दोनों के उद्देश्यों में एकरूपता रहती है। इस तरह अधिका और राजनीतिक स्वतन्त्रता में सामंजस्य बना रहता है।

प्रजातन्त्र के गुण (Merits of Democracy)

1. स्वतन्त्रता एवं समानता पर आधारित—प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता, समानता तथा प्रातृत्व की उच्च भावनाओं पर आधारित है। यह समाज के सभी सदस्यों को स्वतन्त्रता तथा समानता के अधिकार प्रदान करता है और जति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करता। प्रजातन्त्र ने वर्षों से चली आ रही इस परम्परा को नकार दिया है कि कुछ लोग शासन करने के लिए और कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। प्रो. डायमी के अनुसार, "लोकतन्त्र में अधिकारों की समानता तथा परिस्थितियों, भावनाओं और आदर्शों की एकता होती है। प्रजातन्त्र में साधारण मनुष्य में विद्यमान होनता की भावना (Inferiority Complex) को समाप्त कर, एक उन्मुक्त तथा समतावादी समाज की जन्म दिया है।"

2. जन-सहमति पर आधारित—प्रजातन्त्र एक कुराल व्यवस्था है जिसमें सम्पूर्ण जनता को सुख की वृद्धि करने का अवसर मिलता है। यह जन-सहमति पर आधारित शासन-व्यवस्था है।

3. स्थायी शासन—जन-सहमति पर आधारित होने के कारण ही जनतन्त्रात्मक शासन अन्य शासन-प्रणालियों से स्थायी होता है। इसमें जनसाधारण अपनी इच्छानुसार शासकों को बदल सकता है जिसके कारण शक्तियों का जितना भय अन्य राज्यों में होता है ठटना प्रजातन्त्र में और वह भी विशेषकर निवृत्तजलैष्य जैसे प्रजातन्त्र में नहीं रहता।

4. श्रेष्ठ शासन—जे. एस. मिल तथा लॉर्ड ब्राइस दोनों प्रजातन्त्र की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। मिल के अनुसार, "प्रजातन्त्र प्रणाली में समस्त जनता अपना उसका विराल भाग समय-समय पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन करता है।" इसमें समस्त शक्ति जनता में निहित रहती है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार समय प्राप्त होने पर कार्य कर सके।

5. सामाजिक गुणों का पोषक—प्रजातन्त्र शासन का शिलात्मक मूल्य है। यह प्रणाली जनसाधारण में राजनीतिक चेतना जामत करती है, आत्म-विश्वास, उदारता और सहयोग की भावनाओं को सुदृढ़ बनाती है।

6. राष्ट्रीय भावना का प्रेरक—प्रजातन्त्र ऐसे शासन-व्यवस्था है जो राष्ट्रीय भावना तथा देशप्रेम को जामत करती है। जनतन्त्र में प्रत्येक नागरिक यह समझता है कि कानून तथा शासन के स्वरूप का वह स्वयं निर्माता है, अतः शासकगण उसके भाग निर्माता न होकर सेवक होते हैं।

7. वैयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा—प्रो. गैटिल के अनुसार, "लोकतन्त्र में सम्पुष्ट शक्ति पर आधारित न होकर सहमति पर स्थित रहती है। यहाँ 'व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए है' इस सिद्धान्त को न मानकर 'राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है' इस सिद्धान्त को मानता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सर्वप्रधान रूप से अधिक सुरक्षा की सम्भावना है। इस व्यवस्था में जनता का विकास तथा उसकी दृढति सार्वजनिक कार्यों में उनकी रुचि उत्पन्न करना माना जाता है।"

8. सुधार-प्रेरक—प्रजातन्त्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए वातावरण बनाने में सफल होता है। पिछले वर्षों में सप्तर में जितने सामाजिक तथा आर्थिक सुधार हुए उतने राजतन्त्र के इतिहास में कभी नहीं हो पाए। लोकतन्त्र का एकमात्र ध्येय जनकल्याण है और सामाजिक असमानता तथा पुष्टे अनुपयोगी रीति-रिवाजों को जन-सहमति से समाप्त कर, इसमें सच्चे जनकल्याण के लिए प्रयास किए जाते हैं।

9. सामाजिक एकता का साधन—लोकतन्त्र सामाजिक एकता का उत्कृष्ट साधन है। डीवी (Dewey) के अनुसार, "प्रजातन्त्र ऐसे सामाजिक संगठन के आदर्शों के अत्यन्त निष्कट है जिसमें व्यक्ति तथा समाज का सावयव सम्बन्ध रहता है। व्यक्ति समाज का उसी तरह अटूट अंग माना जाता है जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग। इस सावयव (Organic) एकता का अनुभव व्यक्ति केवल लोकतन्त्र में ही कर सकता है चूँकि इस व्यवस्था में व्यक्ति अपने अन्दर सामाजिक इच्छा और आकांक्षाओं का अनुभव करता है और प्रत्येक नागरिक राज्य सत्ता में भागीदार रहता है।"

प्रजातन्त्र के दोष (Demerits of Democracy)

1. **कार्यक्षम एवं आदर्शवादी**—प्रजातन्त्र के सिद्धान्त कार्यात्मिक और आदर्शवादी हैं, जिनका आधार जनसाधारण की समानता है। प्राणिशास्त्रियों के अनुसार प्रजातन्त्रात्मक समानता कोई कल्पना है और परिवारों तथा जातियों की प्राकृतिक उच्चता के सिद्धान्त को तथ्यों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। जर्मन इटैसियन तथा जापानियों ने जर्मनीय उच्चता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए विभिन्न देशों तथा राज्यों में प्राकृतिक असमानता को दृष्टाव्य माना है। प्रजातन्त्र जीव-विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्तों के विपरीत है।

2. **अयोग्य व्यक्तियों का शासन**—शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक योगदान की दृष्टि से समाज के सभी व्यक्ति या वर्ग समान नहीं हो सकते। गरीब-अमीर, मूर्ख-बुद्धिमान, शिक्षित-अशिक्षित सभी प्रजातन्त्रात्मक शासन में समान होते हैं। अंग्लोफोनों के अनुसार प्रजातन्त्र में गुण का महत्त्व न होकर संख्या का महत्त्व अधिक होता है। वोटों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। ऐसे शासन में विवेकहीन व्यक्तियों का सम्मान होता है और योग्य व्यक्ति उपेक्षित रह जाते हैं। इस शासन में मूर्खों तथा अशिक्षितों की संख्या अधिक पायी जाती है। यह बहुमत का शासन है यही कारण है कि प्रजातन्त्र अयोग्य और अशिक्षित लोगों का शासन कहा जाता है।

3. **प्रतिनिधियों का शासन से अनिच्छा**—प्रजातन्त्र को अज्ञानी, अशिक्षित तथा अयोग्य व्यक्तियों का शासन मानने का कारण यह है कि इसमें राज्य-शक्ति ऐसे व्यक्तियों के हाथ में रहती है जिन्हें शासन-कार्य का ज्ञान नहीं होता। स्पेनो के कथनानुसार "शासन एक कला है जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए योग्यता, नियुक्तता तथा अनुभव की आवश्यकता है।" प्रजातन्त्र में अधिकांश ऐसे लोग शासक बन जाते हैं जो शासन का क. क. र. ग. भी नहीं जानते। किसी भी क्षेत्र में कार्य तोड़ने से पूर्व यह आवश्यक है कि कार्य करने वाले व्यक्ति की शिक्षा, अनुभव तथा कार्य क्षमता आदि पर ध्यान दिया जाए, परन्तु जनतन्त्र की विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव में ऐसी किसी योग्यता पर विचार नहीं किया जाता और केवल लोकप्रियता को ही कसौटी माना जाता है।

4. **निर्वाचन में विवेक का अभाव**—चुनाव में मत देने समय जनता विवेक से काम नहीं लेती, बल्कि जो उसे बहका देता है या उसके हाथों में पैसा धपा देता है, उसे ही चुनाव क्षेत्र में समर्पण देकर स्फुट बना देती है। चुनावों के अनुभव बताते हैं कि निर्वाचक अपने प्रतिनिधियों का सही चुनाव नहीं कर पाते। प्रजातन्त्र की राजनीति में हर्क और विवेक का अभाव रहता है।

5. **जनता का राज्य कहना अनुचित**—यह कहना सिद्धान्त रूप से गलत है कि प्रजातन्त्र सधमुक्त जनता का राज्य है। व्यावहारिक रूप में चुनाव सड़ना और राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करना किसी समाज में आसान नहीं है। जनसाधारण के पास इतना धन नहीं होता कि वह चुनाव लड़ सके। केवल धनी लोग ही चुनाव के अखाड़ों में आते हैं और विधानसभाओं के सदस्य बनकर शासन पर कब्जा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जनतन्त्र में धनी लोग व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के सदस्यों को छत्रि लेते हैं और जनता का शासन अपने आदर्श का मञ्जोल बनकर रह जाता है।

6. **प्राप्य सम्पूर्ण जनता द्वारा मतदान में उदासीन होना**—मतदाता चुनाव के मामलों में कोई विशेष रुचि नहीं लेते। सभी देशों में बहुत कम मतदाता ऐसे पाए जाते हैं जो अपने मतदाताधिकार का उचित प्रयोग करते हैं। अधिकांश जनता बिना सोचे-विचारे ही वोट दे जाती है और मतदाताओं की एक बड़ी संख्या वोट का प्रयोग नहीं करती। अमेरिका जैसे सफल जनतन्त्रात्मक देश में औसतन 50-60 प्रतिशत मतदाता ही मतदान में भाग लेते हैं। संसार के विशालतम प्रजातन्त्रिक देश भारत में 60 से 70 प्रतिशत मतदाता मतदान में भाग लेते हैं।

7. **निर्वाचन में अनैतिक साधनों का प्रयोग**—नैतिक दृष्टि से प्रजातन्त्र में झूठ, जालसाजी आदि का बोलबाला रहता है। राजनीतिक प्रचार के लिए झूठे वायदे किये जाते हैं, झूठे कार्यक्रम बनाए जाते हैं और अनैतिक कार्यों का प्रचलन लिया जाता है।

8. **भय आधारित अत्याचारपूर्ण शासन**—प्रजातन्त्र में स्वतन्त्रता और समानता का अभाव होता है। प्रजातन्त्र के नेता स्वार्थसिद्धि के लिए जनता को गुमराह करते हैं और उन्हें झूठा धन दिखाकर उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण करते हैं। इस दृष्टि से प्रजातन्त्र को बहुमत का अत्याचारपूर्ण शासन (Tyranny) कहना असंगत नहीं है।

9. **अस्थायी सरकारें**—प्रजातन्त्र में सरकार अधिक स्थायी नहीं रहती। दलबन्दी के कारण पार्टियों के पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन होते रहते हैं, फलस्वरूप सरकार बार-बार बनती है और बिगड़ती है। शासन प्रणाली स्थायी न रहकर अस्थायी बन जाती है और शासन नीतियों में निश्चितता और दृढ़ता नहीं रहती।

10. **छोटी सी एवं अपव्ययी शासन-प्रणालि**—प्रजातन्त्रात्मक शासन अन्य शासनों की अपेक्षा लचीला एवं अपव्ययी है। शासकीय निर्वाचन तथा प्रतिनिधियों के वेतन एवं भत्तों पर कड़ी ध्येय होता है। भ्रष्टाचार-मुक्त कार्य करते हैं। प्रजातन्त्रात्मक सरकार में कार्यवाहियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है।

11 कार्य की गति एवं क्षमता असतोषजनक—गुणों की अपेक्षा सख्या पर बल देने से प्रजातन्त्र में सर्वत्र अधमता रहती है। प्रशासन में कार्य-कुशलता और द्रुत कार्य का अभाव रहता है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया इतनी समीचीन होती है कि जिन कानूनों के निर्माण में कुछ दिन लगने चाहिए उनमें वर्षों लग जाते हैं। सरकारी विभागों में कार्य की गति मन्द होती है।

12 राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा—प्रजातान्त्रिक देशों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब राष्ट्रीय हितों की स्थानीय हितों के लिए बलिदान किया गया है। 'शक्ति, अधिकार और सरक्षण की होड़ में कुछ लोगों के लाभ के लिए समग्र राष्ट्र के हितों की उपेक्षा की जाती है। सामुदायिक भावना का अभाव रहता है, जिससे राष्ट्रीय एकता सकट में पड़ जाती है। पार्श्व देशों में एक प्रवृत्ति अधिक जोर पकड़ती जा रही है कि संगठित अल्पसंख्यक समुदाय उद्देश्यों की सिद्धि के लिए जनहित की अवहेलना करते हैं। भारत में भाषावार पुनर्गठन के प्रश्न पर जो बहदर उठा था, वह इसी का ज्वलन्त उदाहरण है।"

प्रजातन्त्र की सफलता के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ या परिस्थितियाँ

(Essential Conditions or Circumstances for the Success of Democracy)

प्रजातन्त्र प्रत्येक देश में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। श्री हर्नशा (Hearnshaw) के अनुसार, प्रजातन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें ये हैं—(1) व्यक्तियों में सच्चाई तथा सम्मान की भावना का होना, (2) व्यक्ति शिक्षित हो, (3) व्यक्तियों में राष्ट्रीय स्वाधीन के प्रति रुचि हो, (4) शक्तिशाली जनमत एवं (5) राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में व्यक्तियों की स्वतन्त्रता प्राप्त होना।

फ्रांसिस कोकर (Francis W Coker) की दृष्टि में लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं—(1) नागरिक भावना, (2) बौद्धिक तथा नैतिक उत्साह, (3) समान आर्थिक अवसर, (4) स्वतन्त्र वाद विवाद एवं (5) व्यक्तियों की स्वतन्त्रता।

प्रजातन्त्र के प्रबल समर्थक जे. एस. मिल के अनुसार, प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—(1) जनता में प्रजातन्त्र शासन क्रियान्वित करने की तीव्र अभिलाषा एवं पूर्ण योग्यता, (2) जनता प्रजातन्त्र के लिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सपर्या को तैयार होनी चाहिए एवं (3) जनता द्वारा अपने नागरिक कर्तव्यों का बुद्धिमानी तथा ईमानदारी से पालन की इच्छा।

विस्तार और स्पष्टता की दृष्टि से प्रजातन्त्र की सफलता की आवश्यक शर्तें निम्नांकित हैं—

1. वैधानिक परम्पराएँ—प्रजातन्त्र में उद्घोषित वातावरण को वैधानिक परम्पराओं के विकास द्वारा 'अगाध जल के समान गह्वर' बनाया जाना आवश्यक है। प्रजातन्त्र की खुली आलोचना करने वाले लेखी और सर नार्मन एंजिन का विश्वास है कि यदि कुछ रीतिरिवाज और वैधानिक व्यवस्थाएँ क्रियान्वित की जाएँ तो प्रजातन्त्र सुचारु रूप से चला सकता है।

2. बौद्धिक आवश्यकताएँ—प्रजातन्त्र में शासन का उत्तरदायित्व जनसाधारण का होता है अतः आवश्यक है कि जनता का बौद्धिक स्तर उच्च हो। जनता में इतनी सहज बुद्धि होना चाहिये कि वह सही सरकार का निर्वाचन कर सके और देश की सभी आवश्यकताओं को धली-धौंधी समझ सके। जनता में निर्धारित शक्ति होना चाहिए ताकि देश के सम्मुख उपस्थित समस्याओं के समाधान हेतु वह उचित एवं गमयानुकूल निर्णय ले सक। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रजा में समुचित शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार होना आवश्यक है। डॉ. इकबाल नारण ने बौद्धिक दृष्टि से जनता में प्रजातन्त्र की सफलता हेतु दो गुणों का होना आवश्यक बतलाया है—(1) जनता की समझदारी (Common Sense) एवं (2) जनता में निर्णय-शक्ति की सफलता।

3. समनता एवं साधनानी—जनता कितनी ही सुशिक्षित और उदारमनस क्यों न हो, जब तक वह आनस्य एवं उदासीनता से घिरे रहेंगी तब तक प्रजातन्त्र की सफलता संदिग्ध है। निरन्तर सजग एवं साधनवान रहने से ही प्रजातन्त्र की रक्षा हो सकती है।

4. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समनता—प्रजातन्त्र शासन समनता के स्वर्णिम सिद्धान्त पर आधारित है। इसके लिए आवश्यक है कि समस्त प्रजा को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समनताएँ उपलब्ध हों। समान में जन्म, जाति, रंग, सम्पदा, धर्म आदि के भेद के बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान अवसर प्राप्त हों और सबके साथ समान व्यवहार तथा अवसर की दृष्टि से समान व्यवहार किया जाए। आर्थिक क्षेत्र में सब को मर्द सम्बन्धी न्यूनतम सुरक्षा प्राप्त हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र का प्रभु है। जनता की नैतिक स्वतन्त्रताएँ प्रजातन्त्र के शासन की सफलता के लिए आवश्यक हैं। इनके द्वारा निर्वाह जम्मत-समूह में सहयोग मिलता है।

5. राज्य में शान्ति और सुरक्षा—युद्ध और अशान्ति की व्यवस्था जनताही को जन्म देती है। शान्ति और मुख्यतया की शान्ति में ही प्रजातन्त्र शासन स्थापित हो सकती है।

6. राजनीतिक चेतना—जनतन्त्र की राजनीति जनसाधारण की राजनीति होती है, अतः जनसाधारण में सार्वजनिक धर्मों के प्रति सामान्य जागृति होनी चाहिए उनमें देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और देश की उन्नति के लिए सब कुछ कर-गुजरने की उत्कृष्ट क्षमिता होनी चाहिए। एक सफल प्रजातन्त्र की जनता अपनी सरकार और सार्वजनिक राजनीति में निरन्तर रुचि लेती है और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सदैव जागृत रहती है।

7. राजनीतिक शिक्षा—जनतन्त्र में जनता में वैधानिक तत्परा का होना बाध्यकारी है। उसमें आँख खोलकर अपनी राजनीतिक समस्याओं पर वाद विवाद करने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रीय समस्याओं पर अच्छी तरह से विचार-विमर्श करने की राजनीतिक शिक्षा के बिना जनतन्त्र अर्थात्तीय तत्त्वों के हाथों में आकर हानिकारक होता है।

8. स्थानीय स्वायत्त की आवश्यकता—राजनीतिक शिक्षा के लिए आवश्यक है कि जनता को स्थानीय स्वायत्तता की संस्थाओं द्वारा प्रजातन्त्र की व्यावहारिक शिक्षा दी जाए। प्रजातन्त्र अधिकारीयह उन्हीं राज्यों में सबसे अधिक सफल होता है, जहाँ स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को अधिकतम अवसर दिया जाता है।

9. राजनीतिक दलों की आवश्यकता—प्रजातन्त्र सरकार सबसे अधिक "जनतांत्रिक क्रियाशीलता और विचार की राजनीतिज्ञता के दुर्भाग्यों से जनता की रक्षा करती है।" राजनीतिक दल शासन व्यवस्थाओं को सम्यक् प्रतिनिधित्व और सम्बद्धता प्रदान करते हैं। वे जनमत का निर्माण करते हैं।" एक विकासशील जलन में राजनीतिक दलों का स्वायत्त सिद्धान्तों पर चर्चना आवश्यक है। उनके कार्यक्रम धार्मिक अपना क्षेत्रीय नहीं होने चाहिए।

10. नैतिक आवश्यकता—इतिहास के अनुसार "लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का रूप अनिवार्यतः धार्मिक होता है।" हमका आशय यह है कि लोकतन्त्र में सफलता हेतु उसका व्यक्तियों के अन्तः चारित्रिक आधार पर अवलम्बित रहना बाध्यकारी है।

मानव अधिकार के सिद्धान्त : मानव-अधिकारों का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य (Theories of Human Rights : Marxist Perspective of Human Rights)

मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार विश्व के तथाकथित लोकतांत्रिक देशों के संविधानों द्वारा नागरिकों को दिये गये अधिकार व्यावहारिक महत्व नहीं रखते। स्टालिन के अनुसार, "एक भूखे और बेरोजगार व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई महत्व नहीं है। सभी स्वतन्त्रता वहीं सम्भव है जहाँ शोषण, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति या कल के लिये चिन्ता की समस्या नहीं है।" मानव-अधिकारों का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य केवल संविधान में नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या कर देने में विश्वास नहीं करता, बल्कि इस तथ्य पर बल देता है कि उन अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। यह केवल नागरिकों को समता ही प्रदान नहीं करता, बल्कि विश्वास दिलाता है कि वे शासन के शोषण से मुक्त हो गये हैं। यह नागरिकों को कथ्य करने का अधिकार ही नहीं देता, अपितु ऐसी व्यवस्था में विश्वास करता है कि प्रत्येक नागरिक को कार्य दिया जाये। पारजात्य लोकतंत्रों में नागरिक अधिकारों का स्वरूप व्यक्तिवादी (Individualistic) है, वहीं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में उनका स्वरूप समाजवादी (Socialistic) है। नागरिक अथवा मानव-अधिकारों की मार्क्सवादी योजना पूरे समाज को केन्द्र मानती है। उसका आर्थिक व्यक्तिवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका आधार समाजवादी व्यवस्था है जो नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) पर आधारित है। व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। उसका केन्द्र एक ऐसा समाज है जिसमें सब काम करने वाले लोग किसान और मजदूर हैं। यह समाज सम्पन्न और धिपन्न वर्गों में विभाजित नहीं होता। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य व्यक्ति को अधिकार इस रूप में प्रदान करता है कि उनका प्रयोग कर वह अपने कल्याण के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज का भी कल्याण कर सके। अधिकारों की मार्क्सवादी अथवा साम्यवादी (Communist) अवधारणा अधिकारों के साथ ही उनकी पूर्ति के लिये जोस साधनों में विश्वास करती है। पारजात्य लोकतांत्रिक संविधान में जो अधिकारों की उदारवादी (Liberal) अवधारणा के प्रतीक माने जाते हैं, केवल अधिकारों की पूर्ण साधनों की नहीं। मार्क्सवादी अवधारणा के पौष्टिक परिप्रेक्ष्य संविधानों के अधिकार-पत्रों को कागजी महत्व का बतलाते हैं, व्यावहारिक महत्व का नहीं।

मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेख आवश्यक है। कार्टर्सकी के अनुसार, "अधिकार देने के साथ-साथ हमारा रुझान संविधान नागरिकों पर समाज और राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य आरोपित करता है। रूगो संघ के नागरिकों के कर्तव्य अधिकारों के साथ-साथ चलते हैं। पूँजीवादी देशों की तरह रूसी संविधान बिना अधिकारों के किसी पर कर्तव्य नहीं लादता। अधिकार और कर्तव्य अविभाज्य हैं। इस के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसे

काम मिले साथ ही ठमका भी यह कर्तव्य है कि वह काम करे।" मार्क्सवादी सम्प्रदाय अधिकारों की सर्वव्यापकता में विश्वास करता है।

मार्क्सवादी विचारधारण नागरिक अधिकारों के साथ इस शर्त को आरोपित करती है कि अधिकार सर्वहारा वर्ग (Proletariat) के हितों से नहीं उठकरेंगे और उन अधिकारों से समाजवादी व्यवस्था (Socialistic Order) को बल मिलेगा। मार्क्सवादी अवधारणा नागरिकों के सार्वजनिक संगठन सम्बन्धी अधिकार पर भी प्रतिबन्ध लगाती है। तदनुसार साम्यवादी दल को संविधान के अन्तर्गत विशेष स्थिति प्रदान की जाती है और उसे राज्य एवं सर्वहाराण तथा सर्वहारा वर्ग का मुख्य संगठन माना जाता है।

मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार व्यवस्था की विशेषता यह है कि जहाँ उदारवादी व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों (Civil Rights) को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ मार्क्सवादी व्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है और नागरिक अधिकारों की गण। वास्तविक स्वतन्त्रता तभी सम्भव हो सकती है जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो। प्रायः उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है, लेकिन मार्क्सवादी साम्यवादी धारणा इसे आवश्यक नहीं मानती।

इस साम्यवादी (मार्क्सवादी) परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों की व्यवस्था सोवियत संघ के विघटन के बाद एवं गोर्बाचोव द्वारा अपनाई गई 'ग्लासनेस्त' व 'पेरेस्त्रोयका' की उदारवादी नीतियों के अवलम्बन से अब कम में समाप्त हो गई है, किन्तु अभी चीन (साम्यवादी), उत्तरी कोरिया एवं क्यूबा में यह व्यवस्था विद्यमान है।

मानव अधिकारों का उदारवादी परिप्रेक्ष्य (Liberal Perspective of Human Rights)

उदारवादी परिप्रेक्ष्य में मानव के मूलभूत अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था रहती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, सामाजिक ठरेदों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके और पूर्ण आत्म-सम्मान का जीवन बिता सके। व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक दोनों अधिकार प्राप्त होने चाहिए। व्यक्ति के ये अधिकार पूर्ण अथवा अनियन्त्रित नहीं हो सकते, क्योंकि मानव-स्वभाव में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं और व्यक्ति के स्वयं तथा समाज और राज्य के हित के लिये यह आवश्यक है कि उन अधिकारों पर दृष्टि और न्यायसंगत नियन्त्रण लगाये जायें। देश और समाज के लिए अबाधित तत्वों पर अंकुश रखना आवश्यक है। नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किये जायें उन्हें समुचित न्यायिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिए अर्थात् कार्यपालिका की बिजरी भी संभावित निरकुशता के विरुद्ध और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका अधिकार-सम्पन्न हो। मानव-अधिकारों के उदारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों का आशय स्पष्टता से समझ लेना चाहिये।

नागरिक या अस्ैनिक अधिकार और स्वतन्त्रताएँ (Civil Rights and Liberties)

नागरिक अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्तियों के जान-माल से है। इन अधिकारों के अभाव में सम्य जीवन का विकास सम्भव नहीं है। यद्यपि समय और स्थान के अनुसार नागरिक अधिकार बदलते रहते हैं, तथापि सम्य समाजों में नागरिकों को कुछ न्यूनतम नागरिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं, जैसे—जीवन रक्षा का अधिकार, समानता और स्वतन्त्रता का अधिकार, स्वतन्त्र भ्रमण का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, धारण और प्रकाशन का अधिकार, सभा और सम्मेलन का अधिकार, धर्म और अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का अधिकार आदि। सुव्यवस्थित राज्य का यह कर्तव्य है कि यह इन नागरिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं (Civil Rights and Liberties) की रक्षा करे और यह सुनिश्चन करे कि व्यक्ति के इन अधिकारों का अतिक्रमण न तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा हो और न सरकार के द्वारा ही। व्यक्ति को इन मौलिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के उपयोग का अवसर तभी प्राप्त हो सकता है जब ये राज्य के कानून द्वारा मान्य और संरक्षित हों। एक उदार लोकतन्त्र में स्वतन्त्रता और कानून में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाता है जिसमें स्वतन्त्रता के प्रति अधिक झुकाव होता है। उदार लोकतन्त्र में उसी आचरण की आशा होती है जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होता। यदि व्यक्ति इन कानूनों को तोड़ते हैं और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का उल्लंघन करते हैं तो उनके प्रति न्यायपालिका में कार्यवाही की जा सकती है। नागरिकों को आम जनता एवं सरकार से भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उदार लोकतन्त्र में विधि-शासन (Rule of Law) की स्थापना होती है जिसमें कानून के समक्ष सरकारी कर्मचारी अथवा साधारण व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता है।

नगरिक एवं राजनीतिक अधिकार में अंतर (Difference between Civil and Political Rights)

नगरिक और राजनीतिक अधिकारों में अंतर है। व्यक्ति द्वारा राजनीतिक अधिकारों का उपयोग अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं होता, अतः नगरिक के रूप में होता है और वे उसे राज्य की सम्पूर्ण शक्ति की संधि अधिव्यक्ति तथा प्रशासन में अधिकार प्रदान करते हैं। राजनीतिक अधिकार से सम्पन्न हैं जिनके माध्यम से वे एक नगरिक राज्य के संविधान तथा कानूनों के द्वारा देश की सरकार के साथ सम्बन्ध बनने का अधिकार प्राप्त करता है। राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से ही लोकतन्त्र कार्यरत रहता है और एक लोकतांत्रिक संविधान ही लोगों को यथार्थ रूप में राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। नगरिक अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्तियों के जन्म-मरण से है। इन अधिकारों की अनुपस्थिति में सभ्य जीवन सम्भव नहीं है। ये अधिकार जीवन के व्यभिचरित क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा करते हैं। यद्यपि समय और स्थान के अनुसार नगरिक अधिकार (Civil Rights) बदलते रहते हैं तथापि सभी सभ्य देशों में न्यूनतम नगरिक अधिकार अवश्य पाये जाते हैं। एक उदाहरण के रूप में स्वतन्त्रतापूर्ण राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नगरिकों के इन अधिकारों की रक्षा करे तथा सुनिश्चित करे कि व्यक्तियों के नगरिक अधिकारों का अतिक्रमण न हो अन्य व्यक्तियों द्वारा होता है और न राज्य सरकार द्वारा ही।

कई अधिकार ऐसे होते हैं जो दोनों वर्गों में सम्बन्ध रखते हैं, किन्तु नगरिक अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों पर अतिरिक्त नहीं समझा जा सकता। क्योंकि नगरिक अधिकार व्यक्ति के आधारभूत या मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) हैं जो उसे मनुष्य के नाते मिलने चाहिए। आधारभूत अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक उपायों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन उपायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपाय है—अविरोधपूर्ण निष्पक्ष न्यायिक कार्यवाही (Fair trial without undue delay), सरलता की व्यवस्था अधिकारों या स्वतन्त्रताओं की रक्षा के लिये अनिवार्य है अतः ऐसी स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए जो कार्यपालिका के प्रत्येक अंकुश से पूर्णतः स्वतन्त्र हो। दूसरा उपाय है कि जूरी (Jury) द्वारा अभियोग की सुनवाई की व्यवस्था हो और अपराधी को यह जानने का अधिकार हो कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है? इसके अनिवारित उसे यह अधिकार हो कि वह अपने विरुद्ध अभियोग की सुनवाई खुली अदालत में करा सके और अपने बचाव के लिए कानून की सहायता ले सके। कुछ प्रमुख मानव अधिकार (Some Major Human Rights)

प्रमुख मानव-अधिकार ये हैं—(1) जीवन का अधिकार (Right to Life), (2) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Liberty), (3) सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property), (4) समानता का अधिकार (Right to Equality), (5) सामाजिक अधिकार (Social Rights), (6) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Religious Rights) एवं (7) राजनीतिक अधिकार (Political Rights)।

संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार (United Nations and Human Rights)

मानव-अधिकारों की उदाहरण अवधारणा (Concept) का सर्वोत्तम प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र की 'मानव अधिकारों की घोषणा' (Declaration of Human Rights) में है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान रखे गये हैं और प्रस्तावना में मानव के मूल अधिकारों, मानव की गरिमा और महत्व में सभी छोटे बड़े राष्ट्रों के स्वी-सुख के समान अधिकारों में आस्था दोहराई गई है। चार्टर में मानव अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय शान्ति प्रदान की गई है।

चार्टर में मानव अधिकारों की व्यवस्था—संयुक्त राष्ट्र के चार्टर (Charter) में किसी अन्य विषय पर इतना अधिक बल नहीं है जितना मानव-अधिकारों और मानव-स्वतन्त्रताओं पर दिया गया है। चार्टर के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनेक उद्देश्यों में से एक यह है कि जाति, भाषा, लिंग अथवा धर्म का कोई भेदभाव किये बिना सबके लिये मानव-अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं के सम्मान को प्रोत्साहित किया जायेगा। अनुच्छेद 35 में इन अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के प्रति 'सर्वत्र सम्मान और उनके फलन में संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य' माना गया है। अनुच्छेद 56, 62 और 76 भी मानव अधिकारों की संरक्षण देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को यह वैधानिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मानव अधिकारों की रक्षा करें। मानव-अधिकारों की घोषणा—चार्टर के दायित्वों को निभाने हुए महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा (Declaration of Human Rights) को स्वीकार किया। इस घोषणा में तीन धार्य हैं

जिनमें नगरिक और राजनैतिक अधिकारों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित हैं। घोषणापत्र की 3 से 21 तक की धाराओं में विभिन्न नगरिक और राजनैतिक अधिकारों का समवेश है। इन मानव अधिकारों को लेकट्रिक सविधानों में बराबर मान्यता दी जाती रही है। घोषणापत्र की 22 से 27 तक की धाराओं में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिये गये हैं जिनकी मनुष्य के अल्पसम्मान और स्वतन्त्रता के निरु अवश्यक माना गया है। घोषणापत्र की 28 से 30 तक की धाराओं में यह स्वर्णर किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी सामाजिक और अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसमें विश्व-शान्ति और सुखा हो तथा व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत के पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त हो। घोषणा में यह स्मरण करवाया गया है कि अधिकारों के साथ बर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, जिनका पालन किये बिना हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। कम्यून द्वाप मान्य न होने पर इस घोषणापत्र का अनाग महत्व है। जिस प्रकार नैतिकता के अदरों और नियम कम्यून द्वाप मान्य न होने पर लोगों को तदनुग व्यवहार करने को बाध्य करते हैं, उसी प्रकार मानव के अधिकारों का यह घोषणापत्र उहाँ और सरकारों को मानव-अधिकारों के पालन की प्रेरणा देता है।

न्याय के सिद्धान्त

(Theories of Justice)

भारत में मनु ने अति प्राचीन युग में ही विचारों की वे दो श्रेणियाँ बतला दी थीं जिन्हें आज दीवनी (Civil) और फौजदारी (Criminal) की मंज़ा देते हैं। न्यायिक निष्पत्तता और सत्यता पर मनु ने अत्यधिक बल दिया और कहा, "जिस सभा (न्यायालय) में सत्य असत्य से परिचित होता है उसके सदस्य ही धर्म से गृह हो जाते हैं।" कौटिल्य ने उचित न्याय-व्यवस्था को राज्य का प्राण मानते हुए कहा है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कौटिल्य ने यह सुनिश्चित मत प्रस्तुत किया कि न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना है। न्यायप्रिय शासक के निरु अवश्यक है कि वह असामान्यिक तथ्यों और अव्यवस्था ठहरान करने वाले लोगों को दण्डित करे। कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में 'धर्मस्थाय' तथा 'कण्टक रोधन' नामक दो प्रकार के न्यायमयों का उल्लेख किया है जिन्हें आधुनिक दीवनी और फौजदारी न्यायमयों के समान कहा जा सकता है। कौटिल्य ने न्यायिक सभ्यता एवं प्रक्रिया का वर्णन किया है। सभी भारतीय प्रन्थों में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि न्याय करने वाला अधिकारी निष्पक्ष रहे। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन भारत की न्याय-व्यवस्था धर्म से प्रभावित थी। न्यायमयों के सदस्यों को योग्यता में उनकी धर्म-सम्बन्धी जानकारी को महत्व दिया जाता था। किसी विवाद का निर्णय धर्मसम्मत हो, इसके निरु कई प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थीं।

न्याय की परिभाषाएँ (Definitions of Justice)

आगस्टाइन (Augustine) के अनुसार, "न्याय एक व्यवस्थित और अनुरक्षित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था माँग करती है।"

थॉमस एक्वीनास (Thomas Aquinas) के अनुसार, "न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार दिए जाने की निश्चित एवं समान इच्छा है।"

प्लेटो (Plato) के अनुसार, "न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का समान करना है जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। नगरिक को अपने 'धर्म' की रक्षा तथा सर्वजनिक जीवन में उसके अधिकारों का हो राज्य का न्याय है।"

आर्नोल्ड बेचेट (Arnold Brecht) के अनुसार, "न्याय की धारणा वैश्व स्थिति के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है और वह एक ऐसे बर्तन की संज्ञा है जिसके कई छल होते हैं।"

समाजशास्त्र के विवेकेश्वर के अनुसार, "न्याय वह क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उस परिस्थिति को ठीक किया जाता है अथवा ठीक किया जाता है जिससे अन्याय की शक्त और स्थिति बढ़ती है।"

ह्यूम (Hume) के अनुसार, "न्याय के उदय का एकमात्र आधार सर्वजनिक उपयोगिता है।"

न्याय की अवधारणा के विभिन्न रूप (Various Forms of the Concept of Justice)

पारम्परिक रूप से न्याय की दो अवधारणाएँ प्रचलित रही हैं—नैतिक एवं कानूनी, जबकि आज न्याय की अवधारणा के मुख्य रूप हैं—कानूनी, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। इनकी व्याख्या इस प्रकार है—

(1) प्राकृतिक न्याय (Natural Justice)—इस न्याय के अनुसार मनुष्य को अपने अधिकारों में पूर्ण स्वतन्त्र एवं स्वर्णन तथा चर्च और उस पर कोई बाध नहीं होना चाहिए। यह मनुष्य की प्राकृतिक स्वतन्त्रता है। डॉ. इब्राहिम कदमग के अनुसार, "प्राकृतिक विचारधारा के कारण ही सब मनुष्यों का सर समान माना जाना चाहिए। यह कहना चाहिए कि समान की ओर से व्यक्ति के प्राकृतिक हक में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए, जिससे उसकी समतता नष्ट हो सके। इस आधार पर न्याय की इस रूप में प्रजा गया है जो व्यक्ति प्राकृतिक

स्वतन्त्रता एवं समानता के आधार पर समाज में स्वतः व्यवस्था बनावे रखने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हो।"

(2) नैतिक न्याय (Moral Justice)—परम्परागत रूप में न्याय की अवधारणा को नैतिक रूप से अपनाया जाता है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों के समुचित गवामन के लिए कुछ सार्वभौमिक, अपरिवर्तनीय और अन्तिम प्राकृतिक नियम हैं। इन नियमों के अनुसार जीवन-यापन ही नैतिक न्याय है। यदि हमारा आचरण इन नियमों के प्रतिवृत्त होता है तो वह नैतिक न्याय के विरुद्ध है। नैतिक न्याय के कुछ मुख्य अंग हैं—सत्य भावण, प्राणिमात्र के लिए दया व्यवहार, सत्य-पास्त, उदारता, दानशीलता एवं सदाचरण।

(3) कानूनी न्याय (Legal Justice)—न्याय की अवधारणा के कानूनी रूप को प्राचीन और मध्यकाल में ही नहीं आधुनिक काल में भी मान्यता प्राप्त है। आज कानूनी न्याय एक सर्वोपान्य अवधारणा है और प्रत्येक राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानूनी न्याय की स्थापना के लिए समुचित संगठन और प्रक्रिया अपनाये। विश्व के सभी देशों के न्यायालय कानूनी न्याय की प्रस्थापना करते हैं। कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। कानूनी न्याय में सभी नियम एवं कानूनी न्याय की अवधारणा को दो अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है—समस्त कानूनों का निर्माण एवं द्वितीय कानूनों का क्रियान्वयन। यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार जो कानून बनाए, वे न्यायोचित होने चाहिए और सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि निर्मित कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी व्यवस्था के अनुसार दण्डित किया जाना चाहिए।

(4) राजनीतिक न्याय (Political Justice)—राजनीतिक न्याय की मीग है कि राज्य-व्यवस्था के सभी सदस्यों को ऐसे अवसर सुलभ हों कि वे राज्यव्यवस्था को समर्थन समान रूप से प्रभावित कर सकें और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाए कि सभी व्यक्तियों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। यह अनुभव किया गया कि राजनीतिक न्याय की प्राप्ति एक प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था के अन्तर्गत ही की जा सकती है। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ मुख्य साधन हैं—प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, वरिष्ठ मताधिकार, सभी लोगों को विचार, भाषण, सम्मेलन, सभा आदि की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता, न्यायशास्त्रिकों की स्वतन्त्रता, निष्पक्ष रूप से सार्वजनिक पदों की सुलभता आदि। राजनीतिक न्याय की मीग है कि देश की राजनीति में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं हो।

(5) सामाजिक न्याय (Social Justice)—सामाजिक न्याय का अर्थ है कि नागरिकों के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का वेदभाव नहीं किया जाए और प्रत्येक नागरिक को आत्मविकास के पूर्ण अवसर सुलभ हों। सामाजिक न्याय की मीग है कि समुचित जीवन-यापन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का सृजन हो, राजनीतिक सत्ता करने विधायी और प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा समानता पर आधारित समाज की स्थापना का प्रयत्न करे। आधुनिक काल में सामाजिक न्याय और प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा समानता पर आधारित समाज की स्थापना का प्रयत्न करे। आधुनिक काल में सामाजिक न्याय का विचार लोकतन्त्र होता जा रहा है, क्योंकि साम्यवाद या समाजवाद में सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया है। इसीलिए विश्व के कठोरी लोगों ने समाजवाद को किसी न किसी रूप में अपना लिया है। समाजवाद के प्रति आकर्षण का कारण उसमें मिश्रित सामाजिक न्याय के प्रति उत्पन्न है। अनेक विद्वानों ने सामाजिक न्याय के प्रति उत्पन्नता के आधार पर साम्यवाद को 'नवीन युग का एक नया धर्म' कहा है।

(6) आर्थिक न्याय (Economic Justice)—आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का अंग है। आर्थिक न्याय का अभिप्राय है कि सम्पत्ति सम्पत्ती अन्तर् इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि सम्पत्ति के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच विवेक की दीवार खड़ी हो जाए और व्यक्ति दूसरों के श्रम का शोषण करे अथवा उन्हें अपने से बहुत नीचा मानते हुए उनके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित करे। आर्थिक न्याय की यह मीग है कि सर्वप्रथम समाज के सभी व्यक्तियों को अनिवार्य आवश्यकताएँ पूरी हों और तब कुछ व्यक्तियों द्वारा विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। आर्थिक न्याय यह इजाजत नहीं देता कि एक ओर लोग आलीशान मकानों में रहे तो दूसरी ओर झोपड़ियों को कतारों में। आर्थिक न्याय की स्थापना का मार्ग तब तक प्रशस्त नहीं हो सकता, जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार को सीमित नहीं कर दिया जाए।

भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की व्यवस्था

भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था इस प्रकार की गई है—

(क) सामाजिक न्याय के मूलभूत मानवीय सिद्धांत को संविधान के अनेक कपी में मान्यता मिली है। संविधान के तीसरे और चौथे भाग में सामाजिक न्याय की गारंटी के विविध ढंगों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत भूमि पर कानून के समक्ष सभी नागरिक ही समान नहीं हैं, बल्कि उनकी संपत्ति संरक्षण भी प्राप्त है।

अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के स्थान पर विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्याधीन पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में सब नागरिकों को अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का तथा अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार का अन्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 24 के द्वारा कारखानों में बच्चों से काम करने का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के अन्तर्गत अप्ससंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी हितों तथा अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक समर्थता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी आदि अश्रय की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के कार्यसाधक प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 में संविधान ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति के लिए सहायता उपलब्ध करे। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबन्ध, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार-सहिता, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति और अनुच्छेद 47 आहार पुष्टि और जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य आदि मूल सिद्धान्त हैं जिनका अनुपालन भारत में सामाजिक न्याय को साकार एवं सफल कर सकता है।

(ख) आर्थिक न्याय की व्यवस्था करते हुए संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य से कहा गया है कि वह अपनी नीति का संचालन ऐसा करे जिससे समान रूप से सभी नर-नारियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार विभक्त हो जिसमें अधिकाधिक सामूहिक हित सम्भव हो सके, आर्थिक व्यवस्था ऐसी चले कि धन का उत्पादन तथा वितरण के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर केन्द्रण न हो, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों का दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर किसी को ऐसे व्यवसाय में न जाना पड़े जो उसकी आयु अथवा शक्ति के उपयुक्त न हो, शैशव तथा किशोर अवस्था का रक्षण, नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक न्याय की स्थापना की प्रबल चेष्टाएँ की गई हैं। 'समाजवादी ढंग का समाज', 'लोकहितकारी राज्य' और 'मिश्रित अर्थ-नीति' जैसे पदों में आर्थिक न्याय की भावना व्यक्त होती है। भारतीय राज्य आर्थिक क्षेत्र में किन्हीं अनौचित्य की ओर न जाकर, राष्ट्रीय स्वयं तक पहुँचने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहता है।

(ग) राजनीतिक न्याय संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क प्रताधिकार की स्थापना, सम्प्रदायिक निर्वाचनों का अन्त और अनुच्छेद 19 से 22 के अन्तर्गत विविध स्वातन्त्र्य अधिकारों तथा अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप दिया गया है।

आर्नोल्ड बेचेट और न्याय की अवधारणा

(Arnold Brecht & Concept of Justice)

राजनीति विज्ञान के विद्वानों में प्रमुख रूप से न्याय-सिद्धान्त का विवेचन आर्नोल्ड बेचेट की पुस्तक 'Political Theory' में मिलता है। उनके अनुसार, "न्याय की अवधारणा वीछिद्र स्थिति के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और यह एक ऐसे कर्तव्य की तरह है जिसके कई तन्त्र होते हैं।" न्याय के सम्बन्ध से दूसरी अवधारणा यह है कि सम्प्रदायिक को परम्परागत सत्ताओं पर आधारित होती है अथवा वह परम्परागत सत्ताओं से आगे बढ़ी हुई होती है। प्रथम स्थिति में उसे 'परम्परागत न्याय' (Traditional Justice) एवं दूसरी स्थिति में उसे 'अपरम्परागत न्याय' (Trans-Traditional Justice) कहा जाता है।

परम्परागत न्याय (Traditional Justice)—आर्नोल्ड बेचेट के अनुसार न्याय की परम्परागत अवधारणा सामाजिक जीवन के प्रचलित रीति-रिवाजों, प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित होती है। इन प्रथाओं, परम्पराओं आदि के अनुसार जो कुछ होता है, उसे न्याय समझा जाता है। इस प्रकार की मूलभूत प्रथा अथवा सत्ताओं में पाँच प्रमुख हैं—एक पत्नी विवाह प्रथा, परिवार, निजी सम्पत्ति, वैतुक धन के सम्बन्ध में उत्तराधिकार की व्यवस्था तथा समझौता करने की स्वतन्त्रता और समझौते की बाध्यकारी शक्ति। परम्परागत न्याय की धारणा इन पाँच प्रमुख अधिकारों पर अवलम्बित है। इन आधारभूत सत्ताओं के अनुसार किए जाने वाला आचरण न्याय-भावना के अनुसार समझा जाता है। इन सत्ताओं के औचित्य को चुनौती नहीं दी जाती है। आर्नोल्ड बेचेट के अनुसार परम्परागत न्याय-भावना में निम्नलिखित तत्त्व शामिल हैं—(1) व्यक्ति जाने-अनजाने परम्परागत मान्यताओं और सत्ताओं को तर्कसंगत समझता है, (2) वह उनका प्रयोग क्रमिक तर्क द्वारा कुछ निश्चित पूर्व-कल्पनाओं को प्राप्त करने के लिए करता है, (3) इनके अपार पर व्यक्ति ऐसे नियमों-विनियमों को स्वीकार करता है जो सामाजिक जीवन में स्थिरता, निश्चितता और औचित्य बनाए रखते हैं, (4) वह इन परम्परागत मान्यताओं को सत्ताओं का प्रबल समर्थन करता है इनके विरुद्ध अत्योपेक्षा सहन नहीं करता, उनका प्रतिवाद करता है।

समानता तथा स्वतन्त्रता का साधन (Relation of Equality and Liberty)

राजनीति विज्ञान में समानता एवं स्वतन्त्रता एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, किन्तु व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से अनेक विचारक समानता तथा स्वतन्त्रता को एक-दूसरे का विरोधी मानते हैं। समानता की उपस्थिति में स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है और उसका अर्थ असमानता बन जाता है। डी. टाकविल तथा लॉर्ड एक्टन दोनों इस प्रकार के विचारक हैं जो स्वतन्त्रता तथा समानता को एक-दूसरे का विरोधी मानते हैं। उनके अनुसार समानता स्वतन्त्रता की शत्रु है। लास्की का कहना है कि लॉर्ड एक्टन तथा टाकविल का निष्कर्ष अत्यन्त चरमवादी है। लॉर्ड एक्टन का कथन है कि—“समानता की उत्पत्ति अभिजात्य के कारण स्वतन्त्रता की आशा हो व्यर्थ हो गई है।” वास्तव में स्वतन्त्रता एवं समानता एक-दूसरे की पूरक और साथ-साथ रहने वाली राजनीतिक धारणाएँ हैं। आशीर्वदम् के अनुसार, “स्वतन्त्रता के पुजारियों (टाकविल एवं लॉर्ड एक्टन) का यह विचार कि स्वतन्त्रता और समानता एक-दूसरे के विरोधी हैं, गलत है। प्रभु के आधिकारी कोई मूर्ख नहीं थे कि जिन्होंने ‘स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व’ का गद्य तुल्य किया। ये तीनों शब्द एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्धित हैं। यदि स्वतन्त्रता को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो यह जरूरी है कि समानता किसी न किसी रूप में उनके साथ रहे।”

स्वतन्त्रता एवं समानता को एक साथ रखने के लिए कुछ हदों तक पूरा होना आवश्यक है। राज्य में न वर्गभेद होना चाहिए और न धन के आधार पर कार्य का वितरण। आधुनिक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शक्ति का मूल आधार धन है। अधिकांश जनता जिनकी इज्जत करती है और जिनके पीछे-पीछे चलती है, उनसे इज्जत और मेतृत्व का कारण उनके ज्ञान या गुण न होकर उनके धन की शक्ति है। वे पूँजी के आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। समाज के उत्पादन के साधन उनकी अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित होते हैं। समाचार-पत्रों पर अपने नियंत्रण से वे राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। समाज की आर्थिक शक्ति ऐसे हाथों में आकर मजदूर-वर्ग के लिए घातक सिद्ध होती है। इस प्रकार जहाँ ज्यादा आर्थिक असमानताएँ हैं, वहाँ स्वतन्त्रता की अनुपति और उपयोग उसी अनुपात में कम हो जाते हैं। इन सब परिस्थितियों के आधार पर लास्की का मत है कि “राजनीतिक स्वतन्त्रता तब तक पथार्थ नहीं हो सकती जब तक उसके साथ आर्थिक समानता न जुड़ी हुई हो, क्योंकि राजनीति अग्रे चलकर आर्थिक शक्ति के हाथ की कठपुतली बन जाती है।”

नये सामाजिक आन्दोलन (New Social Movements)

समय परिवर्तनशील है। मनुष्य के विचार एवं दृष्टिकोण समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के लिए समाज में आन्दोलन होते हैं और फलस्वरूप समाज में सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन भी आवश्यक हो जाते हैं। राजनीतिक परिवर्तन राज्य की संरचना/संगठन, संस्थाओं एवं नागरिकों के मनोवैज्ञानिक वैचारिक परिवर्तन के रूप में होते हैं। यह राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है।

राजनीतिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Political Change)

राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्थाओं में नागरिकों के विचार एवं दृष्टिकोण के परिवर्तन को कहते हैं। इसमें राज्य व्यवस्था, राजनीतिक मूल्य मानक, संगठन, ढर्रे, सरपंचों एवं सर्वप्राधिकारिक नीतियों के परिवर्तन मुख्य होते हैं। जिस एवं मूल ने परिवर्तन शब्द को सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा है कि—“सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना, साम्राज्य का आकार, उनके अंगों की रचना, अनुसूचन और उनके ढंग में परिवर्तन है।” यह परिवर्तन राजनीतिक हो या सामाजिक इसका मुख्य कारण क्या है? जनता इसे क्यों चाहती है? आदि तथ्यों को जानना आवश्यक है। परिवर्तन बाढ़ हो या आन्तरिक यह प्रकृति एवं समाज दोनों से सम्भव होता है। राजनीतिक परिवर्तन समाज के विभिन्न समूहों के मध्य अन्तर्क्रिया द्वारा, पुनर्जी रूढ़ि-पीढ़ी समाप्त होने से एवं बदलते परिवेश से सम्भव है। राजनीतिक परिवर्तन समाज में नई-नई शैक्षणिकों के विकास, व्यवहार एवं युद्ध, राजद्रोह, वशापरपरा समाप्त होने से राजनीतिक नेताओं के उदय-पतन, धार्मिक संघर्ष, सामूहिक विकास से सम्भव होता है। कुछ परिवर्तन औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से भी सम्भव होते हैं।

राजनीतिक परिवर्तन के प्रकार (Kinds of Political Change)

विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार बताये हैं। प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन ये हैं—1. सर्वप्राधिकारिक परिवर्तन, 2. राजनीतिक संगठन में परिवर्तन जैसे—राज्य संगठन, संस्था आदि में परिवर्तन, 3. प्रशासनिक परिवर्तन, जैसे—सत्ता-शक्ति परिवर्तन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में परिवर्तन, 4. शासन परिवर्तन, राजनीतिक दल, गुटबन्दी, दबाव समूह आदि में परिवर्तन, 5. क्रांतिकारी परिवर्तन 6. विकासवादी परिवर्तन आदि।

राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव (Impact of Political Change)

राजनीतिक परिवर्तन का राजनीतिक समाजशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? राजनीतिक सामाजिक वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिवर्तनों का अलग-अलग प्रभाव बताया है। सार्वजनिक, बौद्धिक, सामाजिक समूहों आदि के परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक हितों पर पड़ता है। आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव साम्राज्यों के सिद्धान्त पर, आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी का अभिवृद्धि एवं उत्पन्न पर प्रभाव पड़ता है। समाज सङ्गठनों के परिवर्तन का सम्पूर्ण सामाजिक और मौखिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन से राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष की प्रकृति सामाजिक समूहों की प्रमुखता देकर शक्ति संचालन में परिवर्तन लाती है जिससे अर्थव्यवस्था में भी हस्तक्षेप द्वारा परिवर्तन होता है। इस प्रकार राजनीतिक परिवर्तन मनुष्य के जीवन के सम्पूर्ण परिवर्तन का संचालक बनता है।

संघर्ष एवं सुधार (Conflict and Reforms)

उन्नति एवं विकास संघर्ष के कारण होता है। संघर्षों से संघर्ष का जन्म होता है। संघर्ष की उत्पत्ति एवं सुधार मानव जीवन का राजनीतिक पहलू है। समाज में राजनीतिक व्यवस्था संघर्षों का मुख्य कारण है।

राजनीति एवं संघर्ष (Politics and Conflict)

संघर्ष की उत्पत्ति का मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता है। राजनीति का प्रत्यक्ष पहलू संघर्ष लिये होता है। मनुष्य की आवश्यकताएँ असीम होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य प्रयास करता है। प्रयास करने में विभिन्न समूह एवं विभिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है जिनकी आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। इन समूहों की आवश्यकता में टकराव उत्पन्न होता है जो संघर्ष के जन्मदाता होते हैं। क्विन्सी राइट ने राजनीति की परिभाषा में कहा है—“राजनीति एक कला है जिसमें अत्येक समूह एक-दूसरे समूह पर नियंत्रण रखकर उन्नति का प्रयास करता है। यही उन्नति एवं नियंत्रण संघर्ष का कारण होती है।” बर्ट्रेंड रूससेल ने संघर्ष को राजनीति की जड़ माना है।

राजनीतिक संघर्ष के रूप (Forms of Political Conflict)

दो व्यक्तियों द्वारा समान वस्तु प्राप्त करने का प्रयत्न संघर्ष का न्यूनता है। ये वस्तु विभिन्न रूपों में पाती है उसी अनुसार संघर्ष के रूप भी भिन्न-भिन्न होते हैं, यथा—मानसिक संघर्ष, वैचारिक संघर्ष, सामूहिक संघर्ष आदि। मानसिक या बौद्धिक संघर्ष में मनुष्य को मन्त्रिस्थिति का ज्ञान नहीं होता है। वह अनिर्णय की स्थिति में रहता है। सामूहिक संघर्षों में समूह या संगठन में कोई समझौता या सलाह-राय एक मव न होने से पैदा होता है। विचार भिन्नता से भी संघर्ष संभव है।

विचारों में संघर्ष के दो रूप होते हैं—1. हिंसात्मक संघर्ष एवं 2. अहिंसात्मक संघर्ष। प्रथम संघर्ष में मनुष्य मत-भेद दूर करने के लिए युद्ध का चुनाव करता है। युद्ध में हिंसा आवश्यक है, अतः यह संघर्ष हिंसात्मक संघर्ष कहलाता है। राजनीति में भी हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है। वर्तमान में होने वाले चुनाव संघर्ष की पराकाष्ठा हैं। द्वितीय संघर्ष में युद्ध या हिंसा का उपयोग नहीं होता, उसमें विचारों का युद्ध होता है जिसका निदान समझौतों, बैठकों, अध्यास-संविधान के अनुसंधान कार्यक्रमों द्वारा किया जाता है। संघर्ष की प्रकृति के आधार पर एक वर्गीकरण खुला संघर्ष एवं गुप्त संघर्ष का रूप में किया जाता है। खुले संघर्ष में युद्ध, मतदान, लोकमत की सम्मिलित किया जाता है गुप्त संघर्ष में धूँस, धाखाधड़ी, जसूसी गुटबन्दी आदि आते हैं। लोकतन्त्र में संघर्ष आवश्यक होता है।

संघर्ष का संगठन (Organisation of Conflict)

प्रतिपक्षिता की भाँति जीत-हार रूपी संघर्ष के दो संगठन हैं—1. शून्य संघर्ष (Zero Struggle) एवं 2. अशून्य संघर्ष (Non zero Struggle), जैसे—प्रतिपक्षिता में एक को हार, दूसरे की जीत सुनिश्चित होती है इसी प्रकार शून्य संघर्ष (Zero Struggle) में प्रतिपक्षी समान होते हैं, अर्थात् जितने जीत का दावेदार होंगे उतने ही हार के दावेदार होंगे हैं। उनका अन्तर शून्य होता है। अशून्य संघर्ष प्रतिपक्षिता में विकल्प विजय होने है। राजनीति में चुनाव इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

राजनीतिक संघर्ष में सुधार (Political Conflict Reforms)

संघर्षों में कभी सन्धि, समझौता करने हेतु इनमें सुधार आवश्यक है। संघर्षों में सुधार के प्रमुख प्रकार निम्नांकित हैं—

1. त्याग भावना—संघर्षों का समाप्त करने की उद्देश्य प्राप्ति त्याग की भावना है। यदि दो व्यक्तियों में अद्वय राह में संघर्ष है तो एक व्यक्ति अथवा राष्ट्र द्वारा संघर्ष को त्यागना इसका समाधान है।

2. सन्धि—सन्धि करना संपर्क सम्पत्ति का शान्तिपूर्ण तरीका है। सन्धि अथवा समझौते द्वारा दोनों वर्ग एक-दूसरे से सहमत होकर मध्य का मार्ग अपना लेते हैं।

3. संपर्क—संपर्क के समाधान का तरीका संपर्क भी है। इसमें एक दल या समूह अपनी माँग को समाप्त कर अपने आप को समर्पित कर संपर्क सम्पत्ति को घोषणा कर देता है।

4. वार्तालाप—वार्तालाप द्वारा संपर्क टूटा जा सकता है। दोनों पक्षों के संपर्क में कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता कर दोनों पक्षों में वार्ता कराकर मध्यम मार्ग से संपर्क टाँसा जाता है।

5. सर्वमध्य निर्णय—संपर्क में सर्वमध्य निर्णय द्वारा संपर्क वर्ग-दल-एक को सुकाया जाता है। छाड़ी संपर्क इसका उदाहरण है।

क्रान्ति (Revolution)

परिवर्तन का एक रूप क्रान्ति जो अंग्रेजी के 'Revolution' शब्द का पर्यायवाची है। विभिन्न रूपों में इस शब्द का प्रयोग होता है, यथा—परिधमन, परिक्रमण, घूर्णन, चक्र, परिवर्तन, क्रान्ति आदि। 'दो अमेरिकन पौपुल्स एनसाइक्लोपीडिया' के अनुसार, "क्रान्ति किसी राष्ट्र में विस्तृत परिवर्तन की सहायक होती है जिसमें अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं। फलस्वरूप उस देश के नागरिकों के जीवन मूल्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं।"

राजनीतिक क्रान्ति का अर्थ (Meaning of Political Revolution)

राजनीतिक समाजशास्त्र में इस अवधारणा का विशेष महत्व है। इसका प्रयोग राजनीति विज्ञान में प्राचीन काल से होता आया है। सभी विद्वान इसका प्रयोग 1789 से मानते हैं। सर्वसम्मत परिभाषा के अनुसार, "क्रान्ति शासन की संरचना, समर्थन का आधार एवं कार्यों में परिवर्तन असंवैधानिक रूप से किया गया स्वरूप है जिसमें परिवर्तन विशिष्ट वर्ग एवं नागरिकों द्वारा हिंसा अथवा हिंसात्मक घटकों द्वारा किया जाता है।" टी. एच. ग्रीन के अनुसार, "क्रान्ति शब्द को न केवल आधुनिक आन्दोलनों पर लागू करना चाहिए जिसने मानव स्वतन्त्रता को विस्तृत किया है, बल्कि उन सब हिंसक परिवर्तनों पर लागू किया जाना चाहिए जिनका मूल उद्देश्य परिवर्तन हो। ये सब सैनिक क्रान्तियाँ जिनका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, मानकों तथा उद्देश्यों में परिवर्तन हो क्रान्ति की अवधारणा में सम्मिलित होते हैं।"

राजनीतिक क्रान्ति के प्रकार (Kinds of Political Revolution)

राजनीतिक परिवर्तन के तरीकों को राजनीतिक क्रान्ति कहते हैं, जिनमें धन, शक्ति, सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन सम्मिलित है। ये परिवर्तन वैधानिक व्यवस्था द्वारा शान्तिपूर्वक एवं सविधान का उल्लंघन कर असंवैधानिक रूप से किये जा सकते हैं। राजनीतिक क्रान्ति के दो स्वरूप होते हैं—1. शान्तिपूर्ण क्रान्ति एवं 2. खूनी क्रान्ति। प्रथम राजनीतिक क्रान्ति को विद्वान मानने से इनकार करते हैं। सभी विद्वान राजनीतिक व्यवस्था एवं सिद्धान्तों के निर्माण को ही राजनीतिक क्रान्ति मानते हैं। राजनीति के लेखक शान्तिपूर्ण अथवा अहिंसात्मक राजनीतिक क्रान्ति को मानने से सहमत नहीं हैं। महात्मा गाँधी द्वारा कभी भी राजनीतिक परिवर्तन के लिए हिंसात्मक राह नहीं अपनाया गया, अतः अहिंसात्मक राजनीतिक क्रान्ति को भी क्रान्ति के प्रमुख स्वरूप में सम्मिलित किया जाना अव्यवहार्य है। राजनीतिक परिवर्तन के उद्देश्यों के आधार पर दो प्रकार की राजनीतिक क्रान्ति प्रमुख हैं—1. विकासशील आधुनिक राजनीतिक क्रान्ति एवं 2. अविकसित राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपरक क्रान्ति। आधुनिक विश्व के राष्ट्रों में नई राजनीतिक व्यवस्थाएँ विकसित हो रही हैं। उससे हुए राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन को विकासवादी राजनीतिक क्रान्ति कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में विकास से हुए परिवर्तनों में सत्ता में निष्ठा एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन भी हो यह स्पष्टीकरण देता है। निष्ठा परिवर्तन से हुए राजनीतिक परिवर्तन को अविकसित राजनीतिक क्रान्ति कहते हैं। इसके निम्नांकित प्रमुख कारण हैं—1. विदेशी प्रभुत्व द्वारा राजनीतिक क्रान्ति, 2. आन्तरिक राजनीतिक क्रान्ति, 3. सैनिक क्रान्ति, सेना की बगावत, 4. पराजित राष्ट्रों को स्वतन्त्रता देना एवं 5. युद्ध।

राजनीतिक क्रान्ति के कारण (Causes of Political Revolution)

आरलू के अनुसार क्रान्ति के कारणों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—1. भौतिक कारण 2. साधारण कारण एवं 3. विशेष कारण। आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक भिन्नता राजनीतिक क्रान्ति का भौतिक कारण है। राजनीतिक क्रान्ति के साधारण कारणों में निम्नांकित मुख्य हैं—1. नेता-शासक की स्वार्थपरता, 2. राजनीतिक सम्मान का लालच, 3. उच्च मनोभावना का विकास, 4. ऋण-दबाव, 5. शोषण, 6. शासक संपर्क, 7. चुनावी धोखे तथा 8. जातिगत समस्याएँ। राजनीतिक क्रान्ति के विशेष कारणों में धार्मिक पहलू, लोकतन्त्र के अभाव, शक्ति सत्ता का दुरुपयोग, कुल संपर्क परिवार के झगड़े आदि आते हैं।

राजनीतिक क्रान्ति के रोक के उपाय

(Preventive Measures of Political Revolution)

राजनीतिक क्रान्ति के रोक के प्रमुख उपाय हैं—1. शक्ति का विकेंद्रीकरण 2. राजनीतिक शक्ति-सत्ता के पदों का समान वितरण 3. देश-भक्ति का विकास 4. लोकतन्त्र में घटितियों पर रोक 5. नागरिकों से सद्व्यवहार 6. दण्ड की कठोर व्यवस्था आदि ।

राजनीतिक बाध्यता

(Political Obligation)

राज्य न दो आन्तरिक दृष्टि से और न ही बाह्य रूप से पूर्ण है। सभी दृष्टिकोणों से राज्य सम्प्रभुता का विचार औचित्य पूर्ण नहीं रहा है। राज्य की राजनीतिक शक्ति के प्रयोग पर जहाँ व्यावहारिक प्रतिबंध व्यवस्थित हैं वहाँ किसी भी सम्प्रभु को अन्य राज्यों के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा है। यदि वे ऐसा न करें तो वह उनका साथ संपर्क में ठग्न आयेगा। संपर्कों का जेखन कोई भी राज्य नहीं उठा सकता। दुष्प्रवृत्ति से एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ठगर रहा है जिसके अपने विशिष्ट नैतिक मानदण्ड एवं ढाँचे स्थापित हैं। ये मानदण्ड राज्य के व्यवहार एवं गतिविधियों पर नैतिक तोमर लगाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक ऐसा बृहद् रूप प्रकट हो रहा है जो राज्य सम्प्रभुता के बड़ा पक्ष को पर्याप्त सन्तुष्ट ठक सोमित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशाली वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय समाज में दलसम्बन्धी दण्ड व्यवस्था पर निर्भर करती है। आज से कुछ वर्षों पूर्व सत्तर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले यह संप्रदाय बाद में समुदाय यह संप्रदाय स्थापित हुए जिनके माध्यम से निर्णयों और प्रतिबंधों को लागू करने की व्यवस्था अस्तित्व में आई है। ये व्यवस्थाएं प्रारम्भ में भले ही अल्प-विकसित रही हों, लेकिन अब उनका क्रान्तिक विकास होया जा रहा है। यद्यपि समुदाय यह संप्रदाय विश्व शक्ति सम्बन्धी अपने मौलिक उद्देश्य में विचार रूप से सफल नहीं रहा है, फिर भी अनेकानेक अन्तर्राष्ट्रीय संपर्कों को कम करने तथा उन्हें मर्यादित करने में इस सत्ता को विरोध सफलता मिली है। मानवता के मूल्यों पर वह राज्यों की स्वार्थ सिद्धि को नियंत्रित करने की आशा का परिचायक है।

आन्तरिक दृष्टि से राज्य की सर्वोच्च बाध्यकारी शक्ति के विचार की अपेक्षा पहिंचा है। किसी भी समाज में ऐसे अनेक समूह एवं समुदाय हैं जो कुछ निश्चित क्रियाओं को सम्पन्न करते हैं। ये राज्य शक्ति के प्रयोग पर व्यावहारिक तोमर लगाते हैं। इसके अतिरिक्त शासकों को समाज में 'क्रान्ति' की घबरी संप्रदायों पर सदैव ध्यान देना होगा है अन्तः लोकमत भा आज एक सशक्त शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। यह सत्य है कि यह पूर्ण रूप से सगठित न हो, परन्तु कोई भी सम्प्रभु शक्ति उसका उन्मूलन करने की स्थिति में नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड में सदा सम्प्रभु है। वह ऐसा कानून बना सकता है कि प्रत्येक शिशु अथवा धनवान व्यक्ति को सर्वधिकार प्रदान होगा, लेकिन व्यवहार में वह ऐसा कानून अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर ही बना सकता है। वह राही है कि बाध्यकारी शक्ति राज्य का एक महत्वपूर्ण सत्ता है, लेकिन ठाक आत्मिक प्रयोग राज्य के उद्देश्य को ही खलल डल रहा है। मैकडवेल के अनुसार, "बाध्यकारी शक्ति राज्य का एक मापदण्ड है उसका भार नहीं।" नागरिकों को उन्मूलित करने से पहले स्वयं राज्य को अनुसंशोधित होना होगा। यह आवश्यक है कि बाध्यकारी शक्ति-शक्ति लागू करने से पहले स्वयं राज्य की अपनी शक्ति की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए।

नये सामाजिक आन्दोलन

(New Social Movements)

सोलहवीं शताब्दी में सामाजिक जागरण और सुधार आन्दोलन हुए तथा पश्चिमी यूरोप के इतिहास पर यह राज्यों (Nation States) का उदय हुआ। परिणामस्वरूप यूरोप के इतिहास पर आधुनिकीकरण (Modernisation) प्रारम्भ हो गया। युग परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक विचारों में गम्भीर परिवर्तन होने लगे। मैकडवेली (Machiavelli) को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। उसने मध्य युग के विचारों से अलग इतर आधुनिक व्यक्तिवाद और यह राज्य की स्थाना में योग दिया, अनुभूति प्रधान ऐतिहासिक पद्धति को अन्तर्गत और राज्य के प्रकृतियत्ती सिद्धान्त की नैतिकता के बंधनों से मुक्त किया। उसने संनिव प्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और सामन्तवाद (Feudalism) पर प्रहार करके सर्वोच्चतन्त्र केन्द्रिय शक्ति की प्रतिष्ठा की। इस नई धारा में राजनीतिक विचारक यह राज्य की प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन करने लगे तथा यह राज्य का ऐसा स्वरूप समझे आया जो धर्मनिरपेक्ष (Secular) होने के साथ-साथ सम्प्रभुता (Sovereignty) सम्पन्न था।

सत्रहवीं शताब्दी में मुख्यतः दो राजनीतिक विचारधाराएँ उठी—निरंकुशवाद की समर्थन और निरंकुशवाद विरोधी। बोदो (Bodin) एवं होब्स (Hobbs) ने निरंकुशवाद का समर्थन किया और लॉक (Lock) ने सार्वजनिक राज्य

(Constitutional Monarchy) का पथ लिया। रूसो (Rousseau) ने लोकप्रिय सम्प्रभुता की बात की तथा मॉण्टेस्क्यू (Montesque) ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क दिये। कुछ समय बाद फ्रांस में क्रांति हुई जो स्वतंत्रता, समानता और प्राकृतिक सिद्धान्तों पर आधारित थी। जो सारे यूरोप में फैल गए। राष्ट्रीयता का विचार प्रबल हुआ और जनता में राजनीतिक चेतना आई। विभिन्न देशों में निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध क्रांति हुई। क्रांतिकारियों की उमरा और हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में इंग्लैंड में बर्क और अमेरिका में हेमिंस्टन (Hamilton) तथा मडिसन (Madison) ने विचार व्यक्त किए। इससे क्रांतिवादी प्रक्रिया का जन्म हुआ। फ्रांसिसी क्रांति और लोकतंत्रीय सिद्धान्त के गुणों के बीच विवाद पैदा हो गया। बर्क के विरुद्ध थॉमस पेन (Thomas Paine) ने लोकप्रिय सम्प्रभुता का प्रबल समर्थन किया। इस काल में औद्योगिक क्रांति ने मानव के आचार और विचार में पूर्ण परिवर्तन कर दिया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का स्थान औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने ले लिया। व्यक्ति गाँव छोड़कर नगरों में आने लगे। औद्योगिक प्रगति ने यूरोप को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रेरित किया, अतः 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी विचारधारा की प्रमुखता रही। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ा। पूँजीपतियों एवं श्रमिकों के द्वि-टकरावे। शोषण के परिणामस्वरूप मजदूरों की दशा दयनीय बन गई जिसे देखकर मानवतावादियों (Humanists) ने कल्पनाविहीन समाजवाद की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में समाजवादी (Socialist) और साम्यवादी (Communist) सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार हुआ। बातावरण और आवागमन के साधनों का विकास होने पर सारा विश्व एक परिवार बन गया। संसार के मजदूर विश्वव्यापी संगठनों में संगठित होने लगे। विश्व साम्राज्यवाद की समाप्ति ने पूँजीपति (Capitalist) देशों को संगठित कर दिया और वे साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए प्रयत्न करने लगे। विश्व दो खेमों (Camps) में बँट गया और राजनीतिक विचारधाराएँ भी दो भिन्न तथा विपरीत दिशाओं में बह निकली।

कुछ प्रमुख विचारधाराएँ (Some Important Ideologies)

डार्विन (Darwin) के सिद्धान्त के प्रभाव से राजनीतिक विचारकों ने विकास की भाषा में सोचना प्रारम्भ कर दिया। फलतः धर्म तथा मानव सम्बन्धी परम्परागत धारणाएँ गिरने लगीं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से 20वीं शताब्दी तक अनेक राजनीतिक विचारक हुए। उनके साथ अनेक विचारधाराओं का उत्कर्ष और अपकर्ष हुआ। मॉण्टेस्क्यू, बाइको, झूझ, बर्क आदि विचारकों ने अपनी तर्क शक्ति से सामाजिक समझौते सिद्धान्त को कसौटी पर कसा। यह कसौटी पर खरा नहीं उतरा, अतः उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। प्रमुख विचारधाराओं का सारा निम्नलिखित है—

उपयोगितावाद (Utilitarianism)

18वीं शताब्दी में उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। यह विचारधारा मूलतः इंग्लैंड का राजनीतिक दार्शनिकता की उत्पत्ति थी। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से अधिकतम सुख की कामना करता है तथा दुःख से बचना चाहता है अतः प्रेक्ष्य राज्य का ढेरूप अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिये। झूझ, प्रीस्टले (Priestley) तथा हचिसन (Hutchison) आदि ने इस विचारधारा का प्रवर्तन किया। जेरेमी बेन्थम (J Bentham) इसके मुख्य समर्थक एवं व्याख्याता थे तथा जे. एस. मिल (J S Mill) ने इसकी पुनर्संशोधन की।

आदर्शवाद (Idealism)

परिवर्तित परिस्थितियों में उपयोगितावाद निष्फल रहा। इसके स्थान पर आदर्शवादी विचारधारा की स्थापना हुई। जर्मनी के दार्शनिक काण्ट (Kant) तथा हीगल (Hegel) ने राज्य को एक अनिवार्य नैतिक संस्था माना। राज्य सर्वशक्तिमान है तथा उसमें और व्यक्ति में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। T H Green ने उदारवादी आदर्शवाद (Liberal Idealism) की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचारधारा ने राज्य और उसकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जीवशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया। कुछ विचारकों ने भूगोलीय दृष्टिकोण को अधिक मज़ी माना। हर्बर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer) जीवशास्त्रीय दृष्टिकोण का और बेजहॉट (Bégchot) भूगोलीय दृष्टिकोण का प्रतिपादक माना जाता है।

माक्सवाद (Marxism)

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कार्ल मार्क्स (Karl Marx) और एंगेल्स (Angels) के सिद्धान्तों ने राजनीतिक विचारधारा का कायाकल्प कर दिया और राज्य के चिन्तन पर व्यापक प्रभाव डाला। मार्क्स के पहले कुछ विचारकों ने समाजवादी सिद्धान्तों का समर्थन किया। कल्पनाविहीन विचारक साइमन (Simon) फोरियर (Fourier) ओबेन (Owen) आदि ने विकासवादी अहिंसात्मक और शान्तिवादी समाजवाद का प्रतिपादन किया, किन्तु मार्क्स के पदार्पण ने इसे बेगपूर्ण

हिंसात्मक और क्रान्तिकारी रूप दे दिया। मार्क्स ने पूँजीवादी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। उसने समाजवाद को वैज्ञानिक अश्रय प्रदान किया।

पुनर्रचनावाद (Revisionism)

मार्क्स तथा एंजिल्स से प्रेरणा लेकर विचारकों ने सामाजिक पुनर्रचना के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धान्त ग्रेट-ब्रिटेन की धरती के लिए उपयुक्त सिद्ध हुए। इन्होंने विभिन्न समाजवादी आन्दोलनों का सूत्रपात किया। इनमें फेबियनवादी आन्दोलन प्रथम उल्लेखनीय है।

फेबियनवाद (Fabianism)

इस सिद्धान्त ने क्रान्ति और टाढ़ता से दूर वैधानिक उपायों द्वारा समाजवाद की स्थापना का आग्रह किया। यह विनाश की अपेक्षा सुधार को महत्व देता है। विकासवादी समाजवाद का एक अन्य स्कूल (विचारधारा) 'समष्टिवादी समाजवाद' कहा जाता है। इसके राज्य समाजवाद, समूहवाद आदि नाम भी हैं। यह परिवर्तन की द्रिष्टि में विरोध रखते हुए यह चरणा है कि समाजवादी क्रान्ति रक्तपात और हिंसा के बिना नाई जये। इसी सिद्धान्त की एक मुख्य शाखा पुनर्विचारवादी के रूप में बर्नस्टीन (Bernstein) द्वारा प्रतिपादित की गई। इसने मार्क्स के सिद्धान्त को बहुत आन्दोलनात्मक करत हुए आग्रह किया कि मार्क्स के क्रान्तिकारी पहलु की अपेक्षा विकासवादी पहलु पर ज़ोर दिया जाना चाहिए और परिवर्तित परिस्थितियों में मार्क्सवादी सिद्धान्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने चाहिए।

सिन्डीकेलवाद (Syndicalism)

19वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में फ्रांस के आन्दोलन के गर्भ में सिन्डीकेलवाद का जन्म हुआ। यह एक क्रान्तिकारी विचारधारा है जो शक्ति और विकास की अपेक्षा करते हुए क्रान्ति को वन्दन मुक्त करना चाहती है। यह सिद्धान्त उद्योगों का संचालन एवं सम्बन्धित राज्य के हाथ में न देकर मजदूरों के हाथ में देना चाहता है।

ग्रेजी समाजवाद (Guild Socialism)

इसे समाजवाद का अग्रिमो संस्करण कहा जा सकता है। यह फेबियनवाद और सिन्डीकेलवाद के बीच की विचारधारा है जिसका प्रतिपादन 20वीं शताब्दी की प्रथम दो दशकियों में हुआ। सामान्य रूप से इसका उद्देश्य उद्योग कार्य में लोगों की भागीदारी को स्थापना करना तथा वर्तमान वेतन-प्रथा का अन्त करना है। इसके अनुसार एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिसमें क्रान्ति की रचनात्मक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन हो सके। यह पूँजीवादी व्यवस्था और प्रवेशिक प्रतिनिधित्व का अन्त करके कार्यो के आधार पर क्रान्ति के सपने बनाता चाहता है।

आराजकवाद एवं गाँधीवाद (Anarchism and Gandhism)

आराजकवाद और गाँधीवाद दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएँ हैं। आराजकवाद किसी निश्चित सिद्धान्त का नाम नहीं बल्कि एक आधारभूत विचार का प्रतीक है जिसे कई विचारकों ने अपने-अपने तरीकों से व्यक्त किया है। इस विचारधारा को यह आधारभूत मान्यता है कि शक्ति किसी भी रूप में एक गुण है, अतः अश्वत्थनीय एवं अनावश्यक है। इसके अनुसार न्याय की स्थापना के लिये राज्य को समूल नष्ट करके उसके स्थान पर स्वतन्त्र समाज का संगठन किया जाना चाहिए। आराजकवादी विचारक मानते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से अन्ध है, जो गुणों के कारण पैदा होती है। गाँधीवादी विचारधारा एक अर्थ में आराजकवादी नहीं बल्कि सत्यवादी है। यह आधुनिक केन्द्रांकृत राज्य की व्यक्ति की व्यवस्था का शत्रु समझती है। गाँधीवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर आधारित वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर सत्य और अहिंसा पर आधारित ऐसे नवीन समाज की रचना करना चाहता है जिसमें व्यक्ति को अधिकतम स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके।

फासीवादी (Fascism)

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय फासीवादी राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। यद्यपि इसकी मूल धारणाएँ पूर्ववर्ती राजनीतिक चिन्तन में प्राप्त होती हैं। फासीवाद बिना सैद्धांतिक या तार्किक व्याख्या के है। यह राज्य की सर्वोच्चतावादी प्रवृत्ति में विश्वास करता है। इसके अनुसार राज्य ही सब कुछ है। राज्य के बहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। इस विचारधारा के समर्थकों ने युद्ध की प्रशंसा की तथा अनेक कारणों से उसे मान्य समाज के लिए उपयोगी बताया है।

उक्त सभी राजनीतिक विचारधाराएँ आधुनिक राजनीतिक चिन्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं।

राजनीतिक संस्कृति के सिद्धान्त (Theories of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा राजनीतिक समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसको समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति की समझ का ज्ञान अनिवार्य है। राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत सत्ता का परिभ्रमण सत्ता की क्रियाशीलता के सन्दर्भ में राजनीतिक औचित्य की समस्या महत्वपूर्ण है एवं इसकी योग्यता का प्रकाशगामी उपलब्धि है—एक ऐसा भावनात्मक एवं अभिवृत्तिमूलक पर्यावरण उत्पन्न व विकसित किया जाए जो राजनीतिक सत्ता को क्रियाशील कर सके। जब इस प्रकार भावनात्मक एवं अभिवृत्तिमूलक पर्यावरण की स्थापना एक सकारण बन जाती है एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थायी बन जाती है। जब राजनीतिक व्यवस्था को दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से पृथक् करते हैं तो इसे राजनीतिक संस्कृति कहते हैं।

राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति शब्द 'राजनीति' एवं 'संस्कृति' दो शब्दों से मिलकर बना है। विभिन्न विद्वान् इसे अलग-अलग नाम से सम्बोधित करते हैं। संस्कृति को परिभाषित करते हुए डी. बी. टेलर ने लिखा है कि "संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य आदतों एवं क्षमताओं का समावेश रहता है जिसे मानव समाज के एक सरस्य होने के नाते प्राप्त करता है।" 1 टेलर की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति एक सामाजिक देन है। मैकडगर एवं पैज के अनुसार, "संस्कृति हमारे दैनिक प्रतिदिन के रहन-सहन की प्रकृति, साहित्य, धर्म कला, मनोरंजन तथा उपयोग सम्बन्धी अभिव्यक्ति है।" 2

संस्कृति की अवधारणा इन विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। 1— संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस्तान्तरित (Transmit) होती रहती है 2. सीखा हुआ व्यवहार होने के कारण यह एक सामूहिक धारणा है 3 इसकी प्रकृति आदर्शात्मक होती है 4 यह व्यक्तिगत सम्पत्ति न होकर समाज की धरोहर है 5 यह आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है 6 इसमें समष्टानुकूल परिणति होने एवं पर्यावरण से संभाव्यता करने की क्षमता होती है 7 प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है अतः विभिन्न समाजों की संस्कृतियों में भिन्नता पाई जाती है 8 मानव उपलब्धि के रूप में संस्कृति एक प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है 9 यह अति-वैयक्तिक (Super individual) तथा अति-अवयव (Super organic) है 10 यह सार्वभौमिक (Universal) है।

राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय उन विशिष्ट आदतों विश्वासों रीति-रिवाजों कौशलों धारणाओं अभिवृत्तियों धुक्तियों या रुझानों और मूल्यों में होता है जिन्हें राजनीतिक मानव राजनीतिक व्यवस्था से सीख लेता है और उन्हें अपनी आदतों और मनोभावों में उतार लेता है। आण्डर इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहते हैं। उन्होंने इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया है। जी. ए. आण्डर एवं सिडनी वर्ना के अनुसार, "राजनीतिक व्यवस्था एवं इसके घटकों के प्रति विभिन्न राजनीतिक अभिव्यक्तियों तथा व्यवस्था में स्वयं की भूमिका के प्रति मनोवृत्तियों का आशय राजनीतिक संस्कृति है।" 4 प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति का एक व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) सत्ता होता है जो नीतियों, अर्थ एवं समाजों को अनुशासन एवं व्यक्तिगत व्यर्थों को सामाजिक सन्दर्भ प्रदान करता है। लुसियन डब्ल्यू.

1 E. B. Taylor The Origin of Culture p 1

2 MacIver & Page Society p 499

3 Dharmveer Political Sociology p 88

4 G. A. Almond and Sidney Verba The Civic Culture p 12.

पाइ के अनुसार, "राजनीतिक संस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों एवं मनोभावों का कुलक है जो राजनीतिक क्रियाओं को अर्थ एवं सुव्यवस्था प्रदान करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अन्तर्निहित पूर्व धारणाओं एवं नियमों को बताता है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक आदर्श तथा सक्रियशील मान्यताएँ, दोनों सम्मिलित हैं अतः राजनीतिक संस्कृति राजनीति के मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिपरक पहलुओं का समुचित प्रकार से आविर्भाव है।" होत्र मुन्नाउ के अनुसार, "राजनीतिक संस्कृति उन रूपों की ओर ध्यान आकर्षित करती है जिनका पूर्वानुमान समूहों के राजनीतिक व्यवहार से तथा इन समूह के सदस्यों के सामान्य विश्वासों, नियामक सिद्धान्तों, उद्देश्यों एवं मूल्यों से लगाया जा सकता है चाहे उस समूह का आचार कुछ भी हो।"²

राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं विश्वासों का योग है जिससे कि उनका राजनीतिक व्यवहार निर्धारित होता है, अतएव राजनीतिक व्यवस्था का स्थापित बहुत सीमा तक राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर रहता है।

राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति (Nature of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग है और एक व्यक्ति अथवा समूहों समाज के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह होते हैं उन्हें ही सामूहिक रूप से राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। यह एक समाज की ऐतिहासिक विरासत होती है और कुछ सीमा तक राजनीतिक दलों, दबाज समूहों तथा अनेक राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख सलग तथा विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

1. राजनीतिक संस्कृति एक अपूर्व नैतिक धारणा—राजनीतिक संस्कृति का मूल अणु व्यक्ति और समाज के राजनीतिक मूल्य और विश्वास हैं। ये मूल्य और विश्वास सामान्य नैतिक धारणाओं के अंग होते हैं और इन्हें अन्य भौतिक तत्वों की भाँति कोई मूर्त स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। इन्हें समझा और अनुभव किया जा सकता है।

2. राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक और सपक्षित सम्मेलन—राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग है और सामान्य संस्कृति का ही समान अनेक तत्वों का सामूहिक एवं सपक्षित रूप है। ऐतिहासिक विरासत, भौगोलिक परिस्थितियों, समाज की सामान्य संस्कृति, विचारधाराएँ, राजनीतिक व्यवस्था और इनके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक संरचना आदि के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के आधार के रूप में कार्य किया जाता है।

3. राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता—राजनीतिक संस्कृति यदि एक ओर ऐतिहासिक विरासत तथा भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है तो दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक संरचना के द्वारा इसका नियमन किया जाता है। सामाजिक आर्थिक संरचना और राजनीतिक संस्कृति के कुछ तत्व स्थिर नहीं बल्कि विकसित होते हैं। इस दृष्टि से सभी राजनीतिक संस्कृतियों अवस्थाक रूप से गतिशील होती हैं। इसमें से कुछ मन्द परिवर्तनशीलता और कुछ तीव्र परिवर्तनशीलता की स्थिति को अपनाती हैं।

4. राजनीतिक संस्कृति में आस्थाएँ एवं विश्वास—आनुषंगिक आस्थाओं या विश्वासों का सम्बन्ध व्यक्ति की विश्व के बारे में राजनीतिक समझ से है अर्थात् इसका सम्बन्ध इससे है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाओं, सरकारों और प्रक्रियाओं के बारे में स्वयं किस प्रकार के विश्वास रखता है? इससे राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति का अभिप्राय या उद्दीष्टता का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति स्वयं यह विश्वास रखने लग जाता है कि आम चुनाव में उसका मत देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वह समान्यतया मत देने ही नहीं जाएगा। राजनीतिक संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्त्व राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की आनुषंगिक आस्थाओं और विश्वासों का है।

5. मूल्य अभिवृत्तियाँ—मूल्य अभिवृत्तियाँ शासन क्रिया या सरकार द्वारा उन व्यक्तिगत सदस्यों, जिन्हें अभिवृत्ति करना या पाना है तथा वे सार्वजनिक सत्ता जिन्हें राजनीतिक समाज के लिए उत्तरदायी करना है सम्बद्ध आचार्य और विश्वसनीय हैं। राजनीतिक समाज के व्यक्ति स्वयं अपने लिए और समूहों के लिए किस प्रकार के मूल्य अभिवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के लिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की अभिवृत्ति कानून एवं व्यवस्था और स्थिति में हो सकती है तो किसी अन्य समाज में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता को केवल अवस्था, हिंसा और अराजकता की स्थिति में ही लोग चाहते हैं। राजनीतिक समाज ऐसा हो सकता है जिसमें व्यक्ति इसको कोई चिन्ता नहीं करते कि उनका शासन निरक्षर है या लोकतांत्रिक। उनकी रुचि हो सकती है कि उनका समाज समय के साथ धीरे धीरे नहीं नष्ट हो जाय बल्कि चाहें उसके लिए शासन कोई भी साधन अपनाएँ उन्हें इसकी चिन्ता नहीं रहती है।

1 L. W. Fye Aspects of Political Development, p. 104-105

2 Heinz Eulau Op. cit., p. 111

राजनीतिक संस्कृति में इन सखणों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह हर राजनीतिक संस्कृति में समान रूप से पाए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि ॥ राजनीतिक संस्कृति में इन सखणों में मात्रात्मक अन्तर पाये जाते हैं और इस कारण राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा एक सी होते हुए भी हर व्यवस्था में उसकी मात्रा या अंश अलग-अलग पाया जाता है।

संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति (Culture and Political Culture)

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति मूल रूप से समाज की संस्कृति से प्रभावित होती है। उस समाज की संस्कृति विरासत उसके आदर्श और उसके मूल्य व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को धारा को निर्धारित कर देते हैं। हम पी. पर्ना के अनुसार, "किसी देश की राजनीतिक संस्कृति एक तरह से उसकी सामान्य संस्कृति के समान होती है।" सिडनी वर्ग के अनुसार, "राजनीतिक संस्कृति और समाज की अपेक्षाकृत अधिक सामान्य संस्कृति का एक अभिन्न पहलू है।" एक व्यक्ति के राजनीतिक विश्वास उसके अन्य विश्वासों का अंग होते हैं और सामान्य संस्कृति के मूल्यों एवं विश्वास से राजनीतिक संस्कृति अग्रपथित नहीं रह सकती। व्यक्ति के सांस्कृतिक व्यवहार की प्रवृत्तियों उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी समाज के मूल्य सांस्कृतिक जीवन में नैतिक मूल्य गहरे हैं तो शासन एक सीमा से बाहर नैतिक मूल्यों की अवहेलना का साहस नहीं कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो तीव्र जनविरोध के रूप में इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। यदि व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के अन्तर्गत विश्वास की पक्वता रखते हैं तो उनके द्वारा अपने राजनीतिक नेताओं पर विश्वास किया जा सकेगा और शासन के द्वारा के अन्तर्गत शासक वर्ग के व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान का अवधारण करते हुए पारस्परिक सहयोग करेंगे। भारतीय और भारतीय समाज के राजनीतिक व्यवहारों में अन्तर का प्रमुख कारण यह है कि दोनों समानों की सांस्कृतिक सार्वजनिक, मान्यताएँ और आदर्श एक-दूसरे से भिन्न हैं। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति की इस विवेचना से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति का नियमन करती है दूसरी ओर राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति को प्रभावित करती है।

इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति में घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों एक-दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करती रहती हैं। सामान्य संस्कृति व्यापक अवधारणा है, जबकि राजनीतिक संस्कृति अपेक्षाकृत सीमित अवधारणा है। प्रथम में व्यक्ति की सम्पूर्ण मूल्य व्यवस्था, आस्थाएँ और विश्वास सम्मिलित होते हैं, दूसरी में व्यक्ति के केवल राजनीतिक विचारों से या राजनीतिक वस्तुओं से सम्बन्धित मूल्य, आस्थाएँ और विश्वास आते हैं।

राजनीतिक संस्कृति के आयाम (Dimensions of Political Culture)

1. राष्ट्रीय एकक्यता—प्रत्येक राष्ट्र की अलग पहचान होती है। उसका अपना व्यक्तित्व होता है। राष्ट्रीय जीवन में इसे अलग पहचान अपना अलग व्यक्तित्व होने से सामाजिक व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन में सहायता मिलती है। इसी के अनुरूप विकास की दिशा निर्धारित की जा सकती है और उसे गति दी जा सकती है। प्रत्येक नागरिक द्वारा इस राष्ट्रीय एकक्यता के साथ एकाकार हो जाने से राजनीतिक संस्कृति में निश्चार उत्पन्न हो जाता है।

2. अन्य नागरिकों के साथ एकक्यता—राजनीतिक संस्कृति का पहलुपूर्ण पक्ष यह है कि व्यक्तियों का अपने अन्य नागरिक साथियों के साथ तादात्म्य कैसा है? जिस समाज में व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से एकाकार हो जाते हैं वही राजनीतिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलती है और उसमें पर्याप्त गतिशीलता बनी रहती है।

3. शासन निर्णयों में आस्थाएँ—राजनीतिक संस्कृति के प्रथम दो आयामों को होसता उपलब्ध करने में इसका महत्व होता है ॥ जनता सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में आस्थावान रहती है या निराशा हो जाती है। सरकार सबको समुह नहीं कर सकती, फिर भी अधिकांश व्यक्तियों की भाँगी का दृष्टि रूप में रूपान्तरण हो जाए तो राजनीतिक संस्कृति में विभाजन करने वाली शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है।

4. निर्णय की प्रक्रिया में भूमिका—राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न आयामों में से एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि किसी समाज में वहाँ के व्यक्तियों की शासन की निर्णय की प्रक्रिया में क्या भूमिका है? क्या वे उदासीन हैं? या वे प्रभावशाली हैं और सशक्त हैं? यदि जन-साधारण राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती हैं, यह राजनीतिक व्यवस्था ऐसे निर्णय लेगी जिससे जन-साधारण को अधिक लाभ पहुँचे।

राजनीतिक संस्कृति के प्रकार (Kinds of Political Culture)

एक राजनीतिक व्यवस्था को सफल जनसंख्या की एक से अधिक राजनीतिक संस्कृति हो सकती है। चतुर्थ राजनीतिक संस्कृति की सजातीयता की मात्रा अनुभविक स्तर का विषय है। एक राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति सामान्य सहमति हो सकती है अथवा उनमें शिक्षा स्तर, भौगोलिक अधिवास, सामाजिक और

आर्थिक प्रस्थिति एवं धार्मिक विश्वास के आधार पर भेद हो सकते हैं। जब एक राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक दिग्विस्तारों का एक समूह ऐसी स्थिति ग्रहण कर लेता है कि उसे अन्य से अलग किया जा सकता है, उसे 'राजनीतिक उपसंस्कृति' कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत जब इस प्रकार की उपसंस्कृति प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तो राजनीतिक व्यवस्था का एकीकरण सकट में पड़ सकता है। राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न आधारों पर भिन्न-भिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें यहाँ निम्नानुसार विवेचित किया जा रहा है—

1. सत्ता एवं शक्ति के आधार पर—सत्ता और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं—

(अ) अभिजनात्मक (Elite) संस्कृति (ब) जन (Mass) संस्कृति। अभिजनात्मक संस्कृति के मूल्य राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं और इसी पर उसकी कार्यकुशलता निर्भर होती है। जन-संस्कृतियाँ सदैव अनेक तथा असमरस होती हैं। प्रायः इन दोनों संस्कृतियों के मूल्य एक-दूसरे के पूरक होते हैं। राज संस्कृति ही इसका निर्णय करती है कि सामान्य जनो से अभिजनो में भर्ती, पद ग्रहण आदि कैसे होगा? सामाजिकरण प्रक्रियाएँ एक-दूसरे की प्रभावित करती हैं। जब इन उप संस्कृतियों में अन्तर काफी गहरा और विस्तृत होता है या राज संस्कृति का प्रभाव दुर्बल पड़ जाता है, तो उस अवस्था में दृष्टि विघटन, संपर्क आदि व्यवस्था जन्य व्याघ्रों के फैलने का भय रहता है। अभिजनात्मक तथा जन संस्कृतियों के बीच मध्यम वर्ग का एक ठोस स्तर होता है और यह दोनों संस्कृतियों में सन्तुलन बनाए रखता है, इसलिए इन दोनों उप संस्कृतियों के संपर्क की भावना कम हो जाती है।

2. निरन्तरता की दृष्टि से—निरन्तरता की दृष्टि से संस्कृति परम्परागत और आधुनिक हो सकती है। आरम्भ एवं कोलमैन के अनुसार सभी संस्कृतियों में इसका मिश्रित रूप पाया जाता है। रिस ने इनके विकासशील या सभ्रतिकालीन समाज भी कहा है। गतिशीलता एवं परिवर्तन की दृष्टि से कई लेखकों ने संस्कृतियों का वर्गीकरण किया है और लिखा है कि संस्कृतियाँ मन्द परिवर्तनवादी या स्थिरवादी तथा क्रान्तिकारी या प्रगतिशील हो सकती हैं, परन्तु यह निर्धारित करना कठिन होता है कि कौनसी संस्कृति स्थिरतावादी है अथवा कौनसी संस्कृति परिवर्तनशील है। राजनीतिक संस्कृति को कुछ लेखकों ने प्रजातन्त्रात्मक, साम्यवादी, समाजवादी तथा एकतन्त्रवादी संस्कृतियों में बाँटा है।

3. सर्वांग समता की दृष्टि से—सर्वांग समता की दृष्टि से बाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृतियों को तीन विशुद्ध रूपों में बाँटा है—

(अ) संकुचित राजनीतिक संस्कृति—यह आदिम समाजों में होती थी। राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य कर्ता विभिन्न योग्यता वाले नहीं होते। एक ही व्यक्ति एक साथ सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कार्य करता रहता है। इनके प्रतीक स्थानीय होते हैं। सोचने का दायरा और शैली संकुचित होती है।

(ब) प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति—इस राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति आर्थिक रूप से उदासीन रहता है। वह मानता है कि उसे मौँगें नहीं रखनी हैं, आन्दोलन नहीं करने हैं। निवेशों के बारे में वह खामोश तथा निर्गुण के बारे में सचेत रहता है।

(स) सहभागि राजनीतिक संस्कृति—इस संस्कृति में व्यक्ति सचेत और जागरूक रहता है। वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है। वह राजनीतिक व्यवस्था का सक्रिय अंग होता है और व्यवस्था के निवेशों और निर्गुणों दोनों ही प्रकार के कार्यों में वह भाग लेता है, परन्तु यह तीनों प्रकारों की संस्कृति थीं वितुष्ट नहीं होती। एक राजनीतिक संस्कृति में दूसरी राजनीतिक संस्कृति के तत्व मिल जाते हैं। मिश्रित रूप तीन प्रकार के होते हैं—संकुचित प्रजाभावी, प्रजाभावी सहभागि, संकुचित सहभागि। बाइसमैन के अनुसार सर्वांगसमता के तीन मानक निम्न, उदासीनता तथा अलगगव हैं।

4. राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका की दृष्टि से—आरम्भ के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुई होती है अतः राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन राजनीतिक व्यवस्थाओं की भूमिका के सन्दर्भ में ही किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्नांकित चार भागों में संस्कृतियों का बँटवारा किया है—

(अ) ऑग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था—आरम्भ ने इस संस्कृति को अच्छा बताया है, क्योंकि इसमें राजनीतिक साध्य एवं साधनों का बँटवारा पाया जाता है और इसमें परम्परागत, आधुनिक तथा धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण का तत्त्वमेल पाया जाता है। आरम्भ के अनुसार यह संस्कृति बहुमूल्यमुक्त, मुक्त, विवेकसम्पन्न एवं प्रदोगात्मक है।

(ब) महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था—इसने आरम्भ के अनुसार ऑग्ल-अमेरिकी संस्कृति की अपेक्षा कम गुण पाये जाते हैं, क्योंकि कहीं कुछ तत्व परम्परागत हैं, कहीं विवेकी हैं और कहीं राजनीतिक संस्कृति का धुवीकरण पाया जाता है। इस संस्कृति में असन्तुलित विकास के कारण अनेक उप-संस्कृतियाँ पनप गई हैं जिसमें उग्रता पायी जाती है। आरम्भ के अनुसार इस संस्कृति में राजनीतिक नेताओं की श्रद्धा समद और चुनौतियों में कम रहती है और वे जनता के सामने अपने प्रति सम्मान जाग्रत करने, अपने कार्यक्रमों में जनता की अगुआई बनाए रखने, उपदेश और चेदवनी देने के लिए आते हैं।

(स) अन्तरिमो राजनीतिक व्यवस्था—यहाँ नगरो में आधुनिक संस्कृति पायी जाती है और ग्रामीणों में आधुनिक संस्कृति लाने का प्रयास किया जाता है अतः यहाँ मिश्रित राजनीतिक संस्कृति की व्यवस्था पायी जाती है और सप्त वादुता मूल्यों तथा नियमों पर आधारित होता है।

(द) सार्वभौमिकवादी राजनीतिक व्यवस्था—सार्वभौमिकवादी राज्यों में ऐच्छिक संधि नहीं बनाये जा सका है। राज्य राष्ट्रों पर सार्वभौमिक अधिकारों का नियंत्रण रहता है और शासन की सम्पूर्ण शक्ति ऐसे अधिकारी तंत्र में रहती है जिसे एक ही नियम बना राजनीतिक दल निर्वाचित करता है परिणामस्वरूप उनकी राजनीतिक संस्कृति देखने में सामान्यसमयारी दिखती है किन्तु उनका सामंजस्य बनायी है।

राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएँ (Characteristics of Political Culture)

उन्नीस परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं का उत्प्रेषण निम्नलिखित प्रकार ॥ किया जा सकता है।—

1 राजनीतिक संस्कृति शिष्टाचार, अधिभूतियों, विचारों, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा उनकी अभिव्यक्तियों की स्थिति निर्धारकों का सेट होती है। इसका सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था के मानकों तथा सदस्यों के साथ होता है। ये किसी समाज ॥ ऐतिहासिक अनुभव होते हैं जिन्हें समाजोद्धार की प्रक्रियाओं द्वारा जीवन बनाए रखा जाता है।

2. सुविचारण यह है कि राजनीतिक संस्कृति अधिभूतियों, विचारों तथा मनोभावों का समुच्चय है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं का अर्थवत्ता और मुख्यतया प्रमाण करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अन्तर्निहित पूर्वधारणाओं एवं नियमों का बगना है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक आदर्श तथा सक्रियशील मानक दोनों ही शामिल होते हैं।

3. रोये के अनुसार राजनीतिक संस्कृति, अच्छे-बुरे की धारणा का आधार है तथा विचारों और मनोभावों का एक रूप है।

4. यह व्यक्तिगत मूल्यों, विचारों तथा सार्वजनिक अभिवृत्तियों का प्रतिपन है।

5. इसके द्वारा शक्ति और सत्ता के स्वरूप प्रयोग, प्रकार, औचित्यपूर्णता, केन्द्रोपकरण आदि निर्धारित किए जाते हैं।

6. हाज युनाउ की धारणा उन रूपों की ओर इंगित करती है जिनका पूर्वानुमान समूहों के राजनीतिक व्यवहार से तथा एक समूह के सदस्यों के विचारों, नियमक सिद्धान्तों, उद्देश्यों एवं मूल्यों से लगाया जाता है चाहे उस समूह का आकार कैसा भी हो।

7. राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। सामान्य संस्कृति में मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, आधार, कानून, प्रथाएँ तथा दूसरी छगताएँ शामिल होता है जिसका प्रवेश सचेतन या अवचेतन मन, मानसिक, धितन, धारणाओं और व्यवहार में होता है। सामान्य संस्कृति को रसायन बनने, प्रसारित करने और अस्तित्व को बचाने के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक सरचनाओं का सहारा लेना पड़ता है।

8. राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अपेक्षा अधिक गत्यात्मक एवं प्रगतिशील मानी जाता है क्योंकि सामाजिक तार पर हमारी संस्कृति अभी भी छुआ-छूत के रोग से ग्रसित है।

9. सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति में क्षेत्रीय एवं उद्यम स्तरों पर क्षेत्रीय शासक एवं शासितों में अन्तर है।

10. राजनीतिक संस्कृति के विरलेक्षण में विभिन्न वर्गों दबाव, समूहों सभों साम्प्रदायिक दलों आदि से सम्बन्धित अराजनीतिक संस्कृति की अवहेलना नहीं की जा सकती।

11. प्रत्येक पीढ़ी सामाजिकरण के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को प्राप्त कर उसमें सरोधन एवं परिवर्तन करती है। इस प्रकार परम्परा और आधुनिकता का सघर्ष चलता रहता है। यह दृष्टि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों को अधिक प्रगतिशील करता है।

12. राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्कृति से व्याप्त और प्रभावित रहती है। वह उससे मार्ग निर्देशित (Guided) प्रतिबन्धित (Restricted) एवं गत्यात्मक (Dynamic) तथा स्थैतिक (Static) बनती है।

13. राजनीतिक संस्कृति सार्वजनिक घटनाओं एवं व्यक्तिगत कार्यों का आधार होती है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। सतर्क राजनीतिक विरलेषण को राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक नेतृत्वों पर प्रभाव की मात्रा, दिशा आदि का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ विधि का शासन (Rule of Law) प्रजातन्त्र का स्वरूप, औचित्यता विचारवाद, राष्ट्रवाद आदि की प्रकृति राजनीतिक संस्कृति के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है।

14 राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, लक्ष्यों, नागरिक प्ररिष्ठता, जनमत के तथ्यों, राजनीतिक कर्ताओं की सहायित प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है।

15 समाज राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाओं को भिन्न विधियों से कार्य करने में राजनीतिक संस्कृति की सहायता से मदद करता है।

16 राजनीतिक संस्कृति एक अर्थ में समाज से सम्बद्ध समूह के मनोविज्ञान का अभिज्ञान है। वही व्यक्ति और समूह को आवृत करने वाली प्रभावशाली पृष्ठभूमि है।

17 राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पक्षों को सम्पाहित करने वाला तत्व होने के बावजूद उसके समस्त क्रिया-कलापों को उसी समग्रता में देखा जा सकता है।

राजनीतिक संस्कृति के रूप (Types of Political Culture)

सदृश एवं शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को दो भागों में बाँटा जा सकता है—1. जन-राजनीतिक संस्कृति (Mass Political Culture) एवं 2. सभ्यजन राजनीतिक संस्कृति (Elite Political Culture)।

जहाँ राजनीतिक संस्कृति सामान्य जनता की राजनीतिक संस्कृति है जबकि सभ्यजन राजनीतिक संस्कृति सभ्यजनों की राजनीतिक संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति का यह भेद सामान्य जनता से सभ्यजन जनता में भर्ती कैसे होती है? इस जानकारी से स्पष्ट होता है। आम्बुड एच बर्ल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति की निम्नांकित श्रेणियाँ होती हैं¹—1. अमिश्रित या विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति (Pure Political Culture) एवं 2. मिश्रित राजनीतिक संस्कृति (Mixed Political Culture)।

1. अमिश्रित या विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति—इस संस्कृति के तीन उपवर्ग हैं—

(अ) संकुचित राजनीतिक संस्कृति (Parochial Political Culture)—संकुचित राजनीतिक संस्कृति परम्परागत (Traditional) समाज में पाई जाती है। इसमें व्यक्तियों के प्रति सहजतात्मक अभिमुखन (Cognitive Orientation) का अभाव होता है। व्यक्ति संकुचित होता है क्योंकि वह अपने को परिवार में और अपने समुदाय में उलझा हुआ पाता है। राजनीतिक व्यवस्था की केन्द्रीय समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत का परम्परागत ग्रामीण समाज।

(ब) प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति (Subjective Political Culture)—इसमें व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवस्था और निर्गत प्रक्रियाओं के प्रति अभिमुखन उच्च स्तर का होता है लेकिन निवेश नितान्त निम्न स्तर का होता है। यह प्रक्रियाओं और स्वयं के प्रति राजनीतिक अभिनेता के रूप में उनका भावात्मक या अनुसारात्मक और मूल्यात्मक अभिमुखन (Evaluative Orientation) है। यहाँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता या अभिनेता के रूप में व्यक्तियों की स्थिति आवश्यक रूप से निर्दिष्टता की होती है।

(स) सहभागी राजनीतिक संस्कृति (Participant Political Culture)—इसमें व्यक्ति स्वयं को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय और सहभागिता की भूमिका में पाता है। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था का प्रति व्यक्ति के सहजतात्मक, अनुसारात्मक और मूल्यात्मक अभिमुखन अत्यन्त उच्च स्तर के होते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वह अपनी सक्रियतात्मक भूमिका के प्रति सजग होता है। सहभागी राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों का अभिमुखन निवेश और निर्गत दोनों के प्रति होता है।

2. मिश्रित राजनीतिक संस्कृति—इसे आम्बुड एच बर्ल ने चार उपभागों में विभाजित किया है—

(अ) संकुचित प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति (Parochial Subjective Political Culture)—इसमें व्यक्ति को सरकार की विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी होती है लेकिन उसे इसका बोध नहीं होता है कि वह किन रूपों में राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। उसकी अपनी महती राजनीतिक भूमिका होता है अथवा वह स्वयं एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति है यह भावना उसमें अस्पष्ट और अव्यक्तित्व होती है।

(ब) प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृति (Subjective Participant Political Culture)—इसमें कुछ नागरिक उच्च स्तर का राजनीतिक अवबोधन रखते हैं तथा वे सक्रिय होते हैं लेकिन शेष सापेक्षिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। औसत नागरिक यह जानता है कि उसे सक्रिय होना चाहिए और राजनीतिक व्यवस्था में उसे सहभागी बनना चाहिए लेकिन उसे नीतियों के विनियमन अथवा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त कम मिल पाता है।

(स) सहभागिता-संस्कृति राजनीतिक संस्कृति (Participant Parochial Political Culture) - ये राजनीतिक संस्कृति में निरंतर संस्थाएँ सर्वाधिक रूप से स्थानीय होती हैं, जैसे—जातीय-जन-जातीय संघ, लेकिन राष्ट्रीय निर्मित संस्थाएँ अल्पता विद्यमान होती हैं। इसमें निरंतर निर्मित संस्थाओं, दबाव समूहों, रक्षित हितों एवं हित समूहों के दबाव में रहता है।

(द) नागरिक राजनीतिक संस्कृति (Civil Political Culture) - इन राजनीतिक संस्कृतियों के अलावा आमण्ड और बर्न ने एक अन्य प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की चर्चा की है। इसे जन-संस्कृति कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति के सभी तीन आदर्श प्रतिपादनों की विशेषताओं को यह समाहित करता है। यह एक रूप निदेशात्मक और सहपद, सहयोगी और निष्पक्ष अधिकृतियों के सम्मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रजाप्राप्ति और सहभागिता अभिमुखन प्रशस्त होते हैं। इन राजनीतिक संस्कृति में जहाँ एक तरफ प्रजाप्राप्ति अभिमुखन राजनीतिक अभिधन के पर्याप्त अभिक्रम और स्वतन्त्रता के साथ कार्य करते की अनुमति प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सहभागिता अभिमुखन राजनीतिक अभिधन को इसके लिए विवश करते हैं कि वे लोकप्रिय शीघ्रताओं के अधीन कार्य करें।

राजनीतिक सहभागिता (Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में राजनीतिक सत्ता कुछ लोगों के चूने हुए सम्मानान्तरों के हाथों में रहती है, लेकिन इन सम्मानान्तरों का यही प्रभाव होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में अधिकाधिक लोगों की सहभागिता हो। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जितने अधिक नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता होती है राजनीतिक सत्ता को उतना ही अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। सहभागिता को राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता होती है राजनीतिक सत्ता को उतना ही अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। सहभागिता को राजनीतिक सत्ता को औचित्यता प्रदान करती है। जिस समाज में राजनीतिक सहभागिता को मात्र कम होती है वहाँ व्यवस्था या अराजकता पैदा होने की पर्याप्त सम्भावना रहती है। राजनीतिक सहभागिता का आशय है कि राजनीतिक सत्ता में अधिकारधारी लोगों का सहयोग एवं कार्य हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में इसका महत्व और अधिक होता है, क्योंकि प्रजातन्त्र में जनता सरकार को अपनी सहमति देती है अथवा दी गई सहमति वापिस भी लेती है।

राजनीतिक सहभागिता का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता को परिभाषित किया जा सकता है। हरबर्ट मैक मल्लो की अनुसार, "राजनीतिक सहभागिता को उन स्थितियों क्रियाओं बिनाके द्वारा समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जातीयों के निर्माण में भाग लेते हैं, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।" ¹ इस परिभाषा में वस्तु के सदस्यों की राजनीतिक भागीदारी को भी आवश्यक कहा जा सकता है।

तृतीय विश्व के देशों में संस्कृति तथा राजनीति (Culture and Politics in Third World Countries)

किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आधार उसकी राजनीतिक संस्कृति होती है। राजनीतिक संस्कृति से राजनीतिक व्यवस्था का धारि निर्माण होता है। राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक संस्कृति का एक-दूसरे से गहरा सम्बन्ध है और दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक संस्कृति सम्बन्धानुसार बदलती रहती है। जहाँ राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति की मूल मान्यताएँ एक-दूसरे से भिन्न होती हैं, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था पर राजनीतिक संस्कृति के अनुसार बदलाव हेतु अधिक दबाव बना रहता है। प्रेबियल ए. आम्सले के अनुसार, "हर एक राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक क्रियाओं के अभिव्यक्त के विभिन्न प्रतिपादनों में निहित होती है।" ¹

समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति के विभिन्न मुद्दों और परिस्थितियों का अध्ययन हमें प्रेरित करता है कि राजनीतिक संस्कृति के क्षेत्र पर दृष्टिगत करें, तो अवगत होता है कि देश में लोगों की राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति कुछ आस्थाएँ एवं दृष्टिकोण होते हैं, जिन्हें वे सीखते हैं और भागीदार होते हैं। हमें यह जानना है कि राजनीतिक जीवन के सम्बन्ध में नागरिक क्या सोचते हैं और किस प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं? साथ ही यह किन उद्देश्यों का अनुसरण करने को प्राथमिकता देते हैं? अतः लोगों के जीवन का भावात्मक आयाम हमारे अध्ययन का संगत भाग बन जाता है। ²

1 Herbert Mc Glasby : Political Participation Quoted from David Mills, op cit, Vol 12, p 253-254
2 A. Almond : Comparative Political System in Journal of Politics, Vol 18 (1956), p 391-409

भारत की राजनीतिक संस्कृति

(Political Culture of India)

भारत की राजनीतिक संस्कृति के सम्बन्ध में पश्चिमी विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं जिन पर कांड़ी वाद विवाद रहा है। उनमें माइल चीनर व मोर्स जोंस के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति—चीनर के अनुसार भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति है—
1. विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक संस्कृति एवं 2. जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति।

विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक संस्कृति उन लोगों की है जो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। यह राजनीतिक संस्कृति दिन्तो में पाई जाती है। इस पर विशिष्ट वर्ग का आधिपत्य है। इस विशिष्ट वर्ग में समद सदस्य, योजना आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय स्तर के नेता तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी शामिल हैं। इस विशिष्ट वर्ग में वे लोग हैं जिनका शिक्षा प्राप्त है तथा जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय है, जो पश्चिमी विचारों से प्रभावित एवं धर्मनिरपेक्ष विचारक हैं। यह वर्ग आधुनिक विचारों का है। इसका राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक अभिवृत्तियाँ एवं राजनीतिक धारणाएँ, शासन के प्रति उनकी दृष्टिकोण आदि सामान्य जनो से भिन्न है, इसलिए इस विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक संस्कृति सामान्य वर्ग की राजनीतिक संस्कृति से भिन्न है। इस राजनीतिक संस्कृति का उदय स्वाधीनता से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। स्वतन्त्रता के बाद भारत में एक अन्य संस्कृति का विकास हुआ है जो ग्रामीण स्तर से जिला एवं राज्य स्तर तक पाई जाती है। चीनर ने इसे जन राजनीतिक संस्कृति कहा है। इसके अनुसार स्वतन्त्रता के बाद जन साधारण को सक्रिय राजनीति में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। वयस्क मतधिकार के द्वारा राजनीतिक समस्याओं में जन-सहभागिता हुई जिससे इन व्यक्तियों के राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक धारणाएँ, राज्य तथा सरकार के प्रति दृष्टिकोण विशिष्ट वर्ग से भिन्न हैं। चीनर ने इस राजनीतिक संस्कृति के उदय के तीन प्रमुख कारण बताये हैं—1. सरकार के कार्यों का अधिक विस्तार, 2. सत्ता का विकेंद्रीकरण, 3. सत्ता का जनतंत्रीकरण।

राजनीतिक संस्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें ग्रामीणता, जातीयता तथा साम्प्रदायिकता की भावना अधिक पाई जाती है। चीनर के अनुसार विधान सभा तक की राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनमें जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा ग्रामीण एवं शहरी इलाकों की प्राथमिकता देने की तीव्र भावना होती है। स्वतन्त्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग की गयी तथा 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद श्रेणीयता की भावना प्रबल हुई तथा नये राज्यों के निर्माण की माँग उठी, फलतः नये राज्यों का निर्माण हुआ। परिवहन तथा संचार के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में रहने वाली जातियों को एक-दूसरे से सम्पर्क हुआ जिसमें जातीय भेदभाव बढ़ा तथा राजनीतिक दलों ने जाति का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति को आधार बनाया और विभिन्न निर्वाचनों में ठम्मीदवारी के चयन से लेकर मतदाताओं के समर्थन को प्राप्त करने हेतु धर्म तथा जाति को एक साधन के रूप में अधिकाधिक प्रयोग किया है, अतः जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति में स्वीकृति एवं स्थानीयता की प्रधानता है।

□□□

राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त (Theories of Political Economy)

अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त : प्राचीन तथा समकालीन (Theories of Economy : Classical and Contemporary)

प्राचीन विचारधारा

प्राचीन अर्थशास्त्रियों में बणिज्यवादियों का विचार था कि किसी देश में सोना चाँदी के कोष में वृद्धि होना ही उस देश के आर्थिक विकास का मापदण्ड है। इसी आधार पर उन्होंने आर्थिक विकास के लिए निर्यात पर पर्याप्त बल दिया। एडम स्मिथ के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने से देश का आर्थिक विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए ताकि लोग अधिकाधिक उत्पादन कर लाभ प्राप्त कर सकें और जिसके परिणामस्वरूप लोक कल्याण में वृद्धि हो। एडम स्मिथ के समकालीन अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि यदि देश में उत्पादन की मात्रा तीव्र होगी तो आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी, अन्यथा आर्थिक विकास का साम्यवाद द्वारा देश में नै सहकारिता के सिद्धान्त का समर्पण किया। उन्होंने कहा है कि पूँजीवादी को सम्पत्त कर साम्यवाद द्वारा देश में लोक कल्याण व आर्थिक विकास लाया जा सकता है। जे. एस. मिल ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति के कुपरिणामों को दिखाकर यह विचार प्रकट किया कि सहकारिता के सिद्धान्त को महत्व देना चाहिए। सहकारिता ही आर्थिक विकास का माप है।

आधुनिक विचारधारा

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के साधन-साध विवरण को भी आर्थिक विकास का मापक माना है। उन्होंने आर्थिक विकास के माप के लिए किसी एक तत्व पर नहीं, बल्कि अन्य कई तत्वों पर बल दिया है और कहा है कि इन तत्वों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्र का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है। उन्होंने इन तत्वों को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है—(1) राष्ट्रीय आय (2) गरीब जनता को अधिक स्थाप (3) सामान्य एवं वास्तविक विकास दर (4) प्रति व्यक्ति आय एवं (5) सकल राष्ट्रीय उत्पादन।

अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त

आर्थिक विकास और किसी देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। उनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं—

(1) एडम स्मिथ के सिद्धान्त

एडम स्मिथ सम्भवतया पहला विद्वान था जिसने अपनी पुस्तक 'राष्ट्रों का धन' में करारोपण के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से विचार किया। उसने करारोपण की किसी भी अच्छी कर पद्धति के लिए पार सिद्धान्त प्रतिपादित किए—(1) समानता या समता का सिद्धान्त, (2) निश्चिन्ता का सिद्धान्त, (3) सुविधा का सिद्धान्त एवं (4) प्रत्यक्षता का सिद्धान्त। बाद के लेखकों ने करारोपण के अन्य सिद्धान्त भी प्रस्तुत किये जो इस प्रकार हैं—(1) उत्पादकता का सिद्धान्त, (2) लोच का सिद्धान्त (3) सरलता का सिद्धान्त, (4) विविधता का सिद्धान्त, (5) समन्वय का सिद्धान्त, (6) वांछनीयता का सिद्धान्त एवं (7) एककपणा का सिद्धान्त।

(2) हैकशर ओहलिन का सिद्धान्त

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना, किन्तु इन अर्थशास्त्रियों ने मात्र श्रम को ही उत्पादन का साधन माना था। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के अन्य साधनों को भी लागत विश्लेषण में सम्मिलित किया है। इनमें प्रमुख स्थान हैकशर को दिया जाता है। हैकशर के विचारों की विस्तृत व्याख्या ओहलिन ने की और इस सिद्धान्त को 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का हैकशर ओहलिन सिद्धान्त' कहा है। हैकशर ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यक शर्तों को इस प्रकार वर्णित किया है—(1) भिन्न-भिन्न सपेक्ष दुर्लभता अर्थात् विनिमय की स्थितियों में उत्पादन के साधनों की सपेक्ष कीमतों में भिन्नता, (2) विभिन्न वस्तुओं में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों के बीच अनुपातों में भिन्नता एवं (3) सामान्यतया उगमन-निर्गत गुणक के रूप में अपरिवर्तनीय रहते हैं।

हैकशर का मत है कि विदेशी व्यापार उत्पादन के उन्नत साधनों को बढ़ती हुई दुर्लभता को उत्पन्न करता है जो अन्यथा आयातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किये जा सकते हैं। ओहलिन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त मूल्य के सामान्य साम्य सम्बन्धी सिद्धान्त पर आधारित है और इसी का एक विस्तार मात्र है। मूल्य का सामान्य साम्य सिद्धान्त अर्थशास्त्र में अपना विशेष महत्त्व रखता है। उसके अनुसार यह माना जाता है कि किसी वस्तु की कीमत उसकी माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। एक वस्तु की माँग पर अनेक तथ्यों का प्रभाव पड़ता है जैसे—उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ, प्राथमिकताएँ, इच्छाएँ, उनकी आय, अन्य वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी कीमत आदि। वस्तु की पूर्ति उसके उत्पादन के साधनों की उपलब्धि पर निर्भर होती है। जहाँ वस्तु की माँग और उसकी पूर्ति के बीच साम्य स्थापित हो जाता है वहाँ उसकी कीमत निर्धारित हो जाती है। वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत के बराबर होती है। लाभ की सीमानता भी लागत में शामिल होती है। किसी वस्तु की उत्पादन लागत उन सभी साधनों की कीमत का योग होती है जो वस्तु के उत्पादन में सहयोगी बनते हैं। हैकशर ओहलिन की प्रमुख मान्यता है कि समाधनों की भिन्नता के कारण ही विभिन्न देशों में उत्पादन लागतों एवं वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर होता है तथा यही अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देता है।

(3) हैरड-डोमर का सिद्धान्त

हैरड-डोमर के आर्थिक विकास सिद्धान्त की परिकल्पना यह है कि प्रारम्भ में आय का सन्तुलित स्तर यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर है तो प्रति वर्ष सन्तुलन के इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त क्रय शक्ति की मात्रा उतनी होनी चाहिए जो विनियोग द्वारा बढ़ाए गए उत्पादन को खपाने के लिए पर्याप्त हो।

(4) महालनोबिस सिद्धान्त

महालनोबिस मॉडल विकास नियोजन का चार क्षेत्रीय अर्थमिति मॉडल है। इस मॉडल में भारत में 5,600 करोड़ रुपये की धनराशि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में 5 प्रतिशत विकास दर एवं 11 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध करने की परिकल्पना की गई। अनुमानित घन राशि को अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्रों में इस प्रकार वितरित करने का प्रयास किया गया जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र अन्य राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि का क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 11 मिलियन अतिरिक्त व्यक्ति हो सके, इसीलिए इस मॉडल को आर्थिक विकास के मॉडल के स्थान पर वितरण मॉडल की संज्ञा दी गई।

(5) कोन्स का सिद्धान्त

कोन्स ने अपनी पुस्तक 'रोजगार ब्याज तथा मुद्रा की सामान्य सिद्धान्त' में प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की कटु आलोचना करते हुए एक नया रोजगार तथा आय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार बेरोजगारी प्रभावपूर्ण माँग को कभी अन्वेषण उपयोग एवं निवेश पर किए गए व्यय की कमी के कारण होती है।

(6) अमर्त्य सेन का सिद्धान्त

अमर्त्य सेन के कल्याणकारी सिद्धान्त के सम्बन्ध में रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस ने कहा है कि "कल्याणकारी अर्थशास्त्र" में भी सेन के योगदान और उनके सैद्धांतिक दृष्टिकोण के प्रयोग ने अकाल के लिए जिम्मेदार आर्थिक प्रक्रियाओं को समाप्त करने में वृद्धि की है। उन्होंने अर्थशास्त्र और दर्शन के उपकरणों के संयोजन से महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं पर आलोचना को एक नैतिक आयाम दिया है।" अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के कल्याणकारी सिद्धान्त में इन तथ्यों को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया है—(1) निर्धनता और अकाल, (2) सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण, (3) सेन मुजर्दा, (4) विधनता पर पुनर्विचार एवं (5) आर्थिक विकास और सामाजिक अवसर।

(7) गांधीवादी सिद्धान्त

महात्मा गांधी कोई प्रगतिशत अर्थशास्त्री नहीं थे¹ इसलिए उन्होंने विकास का कोई माडल तैयार नहीं किया, परन्तु उन्होंने भारत के विकास के लिए कृषि, कुटीर उद्योग, पशुपालन आदि के लिए कुछ नीतियों का समर्पण अवश्य किया। अण्णय्य श्रोमनरायण ने 1944 में गांधीवादी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की और बाद में 1948 में उसको पुष्टि की। ये प्रकाशन गांधीवादी आयोजन या विकास के ढाँचे का आधार हैं। गांधीवादी योजना का मूल उद्देश्य भारतीय जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक स्तर को उन्नत करना है ताकि 10 वर्षों के अन्दर न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त किया जा सके। गांधीवादी योजना भारत के गाँवों की आर्थिक दशा उन्नत करना चाहती है। इसलिए कृषि के वैज्ञानिक विकास और कुटीर उद्योगों के विस्तार पर बल देती है।

(8) नेहरूवादी सिद्धान्त

1977 से पूर्व तक भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का आधार नेहरू की विनियोग रणनीति थी जिसे विकास का नेहरू मॉडल कहा जाता है। नेहरू मॉडल में भारी उद्योग को अर्थव्यवस्था का आधार माना गया और नेहरू चाहते थे कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत की जाए ताकि विदेशी सहायता पर निर्भरता कम की जा सके। एक मजबूत बुनियाद प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्व रखती है क्योंकि इसके बिना आर्थिक विकास का प्रश्न ही नहीं उठता। नेहरू की विकास रणनीति के फलस्वरूप भारत विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों में दसवाँ स्थान प्राप्त कर सका। हमारी पहली पाँच पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुई प्रगति के सम्बन्ध में छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में लिखा था कि, "यह वस्तुतः बड़े गर्व की बात है कि इस काल के दौरान एक अवकट एवं पराश्रित अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया और इसे अधिक आत्मनिर्भर बनाया गया।"²

(9) राव मनमोहन सिद्धान्त

विकास का राव-मनमोहन मॉडल 1991 में भारत में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विकास के लिए एक नई रणनीति अपनाना था जिसमें निजीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया जाए। देश के स्तर पर दो परिवर्तन किए गए। प्रथम, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गये। दूसरे बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी क्षेत्र को औद्योगिक इकाईयें लगाने की इजाजत दी गई। इनके अलावा धी आर्थिक नीति में कई परिवर्तन किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंहाय्य और पूर्व वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा चालू किए गए विकास के राव-मनमोहन माडल में निजी क्षेत्र को बड़ा कार्य भाग अदा करने पर बल दिया गया।

राजनीतिक विचारधाराएँ (Political Ideologies)

प्रत्येक विचारक ने अपने-अपने दृष्टिकोण से राजनीतिक विचारधारा पर अध्ययन किया है। उदाहरणों ने अपने दृष्टिकोण से तथा अन्य विचारधाराओं यथा—समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद, गंधीवाद व अंग्रेजवाद के विचारकों ने अपनी विचारधारा को अपने दृष्टिकोण से व्यक्त किया है प्रत्येक विचारधारा की प्रकृति अलग है। यहाँ इसी दृष्टि से विचारधाराओं का विवेचन किया जा रहा है। इससे पूर्व विचारधारा की प्रकृति सम्बन्धी जानकारी दी जा रही है।

विचारधारा की प्रकृति (Nature of Ideology)

ऐडो, एम्बरसन एवं क्रिस्टोल के अनुसार, "एक राजनीतिक विचारधारा राज्य की प्रकृति की विविधताओं को बनाने वाले विचारों की एक व्यवस्था होती है और यह उस राज्य के अन्तर्गत रहस्य एवं नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन करती है। ऐसी विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का एक समुच्चय होती है।" एलेन बाल के अनुसार, "राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक विचारों की स्पष्ट, सम्यक् और व्यवस्थित प्रणाली होता है।" राजनीतिक समस्याओं से सम्बन्धित विस्तृत विचार जब व्यवस्थित रूप धारण कर सते हैं तो उसे राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति को निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) राजनीतिक विचारधारा सामाजिक व्यवस्था के साथ अन्य क्रिया का प्रतिफल होती है। (2) आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रारम्भ प्रगतिशील क्रान्ति से माना जाता है जिसमें सर्व प्रथम स्वतन्त्रता, समानता और प्रभुत्व का नाश दिया गया था। (3) राजनीतिक विचारधाराओं में परस्पर अन्तर पाया जाता है। (4) राजनीतिक विचारधाराओं में सिद्धान्त तथा उनकी क्रियान्विष्टि के लिए कार्य पद्धति निर्धारित होती है। (5) राजनीतिक विचारधाराओं में नैतिकता को स्वीकार किया जाता है। (6) राजनीतिक विचारधारा सत्य को पूर्ण तरह अविच्युत नहीं करती है। (7) राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म, विकास तथा उत्कर्ष सामाजिक परिवर्तन में होता है। (8) राजनीतिक विचारधाराओं का कोई निरिक्त क्षेत्र नहीं होता है। (9) राजनीतिक विचारधारा सामन्तव्यता पर्यावरण, विप्लव और अनुराग कायम करने का कार्य करती है। (10) राजनीतिक विचारधाराओं में संगठन, रक्त और सुदृढ़ता स्थापित करने की अनन्त क्षमता होती है। (11) कुछ राजनीतिक विचारधारा बुद्धिमान होती है तथा वे विवेकपूर्ण सामाजिक मूल्यों का विरोध करती है। (12) कुछ विचारधारा राजनीतिक समस्याओं को वैधता प्रदान करने में भी सहायक होती है। (13) इस ज मंगेन्या ने राजनीतिक विचारधारा को अन्तर्राष्ट्रीय या राजनीति में विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्यों को छिपाने का आग्रह माना है। राष्ट्रीय शक्ति और राजनीतिक विचारधारा में गहरा सम्बन्ध होता है। यह राष्ट्र की शक्ति के निम्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे राष्ट्रीय शक्ति का आधारभूत तत्व कहा जाता है।

उदाहरण

(Liberalism)

अन्य विचारधाराओं की भाँति उदाहरण विचारधारा निरिक्त और अन्तर्गत विचारधारा नहीं है। यह न तो किसी एक व्यक्ति के विचारों का परिणाम है और न ही किसी एक युग के साथ जुड़ी हुई विचारधारा है। यह एक दार्शनिक नहीं है, अनेक विचारों का समिश्रण है। यह एक जीवन दृष्टि, जीवन क्रम तथा मूल्यों की एक सुलझी हुई प्रणालि है जिसके अन्तर्गत अनेक सम्बन्ध, अदार्श एवं सामर्थ्य विद्यमान हैं। उदाहरण का उदाहरण स्वतन्त्रता, समानता और वहाँ उदाहरण का उदाहरण स्वतन्त्रता के विरोध स्वतन्त्रता एक प्रकृति के रूप में हुआ था, हालाँकि अनेक व्यक्ति उदाहरण को अन्तर्गत का विरोध तथा प्रगति एवं परिवर्तन का पर्यायवाची मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जब

ब्रिटेन में लम्बे समय से चली आ रही सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं, परम्पराओं एवं रुढ़ियों को बनाये रखना चाहते थे, उस समय उदारवाद के द्वारा सुधार, परिवर्तन और प्रगति का समर्थन किया गया, लेकिन उदारवाद को प्रगति और परिवर्तन का पर्यायवाची नहीं माना गया है। इसके विपरीत उदारवाद परिवर्तन के लिये क्रान्ति के मार्ग को अपनाने में विपरीत है। लोकतन्त्र को उदारवाद का नाम दे दिया जाता है, जो सीमित अर्थ में सही है। आधुनिक लोकतन्त्र बहुसंख्यक वर्ग की सत्ता में विश्वास करता है, लेकिन उदारवाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के प्रति जागरूक है। उदारवाद लोकतन्त्र से कुछ अधिक हो जाता है। उदारवाद परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है और व्यक्तिवाद तथा लोकतन्त्र भी इसमें शामिल है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर अब तक दो प्रकार की विचारधाराएँ रही हैं। एक विचारधारा राज्य को समस्त मानवीय जीवन का केन्द्र और अपने आप में एक साध्य मानती है, लेकिन दूसरी विचारधारा इसका प्रतिपादन करती है कि व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति ही साध्य है राज्य नहीं, इसलिए उदारवाद द्वितीय प्रकार की विचारधारा का पुंज है जो इस तथ्य पर बल देता है कि समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं का केन्द्र व्यक्ति है, राज्य समाज और अन्य संस्थाएँ इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र हैं।

उदारवाद का उदय (Rise of Liberalism)—राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में उदारवाद के उदय के कारण निम्नांकित हैं—

1. **नवजागरण (Renaissance)**—प्राचीन युग में यूनानी जीवन के अन्तर्गत व्यक्ति के जीवन को आधारभूत रूप में महत्व प्राप्त था। उसके चिन्तन का रूप लौकिक था। प्राचीन यूनानियों ने दर्शन, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति कर ली थी, लेकिन मध्य युग में पारसीक दृष्टिकोण को अपना लिया गया और चिन्तन का एकमात्र केन्द्र ईश्वर हो जाने के कारण जीवन के अन्य क्षेत्रों में कोई प्रगति सम्भव नहीं हो सकी। मध्य युग में व्यक्ति को धुन्ना दिया गया, लेकिन आधुनिक युग के प्रारम्भ में लोगों की दृष्टि पुनः यूनानी चिन्तन पर गई और नवजागरण के नाम से एक बौद्धिक चिन्तन का आन्दोलन प्रचल हो गया, परिणामस्वरूप लोगों के विचारों, आदर्शों और चिन्तन पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आने लगा। नवजागरण ने व्यक्तियों के दृष्टिकोण को एक ओर लौकिक बनाया, दूसरी ओर व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को सर्वोच्च महत्व दिया जाने लगा। नवजागरण ने व्यक्ति स्वातन्त्र्य पर बल देकर उदारवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

2. **धर्म सुधार (Reformation)**—मध्य युग धार्मिक निरकुशता के लिए प्रसिद्ध रहा है। धार्मिक क्षेत्र में पोप की निरकुशता का बोलबाला था और पोप शक्तों का जो अर्थ बतलाते थे, वही प्राथमिक माना जाता था। 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार को प्रवृत्ति आरम्भ हुई और मार्टिन लूथर, ज़िगली तथा काल्विन जैसे धर्म सुधारकों के द्वारा धार्मिक निरकुशता का विरोध आरम्भ हो गया। धर्म सुधार ने परम्पराओं के बन्धन तोड़कर आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मार्टिन लूथर ने बताया था कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है और धार्मिक क्षेत्र में शक्ति प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार धर्म सुधार ने उदारवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

3. **औद्योगिक क्रान्ति और पूंजीपति वर्ग का उदय**—मध्य युग में आर्थिक जीवन स्वतन्त्र नहीं था। कृषक सामन्तों के अधीन हुआ करते थे और दस्तकारी तथा व्यापार पर अनेकानेक नियन्त्रण थे। दस्तकारी पर उनकी श्रेणियों का नियन्त्रण हुआ करता था, जो 'गिल्ड' कहलाती थीं। धर्म आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप किया करता था। अनेक धार्मिक तथा नैतिक नियम प्रचलित थे। 18वीं सदी के अन्त में औद्योगिक क्रान्ति होने से घरतुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा जिससे तेजी से समृद्धि आयी और आर्थिक जीवन के नियन्त्रण समाप्त होने लगे। समाज में जो नवीन समृद्धिशाली वर्ग उत्पन्न हो रहा था उसका उद्देश्य अधिकधिक सम्पत्ति अर्जित करना था। यह वर्ग उन समस्त नियमों और प्रतिबन्धों का विरोध करने लगा जो अधिकाधिक सम्पत्ति के अर्जन में बाधक बने हुए थे। यह नवीन समृद्धिशाली वर्ग सामाजिक जीवन में धीरे-धीरे अधिक प्रभावशाली होता चला गया और उसने अपने बड़े हुए प्रभाव से स्वीकार करवा लिया कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और गतिविधियों पर राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक कोई प्रतिबन्ध नहीं रहने चाहिए। आर्थिक स्वतन्त्रता की भावना ने उदारवाद को जन्म दिया।

4. **निरकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया**—उदारवाद के जन्म के लिए प्रमुख उत्तरदायी तत्व निरकुशतावादी शासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी यूरोपीय इतिहास में निरकुश राजतन्त्र सर्वत्र प्रसिद्ध था। इनमें से अनेक राज्यों के शासकों ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर स्वयं को ईश्वर का अवतार मान लिया था। इनमें से कुछ सरकारें इतनी अधिक निरकुश एवं अमर्यादित हो गयी थीं कि "उनके अर्थाधीन कानून निश्चित दिनों के लिए विशिष्ट प्रकार के शोचन निर्धारित करते थे तथा मूर्तों को दफनाने के लिए विशेष प्रकार के धसों की व्यवस्था

की आज्ञा देते थे।" इस प्रकार निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक थी। ऐसे समय में जॉन लॉक, मिल, स्पेन्सर तथा ग्रीन जैसे विद्वानों के द्वारा व्यक्ति स्वातन्त्र्य की उद्घोषणा ने उदारवाद का शखनाद फूंक दिया।

उदारवाद के मूल सिद्धान्त (Main Principles of Liberalism)

1. इतिहास तथा धर्मशास्त्रों का विरोध—उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार, सत्ता या सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है जो बुद्धिसंगत न हो, फिर चाहे वह किना ही प्राचीन क्यों न हो तथा उसे किना ही पवित्र क्यों न समझा जाता रहा हो। इम्पैण्ड के उपयोगितावादी उदारवादियों ने उपयोगिता के नाम पर पहले से चली आ रही व्यवस्था का खण्डन किया है। उनके प्रभाव के कारण 19वीं सदी में इम्पैण्ड के जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उदारवादी सदैव ही विद्यमान व्यवस्था के विरोधी नहीं रहे हैं और आज वे बहुत सीमा तक विद्यमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाये रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं।

2. मानवीय स्वतन्त्रता की धारणा में विश्वास—उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म में स्वतन्त्र 태प्न होता है और स्वतन्त्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये और ऐसा बाधावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादियों ने सदैव मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है और वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में स्वतन्त्रता का समर्थन करते रहे हैं। हेण्टन लास्की के अनुसार, "स्वतन्त्रता के साथ इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, क्योंकि इसका जन्म ही समाज के किसी वर्ग द्वारा अथवा धर्म के आधार पर प्राप्त विशेषाधिकारों के विरोध में हुआ है।"

3. मानवीय विवेक में आस्था—उदारवादी विचारधारा का प्रमुख तत्व मानवीय विवेक में आस्था है। ईसाइयत ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बन्धनों में जकड़ रखा था और ऐसा माना जाता था कि चर्च के अधिकारी, विशेषकर पोप शस्त्रों का जो अर्थ बतलाते थे, वही प्रामाणिक थे, लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में नवत्राण के साथ ही प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने शास्त्रों का अन्धानुसरण करने के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर चिन्तन मनन शायम कर दिया। जॉन लॉक और टॉमस पेन ने समस्त रुढ़िवादियों की चुनौती देते हुए कहा था कि "हमारा अपना मन ही अपना चर्च है।" इस प्रकार उदारवाद का विश्वास है कि भावना पर विवेक की प्रपन्नता दो जानी चाहिए।

4. व्यक्ति साम्य तथा समाज और राज्य साधन—उदारवाद का मूल आधार व्यक्ति है। यह व्यक्ति को साम्य मानकर आगे बढ़ता है। इसके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक कल्याण तथा उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास सबसे अधिक महत्व रखता है। समाज और राज्य तो साधन मात्र हैं और उनका महत्व उसी सीमा तक है, जहाँ तक वे इस सत्य की पूर्ति में सहायक होते हैं।

5. व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास—उदारवादियों का विश्वास रहा है कि व्यक्ति के कुछ जन्मजात अधिकार हैं, जिन्हें प्राकृतिक अधिकार भी कहा जा सकता है। उनका कथन है कि इन अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय सत्ता, समाज या राज्य के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि वे तो इन सत्ताओं के अस्तित्व के पूर्व से विद्यमान रहे हैं और समाज तथा राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिये ही हुई है। इस सम्बन्ध में लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त विशेष रूप से प्रसिद्ध है जिसके अनुसार व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार, जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता के अधिकार हैं।

6. धर्म-निरपेक्ष राज्य का आदर्श—उदारवाद का धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास है। इसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न देशों में किसी एक विशेष धर्म की प्रपन्नता प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में उदारवादियों ने प्रारम्भ से धार्मिक सहिष्णुता और स्वतन्त्रता की अन्वाह बुलन्द की। जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता का कट्टर समर्थक था। 18वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिकों ने चर्च और राज्य को पुष्ट करने के लिए अन्टोलन किया था, परिणामस्वरूप धर्मशास्त्रों के बंद ध्रुम और समुक्त राज्य अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात् यूरोप के सभी देशों में धर्मनिरपेक्षता की लहर तेजी से चल पड़ी। धर्मनिरपेक्षता उदारवाद की एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है।

7. समाज और राज्य कृत्रिम सगठन—उदारवाद समाज और राज्य को प्राकृतिक नहीं, बल्कि कृत्रिम मानते हैं और उनका विचार है कि इसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया गया है। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। समाज और राज्य का सगठन उनके द्वारा अपनी निश्चित योजना के अनुसार किया गया। व्यक्तियों की यह अधिकार है कि वे समाज और राज्य के सगठन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकें।

8. शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन—उदारवाद अपने स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता आया है। यह इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति को नहीं बल्कि कानून की प्रधानता होनी चाहिए। शासक वर्ग भी इन कानूनों को मानने के लिए उतनी सीमा तक बाध्य होना चाहिए जितनी सीमा तक शासित वर्ग। यदि शासक वर्ग मनमानी करता है और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता तो ऐसी स्थिति में जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन उदारवाद की धारणा है कि किसी परिवर्तन हेतु शान्तिपूर्ण और वैधानिक उपाय ही अपनाये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में 1688 की इंग्लैण्ड की मौल्यपूर्ण क्रांति उनका आदर्श है।

9. अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व-शान्ति में विश्वास—उदारवाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरुत्तमता को नहीं मानता और विश्व-शान्ति तथा विश्व-सन्तुलन के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को धीरे-धीरे शान्ति से प्रगति करनी चाहिए और उसे अन्य राष्ट्रों को वैसी ही प्रगति में सहायता देनी चाहिये। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय धैर्यमय की भावना को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और राज्यों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार कर अपना ठेकाई करते रहना चाहिए।

10. लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन—लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवाद का महत्वपूर्ण विचार है। उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचार के विरुद्ध प्रतिहिंसा स्वरूप हुआ है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को उन पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है। वे इस तथ्य पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों को रक्षा का सर्वोच्च उपाय यह है कि शासन को शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष को स्वेच्छाचारी ठग से शासन करने के अधिकार नहीं हों। इसी उदारवादी विचार को अभिव्यक्ति है। दूर प्राप्त के 'मानवीय अधिकारों की घोषणा' में कहा गया है—“राष्ट्र ही तत्त्वतः सम्पूर्ण प्रभुत्व का स्रोत है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से प्राप्त न हुई हो।”

राज्य के उद्देश्य और कार्यों के सम्बन्ध में उदारवाद (Liberalism between Aims & Works of the State)—राज्यों के उद्देश्यों और कार्यों के सम्बन्ध में उदारवादियों का कभी एक दृष्टिकोण नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में उनकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार सदैव परिवर्तित होती रही है। उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत में दो रूप हमारे सामने आते हैं—(1) परम्परागत उदारवाद एवं (2) आधुनिक जनतन्त्रात्मक उदारवाद।

परम्परागत उदारवाद (Traditional Liberalism)—मूल रूप में उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन और उसकी शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक लड़ने वाला आन्दोलन के रूप में हुआ था, फलतः परम्परागत उदारवाद का मूल तत्त्व स्वतन्त्रता रहा है। जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल्स को इस परम्परागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है। प्रो. हॉबहाउस ने अपने परम्परागत उदारवाद के निम्नांकित नौ मूल सिद्धान्त बतलाये हैं—

1. नागरिक स्वतन्त्रता (Civil Liberty)—नागरिक स्वतन्त्रता शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करती है, इसलिए व्यक्तियों पर व्यक्तियों को नहीं बल्कि कानूनों को प्रभुत्व प्राप्त होना चाहिए। मध्य युग की सामन्ती व्यवस्था में सामन्त वर्ग के विशेषाधिकारों का सर्वत्र बोलबाला था। व्यक्तियों को अपने जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। सामन्त वर्ग के द्वारा व्यक्तियों को मनपाने तरीके से सताया जाता था। उन्हें कारागृह में डाल दिया जाता था और उनकी सम्पत्ति को छीन लिया जाता था अर्थात् उनका शोषण होता था। नागरिक स्वतन्त्रता के आदर्श द्वारा इस स्वेच्छाचारिता का विरोध किया गया और यह माना कि व्यक्तियों को इच्छानुसार जीने का अधिकार मिलना चाहिये।

2. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Individual Liberty)—उदारवादियों ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बल दिया है। उनके द्वारा इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वयं अपने सम्बन्ध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिये। व्यक्तियों के जीवन और उनके रहन-सहन में राज्य या समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि सामाजिक हित की दृष्टि से हस्तक्षेप नितान्त आवश्यक न गया हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अन्तर्गत विचार और भाषण की स्वतन्त्रता, रहन-सहन की स्वतन्त्रता, धार्मिक विश्वास तथा आराधना की स्वतन्त्रता आदि पर विशेष बल दिया गया है।

3. सामाजिक स्वतन्त्रता (Social Liberty)—उदारवाद में सामाजिक स्वतन्त्रता का भी विरोध महत्व रहा है। सामाजिक स्वतन्त्रता से तात्पर्य है कि जन्म, सम्पत्ति, वर्ग, जाति अथवा लिंग के आधार पर व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। समाज के सभी व्यक्तियों को विकास के लिये समान और पर्याप्त अवसर मिलने चाहिये, क्योंकि इनके अभाव में स्वतन्त्रता का उपयोग सम्भव नहीं है। विशेष प्रकार के पद, पेशे, व्यवसाय, उच्च शिक्षा, बुद्धिपूर्व तथा निम्न अथवा समुदाय को सदस्यता वरदानगुण गुणों पर आधारित न होकर इनके द्वार सबके लिये खुले होने चाहिये।

4. वित्तीय स्वतन्त्रता (Financial Liberty)—मध्य युग के निरंकुश शासकों द्वारा अनेक बार जनता पर मनमाने कर आरोपित किये जाते थे, परिणामस्वरूप नागरिक चेतना के उदय के साथ इस तथ्य पर बल दिया गया कि नागरिकों पर उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई कर नहीं लगाये जाएँ। उदारवादी सम्पत्ति को व्यक्तियों का एक पवित्र अधिकार मानते थे, इसीलिए उनके द्वारा यह कहा गया कि नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को होना चाहिए। उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। 19वीं सदी के अन्त में अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम इसी प्रश्न को लेकर प्रारम्भ हुआ था और उसका प्रसिद्ध नारा था 'बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं' (No Taxation, without Representation)।

5. आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Liberty)—परम्परागत उदारवाद के सन्दर्भ में आर्थिक स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और उनके द्वारा संचालित उद्योग तथा व्यापार में राज्य के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मध्य युगीन सामन्ती राज्यों ने भूमि, वस्तुओं तथा सम्पत्ति के क्रय-विक्रय, भाड़े पर श्रमिक रखने तथा घन उधार लेने और देने पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगा रखे थे। उदारवादियों ने उन्हें हटाने की माँग की तथा इस बात पर बल दिया कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य द्वारा 'अहस्तक्षेप की नीति' (Policy of Laissez Faire) अपनायी जानी चाहिए। राज्य के द्वारा व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 'मुक्त प्रतियोगिता' के विचार को अपनाया जाना चाहिये। वस्तुओं के मूल्य और उनके उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर, माँग और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिये। व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में 'संविदा की व्यवस्था' प्राप्त होनी चाहिये। साथ ही उन्हें अपनी आर्थिक उन्नति के लिये सच एवं समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

6. जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (Racial and National Liberty)—उदारवादी विचारक यहाँ के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के समर्थक थे तथा भौगोलिक एवं प्रशासकीय क्षेत्रों में स्वशासन के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे। वे जातीय समानता का भी समर्थन करते थे, किन्तु यह जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का समर्थन यूरोपीय राष्ट्रों तथा गैरी जातियों तक ही सीमित रहा है।

7. अन्तर्राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (International Liberty)—उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग का विरोधी रहा है तथा शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्यों के द्वारा परस्पर अधिकधिक समीप आने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

8. राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty)—राज्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतन्त्रता है और इसके अन्तर्गत ये चार बिन्दु सम्मिलित हैं—नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने का अधिकार। उदारवाद की राजनीतिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्र की पर्यायवाची कही जा सकती है।

9. पारिवारिक स्वतन्त्रता (Domestic Liberty)—इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने परिवार के गठन एवं स्वच्छन्द पारिवारिक जीवन बिटाने की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये। इसके साथ त्रियों को विवाह तथा सम्पत्ति के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिये। बच्चों को विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत मातृ-पिता के दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिये। माता-पिता को उनके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिये निश्चित रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये।

उदारवाद की आलोचना (Criticism of Liberalism)—परम्परागत उदारवाद की इसी प्रकार से आलोचना की जाती है जिस प्रकार से व्यक्तिवाद की आलोचना की जाती है, क्योंकि परम्परागत उदारवाद व्यक्तिवाद की तरह ही आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करता है, परन्तु उदारवाद की आलोचनाएँ भी की गयी हैं। उदारवाद के इन आलोचकों में एडमण्ड बर्क का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। एडमण्ड बर्क के अनुसार उदारवाद की वृष्टि यह है कि इसके द्वारा इतिहास और परम्पराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। परम्पराओं के पीछे पीढ़ियों का अनुभव होता है तथा अतीत से सम्बन्ध तोड़ लेना न तो सम्भव है और न ही उचित। आज का जीवन भ्रूतकालीन परिस्थितियों का ही परिणाम है। उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इस दर्शन में मानवीय बुद्धि को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है जो वास्तव में अनुचित है। मानवीय घटनाक्रम निरधारण में बुद्धि की अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा एवं संयोग अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कहीं नहीं है। राज्य न तो किसी समझौते का परिणाम है और न ही यह कोई व्यावसायिक ढंग को सन्तुष्ट करता है जिसे इच्छानुसार भंग किया जा सकता है। वस्तुतः राज्य उच्चतम मानवीय गुणों के विकास तथा महानतम आदर्शों की प्राप्ति में क्रियारत एक शाश्वत संस्था है। आदर्शवादी एवं फसीवादी विचारक

समष्टिवाद के उद्देश्य—समष्टिवाद एक शोषाविहीन और वर्गाविहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। समाज में इसके लक्ष्य को निर्माणित बिन्दुओं के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है—

(1) उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की समाप्ति, (2) प्रमुख उद्योगों एवं सामाजिक सेवाओं पर सामाजिक नियन्त्रण, (3) उत्पादन का सामान्य आन्तरिकताओं के आधार पर निर्धारण, (4) समाज में व्यक्तिगत लाभ की भावना के स्थान पर सर्वजनिक लाभ की भावना की बढ़ावा, (5) समाज में प्रतियोगिता के स्थान पर सामूहिक सहयोग की भावना पर बल, (6) राजनैतिक और आर्थिक पद्धतियों की समाज रूप से पुष्टि, (7) निर्वन वर्ग और श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण, (8) उत्पादन के मुख्य साधनों पर केन्द्रीय प्रजातांत्रिक सत्ता का नियन्त्रण, (9) उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए शक्तिपूर्ण रकतहीन और क्रमिक उपायों का अवलम्बन, (10) वर्ग सघर्ष के स्थान पर वर्ग सामंजस्य पर जोर एवं (11) प्रजातन्त्र एवं व्यक्ति की स्वतन्त्रता में अटूट विश्वास।

समष्टिवादी अपने उन उद्देश्यों के औचित्य को इन कारणों से सिद्ध करते हैं—उनका जबरदस्त प्रारंभ पूर्ववाद एवं उस पर आधारित समाज व्यवस्था पर है। उनका कथन है कि पूँजीवादी व्यवस्था भयंकर आर्थिक विपन्नताओं को जन्म देती है। इसके कारण एक ओर केवल वर्ग सघर्ष की ज्यादा प्रवृत्ति होती है, मनुष्यों में मनोमनित्य, घृणा, ईर्ष्या एवं विषाद को जन्म मिलता है तथा दूसरी ओर दुष्ट, दमिष्टता, भूख, शोषण बढ़ते जाते हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि समाज में समानता समाप्त हो जाती है और मनुष्य कष्टमय जीवन बिताते हैं। समष्टिवाद प्रजातन्त्र की पूर्ण देखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि आर्थिक स्वतन्त्रता के अभाव में राजनैतिक स्वतन्त्रता व्यर्थ ही नहीं एक धोखा भी है।

समष्टिवाद क्यों?—यद्यपि समष्टिवाद की परम्परा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही मिलती है, लेकिन यह मूलतः 20वीं शताब्दी की विचारधारा है। आधुनिक युग में समष्टिवाद के उदय के कारण प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए सी. ई. एम. जोन्स ने बताया है कि वे प्रमुखतः दो हैं—प्रथम मार्क्सवाद और दूसरा व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इन कारणों के मूल में पूँजीवादी व्यवस्था छिपी हुई है जिसके विरुद्ध सारा समाजवादी आन्दोलन छिड़ गया। समष्टिवाद के जन्म का प्रमुख कारण व्यक्तिवाद से उत्पन्न दोषों के निपटारा से बहर होना है। व्यक्तिवाद ने पूँजीवाद को जन्म दिया जिससे राष्ट्रीय क्षेत्र में शोषण और फलस्वरूप समाज में गरीब और अमीर दो वर्गों का निर्माण एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का बोलबाला हुआ। उन्हें मार्क्स का वर्ग-सघर्ष का सिद्धान्त और सर्वप्रथम वर्ग का अधिनायकत्व स्वीकार नहीं लगा। उन्हें इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि इससे एक वैश्वीक साम्राज्यवाद की स्थापना का उन्हें भय लगा इसलिए मार्क्सवादियों का राज्य के मुद्दे जाने का सिद्धान्त भी उन्हें अस्वीकार लगा, इसलिए उन्होंने ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो मार्क्स द्वारा पूँजीवाद की की गई बुद्धियों से तो समझत हो, लेकिन साथ ही मार्क्स की पद्धति का अनुकरण न हो, अतः विकल्प के रूप में समष्टिवाद अथवा राज्य समाजवाद का सिद्धान्त सामने आया।

समष्टिवाद के मूल सिद्धान्त—ये निम्नलिखित हैं—

(1) सामाजिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में राज्य—समष्टिवादी राज्य को आवश्यक सत्ता मानते हैं। उनके लिए समाज परिवर्तन का माध्यम राज्य है। वे केवल राज्य के वर्तमान पूँजीवादी स्वरूप को बदलने के पक्ष में हैं। वे मार्क्सवादियों की भाँति राज्य को एक वर्ग की सत्ता नहीं मानते, बल्कि उसे वे सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता मानते हैं। वे व्यक्तिवादियों की भाँति राज्य को न आवश्यक बुझाई मानते हैं और अग्रजवादीवादियों की भाँति इसे न एक अनावश्यक बना ही। वे राज्य को एक नकारात्मक अवस्था मानते हैं। इनके अनुसार प्रजातन्त्रोप राज्य अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है और वह अन्य सामाजिक संस्थाओं की अपेक्षा आधुनिक औद्योगिक समाज के हितों के साथ सहसम्बन्धित तथा प्रभावकारी ढंग से व्यवहार करते में समर्थ है। प्रजातन्त्रोप राज्य का स्वाभाविक कार्य समूचे राष्ट्र के मौलिक हितों की अभिवृद्धि एवं परंपरागततापूर्ण एवं न्यायपूर्ण व्यवहार के राष्ट्रीय अन्दरों की रक्षा करके व्यक्तिगत कार्यों की समित्त करना तथा उनकी कमी की पूर्ति करना है। वह दुर्बलों की सहायता तथा सबलों के अन्यदों का दमन करता है और ऐसी सैक्यूलर सुविधाएँ प्रदान करता है जो अकेले व्यक्ति ही तथा छोटी सत्ताओं के द्वारा सम्भव नहीं है। वर्तमान विकसित देशों में इस प्रकार के कार्य करने लगे हैं। वे अक्षिओं की व्यवस्था करते हैं, सिरों एवं बानधों के क्रम पर प्रतिक्रिया लगाते हैं, मरुत पदार्थ निषेध की व्यवस्था करते हैं, जनसंख्या को रखा करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था एवं डाक का प्रबन्ध करते हैं और देश की स्वाभाविक समृद्धि की रक्षा करते हैं। इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत आर्थिक जीवन में जो प्रवृत्तियाँ निम्न होती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास और परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रबन्ध का केन्द्रीकरण करते हैं। प्रविष्य में सर्वजनिक आर्थिक कार्यों का विस्तार स्वाभाविक होगा। राष्ट्रीय सार्वभौम स्वयं उन सेवाओं के लिए प्रबन्ध करेंगे जो परम आवश्यक हैं, जैसे—सड़कें, रेल, वायुमार्ग, बैंक, सामाजिक बीमा, मुद्रास्फीति-निरोधक, जल, प्रकाश और अन्य स्थानीय उद्योगों वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे, अन्य सार्वभौम विभाग, कारखानों के मजदूरों तथा मजदूरों के पारस्परिक विवादों के निर्णय के लिए हस्तक्षेप करेंगे। समष्टि के समुचित विकसन हेतु अधिकतम कर लगाने का प्रबन्ध किया जाएगा।

हैनरी जार्ज के सिद्धान्त, मार्क्स के सिद्धान्त एवं जॉन स्टुवर्ट मिल के व्यक्तिवाद के सिद्धान्त के अन्तर्गत विवक्षित होने वाले समाष्टिवाद का प्रभाव पड़ा था। जार्ज बर्नार्ड शा और सिडनी वेब जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके प्रारम्भिक सदस्यों में से थे। अन्य सदस्यों में प्रो. ग्राहमवाला, एच. जी. वेल्स, श्रीमती एनीबेसेन्ट, कार्ल जेलास्की, विलियम कनर्क, जे. आर. मैकडोनाल्ड थे। इस सोसाइटी ने समस्त शिक्षित मध्यवर्ग की जनता में समाजवाद को प्रसारित करना अपना लक्ष्य बनाया।

एडवर्ड आर. पोस ने अपनी पुस्तक 'History of the Fabian Society' में उस सामान्य समझौते का उल्लेख किया है जिससे प्रारम्भिक फैबियन समाजवादी प्रतिज्ञाबद्ध थे। उसके अनुसार, "इस सोसाइटी के सदस्य यह मानते हैं कि प्रतियोगिता की प्रणाली में सुख-सुविधाएँ कम व्यक्तियों को मिलती हैं और अधिक जनता को कष्ट मिलता है, इसलिए समाज का पुनः संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि समाज के समस्त व्यक्तियों का सुख एवं कल्याण सुनिश्चित हो सके। शा द्वारा तैयार किए गए घोषणापत्र से जो सितम्बर, 1884 में स्वीकार किया गया सोसाइटी ने स्पष्ट शब्दों में समाजवाद को स्वीकार किया और कहा कि भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और राज्य को प्रत्येक उत्पादन विभाग से अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतियोगिता कलनी चाहिए।¹ स्वयं जार्ज बर्नार्ड शा के अनुसार फैबियन लोग क्रान्तिवादी शब्दावली के विनाश का त्याग कर सामान्य पार्लियामेन्टरी ढंग पर व्यावहारिक सुधार के लिए कठिन श्रम करने हेतु राजी हो गए।² सन् 1887 में फैबियनवादियों ने अपने समाज का उद्देश्य इन शब्दों में प्रकट किया—फैबियन समाज समाजवादियों का समाज है जिसका उद्देश्य समाज को पुनर्गठित करना है। यह नया संगठन भूमि तथा उद्योग धन्यों की व्यक्तिगत तथा वर्ग के स्वामित्व से बाहर निकाल कर समाज को उसका स्वामी बना कर दिया जाता है जिससे सामान्य लाभ के लिए कार्य करे। इस रीति से ही प्राकृतिक तथा मनुष्य के द्वारा प्राप्त किए हुए लाभों का समस्त जनता में समानता के आधार पर वितरण किया जाता है। सिडनी वेब ने इतिहास को लोकतन्त्र की अदम्य प्रगति बताते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन जनतन्त्रिय पद्धति द्वारा ही सम्भव हैं, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन हृदय से होता है और जनतन्त्रिय पद्धति द्वारा ही हृदय परिवर्तन सम्भव है।

फैबियनवाद की विशेषताएँ—फैबियनवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद में विश्वास रखता है। फैबियनवादी विचारक लोकतन्त्र और समाजवाद को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानते हैं। फैबियनवाद न तो मार्क्स की ही पूर्ण रूप से सही मानता है जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद पर आधारित है और न ही यह लोकतन्त्र का वह अर्थ समझता है जिसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम पर सामाजिक विषमता को प्रोत्साहन मिलता है। यह हर प्रकार के विशेषाधिकारों एवं अनार्जित आय का विरोध करता हुआ सामाजिक न्याय को व्यवस्था करता है।

फैबियनवादी उद्योगों के साथ-साथ भूमि का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। बर्नार्ड शा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमि का सार्वजनिक स्वामित्व समाजवाद की प्रथम दशा है। उनका कथन है कि विश्व के अधिकांश भाग का अब भी औद्योगिकरण नहीं हुआ है और इससे उन देशों में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का कोई औचित्य ही नहीं है। भूमि के राष्ट्रीयकरण से ही वहाँ की समस्याओं का समाधान सम्भव है। प्रो. कोकर के अनुसार, "राज्य (पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका के 19वीं सदी के प्रजातन्त्रिय राज्य) के द्वारा किए जाने वाले कार्य के औचित्य तथा प्रभावकारिता में अटल विश्वास था। यह राज्य जनता का प्रतिनिधि एवं सरसक, जनता का अभिभावक, व्यवसायी, प्रबन्धकर्ता, संचिद, यहाँ तक की उसका सहायक भी है। इन हैसियतों में वर्तमान राज्य बिना किसी क्रान्तिकारी परिवर्तनों के यदि निर्दोष नहीं तो कम से कम विश्वासपात्र अवश्य बनाए जा सकते हैं। मर्यादधिकार का विस्तार करने, राज्य कर्मचारियों को विशेष रूप से सुदृढ़ बनाने और शिक्षा के सुयोग समान कर देने के सम्बन्ध में परिवर्तन कर देने की आवश्यकता है। इन सुधारों के अतिरिक्त राजनीतिक दशान्तर में कोई मौलिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यदि प्रजातन्त्र के नागरिक इन सत्ताओं का जो उनके पास हैं, पर्याप्त रूप में उपयोग करें तो वे अपनी राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा शान्ति-शान्ति, भूमि तथा औद्योगिक पूँजी दोनों से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ को समाज के हाथों में सौंप सकेंगे।"³

फैबियनों की एक समाजवादी योजना है जिसके मुख्य तत्व हैं—(1) उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना, (2) उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत उपयोग की व्यवस्था, (3) इस व्यवस्था का निर्माण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाए रख कर, (4) सत्ता का विकेंद्रित स्वरूप जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय और स्थानीय स्वामित्व की व्यवस्था, (5) भुखमरी एवं बेरोजगारी के विरुद्ध राज्य सरकार की गारंटी, (6) सरकार पर क्रमिकों का वर्चस्व एवं (7) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का समाजवादी उपयोग।

1. Edward R. Pease - History of the Fabian Society, p. 32.

2. George Bernard Shaw, Sidney Webb, William Clark - Fabian Essays in Socialism & Fabian Society Tracts, Vol. 1-2.

3. कोकर: वही, पृ. 101.

फैबियनवाद और मार्क्सवाद में सपन्नता एवं अन्तर

फैबियनवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है और दोनों में इस तथ्य पर सहमति है कि पूँजीवाद एक घृणित सत्ता है तथा इसके समाप्त करने की आवश्यकता है। दोनों एक शोषण-विहीन एवं वर्ग-विहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं लेकिन दोनों में मूल अन्तर है जो रैडिकल और व्यावहारिक भी है। रैडिकल दृष्टि से फैबियन लोग मार्क्स के वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं और न ही वे भविष्य में मध्यम वर्ग के साथ में विचारवादी रहते हैं। वे राज्य के मुर्दा जाने में विश्वास नहीं रखते। वे इसे न केवल कार्यात्मक एवं व्यावहारिक मानते हैं बल्कि इसे अनावश्यक भी समझते हैं। वे राज्य को समाज का मित्र मानकर चलते हैं और उसे सामाजिक गतिविधियों एवं उनके परिवर्तनों के केन्द्र में अवस्थित करते हैं। फैबियन मार्क्स के श्रम सम्बन्धी और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्तों के स्थान पर समाज को बस्तुओं का मूल्य उत्पन्न करने का प्रमाण कारण मानते हैं। वे यह कहते हैं कि मूल्य सामाजिक परिस्थितियों की उपज है अतः उसमें होने वाली वृद्धि का साथ समाज को मिलना चाहिए। फैबियन सर्वहारा वर्ग के अभिवाक्यत्व में विश्वास नहीं रखते।

व्यावहारिक दृष्टि से दोनों के दृष्टिकोणों में पर्याप्त अन्तर है। फैबियन समाज परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण तरीकों को मान्यता देता है जबकि मार्क्सवादी इनकी सम्प्रतिता में सन्देह करते हैं। फैबियनवादी विश्वास करते हैं कि धीरे धीरे विद्रोहात्मकी प्रक्रिया से जनतन्त्रात्मक एवं आहिंसात्मक मार्ग द्वारा समाजवाद की स्थापना हो सकती है। श्रीमती एनीबेसेन्ट के अनुसार, 'ऐसी कोई रैडिकल-विन्दु नहीं होगी जिसे पार कर समाज व्यक्तिवाद से समाजवाद की ओर अग्रसर होता है। परिवर्तन सदैव अधिम दिग्ग की ओर होता रहता है और हमारा समाज समाजवाद के मार्ग पर सही बढ़ रहा है।

आलोचना एवं मूल्यांकन—फैबियनवाद की अनेक दृष्टियों से कटु-आलोचना की गई है। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार, 'फैबियन समाज समाजवादी सगठन का सबसे कम स्पष्ट एवं अनिश्चित सिद्धान्त है। व्यावहारिक तथा सिद्धान्त रूप में यह एक झुठे झूठे के नीचे है जो अपने उद्देश्यों के विषय में कोई सन्देह प्रकट नहीं करना चाहता। फैबियनवाद अपनी सफलता के लिए पास्ताची पर निर्भर करता है।' कहा गया है कि यह समाजवाद है ही नहीं, बल्कि एक उदारवादी लोकतन्त्रवाद है, क्योंकि यह खुले रूप में शोषक वर्ग का मुकाबला करने के लिए कभी मैदान में उतरता ही नहीं, फिर भी अपनी सफलता पर निश्चित मात्र सन्देह नहीं करता। यह अपने बुद्धिवातुयों से काम निकालता है और एक अर्थ में यह छतारनाक सिद्धान्त है, क्योंकि यह शोषक वर्ग पर प्रहार नहीं करता और सहजसिद्ध की बात करता है। सहजसिद्ध का सिद्धान्त तो केवल बुद्धिवादी वर्ग के हित में ही जाता है और श्रमिक वर्ग इसके नीचे पिस्तता रहता है।

यह कहा जाता है कि फैबियनवाद 'उपदेशक अधिक है और कार्यक्रम में कम है। वेब ने कहा था कि फैबियनवाद समाजवादी विचारों को समाज के सभी वर्गों के पास पहुँचाना चाहता है और उनके मस्तिष्क को बदलना चाहता है लेकिन क्या समाजवादी विचारों की आवश्यकता बुद्धिवादी वर्ग के लिए है? वह इन विचारों को क्यों स्वीकार करने लगा। हृदय परिवर्तन और मस्तिष्क परिवर्तन की बातें कोषो नजर आती हैं, इसीलिए एडिन्स ने फैबियनों को धार्मिक युग का उपदेशक कहा है जो क्रांति से डरते हैं। यह सही है कि फैबियनवाद एक समाजवादी आन्दोलन के रूप में उभर कर सामने नहीं आया। यद्यपि इसका समाजवादी भित्त की कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है फिर भी समाजवादी इतिहास में इसको स्थान प्राप्त है।¹ फैबियनवाद की देन यही है कि हमने समाजवाद को बौद्धिक धरातल प्रदान किया है और जो व्यक्तिवाद और साम्यवाद से पिछे हुए वे उन्हें समाजवाद की ओर गम्भीरता से सोचने के लिए बाध्य किया है।

रैडिकलवाद या पुनर्विचारवाद और बर्नस्टीन

(Revisionism and Edward Bernstein, 1850-1932)

कार्ल मार्क्स के बाद उसके दर्शन को लेकर उसके समर्थक कई गुटों में बँट गए। इसके अनेक कारण थे। मार्क्स के उन देशों में रहने वाले अनुयायी जहाँ जनतन्त्र अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था, मार्क्स के कुछ सिद्धान्तों जैसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष एवं क्रांति की अपरिहार्यता आदि विचारों से आशयल नहीं थे और वे मार्क्सवाद को जनताधिकारी के अन्तर्गत ढालना चाहते थे। कुछ दूसरे अन्य समर्थक अपने-अपने देशों की भौतिकवादी, ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप मार्क्सवाद को ढालना चाहते थे। कुछ अन्य लोगों ने मार्क्स के सिद्धान्तों पर आपत्ति प्रकट की। उन्होंने क्रांति के सिद्धान्त को एक विकासशील रूप देने का प्रयत्न किया, जबकि दूसरों ने इसके इतिहासिक स्वरूप को अधिक महत्व दिया। जिन लोगों ने मार्क्सवाद के क्रांतिकारी पहलू की अपेक्षा उसके विकासवादी पहलू पर अधिक जोर दिया और मार्क्सवाद को परिचित परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने का प्रयास किया, इनमें प्रमुख रैडिकलवादी (Revisionist) हैं। जिन लोगों ने मार्क्सवाद का संशोधन किया उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति एडवर्ड बर्नस्टीन (Bernstein) हैं। जिन लोगों ने मार्क्सवाद की परिभाषा देना उपयुक्त रहेगा—

जोर्डन स्काफ के अनुसार, "पुनर्विचारवाद एक ऐतिहासिक विचार है जिसने पहली बार जर्मन सोशियल डेमोक्रेसी में गत शताब्दी के अंत में एडवर्ड बर्नस्टीन के अर्थों को प्रस्तुत किया गया था। भ्रान्तिपूर्ण क्रान्ति विरोधी पुनर्विचारवाद मार्क्सवाद के सशोधन के कारणों का आदर्श प्रस्तुत करता है।" बोरक के अनुसार, "एक सशोधनवादी के लिए समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए समाज का अर्थ है व्यक्तिगत पूंजीवाद पर राज्य का प्रतिबन्ध। यह प्रतिबन्ध व्यक्तिगत स्वार्थियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में राज्यीय हस्तक्षेप का रूप ले सकता है अथवा पूंजी के किसी भाग विशेष में व्यक्तिगत स्वार्थित्व के स्थान पर राज्य के स्वार्थित्व की स्थापना का रूप ले सकता है।"¹

एडवर्ड बर्नस्टीन के विचार—बर्नस्टीन का जन्म जर्मनी के जर्मन नगर में हुआ था। जर्मनी में गान्धी प्रजातंत्र की विचारधारा बर्नस्टीन के जन्म के पहले ही प्रचारित थी और उसका नेतृत्व फर्डिनेन्ड लेसली का था। लेसली Universal Germanmens Association का नेता था जिसका उद्देश्य समाज में वर्ग संघर्ष का शांतिपूर्ण, वैधिक एवं जनतांत्रिक पद्धति से दूर करना था। 1864 में लेसली की मृत्यु हो गई और वेबिन और ले बुन्नेथ ने संगठन का नेतृत्व किया। बर्नस्टीन 22 वर्ष की आयु में जर्मनी की Social Democratic Party में शामिल हो गया। 1878 में समाजवाद विरोधी कानून के पारित होने पर उसे जर्मन छोड़ना पड़ा और वह दो दशकों तक स्विट्जरलैण्ड और इंग्लैंड में निर्वासित रूप में रहा। इंग्लैंड में जब वह आया तो मार्क्स की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उसने एड्रिअन से सम्पर्क बनाए रखा। वह इंग्लैंड में फैबियनों के सम्पर्क में भी आया। उसके विचारों का एक और सङ्गम है जिसका सशिव अमेरी अनुवाद 'Evolutionary Socialism' के नाम से प्रकाशित हुआ है। उसकी एक 'Problem of Socialism' नामक लेखमाला भी प्रकाशित हुई है।

बर्नस्टीन पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश की आवश्यक नहीं मानता था। वह मार्क्स की इस भविष्यवाणी से सहमत नहीं था कि विकास की अपनी प्रक्रिया के द्वारा पूंजीवाद का विनाश अवरूपवाही है। बर्नस्टीन ने बताया कि जिस प्रकार से पूंजीवाद का विकास हो रहा है उसमें उसके विनाश के बीज नहीं हैं, इसलिए उसने जर्मन सामाजिक जनतांत्रिक दल को चेतावनी दी कि उसे ऐसी कोई योजना नहीं बनानी चाहिए जो इस मान्यता पर निर्मित हो कि पूंजीवाद का विनाश पूर्व निर्दिष्ट है। बर्नस्टीन ने मार्क्स की अलोचना करते हुए उसके चिन्तन में अनेक स्वप्नलोकिय तत्वों की दूँदा। उसने लिखा कि "यद्यपि मार्क्स और एङ्गल्स के मैनीफेस्टो में सामाजिक विकास की प्रक्रिया सही है, लेकिन उसका समय निर्धारण ठाक नहीं है। उसने कहा कि सामाजिक दशार्थ उस तरीके से नहीं बदलती हैं जिसका कि मैनीफेस्टो में उल्लेख किया गया है। बर्नस्टीन ने बताया कि मार्क्स की यह भविष्यवाणी कि गरीब ज्यादा गरीब होते जाएँगे, गलत साबित हुई है। उसने बताया कि पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ छोटे-छोटे पूंजीपतियों का विकास हुआ है और मध्यम वर्ग की स्थिति भी सुदृढ़ हुई है।"² उसने इस कि समाज में पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई है। उसने मार्क्स के इस कथन को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया कि केवल श्रमिक वर्ग ही पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध बग़ावत कर सकता है। उसने बताया कि पूंजीवाद से समाजवाद की ओर आवर्तन शान्ति-शान्ति होता है और समाज स्वयं पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध जाग्रत होता है। उसके कथन का सार यह था कि परिवर्तन की दिशा में केवल श्रमिक का ही नहीं अपितु सारे समाज का योगदान होगा है, इसलिए सर्वोच्च वर्ग के अधिनायकत्व की धारणा वृथा एवं अटपटी है।

बर्नस्टीन समाजवादी आन्दोलन को आधुनिक प्रजातंत्रिक आन्दोलन की श्रेणी में मानता था। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि समाजवाद की स्थापना वर्ग संघर्ष का प्रतिफल नहीं होगी, बल्कि श्रमिक वर्ग की लोकतंत्र की ओर मोड़कर उसके जीवन-स्तर को उन्नत करने से होगी। वह इस राय का था कि श्रमिकों में राजनीतिक जागृति आनी चाहिए तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए। उन्हें अपने व्यावसायिक एवं औद्योगिक संगठनों को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

बर्नस्टीन समाजवाद और प्रजातंत्र की एक-दूसरे का पूरक समझता था। उसके अनुसार, "बिना कुछ प्रजातंत्रिक परिपक्वताओं एवं संस्थाओं के आज का समाजवादी सिद्धान्त वास्तव में सम्भव नहीं होगा। जिस-देह मन्दूर आन्दोलन तो होगा, किन्तु सामाजिक प्रजातंत्र नहीं। आधुनिक समाजवादी आन्दोलन और उसकी सैद्धांतिक व्याख्याएँ प्रगति की महान् क्रान्ति तथा औचित्य की उन भावनाओं का प्रतिफल है जो उस क्रान्ति के द्वारा मजदूरों के आन्दोलन तथा मजदूर आन्दोलन में सामान्य स्वीकार कर ली गई है। प्रजातंत्र और समाजवाद में परस्पर अन्तर्विरोध नहीं है। प्रजातंत्र समाजवाद की शक्ति है। प्रजातंत्र समाजवाद का केवल साधन ही नहीं उसका सार भी है।"³ बर्नस्टीन ने मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को सर्वोत्तम बताया। उसने बताया कि समाज की प्रगति का आधार उत्पादक शक्तियों ही नहीं है, बल्कि कानूनी व्यवस्थाओं, नैतिक मान्यताओं, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों, भौतनैतिक एवं ऐतिहासिक अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। जिस-देह, मार्क्स और एङ्गल्स ने इनके गौण तत्वों के रूप में अवयव स्वीकार किया था, लेकिन

1. **बोरक** : आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 107.

2. **Edward Bernstein** : Evolutionary Socialism, p. 9.

3. **Bernstein** : Evolutionary Socialism, p. 166.

उपलब्ध होने चाहिए। प्रोफेसर कोबर के अनुसार, इस प्रकार फासिज्म की सम्पूर्ण विचारधारा में प्रभुत्व सम्पन्न राज्य तथा दुर्विवार शासन का प्राधान्य है। राष्ट्र के सर्वशक्तिमान प्रेमीबद्ध समर्थन द्वारा व्यक्तिगतों के समस्त विशिष्ट हितों का दमन होना चाहिए। नागरिकों के राजनीतिक दायित्व उनके अधिकारों से अधिक गहनत्वपूर्ण है। यह फासिस्ट सर्वत्र भावाद (Totalitarianism) है जो व्यक्ति के जीवन के किसी भी क्षेत्र को राज्यशास्य से विमुक्त नहीं मानता।

फामिस्टों ने स्वेच्छस्वायत्तों द्वारा प्रतिपादित 'स्वतन्त्रता', 'समाप्ता' और 'प्रातुत्व' के स्थान पर 'दायित्व', 'अनुशासन' और 'श्रेणीबद्ध संगठन' ये तीन नारे दिए। उन्होंने बताया कि इटली को कानून, व्यवस्था और कार्यपुनरास्था की आवश्यकता है और न कि स्वतन्त्रता, समाप्ता और प्रातुत्व के पिछे-पिछे और अर्गहीन नारों के। उन्होंने यह कहा कि वास्तविक स्वतन्त्रता ऐसी राजनीतिक प्रणाली के अन्दर सम्भव है जो दुइता के साथ इन तीनों नारों को लागू कर सके।

राष्ट्रीय समाजवाद या नाजीवाद

(National Socialism or Nazism)

नासोवाद और प्योसोवाद में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है। जर्मनी, जहाँ नासोवाद पनपा और फासोवाद के धर इटली की आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप ही ये दो विचारधाराएँ बाली गई हैं। दोनों देशों की परिस्थितियों में बहुत कुछ अनुरूपता थी अतः दोनों विचारधाराओं में समानता है। दोनों में जो अन्तर कहा जा सकता है वह दो देशों की परिस्थितियों के अन्तर का परिणाम हो सकता है, लेकिन यह अन्तर मौलिक नहीं है।²

जर्मन परिस्थितियाँ एवं नाज़ीवाद

जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होकर 1919 की वार्साय की संधि को मानने के लिए मजबूर किया गया था। यह संधि अप्रतिष्ठित संधि थी। जर्मनी को इस संधि के परिणामस्वरूप भयंकर आर्थिक, क्षेत्रीय एवं सामरिक हानि के साथ उसके राष्ट्रीय स्वाधिमान को जबरदस्त छोट पहुँचाई गई थी। जर्मन राष्ट्र तिलमिला उठा। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चली थी। वार्साय संधि के उपासक सरकारें अस्थिर हो गईं थीं वे कोई भी राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने में सफल नहीं थी। उसे एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो राष्ट्रीयता के डबलते हुए युन को खीला सके और राष्ट्रीय शक्ति को संगठित कर अपने छोटे हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। 1920 में जर्मन मजदूर दल का संगठन किया गया जिसने राष्ट्रीय समाजवाद अथवा नाज़ीवाद को जन्म दिया। परिस्थितियों के कारण मजदूर दल की प्रकृति समाजवादी न होकर अधिकाधिक राष्ट्रीय होती चली गई और एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में इसे जातीय रंग भी मिल गया। इसने जर्मन जाति को आर्य जाति घोषित किया और उसके झण्डे के नीचे सभी गैर यहूदी को एकत्रित किया गया। हिटलर ने सभी वर्गों—किसान, मजदूर, छोटे एवं बड़े पूँजीपतियों, ब्राह्मणपतियों, वैतनधोर्गों, कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों आदि सभी से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से सबद्ध करने का झूठा वायदा किया। यह मजदूर दल आगे चल कर राष्ट्रीय समाजवादी दल कहलाया जिसे 1920 के चुनाव में जर्मन संसद में 12 स्थान प्राप्त हुए, लेकिन इसके उपरान्त इसे आशातित सफलता प्राप्त हुई। 1930 में इस दल को 130 स्थान मिल गए। सन् 1932 में तो यह जर्मनी का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया, इसे संसद में 37 प्रतिशत मत एवं 230 स्थान प्राप्त हुए। हिटलर प्रभावशाली और कुशल नेता सिद्ध हुआ। उसने अपने पुँआधार प्रचार कार्य में वार्साय की संधि की भर्त्सना की एवं जर्मनी को गौरवशाली बनाने पर जोर दिया। उसने जर्मनी का एक सामरिक शक्ति बनाने पर बल दिया और साथ ही माँग की कि सतिपूर्ति की शर्तें समाप्त कर दी जाएँ एवं यहूदियों को जर्मनी से निकाल बाहर किया जाए। उराका प्रभाव इस सीमा तक बढ़ गया कि उसे 29 जनवरी, 1933 को जर्मनी का चांसलर बनने के लिए आमन्त्रित किया गया। एक बार सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने सर्वाधिकारी राज्य की स्थापना की और स्वयं वर्गों का वानाशाह बन गया। नाज़ीवाद की परिणति द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में हुई क्योंकि हिटलर का उद्देश्य युद्ध के संसार में 'जके' अधिपत्य को स्थापित करना था। हिटलर को, यहूदी, कुर्, रूढ़ि, वार्साय, गै, यरिश, गै, यामा, बन्दे, के, लिग, कापी, थी, द्वितीय विश्व युद्ध जिसे उसने प्रारम्भ किया था, प्रारम्भिक वर्षों में हिटलर एवं मुसोलिनी के पक्ष में रहा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल गई। 1945 का अप्रैल माह निर्णायक सिद्ध हुआ। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन जनरलों को आत्म-समर्पण के लिए बाध्य कर दिया। हिटलर ने 30 अप्रैल, 1945 को दुर्गति से बचने के लिए आत्महत्या कर ली।

माजीवाद के सिद्धान्त—माजीवाद एवं सोत वही है जो कि फासीवाद के हैं। जिन परिस्थितियों में इन विचारधाराओं का उदय हुआ वे भी सामान थी। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध में इटली जिन राज्यों के साथ था, लेकिन उसके साथ किए गए वायदे पूरे न किए जाने के कारण वह धोर असन्तुष्ट था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त वहाँ की स्थिति काबू के बाहर हो चली थी। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी और इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुआ था। दोनों ही देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, सरकारें इसे नियन्त्रण में लाने में असमर्थ थीं, जनसाधारण श्रम्य एवं डोलित था, वर्साय की सन्धि को राष्ट्रीय असम्मान समझा जाता था लेकिन

जर्मन राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि कुछ पृथक् और अनेक तत्वों से मिश्रित थी। जातीय श्रेष्ठता और विस्तारवाद के मध्य में नाज़ी राज्य है जो नाज़ीवाद की मूल संस्कृति है। नाज़ी राज्य एक सर्वाधिकारी राज्य था जिसका लक्ष्य साम्राज्य विस्तार था। हिटलर ने अपनी आत्मकथा 'मेन केम्फ' में शिक्षण संस्थाओं, समाचार-पत्रों, चर्चाचक्रों आदि पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही है। उसने रक्त की शुद्धता पर जोर दिया है। उसका कथन है कि "प्रत्येक लड़के-लड़की को इस तथ्य का अहसास होना चाहिए और जब तक उसे यह ज्ञान न हो जाए, उसे स्कूल अथवा कॉलेज छोड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।" इतना ही नहीं हिटलर ने कला पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसने कहा कि "सर्वाधिकारी राज्य कला से पृथक् अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। उसकी भाँति है कि कलाकारों को राज्य के प्रति सकात्मक नीति अपनानी चाहिए।" रोजनबर्ग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि "जर्मन विश्वविद्यालयों से बिना किसी मर्यादा के अध्ययन को दिगम्बर स्वतंत्रता समाप्त कर दी जानी चाहिए और उसके स्थान पर सच्ची स्वतंत्रता अर्थात् राष्ट्र की सजीव शक्ति बनाने की स्वतंत्रता प्रतिष्ठापित कर दी जानी चाहिए, ऐसा हिटलर के अधीन जर्मनी में कर दिया गया।"

विज्ञान और अर्थव्यवस्था नाज़ी राज्य में मर्यादित थी। अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य के अधीन थी। राज्य ने ममस्त अर्थव्यवस्था को जैसा चाहा काम में लिया। अर्थव्यवस्था युद्ध-अर्थव्यवस्था थी और इसी दृष्टि से उत्पादन होता था। सारे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन की स्वायत्तता ग़रब हो गई थी। इनका उपयोग नाज़ीवाद के समर्थन के लिए किया जाता था। नाज़ीवाद जैविक सिद्धान्त की दृष्टि से राष्ट्र की एक जीव मानता है और जीव की जीवित रखने के लिए उसका पोषण आर्थिक समृद्धि एवं विकास उसका विस्तार मानता है। इस प्रकार का विस्तार एक राष्ट्र की जीवित रखने के लिए आवश्यक है। नाज़ीवाद सीमोल्लप्पन में विश्वास करता है। वह राज्य की कोई निश्चित सीमा नहीं मानता। श्री सेबाइन ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राचीन राज्य इस बात के लिए बाध्य होते हैं कि वे अपने स्थान का विस्तार करें। राज्य की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उसकी एक आसानी सीमानेखा होती है। वह सतत विकास में शक्ति का एक बिन्दु मात्र होती है। श्रेष्ठ सीमान्त वह है जो विकास के अनुकूल हो, जो दूसरे राज्यों में प्रवेश करने तथा सीमा-घटनाओं की बढ़ावा देने के लिए अनुकूल होता है। प्रगति सधर्ष के माध्यम से ही होती है। श्रेष्ठ जाति हीन जातियों का शोषण करके अपने जीवन-स्तर को ऊँचा रखे और हीन एवं अधीनस्थ जातियों की इस बात के लिए विवश कर दिया जाए कि वे बहुत हल्के स्तर का जीवन बिताएँ। एक शक्ति सारे ससार पर शासन स्थापित करे। सारा ससार नियन्त्रण के कुछ क्षेत्रों में बाँट दिया जाए और प्रत्येक क्षेत्र पर एक नियन्त्रणकारी शक्ति शासन करे।

आलोचना एवं मूल्योक्त—फ़ासीवाद एवं नाज़ीवाद दोनों राजनीतिक दर्शन कम और राजनीतिक तत्काल अधिक हैं। सेबाइन के अनुसार, कुछ लोगों के मत में, फ़ासिस्टवाद और राष्ट्रीय समाजवाद (हिटलरवाद) दर्शन नहीं हैं। उनकी पद्धतियों में भीड़ के मनोविज्ञान और आतंक का पित्रण था। उनके नेताओं का एक ही उद्देश्य था—शक्ति को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना। फ़ासीवादी और नाज़ीवाद धीरे-असहिष्णु हैं। इनके अनुसार सारा सत्य केवल इनके चिन्तन में है, शेष सब मिथ्या है और इनके विचार में जो इनके साथ नहीं हैं वे पोर शत्रु हैं इसलिए उनका ख़ात्मा करना आवश्यक है।

दोनों फ़ासीवाद और नाज़ीवाद जातीयता के पोषक और लोकतन्त्र के विरोधी हैं। यद्यपि फ़ासीवाद के लिए इतना नहीं कहा जा सकता जितना की नाज़ीवाद के लिए कि यह जातीयता का पोषक है। भुसोलिनी श्रेष्ठ व्यक्तियों (Elites) की बात कहता था और केवल उन्हें ही शासन-प्रक्रिया से सम्बद्ध करना था। उसने सर्व-साधारण को ठीक-सुलझा कर से देखा। दोनों ही विचारधाराएँ लोकतन्त्र की घोर विरोधी हैं। दोनों ही विचारधाराएँ युद्ध और हिंसा पर जीवित हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इनका जीवन युद्ध और हिंसा है। द्वितीय विश्व महायुद्ध इन दोनों विचारधाराओं के उत्कर्ष का ही परिणाम रहा है। ये नीतियों के पशु महामानव के विकास के लिए अस्तित्व के लिए सधर्ष का दार्शनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। नाज़ीवाद को राष्ट्रीय समाजवाद कहा गया है लेकिन इसका स्वरूप न राष्ट्रीय है और न समाजवादी। यह हिटलरवाद है जो एक व्यक्ति की तानाशाही का दूसरा नाम है। इनकी शब्दावली में राष्ट्रीयता का अर्थ आर्य-जाति की प्रभुता से है और समाजवाद का अर्थ जर्मन सर्वहारा राष्ट्र के विकास पर अन्ध-दिव्य वर्चस्व से है। सब तो यह है कि यहाँ राष्ट्रीयता और समाजवाद दोनों ही शब्दों का अर्थ बदल गया है। फ़ासीवाद और राष्ट्रीय समाजवाद की प्रशंसा सैद्धांतिक स्तर पर करना कठिन प्रतीत होता है। इनके प्रभाव के सम्बन्ध में यह अवश्य कहा जा सकता है कि प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त इटली और जर्मनी में उत्पन्न स्थिति का सामना केवल मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाह ही कर सके थे। जब प्रतिनिधि सम्मार्प तथा ठंडर राखीय नीतिपूर्ण इच्छा-शक्ति और कार्य-शक्ति के अभाव में विघ्न रहती है अथवा सामुदायिक हितों के सम्मने राष्ट्रीय हितों की हत्या होने देती है, तब जनता किसी भी ऐसे व्यक्ति के निकरुश शासन में रहने के लिए तैयार हो जाती है, जो चाहे जिस प्रकार सत्ता हस्तगत करे और चाहे जिस प्रकार शासन करे, परन्तु मुख्यतः कथन रख सके, मुशताम स्थापित कर सके और देश के अन्दर और बाहर उसके लिए आदर प्राप्त कर सके।

हिटलर और मुसोलिनी ने अन्य समय में जो कुछ क्रमशः जर्मनी और इटली को दिया वह शायद किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत कदापि सम्भव नहीं है। जर्मनी और इटली का इतना जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक निर्माण हुआ

यूरोप और विश्व इनसे घर्ष उठे। इन देशों के निवासियों में एक नवीन आध्यात्मिक एकता का निर्माण किया गया और जनता में अभूतपूर्व जोश का संचार हुआ। ऐतिहासिक सफलता का श्रेय फ्रांसिस और नाजी दलों के उतम संगठनों एवं मुसोलिनी और हिटलर के प्रभावशाली नेतृत्व को है। वानरशाही राष्ट्र को तीव्रगति से आर्थिक और सामरिक निर्माण भी कर सकती है और फिर उसे गर्त में से भी ज्वा सकती है—इन दोनों का सबूत हमें फासीवाद और नازیवाद में मिलता है।

मार्क्सवाद

(Marxism)

मार्क्सवाद समाजवाद की प्रथम सीमा है। समाजवाद की प्रथम सीमा पर लाने का श्रेय कार्ल मार्क्स को है। इसमें एंगेल्स की भी अहम भूमिका धानी जाती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार, "साम्यवाद अपने शाब्दिक अर्थ में अवश्य ही एक पद्धति या सिद्धान्त है। यह उन नियमों को स्थापित करता है जिनके द्वारा पूँजीवादी को समाजवाद में बदला जा सकता है।"

मार्क्सवाद की विशेषताएँ—मार्क्सवाद की विशेषताएँ हैं—(1) मार्क्स का समाजवाद इतिहास के विकास और उसकी भौतिकवादी व्यवस्था पर आधारित है (2) यह सामाजिक परिवर्तन के नियमों की व्याख्या करता है (3) मार्क्सवाद एक भौतिकवादी विचारधारा है (4) इस वाद के अनुसार पदार्थ ही विचारों के स्रोत होते हैं एवं (5) यह वाद वर्ग-संघर्ष पर आधारित एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था है।

मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धान्त—इस विचारधारा के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—(1) दृष्टात्मक भौतिकवाद (2) इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (3) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (4) वर्ग संघर्ष (5) सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व एवं (6) साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना।

मार्क्सवाद के प्रमुख ग्रन्थ—मार्क्सवाद के प्रमुख ग्रन्थ हैं—(1) साम्यवादी घोषणा-पत्र (2) कार्ल मार्क्स वैल्स ग्रुस एण्ड प्रोफिट, 1865 (3) एन्जिल्स सोशियोलिज्म यूरोपियन एण्ड साइंटिफिक, 1880 एवं (4) दास कैपिटल।

अराजकतावाद

(Anarchism)

इस विचारधारा के प्रतिपादक एवं समर्थक थितीसप गौडविन हैं। इसके अन्य समर्थक जोसेफ प्रोपी, माइकिल बाकुनिन, पीटर क्रोपोटकिन हैं। क्रान्तिस्त कोकर के अनुसार, "अराजकतावादी सिद्धान्त के अनुसार राजनीतिक सत्ता किसी भी रूप में अनावश्यक एवं अवाञ्छनीय है। आधुनिक अराजकतावाद में राज्य के सैद्धान्तिक विरोध के साथ वैयक्तिक सम्पत्ति की सत्ता का विरोध तथा संगठित धार्मिक सत्ता के प्रति शत्रुता का भाव भी समाविष्ट है।"

अराजकतावाद की भ्रान्तताएँ—अराजकतावाद की भ्रान्तताएँ इस प्रकार हैं—(1) यह विचारधारा सम्पत्ति का विरोध करती है (2) यह विचारधारा राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहती है (3) यह विचारधारा धर्म का विरोध करती है (4) इस विचारधारा के अनुसार मानव स्वभाव से अच्छा है सहयोगी है एवं सामाजिक है (5) यह विचारधारा स्वतन्त्रता एवं समानता में विश्वास करती है एवं (6) यह विचारधारा सहकारिता के आधार पर ऐच्छिक एवं अस्थायी समुदाय का निर्माण करने में विश्वास करती है।

इस प्रकार अराजकतावाद राज्य सम्पत्ति तथा धर्म के अस्तित्व का विरोधी है।

गान्धीवाद

(Gandhism)

गान्धीवाद जीवन के अनेक क्षेत्रों में महात्मा गान्धी के राजनीतिक, तात्विक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं दारानिक मान्यताओं एवं अभिप्रायों का विरलेषण है। गान्धीवाद में सिद्धान्त भी है और व्यावहारिक भी है। गान्धीवाद के मूलभूत सिद्धान्त इस प्रकार हैं—(1) ईश्वर सभी प्रकार के मूल्यों का आधार है अतः इसकी सत्ता में दृढ़ आस्था (2) मानवीय आत्मा की समानता में विश्वास रखना (3) सत्याग्रह क्रान्ति का अन्त (4) सामूहिक अहिंसा का सिद्धान्त (5) मनुष्य के शरीर मन एवं आत्मा की अखण्डता का सिद्धान्त (6) समाज, राज्य अथवा किसी सत्ता का हित उन व्यक्तियों से अलग नहीं है जिन्हें उसका निर्माण हुआ है (7) साध्य से साधन का अधिक महत्व है क्योंकि साध्य दिशा प्रदान करता है तो साधन का सम्बन्ध साधन रूप में जीवन से है एवं (8) अन्तः अनुभूति ज्ञान का उच्चतम रूप है। डॉ. राममनोहर लोहिया के अनुसार, महात्मा गान्धी दार्शनिक-उदारवादी तथा बहुलवादी थे। यद्यपि महात्मा गान्धी का सम्बन्ध सम्पूर्ण जीवन में तरह-तरह की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान से था। उनकी बुद्धि आध्यात्मिक रहते हुए भी व्यावहारिक थी। गान्धीवाद के प्रमुख व्याख्याकारों में डॉ. जवाहरलाल नेहरू डॉ. राममनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, आचार्य विनोबा भावे एवं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मुख्य हैं।

शक्ति तथा अधिमत्य के सिद्धान्त (Theories of Power and Hegemony)

अभिजन सिद्धान्त, समूह सिद्धान्त और शक्ति सिद्धान्त, ये तीनों सिद्धान्त अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत लोकप्रिय हुए और प्रत्येक ने अपने आप में एक सम्पूर्ण राजनीतिक सिद्धान्त होने का दावा किया।¹ अभिजन सिद्धान्त का आधार था कि प्रत्येक समाज में दो अलग-अलग वर्ग होते हैं—(1) कुछ ऐसे थोड़े व्यक्ति जिनके पास क्षमता होने से उन्हें समाज में नेतृत्व का अधिकार मिला होता है एवं (2) असंख्य ऐसे जन साधारण हैं जो भाग्य से उनके नेतृत्व के समाज में शामिल होना लिखा कर आए हैं।

इनमें प्रथम वर्ग अभिजनों का कहलाता है। राजनीतिक अभिजन सिद्धान्त का विकास 1950 के दशक में अमेरिका में समाज विज्ञानियों शुम्पीटर जैसे अर्थशास्त्रियों, लावेस जैसे राजनीति वैज्ञानिकों और सी. राइट मिल्स जैसे समाजशास्त्रियों के द्वारा विभिन्न रूपों में हुआ और उसके सूत्र फासीवाद के पूर्व अनेक यूरोपीय विचारकों द्वारा शुरू हुए थे। इनमें इटली के निवासी बिल्फ्रेडो पैरेटो और गोतफ्रो यास्कर स्विस्-जर्मन, राबर्ट मिचेल्स और स्पेनवासी जॉर्ज आर्टेगा बाई, गैसट प्रमुख थे। पैरेटो (Pareto) की मान्यता थी कि प्रत्येक समाज का शासन एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में होता है जिसके पास सम्पूर्ण सामाजिक और राजनीतिक सत्ता पर अधिकार स्थापित कर सने के आवश्यक गुण होते हैं।

पैरेटो (Pareto)

पैरेटो के अनुसार जो लोग समाज और राज्य के उच्चतम शिखरों व स्थानों पर पहुँच जाते हैं, वास्तव में वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन लोगों को 'अभिजन' का नाम दिया गया है। अभिजन वर्ग में उन सभी सफल व्यक्तियों को गिना जा सकता है जो प्रत्येक धन्ये में तथा समाज के प्रत्येक स्तर पर शिखर तक पहुँच जाते हैं। पैरेटो के अनुसार डॉक्टरों, वकीलों, वैज्ञानिकों एवं चोरों और बेरपाशों के भी अभिजन होते हैं। वह यह मानता है कि विभिन्न व्यवसायों और सामाजिक स्तरों पर मिलने वाले अभिजन सामान्यतया समाज के एक ही वर्ग से बनते हैं—जो अमीर है वही बुद्धिमान भी है और जो बुद्धिमान है उसके पास गणित को समझने, संगीत में परिणत होने तथा उच्च नैतिक चरित्र रखने आदि की क्षमता होती है। पैरेटो के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं—(1) एक उच्च वर्ग जिसे हम अभिजन वर्ग कहते हैं और जो शासक अभिजन और शासन के बाहर के अभिजन इन दो उपवर्गों में बाँटे जा सकते हैं (2) एक निम्न वर्ग अर्थात् गैर अभिजन वर्ग है। इनमें पैरेटो के अध्ययन का केन्द्र-बिन्दु शासक अभिजन वर्ग था, जिसके बारे में पैरेटो का विश्वास था कि वह बल प्रयोग और चालाकी दोनों के मिश्रित आधार पर शासन करता है। उसने इन दोनों में से बल प्रयोग को अधिक महत्व दिया है।

सिद्धान्त के मूल स्रोत—पैरेटो ने अभिजन वर्ग में परिवर्तन होते रहने की संकल्पना का विकास किया। उनके अनुसार इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति और अभिजन अन्तर्गत रूप से उच्च स्तर से निम्न और निम्न से उच्च स्तर की ओर जाते रहते हैं अतएव पैरेटो को सबसे अधिक चिन्ता यह थी कि अभिजन वर्ग के नष्ट हो जाने के कारण समाज में जो असन्तुलन पैदा हो जाता है उसे किस प्रकार से रोका जाए। इसने अपनी रचनाओं में अभिजन वर्ग में होने वाले भिन्न प्रकार के परिवर्तनों एवं प्रत्यावर्तनों की बात कही है। उसके अनुसार कभी शासक वर्ग के विभिन्न समूहों तक परिवर्तन की यह प्रक्रिया सीमित रहती है और कभी अभिजन वर्ग तथा गैर अभिजन वर्ग के बीच परिवर्तन एवं प्रत्यावर्तन होता दिखाई देता है। दूसरे प्रकार के परिवर्तन में व्यक्ति निम्न स्तर से ऊपर उठकर तत्कालीन अभिजन वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं और निम्न वर्ग के व्यक्ति मिलकर नये अभिजन वर्गों का निर्माण करते हैं तथा शासक अभिजन वर्ग के विरुद्ध शक्ति के संघर्ष में लग जाते हैं। शासक वर्ग की जिस अवस्था के कारण सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है और नये अभिजन वर्ग की रचना होती है उसके कारणों का उल्लेख करते हुए पैरेटो कहता है कि "विभिन्न प्रकार के अभिजन वर्गों के मनोविकास में परिवर्तन होता रहता है।" पैरेटो ने अपनी 'अवरोधों' की संकल्पना विकसित की है। 'अवरोधों' से पैरेटो का आशय वास्तविक रूप में उन गुणों से है जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन में ऊँचा

उठ सकता है। ठाने 'अवशेषों' के छ गुणों की एक तालिका तैयार की है। वह उनमें से दो प्रकार के गुणों को अधिक महत्वपूर्ण 'अवशेष' मानता है। उसने उनका नाम 'मिश्रित तत्व' (Combination) और 'समुच्चय सातत्य' (Persistence of Aggregates) दिया है। वह मानता है कि इन्हीं की सहायता से शासक वर्ग अपने आप को सत्ता में बनाए रखने में सफल होता है। साधारण शब्दों में मिश्रित तत्व' नाम के अवशेष का अर्थ चालाकी और 'समुच्चय सातत्य' नाम के अवशेष का अर्थ बल प्रयोग है। पौरेटो ने 'अभिजन' के इन दो वर्गों को 'संदेहियों' (Speculators) एवं किराया जीवियों (Rentiers) का नाम दिया है। पौरेटो के अनुसार एक वे हैं जो चालाकी से शासन करते हैं तथा दूसरे बल प्रयोग द्वारा शासन करने वाले हैं। यहाँ मैकिन्गलेसी द्वारा मुझाए गए उन दो शासक वर्गों के नाम थार आते हैं जिन्हें उसने 'सिद्धों' और 'सोमहिद्धों' का नाम दिया था। बल प्रयोग को व्यापारिक अथवा विवेक सम्पन्न ठहराने के लिए अभिजन शब्द साधनों' (Derivations) अथवा 'मिथकों' (Myths) का निर्माण करते हैं जिनके द्वारा जनता की दृष्टि में उनके वे काम तर्कसम्पन्न कार्यों की श्रेणी में गिने जाएँ और वे जनता को निपटवण में रख सकें।

मोस्का (Mosca)

पौरेटो को पॉल मोस्का भी अभिजन वर्ग में प्रत्यावर्तन के सिद्धान्त में विश्वास करता है। आदेश देने की अभिवृत्ति और राजनीतिक नियन्त्रण का प्रयोग करने की क्षमता को वह अभिजन वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। उसके अनुसार शासक वर्ग में जब यह अभिवृत्ति कम हो जाती है और शासक वर्ग से बाहर के लोग जब इन अभिवृत्तियों को विकसित करते हैं तब पुराने शासक वर्ग की पदस्थिति और उनके स्थान पर नये शासक वर्ग की स्थापना आवश्यक हो जाती है। मोस्का का मतना है कि यह एक प्रकार का सामान्य नियम है कि हमने समय तक शासन कर लेने के बाद शासक वर्ग या तो जन साधारण को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पाता या जो सुविधाएँ वह देता है वे जन साधारण को दृष्टि में महत्वहीन हो जाती हैं अथवा किसी नए धर्म का उत्थान हो जाता है अथवा समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक शक्तियाँ नये ऐसा कोई परिवर्तन आ जाता है और इस स्थिति में सत्ता परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। मोस्का आदर्शवाद तथा मानवतावाद का उतना कठोर आलोचक नहीं है जितना पौरेटो, साथ ही बल प्रयोग पर भी उसका अधिक आग्रह नहीं है। वह एक गतिशील समाज में और सभ्यता-बुझाने के द्वारा परिवर्तन लाने के तरीके में विश्वास रखता है। उसने शासक अभिजनों को यह सलाह भी दी है कि वे जनमत में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक व्यवस्था को धीरे धीरे उन परिवर्तनों के अनुसार ढालने की कोशिश करें। मोस्का ने अभिजन वर्ग में सम्मिलित सामाजिक समूहों के गठन की गहराई से व्याख्या की है और अन्य 'सामाजिक शक्तियों' को समुचित करने और उनके प्रभाव को सीमित करने में उन सामाजिक शक्तियों को, जिनको पौरेटो ने 'शासक वर्ग से बाहर' का अभिजन वर्ग बताया था, भूमिका की स्वीकार किया है।

मोस्का ने अभिजन वर्ग में 'उप-अभिजन वर्ग' की संकल्पना दी जिससे उसका अर्थ लोक सेवकों, औद्योगिक व्यवस्थापकों, वैज्ञानिकों और विद्वानों के नये मध्यम वर्ग (अभिजन वर्ग) से था और जिसे उसने समाज के प्रशासन का आवश्यक तत्व बताया। उसके अनुसार किसी भी राजनीतिक अवयव का स्थायित्व नैतिकता, कुशाग्रबुद्धि और कार्य कुशलता के उस स्तर पर निर्भर करता है जिसे समाज का दूसरा स्तर प्राप्त कर चुका होता है।

मिचेल्स (Michels)

जिन अन्य व्यक्तियों ने अभिजन सिद्धान्त को आगे बढ़ाया है उनमें रोबर्टो मिचेल्स और ओट्टो वार्ड गैसेट के नाम प्रमुख हैं। रोबर्टो मिचेल्स का नाम 'स्वल्पतन्त्र के सौह नियम' (Iron Law of Oligarchy) के सिद्धान्त से जुड़ा हुआ है जिसे वह इतिहास के सौह नियमों में एक ऐसा नियम मानता है जिसके पक्षों से अधिक से अधिक लोकतांत्रिक सफलताएँ, और इन सफलताओं में अधिक, वे अधिक, राजनीतिक दल हार कर नहीं निकल सके हैं।¹

इस नियम का सबसे ज्यादा समर्थन सगठन के तत्व द्वारा मिलता है। सगठन के बिना आधुनिक युग में आन्दोलन अथवा राजनीतिक दल सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सगठन वास्तव में स्वल्पतन्त्र का ही दूसरा नाम है। मिचेल्स लिखता है "मनुष्यों के प्रत्येक ऐसे सगठन में जो निश्चित सत्त्वों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है अन्तर्गत स्वल्पतांत्रिक प्रवृत्तियों मौजूद रहती हैं। स्वल्पतन्त्र महान सामाजिक समुच्चयों के सामान्य जीव का एक पूर्ण निर्यात रूप होता है। मनुष्यों के बहुमत के लिए गुलामी की अपने शास्वत मनोवृत्ति के कारण, एक अल्पसंख्यक वर्ग के प्रभुत्व को मानना उसकी अपनी पूर्व निर्यात है।"

सामाजिक जीवन के सभी रूपों में नेतृत्व एक आवश्यकता है। सभी व्यवस्थाओं और सभ्यताओं में कुलीनतन्त्र की विशेषताओं का प्रदर्शन होता है।² जैसे किसी आन्दोलन या राजनीतिक दल का विस्तार बढ़ता है तब उतरदायी नेताओं के एक आन्तरिक समूह के हाथों में सत्ता सौंप दी जावे और समय के साथ-साथ सगठन के सदस्य उन्हें निर्देशित

1 एल्फ्रेड द ग्रेजिया टैबर्टो मिचेल्स फर्स्ट लेक्चर्स इन पोलिटिक्स सोशियोलॉजी, पृ 142

2 रोबर्टो मिचेल्स वही 11 32 390 400 402

भारतीय राजनीतिक विचार (Indian Political Thought)

प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक भारत में मनु, याज्ञवल्क्य, वृहस्पति, शुक्राचार्य, कौटिल्य, राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविन्द रानडे, बासु मंगलचर, तिलक, स्वामी विवेकानन्द, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, एम. एन. राय, भीमराव अम्बेडकर, रामफरोहर लोहिया, तथा स्वामी नईकर एवं अन्य ऐसे राजनीतिक विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाया है। यहाँ इन विचारकों के प्रमुख विचारों की जानकारी दी जा रही है।

मनु (Manu)

वैदिक काल में मनु नामक राजर्षि हुए जिनकी कृति 'मनुस्मृति' को स्मृतिग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन भारतीय साम्यता के ऐतिहासिक विकास में मनु की 'मनुस्मृति' और याज्ञवल्क्य की 'याज्ञवल्क्य स्मृति' का योगदान रहा है। मनु और याज्ञवल्क्य द्वारा मान्य धर्म पर लिखे गए इन दो नीतिग्रन्थों ने हिन्दुओं की सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ये स्मृतियाँ प्राचीन वैदिक परम्परा के सुविख्यात ग्रन्थों और ऋषियों द्वारा लिखी गई तथा वे सम्पूर्ण धर्म-संहिताएँ हैं, जिनमें आर्य जाति के सभी वर्गों और समूहों के लिए धार्मिक नियम दिए गए हैं।

मनु के राजनीतिक विचार

राज्य सम्बन्धी विचार

मनु ने मनुस्मृति के सातवें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन किया है। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा मानी गई है, उसमें सामाजिक अनुबन्ध-विधान का आशय होता है। यह उल्लेख है कि यदि काल में जब विश्व में कोई राजा नहीं था, बलवानों के बल से लोग इधर-उधर भागते-फिरते थे। उनकी रक्षा के लिए ईश्वर ने इन्द्र, वायु, सूर्य, अग्नि, यक्ष, चन्द्रमा, कुबेर आदि देवताओं के सारभूत अंगों से राजा का निर्माण किया तथा राज्य एवं राजा की उत्पत्ति हुई। यद्यपि यह राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धान्त (Divine Origin of State) है, तथापि सामाजिक सविदा की भावना इसमें अन्तर्निहित है। मनु और याज्ञवल्क्य ने राज्य के सावधान्य स्वरूप की कल्पना की है। दोनों ने राज्य को राजागी माना है। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं—(1) स्वामी (राजा), (2) मन्त्री, (3) पुर (अर्थात् किने, फाकोटे आदि से सुशोभित राजधानी), (4) राष्ट्र, (5) कोष, (6) दण्ड एवं (7) मित्र। मनुस्मृति में राजतन्त्र का उल्लेख है, अतः प्रतीत होता है कि इस काल में राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली ही प्रमुखतया विद्यमान थी। मनु के अनुसार राजा के कार्यक्षेत्र में सभी वर्गों से स्वधर्म और सामान्य कानूनों का अनुपालन, गन्तव्य राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना, राज्य को बाह्य विप्लव से मुक्त रखना, मनुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण के लिए आवश्यक कानून बनाना, विभिन्न समूहों तथा परिवारों एवं आर्थिक समूहों के बीच उठने वाले विवादों का निर्णय करना, वैश्यों को व्यापार-वृद्धि-प्रशुफलान् आदि के लिए विवश करना, शूद्रों को बाह्य सेवा के लिए बाध्य करना, वर्ग-संघर्ष को रोकना, शिशा का प्रसार करना, राजकीय व्यय के लिए विविध कर संग्रह, आपराधियों को दण्ड देना आदि सम्मिलित हैं।

राजा सम्बन्धी विचार

मनु ने अनेक देवताओं के सारभूत नियम अंश को लेकर राजा की सृष्टि करने का जो उल्लेख किया है उससे राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त में विश्वास प्रकट होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा में दैवी अंश की कल्पना की गई है। मनुस्मृति में यहाँ तक लिख दिया गया है कि विभिन्न देवता राजा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और राजा स्वयं एक मष्टान् देवता बन जाता है। मनु के अनुसार राजा बाह्यों के प्रति सदैव सेवाशील और निष्पक्ष रहें। राजा जितेन्द्रिय बने,

शासन सम्बन्धी विचार

मनु ने शासन सम्बन्धी सिद्धान्तों, मंत्रियों राजा और मंत्रियों के सम्बन्धों, राजा द्वारा मंत्रियों से पारमर्श अथवा मन्त्रणा की प्रक्रिया और महत्त्व, राज्यकर्मचारियों आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। मनु का अभिमत है कि शासन का सर्वोपरि सत्य प्रजा की हर प्रकार से हित-साधना है। मनु ने कहा है कि शासन धर्म, अर्थ और काम के पालन में स्थापना करे, राजा (शासन) अग्रगण्य भूमि और वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे, प्राप्त भूमि और वस्तुओं को रक्षा करे, रक्षित भूमि और वस्तुओं का संवर्धन करे और जो वृद्धि हो उसका सुधारों में दान करे ताकि प्रजा में संतोष और सौन्दर्यिता का विस्तार हो। राज्य के रक्षण, शत्रुओं का वध, दुष्टों का दमन, प्रजा का हितवर्धन, राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों का समुचित नियन्त्रण और निरीक्षण, भ्रष्टाचार का उन्मूलन आदि ये मूल सिद्धान्त और सत्य जिन्होंने पूर्ण की दिशा में शासन को चलाना चाहिए। मनु ने राजा को राज्यकर्ष में पारमर्श देने के लिए मंत्रियों की व्यवस्था की है। 'मन्त्रि-परिषद्' शब्द का उल्लेख मनुस्मृति में नहीं आया है। मनुस्मृति में 'सचिव, और पाण्डित्य्य स्मृति में 'मन्त्री' शब्द आये हैं। मनुस्मृति में 'सचिवान्' अर्थात् सचिव शब्द के बहुवचन का प्रयोग हुआ है जिससे मन्त्रि-परिषद् अथवा मन्त्रिपरिषद् का अर्थ लिया जा सकता है। मनु के अनुसार अकेले आदमी के लिए सरल काम भी निष्पन्न हो जाते हैं, अतः शासन के जटिल कार्यों के निर्वहन में पारमर्श और सहायता के लिए राजा को मन्त्री नियुक्त करने चाहिए। मनु और पाण्डित्य्य ने मन्त्रणा के महत्व को समझा है और यह अवस्था दी है कि राजा को शासन-कार्य में मंत्रियों से एकान्त में अलग-अलग अथवा आवश्यकतानुसार समुक्त मन्त्रणा करनी चाहिए। मन्त्री इतने ही नियुक्त करने चाहिए जिनसे कार्य चमक उठे। मंत्रियों को उनकी आवश्यकतानुसार कार्य सौंपना चाहिए। मन्त्रणा में गोपनीयता के सिद्धान्त का अनुपालन किया जाना चाहिए।

राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्बन्ध में भी मनु ने नीति-सुलभ व्यवस्था दी है। यह निर्देश है कि प्रशासनिक नीति और कार्यों के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कर्मचारी और अधिकारी वर्ग ईमानदार, अनुभवी, बुद्धिमान और कर्तव्य-परायण होने चाहिए, प्रष्ट अधिकारियों के प्रति राजा को कठोर व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मन्त्रवृत्त गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रदेशिक प्रशासन सम्बन्धी विचार

मनु ने भूमिगत आधार पर राज्य को चार (अथवा दूरी और राह में विभाजित किया है। पुर या दुर्ग से आसपास राजधानी से है जो चारों ओर से सुरक्षित भूमिधर्मों से घेरकर और ३३ प्रकार से स्वस्थ भू-भाग में बसाई जानी चाहिए। शासन व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए राष्ट्र को छोटी-बड़ी बस्तियों और क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में 1 ग्राम 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1000 ग्रामों के अलग-अलग संगठनों की व्यवस्था है। ग्राम की सबसे छोटी इकाई माना गया है जिसके अधिकारी को ग्रामिक कहा गया है। मनु के अनुसार ग्रामिक का मुख्य कार्य ग्राम में शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा राजस्व को एकत्रित कर 10 ग्राम के अधिकारी के पास भेजना है। सभी संगठनों के लिए अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। 10 ग्रामों के संगठन के अधिकारी को दस ग्रामपति और 20, 100 तथा 1,000 ग्रामों के अधिकारियों को इम्पार, विराटी, राती (राताध्यक्ष) और सहस्रपति कहा गया है। इन सभी अधिकारियों के कार्य और दायित्व अपने अधीनस्थ और उच्चाधिकारियों के प्रति उसी प्रकार माने गए हैं जैसे ग्रामिक के 10 ग्रामपति के प्रति। सभी अधिकारियों के वेतनों का उल्लेख है। राष्ट्र में ग्रामों के अलावा नगरों का उल्लेख भी आया है, जो काफी कम थे। नगर के अधिकारी को 'स्वार्थचिन्तक' नाम दिया गया है जिसका स्पष्ट आशय यही है कि वह अधीनस्थ प्रजा के हितों की चिन्ता करना सर्वोपरि कर्तव्य माने।

परिषद् अथवा विधायिका

मनुस्मृति में 'परिषद्' शब्द आया है जिसका आशय विद्वान् व्यक्तियों की विधायिका से है। यह उल्लेख है कि परिषद् में तीन से दस सदस्य होने चाहिए। कम से कम तीन व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग वेद का प्रकाण्ड पण्डित हो। यदि परिषद् में समुचित विद्वान् 111 व्यक्ति मिलें तो वेदों के ज्ञाता 3 व्यक्तियों को पर्याप्त माना गया है, अन्यथा एक व्यक्ति ही उचित समझा गया है बशर्त कि वह राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करने की क्षमता रखता हो। मनुस्मृति में कुत्स, जाति, त्रेणी और जनपद नामक जनता की सप्तीय संस्थाओं का भी उल्लेख है और राजा का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह उन संस्थाओं द्वारा अपने लिए बनाए गए नियमों को स्वीकृति प्रदान करे। मनु ने राजा के न्यायपूर्ण आचरण पर बल दिया है। दण्ड को न्याय का स्थापक माना है। लोग दण्ड के कारण स्थिर रहते हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह देश, काल, अपराध की गुरुता आदि पर विचार करके अपराधियों को उचित दण्ड दे। दण्ड शक्ति के बल पर राजा राज्य कर सकता है। प्रजा का रक्षक दण्ड ही है। समुचित दण्ड व्यवस्था के

वैकल्पिक नीतियों एवं कार्यों को बताया गया है। तत्कालीन जटिल राजनीतिक वातावरण को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने अपने निजी शब्दों का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र को उस समय स्थित राजनीति के प्रयोगों पर ही आधारित नहीं रखा, बल्कि अपने उस व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान पर अश्रित रखा जो उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति और समस्याओं का अध्ययन करने पर प्राप्त किया था।

सामाजिक व्यवस्था—अर्थशास्त्र का प्रारम्भ समाजों के उद्देश्य की परीक्षा से होता है जबकि मानवीय अस्तित्व की योजना में त्रयी, अर्थात् धर्म, धन और दण्ड का सही स्थान निर्धारित किया जा सके। ये सभी मानवीय ड्रम के प्रकाश हैं। इनके द्वारा जीवन के सब धर्म एवं महान् कार्यों को आसानी से पूरा किया जाता है। ग्रन्थ में स्वाभाविक एवं कृत्रिम शास्त्रों, धर्म और अधर्म, नय और अनय तथा उचित और अनुचित के बीच अन्तर बतलाया गया है। यह ग्रन्थ मनुष्य व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था का आधार मानकर चलता है। इसमें सभी के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। सत्यवादिता, शुद्धता, सहिष्णुता, क्षमाशीलता तथा किसी को नुकसान न पहुँचाना आदि व्यवहार व्यक्ति को स्वर्ग से जाते हैं। एक सुशिक्षित स्वामी अनुशासित रूप से कार्य करते हुए तथा श्रेष्ठ सरकार की सहायता प्राप्त करते हुए समस्त पृथ्वी का निर्वाचन रूप से उपयोग करता है। ग्रन्थ में पार्वतों, पुण्ड्रितों, मन्त्रियों आदि की योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं और गुणवत्ताओं द्वारा मन्त्रियों के चरित्र एवं आचरण की परीक्षा करने आदि का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त राजा और सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य बतलाए गए हैं। राज्य के विभिन्न विभागों का वर्णन है जो अलग-अलग अक्षय के अधीन रहकर अपने-अपने क्षेत्रों में प्रक्रिया तथा प्रशासन का निपटारा करते हैं।

कानून, न्याय एवं दण्ड व्यवस्था—अर्थशास्त्र के कुछ अध्यायों में नागरिक कानून की व्यवस्था की गई है। इसमें समझौते एवं संधिदाओं की कानूनी प्रक्रिया का वर्णन और वैधानिक झगड़ों की सुलझाने के लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके बाद पौरजदार कानून अर्थात् कस्टम शोधन का वर्णन किया गया है तथा ऐसे अनेक प्रवास वर्णित किए गए हैं जिनके द्वारा कारीगरों, व्यापारियों तथा श्रमसैनिक अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य जनता की रक्षा का जा सके। इसके कुछ अध्याय शांति और युद्ध नीति, बाढ़ छत्रों की प्रकृति, आक्रमणकारियों एवं शक्तिशाली राज्यों के कार्य, युद्ध और रणनीति तथा राजा को समायोजन करने के गुण बताते हैं एवं साम्राज्य को बढ़ाने के साधनों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दण्ड नीति को सभी पुरुषों का स्रोत माना गया है। जीवन और सम्पत्ति की रक्षा तथा वर्णाश्रम धर्म का पालन केवल एक मुख्यवस्तुत्व एवं सुखसाधित समाज में हो सकता है। दण्डपर सत्ता में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को धारण करने वाला होता है। जब तक वह इनकी रक्षा करता है, वह अन्तरिणील होते हुए जीवन को आनन्ददायक बनाने में मदद करता है, किन्तु जब दण्डपर कमजोर होता है और सम्प्रभुता की रक्षा नहीं कर पाता तो नैतिक एवं आधिपतित्व अस्तित्व के ये साधन जीवन को नष्ट कर देते हैं। राज्य शक्ति के अभाव में मानवीय आत्मा दुर्बल हो जाती है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती। वर्णाश्रम धर्म तथा अर्थ और काम सम्पूर्ण सकृति और सम्यक्ता के आधार हैं इसलिए इनकी स्थापना हेतु अर्थशास्त्र ने राज्यशक्ति का संगठन किया है। ग्रन्थ ने इन विभिन्न आपत्तियों का वर्णन किया है जो साम्राज्य को एकीकृत करने में आन्तरिक और बाह्य रूप से आ सकती हैं। आन्तरिक रूप से वह होता था जो मन्त्री, पुण्ड्रित, सेनपति और दुबयन द्वारा उत्पन्न किया जाता था। अनेक सक्त सभों, श्रेणियों एवं नियमों द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। स्वामी के आपत्तियों अनेक बार सक्तों के कारण बन जाते हैं, अतः उसे अपनी भावनाओं, श्रेष्ठ कार्यरता आदि के प्रति आन्तरिक सजगता रखने को कहा गया है। राजा को असुविधा जीवन की विशेषताएँ अपने व्यवहार में से पूर्ण रूप से समाप्त करने का निर्देश है। कौटिल्य के कथनानुसार, "जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण नहीं है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा चाहे वह सम्पूर्ण पृथ्वी का स्वामी ही क्यों न हो।"

सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार—जहाँ तक सरकार के रूपों का सम्बन्ध है अर्थशास्त्र इतना अधिक विवश नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायी केन्द्रीकृत एवं कार्यकुशल सरकार प्रस्तुत करना था जो जनता को शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उसकी नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक बन सके। इसमें उन गणगणों का विशेष किया गया है जो शक्तिशाली सरकार रखने में असमर्थ होते हैं। ये कमजोर गणराज्य विघटनकारी प्रकृतियों एवं बाह्य आक्रमणों को आमंत्रित करते हैं। एकता और संगठन प्रत्येक राज्य का एक मुख्य आधार माना गया है। इसके अभाव में वह राज्य किसी भी सेना के द्वारा जीता जा सकता है। गणराज्य यदि शक्तिशाली है तो अर्थशास्त्र उसका आदर करने को तैयार है।

मन्त्री—मन्त्रियों की व्यवस्था एवं देखरेख पर अर्थशास्त्र ने पर्याप्त जोर दिया है। राजा की सत्ता के लिए सर्वाधिक गम्भीर खतरा और साम्राज्य के विनाश का स्रोत मन्त्रियों की महत्वाकांक्षा होती है। यही कारण है कि मन्त्रियों के आचरण के लिए उच्च मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इस पद के लिए उच्च योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। मन्त्रियों के द्वारा राज्य के सारे कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। उनके द्वारा ये प्रमुख शक्तियाँ निहित रहती हैं इसलिए अर्थशास्त्र ने स्वामी को इनके विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए सजग रहने को कहा है। यदि राजा को यह अन्देश हो कि आन्तरिक और बाह्य

स्थानीय प्रशासन

कौटिल्य ने स्थानीय प्रशासन के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उस समय राज्य के दो भाग किए जाते थे—दुर्ग और जनता। कौटिल्य ने दुर्ग को पुर अथवा नगर का पर्यायवाची माना है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग को चार भागों में बाँटा जाना चाहिए और प्रत्येक भाग के लिए एक स्थानिक नाम का कर्मचारि नियुक्त किया जाना चाहिए। स्थानिक के अधीन गोप नामक कर्मचारी रखे गए हैं। उस युग में इन कर्मचारियों को उन सगठनों के ऊपर नियुक्त किया जाता था जो 10, 20, 40 कुटुम्बों के समूह से संगठित किए जाते थे। इन ग्रुपों का यह काम था कि वे अपने अधीन कुटुम्बों के सदस्यों की जनगणना करें, उनकी आय-व्यय का ब्यौटा रखें तथा उससे अपने स्थानिक को पतिवित्त करावें। स्थानिक इस सूचना को नागरिक तक पहुँचाता था। नागरिक नगर के अध्यक्ष को कहते थे। उसका मुख्य कर्तव्य अपने नगर में शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना था। इस उद्देश्य की पूर्ण करने के लिए उसे अनेक कार्य सम्पन्न करने होते थे, जैसे रात्रि में राहगीरों के ठहरने के नियम बनाना और रात्रि के समय नगर में आगमन सम्बन्धी नियम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना आदि। स्थानीय प्रशासन का दूसरा अंग जनपद था। कौटिल्य के अनुसार जनपद के मध्य और अन्त में दुर्ग होने चाहिए जो आपसित बजान में अपने जनपद के निवासियों और बाहर से आने वाले व्यक्तियों के भोजन की दृष्टि से पर्याप्त सम्पन्न हो। जनपद की रक्षा के लिए कौटिल्य ने विभिन्न बस्तियों बनाने की योजना प्रस्तुत की है। उनके कथनानुसार शासन कार्य एवं राजकीय के समय की दृष्टि से दस गाँवों के बीच सत्रहवा, दो सौ गाँवों के बीच स्रवटक, चार सौ गाँवों के बीच प्रोममुख और आठ सौ गाँवों के बीच स्थानीय नाम की बस्तियाँ बनानी चाहिए। कौटिल्य का कहना था कि जनपद में एक अथवा दो कोस के अन्तर पर ग्राम की स्थापना करनी चाहिए ताकि वे एक-दूसरे की रक्षा करने में समर्थ हों। इन गाँवों में अधिकतर सख्त रित्तियों एवं विज्ञानों की होनी चाहिए। एक गाँव में कम से कम सौ और अधिक से अधिक पाँच सौ घर होने चाहिए। ग्राम के शासन का सञ्चालन गाँव के बृद्धों एवं ग्रामिक के द्वारा किया जाना चाहिए।

न्यायिक व्यवस्था

कौटिल्य ने स्वधर्म पालन को मनुष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है। इस कर्तव्य की पूर्ण करने ही व्यक्ति इस लोक वा सुख और परलोक का आनन्द प्राप्त कर सकता है। स्वधर्म पालन का कर्तव्य ऐसा है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पूर्ण करने के लिए इच्छुक नहीं होता, जब तक ऐसा करने के लिए उसे पुरस्कृत या दण्डित न किया जावे। ऐसी स्थिति में न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाना अत्यन्त आवश्यक है। कौटिल्य का मत है कि उचित न्याय विवरण करने के लिए सरकार द्वारा न्याय की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण केंद्रों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की जा सके। न्याय कार्य को कौटिल्य ने दो क्षेत्रों में विभजित किया है—व्यवहार (दीवानी) और कष्टक शोधन (फौजदारी)। प्रथम क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिकों के पारस्परिक सम्पर्क को लिया जाना चाहिए। नागरिकों के मध्य होने वाले कन्हा के मूल कारणों को खोज कर न्यायालय को उनकी विवेचना करना और निर्णय के आधार पर दोषी को उचित दण्ड देने चाहिए। निर्दोषों को उसके अधिगार दिमाने की चेष्टा की जानी चाहिए। दूसरे क्षेत्र में मनुष्य जीवन के उस अंश को लिया गया है जिसमें व्यक्ति का राज्य के कर्मचारियों, व्यापारियों एवं व्यवसायियों तथा कुछ विशेष कोटि के दुष्ट व्यक्तियों से सम्बन्ध रहता है। इन विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा सामान्य लोगों का शोषण किया जाता है। उन्हें इस शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना किया जाना जरूरी है। ये दोनों क्षेत्र वर्तमान में क्रमशः दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों का क्षेत्र हैं। मनु ने व्यवहार के क्षेत्र को निर्धारित करके उसके विषयों को सूचीबद्ध किया है, किन्तु कौटिल्य ऐसा न करके उनका अनन्त वर्णन करते हैं। इस क्षेत्र में जो विभिन्न विषय आते हैं, वे—स्त्री, पुरुष की धर्म व्यवस्था, परस्त्री हरण एवं परस्त्री का परपुरुष से सम्बन्ध, दाय भाग, अश्व विभाग, पुर विभाग, वस्तु विवाद, ऋण लेकर न देना अथवा बिना दिए माँगना, स्वामी रहित वस्तु का विक्रय, सझे का व्यापार, दान, वेत्त, प्रतिज्ञा का भंग करना, दास कार्य ब्रह्म-विक्रय विवाद, पशु स्वामी तथा पशु विवाद, सीमा विवाद, डाक-चोरी, भाषाद, कटोर वस्त्रों का प्रयोग आदि। इन विभिन्न विवादों को सुनाने के लिए कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया है। न्यायालय छोटे और बड़े विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। इन न्यायालयों की स्थापना विभिन्न बस्तियों में की जानी चाहिए तथा इनमें विवादों को सुनने और उन पर निर्णय देने के लिए तीन न्यायाधीश और तीन अमात्य होने चाहिए। स्थानीय महत्व के विवादों को सुनाने के लिए स्थानीय न्यायालयों की स्थापना करना बताया। न्याय कार्य का सम्पन्न ग्राम के बृद्धों एवं ग्राम सामन्तों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि किसी विषय पर वे एक मत न हो सकें तो गाँव के धार्मिक लोगों से अनुमति लेकर निर्णय लेना चाहिए। न्याय के क्षेत्र में मध्यस्थता के मिश्रण को पर्याप्त महत्व दिया गया है। विवाद में सम्बन्धित दोनों पक्ष किसी व्यक्ति को मध्यस्थ बनाकर उससे विवादप्रस्त विषय का निर्णय करा सकते हैं। मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को अनिवार्य

रामदा जात चाहिए। कौटिल्य ने न्यायालयों की कार्य प्रणाली का विस्तार के साथ वर्ण किया है। उनके मतानुसार अर्थ प्रस्थाओं एवं साधुओं को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस स्वतन्त्रता के हान करने वाले प्रत्येक न्यायाधीश एवं कर्मचारी को दण्ड का भोग्य माना गया। कौटिल्य के अनुसार, "भटना चाहे बितनी पुतानी हो जाए उसके प्रमाणित हो जाने पर छोटी को अवश्य दण्ड दिया जाए और अपकारी को छोड़ना नहीं चाहिए।" कौटिल्य पूर्व निर्धारित विचारों पर निर्णय लेने का विरोध करते हैं। जो व्यक्ति साक्ष्य द्वारा सच्चा प्रमाणित हो जाए उसे ही सच्चा मानना चाहिए। व्यवहार क्षेत्र में कौटिल्य ने साक्षी का पर्याप्त महत्व बताया है। वे साक्ष्य को लिखित प्रमाण, भोग प्रमाण और शपथ प्रमाण इन तीनों भागों में विभाजित करते हैं। प्रमाणों की सत्यता को परखने के लिए उन्होंने भेदक तरीके बताए हैं। महत्त्वपूर्ण अभियोगों में जहाँ द्वारा प्राप्त सूचनाएँ भी उपयोग्य थीं। अपराधों का दूसरा क्षेत्र कौटिल्य द्वारा कष्टक शोधन कहा गया है। इसके अन्तर्गत उन तथ्यों का वर्णन है जिससे राज्य के व्यवसायों एवं दुष्ट जनों से प्रजा की रक्षा हो सके। कौटिल्य का मत है कि यदि राज्य के विभिन्न व्यवसायियों पर निबन्धन न लगा गया तो वे प्रजा का हाहण्य एवं पीड़न करने लगेंगे। कम लेना-बिक्री के मास में गिरावट करा, अराज्य के तम पर दंडित करना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना आदि क्रियाओं से व्यापारी वर्ग भोली भानी प्रजा को ठग सकता है इसलिए उन पर निबन्धन रखना अनिवार्य है। कौटिल्य ने व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न नियमों का उल्लेख किया है और बताया है कि जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा वह राज्य के दण्ड का पागोदार होगा। व्यावसायिकों की भाँति राज्य के कर्मचारियों पर कड़ा निबन्धन रखने की बात कही गई है ताकि वे स्वार्थित होकर अपने कर्तव्य पालन के मार्ग से हट न जाएँ। इस मार्ग की दृष्टिकोण के लिए धर्मों का व्यवस्था की गई है। कौटिल्य के अनुसार दुष्ट कर्मचारियों को उनके दोष के अनुसार दण्ड देकर उनके आचरण की गतिर रूढ़ि करना चाहिए ताकि राज्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रजा का कल्याण कर सकें। दुष्ट जनों से राज्य की सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने की आशंका रहती है। चोर, डाकू, व्यभिचारी, बन्धक, धातक आदि होने पर लोगों का जीवन निर्भयता एवं सुख के साथ व्यतीत नहीं हो सकता। राज्य को इन दुष्ट जनों से प्रजा की रक्षा के लिए पुनिता एवं धर्म आदि की नियुक्ति करनी चाहिए। अपराधी कर्मचारियों को दण्ड देने का व्यवस्था की गई है। शत्रुओं अपना बरसमानों से बहुमुख्य भाग चुनने वाले कर्मचारियों को गुरु दण्ड देने और कम कीमत वाली वस्तुएँ चुराने पर केवल जुर्माना करने का उन्मेष है।

दण्ड व्यवस्था

अपराधी को दण्ड देते समय किन तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए, इस सम्बन्ध में कौटिल्य ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि दण्ड को निर्धारित करते समय अपराध की मात्रा, अपराधी की सामर्थ्य, अपराधी का वर्ग, अपराधी में सुधार की सम्भावनाओं आदि बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने दण्डों को तीन भागों में विभक्त किया है—अर्धदण्ड, शारीरिक दण्ड और बचतगार (बाल्यार) दण्ड। अर्ध दण्ड के अन्तर्गत हम ठर दण्डों को समझित कर सकते हैं जो जुर्मन के रूप में अपराधियों को देने पड़ते थे। ये पण के आठवें भाग से लेकर सहस्रों पण तक निर्धारित किए जा सकते थे। अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता लगता है कि आर्थिक दण्ड का प्रयोग दीवानी अभियोगों तथा कम महत्व के सैन्यदारी अभियोगों में किया जाया था। जो मनुष्य जाना बिठाकर, फँसाकर या अन्य किसी प्रकार से शरीरगत एवम्भीय मृग, पशु, पक्षी, मछली आदि पकड़े उससे उनकी कीमत वसूल की जाती चाहिए तथा उन पर उक्त ही जुर्माना किया जाना चाहिए। शिल्पियों के छोटी मोटी वस्तुओं की चोरी पर एक सौ पण का और छोटी के सामान चुराने पर दो सौ पण का जुर्माना करने का कहा गया है। कौटिल्य शारीरिक दण्ड को कायदण्ड का नाम देते हैं। अपराध के अनुसार यह दण्ड छोटा-बड़ा होता है। दण्डों में बेल गालन, गोदरे लगाए, रस्सी से बांधना, उन्हें सड़कना, हाथियों से कुचलना कर प्राण लेना, हाथ पैर आदि अंगों को कटवाना, शरीर एवं शरीर पर जलते हुए अंगारे रखकर प्राण लेना जल में डुबाना शरीर की छात्र निकलवाना तथा वष कर देना प्रमुख थे। तीसरे प्रकार का दण्ड बचतगार दण्ड और बन्दीगृह के अधिकारी को बचतगारप्रभय कहा गया है। उस समय बन्दीगृहों में स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाती थी। इसमें अनेक कोठरियाँ होती थी तथा इनकी सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाता था। बन्दीगृह में रहने वाले अपराधियों को सामान्य सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। उनकी स्वातन्त्र्य के अनुसार उनसे काम लिया जाता था। समय समय पर उनके आचरण तथा व्यवहार की जाँच की जाती थी और उसके आधार पर उनसे सलूक किया जाता था। बन्दीयों पर कठोर अनुशासन रखा जाता था। कौटिल्य ने दण्ड सिद्धान्त में विशेष परिस्थितियों को पर्याप्त महत्व दिया है। उदा. युग में दण्ड के भय से आतंक पैदा करने की चेष्टा की जाती थी, अपराधी को अपमानित एवं सज्जित किया जाता था। बन्दीयों के आचरण को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए जाते थे।

आर्थिक व्यवस्था

अर्थशास्त्र में राजनीति के साथ उन विषयों का भी अध्ययन किया गया है जो धन से सम्बन्ध रखते हैं।

राज्य कोष—कौटिल्य ने राज्य के लिए कोष को अत्यन्त उपयोगी माना है। व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत कार्य धन के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता जो राज्य सम्पन्न जैसा महान् कार्य इसके बिना कैसे सम्पन्न किया जा सकता है? राज्य कोष के आधार पर ही सेना का संगठन करता है और अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है। कोष वृद्धि के लिए राज्य को क्या उपाय अपनाने चाहिए, इस सम्बन्ध में कौटिल्य ने राज्य के कोष-संचय के लिए कई मार्ग बताए हैं। इन मार्गों को अन्ध-शरीर और अन्ध-मुख नाम की दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौटिल्य ने इन दोनों श्रेणियों में आने वाले अन्ध के धनपनों की व्याख्या की है। कौटिल्य ने अप्रतिफल में कोष संचय के लिए कुछ विशेष सिद्धान्तों की रचना की है। सक्दकाल में राज्य के कार्य को चलाने के लिए विशेष स्तों से आय प्राप्त की जान का व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए राज्य के जिन भागों में पर्यटन वर्षा होती है और जहाँ अन्न का उत्पादन पर्याप्त होता है उनसे राजा अन्न का एक-तिहाई या एक चौथाई भाग माँग सकता है। दूसरे, उपरिष्ठ अनाज में से बीज तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए छोड़ कर अधिक अनाज को खरीदा जा सकता है। तीसरे, समस्त किसानों को सनझकर गर्मी में फसल कटा सकता है चौथे व्यक्तियों से धन माँगा जा सकता है। पाँचवें, पशु रखने वालों से उनके पशुओं की आपी आय राज्य को देने के लिए कड़ा जा सकता है। छठे, धन एकत्रित करने के लिए गुप्तचरों की सहायता ली जा सकती है। सातवें धार्मिक सन्धियों के अभ्यस धन संग्रह में राज्य की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार सक्दकाल में राज्यकोष के लिए धन एकत्र किया जाता है।

कोष संचय के अतिरिक्त कौटिल्य ने उन कारणों का भी उल्लेख किया है जिनसे कोष को समृद्ध बनाने में सहायता प्राप्त होता है। प्रथम राज्य के निवासियों को सब तरह से सम्पन्न और समृद्ध होना चाहिए। दूसरे, निवासियों का आचरण तथा व्यवहार भ्रष्टाचार रहित हो। तीसरे, राज्य की आय का कर्मचारियों या किसी के द्वारा अपहरण न किया जाए। चौथे, राज्य के कर्मचारियों की सख्या केवल उतनी ही होनी चाहिए जितनी की आवश्यकता हो। पाँचवें, राज्य का उद्योग तथा व्यापार उन्नत होना चाहिए। छठे, राज्य में अन्न का उत्पादन अधिक होना चाहिए। कौटिल्य ने उन विभिन्न मार्गों का उल्लेख किया है जिनमें होकर राज्य की सचिव निधि का व्यय होता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस धन को गलत कार्य में नहीं लगाया जाए। कौटिल्य का कहना है कि देव पूजा, पित्र पूजन, दान, अन्तर्पुर, राजकीय स्तों, दूत, कोष्टागार, शस्त्रागार, पशु गृह, उद्योग-धर्मों में कार्य करने वाले, बेगार, पैदल अश्वारोही, हस्तारोही, और रथारोही सना, गौ मण्डल, पशु, मृग, पक्षी तथा सर्प आदि जन्तुओं का संग्रह, काष्ठ, तृण, बगीचों की रक्षा आदि के कार्यों में राजकोष का व्यय होना चाहिए। इन विभिन्न विषयों में धन की कितनी मात्रा लगाई जाए वह भी कौटिल्य ने निर्दिष्ट किया है। सावर्जनिक व्यय के सम्बन्ध में कौटिल्य ने जो निष्ठा है कि वह अत्यन्त स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं विस्तृत है।

कौटिल्य ने कोष की वृद्धि के कारणों की भी विवेक के साथ के कारणों का भी उल्लेख किया है। उनके मतानुसार आठ कारणों से कोष का क्षय हो सकता है। ये हैं—प्रतिबन्ध, प्रयोग, व्यवहार, अवस्तर, परिहर्ण, उपभोग, परिवर्तन और अपहरण। जब लाभदायक कार्यों में धन की नहीं लगाना जाता अथवा लाभकारी कार्यों में लगाने पर धन ॥ प्रत्येक आय को राजकोष में जमा नहीं करवा जाता तो यह प्रतिबन्ध कहलाता है। कोष क्षय के दूसरे तथा तीसरे कारण का अनुसर राजकोष के धन की सार्वजनिक कार्यों में लगाने की अपेक्षा किसी लाभ के कार्यों में तथा निज व्यवहार में लगाना जाता है। ऐसा करने से राजकोष घटता जाता है। अवस्तर के अनुसार राज्य के धन की समय पर एकत्रित नहीं जाता था। जब भुगतान का समय नहीं होता है तब उसकी उगही की जाती है। राज्य के कर्मचारी सार्वजनिक समिति का उपभोग स्वयं करते हैं अथवा दूसरों से करते हैं। जब राजकोष के द्रव्यों की द्रव्यों में बदल दिया जाता है तो उसकी क्षति का सातवीं कारण परिवर्तन पैदा हो जाता है। अपहरण के उन्मर्गत प्राप्त धन को जमा नहीं किया जाता और व्यय किए बिना यह लिख दिया जाता है कि व्यय कर दिया गया। इन समस्त कारणों से सार्वजनिक धन का अभ्यय होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय (वैदेशिक) सम्बन्ध

मण्डल सिद्धान्त—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कौटिल्य ने राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन करने के लिए मण्डल सिद्धान्त का अश्रय लिया है। उन्होंने राज्यों का अति राज्य, मित्र राज्य, उदासीन राज्य तथा मध्यम राज्य के रूप में विभाजन किया है। इनमें से प्रत्येक राज्य का एक मण्डल होता है और उसमें वे चारों प्रकार के राज्य सम्मिलित रहते हैं। इन राज्यों को अलग-अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं और वे भिन्न-भिन्न वृहद् मण्डल की रचना करती हैं। मण्डल सिद्धान्त के अनुसार मण्डल का केन्द्रीय राजा 'विजिगिषु' राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को शत्रु समझते हैं अर्थात् उन्हें जटकर अपना राज्य सोपा में मिलाते की इच्छा रखता है। मण्डल सिद्धान्त के आधार पर कौटिल्य ने किसी राज्य के मित्र एवं शत्रु राज्य होने की व्याख्या की है।

बाह्यगुण्य नीति—अन्तर्देशीय सम्बन्धों का संचालन उपायों एवं बाह्यगुण्य के आधार पर किया जाता है। ये उपाय चार होते हैं—साम, दण्ड और वेद। इनके अतिरिक्त छ गुण या सहाय होते हैं—सन्धि, धिम्न, यान्, आसन, सश्रय तथा दैधी भाव। कौरविल्य ने इन उपायों तथा गुणों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इन्हीं प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए इनके प्रयोग के अवसरों की व्यवस्था की है। इन छ सहायों में सन्धि का आशय समझौता, विग्रह का अर्थ युद्ध, यान का तात्पर्य शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना, आसन का अर्थ तटस्थता, संश्रय से अधिप्राय बलवान का आश्रय लेना है और दैधी भाव से तात्पर्य सन्धि और युद्ध का एक साथ प्रयोग करना है। इन छ गुणों से समन्वित नीति परिचिति विरोध के अनुकूल अपनाई जानी चाहिए।

सेना एवं युद्ध

कौरविल्य ने सैनिक बल को राज्य की सम्पत्तियों में स्थान दिया है। उन्होंने सेना के छ प्रकारों का वर्णन किया है। ये हैं—घोस सेना जो राजधानी की रक्षा करती थी, वृत्त सेना जो घेतन भोगी सैनिकों से पूर्ण होती थी, श्रेणी सेना जो विभिन्न प्रदेशों में रखी जाती थी, मित्र बल अर्थात् मित्र राजा की सेना, शत्रु बल अर्थात् शत्रु राजा की सेना और अटवी बल अर्थात् जंगल की सुरक्षा के लिए नियुक्त सेना। सेना के इन प्रकारों की उपयोगिता उल्लेख पटती जाती है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान मित्र बल को तथा अन्तिम स्थान अटवी बल को दिया जा सकता है। सेना में वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया। कौरविल्य का कहना है कि युद्ध विद्या में कुराल एवं विनयशील धर्मिय सेना सबसे अच्छी होती है। कौरविल्य ने व्यूह तथा दुर्ग बना कर युद्ध करने के लिए कहा है। उनका मत है कि सेना की छाया से पौध सौ धनुष की दूरी पर दुर्ग बनाया जाए अपना भूमि की सुविधा के अनुसार व्यूह बनाया जाए और युद्ध किया जाए। व्यूह अनेक प्रकार के बनाए जा सकते थे। इनका वर्णन करने के लिए कौरविल्य ने यह बताया है कि अमुक व्यूह के विरुद्ध अमुक व्यूह की रचना विजय प्राप्ति के लिए फलदायक रहेगी। कौरविल्य ने युद्धों की प्रक्रियाओं के आधार पर चार भागों में विभाजित किया है—प्रकाश युद्ध, धर्म युद्ध, कूट युद्ध और गुणी युद्ध। इन चारों प्रकार के युद्धों का परिचयित के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। कौरविल्य सेना के चार अंगों—पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ में हस्तिबल (हाथियों की सेना) को श्रेष्ठ मानते हैं। पैदल सैनिकों में वंशानुगत सैनिक (मौल), वैतनिक (भुल्ल), श्रेणीगत तथा मित्र एवं कषापली सैनिकों को क्रमशः उच्चतर माना है। सेना मुख्यतः शत्रुओं की ही होनी चाहिए। कौरविल्य के अनुसार शत्रु पर विजय पाने हेतु तीन शक्तियाँ अपेक्षित हैं—(1) उत्साह शक्ति, (2) प्रभाव शक्ति एवं (3) धन्य शक्ति। धन्य शक्ति से तात्पर्य परामर्श सेना है। इनमें उत्साह शक्ति ही श्रेष्ठ होती है।

दूत एवं गुप्तचर

अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों एवं राज्य की आन्तरिक शान्ति-व्यवस्था के लिए गुप्तचरों तथा दूतों का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। कौरविल्य ने दूतों की राजा का मुख कहा है क्योंकि इनके माध्यम से वह अपनी बात अन्य राजाओं से कह पाता है तथा उनकी बात को सुन पाता है। कौरविल्य ने दूतों को उनकी योग्यता तथा अधिकारों में आधार पर तीन भागों में विभाजित किया है—निमुहार्थ, परिधितार्थ एवं शासनहर। इन तीनों प्रकार के दूतों के अधिकार तथा स्थिति के सम्बन्ध में कौरविल्य ने पर्याप्त लिखा है।

धर्म और नैतिकता

कौरविल्य का अर्थशास्त्र एक प्रकार से राजनीतिज्ञों के लिए निर्देशक ग्रन्थ है जिसके अनुसूतन के बाद वे राज्य की स्थापना करने तथा उसे बनाए रखने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते थे। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि ग्रन्थ द्वारा किसी आदर्श व्यवस्था का वर्णन किए जाने की अपेक्षा केवल व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार किया जाता। कौरविल्य के ग्रन्थ में हमें नैतिकता और धर्म की पूर्ण अवहेलना प्राप्त नहीं होती क्योंकि उनका अर्थशास्त्र हमसे पहले वेदों तथा स्मृतियों में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त इसमें राजा को पुरोहित की नियुक्ति करना अनिवार्य माना गया है। उसने बाह्यगुण्य की स्मृतियों की भीति सामाजिक तथा कानूनी विशेषाधिकार रखी है। इस सबसे यह प्रतीत होता है कि कौरविल्य राजनीति को धर्म और नीति से वंचित नहीं करना चाहते थे। कौरविल्य ने राजा के स्वैच्छाकारी करने के मार्ग में अनेक प्रतिबन्ध लगाए हैं। उनका कहना है कि राजा को सर्वे जन कल्याण के कार्य करने चाहिए और जो कर लगाया जाए वह न्यायोचित हो। राजा को अपने मंत्रियों पर कड़ा नियन्त्रण रखना चाहिए, वह सभी व्यक्तियों को न्याय प्रदान करे तथा जिन लोगों ने धर्म की सीमाओं का उल्लंघन किया है, उन्हें दण्ड दे। अर्थशास्त्र का राजा धर्म शास्त्रों एवं नीति शास्त्र के सुस्थापित सिद्धान्तों के अधीन कार्य करता है। इस रूप में वह अत्याचारी नहीं हो सकता। भारतीय जनता अत्याचारी शासन को सहन करने की अभ्यस्त नहीं थी। धर्म से दूँधा हुआ होने के कारण राजा प्रायः समस्या पर अपने मंत्रियों एवं परामर्शदाताओं से राय लेता था।

कौटिल्य का मूल्योत्कन एवं देन

डॉ. नाहर के अनुसार "कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन भारत की शासन-पद्धति, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का विस्तृत विवेचन है। ई. पू. चौथी शताब्दी के इतिहास के लिए इस ग्रन्थ से अच्छी सहायता मिलती है।¹ डॉ. आर. एस. त्रिपाठी के अनुसार "कौटिल्य अथवा चाणक्य चन्द्रगुप्त का प्रमुख मन्त्री था। उसका अर्थशास्त्र राजनीति और शासन पर एक अपूर्व ग्रन्थ है। इसके सैद्धान्तिक रूप के बावजूद भी भारतीय साहित्य में इसका स्थान अद्वितीय और अद्वितीय है।² डॉ. पी. एल. भार्गव के अनुसार "मेगस्थनीज का भारत-वृत्तान्त उस 'ग्रन्थ का बड़ा सटीक चित्र देता है जिसकी अनेक अंशों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूर्ति होती है।³ प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तकों में कौटिल्य का प्रमुख स्थान है। सालेयोर के अनुसार "प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है।⁴ रामास्वामी ने 'अर्थशास्त्र' के महत्व को इस प्रकार प्रकट किया है, "कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' कौटिल्य के पूर्व की रचनाओं में यत्र-तत्र बिखरी हुई राजनीतिक चतुर्थ एवं प्रशासन-कला के सिद्धान्तों का संग्रह है। कौटिल्य ने प्रशासन-कला के एक पुष्प एवं विराट विज्ञान की रचना करने के प्रयास में उनकी नवीन रूप में व्याख्या की है।⁵ कृष्णाएव का भी ऐसा ही मत है, "अर्थशास्त्र का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय पारलौकिकता की ओर राजनीति के आकर्षण की प्रवृत्ति के दोष का निपटारा किया है।⁶ बर्मान राजनीतिक मर्म में भी कौटिल्य के राजनीतिक चिन्तन की प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है। बन्धोपाध्याय के अनुसार, "महाकाव्यों और पुराणों के महापुरुषों के बाद भारतीयों का अन्य किसी नाम से इतना अधिक परिचय नहीं है जितना की चाणक्य के नाम से है। भारत में शासन-कला, कूटनीति के विचारधाराओं एवं जिज्ञासुओं की कौटिल्य की नीतियाँ बतलाई जाती हैं।⁷

मानवेन्द्र नाथ राय

(Manvendra Nath Roy)

मानवेन्द्र नाथ राय जिनके बचपन का नाम नरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य था, अत्यन्त उच्च कोटि के विद्वान् और विचारक तथा एक प्रभावशाली लेखक और वक्ता थे। उन्होंने विपुल साहित्य लिखा और लगभग छ-हज़ार पृष्ठों की एक विपुल पुस्तक 'आधुनिक विज्ञान के दार्शनिक परिणाम' (The Philosophical Consequences of Modern Science) लिखी।

जीवन परिचय (Life-Sketch)

एम्. एन. राय (1886-1954) अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में बंगाल के ब्रान्तिकारी समुदाय आन्दोलन की ओर आकर्षित हुए। विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सत्यनरकर आदि उग्रपुत्र के परिचयों ने उन्हें प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति से दुःख होकर उन्होंने ब्रान्तिकारी दल से नाता जोड़ लिया। भारत में मराठा ब्रान्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के आकांक्षी यतीन्द्र मुखर्जी का बार्दा हाथ बनने का उन्हें भी भाग्य प्राप्त हुआ। एक ब्रान्तिकारी के रूप में 1910 और 1915 में उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर जर्मनी ने भारत में अशांति उत्पन्न करने की बात खेती ताकि ब्रिटिश सेनाओं का ध्यान बँट जाए। जर्मनी ने गुप्त रूप से भारत में ब्रान्तिकारी दल को धन और हस्त्र भेजने की व्यवस्था की। राज्यों की गुप्त सहायता प्राप्त करने के लिए राय 1915 में 'डच ईरान' के लिए पलायन कर गए। उद्देश्य में असफल रहने पर वे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में घूमते रहे और 1917 में वे मैक्सिको जा पहुँचे। मैक्सिको में उन्होंने समाजवादी शक्तियों को संगठित करने में विशेष रुचि ली और उन्हीं के प्रभाव से मैक्सिको के समाजवादी आन्दोलन की अन्तर्राष्ट्रीय दिशा में मोड़ा। राय मैक्सिको में समाजवादी दल की नेशनल कन्फ़रेंस के प्रधान सचिव बन गए। माइकेल बोरोडेन ने उन्हें मार्क्सवाद की ओर प्रेरित किया। राय ने मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की। 1919 में वे रूस गए और एक दशहारी तक साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय (Communist International) के घनिष्ठ सम्पर्क में रहे। अपनी बौद्धिक प्रतिभा से उन्होंने लेनिन को बड़ा प्रभावित किया। 'मार्क्स इन्स्टीट्यूट के पूर्वार्ण विभाग' (Oriental Department of the Moscow Institute) के प्रधान के रूप में राय ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रभावित करने की चेष्टा की और भारत में साम्यवादी दल की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। 1927 में उन्हें एक प्रतिनिधि मण्डल के नेता के रूप में चीनी साम्यवादी दल की परामर्श देने के लिए चीन भेजा गया। उन्होंने

- 1 डॉ. एच. एम. नाहर : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 8.
- 2 डॉ. आर. एस. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 115.
- 3 डॉ. पी. एल. भार्गव : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 173.
- 4 Saleure B. A. : Ancient Indian Thought & Institutions, p. 54.
- 5 Ramaswami, T. N. : Essentials of Indian State Craft, p. 1.
- 6 Krishna Rao, M. V. : Studies in Kautilya, p. 172.
- 7 Bandhopadhyaya, N. C. : Kautilya, p. 1.

चीनी साम्यवादियों को सत्ताह दी कि वे अपनी सामाजिक आधारभूमि को विस्तृत करने के लिए कृषि क्रान्ति की योजना (Plan of Agrarian Revolution) पर अमल करें।

राय एक मौलिक और स्वतंत्र विचारक थे। साम्यवादी जगत् पर रूस का एकाधिकार उन्हें रुचिकर नहीं था। 1928 में तृतीय साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व के रूसी एकाधिकार का उन्होंने विरोध किया। स्टालिन की उपद्रामपन्थीय विचारधारा उनकी आलोचना की शिकार बनी। फलस्वरूप 1928 में राय को कमिन्टर्न से निकाल दिया गया। राय राम बदले कर भारत लौट आए लेकिन कानपुर बन्द्योब केस के सम्बन्ध में 1931 में उन्हें लगभग 6 वर्ष के लिए कारागार में दस दिया गया। 15 वर्ष के निर्वासन और 6 वर्ष के कारावास के बाद 1936 में मंगेवेन्द नाथ राय सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में वृत्त पड़े। उन्होंने गांधीवाद के विरुद्ध अभियान चला कर दिया; उन्होंने गांधीवाद को एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक दर्शन बताया जिसका 'सामाजिक सम्मन्ध का सिद्धान्त' अव्यावहारिक था। राय कांग्रेस में रहे लेकिन गांधीवादो नेतृत्व से कटई समुह न हो सके अतः शुन्य होकर उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर ही League of Radical Congressmen बनाई। 1940 में राय ने अपने साथियों सहित कांग्रेस को सदा के लिए छोड़ दिया और अपनी अलग रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी (Radical Democratic Party) की स्थापना की। उनका साप्ताहिक पत्र स्वतंत्र भारत (Independent India) जिसकी नींव वे 1937 में ही डाल चुके थे, कांग्रेस की रीति-नीति पर कठोर प्रहार करता रहा। इस पत्र को आगे चलकर 1949 में 'रेडिकल ह्यूमैनिस्ट' (Radical Humanist) नाम दिया गया। राय ने आरोप लगाया कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस धरखा कातने वालों का संघ बननी जा रही है। राय ने वैज्ञानिक राजनीति (Scientific Politics) की कलाकृत की। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन का समर्थन उन्होंने हालाँकि नहीं किया कि यह आन्दोलन उनकी दृष्टि में कांग्रेस के औद्योगिक और पूँजीवादी सरसों द्वारा संगठित था। राय ने गांधी को 'धर्मित और कांग्रेस को भारतीय पूँजीवाद द्वारा पोषित सत्ता बताया। 1946 में राय की विचारधारा में एक आधारभूत परिवर्तन आया। 1947 में उन्होंने अपने दल को भंग कर दिया और वे अपने 'नवीन दर्शन' (New Philosophy) को पूर्णता देने में लग गए जो 'मौलिक मानववाद' (Radical Humanism) के नाम से विख्यात है। 1954 में राय की मृत्यु हो गई।

राय और रौमांटिक क्रान्तिवाद (Roy and Romantic Revolutionism)

राय अपने चिन्तन के प्रथम काल (1901-1915) में एक रोमांटिक क्रान्तिकारी रहे। यकिमचन्द के आनन्द मठ के सामाजिक आदर्शवाद ने उन्हें अनुप्राणित किया। वे 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' (Cultural Nationalism) से प्रभावित थे। राय पर आनन्द मठ और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा तथा अन्य आतंकवादियों के समान वे यह विश्वास करने लगे कि आतंकवादी दवाओं से ब्रिटेन की भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। हथियार एकत्र करने के लिए भूमिगत आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए और संगठन के कार्य के लिए आवश्यक घन राजनीतिक इकैती के साधनों से प्राप्ति किया जा सकता है। राय के अनुसार, स्वतन्त्रता प्राप्ति के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रान्तिकारी दिसात्मक साधनों को अपनाना हेतु नष्ट है। यद्यपि तत्कालीन आतंकवादी राय के इन विचारों से प्रभावित हुए, तथापि यह क्रान्तिकारी या आतंकवादी आन्दोलन मुद्दिजीवियों को प्रभावित न कर सका, क्योंकि इस आन्दोलन में सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का निरन्तर अभाव था। यह मध्यमवर्गीय युवा वर्ष तक ही सीमित था, जन-साधारण का समर्थन इसे नहीं मिला।

राय और मार्क्सवाद (Roy and Marxism)

मार्क्सवादी के रूप में राय का द्वितीय जीवनकाल 1917 से 1946 तक रहा जिसमें प्रारम्भिक चरण में अर्थात् 1917 से 1930 तक उन पर रुढ़िवादी साम्यवाद का रण चढ़ा रहा, अगले चरण में 1930 से 1939 के दौरान वे एक रेडिकल कांग्रेसी (Radical Congressmen) रहे और तीसरे चरण अर्थात् 1940 से 1946 के दौरान उनकी चिन्तन शैली एक मौलिक लोकतन्त्रवादी (Radical Democrat) की रही। राय का मार्क्सवादी स्वरूप एक-सा न रहा बल्कि समय के साथ उसमें परिवर्तन आते गए उन्होंने लेनिन, स्टालिन आदि साम्यवादी महारथियों के विचारों और क्रिया-कलापों का अध्यापन नहीं किया। फलस्वरूप रूसी साम्यवाद के साथ उनके मतभेद बढ़ते चले गए और 1928 में वे 'कॉमिन्टर्न' से निष्कासित कर दिए गए।

मार्क्सवाद की आलोचना

(1) मार्क्सवाद में दो परस्पर विरोधी और असंगत प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। एक प्रवृत्ति शोषण की निन्दा करती है तो दूसरी प्रवृत्ति इन्दात्मक मौलिकवाद और वर्ग-संघर्ष पर बहुत अधिक बल देती है। राय को मार्क्स की प्रथम उदात्त प्रवृत्ति ही रुचिकर थी जिसने मार्क्स को संसार में शोषित और पीड़ित वर्ग का प्रमुख हितैषी बना दिया

था। रूस के साम्यवादी यद्यपि रीढ़ की मृदा करते थे, लेकिन उनका विशेष आग्रह मार्क्स का इन्द्रात्मक ऐतिहासिक और वर्ग-सर्पण था। उस का कहना था इस प्रवृत्ति में निष्ठा का अर्थ सर्वाधिकारवाद अथवा तानाशाही का विकास है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रेमी राय ने मार्क्सवादियों अथवा रूसी साम्यवादियों की सर्वाधिकार प्रवृत्ति को पसन्द नहीं किया। अपनी इन मान्यताओं के कारण ही राय रूसी साम्यवादी शासन का समर्थन नहीं कर सके और साम्यवादी आन्दोलन तथा मार्क्सवाद से अलग हो गए।

(2) राय मार्क्सवाद की वैज्ञानिक पद्धति के प्रशंसक थे। उसे कट्टरपथ का रूप देना उन्हें स्वीकार न था, अतः स्वाभाविक था कि लेनिन और उसके अनुयायियों से जो मार्क्सवाद को एक कट्टरपथ बनाने के पथ में थे। राय का अभिमत था कि मार्क्सवाद को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मार्क्सवाद को समय के अनुकूल एक सर्वत्र और गतिरहित दर्शन बनाया होगा जिसमें आवश्यक संशोधन बना रहे। मार्क्सवाद को यदि कट्टरता और सख्ती के घेरे में बंध दिया गया तो उसकी जीवन शक्ति का हानि हो जाएगा।

(3) राय ने मार्क्स के इन्द्रात्मक दर्शन का विशेष किया और इसे मानव-प्रवृत्ति के मार्ग में बाधक माना। राय ने मार्क्स के इस विश्वास से असहमति प्रकट की कि इतिहास उत्पन्न-सामग्रियों के विकास से उत्पन्न घटनाओं की मृच्छा है।

(4) राय के अनुसार, इतिहास की मार्क्सवादों ध्येयता भी दोषपूर्ण है क्योंकि वह सामाजिक प्रक्रिया में मर्यादित क्रिया को बहुत कम स्थान देती है। मानवैक्य राय ने मार्क्सवाद की नई ध्येयता करने का प्रयत्न किया। उन्होंने बताया कि इतिहास में वैचारिक और भौतिक दो समानांतर प्रक्रियाएँ देखने को मिलती हैं। चिन्तन एक शारीरिक प्रक्रिया है जो शरीर तथा परिवेश को परस्पर क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है किन्तु यह उत्पन्न हो जाने पर विचार अपने निजी विकास नियम का अनुसरण करते हैं। विचारों की गति तथा सामाजिक प्रक्रियाओं की इन्द्रात्मक गति के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है, किन्तु राय का स्पष्ट मत है कि किसी भी विरिष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भ में सामाजिक घटनाओं तथा विचार आन्दोलनों के बीच कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता।

(5) राय ने मार्क्स के वर्ग-सर्पण के समग्रशास्त्र (Sociology of Class-Struggle) में संदेह प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि मानव इतिहास में विभिन्न सामाजिक वर्गों का अस्तित्व रहा है और उनमें खींचतानी भी रही है लेकिन इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि सामाजिक एकता और बन्धन के तत्व विशेष प्रबल रहे हैं। इन शक्तिशाली तत्वों के कारण समाज मुख्य रूप से अलग-थलग टुकड़े टुकड़े हुआ है।

(6) राय ने मार्क्स की इस धारणा को गलत बताया है कि "मध्यम वर्ग (Middle Class) का स्तेप हो जाएगा। मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत मध्यम वर्ग का विकास हुआ है और आर्थिक प्रक्रियाओं के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ रही है। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व इतिहास में मध्यम वर्ग का जो सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व रहा है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते।"

(7) मार्क्सवाद के विरुद्ध राय की एक गम्भीर अपेक्षा यह रही है कि उसमें नैतिक नियमों के चलने के निर कोई स्थान नहीं है। मार्क्सवादी दर्शन व्यक्ति को अनेकित्व स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करता। यह दर्शन व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता देता है कि वह ऐतिहासिक आवश्यकता की समझ से और स्वयं को उसके समक्ष प्रस्तुत-पूर्वक समर्पित कर दे। राय ने कहा, स्वतन्त्रता की यह धारणा तो गुलामी की धारणा है जिस पर चलने से समग्र 'स्वेच्छापूर्ण गुलामी' का समूह बन जाएगा। समाज के विकास में नैतिक शक्ति की अवहेलना करना मार्क्सवाद का गम्भीर दोष है।

राय का मौलिक मानववाद (Roy's Radical Humanism)

'कॉमिन्टर्न' से निष्कासित होने और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश करने के बाद मानवैक्य राय मार्क्सवाद से हटते गए। भारतीय राष्ट्रीय कमिंस में रहते हुए उन्होंने गाँधीजी नेतृत्व की कटु आलोचना की। जब उन्होंने देखा कि कमिंस में उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है तो उन्होंने कमिंस का परित्याग करके दिसम्बर, 1940 में अपनी पृथक् 'रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी' का गठन किया। 1945-1946 के निर्वाचनों में इस पार्टी को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। राय को विश्वास था कि जब तक भारत में सांस्कृतिक और दार्शनिक क्रान्ति नहीं आयेगी तब तक मौलिक लोकतन्त्र (Radical Democracy) के सिद्धान्तों को नहीं समझ सकते, अतः उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को पण करके अपनी सम्पूर्ण शक्ति भारतीय पुनर्जागरण के प्रसार में लगा दी जिसका उद्देश्य मौलिक मानववाद के विकास के निर मार्ग प्रशस्त करना था। अपने जीवन के अन्तिम सात वर्षों में अर्थात् 1947 से 1954 की अवधि में वे भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मौलिक मानववाद (Radical Humanism) के विज्ञान के रूप में विख्यात हुए। राय ने अपने मानववाद को मौलिक इसलिए कहा क्योंकि वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनका मानववाद पूर्ववर्ती और सम्प्रदायीन सभी विचारों को दृष्टिगत मानववाद से भिन्न है। पहले के मानववादी व्यक्ति को किसी अति-मध्यमवर्गीय और अति-प्राकृतिक सत्ता के अधीन करने की इच्छा की धारणा से नहीं बचा घर थे और आधुनिक मानववादी अपने दर्शन में

मनुष्य को सीमित केन्द्रीय स्थान नहीं दे सके। यन्त्रात्मक राज्य, रबीन्द्रनाथ टैगोर, अविन्द घोष, गोपालकृष्ण गोखले, महात्मा गांधी आदि मानवता के उपासक थे, लेकिन राय का मानवतावाद भिन्न था। राय ने स्वतंत्रता के तीन आधार स्तम्भ बताए—मानववाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है अतः वह स्वतंत्रता को कामना करता है। स्वतंत्रता के मार्ग में कठिनाइयाँ और बाधाएँ आती हैं जिनके लिए औशिक रूप से प्रकृति और औशिक रूप से मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। न केवल प्राकृतिक बाधाओं ने वन, धर्म और जादू ने मानव स्वतंत्रता को सीमित किया है। धर्म ने अपना भुविवादी चरित्र छोड़कर अपनी कठोरता और कटुता से मानव स्वतंत्रता और मानव सम्पत्ता को आघात पहुँचाया है। परिवार, राज्य, कानून, विवाद और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएँ भी अपने रुढ़िवादी और गतिहीन रुढ़ के कारण मानव स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएँ पहुँचाती रही हैं।

राय ने अपने नव-मानववाद में व्यक्ति को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर विश्व-मनुष्यत्व की दीक्षा दी। उन्होंने लोगों को 'प्रेम और विश्वास के राष्ट्रमण्डल' का सदस्य बनाना चाहिए जिसे भौगोलिक सीमाओं ने दूषित न किया हो। डॉ. वर्मा के अनुसार, "नवीन मानववाद का दृष्टिकोण विश्व राज्यवादी है। उसके समाज-दर्शन में राष्ट्रवाद अन्तिम अवस्था नहीं है। राष्ट्रवाद का आधार जातिगत श्रेष्ठता है और जिस सीमा तक वह सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा करता है वहाँ तक प्रतिस्पर्धावादी है, इसलिए राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व-मनुष्यत्व की आवश्यकता है। अविन्द टैगोर तथा गांधी की नीति राय भी मानव जाति के सहकारिता मूलक सपने में विश्वास करते हैं।— नवीन मानववाद स्वतंत्र मनुष्य के समाज तथा विराटरी के आदर्श को साकार करने के लिए प्रतिज्ञावद्ध है।" राय ने विश्व-सपने का तत्साह के साथ समर्पण किया। उनके अनुसार, "नवीन मानववाद विश्वराज्यवादी है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का विश्व-राज्य राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से परिबद्ध नहीं होगा। वे राज्य पूँजीवादी, धर्मवादी, समाजवादी, साम्यवादी अथवा अन्य प्रकार के क्यों न हों। राष्ट्रीय राज्य मानव के बीसवीं शताब्दी के पुनर्जीकरण के आघात से विलुप्त हो जाएँगे।" राय ने विश्व-राज्यवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के बीच भेद किया। उन्होंने आध्यात्मिक समाज अथवा विश्व-राज्यवादी मानववाद का समर्पण किया। अन्तर्राष्ट्रीयतावाद में प्रत्येक राष्ट्रीय राज्यों के अस्तित्व का विचार है जबकि राय का विश्वास था कि एक सच्ची विश्व सरकार की स्थापना राष्ट्रीय राज्यों का निराकरण करके ही की जा सकती है।

राय और मौलिक लोकतन्त्र (Roy and Radical Democracy)

राय पूँजीवादी लोकतन्त्र और साम्यवाद के विरुद्ध थे क्योंकि इन दोनों के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास होता है। राय के अनुसार वर्तमान सामाजिक ढाँचा ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपने जनसिद्ध अधिकार अर्थात् स्वतंत्रता का समुचित उपयोग नहीं कर पाता। राज्य एक ऐसा संगठन है जिसने एक शास्यकारक संस्था का रूप ग्रहण कर लिया है। राज्य का निर्माण स्वतंत्र और ज्ञानिपूर्ण जीवन के लिए मनुष्यों के सहकारी प्रयोग द्वारा हुआ है। यह शक्ति पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित है। राय ने 19वीं शताब्दी के उदारवादी लोकतन्त्र को एक ऐसा औपचारिक लोकतन्त्र माना है। जहाँ विश्व के बहुमूल्यक राजनेता और विद्वान राजनीतिक दलों को लोकतन्त्र की अनिवार्यता मानते हैं वहाँ राय ने सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए राजनीतिक दलों को कार्य पद्धति को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यदि नैतिक उत्थान करना है तो वर्तमान दल-पद्धति को समाप्त करना होगा। विश्व के नैतिक पतन का एक मूल कारण वर्तमान दल-पद्धति है। राजनीतिक दल अपने चुनाव अभियानों द्वारा जन-साधारण को वास्तविक राजनीतिक शिक्षा नहीं देते, अपितु राजनीतिक घालबाजियाँ और कुशिला सिखाते हैं। इन दलों से जन-साधारण में विवेक जाग्रत नहीं होता, बल्कि उनकी ठग्यूलत भावनाएँ उमड़ती हैं। ये दल जनता को ठगसा कर इस प्रकार का घातावरण पैदा करते हैं जिसमें राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक समस्याओं पर विवेकपूर्ण विचार सम्भव नहीं होता। राजनीतिक दलों का उद्देश्य शासन-सत्ता के लिए छान-छाप्टी करना है, उन्हें जनता के कारतविक शिष्टों की ओर झुका नहीं होती। जिन्होंने जयप्रकाश नारायण आदि सर्वोदयी विचारक राजनीति को समाज के रोगों का मूल कारण मानते हुए उसके स्थान पर लोक-नीति को प्रतिष्ठित करना चाहते थे और सभी राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों का विवेकीकरण करना चाहते थे तथा गाँवों को स्वशासित और आत्म-निर्भर इकायाँ बनाना चाहते थे। मुख्य अन्तर यही है कि वे स्वायत्त शासन ग्राम गणराज्यों के स्थान पर 'जन समितियों (Peoples Committees) को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। राय की मान्यता थी कि जन-समितियों अथवा स्थानीय व्यक्तियों की समितियों के विकास से दल-विहीन यथार्थ लोकतन्त्र अर्थात् सर्गठित लोकतन्त्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। जन-समितियों के माध्यम से सर्वजनिक समस्याओं के प्रत्येक में जन-साधारण को अधिकधिक भाग मिल सकेगा। उन्होंने आग्रह किया कि हमें अपने मतित्व से यह धारणा निवारित करनी चाहिए कि राजनीति का एकमात्र रूप 'सत्ता-प्रधान राजनीति' है।

राय और राष्ट्रवाद (Roy and Nationalism)

मानवेंद्र नाथ राय श्राव्य में मार्क्सवादी रहे और बाद में मौलिकतावादी। ये विचारधाराएँ राष्ट्रवाद से भेद नहीं खाती, अतः स्वाभाविक है कि राय ने राष्ट्रवाद को एक प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति बताया हुए प्रत्येक समाज और प्रत्येक देश

को इससे बचने का संदेश दिया। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटिश सत्ता के साथ कांग्रेस के सहयोग की नीति से राय को बड़ा कष्ट पहुँचा। उनकी धारणा थी कि घुपे शक्तिवादी प्रसंगवाद अथवा अधिनायकत्व की स्थानता के लिए लड़ रही है जबकि मित्र-राष्ट्र लोकतन्त्र की रक्षा के लिए युद्धरत हैं, अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मित्र-राष्ट्रों की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। राष्ट्रीय हित और गौरव की आड़ लेकर ब्रिटिश सरकार से सौदेबाजी न करके प्रसंगवाद का अन्त करने के लिए कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहायता देनी चाहिए। जब कांग्रेस ने इसकी कोई परवाह न की और गाँधी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' चलाया तो मानवैन्द्रनाथ को निराशा हुई। उन्होंने कांग्रेस को एक 'फ़ासिस्ट संगठन' (Fascist Organisation) तक बढ़ दिया और ब्रिटिश सत्त्व से अलग होने की 'भारत छोड़ो आन्दोलन' को निरममतापूर्वक कुचल दिया जाय। राय का यह व्यवहार निःसंदेह देशद्रोहपूर्ण, अपराधी और घोर निन्दनीय था। वे इस बात को भूल गए कि ब्रिटिश सत्ता अनेक दशाब्दियों से भारतीयों को स्वराज्य देने अथवा उसराज्यी शासन की स्थापना करने के बारे में कैसे झूठे आश्वासन देती आ रही थी और अंग्रेजों ने देश के स्वाधीनता आन्दोलन को दबाने के लिए लागू पार कितने अत्याचार किए थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हिमायत करके और राष्ट्रवादियों को कुचलने की अर्पण करके राय ने अपने उच्चतम पक्ष पर सदैव के लिए कलक रूपाई धब्बा लगा दिया।

राय का मूल्योन्मूलन एवं देन

मानवैन्द्र नाथ राय आधुनिक भारत में दर्शन और राजनीति के विद्वान् थे, पर दुर्भाग्य यह है कि उनकी प्रतिभा ध्वसात्मक थी, न कि रचनात्मक। राय ने भौतिकवादी होने के नाते, धर्म और आध्यात्मिक दर्शन की दुष्प्रशस्तिपूर्वक प्रशंसा की। उन्होंने राष्ट्रवाद को पुराना और सङ्ग-रहित आदर्श बताया तथा यहाँ तक कह दिया कि "राष्ट्रवाद की परजय भारतीय स्वतन्त्रता की शर्तें हैं।" वास्तव में, राय के दृष्टिकोण और चिन्तन-दिशा का निर्माण अहंकारपूर्ण सम्प्रदायी बुद्धिवाद में भरा हुआ था। वे मूल्य-विहीन बुद्धिवादी थे, अतः भारतीय राष्ट्रवाद की दबी हुई भावनाओं की परधानने में वे आतङ्कन रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस को फ़ासीवादी संगठन बनाना और ब्रिटिश हुकूमत से 'भारत छोड़ो आन्दोलन' को कुचल देने की अर्पण करना राय का एक ऐसा दुष्कार्य था जो उनके ध्वसात्मक रूप को प्रकट करता है। राय ने यह मानकर घुप की कि भौतिकवाद एकमात्र सम्भव दर्शन है। वे भूल गए कि ज्ञान असीम है, अतः एक सिद्धान्त अन्तिम नहीं माना जा सकता। राय ने भारतीय सत्कृति की महानता को न समझ पाने की भूल की। अपने को आधुनिक मानने की सतक में उन्होंने भारतीय सत्कृति और गाँधीवाद के विरुद्ध जहर उगलना और स्वयं को ऐसे बुद्धिवादी के रूप में प्रस्तुत किया जिसे भारतीय समाज में समुचित स्थान मिलना कठिन है।

महात्मा गाँधी

(Mahatma Gandhi)

पूर्व और पश्चिम के जिस सम्न्वय का आरम्भ स्वामी विवेकानन्द ने किया था उसे व्यापक आयाम पर आगे बढ़ाने का कार्य गाँधी, अरविन्द, रवीन्द्र और नेहरू ने किया। इनका अन्तः ढंग एवं कार्य प्राणी की किन्तु इनके प्रयत्न पूर्व और पश्चिम को निकट लाए। इसीलिए इनके युग को एक 'समन्वय या सम्न्वय का युग' (The Era of Synthesis) कहते हैं। इन सभी विमूर्तियों ने सम्न्वय और सहिष्णुता पर बल देते हुए राष्ट्र-निर्माण के वैचारिक और व्यावहारिक आयाम पर अपनी भूमिभू निभायी। महात्मा गाँधी ने सर्वोदय का जो मूल सूत्र उभे जयजयन्त नगण और विनोबा भवने ने आगे बढ़ाया। आचार्य विनोबा 'सर्वोदय के प्रतीक' बन गए। जहाँ-जहाँ नेहरू, जयजयन्त नगण, राममनोहर लोहिया आदि ने भारत के लिए समाजवाद के सम्न्वय में अपने विचार प्रस्तुत किए तो मानवैन्द्र नाथ राय का नाम सर्वप्रथम रूप से 'मानवतावाद' के साथ जुड़ गया।

महात्मा गाँधी : जीवन-परिचय (Mahatma Gandhi : Life-Sketch)

मोहनदास करमचन्द गाँधी (1869-1948) का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को कच्छियावाड़ स्थित पोरेबन्दर में एक धार्मिक घरेलू में हुआ था। उनके पिता करमचन्द पोरेबन्दर राज्य के दीवान थे। उनकी मता पुर्तगी बर्ग नेक और धार्मिक प्रवृत्ति की मिला थी। 1876 में गाँधीजी अपने माता-पिता के साथ राजकोट चले गए जहाँ उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई और 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। 1881 में उन्होंने हाईस्कूल किया और 16 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहान्त हो गया। 1884-85 में कुसावति में पहलक उन्होंने चैटेली-छिने मॉस-मण्डा किया, लेकिन उनका सत्यवादी मन इस को छिपा नहीं सका। उन्होंने अपने माता-पिता से सना-याचना कर अपने दोषों का प्रदर्शित किया, असत्य का त्याग कर सत्य का वापस किया।

गाँधीजी 1887 में मैट्रिक पास करने के बाद कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 में इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्टर होकर भारत लौटे। राजकोट और मुम्बई में उन्होंने वकालत की किन्तु उन्हें विस्मय का समाप्ता करना पड़ा। गाँधीजी की असफलता का मुख्य कारण यह था कि वे चटुर्बर्गाल और चटुर्द्वय की ऐतिहासिक की नीति

दृष्टि में असह्य मानते थे। अन्त में दादा अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी नामक एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था जो दक्षिण अफ्रीका में ची, कानूनी कार्यवाही के दौरे पर के लिए उन्हें नियुक्ति मिली और वे 1893 में डरबन पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका में नेटान के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारता के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में गए थे केवल एक वर्ष के लिए ही, किन्तु रह गए बीस वर्ष। अफ्रीका में उन्होंने उस अत्याचार और अन्याय को देखा जो वहाँ की गरीबी सरकार प्रशासी भारतीयों पर रण और जातिभेद के नाम पर कर रही थी। 1893 से 1914 तक गांधीजी ने वहाँ गरीबी सरकार के विरुद्ध अपना अधिसात्विक युद्ध सद्गता और सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने के समय तक गांधीजी ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोगी के रूप में अधिक सक्रिय रहे। 1914 में भारत लौटने पर मुम्बई की जनता ने गांधीजी को 'महात्मा' की उपाधि दी। 1915 में ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें 'केसरी हिन्द' स्वर्ण पदक प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधीजी भारत में हो रहे और उन्होंने देश की आजादी के लिए कठोर संघर्ष किया। 1915 में गांधीजी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 'सत्याग्रह आश्रम' (जो बाद में साबरमती के नाम से प्रसिद्ध हुआ) की स्थापना की। भारत में महात्मा गांधी ने जो गतिविधियाँ प्रारम्भ की वे ब्रिटिश सरकार की आशा के प्रतिरुद्ध थीं। 1917 में उन्होंने भारतीय मजदूरों को बन्धक बनकर श्रम करने हेतु देश के बाहर भेजने की नीति का विरोध किया। उसी वर्ष वे चीन जापानों में गए। भारतीयों को देश की जीव बचने के लिए चम्पारन (बिहार) गए। चम्पारन के सत्याग्रह ने बीस साल से शांति किसानों को प्रभावित किया। यह सत्याग्रह का व्यापक प्रयोग था जिसमें एक शताब्दी से चले आने वाले अन्याय पर अधिक सत्याग्रह द्वारा निवारण हुआ। फरवरी, 1919 में गांधीजी ने रोलट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह की प्रविष्टि की। 16 अप्रैल, 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुई तथा भारतव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ दिया गया। पंजाब में उनके प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को तोड़ने पर उन्हें हिरासत में लेने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया और मुम्बई से जाकर छोड़ दिया गया। देश के कई भागों में हॉट-हॉट और हिंसालक घटनाएँ होने पर गांधीजी ने 18 अप्रैल को सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया। गांधीजी ने 'नवजीवन' गुजराती मासिक और 'यंग इण्डिया' (Young India) अंग्रेजी साप्ताहिक का सम्पादन अपने हाथ में ले लिया। जनवरी, 1920 में गांधीजी वायसराय के पास एक राष्ट्रमण्डल लेकर गए जिसमें टर्की के मुल्तान (मुसलमानों के छात्रों) को इस्लाम के परिवर्तन स्थानों पर अपने अधिकारों से वंचित न करने सम्बन्धी दबाव ब्रिटिश सरकार पर डालने की माँग की गई। 1 अगस्त को गांधीजी ने वायसराय के नाम पर सिखर केसरी हिन्द पदक, जुलु-मुद्ध पदक तथा कोम-मुद्ध पदक प्राप्त लौटा दिये। सितम्बर में सन्ना साजपराय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधीजी ने पंजाब की घटनाओं तथा खिलाफत के समर्थन में असहयोग कार्यक्रम के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली। नवम्बर में उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। नानपुर में हुए कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में गांधीजी ने सभी वैधानिक एवं शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा भारतीयों द्वारा स्वतन्त्र्य प्राप्ति को कठिन या लक्ष्य निर्धारित किया। 1920 से जुलु-पर्वत गांधीजी राष्ट्रीय आन्दोलन के सहाय मार्गदर्शक चिन्ता सभी कुछ रहे। उन्होंने 1921, 1930 और 1942 के महान् असहयोग आन्दोलनों में भारतीयों को सक्रिय किया। कई राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए और अन्त में 1947 में भारत स्थापित हुआ। हिन्दू मुस्लिम एकता तथा सहअस्तित्व के वे महान् समर्थक रहे। यह दुर्भाग्य था कि उनके अग्र्य प्रयासों के बावजूद स्वतन्त्र्य-प्राप्ति के पूर्व कुछ वर्षों में हिन्दू और मुसलमानों के बीच विषेद की छाई गड़ी होती गई। इसका परिणाम निकला—भारत का विभाजन। 1947 में भारत खण्डित हो गया। महात्मा गांधी को इससे गहरा प्रभाव लगा। इसी स्थिति में 30 जनवरी, 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक हिन्दू ने उन्हें बन्दूक की गोलियों से घायल कर दिया और होठों पर ईश्वर का नाम लिए वे शहीद हो गए।

गांधीजी की मृत्यु उनके जीवन की तरह अवाच्य नहीं गई। उनकी मृत्यु से वे विचार और सिद्धान्त और अधिक सजीव हो उठे जिनके लिए वे जीवनभर लड़े। मृत्यु के बाद महात्मा गांधी अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो उठे और यही कारण है कि ससार में करोड़ों व्यक्ति आज उनके विचारों और सिद्धान्तों से प्रभावित हैं।

गांधी का आध्यात्मिक आदर्शवाद (Gandhi's Spiritual Idealism)

महात्मा गांधी के आध्यात्मिक आदर्शवाद में ईश्वर सत्य, नैतिकता, साधन की श्रेष्ठता, अहिंसा आदि का विशिष्ट स्थान है और उपयुक्त होगा कि हम इन्हें से प्रत्येक का पृथक् विवेचन करें, पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि गांधीजी के आध्यात्मिक दर्शन में वे विभिन्न पहलुओं की विविधता हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

1. ईश्वर की अवधारणा (The Concept of God)

गांधीजी के जीवन और जितन में ईश्वर के प्रति अद्भुत विश्वास था। वस्तुतः उनके लिए ईश्वर और सत्य अथवा सत्य और ईश्वर में कोई भेद न था। उनका कहना था कि सत्य ईश्वर है, सत्य का निषेध ईश्वर का निषेध है। गांधीजी का विश्वास था कि ईश्वर में आस्था जीवन को निवारती है और हृदय में श्रद्धा तथा प्रकाश का सागर

उंहेलती है। ईश्वर-भक्ति जीवन को पवित्र, उदार और सहिष्णु बनाती है। हम ईश्वर को बुद्धि से नहीं माप सकते, तर्क को कसौटी पर नहीं कस सकते, विज्ञान के नियमों से नहीं समझ सकते, बल्कि श्रद्धा के बल पर उसकी अनुभूति कर सकते हैं। श्रद्धा ही वह प्रकाश किरण फैलती है जिसके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार सम्भव हो। यदि हम अपने हृदय में ईश्वर की उपस्थिति के सत्य की जाँच करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने अन्दर जीवन श्रद्धा का विकास करना चाहिए। गाँधीजी ने कहा कि ईश्वर एक सर्वव्यापक सत्य है। ईश्वर शुभ-अशुभ का मालिक है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह नुप है। ईश्वर ने नुआई पैदा की है, पर वह स्वयं उससे अद्वैत है। नुआई से मुक्त करना ईश्वर-ज्ञान प्राप्त करने का एक सबल मार्ग है। गाँधीजी ने ईश्वर को मानवता से पृथक् नहीं माना। उन्होंने ईश्वर शब्द का अर्थ विस्तार से किया और उसे 'दरिद्रनाश' कहकर पुकारा जिसका अर्थ है 'गरीबों का ईश्वर'। उन्होंने 'स्वर्ग के भगवान' को धरती पर उतार दिया, उसे अलौकिक से लौकिक बना दिया, दूसरे शब्दों में ईश्वर का सामाजीकरण और मानवीकरण कर दिया। गाँधीजी ने ईश्वर को महान् लोकतन्त्रवादी कहा, क्योंकि उसने हमें नुआई और अच्छाई के बीच अपना चुनाव खुद कर लेने की खुली छूट दे रखी है।

2. सत्य की अवधारणा (The Concept of Truth)

महात्मा गाँधी का सम्पूर्ण जीवन सत्यमय था। सत्य के सामने वह समझौता नहीं करते थे, सत्य और ईश्वर में वह भेद नहीं मानते थे। गाँधी दर्शन से सत्य को हटाने का प्रयत्न किया जाए तो यह एक असम्भव कार्य होगा। गाँधीजी का आग्रह था कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और कार्य सत्य के लिए होना चाहिए। सत्य के अभाव में हम किसी नियम का शुद्ध पालन नहीं कर सकते। बाणी, विचार और आचार का सत्य होना सत्य है। सत्य की अर्चना ईश्वर की सच्ची भक्ति है। गाँधीजी सापेक्ष सत्य अर्थात् साधन स्वरूप सत्य में और शुद्ध सत्य में स्पष्ट भेद मानते थे। उनकी मान्यता थी कि सापेक्ष सत्य वह सत्य है जिसे हम किन्हीं विशेष परिस्थितियों के सम्बन्ध में देखते हैं। वह सम्पूर्ण सत्य नहीं होता। जो एक प्रकार की परिस्थितियों में सत्य हो सकता है, सम्भव है वह भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में सत्य न हो। शुद्ध सत्य अन्तिम सत्य है। यही है, यही था और यही रहेगा। सत्य के शुद्ध अर्थ में गाँधीजी सत्य और ईश्वर को एक ही मानते थे। वे ईश्वर की पूजा सत्य के रूप में करते थे। इस अर्थ में सत्य मानव जीवन का सत्य बन जाता है। गाँधीजी का मत था कि 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' का सिद्धान्त एक हृदयहीन सिद्धान्त है जिसने मानवता को बड़ी हानि पहुँचाई है। वास्तविक सत्य और मानवीय सिद्धान्त तो 'सभी व्यक्तियों का अधिकतम सुख' का है और यह सिद्धान्त पूर्ण आत्म-बलिदान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय जीवन का अन्तिम सत्य है। नगे को बल दान, भूखे को अन्न दान और बेघर को आश्रय दान करना सत्य है। यही ईश्वर है और इसे प्राप्त करना चाहिये।

3. साधन तथा साध्य की अवधारणा (The Concept of Means and Ends)

गाँधीजी ने साध्य को जितना महत्व दिया उतना ही साधन को। गाँधी दर्शन में इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। साध्य का ऊँचा होना जरूरी नहीं है। साधन की उच्चता एवं नैतिकता आवश्यक है और सत्य पूरा जाए तो साधन का अधिक महत्व है, क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता है उस कर्म का फल मनुष्य के हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म जरूर साध बन जाता है, इसलिए जो हाथ में होता है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। महात्मा गाँधी के अनुसार, "साधनों की तुलना बीज से की जा सकती है और साध्य की वृक्ष से और जो अद्भुत सम्बन्ध बीज और वृक्ष में है वही साध्य और साधन के बीच है।" साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए अन्यथा एक की अपवित्रता दूसरे को प्रदूषित कर देती है। गाँधीवाद में 'साधनों की पवित्रता' का विचार उसे मार्क्सवाद से भिन्न करता है। जहाँ मार्क्सवाद एक वर्गहीन समाज के आदर्श की प्राप्ति के लिए हिंसा और क्रान्ति का उपदेश देता है वहीं गाँधीजी के अनुसार खून की बूंद गिरते ही जिस बीज पर वर्गहीन समाज मिले वह बीजमट मईगी है। गाँधीजी की आस्था खून का कतरा गिरा बिना ही रचापित होने वाले वर्गहीन समाज में है। साधनों की पवित्रता का यह विचार राजनीति को गाँधीजी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है, पर दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक राजनेता 'मैकियावेली राजनीति' के उपासक हैं।

4. कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धान्त (Theories of Karma and Re-birth)

महात्मा गाँधी का कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास था। उनका कहना था कि कर्म का सिद्धान्त स्वतंत्रता का सिद्धान्त है जो हमें अच्छे और बुरे में चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है। हमारी स्वतंत्रता हमारे प्रयत्नों पर निर्भर है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध में गाँधीजी ने कहा था कि उन्हें इस सिद्धान्त में उतना ही विश्वास है जितना कि अपने दर्दमान शरीर के अस्तित्व में।

5. अहिंसा की अवधारणा (The Concept of Non-violence)

गान्धीजी का अनुग्रह था कि मानवीय सम्बन्धों की सभी समस्याओं का हल अहिंसा है। अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली है। अहिंसा एक-दूसरे के प्रति प्रेम और आदर को जन्म देती है तथा सभी मनुष्यों को समान सपने को प्रेरणा देती है। गान्धीजी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सभी परिस्थितियों में किया और भूषण तथा शंकाओं पर विजय पाने में सफल हुए। गान्धीजी ने जिस अहिंसा का प्रतिपादन किया वह निष्पक्षिक धारणा न होकर बलुत एक विधेयमक शक्ति है। यह बुराई को अच्छाई से जीतने का सिद्धान्त है जिसमें कोई बदले की भावना, कोई हृदय, कोई प्रतिकार नहीं है, कोई सगठित युद्ध या गुप्त हत्या नहीं है।

गान्धीजी के अनुसार यह अहिंसा का औचितिक अर्थ है। अहिंसा में इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दु आते हैं। "कुविचार हिंसा है। उदात्तरी विध्य-भावण किसी को बुरा चाहना हिंसा है। जगत् को जिस चीज की आवश्यकता है, उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है।" गान्धीजी का अहिंसा की अवधारणा, मनु बचन और कर्म से सम्बन्धित है। गान्धीजी के अनुसार अहिंसा सधौच नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। अहिंसा के तीन रूप हो सकते हैं—जाग्रत अहिंसा (Enlightened Non-violence), औचित्य अहिंसा (Reasonable Non-violence) तथा भीड़ों की अहिंसा (Non-violence of the Cowards)। जाग्रत अहिंसा वह है जो व्यक्ति में अन्तर्हिंसा की पुकार पर स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। इसे व्यक्ति अपने आचारिक विषयों को उत्कृष्टता अथवा नैतिकता के कारण स्वीकार करता है। अहिंसा में असम्यक् को भी सम्मेल में बदल देने की अपार शक्ति निहित होती है। औचित्य अहिंसा वह है जो जीवन के किसी क्षेत्र विशेष में आवश्यकता पड़ने पर औचित्यानुसार एक नीति के रूप में अपनाई जाए। यद्यपि यह अहिंसा दुर्बल व्यक्तियों की है, तथापि इसका पालन ईमानदारी और दृढ़ता से किया जाए तो काफी शक्तिशाली और सापदायक सिद्ध हो सकती है। भीड़ों की अहिंसा डरपोक और क्षयों की अहिंसा है, यह 'निष्क्रिय अहिंसा' (Passive Non-violence) है। महात्मा गान्धी के अनुसार अहिंसा एक दर्शन नहीं है बल्कि कार्य करने की एक पद्धति है, हृदय-परिवर्तन का साधन है। उन्होंने अहिंसा को वैयक्तिक आचरण तक सीमित न रखकर मानव-जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में लागू किया। गान्धीजी की अहिंसा पारलौकिक शान्ति या मोक्ष प्राप्ति का ही साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक शान्ति, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक सम्मेल और पारिवारिक निर्माण का साधन है। यह मानव हृदय की दिव्य ज्योति है।

6. धर्म सम्बन्धी अवधारणा (The Concept of Religion)

धर्म से महात्मा गान्धी का अभिप्राय और किसी औपचारिक रुढ़िगत धर्म से नहीं है, बल्कि विश्व के व्यवस्थित नैतिक अनुशासन से है। गान्धीजी का धर्म 'सम्प्रदायवाद' को नहीं मानता था, वह मानव-समाज का शाश्वत तत्व है जो हिन्दुत्व, इस्लाम और ईसायित्व से परे है। गान्धीजी ने हिन्दु धर्म में गहरी आस्था प्रकट की, क्योंकि यह धर्म अन्य सब धर्मों के साथ शान्तिपूर्वक रहने में विश्वास करता है और इस प्रकार का कोई दावा नहीं करता कि सत्य एकमात्र उन्ही में है। "सब धर्म एक-दूसरे के साथ शान्ति से रहें, हर एक आदमी के लिए अपना निज धर्म बना रहे, यही हिन्दु धर्म है।" गान्धीजी ने हिन्दुवाद के आध्यात्मिक नैतिक सार को ग्रहण किया। हिन्दु धर्म में आस्था रखते हुए उन्होंने इसकी आधारभूत सम्बन्धी रुढ़ियों, पाठश्रुतियों या प्रान्तिधर्मों का पक्ष नहीं लिया। महात्मा गान्धी के लिए धर्म और नैतिकता पर्यायवाची शब्द थे। उनकी दृष्टि में नैतिकता के आधारभूत सिद्धान्त सत्य और अहिंसा थे। उन्होंने इन दो सिद्धान्तों को 11 सिद्धान्तों में विवक्षित किया और इन सिद्धान्तों से पूर्ण एक गीत गान्धीजी की प्रातःकालीन और सन्ध्याकालीन प्रार्थनाओं में गाया जाता था। ये 11 सिद्धान्त थे—अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अस्वग्रह, शरीर-त्रय आस्था, सर्वत्र-प्रथम-सर्वत्र, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी, स्पर्श-भावना। इसमें प्रथम पाँच हिन्दुवाद और जैन धर्म के आधारभूत नैतिक सिद्धान्त हैं तथा अन्य 6 इन्हीं सिद्धान्तों में से निकले हैं जो समय की आवश्यकताओं के अनुकूल ठाँसे जा सकते हैं। गान्धीजी यद्यपि सभी धर्मों को सत्य मानते थे, किन्तु उनका यह विश्वास नहीं था कि वे सर्वथा भ्रष्टहीन हैं। सभी धर्म मनुष्यकृत हैं, अतः उनमें अपूर्णता रहना स्वाभाविक है। धर्म-परिवर्तन में उन्हें कोई आस्था नहीं थी। उनके आश्रय में मुसलमान, ईसाई और पश्चित सभी थे, लेकिन उन्होंने किसी को हिन्दु बनने या धर्म परिवर्तन करने को नहीं कहा। भारत में ईसाई सन्तों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा "जो भानवतावादी कार्य उन्होंने किया है वह उत्तम है, लेकिन उसका मूल्य जाता रहेगा यदि वे अपना उद्देश्य दूसरों को ईसाई बनाने का रखेंगे।" महात्मा गान्धी का कहना था कि धर्म की आराधना के लिए हमें किसी गुप्त धर्म या अथवा किसी पर्वत-शिखर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म की अभिव्यक्ति समाज में हमारे कार्यों में होनी चाहिए। गान्धीजी ने धर्म का मानवीकरण और सामाजिकरण किया। उन्होंने पीड़ितों, असहायों और अपावप्रस्त लोगों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। प्रार्थना की शक्ति में अपना अहिंसा विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति प्रार्थना कोई याचना (Petition) नहीं बल्कि ईश्वर का यशोमान है और आत्म्य की आवाज है। प्रार्थनाओं से व्यक्ति

सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance)—सत्याग्रह को अच्छी तरह समझने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध में उसका अन्तर्गम्य स्वरूप अवश्य है। इन दोनों में मूलभूत अन्तर निम्नांकित है—

(1) निष्क्रिय प्रतिरोध कायमसाक्ष राजनीतिक शस्त्र है, जबकि सत्याग्रह नैतिक आश्रय है जिसका अन्तर्गम्य है शरीर शक्ति को अशेष अन्तर्गम्य की श्रेष्ठता। (2) निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल का शस्त्र है जबकि सत्याग्रह का प्रयोग वे लोग कर सकते हैं जिनमें बिना मारे मरने का साहस है। (3) निष्क्रिय प्रतिरोध में उद्देश्य होता है प्रतिपक्षी को हराकर पेशान करना कि वह हार माने से, जबकि सत्याग्रह का उद्देश्य है प्रेम और धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करके विरोधी का हृदय परिवर्तन करना और उसकी भूल सुधारना। (4) निष्क्रिय प्रतिरोधी के लिए प्रेम ही गुनाह नहीं, जबकि सत्याग्रह में गुण, दुर्भावना आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार "सत्याग्रह गत्याग्रह है, निष्क्रिय प्रतिरोध स्थित्याग्रह है।" (5) निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा से सामान्य रूप से दूर रहा जाय है क्योंकि दुर्बल व्यक्ति हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह उचित अवसर पर हिंसात्मक उपयोग के प्रयोग के विरुद्ध नहीं है। दूसरी ओर सत्याग्रह हिंसा के रूप में अनुकूलता परिस्थिति में हिंसा के प्रयोग की आज्ञा नहीं देता। (6) निष्क्रिय प्रतिरोध में आन्तरिक शुद्धता का अभाव है। सत्याग्रह की तरह वह साधनों की शुद्धता को आवश्यक नहीं मानता और प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के चरित्र की नैतिकता की उपेक्षा करता है। दूसरी ओर सत्याग्रह में उद्देश्य निष्ठ और सत्याग्रही के आन्तरिक गुणों में धनित सम्पन्न है। (7) निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग रणवर्धनीय नहीं हो सकता। सत्याग्रह की तरह उसका प्रयोग अपने विरुद्ध सम्बन्धियों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। दुर्बलता और निराशा की भावना से उपपन्न निष्क्रिय प्रतिरोध नैतिक दुर्बलता को बढ़ाता है। दूसरी ओर सत्याग्रह सदैव आन्तरिक शक्ति पर जोर देता है और वास्तव में उसका विकास करता है। (8) निष्क्रिय प्रतिरोध की अपेक्षा सत्याग्रह अन्धारा और अत्याचार का अधिक प्रभावशाली और निश्चित विरोध है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध सदैव सक्रिय होता है।

सत्याग्रह की तकनीक—सत्याग्रह की विभिन्न प्रणालियाँ हैं। इसकी तकनीकें बहुमुखी हैं। सबसे पहले सत्याग्रही सम्मेलन का विवेचन करता है अर्थात् शासकीयपूर्वक बिना किसी पूर्वग्रह के शिकायत का अध्ययन करता है। वह देखता है कि शिकायत करने वाला स्वयं इस शिकायत को दूर करने के लिए आतुर है या नहीं। सत्याग्रह का कर्तव्य है कि वह पहले अन्यायी को समझाए-बुझाए। समझाने-बुझाने के सारे प्रयासों में असफल हो जाने के बाद वह जिस अन्याय के विरुद्ध मोर्चा लेना चाहता है उसका अग्रगण्य प्रचार प्रारम्भ करता है। प्रचार के साथ वह उन सभी तत्वों का ध्यान रखता है जो अन्याय के शिकार हैं। सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ने से पहले सत्याग्रही पीड़ित पक्ष को अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करता है ताकि शोषक और शोषित के बीच कोई समझौता हो सके। सत्याग्रह आन्दोलन में गोपनीयता का अभाव रहना जाता है। सत्याग्रह विरोधी का आदर करते हुए चलता है। उसका उद्देश्य विरोधी को नीचा दिखाना नहीं होता, क्योंकि उसे नीचा दिखाने से वह कभी उनमें समझौता और चेतना प्राप्त नहीं कर सकता। सत्याग्रही मुर्दा का विरोध करता है व्यक्ति का नहीं। सत्याग्रह आन्दोलन में अन्तर्द्वेष की भावना का विशेष महत्व है। सत्याग्रह को नैतिक युद्ध की सारी चालें ही जानकारी होनी चाहिए। सद्गुणों उसमें मूट-मूट कर गरी होनी चाहिए।

महात्मा गाँधी ने समस्त-समय पर सत्याग्रह अश्वधार से नए-नए अस्त्र दिए, क्योंकि वे धनते थे कि सत्याग्रह की आत्मा घरी रहती है केवल अस्त्र बदल जाता है। गाँधीजी ने जिन अस्त्रों का प्रयोग किया उनमें असहयोग, नायक अस्त्र प्रमुख है। यह आसहयोग इन्द्रजित्, सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार, धर्म, नागरिक अवज्ञा, हिंसा, उपवास आदि साधनों के माध्यम से किया जाता है।

चन्द्र-सूरी निर्माणकारी तत्त्वतात्मक कार्यक्रम—महात्मा गाँधी ने निर्माणकारी कार्यक्रमों को सत्याग्रह का एक अभिन्न अंग बताया। गाँधीजी ने जो चन्द्र-सूरी निर्माणकारी कार्यक्रम बताए वे सारीशत इस प्रकार हैं—छाड़ी का प्रचार प्रसार, प्रायोगिक को प्रोत्साहन, मध्य-स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान, बुनियादी शिक्षा, मौखिक शिक्षा, नारी उद्धार, समग्र ग्राम-सेवा, राष्ट्र भाषा प्रचार, मातृभाषा-प्रेम, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन, साम्प्रदायिक एकता, अखिलेश्वर, नरानन्द आदिवासी सेवा, मन्दिर, किसान एवं विद्यार्थी संगठन बनाना।

विदेशी आक्रमण और युद्ध के विरुद्ध सत्याग्रह—महात्मा गाँधी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह को प्रभावशालीता में पूरी आस्था प्रकट की। उनका अभिप्राय था कि विदेशी आक्रमण और युद्ध के विरुद्ध सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिये। युद्ध से हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। सत्याग्रह युद्ध के समान प्रबल प्रभावशाली साधन है तथा उससे श्रेष्ठ है। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध गाँधीजी ने अहिंसा और सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। उन्होंने एबीसीनिया के निवासियों, चैको, पोलैंड तथा आक्रमण से पीड़ित अन्य पक्षों को परामर्श दिया कि वे आक्रमणकारियों के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति अपनाएँ। गाँधीजी की दृढ़ मान्यता थी कि अहिंसात्मक प्रतिरोध अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग से आक्रमणकारी पर निरन्तर ऐसा "आक्रमण" करता रहता है जिसमें अन्तिम विजय उसकी होती है।

स्वराज्य राज्य अराजकता

(The Swarajya ~The State The Anarchy)

महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावादी थे। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में बिखरे हुए रूप में आदर्श अहिंसक समाज का रूपरेखा को समझाया था। एक आदर्श जनतन्त्रवाणी समाज में वे यद्यपि किसी रूप में राज्य के अस्तित्व के विरोधी थे, लेकिन व्यवहारवाद विचारक होने के नाते उन्होंने 1946 में स्पष्ट रूप से कहा था कि सत्तार में क्या बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं है यदि हम इस प्रकार के आदर्श अहिंसक समाज के लिए निरन्तर कार्य करते रहे तो ऐसे समाज का आविर्भाव इस समाज तक हो सकता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो।

राज्य हिन जनतन्त्र—राज्य के सम्बन्ध में गांधीजी की विचार दार्शनिक अराजकतावाणी थी। उनका मत था कि राज्य एक आवश्यक दुर्गुण है जो मानव-जावन के नैतिक मूल्यों पर आधारित करता है। गांधीजी का तर्क था कि प्रत्येक राज्य में सरकार सत्ता का पथ दिखाकर नागरिकों से कार्य करवाती है और उन्हें कानून के अनुसार चलन का बाध्य करती है। शासन व्यवस्था चाहे कितनी ही लोकतन्त्री हो, राज्य की जड़ में सदैव हिंसा होती है अर्थात् लोगों का शासन करने का प्रवृत्ति होता है। राज्य के विरोध में गांधीजी का दूसरा सबल तर्क यह था कि राज्य एक बाध्यकारी शक्ति है जो मानव के व्यक्तित्व के विकास को कुण्ठित करती है। राज्य व्यक्तित्व का विनाश करके मनुष्य मात्र को सबसे बड़ी हानि पहुँचाता है। राज्य का विरोध में गांधीजी का तीसरा मुख्य तर्क यह था कि अहिंसा पर आधारित किसी आदर्श समाज में राज्य सर्वथा अनिवार्य है। यद्यपि बाकुनिन, प्रोपोटेकिन तथा अन्य अराजकतावादी राज्य को अनिवार्यक समझते थे, लेकिन उनका मुक्तिवर्ग के विपरीत गांधीजी की मुक्तिवर्ग पूर्णतः नैतिकता प्रधान थी।

गांधीजी द्वारा कल्पित आदर्श अहिंसक समाज—महात्मा गांधी ने राज्य-सत्ता में अविश्वास व्यक्त करते हुए एक आदर्श अहिंसक समाज का कल्पना की। उन्होंने कहा कि यह आदर्श समाज विकेंद्रित समाज होगा। सत्ता उसका प्रत्येक क्षेत्र की विरूपता होगा। गांधीजी ने कल्पना की कि आदर्श जनतन्त्र लाभदायक स्वावलम्बी और स्वशासित सत्याग्रही ग्राम-समाजों का संचय होगा। अहिंसक समाज में सच और समुदायों का संगठन स्वेच्छा का आधार पर होगा। गांधीजी ने आदर्श ग्राम-समुदायों का अपने लेखों में वर्णन किया है। अराजकतावादी समाज का एकमात्र महत्वपूर्ण साधन होगा। धर्म या सामाजिक नाति-भावना धर्म मुक्ति की अन्तर्गत पर प्रभाव डालेगा और स्वतन्त्रता तथा सामाजिक एकता का सामना करेगा।

राज्य रहित समाज का सम्मन्धान—गांधीजी स्वर्णित कल्पनावादी नहीं थे। वे आमुल-पुल एक व्यावहारिक विचारक सत्त और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने एक आदर्श का कल्पना की, लेकिन व्यवहार में यही आशा प्रकट की कि हम उस आदर्श की ओर पहुँचने का प्रयत्न करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। समाज राज्य रहित तभी बन सकता है जब मनुष्य पूरा तरह आत्म-समय बन जाए और समाज का प्रति अपने कर्तव्यों का पालन बिना राज्य के करन ला। इसलिए 1931 में राज्य रहित समाज के बारे में उन्होंने कहा कि, "जावन में आदर्श क्या पूरा तरह कार्यान्वित नही होता।" वास्तव में गांधीजी का मत था कि राज्य रहित समाज के आदर्श की मनुष्य अपने जावन में पूरा तरह कार्यान्वित नहीं कर सकेगा। 1946 में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी इस प्रश्न में कोई रुचि नहीं है और सत्तार में कहीं भी बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं है परन्तु उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि लोगों द्वारा इस प्रकार के समाज के लिए निरन्तर कार्य करने से ऐसे समाज का आविर्भाव इस समाज तक हो सकता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो।

संसदीय लोकतन्त्र—गांधीजी ने प्रचलित लोकतन्त्र में अविश्वास व्यक्त किया। संसदीय लोकतन्त्र की उनकी आलोचना का मुख्य आधार यह था कि उसमें ईमानदारी और दौंग तथा प्रश्न की अधिकता है। परिणाम के राज्य नाममात्र के लोकतन्त्र है। उनमें लोकतन्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रति वास्तविक सत्य नहीं पाया जाता। शस्त्रोद्योग का हाद का पूज्यवाद साम्राज्यवाद तथा शोषण का राजनीतिक अधिकार और नैतिकता तथा दुर्बल नृत्त्व का यही कारण है। गांधीजी ने संसदीय की जननी ब्रिटिश संसद की कटु आलोचना करते हुए उसे बॉल की सजा दी, क्योंकि उसने क्या कोई अच्छा काम अपने-आप में नहीं किया। गांधीजी का कहना था कि यदि मतदाता समझदार हैं और अच्छे स अच्छे सत्य चुनकर संसद को भेजते हैं, एसी संसद का काम इतना अच्छा होगा चाहिए कि दिन-प्रतिदिन उसका तब बढ़ता नजर आए और लोगों पर उसका असर पड़ता जाए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है और सभी लोग इससे सहमत हैं कि संसद के सदस्य अधिकांश में दौंग और स्वार्थी होते हैं। गांधीजी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व का उपहास उड़ाया। ग्रामसभा का पार्लियामेंट का उदना चिन्ता नहीं होता ब्रित्ता अपनी सत्ता को होती है।

निर्वाचन—महात्मा गांधी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं थे, लेकिन उसका प्रचलित स्वरूप से उन्हें कोई आकर्षण न था। चुनवों द्वारा एक श्रेष्ठ-कार्य वर्ग जन्म लेता है जिसके द्वारा व्यक्ति का नैतिक पत्रन कर दिया जाता है। स्वराज्य पर गांधीजी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि "स्वराज्य से मेरा अर्थ है उन वस्तु-वस्तुओं का

जन्म-मर्णा। गांधीजी राष्ट्रवादी थे, लेकिन जो राष्ट्रवाद आज दुनियाँ के लिए खतरा हो रहा है और जिसने संसार की शक्ति के लिए भारी खतरा उत्पन्न कर दिया है, उस राष्ट्रवाद के गांधीजी सम्पर्क नहीं थे। उनका राष्ट्रवाद नैतिक साम्राज्य, जीवन की सहिष्णुता तथा अध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आधारित था। उनका राष्ट्रवाद उनके विश्व-प्रेम का एक अंग था। गांधीजी विश्व को एक और पवित्र भारत का दान करना नहीं चाहते थे, उसकी सेवा के लिए साहस, परिश्रम और आत्म-विश्वास। भारत को भेंट करना चाहते थे। उनका कहना था कि "यूरोप के लोगों पर लौटता हुआ भारत मानवता को क्या आशा दे सकता है?" गांधीजी के राष्ट्रवाद में एक ओर भय का एक प्रबल साधन बनाने की आकांक्षा थी। गांधीजी का राष्ट्रवाद प्रेम, अहिंसा और बन्धुत्व से परिपूर्ण था। गांधीजी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि यदि हम भारत में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। 'हरिजन' में उन्होंने लिखा—"यदि हम भारतीय राष्ट्रियता का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हम क्षेत्रीयता की जमीनों को छोड़ना ही होगा।"

स्वतन्त्रता का दर्शन (Philosophy of Freedom)

गांधीजी के हृदय में राजनीतिक स्वतन्त्रता की उत्कृष्ट कामना थी। वे स्वराज्य को सत्य का एक अंग मानते थे, अतः स्वतन्त्रता उनके लिए एक पवित्र वस्तु थी। उनका विश्वास था कि स्वराज्य संघर्ष के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साम्राज्यवादी देशों को उन्होंने यह चेतावनी दे दी कि दूसरों पर साम्राज्य स्थापित करने की सलाह उसका नैतिक पतन कर देगी। गांधीजी ने नैतिक के इस बचन को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए स्वराज्य-प्राप्ति उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधीजी राजनीति का स्वतन्त्रता के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहते थे, वे सर्वोदय के उपासक थे, उनका स्वराज्य लाखों करोड़ों दलितों के लिए था। गांधीजी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के अर्थ में स्वतन्त्रता का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए अर्पण कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत और नागरिक दोनों स्वतन्त्रताओं का पक्ष लिया। उन्होंने भाषण और लेख की स्वतन्त्रता को स्वराज्य की आधारशिला माना।

गांधीजी के आर्थिक विचार (Economic Ideas of Gandhiji)

गांधीजी ने सामाजिक आर्थिक विचारों की कोई निश्चित योजना प्रस्तुत नहीं की, बल्कि समय-समय पर जो भाषण दिए और लेख लिखे, उनसे हमें उनके सामाजिक आर्थिक दर्शन का बोध होता है।

सहकार या प्रत्यास था मित्रान

गांधीजी समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को मिटाना चाहते थे, व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त चाहते थे, लेकिन मार्क्सवादी प्रोलेटेरियन क्रान्ति के पक्ष में नहीं थे। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए गांधीजी ने 'सहकार का सिद्धान्त' (Principle of Trusteeship) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में भारी सम्पत्ति मिली है अथवा किसी ने व्यापार-उद्योग के रूप में धन एकत्र किया है वह सम्पत्ति भारत में इस व्यक्ति को न होकर सारे समाज की है, अतः यह उचित होगा कि जिस व्यक्ति ने सम्पत्ति का संचय किया है वह स्वयं को सम्पत्ति का स्वामी न समझ कर दूसरी सन्तुष्टि। सम्पत्ति उसके पास रहे, वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उसमें से वाजिब खर्च करे और शेष को समाज की धरोहर समझे, जिसका उपयोग समाज के लिए होना चाहिए। सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सम्पत्ति पर ही व्यक्ति अपना अधिकार समझे और धन का शेष भाग राष्ट्र का मानते हुए सभी के कल्याण पर खर्च करने की तयारी रहे।

औद्योगीकरण

गांधीजी बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार बड़े पैमाने के उत्पादन से विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का उपयोग बन्धुत्व की आत्मा को बुरा करता है और वह परिश्रम से कमजोर करता है। गांधीजी ने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया अर्थात् ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें श्रमिक अपना स्वामी हो। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के शोषण और हिंसा के लिए कोई अवसर नहीं रहेगा। महान्ता गांधी का विश्वास था कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले गरीब देश के लिए मशीनों का उपयोग लाभप्रद नहीं होगा। अधिक जनसंख्या को कम पर लगाने की दृष्टि से उत्पादन की ऐसी प्रणालियाँ कम में सहायी होंगी जिनमें अधिकधिक श्रमिकों की खपत हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे मशीनों द्वारा संचालित उद्योगों के विरोधी थे। व्यवहारिक होने के नाते गांधीजी अदलावत और पर्यायवाद में संधि करते हुए चले। अन्तिम रूप में उनका आग्रह था कि बड़े पैमाने के उद्योगों को कुटीर उद्योगों का प्रतिद्वंद्वी न बनकर उनका सहायक बनना चाहिये। उद्योगों के क्षेत्र में गांधीजी प्रयोगों और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने देते थे कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले विकासशील देशों में छोटे उद्योगों से न केवल पूर्ण रोजगार की व्यवस्था होती है, बल्कि काम करने वालों को अधिक आत्म-सन्तोष प्राप्त होता है। ऐसे उद्योगों द्वारा विदेशों से महंगी और पेटेंट मशीनें मँगाने का व्यय बचता है तथा देश की अर्थ-निर्भरता में वृद्धि होती है। उत्पादन व्यय

सुरक्षा, रक्षण और प्रदूषण रहित वातावरण इन सभी दृष्टिकोणों से संपु-उद्योग व्यवहार्य और वांछनीय लगता है, किन्तु यह बहिष्कृत और विरक्त है। भारत में गांधीवाद का अनुसरण कम होता है किन्तु उन्कर प्रचार अधिक किया जाता है। विवेकीकरण

गांधीजी केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के विरुद्ध थे क्योंकि उनका विश्वास था कि इसकी नींव हिंसा पर आधारित है, अतः उन्होंने विवेकित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि उत्पन्न होने वाले अनेक स्थानों पर छोटे पैमाने का काम किया जाए, पैसे में छोटी इकाइयाँ स्थापित की जाएँ। विवेकित व्यवस्था को वे लोकतन्त्र का जीवन इतना समझते थे। उनके अनुसार "अहिंसात्मक राज्य की स्थापना के लिए कारखाने वाली संस्था को कोई आवश्यकता नहीं है।" गांधीजी इस की भी। राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक नहीं थे। वे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे लोकतन्त्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वशासन और संपु-स्तरीय उद्योगों के लिए यह बाधक सिद्ध होगा।

अर्थव्यवस्था के प्रति वैयक्तिक दृष्टिकोण

गांधीजी ने आर्थिक विचारों को नैतिक आधारितता प्रदान की। उनके अनुसार सच्चा अर्थशास्त्र कभी उच्चतम नैतिक मूल्य के विरुद्ध नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र को न्याय-भावना से परिपूर्ण होना चाहिये। वह अर्थशास्त्र जो व्यक्ति अपना राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर आपत्त करता है, अनैतिक है, इसलिए पारपूर्ण है। मनुष्य अपने लिए नैतिक लाभ की आशा से कर्म करने को प्रेरित हो, इस प्रकार का विचार पतन की ओर से जाने वाला है। गांधीजी ने मनुष्य के धार्मिक सम्बन्धों का आधार धर्म को नहीं, प्रेम को बनाया और कहा कि मालिक अपने नीकर से जितना काम प्रेमपूर्ण व्यवहार से ले सकता है उतना आर्थिक प्रलोभन या दबाव से नहीं।

गांधीजी का सामाजिक चिन्तन

(Social Thought of Gandhiji)

गांधीजी ने भारतीय समाज में व्याप्त वृत्तियों पर प्रहार करते हुए समाज का नव-निर्माण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि 'असुर्यता हिन्दू समाज का घोर अभिशाप है। इन्हीं समाज में दारों पैदा करने, इसे कमजोर कर डालना है। यह 'पापमूलक संस्था' किसी धर्म का अंग नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है।' असुर्यता एक पुनः है जो हिन्दू समाज को अन्दर ही अन्दर टूट जा रहा है। अपने प्रवास में उन्हें सफ़लता मिली और स्वतन्त्र भारत के संविधान में किसी भी रूप में असुर्यता को एक अपराध घोषित कर दिया गया। गांधीजी ने मोक्षता को असुर्यता-निवारण के बिना स्वयं का अर्थ नहीं है। गांधीजी ने अश्वेतों से जिन्हें वे हरिजन कहते थे, प्यार किया तथा उनकी सेवा करते और छाते-छाते थे। गांधीजी ने हरिजनों को उपदेश दिया कि वे शांति में रहें, शांति में रहें, शांति में रहें, अपने दुर्घटनाओं को दूर करें और दूसरों की छोड़ी हुई मूठने स्वीकार न करें। इससे अनेक बीमारियाँ फैलती हैं। गांधीजी ने पश्चिम की औद्योगिकी संस्था के लोगों को गिनाया जिसमें व्यक्ति की सम्पत्ति और समृद्धि उसकी प्रतिष्ठा की सूचक होती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक प्रगति तो नैतिकता, सत्य और अहिंसा की प्रगति में निहित है। औद्योगिकी संस्था नैतिक विनाश की ओर से जाने वाली है। हमें आध्यात्मिक आचरण को प्रयत्नता देनी चाहिए। सदा जीवन और उच्च विचार—यह हमारा आदर्श होना चाहिए। भारतीय नारी की दुर्दशा से गांधीजी दुःखी थे। यह दलील मान्य नहीं थी कि विधवाँ दुर्दिन तथा योग्यता में पुर्णों से किसी प्रकार कम हैं। वे इतिहास को इसी मानकर कहते थे कि प्राचीन भारत में जीवन के अनेक क्षेत्रों में पुर्णों से स्त्रियों आगे थीं और सामाजिक जीवन में उन्होंने अपने को ऊपर उठाया है। इसी सुनिश्चित आत्म-त्याग है और रही तथा पुर्ण का समान दर्जा है और एक के अस्तित्व का औचित्य दूसरे के बिना सिद्ध नहीं होता। गांधीजी ने स्त्रियों को पुर्णों के समान अधिकार और आजादी देने का पक्ष लिया। गांधीजी ने पदों प्रथा पर आपत्त किया। स्त्रियों अपने असती रूप में आएँ और फिर सन्देश दें। गांधीजी ने स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता का पोषण ही नहीं किया, बल्कि उनको राजनीतिक स्वतन्त्रता की भी वकालत की। उन्होंने स्त्रियों के मतधिकार का पक्ष लिया।

गांधीजी ने एक और सामाजिक समस्या—विधवा पुनर्विवाह पर ध्यान दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए। गांधीजी को बाल विवाह मान्य नहीं थे। उन्होंने समाज-सुधारकों से अनुरोध किया कि वे इसका विरोध करें। बाल विवाह से दम्पति के स्वास्थ्य का ह्रास होने के अतिरिक्त बच्चे अधिक पैदा होते हैं। भारत में बाल-विधवाओं के अस्तित्व का एक प्रमुख कारण बाल विवाह है। यह हमारे सामाजिक, नैतिक तथा शारीरिक ह्रास का भी प्रमुख कारण है। गांधीजी की धारणा थी कि परिवर्धन बहुत बड़ी बुराई है। उनकी दृष्टि से शराबी और चोर एक ही पैली के चट्टे-चट्टे हैं क्योंकि जहाँ चोर केवल धन सम्पत्ति चुराता है वहीं शराबी न केवल अपनी सम्पत्ति को, बल्कि अपनी तथा अपने पड़ोसी की इज्जत को भी जोखिम में डालता है। चूँकि महिला पान से शरीर तथा

आत्मा दोनों की रूढ़ि होती है, इसलिए व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए ही वह सर्वाधिक हानिकारक है। गांधीजी गौरवा के हिमायती थे। उनकी राय में गौरवा का अर्थ मनुष्य, पशु तथा पक्षी तीनों की सेवा है। गांधीजी को विश्वास था कि भारतवासियों की बहुत सी सामाजिक समस्याओं का समाधान उच्च शिखा पद्धति से हो सकता है—ऐसी पद्धति जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो। गांधीजी स्वीकार करते थे कि पशुपति देश में सामाजिक सुधारों को स्थापित करना स्थापना को स्थापित करना है। गांधीजी ने समाज सुधारकों को चेतावनी दी कि उनका काम कठिन और ठकाने वाला है और निस्वार्थ भावना से समाज सेवा करना आसान नहीं होता। समाज सेवा को शान्त तथा धैर्यवान होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति किसी राष्ट्र की अमूल्य निधि होता है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के वैचारिक आधार (1932-40 में महात्मा गांधी की सक्रियता)

राष्ट्रीय आन्दोलन में व्याप्त रहने के कारण गांधीजी उसके वैचारिक पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे पाए। विद्वान् लेखक धर्मपाल ने अपने एक शोधपूर्ण लेख में इस प्रकार को अग्रिम उद्घाटन हुए यह सिद्ध किया है कि 1932-40 के पूरे समय में गांधीजी राष्ट्रीय आन्दोलन के अनेक वैचारिक आधारों को स्पष्ट करने में लगे थे। 1919 से 1931 तक के समय को भारतीय जन के एकत्रीकरण को ऐसे दौर के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने स्वयं को, तथा अंग्रेजों को और सारे सत्ता को यह आधार का दिया था कि ब्रिटिश राज के खिलाफ और उनके नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में जो सफल हुआ है, वह स्पष्ट राजनीतिक स्थापना को ओर बढ़ रहा है। 1933 से शुरू होकर 1940 तक पूरे अंग्रेज के साथ चले दौर के निरुद्ध भविष्य में सम्भावित आवाजों के लिए महात्मा गांधी द्वारा उसकी अन्तर्वस्तु और सत्ता का स्वरूप प्रस्तुत करने के प्रयास के दौर पर देखा जा सकता है। एक नया दौर 1932 में शुरू हुआ जब 'दलित वर्गों' के नाम से परिभाषित समूहों को हिन्दुओं से अलग करने की अभियानों द्वारा रथी गई रणनीति के खिलाफ गांधीजी ने अपना उपवास शुरू करने का फैसला लिया। उपवास शुरू होने के कुछ दिनों के अन्दर 'दलित वर्गों' और शेष हिन्दुओं के प्रतिनिधियों के बीच मामला सुलझा लिया गया। इस अवसर पर 25 सितम्बर, 1933 को मुम्बई में हिन्दुओं की ऐतिहासिक सभा हुई जिसमें प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि "आज से हिन्दुओं में किसी को जन्म के आधार पर अलग नहीं मना जाएगा और अब तक जिन्हें ऐसा माना जाता रहा है, उन्हें ऊँचों, विद्यालयों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक सभ्यताओं के उपयोग के मामले में वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो अन्य हिन्दुओं को प्राप्त हैं।"

1934 में उन्होंने कहा—"असुरधरा के खिलाफ अभियान में अब अलग नाम से चिन्हित लोगों की रस्मी असुरधरा के उन्मूलन से ज्यादा का समावेश होने लगा है। शहर में रहने वाली के लिए गाँव अलग बन गए हैं और इस व्यापक असुरधरा को खत्म करने के लिए प्राचीन उद्योगों का नवीकरण अधिक जरूरी हो गया है।" असुरधरा उन्मूलन के प्रयासों, शहर और गाँव के बीच खाई कम करने की कोशिश और प्राचीन उद्योगों के पुनर्जीवन की पहल ने ब्रिटिश दायरे वाली विद्यमान शिखा पद्धति की व्यर्थता को स्पष्टता से साक्षात्कार करा दिया और सभी स्तरों पर उपयोगी पद्धति को जल्द प्रकट हुई। पहले कदम के रूप में यह पद्धति सम्मले आई जिसे गांधीजी की बुनियादी शिक्षा कहा जाता है और जो हाथ के काम के माध्यम से प्रदान की जाती है। 1934 से 1940 को शुरूआत तक, गांधीजी स्वयं की गांधी सेवा सभ के सदस्यों तथा लोगों के साथ ऐसे विचारों के लिए प्रयत्न कर रहे थे जो नर भारत की क्रियाशीलता के लिए उनकी दृष्टि से अपेक्षित मार्ग से संस्थाओं और संरचनाओं से पूर्णतः सम्बन्धित थे। सितम्बर, 1939 में यूरोप में युद्ध शुरू होने के साथ, भारत में राजनीतिक परिस्थितियों में नाटकीय बदलाव आया। भारतीय राष्ट्रीयता और ब्रिटिश सत्ता में टकराव आसान दिखने लगा। अन्य कारणों के सम्मिश्रित प्रभाव से, गांधीजी ने फरवरी, 1940 में सभ को सन्नाह दी कि वह खुद को सिकोह से। राजनीति में भाग निर निर वह एक सततचोला विद्यमान या रोष सत्ता बन सकती है, इसलिए गांधीजी की इच्छा थी कि वह मुम्बईजित दंग से उन संस्थाओं, संस्थानों और राजतन्त्र के आधारों पर काम करें, जिनसे वे स्वयं और एक संस्था के दौर पर गांधी सेवा सभ निम्नो छ वर्षों से सक्रियता से सतन रहा है। जल्दी ही यह पृष्ठभूमि में पड़ गया। गांधीजी ने नया सक्रिय अवस्था आन्दोलन आरम्भ किया और बाद में अंग्रेजों से कहा 'भारत छोड़ो'। फलतः देशव्यापी गिरफ्तारियाँ हुईं और भारत विभाजन की सम्भावना सामने आई तथा 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ।

महात्मा गांधी का मूल्यांकन एवं देन

गांधीजी का मूल्यांकन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने हमें एक नैतिक पीढ़े प्रदान की, हजार आन्दोलन को जगया और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। गांधीजी ने राष्ट्र में यह अनुभूति पैदा की कि हम निरुद्ध हैं पर बुद्ध नहीं, हम शान्ति हैं पर भाग्य के श्रोते नहीं हैं, हम पशुपति हैं, पर उस पशुपति का सौंकरों को चुरा बिना हम न होंगे। गांधीजी ने राष्ट्र को मार्ग बदला और अधिसूचना सत्ता का अन्त प्रदान किया। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में गहरे परिवर्तन किए। जीवन की एक व्यापक धारणा के कारण सामाजिक, आर्थिक, अधिष्ठित क्षेत्रों में रूढ़ि की।

उन्होंने हिन्दुओं को जगाया, सामाजिक कुपितियों के निवारण की गति को तेज कर दिया और अछूतों तथा उत्पीड़ितों को आस्था प्रदान किया। उन्होंने किसानों की ओर निरन्तर के भाव से देखा, गृह-उद्योगों का उद्धार किया और देशी कलाओं को पुनर्जीवन प्रदान किया।¹ डॉ. रामकृष्णन के अनुसार, "गौंधीजी नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के महान् देवता के रूप में सदैव स्मरण किए जायेंगे जिनके बिना पण ब्रह्म विश्व को शक्ति प्राप्त न होगी।" डॉ. राजेन्द्रप्रसाद के अनुसार, "भारतीय राजनीति की और दुनिया के सारे पीड़ित इंसानों को गौंधीजी की देन वह अतोन्मत्त तरीका है जो उन्होंने मुझ से सहने के लिए बताया और हमें प्रदान किया। उन्होंने भारत को तथा दुनिया को बुद्ध की जगह एक नैतिक शासन दिया। उन्होंने राजनीति को असत्य से उठाकर आदर्शवाद पर पहुँचा दिया जिसमें संघर्ष चाहे जितना अच्छा हो, पर शुद्ध सत्यता के अन्तर्गत और किसी तरह के साधन किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराये जा सकते। उन्होंने सत्य को राजनीति में सबसे ऊँचा रखा।" रामकृष्णन के अनुसार, "गौंधीजी राजनीतिक पुरुष एवं धनुष्य के उद्धारक तथा नए मूल्यों के सम्पादक थे।"

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

(Dr. B. R. Ambedkar)

डा. सहेब भीमराव अम्बेडकर 20वीं शताब्दी के चिन्तक, दूरदर्शी, वक्ता, ओजस्वी लेखक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध पारंगत योद्धा की भाँति संগ্রाम कर दीन-हीन तथा दलितों की सामाजिक अवस्था सुधारने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म और शासन-सौजन्य अछूतों के गरीब परिवार में हुआ था। उस समय सुआहुत का प्रभाव सारे देश में फैला हुआ था, फिर भी उन्होंने जोश एवं सत्य के साथ हिमिया प्राप्त की। स्वतन्त्र भारत के वे प्रथम कानून मंत्री बने।

डॉ. अम्बेडकर : जीवन परिचय (Dr. Ambedkar - Life Sketch)

महाराष्ट्र के महार परिवार में इन्दौर के पास महु छान्नी में 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉ. अम्बेडकर (1891-1956) ने सुआहुत की पीड़ा बचपन से ही महसूस की थी। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था जो कबीर के अनुयायी होने के कारण जाति-प्रथा को नहीं मानते थे। डॉ. अम्बेडकर के बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनकी शिक्षा-दीक्षा महाराष्ट्र में हुई। 1907 में उन्होंने सतरा से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त कर उन्होंने मुम्बई के एलफिन्स्टन कॉलेज से उच्च शिक्षा पाकर अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय से 1915 में एच. ए. (अर्थशास्त्र) कर 1916 में लन्दन के 'स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एण्ड पोलिटिक्स साइंस' में प्रवेश लिया, किन्तु उन्हें बड़ौदा राज्य के 'सेना सचिव' पद पर कार्य करने हेतु भारत आना पड़ा। 1920 में वे पुनः लन्दन चले गए और 1921 में एम.एस.सी. करने के बाद वहीं से उन्होंने 'The Problems of the Rupee' शोध ग्रन्थ लिखकर पी.एच.डी. की उपाधि ली और वकालत की 'बा एट लॉ' की उपाधि ली।

डॉ. अम्बेडकर ने भारत आकर स्वतन्त्र रूप से वकालत का अपना काम शुरू कर दिया, पर समाज के ठेकेदार उन्हें अछूत ही समझते थे। उनकी व्यावसायिक कुशलता का किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन टॉक एक्सचेंज के व्यापारी उनको किनारा किए रहते थे। एक कंसिज में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त होने पर सहयोगियों को यह गवारा नहीं हुआ कि वे एक पढ़े से पानी पीएँ। अपनी योग्यता के बल पर अम्बेडकर ने छात्रों को अपना प्रशंसक बना लिया था। 1927 में उन्होंने मुम्बई से 'बहिष्कृत भारत' समाचार पत्र निकाला और 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय 'दलित वर्ग संघ' (All India Depressed Class Association) का अध्यक्ष पद सम्भाला तथा हिन्दुओं की जाति प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1930 एवं 1931 में लन्दन में प्रथम और द्वितीय 'गोलेमेज सम्मेलन' (Round Table Conference) में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया तथा भारत की विधान परिषदों में हिन्दुओं से पृथक् दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की माँग की। यद्यपि डॉ. अम्बेडकर देश की स्वतन्त्रता हेतु किए जा रहे आन्दोलन के समर्थक थे, किन्तु महात्मा गाँधी एवं कांग्रेस पार्टी की नीतियों से दलितों के पक्षधर होने के कारण उनका मतभेद था। डॉ. अम्बेडकर दलितों के पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग करते थे जबकि गाँधीजी इस पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग को हिन्दुओं की विभाजित करने का बहाना मानते थे और उसका विरोध करते थे। डॉ. अम्बेडकर के मतभेद गाँधीजी एवं कांग्रेस से फटपूर होते गए। गाँधीजी दलितों के हिन्दुओं से पृथक् प्रतिनिधित्व का विरोध करते रहे जबकि अम्बेडकर पृथक् प्रतिनिधित्व के प्रबल पक्षधर बने रहे। अन्ततः अम्बेडकर सफल हुए जब 1932 में 'मैकडोनाल्ड पंचल' द्वारा सरकार ने अस्पृश्यों (अछूतों) को सवर्ण हिन्दुओं से पृथक् प्रतिनिधित्व प्रदान किया, किन्तु 'पूना समझौते' (Poona Pact) पर उन्हें हस्ताक्षर करने पड़े। जिसमें कहा गया कि कोई अस्पृश्य नहीं। सम्पूर्ण दलित वर्ग (अछूत) हिन्दु हैं, उनसे अलग नहीं।

डॉ. अम्बेडकर ने 1936 में 'स्वतन्त्र मजदूर दल' (Independent Labour Party) की स्थापना कर दलितों द्वारा एवं मजदूर किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य प्रारम्भ किया। इस दल के तत्कालीन प्रमुख 1937 का चुनाव लड़ा गया और इस दल ने अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित 15 स्थानों में से 13 स्थानों पर विजय प्राप्त की। मुम्बई विधानसभा के सदस्य के रूप में अम्बेडकर ने किरायेदार कानून, हड़ताल विरोधी विधेयक का तीव्र विरोध किया और मजदूरों के लिए सत्याग्रह के अधिकार की वकालत की। 'स्वतन्त्र मजदूर दल' को अम्बेडकर ने 'अखिल भारतीय अनुसूचित जाति सघ' (All India Scheduled Caste Federation) का रूप दे दिया। 7 अगस्त, 1942 को उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद (Council) का सदस्य मनोनीत किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने 1942 में मुम्बई विधानसभा में देश भक्ति के समर्पन में कहा—“मेरा विरोध कुछ मामलों में सर्वानुमति हिन्दुओं से है। मैं रायच सेता हूँ कि मैं अपने देश की रक्षा अपना जीवन समर्पित कर दूँगा।” यद्यपि अम्बेडकर ने 1942 के गांधीजी द्वारा प्रवर्तित 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का विरोध किया था, तथापि यह विरोध देश की स्वतन्त्रता का विरोध न होकर इस स्वतन्त्रता के लिए गांधीजी एवं कांग्रेस द्वारा अपनाई गई रणनीति से था। डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे। उनकी देश भक्ति में किसी को संदेह नहीं था, इसीलिए कांग्रेस के सहयोग से वे 'सविधान सभा' (Constituent Assembly) के सदस्य निर्वाचित हुए और उन्हें 'सविधान प्रारूप समिति' (Constitution Draft Committee) का अध्यक्ष बनाया गया। इस दायित्व का उन्होंने पूर्ण योग्यता से निर्वहन किया और सविधान निर्माण में उनके अपूर्व योगदान के कारण उन्हें 'आधुनिक युग का मनु' कहा गया। 3 अगस्त, 1949 को डॉ. अम्बेडकर भारत सरकार के विधि मंत्री (Law Minister) बने और 'हिन्दू कोड बिल' (Hindu Code Bill) के निर्माण में उनका योगदान रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू से उनके मतभेद बढ़ते गए जिसके कारण 27 सितम्बर, 1951 को उन्होंने मंत्रिमण्डल से स्टीच दे दिया। हिन्दू धर्म में दलितों (अद्वैतों) की असमानजनक स्थिति उनके स्वाभिमान को सहा नहीं थी, अतः उन्होंने 5 लाख दलित अनुयायियों सहित 14 अक्टूबर, 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर धर्मपरिवर्तन कर लिया। 6 दिसम्बर, 1956 को अम्बेडकर का निधन हो गया।

सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता और दलितोद्धार

डॉ. अम्बेडकर ने देश के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिन्दू धर्म के चतुर्थी वर्ग से उनकी अस्मरण्या तदाकथित दलित वर्ग के पिछड़ेपन का मूल कारण है। जब तक इस अस्मरण्या को मिटाया नहीं जाता, सामाजिक समानता का प्रश्न ही नहीं उठता। डॉ. अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे लोगों को प्रेरणा दी कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजें। डॉ. अम्बेडकर का विरोध छुआछूत के विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि यह भारत-भूमि में जातिवाद और वर्गभेद को मिटा देना चाहते थे। उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए मैदान में आकर लड़ने का फैसला किया और 1927 में पहाड़ पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। चारदार ताताब से सामूहिक रूप में पानी पीया गया। उन्होंने गुजरात में कालाराम मन्दिर में अद्वैत के प्रवेश पर विरोध के विरुद्ध एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया। समय के साथ अस्मरण्या पर डॉ. अम्बेडकर के प्रहार तेज होते गए। विदेशी शासन से मुक्ति के सपने में डॉ. अम्बेडकर अन्य राष्ट्रीय नेतृत्वों से पीछे न थे। वे यह मानते थे कि स्वराज्य मिलने पर सामाजिक समानता लाने की दिशा में समुचित प्रगति हो सकती है।

सविधान रचना

संसद—सविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने प्रजातान्त्रिक एवं संसदीय प्रणाली का समर्थन किया। डॉ. अम्बेडकर का मत था कि प्रजातान्त्रिक प्रणाली भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस व्यवस्था में सभी को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने द्विसदनीय विधानमण्डल का पक्ष लिया। संसद के कार्यकाल के सम्बन्ध में चाण्डिदास के समय के टी. तारु ने सुझाव दिया था कि आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के बाद संसद का निर्वाचन केवल अवशिष्ट समय के लिए होना चाहिए न कि पूर्ण अवधि के लिए, किन्तु यह सुझाव स्वीकृत नहीं हुआ। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि चुनाव कोई मामूली कार्य नहीं है। इसमें अत्यधिक व्यय होता है और यह किसी रूप में उचित नहीं होगा कि सरकार छोटी अवधियों के लिए चुनाव करकर जनता पर व्यय का अनावश्यक बोझ डाले। डॉ. पट्टाभिसीतारमैया और अन्य सदस्यों ने यह राय व्यक्त की कि संसदकाल के दौरान संसद की अवधि अकेले राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि संसद की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए। विशिष्ट समिति ने इस सुझाव में कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाई। फलस्वरूप डॉ. अम्बेडकर ने यह संशोधन रखा कि संसद की अवधि 'संसद के कानून द्वारा' (By Parliament by Law) बढ़ाई जा सकती है न कि 'राष्ट्रपति द्वारा' (Not by President) जो स्वीकार कर लिया गया।

राष्ट्रपति—डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति को सांविधानिक अध्यक्ष बनाने का पक्ष लिया। राष्ट्रपति की स्वेच्छा का क्षेत्र क्या है? इस पर डॉ. अम्बेडकर ने सविधान सभा में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि सविधान में राष्ट्रपति के स्वेच्छिक कृत्य नहीं, बल्कि स्वेच्छिक परामर्शिकार (Prerogatives) हैं। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी व्याख्या इस प्रकार व्यक्त की—संसद

के विघटन के सम्बन्ध में अंग्रेजी संविधानिक विधि-वेताओं का कोई विधिगत मत नहीं है। कुछ व्यक्तियों का मत है कि सम्राट अथवा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की मंत्रणा स्वीकार कर लेनी चाहिए यदि वह देखे कि सदन अदृश्य हो गया है अथवा सदन होके-बन्धा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस सम्बन्ध में एक मत यह है कि प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमण्डल ऐसा पत्राचार दे अथवा न दे परन्तु यदि राष्ट्रपति के अनुसार सदन स्वेच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से सदन का विघटन कर सकता है। ये राष्ट्रपति के परमाधिकार हैं। ये देश के प्रशासन के अन्तर्गत नहीं आते।

संघीय कार्यपालिका—संविधान सभा में संघीय कार्यपालिका के स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त वाद-विवाद के उपरान्त संविधान की धारा 74 के अन्तर्गत एक संघीय मंत्रि-परिषद् हो जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देना हो। मंत्रि-परिषद् ही देश की वास्तविक कार्यपालिका हो और इसका अर्थात् प्रधानमंत्री कहलाए।

मंत्री की योग्यताएँ—एक मंत्री की योग्यताएँ (Qualifications) क्या हैं यह विषय संविधान-सभा में रोचक वाद-विवाद का विषय रहा। मोहम्मद ताहिर ने प्रस्ताव किया कि ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त न किया जाए जो अपनी नियुक्ति के समय सदन का निर्वाचित सदस्य न हो, किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को आस्वीकार कर दिया। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि यदि कोई योग्य व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र में किसी कारणवश पराजित हो गया हो तो उसे इस आधार पर मंत्री बनाना अनुचित न होगा कि वह अपनी नियुक्ति से 6 माह की अवधि के भीतर किसी न किसी प्वाण्ड क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हो सके। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि किसी गैर संसद सदस्य को मंत्री बनाने की सुविधा 6 माह तक सीमित रखी गई है। अम्बेडकर का दूसरा प्रस्ताव के. टी. शाह ने रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल में से की जानी चाहिए। अम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था का उल्लेख करने के विचार से असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह पूर्ण सम्भव और व्यापारिक है कि चुनाव से सत्तर में कभी ऐसे अनेक दल आ जाएँ जिनमें से किसी का बहुमत न हो। इस स्थिति में, श्री शाह द्वारा प्रस्तावित संस्थापन पर आचरण करने से सरकार का निर्माण असम्भव हो जाएगा। अम्बेडकर ने के. टी. शाह के सुझाव को इस आधार पर अमान्य ठहराया कि संवत्कालीन अवस्था में यदि किसी मिश्रित मंत्रिमण्डल (Coalition Ministry) के निर्माण की आवश्यकता हो, जिसमें अल्पसंख्यक दल को लेना पड़े तो शाह के प्रस्ताव के अन्तर्गत मंत्रिमण्डल का निर्माण नहीं हो सकेगा।

आपातकालीन प्रावधान—संविधान में इन आपात-उपबन्धों से सम्बद्ध अध्याय की सभा में और बाहर जितनी कटु-आलोचना की गई उतनी और किसी अध्याय की नहीं, किन्तु संविधान सभा में अधिकारा सदस्यों का स्पष्ट मत था कि देश के हित में स्वतन्त्रता की अपेक्षा सुरक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। केन्द्र को इस दृष्टि से सर्वोच्च-शक्ति-सम्पन्न इसलिए होना चाहिए कि राज्य तथा सभ को इकाइयों का आक्रमण का सम्फलपूर्वक सामना करने की शक्ति नहीं रखती और आन्तरिक विलास्य की सुलझाने के सम्बन्ध में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपात-काल में विकीर्ण सत्ता विनाश का कारण बन सकती है। डॉ. अम्बेडकर ने यह महत्वपूर्ण तर्क दिया कि "केन्द्र ही सम्पूर्ण देश की समान भलाई के लिए कार्य कर सकता है, अतः केन्द्र को आपातकाल में राज्य सरकारों की शक्तियाँ ग्रहण करने का अधिकार दे देना व्यापोगित है।" संविधान के श्राव्य की प्रस्तावना करते समय डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति को इन शब्दों में स्पष्ट किया—“भारत के श्राव्य संविधान में भारत सभ का अध्याय जिस अधिकारों को बताया गया है उसे ‘सभ का राष्ट्रपति’ की सहायता दी गई है। इस उपाधि से अमेरिका के राष्ट्रपति का ध्यान आता है, परन्तु सभा की समानता के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित शासन प्रणाली के साथ श्राव्य में परिकल्पित शासन-प्रणाली का सम्बन्ध नहीं है। दोनों में मौलिक भेद है। अमेरिका में अध्यात्मिक शासन है और कार्यपालिका सत्ता राष्ट्रपति में निहित है तथा प्रशासन सत्ता उसी के हाथों में है। भारत में राष्ट्रपति का स्थान खरी होगा जो ब्रिटिश सम्राट का संविधान के अन्तर्गत है। यह श्राव्य-ध्याय तो होगा, किन्तु कार्यपालिका का मुखिया नहीं। यह राष्ट्र का प्रतिनिधि है, शासक नहीं, यह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में इसका स्थान अनुष्ठानिक मुद्रा का है जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णय प्रख्यात किए जाते हैं।”

निवारक नजरबन्दी अनुच्छेद—संविधान सभा में निवारक नजरबन्दी सम्बन्धी अनुच्छेद की संविधान में शामिल करने का तर्कसम्पत् उत्तर देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि “यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था धंग करने वाले देश की रक्षा सेवाओं (Defence Services) में गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों का विशेष करना कार्यपालिका के लिए आवश्यक हो सकता है। मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को राज्य के हितों पर वरीयता प्रदान नहीं की जा सकती है।”

धार्मिक स्वतन्त्रता—धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार चर्चित रहा। संविधान सभा में यह तर्क दिया गया कि धार्मिक स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति और धर्म-निषेध राज्य की धारणा—ये परस्पर विरोधी अवधारणाएँ हैं। डॉ. अम्बेडकर ने सदन में एक स्थल पर स्पष्ट किया कि “धर्म-निषेध राज्य का यह अर्थ नहीं है कि हम धार्मिक धारणाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे। इसका अर्थ है कि यह संसद देश के नागरिक पर विशेष धर्म लादने का अधिकार नहीं रखती। यह एक परिसीमा संविधान स्वीकार करता है।”

संविधान सरोपन—सौविधानिक उपचार का अधिकार सम्बन्धी अनुच्छेद संविधान-सभा में रोचक और महत्वपूर्ण विवाद का विषय बना। इस अनुच्छेद के महत्व की व्याख्या करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि "यदि कोई मुझे यह पूछे कि संविधान का वह कौनसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान ग्राह्य हो जायेगा, इस अनुच्छेद को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान का हृदय तथा आत्मा है और मुझे प्रसन्नता है कि सदन ने इसके महत्व को समझा। भविष्य में कोई संसद इस अनुच्छेद में अधिक से अधिक सुधारों को नहीं कर सकती क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की सहायता निधानों की शक्ति सम्पद की दृष्टि से बनाई गई किसी विधि पर अंग्रेज नहीं बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार सौविधानिक सरोपन द्वारा सीना जा सकता है। सौविधानिक सरोपन करने की विधि संविधान द्वारा निर्धारित है। मेरे विचार में यह व्यक्ति की मारुत का सबसे महत्वपूर्ण परिमाण है।"

नीति-निर्देशक तत्त्व—राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त आधुनिक सौविधानिक प्रणाली की नवीन विशेषता है और संविधान-निर्माता अद्वितीय गौरव के संविधान से प्रभावित हुए थे क्योंकि उसमें एक अध्यापक राजनीति के निर्देशक सिद्धान्तों पर है। इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों के महत्व को इंगित करते हुए संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने यह विचार व्यक्त किया था—

"निर्देशक सिद्धान्त उन अनुच्छेद-युक्तों के समूह हैं जिन्हें उपनिवेशों के गवर्नर जनरल अथवा गवर्नरों के नाम जारी किए जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत ये अनुदेश-पत्र भारतीय गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को जारी किए थे जिन्हें निर्देशक अथवा सिद्धान्त कहा जाता है अनुदेश-पत्र का दूसरा नाम है। अन्तर इतना है निर्देशक सिद्धान्त कार्यपरिचालन एवं विधान-मण्डल दोनों के कार्यों का निर्देशन करते हैं। यथाप्राप्त को सत्ता के प्रयोग में स्वच्छन्द नहीं रखना चाहिए। सत्ता का प्रयोग करते समय उसे इन निर्देशक सिद्धान्तों का आदर करना होगा वह इनकी अवहेलना नहीं कर सकता।" गन्तव्य-मन्त्रक भारत के राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता के सम्बन्ध में मौलाना हसरत मोहनी ने यह प्रस्ताव रखा कि "प्रमुख-सम्पन्न स्वतंत्र गणराज्य" शब्द प्रस्तावना में रख दिये जायें। उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारत राष्ट्र-मण्डल का सदस्य बना रहेगा तो वह इंग्लैंड की तरह ब्रिटेन के अधीनस्थ एवं गन्तव्य-मन्त्रक अधिराज्य (A Republic Dominion under Britain) होगा, परन्तु डॉ. अम्बेडकर ने अमहत्वपूर्ण प्रकट करते हुए स्पष्ट किया कि 'सम्पन्न' (Sovereign) शब्द 'स्वतंत्रता' (Independence) का अभिव्यक्ति करता है और एक स्वतंत्र देश किसी दूसरे स्वतंत्र देश के साथ किसी स्थिति में बँधता है तो वह इस कारण कम से कम प्रमुख-सम्पन्न (Less Sovereign) नहीं हो जाता। अन्त में संविधान सभा द्वारा मौलाना हसरत मोहनी का सरोपन अस्वीकार कर दिया गया और भारत को एक सम्पन्न लोकतन्त्रिक गणराज्य (A Sovereign Democratic Republic) घोषित कर दिया गया।

संविधान की प्रस्तावना—'प्रस्तावना' में निहित 'हम भारत के लोग' (We the People of India) शब्द पक्षा के विषय रहे। एन.ए. राह ने कहा कि 'हम भारत के लोग' शब्द समुचित नहीं क्योंकि संविधान निर्माता सभा सदस्य मन्त्रिपरिषद् के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गईं, परन्तु विशेष समिति (The Special Committee) का अभिमत था कि 'भारत के लोग' शब्दों का अर्थ भारत की जनता (The People of India) से है और संविधान निर्माता सभा भारत की जनता के नाम पर बैठ रही है, लेकिन राष्ट्र-मण्डल की भारत की सदस्यता ने संविधान सभा के अनेक सदस्यों की शक्यता बना दी कि अन्तर्गत बनने में यह सरोपन रखा कि हमको स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व कर दिया जाय कि सम्पन्न भारत की जनता में निहित है। पूर्णता बनने के सरोपन प्रत्यक्ष का महत्त्वपूर्ण स्थायी द्वारा जोरदार समर्थन किया गया लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने तर्क-सम्पन्न उत्तर देते हुए कहा कि 'प्रस्तावना' इस बात की अच्छी तरह अभिव्यक्ति कर देती है कि सम्पन्न भारत की जनता में निहित है और संविधान सभा इस बात की सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से घोषित कर रही है। यद्यपि संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई है, लेकिन वह प्रतिनिधित्व रूप से एक प्रतिनिधि सभा (A Representative Body) है। अमेरिकन संविधान अनधिकृत एक और छोटी सत्ता द्वारा दायर किया गया था और जब वह सत्ता संपूर्ण राज्य अनेकता की जनता की तरफ से संविधान की घोषणा कर सकती थी तो भारत की बड़ी संविधान सभा के लिए ऐसा करना उचित है कि वह सम्पूर्ण भारत की जनता की तरफ से बने। सभा में डॉ. अम्बेडकर का तर्क ही मान्य हुआ और पूर्णता बनने का सरोपन अस्वीकार कर दिया गया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु प्रत्यक्षता—डॉ. अम्बेडकर और उनके समान विचारधारा वाले सदस्यों के प्रत्यक्ष अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था किए गए और इनको कुछ शिफारिशें दी गईं। एकमात्र यही शिफारिश थी जिससे अवसरों की समानता के मूलभूत अधिकार को मन्त्र प्रदान की जा सकती था। ये शिफारिशें जाति के आधार पर दी गईं और इसका अर्थ यह था कि जाति-प्रथा के कारण ही उत्पन्न की गई स्त्री-पुरुष विभेद नष्ट हो।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उन्नत बनाते हेतु डॉ. अम्बेडकर ने उनके लिए सवैधानिक प्रावधान कराये और कानून बनवाये बल्कि उनके जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार हेतु प्रयास किये। दलित कहलाने वाला यह वर्ग अपनी नुरी आदतों और हीन भावना के कारण हिन्दू समाज में हीन समझा जाता है। इस तथ्य को समझते हुए डॉ. अम्बेडकर ने इन्हें अपनी नुरी आदतों (सर्वण जातियों से भौगना, नशा करना, गंदे कपड़े पहनना, मुर्दा जानवर का मांस खाना, झूठ बोलना, निरसरा रहना आदि) को त्याग कर सम्मानपूर्ण जीवन बिताने की प्रेरणा दी। उन्होंने तीन बिन्दुओं पर बल दिया—(1) अशुच संगठित हों (2) वे शिक्षित हों (3) वे अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। उन्होंने अपनी अशुच जाति 'महार' के सम्मेलन में कहा था कि "यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकामले में अच्छी दशा में देखने की इच्छा नहीं रखते तो धनुष और जलकर में कोई अस्त्र नहीं है।" महार महिलाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि "यदि तुम्हारे पति और सड़के शायन पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी जरूरी महापुरुषों के लिए है उतनी ही स्त्रियों के लिए आवश्यक है। यदि तुम लिखना-पढ़ना जान जाओ तो बहुत उन्नति होगी, जैसे तुम होगी, वैसे ही तुम्हारे बच्चे बनेंगे। अच्छे कार्यों की ओर अपना जीवन मोड़ दो। तुम्हारे बच्चे इस ससार में चपकते हुए हों। कभी यह मत सोचो कि तुम अशुच हो। साफ-सुथरे रहो। जिस प्रकार के कपड़े सर्वर्ग स्त्रियाँ पहनती हैं तुम भी पहनो। यह देखो कि वे साफ हैं।" उन्होंने 'महार वतन' कानून का विरोध किया, क्योंकि इसके द्वारा महारों को बहुआ मजदूर एवं दास की श्रेणी में लाया गया था। उन्होंने सर्वर्ग एवं अशुचों में सपना लाने हेतु 'समता सैनिक दल' की स्थापना भी की। दलितों के लिये पुष्क प्रशिक्षित्व की भीषणता उन्होंने हिन्दू समाज की असमानता को दूर करने का प्रयास किया। सविधान के अनुच्छेद 15, 16 व 17 द्वारा उन्होंने अस्पृश्यता को गैर-मान्यता व अपराध मानने का प्रावधान कराया।

पुष्क स्त्रियों को सभानता

डॉ. अम्बेडकर ने पुष्क एवं स्त्रियों की सभानता के लिये काफी काम किया। पहले उन्होंने जिन कानूनों का मसौदा तैयार किया, हिन्दू कोड बिल उनमें से एक था जिसे उन्होंने 1951 में संसद में पेश किया। इसमें सम्पत्ति और विवाह के मामलों में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिलाया गया। 1951 में उन्हें अपने कार्य में सफलता नहीं मिली, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने पद से त्याग-पत्र दे दिया। वह उनकी मेहनत का फल था कि आगे चलकर हिन्दू कोड बिल पार भागों में बंट कर पास हो गया। इस बिल का उद्देश्य हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में सुधार करना है। इस कानून के द्वारा स्त्री-पुरुष को तत्ताक की व्यवस्था की गई तथा स्त्रियों को वैदिक सम्पत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर का मूल्यांकन एवं देन

डॉ. अम्बेडकर अपने जीवन के अन्तिम समय तक सामाजिक न्याय और दलित-उद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। उन्हें औद्योगिक और जाति-धीन के पैदावार से घृणा थी। 14 अक्टूबर 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पूर्व-प्रवृत्ति के अनुसार नागपुर में दो लाख दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। गौतम बुद्ध भारत में जन्मे थे और उनके धर्म में जाति-धीन अथवा सुआश्रित के लिए कोई स्थान नहीं था। डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन में 17 पुस्तकों की रचना की। अन्तिम दिनों में उन्होंने 'गोस्वाम आक बुद्ध' का लेखन कार्य किया। 5 दिसम्बर 1956 को मध्य रात्रि को अम्बेडकर का देहावसान हो गया। उनका निधन हाजिर समाज के लिए शोक का कारण था। नेहरूजी ने उनकी मृत्यु पर कहा कि डॉ. अम्बेडकर हिन्दू समाज के लिए गए दयनात्मक कार्यों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक थे। डॉ. अम्बेडकर के विचार आज उतने ही समीचीन और सार्यक हैं जितने की पहले थे। गौपीजी ने उनके सम्बन्ध में कहा था कि "ध्विष्य में डॉ. अम्बेडकर के नाम के साथ चाहे किसी विशेषण का प्रयोग हो, वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।" डॉ. अम्बेडकर को 'दलित वर्ग का मसीहा' या 'वैष्णव' कहा गया है क्योंकि वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दलितोद्धार के लिए संघर्ष किया और सर्वर्गों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। डॉ. बी. पी. वर्मा के अनुसार, "डॉ. अम्बेडकर दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले अभूतपूर्व सेनानी थे। भारत के दलित वर्ग के लिए 20वीं सदी में जो कार्य उन्होंने किया वह अनूपन है, इसीलिए उन्हें 'दलितों का मसीहा' कहा जाता है। उनकी तुलना अमेरिका के महान् नीग्रो नेता मार्टिन लूथर किंग से की जा सकती है जिसने अमेरिका के र्वेत लोगों के विरुद्ध सम्पन्न नीग्रो प्रजाति का आक्रोश व्यक्त किया।"¹

राजनीतिक विचार (Political Thoughts)

प्लेटो

(Plato, 427-347 B.C.)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

प्लेटो को यूनान का महान् दार्शनिक माना जाता है। उनके विचारों का राजनीतिक विचारों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो का जन्म ईसा से 427 वर्ष पूर्व एथेन्स के एक कुलीन परिवार में हुआ था। परिचयी जगत् में सर्व प्रथम आदर्श राज्य (Utopia) की कल्पनिक योजना प्रस्तुत करने वाले इस विद्वान् दार्शनिक की माता का नाम परिक्लियनी और पिता का नाम एरिस्टोन था। प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्लेटो सुक्रात के चरणों में शिष्य बन आठ वर्ष तक अध्ययन करता रहा। उसने राजनीति विज्ञान और दर्शन पर लगभग 38 ग्रन्थ लिखे। इनमें से उसके प्रमुख ग्रन्थ इस प्रकार हैं—(1) टी रिपब्लिक (386 B.C.), (2) टी स्टेट्स मैन (360 B.C.), (3) टी साज (347B.C.)। 81 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया।

रिपब्लिक

विश्व के सभी विद्वान् 'रिपब्लिक' को प्लेटो की महानतम एवं सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। इस पुस्तक में प्लेटो ने अनेक विषयों का वर्णन किया है। "प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा का इसमें विशद विवेचन है। मानव के कर्मानुसार सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का इसमें उल्लेख है। इतिहास का दर्शन इसमें विद्यमान है। राज्यों के उत्थान और पतन की चक्रवर्त्य व्याख्या द्वारा उनके पीछे वर्तमान आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की भी मांगें इसमें मिलती हैं। इस ग्रन्थ में शील की विशिष्टता बड़ी उत्कृष्ट शैली में प्रतिपादित कर प्लेटो ने मानव जीवन को एक उच्चतम धरातल पर ले जाने का प्रयास किया है। दार्शनिक तत्त्वों का पर्याप्त उद्घापोह इसमें दृश्य है। इन सभी विषयों को एक सूत्र में गाँठित एवं संयोजित करने वाली प्लेटो की 'रिपब्लिक' पुस्तक दर्शन की एक आध्यात्मिक कृति है।¹

(1) रिपब्लिक में वर्णित न्याय-सिद्धान्त—प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना में न्याय-सिद्धान्त को अत्यन्त महत्व दिया है। न्याय-सिद्धान्त एक ऐसी नीति है जो समाज से अशान्ति, अव्यवस्था, कर्तव्य-विमुखता तथा बुद्धिहीनता आदि व्याधियों को दूर कर सकती है। प्लेटो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सतोंपपूर्वक अपना निश्चित कार्य करता रहे। उसकी दृष्टि में यही सामाजिक न्याय है जिसे सामाजिक जीवन का सच्चा सिद्धान्त कहा जा सकता है। प्लेटो की रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय के झूठे सिद्धान्तों को समाज से दूर कर, सच्चे न्याय धारण को प्रतिष्ठित करना था। प्लेटो की रिपब्लिक का आरम्भ और अन्त न्याय के वास्तविक स्वरूप की भीमासा से होता है। उसने अपने सामग्र्य-ज्ञान प्रकलित न्याय सिद्धान्तों की ध्वनियाँ उठाईं। उनमें से तीन प्रमुख सिद्धान्त ये थे—(i) न्याय की परम्परावादी अथवा सेरेन्स का सिद्धान्त, (ii) न्याय की उदयवादी अथवा हेसोपेक्स का सिद्धान्त एवं (iii) न्याय की व्यवहारवादी अथवा ग्लार्का का सिद्धान्त।

न्याय सिद्धान्त की विशेषताएँ—प्लेटो के न्याय सम्बन्धी सिद्धान्त की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) प्लेटो का न्याय बाह्य जगत् की वस्तु न होकर आन्तरिक स्थिति है। यह व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि है।
- (2) उसका न्याय अहस्तक्षेप के सिद्धान्त से समुक्त है। आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के कार्य निर्धारित हैं और सामाजिक न्याय प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा करता है कि वह दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे।

- (3) प्लेटो का सामाजिक न्याय कार्य-विशेषीकरण का सिद्धान्त है। मनुष्य की तीन प्रवृत्तियों-ज्ञान, साहस और पृथ के आधार पर प्लेटो ने समाज को शासक, सैनिक और उत्पादक तीन वर्गों में बाँटा है।
- (4) प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शनिक शासन द्वारा की गई है। योग्य शासन के लिए सैनिक एवं शासक-वर्ग में सम्पत्ति तथा नारी के साम्यवाद की व्यवस्था है जो निस्वार्थ समाज-सेवा की परिस्थिति का निर्माण कर सकेगी।
- (5) प्लेटो का सामाजिक न्याय सामाजिक एकता का सिद्धान्त है। कार्यों और गुणों के आधार पर विभाजित समाज के तीन वर्ग भिन्न-भिन्न होते हुए भी सामाजिक एकता के प्रतीक हैं।
- (6) प्लेटो ने व्यक्ति एवं समाज दोनों स्तरों पर न्याय के गुणों को सम्पादित के लिए एक व्यवस्थित शिक्षा क्रम प्रस्तुत किया है।
- (7) प्लेटो का राज्य एक नैतिक इकाई है अतः उसका न्याय सिद्धान्त एक नैतिक मान्यता है, कानूनी नहीं है।
- (8) प्लेटो का न्याय मानव जीवन की समग्रता को लेकर चलता है तथा वह व्यक्ति के ध्येयान्तर का गुण और समाज की सामञ्जस्यपूर्ण स्थिति का दूसरा नाम है।
- (9) व्यक्तिगत स्तर पर न्याय व्यक्ति की अपनी आत्मा में वृद्धि के शासन द्वारा समन्वय की स्थापना है। सामाजिक स्तर पर वह व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने कार्य करते हुए दूसरों के कर्तव्यों में बिना हस्तक्षेप किए सामाजिक एकता को बनाए रखना है।

(2) रिपब्लिक में वर्णित शिक्षा सिद्धान्त—प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का विवेचन किया है कि कैसे ने 'रिपब्लिक की शिक्षा' को सर्वोत्कृष्ट वृत्ति की सजा दी है। प्लेटो ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा समाज के घटक एक सामाजिक चेतना से अनुशासित होकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। अच्चे जीवन में आने वाली बाधाओं को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षा ऐसा अधिकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना समुचित स्थान बना पाता है और उसके अनुसार अपने को ढालता है।

प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएँ—प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में एपेस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों के गुणों को सम्मिलित किया है तथा दोनों के दोषों को दूर करने की कोशिश की। उसने एपेस की बौद्धिक शिक्षा के साथ स्पार्टा का तथ्यमय शारीरिक शिक्षण जोड़कर शिक्षा को व्यक्तित्व और राष्ट्र दोनों के विकास का माध्यम माना है। उसने स्त्री एवं पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है। प्लेटो स्त्रियों और पुरुषों को समान शिक्षा को वकालत करते हुए उत्पादक और श्रमिक वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित रखना चाहता है। वह सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की योजना रखता है, किन्तु सभी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं और जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की शक्ति है। प्लेटो ने अपनी प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा योजना में शिक्षा के पाठ्यक्रम का विस्तार से विवेचन किया है।

(3) रिपब्लिक में वर्णित साम्यवाद का सिद्धान्त—प्लेटो अपने साम्यवाद को राज्य के दो वर्गों—शासकों तथा सैनिकों तक सीमित रखता है। वह तृतीय बड़े वर्ग अर्थात् जन साधारण के लिए साम्यवादी व्यवस्था की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। प्लेटो की साम्यवाद की योजना दो भागों में विभाजित है—(1) सम्पत्ति का साम्यवाद एवं (2) परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद।

सम्पत्ति का साम्यवाद—प्लेटो शासकों तथा सैनिकों के लिए सम्पत्ति का निषेध करता है। वह इन दोनों वर्गों को राज्य के अधिभावक के नाम से सम्बोधित करता है। उसका विश्वास है कि सम्पत्ति व्यक्ति को अपने पद से विचलित कर सकती है। सम्पत्ति पर शासकों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए जिससे उनके मन और मस्तिष्क से सम्पत्ति के प्रति मोह को दूर किया जा सके। वह शासकों के लिए सम्पत्ति को अवैतिक बताते हुए कहता है कि एक व्यक्ति के हाथ में सम्पत्ति और शासन की शक्ति केन्द्रित रहने से वह पथभ्रष्ट होकर धोषण परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। उसके अनुसार शासक तथा सैनिक वर्ग निजी सम्पत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। उसने रिपब्लिक में इनकी दिनचर्या का वर्णन दिया है।

परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद—प्लेटो ने अधिभावकगण के लिए निजी सम्पत्ति का निषेध करने के साथ उन्हें निजी परिवार का त्याग कर सारे राज्य को अपना बृहत् परिवार मानने के लिए कहा है। इसमें प्लेटो का उद्देश्य यह है कि शासक और सैनिक वर्ग कथन के समान कामिनी के मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पूरी तन्त्र पालन करते रहें। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से प्रबल होता है। परिवार के उन्मूलन के पक्ष में प्लेटो का नारी जाति विमुक्ति तर्क भी है। प्लेटो के समय में यूनान में नारी जाति की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। प्लेटो की यह मान्यता थी कि नारी जाति के उत्थान के लिए उनका कार्यक्षेत्र

अधिक व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। ज्योति ने परिवार सम्बन्ध की योजना तीन भागों से प्रस्तुत की थी—(1) वह परिवार के पुरुष एवं सहायकवर्गों शुद्ध शक्तियों से अभिव्यक्त वर्ग की मुक्त स्थापना तथा। (2) वह तत्पश्चात् वर्गों की मुक्ति तथा सन्तानधिकाय का पक्षपात। (3) उक्त सन्तान वर्ग के निरप्रभन्त शासक की दृष्टि से ज्योति की यह योजना बलवन्त लानी थी।

(4) रिपब्लिक में वर्णित अदार्श राज्य—ज्योति के समय में दून में एकाधिक अग्रवर्ग काय थी। उन्नी की प्रतिक्रिया स्वयं तत्पश्चात् एक 'अदार्श राज्य' की कल्पना का उसे 'रिपब्लिक' में प्रस्तुत किया। उक्त अदार्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उन्नेषा की है। ज्योति व्यक्ति और राज्य में जीवन्त और जीव का सम्बन्ध मानता है। उसका विश्वास है कि जो युग और विशेषण अल्प मात्र में व्यक्ति में पाई जाती है, वे विद्यमान रूप में राज्य में पाई जाती हैं। राज्य मूलतः व्यक्ति की भावना का बल रूप है अर्थात् भावना (वेग) अपने पूर्ण रूप में जब बल प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारा का लेटी है। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विद्यमान रूप है। जिन प्रकृतियों में अदार्श मानव का भावना बलान्तर, साहस और विवेक के तीन तत्वों से युक्त है, उसी प्रकार राज्य को उपयुक्त करने में तीन तत्व महत्व होते हैं—(1) आर्थिक तत्व, (2) सैनिक तत्व एवं (3) दार्शनिक तत्व।

(5) रिपब्लिक में कानून का नियम—ज्योति के व्यवस्थापक रिपब्लिक, दोषपूर्ण अदार्श राज्य के विवेक के प्रभाव में यह विचार करना उचित है कि उक्त अदार्श 'रिपब्लिक' में कानून और लोकमत के प्रभाव को विवेकपूर्ण ढंग दिया है।

(6) ज्योति और पारिवारिक—ज्योति की धारणाओं का अग्रवर्ग विचार काय था है। उसे इतिहास में प्रथम पारिवारिक होने का ज्ञेय प्राप्त है। ज्योति के पारिवारिक में राज्य से उत्पन्न होने वाले राज्य में है जहाँ पारिवारिक है उन्नी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं। इन्होंने एक दल के विचार किन्हीं अन्य दल का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। ज्योति का पारिवारिक प्रभाव विशेष है। ज्योति ने प्रत्यक्ष को अग्रवर्गों का शासन बना है। ज्योति के पारिवारिक में उसके विचार सम्पत्ति अर्थात् के विचारों का मान्य है। वह राज्य की सर्वोच्चता और कुलस्तर में विश्वास करता है। ज्योति के अनुसार व्यक्ति को राज्य में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्ने व्यक्ति के अधिकारों को महत्व नहीं दिया।

स्टेडमैन

ज्योति ने इन्होंने कानून पर नए दृष्टिकोण से विचार किया है। इन्होंने उक्त व्यक्तियों की उन्नी भावना नहीं की किन्तु उन्ने 'रिपब्लिक' में की थी। इन्होंने निम्नलिखित संविधानों का संकेत निम्न है। ज्योति के इन्होंने व्यक्त कि वह विचार सैनिक उन्ने पूर्ण और सुनिश्चित है।

(1) स्टेडमैन में अदार्श शासन और कानून मन्त्रालय विचार—'स्टेडमैन' ज्योति की एकाधिक रचना नहीं है। इन्होंने अधिकतर परिभाषाओं पर विचार किया गया है और इसका मुख्य विषय अदार्श शासन का स्वरूप है। 'स्टेडमैन' में ज्योति ने उक्तका अन्वय शासन की स्वीकृति तथा अग्रवर्गों से बलवन्त है किन्तु प्रभुत्व सम्पन्न होने के बजाय वही यह निर्णय करता है कि वह अन्नी शक्तियों का बल और शक्ति कर्तव्य में प्रयोग की। ज्योति ने अपने विचार के आगे बढ़ाते हैं कि शासन के अग्र पर निम्नलिखित अन्वय निम्नलिखित का संशोधन किया है। उन्ने स्वीकार किया है कि एकाधिक शासन में सन्तान्ति विधि का कानून सौभाग्यवाद और राज्य के बल बल की मदद सैनिक दृष्टियों के निरस्त स्वरूप होता है। दूनली स्टेडमैन का निर्णय की प्रभुता में विश्वास था। स्टेडमैन में ज्योति कानून को अग्र स्तर देता है।

(2) स्टेडमैन में राज्य का वर्गीकरण—ज्योति ने अपने 'स्टेडमैन' में राज्य का जो वर्गीकरण किया है वह 'रिपब्लिक' में कि वह वर्गीकरण से भिन्नता निम्न है। उक्तका राज्य वर्गीकरण निम्नलिखित है—

राज्यों के प्रकार	राज्यों की संख्या	राज्यों के रूप
(1) कानूनविषय या कानून से सम्बन्धित राज्य	(i) एक व्यक्ति का राज्य (ii) कुछ व्यक्तियों का राज्य (iii) बहुत से व्यक्तियों का राज्य	राज्य कुल्लि दल प्रत्यक्ष
(2) कानून द्वारा सम्बन्धित न होने वाले राज्य	(i) एक व्यक्ति का राज्य (ii) कुछ व्यक्तियों का राज्य (iii) बहुत से व्यक्तियों का राज्य	निम्नलिखित अन्वय अधिकारों प्रत्यक्ष

सारा

'साज' प्लेटो का अतिम ग्रन्थ था। इसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के एक वर्ष बाद हुआ। समाजशास्त्रीय और सांख्यिक विश्लेषण की दृष्टि से यह प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना है। 'साज' में प्रतिपादित मुख्य सिद्धान्त निम्नांकित हैं—

(1) आत्म संयम का महत्व—प्लेटो के अनुसार आत्म-संयम के कारण विवेक अबाधित रूप से अपना कार्य करता है। यह राज्य की आधारशिला है। आत्म संयम पर आधारित न होने वाला राज्य अपूर्ण एवं दोषपूर्ण है। यदि व्यवस्थापक ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जिससे लोग आत्म संयमो भन तो इसने तीन आदर्शों की प्राप्ति होती है—(1) स्वतन्त्रता (2) एकता एवं (3) सुखवृद्ध। प्लेटो के अनुसार आत्म संयम राज्य को पूर्ण और दोषहीन बना सकता है।

(2) कानून विषयक सिद्धान्त—प्लेटो ने 'साज' में कानून की पुनर्जाति की है। उसने कानून के स्वरूप आवश्यकता, व्यवहार आदि पर प्रकाश डालते हुए राज्य में कानून की प्रभुता स्थापित की है। वह कानून का शासन स्थापित करना चाहता है क्योंकि कानून दर्शन तथा ज्ञान का साकार रूप है। मनुष्य को दो कारणों से कानून की आवश्यकता होती है—(1) प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक द्वंदों को समझने की समझ नहीं होती एवं (2) यदि वह समझ भी जावे तो अपने वैयक्तिक स्वार्थों और वासनाओं के कारण उसके अनुकूल आचरण नहीं करता। जग के अनुसार 'कानून' से व्यक्ति मर्यादा भरा व्यक्ति को भलाई की पूर्ण राई को अपना कर्तव्य मानता है।

(3) इतिहास की शिक्षा—'साज' में प्लेटो ने बताया है कि हमें भूतकालीन अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वह इतिहास के आधार पर एक निश्चित शासन प्रणाली का समर्थन करता है जिसमें राज्य की सत्ता और जनता की सहमति को स्वीकार करता है। इतिहास के उदाहरणों के आधार पर उसने कानून के नियम और मिश्रित संविधान की व्यवस्था को पुष्ट किया है।

(4) मिश्रित राज्य—प्लेटो ने 'साज' में जिस आदर्श राज्य की विवेचना की है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता मिश्रित संविधान अथवा मिश्रित राज्य का सिद्धान्त है। 'साज' में वर्णित आदर्श राज्य के निर्माण के लिए राजा और धन, धनी और निर्धन बुद्धिमान और शक्तिशाली सभी व्यक्तियों और वर्गों का सहयोग आवश्यक है।

(5) राज्य की भौगोलिक स्थिति व जनसंख्या—प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कान्यनिक भौगोलिक रूपरेखा खींची है। उसका मत है कि राज्य सागर तट से पर्याप्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि सागर तट के निकट होने से विदेशी व्यापारियों की उस पर सदैव निदृष्टि सगी रहेगी और रक्षा के लिए बहुत अधिक सैनिक व्यय करना पड़ेगा। उसके अनुसार राज्य चारों ओर से सुरक्षित सीमाओं से घिरा हुआ हो जिससे उस पर सुगमता से विदेशी आक्रमण न हो। उसने राज्य की जनसंख्या 5040 निर्दिष्ट की थी।

(6) सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएँ—प्लेटो सामाजिक क्षेत्र में मिश्रित व्यवस्था को पसन्द करता था। वह विभिन्न तत्वों के सामनस्य का पक्षपाती था। उसके अनुसार विवाह विभिन्न वर्गों और परिशों का मिलन होना चाहिए और सम्पत्ति निजी स्वामित्व एवं सार्वजनिक नियंत्रण में होनी चाहिए। बच्चों को स्वेच्छा से अपने धन का कुछ भाग निर्धनों को देना चाहिए ताकि नागरिकों में वर्ग-समर्थ उत्पन्न न हो।

(7) विवाह तथा परिवार विषयक विचार—'रिपब्लिक' की भाँति 'साज' में यह स्वीकार किया गया है कि स्त्रियों एवं पुरुषों की समान शिक्षा पाने एवं समस्त कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। प्लेटो ने 'साज' में स्त्रियों के सामन्यवाद को समर्थन कर दिया था। वह इस विचार को स्वीकार करता है कि स्त्रियाँ सब की सम्पत्ति होनी चाहिए। प्लेटो का मत है कि विवाह का उद्देश्य वैयक्तिक आनन्द नहीं अपितु राज्य का हित होना चाहिए। विवाह के बाद पति-पत्नी को विवाह के प्रथम दस वर्ष तक राज्य के निरीक्षकों की व्यवस्था में रहना चाहिए। उसने राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित की है। इसके लिए उसके तीन सुझाव हैं—(1) महिला निरीक्षक दल फलकार द्वारा पति-पत्नी को अधिक सन्तान पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें (2) अधिक सन्तान पैदा करने वाले पति-पत्नी को राजकीय सम्मान और विशेषाधिकार दिए जाएँ एवं (3) 35 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले अविवाहितों या सन्तान हीन व्यक्तियों पर कर लगाया जाए। प्लेटो के अनुसार सन्तान पैदा करना केवल भौतिक और राजकीय आवश्यकता ही नहीं बल्कि नैतिक आवश्यकता है।

(8) शैक्षणिक तथा धार्मिक संस्थाएँ—'साज' में प्लेटो ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसमें पाठ्यक्रम को सामान्य रूपरेखा 'रिपब्लिक' की भाँति ही है। उसके द्वारा समस्त नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का विचार व्यक्त किया गया है। प्लेटो धर्म को सत्यगत रूप देना चाहता है। उसने 'साज' में धार्मिक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्लेटो नास्तिकता का विरोध करता है।

(9) प्लेटो के आदर्श राज्य का सर्वांग रूप—प्लेटो ने अपने ग्रन्थ 'साज' में आदर्श राज्य का जो सम्पूर्ण चित्र खींचा है उसकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(1) आत्म संयम का महत्व (2) कानून का सिद्धान्त (3) मिश्रित संविधान

(4) राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या (5) सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएँ (इसमें सम्पत्ति एवं आर्थिक व्यवस्था, श्रम-विभाजन, शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था और स्थानीय शासन की सम्मिलित विस्थापिताएँ) (6) विवाह एवं परिवार विषयक विचार (7) शिक्षा और धार्मिक संस्थाएँ। इनके अतिरिक्त प्लेटो ने शान्ति एवं युद्ध, ऐतिहासिक शिक्षा, अपराध एवं दण्ड आदि पर राज में विराट् विवेचन प्रस्तुत किया है।

अरस्तू

(Aristotle, 384-322 B.C.)

जीवन-परिचय (Life Sketch)

अरस्तू यूनान का महान् दार्शनिक राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था। उसके राजनीतिक विचारों का पश्चिम के राजनीतिक चिन्तन एवं सम्पूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। अरस्तू का जन्म यूनान के स्टेगिरा नामक नगर में 384 ई. पू. में हुआ था। उसके पिता निखोमैकस मसोडोनिया के राज्य दरबार में चिकित्सक रह चुके थे। 18 वर्ष की आयु में वह एथेन्स जाकर प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकादमी में भर्ती हो गया और 347 ई. पू. में प्लेटो के देहवसान तक वहीं रहा। उनकी मृत्यु 322 ई. में हुई।

अरस्तू के ग्रन्थ (Works of Aristotle)

उसने सभी विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे। उसके हुए लिखित ग्रन्थों की संख्या लगभग 400 बताई जाती है। उसके विभिन्न विषयों पर लिखे गए ग्रन्थ इस प्रकार हैं—(1) राजनीति पर—‘पॉलिटिक्स’ एवं ‘दी कन्स्टीट्यूशन’। (2) साहित्य में—‘मेटाफिजिक्स’ और ‘साल’, ‘मेटाफिजिक्स’, ‘मेटाफिजिक्स’ एवं ‘मेटाफिजिक्स’। (3) दर्शन पर—‘मेटाफिजिक्स’ के पाँच भागों का श्रम ‘मेटाफिजिक्स’ एवं ‘मेटाफिजिक्स’। (4) भौतिक विज्ञान पर—‘मेटाफिजिक्स’। (5) शरीर विज्ञान पर—‘हियेरोजेन’ ग्रन्थ एनीमल्स।

(1) अरस्तू के राज्य सम्बन्धी विचार—‘पॉलिटिक्स’ की प्रथम पुस्तक में अरस्तू ने राज्य सम्बन्धी सिद्धान्तों का वर्णन किया है। उसके राज्य सम्बन्धी विचार बाई दस वर्ष बाद भी प्रासंगिक हैं। अरस्तू यह सिद्ध करने चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं तथा यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। उनके राज्य विषयक विचारों का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है—

(क) राज्य का प्रारम्भिक—अरस्तू के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म और विकास प्राकृतिक रूप से हुआ है। वह कहता है कि “मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जो अपने स्वभाव से ही गणकीय जीवन के लिए बना है।” उसने राज्य के विकास की तीन स्थितियाँ बताई हैं¹—(1) गृहस्थी, (2) ग्राम एवं (3) नगर राज्य (पॉलिस)।

(ख) राज्य एक स्वाभाविक संस्था—प्लेटो की भाँति अरस्तू का यह मानना है कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है अपितु यह एक प्राकृतिक समुदाय है। अरस्तू राज्य को एक ऐसा समुदाय मानता है जिसका बिना मनुष्य का जीवन सम्भव नहीं है। अरस्तू के अनुसार, “जो व्यक्ति राज्य से बाहर रहता है वह या तो परा है अथवा दबता।”

(ग) राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में है—अरस्तू राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं, अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह सबके ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में मिलते हुए हैं। उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य का विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

(घ) राज्य मनुष्य से पहले—अरस्तू का कहना है कि ‘राज्य मनुष्य से पहले’ है। इस सम्बन्ध में उसका तर्क है कि राज्य एक समग्रता है और व्यक्ति उसका अंग है अर्थात् राज्य और व्यक्ति का बड़ा सम्बन्ध है जो शरीर का उसके अंगों से होता है। समग्र पहले आता है और अंग बाद में इस सन्दर्भ के आधार पर राज्य पहले हुआ।

(ङ) राज्य अंतिम और पूर्ण संस्था—अरस्तू नगर राज्य को मानव समाज का सर्वोत्तम समुदाय और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मानता है। परिवार और ग्राम के बाद राज्य में मानव के विकास लक्ष्य की पूर्ति होती है। अरस्तू के अनुसार, नगर-राज्य के बाद राज्य का कोई अन्य कार्य नहीं रह जाता। उसकी दृष्टि में यह सामाजिक विकास का चरम रूप है। परिवार से आरम्भ होने वाला विकास नगर राज्य में परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है।

(च) राज्य का नैतिक स्वभाव—अरस्तू यह प्रतिपादित करता है कि राज्य का स्वभाव नैतिक है अर्थात् राज्य का प्रकृति एक सार्वजनिक व्यवस्था के समान है। प्रत्येक सार्वजनिक जीवन का विकास स्वाभाविक रूप में होता है। उसका कार्य उसके विभिन्न अंगों द्वारा किए जाते हैं। यह प्रक्रिया राज्य पर भी लागू होती है। उसके समस्त कार्य उसके अंगों में मिलकर होते हैं एवं सार्वजनिक जीवन का निर्माण होता है उसी प्रकार राज्य नगर प्रकार के अंग-व्यवस्थाएँ एवं समुदायों में मिलकर बना हुआ एक सम्पूर्ण राज्य है।

(छ) राज्य का आत्मनिर्भर होना—आरतु राज्य की विशेषता यह मानता है कि वह आत्मनिर्भर इकाई है। वह अपने 'आचार शास्त्र' में लिखता है कि "आत्म-निर्भरता यह गुण है जिसके द्वारा स्वतः जीवन वाछनीय बन जाता है तथा उसमें कोई अभाव नहीं रह जाता।" नगर राज्य को 'आत्म-निर्भर' कहने से आरतु का यही अभिप्राय है कि नगर उा समस्त स्थितियों और कलाकरणों की पूर्ति करता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। उसक अनुसार आत्म-निर्भर राज्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकता है।

(ज) राज्य का एकल्य और बहुल्य—उसका सिद्धान्त है कि राज्य नागरिकों का नियन्त्रण एवं नियमन को तथा अन्य कार्यों के लिए यह ठन्डे पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करे। उसकी दृष्टि में एकल्य ही राज्य का आदर्श स्वरूप नहीं है। आरतु के अनुसार राज्य का स्वरूप बहुल्य में है।²

(झ) राज्य के उद्देश्य और कार्य—आरतु का विश्वास है कि मनुष्य का उद्देश्य जीवन नहीं अपितु एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन को प्राप्ति है और इसा श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति कागन राज्य का उद्देश्य है। राज्य सदस्यों जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्यों का एक नैतिक संगठन है, अतः उसका सत्य अपने सदस्यों की अधिकतम भलाई करना है। आरतु का मत है कि "राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए।"³

(झ) राज्य और व्यक्ति का सम्बन्ध—आरतु ने व्यक्ति और राज्य में गहरा सम्बन्ध बताते हुए राज्य और व्यक्ति की तुलना कई दृष्टिकोणों से की है। एक व्यक्ति के समान राज्य को सहस्र आत्म-नियन्त्रण तथा न्याय के गुण प्रदर्शित करने होंगे हैं। राज्य व्यक्ति के समान आत्म-निर्भर और नैतिक जीवन व्यतीत करता है। वह नैतिक विषयों का पालन करता है और व्यक्ति के समान ही अपने सभी सदस्यों को नैतिक विधि मानने के लिए बाध्य करता है।

(2) आरतु के द्वारा प्रथा सम्बन्धी विचार—आरतु के दासता सम्बन्धी विचार उसकी रुढ़िवादिता के प्रमाण हैं क्योंकि उस समय दास-प्रथा तत्कालीन युगने जीवन का विशेष अंग थी। यूगन का आर्थिक ढांचा इस प्रकार का था कि वहाँ भूमि का स्वामित्व कुलीन परिवारों के हाथ में था जो परिश्रम नहीं कर सकते थे। वे सारा परिश्रम दासों से करवाते थे। यूनान में दासों की भारी संख्या थी तथा दास वहाँ की राष्ट्रीय सम्पत्ति माने जाते थे। आरतु के अनुसार दास प्रथा के आधार थे—(1) दास-प्रथा को आरतु स्वाभाविक व्यवस्था मानता था, (2) दास-प्रथा से दोनों पक्षों को लाभ होता था एवं (3) आरतु नैतिक दृष्टि से दास-प्रथा को आवश्यक मानता था।

दासता के प्रकार—आरतु दासों के दो प्रकार बताता है—(1) स्वाभाविक दास एवं (2) वैधानिक दास। जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि और अयोग्य होते हैं वे स्वाभाविक दास होते हैं। युद्ध में अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बन्दी वैधानिक दास कहलाते हैं।

(3) आरतु के सम्पत्ति सम्बन्धी विचार—सम्पत्ति सम्बन्धी विचार व्यक्त करते हुए आरतु ने कहा है कि सम्पत्ति परिवार का आवश्यक अंग है। उसके बिना दैनिक जीवन सम्भव नहीं है। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की भौतिक सम्पत्ति को आवश्यकता स्वाभाविक है। सम्पत्ति जो परिवार का आवश्यक अंग है उसका स्वामित्व जल्द्वरी है। सम्पत्ति और परिवार मानव की प्रकृति दत्त है। मनुष्य को सुखा प्राप्त करने को भोजन चाहिए, निवास के लिए मकान और प्रकृति द्वारा दी गई सदी-गर्मी से बचने के लिए कपड़ चाहिए। ये सम्पत्ति के भाग हैं। आरतु ने सम्पत्ति को दो भागों में बाँटा है—(1) निजीय—इस सम्पत्ति में धन, मकान, खेत, खलिहान आदि आते हैं। (2) सजीव—इस सम्पत्ति में दास और भेड़क आदि आते हैं। आरतु के अनुसार परिवार के लिए दोनों प्रकार की सम्पत्ति उपयोगी होती है।

(4) आरतु के परिवार सम्बन्धी विचार—आरतु के अनुसार परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम सोपान है। यह वह आधारशिला है जिस पर सामाजिक जीवन का भवन स्थिर रहता है। यहाँ से व्यक्ति का जीवन प्रारम्भ होता है। परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार में बासक माता की गोद और पिता के संरक्षण में पालित-पोषित होकर नागरिकता की प्रथम शिक्षा ग्रहण करता है और यही पर उसे जीवन समाप में सज्जने के लिए तैयार किया जाता है। उसके अनुसार परिवार एक छोटा समान है जहाँ मनुष्य के जीवन को शिक्षित होने का अवसर मिलता है। आरतु के अनुसार परिवार का स्वरूप पैतृक है और परिवार के सदस्यों का कार्य अलग होता है। पुरुष परिवार का संचालक और शासक है। वह स्त्री की अपेक्षा अधिक गुणवान और समर्थ होने के कारण परिवार पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है। आरतु के अनुसार परिवार के सदस्यों में परस्पर पूर्णतया श्रद्धा का वातावरण होना चाहिए।

(5) आरतु के नागरिकता सम्बन्धी विचार—आरतु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो न्याय अथवा राज्य के विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्यों में भाग ले। उस समय राज्य के सभी नागरिक साधारण सभा के सदस्य होते थे और

1 Foster Master of Political Thought p 129

2 Barker Politics, p 40-42.

3 Aristotle Politics (Barker's Trans) ¶ 118

यह सभा वर्ष में कम से कम एक बार सम्मेलन होकर राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन करती थी तथा विभिन्नार्थ सम्बन्धी कार्य करता थी। एदेन में यह सर्वोच्च सत्ता होती थी और सभा के सदस्य के गये प्रत्येक एदेन वाली राजसत्ता में भाग लेता था। किसी नगर राज्य में सभी व्यक्ति न माध्याम सभा के सदस्य होते थे और न ही राज्य प्रशासन में भाग लेते थे। यूनान के किसी राज्य में विदेशियों, दासों, स्त्रियों तथा बच्चों को नागरिकता के अधिकार नहीं थे। यूनानी नागरिकता अपुनिक नागरिकता को अपेक्षा अधिक संकुचित थी।

(6) अरस्तू के कानून सम्बन्धी विचार—अरस्तू ने अपने ग्रन्थ 'पॉलिटिक्स' में कानून को राज्य में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उनके अनुसार राज्य में सर्वोच्च शक्ति का इससे अधिक सम्बन्ध है कि वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा शासित हो अथवा सर्वश्रेष्ठ कानूनों द्वारा क्योंकि वह शासन अपने प्रवाजनों की प्नाई के लिए कानून के अनुसार होता है।¹ अरस्तू ने कानून की सर्वोच्चता को श्रेष्ठ शासन का एक बिन्दु माना है। उसने कानून को उन मामलों बन्धों का सामूहिक नाम दिया जिनके अनुसार व्यक्तियों के कार्यों का नियमन होता है। वह कानून तथा विवेक बुद्धि को समान तथा पर्यायवाची मानता है। उसके अनुसार विवेक बुद्धि मानव कार्यों के नियमन के लिए एक आध्यात्मिक बंधन है। एक तरह से नीति और कानून को सामान्यक सदाई है। अरस्तू के मत में नीति के समान कानून का एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए राज्य के नागरिक प्रयत्नशील रहते हैं। अरस्तू का कहना है कि इस सम्बन्ध में सविद्यमान का महत्वपूर्ण स्थान है, जो लिखित कानूनों की घोषित करने के साथ अलिखित प्रथाओं और रीति-रिवाजों को बध्ता है। कानून के स्वरूप को बताते हुए अरस्तू का कहना है कि आदर्श कानून प्राकृतिक होते हैं। वह संविधान के लिए कानूनों की आवश्यकताओं पर बल देता है।

(7) अरस्तू के व्याप सम्बन्धी विचार—अरस्तू 'पॉलिटिक्स' में व्याप को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताता है। उसने व्याप का अर्थ नैतिक कार्य का व्यवहार रूप में प्रकट करने बताया है। अरस्तू के अनुसार सम्पूर्ण इन का उद्देश्य नैतिक कल्याण है। व्याप समस्त गुणों का समूह है। वह व्याप का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उसके दो भेद करता है—(1) सामान्य व्याप एवं (2) विशेष व्याप। व्याप में नैतिक गुण एवं अच्छाई के सभी काम आ जाते हैं। अच्छाई के सभी कार्यों सभी सदगुणों तथा समस्त संपत्तियों की ही अरस्तू सामान्य व्याप समझता है। विशेष व्याप से अरस्तू का तात्पर्य प्नाई के विशेष रूपों से है। इस व्याप को वह अनुप्राप्तिक संपत्तियों के कार्य में लेता है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को को मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति इस ढंग में आती है। उसने इसके दो उप-विभाग किए हैं—(क) विवरणमय व्याप एवं (ख) सुधारमय व्याप। विवरणमय व्याप में अरस्तू ने बताया है कि राज्य को चाहिए कि वह अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों सम्मानों तथा अन्य लाभों और पुरस्कारों का बंटवारा या विवरण व्याप पूर्ण रीति में करे। अरस्तू के अनुसार सुधारमय व्याप एक नागरिक से दूसरे नागरिक के सम्बन्ध को निश्चित करता है।

(8) अरस्तू के शिक्षा सम्बन्धी विचार—अरस्तू के अनुसार शिक्षा आदर्श राज्य के लिए अनिवार्य एवं है। आदर्श राज्य के निर्माण और स्थापित के लिए उपयुक्त शिक्षा पद्धति परम आवश्यक है। अरस्तू के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना है ताकि राज्य और नागरिकों में किसी प्रकार का विवाद न रहे और नागरिकों के मानसिक स्तर की उन्नति हो।

शिक्षा के तीन मूल सिद्धान्त—अरस्तू ने शिक्षा के तीन मूल सिद्धान्त बताए हैं—(1) सभी नागरिकों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था (2) शिक्षा द्वारा नागरिकों को संविधान बनाम रूप (3) शिक्षा द्वारा नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना।

(9) अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण—अरस्तू ने संविधानों का वर्गीकरण दो सिद्धान्तों के आधार पर किया है—(1) सत्ता अर्थात् शासन सत्ता किसे व्यक्तिक है, स्थिति है? एवं (2) तात्पर्य का उद्देश्य अर्थात् राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ साधन? उसके वर्गीकरण का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है—

संविधान का रूप या शासकों की संख्या	सामान्य राज्य जो सार्वजनिक कल्याण की चेष्टा करते हैं	वृष्ट राज्य जो सार्वजनिक कल्याण की चेष्टा करते हैं
एक व्यक्ति का शासन कुछ व्यक्तियों का शासन अनेक व्यक्तियों का शासन	राजतन्त्र या एकेतन्त्र कुर्नैतन्त्र संवत्त तन्त्र	निराशा शासन अन्यतन्त्र या स्वार्थी तन्त्र अधिपतीयी लोकतन्त्र

उसने अपने वर्गीकरण को पूर्णरूप से ब्याख्या की है। इसके अतिरिक्त अरस्तू ने अपने वर्गीकरण के ये आधार बताए हैं—(1) आर्थिक आधार, (2) पौनिक गुणों का आधार एवं (3) कार्य प्रणाली का आधार।

आर्थिक आधार में उसने धनिकतन्त्र में धनिकों का तथा जनतन्त्र में गरीबों का शासन बताया है। गुणों के आधार पर उसने जनतन्त्र में समानता एवं स्वतन्त्रता के तत्त्व पर धनिक तन्त्र में धन पर कुलीन तन्त्र में गुणों पर तथा संयुक्त जनतन्त्र में धन एवं स्वतन्त्रता के तत्त्व पर बत दिया है। शासन प्रणाली को दृष्टि से उसने बताया है कि कौन कौन से पदों पर सम्पत्ति वाले व्यक्ति ही शासन करते हैं तो कहीं सम्पत्ति वाले भी शासन में भाग ले सकते हैं।

(10) सर्वश्रेष्ठ ध्यायव्यवहारिक राज्य या सर्वोत्तम संविधान—अरस्तू ने अपने सर्वोत्तम अथवा आदर्श संविधान का वास्तविक उदाहरण नहीं दिया है। उसने श्रेष्ठता की दृष्टि से शासन प्रणालियों अथवा संविधान या राज्यों का जो क्रम निरूपित किया है वह है—(1) आदर्श राजतन्त्र (Ideal Royalty), (2) विशुद्ध कुलीनतन्त्र (Pure Aristocracy), (3) मिश्रित कुलीनतन्त्र (Mixed Aristocracy), (4) संघ राजतन्त्र (Polity), (5) अधिकतम उदारजनतन्त्र (Most Moderate Democracy), (6) अधिकतम उदार धनिकतन्त्र (Most Moderate Oligarchy), (7) जनतन्त्र तथा धनिकतन्त्र के बीच के दो प्रकार, (8) अति जनतन्त्र (Extreme Democracy), (9) अति धनिक तन्त्र (Extreme Oligarchy) एवं (10) तानाशाही (Tyranny)। अरस्तू ने क्रमबद्धता के अनुसार उक्त संविधानों की जो सूची दी है उसमें अत्युत्तम संयुक्त जनतन्त्रीय संविधान (Polity) ही उत्तम संविधान है।

(11) आदर्श राज्य—अरस्तू के आदर्श राज्य की विशेषता है—“कानूनों की प्रभुता तथा एक समुचित और समुचित माता में सम्पत्ति एवं निरन्तर पारिवारिक जीवन उपलब्ध है।” अरस्तू ने कहा है कि जो शासन अपनी प्रजा की भलाई हेतु होता है वह कानून के अनुसार होता है। ठाका आधार मानव प्रकृति के स्वरूप पर निर्भर होता है। उसके आदर्श राज्य की विशेषताएँ निम्नलिखित प्रकार से हैं—

- (i) राज्य का धर्म आवश्यकतानुसार होना चाहिए। यह न इतना छोटा हो कि आजीविका कठिन हो जाए और न इतना बड़ा कि व्यक्ति विस्तारिता का जीवन बिताए।
- (ii) आदर्श राज्य के नागरिकों का चरित्र और उनकी योग्यता युवावी विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अरस्तू की धारणा है कि आदर्श राज्य में धन्य और नागरिक गुण समान होने से सभी अच्छे नागरिक होंगे।
- (iii) जनसंख्या न बहुत अधिक हो और न बहुत कम।
- (iv) अरस्तू ने आदर्श राज्य में 6 प्रकार की आवश्यकताएँ मुख्य मानी हैं—पोषण, कला-कौशल, शास्त्र, सम्पत्ति, सार्वजनिक देश पूजा और सार्वजनिक हित का निर्धारण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने राज्य में छह वर्ग कृषक, शिल्पी, योद्धा, सम्पत्तिशाली वर्ग, पुरोहित और प्रशासक होना आवश्यक माना है।
- (v) अरस्तू आदर्श राज्य में शिक्षा पर ध्यान देता है। आदर्श राज्य का उद्देश्य एक शुभ जीवन की प्रति है और शुभ जीवन के लिए व्यक्ति का चरित्रवान, स्वायत्त और बर्तव्य-परायण होना आवश्यक है। यह कर्म शिक्षा के द्वारा हो सकता है।
- (vi) अरस्तू अपने आदर्श राज्य के लिए अन्य विशेषताओं का भी वर्णन करता है जैसे—बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए रक्षा के अच्छे साधन, राज्य में धनी, सड़कों एवं निम्नो आदि की सुन्दर व्यवस्था आदि।

(12) अरस्तू के क्रांति सम्बन्धी विचार—अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में हर छोटा-बड़ा परिवर्तन। यह आवश्यक नहीं है कि संविधान में पूर्ण परिवर्तन होता है या आंशिक, सशस्त्र होता है या बिना किसी विशेष घटना के। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति भी कहा दे सकते हैं किन्तु जब संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में परिवर्तन होता है इसे आंशिक क्रांति कहा जाना चाहिए। संविधान में परिवर्तन निर्वाचन द्वारा, धोखे से सशस्त्र विद्रोह से अथवा अन्य रक्तहीन उपधों द्वारा हो सकता है। अरस्तू ने क्रांति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके 5 प्रकार बताए हैं—(1) आंशिक और पूर्ण क्रांति, (2) रक्त पूर्ण और रक्तहीन क्रांति, (3) व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत क्रांति, (4) वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति एवं (5) वैचारिक क्रांति।

मैकियावेली

(Machiavelli, 1469 1527)

जीवन परिचय (Life Sketch)

बौद्धिक पुनर्जागरण ने लोगों के जीवन में नई चेष्टा, स्वतन्त्रता के लिए एक नवीन प्रेम और जीवन में नवीन मूल्यों के प्रति अनुगम पैदा कर दिए। ज्ञान और पुनर्निर्माण के ऊष्णकाल में मैकियावेली पैदा हुआ था, जिसने विश्व को नई

मृत्यु और दिरा प्रदान की। फ्लोरेंस मैकिवेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 में हुआ था। उनका पिता वकील था। 1490 में मैकिवेली ने एक साधारण प्रशासकीय पद पर कार्य शुरू किया। 1498 से 1512 तक उसने फ्लोरेंस की 'कोसिल ऑफ दै' के सचिव पद पर कार्य किया। उसने असा रीथ जीवन अच्छे कार्य में व्यतीत किया। 1527 में उनका देहवसान हो गया।

मैकावालेली के ग्रन्थ (Works of Machiavelli)

मैकिवेली ने दो महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिसके कारण उनका नाम राजनीति दर्शन में अमर हो गया। उनके ये दो ग्रन्थ हैं—(1) *डिस्कॉर्सेस ऑन लिवि (Discourses on Livy)* (2) *दी प्रिंस (The Prince)*।

मैकिवेली युग शिरो के ग्रन्थ में

मैकिवेली के चिन्तन पर उनकी दुगन परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव था, इसलिए उनके दर्शन के विद्वान् इतिहास ने लिखा है कि "यह प्रतीति सम्पूर्ण फ्लोरेंस निवासी चरित्रिक अर्थ में असम बन्धन का शिरो था।"¹

(1) मैकिवेली के मानव स्वभाव सम्बन्धी विचार—मैकिवेली की धारणा थी कि मनुष्य जन्म से बुरा होता है। अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण वह अधार्मिक हो जाय होता है। मानव प्रकृति में घोर स्वार्थ एवं दुष्ट होता है। मैकिवेली का विश्वास था कि मनुष्य की स्वार्थ भावना और उसका अहंकार उसके सारे क्रियाकलापों के मूल में होते हैं। वह विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त होता है तथा परोपकार जैसी धारणाओं से अनर्पित होता है। उसने निष्कर्ष है कि "समान्यतः मनुष्यों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है वे क्रूर, चलायमान, मिथ्यावादी, दारपक और स्वार्थ विमुख होते हैं। वे तभी तक अपने बन्ध रहते हैं जब तक सम्पत्ति उनके पास है। वे तभी तक अपने लिए अपना गुलू समर्पित जीवन अर्पित का बलिदान करने के लिए प्रसुत रहेंगे जब तक वस्तु में ऐसे बन्धनों की आवश्यकता दूर रहती है लेकिन जैसे ही वह आवश्यकता निकट आती है वे अपने विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं।—मनुष्य उसी समय तक किसी से प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है लेकिन जब वे अपनी कार्य स्वार्थ सिद्ध नहीं देखते तब वे विद्रोह कर देते हैं।" मैकिवेली का यह वाक्य बड़ा ही प्रसिद्ध है कि "मनुष्य निष्ठा की मृत्तु का दुष्ट असली से भूय रहता है, पर निष्ठा का हानि नहीं करता।"

(2) मैकिवेली के राज्य और नैतिकता सम्बन्धी विचार—राजनीति दर्शन में मैकिवेली ने सर्वप्रथम राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से पृथक् रखने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। मैकिवेली के अनुसार पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, लोक-पारलोक, अच्छा-बुरा, शत्रु-मित्र आदि के विचार दारपक मनुष्य के लिए हैं। राजा का इनका धर्म नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार सच्चा राजा वही है जो शक्ति, धन और पदवी सब अपने हाथों की तरह चलायता है और सफल हो सके।

(3) मैकिवेली के राज्य सम्बन्धी विचार—मैकिवेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम सत्ता है जिस मनुष्य ने अपनी अनुविषाओं को दूर करने के लिए बनाया है। वह राज्य के अस्तित्व का कारण मनुष्य का स्वार्थ भावना है और राज्य की मुख्य विशेषता बलका निरंतर विस्तार है। मैकिवेली नगर राज्य की ओर ही निरन्तर विकासशील राज्य स्थापना का दायित्व था। स्वार्थ को राज्य की उत्पत्ति का कारण बताते हुए मैकिवेली यह स्वीकार करता है कि राज्य की स्थापना असम्यक् परिस्थितियों को सांठित करने के लिए हुई थी। वह स्वार्थ के अतिरिक्त यह बताना है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरवादी न होकर समाज के बल का परिणाम है। मनुष्य की दुष्टता और स्वार्थभाव को समित एवं नियंत्रित करने के लिए बलशाली बाह्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो राज्य द्वारा पूरी की शक्त है।

उसने बताया है कि आदर्श राजा को किसी दायित्व से राज्य का अधिकार सम्पन्न और अधिकार बलवान् चाहिए। उसने बताया कि "मनुष्य मानवता और मनुष्य के अर्थों से निरुद्ध बन्ध है, अतः राजा को इन दोनों के साथ व्यवहार करने के तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। उसने राजा का यह शिक्षा दी है कि उस दायित्व होने दूर सर्वेष्ट पद्धत रखना चाहिए कि कोई उसकी कमजोरियों का अनुचित लाभ न उठाए।"

(4) मैकिवेली के सरकार सम्बन्धी विचार—राज्य छोटी अथवा बड़ी के वर्गीकरण मैकिवेली ने इस उद्देश्य से किया है कि आदर्श शासन कल्पित जा सके। अपने का अनुमान करते हुए उसने सरकारों का उनका शुद्ध एवं अशुद्ध रूप मानकर छ पाँचों में विभक्त किया है—सामान्य रूप—(1) राज्य (2) कुलेन्द्रव एवं (3) गणतन्त्र। विद्वान् रूप—(1) आन्दोलन (2) वर्तमान एवं (3) घोटका।

(5) नागरिक सेवा और सैनिक शक्ति सम्बन्धी विचार—मैकिवेली की मान्यता है कि शासक को नागरिकों की शक्तिशाली सेना का निर्माण करना चाहिए, जिसे के उत्तुंग पर अधिकार रहता सफल है। उसे जहाँ कुल्ले बर्न से अधिक है, वहाँ भंडे के सिन्हा से घृण है। मैकिवेली के विचार से इटली में उस समय अराजकता का मुख्य

1. During "Machiavelli the brilliant Florentine was in the full best sense the child of his times."

वारंग भाई के भिपारी थे। मैकियावेली मानता था कि फ्रांस को अपनी सेना का राष्ट्रीयकरण करने से लाभ हुआ है। मैकियावेली का विचार था कि 17 से 40 वर्ष की आयु के बीच के समस्त सभ्य नागरिकों को सैनिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।

(6) साम्राज्यवाद या राज्य प्रसार सम्बन्धी विचार—मैकियावेली के मतानुसार राज्य को प्रसरणशील होना चाहिए। अंग्रेजों सीमा रेखा बढ़ाकर राजा को चाहिए कि वह दूसरे राज्यों को आत्मसत्ता को और साम्राज्य विस्तार द्वारा अपने गौरव का परिचय दे। मैकियावेली के अनुसार निर्दोषकरण या दूहीकरण से राज्य में एकरूपता आ जाती है। मनुष्य स्वभाव से महन्-कांक्षी है और एक दूरदर्शी राजा का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह नई भूमि पर अधिभार करे नए उपनिवेश बसाए साम्राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाए तथा शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था करे।

(7) सम्प्रभुता और विधि सम्बन्धी विचार—मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से 'सम्प्रभुता' शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं किया किन्तु उसने राजा की शक्तियों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसमें सम्प्रभुता का आभास होता है। मैकियावेली स्वयं परिवर्तन घाटी था इसलिए उसने सत्ता तथा अखण्ड सम्प्रभुता की बात नहीं की है। उसकी सम्प्रभुता एशान्द्र, सैनिक, धर्म निर्पक्ष और स्वतन्त्र चेतना से संयुक्त है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में मैकियावेली भीषित सम्प्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करता है। विधि के सम्बन्ध में मैकियावेली के विचार संकुचित हैं। वह नागरिक विधि के अस्तित्व को स्वीकार करता है और विधियों को शासक के प्रभाव का माध्यम मानता है। उसके अनुसार राज्य-विहीन समाज में विधियाँ न होने से पूर्ण अराजकता थी। उसके अनुसार विधियों का मुख्य कार्य सामन्त्य एवं सम्बन्ध की स्थापना करना है। उसके अनुसार सभी विधियाँ नागरिक हैं जो शासक के द्वारा प्रणीत होती हैं।

(8) सर्वशक्तिशाली विधिकर्ता या विधापक—मैकियावेली ने विधापक के कार्य एवं महत्त्व को बहुत ही सतत भाषा में ध्वनित किया है। उसके अनुसार सभ्य राज्य की स्थापना एक आदमी के द्वारा की जा सकती है। मैकियावेली के अनुसार "हमें सामान्य नियम के रूप में यह मन्त्र लेना चाहिए कि किसी गणराज्य अथवा राजाज्य का सगठन अथवा दशाब्दी पुरानी सत्ताओं का सुधार तभी सम्भव है जब वह व्यक्ति के द्वारा किया जाए। यही तक है कि जिस व्यक्ति ने इस सविधान की कल्पना की हो वही उसे कार्यान्वित भी करे।"

मैकियावेली आधुनिक राजनीति का जनक

मैकियावेली को 'आधुनिक राजनीति का जनक' कहा जाता है। इनमें उसे मध्ययुग और आधुनिक युग का सम्बन्ध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक माना है। प्रो. जॉस उसे राजनीतिक सिद्धान्तवादी न मानते हुए आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों के पिता की सभा से विभूषित करता है। मैकियावेली राजनीतिक विचारों के इतिहास में अमर स्थान रखता है क्योंकि वह पहला राजनीतिज्ञ है जिसने मध्ययुग के विचारों का छटन प्रारम्भ किया था और आधुनिक विचारधारा का श्रोतगण किया। यद्यपि उसे आधुनिक युग का पूर्ण प्रतिनिधि कहना अत्युक्तिपूर्ण है। मैकियावेली की स्थिति एक ऐसे विचारक की है जो मध्ययुग और आधुनिक युग की सीमाओं पर उत्पन्न हुआ था और जिसने मध्य युग के साम सामान्य विच्छेद करके आधुनिक सिद्धान्तों से नाता बनाया। उसने चिन्तन में ये दृष्ट ऐसे हैं जो उसे आधुनिक राजनीतिक चिन्तक के रूप में स्थान प्रदान करते हैं—(1) उसने राजनीतिक चिन्तन को वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया। (2) उसने धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर राजनीति को धर्म के नियन्त्रण से बाहर किया। (3) उसने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। (4) उसको ही सम्प्रभु राष्ट्रीय राज्य के सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय दिया जा सकता है। यह एक आधुनिक अवधारणा है। (5) उसने मध्ययुगीन कल्पनावेद से ऊपर उठकर यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया। (6) उसकी आधुनिक राष्ट्रीयता का अग्रगामी विचारक माना जाता है। (7) उसने अपने चिन्ता में यद्यपि सत्ता राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया लेकिन व्यवहार में वह गणतन्त्रात्मक-जनतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक था। इन कारणों से मैकियावेली को 'यथार्थवादी विचारक' और 'आधुनिक राजनीतिक विचारक' के रूप में जाना जाता है।

हॉब्स

(Hobbes, 1588-1679)

जीवन-परिचय (Life Sketch)

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनुवर्षवादी सिद्धान्त की प्रथमता 17वीं और 18वीं शताब्दी में रही है। इस सिद्धान्त का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने किया। टॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल, 1588 को इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित माज्मरो नगर में हुआ था। अपने बाल्यकाल में हॉब्स अध्ययनशील एवं अनुशासित स्वभाव का किन्तु इरपोक था। उसने राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित और दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया था। 1679 में 91 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया।

(4) हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों सम्बन्धी विचार—हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार आदि कालीन अवस्था में मानव-जीवन की रक्षा के लिए उपयोगी व्यवहार स्वातन्त्र्य या जो प्रत्येक व्यक्ति में स्वभावतः निहित था। व्यक्ति को अपने जीवन पारण के लिए किसी को लूटने या मार डालने की स्वतन्त्रता थी। टी. एच. हम्मेली ने ऐसे अधिकार को शेर का अधिकार कहा है। प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्राकृतिक नियम ये जिनका पालन करने में प्राकृतिक अधिकार प्रविष्ट के उद्देश्य की पूर्ति होती थी। हॉब्स का मत है कि मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक-दूसरे की हत्या और लूटमार का अधिकार मिल जाता है जिससे जीवन असुरक्षित हो जाता है। हॉब्स ने प्राकृतिक नियमों को 'शर्तों' की धाराओं का नाम दिया है। उसने 19 प्राकृतिक नियम गिनाए हैं। हॉब्स के तीन नियमों का सार यह है कि "दूसरों के साथ वृत्त वैसा ही करो जैसा अपने लिए उनसे चाहते हो।" उसके कुछ नियम इस प्रकार हैं—(1) प्रत्येक व्यक्ति को अन्य लोगों के साथ मित्रवत चलना चाहिए। (2) प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को अपने समान सम्पन्नता चाहिए। (3) किसी व्यक्ति को कर्म, शब्द, मुद्रा या संकेत द्वारा दूसरे के प्रति धृष्टता प्रकट नहीं करनी चाहिए। (4) भविष्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक को उन दूसरे मनुष्यों की पिछली वृत्तियों को क्षमा कर देना चाहिए जो परचाप करके क्षमा चाहते हैं।

(5) हॉब्स के आत्म रक्षा की प्रकृति और बुद्धिसंगत आत्म रक्षा सम्बन्धी विचार—हॉब्स के अनुसार, मनुष्य अपनी जीव-शक्ति को कायम रखने और बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। आत्म-रक्षा का उद्देश्य मनुष्य ने जैविक अस्तित्व को कायम रखना है। इसमें सहायक शक्ति है और जो असाहायक है वह अशुभ है। हॉब्स को यह स्पष्टतः मालूम था कि आत्म-रक्षा का सिद्धान्त इतना आसान नहीं था जैसा कि वह अब तक माना गया है। जीवन आतंकार नहीं है जिसमें साथ ही एक समय में हमेशा के लिए प्राप्त कर लिया जाए। जीवन में आत्म रक्षा के साधन की खोज करनी पड़ती है। चूंकि सुरक्षा के साधन कम हैं इसलिए जीवन-समर्थ अनन्त है। मानव प्रकृति की मूल आवश्यकता सुरक्षा की इच्छा है। इस इच्छा को शक्ति की इच्छा से पूरक बना दिया जा सकता है। हमें आज सुरक्षा की जितनी आवश्यकता है उसे नित्यव्रति साक्षात् करने की जरूरत है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य निरन्तर सुरक्षा की आवश्यकता का अनुभव करता है। वह मानव प्रकृति में अभिन्नता और विवेक इन दो सिद्धान्तों की चर्चा करता है। इच्छा अथवा अभिन्नता के कारण मनुष्य उन सभी वस्तुओं की प्रशंसा करना चाहता है जिनमें अन्य व्यक्ति चाहते हैं। इसका परिणाम यह है कि वे निरन्तर सापेक्षता रहते हैं, लेकिन विवेक अथवा बुद्धि द्वारा मनुष्य पारस्परिक संपर्कों को मूलना सीखते हैं। विवेक बालाता है कि आत्म रक्षा का उद्देश्य सभी प्राप्त किया जा सकता है जब शक्ति हो।

(6) हॉब्स के राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप सम्बन्धी विचार—हॉब्स बुद्धिवादी है। उसके मतानुसार जब मनुष्य जान जाग है कि उनकी 'धुन' का प्रथम पारंपरिक प्रयोगिता के कारण है तो विवेक उसे मार्ग दिखाता है। जब वह यह सिद्धान्त मान लेता है कि 'तू भी दूसरों के साथ यथा न कर जो तू अपने साथ दूसरों द्वारा किया जाना अन्यायपूर्ण समझता है। हॉब्स मानता है कि यदि मनुष्य स्वभाव से हा शक्तिपूर्ण होता और बिना किसी सर्वोच्च शक्ति या शब्दिका के रह सता तो शासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती पर मनुष्य ऐसा नहीं है। वह अपनी शक्तियों और अपने सवर्गों को नियंत्रण में नहीं रख सकता। उसकी स्वार्थी वृत्तियाँ संपर्क के बाध होती रहती हैं। अतः स्वभावतः एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय की आवश्यकता पड़ती है जो मनुष्यों को नियंत्रण में रखकर उनको अनुशासन बद्ध करे। हॉब्स ऐसी सत्ता अथवा शक्ति राज्य में पाता है जिसकी इच्छा समस्त व्यक्तियों की इच्छाओं की प्रतिनिधि होती है और जिसमें यह सामर्थ्य होती है कि यह सबसे विवेक के अनुसार आग्रह करे और ऐसा न करने वाले को दण्ड दे। हॉब्स के मतानुसार राज्य एक सामाजिक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। उसके अनुसार एक राज्य की स्थापना तब होती है जब अनेक व्यक्ति एक-दूसरे से यह समझौता करते हैं कि समस्त व्यक्ति उस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के कार्यों को अपना कार्य समझेंगे जिसे उनके अधिकांश भाग ने अपना प्रतिनिधि चुना है पर उन्हीं से किसी ने उसके पक्ष में मत दिया हो या विरोध में। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि मनुष्य शक्तिपूर्वक और दूसरों के विरुद्ध सुरक्षित रहे। यह समझौता इस प्रकार हुआ है मानो प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति ने यह कहा हो कि 'मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अपना शासन स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूँ कि तुम अपने इस अधिकार को इसी तरह इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समर्पित कर दो।' इस तरह जब समुदाय एक व्यक्ति में संकुचित हो जाता है। इस राज्य या लेटिन भाषा में 'सिविलास' (Civitas) कहते हैं। हॉब्स के अनुसार यही उस महान् लेविथायान या देवता का जन्म है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्रछाया में हमारी शान्ति तथा सुरक्षा निर्भर है।

(7) हॉब्स के प्रभुसत्ता सम्बन्धी विचार—हॉब्स प्रभुसत्ता का प्रकण्ड समर्थक है। उसकी प्रभुसत्ता का आधार सामाजिक संविदा है। स्पष्ट या अस्पष्ट किसी रूप में संविदा या अनुबंध से प्रभुसत्ता प्राप्त होती है। हॉब्स का 'लेविथायान'

अथवा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शासक निरवश है। उसका आदेश कानून है। उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। प्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, स्थाई एवं अद्वेय है। राज्याज्ञा न्याय-समस्त और कानून-समस्त होती है। उसका हस्तक्षेप कानून और विचारों पर होता है। गौटो ने प्रभुमता पर जो मर्यादाएँ लगाई हैं उन्हें हॉब्स हटा देता है। गौटो के अनुसार "राज्य का अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ है जिसने प्रभुमता में इतना अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया हो।"¹

हॉब्स के अनुसार सम्प्रभुता सभी विधेयान्त्रिक कानूनों की स्रोत है। व्यक्ति सुरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों तथा वैयक्तिक अधिकारों का परित्याग कर देते हैं, एक स्वाभाविक रूप से उन सब की तरह एक विधि-निर्माण की शक्ति सम्प्रभु के पास रह जाती है। सम्प्रभु समाज की ओर से यह गृह्यत्वपूर्ण निर्णय करता है कि सामाजिक शान्ति और सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए?

(8) हॉब्स के नागरिक कानून सम्बन्धी विचार—सामान्य नागरिक विधियाँ सम्प्रभु की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं। विधियाँ न केवल नियमों अथवा ऐतिहासिक परम्पराओं का नहीं, बल्कि सम्प्रभु की दृढ़ सत्त्व-क्रिया प्रमाण हैं। विधि सम्प्रभु की शक्ति की घोषक है जो प्रजाजन के लिए कर्मों की घोषणा करती है। विधियाँ मान्य व्यवहार को विनियमित करने एवं उसका मानदण्ड प्रस्तुत करती हैं। ये उस सम्प्रभु का आदेश हैं जिसमें अपने अधिकारों का पालन करने की क्षमता है। प्रजा इन विधियों को नैतिक मूल्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि इसलिए मानती है कि वे सम्प्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। हॉब्स के अनुसार विधि के दो विभाग हैं—(1) विवरणात्मक या निषेधात्मक एवं (2) आदेशात्मक या दण्डात्मक। प्रथम विभाग में नागरिकों को वैध-अवैध कार्यों का ध्यान बताना जाता है और दूसरे विभाग में राज के अधिकारों को, जनता के प्रति अवस्थाानुसार क्या दण्ड पिघाना है, इसकी व्याख्या की जाती है। सम्प्रभु विधि का मात्र स्रोत और व्याख्याकार है।

(9) हॉब्स के राज्य तथा धर्म सम्बन्धी विचार—हॉब्स यह स्वीकार नहीं करता कि अन्य कोई सम्प्रभु राज्य के समकक्ष है। वह धर्म को विधि एवं शासन के नियन्त्रण में मानता है। उसने धर्म को पूर्ण तरह नागरिक शक्ति के अधीन कर दिया। हॉब्स ने धर्म का आधार अदृश्य शक्ति का भय बना है। मनुष्य शास्त्रव नरक के भय से काँपता है और आध्यात्मिक सत्ता उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाती है, अतः उसने अनुसार राज्य को इस खतरा से अपनी रक्षा प्रजा की रक्षा करना चाहिए।

(10) हॉब्स के व्यक्तिवाद सम्बन्धी विचार—निषेध सम्प्रभुता का समर्थक होते हुए भी हॉब्स व्यक्तिवादी है। वह मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवादी है जिसके राजदर्शन का प्राथमिक सूत्र व्यक्ति है। आस्तु के समान समाज नहीं। 'उमरी विचारधारा में व्यक्ति अलग इकाई है और राज्य बाहर की एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें एकता के भूत में बाँधती है और उनके समान स्वार्थों में साम्यस्य स्थापित करती है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के स्वार्थ से धन्य, किसी सत्ता का उद्वेग न हो सकता है और न होना चाहिए। हॉब्स पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के हित को एवं उसके अधिकारों के अधिकार को सर्वोपरि माना।' हॉब्स का निरुत्तराव दृढ़ नहीं है। नागरिक विधियों के संस्था में स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। 'सोविपादन' अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता। सेवाइन के अनुसार "हॉब्स के विचारों में व्यक्तिवाद का अर्थ पूर्ण रूप से अप्रुणिक है। इस दृष्टि से हॉब्स आधुनिक युग का विचारक समझ लिया गया था।"² हॉब्स व्यक्ति के हित का समर्थन होने के कारण प्रबल व्यक्तिवादी था।

जॉन स्टुअर्ट मिल

(John Stuart Mill, 1806-1873)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

विख्यात वैयक्तवादी जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद के दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। 20 मई, 1806 को लन्दन में जेम्स मिल की उसके पिता ने बचपन से ही वैयक्त के आदर्शों के अनुसार ज्ञानों का पूरा प्रयत्न किया था। जेम्स के कठोर अनुशासन में स्टुअर्ट मिल ने बाल्यवस्था से गहन अध्ययन में रूचि ली। मात्र 8 वर्ष की अवस्था तक उसने जेरोचेन, हेरोडोरस, आइसोक्रैटस के ग्रन्थों का और प्लेटो के छ सवतों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। 11 वर्ष की अवस्था में उसे निम्नो द्वाय लेटिन में लिखित 'रोमन शासन का इन्द्गल' पढ़ने को दिया गया। 13 वर्ष की अवस्था में उसने एडम स्मिथ और रिक्डों की अर्थशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकें, तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान के जटिल विषयों का गहन अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। वह बचपन से अपने कठोर बौद्धिक अनुशासन में रहा कि उसकी प्रबलतम आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो पाई, वह प्रकृतिक सौन्दर्य से दूर रहा और बाल्य-सुखमयी मनोरंजन भी उसे नहीं मिल पाया। 14 वर्ष की आयु में उसे वैयक्त के छोटे भाई के साथ एक वर्ष के लन्दन भेजा गया। वहाँ उसे

1 Gentle "No writer has taken a more extreme view than Hobbes of the absolute nature of sovereignty"
2 महान्त राजनीतिक दर्शन का इतिवृत्त, खण्ड 1, पृ. 421

धूमने और प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द लेने का अवसर मिला। बाद में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम, यात्रा के प्रति आकर्षण और फ्रेंच भाषा के प्रति अनुराग—ये जीवन-चर्य-तत्त्व उसके साथ रहें।

अति कुशाम्बुद्धि और मेधावी मिल में अध्ययन और कार्य करने की तीव्र आकांक्षा थी। प्रौढ से लौटकर उसने जैन आस्टिन और रोमन कानून तथा अन्य कानूनों की शिक्षा प्राप्त की। वह विभिन्न सामाजिक-संस्थाओं में भाग लेने लगा और शीघ्र ही उसने पाषण्ड-कला में निपुणता प्राप्त कर ली। 16 वर्ष की अवस्था में वह 'उपयोगितावादी सोसाइटी' (Utilitarian Society) का सदस्य बन गया और लगभग साठे होन वर्ष तक वह बाद विचारों में प्रमुख वक्ता रहा। 17 वर्ष की अवस्था में ईस्ट इण्डिया कम्पनी में एक क्लर्क के रूप में नियुक्त हुआ और सन् 1856 में अपने विभाग का अध्यक्ष बन गया। दो वर्ष बाद वह पद निवृत्त हो गया। नौकरी के व्यस्त काल में भी उसने अपनी साहित्यिक गतिविधियों में शिथिलता नहीं आने दी।¹ अनवरत श्रम और बौद्धिक व्यापार के फलस्वरूप युवावस्था में ही मिल को हल्के हृदय रोग का सामना करना पड़ा। उसने बर्हसवरथ कॉलरिज आदि का गहन अध्ययन किया। इन महाकवियों की रचनाओं को पढ़कर मिल में जीवन की अधिक मार्मिक वस्तुओं और मानव-मस्तिष्क की सूक्ष्म क्रियाओं के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। उसके स्वभाव और चिन्तन में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। देविदसन के अनुसार, "उसके हृदय में एक नवीन मानव का आविर्भाव हुआ जिसमें अधिक गहरी सहानुभूति थी, जिसका बौद्धिक दृष्टिकोण अधिक व्यापक था, जिसने मानव की आवश्यकताओं को अधिक समझा था और जिसने बुद्धि के साथ भावनाओं की तुल्य के महत्व को अनुभव किया था।" मिल् 59 वर्ष की अवस्था में समुद्र का सदस्य निर्वाचित हुआ। वह सन् 1865 से 1868 तक समुद्र सदस्य के रूप में आयरलैण्ड में भूमि-सुधार, किसानों की स्थिति, महिला गताधिकार, बौद्धिक कार्यकर्ताओं की स्थिति आदि के सम्बन्ध में अत्यन्त क्रियाशील रहा। लन्डन में उस प्रचारक के रूप में उसने विशेष ख्याति अर्जित की। उसने समस्याओं पर स्वतन्त्र और निर्भीक विचार व्यक्त किए। शासन और विरोधी दलों ने उसे पूरा सम्मान दिया। प्रधानमंत्री ग्लेडस्टन ने कहा था, "जब मिल का प्राण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी सत्ता का प्रथम सुन रहा हूँ।"

रचनाएँ और पद्धति

मिल ने अपने सघनपूर्ण जीवनकाल में न्यायशास्त्र, अध्ययन-शास्त्र, आचार शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र—सभी महत्वपूर्ण विषयों पर लिखा। उसकी कृतियाँ उसके जीवनकाल में ही प्रकाशित हो गई थीं और कुछ मृत्यु के बाद प्रकाशित हुईं। उसके प्रमुख ग्रन्थ हैं—

- 1 Plato's Dialogues, 1834
- 2 The System of Logic, 1841
- 3 Some Unsettled Questions in Political Economy, 1844
- 4 The Principles of Political Economy, 1848
- 5 Emancipation of Women, 1853
- 6 On the Improvement in the Administration of India, 1858
- 7 A Treatise of Liberty, 1859
- 8 Parliamentary Reforms, 1859
- 9 Considerations of Representative Government, 1860
- 10 Utilitarianism, 1861
- 11 Examination of Hamilton's Philosophy, 1865
- 12 August Comte and Positivism
- 13 Subjection of Women, 1869
- 14 Autobiography, 1873
- 15 Three Essays on Religion, 1874
- 16 Letters, 1910

मिल के उपयोगितावादी विचार

(MIL) on Utilitarianism)

जेम्स मिल के प्रयत्नों और बेन्थम के प्रति उसकी श्रद्धा ने स्टुअर्ट मिल को बड़ा उपयोगितावादी बना दिया। बेन्थम के उपयोगितावादी सिद्धान्त पर आलोचकों ने निष्पक्षता और हेतुता के आरोप लगाये थे। मिल ने आलोचकों के प्रहार का जोरदार उत्तर देते हुए उपयोगितावाद में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए तथा उसमें अनेक नए सुधारों का समावेश कर दिया जिसके फलस्वरूप मूल सिद्धान्त प्रायः समाप्त हो गये। बर्हसवरथ कॉलरिज, कॉन्टे, डार्विन, स्पेंसर आदि के प्रभाव तथा इंग्लैण्ड की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण मिल के प्रारम्भिक बेन्थमवादी विचारों में सारी श्रद्धा परिवर्तित आता गया और उसने नवीन सिद्धान्तों पर बल देना शुरू कर दिया। उपयोगितावाद की रक्षा करने के प्रयत्नों में उसने इतना संशोधन कर दिया कि उसका स्वरूप ही बदल गया। वेपर के अनुसार, "उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसकी रक्षा करने की इच्छा से मिल ने सम्पूर्ण उपयोगितावाद को एक तरफ फेंक दिया।"² उसने उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया और राजनीतिक चिन्ता के क्षेत्र में इसे प्रायः अन्तिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक माना जात है। मिल उपयोगितावाद पर विचार उसके प्रख्यात निबन्ध 'Utilitarianism' में उपलब्ध हैं।

1 William Ebenstern Great Political Thinkers p. 530-531

2 Weyper Op Cit (Hindi) p. 141

मिल द्वारा उपयोगितावाद की पुनर्संमीक्षा

(Mill's Restatement of Utilitarianism)

आरम्भ में मिल बेन्थम के सिद्धान्त के आधार पर आगे बढ़ा। उसने बेन्थम के सम्मान सुख की प्राप्ति और दुःख की विमुक्ति को व्यक्ति का अभीष्ट माना। उपयोगितावाद की परिभाषा देते हुए उसने लिखा—“वह मत जो उपयोगितावाद अथवा अधिकतम सुख के सिद्धान्त की नैतिकता का आधार समझता है, यह मानता है कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही है जिस अनुपात में वह सुख की वृद्धि करता है। जो कार्य सुख से विपरीत दिशा में जाता है वह गलत है। सुख का अर्थ आनन्द की प्राप्ति और दुःख का अभाव। दुःख का अर्थ है पीड़ा या कष्ट तथा आनन्द का अभाव। इस सिद्धान्त द्वारा स्थापित नैतिक मापदण्ड को अधिक स्पष्ट करने के लिए इससे अधिक कहना अनावश्यक है, विशेष रूप से यह कि सुख और दुःख की धारणाओं में क्या सम्मिलित है और उनका उद्देश्य क्या है? यह एक खुला प्रश्न है, परन्तु वे पूर्ण व्याख्याएँ जीवन के उस सिद्धान्त को प्रभावित नहीं करतीं जिस पर नैतिकता का यह सिद्धान्त आधारित है कि सुख और दुःख से मुक्ति जीवन का एकमात्र लक्ष्य है समस्त बौद्धिगम्य वस्तुएँ जिनका उपयोगितावादी घोषणा में यह स्थान है जितना अन्य किसी घोषणा में बौद्धिगम्य इसलिए है कि यह उनमें सुख का निवास है अथवा वे सुख-वृद्धि या दुःख-निवृत्ति का साधन हैं।”¹ मिल ने बेन्थम के सुखवाद को स्वीकार किया किन्तु कालान्तर में उसके विचारों में शक्ति-शक्ति एक ब्रति हुई तथा उसका विवरण ऐसा हो गया जिसमें बेन्थम तथा उसके उपयोगितावादी चिन्तन में गहरे अन्तर उभर आए। यह देखा उपपन्न होगा कि कहाँ तक वह बेन्थम के साथ है और कहाँ तक उससे पृथक् रहा। उसके द्वारा किया गया बेन्थम के सिद्धान्त का रूपान्तर निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट हो सकेगा—

1. सुखों में मात्रात्मक तथा गुणात्मक अन्तर है—बेन्थम सुखों और दुःखों के मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता था गुणात्मक भेद को नहीं, किन्तु मिल ने इन दोनों भेदों को स्वीकार किया है। उसने कहा है कि सुख और दुःख के गुणात्मक अन्तर को मानना पूर्णतः उचित है। कुछ सुख मात्रा में कम होने पर इसलिए प्राप्त करने योग्य हैं, क्योंकि वे श्रेष्ठ और ठोक्ठ हैं। शारीरिक सुखों की तुलना में मानसिक सुख श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे अधिक स्थायी और सुस्पष्ट होते हैं। मिल के अनुसार सुखों में केवल कम या अधिक का अन्तर नहीं होता, बल्कि उनके गुणों का भी अन्तर होता है। वे अपने महत्त्व के आधार पर उच्च अथवा निम्न हो सकते हैं। सुसम्बन्ध और परिष्कृत शक्तियों वाले व्यक्तियों को जिनसे सुख मिलता है वह सुख मूढ़ व्यक्तियों के इन्द्रियोन्मुख आनन्द से अधिक श्रेष्ठ होता है।

2. सुखों की गणना-पद्धति में परिवर्तन—मिल द्वारा सुखों में गुणात्मक भेद मान लेने से बेन्थम का सुखवादी मापदण्ड खण्डित हो जाता है। सुखों को नापने अथवा उनका मूल्योत्पन्न करने के बेन्थमवादी प्रयत्नों का मूल्य नहीं रहता। बेन्थम सुख की मात्रा को सुखवादी गणना पद्धति में मापना चाहता था जबकि मिल का मत था कि विद्वानों के प्रमाण ही सुखों की जाँच अथवा निर्णय के सही आधार हैं। “वे सुख प्रदान करने वाली विषयियों की प्रशंसा का निर्णय उन्हीं व्यक्तियों द्वारा हो सकता है जिन्हें दोनों अनुपस्थितियों का ज्ञान हो।”²

3. बेन्थम के सिद्धान्त का उद्देश्य सुख या आनन्द-प्राप्ति और मिल का शान्तिनता और सम्मान पर बल—बेन्थम के अनुसार, “मिल की धारणा थी कि आनन्द गुण तथा मात्रा दोनों में मिल होते हैं।” उसके अनुसार, जीवन का अन्तिम उद्देश्य उपयोगितावादी नहीं, बल्कि शान्तिनता (Dignity) है। अपना पुस्तक ‘आनन्द-निबन्धों’ में यह लिखता है कि व्यस्तवाद का प्रभाव सामान्य विचारधारा द्वारा कठिनाई से पहचाना जाता है। वह हम्बोल्ट (Humboldt) के स्वयं अनुपूर्व (Self Realisation) के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। मिल का मत है कि “केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य क्या करता है? यह भी महत्वपूर्ण है कि उसके काम करने के तरीके क्या हैं?” मिल ने राज्य की नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक नैतिक मस्यदा प्रेषित किया है। राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं, बल्कि व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना है। मिल उपयोगितावाद को रखा इसमें पूर्ण परिवर्तन साकर कर सका है।

4. मिल की नैतिकताएँ बेन्थम से अधिक सन्तोषजनक—सम्मान अथवा शान्तिनता का उपयोगितावादी विचार मिल को नैतिक भाषा के उपयोगितावादी विवेचन की प्रेरणा देता है। बेन्थम ने नैतिक भाषा का कारण मनुष्य की स्वायत्तता को माना है, परन्तु मिल का विचार इससे भिन्न है। उसके अनुसार, भय, मृत्यु, स्वयं, नैतिकता में उसी प्रकार का पड़ोस है जिस प्रकार प्रेम सहानुभूति तथा धार्मिक धारणा में। मिल अधिक स्वयं-वादी प्रतीत होता है। वह दो एच ग्रोन के विचार को स्वीकार करता है जिसके अनुसार सार्वजनिक कर्तव्यों तथा उतारदायित्वों का जन्म दार्शनिक आधार पर व्यस्तता अधिकारी तथा हितों से नहीं हो सकता। मिल के अनुसार नैतिक भाषा की धारणा उपयोगितावादी सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकती। उसकी नैतिकताएँ बेन्थम से अधिक सन्तोषजनक हैं।

1 *Worper Political Thought*, p. 115

2 *Mill Utilitarianism*, p. 10

5. स्वतन्त्रता उपयोगिता से अधिक उच्च और मौलिक—बेन्थम के उपयोगितावाद में मिल एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। वेपर के अनुसार "मनुष्य की आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का विचार उसे स्वतन्त्रता के अनुपयोगितावादी विश्लेषण की ओर अपसर्ग करता है। सच्चे उपयोगितावादी के लिए स्वतन्त्रता उपयोगिता से निम्न है, परन्तु मिल के लिए स्वतन्त्रता उपयोगिता से उच्च और मौलिक है।"

6. सुखों की प्राप्ति अप्रत्यक्ष ढंग से होती है—मिल ने 'अधिकतम व्यक्तिगतों के अधिकतम सुख' की कल्पना की स्वीकार करते हुए इसमें बेन्थम की व्याख्या की त्रुटि को दूर करने की चेष्टा की है। बेन्थम के अनुसार राज्य के कार्यों की माफ-तोल् करते समय विस्तार पर भी बल दिया जमा चाहिए अर्थात् यह देखना चाहिए कि राज्य को कितनी जनसंख्या को उस कार्य से सुख पहुँचेगा। यह प्रश्न अविवारित रह गया था कि एक व्यक्ति के सुख की खोज में लगे रहने पर वह अन्य व्यक्तियों को सुख किस तरह पहुँचा सकेगा। मिल ने इसका समाधान करते हुए बतलाया कि यद्यपि अपना अधिकतम सुख प्राप्त करने की लालसा व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य रहता है, तथापि वह सामाजिक हित के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकतम सुख का रूप धारण कर लेता है। ग्राह्मर ने व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है कि उसे उसी सुख प्राप्त होता है किन्तु बाद में वही सुख साध्य बन जाता है।

7. मिल का सिद्धान्त नैतिक, बेन्थम का राजनीतिक—अन्य दृष्टिकोण से मिल की धारणा बेन्थम की धारणा से भिन्न है। बेन्थम अधिकतम सुख के सिद्धान्त को एक राजनीतिक सिद्धान्त समझता था नैतिक नहीं। उसकी रधि इसमें अधिक थी कि "विधि-निर्वाता और शासक सामाजिक नीतियों के निर्धारण तथा विधि निर्माण में इसका प्रयोग करें।" मिल के अनुसार, "जब तक व्यक्ति के अपने और दूसरों के आनन्द की तुलना का प्रश्न है, उपयोगितावाद की माँग है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहना चाहिये जैसे वह एक निष्क्रम तथा कर्णधारहीन दरार हो।" इस मसौह के स्वर्णिय नियम में हमें उपयोगितावादी आधार शास्त्र की पूर्ण आत्म्य के दर्शन होते हैं। जैसा आचरण आप दूसरे से चाहते हैं वैसा ही आपरण दूसरों के साथ करना और अपने पहुँचियों से वैसा ही गैर करना जैसा आप स्वयं से चाहते हैं यही उपयोगितावादी नैतिकता का सर्वोत्कृष्ट आदर्श है।"

8. मिल द्वारा अन्तःकरण के तत्व पर बल—मिल ने अन्तःकरण का अर्थ आत्मनुभूति दियों (Intuitionists) की तरह किसी अन्तर्नैतिक शक्ति से नहीं लिया। उसने कहा कि अन्तःकरण भावनाओं का एक पिण्ड है जिसे हमारे भाषाचार के कारण दुःख पहुँचता है एवं सदाचार के नियमों का उल्लंघन करने से हमें पराकाष्ठा की आग में जलना पड़ता है। यही अन्तःकरण का तत्व है चाहे उसके स्वरूप और मूल में हमारे विचार कुछ भी हों। मिल ने अन्तःकरण के तत्व को 'मान्यता के कल्याण की भावना' भी कहा है और इसे दूसरों के दुःख-सुख की चिन्ता कहकर पुकारा। उसने इसे एक स्वाभाविक भावना माना।

मिल के उपयोगितावादी विचारों का मूल्योत्कंठन

मिल और बेन्थम के उपयोगितावादी विचारों में गहरा अन्तर है। मिल बेन्थम के विचारों में परिष्कार और सशोधन करते हुए बेन्थम की मौलिक मान्यताओं पर कुठाराघात कर देता है। मिल ने उपयोगितावाद के राजनीतिक स्वरूप को मुलाकर उसे नैतिक जीवन के अनुकूल बनाने की चेष्टा में बेन्थम के सुखवाद के मौलिक विचारों को अस्वीकार कर दिया। उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा करने में उसने उसका स्वरूप विकृत कर दिया। यद्यपि गुणात्मक पहलु पर जोर देने से उपयोगितावादी विचारधारा में मानवीयता का अधिक समावेश हुआ है तथापि इससे बेन्थम का मापक चक्र अस्त-व्यस्त हो गया। सुखों के गुणात्मक अन्तर को किस प्रकार नापा जाए, यह भी एक जटिल प्रश्न बन गया है। प्रो. सेबाइन के अनुसार, "उसने अपने सचवाद में सुख के उच्च और निम्न स्तर पर नैतिक सिद्धान्त और जोड़ दिया। इसका अधिप्राय यह हुआ कि इसने उपयोगितावाद को पूर्णरूप से एक अनिश्चित सिद्धान्त बना दिया। सुखों के गुण को पाखने का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया था और यदि यह किया भी जाता तो वह सुख नहीं होता है।" बेन्थम का उपयोगितावाद परम्परागत नैतिक मान्यताओं के मूल्योत्कंठन की कसौटी है जबकि मिल का उपयोगितावाद एक ऐसा सिद्धान्त है जिससे उसके नैतिक-स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है, मैक्सरी (Maxcy) के अनुसार "मिल की उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा में बेन्थम की मान्यताओं का अंश कम रह गया है।" मिल ने अपनी विशाल-इदयता से उपयोगितावाद को नैतिक जीवन के अनुकूल बनाया और कुछ काल के लिए जनता को मुग्ध कर दिया, किन्तु अन्त में इसके कारण उत्पन्न असंगतियों ने उसकी ख्याति को ठेस पहुँचाई। उपयोगितावाद की रक्षा में तर्कशास्त्र का खजाना खाली करने वाले मिल से उपयोगितावाद का पक्ष प्रबल न हो सका। उसने बेन्थम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद के आलोचकों की शान्त कर दिया, परन्तु बदले में बहुसंख्यक आलोचकों को जन्म दिया जो इस पवित्रित और सशोषित उपयोगितावाद के विरुद्ध लड़कों की बौद्ध करके लगे। मिल ने बेन्थम के उपयोगितावाद में नैतिक सिद्धान्तों का सम्मिश्रण कर इसे मानवीय बनाने का सप्राहनीय कार्य अवश्य किया, लेकिन दार्शनिकता की ओर बढ़ने का दुष्परिणाम यह हुआ कि उपयोगितावाद की व्यावहारिकता समाप्त हो गई।

मिल की स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा

(Mill's Concept of Liberty)

मिल के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों का सारांश उसकी पुस्तक 'On Liberty' में है। मिल के मनप राज्य का वर्णन बहुत बड़ा गया था और साकार जनहित के नाम पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को विनियमित करने वाले कानून बनाने लगे थे। सामाजिक व्यवस्थान द्वारा सामान्य जनता को सुख-वृद्धि के प्रयास में ब्रिटिश सरकार जिन प्रकार वैयक्तिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने लगे थे उनमें : उन को यह पता हो गया था कि जनता का बहुमत अथवा लोकप्रिय शासन कहीं भूतकालीन निकुरा शासन के समान आतङ्कपूर्ण और स्वेच्छाचारी न बन जाए; उनका विश्वास था कि राज्य द्वारा अधिक अधिकारियों के निर्माण का अर्थ है—व्यक्ति और उसकी स्वतन्त्रता पर अधिक प्रतिक्रिया द्वारा राज्य के समग्र नागरिक के व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को नष्ट करने का। उसकी मान्यता थी कि राज्य को वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हनन करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता के शासन के नाम पर बहुमत द्वारा अन्याय पर मनचढ़े प्रतिबन्ध लगाया अथवा लोकप्रिय के नाम पर अन्याय कानूनों को लागू देना सर्वदा अवैधानीय है। अपने इन विचारों के कारण मिल ने मानव-स्वतन्त्रता के व्यक्तिगत स्वरूप का प्रतिपादन किया।

मिल के चिन्तन में व्यक्ति का स्थान

मिल व्यक्ति का भुगतारी है। उनका सम्पूर्ण राजनीतिक चिन्तन व्यक्ति के मूल्य पर आधारित है। मिल व्यक्ति को सामाजिक भागी स्वीकार करता है वह यह विश्वास भी व्यक्त करता है कि व्यक्ति समाज के हित में स्वेच्छा से योग नहीं देगा। "व्यक्ति के हितों को व्यक्ति ही समझ सकता है, न कि समाज। अपने सर्वोत्तम हित को व्यक्ति सर्वोत्तम रूप से जानता है और वही उसे सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त कर सकता है।" मिल का विश्वास है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए। मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है इसलिए उसे अपने सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज अथवा राज्य को व्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं लगाना चाहिए।

व्यक्ति की राज्य और समाज के हस्तक्षेप से रक्षा होना आवश्यक है

मिल को धारणा थी कि अपने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विकास करना मनुष्य का धर्म है, किन्तु इस धर्म की प्रगति में राज्य और समाज द्वारा कुछ बाधाएँ पैदा की जाती हैं जिसका निराकरण आवश्यक है। इन बाधाओं के निराकरण की अवस्था ही स्वतन्त्रता है। समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन अनुचित है। समाज यह बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी मान्य धर्मग्रन्थों को छोड़कर नवीन धर्मग्रन्थों की स्थापना करे। यदि कोई ऐसा दुस्साहस करता है तो समाज के पक्ष में उसे पकड़ने के लिए दलबद्ध रहते हैं, पर समाज को ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। समाज को व्यक्ति के अधिकार के उस भाग का नियंत्रण करना उचित है जो दूसरों से सम्बन्धित हो। व्यक्ति अपना अपने शरीर का ठग अपने मस्तिष्क का स्वयं स्वामी है, एक समाज की निकुराशा से व्यक्ति की रक्षा होनी चाहिए।

मिल की स्वतन्त्रता का स्वभाव

मिल ने जिस स्वतन्त्रता का पक्ष-पोषण किया है, वह एक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है। उसका विवरण है कि स्वतन्त्रता के अभाव में किसी प्रकार का आत्म-विकास नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता और आत्म-विकास का यही सम्बन्ध उनके अध्ययन का केन्द्रबिन्दु है और उसका ठीक है कि समाज को प्रसन्नता के लिए स्वतन्त्रता अनिवार्य है। 'आत निवर्दी' में स्वतन्त्रता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मिल ने लिखा है कि "मानव जति किसी धर्म के स्वतन्त्रता में केवल एक आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है और वह है अन्याय। साथ समाज के किसी सदस्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए हो सकता है कि उसे दूसरों की हानि पहुँचाने से रोका जाए। उसका अन्तः भौतिक या नैतिक हित इसका पर्याप्त औचित्य नहीं है। व्यक्ति को किसी काम के निषेध करने या न करके के लिए विवश करना इस आधार पर उचित नहीं माना जा सकता कि ऐसा करना उस व्यक्ति के हित में है या ऐसा करने से उसके हित में वृद्धि होगी या ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण है। समाज मानव आचरण के उसी अंश को नियंत्रित कर सकता है जो दूसरे व्यक्तियों से सम्बन्धित हो। स्वयं अपने कर्मा में उसकी स्वतन्त्रता अधिकारित निषेध है।"

"मिल की दूसरी परिभाषा के अनुसार अपनी इच्छानुसार कार्य करने की हट स्वतन्त्रता है। आत यदि यह समझे है कि अनुक व्यक्ति का अनुक पुत्र की पार करना खतरनाक है इस पर एक लक्षणकर अप उचित करते हैं। स्वतन्त्रता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होती है तथा किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है दूसरे की नहीं हो सकती। स्वतन्त्रता की यह परिभाषा नियंत्रण के लिए दावेदार खुला रखती है। यदि एक बार यह मान लिया जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छा को अपने अन्तः ही रख चला सकता है और स्वतन्त्रता उसी को कहते हैं जो अपनी इच्छा होती है, वह अन्वेषण-परिपक्व

मानुष को नर्क में जाने से बचाने के कार्य और उसे मुक्ति दिलाने के प्रयत्न भी उचित है। मिल के अनुसार व्यक्ति पर स्वतन्त्र होने के लिए दबाव भी हासल जा सकता है। यहाँ वह अतिवादों से बचा जाता है। उसकी ये परिभाषायें भी वैश्व्य की परिभाषायों से भिन्न हैं। "मिल की स्वतन्त्रता का स्वरूप तब इच्छितशाली बन जाता है जब हम देखते हैं कि वह अलग पुरुषों और स्त्रियों की उत्पत्ति चाहता है, क्योंकि उसका विचार है कि सभी आदर्शों और एक समान वस्तुएँ व्यक्तिगत हैं और व्यक्तियों से आती चाहिए।"

मिल के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों के दो प्रकार—मिल के अनुसार स्वतन्त्रता के दो प्रकार हैं—(1) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (Freedom of Thought and Expression) एवं (2) कार्यों की स्वतन्त्रता (Freedom of Action)।

1 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (Freedom of Thought and Expression)—विचारों की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मिल के सर्व प्रभावशाली हैं। मिल के अनुसार समाज और राज्य को व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता हानी चाहिए, फिर चाहे ॥ विचार समाज के अनुकूल हों या प्रतिकूल। मिल के वैयक्तिक स्वतन्त्रता के तर्कसंगत मत निम्न रूप में निम्न प्रकार हैं—

1 विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबन्ध लगाना है और सत्य पर प्रतिबन्ध का अर्थ समाज को उपयोगिता का हानि करना है परिणामस्वरूप समाज का पतन अवश्यम्भावी है।

2 अभिव्यक्ति द्वारा सत्य विचारों को प्रकट होते हैं। दमकारी उपारों द्वारा सत्य को बाधित नष्ट किया जा सकता। उम्मेद निम्नलिखित विचारों का सम्बन्ध है धर्मस्वरूप सामाजिक प्रगति अवश्य अपेक्षित होती है।

3 सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। समाजवाद एक पक्ष सत्य के एक पक्ष को देखता है और दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष को। सत्य के समग्र रूप को समझने के लिए ठीक जितने अधिक दृष्टिकोण से देखने की स्वतन्त्रता दी जाएगी उतना अच्छा होगा। ये विविध दृष्टिकोण एक-दूसरे को पूरक होते हैं जिसके सम्बन्ध में वास्तविकता का पता चलता है और समर्थन प्राप्त होता है।

4 यदि कोई व्यक्ति अधिक सत्य कोसता है तथा मिथ्या मानता है फिर भी राज्य का उसके विचार स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहाँ जब उसके दृष्टि को समझा जाए, तब उसके समर्थन नहीं करेगी। यदि कोई व्यक्ति सत्य को तो नम्र करने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती चाहिए क्योंकि हो सकता है कि सत्य को व्यक्ति किसी नई विचार-प्रणाली का अविच्छेद करने में सफल हो जाए।

5 यदि किसी व्यक्ति का विचार गलत है तो उसके व्यक्त होने देने में समाज की हानि नहीं है। इसमें समाज द्वारा स्वीकृत सत्य का स्वरूप और विचरोण। मान्यों की तुलना करके हम सत्य को परख सकते हैं। मिथ्या और सत्य में विरोधाभास है अतः सत्य को एक सजीव रूप से समाज में प्रस्तुत किया जा सकता है।

6 तर्क-बुद्धि से सत्य की परख होती है, ज्ञान का विकास होता है और मिथ्या एवं अन्य-विश्वासपूर्ण पारम्पर्यों का अन्त होता है।

2 कार्यों की स्वतन्त्रता (Freedom of Action)—वैयक्तिक स्वातन्त्रता का महत्वपूर्ण पक्ष कार्य की स्वतन्त्रता है। मिल का मत है कि "विचारों की स्वतन्त्रता अपूर्ण है यदि इन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतन्त्रता न हो।" दृष्टि संकल्प, दृष्टि—ये मानुष के अधिकार हैं अतः और कार्यों द्वारा मनुष्य अपना आनन्द समाज को देता है। यह अनुदाय उसके व्यक्तित्व का मानवीय तत्व है सामाजिक प्रगति का अनवरत साधन है।

मिल के इन विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव-जीवन के दो पक्ष हैं—व्यक्तिगत और सामाजिक। इसके अनुरूप वह व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है—(1) स्व-सम्बन्धी कार्य (Self regarding Actions) एवं (2) पर-सम्बन्धी कार्य (Other regarding Actions)। व्यक्ति के स्व-सम्बन्धी कार्य वे हैं जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों की परिधि व्यक्ति स्वयं है जैसे—कपड़े पहनना, शिखा प्राप्त करना सिगरेट पीना, पान खाना आदि। व्यक्ति को ऐसे कार्यों का अपनी इच्छानुसार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इनमें राज्य का हस्तक्षेप बाधनीय नहीं है। व्यक्ति के स्व-सम्बन्धी कार्यों की स्वतन्त्रता न देना उसे पशु बनाना है। व्यक्तिगत कार्यों की स्वतन्त्रता का अभाव समाज की प्रगति के लिए खतरा बन जाता है। पर-सम्बन्धी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज अथवा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है क्योंकि यद्यपि व्यक्ति की स्वतन्त्रता आवश्यक है तथापि इसके द्वारा दूसरों की स्वतन्त्रता का बलिदान नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति समाज में अप्रसन्न और अनैतिकता को प्रोत्साहन देता है अथवा ऐसे समूहों का निर्माण करता है जिनसे सामाजिक शान्ति और सुरक्षा भंग होती हो तो राज्य को अधिकार है कि वह उसके कार्यों में हस्तक्षेप करे, लेकिन वहाँ तक नहीं तक यह हस्तक्षेप

व्यक्ति के सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक हो। अपना पूर्ण अधिकार करने वाले व्यक्तिगत कार्य मिन के अनुसार, राज्य द्वारा प्रतिबन्धित हो सकते हैं, जैसे—आत्महत्या का कार्य। मिन ने कार्यों की स्वतन्त्रता को चरित्र-निर्माण और सामाजिक विकास की दृष्टि से न्यायपूर्ण बतलाया है। चरित्र-निर्माण में व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा के बाद किया गया मकल्प कार्य रूप में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों लाभ देता है। बुरी अदालतें अथवा क्रियाओं को रोकने के लिए राज्य को परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए।

मिल की स्वतन्त्रता के मूलभूत तत्व—मिल द्वारा प्रतिपादित की गई स्वतन्त्रता के प्रमुख उत्तर ये हैं—(1) यह नकारात्मक स्वतन्त्रता है, विधेयात्मक नहीं। कानून का अभाव ही स्वतन्त्र माना गया है। (2) मिल द्वारा स्वतन्त्रता की एक अध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। (3) समाज से पृथक् रहकर व्यक्ति स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है। मिन की स्वतन्त्रता की धारणा समाज की व्यक्तिवादी धारणा पर आधारित है। (4) मिन द्वारा स्वतन्त्रता के पक्ष में दिए गए तर्क उपयोगितावाद सिद्धान्तों का अवकिरण करते हैं। जब मिन कहता है कि एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा सम्पूर्ण मानव-जाति के विरुद्ध की जानी चाहिए तो उसका उपयोगितावादी आधार से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। (5) मिन पिछड़े हुए राष्ट्र के लोगों को स्वतन्त्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। (6) राष्ट्रीय प्राप्ति और सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वतन्त्रता का अपहरण किया जा सकता है।

मिल की राज्य सम्बन्धी धारणा

(Mill's Concept of the State)

मिल की मान्यता है कि राज्य स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम है। राज्य के यांत्रिक सिद्धान्त (Mechanistic Principles) यदि मानव इच्छा अथवा मानव व्यक्तित्व की अपेक्षा करते हैं, तो वे अमूर्त हैं। मिन ने राज्य और उसकी समस्याओं को स्वाभाविक मानने वालों तथा उन्हें अविवेक और मानव प्रयासों का फल समझने वालों के बीच का मार्ग प्रणय किया है। उसका विश्वास है कि राज्य का विकास दुआ है। यह विकास जड़ वस्तुओं की तरह न होकर, चेतन वस्तुओं के समान हुआ है, राज्य को उत्पत्ति मानव-दिन के लिए हुई है, क्योंकि जितने राजनीतिक संगठन हैं उन सबका अस्तित्व सार्वजनिक कल्याण के लिए है। सभी समाज अपने अस्तित्व की प्रत्येक अवस्था में अपना स्वरूप व्यक्ति के स्वीच्छिक प्रयत्नों द्वारा ग्रहण करते हैं, अतः अन्य वस्तुओं की भाँति इन व्यक्तियों द्वारा अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है। यह मनुष्य की दक्षता और बुद्धि पर निर्भर करता है। राजनीतिक यंत्र स्वयं कार्य नहीं करता। सामान्य व्यक्तियों द्वारा उसका निर्माण होता है और उन्हीं के द्वारा उसका संचालन होता है। यह उनके सुपचाप रहने से नहीं, बल्कि सक्रिय योगदान से क्रियाशील होता है, अतः राज्य को उन व्यक्तियों के गुणों और शक्तियों के अनुकूल ढाला जाना चाहिए जो इसके संचालन के लिए उपयुक्त हों।

राज्य के संचालक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए मिन ने व्यक्तियों के कर्तव्यों में राज्य के हस्तक्षेप को पूर्णतः निषिद्ध न ठहरा कर, वैयक्तिक विकास की कुछ स्थितियों में उसका हस्तक्षेप अनिवार्य माना है। उसकी मान्यता है कि व्यक्ति के सुख के लिए समाज का सुख आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवन-संपर्ष में सभी व्यक्ति समाज में समाप्त नहीं हैं। यदि राज्य सभी व्यक्तियों के जीवन को सुखी बनाता चारता है और प्रत्येक को आत्म-विकास की सुविधाएँ देना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वह समाज में व्याप्त विषमताओं और भिन्नताओं को पूरा करे। मिन चाहता है कि भूमि, उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं रहना चाहिए। सम्पन्नता न होते हुए भी मिन के हृदय में सम्भवतः समाजवाद के प्रति प्रबल सहानुभूति विद्यमान है, क्योंकि उसे उस समाजवाद से कोई सहानुभूति नहीं है जो भूमि के राष्ट्रीयकरण का समर्थक हो। वह सम्पत्ति का उठना प्रबल पक्षधर नहीं है जितना बेन्दन है।

मिल के अनुसार राज्य को सहायक इन कार्यों से अपना सम्बन्ध रखना चाहिए—(1) राज्य बाह्य अक्रमण अथवा आन्तरिक अशांति से देश की रक्षा के लिए सेना की व्यवस्था करे। (2) सार्वजनिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबन्ध करे। (3) अत्यन्त उपयोगी एवं कम से कम कानून बनाने के लिए विधान-मण्डल का निर्माण करे। (4) कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों को दण्डित करने के लिए न्यायालयों की स्थापना करे। (5) व्यक्ति को उम्मेद महत्व बतलाए और इसके लिए प्रचार करे। (6) चेतना को देने का काम करे और इस तरह सम्भावित दुर्घटनाओं को ओर सकेत करे।

मिल की शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली सम्बन्धी धारणा

(Mill's Concept of Best Form of Government)

मिल के अनुसार शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली वह नहीं है जो अधिकतम कुशल हो, अपितु वह है जो नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो और सर्वसाधारण को नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराती हो। श्रेष्ठ शासन की प्रधान विशेषता यह है कि वह जनता के गुणों और बुद्धि का विकास करने वाला हो।

शासन सार्वजनिक कार्य के लिए संगठित व्यवस्था का नाम ही नहीं है, बल्कि इसका मानव-मस्तिष्क पर उनपर और गहरा प्रभाव होना चाहिए। शासन का मूल्य उसके द्वारा और अधिक जगजग चाहिए। शासन की सार्वजनिकता मनुष्यों एवं अन्य मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव से मापी जानी चाहिए। शासन की उत्पत्ति की प्रथम कसौटी यह जानना है कि वह नागरिकों में गार्सिक एवं नैतिक गुणों का कहीं तक संचार करती है? उनके चरित्रिक एवं नैतिक विकास के लिए कितना प्रयास करती है? इनसे सर्वश्रेष्ठ रूप से विचारित करने वाली शासन प्रणाली ही 'शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली' मानी जाएगी। उक्त शासन की एक कसौटी है कि उससे द्वारा शासितों में किस माध्यम तक वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से गुणों की वृद्धि होती है। केवल प्रशासन के क्षेत्र में शासन की सफलता उमड़ी उतरती का बिंदु नहीं है।

मिल की प्रतिनिध्यात्मक शासन सम्बन्धी धारणा

(Mill's Concept of Representative Government)

मिल के साथ प्रजातन्त्रवाद प्रगति पर था किन्तु शासन की सम्पूर्ण बुनियादी तथा मसद् का उच्चवर्गीय अधिनायकत्व चिन्ता के विषय थे। व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रत्यक्ष समर्थन करने के बाद मिल ने अपना ध्यान ऐसे शासन का ओर केन्द्रित किया जिसमें व्यक्ति का अपना प्रतिनिधित्व सम्भव हो और प्रजातन्त्रिक नियमों के अनुसार प्रत्येक वांछित प्राप्त व्यक्ति इसका अवसर प्राप्त कर सके। मिल ने कहा कि सच्चा प्रजातन्त्र यह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन-कार्य में भाग लें। सरोतम आदर्श शासन यह है जिसमें सर्वोच्च नियन्त्रण शक्ति या सम्प्रभुता पूरे समाज की योग्यतायुक्त इकाई में निहित हो और प्रत्येक व्यक्ति इस सम्प्रभुता के निर्माण में केवल योग्य हो न दे बल्कि सम्मिलित होने पर सर्वजनिक पद ग्रहण कर तथा शासन में भाग लेकर अपना कर्तव्य पूरा करे, पर चूँकि यह प्रयोग सम्भव नहीं है और आज के विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र नहीं चल सकता, अतः मिल की दृष्टि में सर्वोत्तम शासन अल्पसंख्यक प्रजातन्त्र अथवा प्रतिनिधि शासन (Representative Government) होना चाहिए। यद्यपि प्रजातन्त्र का यह रूप योग्ययुक्त नहीं है पर मिल का विश्वास है कि शासन का स्वभाव मनुष्य द्वारा निर्धारित होता है अतः 'मनुष्य द्वारा निर्धारित अन्य चीजों की भाँति इसके अच्छा भी बनाया जा सकता है और बुरा भी।'

प्रतिनिधि शासन का सिद्धान्त—मिल के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक सरकार यह है जो तीन शर्तों को पूरा करे—1. वे लोग जिनके लिए ऐसी सरकार का निर्माण किया जाए, ऐसी सरकार को स्वीकार करने के इच्छुक हों या इतने अनिच्छुक न हों कि इसकी स्थापना में बाधा पैदा करें। 2. ऐसी सरकार के स्थायित्व के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो वह सब करने के लिए वे इच्छुक और योग्य हों। 3. ऐसी सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों से जो कुछ सरकार चाहे वह करे के लिए वे तत्पर और योग्य हों। शासन की जो आवश्यक शर्तें हों वे उन्हें पूरा करने के लिए वैध हों।

प्रतिनिध्यात्मक सरकार में उपर्युक्त तीन के अतिरिक्त निम्न तत्व हैं—

- (1) सम्पूर्ण या उनकी संख्या के बड़े भाग के लोगों का सरकार के कार्यों में सहयोग। (2) सम्पूर्ण या उनकी संख्या के बहुत बड़े भाग के लोगों के द्वारा ये नियन्त्रण शक्ति। (3) समय-समय पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा लोगों का प्रतिनिधित्व। (4) अन्तिम नियन्त्रण शक्ति का सविधान में स्थापन और सविधान लिखित न हो तो व्यावहारिक रूप से जनता द्वारा उसका प्रयोग। (5) राज्य की सन्निय राजनीति में नैतिकता या स्वयं परम्पराएँ। (6) वे सभी तत्व जो एक अच्छी सरकार के लिए आवश्यक होते हैं जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। (7) सरकार के अंगों में कार्यों का विविध बँटवारा। (8) एक संगठित विरोधी दल। (9) अनुपातिक प्रतिनिधित्व। (10) सार्वजनिक मताधिकार। (11) निष्पक्ष न्यायपालिका। (12) अल्पसंख्यकों की रक्षा।

मिल मसद् में संगठित विरोध के पक्ष में है क्योंकि ऐसा न होने पर सरकार सही रूप में प्रतिनिधित्व न कर केवल निरकुश बहुमत पर आश्रित हो जाएगी। प्रशासकीय अंग अथवा कार्यपालिका की निरकुशता पर अकुरा रखने के लिए वह एक सजग एवं सतर्क व्यवस्थापिका चाहता है जो कार्यपालिका के कार्यों की सुलभ आलोचना करे और जल्द पड़ने पर परिवर्तन प्रस्ताव पास कर उसे भंग करने में सक्षम हो। मिल ने लिखा है—'प्रतिनिधि सभा (पार्लियामेण्ट) वह है जिसमें राष्ट्र के सामान्य मत का ही प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक अंग के मत का प्रतिनिधित्व हो, सम्भवतः राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग और योग्य व्यक्तियों के विचारों का प्रतिनिधित्व हो, जहाँ विचारों पर स्वच्छन्द चार विवाद और उनका मध्यम ही देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के सही प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त वक्ता प्राप्त कर सके, लोगों के विरोधों को अनिच्छा के कारण न तुकरा कर, विवेक और तर्क तथा सत्यता के द्वारा चुनौती दी जाए, वहाँ राष्ट्र का प्रत्येक दल या जनमत अपनी-अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सके और सही या गलत विचारों को पकड़ करने का अवसर प्राप्त कर सके, वहाँ राष्ट्र के मान्य विचारों की प्रत्यक्ष रूप में सरकार के सम्मुख अधिव्यक्ति हो सके, जहाँ सरकार को उसकी गलतियों के लिए सुझाया जा सके और सरकार बिना शक्ति प्रयोग किए अपदस्थ होना स्वीकार करे तथा जिसमें सभी प्रतिनिधि सही रूप में ईमानदारी के साथ चुने गये हों।'

संसद में प्रतिनिधियों की स्थिति के बारे में मिल के विचार बर्क से मिलते-जुलते हैं। वह प्रतिनिधियों को जनता का प्रत्यायुक्त (Delegate) मात्र नहीं मानता, बल्कि उसकी राय में वह एक उप-प्रदर्शक और शिक्षाप्रद व्यक्ति होना चाहिए। यदि उसे अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करने के लिए छोटी-मोटी समस्याओं पर संप्रतीति करने पड़े तो उसे निर्भोक्त रूप से अपनी सम्पत्ति प्रकट करने चाहिए। प्रतिनिधि-शासन प्रणाली का प्रमुख दोष जटिल प्रतिशरणा करना है जो वह अपनी दृष्टि से दूर करना चाहता है। मिल की मान्यता है कि चरित्रवान व्यक्ति राज्य की जीवन शक्ति होते हैं और जिस शासन में व्यक्तियों के विकास के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हैं वह शासन-व्यवस्था उपयुक्त नहीं हो सकती, फिर चाहे प्रशासनिक दृष्टि से वह कितनी सरल और कुशल क्यों न हो। निरक्षर शक्ति सम्पन्न और सन्तान पूर्ण होने पर इसीलिए आदर्श नहीं माना जा सकता है कि उसमें नागरिकों के चारित्रिक विकास की अपेक्षा की जाती है। प्रतिनिधि शासन वाला लोकतन्त्र श्रेष्ठ इसलिए है कि अन्य किसी शासन-व्यवस्था की अपेक्षा उसमें व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास की प्रचल सम्भावना होती है।

क्रियात्मक सरकार के कार्य—मिल के अनुसार, “निर्वाचित प्रतिनिधि-परिषद का कार्य शासन का नियन्त्रण और निरीक्षण मात्र है। इस परिषद को सक्रिय रूप में कानून-निर्माण अथवा शासन कार्य नहीं करने चाहिए।” मिल ने प्रतिनिध्यात्मक सरकार के जिन मुख्य कर्तव्यों का उल्लेख किया है, वे इन प्रकार हैं—1. प्रतिनिधि-शासन व्यक्तियों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे जिसमें सत्य की खोज करके तदनुकूल अपने विचारों का निर्माण कर सके। 2. शासन ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिससे व्यक्तियों का धार्मिक सुधार हो सके। 3. इस सम्बन्ध में राज्य द्वारा कानूनों का निर्माण कम से कम किया जाए, क्योंकि कानून से प्रतिबन्ध लगते हैं। शासन को अधिक कानून बनाकर नागरिकों के वैयक्तिक जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जीवन के अधिकतर परलू सरकार के विनियमों के बिना रहने चाहिए। कानून-निर्माण का कार्य विधायिका सभा को दिया जाना चाहिए। 4. प्रतिनिधि सभा को इन महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करना चाहिए—सरकार पर दृष्टि रखना, उन पर पूर्ण नियन्त्रण रखना, सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालना, उसके आस्तित्वजनक कार्यों को रोकना एवं उनका औचित्य सिद्ध करना, विश्वासतावां शासकों को पदभ्रमन कर उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करना, सरकार के इन कार्यों की निन्दा करना आदि। संसद में जनता की या बर्ग की शिकायत पर विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद होना उपयोगी है। 5. मिल के अनुसार, “प्रतिनिधि-निकायों के कार्य को इन विवेकसम्पन्न सीमाओं के अन्तर्गत रखकर लोकप्रिय नियन्त्रण का स्थापन ठोका जा सकता है और महत्वपूर्ण कुशल व्यवस्थापन तथा प्रशासन प्राप्त हो सकता है। इन क्षेत्रों को मिलाने का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि नियन्त्रण एवं आलोचना यन्त्र को वास्तविक प्रशासन यन्त्र से अलग रखा जाए। इसमें पहले की जनता के प्रतिनिधियों की सौंप दिया जाए तथा दूसरे की विरोध ज्ञान एवं कुशलता-प्राप्त थोड़े से व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखा जाए जो राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हों।”

निर्वाचन के सम्बन्ध में मिल के विचार

प्रतिनिधि शासन का निर्माण निर्वाचनों द्वारा होता है। अतः मिल ने प्रतिनिधि-शासन पर विचार व्यक्त करते समय निर्वाचनों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने कहा कि निर्वाचित-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसने सरकार के सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और समतावान व्यक्ति ही पहुँच सके। योग्य व्यक्ति ही शासन का संचालन कर सकते हैं। मिल ने निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जिनमें शासकों का चुनाव अज्ञानी एवं विवेकहीन जनता के हाथों में न पड़े सके और जिनसे सामूहिक सामान्य बुद्धि और शासक के दोष कम हो जाएं। मिल ने इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) और बहुल मतदान (Plural Voting) का सुझाव दिया। मिल की आशा थी कि “अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एक ठोकाद्वार के लिए आवश्यक गुणों को समुचित महत्व मिल सकेगा और विवेकहीन जनता के बहुमत के दोष दूर हो सकेंगे।” अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए मिल ने सुझाव दिया कि कुल मतदाताओं की संख्या में संसद की प्रतिनिधि संख्या का भाग देकर मतों की औसत संख्या निकाल लेनी चाहिए और मतों की एक ऐसी संख्या निर्धारित कर देनी चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद कोई प्रत्याशी संसद की सदस्यता प्राप्त कर सके। मिल के निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विचार निम्नानुसार हैं—

1. मताधिकार एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है सभी को नहीं दिया जाना चाहिए। प्रजातन्त्र को बड़ा धरातल अनिवार्य और मूर्ख व्यक्तियों से है, अतः आवश्यक है कि मताधिकार उन्हीं लोगों को प्राप्त हो जो एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखते हों। केवल वयस्क हो जाने से कोई मत देने का अधिकार नहीं हो सकता।

2. मताधिकार प्रदान करने में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मिल महिमा मताधिकार (Right of Vote to Women) की वकालत करने वाले प्रथम कोटि के विचारकों में है। उसे यह बहुत अन्यायपूर्ण प्रतीत होता था कि महिलाओं को मतदान अधिकार से वंचित रखा जाए। उन दिनों ग्रेट-ब्रिटेन में नारी का स्थान पर की चारदीवारी तक सीमित था। मिल नारी की स्थिति में वही स्थान प्रदान करना चाहता था जो पुरुषों को प्राप्त था। उसने

कहा कि "महिलाओं की अपेक्षा किसी भीतर उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का लक्षण नहीं है, बल्कि यह उनकी भावों की दृष्टि का परिणाम है। यदि नारी और पुरुष में कोई अंतर है तो भी पुरुष की अपेक्षा नारी को मतदान का अधिकार की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि से पुरुष को तुलना में निर्बल होने के कारण उसे अपने राष्ट्र के लिए काम करना और समानता पर निर्भर रहना पड़ता है।"

3. निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं बहुत मतदान के आधार पर होना चाहिए। बहुत मतदान (Plural Voting) को विरोधित मिल ने प्रस्तावित व्यक्तियों को अतिरिक्त व्यक्तियों की तुलना में बग़र अधिकार दिताने हेतु को।

4. विधान को मूर्त से अधिक घोट देने का अधिकार मिला चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक तथा अधिक से अधिक पाँच मत देने का अधिकार दिया है। मिल ने समानता को क्यों भी विधेयता पर यह निश्चित कर दिया कि जिस सभा को कितने मत देने का अधिकार मिलना चाहिए।

5. मिल ने गुण मतदान का विरोध नहीं करके सुले मतदान को उचित ठहराया। मत देने का अधिकार एक व्यक्ति अतिरिक्त है जिसका प्रयोग बुद्धिमत्ता एवं समझदारी से किया जाना चाहिए। अतः इसमें गोपनीयता रखना 'किसी गुण-गुण दिए जाने वाले अनुचित कार्य' के समान है।

6. मिल ने सुझाव दिया कि ऐसे स्वतन्त्र व्यक्ति जो बौद्धिक दृष्टि से योग्य हों, अच्छे लेखक या सामाजिक कार्यकर्ता हों, जिनसे अपने कार्य के कारण हर जिले में प्रतिनिधि प्राप्त कर ली जाये तथा किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों, तो उन्हें योग्यता के आधार पर चुन लेना चाहिए।

7. समझ को मान्यता प्रकृति पर अकुल रहने की दृष्टि से द्वि-राष्ट्रीय सभा उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त समावाधान के कारण निम्न सदन पर कार्यभार बढ़ जाता है यह उच्च सदन द्वारा हल्का किया जा सकता है। मिल द्वितीय सदन में कुछ सुधार चाहता था।

8. ठाकुर विचार का कि मतदाताओं के लिए शिक्षा की योग्यता के साथ सरकारी सम्पत्ति की योग्यता (Property Qualification) निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि सम्पत्तिवान मतदाता सम्पत्तिहीन मतदाताओं से अधिक उदारमनस्कृति से अपने मत का प्रयोग करेंगे।

मिल का योगदान और स्थान

(Mill's Contribution and Place)

यह सत्य नहीं है कि मिल ने किसी नए सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया। उसके सिद्धान्त में सगति नहीं है और उसके विचार में अनेक परस्पर विरोधी तथ्यों का मिश्रण है, परन्तु केवल इन्हीं आधारों पर हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। यह देखना अधिक शिष्ट होगा कि वहाने जो कुछ लिखा है उसमें सत्य कितना है? उसकी विवेचनात्मक दृष्टि क्या है और अपने युग की दृष्टि से किस प्रकार प्रभावित किया है और यदि लेखकों की योग्यता का निर्णय इस तथ्य से होता है कि नीति पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है तो मिल का स्थान निश्चित रूप से ऊँचा है। एक न्यायशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक के रूप में वह एक अवतार समझा जाता था।

मिल ने एक मोड़ी से अधिक समय तक राजनीतिक विचारों के क्षेत्र को प्रभावित रखा और उसके प्रयोगों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त हुआ। मिल ने उपयोगितावाद के तर्कपरत को विकसित किया और आगमनात्मक पद्धति (Inductive Method) की प्रविष्टि दूर की। बेन्थम के उपरान्त उपयोगितावाद के बहुत से आलोचक उत्पन्न हुए और इस विचारधारा के सम्बन्ध में प्रश्न पैदा हुए। मिल ने उन सब आलोचकों को निरस्त किया तथा उनके द्वारा प्रस्तावित गये प्रश्नों का अन्त किया। आज उपयोगितावादी अर्थशास्त्र अलग विषय बन गया है। मिल ने उपयोगितावाद की एक बड़ी प्रविष्टि को दूर किया। बेन्थम ने सुख को गुणात्मक नहीं केवल मात्रात्मक बतलाया था। मिल ने कहा कि सुखों में गुणात्मक अन्तर होता है। उपयोगितावादी विचारधारा को मिल की यह एक जबरदस्त देन थी। मिल इस बात के लिए प्रशंसा का पात्र है कि उसने समानता की उपयोगितावादी कल्पना प्रस्तुत की। प्रजातन्त्र सम्बन्धी मिल के आलोचनात्मक विचारों का महत्व आज ज्यों का त्यों बना हुआ है। आधुनिक प्रजातन्त्र देशों में ये दोष पाए जाते हैं, जिनकी ओर मिल ने संकेत किया था। मिल के इस कथन को चुनौती देना कठिन है कि "सुदृढ़ आधार के बिना प्रजातन्त्र का भवन अधिक दिन खड़ा नहीं रह सकता तथा सार्वजनिक शिक्षा के बिना सबके लिए माताधिकार निरर्थक है।" प्रजातन्त्र की सम्भलता के लिए दिए गए उसके सुझाव प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनका व्यावहारिक पक्ष सफल है। प्रजातन्त्र की प्रयोगात्मक शिक्षा में मिल ने बहुमूल्य योगदान किया है। नारी स्वतन्त्रता सम्बन्धी उसके विचारों की सत्यता का प्रमाण यह है कि लगभग सभी देशों ने उसके विचारों पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है। राजनीतिक विचारों को मिल की सर्वोच्च देन उठाया व्यक्तिवाद है जिसे उदारवाद कहा अधिक उपयुक्त होगा।

"हीनस का विश्वास था कि स्वतंत्रता को एक सामाजिक व्यवहार समझना चाहिए। वह इस सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता है जो समुदाय के नैतिक विकास के अणु पर उत्पन्न होती है। वह एक विरासत प्रतिभा की वस्तु नहीं है।" वह एक प्रकार की स्थिति है जो व्यक्ति को समुदाय की नैतिक और वैधानिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होती है, अतः उसे स्वच्छा अथवा व्यक्तिगत प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता व्यक्तिगत क्षमता को महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों के निष्पादन में लगा देने में है।¹

फार्ल मार्क्स

(Karl Marx, 1818-1889)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

वैज्ञानिक समाजवाद के उन्मादक फार्ल मार्क्स ने समाजवाद को स्वयं लोक से निकालकर एक जनक्रान्ति के रूप में इस प्रकार बदल दिया है कि आज का युग समाजवाद का युग कहलाने लगा है। फार्ल मार्क्स का जन्म एक मुश्री मध्यम वर्गीय परिवार में परिचयी एरिशा के ट्रीबिन नगर में 5 मई, 1818 को हुआ था। उसका पिता एक साधारण वकील तथा माता एक यहूदी महिला थी। मार्क्स बचपन में प्रतिभाशाली था। 1836 में मार्क्स ने न्यायशास्त्र के अध्ययन के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1841 में उसने जेन विश्वविद्यालय से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। 1849 में मार्क्स जर्मन में बस गया और अपने जीवन के शेष 34 वर्ष वहीं बिताए। 1883 में फार्ल का निधन हो गया।

मार्क्स के ग्रन्थ (Works of Marx) — फार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण रचनाएँ ये हैं—

(1) दी फिलॉसफी ऑफ पावर्टी (1847) (The Philosophy of Poverty, 1843)

(2) दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो (1848) (The Communist Manifesto, 1848)

(3) दास कैपीटल, (1867) (Das Capital, 1867)

(4) क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस (Class Struggle in France)

1. मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद सम्बन्धी विचार

मार्क्सवादी समाजवाद को सर्वोच्च समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से सम्बोधित किया जाता है। मार्क्स अपने समाजवाद को वैज्ञानिक मानता है, क्योंकि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स का दर्शन पिछट तथा सुगम्य है। केटलिन के अनुसार, इसका क्रान्तिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर स्थित है, वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धान्त पर, आर्थिक सिद्धान्त इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आर्थिक व्याख्या मार्क्स हीगेल के द्वन्द्ववाद पर और द्वन्द्ववाद भौतिकवादी आध्यात्मिक विद्या पर स्थित है। स्पष्टतः मार्क्स की विचारधारा के चार आधार स्तम्भ हैं—(1) द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism), (2) इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (Materialistic Interpretation of History), (3) वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त (Theory of Class Struggle) एवं (4) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value)।

(1) द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद

फार्ल मार्क्स का सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शन द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त पर आधारित है। द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन की वह आधारशिला है जिसका आश्रय समस्त साम्यवादी लेते हैं। शार्ट हिस्ट्री ऑफ़ दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ दी सोवियट यूनियन में अधिकृत रूप से कहा गया है कि "द्वन्द्ववाद की सहायता से हम प्रत्येक स्थिति के प्रति सही दृष्टिकोण बना सकते हैं। सामंथ्य घटनाओं के आन्तरिक सम्बन्धों की समझ सकते हैं, उनकी दिशा को जान सकते हैं कि वे वर्तमान में किस प्रकार और किस दिशा में चल रही हैं, वह यह भी देख सकते हैं कि भविष्य में उनकी दिशा क्या होगी?"² मार्क्स के अनुसार भौतिक पदार्थ इस जगत् का आधार है। भौतिक जगत् की वस्तुएँ वयः घटनाएँ परस्पर अवलम्बित हैं। भौतिक जगत् में परिवर्तन होता रहता है। कुछ प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं, कुछ नष्ट होती हैं तो कुछ की पुनरावृत्ति होती है। यह विकास क्रम निरन्तर चलता रहता है। मार्क्स कहता है कि विकास की पृष्ठभूमि में समस्त शारीरिक पदार्थों में एक आर्थिक विरोध रहता है जिससे भौतिक जगत् का विकास होता है। इसके तीन अंग होते हैं—(1) वाद (2) प्रतिवाद एवं (3) संवाद अथवा संश्लेषण।

1. सेगल . राजनीतिक दर्शन का इतिहास, खण्ड 2, पृ. 616.

2. Quoted in Cerev Theory and Practice of Communism, p 28.

मार्क्स का भौतिक दृष्टांत का सिद्धान्त विकासवाद का सिद्धान्त है। उदाहरणार्थ यदि गेहूँ के दाने (पदार्थ) के द्रव्य का अध्ययन करें तो विदित होगा कि उसका विकास हो रहा है। उसे जमीन में गड़ा देने से उसका वह रूप नष्ट हो जाता है वह अकुर के रूप में धकेट होता है। अकुर अपनी स्थिति पर स्थिर नहीं रहता, उसका विचार एक लहलहाते पौधे के रूप में होता है। इस सपर्य पूर्ण स्थिति का परिणाम यह होता है कि गेहूँ के एक दाने के विकास के द्वारा अनेक दाने उग आते हैं। विकास का यहो दृष्टांतक सिद्धान्त भौतिकवादी है। यदि गेहूँ का बीज 'वाद' है तो पौधा उसका प्रतिवाद है और पौधे का नष्ट होकर नए दानों का जन्म 'सवाद' अथवा 'संश्लेषण' है। वही सपर्य विकास के सोपान के रूप में प्रगट चलता रहता है। यह सपर्य बाढ़ न होकर आंतरिक होता है।

(2) इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या

मार्क्स के अनुसार "वैध सम्बन्धों और राज्य के रूपों को न तो स्वतः उनके द्वारा समझा जा सकता है न ही मानव मस्तिष्क की सामान्य प्रगति द्वारा उनके व्याख्या की जा सकती है बल्कि वह जीवन की भौतिक अवस्थाओं के मूल में स्थित होती है।" भौतिक जीवन में उत्पादन की विधि जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विधियों के सामान्य स्वरूप का निरूपण करती है। मनुष्यों को चेतना उनके अस्तित्व का निरूपण नहीं करती, प्रत्युत उनका सामयिक अस्तित्व उनकी चेतना का निरूपण करता है। प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्थाएँ उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसके व्यापार, उद्योग और कला दर्शन और रीतियों, आचार्य परम्पराओं, नियम, धर्म और नैतिकता मार्क्स के अनुसार जीवन की भौतिक अवस्थाओं के द्वारा प्रभावित रूप ग्रहण करती हैं। जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उसका आराम कातावरण, उत्पादन वितरण और वितरण से है और इसमें उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस सिद्धान्त के अनुसार, सामाजिक और राजनीतिक जटिलता जीवन की भौतिक अवस्थाओं के कारण अर्थात् उत्पादन तथा वितरण के तरीकों में परिवर्तन के कारण होती हैं सत्य तथा न्याय के अमूर्त विचारों का भगवान की इच्छा के कारण नहीं। उनके कारण उनके युग की आर्थिक व्यवस्था में पाये जा सकते हैं उनके दर्शन में नहीं। वस्तुतः आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक चरण के अनुक्रमण में एक समुचित राजनीतिक स्वरूप और समुचित वर्ग का आकार है, इसलिए मार्क्स का दर्शन वह ऐतिहासिक सिद्धान्त है जो विकास के स्वाभाविक रूप को उपस्थित करता है। मार्क्स कहता है कि उत्पादन एवं उत्पादन शक्ति के विकास से दृष्टवादी भावना का जन्म होता है और दृष्टवादी भौतिकवाद के सिद्धान्त के अनुसार इतिहास की प्रत्येक अवस्था वर्ग सपर्य का इतिहास है। इतिहास की प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिवर्तन आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। मार्क्स उत्पादात्मक सम्बन्धों अथवा आर्थिक दशाओं के आधार पर इतिहास को पाँच युगों में विभाजित करता है—(1) आदिम साम्यवाद का युग (2) दास युग (3) सामंतवादी युग (4) पूँजीवादी युग एवं (5) समाजवादी युग।

मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवाद में मनुष्य कदमूल या फल खाकर अथवा शिकार के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उत्पादन तथा उपभोग करता था अतः समाज वर्ग सपर्य से रहित था। दास युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान हुए। भूमि के स्वामित्व की समस्या से सामंतीवर्ग का जन्म हुआ। इस तरह अब समाज में दो वर्ग हो गए। एक स्वामी वर्ग और दूसरा दास वर्ग। सपर्य के फलस्वरूप नवीन सामंतवादी युग का जन्म हुआ। इसमें राजाओं के हाथ में शासन आ गया। उन्होंने अधीनस्थों को भूमि प्रदान की और वे बदले में सामान्त राजा को आर्थिक और सैनिक सहायता देने लगे। छोटे किसान सामंतों से भूमि लेकर कृषि करते थे एवं बदले में अनाज लगान के रूप में देते थे। उत्पादन के साधनों पर सामंत राजा और सामंतों का अधिकार होने तथा किसानों की दशा खराब होने के कारण इस युग में सामंत और कुलक दो वर्ग बन गए। सामंतवादी युग में सपर्य डोना स्वाभाविक था। इसके बाद पूँजीवाद का विकास हुआ। यह औद्योगिक युग था। हाथ का काम इस युग में मशीन से होने लगा। इससे कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। इस युग में उत्पादन के साधन पूँजीपतियों के हाथों में चल गए। पूँजीपतियों के अत्यधिक शोषण से समाज में दो वर्ग पूँजीपति और श्रमिकों के बन गए। इनमें आपस में सपर्य होना स्वाभाविक होने से मार्क्स के अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों पर श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा तथा उत्पादन के समस्त साधनों का सामाजिककरण कर दिया जाएगा। पूँजीपतियों के विनाश के बाद श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व समाप्त हो जाएगा और राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के इस काल विभाजन के मूल में मार्क्स की यह धारणा निहित है कि जब तक पूर्ण उत्पादन की स्थिति नहीं आती, सभी समाज बदले रहेंगे। यह मानव इतिहास की पूँजी वर्ग सपर्य को मानता है।

(3) वर्ग सपर्य का सिद्धान्त

मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग-सपर्य का सिद्धान्त ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपसिद्धि है और वह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त के अनुकूल है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संगठन का आधार उत्पादन प्रक्रिया में व्यक्ति का स्थान है। वर्ग संगठन के अपने सिद्धान्त में 'मार्क्स' मुख्य रूप से दो वर्गों की धारणा करता है जो आधुनिक समाज में

एक मात्र उपाय मार्क्स के अनुसार क्रान्ति है और इस क्रान्ति द्वारा साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में राज्य में वर्ग संपर्क का अन्त हो जाएगा और सभी को समाज में स्वतन्त्र विकास के लिए रास्ता होगा—“प्रत्येक व्यक्ति का स्वतन्त्र विकास।”

स्तादिमीर इलियच लेनिन

(V. I. Lenin, 1870-1924)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

स्तादिमीर इलियच लेनिन रूप की बोल्शेविक क्रान्ति के कर्णधार थे। उन्होंने अपनी अनेक वृत्तियों के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धान्त और व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। लेनिन का जन्म 1870 एवं उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। लेनिन ने मार्क्स और एन्गल्स के विचारों को प्रामाणिक मार्ग दर्शक के रूप में स्वीकार किया तथा उसने समाजवादी क्रान्ति के विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए और समाजवादी व्यवस्था को व्यावहारिक रूप में चलाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धान्त की नई व्याख्या प्रस्तुत की।

साम्यवादी दल की भूमिका

लेनिन ने एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ के नाते यह अनुभव किया कि सम्पूर्ण सर्वहारा वर्ग को संघटित तथा सावधान और संगठित होने में काफी अधिक समय लगेगा और इसमें बहुत-सी कठिनाइयाँ आएँगी। पूँजीपति लोग कभी श्रमिक नेताओं को भिन्न-भिन्न प्रलोभन देकर और श्रमिक वर्ग को छोटी-छोटी सुविधाएँ एवं रियायतें देकर क्रान्ति के मार्ग से विमुख करने का प्रयत्न करेंगे। लेनिन ने साम्यवादी दल के लिए ‘क्रान्ति की अग्र पंक्ति’ (Vanguard of Revolution) की भूमिका निर्धारित की। लेनिन के अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था में समाज धनी और निर्धन दो वर्गों में बँट जाता है तथा सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा पर आधारित होते हैं। इसी कारण प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल बनते हैं और ये प्रतिस्पर्धी दल वर्गीय आधार के अनुसार भिन्न-भिन्न नीतियों को प्रोत्साहन देते हैं। इनमें साम्यवादी दल सर्वहारा वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीवादी दल सत्ता में होते हैं, इसलिए यहाँ साम्यवादी दल प्रमुख विपक्ष का दायित्व निभाता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य जन साधारण में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। वहाँ यह दल क्रान्तिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाकर पूँजीवादी व्यवस्था को गिराने का काम करता है। क्रान्ति के पश्चात् जब साम्यवादी दल सत्ता में आ जाता है तब उसकी भूमिका में परिवर्तन हो जाता है। क्रान्ति के पश्चात् यह दल समाजवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए ‘सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व’ (Dictatorship of the Proletariat) स्थापित करता है। इस व्यवस्था में किसी प्रतिस्पर्धा करने वाले दल के अस्तित्व को सहन नहीं किया जाता। इस स्थिति में पुराना पूँजीपति वर्ग पराजित अवस्था में होता है फिर भी उससे यह खतरा सदैव बना रहता है कि वह वर्ग प्रति क्रान्ति (Counter Revolution) करके पुनः सत्ता में आने का प्रयत्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में साम्यवादी दल का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह पुराने पूँजीपति वर्ग तथा प्रति क्रान्तिकारी शक्तियों का दमन करके वर्ग भेद मिटाने का प्रयत्न करे। सत्ता में आने पर साम्यवादी दल उत्पादन के साधन प्रमुख संसाधनों को सामाजिक स्वामित्व में लाकर समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। यह दल उत्पादन की शक्तियों के पूर्णतम विकास के उद्देश्य से तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान देता है तथा समाज के सभी स्वस्थ काम करने योग्य व्यक्तियों को श्रम करना अनिवार्य बना देता है। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘स्टेट एण्ड रिवोल्यूशन’ (State and Revolution) में लिखा है “समाजवादी दौर में व्यक्तियों के अधिकार इस रूप में निर्धारित किए जाते हैं—सबसे अपनी क्षमता के अनुसार, सबको अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार (From each according to his capacity, to each according to his need)।” इसमें सभी लोग कामगार होते हैं, इसलिए समाज वर्ग होन हो जाता है। उत्पादन की शक्तियों सम्पूर्ण समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रूककर निर्धारित की जाती हैं अतः इसमें सब कामगारों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव हो जाता है तथा समाज में प्रतिस्पर्धा की भावना पूर्णरूप से खत्म हो जाती है।

साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष

लेनिन के अनुसार विकसित देशों के पूँजीपति अपने देशों की मंडियों में लाभ कमा लेने के पश्चात् अल्प विकसित देशों पर अपनी गिद्ध दृष्टि डालते हैं, जहाँ उन्हें कच्चा माल कौड़ियों के मोल मिल जाता है तथा तैयार माल मुँह मीठी बेमेलों पर बिक जाता है। ये पूँजीपति अपने देश के मजदूरों को छोटी-छोटी रियायतें, लाभ या सातप देकर शांत कर देते हैं और अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर के अल्प विकसित राष्ट्रों का भापूर शोषण शुरू कर देते हैं, अतः लेनिन ने सुझाव दिया कि बीसवीं शताब्दी में अल्पविकसित राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद के विरुद्ध बड़ी भूमिका अदा

माओ-त्से-तुंग (Mao-Tse-Tung)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

अपने जीवनकाल में पुरान-पुरान बन जाने वालों की सख्या अंगुनियों पर गिनी जा सकती है। माओ-त्से-तुंग इन्हीं में से एक थे। मध्य चीन के दक्षिण में स्थित हुनान प्रान्त के शाओशान गाँव में चीन और जापान के बीच संघर्ष छिड़ने के एक वर्ष पहले 26 दिसम्बर 1893 को माओ का एक किसान परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता माओ शुन चेह लाम्हे, तगढ़े किसान थे जो कईदाँरों से मुक्ति पाने के लिए सेना में भरती हो गए, किन्तु एक साल की नौकरी के बाद वह पर लौट आए और मृगतों और चावल के व्यापार से उन्होंने नया जीवन आरम्भ किया। कुछ ही वर्षों में वह एक सम्पन्न किसान बन गए। माओ के पिता का स्वभाव कठोर था, जबकि उनकी माता बेन ची मेई ममता और दया की भूमि थी। माओ-त्से-तुंग पिता की अपेक्षा अपनी माता के अधिक नजदीक थे। बचपन से माओ अपनी धुन के धक्के से और जो काम करते थे सोच विचार कर करते थे। माओ-त्से-तुंग पाँच वर्ष की आयु से खेती के कामकाज में अपने पिता का हाथ बंटाने लगे थे। सात वर्ष की आयु में उन्हें एक निजी शिक्षक के यहाँ लिखना पढ़ना सीखने के लिए भेजा गया ताकि वह हिस्सा किताब रख सके और चिट्ठी-पत्र लिख सके, लेकिन माओ का मन किताबों में रम गया। 14 वर्ष की आयु में 1907 में माओ का अपने से चार वर्ष बड़ी लड़की से पहला विवाह हुआ। माओ ने स्वीकार किया कि अपनी पहली पत्नी से उनकी कभी नहीं पटी और अन्त में उन्होंने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया। 1911 में वह टैपेट्स परीक्षा में सफल हुए। माओ को देशव्यापी निर्धनता, धरापार और शोषण का अहसास था। वे विदेशियों द्वारा बार किए गए राष्ट्रीय अपमान से परिचित थे। इन सबने उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनों का इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने इस शाताब्दी की चीन की पहली क्रांति देखी और उसमें भाग लिया और सेना में भरती हो गए। मुन्वात सेन के नेतृत्व में 1911 में हुई इस क्रांति ने 267 वर्ष पुराने मौर साम्राज्य को उखाड़ फेंका। सुन के राष्ट्रपति बनने पर माओ ने सेना छोड़ दी। उसके बाद उनका जीवन कुछ समय के लिए अव्यवस्थित रहा और अन्त में उसने हुनान स्टेट कॉलेज में प्रवेश लेकर डिग्री प्राप्त की। 1918 में वे पीकिंग गए और विश्वविद्यालय पुस्तकालय में नौकरी कर ली। यहीं वे चीन के बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निकट सम्पर्क में आए। 1920 में उन्होंने हुनान में एक सम्प्रदायी संगठन की स्थापना की।

डॉ. मुन्वात सेन के निधन पर 1925 में च्यौंग काई शेक ने कॉमिटिंग का नेतृत्व सम्भाला। सोवियत सघ ने इस आशा से च्यौंग का समर्थन किया कि वे उत्तरी चीन के मुद्र-लोलुपों को उखाड़ फेंकने में सफल होंगे, किन्तु जब च्यौंग ने हाप्राई के कम्युनिस्टों पर प्रहार किया तो च्यौंग और कम्युनिस्टों के बीच घूट पड़ गई। सितम्बर 1927 में माओ ने च्यौंगशा में विफल कृषक क्रांति का नेतृत्व किया। माओ अपने सहयोगियों सहित च्यौंग काँग पर्वतमाला में शरण लेने पर विवश हुए। अगस्त 1929 में माओ ने क्वांगसी में सोवियत साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद माओ और उनके साथियों को कदम-कदम पर मुसीबतों का सहपन करना पड़ा। 1931-33 के बीच च्यौंग काई शेक ने कम्युनिस्टों के सफाए के लिए ऐतिहासिक अभियान संचालित किया। माओ की दूसरी पत्नी को कॉमिटिंग ने मृत्यु दण्ड दिया। च्यौंग की सेना का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि कम्युनिस्टों को लाम्हे कूच का निर्णय करना पड़ा। अक्टूबर, 1934 में कोई 90,000 स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने हास्यास्त्रों और रसद सहित माओ के नेतृत्व में 6,000 मील लम्बी यात्रा आरम्भ की। इनमें से केवल 8,000 ही 1935 में केनान स्थित माओ की अपेक्षा सुरक्षित अग्रे तक पहुँच गए। अनेकों की मृत्यु हो गई और अन्य राश छोड़ गए। स्वयं माओ को किसानों के साराण में अपने बच्चे छोड़ने पड़े जिनसे वह फिर कभी नहीं मिल सका, किन्तु इस अभियान से माओ को ठोस अनुभव प्राप्त हुआ। उसे किसानों की कठिनाइयों का बोध हो गया और वह जान गया कि उनके असन्तोष से कितरा प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। 1946 में चीन में व्यापक गृहयुद्ध छिड़ गया।

च्यौंग के पास थोड़ा विरासत सेना थी, किन्तु वह माओ के सैनिकों के छापापार युद्ध का मुकाबला नहीं कर सका। जनवरी, 1949 में कम्युनिस्टों का पीकिंग पर अधिकार हो गया। उसके बाद नानकिंग का पतन हुआ और अक्टूबर 1949 में माओ ने चीनी जनतादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। उसी वर्ष वह अपनी प्रथम विदेश यात्रा पर मास्को गए। उसने दूसरी और अन्तिम विदेश यात्रा 1957 में की जो मास्को की थी। गणराज्य की स्थापना के बाद माओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष बना। 1958 में उसने राष्ट्राध्यक्ष का पद त्याग शाओ ची के पक्ष में छोड़ दिया। 1959 के बाद शेष विश्व के प्रति चीन का रुख उत्तरोत्तर आक्रामक होता गया जो इसका प्रतीक था कि माओ की नीति आन्तरिक मामलों की ओर से मन्तर्विदेशीय मामलों की ओर झुक रही थी। 1963 से अध्यक्ष माओ अपनी क्रांति की धारणा का एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के मुक्ति आन्दोलनों के

लिए निर्यात करने लगा। सोवियत सघ से चीन के सम्बन्ध उदरोगत बिगड़ते गए और इस बिगड़ का प्रभाव चीनी नेतृत्व पर पड़ा। यद्यपि 1961 में माओ ने सॉई मॉंटगोमरी से कहा था कि वह 73 वर्ष से अधिक जीना नहीं चाहता, किन्तु वह यह सहन नहीं कर सका कि उसके नेतृत्व को कोई चुनौती दे और 73 वर्ष पूरा करने के पहले उसने एक और क्रान्ति का नेतृत्व किया। यह था 1966 की महान् सांस्कृतिक क्रान्ति जिसमें माओ के लाख रक्षकों ने माओ विरोधियों को चुन-चुनकर मौत के पाट उतार दिया। उसके मृत्यु पर्यन्त (रात्रि 8, 9 सितम्बर, 1976) वह अपनी लगातार बीमारी के बावजूद चीन का नेतृत्व करता रहा।

चीनी मार्क्सवाद (माओवाद) के प्रमुख सिद्धान्त

माओवाद चीन की परिस्थितियों के अनुकूल मार्क्सवाद-लेनिनवाद का माओवादी चीनी-संस्करण है। माओ ने अपने मनचाहे ढंग से मार्क्सवाद-लेनिनवाद को प्रतिपादित किया और उसे चीन में ऐसी व्यावहारिक दिशा प्रदान की जिसमें न केवल पूँजीवादी विश्व को बल्कि स्वयं साम्यवादी जगत् को खतरा पैदा हो गया है। चीन में माओ को देवता तुल्य, वर्तमान शासकी का सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति और मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सर्वोत्तम प्रवक्ता तथा उसके विचारों का रचनात्मक विरोध पाप और अपराध माना जाता था, परन्तु अब ऐसा नहीं है। माओ के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

1. सशस्त्र क्रान्ति आज उतनी आवश्यक है जितनी मार्क्स या लेनिन के समय में थी। माओ का मार्ग है—क्रान्ति द्वारा गृह-युद्ध भड़काना और चोट पर चोट करते हुए अन्तर्वेगन्वा साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर अधिकार जमा लेना। माओ की दृष्टि में सर्वहारा वर्ग क्रान्ति की संचालक शक्ति है और इस वर्ग को शक्ति प्रयोग के लिए छापाभार युद्धों का आश्रय लेना चाहिए। चीन के गृह-युद्ध अर्थात् व्यापकई शोक के विरुद्ध संघर्ष में माओ ने छापाभार युद्धों की प्रभावशालिता को सिद्ध कर दिखाया और आज यह एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध प्रणाली के रूप में सुनिरासित है। माओ ने स्टालिनोत्तर रूसी शासकों पर सशोधनवादी होने का आरोप लगाया और कहा कि वे क्रान्ति के पथ से विचलित हो गए हैं। माओ की एक बड़ी देन यह मानी जा सकती है कि उसने क्रान्ति के नेतृत्व में किसानों की सम्मिलित किया। यद्यपि रूसी क्रान्ति में किसान सम्मिलित थे, लेकिन नेतृत्व केवल श्रमिकों के हाथ में था।

2. माओवाद साम्यवाद, पूँजीवाद और साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है। वह पूँजीवाद के शत्रु पर साम्यवाद का महल खड़ा करना चाहता है। माओ की मान्यता के अनुसार दो महायुद्ध पार्श्वतः पूँजीवाद को ज्वरित कर चुके हैं, अब उसे एक और प्रवल धक्का देना है और यह सड़खड़ाती हुई दीवार अपने अन्त गिर जाएगी। साम्यवादियों को चाहिए कि वे पूँजीवादी देशों में क्रान्तियों, युद्धों और संघर्षों को भड़काएँ। माओ के अनुसार यद्यपि पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में अन्तर्विरोध है, लेकिन इनमें एक आधारभूत अन्तर यह है कि जहाँ पूँजीवाद के अन्तर्विरोध का अन्त केवल युद्ध और शक्ति द्वारा हो सकता है, वहीं समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्विरोध शान्तिपूर्वक दूर किए जा सकते हैं।

3. माओवाद शक्ति का दर्शन (Philosophy of Power) है। राजनीतिक शक्ति के सम्पूर्ण प्रयोग से मनुष्यों के हृदय परिवर्तन कर सभी सामाजिक शक्तियों को नियन्त्रित किया जा सकता है। माओ के शक्तिवादी विचार मार्क्स की इन मौलिक धारणा के प्रतिकूल थे कि आर्थिक परिस्थितियाँ मानव-विचारों और सभ्यताओं का निर्माण करती हैं। माओ का कहना था कि विचारों से समाज का निर्माण होता है और विचारों के बदलने शक्ति का महत्व है। सैनिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजनीतिक शक्ति बन्दूक की नली से उदयन होती है और बन्दूक से कोई वस्तु उत्पन्न की जा सकती है।

4. माओवाद युद्ध की अनिवार्यता और शक्ति के प्रयोग का संदेश देता है। माओ के लिए शक्ति तथा सशक्तता का धारणा का कोई महत्व नहीं है। माओ के अनुसार अगला महायुद्ध सम्पूर्ण साम्राज्यवादी पूँजीवाद का पूर्ण रूप से विध्वंस करने वाला होगा। प्रथम महायुद्ध ने सोवियत क्रान्ति की भूमिका का निर्माण किया, द्वितीय महायुद्ध के बाद चीन की क्रान्ति सम्पन्न हुई और अब तृतीय महायुद्ध सम्पूर्ण विश्व में समाजवाद के प्रदुर्भाव के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण कर देगा।

5. उस समय विश्व विरोधी शक्तियों में विभाजित था। एक ओर साम्राज्यवादियों का शक्ति का जिसमें अमेरिका और उसके साथी तथा अन्य प्रतिस्पर्धी देश थे। दूसरी शक्ति साम्राज्यविरोधियों का है जिसमें साम्यवादी जगत् और चीन थे। इन दोनों शक्तियों से पृथक् उदय हो रहे हैं। उदय के केवल धोखे का गुंडा है। यदि भारत ने माओ के इस विचार का सही मूल्यकन किया होता तो वह चीन के निर्लज्ज आक्रमण के प्रति आरम्भ से चेष्टे में न रहता। सोवियत सघ के विखण्डन से माओवादी विचारधारा विमूढनित हो गई और रूस पूँजीवादी राष्ट्र अमेरिका की ओर झुका।

॥ माओवाद लोकतन्त्रात्मक अधिनायकवाद (Democratic Dictatorship) का पक्ष-पोषण करता है। उसकी रचनाओं 'New Democracy', 'On Coalition Government', 'The Present Position and Task Ahead', 'The Peoples Democratic Dictatorship' आदि के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि माओवाद साम्यवादियों के लिए लोकतन्त्र और गैर साम्यवादियों के लिए अधिनायकतन्त्र है और यह मिलकर लोकतन्त्रात्मक अधिनायकवाद हो जाता है। माओवाद लोकतन्त्रात्मक इसलिए है कि यह 'जनता' के हितों की पूर्ति के लिए शासन करता है और अधिनायकवाद इसलिए है कि यह क्रान्ति विरोधी शक्तियों का दमन करने के लिए निरपेक्ष शक्ति का प्रयोग करता है। माओ को उदारवाद, सहअस्तित्व जैसे शब्दों से घृणा है। माओ के दर्शन में प्रतिक्रियावादियों और गैर साम्यवादियों के प्रति उदारता के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। माओ की दृष्टि में राज्य एक विशेष वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन करने का साधन है, अतः राज्य का कर्तव्य है कि श्रमिक वर्ग के हितों के विरोधी तत्वों को नियंत्रणपूर्वक कुचल दे।

7 माओ धर्मनिरपेक्षता का प्रतिष्ठापक है लेकिन ने यह स्वीकार किया था कि दल के उच्च सिद्धान्तों का प्रतिपादन ब्रह्म उच्च तार के व्यक्ति कर सकते हैं, किन्तु उसने व्यक्ति-पूजा स्वीकार नहीं किया पर माओ को 'वर्षा और करों' में अन्तर था। माओ ने एक ओर तो 'सैकड़ों फूलों के एक साथ खिलने' की बात कही, पर दूसरी ओर अपने कठोर अधिनायकवाद की इस प्रकार स्थापना की कि चीन में माओ सबसे बड़ा देवता अर्थात् भगवान बन गया। केवल माओ की तन्त्रशाही रही जिसका हर शब्द अन्तिम सत्य का उद्घोषक था। माओ ने अपने विरोधियों को सांस्कृतिक क्रान्ति के नाम पर खून खर देने में कोई कसर नहीं रखी। चीनी गणराज्य के अग्रगण्य लिण्गें शओ चौ और चीन के सुरक्षा मन्त्री लिन-बियाओ जैसे शक्तिशाली भी इस सांस्कृतिक क्रान्ति के शिकार हुए। माओ ने चीन का 'माओकरण' करने का पूरा प्रयत्न किया और 'माओ की सत्त पुस्तक' का पाठ घर घर में किया जाना अनिवार्य बना दिया। इस सत्त पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार हैं—(1) युद्ध में शस्त्र की तुलना में मनुष्य का महत्व अधिक है, क्योंकि निर्माणक वस्तु मनुष्य है न कि शस्त्र, (2) सेना में राजनीति को अन्य सैनिक कार्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये, (3) माओवाद सच्ची राजनीति तथा सच्चा अर्थशास्त्र है अतः इसे सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिये, (4) माओवाद सच्चा आदर्शवाद है एवं (5) जीवन विचारों और रचनात्मक व्यावहारिकता को छोड़ें किताबी, काल्पनिक तथा सिद्धान्तवादी विचारों की अपेक्षा श्रमिकता दी जानी चाहिये।

माओ के अनुसार प्रत्येक चीनी साम्यवादी को इन चार इच्छाओं को स्वीकार करना चाहिये—(1) सबसे अच्छा तरीका यह है जो राजनैतिक वैचारिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। (2) उसी साथी को श्रेष्ठ मानना चाहिए जो तीन-आठ (त्रि-आठक) को कार्य प्रणाली के लिए उत्तम हो। इस त्रि-आठक का अधिप्राय तीन प्रवृत्तियों और आठ चारित्रिक गुणों से है—(अ) अपनी सही राजनैतिक प्रकृति को पकड़े रखना (आ) अपने कर्तव्य-पालन में क्रम और सहयोग का परिचय देना, (इ) अपनी मुक्तियों में तत्वीयमान काम करना। आठ चारित्रिक गुणों में एकता, सतर्कता, निरपेक्षता, सहिष्णुता आदि सम्मिलित हैं। (3) वह साथी श्रेष्ठ है जो सैनिक प्रशिक्षण की दृष्टि से उत्तम हो एवं (4) जो सैनिकों के लिए जीवनव्यवस्था करने में निपुण हो।

॥ माओ ने समाजवादी क्रान्ति के लिए जिस पद्धति की विवर्तित किया उसे 'टुन टुन (Fight, Fight), टा, टा, टा, टा (Talk, Talk, Talk, Talk) सिद्धान्त कहते हैं। इनका अधिप्राय है कि सर्वप्रथम विरोधी पर आक्रमण कर उसे हता निर्बल बना देना चाहिए, कि वह लड़ने के सिद्धान्त को छोड़कर मेज पर बातचीत के लिए तैयार हो जाए। कुछ दिनों तक समय-समय-वर्ती चलनी चाहिए लेकिन समझौते की शर्तें ऐसी रखी जानी चाहिए कि शत्रु उन्हें स्वीकार करने को तयार न हो। उसके ऐसा करने पर उस पर शान्ति भग का आरोप लगाया चाहिए और इस आरोप का प्रचार करना चाहिए। इसी समय शत्रु पर पुनः भयकर आक्रमण कर उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लेना चाहिये। संक्षेप में पहले लड़ो, फिर निर्बल बनाकर बात-चीत करो और सब कर्तव्य बग्न करने के मुन्द लड़ो और अधिकार जमा लो।

माओ के कुछ अन्य विचार

ज्ञान—अपने सामाजिक व्यवहार में मनुष्य विभिन्न प्रकार के सपनों में व्यस्त रहता है और अपनी सफलताओं और असफलताओं से प्रचुर अनुभव प्राप्त करता है। मनुष्य की पाँच ज्ञान-द्रव्यें—आँख, कान, नाक, जीभ और त्वच—के जरिए उसके महत्वपूर्ण वस्तुगत बाह्य जगत् की असंख्य घटनाओं का प्रतिबिम्ब पड़ता है। ज्ञान शुरू में इन्द्रिय-प्राप्त होता है। धारणात्मक ज्ञान अर्थात् विचारों की स्थिति में तब तक पहुँचा जा सकता है जब इन्द्रिय-प्राप्त ज्ञान काफी मात्रा में प्राप्त कर लिया जाता है। यह ज्ञान-प्राप्ति की एक प्रक्रिया है तथा ज्ञान प्राप्ति की समुची प्रक्रिया मजिल है—एक ऐसी मजिल जो हमें वस्तुगत पदार्थ में मनोगत चेतना की ओर ले जाती है। मनुष्य का ज्ञान व्यवहार को करीबी के जरिए छलांग भर कर एक नई मजिल पर पहुँच जाता है। यह छलांग पूर्ववर्ती छलांग से अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही ज्ञान प्राप्ति की पहली छलांग अर्थात् वस्तुगत बाह्य जगत् को प्रतिबिम्बित करने के बीच बनने वाले विचारों, सिद्धान्तों, नीतियों, योजनाओं अथवा उपायों का सही अथवा गलत होना साबित करती है। सच्चाई को पहचाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। सही ज्ञान की प्राप्ति केवल पदार्थ से चेतना की तर्फ जाने और फिर चेतना से पदार्थ को तरफ लौटने की प्रक्रिया को, अर्थात्

व्यवहार से ज्ञान का आर और ज्ञान से व्यवहार का ओर जाने की प्रक्रिया को बार-बार द्वापरे से होना है। यही वास्तविकता का ज्ञान-सिद्धान्त अथवा इन्द्रायक भौतिकवाद का ज्ञान-सिद्धान्त है।

आध्यात्म—आध्यात्मवाद और आध्यात्मवाद दुनियाँ में सुगम चले हैं क्योंकि इनमें मानने वाले वस्तुगत यथार्थ का आधार बनाए बिना अथवा वस्तुगत यथार्थ का किसी पर परछाई बिना मन चाह अनगल बने का सच है। दूसरी तरफ भौतिकवाद और इन्द्रायक वास्तव में प्रयत्न साध्य चले हैं। इसमें वस्तुगत यथार्थ का आधार बनाता और उस किसी पर परछाई जल्दी है। यदि कोई प्रयत्न नहीं करेगा तब उसके लिए आध्यात्मवाद और आध्यात्मवाद का उद्देश्य में गिरने का सम्भावना बना रहेगा।

विश्लेषण—जब हम किसी चीज का अध्ययन करें तो हमें उसका अन्तर्वस्तु का परिणाम करना चाहिए उसका बाह्य रूप का अन्तर्वस्तु का दृश्य के दृश्य के लिए नागरिक मनन चाहिए तथा एक बार देखें धर का लो पर हमें उस चीज का अन्तर्वस्तु का दृश्य से पढ़ें लेना चाहिए। विश्लेषण का यही पद्धति एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक पद्धति है।

अन्तर्विरोध—किसी वस्तु का विकास का मूल कारण उसका बाह्य नहीं बल्कि उसके भीतर होता है। उसका आन्तरिक अन्तर्विरोध में निहित होता है। यही ज्ञान का अन्तर्विरोध है वस्तु में निहित रहता है इसलिए हर वस्तु गतिमान और विकासशील होता है। किसी वस्तु के भीतर विरोधमान अन्तर्विरोध उसका विकास का मूल कारण होता है जबकि बाह्य और अन्य वस्तुओं का बाह्य कारण के कारण विकास का मूल कारण होता है।

अनुशासन—जन्म में जन्म केन्द्राध्यात्म से जुड़ा रहता है और आध्यात्म अनुशासन से। यही दान एक ही वस्तु के दो विरोधमान हैं जो परस्पर विरोध में हैं और एकान्वय भी तथा हम इनमें से एक को दूसरे का दूसरे पर एकपक्षीय और नही देना चाहिए। जन्म का काम आध्यात्म अनुशासन, जन्म केन्द्राध्यात्म के बिना तब चल सकता है। हारा जन्म केन्द्राध्यात्म जन्म केन्द्राध्यात्म का एक ही दान आध्यात्म और अनुशासन का एक ही सच होता है। इस व्यवस्था में जन्म व्यवस्था जन्म और आध्यात्म के अन्तर्विरोध करता है लेकिन उसे समझवाना अनुशासन की मांगों के अन्तर्विरोध रहता पड़ता है।

नैतिकता—यह दुनिया तुम्हारी है यह हमारा है लेकिन अन्तर्विरोध यह तुम्हारा हो जाता है। हम नैतिकता का अन्तर्विरोध और जन्म शक्ति से भरपूर सुख या नौ बने का सुख का वह अपना जन्म का पुरवहार मानने में है। हमारा जन्म हम पर लगा हुआ है। हमें यह समझने में अपने तमाम नैतिकता का मूल देना चाहिए कि हमारा दान अब बहुत गहरा है। हम छोड़ें स समय में इस स्थिति को बुनियादी रूप में नहीं बन सकते तब मात्र अपना धुवा पाड़ा और समस्त जन्म के संपूर्ण प्रयत्नों द्वारा और स्वयं अपने भुजबन के भीतर काम करते कुछ दार्शनिकों में हम अपने देश का मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं। समझवत्ता व्यवस्था कायम होने से भावना के एक आध्यात्म समाज तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो गया है किन्तु इस आध्यात्म का वास्तविक रूप देने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा।

मिथ्या—काम करने लयक हो सके को समान कार्य के लिए समान वस्त्र के सिद्धान्त के अन्तर्विरोध जन्म के माँ में पर तैयार होने का मौखिक दा। यह कार्य जन्मविरोध हो जाना चाहिए।

सहित्य—कला एवं सहित्य का समालोचना के दो माध्यम रहते हैं—एक दार्शनिक माध्यम और दूसरा कलात्मक माध्यम। सहा दार्शनिक माध्यम में हर वग अपने स्वयं का दार्शनिक और कलात्मक माध्यम होता है लेकिन सहा समग्रों में सहा वग हमारा राजनीतिक माध्यम का प्रमुख स्थान देते हैं और कलात्मक माध्यम का भी। हम जिस चीज का मार्ग करते हैं वह राजनीति और कला का एक ही विषय-वस्तु और रूप का एक ही दार्शनिक राजनीतिक विषय-वस्तु और यथार्थ-समग्र अपेक्षित भूत कलात्मक रूप का एक ही। व कलाकृतियों जिनमें कलात्मक प्रतिभा का अभिव्यक्ति है किन्तु शक्तिमान होती है फिर चाहे वे दार्शनिक दृष्टि से किन्तु राजनीतिक कथों न हों। इसलिए हम ऐसा कलाकृतियों के समान का जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण गम्भीर होता है तथा पाठ्यरत्न एवं नरबारा जैसे चीजों का उन कलाकृतियों का जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण गंभीर होता है किन्तु जिनमें कलात्मकता का अभिव्यक्ति हो वह कलाकृतियों का राजनीतिक कथों न हो, विरोध करते हैं। सहित्य और कला के प्रयत्न पा हल इन दोनों माँ में पर सच करना चाहिए।

अध्ययन—जन्म एक वैज्ञानिक वस्तु है और इस माध्यम में बर्तमान या घटना का अनुभव नहीं हो जा सकता। उल्टा दमनगार और जन्म का दृष्टिकोण गिरने के से अव्यवस्था है। अन्तर्विरोध अध्ययन का रहता है। अब तक हम अन्तर्विरोध से नया नही टाढ़ें तब तक हम कुछ नहीं साध सकते हैं। हमें सचने के लिए तत्त्वज्ञान रहने और सिद्धान्त का अपेक्षित करने का स्वयं अन्तर्विरोध चाहिए।

मास्टर और समन्वय—मनुष्य सिद्धान्तों का दृष्टि से समग्र का सहा रहता है कला एक ही लेकिन हर देश का कला का एक विशाल दृष्टिकोण रूप और उसका दृष्टिकोण रहता है किन्तु इस कुछ व्यक्ति नही समझते। व अन्तर्विरोध के राष्ट्रीय गुण का अव्यवस्था करते हैं और परिणाम की अपेक्षित यह सचकर करते हैं कि परिणाम हर देश में उनमें है। व पूरा परिणाम-कारण का सचकर करते हैं—कला कला, कला समग्र, विज्ञान, नाटक, गान और नृत्य और सहित्य

सबसे अपना ऐतिहासिक महत्व है। चीनी संस्कृति को ग्राह्यीकार करके जो लोग पूर्ण परिणामीकरण का आग्रह करते हैं उनका कहना है कि चीनी चीनों के अपने नियम नहीं हैं, इसलिए वे ठाका अध्ययन करने या उनका विकास करने के लिए प्रारुण नहीं है। यह चीनी वंश के प्रति राष्ट्रीय नकारात्मकता की प्रकृति है। हमें अरब देशों की संस्कृति सीखनी चाहिए और उनमें दशता प्राप्त करना चाहिए। हमारे लिए विशेष रूप से यह आवश्यक है कि मूलभूत सिद्धान्त में निपुणता प्राप्त करें। मार्क्सवाद एक मूलभूत सिद्धान्त है जिसका जन्म पश्चिम में हुआ है। इस सम्बन्ध में हम यह अनार कौन करे कि क्या चीनी है क्या पश्चिमी? अतएव हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जहाँ आधुनिक संस्कृति का प्रश्न है, पश्चिम का मानदण्ड हमसे ऊँचा है। हम पीछे छूट गए हैं।

मूल्यों का

माओ तो युग क्रान्तिद्वारा और क्रान्तिकारी किसान थे। यदि माओ न होते तो चीनी क्रान्ति न होती। अंग्रेजी या ग्रेट ब्रिटेन में रिवोल्यूशन या क्रान्ति का जो अर्थ है चीनी में, यमिंग शब्द का उससे भिन्न अर्थ है—शासक वर्ग को शासन करने के देवी अभिचार। यथार्थ कर देना शुद्ध राजनीतिक अर्थ है। सताव्वियों से चीनी किसान दबा हुआ था। उसे समाज में कोई अधिकार प्राप्त न था। समय-समय पर उसने राजवशों को गद्दी से उतार दिया था, परन्तु इससे कोई परिवर्तन नहीं आया था। सभी चतुर सिद्धान्तवादियों की भाँति चीनी सिद्धान्तवादियों ने राजवशों के पता को लेकर एक सिद्धान्त गढ़ रखा था। वह ईश्वरचक्र सिद्धान्त है अर्थात् यह ईश्वर की इच्छा की एक अमूर्त राजवश का पता हो, तो वह हुआ। इस सिद्धान्त से स्वयं की शक्ति कर चीन का ब्रह्मण वर्ग निर्दिष्ट हो जाता था, परन्तु किसान पिछड़ा रहता था और माओ और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह स्थिति बदल दी। सन् 1926 में उसने सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि किसान आगामी क्रान्ति का बाहक होगा। उन्होंने किसानों को बताया कि साम्यवादियों (जो उस समय कैबल बीना साक्षर थे) क्रान्ति करी होगी, बाकी सब साम्यवादियों की पूजा करते रहेंगे। राजवशों को गद्दी करने से कुछ नहीं होगा। आवश्यक यह है कि राज्य को पुनर्जीवित करने को तोड़ दिया जाए। चीनी किसान ने माओ के गन्देश को समझा और उसका अनुसरण किया। माओ का बलिष्ठ योगदान यही है कि उसने विशाल चीनी किसान-समाज में जनवादी चेतना उत्पन्न की। 18 वर्ष के भीतर साठ करोड़ चीनी किसानों ने जनशक्ति का रूप ग्रहण कर लिया और समाज की काया पराट दी, जैसा चीनी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

माओ ने क्रान्ति का दो अर्थ दिए—प्रथम, क्रान्ति शासनवश को शासनाधिकार से वंचित करती है, द्वितीय, क्रान्ति शासन के विभागों और मन्त्रियों को अग्रगण्य करती है। माओ इसके लिए बहुत उत्सुक था कि चीनी क्रान्ति का दूसरा विच्छेद पुराने विचारों पुरानी आदतों, पुरानी रीतियों और पुरानी संस्कृति से सम्बन्ध करे। माओ का प्रमुख योगदान अधिपत्या के मार्क्सवादी सिद्धान्त की समग्र उर व्यवहार में परिणत करना था। वह पहला कम्युनिस्ट था जिसने ऐसा किया। उसके जीवन के अन्तिम वर्ष पुराने दौरे के शिल्पक क्रान्तिकारी सचर्य का संगठन करने में बीते। उसके निरन्तर क्रान्ति के प्रयोग उसके अन्तर्-आध्यात्म अधिपत्या पर आक्रमण जारी रखने के लिए उसके पार्टी के पुरे जाने के प्रयत्न इसी 'दूसरे विच्छेद' के उद्देश्य थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा था कि दूसरा विच्छेद कायम रह सकता है।¹

दुर्भाग्यवश माओ के अन्तिम क्रान्तिकारी और विस्तारवादी विचार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुए। अरब के आणविक युग में माओवाद जैसी शक्ति, हिंस्र और बर्ष सघर्ष को उत्प्रेषक प्रोत्साहन देने वाली विचारधारा मानवता को महाविनाश के बगार पर ला सकती है। द्विस्तर और मुसोलिनी की तरह 'शुद्ध और शक्ति' का गीत गाता भ्रष्टाचारक है। माओ ने इस तथ्य की चेष्टा कर दी थी कि मार्क्सवादी साम्यवाद की जन्मभूमि सोवियत रूस तक समय की गति की पहचान कर सहअस्तित्व की बात करने लगा है और 'शुद्ध की अनिवार्यता' में उसका विश्वास शिथिल पड़ने लगा है। माओ भूल गए कि आणविक युद्ध में विजय और विजित दोनों का महाविनाश होगा। शक्ति प्रदर्शन चाहे वह माओवादी हो या कोई अन्य यद्पी, निर्जित रूप से सम्पूर्ण मानवता के लिए घातक है और मार्क्स की इस मौलिक धारणा के विरुद्ध है कि आर्थिक शक्तियाँ मानव-विचारों और समस्याओं का निर्माण करती हैं।

□□□

भारतीय राष्ट्रवाद (Indian Nationalism)

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध धननीतिक-राष्ट्रवादी चेतना के फसने-फूलने और एक संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्भव और विकास का काल था। इस काल में भारत में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने देश में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय चेतना जागृत की। इनमें से महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेताओं की जानकारी आगे दी जा रही है।

दादाभाई नौरोजी

(Dadabhai Naoroji)

गोखले के अनुसार "वह उच्चतम कोटि की देश-भक्ति के एक पूर्णतम उदाहरण थे। कृषि की स्थापना से पूर्व 40 वर्षों तक वे भारत में सार्वजनिक जीवन को संगठित करते रहे और कृषि की स्थापना के बाद 20 वर्षों में अधिक समय तक वे राष्ट्रीय भारत के सर्वमान्य नेता रहे। जीवन के हर क्षेत्र में दादाभाई को सम्मान मिला और देशवासियों ने प्रेमपूर्वक उन्हें 'भारत का पितामह' (Grand Old Man of India) की उपाधि दी। दादाभाई भारत में राजनीतिक जागृति के अग्रदूत तथा अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लोभविह, वैदेशिक व्यापार, राष्ट्रीय आय जैसी समस्याओं में गहरी रचि दी। उनका 'निर्गम का सिद्धान्त' (Drain Theory) भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक चिन्तन में उतना विस्फोटक बन गया था जितने मार्क्स के 'शोषण' और 'वर्ग संघर्ष' के सिद्धान्त मार्क्सवादी तथा समाजवादी क्षेत्रों में बन गए हैं।"

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

दादाभाई नौरोजी (1825-1917) का जन्म मुम्बई में 4 सितम्बर 1825 को हुआ। उनके पिता नौरोजी फार्वनजी दौर्दा एक गरीब पारसी थे और उनकी माता का नाम माणिक बाई था। उनके नाम के साथ जुड़ा 'भाई' (भावा) शब्द उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। दादाभाई का विवाह 11 वर्ष की अल्पावु में सोहणबजी श्राफ की कन्या गुलबाई के साथ हो गया। दादाभाई ने 'एलफिन्स्टन सम्प्रान' में अपनी शिक्षा प्राप्त की। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने शिक्षा सम्बन्धी अनेक पारिवारिक जीते। दादाभाई के प्राध्यापक उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे और प्रो. अल्लेक्ज ने उन्हें 'भारत की आशा' (The Promise of India) कहा था। दादाभाई नौरोजी की सार्वजनिक जीवन में रचि शीघ्र ही प्रसुटित होने लगी। 1853 में अपने कुछ सहयोगियों सहित उन्होंने मुम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। 1854 में वे एलफिन्स्टन कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शन के प्राध्यापक नियुक्त हुए। वे प्रथम भारतीय प्राध्यापक थे जो देश के किसी सम्मानित कॉलेज में नियुक्त हुए थे। 1855 में उन्होंने कॉलेज से त्यागपत्र देकर व्यापार शुरू कर दिया। 1868 में अपने कुछ साथियों के सहयोग से उन्होंने लन्दन में ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन की स्थापना की जिसकी शायद ही मुम्बई कोलकाता, चेन्नई आदि बड़े भारतीय नगरों में खोली गई।

1873 में दादाभाई भारतीय विद्य के सम्बन्ध में नियुक्त फासेट प्रवर समिति (Fawcett Select Committee) के सम्मुख उपस्थित हुए। 1874 में बड़ौदा के दीवान बने। 1875 में वे मुम्बई कॉरपोरेशन के सदस्य बने और 1885 में मुम्बई प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद (Bombay Provincial Legislative Council) के अतिरिक्त सदस्य (Additional Member) बने। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटेन को अपने राजनीतिक जीवन का कार्यक्षेत्र बनाया तकि वे वहाँ रहकर भारतीय दिवों के लिए लड़ सकें। 1892 में केन्द्रीय फिसवरी से चुनाव लड़कर वे ब्रिटिश लोकसभा के सदस्य बने तकि इस महान सभा में वे भारत के दिवों का समुचित ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें। वे ब्रिटिश संसद के 1892 से 1895 तक सदस्य रहे। इसके बाद उन्हें 'उपलब्ध व्योमन' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यह

कमीशन भारत सरकार के सैनिक-औद्योगिक खर्चों की जाँच के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था और इसमें दादाभाई का बड़ा हाथ था। दादाभाई और उनके सहयोगी चार्ल्स ब्रेडलाफ के निरन्तर प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटिश लोकसभा में यह प्रस्तावित पाति हो सका कि साम्राज्य सेवाओं (Imperial Services) के लिए इम्पेण्ड और भारत में सैन्य-साथ परीक्षार्थ हो। कुछ पुरुषों में दादाभाई नौरोजी ने बर्मिंघम से अपना क़ाता जोड़ा और जीवन-पर्यन्त उसका सेवा की तथा उसे विकास की स्तोदियों पर चढ़ते हुए स्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य तक ले गए। वे 1886, 1893 और 1906 में क्रमशः कोलकाता बर्मिंघम, साहौर बर्मिंघम और पुन कोलकाता बर्मिंघम अधिवेशन के सभापति रहे। 40 वर्ष के अत्यल्प समय से उन्होंने बर्मिंघम के जन्म से पूर्व भारत में सर्वोत्तम सार्वजनिक जीवन को जन्म दिया और इसके उपरान्त पर्याप्त समय तक वे भारत के राष्ट्रीय नेता रहे। भारत में सभ्यता का ह्रास या निष्कासन (Economic Drain) उनके वक्तव्य का मुख्य विषय रहा था और उन्होंने सेवा पर व्यय कम करने और स्वायत्त शासन, स्वदेशी और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक 'भारत में गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन' (Poverty and Un-British Rule in India) के अन्तर्गत आर्थिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं को लिया। यद्यपि ब्रिटिश शासन के प्रति, अपने जीवन की सन्ध्या में दादाभाई का रवैया कठोर हो गया और उन्होंने स्वराज्य को बर्मिंघम का ध्येय धीरे-धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने कभी झर्झर और हिंसात्मक उपायों का पक्ष नहीं लिया। उदार और सौविधानिक प्रयोगों में उनका आजीवन अटूट विश्वास बना रहा। दादाभाई ने त्याग और सेवामय जीवन व्यतीत किया तथा देशवासियों के मन में राष्ट्र की ऊँचा उठाने का महान् आदर्श रखा। 30 जून 1917 को इन्का स्वर्गवास हो गया। भारत एवं इम्पेण्ड ने दादाभाई को श्रद्धांजलि अर्पित की।

दादाभाई नौरोजी का राजनीतिक दर्शन

(Political Philosophy of Dadabhai Naoroji)

दादाभाई नौरोजी के राजनीतिक विचार तत्कालीन उदारवादी-भित्तावादी चिन्तन से प्रभावित थे। उन्हें ब्रिटिश न्याय-प्रियता में विश्वास था, लेकिन अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में वे ब्रिटिश शासन के प्रति बटोर हो गए। ब्रिटिश उपेक्षावादी और शोषणवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध सीखी आलोचना करने के बावजूद उदार और सौविधानिक उपायों में उनकी मृत्यु-पर्यन्त अटूट आस्था बनी रही। दादाभाई ने निरंकुश साम्राज्यवादी व्यवस्था की रैप मानते हुए शासन की नैतिक शक्ति में विश्वास प्रकट किया और भारतीय आकांक्षओं तथा यहाँ की समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनता में स्वस्थ चेतना जाग्रत करने का प्रयत्न किया। उनके राजनीतिक विचारों को हम निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं—

राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार का पौषण

दादाभाई नौरोजी का जीवन सार्वजनिक मान्यताओं और उच्च आदर्शों से अनुप्राणित था। उन्होंने व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नैतिक शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति चाहे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले अथवा जीवन का कोई कार्यक्षेत्र चुने, उसका आधार नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि नैतिकता किसी कार्य या किसी सत्ता की स्थायित्व दे सकती है। राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार की उन्होंने वर्णना की और कहा कि न्याय, उदारता एवं मानवता की आधारशिलाओं पर राजनीतिक व्यवस्था की एकता कायम रखी जा सकती है। कोई राजनीतिक व्यवस्था यदि यह पारंपरिक बल पर आधारित है तो कभी दीर्घजीवी नहीं हो सकती। नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षओं में सादृश्य हो, तभी राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व होने की आशा की जा सकती है। 1893 में साहौर कॉंग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में नौरोजी ने कहा था कि किसी साम्राज्य का निर्माण अन्ध-शक्तियों के बल पर किया जा सकता है, लेकिन उसका परिणाम केवल शासक नैतिक शक्ति के आधार पर सम्भव है अतः सैनिक अथवा अस्वबल की अपेक्षा शेष शक्तियों और पारस्परिक विश्वास की राजनीतिक शक्ति का आधार बनाया जाए। यदि इम्पेण्ड ने पारंपरिक बल और उत्तेजना की नीति का अनुसरण किया तो यह उसे साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर करेगा।

ब्रिटिश चरित्र और शासन-व्यवस्था की प्रशंसा तथा निर्भीक आलोचना

दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश-प्रशासन, ब्रिटिश-संस्थाओं और ब्रिटिश-चरित्र की जहाँ उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की, वहाँ उसकी निर्भीक आलोचना भी की। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि यदि ब्रिटिश जनता अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनी रही और न्याय, निष्पक्षता तथा स्वाधीनता की अपनी परम्परागत परिपाटी के अनुसार कार्य करती रही तो भारत निश्चय ही स्वशासन-प्राप्ति की दिशा में अग्रे बढ़ सकेगा। 1906 में कोलकाता बर्मिंघम के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अपने मत के मूल सिद्धान्त को निम्नांकित शब्दों में पुनः दोहराया—“ब्रिटिश सरकार को अधीनता में हमारे साथ कोई बड़ा जुल्म नहीं होता। अन्य शासकों की तुलना में इस शासन में हम अधिक सुखी हैं। हमें जो पुराई इस शासन में दिखाई देती है या जिसकी हम शिकायत करते हैं, उसका मूल कारण सत्ता में आने वाले यूरोपीय अफसरों का अज्ञान है। इस देश में प्रचलित सम्प्रदायों, धार्मिक और सामाजिक विचारों तथा रीतियों के सम्बन्ध में यह अफसर ऐसे कानून

और नियम बना सकते हैं, जो इस देश के लिए हानिकारक हों और इसके बावजूद वे ठन्ठ तक यह समझते रह सकते हैं कि उन्होंने ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाया है। उन्हें अधिकांश ठीक समझते हैं, लेकिन देशवासी गलत मानते हैं अतः यदि हम इस तरह की एक समस्या हों, हम सुधार के सुझाव दे सकते हैं।¹ दादाभाई नौरोजी के अनुसार भारत की जनता को अपने दुखों के आगे ब्रिटिश शासन की अच्छाइयों की नहीं भूलना चाहिए। इस देश में ब्रिटिश शासन के स्थापित हो मानवर आगे कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि उसी पर हमारी आशाएँ निर्भर हैं। भारत का भाग्य ब्रिटिश शासन के साथ जुड़ा हुआ है और किसी अन्य शासन को हम अपने सिर पर नहीं लादना चाहते।

ब्रिटिश शासन के इस गुप्त-गान के पीछे दादाभाई के हृदय में गंभीर हुकुमद का भय नहीं था। वह एक उदात्तादी राजनीतिज्ञ थे जो भारत की आवाज, गौरव और आवश्यकता को सदैव धापा में रखना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोषों को उजागर किया, उनकी धापा में चेतावनी, तौछेपन और आक्रोश की भी गूँज रही लेकिन वह ऐसी कभी नहीं रहो जिससे हिमा या क्रान्ति को प्रोत्साहन मिले और इंग्लैण्ड तथा भारत की जनता के बीच कटुता बढ़े। दादाभाई ने ब्रिटिश शासन प्रणाली की कमियों की ओर संकेत करते हुए निर्भीकतापूर्वक कहा कि "वर्तमान शासन-प्रणाली भारतीयों के लिए विनाशकारी और निरक्षर है तथा इंग्लैण्ड के लिए आपत्ताहीन और उसके राष्ट्रीय चरित्र, आदर्शों एवं परम्पराओं के प्रतिफल है। इसके विपरीत यदि सच्चे अर्थ में ब्रिटिश मार्ग अपनाया जाए तो इससे ब्रिटेन और भारत दोनों लाभान्वित होंगे।" दादाभाई ने चेतावनी दी कि निकुरा और स्वेच्छाचारी शासन स्थापित नहीं रह सकता, क्योंकि बुद्धि और धृति शासन-व्यवस्था विनाश की ओर अग्रसर होती है। उन्होंने इस शासन-व्यवस्था को "धूर स्वाग" की मजा दते हुए इसमें आमूल परिवर्तन की माँग की। ईस्ट इण्डिया एगोसिएशन के 2 मई, 1867 के सम्मेलन में दादाभाई ने स्पष्ट किया कि यद्यपि ब्रिटिश शासन के कारण भारत को शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से लाभ पहुँचा है, लेकिन उपलब्ध ठीकड़े यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि इंग्लैण्ड की शक्ति और समृद्धि को बढ़ाने में भारत का विशेष योगदान रहा है। दादाभाई ने यह बताया कि इंग्लैण्ड को भारत से प्रतिवर्ष कितना धन प्राप्त होता है और किस तरह भारतीय शासन में भारतीयों की भर्ती नहीं की जाती। दादाभाई ने सेल्फवरी के इन शब्दों की दोहराया कि "अन्याय चलवान से धनवान का नाश कर देना।" 3 सितम्बर, 1880 को भारत के राज्य अवर सचिव लुई मालेट को अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि भारतीयों को ब्रिटिश महानगर न्यायप्रियता और चरित्र में विश्वास है, इसलिए वे (भारतवासी) ब्रिटिश शासन के भ्रष्ट बने हुए हैं। विगत में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं हुआ है जिसमें विजेता के रूप में अग्रेजों की भाँति शक्तियों के कल्याण को अपना कर्तव्य माना हो। यदि वर्तमान निर्गम बन्द कर दिया जाए और देश के विधि-निर्माण कार्य में भारतीय प्रतिनिधियों को अपनी राय देने का अवसर प्रदान किया जाए तो भारत को ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत एक ऐसे पवित्र की आशा हो सकती है जो उनके इतिहास के महानतम और सबसे गौरवशाली युग में बढ़ा-बढ़ा हो।²

ब्रिटिश लोकमन को भारतीय समस्याओं के प्रति जगाने की चेष्टा और भावी अनिष्ट की स्पष्ट चेतावनी

दादाभाई ने भारत के पक्ष में अथक प्रचार किया। उन्हें विश्वास था कि यदि ब्रिटिश जनता को भारतीय स्थिति और भारतीय समस्याओं तथा मानव के प्रति सही जानकारी दी गई और भारत के बारे में ब्रिटिश जनता का अज्ञान मिटा दिया गया तो दोनों देशों के सम्बन्ध सुदृढ़ हो जाएँगे और दोनों को इससे स्थायी लाभ पहुँचेगा। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश मिरा के सहयोग के बिना भारत के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड में स्वयं लोकमत नहीं बनाया जा सकेगा और न ब्रिटिश संसद के सदस्य भारत के सुधारों की आवश्यकता समझ सकेंगे। अतः दादाभाई ने डब्ल्यू. सी. बनर्जी आदि के सहयोग से 'सन्तन इण्डियन सोसाइटी' की स्थापना की जिसका उद्देश्य अंग्रेजों और भारतीयों का सम्पर्क बढ़ाना था। 1 दिसम्बर, 1866 को 'ईस्ट इण्डिया एगोसिएशन' की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश जनता और सरकार को ईस्ट इण्डिया से सम्बन्धित मामलों का सही ज्ञान कराना था और भारत के कल्याण में रुचि रखने वाले सभी लोग इसके सदस्य बन सकते थे। दादाभाई ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और जनता के सामने सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश का प्रश्न उठाया और यह प्रस्ताव किया कि भारत तथा इंग्लैण्ड दोनों स्थानों में सिविल सर्विस के लिए एक साथ प्रतिस्पर्धा-परीक्षा आरम्भ करने की व्यवस्था हो। विनयी अनुरोध प्राप्त यह अपेक्षा किया करते थे कि भारतीय उन्मत्ततापूर्ण पदों के योग्य नहीं हैं। उन्हें यह भय था कि योग्यता, ईमानदारी और कार्य-क्षमता की दृष्टि से अंग्रेजों की तुलना में भारतीय अनुपयुक्त हैं, लेकिन दादाभाई नौरोजी को भारतीयों की योग्यता और कार्य-क्षमता में पूर्ण विश्वास था और वे नहीं चाहते थे कि यूरोपीय एशियाई जातियों के सम्बन्ध में जो अनर्गत बातें कहा करते थे उन्हें दोहराएँ। दादाभाई ने "भारत में भारतीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता के प्रमाण" नामक पुस्तिका प्रस्तुत करते हुए अकादमिक प्रमाण पत्र दिए जिससे यह सिद्ध हो गया कि शासन

1 आर. सी. मसानी, पृ. 25

2 Poverty and Un-British Rule in India, p. 236.

3 Poverty and Un-British Rule in India, p. 201-202.

अंग्रेजों को उन अधिकारों को क्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। दादाभाई की राजनीतिक पद्धति में शान्तिप्रियता, विवेक, सन्तुष्टि, सयम और अहिंसा की प्रधानता थी। वे यह नहीं चाहते थे कि कोई आन्दोलन हिंसात्मक रूप ग्रहण करे अथवा असन्तुष्ट एवं असयम रूप में चले। दादाभाई यह जानते थे कि अवेज भौतने की नदी अशुभ कठने की भाषा समझत है, लेकिन वे यह जानते थे कि गणतन्त्र तत्त्वान्तर परिस्थितियों में नाटन की स्थिति में नारी से वे लगातार शौक कर विविध शरणों को जानने का प्रयत्न कर सकते थे। दादाभाई की यह अनुभूति थी कि भारत का राजनीतिक मुक्ति के लिए समर्थ बड़ा सम्यक उमेग और इस सम्ये रखे की सौझियाँ सने-सने एक-एक करके बढ़ते होगी। अभी प्रारम्भिक स्थिति थी अन्तिम समर्थ को नहीं। औद्योगिक आन्दोलन की दादाभाई की धारणा मोघले और फोरोनशाह मेहता जैसे उदारवादिश की धारणा से अधिक और व्यावहारिक थी। दादाभाई के औद्योगिक आन्दोलन में स्वदेशी और बहिष्कार के लिए स्थान था। उन्होंने इन दोनों का प्रभावपूर्ण समर्थन किया और 'बग-भग' से उत्पन्न बलावण में बौद्धिक की समिति स प्रस्ताव पारित करवाया जिससे नौवरा के उन्नायी और अनुशासकी दोनों पक्ष सन्तुष्ट हो गए। स्वराज्य की भाँषा और उतापाने के लिए स्वदेशी का बहिष्कार के राधा की उन्नाय करके के कारण दादाभाई का मग ह दोनों पक्षों के अधिक विचार समझे जाने लगे। दादाभाई ७५वें की दायापूर्ण नाल से निराश और न्यु होकर अधिक उदा हो गए और उनकी भाषा कठोर होती गई। उनकी आत्मा मग तान रहन करने वाली हो गई लेकिन दादाभाई ने अपना सन्तुला नदी रक्षण। उन्होंने ब्रान्तियों और हिंसमक प्रवृत्ति को नौ कक्षावा तथा औद्योगिक आन्दोलन के मार्ग से बँ बिचलित नहीं हुए।

बाल गंगाधर तिलक (Bal Gangadhar Tilak)

गौधार्जी ने कहा था कि "हमारे समय के किसी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के सन्देश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य।" प्रारम्भिक दिनों के राष्ट्रीय भाव पर बाल गंगाधर तिलक का अद्वितीय स्थान था और स्नेह तथा सम्मान से उन्हें 'लोकमान्य', 'जनता के मित्र' नामक, सर्व सम्मानित कहकर पुकारा जाता था—'लोकमान्य तिलक का राजनीतिक मन्त्र—'स्वशासन मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर हूँ'—'भारतीयों के होठों पर था। तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राजनीतिक आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए धार्मिक जोरा का प्रयोग किया।

जीवन परिचय (Life-Sketch)

लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कौण्डविले के तलागिरी स्थान पर ऐसे महाराष्ट्रीय पितृपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसका सम्बन्ध पेशवाओं से था। बाल्यावस्था से तिलक मेधावी और मखर बुद्धि के थे। 1879 में उन्होंने एन.ए. की बी. परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। कॉलेज जीवन से ही उनकी रुचि सार्वजनिक कार्यों की ओर बढ़ती गई और जब 18-वें पुष्पा गया कि गणित में एम.ए. न करके (चूँकि तिलक को गणित में अत्यधिक रुचि थी) वे कानून क्यों पढ़ रहे हैं उनका उत्तर था—'मैं अपना जीवन देश के जन-जागरण में लगाना चाहता हूँ और मेरा विचार है कि इस काम के लिए अहिंस्य अथवा विज्ञान की किसी उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान उपयोगी होगा। मैं ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें मुझे ब्रिटिश शासकों से संपर्क न करना पड़े।' अपने सार्वजनिक जीवन के चार दशकों में तिलक की सार्वजनिक विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में प्रस्तुति हुई। एक शिक्षाशास्त्र के रूप में उन्होंने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल दक्षिण शिक्षा समाज (Deccan Education Society) तथा फर्ग्युसन कॉलेज के व्यवस्थापक के रूप में व्यक्ति अर्जित की। अपने परिश्रम से उन्होंने महाराष्ट्र में एक सैशणिक प्रगति उत्पन्न कर दी। ओरिएण्टल सोसाइटी के लिए ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों की प्राचीनता सिद्ध करने वाले एक विद्वत्पूर्ण विषय 'वेदों का उद्गम स्थल उत्तरी ध्रुव' (The Arctic Home of the Vedas) के कारण दूर-विदेश में उनका ख्याति फैल गई। उनके 'गीता रहस्य' ग्रन्थ से उनकी छवि में वृद्धि हो गई थी।

लोकमान्य तिलक ने आर्थिक अन्याय के विरुद्ध लोहा लिया। 1896 के अकाल में लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया और कपड़ों के मच से आर्थिक मामलों से सम्बन्धित अपने महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जैसे—वितीय विकेन्द्रीकरण स्थायी बन्दार आदि। 1889 में बर्मिस में अपने प्रवेश के बाद बर्मिस के कार्य-कलापों में तिलक ने भूमिका अदा की। उदारवादियों की नीतियों से असन्तुष्ट तिलक ने अपनी शक्ति महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आन्दोलन को सुसज्जित करने में लगाई और भारतीय नवयुवकों में यह भाव भरने की चेष्टा की कि देश अपनी स्वतन्त्रता किसी की दया के बल पर नहीं, अपनी सामर्थ्य के बल पर अर्जित करे। 'अपने 'केसरी' तथा 'मसरा' नामक पत्र तथा 'शिवाजी और गणपति उत्सवों' द्वारा उन्होंने जाता में देशभक्ति

विचार था कि यदि वार्ता सफल न हुई तो अन्दोलन को पुनः छेड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार 1 उन्हें गिरफ्तार कर लिया और योजना असफल हो गई।

तिलक की समाज-सुधार पद्धति

लोकमान्य तिलक को समाज-सुधारकों का रुख पसन्द नहीं था। उन्हें इससे कह था कि समाज-सुधारक पारिवारिक विचारों को हिन्दू समाज में दृष्टान्त चाहते थे और हिन्दू धर्म तथा समाज के प्रति इनमें भ्रष्टाचार और उपेक्षा के भाव थे। तिलक परिवर्तन के पक्षपाती थे लेकिन उन आधारों को नहीं भंगना चाहते थे जो सुदृढ़ नहीं थे। सामाजिक परिवर्तन और सुधारों को स्वीकार करते हुए वे इस पक्ष में नहीं थे कि भारतीयों का परिचयपूर्ण कर दिया जाए। तिलक उन लोगों के विरोधी थे जो समाज-सुधार का आधार वेद-पुराणों में ढूँढ़ते थे और तिलक को उनके पाण्डित्य का घण्टाघण्ट करने में कठिनाई नहीं हुई।¹ तिलक इसके विरोधी थे कि राज्य द्वारा कर्मून बना कर सामाजिक सुधार लया जाय। तिलक सामाजिक सुधारों के स्वाभाविक विकास के हामी थे और यह नहीं चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तनों का निर्माण प्रशिक्षण से मिले। डॉ. कुमुद शर्मा का मत है कि "तिलक का कहना था कि हमारा उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करना तथा 'नवराज्य' को प्राप्ति होना चाहिए। स्वराज्य को प्राप्ति के बाद सामाजिक परिवर्तनों का क्रम आरम्भ करना चाहिए।"

सामाजिक दर्शन

तिलक के सामाजिक दर्शन के महत्वपूर्ण तथ्य थे—(1) वे सामाजिक परिवर्तन के विरोधी नहीं थे क्योंकि उन सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते थे जो परिचय के अन्वयानुकरण से होत, (2) तिलक ने राजनीतिक जागरण और राजनीतिक सुधारों को सामाजिक सुधारों की तुलना में प्राथमिकता दी क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक दो मोर्चों पर शक्ति को विभाजित करना उन परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं था, (3) सामाजिक सुधार सहज और स्वाभाविक रूप में होने चाहिए ताकि समाज में असन्तोष न फैले और सामाजिक संगठन में बाधा न पड़े एवं (4) तिलक नहीं चाहते थे कि भारत को टोस और पदार्थवादी भूमि पर आधारित था। वे उदार परम्परावादी थे। उनमें रुढ़िवादिता देखने को मिलती थी, क्योंकि तत्कालीन समाज वैसा था और उस समाज को अपने साथ लेकर विदेशी हुकुमत के खिलाफ शक्तिशाली मोर्चा बनाना आवश्यक था। तिलक एक प्रजातन्त्रवादी नेता थे जो जनमत का निरूपण करने में विश्वास नहीं करते थे। बदलते समय के अनुसार रुढ़िवादिता में भारतीय आधारों में आवश्यक परिवर्तन कर लिया जाए यह उन्हें अभीष्ट था। तिलक सामाजिक परिवर्तन क्रमिक और सावधानी रूप में पसन्द करते थे तथा परिचयीकरण की प्रवृत्ति के विरोधी थे।

तिलक के शैक्षणिक विचार और कार्य

(Educational Ideas and Works of Tilak)

लोकमान्य तिलक के मतानुसार, "पढ़ना-लिखना, सीख लेना ही शिक्षा नहीं है शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए, हमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव दे।" लोकमान्य तिलक महान शिक्षा-शास्त्री थे। वे और आगरकर महाराष्ट्र में शिक्षा-आन्दोलन के प्रणेता थे। शिक्षा के सम्बन्ध में मरमदलीय नेताओं के विचारों से तिलक सन्तुष्ट नहीं थे। नरम दल भारत में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के लिए अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञ था, जबकि तिलक और उनके उग्रवादी सहयोगियों की शिक्षायत थी कि यह प्रणाली छात्रों को देश की सही स्थिति से अवगत रखती है और उन्हें जीवन में किसी जीविका के लिए तैयार नहीं करती। तिलक शिक्षा ठीकी की मानते थे जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, उसमें देश के सच्चे नागरिक गुणा का संचार करे और पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव दे। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा की वकालत की। राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम का अंग रही थी और बाल्य के राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में इस स्थान दिए जाने से पहले तिलक, आगरकर तथा चिपलूणकर के मन में इसकी एक रूपरेखा बन चुकी थी। फर्ग्युसन दूनो ने न्यू इंग्लिश स्कूल और फर्ग्युसन कॉलेज की स्थापना हुई तथा दक्षिण शिक्षा समाज का निर्माण किया गया। तिलक के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा से राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकेगा, देशवासियों मनमानता से ऊँचे उठकर संगठित हो सकेंगे और देश की शक्ति को बढ़ा सकेंगे। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा का ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जो व्यावहारिक था और देशवासियों के स्वाभाविक विकास में सहायक था। राष्ट्रीय शिक्षा के सन्दर्भ में तिलक के मुख्य विचार बिन्दु निम्नांकित थे—

(1) उद्योग एवं प्राथमिक शिक्षा शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अंग बने

तिलक ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में चलने वाली पाठ्य-पुस्तकों से छात्रों को शिक्षा का भ्रम ज्ञात नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ, उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता कि आयात-निर्यात की शोषक नीति से विदेशी हुकुमत भारत का दष्टि बन

रही है और भारतीयों की जीविका खीन रही है। जहाँ दूसरे देशों में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है वहाँ भारतीय शिक्षण संस्थाएँ केवल अक्सर पैदा करने के लिए बने हैं। तिलक ने इसका आग्रह किया कि शिक्षा-पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए।

(iv) धार्मिक शिक्षा पर बल

स्वातन्त्र आन्दोलन में क्रान्तिकारी और नैतिक संपर्क करने वाले वर्ग प्राचीन ग्रंथों तथा प्राचीन कीर्तियों से प्रेरणा पाते दिखाई देते हैं। तिलक धार्मिक शिक्षा पर जोर देते थे और कहा करते थे कि "किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है, यदि वह उससे अनभिज्ञ है?" धार्मिक शिक्षा का अभाव इसका कारण है कि देशभर में मिशनरियों (इंग्लिश पादरियों) का प्रभाव बढ़ गया है।¹ तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से हाथ डेढ़े बढ़ते हैं। तिलक को मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और धारमिक कलह को दूर करने की कुंजी है। हिन्दुओं को सच्चे हिन्दु धर्म और मुसलमानों को सच्चे इस्लाम की शिक्षा देने से एक-दूसरे के धर्म के लिए सम्मान और सहिष्णुता का प्रसार होगा। तिलक के अनुसार चरित्र-निर्माण के लिए धर्मनिरपेक्ष (Secular) शिक्षा पर्याप्त नहीं है उसके लिए धार्मिक शिक्षा आवश्यक है।

(iii) स्वतन्त्र देशों जैसी शिक्षा प्रणाली पर बल

तिलक के अनुसार भारतीय शिक्षण-संस्थाओं में यदि स्वतन्त्र देशों जैसी शिक्षा-प्रणाली चालू की जाए तो इससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। कुछ और सरकारें शिक्षण संस्थाएँ तिलक के विचारों के अनुरूप शिक्षा-क्रम रखने को तैयारी करें, लेकिन उन्हें पथ था कि ऐसा करने से उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता बन्द हो जाएगी, अतः तिलक ने निम्नलिखित दिया कि "हमें अपने स्वतन्त्र स्वयं स्थापित करने चाहिए और अपना काम निस्वार्थ भाव से शुरू करना चाहिए।" तिलक चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस काम को हाथ में ले, परन्तु कांग्रेस कोई खतरा ठठाने को तैयार नहीं थी।

(iv) मातृभाषा को प्रधानता

तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। वे कहते थे कि "आज जो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी लिख सकेता है वही शिक्षित माना जाता है, किन्तु किसी भाषा का ज्ञान हो जाना शिक्षा नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है उसमें अब 20-25 वर्ष लग जाते हैं। अंग्रेजी हमें सीखनी है, पर उसकी शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कारण नहीं है। मुस्लिम राज में हमें फारसी सीखनी होती थी, पर उसे सीखने के लिए बाध्यता नहीं थी।"

(v) एक लिपि, एक राष्ट्रभाषा का समर्थन

तिलक का विश्वास था कि राष्ट्रभाषा राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है, अतः उन्होंने इसकी पैरवी की कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाए। उनके शिष्य सावरकर ने, जो इसी भाषा सम्बन्धी नीति के समर्थक थे वहाँ तक कि सन्धन के एक सम्मेलन में उन्होंने इसका आग्रह किया कि स्वतन्त्र के प्रस्ताव को अंग्रेजी में नहीं, भारत की सार्वजनिक भाषा हिन्दी में लिखा जाए। तिलक राष्ट्रीय एकता और भाषा-भेद से विभावित देश को एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा को महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। वास्तव में तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। दिसम्बर 1950 में काशी रागरी प्रकाशित सभा में एक वाक्य में उन्होंने कहा कि देवनागरी न केवल सभी आर्य भाषाओं की लिपि बल्कि राष्ट्रभाषा की लिपि भी बने। तिलक ने देश की भाषा समस्या पर विचार किया। उन्होंने देख लिया कि इसके मार्ग में क्या बाधाएँ हैं और उनका हल ढूँढ निकाला। कालान्तर में ये बाधाएँ उपस्थित हुईं और विधान-निर्मात्री परिषद ने उन्हें उसी उपाय से दूर किया जो तिलक ने सुझाया था। तिलक जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी-अपनी लिपि पर अटेंगे। उन्होंने देशवासियों से समान लिपि की राष्ट्रीय आवश्यकता के समक्ष क्षेत्रीय विरोधों को दबा देने की अपील की। एजनीश और जेल में फँसे रहने के कारण तिलक की एक लिपि और राष्ट्रभाषा का आन्दोलन चलाने के लिए समय नहीं मिला, पर उन्होंने सूर रूप में एक विचार प्रस्तुत कर दिया जिसका विकास बाद में हुआ। तिलक ने रोमन लिपि अपनाने का विरोध किया।

(vi) अंग्रेजी की महत्ता स्वीकार करना

राष्ट्रीय शिष्टा के पक्ष-पक्ष होते हुए भी तिलक अंग्रेजी के महत्त्व को अस्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था कि मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि विदेशी भाषा की शिक्षा छात्र समझ नहीं सकते, अन्यथा अंग्रेजी शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रगति और जागृति में प्रमुख रूप से सहयोगी है। अंग्रेजी सम्बन्धी तिलक के विचारों से ध्वनित होता है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में बंधनकारी विचारक थे।

तिलक का राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy of Tilak)

तिलक भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान करके कंग्रेस को एक जन-आन्दोलन के रूप में परिणत कर दिया। तिलक ने जन नेताओं के सामने एक रचनात्मक कार्यक्रम विकसित किया। उनके अनुसार "एशिया तथा ससार की शान्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि भारत को 'ए' शासन प्रदाता करने पूर्व में स्वतन्त्रता का गठ बना दिया जाए।" तिलक उग्र राष्ट्रवादी थे, लेकिन उन्होंने हिंसा और रक्तपात को प्रोत्साहन नहीं दिया। तिलक के राजनीतिक दर्शन को निम्नांकित बिन्दुओं में समझा जाना चाहिए—

तिलक के राजनीतिक चिन्तन के आधार

तिलक ने यथार्थवादी व्यावहारिक नेता की भूमिका अदा की। उदारवादियों की निर्मिथ्य नीति को प्रतिज्वल्य के रूप में तिलक ने सम्पूर्ण देश को मूर्त और गतिशील विचार देकर जन-जागरण उत्पन्न किया। वे मैकिन्गावेनी और हॉक्स की नीति यथार्थवादी नहीं थे अथवा उन्होंने प्लेटो, अरस्तू या सिसरो की नीति सर्वोत्तम राज्य के लक्षणों और सम्भावना का विश्लेषण नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीतिक दासता से मुक्ति था और एक व्यावहारिक राजनीतिक नेता के रूप में उनके कार्यकलाप रहे, उनकी चिन्तनधारा बड़ी। तिलक के राजनीतिक चिन्तन में भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख धारणाओं तथा आधुनिक यूरोप के राष्ट्रवादी और लोकतान्त्रिक विचारों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है।¹ तिलक के राष्ट्रदर्शन में एक ओर भारतीय चिन्तन की आधारभूत धारणाओं के दर्शन होते हैं और दूसरी ओर आधुनिक पारंपार्य राष्ट्रवादी एवं लोकतान्त्रिक विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। जॉन स्टुअर्ट मिल की राष्ट्रीयता की परिभाषा से तिलक सहमत थे। 1919 और 1920 में उन्होंने विल्सन (Wilson) की 'आत्म-निर्णय' की धारणा को स्वीकार करते हुए भारत में इसके व्यावहारिक प्रयोग की भाँगी की थी। तिलक मैजिनी और बर्क के विचारों से प्रभावित थे। तिलक के राष्ट्रवाद का दर्शन आत्मा की सर्वोच्चता के वेदान्तिक आदर्श और मैजिनी, बर्क, मिल तथा विल्सन की धारणाओं का सम्मिश्रण था। इस सम्मिश्रण को तिलक ने 'स्वराज्य' शब्द द्वारा व्यक्त किया।²

तिलक का चिन्तन आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित था अतः स्वाभाविक था कि उन्होंने स्वराज्य की नैतिक और आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की। तिलक ने स्वराज्य को केवल एक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक धर्म भी माना। राजनीतिक रूप में उन्होंने स्वराज्य का अर्थ स्वशासन (होम रूल) बताया, किन्तु नैतिक सन्दर्भ में इसका अर्थ आत्म-नियन्त्रण की पूर्णता माना जो कि सबसे बड़ा स्व-धर्म है। स्वराज्य का आध्यात्मिक महत्त्व बताते हुए तिलक ने कहा कि इसका आशय आत्मिक स्वतन्त्रता से है। स्वराज्य की प्राप्ति आत्मा की स्वतन्त्रता के आधार पर ही हो सकती है। वस्तुतः तिलक ने राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की स्वतन्त्रता की कामना की।

तिलक का राष्ट्रवाद और पुनरुत्थानवाद

तिलक की राष्ट्रीयता पुरातनवादी और पुनर्निर्माणवादी थी। उन्होंने वेदों और गीता से आध्यात्मिक शक्ति तथा राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करने का सन्देश दिया और भारत की प्राचीन परम्पराओं के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना करनी चाही। 13 दिसम्बर 1919 को 'मराठा' के अंक में उन्होंने लिखा कि "राष्ट्रवादी पुरानी नींव पर निर्माण करना चाहता है। जो सुधार पुनरुत्थान के प्रति असम्मान की भावना पर आधारित है, उसे राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपनी समस्याओं को अंग्रेजियों के ढाँचे में नहीं दफनाना चाहते, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते।"³ तिलक ने कहा कि भारतीय वेदों और गीता के महान् सन्देशों से नई शक्ति और नई स्मृति ग्रहण करें, क्योंकि तभी राष्ट्र वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकेगा जिसके बल पर ब्रिटिश नीतिवादी से लोहा लेकर, स्वराज्य की स्थापना सम्भव होगी। सुधार के नाम पर प्राचीन का अन्याय राष्ट्रियता के पतन का सूचक है। यदि भारत में राष्ट्रीयता का प्रसार करना है तो प्राचीन सस्कृत का पुनर्जागरण अनिवार्य है।

तिलक ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में आदिम जातियों में अपने कबीले के प्रति जो शक्ति रहती थी उसी का आधुनिक नाम राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का सम्बन्ध सभेगी और अनुभूतिशील से होता है। जो आध्यात्मिक प्रभाव और लगाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, वे अब राष्ट्रवाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गए हैं। जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है वह स्वस्थ राष्ट्रवाद है। तिलक की मान्यता थी कि विपारधाराओं, जाति-भेदों, मत-मतान्तरों आदि के कारण देश में राष्ट्रीयता की भावना उस तेज़ी से नहीं फैल सकती जिस तेज़ी से यह समान भाषा, समान धर्म और समान संस्कृति वाले देश में फैल सकती है। उन्होंने भारत को राष्ट्रीय एकता के लिए आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल दिया। वे तत्त्व प्राचीन काल से ही भारत में

1. 2. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, 'वेदों', पृ. 197

3. तिलक 'मराठा' पत्र

विद्यमान थे पर अब आवश्यकता उन्हें जगाने और संगठित करने की थी। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सवों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। राष्ट्रीयता के आवेश को आध्यात्मिक रंग देने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को जाग्रत किया और शिवजी की उपासना का पन्थ भी शुरू किया। गणपति उत्सव द्वारा उन्होंने एक धार्मिक उत्सव को सामाजिक एवं राजनीतिक अर्थ दिया तथा शिवजी उत्सव द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को संगठित करने का काम किया। तिलक के अनुसार उत्सव प्रतीक का काम करते हैं जिनसे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। उत्सवों का दोहरा महत्व है—एक ओर तो इनके माध्यम से एकता की भावना अभिव्यक्त होती है और दूसरी ओर उत्सवों में भाग लेने वाले व्यक्ति यह अनुभव करने लगते हैं कि उनके समूह और उनकी एकता को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि देशवासियों के भावों में तोड़ता साते हैं तथा इनकी राष्ट्रवादी भावना को प्रमुख नहीं होने देते। इसे राष्ट्रवाद का प्रतीकत्वपूर्ण प्रदर्शन कहा जा सकता है जिससे सांस्कृतिक अभिवृद्धि होती है और संपूर्ण राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। तिलक ने प्राचीन उत्सवों को आधुनिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बना कर ऐतिहासिक और नैतिक प्रतिष्ठा का सबल उदाहरण दिया।

तिलक का राजनीतिक उद्देश्य और आक्रामक राष्ट्रवाद

तिलक का राष्ट्रवाद उग्र और तेजस्वी था तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें उग्रवादी राजनीति तथा राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। तिलक ब्रिटिश सरकार को साम्राज्यवादी निरंकुश नीति को सहन नहीं कर सके। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के निरंकुश कार्यों की 'केसरी' में क्रोध आलोचना प्रकाशित की। उन्होंने स्पष्ट मत रखा कि ब्रिटिश सरकार पर प्रार्थनाओं और नम्र विवेदन का कोई असर होने वाला नहीं है अतः हमें अपनी मांगों को 'हक' (Right) के रूप में रखना चाहिए तथा दबावकारी उग्र साधनों (हिंसात्मक नहीं) का आश्रय लेकर विदेशी हुकूमत को यह सोचने पर मजबूर कर देना चाहिए कि भारतीयों की मांगों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। 1905 में बंगाल-विभाजन पर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का बिगुल फूटने का अवसर मिला जिसका उपयोग उन्होंने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने तथा ऐसे राष्ट्रवादी आन्दोलन का संचालन करने के लिए किया जिसमें सभी वर्ग और जातियों का योगदान हो और जो देश के हर मगर और गाँव तक फैला हो। बंग-भंग की घटना के बाद 'लाल-बाल-पाल' भारत में उग्र राष्ट्रीयता की विपुर्ति बन गए। पन्नाय महाराष्ट्र और बंगाल संगठित रूप में सरकार की नीति-नीति पर आक्रमण करने लगे।

ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई पर उग्रवादी आन्दोलन वेनी पकड़ता गया। तिलक ने 'स्वराज्य' का मंत्र फूँका। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए तिलक तथा उनके उग्रवादी साथियों ने इन चारों पर जोर दिया—(1) स्वदेशी (Swadeshi), (2) बहिष्कार (Boycott), (3) राष्ट्रीय शिक्षा (National Education) एवं (4) निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance)। यह कार्य नव राष्ट्रीय हस्त का माध्यम से किया जाने लगा जिसका मुख्य अंगार तिलक थे। 1905 से 1909 तक इस दल ने राष्ट्रीय शिक्षा, दलित वर्ग-उत्थान, राष्ट्रीय पत्रों की स्थापना आदि के विभिन्न आन्दोलन चलाए। तिलक ने अपने प्रयासों से कांग्रेस को एक जन-आन्दोलन में परिणत कर दिया और स्वाधीनता प्रमाण सिद्धित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चे-बच्चे की जवान पर यह नारा गूँज गया—“स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे।”

तिलक का उग्रवादी रुढ़ कांग्रेस के उदारवादियों से मेल नहीं खा सका। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन विखेद से पूर्व एक भाषण में तिलक ने कहा कि “हमारा उद्देश्य स्वशासन है और इसे शीघ्र प्राप्त करना चाहिए। हमारा राष्ट्र आत्मकथायी दमन के लिए नहीं है। आप भीरु और कायर न बनें। जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना होगा। हमारा उद्देश्य पुनर्निर्माण है, हमारा स्वराज्य का अदर्श विशिष्ट लक्ष्य है जिसे जन-समुदाय समझे। स्वराज्य में जनता का शासन जनता के लिए होगा। उदारवादियों डरिए मत। बहिष्कार दलित राष्ट्रों के लिए साधन है। हमारा तीसरा अदर्श राष्ट्रीय शिक्षा है जिसके सम्बन्ध में पिछड़ी कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था।” तिलक का विश्वास सगठन-शक्ति और आत्मनिर्भरता में था। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि वह राजनीतिक आन्दोलन चला कर सरकार पर दबाव डाले और मातृभूमि के लिए कष्ट एवं त्याग सहन करे। 2 जनवरी 1906 को कोलकाता में अपने एक भाषण में तिलक ने घोषणा की कि “प्रार्थनाओं और विरोध के दिन समाप्त हो गए हैं। हमारी प्रार्थनाओं को शासन नहीं सुनेगा क्योंकि उनके पीछे दुष्ट संकल्प का अभाव है। हमारा में परिवर्तन की आशा मन कीजिए। प्रार्थना प्रसन्नता से प्रयत्न करना प्रतिरोध (Prayer, Please and Protest) कोई ठीक काम नहीं करेगा। क्या आप यह आशा करते हैं कि विद्रुह निरंकुश तंत्र से वे प्रमुद तन्त्र की ओर बढ़ेंगे? ब्रिटिश जनता को शिक्षा देना बर्बर है शब्दों से उन्हें आप सन्तुष्ट नहीं कर सकते। बंग-भंग की शिक्षाएँ भारत का धावी आधार हैं। स्वदेशी हमारे अस्त्रिय पुकार है और इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे फिर चाहे शासक किताबी छे अनुसरी कर दे। शासन से मोर्चा लेने के दो उपाय हैं—“स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा।”

अत्याचारी हो जाते हैं, क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जानती। अगर वह एक होकर ऐसा करे तो शासक उसके सामने रजिंदार हो जाएंगे।¹ तिलक 'केसरी' में ऐसे लेख लिखते रहे जिनमें किसानों, मजदूरों, कारीगरों, दूकानदारों, जुलाहों, मोलों आदि की मुश्किल और उन्नति के लिए जिनाई ध्येय की गई थी। यह कहा गया था कि ये जातों के मुख्य अंग हैं और उनकी दशा में सुधार होना चाहिए।² जन-शक्ति को व्यक्त करते हुए केसरी के एक लेख में उन्होंने लिखा कि "अगर 500 लोग जुने हुए प्रतिनिधियों की तरह वर्ष में एक बार एकत्रित हो और प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें तो सरकार कोई प्रार्थना स्वीकार न करेगी। ऐसा प्रार्थना-पत्र तभी वजस्टार हो सकेगा जबकि ग्रन्थों, जिलों, नगरों और गाँवों से प्रार्थना-पत्र उरलना सम्पूर्ण करे।" शिक्षितों से उनका अप्रार्थ था "आप जनता के स्वाभाविक नेता हैं। आपको उनकी झीपड़ियों तक जाना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें संगठित करना चाहिए और उनकी दशा में सुधार करना चाहिए। स्वयं को जनता से इसलिए अलग समझना कि हमने कुछ पुस्तकें पढ़ ली हैं, भूर्खतापूर्ण है। हम उनमें में हैं और हमें उनमें के बीच रहना चाहिए।"

तिलक का कहना था कि यदि जनता संगठित होती है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहती है तो शासक आतंकवादी नहीं बन पाते और जनमत को सन्तुष्ट करने की फिक्र में रहते हैं। तिलक ने पत्रकारिता द्वारा जनता में चेतना फैलाने और उसे स्वायत्त के प्रति सचेत किया।

पेरिस-शान्ति सम्मेलन की ज्ञापन

तिलक ध्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे जो राष्ट्र के हित के लिए कोई अवसर नहीं चूकते थे। अवसर आने पर वे अवैधानिकता की पद्धति का भी प्रयोग करते थे। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर पेरिस में हुए शान्ति सम्मेलन के अध्यक्ष को उन्होंने एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सम्मेलन में सरकार द्वारा धनोन्नत व्यक्ति (बीकानेर भोरा और एम. पी. सिन्हा) भारत का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस ज्ञापन में तिलक ने एशिया और विश्व की राजनीति में भारत की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया और भारत के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार की माँग की।

1919 के अधिनियम के प्रति तिलक का रुझ और

कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का घोषणा-पत्र

1919 के मोष्टफोर्ड सुधारों के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक ने व्यावहारिक राजनीतिज्ञता का परिचय देते हुए कहा कि नौकरशाही द्वारा भारत को जो दिया जा रहा है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और अपना आन्दोलन जारी रखना चाहिए ताकि 'स्वराज्य' का सङ्घ प्राप्त किया जा सके। तिलक ने गाँधीजी की 'असहयोग' सहयोग की पेशकश पसन्द नहीं की। उनका तर्क था कि सहयोग एक पर्याय नहीं, पारस्परिक होगा है। "सत्ताधारियों को यह घोषणा करने दो कि वे किस प्रकार हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं और हम उन्हें विश्वास दिलवायेंगे कि यदि वे सहयोग करते हैं तो हम उनके साथ सहयोग करेंगे।" अमृतसर कांग्रेस में तिलक, गाँधी आदि के विचारों को सम्मान देते हुए यह घोषित की कि मोष्टफोर्ड सुधार यद्यपि अपर्याप्त, असन्तोषजनक और निराशाजनक हैं, लेकिन देश को उन्हें क्रियान्वित करने में अपना सहयोग देना चाहिए ताकि पूर्ण स्वराज्य की यथारोपी स्थापना हो सके।

तिलक ने अमृतसर कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप कार्य शुरू किया और मोष्टफोर्ड सुधार योजना के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली विधान-परिषदों के लिए चुनाव लड़ने हेतु 'कांग्रेस लोकतन्त्री दल' (कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी) की स्थापना की। 20 अप्रैल, 1920 को इस दल का घोषणा-पत्र जारी किया गया जिसमें मुख्य बिन्दु निम्नांकित थे—(1) कांग्रेस में आस्था, (2) प्रजातन्त्र का आरम्भ, (3) शिक्षा का प्रसार, (4) गतिविधियों का विस्तार, (5) धार्मिक सहिष्णुता, (6) राष्ट्रसंघ के निर्माण का स्वागत, (7) 1919 के अधिनियम का बहिष्कार, (8) शिक्षा, आन्दोलन और संगठन का नारा, (9) सामाजिक और धार्मिक न्याय प्रदान करना, (10) अधिकारों को उचित धेतन, (11) रेलों का राष्ट्रीयकरण, (12) नागरिक सेना एवं (13) भाषाई आधार पर प्रान्तों का गठन।

क्या तिलक भारतीय अशांति के जनक थे?

सर वेलेन्टाइन शिरोस ने अपनी पुस्तक 'इण्डियन अनरेस्ट' (भारतीय अशांति) में तिलक को 'भारतीय अशांति का जनक' (Father of Indian Unrest) की उपाधि दी है और कहा है कि वह कट्टर हिन्दू धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद के महान् पुजारी थे तथा सरकार के प्रति जनता में द्वेष फैलाने वाले आक्रुतों में से एक थे।

तिलक के चिन्तन उनकी कार्य-शैली और उनके कार्यकलापों के विवरण से स्पष्ट होता है कि तिलक का उद्देश्य किसी सरासरी विद्रोह को फैलाना नहीं था। तिलक हिंसक क्रान्ति पैदा नहीं करना चाहते थे। तिलक जनता को इस सीमा तक उग्र नहीं करना चाहते थे कि वह हथियारों का सहारा ले। तिलक वैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर भारतीय जनता

काकावास से मुक्त होकर सार्वभर वित्तक के लोकतांत्रिक स्वतन्त्र दल में सम्मिलित हो गए और बाद में हिन्दू महासभा को सदस्यता स्वीकार कर ली। दिसम्बर, 1937 में वे अहमदाबाद अधिवेशन में हिन्दू महासभा के प्रधान चुने गए। अल्पकाल के तीन वर्षों में बीर सावरकर ने हिन्दुओं में हिन्दू राष्ट्रवाद और संगठन की भावना का संचार करने के लिए परिश्रम किया। 26 फरवरी, 1966 को इनका देहान्त हो गया।

हिन्दुत्व का सिद्धान्त (Theory of Hindutva)

यार सावरकर हिन्दुत्व और हिन्दू राष्ट्र के समर्थक थे तथा हिन्दू सांस्कृतिक और दार्शनिक उपलब्धियों में उन्हें विश्वास था। उनके जीवन जेल में निकलकर लेकिन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग का जो अवसर मिला, उन्होंने हिन्दुओं को संगठित करने एवं राष्ट्रवाद की भावनाएँ भरने का प्रयास किया। हिन्दुओं का पुनरुत्थान उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। सावरकर ने अपनी पुस्तक हिन्दुत्व में हिन्दू की परिभाषा करते हुए कहा कि "हिन्दू वह है जो सिरु नदी से समुद्र तक सम्पूर्ण भारतवर्ष को अपनी विनयभूमि और पुण्यभूमि मानता है।" सावरकर ने हिन्दुत्व अथवा हिन्दू होने की तीन कसौटीयों बताई—

(I) राष्ट्र अथवा प्रादेशिक एकता—सावरकर का विश्वास था कि प्रादेशिक सन्निभता एकता की भावना का सञ्चार करती है। एक हिन्दू के मन में भिन्न से बहुत कुछ तक और हिमास्य से अत्यन्तुमर्ष तक सम्पूर्ण भौगोलिक प्रदेश के प्रति अनुत्तम होता है।

(II) जाति अथवा शक्त सम्बन्ध—हिन्दू वह है जिसकी नसों में उन लोगों का रक्त बहता है जिसका मूल स्रोत वैदिक सप्तसंघ के हिमालय प्रदेश में बसने वाली जाति थी। सावरकर ने किसी जातिगत या नस्लगत श्रेष्ठता का सिद्धान्त प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि इस तथ्य पर बल दिया कि सदियों के ऐतिहासिक जीवन के फलस्वरूप हिन्दुओं में ऐसी जातिगत विशेषताएँ विकसित हो गई हैं जो जर्मनों, चीनियों अथवा इण्डोपोषियाइयों से भिन्न हैं।

(III) सत्कृति—जिस व्यक्ति को हिन्दू सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है वह हिन्दू है।

उन्होंने कमिश्नर द्वारा प्रतिपादित 'भारतीय राष्ट्रवाद' के विचार से असहमति प्रकट की जिसके अनुसार राष्ट्रवाद प्रादेशिक होता है अतः भारत में उत्पन्न और पोषित सभी व्यक्ति बिना जाति और धर्मपरक के भारतीय राष्ट्र का निर्माण करते हैं। सावरकर ने कहा कि राष्ट्रीयता के लिए प्रजातीय, भाषाई, धार्मिक तथा अन्य एकता का होना अनिवार्य है। यदि जनता पर प्रादेशिक राष्ट्रीयता थोपी जाए, जैसा कि पोलेण्ड और चेकोस्लोवाकिया में किया गया तो राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता।

सावरकर ने कहा कि हिन्दुत्व वह धनु है जिसे छोपा नहीं जा सकता। हिन्दुओं में सदियों से जो विशेषाण और प्रजातिक तत्व विकसित हो चुके हैं, उनके आधार पर हिन्दुत्व को पहचान सकते हैं और जाति छो देने के बाद यह विनश्वर नहीं हो सकता। भारतीय राष्ट्र जैसा न कुछ है और न हो सकता है। इस देश में हिन्दू राष्ट्र रहा है और भविष्य में हिन्दू राष्ट्र ही रहेगा। सावरकर ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता से पीड़ित होकर बताया कि मुसलमान और ईसाई भारत को इस तरह ध्वस्त नहीं कर सकते जिस तरह हिन्दू करते हैं। ऐसा कहने में सावरकर के हृदय में मुस्लिम गमात के प्रति पूर्ण नफरत थी। सावरकर हिन्दुओं और मुसलमानों में प्रेम और सहिष्णुता का वातावरण देखना चाहते थे लेकिन भारत में सदियों से मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश हुकूमत तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि विदेशी से आई जाति भारत को उतना ध्वस्त नहीं कर सकती जितना इसी देश में जन्मी हुई जाति। सावरकर उन मुसलमानों के प्रति पूर्ण आदर रखते थे जिनके हृदय में भारत से प्रेम था जो भारत के लिए उसी प्रकार मर मिटने को तैयार थे जिस प्रकार हिन्दू। सावरकर ने कहा कि मुसलमानों का भारत भूमि के साथ कोई भावनात्मक सम्बन्ध नहीं है। सावरकर का कथन उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को पीड़ा पहुँचाने वाला था जो भारत से ध्वस्त करने के देश के विधाजन को आत्मघातक मानते थे और जिनमें साम्प्रदायिकता नहीं थी। बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं से पृथक् मुस्लिम राज्य के निर्माण की माँग ने सावरकर के विचारों को सत्य सिद्ध कर दिया।

सावरकर को तुष्टीकरण की नीति में विश्वास नहीं था। वे मुसलमानों के सहयोग का स्वागत करते थे लेकिन उन्हें विश्वास था कि स्वराज्य मुसलमानों के सहयोग के बिना प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि "हिन्दू अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए यथासामर्थ्य संपर्क करते रहेंगे। यदि तुम साथ देते हो तो तुम से मिलकर संपर्क करेंगे यदि तुम साथ नहीं देते तो तुम्हारे बिना लड़ते रहेंगे और यदि तुम विरोध करोगे तो उन विरोध के बावजूद युद्ध जारी

रखेंगे।" सावरकर ने मिश्रित विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जिसमें अङ्ग्रेजों के बालक सर्वत्र हिन्दू बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ग्लासगो जिले में जो मिश्रित विद्यालय स्थापित हुए उनके प्रभाव स्वरूप वहाँ विदेशी मिशनरियों द्वारा हिन्दुओं को ईसाई बनाए जाने से व्यक्तियों की संख्या गण्य हो गई और अनेक मिशनरियों को अपना कार्य बन्द कर देना पड़ा। सावरकर ने हिन्दुत्व का सेवा और राष्ट्र की सेवा के बीच पक्का सम्बन्ध स्थापित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जितना हिन्दू होगा, वह उतना देश-भक्त होगा। स्वतन्त्र और स्वाधीन भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि हिन्दुत्व का विकास किया जाए। हिन्दुत्व मानव-सम्पत्ता को प्रकाश में लावेगा है। सावरकर ने यह कहा कि यदि हिन्दुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और अन्य जातियों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वह हिन्दुत्व के लिए अहितकर होगा। सावरकर ने राजनीति का हिन्दूकरण कर दिखाया। 'वीर सावरकर ने हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के रूप में देश को राजनीति के हिन्दूकरण तथा हिन्दुओं के सैनिकीकरण का मार्ग दिखाया।' उनका इस बारे में सर्वोपरि साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का द्योतक माना गया, पर वास्तविकता यह थी कि सावरकर हिन्दुत्व के पुनर्जागरण में आस्था रखते थे, हिन्दू सामाजिक संगठन में प्रवेश करके बुराईयों को मुक्त करने के आकांक्षी थे, गुगलगांनों के प्रति उनका कोई दुर्भाव नहीं था। उनकी पूर्णा थी कि मुस्लिम लोग जैसे कटारपक्षी धार्मिक सम्प्रदाय तथा ब्रिटिश शासन को 'फूट डालें और राज करें' की नीति से। सावरकर चाहते थे कि समानता की चढ़ाई करने वाले मुसलमान देश के विभाजन की भाँति त्याग कर संगठित और राजशाही शासन के निर्माण का प्रयास करें।

सावरकर और अहिंसा

(Savarkar and Non-Violence)

वीर सावरकर क्रान्तिकारी थे किन्तु गौरीचंद अहिंसा में विश्वास नहीं था। डॉ. वर्मा के अनुसार, "सावरकर विरुद्ध अहिंसा के पक्ष के आलोचक थे और उसे भिन्नियों का पक्ष मानते थे। उनका कहना था कि सत्ता और देवदुर्ग की दुनियाँ में हिंसा को अपनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किन्तु अन्तर्विरोधों और बुराईयों से पर्याप्त इस जगत् में न्याय के छाँटने की गई हिंसा उचित है।" सावरकर का विचार था कि यदि अन्य बातें समान रहें, तो सैनिक शक्ति से सम्पूर्ण राज्य प्रगति और बराबरी का अर्थ कर सकते हैं, दुर्बल राज्यों की पतन और पराधीनता का मुख दर्शाता है। अपने मत की पुष्टि उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर की। जब भारत में अहिंसावादी चोटमन की प्रधानता रही तो उसे हूणों और शर्कों ने रौंद डाला, इसीलिए सावरकर ने हिन्दुओं के सैनिकीकरण का समर्थन किया और द्वितीय महायुद्ध के दौरान हिन्दुओं की फौज में पठान होने की सलाह दी, क्योंकि वे आधुनिक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग सीख जाएँ। सावरकर ने स्कूनों और कॉलेजों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा का समर्थन किया। क्रान्तिकारी सावरकर को दासता को वैधता दान देने के लिए हिंसात्मक साधनों का आश्रय लेने में तनिक भी हिचक न थी। उन्होंने क्रान्तिकारी विचारों का समर्थन तथा अहिंसक साधनों का अस्वीकार किया।

अखण्ड भारत

वीर सावरकर ने अखण्ड अखण्ड भारत की कामना की। अपने अन्तर्गत प्रदासों के बावजूद सावरकर देश का विभाजन नहीं होक सके। क्योंकि वे देश के विभाजन की योजना स्वीकार की और सावरकर ने कहा—“है देशकामियों! भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिसका जन्म राष्ट्र को सुसंगठित करने के लिए हुआ था अपने लक्ष्य के साथ विरसताप किया है। उसने अपने अस्तित्व के मौलिक को खो दिया है तथा कृत्रिम राष्ट्रीयता के रोग का शिकार बनकर देश को राष्ट्रीय अखण्डता पर आपात किया है।” देश का विभाजन हो जाने पर सावरकर ने अखण्ड भारत के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी और अगस्त 1947 में एक हिन्दू सम्मेलन आयोजित करके अपने आध्यात्मिक धारण में हिन्दुओं से अपील की कि वे पाकिस्तान को इसी प्रकार स्वीकार न करें जिस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश शासन को स्वीकार नहीं किया था।

सावरकर का योगदान स्वतन्त्रता के लिए

सावरकर के उग्र और क्रान्तिकारी विचारों, हिन्दुत्व के प्रति असीम जोश आदि के कारण उन पर छोटकारों की गई, पर उन्हें अपने भारत देश से अग्रगण्य प्यार था अपने देश के लिए सब कुछ चुटु देने की तनमें सम्मन थी और वे किसी कीमत पर देश का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों से शृंगार नहीं की, उन्होंने साम्प्रदायिकता को उठाया नहीं, पर उन्हें यह महान नहीं था कि हिन्दुओं के साथ विश्वासघात किया जाए, हिन्दुओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए, हिन्दुओं की सम्पत्ति लूटी जाए, हिन्दू मौज-महिर्नों की इज्जत पर हाथ डाला जाए और हिन्दुओं को निर्बल और अशक्त बनाए रखने के प्रयास सफल हों। वे अत्यधिक जोशीले थे और जोश के प्रभाव में बहकर ऐसा कह देते थे जिन्हें व्याख्या प्रस्तुत करना सम्भव था।

जब कॉंग्रेस 1937 के चुनावों में भाग लेने को तैयार हुई तब जयप्रकाश ने कॉंग्रेस को छोड़ दिया। 1942 में गाँधीजी ने 'क्रो और मरो' का आह्वान किया। उस समय जयप्रकाश इलाहाबाद जेल में नजरबन्द थे। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया। वे 18 सितम्बर, 1943 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए। उन्हें एक अप्रैल, 1946 को जेल से रिहा किया गया। उनकी सेवाओं और त्याग से प्रभावित होकर 1946 में गाँधीजी ने कॉंग्रेस के राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया, किन्तु कार्यसमिति ने यह स्वीकार नहीं किया। देश की स्वातंत्रता के पश्चात् उन्होंने सरकार में किसी पद पर बने रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस छोड़कर भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई जिसे प्रजा समाजवादी पार्टी का रूप लिया। 1952 में विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाए जा रहे सर्वोदय आन्दोलन की तरफ आकर्षित हुए। वे दलगत और सत्ता की नीति से निराश हो गए थे। सर्वोदय आन्दोलन से उन्हें व्यावहारिक जीवन में उतरने का अवसर मिला। अप्रैल, 1954 में उन्होंने अपने जीवन को सर्वोदय आन्दोलन के प्रति समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। प्रजा रोशलिस्ट पार्टी के नेता पद का त्याग करके उन्होंने 1954 में शोहोर में एक आश्रम स्थापित किया और सर्वोदय आन्दोलन एवं ग्रामोत्थान के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुआत की। 1970 और 1972 के बीच उन्होंने अपना समय और शक्ति बिहार के भुजपुरपुर जिले में नक्सलवादी विद्रोह को समाप्त करने में लगाई। 1972 के आरम्भ में इसके आदर्शों से प्रेरित होकर चम्पन घाटी के 400 टाकुओं ने इनके सनस आत्म-समर्पण कर दिया।

मार्च, 1974 में बिहार में उत्पन्न विद्रोह के फलस्वरूप जयप्रकाश को पुनः राजनीति में उतगा पड़ा। सरकार की नीतियों के विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने छात्र सभ्य समिति का नेतृत्व किया। यह सभ्य एक वर्ष जारी रहा। जून, 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाने के लिए दोषी ठहराया था, तब विपक्षी दल के नेताओं ने उनके त्याग-पत्र की माँग की थी। गैर-कम्युनिस्ट विरोधी दल के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में दिल्ली में 23 जून, 1975 को बैठक बुलाई। बैठक में श्रीमती गाँधी से त्याग-पत्र माँगने के लिए विशाल आन्दोलन के कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया। 26 जून, 1975 को देश में आन्तर्गत आपत्त स्थिति घोषित कर दी गई और जयप्रकाश नारायण और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को नजरबन्द कर दिया गया। गम्भीर रूप से बीमार पड़ जाने पर 12 नवम्बर, 1973 को जयप्रकाश को जेल से रिहा कर दिया गया। 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा की गई। जयप्रकाश आगे आए और जनता पार्टी के गठन में सक्रिय सहायता की। जनता पार्टी ने चुनावों में विजय प्राप्त की और केन्द्र में नई सरकार बनाई। जयप्रकाश को चुनावों के पश्चात् 'लोकनायक' के नाम से जाना जाने लगा। जेल में बन्दी होने के दौरान उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई। विशिष्ट उपचार के लिए मई, 1977 में वे अमेरिका गए और स्वास्थ्य लाभ के बाद स्वदेश लौट आए।

अस्वस्थ होने के बावजूद वह अपने विवेक और दार्शनिकता से राष्ट्र को दिशान्तर निर्देश देते रहे। राष्ट्रीय मामलों में वे रुचि लेते रहे और अपने अनुभव और राय देते रहे। जनता सरकार के विभिन्न घटकों की आपसी फूट से वे निराश होते गए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जनता सरकार आपसी फूट के कारण जन-आकांक्षाओं पर खरी नहीं उठती है। जयप्रकाश का 8 अक्टूबर, 1979 को निधन हो गया।

आधुनिक लोकतन्त्र पर विचार (Thought on Modern Democracy)

जयप्रकाश नारायण ने आधुनिक लोकतन्त्र और उसकी राजनीति पर प्रहार करते हुए फरवरी, 1970 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने दीक्षन्त भाषण में कहा था कि "आज की राजनीति में विमृशलता फैलती जा रही है। दलों के अदरों के विस्तार का अपेक्षा उनका स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण आदर्शों का अवमूल्यन, व्यक्तिगत तथा विशेष हितों के लिए दल-निष्ठा का परिवर्तन, विधायकों का क्रय-विक्रय, दल की आन्तरिक अनुशासनहीनता, दलों के बीच अवसरवादी मित्रता तथा सरकार की अस्थिरता आदि आज के विचारणीय विषय बन गए हैं।" जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतन्त्र की समस्या नैतिक समस्या है। लोकतन्त्र के लिए सविधानों, शासन-प्रणाली, दलों और चुनावों का महत्व है, लेकिन जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का समुचित विकास नहीं हो जाता तब तक वे वांछित फल नहीं दे सकती। लोकतन्त्र का सफल संचालन तभी सम्भव है जब देश के नागरिक सदाशिव हों, अहिंसावादी, स्वतन्त्रता-प्रेमी हों तथा दमन का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने की उनमें क्षमता हो, वे सहयोग और सहप्रतिद्वन्द्व में पूर्ण विश्वास रखते हों, उनमें दूसरों के कियारों को सुनने, समझने तथा सहन करने की क्षमता हो, वे कर्तव्यपरायण हों, उनमें उदारदर्शित्व की भावना हो और सीधा तथा सरल जीवनयापन करने में वे श्रद्धा रखने हों तथा मानव अधिकृत्य और समानता की भावना से पूर्ण हों।

जयप्रकाश की दृष्टि में आधुनिक ससदीय पद्धति अनुपयुक्त है जो दलगत राजनीति पर कार्य करती है और "अनुभव यह बतलाता है कि आज के व्यापक निर्वाचनों में जिनमें शक्तिशाली केन्द्र-नियन्त्रित दलों द्वारा प्रचुर धन और कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग किया जाता है, सदाता की अपेक्षा दलों और प्रचार-साधनों के पीछे निहित शक्ति तथा हितों का

प्रतिनिधित्व होता है।¹ जयप्रकाश के अनुसार जीकराही बनकर होती जा रही है तथा सर्वोच्च अधिकारियों और कर्मचारियों पर जनता की निर्भरता बढ़ रही है। प्रजापिता का खेदा सेवक का न होकर स्वामी का होना जा रहा है। व आधुनिक लोकतन्त्र में राजनैतिक दलों की भूमिका स असन्तुष्ट है। यह दलगत राजनीति जनता के नैतिक चरित्र को गिराती है और उसे स्वातंत्र्य मानव विचार और अधिष्ठातृ का कल्याण प्रश्न नहीं कराती। राजनैतिक दल और उनकी कार्यप्रणाली इस प्रकार है कि जहाँ उनके आगे आवाहण बन गई है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार आज का भारत लोकतन्त्र नहीं दलतन्त्र (Partyocracy) है जहाँ धन सगठन और प्रचार पर आधारित राजनैतिक दल शासन करता है। जयप्रकाश के अनुसार भारत में सेक्टर ग्राम-पंचायत तक वास्तविक लोकतन्त्र के सूत्र के लिए और मार्गीकृत की भाँति पैदा करने के लिए प्रत्येक जगह पर एक साथ सत्याग्रह चलाया जाना चाहिए। राजनैतिक दलों के विरुद्ध लिए गए सत्याग्रह में जनता यह समझ पाएगी कि वे स्वकार के स्वामी हैं अथवा गलत सेवक हैं। जयप्रकाश का यह मुद्दा यह था कि राजनैतिक दलों को स्वयं एक आत्म-निषेध अध्यादेश (Self denying Ordinance) पास करा जाए जिसमें कहा गया हो कि स्थानीय सभाओं के मण्डलों से स्वयं को दूर रखें और वे जन-इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल हों। ठाँके प्रमाण नियंत्रण के अधीन होंगे।

जयप्रकाश आधुनिक निर्वाचन पद्धति के विरुद्ध थे। उनका विश्वास था कि वे निर्वाचन जनता की नियंत्रणकारी सत्ता नहीं रखते। वर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में दोष है। इनका जनता की कोई वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती। एक का आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओं के शक्तिपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक है कि आम चुनाव की पद्धति को सफल किया जाए। वर्तमान निर्वाचित सभ्य कार्य करते रहें उनमें से कुछ सभ्य साधारण से बच गए हैं। शक्ति का हस्तारण और प्रशासन का विवेकाकरण सब तक नहीं हो सका जब तक कि स्थानीय प्रशासन के केन्द्र तथा सभाओं का शासन नहीं होती और जब तक कि सरकार के विधायन अंगों में वैधानिक तथा सत्ता सम्पन्न न हों। ग्राम-सभा तथा ग्राम-सभा-परिषद् के माध्यम से चुनाव होने चाहिए। इस सम्बन्ध में जयप्रकाश नारायण ने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जो इस प्रकार है—ग्राम-सभा परिषद् द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार का नाम उस क्षेत्र की समस्त ग्राम-सभाओं का मेल लिए जाए और तत्पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार के नाम पर मतदान हो। जयप्रकाश के अनुसार निर्वाचन विधियों में स कोई विरूपण अपनाया जाए—

(1) "सर्वाधिक मत प्राप्त उम्मीदवार के सम्बन्ध में एक घोषणा प्रेषित की जाए कि ग्राम-सभा उम्मीदवार सभ्य ५ लिए उसे प्रतिनिधि के रूप में चयन चाहती है। ऐसे सभी उम्मीदवारों में से जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हों उस मत पर राज्य-विधायिका का संसद (जिसने लिए वह चुना गया है) के लिए सभ्य घोषित किया जाए।

(2) ग्राम-सभा की बैठक में प्रत्येक उम्मीदवार को मिलने वाले मतों को नोट किया जाए ताकि दूरे निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न ग्राम-सभाओं की बैठक में प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्यक्ष मत मिले जा सके और सर्वाधिक मत-प्राप्त व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हो।²

जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तावित यह निर्वाचन-पद्धति ग्राम-सभा को प्रशासकीय मशीनरी का मूल आधार मानकर चलता है और लोकतन्त्र के दूसरी स्तर को भिन्न स्तर से मिलाती है। जयप्रकाश जी के शब्दों में यह ग्राम-सभाओं को स्थानीयता से ऊपर उठती है और उन्हें सम्मान, शक्ति एवं महत्त्व प्रदान करती है। नागरिक प्रवृत्तता परिणत और ग्राम-सभा के माध्यम से निर्वाचन में संगठित रूप से भाग ले सकना है। उनके अनुसार राज्य का हाथ ग्राम-सभा पर आधारित होना चाहिए न कि पृथक् बिछे हुए मतदाता। हमारे लोकतन्त्र की मुख्य समस्या यह है कि हम किसी प्रकार "मनुष्य को मनुष्य के सम्पर्क में लाएँ ताकि वे परस्पर सार्थक, स्विकृतपूर्ण और निर्यन्त्रित सम्पर्क रखते हुए रह सकें। जयप्रकाश नारायण दल-निर्षेध लोकतन्त्र के समर्थक थे तथा इस बात को मानते थे कि मतदाताओं का कर्तव्य मतदान के साथ सम्पर्क नहीं हो जाना, बल्कि निर्वाचन प्रतिनिधि और मतदाता के बीच निर्याप्त सम्पर्क रहना चाहिए ताकि वे ठारणित्व का निरोध कर सकें।

जनतन्त्र समाज (Jantantira Samaj)

1954 में जयप्रकाश नारायण दलीय राजनीति से विमुख रहे पर अपने विचारों को व्यावहारिक काम पहचाने की आकांक्षा रही और परिणामस्वरूप अप्रैल, 1974 में जनतन्त्र समाज के रूप में एक निर्दलीय संगठन स्थापित किया गया। जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से 1973 में कुछ बुद्धिजीवी राजधानी में एकत्रित हुए और एक निर्दलीय संगठन बनाने की योजना बनाई। जयप्रकाश के नेतृत्व में यह स्वयं 23 अप्रैल, 1974 को पुरा हुआ जब राजधानी के गौधी प्रतिनिधित्व

1 Ja prakash Narain, Soc & Econ Sarvodaya and Democracy p 215

2 निर्वाचन अध्याय के लेख से उद्धृत, पृष्ठ 52

3 पृष्ठ 53

जनता को शिक्षित और संगठित करने की कोशिश कर रहा है ताकि जनता अपने कर्म से अपने जीवन में परिवर्तन ला सके और उसे बेहतर बना सके। सामाजिक परिवर्तन का यह पथ है जिससे और परम्परागत राजनीति ने बहुत कम ध्यान दिया है। राजनीति कानून और प्रशासन की प्रक्रिया अपेक्षा और विकास पर अभिज्ञ रही है। कानून या प्रशासन जनता के सक्रिय संयोग के बिना नहीं हो सकता। जब तक जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरण पैदा हो तो वह संगठित नहीं हो सकती। बिहार आन्दोलन सघर्ष संघर्षियों और जनता सरकार के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है।"

बिहार आन्दोलन अनेक कमजोरियों का शिकार बना। इसमें छात्र अतिशय पर ज्यादा बल दिया गया। प्रदर्शन क्षेत्र आग बझा लेकिन शहरी क्षेत्र नहीं। फिर भी आन्दोलन जयप्रकाश के व्यक्तिगत बल बहुत दूर तक फैलित हो गया। उसका फल यह हुआ कि अल्पसंख्यक के कारण जब जयप्रकाश सक्रिय नहीं हो पा रहा थे, उनके इर्द गिर्द की भीड़ बढ़ रही थी। जनता पार्टी ने लोकप्रियता की आशाओं पर बुलबुल किया और उन्हें कहना पड़ा कि "जनता पार्टी हमारे आन्दोलन के गर्भ से पैदा हुई है, इसलिए उसकी सफलता विफलता के लिए हम जिम्मेदार हैं, विशेषकर वे सुबह और छात्र जिन्होंने आन्दोलन में जनता पार्टी के निर्माण में उदात्त उत्सवों के बिना करने के अभियान में हिस्सा लिया है। जनता पार्टी जिस दंग से और जिस रूप से बनी है वह अपनी वर्तमान गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। जनता पार्टी में जो अभिभाषार्थ जनता ने की थी वे पूर्ण नहीं हुई। रूपा आज कुछ हाथों में केन्द्रित है। जब तक सत्ता का केन्द्रीयकरण होगा, तब तक तानाशाही का खतप बना रहेगा इसलिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण जरूरी है। इसके अलावा अर्थिक, सामाजिक समस्याओं के हल की दिशा में वह विशेष कुछ नहीं कर पाई है। इस कारण जनता में असन्तोष फैल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, मुझे जनता को तथा अन्य आन्दोलनकारियों को क्या करना चाहिए, यह एक विधार्मिक प्रश्न है।"

सेना संविधान के लिए

अप्रैल, 1975 के अंतिम सप्ताह में अपनी ठंडीसा यात्रा के दौरान जयप्रकाश ने विचार प्रकट किया कि सरासरी नागरिकों को अंतर्गत आशय नहीं माननी चाहिए जिसे सरकार ने गम्भीरता से लिया और तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री ने उसे 'देशद्रोह' बताया। जयप्रकाश की भ्राता कभी नहीं रही कि सेना विद्रोह पर उठे। जयप्रकाश ने केन्द्रीय गृहमंत्री के आरोप का जवाब देते हुए स्पष्टीकरण किया "मैंने इस सम्पत्ति की ओर इशारा किया था कि देश में किसी प्रकार की तानाशाही प्रवृत्तियों प्रज्वलित का गला घोटने का प्रयत्न कर सकती है, ऐसी स्थिति में सेना का बर्तन देश, उसके ध्वज और उसके संविधान के प्रति है। देश के समर्थन या मौलिक कानूनों में भले ही स्पष्ट रूप से यह न लिखा हो, मेरा का यह कर्तव्य है कि वह अपनापक्षधरों खतरों से देश की रक्षा, अगर कोई दलील सरकार या दलील नेता अपना दल और सत्ता के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहे तो सेना का यह कर्तव्य है कि वह अपना उपयोग न होने दे।"

जयप्रकाश नारायण ने सेना के सम्पर्क में एक और स्पष्टीकरण किया—“मैं प्रत्यक्ष इस तथ्य की ओर इशारा करना हूँ जो कि ऐतिहासिक तथ्य है कि एक हिंसक क्रान्ति तब तक कामयाब नहीं होती जब तक कि सत्ताका दल का विघटन नहीं होता और अधिकारी सेनाई या तो टटल रहे हैं या फिर क्रान्ति के पक्ष में पक्षी जा रहे हैं। मैंने यह बताया है कि एक शांतिपूर्ण क्रान्ति में सेना को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर यदि सत्ताधारी एक शांतिपूर्ण क्रान्ति को दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल करे तो सेना को इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए। मैंने नागरिक अध्यायिका की अवस्था में सरासरी सेनाओं के उपयोग की आलोचना की है, क्योंकि ऐसी गड़बड़ी में अतीतक सरासरी दल होने हैं। अगर इस सबका मतलब देशद्रोह होता है तो मुझे उस अपराध के कटपरे में खड़े होने में कोई हिचकिचाहट नहीं।"

पुलिस के सिलसिले में उन्होंने कहा कि वर्तमान आन्दोलन में पुलिस ने ज्यादा बल का प्रयोग किया है। "मैं यह अर्थपूर्ण समझता हूँ कि पुलिस को यह समझाऊँ कि मैं उन्हें विद्रोह करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उन्हें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए मगर उन्हें ऐसी आशय नहीं माननी चाहिए जो गैर-कानूनी हो या उनके अन्तःकरण के विरुद्ध। मैं नहीं मानता कि यह सख्तनाक है। मगर यदि है तो यह शांतिपूर्ण क्रान्ति का हिस्सा है।" जयप्रकाश नारायण का मत था कि आन्दोलनकारियों को पुलिस के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सघर्ष उनके साथ नहीं है। वे राज्य के स्थायी कर्मचारी हैं और सरकार बदलने पर वे सेवा में रहेंगे। जयप्रकाश नारायण ने यह मत बताया कि उन्होंने सेना या पुलिस को जनता आन्दोलन में शामिल होने के लिए कहा है।

दलीय चरित्र सुधार

जून, 1978 में जनता पार्टी के चरित्र सुधार सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में लोकनायक ने कहा कि "मैं अपने देश के भविष्य के बारे में आशय हूँ कि चाहे जो अन्दरूनी कमजोरियाँ, झगड़े, मतभेद नजर आते हैं, उन सबके बावजूद हम इकट्ठे रहेंगे और जहाँ भी राष्ट्रहित का प्रश्न आएगा वहाँ हम सब एक होंगे। आज जो हो रहा है मैं उसकी देखा हूँ

और उसमें घबराता नहीं हूँ कि छोटी-छोटी पार्टियाँ बन कर और उनके आपस के अस्थिर गठबन्धनों के आधार पर प्रॉस में जैसे राजनीति चली वैसी वहाँ न चले और एक मजबूत सत्ता रहे जिनके हाथ में सत्ता हो और तात्कालिक विकल्प जो है। यह उसी प्रकार का हो तो एक तरफ जनता पार्टी है, उसमें बहुत-सी पार्टियाँ मिलती हैं, लेकिन बिना होकर उन्होंने अपना अस्तित्व कायम रखा है। उनके लिए कि वे बाहर अपने संगठनों की तोड़ डालें तभी जनता पार्टी का सही मायने में एकीकरण हो सकता है। नहीं तो डर रहता है कि वे आपस में मतभेद के कारण पार्टी छोड़कर चले जाएँगे—अपना पर बनाकर रखा है पहले से और वहाँ कुछ काम चलता है यह सब खत्म होना चाहिए और जनता पार्टी में सबसे मिलाकर सही मायने में एक पार्टी बनाना चाहिए। जो हमने ही उनकी वफ़ादारी जनता पार्टी के साथ ही और वे जो परिवर्तन, ढेरिय या कार्यक्रम साना चाहते हों, वह साने का प्रयत्न अन्दर से करें। बाहर गुट बनाकर और पार्टियाँ बनाकर और उनमें जनता पार्टी में आकर कुछ मत देकर उसमें अपनी टुकड़ियों को बल देना गलत है।

जनसमिति . जनतापति का दर्शन

मार्च 1977 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी की कैबिनेट सरकार के पतन के कुछ दिन बाद जयप्रकाश नाटयण ने अकाराधायी की एक भेटवार्ता में 'लोकतन्त्र' को निर्वाध गति से चलाने की एक धानी लोगों के हाथ में सौंपने की कोशिश की। कैबिनेट सत्ता से हट चुकी थी—जयप्रकाश नाटयण का एक तात्कालिक लक्ष्य पूरा हो चुका था, पर उन्होंने बिना समय गँवए अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को साधने रखा दिया। जयप्रकाश नाटयण ने प्रथम धरण के रूप में जनसमितियों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। यह सुझाव नया नहीं था। 1974 में 'लोकतन्त्र के लिए युवा' नामक एक अभियान में जयप्रकाश ने युवकों के बीच निगमानी समितियों के गठन का प्रयास किया था। उन समितियों का स्वरूप सीमित था। चुनाव के दौरान होने वाले ब्रह्मचार आदि पर युवक नजर रहें। वह काम ज्यादा पैल नहीं सका। बिहार आन्दोलन की लम्बी अवधि में जयप्रकाश ने इस कार्यक्रम को बिलुप्त ढंग से सोचा। चुनावी निगमानी की सीमाएँ तोड़ी और चुनाव के बाद जीते हुए प्रतिनिधियों और मतदाताओं के बीच सवाद और सम्पर्क के आयाम इसमें जोड़े। मार्च 1977 के चुनाव अभियान में उन्होंने इस विचार को रखा। 20 मार्च 1977 के फैसले ने परिस्थिति बदल दी। यह फैसला कैबिनेट को असह्युक्त या जनता पार्टी को स्वीकृत किए जाने तक ही सीमित नहीं था, उसने रोटी और प्रगति के बदले सरकार और सत्तारूप दल के हाथ में अपनी व्यक्तिगत आजादी और देश के लोकतन्त्र को गिरवी रखने से इनकार किया और बताया कि लोकतन्त्र का अर्थ 'जनता के साथ पर' चलने वाली सरकार नहीं है, बल्कि जनता की इच्छा द्वारा चम्पने वाली सरकार है।

जनसमितियों की जिम्मेदारियाँ कुछ इस प्रकार होगी। अपने स्तर पर यह निगमानी करना कि सरकार की योजनाएँ और कार्यक्रम उनकी पोषित नीति के अनुरूप ही चलती रहे। पिछड़े वर्गों के लिए बर्बाई गई कल्याणकारी योजनाएँ निर्बाध रूप से लागू होती रहे, गरीबों और विशेषकर पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, अपने क्षेत्र में लाकसभा और राज्यसभा के लिए चुन कर भेजे गए प्रतिनिधियों से हर तीन महीने में एक बार मिलना तथा प्रतिनिधियों से उनके वर्तमान काम और ध्विष की योजनाओं का विवरण प्राप्त करना तथा अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं पर उनमें विचार विमर्श करना, वहाँ में एक बार इन प्रतिनिधियों से उनकी आय और सम्पत्ति का ब्यौर लेना, स्थानीय अत्याचारों, अन्यायों तथा स्थानीय झगड़ों की पुलिस और अदालत की कम से कम मदद लेते हुए सुस्तज्ञान का प्रयत्न करना, स्थानीय विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासकीय एजेंसियों की मदद लेना, मदद करना और ज़रूरत पड़ने पर जनता की भगडित करके शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक सत्याग्रह के जरिए प्रशासन और समाज की गलत कार्यों से विरत करना और सही कार्यों की तरफ प्रेरित करना।

संगठन के ढाँचे को चार स्तरों में बाँटा गया—देहाती इनाकों में गाँव को तथा शहरी इलाकों में 150 से 200 परिवारों की सभा की बुनियादी इकाई माना गया। दूसरे स्तर में पंचायत और शहर की 8 से 10 हजार तक की आबादी के मोहल्ले की शामिल किया गया। तीसरे स्तर में प्रखण्ड और वार्ड तथा चौथे स्तर में संसदीय चुनाव क्षेत्र आएगा। बुनियादी इकाई का गठन गाँवजन की ठग्यस्थिति में सर्वांगुणित से किया जाएगा। इसमें 5 से 15 सदस्य चुने जाएँगे। सावधानी बरती जाएगी कि इसमें स्त्रियाँ, स्त्रियन और अन्य कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। समिति का काम से कम आधा भाग मुवाओं का हो। समिति का एक सयोजक रहेगा। यह समिति किसी राजनीतिक पार्टी की समिति का रूप न ले, इसलिए यह ध्यान रखा जाएगा कि इसमें आने वाले सदस्य चाहे किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हों या न हों, वे पूरे समाज के विश्वासपात्र हों, लेकिन सयोजक का गैर-राजनीतिक होना आवश्यक माना गया है। प्राचीन सरीय जनसमितियों के संयोजकों और हर गाँव से एक अन्य प्रतिनिधि को मिलाकर पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। प्रखण्ड या संसदीय स्तर की समिति में क्षेत्र की हर पंचायत समिति के तीन या चार सदस्य होंगे। यह माना गया है कि प्रखण्ड या संसदीय स्तर की समितियों के सदस्य लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव लड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। शहरी स्तर का संगठन इसी ढाँचे पर खड़ा किया जाएगा। इस तरह कोशिश की जाएगी कि ये जनसमितियाँ देश की राजनीतिक प्रवृत्ति का एक इकाई और बन सकें और मतदाताओं और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच आम जनता

और प्रशासन के बीच एक मजबूत पुल की भूमिका निभा सकें। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि "सरकार में ग़ने या कुर्सी सम्भालने के बाद ग़लती किसी व्यक्ति से हो सकती है इसलिए उसे यह ख़ुशी होनी चाहिए कि दूसरे उम्मीदवारों के सहयोगियों का गठन सरकार के हित में कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल आज सत्ता में हैं उनमें मुझे आशा है कि वे इस तरह के कदम का स्वागत करेंगे। इन समितियों को वे अपना विरोधी नहीं, अपने सहयोगी की तरह मानेंगे।"

जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय जनसमिति की स्थापना के लिए उत्सुक थे। उनकी आवश्यकता के कारण यह समिति भी विमल्व से जिसकी पहली बैठक घटना में दिनांक 30-31 जुलाई, 1977 को जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुई। इस समिति में 30 सदस्य नियुक्त किए गए, जिनमें प्रमुख थे—आचार्य कृपतानी, एम. सी. छांगना, बी. के. जॉन, नारायण देसाई आदि। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। एक प्रस्ताव में मईगाई और बेरोजगारी में वृद्धि और भ्रष्टाचार पर चिन्ता व्यक्त की गई और सरकार से आग्रह किया गया कि केन्द्र और राज्यों की सरकारें आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में सक्रिय हों—जनता ने उन्हें इसीलिए चुनकर सत्ता सौंपी है। दूसरे प्रस्ताव में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आर्थिक तथा अन्य अपराधियों को नज़रबन्द करने के विचार का ग़लत बताने हुए सभी राजनीतिक बन्दिनों को रिहा करने की माँग की गई। अन्य प्रस्ताव में हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अमानवीय व्यवहार को निन्दा की गई और कहा गया कि ऐसी घटनाओं को कमजूर और व्यवस्था का मामला बना कर नहीं ठाम्ना जा सकता—सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए।

उद्घाटन भाषण में जयप्रकाश नारायण ने समिति की उपयोगिता, कार्य-विधि और सदस्यों की व्याख्या की—

1. समिति जनता और उन प्रतिनिधियों के बीच कड़ी का काम करेगी। यह जनता का कर्तव्य है कि उसके निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कर्तव्य पथ से झुट न होने पाएँ।

2. जनशाक्ति को संगठित और विकसित करना समिति का कर्तव्य है—जो उसे उदाहरण प्रस्तुत करके करना है।

3. जनसमितियों को राजनीति जाति या वर्गों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और दलित तथा शोषित वर्गों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

हर गाँव और मोहल्ले में जनसमिति बनाने का आन्दोलन जमा नहीं, पर जनसमितियों के दर्शन में हमें लोकतन्त्र के हाथ सराकट रखा कबच का बोध होता है जो महत्वपूर्ण है।

नेतृत्व, लोकतन्त्र, योग्यता एवं शासन-प्रणाली पर जयप्रकाश के विचार

जुलाई, 1978 में एक साप्ताहिक में लोकनायक जयप्रकाश ने नेतृत्व की आवश्यकता, लोकतन्त्र के लिए भारतीयों की योग्यता, भारत के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली, जनता पार्टी का संगठन एवं कर्तव्य आदि पर प्रकाश डाला, जो निम्नांकित प्रकार से हैं—

नेतृत्व—"बिना नेतृत्व के व्यक्ति संगठित नहीं हो सकते हैं। जब गोकुल डूब रहा था तब कुञ्ज न होते तो उसका उद्धार न होता। जब नेतृत्व दिया तो सभी उस पर चले गए। नेता जो भारतीय मूल्यों की मानता हो और जिसके प्रति भारतीय जनता की प्रशंसा हो, उसका अनुसरण व्यक्ति कर सकते हैं फिर चाहे वह कितना ही ऊर्ध्वतकरी कार्यक्रम या विचार रखे।" "दक्षिण भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है यदि वह प्रभावशाली हो और उत्तर की स्वीकार्य हो—दक्षिण के निवासी को भारतीय नहीं मानते, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन उत्तर के जिस बात की कहें उसे दक्षिण के निवासी मानें, यह नहीं हो सकता। आज भारतीयता यदि है तो (अपने शुद्ध रूप में नहीं कह सकते पर बदनाम के साथ करें) वह दक्षिण में ही है। उत्तर में मुस्लिम शासन की बग़ल से फर्क पड़ गया है। आज तक हमनामर लोग आगे रहे उनका भी असर पड़ा है। जो बाहर से आए थे वे भारत के भुक्कबने सांस्कृतिक दृष्टि से कम थे, पर वे यहाँ समाज हो गए। आज के भारत में हमें सोचना पड़ेगा कि भाषा की नीति को किस तरह बनारें कि दक्षिण की तिरसेदारी ठममें हो सके। विभिन्न भाषाओं के लिए केन्द्र में स्थान किम्बु तरह हो यह सोचना चाहिए।"

क्या हिन्दुस्तानी लोकतन्त्र के योग्य है?—हम लोकतन्त्र के योग्य नहीं, यह ग़लत बहस है। हमारे जैसा लोकतन्त्र एशिया में और कहीं नहीं है—जापान और इराक़ल को छोड़कर जिनमें नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, स्थापित सत्ता से असहमति की आजादी और उस सत्ता के विवेकीकरण के अधिकार सविधान सम्पन्न हैं।

"हम लोकतन्त्र के योग्य हैं इसका एक और प्रमाण है। जब इमर्जेन्सी लागू हुई, दो लाखों व्यक्ति उत्तर भारत में गिरफ्तार हुए थे और दमन के जो उपाय किए गए थे वे इमर्जेन्सी के आवश्यक अंग नहीं थे। कर्जिस ने उसको बदरत किया—पुरानी कर्जिस ने भी जनता को जब मौक़ा मिला उसने चुनाव में जबाब दिया। अतः लोकतन्त्र कोई विदेशी चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ लगा दिया गया हो। इस मिट्टी में उनकी गाधार है, यदि है, वे हमारे मानस में बस कर रहे हैं। मगध भारत में साम्राज्यवाद का केन्द्र रहा। सिक्खियों का गणतन्त्र वैराज्य। जयप्रदीप लोकतन्त्र वक्रसंघ। यह जनान्विक

और लोकतांत्रिक परम्परा है कि वे लोकतन्त्र जैसे अन्य लोकतन्त्र वे, वैसे ही नागरिक पर लागू होते थे दस्यु पर नहीं। मुनव की पद्धति हमारे यहाँ रही है।"

भारत के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली—सम्प्रा— वर्गीय भारत में ससदीय लोकतन्त्र की जगह राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए। जयप्रकाश जी इसके विरुद्ध थे—“हमारे देश में एकलपक्ष सरकार नहीं हो सकती—राष्ट्रपति प्रणाली का तानाशाही में बदल जाना असमंजस है। उसमें एक व्यक्ति होता है जिसके चारों ओर व्यक्ति होते हैं। यह ठीक है कि बिना एक व्यक्ति के नेतृत्व में ससदीय लोकतन्त्र नहीं चल सकता, परन्तु हमारे देश में जो परिस्थितियाँ हैं, ठामें राष्ट्रपति प्रणाली लोकतन्त्र से अलग चली जाएगी। हमारे यहाँ विभिन्नताएँ हैं, भाषावार राज्य हैं। ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति प्रणाली के पैर मजबूत नहीं हो सकते।"

दलीप सैंगटन और कर्णव्य—लोकनायक का विचार था कि “आज हमारे विचारकों पर जनता का अंकुर नहीं रहा। सशक्त असहमति को निरासह करना गलत है।” जयप्रकाश के अनुसार पार्टी के बाहर के संगठनों की समानता करना चाहिए। “यै बराबर इसके पक्ष में रहत हूँ। जनता पार्टी के घटक अपने बाहर के संगठनों को समान नहीं करना चाहते। वे सही मायने में एकीकरण नहीं चाहते हैं और अवसरवादिता से काम से रहे हैं।"

जयप्रकाश नारायण ने शिखर राजनीति की छपटाईनाता की ओर ध्यान दिलाया। “नेता उसके साथ चिपके रहेंगे तो व्यक्ति सरकार से नहीं जुड़ सकेंगे। राजनीतिक आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा। आज लेनी में नुकसा। हो रहा है क्योंकि गाँव और शहर का असन्तुलन हमारी राजनीति में व्याप्त रहा है। कारण यह है कि जो राजनीति में गाँव से आए हैं वे शहर में वैसी नीतियाँ निरचित करते हैं जो मध्य वर्ग और उसके हितों को सामने रखती हैं। मजदूर वर्ग या धूमिहीन श्रमिकों का संगठन होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के श्रमिकों के बीच उनके अपने नेता होने चाहिए—वर्गीय कि वह सचरवाहिनी के माध्यम से होगा, पर मैं अपनी बीमारी के कारण निर्देश नहीं दे सकूँ।” सम्पूर्ण क्रांति की मेरी धारणा में ऐसा मध्य चाहिए जिसमें सब मिल जाएँ और नई चीज तैयार हो। वह शिखर राजनीति में चलते रहने पर नहीं हो सकता है। जयप्रकाश नारायण आगे की ओर देखते रहे जबकि राजनीति का धरित्र पीछे की ओर लौट रहा है। वह निराशावादियों की तरह यह नहीं मानते थे कि इस देश को सेना या पुलिस ठीक कर सकती है। “सैनिक या पुलिस तख्ता पलट तभी सम्भव होगा जब आर्थिक गतिरोधक हो जाए और आर्थिक सकट हो। जब हम बंद रहे हैं यह सहता नहीं दिखाई पड़ता है।"

भूदान आन्दोलन की एक नया आधार

1957 में बनारस में आयोजित प्रतिपाद देशों के समाजवादियों के सम्मेलन में जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि राजसत्ता के जरिए समाजवाद साने की कोशिश मानव-जाति की ‘कल्याणकारी राज्य’ तक से जा सकती है, आजादी, समता और भाईचारे तक नहीं। इस अवसर पर जे पी ने भूदान आन्दोलन के जरिए लोकशास्त्र को ज्ञात करने की सम्भावनाओं को रेखांकित किया। भूदान आन्दोलन धीरे-धीरे सघात हो गया जिसके दो कारणों थे—ग्रामियों और सरकारी मशीनरी के आन्दोलन का अन्तरांग हिस्सा मान लिए जाने पर भूदान का नैतिक पक्ष कुण्ठित हो गया। दूसरे आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने भूदान या धूमि वितरण के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। असफलताओं के बावजूद भूदान से जितनी जमीन बँटी उतनी शायद कोई राज्य सरकार सीमाबन्दी कानून के अधीन ही बँटवा सकी है।

1970 में मुजफ्फरपुर की जनसभा में जे पी ने भूदान आन्दोलनों को नया आयाम दिया। ग्राम प्राप्ति की पुष्टि और स्वायत्त की स्थापना जल्दी है, जिसके लिए ग्राम सभा की स्थापना जमीन का बीसवाँ हिस्सा भूमिहीनों में बाँटना, ग्रामकोष की स्थापना और शान्ति सेना की स्थापना की जाए। नक्सलपथी समस्या के संदर्भ में जे पी ने बासगीत जमीनों के पर्वे दिखतने, मजदूरों की समस्याएँ समझने और सुलझाने और शक्तिशाली तत्वों के शोषण से गरीबों की बचाने के लिए खुद काम करने का सकल्प किया। मुसहरी प्रखण्ड जे पी की प्रयोगशाला बना।

जयप्रकाश नारायण का योगदान एवं मूल्यांकन

डॉ. वर्मा के अनुसार “जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के क्षेत्र में सुविख्यात व्यक्ति रहे हैं। यह उनका महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने भारत में समाजवादी आन्दोलन को केंद्रित के झण्डे के नीचे चल रहे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम के साथ सम्बद्ध कर दिया। मोरन्देव तथा जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी विचारधारा को जाता को साम्राज्यवादी राजनीतिक आधिपत्य तथा देशी सामन्तवाद की दसता से मुक्त करवाने की दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने समाजवादी दर्शन को दो बुद्धों का समरूपोष बनाया—राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम तथा सामाजिक क्रांति। भारत के जर्जरित ग्रामीण समाज की विकसल दरिद्रता के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने उन सामाजिक तथा यान्त्रिक बन्धनों के उन्मूलन पर बल दिया जो कृषि के उत्पादन में बाधा डाल रहे थे।”¹

सुभाषचन्द्र बोस

(Subhash Chandra Bose, 1897-1945)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

सुभाषचन्द्र बोस (1897-1945) का नाम भारत के इतिहास में स्वतंत्र अर्थों में अंकित है और उन्होंने भारत की आजादी के लिए सब कुछ न्यौतार कर दिया। उनके महान् त्याग के कारण जनता ने उन्हें देश के दायित्व से सुशोभित किया। अपने दृढ़ संकल्प और अदृष्ट शौर्य द्वारा उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए विदेश में बिना किसी साधन और सहायता के एक विरहजन्य समग्र पैदाश करके संसार में कार्य-साधना का एक आदर्श उदाहरण कर दिया। वह प्रतिभासम्पन्न छात्र थे। आई सी एस की परीक्षा पास की, परन्तु मई, 1921 में त्याग दे दिया और 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में कदम पड़े।

वह महात्मा गाँधी के विचारों से सहमत न हो सके। महादेव माधन और सत्य का था। महात्मा गाँधी अपनी आत्मशक्ति को प्रेरणा से कार्य करते थे, जबकि कमल बुद्धि एवं तर्क से चलते थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि गाँधीजी को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ था और उनकी योजना में स्पष्टता का अभाव रहता था। गाँधीजी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता संग्राम की राह से मुम्बई को बड़ी निराशा हुई और वे पत्नी कार्यक्रम निरस्त करने के विरुद्ध विचार करने लगे। विचारजन्यता के रूप में उन्हें एक योग्य नेता प्राप्त हो गया। मुम्बई की दोगुना कार्यशुद्धता और संगठन क्षमता अद्वितीय थी। सरकार ने उन्हें अपनी ओर लाने का प्रयास प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। मुम्बई की महिलाओं से आदित्य सरकार ने उन्हें नवतन्त्र करके 1925 में मान्यता देना प्रारम्भ किया। निष्कर्ष को छोड़कर अन्य किसी नेता ने इतना कुछ नहीं किया बिना मुम्बई ने। उन्हें दस बार कारागार में डाला गया और अन्ध के आठ वर्ष उन्हें जेल में बिताते रहे। मुम्बई को समझौतावादी रवैया प्रस्तुत न था वे प्रवृत्ति से विरोधी थे।

महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन में मुन्षाब को निष्पक्ष नहीं बँद, बल्कि उन्होंने इसमें सहयोग किया और जेल गए, पर जब 1934 में गांधीजी ने आन्दोलन को बन्द करने से लिया तो मुन्षाब ने अग्रजों से शर्तों में कहा—“इसका यह मत है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधीजी अनन्य रहे हैं।” कारणों में बंस का स्वाम्य छूटा हो गया, असे सरकार ने उन्हें यूरोप जायज निकाला करने की अनुमति प्रदान की। यूरोप में उन्होंने विभिन्न राजनीतियों से भेंट की और उनके समक्ष भारत की स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया। बन्स लौटने पर 1938 में उन्हें त्रिपुरा काँग्रेस का सम्पन्न निर्वाचित किया गया। वहीं से अनेक नेताओं से उनका टाँट मजबूत रहा। 1939 में उन्होंने डॉ. पट्टाभिसाराम का पालन कर वहीं से सम्पन्न किया। जब मुन्षाब का विशेष बड़ा गया तो उन्होंने मद से त्याग देकर ‘चारवर्ष काक’ नामक दल का संगठन किया। शीघ्र ही उनके हन्डे के नीचे बहुत से नवयुवक सम्मिलित हो गए। गांधी ने उन्हें नज़रबन्द कर लिया। इस पर उन्होंने सरकार को चेतावनी भरा पर दिया—“मुझे मुन्षाब का दीविर, मरणा में जीवित रहने से इनकार कर दूँगा। इसका निश्चय करना मेरे बस में है कि मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ। शरीरों का खूा धर्म का बीज होता है। मुझे आज अवसर मिला बहिरु जिससे भारत स्वतंत्र और प्रगती हो। असे देशभक्तियों का मुझे गरी, बल्लस है—मूलतः यह कि दासता, समुपे के निरु ससे पन्था पाई है। इस पर का सरकार पर प्रभाव पड़े।” मुन्षाब के अनशन और जवाहरन उन-आन्दोलन के मय में उन्हें मुक्त कर दिया गया।

जेल से मुक्त होते ही मुग़ल जन-अन्दोलन को समर्थित करने में लग गए। महामुद दुरु हॉन पर क्रॉन अन्दोलन के लिए जनता का आह्वान किया और यह भीग रखी कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाए जिसे गरीबों, किसानों, दुर्गम जनता, सभी शक्तिशाली इष्टांतरित कर दे। बॉस के इन कथनों से अत्यधिक होकर सरकार ने उन्हें उनके मक़द में मदद कर दिया और बड़े पैमाने पर पैसा दिया, लेकिन मुग़ल पुलिस को अंतर्धों में घुस जाँकर ग़दब हो गए। यह रहस्य बाद में खुला कि वे पार से छद्मवेश में ग़दब होकर कब्ज़ा करते हुए पेरिस, रूस, जर्मनी और ज़पान गए हैं। जब मुदूर पूर्व में ज़पान मित्र एग्री की सेनाओं को घुस चला रहा था। भारत को मुग़लों से छुटकारा दिलाने के लिए ज़पान की सहायता से भारत पर अक्रमा करने के उद्देश्य से मुग़ल ने आज़ाद हिंद फौज अर्थात् भारतीय सेना (Union Liberation Army) का समर्थन किया। 'जय हिन्द', 'दिल्ली चलो' और 'लाल क़िला हमारा है' अदि उनके नारे थे। मुग़ल के सैन्यदल में आज़ाद हिंद फौज ने फरवरी, 1944 में भारत पर उतरापूर्व की ओर से अक्रमा किया और इम्फ़ाल (आसाम) पर अधिकार कर लिया। आज़ाद हिंद फौज इम्फ़ाल से आगे न बढ़ सकी और ज़पान की हार होने लगी। अगस्त 1945 में ज़पान ने आज़ादों की महारक शक्ति के साथ घुटने टेक दिए और ज़पान के अर्पण कर प्रदेशों पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। मुग़ल को लोकियो कायदा पड़ा किन्तु उनके में वापस दुर्घटना में उनका जान हो गया।

मुभाष चन्द्र बोस के राजनीतिक विचारों की पृष्ठभूमि

मुभाष कर्मयोगी थे, राजनीतिक दार्शनिक अथवा सैद्धांतिक विचारक नहीं। उनके लिए यह जगत् 'कर्म-क्षेत्र' था। प्रारम्भिक अवस्था में बोस वेदोक्त दर्शन के प्रशंसक थे, किन्तु कालान्तर में वे सामाजिक और राजनीतिक व्यापार्यवादी बन गए। 'शक्ति' को उन्होंने सम्मान दिया। भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि अतिशय अहिंसा देश के पराभव के लिए बरतारदायी थी। भारतीय भौतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पतनोन्मुख इसलिए हुए कि उन्होंने धार्मिक और प्राकृतिक शक्तियों में अत्यधिक विश्वास किया, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के सम्बन्ध में उदासीनता प्रकट की, सन्तोष की भावना रखी और अहिंसा के पीछे घातल बने रहे।¹ बोस ने भारत के राजनीतिक इतिहास में मुस्लिम शक्ति की सर्वोपेक्षा को चुनौती दी। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 'मुस्लिम ध्वज' थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन भारत के केन्द्रीय और प्रांतीय प्रशासनों से हिन्दुओं का मुस्लिम शासन के साथ संयोग था। भारतीय सत्ता की समन्वयकारी शक्ति ने विदेशी तत्वों को भारतीय समाज में अन्तर्गता कर दिया, केवल अंग्रेज इसके अपवाद थे।

मुभाष बोस के राजनीतिक विचार

राजनीतिक चर्चायावाद में विश्वास—मुभाष ने गांधीजी की तरह 'राजनीति के आध्यात्मिकरण' की बात नहीं कही। उन्हें राजनीति और नैतिक प्रश्नों को अथवा धार्मिक तथा राजनीतिक मामलों को मिश्रित करना पसन्द न था। उनका विश्वास राजनीतिक सौदेबाजी में था। उन्होंने जीवन में कहा—राजनीतिक सौदागरों का रहस्य यह है कि आप धातव्य में जितने शक्तिशाली हैं उससे अधिक शक्तिशाली दिखाई दें। अपनी आवाज को बलशाली शक्तों में रचना चाहिए। ब्रिटिश सत्ता के सामने विनाश शब्दावली उन्हें पसन्द नहीं आई। उनका विचार था कि महात्माजी की, जो अपने देश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राजनीतिक शक्ति के स्तर में कोसना चाहिए था। यदि गांधी स्टालिन, मुसोलिनी अथवा हिटलर की भाषा में बोलते तो ब्रिटिश सत्ता उनकी बात को समझती और सम्मान देती। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए मुभाष सशस्त्र संघर्ष के समर्थक थे और आजाद हिन्द फौज का गठन करके तथा देश को गुलागो से मुक्त कराने के लिए सैनिक अभियान चलाकर अपने विचार को साकार कर दिखाया।

मुभाष ने भी कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए त्याग और कष्ट सहने की आवश्यकता है। देशवासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बंदी से घरे रास्ते पर चलना पड़ेगा, घोर कष्टों से जूझना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए महान नैतिक तैयारियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि नैतिक बल के अभाव में कष्ट सहने और त्याग करने की क्षमता नहीं आ सकती।

पूर्ण स्वाधीनता के प्रशंसक—मुभाष औपनिवेशिक स्वराज्य के विरोधी थे। वे नेहरू रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं हुए और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1929 के कांग्रेस-प्रस्ताव पर उन्होंने इसी शर्त पर हस्ताक्षर किए कि यदि अंग्रेजों ने इसे स्वीकार न किया तो कांग्रेस के अगले अधिवेशन में 'पूर्ण स्वतंत्रता' का लक्ष्य घोषित किया जाएगा। मुभाष को मनोकामना 1930 के साठार अधिवेशन में पूरी हुई। 'पूर्ण स्वाधीनता' के लिए पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन। पन्ना, अन्य नेताओं के साथ मुभाष जेल गए, पर जब आन्दोलन मध्य में गांधी-इरविन समझौते से भंग हो गया, तो इस समझौतावादी नीति से उन्हें बहुत शोक हुआ। मुभाष पूर्ण स्वतंत्रता के लिए इतने अधीर थे कि वे किसी भी डिस मिल अथवा शिफ्टल नीति को सहन नहीं कर सकते थे। उसकी दृष्टि में अहिंसा की नीति समयानुकूल नहीं थी। उन्हें यह विश्वास था कि अहिंसा से भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है इसलिए कांग्रेस की नीति से निराश होकर, मुभाष ने भारत में बाहर सैन्य-संगठन किया और शास्त्रबल पर भारत को आजाद कराने का संघर्ष छेड़ा।

गांधीजी की नीति से असहमति, पर गांधी के प्रशंसक—मुभाष यद्यपि महात्मा गांधी की इज्जत करते थे तथापि उन्हें गांधीजी की अहिंसावादी नीति में निष्ठा नहीं थी। वे गांधीजी की भौतिक राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों को राक्षस नहीं करते थे तथा गांधीजी की तरह धर्म और राजनीति का बन्धन स्वीकार्य न था, वे गांधीजी के दृढ़ परिण एव अधिक परिश्रम के प्रशंसक थे और उन्हें 'एट्टिटा' के नाम से सम्बोधित करते थे। मुभाष गांधीजी के चर्च समन्वय और दृष्टीशील के सिद्धान्त के आलोचक थे, किन्तु देश की आजादी के लिए गांधीजी की आवश्यकता को वे अंगूठ न करते थे।

दूसरी कार्यक्रम—मुभाष को विश्वास था कि गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन की शक्ति क्षीण होगी और भारत में वामपंथी दल की शक्ति बढ़ेगी, इसीलिए उन्होंने नए दल के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जिसमें उनके राजनीतिक विचारों का सार निहित है। इस कार्यक्रम को, जो मुभाष बोस की पुस्तक 'The Indian Struggle' में दिया गया है, डॉ. वर्मा ने अग्र रूप में प्रस्तुत किया है²—

1 Subhash Bose The Indian Struggle, p. 192

2 विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, पृ. 399

(1) वह दल किसानों और मजदूरों के हितों का समर्थन करेगा, न कि जमींदारों, पूँजीपतियों और साहूकार वर्गों के निहित स्वार्थों का।

(2) वह भारतीय जनता की पूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक भुक्ति के लिए कार्य करेगा।

(3) वह अन्तिम उद्देश्य के रूप में सप्तात्मक शासन का समर्थन करेगा, किन्तु कुछ वर्षों तक वह अधिनायकवादी शक्तियों से सम्पन्न एक मजबूत केन्द्रीय सरकार में विश्वास करेगा जिससे भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

(4) देश के खेतिहर तथा औद्योगिक जीवन का पुनर्संगठन करने के लिए ठोस राजकीय नियोजन की सुदृढ़ तथा समुचित व्यवस्था में विश्वास होगा।

(5) वह नई सामाजिक व्यवस्था का ठन पुनर्गठन गाँव समाजों के आधार पर निर्माण करने का प्रयत्न करेगा जिनमें गाँव में पंच शासन करते थे। वह जाति जैसी वर्तमान सामाजिक दीवारों को ध्वस्त करने की भी चेष्टा करेगा।

(6) वह आधुनिक शासन में प्रचलित सिद्धान्तों तथा प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए नई मुद्रा-व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयत्न करेगा।

(7) वह जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने तथा सम्पूर्ण भारत में समान भूमि-व्यवस्था कायम करने की कोशिश करेगा।

(8) वह उस प्रकार के लोकतन्त्र का समर्थन नहीं करेगा जैसाकि विक्टोरिया के शासनकाल के मध्य में इंग्लैण्ड में प्रचलित था। वह ऐसे शक्तिशाली दल के शासन में विश्वास करेगा जो सैनिक अनुशासन के द्वारा परस्पर आबद्ध होगा। जब भारतवासी स्वतन्त्र हो जाएँगे और उन्हें पूर्णतः अपने साधनों पर निर्भर रहना होगा, उस समय देश की एकता को कायम रखने तथा अराजकता को रोकने का यही साधन होगा।

(9) भारत की स्वतन्त्रता के पक्ष को मजबूत बनाने के लिए वह अपने आन्दोलन को भारत के भीतर तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सहारा लेगा और उसके लिए विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा।

(10) वह सब उग्रवादी संगठनों को एक राष्ट्रीय कार्यपालिका के अन्तर्गत संगठित करने का प्रयत्न करेगा जिससे जब कोई कार्यवाही की जाए तो अनेक मोर्चों पर एक साथ कार्य किया जा सके।

फारवर्ड ब्लाक की स्थापना—कैप्टन की अध्यक्षता का परित्याग कर मई, 1939 में सुभाष बोस ने फारवर्ड ब्लाक नामक नया राजनीतिक दल स्थापित किया। फारवर्ड ब्लाक के झण्डे के नीचे सुभाष देश की कामपची शक्तिपक्ष को समुक्त करना चाहते थे। इस दल का उद्देश्य था—अहिंसावादी के चक्कर में न पड़ते हुए भारतीय स्वतन्त्रता को राष्ट्रातिरोगी प्राप्त करने के काम में सलग्न रहना। जनवरी, 1941 में बोस ने फारवर्ड ब्लाक दल के प्रमुख सिद्धान्तों का सार इस प्रकार व्यक्त किया—(1) एक पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा उसके प्राप्त करने के लिए अविचल साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष। (2) एक पूर्णतः आधुनिक समाजवादी राज्य। (3) देश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए वैज्ञानिक एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन। (4) उत्पादन तथा वितरण पर सामाजिक स्वायत्तता तथा नियन्त्रण। (5) व्यक्ति को धार्मिक पूजा-पाठ में स्वतन्त्रता। (6) हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार। (7) हर वर्ग को भाषा विषयक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता। (8) नवीन स्वतन्त्र भारत के निर्माण में समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को लागू करना।

आजाद हिन्द फौज की स्थापना—सुभाष ने अपने फारवर्ड ब्लाक दल के माध्यम से देश के नवयुवकों में क्रान्तिकारी भावनाओं का संचार किया। जून, 1940 में बोस की मुलाकात बीर सावरकर से हुई। उन्होंने सावरकर से कहा कि वे कोसकाला में सार्वजनिक स्थानों से अंग्रेजों की मूर्तियाँ हटाने का आन्दोलन छेड़ने की उत्सुक हैं। सावरकर ने ब्रह्म छोटे आन्दोलन चलाकर अपनी शक्ति का अपव्यय न करके की सलाह दी और कहा कि उन्हें भारत से बाहर जाकर भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा कर देनी चाहिए और फ्रांसिस्ट तथा नाजी शक्तियों के हाथों में पड़ गए भारतीय कैदियों को सही नेतृत्व देकर देश को स्वतन्त्र कराने के लिए बंगाल की छाद्दी अथवा बर्मा की ओर से सैनिक अभियान करना चाहिए।¹ सरकार की नजरों में धूल झोंक कर वे कानुन पहुँच गए और जर्मनी में हिटलर ने उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। जो भारतीय सैनिक जर्मनी और इटली के हाथों में पड़ गए थे उनको मिलाकर सुभाष ने मुक्ति सेना बनाई जिसका कार्यालय ड्रेसडन (जर्मनी) में रखा गया। दिसम्बर, 1941 में जापान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दी। 1942 में टोकियो में आजाद हिन्द फौज के गठन की घोषणा की गई जिसमें 50,000 से अधिक भारतीय सैनिक भर्ती हुए। जून, 1943 में बोस ने टोकियो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आराधना करना व्यर्थ है कि वे अपने साम्राज्य को स्वयं नष्ट कर देंगे। हमें भारत के भीतर और बाहर से स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 21 अक्टूबर, 1943 को सुभाष ने आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतन्त्र भारत की स्थायी सरकार बनाई। जापान, जर्मनी, फिलीपाइन, कोरिया, इटली, चीन, म्यान्मार् और आयरलैण्ड ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी।

जापान ने अण्डमान और निकोबार द्वीप आस्थापी सरकार को दे दिए। सुभाष ने अण्डमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वतन्त्र द्वीप रखा। 30 दिसम्बर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतन्त्र भारत का झण्डा फहरा दिया गया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिन्द फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और राम्पू, कोहिया, पलेस आदि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। सुभाष ने 22 सितम्बर 1944 को 'शहीद दिवस' मनाया और अपने सैनिकों से कहा—'हमारी मातृभूमि स्वतन्त्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें स्वतन्त्रता देता हूँ। यह स्वातन्त्र्य देवी की माँग है।' जर्मनी ने द्वार मानती और अगस्त 1945 में जापान ने घुटने टेक दिए। जापा के अधीन जो प्रदेश थे, वे अंग्रेजों के अधिकार में चले गए। सुभाष को टोकियो को तरफ पलायन करना पड़ा और हवाई दुर्घटना में उनका देहान्त हो गया।

जवाहरलाल नेहरू

(Jawaharlal Nehru, 1889-1964)

महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के सम्बन्ध में कहा था कि "जहाँ उनमें एक योद्धा के समान राहस्य और छपलता है, वहाँ एक राजनीतिज्ञ की सी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी भी है। -- वे एक निष्ठ, निष्कलक और निर्दोष सरदार हैं। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है।" जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव-मुक्ति के प्रति सेवाएँ पारम्परिक रही। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वे यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका योगदान अमूल्य था।¹ इसमें सन्देह नहीं कि पं. नेहरू की मृत्यु से हमारे देश के इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। पं. नेहरू की यह विशेषता थी कि एक राजनीतिज्ञ होते हुए भी वे मैकिन्डवेल्सीय राजनीति से बहुत दूर थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में "जवाहरलाल ने राजनीतिक सपनों के क्षेत्र में नहीं बहुतों छल और आत्मप्रवचन पत्रों को विकृत कर देते हैं, शुद्ध आचरण के आदर्श का निर्माण किया।"²

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

पं. जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) का जन्म 14 नवम्बर, 1889 को इलाहाबाद में एक सम्पन्न कश्मीरी परिवार में हुआ था। वे मोतीलाल नेहरू और स्वरूपलाली के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता देश के प्रसिद्ध वकील थे। 15 वर्ष की आयु में 1905 में उन्हें इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध 'हैरी स्कूल' में प्रविष्ट करवाया गया, 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया, जहाँ से उन्होंने विज्ञान में मानस भी परीक्षा पास की तथा 1912 में वे 'इनर टेम्पल' से वकील बने। अपने छात्र जीवन में नेहरू भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में दिलचस्पी लेते रहे। 1904 में जापान के हाथों रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र की पराजय ने नेहरू के हृदय में भारत राष्ट्र की स्वतन्त्रता के सपने घर दिए।

भारत लौटने पर जवाहरलाल नेहरू ने वकासत शुरू की, लेकिन शीघ्र ही वे राजनीतिक समारमियों की तरफ बढ़ चले। 1912 में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई जो इस रूप में फलीपूत हुई कि गांधीजी ने जवाहर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और यह घोषितवाणी कर दी कि 'मेरे मरने के बाद जवाहरलाल मेरी ही भाषा बोलेंगे।' 1916 में उनका विवाह कप्तान कौल से हुआ। उनके एक पुत्री हुई, इन्दिरा प्रियदर्शिनी, जिसने भारत के प्रधानमंत्री पद को भूरोषित किया। 1918 में नेहरू होमरूल लीग के सक्रिय बने और 1920 में वे भारत के किसानों की समस्याओं तथा अन्धकारों में गहरी दिलचस्पी लेने लगे। "1920 का साल नेहरू के राजनीतिक जीवन में निर्णायक मोड़ का था"³ और उनके दिमाग में "गांधी की नंगी-भूजी जनता की भारत की तस्वीर" बनी रही। 1922 में वे इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने। 1927 में अन्तर्राष्ट्रीय गणतान्त्रिक आन्दोलन के साथ उनके व्यापक और दीर्घकालीन सम्पर्कों की शुरुआत हुई। बुर्गेला में हुए पौर्णिव राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1928 में साइमन कमीशन (Simon Commission) के विरुद्ध लखनऊ के प्रदर्शनों में उन्होंने पुलिस की लाठियों खाई और Independence League की स्थापना की। 1929 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। उनकी अध्यक्षता में अर्द्धरूप को पूर्ण स्वायत्त का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया। जवाहरलाल 1936, 1937 और 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

नेहरू ने देश का दौरा किया और भारतीयों में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए एक अभिलाषा पैदा कर दी। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान उनका 9 वर्ष से अधिक का समय जेलों में कट्य। 1931 तथा 1936 में क्रमशः उनके पिता तथा पत्नी का देहान्त हो गया। 1938 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में उन्होंने भाग

1 डॉ. श्यामसुन्दर, नेहरू, पृ. 7

2 हिन्दुस्तान, दिनांक 11 नवम्बर 1970 (सम्पादनकौन)।

3 डॉ. मोरिस, जवाहरलाल नेहरू, जीवन, पृ. 3 (हिन्दी अनुवाद)।

लिया : 1945 में वे 'सिमला सम्मेलन' में भाग लेने गए। 1946 में उन्होंने भारत की अन्तर्निष्ठ सरकार का निर्माण किया और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत की आजादी की वेला में जवाहरलाल ने अपने भाषण में कहा—“आधी रात के घण्टे के साथ जबकि रासरा सो रहा है, भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर जागेगा। एक क्षण आता है जो इतिहास में कभी ही आता है जब हम पुछने से नए की ओर बढ़ने हैं जब एक युग समाप्त होता है और जब बहुत दिनों तक दवाई हुई राष्ट्र की आत्मा बोल उठती है। यह उचित ही है कि इस पवित्र अवसर पर भारत की और उसके निवासियों को और उससे भी बड़ी मानवता को सेवा का सफल लें।”¹ “भारत की सेवा का अर्थ है उन लाखों लोगों की सेवा जो कष्ट सह रहे हैं तथा गरिबी और अज्ञान और रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना।”²

जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त, 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक अर्थात् अपनी मृत्यु तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 17 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक सफल आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा की जमाने का श्रेय उन्हीं को है। अक्टूबर, 1962 में साम्यवादी चीन के हमले का सट्टा नेहरू को झेलना पड़ा। इससे उन्हें यह आभास हो गया कि शान्ति में पूर्ण आस्था रखते हुए भारत को सैनिक दृष्टि से एक सफल राष्ट्र बनना होगा। जवाहरलाल नेहरू की कृतियों में 'विश्व इतिहास की झलक' तथा 'भारत की खोज' (Glances of World History and Discovery of India) प्रसिद्ध हैं। नेहरू एक महान् देशभक्त, कर्मठ राजनेता शान्तिदूत, विलक्षण बुद्धिमान और युगदृष्टा पुरुष थे जिन्हें साहित्य, दर्शन एवं प्रकृति से प्रेम था। उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें उनकी 'आत्म-कथा' विशेष उल्लेखनीय है।

विचारों के दार्शनिक आधार

(Philosophical Foundations of Thoughts)

नेहरू का चिन्तन उनके पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा गाँधी, एनी बीसेन्ट, बुक्स, रसेल, कार्ल मार्क्स, कॉन्ट, स्पेन्सर, आइन्स्टीन, आल्फ्रेड नोबेल, मिल, बर्नार्ड शॉ आदि से प्रभावित था। नेहरू के चिन्तन और व्यवहार को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका महात्मा गाँधी की रही। गाँधीजी से उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, शान्ति और नैतिकता से परिपूर्ण राजनीति का पाठ पढ़ा, परन्तु वे गाँधीजी की शिक्षाओं और आदर्शों को अटल सिद्धान्तों के रूप में ग्रहण नहीं कर सके। मृत्युपर्यन्त नेहरू मानवतावादी भावना से ओत-प्रोत, भावुक और संवेदनशील रहे लेकिन गाँधीजी की आध्यात्मिकता उनको प्रवेश नहीं कर पाई। न वे पूर्ण नास्तिक रहे न पूर्ण आध्यात्मिकतावादी और न ही पूर्ण भौतिकतावादी। कार्ल मार्क्स के भौतिकवादी विचारों का प्रभाव उन पर अवश्य पड़ा, लेकिन वे पूर्ण भौतिकवादी नहीं बन सके। उन्होंने भौतिक पदार्थ को अन्तिम सत्य नहीं माना। भौतिक विज्ञान के प्रति विज्ञान का एक छात्र होने के नाते, उनकी रुचि थी। आइन्स्टीन, प्लैंक तथा हेसेन्बर्ग के भौतिकवादी शोधों का प्रभाव उनके चिन्तन पर पड़ा लेकिन इस दृष्टि से उन्हें हम कॉन्ट की अपेक्षा स्पेन्सर के अधिक निकट पाते हैं। नेहरू ने यह नहीं माना कि कोई ऐसा जगत् है जो हमारी दृष्टि अथवा चिन्तन से परे है।

नेहरू पर बुद्ध और ईसा के विचारों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने बुद्ध और ईसा के समान मानव आदर्शों और नैतिकता की शक्ति में विश्वास प्रकट किया। नेहरू जीवन-पर्यन्त शान्ति और नैतिकता के उपासक रहे, नेहरू सपर्यमय जीवन के उपासक थे जिन्होंने अपने जीवन में कर्म को प्रधानता दी। बौद्ध-दर्शन से प्रभावित नेहरू ने भ्रम समर्पण नहीं किया कि हम ससार का परित्याग कर दें अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर को यातनाएँ दें।

नेहरू मूलतः एक राजनीतिज्ञ थे, हॉब्स या रूसो या सिसरो (Hobbes, Rousseau or Cicero) की नीति राजनीतिक दार्शनिक नहीं। राजनीतिक-शक्ति-सम्पन्न होने के कारण उन्हें इस बात के अवसर मिले कि वे अपने विचारों को व्यावहारिक जामा पहना सकें। डॉ. बी. पी. वर्मा के अनुसार, “हम उन्हें एक सामाजिक आदर्शवादी कह सकते हैं जो साधारण व्यक्ति की भावनाओं के लिए एक जनतन्त्रीय दृष्टिकोण में आस्था रखता हो। नेहरू पर गीता का प्रभाव था। गीता के कर्म के सन्देश को उन्होंने अपने जीवन में उठाया और निभाया था। नेहरू ने अपने जीवन, विचारों और कार्यों से देशवासियों और सम्पूर्ण मानव जाति को सन्देश दिया कि फलफल की चिन्ता किए बिना, हम यन्त्रपूर्वक अपने कर्म में लगे रहें।”

मानवतावाद (Humanism)

नैतिक आदर्शवाद में नेहरू की गहन आस्था जीवन-भर बनी रही। पौष्टिक और शैक्षित के प्रति उनके हृदय में प्रीति और सहानुभूति थी। “एक मानव के रूप में उनके चिन्तन में सुकुमारता, भावना की अद्वितीय कोमलता और महान् एवं उदार प्रवृत्तियों का अद्भुत सम्मिश्रण था।” नेहरू जीवन-पर्यन्त मानव-जीवन के उत्थार स्तरों के लिए सपर्यशोक्त रहे। उनका सन्देश था कि व्यक्ति को व्यावहारिक और अनुभव प्रधान, नैतिक एवं सामाजिक, परोपकारी तथा मानवतावादी

नेहरू ने राष्ट्रीय आत्म-निर्णय (National Self-determination) के सिद्धान्त पर बल दिया और साम्राज्यवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संपर्पशील देश में एक स्वस्थ शक्ति होती है, लेकिन देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद वही राष्ट्रीयता प्रतिक्रियावादी और विकीर्ण बन सकती है, अतः ऐसी सर्वांग राष्ट्रीयता से बचना चाहिए। नेहरू ने राष्ट्रवाद में मानवता का समावेश किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर धर्म, जाति और सस्कृति का सहारा नहीं लेना चाहिए। नेहरू ने मिस्र, मोरक्को, इण्डोनेशिया, अल्जीरिया, कांगो आदि देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों का स्वागत किया। अरब राष्ट्रवाद के अभ्युदय को उन्होंने शुभ लक्षण बताया।

अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (Internationalism)

नेहरू अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के पोषक थे। उन्होंने अपने देश को कॉमिंस को और सम्पूर्ण मानव समाज को व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने कॉमिंस को महसूस कराया कि स्वतन्त्रता के लिए भारतीय संघर्ष एक वैश्विक संघर्ष का भाग था तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे सफल बनाया जा सकता था। "विश्व शान्ति और विश्व सम्प्रदाय के विचार में नेहरू का विश्वास था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य-पत्र के प्रति आस्था दिखाई।" ¹ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नेहरू जी की धारणा थी कि "हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जबकि विदेशी मामलों जैसे शब्द अप्रासंगिक हैं। हम एक-दूसरे पर अधिकारिक अवलम्बित होते जा रहे हैं तथा विश्व के दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। सभी राष्ट्र राष्ट्रीयता राजनीतिक कट्टरता का एक रूप हैं। उनका विश्वास था कि युद्ध अवश्यम्भावी नहीं है और शान्ति ही व्यावहारिक है इसलिए उन्होंने गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाया।" गुटों से अलग रहने की नीति से नेहरू का आशय यह नहीं था कि "एकगिता (Isolation) के मार्ग पर चला जाए। संसार में शान्ति की स्थापना के लिए नेहरू भारत को विश्व के मामलों में सहभाग्य बनाना चाहते थे। अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रोत्साहन के लिए वे हर सम्भव उपाय करने को तत्पर थे।"

नेहरू का हृदय सर्वोदय की भावना से परिपूर्ण था। वे कहा करते थे—हम सबके मित्र हैं और हमारा कोई शत्रु नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीयता में उनकी आस्था से सभी देश अवगत थे। जून 1955 में मास्को विश्वविद्यालय ने इनका अभिनन्दन करते हुए कहा था कि नेहरू ने राष्ट्रों के मूल अधिकारों की मान्यता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और मिद्दान्तों की रक्षा की है और वे एशिया तथा विश्व में तनाव को कम करने के लिए सच्चे दिल से प्रयत्नशील रहे हैं। नेहरू को अन्तर्राष्ट्रीयता की प्रेरणा विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गाँधी जैसे महान् व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी। नेहरू ने कहा था—"मेरी राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता पर आधारित है और आधुनिक विश्व विज्ञान, व्यापार और यातायात के साधनों के कारण अन्तर्राष्ट्रीयता की नींव पर खड़ा है। कोई भी राष्ट्र विश्व से विमुख नहीं रह सकता।" ² नेहरू की मान्यता थी कि अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना एक स्वतन्त्र देश में पनप सकती है किसी गुलाम देश का दिमाग और ताकत आजादी पाने की कोशिश में लगी रहती है। नेहरू महान् अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे अतः उन्होंने राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीयतावादी आदर्श का समर्थन किया। नेहरू अन्तर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण व्यवहार में लागू करना चाहते थे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रण्यों के आचरण का एक नया मौलिक सिद्धान्त दिया जो 'पंचशील' के नाम से विख्यात है। इसमें पाँच सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए—(1) एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोत्तम सत्ता के लिए पारस्परिक सम्बन्ध, (2) अनाक्रमण (3) एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप, (4) समानता और पारस्परिक लाभ एवं (5) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आर्थिक सहयोग।

विश्व के सभी रण्यों ने (अपवाद स्वरूप कुछ राष्ट्रों की छोड़कर) पंचशील के सिद्धान्तों में आस्था प्रकट की। पंचशील द्वारा नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे नैतिक मार्ग का अनुसरण करने में विश्वास करते हैं। इस सिद्धान्त द्वारा उन्होंने मैकिवावेनी राजनीति और शक्ति-राजनीति में अपनी अनास्था प्रकट की और कहा कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम बल प्रयोग की पूरी तरह बहिष्कृत नहीं कर सकते तो उसे न्यूनतम अवश्य कर सकते हैं। पंचशील के सिद्धान्त के मूल में धारणा यह रही है कि राष्ट्र एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें और एक-दूसरे के अधिकारों तथा दावों का शान्तिपूर्वक और सच्चाई के साथ मूल्यांकन करें, किन्तु नेहरू शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। नेहरू के आलोचकों का कहना था कि कश्मीर, गोवा, पाकिस्तान तथा तिब्बत के सम्बन्ध में नेहरू का नैतिक और मानवतावादी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद विकृत होकर तुष्टीकरण की नीति में परिवर्तित हो गया। कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में भारत पर पाकिस्तान और चीन के अग्रक्रमण के आधार पर पंचशील सिद्धान्त की व्यावहारिकता की चुनौती दी गई है। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज के आणविक युग में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व ऐसा विच्छेद्य है जिससे मानव सभ्यता की रक्षा हो सकती है, परन्तु यदि पंचशील के सिद्धान्त पर ईशान्वरों से अमल किया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय तनावों में कमी होगी और संघर्ष के कारणों का उन्मूलन किया जा सकेगा।

अन्य राजनीतिक विचार (Other Political Ideas)

जवाहरलाल नेहरू युग दृष्टा एवं कर्म प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने इस देश को स्वाधीनता, समृद्धि, सौहार्द और सुख के द्वारों में घातने का प्रयास किया। जवाहरलाल राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वावलम्बन और बौद्धिक विकास को आवश्यक मानते थे। नेहरू देश को लोकतन्त्र और समाजवाद की दिशा में देखते रहे। उन्होंने युद्ध का विरोध करते हुए शांति और अमलमत्ता की नीति में अपना गहन विश्वास प्रकट किया। स्वतन्त्र भारत में उन्होंने कल्याणकारी राज्य को नींव डाली।

युद्ध, शांति और तटस्थता (असंलग्नता) पर नेहरू के विचार

नेहरू ने युद्ध का विरोध करते हुए विश्व-शांति को मानव-कल्याण का मार्ग बताया। अपने प्रधानमन्त्रित्व काल में उन्होंने अपने विचारों और कार्य-कलापों से विश्व-शांति की स्थापना की दिशा में प्रभावशाली और सहायनी कार्य किया। इतिहास में नेहरू को गहरी स्मृति थी। उन्होंने उन कारणों की खोज की जो युद्धों को जन्म देते हैं। उनका कहना था कि किसी न किसी कारणवश हर देश, काल और परिस्थिति में युद्ध होते रहे हैं। नेहरू ने युद्ध के कारणों और स्वरूप का जो चित्र खींचा वह संक्षेप में इस प्रकार था—

(1) एक समय मनुष्य की वर्णव्यवस्था युद्ध का स्रोत थी। यूरोप में धर्म युद्ध (Crusades) इसके प्रमाण हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण धार्मिक भावना से प्रेरित थे। बहुत से यूरोपीय देशों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मतवालाभिचारों के बीच जो संघर्ष हुए उनका स्वरूप धार्मिक था।

(2) युद्धों का दूसरा स्वरूप सामन्तवादी था। उदाहरणार्थ, भारत में राजपूत नैराहों के बीच होने वाले युद्ध अपने चरित्र में मुख्यतः सामन्तवादी थे।

(3) प्रत्येक युग में राजनीतिक शक्ता और गौरव के लिए युद्ध होते रहे हैं तथा आज भी की रहे हैं।

(4) युद्धों का एक स्वरूप राजनीतिक रहा है। उदाहरणार्थ, सिकन्दर महान् की विजय का स्वरूप राजनीतिक था। रवेन्स और स्पार्टा के बीच के युद्ध राजनीतिक थे।

(5) वर्तमान युग में युद्धों का कारण आर्थिक है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हैं।

(6) युद्धों का एक कारण राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच अस्पष्ट वैचारिक मतभेद है। वैचारिक और सैद्धान्तिक मतभेदों के फलस्वरूप शीतयुद्ध प्रवृत्त है जो सारांश युद्ध का रूप से सकता है।

नेहरू ने युद्ध और शांति के विषय में विचार प्रकट किए, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और असंलग्नता (Non Alignment) की नीति की वकालत की। वे शांति के प्रयोग को हर परिस्थिति में दुकराने का उपदेश देते थे लेकिन यथार्थवादी राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने अक्सर पड़ने पर राजु का अथवा विरोधों का बलासम्भव अपनी सम्पूर्ण शक्ति से मुकाबला करने में विश्वास प्रकट किया। पाकिस्तानी एवं चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में नेहरू ने दृढ़ता का परिचय दिया। उनकी निष्ठा समस्या के सम्मानपूर्ण और शान्तिपूर्ण समाधान में बनी रही। नेहरू के अनुसार, "हमें अपनी रक्षा करनी है—और स्वयं को संकटकालीन स्थिति के लिए तैयार रखना है। हमें आक्रमण और अन्य प्रकार के अनाचार का सामना करना है। युद्ध के सामने झुकना बुरा होता है। युद्ध और आक्रमण का प्रतिरोध करते समय हमें शान्ति बनाए रखनी चाहिए और अपने विरोधियों के सामने प्रियता का हाथ बढ़ाए रखना चाहिए।" नेहरू ने ऐसी शान्ति का उपदेश कभी नहीं दिया जो हमें कर्तव्य से विमुख करती हो। उनका दृष्टिकोण किन्तु व्यावहारिक और सन्तुष्टि था—उन्होंने 12 जून 1945 को भारत की शान्तिवादी नीति के संदर्भ में कहा था—“हमारी पड़ोसी नीति यह होनी चाहिए कि हम भोखण अप्रति (वृद्धि महायुद्ध जैसी) को घटित होने से रोके। दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति ऐसी स्थिति बनाने की होनी चाहिए कि यदि युद्ध छिड़ जाए तो हम इसे रोकने में समर्थ हो सकें।”

नेहरू और लोकतन्त्र

जवाहरलाल नेहरू और लोकतन्त्र को विलग नहीं कर सकते। नेहरू ने लोकतन्त्र को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया, अपितु आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को लोकतन्त्र की परिधि में लिया। उनका कहना था कि नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता देना ही पर्याप्त नहीं है उन्हें अवसरों की समानता दी जानी चाहिए, आर्थिक विषमताओं का अन्त किया जाना चाहिए। सामाजिक रुढ़ियों और आर्थिक असमानताओं से पूर्ण शायज लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। भूखे व्यक्ति के लिए मताधिकार महत्व नहीं रखता। यदि समाज में ऊँच-नीच, शूद्र-अशूद्र के भेदभाव हो, दरिद्रों की कतार हो धन का न्यायपूर्ण वितरण न हो, कर्मभेद का प्रसार हो और मुद्दी भर शिक्षित लोग निरक्षर जन-साधारण को अपने द्वारों तक दबाए हों तो लोकतन्त्र की बात करना निरर्थक है। नेहरू महत्त्व गौधी के राजनीतिक उदात्ताधिकारी थे, वे साधनों की पवित्रता के सिद्धान्त में निष्ठा रखते थे। नेहरू को जनता से प्यार था, जन-सम्पर्क को वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। अपने प्रधानमन्त्रित्व काल में नेहरू ने अपनी अविराम यात्राओं और अवगत भाषणों द्वारा जनता से

सम्पर्क स्थापित करने की प्रणाली विकसित की। उन्होंने यह बताया कि शासकों और शासितों के मध्य स्थित मध्यम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होता है। नेहरू ने जनता को अनुरागमन और भाव्य की प्रेरणा दी। उनका उद्देश्य था कि जनता में उस सामुदायिक भावना को दृढ़ किया जाए जिसे मैकडोवर (MacDowall) ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बताया है।

नेहरू लोकतन्त्र की नैतिक मानदण्डों और मान्यताओं की योजना बनाते थे। उन्होंने कहा था कि "मेरे विचार में गणतन्त्र का अर्थ सरकार तथा किसी सम-बन्धन सम्मता से अधिक है। यह जीवन के नैतिक मानदण्डों तथा मान्यताओं की राजता है। गणतन्त्र के लिए अनुरागमन, सहिष्णुता तथा पारस्परिक सम्भावना आवश्यक है। अपनी स्वतन्त्रता के लिए दूसरों की स्वतन्त्रता के प्रति आदर भाव होना आवश्यक है। गणतन्त्र में परिवर्तन पारस्परिक विचार विमर्श तथा सम्मेलन-पुञ्जों से किए जाते हैं, हिंसक उपायों से नहीं। गणतन्त्र का अर्थ समानता है। "मैं किसी मध्यम-मान्यता अथवा धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किन्तु मैं मानव की नैतिक आध्यात्मिकता में विश्वास करता हूँ—इसको कोई चाहे धर्म कहे, अथवा न कहे, मैं व्यक्ति की सच्चा गरिमा में विश्वास रखता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान अग्रेसर दिया जाना चाहिए। मुझे ऐसे सम-समाज में पूरा विश्वास है। एक आदर्श के रूप में इस उद्देश्य को पूरा करना ही संभव है, जिसमें भिन्नता न हो, मुझे धनी-व्यक्तियों की बेहदगी और निर्धनों की दरिद्रता नहीं प्यारी।"¹

लोकतन्त्रवादो होने के नाते व्यक्ति के महत्त्व में नेहरू का विश्वास था। मानवता के बड़े-बड़े के दोर पर किसी व्यक्ति को नहीं कैद देना चाहिए। उसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्यपूर्ण माना जाना चाहिए और किसी को चाहे वह राज्य हो अथवा संगठन—व्यक्ति को दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उनका मुख्य सिद्धान्त था कि राज्य व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए² नेहरू अपने विरोधियों के विचारों के प्रति सहनशीलता और सम्मान की भावना रखते थे। उनकी दृष्टि में हठकदमिता और रुढ़िकदमिता की प्रवृत्ति लोकतन्त्र के लिए घातक थी। लोकतन्त्र एक गतिशील विचारप्रणाली है और समयानुसार परिवर्तनों तथा अनन्तता के साथ लोकतन्त्र का क्षेत्र अधिकधिक विकसित होता जाता है। लोकतांत्रिक भावना की माँग है कि हम अपनी समस्याओं का निराकरण अपनी विचार-विमर्श, वर्क-विचर्क और शान्तिपूर्ण उपायों से करें। नेहरू समदीय सरकार को अच्छा इमॉनिर समझते थे। यह समस्याओं को हल करने का शान्तिपूर्ण उपाय है। नेहरू हर धन को लोकतांत्रिक रूप से करने के समर्थक थे। वे समुचित सांविधानिक साधनों द्वारा अपनी नीतियों मनवने और निर्णयों में परिवर्तन करने के प्रयत्नों के पक्ष में थे, लेकिन प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action) जैसी आन्दोलनत्मक तकनीक उनकी दृष्टि में अलोकतांत्रिक थी। सर्वोपनिषद्वाद और हिंसालक साधनों के प्रति उनका विरोध इतना उग्र था कि उन्होंने ऐसे समय मुसोलिनी और हिटलर से गिनने तक से इनकार कर दिया था जब विश्व के बड़े राजनीतिज्ञ इन तत्काराओं से मिलने में अपना गौरव समझते थे। नेहरू का विश्वास था कि लोकतन्त्र की कुण्डली ऐसी नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। यदि ठन्कू नैतिक परिवर्तन का पालन किया जाए तो लोकतन्त्र के सच्चे सफल्य में संदेह नहीं है।

एकता और धर्म-निरपेक्षता

जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास का विवेकपूर्ण विश्लेषण किया था तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपनी फूट और साम्राज्यवाद की विच्छेदन के कारण भारत अपने गौरव को खो बैठा है। नेहरू का विश्वास था कि एकता के अभाव में देश अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं रख सकता। यदि हम दल, राज्य, भाषा, जाति आदि को महत्त्व देंगे और अपने देश को भूल जाएँगे तो सर्वनाश की आशंका करेगा। यदि हम सम्म-भारा और दल को दूर से अधिक महत्त्व देंगे तो यह धष्ट का चिन्ता होगा। नेहरू ने देश के राजनीतिक एकीकरण की अपेक्षा मानते हुए देश की भावनात्मक एकता पर बल दिया। विविधता को समान्य करना आवश्यक नहीं है, लेकिन पारस्परिक बन्धनों में समाज कर अपनी शक्ति खो देना मूर्खता है। विविधता में एकता को बनाए रखने में देश और समाज का कर्त्तव्य है, जो गतिविधियों लोगों को एक करती हैं, उनके प्रसार का प्रयत्न किया जाना चाहिए और जो फूट डगमगी हैं उनका परित्याग कर देना चाहिए। भारत में अनुरागमन और एकता को प्रथम स्थान दिया जाना आवश्यक है।

नेहरू ने देशवासियों को एकता की समस्या का चुनौती से मुकाबला करने का संदेश दिया। उनका कहना था कि देशवासियों की निम्न किसी गुट, वर्ग या दल विशेष के प्रति न होकर राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। नेहरू ने राजनीतिक एकीकरण की अपेक्षा भावनात्मक एकीकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि "राजनीतिक एकीकरण कुछ भीमा तक हो ही चुका है, किन्तु मैं जो चाहता हूँ वह इससे अधिक है—भारतीयों का भावनात्मक एकीकरण, जिससे हम सब भिन्न-भिन्न सदुक्त हो सकें और एक शक्तिशाली राष्ट्रीय इकाई बन जाएँ।" जवाहरलाल नेहरू ने धर्म-निरपेक्षता के प्रति अपनी निष्ठा रखी।

1. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, वही, पृ. 106-107

2. डॉ. ए.ए. कृष्णन, वही, पृ. 111

में भौतिक वस्तुएँ जीवन के बौद्धिक और नैतिक मूल्य समन्वित हैं। जीवन का सर्वांगीण विकास करना एक अच्छे राज्य की कसौटी है, पर इस उद्देश्य में राज्य की सफलता अपने नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता पर निर्भर है, क्योंकि मानव जीवन से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान मानव चरित्र पर निर्भर करता है।

मार्क्सवाद-साम्यवाद (Marxism Communism)

विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के अनुसार "नेहरू के मन में मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अथवा उसके विरोध में जो मार्क्सवादी साम्यवाद मिलती थी उससे जो सवैवात्मक अनुगम उदयन हो गया था, वह आयु की वृद्धि तथा समय के साथ क्षीण हो गया।"

नेहरू द्वितीय महायुद्ध तक मार्क्सवाद अथवा साम्यवाद के प्रति आकृष्ट रहे, लेकिन महायुद्ध के बाद यह प्रभाव क्षीण होने लगा और उनके विचारों में परिवर्तन आ गया। जैसे-जैसे नेहरू की आयु बढ़ी, प्रशासन की जिम्मेदारियाँ आईं¹ अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की विनाशकारी कार्य-प्रणाली प्रकट हुई, उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण साम्यवाद के प्रति जो झुकाव पैदा हो गया था, वह कम हो गया, इसीलिए परिचय के उद्घाटनी राजनीतिज्ञ नेहरू की भारत तथा एशिया के अन्य भागों में साम्यवाद की प्रगति के विरुद्ध अवरोध मानने लगे थे। नेहरू के मार्क्सवादी-साम्यवादी चिन्तन पर दो भागों में विचार करना होगा—प्रथम द्वितीय महायुद्ध तक का चिन्तन एवं द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् का चिन्तन।

उनकी कृतियों 'विरह इतिहास की झलक' एवं 'भारत की खोज' के अध्ययन से नेहरू पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 'नेहरू और मार्क्सवाद' के लेखक राशि भूषा के अनुसार, "मार्क्सवाद में दबकोन करने वाली किसी पार्टी का सदस्य न होने के बावजूद नेहरू ने मार्क्सवादी विचारधारा के प्रचार के लिए काम किया।"² मार्क्सवाद की ऐतिहासिक भूमिका के सम्बन्ध में नेहरू के अनुसार, "यह इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव जीवन और मानव उमांगों की व्याख्या करने का तरीका है।" नेहरू की मार्क्स की विरह तथा इतिहास की धारणा में प्रशंसा मिली। मार्क्सवादी इतिहास दर्शन के वैज्ञानिक, धर्म-विद्या विरोधी विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा अन्यविश्वास विरोधी दृष्टिकोण ने उन्हें प्रभावित किया।³ "नेहरू ने मार्क्सवादी दर्शन के एकलमक तथा चिन्तन और पदार्थ का अद्वैतवाद, पदार्थ की निरन्तर गतिशीलता, तत्त्वों के पारस्परिक संपर्क एवं सयोगजनक घटनाओं के कारण तथा उनके व्यक्त प्रभाव, क्रिया, प्रतिक्रिया और उनके संपर्क के माध्यम से उनके क्रमिक विकास तथा परिवर्तनों द्वारा समाज में आने वाली क्रान्तियों का मूल्यकन करके दृढ़तामयता के सिद्धान्तों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की।"⁴

मार्क्सवादी दर्शन उन्हें पूर्ण रूप से समुष्ट नहीं कर सका और न उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सका। समाज-व्यवस्था और वर्गों की राजनीति के सम्बन्ध में नेहरू के विचार मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। नेहरू ने मार्क्स के वर्ग-संपर्क के सिद्धान्त द्वारा यह सन्निहित करने की कोशिश की कि मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो समाज में घटने वाली घटनाओं का मूल्यकन करता है। जो मार्क्सवाद पर यह तात्पर्य लाता है वह समाज में अस्तित्व पैदा करता है या वर्ग-संपर्क की जन्म देता है। उन्हें नेहरू ने कहा कि "मार्क्स ने वर्ग-संपर्क का विचार नहीं किया, उसने यह सन्निहित किया है कि वर्ग-संपर्क तो पहले से मौजूद है और किसी न किसी रूप में सदा चला आ रहा है। नेहरू ने यह मान्यता प्रकट की कि साम्यवाद और पूँजीवाद के बीच जो विश्व व्यापी सन्घर्ष चल रहा है उसी का हिस्सा भारत का स्वधीनता संग्राम है।

नेहरू अपने जीवन के सम्बन्धान्तरण में मार्क्सवाद-साम्यवाद से दूर हो गए। मानव जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्त्व में उनका विश्वास बढ़ता गया, क्योंकि साम्यवाद में इन मूल्यों का महत्त्व नहीं है। फलस्वरूप नेहरू गांधीवाद के अधिकाधिक निकट आते गए और मार्क्सवाद-साम्यवाद के प्रभाव से दूर हटते गए। सिंगपुर में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि "एशिया में साम्यवादी आन्दोलन उलूख का रातु है। भारतीय स्थिति के सम्पर्क में नेहरू ने वर्ग-संपर्क के समाजशास्त्र में विश्वास करना छोड़ दिया और गांधीजी की शक्ति से कहने लगे कि वर्ग-संपर्क हैं। शान्तिपथ तरीकों से मुनजाया जा सकता है।"⁵

आर्थिक स्तर पर कल्याणकारी राज्य (Welfare State on Economic Level)

जन-कल्याणकारी राज्य के प्रति नेहरू की चिन्तन और व्यवहार रैली का चित्र फ्रैंक मॉरेस (Frank Morriase) ने अपनी पुस्तक 'जवाहरलाल नेहरू जीवनी' में किया है।⁶ नेहरू आर्थिक स्तर पर भारत को जनकल्याणकारी राज्य बनाने हेतु जीवनपर्यन्त प्रयत्नशील थे। समाजवादी का कल्याणकारी राज्य वर्षों से, नेहरू का भारत के लिए आदर्श रहा, उनकी यह धारणा थी कि यह जोर-जबाबदारी से उठी, सहमति और विचारों से युक्त आदर्श-प्रदान से स्थापित जाना चाहिए।

1. राशि भूषा नेहरू और मार्क्सवाद, पृ. 28.

2. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, वही, पृ. 331.

3. राशि भूषा नेहरू और मार्क्सवाद, पृ. 92.

4. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, वही, पृ. 382.

5. फ्रैंक मॉरेस, वही, पृ. 386-396.

नेहरू चाहते थे कि इसके लिए जनता में राज्यात्मक भावों के प्रति तीव्र आकर्षण पैदा करना होगा, नियोजित होगा और यह भावना पैदा करनी होगी कि योजना उनके लिए और उनके द्वारा है। पंचवर्षीय योजनाओं को भी नेहरू की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्बन्धी से सफल किया।

नेहरू भारत को जन-कल्याणकारी राज्य बनाने में औद्योगीकरण को महत्वपूर्ण मानते थे। वे औद्योगीकरण की बुझियों के प्रति सज्ज थे। नेहरू की दृष्टि में भारत की समस्या थी—पूँजी का अभाव और श्रमिकों का ग्राह्यत्व। उनका कहना था कि उस जन-शक्ति का जो उपयोग नहीं कर रहा है उपयोग किया जाए। श्रमिकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो, भारत में श्रमिकों को काम में लगाने के उपयोग में लाएँ, न कि बेकारी पैदा करने के। नेहरू ने देश में व्याप्त अनुचित आत्म-सन्तोष को उचित नहीं माना।

देश को आर्थिक स्तर पर जन-कल्याणकारी रूप देने में नेहरू ने सामुदायिक योजना को महत्व दिया। सामुदायिक विकास का गौरी का कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1952 को आरम्भ किया गया। किसानों की सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आज जो काम यहाँ आरम्भ हुआ है, यह एक क्रान्ति का प्रतिकार है। यह अव्यवस्था पर आधारित क्रान्ति नहीं है अपितु गौरी दूर करने के प्रयत्न पर आधारित है। यह भाषणों का अवसर नहीं है। हमें भारत को अपनी मेहनत से गहना बनाना है।" "सुधरे हुए स्वायत्त बेहतर शिक्षा और समाज सेवा के बड़े हुए भाव से भारत नवजीवन और विस्तृत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।" नेहरू की कल्याणकारी भावना में 'गौरी' और 'पिछड़ेपन' का स्थान न था।

राम मनोहर लोहिया

(Ram Manohar Lohiya, 1910-1967)

"लोहिया गौरीजी के सत्याग्रह और अहिंसा के अछूट समर्थक थे; लेकिन गौरीवाद को अमूर्त दर्शन मानते थे वे समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स को एकदली मानते थे, वे राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व सरकार का सपना देखते थे, वे आधुनिकतावादी आधुनिक थे, लेकिन सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे वे बिहारी और क्रान्तिकारी थे, लेकिन शांति और अहिंसा के अमूर्त व्यासक थे।"¹

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

डॉ. राममनोहर लोहिया (1910-1967) स्वाधीनता संग्राम के सेनानी और भारत में समाजवादी आन्दोलन के अग्रणी उद्ग्राहक थे। वे समाजवादी विचारों के 'उग्र-प्रचारक' (Fiercy Propagandist) माने जाते थे पर मास्को का पिछलग्गू बनने की दृष्टि से गौरीवादी समाजवाद के समर्थक थे। 1952 में वे कांग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे और उन्होंने के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1953 में एशियाई समाजवादी सम्मेलन (Asian Socialist Conference) सम्पन्न हुआ। 1953 में लोहिया ने 'इक्विडिस्टन्ट थ्योरी' (Equidistant Theory) नामक पुस्तक लिखी और समाजवादियों को कांग्रेस तथा साम्यवादियों से दूर रहने का परामर्श दिया। जून 1953 में बैतुल अधिवेशन में डॉ. लोहिया ने अपने सहयोगियों से कांग्रेस-सहयोगी नीति की आलोचना की। जब प्रजा समाजवादी दल कांग्रेस के प्रति मैत्री एवं समझौतावादी रुझान अपना रहा तो लोहिया ने 1955 में नए समाजवादी दल का निर्माण कर लिया जिसका नाम 'भारतीय समाजवादी दल' रखा गया। वे संयुक्त समाजवादी दल के अध्यक्ष बने। लोहिया ने भारत की परराष्ट्र नीति की आलोचना की। नेहरू की गुट-निरपेक्षता की नीति पर प्रहार करते हुए उन्होंने माँग की कि भारत को विदेशों में मित्रों की खोज करने चाहिए। डॉ. लोहिया का व्यक्तिगत विवादास्पद रहा। उन पर माक्स और गौरी दोनों का प्रभाव रहा, लेकिन न वे पुरे मार्क्सवादी हो बने और न पुरे गौरीवादी ही। वे 'समन्वयवादी विचारधारा' (Synthetic Ideology) के समर्थक थे और चाहते थे कि मार्क्सवाद या गौरीवाद का अनुकरण न करके उनके सिद्धान्तों की अमूल्य बातों को सीखा जाए।

राजनैतिक और सामाजिक विचार

डॉ. लोहिया ने इतिहास की गहरी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि इतिहास अपने निरिपत चक्र के अनुसार घूमता रहता है। इस चक्र में पुनरावृत्ति होती रहती है। लोहिया का विचार विख्यात यूनानी दार्शनिक अरस्तू के 'चक्र सिद्धान्त' (Cyclical Theory) का स्मरण दिलाता है। इतिहास सरल रेखा की भाँति आगे नहीं बढ़ता, बल्कि चक्रवत् गति से प्रभावित होता है। 'समय चक्र' के दौरान एक देश जो उन्नति के चरण शिक्षा पर है वह पतन के गर्त में गिर सकता है और पतन के गर्त में गिरा हुआ देश उन्नति करने लगे। डॉ. लोहिया की ऐतिहासिक धारणा 'ऐतिहासिक विकास' की धारणा से भिन्न थी।² लोहिया ने मार्क्स की दृष्टात्मक भौतिकवाद की धारणा को स्वीकार किया, किन्तु परम्परावादी मार्क्सवादियों की तुलना में उन्होंने चेतना पर जोर दिया। "लोहिया ऐसे सिद्धान्त की रचना के पक्ष में थे जिन्हें के अन्तर्गत आता अथवा सामान्य उद्देश्यों तथा इष्ट अथवा आर्थिक उद्देश्यों का परस्पर सम्बन्ध हो कि दोनों का स्वातंत्र्य अस्तित्व

1 ओंकार शर्मा, लोहिया के विचार, पृ. 10.

2 Ram Manohar Lohiya, *The Wheel of History*, p. 13-51

कायम रह सके।¹ लोहिया ने अपनी पुस्तक 'इतिहास चक्र' (The Wheel of History) में बताया कि इतिहास में जाति और वर्गों का संघर्ष दिखाई देता है। जातियों का रूप सुनिश्चित होता है जबकि वर्गों की आन्तरिक रचना शिथिल होती है और इन दोनों के बीच आन्तरिक क्रिया होती रहती है और वर्ग और जाति के बीच की आन्तरिक कृत्वल इतिहास को गति देती है। जातियों में गतिहीनता और निष्क्रियता पाई जाती है। जातियों की शक्तियों का प्रतिबिम्ब शक्ति है। वर्ग सामाजिक गतिशीलता की शक्तियों के साथ जातियों की शक्ति होकर वर्गों में परिवर्तित हो जाती है और वर्ग संगठित होकर जातियों में बदल जाते हैं।

लोहिया ने गांधीवाद और मार्क्सवाद के सिद्धान्तों की मिलाकर भारतीय समाजवाद का निर्माण करना चाहा। उन्हें पारंपरिक समाजवाद का अनुकरण अधिक नहीं था। उन्होंने मौलिक चिन्तन तथा एशियायी समाजवादियों की पहल पर जोर दिया। प्राचीन समाजवाद को लोहिया ने मृत सिद्धान्त और 'कल की बात' कहा तथा उसके स्थान पर कम्युनिज्म समाजवाद की बजाय रखा। लोहिया के अनुसार समाजवाद के तीन मुख्य तत्व थे—सभी ठगो, बैद्यों तथा बांग्ला देशियों का राष्ट्रीयकरण, सन्तुष्ट संसार में जीवनस्तर का सुधार तथा एक विश्व संसद की स्थापना। यह समाजवाद आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में था। लोहिया का विश्वास था कि यह समाजवाद सहकारी क्रम और आम सरकार के माध्यम से व्यवहारिक रूप ग्रहण कर सकता था।² 1952 में कमिंस समाजवादी दल के अध्यक्ष के रूप में लोहिया ने गांधीजी के विचारों को समाजवादी चिन्तन में अधिक स्थान देने की बात कही। उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि साम्यवादियों की तरह बड़े कारखाने न लगा कर, लघु मशीनों की महत्व दिया जाए ताकि छोटी लागत लगाकर अधिकाधिक मनुष्यों को कार्य मिल सके। अपने समाजवादी सहयोगियों—जयप्रकाश नारायण, अरुण मेहता आदि से उनके नीति-विषयक मतभेद बने रहे। उन्होंने कमिंस और समाजवादियों के बीच वैसी की समझौतावादी नीति को अपसंख्य नहीं माना। जून 1953 में अरुण मेहता ने यह विचार प्रस्तुत किया कि 'पिछड़े हुए अर्थव्यवस्था' की क्या 'अनिवार्य मजबूरियाँ' हैं? इसमें उन्होंने यह स्पष्टित करने का प्रयत्न किया कि कमिंस की विचारधारा समाजवादी विचारधारा के निकटतम आती जा रही है। उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि ऐसी परिस्थिति में कमिंस और प्रजा समाजवादी दल में सैद्धान्तिक मंथन हो जानी चाहिए, लेकिन इसके अभाव में डॉ. लोहिया ने अपना 'समानांतर सिद्धान्त' (Equidistant Theory) रखा और यह मुक्ति प्रस्तुत की कि समाजवादी आज कमिंस से उल्टे हो दूर हैं जितने साम्यवादियों से और ये समानांतर रेखाएँ अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों के कारण कभी मिल नहीं सकती। लोहिया ने यह पसन्द नहीं किया कि प्रजा समाजवादी दल कमिंस से विरता करे और वह भी नीति-विषयक मुद्दों पर।³

अप्रैल 1966 में कोटा में संयुक्त समाजवादी दल ने अपने अधिवेशन में कुछ सिद्धान्तों की स्वीकार किया और डॉ. लोहिया के निर्देशों के अर्पण राजनीतिक कार्यक्रम तय किया। डॉ. लोहिया ने दल को 7 प्रस्तावों को पारित करने की सलाह दी। उनमें मत था कि इन प्रस्तावों को ध्यानीय करने पर समाजवाद के सार्वभौम सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया जा सकता था—1. रोजी-रोजगार समानता की स्वीकृति, 2. रंग-भेद पर आधारित असमानताओं की समाप्ति, 3. न्याय और जाति-सम्बन्धी असमानताओं की समाप्ति, 4. विदेशियों द्वारा दमन की समाप्ति और विश्व सरकार का निर्माण, 5. व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आधारित आर्थिक असमानता का विरोध एवं उत्पादन की योजनाबद्ध वृद्धि, 6. व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध एवं 7. युद्ध शक्तों का विरोध तथा सविनय अवज्ञा के सिद्धान्त की स्वीकृति।

डॉ. लोहिया समाजवादी आन्दोलन के कीर्ति-स्तम्भ थे। उन्होंने भारत की अलग-अलग की दृष्टि से सोचा था। समाजवादी नेताओं में जयप्रकाश नारायण और डॉ. नीरजदेव पर जहाँ मार्क्सवाद का अधिक प्रभाव रहा वहीं लोहिया पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव अधिक था। लोहिया समाजवादी धारा के गरम प्रवक्ता थे जिनके भ्रमण-आँकड़ों और आलोचना में भरे रहते थे। लोहिया की विशेषता थी कि 'उन्होंने समाजवादी चिन्तन की संस्थाओं की शृंखला की दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया। वे कभी पंढरवादी नहीं थे। उन्होंने कभी तथा चिन्तन के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की समस्या को सदैव ध्यान में रखा। वे चाहते थे कि मनुष्य के जीवन और स्वभाव की अपेक्षात्मक हो। वे इस पक्ष में नहीं थे कि व्यक्ति के विशिष्ट पहलू की एकांगी और सीमित वृद्धि हो।'⁴

1. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा : वही, पृ. 447.

2. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा : वही, पृ. 447.

3. लेबरन सन्दीप (नवम्बर-मार्च, 1972) जनकपुर मुक्त का लेख : राष्ट्रीय समाजवादी दल की बदलते रूप पृ. 124.

4. वही, पृ. 123.

5. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा : वही, पृ. 443.

भारतीय स्वाधीनता संग्राम का स्वरूप एवं रणनीति (Nature & Strategy of Indian Freedom Struggle)

राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का पर्याय है। "जब किसी राष्ट्र के नागरिक स्वान्, भेदापन, छान पान, धन-सहन भाषा-साहित्य, मूल्य, मान्यताओं, जाति समूह और धर्म आदि के अन्तर होते हुए भी सभी को एक समझते हैं और राष्ट्रिय के समक्ष अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का परित्याग करते हैं यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है।" समाज विज्ञानी ब्रुबेज (Brubaches) के अनुसार "साधारण रूप में राष्ट्रीयता देश प्रेय की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक श्रेय की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में स्वान्, जाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं के सम्बन्ध उल्लिखित होते हैं।" 1961 में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की रिपोर्ट (National Integration Conference Report, 1961) के अनुसार "राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों के हृदयों में एकता, संगठन, समिष्टता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रतिक्रिया एवं भावना का विकास किया जाता है।" डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार "राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है, जिसमें सत्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का प्रमाण सम्बन्ध है।"

भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

भारतीय राष्ट्रवाद का उदय 1857 की क्रांति के समय से माना जाता है। 1857 का व्यापक सैनिक विद्रोह अंग्रेजी राज के विरुद्ध भारतीयों का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम था जिसे निर्भयता से कुचल दिया गया और फरिगियों ने कठोर नियम बमून लागू किये। बामसन गैरत और मैलेसन द्वारा लिखित कुछ अश्ल अंग्रेजी दमन नीति को स्पष्ट करते हैं—"हर एक हिन्दुस्तानी जो अंग्रेजों की तरफ से नहीं सह रहा था उसे हत्या माना जाए। दिल्ली निवासियों का कल्ले-आम किया जाए।" 1) ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में गवर्नर जनरल की ठकालीन दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, "यौन-गर्व में आग लगाकर लोगों को मार डाला गया। पौंसो देने वाले हल जिलों में गये। पौंसो देने वाले लोग शौकिबा से जिन्होंने कलात्मक ढंग से लोगों को मारा। कई जान लेने के ढंग आविष्कृत किये गये। और सम्बरकर की पुस्तक 'स्वातंत्र्य संग्राम का पहला युद्ध' पर प्रतिक्रिया लगा दिया गया। इससे सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीयता की धूम धप गई और जनक्रान्ति की बल मिला।" 2) अंग्रेजी शासकों ने क्रांति के बाद शासन व्यवस्था में सुधार किए और शासन के कार्यों में भारतीयों का सहयोग लेना आरम्भ किया लेकिन सुधारों की गति धीमी थी। कई स्वयंसेवी राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों का स्थापना हुआ। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों की स्थापना में अग्रम भूमिका हलबर्ट विल की रही। इसके अनुसार भारतीय व्यावाधीशों को भी यूरोपीय अपराधियों को दण्ड देने का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेजों ने इस विल का विरोध किया। डेनरी कौटन के अनुसार, यूरोपियन। द्वाारा इस न्याय संगठन बनून का विरोध करने पर भारतीयों को राष्ट्रीय राजनीतिक सभा के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई जिसके माध्यम से वे अपनी आवाज सरकार तक पहुँचा सके। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सन् 1883 के अन्तिम माह में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अखिल भारतीय संगठन की मुहूर्त रूप देने की अनुशासा की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने भारतीयों को योजना का अनुमोदन किया। डफरिन के बधनों से आरम्भ होकर सर ए. ओ. ह्यूम ने कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों एवं पचास शिक्षित नवयुवकों से स्वातंत्र्य हितार्थ अपील की, फलस्वरूप 28 दिसम्बर, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय

1 V. J. Savarkar First War of Freedom p. 89

2 डॉ. सुभाष करपूर - सार्वजनिक विकास और स्वातंत्र्य संघर्ष पृ. 45

धर्म सुधारक, विचारक एवं सत्यप्रिय व्यक्तित्व—राजा राममोहन राय सर्वधर्म धिय एवं सत्यनिष्ठ विचारक थे। उन्होंने हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई धर्मों का अध्ययन एवं चिन्तन किया। उन्होंने एकेस्वरवाद, एण कर्मों से दूर रहने एवं सच्चे, शुद्ध जीवन पर बल दिया। ब्रह्म समाज में परमेश्वर की उपासना का ढंग सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए उपयुक्त था। जप, माता और अङ्गुष्ठ रहित जीवन को अपनाना राजा राममोहन राय ने उत्कृष्ट जीवन बतलाया।

महान् समाज सुधारक एवं अन्याय विरोधी—राजा राममोहन राय समाज सुधारक थे। सती प्रथा को अमानवीय समझ करार देते हुए उन्होंने इसके विरुद्ध आन्दोलन चलाया। अतिवादी एवं कट्टर व्यक्तियों ने उनका विरोध किया। उनके आग्रह को मानते हुए तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिन ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। जूरी एक्ट 1827 के अनुसार ईसाइयों के मुकदमों के दौरान कोई मुस्लिम या हिन्दू जूरी का सदस्य ही बन सकेगा जबकि हिन्दू मुस्लिमों के मुकदमों की सुनवाई के दौरान ईसाई जूरी के सदस्य बन सकेंगे। इस कानून का राजा राममोहन राय ने विरोध किया एवं ब्रिटिश सरकार को इसके खिलाफ ज्ञापन भेजा। सेना के भारतीयकरण को भी गंभीर राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश शासकों के समक्ष रखा।

आधुनिक युग प्रणेता—राजा राममोहन राय आधुनिक युग प्रणेता हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अनुशार "राजा राममोहन राय ने आधुनिक युग का सूत्रपात किया है। वे भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पिता और राष्ट्र के अमरदूत हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों के द्वारा राजनीतिक जागृति के लिए मार्ग तैयार किया"।¹

भारतीय राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नवजागरण के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883)

भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक सांस्कृतिक महानता में विश्वास पैदा कर पुनर्जागरण करने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। मूलतः कर के नाम से पहचाने जाने वाले बौद्धिक व्यक्तित्व का जन्म 12 फरवरी 1824 को काठियावाड़ (सौराष्ट्र) के धीरवी जयपद के टक्करा ग्राम में हुआ। उन्होंने मानसिक परतन्त्रता से भारतीयों को मुक्त करने के लिए हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाकर भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में दूरदर्शी और प्रेरणास्पद कदम उठाया। स्वामी दयानन्द के शब्दों में—“जिस देश में एक भाषा, एक धर्म और एक वेशभूषा को महत्व नहीं मिलेगा, उसकी एकता लड़खड़ा रहेगी।” स्वामीजी ने गरी प्रतिष्ठित शब्दों के सम्मान, हिन्दू धर्म और ब्रह्मपर्यं के पालन पर जोर दिया। वे गैर अद्वैत श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले स्वामी जो यति पूजा के विरोधी थे। वे वेदों के आदेशों पर चलते थे एवं वैदिक मंत्रों से नियमित सध्या एवं हवन करते थे। उनके जीवन का लक्ष्य सर्वथा सत्य का प्रचार, एकता और समस्त भारतीयों को प्रेममय बनाना था। वे देशी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिससे भ्रष्टाचार में कोई प्राणी जीवनपर्यन्त दुष्टी न हो।

स्वामीजी स्वातंत्र्य के समर्थक थे। उनका कहना था, “स्वातंत्र्य से अच्छा सुराज कभी नहीं हो सकता।”। स्वदेशी वस्तुओं और वेशभूषा के समर्थक थे। वे कहते थे—“जब अंग्रेजों ने भारत आकर तुम्हारी वेशभूषा नहीं अपनाया तो तुम्हें अपने देश में ही अपनी वेशभूषा को छोड़ने की क्या आवश्यकता है।”² स्वामीजी का विचार था, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से पराधीनता एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग्रत होता है।³ उन्होंने वेदों का हिंदी में भाष्य किया और शास्त्रार्थ द्वारा ईसाई धर्म का हिन्दू धर्म पर आक्रमण से रक्षा की। उनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश राष्ट्रवाद के लिए बरदान साबित हुई। स्वामी दयानन्द सरस्वती राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन नहीं किया था, आ लेखन में कोई बग़ावत नहीं थी। सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित लेखों में उनके द्वारा देश की पराधीनतावश हुई दुर्दशा को पढ़कर पाठक भावुक हो जाते थे। 7 अप्रैल 1875 को मुम्बई में स्वामीजी ने आर्य समाज की स्थापना की। 30 अक्टूबर, 1883 को उनका निधन दूध में जहर पिलाने से हो गया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती के अवसान के बाद उनके अनुयायियों ने राष्ट्रवाद की उन्नति का क्रम अचरित रखा। शाला राजपूतवर्ष, स्वामी ब्रह्मानन्द, सरदार भगतसिंह, लाला हरदयाल और भाई परमानन्द आर्य समाज के समर्थक थे। राष्ट्रीयता के क्षेत्र में आर्य समाज के समर्थकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया।

भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान और व्यावहारिक धर्म का प्रचार रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानन्द

स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। काली देवी के उपासक रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने धार्मिक एवं राष्ट्रीय उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रामकृष्ण

1 डॉ. सुधाकर कश्यप, सांस्कृतिक विश्वास एवं स्वतन्त्रता समर्थक पृ. 67

2 S. N. Banerji, A Nation in the Making p. 40-44

परमहंस का मानना था कि पाश्चात्य सस्कृति से भारतीय सस्कृति श्रेष्ठ है, क्योंकि पाश्चात्य सस्कृति भौतिक है जबकि भारतीय सस्कृति आध्यात्मिक है। वे सभी धर्मों को समान धर्मों का अंश मानते थे। रामकृष्ण परमहंस के उद्देश से चन्द्रसेन जैसे विद्वान् एवं नोबल जैसे नाटिक ईश्वर के अन्य भवत बन गये। एक सन्त के शब्दों में, "आर्य समाज और हिंदोसोफिकल सोसायटी की कमी रामकृष्ण परमहंस ने पूर्य की। उन्होंने धर्म की व्यावहारिक बनाकर धार्मिक और सांस्कृतिक जगृति उत्पन्न की।" उनका स्वर्गवास 15 अगस्त, 1886 को हुआ। उनके देहावसान के बाद नोबल जो विवेकानन्द बने, ने सन् 1886 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का स्थापना के पीछे विवेकानन्द का उद्देश्य राष्ट्रवाद के उत्थान के साथ वेदान्त और व्यावहारिक धर्म का प्रचार देश-विदेश में करना था। विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन का मुख्य कार्यालय कोलकाता के बेल्लेयर में तथा बांग्लादेश में मठ स्थापित किए। रामकृष्ण मिशन की शाखाएँ म्यांमार, मलाया, अमेरिका, क्रीतका तथा यूरोप में स्थिति की गईं।

विश्व धर्म सम्मेलन शिवागो में—स्वामी विवेकानन्द ने भारतवर्ष में पैदा भ्रमन कर आध्यात्मिक उद्देश्य दिए। 1893 में स्वामी विवेकानन्द विश्व धर्म सम्मेलन में शिवागो में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। स्वामी विवेकानन्द ने समानता के नाते जब सम्मेलन में उपस्थित लोगों को धर्म-बहिष्कार कहकर पुकारा तो सब स्तब्ध हो गये। विवेकानन्द ने स्पष्ट किया कि भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व गुरु है और रहेगा। उनकी पर्यु एवं अध्यात्म अनेक भाषा में कम न थी। उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में कहा, "जब तुम हिन्दू धर्म के बारे में नहीं जानते तो हाग्वरम के बारे में फैसला कैसे कर सकते हो?" शिवागो सम्मेलन की विद्वान् शक्तों के उन्मत्तमान अध्यक्ष स्वामी विवेकानन्द ने भारत का आह्वान किया था—"गर्ब से जागो कि हम भारतवर्षी हैं, और प्रत्येक भारतवर्षी मेरे भाई है भारतवर्षी मेरे प्रान्त है, भारत के देवो-देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत का रामान् मेरे बचन का झुका, मेरी जयन्ती की फुलवाये, मेरा पवित्र स्वर्ग और मेरे बुढ़ये का कारो है। चाई यन्ने कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च है, भारत का कल्याण मैं मेरा कल्याण है।"

भारतीय राष्ट्रवाद का नूतन अध्याय द्विधोसोफिकल सोसायटी एवं एनी बीसेन्ट

1875 में कली मरिला मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल अन्वर्ट ने न्यूयार्क में द्विधोसोफिकल सोसायटी की स्थापना की। वे स्वामी दयानन्द सरस्वती के निमन्त्रण पर भारत आये थे। उन्होंने हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता की मित्र किया। बहाने आर्य समाज एवं स्वामी दयानन्द ने "स्वधर्मो रक्षणे श्रेयः" पर बल दिया, तथापि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने उनके तर्कों का नहीं माना और उनकी क्षतिपूर्ति का कार्य द्विधोसोफिकल सोसायटी ने पूरा किया। राष्ट्रवाद पर जोर देने एवं पाठशालों के बहाने में न आने के लिए मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल अन्वर्ट ने धुरजोर प्रयास किया। निमिरे एनी बीसेन्ट इस गतिपटी की प्रमुख कार्यकर्त्री बन गयीं।

एनी बीसेन्ट—एनीबीसेन्ट मूलतः आपसीगढ़ की रहने वाली थी। वे 1893 में भारत में द्विधोसोफिकल सोसायटी की सदस्या बनकर आई थीं। वे इस सोसायटी की अध्यक्ष बन गईं। वेद व्यवस्था वर्ग व्यवस्था एवं टांगिपटी में उनकी आस्था थी। उनके अनुसार हिन्दू सस्कृति पाश्चात्य सस्कृति से श्रेष्ठ थी। निमिरे एनी बीसेन्ट ने सैद्धांतिक हिन्दू लाईकूज एवं बलिष्ठ की बागनी में स्थापना की। उनका विश्वास मुर्तिपूजा में था एवं वे बाल-विवाह सही प्रथा के विरुद्ध थीं। इण्डियन होमरूल आन्दोलन की चलने का त्रेय उनकी की जाता है। इण्डियन नेशनल काँग्रेस में उनकी उन्मत्तनीय भूमिका रही। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस में उन्हें अध्यक्ष चुना गया।

भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के कारण

भारत में पाश्चात्य सम्पर्क और ब्रिटिश राज्य के विस्तार पाश्चात्य शिष्टा के शास्य एवं विप्लव के प्रसम्बरण भारतीय राष्ट्रवाद की अप्रतुर्ब दिशा मिली, परिणामस्वरूप भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। प्रारम्भिक काल में पाश्चात्य सम्पर्क हानिकारक सिद्ध हुआ, परन्तु भारतीयों के मानसिक क्षितिज के विकास के साथ परिवर्तित परिस्थितियों की परिणति एक नये दृष्टिकोण को लेकर हुई। पाश्चात्य सम्पर्क और पाश्चात्य शिष्टा ने भारतीयों के जीवन में बौद्धिक एवं राजनीतिक परिवेश की नींव डाली। भारतीय विद्वानों, विचारकों एवं सुधारकों ने भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति के प्राचीन स्वरूप का समन्वय पाश्चात्य संस्कृति से कर ठोस सञ्जलभ आदाम बनाया। विदेशी राज्यों ने भारतीय अंदोल के गौरव की अनुकूलता को क्षीण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरी ओर पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाओं, पाश्चात्य चिन्तन ने भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक स्वरूप एवं सामाजिक मूल्यों पर क्रांतिकारी छान छोड़ी। पाश्चात्य बुद्धिवाद, उदारवाद तथा पुनर्जागरण की लहरों से भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चिन्तन प्रभावित हुआ। भारत में नवीन जनता के उद्भवित कारण थे—

1. **पारचात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव**—अंग्रेजों के सम्पर्क से भारत में पारचात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रसार हुआ। लॉर्ड मैकाले ने लॉर्ड विलिंगडन बैटिक के कक्ष में अंग्रेजी सरकार से अप्रार्थ किया कि "भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए ताकि भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार जैसी लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली को मँग करे।" 1813 में चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीयों में शैक्षणिक प्रचार-प्रसार के लिए एक लाख रुपये खर्च करना तय किया गया। 1833 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था, "अंग्रेजी इतिहास में वह गर्व का दिन होगा जब पारचात्य ज्ञान में शिक्षित होकर भारतीय पारचात्य संस्थाओं की मँग करेगे।"¹

2. **समाचार-पत्र और साहित्य**—भारतीय राष्ट्रवाद के उदय, विकास और प्रसार के मूल में अंग्रेजी एवं भारतीय प्रेस की उत्प्रेक्षणीय भूमिका रही। समाचार पत्रों ने विदेश नीति के विवादों, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों एवं ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, प्रशासनिक व्यापारों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। राजनीतिक संगठनों, नेताओं ने समाचार-पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद पैदा किया। शरद्विध अवस्था में प्रेस अंग्रेजी समाचार-पत्र विकासशील थी, लेकिन कानाडा में विभिन्न भाषी समाचार-पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की दमनीय नीति की आलोचना की गई तो अंग्रेज सरकार ने 1879 में कर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर भारतीय समाचार-पत्रों की अधिकांशता की स्वतन्त्रता पर रोक लगा दी। उस समय हिन्दू पेट्रियोट, हिन्दी मित्र, अमृत कान्त पत्रिका, केसरी, नवशक्ति तथा सत्या नामक पत्र प्रमुख थे। साहित्य की भूमिका राष्ट्रवाद के उदय में कम नहीं रही। बंकिमचन्द्र चटर्जी के आनन्दमठ, उनके गीत 'वन्दे मातरम्', रवीन्द्रनाथ टैगोर के 'जा गण मन' एवं मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती' नामक पुस्तक ने भारतीय राष्ट्रवाद को जाग्रत करने में समर्पित भूमिका का निर्वहन किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटक 'भारत दुर्दशा' ने भारतीयों की दमनीय दशा को प्रस्तुत किया। दादाभाई नौरोजी, रीनबन्धु मिश्र, लोकमान्य तिलक के साहित्य ने उत्साह एवं राष्ट्रवाद की भावना से पूर्ण कर दिया, फलस्वरूप भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।

3. **सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन**—18वीं-19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन हुए। जिन्होंने राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, धर्मोत्तरीकित्तल सोसायटी एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की महानता, आध्यात्मवाद के साथ राष्ट्रवाद की प्रोत्साहित करने में सफल हो सके। राजा राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, पी. सी. सरकार, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पादरियों द्वारा फैलाने जा रहे दुष्प्रचार से बचने, हिन्दुत्व को अपनाने, अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर विश्वास करने, कुरीतियों को त्यागने एवं भारत की महानता प्रचारित कर देशवासियों में स्वाधिन्यम एवं राष्ट्रवाद की लहर जाग्रत की। भारत के गौरवशाली अतीत के प्रति जनता में विश्वास पैदा किया।

4. **यातायात के आधुनिक साधन**—अंग्रेजों के अपने व्यापारिक हितों के विकास, भारत के प्रशासन पर अपना नियन्त्रण मजबूत करने एवं अधिकाधिक आर्थिक लाभ उठाने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासकों ने रेलमार्ग, सड़कें एवं संचार व्यवस्था का निर्माण किया, यन्त्रों से साधन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को परस्पर निकट लाने में उपयुक्त साबित हुए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन शर्माहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यातायात के साधनों के विकास ने भारतीयों को सामाजिक रूप से सशक्त किया। रेल, सड़क आदि साधनों के सुलभ होने पर राष्ट्रवाद की लहरें सम्पूर्ण देश में गीरे समय में फैल गई।

5. **आर्थिक शोषण**—ब्रिटिश उद्योग एवं व्यापार ने आवश्यकतानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। उन्होंने भारत को ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादों की खपत के लिए उचित समझौता और उद्योगों के लिए कच्चे माल प्राप्त के लिए भारत का शोषण किया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर लेकर इंग्लैण्ड भेज देते और उसके द्वारा निर्मित माल का भारत से मनमाना बल वसूल जाता था। फलस्वरूप भारतीय उद्योग-धन्धे चौपट हो गए और अंग्रेजों का व्यवसाय उन्नति की ओर अग्रसर हो गया। यथा—विदेशों में भारत की वस्तु की घटती कीमत पर विरोध था, लेकिन अंग्रेजों ने लिवायुल और संकाशापर के कपड़ा उद्योगों की उन्नति के लिए इस उद्योग को नष्ट कर दिया। उस लौहा इंग्लैण्ड में स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धान्त प्रचलित था और 1877 में अणत शूल्स हटा लिया। इससे भारत में विदेशी कपड़े की बिक्री होने लगी। परिणामस्वरूप भारत का कपड़ा उद्योग बन्द हो गया।

6. **भारत के उद्योग, व्यापार एवं कृषि का विनाश**—भारतीय व्यापार को इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति ने तबाह कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की दमनीय दशा का प्रभाव 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रदर्शित हुआ। मार्क्स ने विवरण देते हुए इस दुर्दशा को स्पष्ट किया था, "सन् 1780 से 1850 के बीच भारत में ब्रिटेन से आये माल की कुल कीमत 386152 से बढ़कर 80,24,000 पौण्ड हो गई। 1850 में ब्रिटेन का कुली कपड़ा उद्योग का जो माल विदेशों में निर्यात किया जाता था उसका चौथा हिस्सा भारत में पहुँचता था। ब्रिटेन की जनसंख्या का आठवाँ हिस्सा इस उद्योग में लगा

हुआ था और इस उद्योग से ब्रिटेन की कुल आय का बारहवाँ हिस्सा मिलता था।¹ 1818 से 1836 के बीच ब्रिटिश ने भारत को चाय का निर्यात किया उसका अनुपात में वृद्धि 1 5200 था। 1824 में ब्रिटेन ने भारत का 60 00 000 गज मलमल भेजा था, लेकिन 1836 में 6 40 00 000 गज मलमल का निर्यात किया था। मलमल के लिए प्रसिद्ध ब्राह्म का आबदा 1,50 000 से घटकर 20 000 हो गई। एशिया में अमृतपूर्व क्रांति हुई जिससे भारतीय समाज का घुटा का रूप में पहचाने जाने वाले कारण और चारों ओर अस्तित्व सम्पूर्ण हो गया। गाँवों के अर्थिक जीवन को असन्तुलित एवं औद्योगिक नज़रों का नष्ट कर दिया गया। कृषि पर अत्यधिक संपन्न निदा गया और विचार के लिए असहयोग का मूख अपनया गया जिससे कृषि के क्षेत्र का विकास अवरोधित हो गया। कर में प्राप्त होने वाला राशि का 0.8 प्रतिशत का न्यूनतम धन सार्वजनिक निर्माण पर व्यय किया गया।

7 लार्ड लिटन की दमनकारी नीति—लार्ड लिटन की दमनकारी नीति ने राष्ट्रीय चेतना को बर्बाद किया। उनका शासन 1876-81 भारतीय राष्ट्रीयता का बाजोरोना का समय कहा जाता है। 1876 से 1878 तक दार्जिलिंग भारत में भयंकर अधोल पडा। ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंटों का सहायता नहीं की, इससे भारतीयों में अहिंसा सरकार के विरुद्ध राय का गया। लार्ड लिटन ने राज्यों, नवजात, महापुरुषों का बहुत बड़ा दरबार किया जिस पर अत्यधिक धन व्यय किया गया एवं घोषणा का मूख कि महापुरुष बिकेटोरिया ने भारत का सम्राज्ञा का उपधि धारण कर ला है। भारतीयों द्वारा दरबार का कड़ा आलोचना की गई। लार्ड लिटन ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध के लिए द्वितीय अफगान युद्ध में भारत का कराहो रुकवा नष्ट कर दिया। ब्रिटेन ने रूस विधायक लागू किया जिसका अनुसार भारतीयों का शासन रखने के लिए लार्डसेन सलाह अहिंसा था, अहिंसा को नहीं। बर्नाकूलर प्रस एव लार्ड लिटन की देन था, जिससे भारत के समाचार-पत्र को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। अर्थात् कर का हटाना, भारतीय वस्त्रों पर शुल्ग लगाना एवं अन्य दमनकारी कानून राष्ट्रीयता का ज्वाला को प्रज्वलित करने में कामयाब हुए और समस्त भारतीयों ने अहिंसा से छुटकारा पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया।²

8 भद्रभक्तियों व्यवहार—भारतीयों के साथ पशुपतियों व्यवहार राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के साथ निम्न स्तर का व्यवहार किया जाया था। रेलवे कंपार्टमेंट में भारतीय अहिंसा के साथ नही बैठ सकते थे।

9 1857 की क्रांति—1857 का सैनिक विद्रोह राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण रहा। गाय के गोबर बाल कानून को मूख से खत्म करने का प्रयत्न करने के नतीजे में राष्ट्रीयता का प्रथम संप्रदाय हुआ। राष्ट्रीय क्रांति विफल रही, पर राष्ट्रीय चेतना भारतीय मानसिकता पर हवा खा गई।

10 इनडिपेंडेंट बिल सचिवी विचार—राष्ट्रीय आन्दोलन को इतकट बिन्दु में प्रवेश दिया। लार्ड लिटन का शासन काल में 1883 में लार्ड लिटन विधि भेजा था। उसने कानून व्यवस्था के विधायक पदों को दिया जिसमें कहा गया कि सचिव न्यायाधीशों को, चाहे वे भारतीय हों या अहिंसा, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अनुसार भारतीय व्यवस्था अहिंसा को दृढ़ कर सकते थे। इसका अहिंसा ने पुनः विचार किया। फलस्वरूप 1883 में अहिंसा निति के विचार के लिए सुन्दरनाथ बनर्जी ने एक कानून बुलाई, जिसका परिणाम राष्ट्रवाद की जागृति में सकारणक रहा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

एक क कई प्रांतों और नगरों में अनेक राजनातिक संगठनों की नींव डाल चुका था, परन्तु एक अहिंसा भारतीय राजनातिक संगठन का आवश्यकता था। इस दिशा में टल्मेखनाथ कार्य एक सेवकविभूत सरकार अधिकाय सा ए ओ ह्यम न किया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कहलाए। उन्हें इस संगठन के निर्देश दायित्व से प्राप्त हुए थे। उस संगठन की उद्देश्य अमनुष्य भारतीय बुद्धिजीवियों के समान सुरक्षा व्यवस्था करना था। सर ए. आ. ह्यम ने 1 मार्च, 1883 को कोलकाता विस्तारितान्य के सत्रों को एक पत्र लिखकर निवेदन पत्र से भर्तु सब में जुड़ जाने को अनुरोध का जिससे राष्ट्र का वैदिक, सामाजिक तथा राजनातिक पुनर्जागरण हो सके एवं व्यवस्था अमनुष्य सेना तैयार हो सके। परिणामस्वरूप 1884 में दिव्योत्सविकल कानून हुआ, जिसने दश के वैदिक एवं लिखित बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय सभा को स्थापना के विचार को मूर्त रूप देने का निश्चय किया। दिसम्बर 1884 में इंडियन नेशनल यूनिन को स्थापना की गई, जिसके उत्प्रेक्षणा प्रवर्तकों से 28 दिसम्बर, 1885 का मुम्बई का गाकुलदास तेजदल सम्मेलन राष्ट्रवादी में एक कानून का आयोजन हुआ। इसमें भारत के सब क्षेत्रों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नव विचार विमर्श एवं वाद विवाद के बाद इस सभा का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) रखा गया।

1. मार्क्स एंडे, सत्र प्रश्न अध्याय-15, अनुभाग-5.

2. Ishwari Prasad History of Modern India, p. 308.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य

यद्यपि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य को रद्द के लिए हुई थी परन्तु वही कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीयता का माध्यम बना। जिन विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश साम्राज्य को रद्दार्थ कांग्रेस की स्थापना हुई उनका अनुसार कांग्रेस के जनक सर ए. ओ. ह्यूम अवकाश-प्राप्त अग्रज पदाधिकारी थे जिन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डार्विन एवं अन्य प्रमुख अंग्रेज अधिकारियों का विश्वास प्राप्त था। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सैनिक विद्रोह में अग्रज अधिकारियों को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों में असन्तोष व्याप्त होता जा रहा। तथा राज्यवाद उभरना शुरू है अतः विद्रोह की ज्वाला पुनः भड़क सकती है। इसी विद्रोह के भय से मुक्ति पाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि उनके विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति न हो और इस समस्या का माध्यम से भारतीयों का झोझ झन्डो से निपटसता रहे। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को एक देशव्यापी संगठन द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम मानने वाली दूसरी विचारधारा के समर्थक स्वीकार है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे देश प्रेम और राष्ट्रीयता का अस्तित्व था।

1885-1905 कांग्रेस के उद्देश्य, कार्यक्रम, प्रभाव एवं ब्रिटिश दृष्टिकोण

दिनांक 1 मार्च 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व सर ए. ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। उन्होंने कीर्तिकाव्य शिखरिणीय के स्तानको को सम्योहित करते हुए अपील की—“आप सर्वाधिक रूप से शिक्षित भारतीय हैं। आपकी स्वाभाविक रूप से भारत की घातमिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का महत्वपूर्ण साधन माना जाएगा। यदि व्यक्तिगत हो या जातीय महत्वपूर्ण स्त्रोत अन्दर से होने चाहिए तथा इसका आधार आप हो जो इस देश के सभ्य, ज्ञानी एवं प्रगतिशील सम्पन्न नागरिक हों। आप देश के प्रिय पुत्र हो, देश इस कार्य की शुरुआत के लिए आपको देखता है। व्यर्थ मैं यह जैसे विदेशी भारत तथा उसके बच्चों को प्यार करते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। इस देश का लिए तथा उनके भले के लिए समय एवं धन देते हैं तथा विचार करते हैं। वे अपना शिरा एवं मुझावों से सहायता कर सकते हैं। वे इस कार्यकर्ताओं के लिए साधनरूप अपना अनुभव योग्यताएँ तथा ज्ञान प्राप्त करें, किन्तु इसमें जातीयता का आवश्यक गुण नहीं। वास्तविक कार्य देशवासी स्वयं कर सकते हैं।” “आप इस भूमि के जनक हैं। आप में से 90 व्यक्ति भा आत्म त्याग की सतीयजनक इच्छा देश के लिए गर्व एवं पर्याप्त ध्यान, परिव्रता एवं निस्वार्थ देशभक्ति की भावना नहीं रखते हैं तो भारत के लिए कोई आशा नहीं हो जाती है। उनके घेरे निम्न एवं अराहत्य होकर विदेशी शासकों का हाथ में पत्र बने रहेंगे। जब वे व्यवस्था पर घाट करेंगे तभी स्वतंत्र हो सकते हैं और जब तक नेताओं के विचार निम्न एवं स्थायी रहेंगे, वे देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। हर राष्ट्र एक अच्छी सरकार अपनी योग्यता अनुसार रख सकता है। यदि आप देश का सबसे शिक्षित व्यक्ति चुनेंगे तो वह व्यक्तिगत सुख एवं स्वार्थी लक्ष्यों का निरखार नहीं कर सकेंगा। तुम्हारे लिए एवं देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्थ होगा। एक अधिक निष्पक्ष प्रशासन प्रबन्ध में हिस्सा होगा तब हम तुम्हारे दोस्त बनने होंगे। पत्र के अन्त में उन्होंने अभिव्यक्त किया कि आम रजिस्ट्रार। एवं निस्वार्थ भावना स्वतंत्रता एवं धुशी के पक्ष-प्रदर्शक हैं।” सर ए. ओ. ह्यूम की अपील का शिक्षित भारतीयों द्वारा प्रयुक्त दिया गया। सम्पूर्ण देश में नेताओं से सम्बन्ध स्थापित करने के बाद ह्यूम ने दिसम्बर 1885 में देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों की संगठित कर एक सभा बुलाने का निश्चय किया। ह्यूम ब्रिटेन गये और वहाँ जाकर प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिज्ञों, जैसे लॉर्ड रिपन, जान ड्राइट आदि से सम्पर्क प्राप्त किया। इन गतिविधियों के उपरान्त डबल्यू. सी. बनर्जी की अध्यक्षता में मुम्बई में सम्पन्न पाठशाला के भवन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। सर ए. ओ. ह्यूम ने सभा के सचिव के रूप में उतारदायित्व निभाया। प्रथम अधिवेशन में 100 सदस्य उपस्थित हुए जिसमें सर्वाधिक मुम्बई के 38, चेन्नई के 21 बंगाल एवं पंजाब से तीनों ही प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली सभा में देश के विभिन्न भागों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए जिनमें बैरिस्टर, व्यापारी, भूमि पति, मैनेजर, डॉक्टर, पत्रकार, कानून सलाहकार, वकील, अधिकांश एवं सभी धर्मों के अनुयायी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ मामों ब्रिटिश सरकार के सम्पर्क रखी गईं वे हैं—(i) केन्द्र और प्रान्तों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। निर्धारित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए तथा उन्हें सभी प्रश्नों पर वक्ता करने बजट पर वाद विवाद करने के अधिकार दिए जाए। (ii) उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अवसर दिया जाए। (iii) सैनिक व्यवस्था में कमी की जाए। (iv) एक शाही आयोग भारतीय प्रशासन की जांच करे।

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में व्याख्यान और प्रस्तावों की भाषा विनय थी इसमें ब्रिटिश शासकों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन हुआ था। डबल्यू. सी. बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह स्वर में कहा था—“अधिकारी वर्ग के प्रति राजभक्ति का इजहार करती कांग्रेस सिर्फ इतनी माँग करती है कि सरकार को विस्तृत किया जाए और जनता

को सरकार में उसका उचित हिस्सा दिया जाए।" भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में संगठन को निश्चित आकार देने हेतु कुछ उद्देश्य इच्छु सी बज्जों ने अपने अध्यक्षीय भाषण में रखे। नये संगठन के लिए सुचीबद्ध किए उद्देश्य थे—1. ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय हित के लिए कार्य कर रहे व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं में व्यक्तिगत नियुक्ति और मैत्री भाव को बढ़ाना। 2. राष्ट्रवाद के भावों द्वारा राष्ट्र प्रेमियों के प्रत्यक्ष मित्रतापूर्वक व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्रीयवाद से उत्पन्न पक्षपात को दूर करना और सॉर्ड रिपन के शासनकाल में जमीं भावनाओं को प्रोत्साहित करना। 3. शिक्षित भारतीयों के सामयिक एवं सामाजिक सुधार से सम्बन्धित विचारों को क्रियान्वित करना। 4. आगामी वर्षों में स्वदेशी राजनीतिक हस्तियों के सार्वजनिक हित में किए जाने वाले कार्य के तरीकों का निर्धारण करना। समय के परिवर्तित होते रहने के साथ कांग्रेस के लक्ष्य आवश्यकतानुसार बदलते गए। आरम्भ में कांग्रेस ने छोटी माँगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा, किन्तु बाद में अपने उद्देश्यों को व्यापक बनाते हुए स्वशासन की माँग की गई। प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस प्रार्थना पत्र प्रस्ताव आदि पर विश्वास करती थी, आगे चलकर प्रत्यक्ष विधि-आन्दोलन आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन तक आ गई।

1885 से 1905 तक कांग्रेस के कार्यक्रम

1885 से 1905 तक कांग्रेस ने अनेक प्रस्ताव अपने अधिवेशनों में पास किए। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था। अपने विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये माँगें रखी गईं—1. गवर्नर और वायसराय की विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, अधिकारियों का बजाए चुने हुए सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए। 2. ब्रिटिश सेना की संख्या कम की जाए और सेना पर होने वाले अत्यधिक व्यय का रोक लगा जाए। 3. भारतीय सचिव को भारत परिषद से हटाया जाए। 4. स्थानीय सभाओं से सरकारी नियंत्रण हटाकर, उन्हें शक्तिशाली प्रदान की जाए। 5. नमक कर को हटाया या कम किया जाए। 6. बेरोजगारी को मिटाने, कृषि पर दबल काम किए जाने के प्रयास किए जाएं। 7. पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए एवं नये उद्योगों की स्थापना हो। 8. कार्यपालिका और न्यायपालिका को असल किया जाए। 9. विदेशों में भारतीय हितों की रक्षा की जाए। 10. भारतीय प्रशासनिक सेना (आईसीएस) की परीक्षाएँ भारत में कराई जाएं। 11. कृषि कर में कमी एवं किसानों को जमीनारों का शोषण से मुक्त कर दिया जाए। 12. कर्माभ्युक्त प्रेस एक्ट को हटाया जाए, प्रेस और समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता दी जाए। 13. किसानों का कम व्याज पर ऋण सुलभ करने के लिए कृषि बैंक खोले जाएं। 14. बड़े पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न की जाए। 15. भारत की निर्पेक्षा के कार्यों को छोड़कर उनके दूर किया जाए। 16. उद्योग, व्यावसायिक, टेक्नीकल, कॉलेज एवं स्कूल खोले जाएं। 17. सैनिक शिक्षा के लिए भारत में प्रविष्टा केन्द्र स्थापना जाए।

भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस के प्रथम युग (1885 से 1905) में कांग्रेस का आन्दोलन हुए, बेहरबर्न, व्योरेसफर बज्जों, सुरेन्द्रनाथ बज्जों, दादाभाई नौरोजी, सर श्रीरामजी मेहरा, गोपालकृष्ण गोखले, रामबहादुर मोक्ष, रामदास, मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक जैसे प्रखर बुद्धिवादी नेताओं के हाथ में रहा। 1896-97 तथा 1899-1900 में अकाल के हालात आ जाने के कारण भारतीयों की दुर्दशा बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज सरकार इसके प्रति उदासीन रुख अपना रही थी। एक करोड़ लोग मरे जा चुके थे और अनवरत लोग बूख से मर रहे थे, परन्तु अंग्रेज अत्र विदेश भिजवा रहे थे। 1901 में कलकत्ता में हुए 17वें अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। इस निम्ति में दुखी होते हुए तत्कालीन कांग्रेस स्वयंसेवक समिति के अध्यक्ष महात्मा जे. एन. राय ने कहा कि "प्रत्येक राजनीतिक प्रश्न मूल रूप से राजनीतिक प्रश्न है और इसमें आर्थिक प्रश्न का समावेश प्रमुख है। शीघ्र ही विश्व के बाजार रातोरात बन जायेंगे जहाँ विभिन्न राष्ट्रों के भाग का फैसला होगा।" इसी अधिवेशन में दुर्दशा की पुनरावृत्ति पर श्रेष्ठ प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दुर्दशा के ये कारण बताए गए—(अ) देशी उद्योग, व्यवसाय की अवनति, (ब) भारतीय पूँजी का निष्कासन, (स) कर भार में अत्यधिक वृद्धि, (द) प्रशासन के सैन्य एवं नागरिक विभागों में घनत्व का अभाव। कांग्रेस के 17वें अधिवेशन में देश में साधनों का विकास, खेती में कमी, कृषि विकास और उद्योगों के विकास की माँग उठाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम युग में कांग्रेस की नीति उदाहरणीय थी। सुधारवादी राजनीतिक संगठन की इच्छा थी। कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था किन्तु ब्रिटिश सरकार की जन्मजात अत्यधिकता तथा प्रजातान्त्रिक भावनाओं में विश्वास था क्योंकि वे अंग्रेजों सभ्यता एवं संस्कृति के आदर्श सचि में होते हुए विश्व वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उदारवादी भारत में नीकराजती के अन्तोलक एवं शासन में भारतीयों को अधिक अधिकार दिए जाने के पक्षपाती थे। ब्रिटिश संगठनों, सभाओं और अंग्रेजों की सहायता में उनका अटूट विश्वास था। उन नेताओं का मानना था कि भारत सार्वभौमिक उपायों द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति का पालन करते हुए ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करता चला जाएगा।

क्रान्तिकारी आन्दोलन के उदय के कारण

1. मध्यमवर्गीय आन्दोलन—क्रान्तिकारी आन्दोलन बंगाल में मध्यम वर्ग में फैला जिसमें पारिवारिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों ने भाग लिया। नवयुवकों के जोश ने इस आन्दोलन को गति दी। "सत्यन टाइम्स" के सवाददाता सर वेलेण्टाइन शिरोल का मत था कि क्रान्तिकारियों में पारिवारिक सम्पदा और संस्कृति के विरुद्ध कटुपथी बहनों ने एव अन्य जाति के नवयुवकों ने भाग लिया। गैर के अनुसार "क्रान्तिकारी आन्दोलन ब्रज्जनों द्वारा आयोजित पद्धत नहीं था बंगाल और पंजाब में इसके नेता अन्य जाति के थे।"

2. कॉमिस की अक्षमता पर तीखे प्रहार—अखिल भारतीय कॉमिस का प्रारम्भिक स्वरूप नरमवर्दी था, उसकी कार्यवाही धीमी थी जबकि नवयुवक वर्ग चाहता था कि सक्रिय राजनैतिक आन्दोलन के तयके अपनाए जाएं। अरविन्द घोष ने कॉमिस के तयकों की अक्षमता पर लेखमाला 1893 में "इन्दुप्रकाश" में लिखी जिसका नाम था "यू नैन्स फॉर ओल्ड"। उन्होंने विधान परिषदों के और भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ होने वाली परीक्षाओं को हाथ की मर्झा बतलाया और इस प्रकार की बातचीत की हैसी ठहरी कि ब्रिटिश शासन बरतान है और परमात्मा ने हमें इम्पेड का न्यायपूर्ण और उदार शासन की गोद में डाला है। अरविन्द घोष ने देतावनी दी—"अंग्रेजी राज के दुर्ग की दीवारें अभी फूटी नहीं हैं और गुरुबी की बाली छाया दिन-ब-दिन देश पर छाती जा रही है।" उन्होंने कॉमिस की मध्यमवर्गीय स्थायी, सार्वजनिक कार्य में धीली तथा निस्कार्य देशभक्ति का खोखला दावा करने वाली संस्था कहा। बान गंगाधर तिलक तथा अन्य नेताओं ने कॉमिस की नम नीति पर प्रहार किया। धनस्वरूप जहाँ एक बड़े वर्ग में उग्रवाद का जन्म हुआ, वहीं अधिक जोशों ने एक छोटे वर्ग की क्रान्तिकारी भावनाएँ उमड़ी और क्रान्ति का दौर चल पड़ा। अतः अखिल भारतीय कॉमिस को अपनी नरमवर्दी नीति को गिनारजिन देकर, सक्रिय राजनैतिक आन्दोलन को रूप में स्वीकार करना पड़ा।

3. आर्थिक कारण—19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में देश में आर्थिक अमनोश की लहर व्याप्त हो गयी और जनता भारत सरकार की अर्थ नीति से शुक हो गयी। अनेक भारतीय अर्थशास्त्रियों ने प्रमाण देकर भारत के शोषण और उसके परिणामों पर प्रकाश डाला। अकाल महामारी और भूदानों के कारण जनता की गरीबी बढ़ चुकी थी अतः सहारा पाकर नवयुवक क्रान्ति के मार्ग पर चल पड़े। लॉर्ड वेल्स के अनुयायी "अधिक दरिद्रता और अधिक अमनोश क्रान्ति को जन्म देते हैं।"

4. सरकार की प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी नीति—क्रान्तिकारी आन्दोलन के विस्फोट में सरकार की प्रतिक्रियावादी और दमनकारी नीति का हाथ रहा। लॉर्ड कर्जन की नीति ने क्रान्ति को प्रोत्साहित किया। पी. सी. राय के अनुसार उग्रवर्दी आन्दोलन की क्रान्तिकारी मन्त्रालय को लॉर्ड कर्जन की देन रहना अनुपपन्न नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन के आर्थिकशास्त्र सिद्धांत एक, भारतीय विस्त्रुविद्यालय अधिनियम तथा बंगाल विभाजन जैसे कार्यों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को बढ़ाने में योग दिया। सरकार ने जन-आन्दोलन को कुचलना चाहा, परन्तु उग्रवाद और क्रान्ति का उतेजक प्रसार हुआ। नवयुवकों ने देखा कि सभाओं, जुलूसों, बहिष्कार आदि के तयके विदेशी हुकूमत पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं फलतः उनकी बड़ी सख्त क्रान्ति के मार्ग पर चल पड़ी जिन्होंने विस्फोटक और हिंसामय साधनों को अपनाया शुरू कर दिया।

1908 में भारत सचिव लॉर्ड मर्ले ने वादमय लॉर्ड मिथो को लिखा कि "उग्रवाद तथा अन्य अपराधों के सम्बन्ध में जो दण्ड दिए जा रहे हैं, उनके कारण मैं चिन्तित हूँ। हम व्यवस्था बढ़ाते हैं, लेकिन व्यवस्था सने के लिए पोर कठोरता के उपयोग से सफल नहीं मिलेगी। इसका परिणाम उल्टा होगा और लोग बम का सहाय लेंगे।" मोन्टेग्यु ने 1910 में स्वीकार किया कि "दण्ड संहिता की सजाओं ने तथा नरक चक्राने की नीति ने माधारा और बिगड़े नवयुवकों को शहीद बनाया और बिलसकारी पत्रों की सख्या बढ़ा दी।"

5. सार्वजनिक आन्दोलन की विफलता—नाम दम की अतःक्रान्ति के काम धर्मोंय युवकों का वैधानिक मार्ग में विश्वास नहीं रहा। उन्हें विश्वास हो गया कि हाथ-पैर जोड़ने और प्रार्थना-पत्र भेजने से देश की आजादी नहीं मिल सकेगी। आजादी पाने के लिए शक्ति संचित करनी होगी तथा तब माधनों का सहाय लेकर विदेशी हुकूमत की जड़ें उखाड़नी होंगी। क्रान्तिकारियों ने कहा "अंग्रेजी शासक पश्चिम बल का प्रयोग करते हैं पर दण्डित हैं।" उन्होंने नया लगाया कि "तलवार हाथ में लो और सरकार को मिटा दो।" "की लक्ष्य नैतिकता के प्रभाव में जन नहीं हो सकना, वह मोली और बम के प्रयोग से हो सकता है।"

6. विदेशी क्रान्तिकारी सभाओं से प्रेरणा—रूस, इटली आदि की युव क्रान्तिकारी सभाओं से भारत के जोशोंने नवयुवकों को प्रेरणा मिली। उन्हें यह चह पैदा हुई कि देशी क्रान्तिकारी देश-विदेश में युव सम्पर्क कायम करें और विदेशी सत्ता को उखाड़ दें।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का विकास

क्रान्तिकारी आन्दोलन को निर्देशित एवं निर्दिष्ट करने वाली कोई केंद्रीय संस्था नहीं थी, अतः इस आन्दोलन की गतिविधियाँ प्रान्तों स्तर तक सीमित रही और एक सीमा तक विदेशों में रही।

पञ्चाब में क्रान्तिकारी आन्दोलन—1907 में क्रान्ति की आग पञ्जाब में फैल गई। सरदार अजीतसिंह भाई परमानन्द उनके छोटे भाई बालमुकुन्द तथा लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारियों का संगठन करने में पहल की, तथापि पञ्जाब का क्रान्तिकारी आन्दोलन बगल और महापट्ट के क्रान्तिकारी आन्दोलन के समान नहीं था। वहाँ गुप्त सत्कार नहीं खेती गई और न ही राजनीतिक हत्याओं अथवा ठगैरियों का दौर चला। पञ्जाब के प्रमुख क्रान्तिकारियों ने 'अनुमन-मुहिबाने वतन' नामक एक सभा स्थापित की जो 'भारत माता' के नाम से प्रसिद्ध थी। 'उपनिवेश'करण विधेयक, जिससे मलगुजारी में वृद्धि हुई और सम्पत्ति-विभाजन के अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ, का विरोध करने के लिए सरदार अजीतसिंह और सैफुद्दीन हजरतिया ने 'इंडियन पेट्रिओट्स एसोसिएशन' (Indian Patriots Association) नामक सभा की स्थापना की। सरदार अजीतसिंह ने किसानों की विद्रोह के लिए भड़कावा और किसानों ने सरकार का कर न देने की प्रवृत्ति की। सत्यनान्त एव प्रबोधचन्द के अनुसार, "सरदार अजीतसिंह, सूची अम्बाप्रसाद, लाला पिंडोदास एव लालचन्द फलक ने पञ्जाब में जागृति लाने का निरर्थक कार्य किया जो बागल में बकिमचन्द्र दहियाँ तथा अन्य बागली लेखकों ने किया।" 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के प्रान्त लेने का प्रथम क्रान्तिकारियों ने किया। पञ्जाब में क्रान्तिकारी आन्दोलन की अमेरिका से लंटे कुछ सिक्खों ने मजबूत किया। पञ्जाब में स्थिति उस समय शान्त हो गई जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मिन्टो ने उपनिवेश'करण विधेयक को 'वीटो' (Veto) कर दिया।

विदेशों में क्रान्तिकारी आन्दोलन—भारत के बाहर क्रान्तिकारी क्रियाशील हुए। इम्फण्ड में श्यामजी कृष्ण वर्मा और बीर सक्ताकर ने, फ्रांस में मैडम कामा ने और अमेरिका में लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद के संगठन में भूमिका निभाई। इम्फण्ड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 'इंडियन होमरूल सोसैटी' की स्थापना की तथा क्रान्तिकारियों का सुसांठित दल बनाया जिसका केन्द्र 'इंडिया हाउस' था। इम्फण्ड से भारत में क्रान्तिकारियों को इशियार तथा सहाय्य पञ्जाब का प्रथम किया गया। जुलाई 1909 में क्रान्तिकारी दल के एक सदस्य ने 'इंडिया हाउस' के सर विलियम बिनी की हत्या कर दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस दल को छिन्न-भिन्न कर दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रान्तिकारी यूरोप के अनेक देशों में क्रियाशील हुए। क्रान्तिकारी नेता वीरचन्द्र चट्टोपाध्याय ने जर्मनी के विदेश कार्यालय की सहायता से बर्लिनवासी भारतीयों की एक समिति बनाई और स्वयं उसके सचिव बने। यह समिति 'भारतीय स्वतन्त्रता समिति' के नाम से जाना गई। वीरचन्द्र और समिति ने बादाद इन्डो-यूरोप, पर्सिया और कबुल में अपने प्रचार मण्डल भेजे जिन्होंने भारतीय सभा की दुकानियों और भारतीय मुद्र-बन्दियों के बीच काम किया। एजा महेन्द्र प्रधान को मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अबेदुल्लाह के माध्यम से कबुल भेजा गया जहाँ उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार काई।

लाला हरदयाल अमेरिका पहुंचे जहाँ तरकामा दास और मोहनसिंह ने परिचयों दत्त पर बसे भारतीय प्रवासियों के बीच क्रान्तिकारी संदेश दिए। उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की और 1 नवम्बर, 1913 से सप्ताहिक गदर नामक पत्र प्रकाशित किया। पार्टी ने बही नाम अपना लिया। इसके कार्यक्रमों में सैनिकों के बीच कार्य, अधिकारियों की हत्या, क्रान्तिकारी, साम्राज्यवाद विरोध सहाय्य का प्रकाशन और अस्त्र प्रशिक्षण थे। इसका मुख्य कार्यालय सप्त-प्रसिद्धियों में रहा। राष्ट्र अमेरिकी दत्त और पूर्व के देशों में स्थापित हुई। विचार यह था कि एक साथ सारे ब्रिटिश उपनिवेशों में क्रान्ति की जाए। गदर ने एक विषय प्रकाशित किया—अधरपकड़ा है बीर सिन्धियों की। वेल्स मृत्यु। पुनश्च इन्द्र। केवल स्वतन्त्रता। मुद्रस्थान भारत। वास्तव में विदेशों में क्रान्तिकारी विचारधारा ने अभी बल पकड़ा और भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में स्फूर्ति का संचार किया। सर वेलेन्टिन रिटेल के अनुसार इन्डो-अमेरिकन एसोसिएशन और यंग इंडिया एसोसिएशन नामक दो सत्कार भारत की समस्त राजद्रोही सत्कारों से सम्बद्ध थी। क्रान्तिकारी आन्दोलन को असफलता हमलए हाथ लगा क्योंकि भारतीय नदामों में पारस्परिक समन्वय का और भारतीय क्रान्तिकारियों तथा विदेशों की मदद पक्षियों से सम्पर्क का अभाव था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने क्रान्तिकारियों से बदला लिया। सप्त-प्रसिद्धियों में गदर पार्टी के नेताओं पर मुकदमे चले, अनेक अमेरिकी में क्रान्तिकारी गतिविधियों की सम्भवनाएँ खत्म हो गईं।

क्रान्तिकारी आन्दोलन की प्रकृति और कार्य प्रणाली

क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद लाल-बल-पास, धोष अदि के राजनीतिक उपवाद से भिन्न था। दण्डको, ठगैरियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति से असन्तुष्ट होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सक्रिय विरोध का प्रदर्शन करते थे, लेकिन यह विरोध शान्तिमय और दबावपूर्ण होता था। क्रान्तिकारी नवदुक्क उदार राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण से सम्मत नहीं थे। उनका विचार था कि जो साम्राज्यवाद पशु बल पर आधारित है उसे शक्तिपूर्व आन्दोलन की सफल प्रणाली से नहीं बल्कि हिंसा द्वारा बर्बाद कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिद्वन्द्वी और दमनकारी नीति ने उनकी धारणा को पुष्ट कर दिया था।

क्रान्तिकारी 'बम नैति' (The Cult of the Bomb) में विश्वास रखते थे। साथ ही साधन से अधिक उद्देश्य मानते थे। उनकी दृष्टि में साथ ही पवित्रता साधनों का औचित्य थी, अनेक स्वतन्त्रता प्रशिक्षण के लिए उन्होंने हत्याओं, लूट, दण्ड, सरकारी सम्पत्ति के विनाश, टोड़-फोड़ अदि को अनुचित नहीं समझा। क्रान्तिकारी युवाओं का व्यक्तित्व मित्रवत्तों से, क्रान्ति

4. भारतीय राजनीति के अधिपति नेता मधुसूदन वर्मा के ये, जिनका हिंसामय कार्य में विश्वास नहीं था। उनसे आस्था सौवधानिक साधनों में थी। वे उपकारी दंड-वर्गीक अपना सकते थे, लेकिन हिंसामय और विस्फोटक तरीके नहीं। इन नेताओं का क्रान्तिकारी आन्दोलन को सहयोग नहीं मिल सका।

5. क्रान्तिकारी आन्दोलन धनाभाव से परेशान रहा। भारत का धनिक वर्ग तुर्क और हिंसामय तरीकों से परेशान था। उसने सौवधानिक तरीकों को आर्थिक सहायता दी परन्तु क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति उसका दृष्टि अपेक्षापूर्ण रहा। बहुसंख्यक हिन्दुओं को भी जो हिंसामय तरीकों के विरोधी रहे हैं, क्रान्तिकारियों से कोई सहानुभूति नहीं थी।

6. अंग्रेजी सरकार की घोर दमन नीति ने भारत में क्रान्तिकारियों को पनपने नहीं दिया। सरकार ने 1907 में राजद्रोहात्मक सभा पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 'सैडिशन मीटिंग्स एक्ट' (Seditious Meetings Act) पारित किया। 1908 में धोबदारो कानून में संशोधन लागू उपकारी और क्रान्तिकारी नवयुवकों को कठोर दण्ड दिए गए। 1908 में समाचार सम्बन्धी कानून तथा 1910 में प्रेस सम्बन्धी कानून बनाकर उपकारी द्वारा प्रकाशित समाचार-पत्रों को बन्द कर दिया गया। 1911 में विद्रोही सभाओं सम्बन्धी कानून पास करके अधिकारियों को अधिकार सौंप दिए गए कि वे अव्यष्टि सभाओं पर निगरान रख सकें। उपकारी राजनीतिक बन्धियों के साथ सरकार ने निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया, यथा—भागदत्त, काला पानी, देश निर्वासन कठोर शारीरिक यांत्रिक। सरकार की दमनकारी नीति ने जनता को भयभीत कर दिया था अतः क्रान्तिकारियों को अपना समर्थन देने से कटपनी रही।

7. क्रान्तिकारी अनुरागिण उत्साही और बलिदान प्रकृति के थे, लेकिन विदेशी हुकूमत से लड़ने के लिए उनके पास आक्र-शस्त्रों का अभाव था। घोर-छिपे जो हथियार प्राप्त होते थे वे अनर्थक थे।

8. भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के अवतरण ने क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद की अयोग्यता शुरू कर दी। फिर भी अहिंसा का वाद क्रान्तिकारी धारणा को नहीं मिटा सका। सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आज़ाद और यतीन्द्रनाथ जैसे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रवर्तकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्त की अलखल चेष्टा में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया।

असहयोग आन्दोलन : प्रस्ताव और कार्यक्रम

अगस्त, 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व गांधीजी के हाथों में आ गया। 1919 तक राष्ट्रीय आन्दोलन शिक्षित वर्ग तक सीमित था लेकिन महात्मा गांधी ने उसे जन-आन्दोलन बना दिया। उनके नेतृत्व में कश्मिर् जनता का संगठन बन गई। गांधीजी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए अहिंसामय संघर्ष चला। मोहनदास करमचन्द गांधी (1869-1948) गोपालकृष्ण गोखले की प्रेरणा से, प्रथम महापुरुष के दीर्घ, जनवरी 1915 में अमरीका से वापस आए। गोखले के विचारों ने गांधीजी को प्रभावित किया। वे गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सरकार के साथ सहयोग की नीति में उनका विश्वास था। महापुरुष के बीच गांधीजी ने युद्ध प्रयासों में अंग्रेजी सरकार की पूर्ण सहायता की और इसके लिए उन्हें वैसी हिन्दू स्वर्ण पदक से विभूषित किया था 1919 में रोलेट एक्ट के प्रसन को लेकर शुरू का 'सहयोगी' बाद में 'असहयोगी गांधी' बन गया। 31 दिसम्बर, 1919 को 'दंग इण्डिया' में गांधीजी ने लिखा था कि 'मान्य फोर्ड' योजना और उसके साथ की गई वदुषोचना से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ न्याय करना चाहती है और भारतीय जनता को अपने समस्त सन्देहों का अन्त कर लेना चाहिए, अतः हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी आलोचना करें, वाद उनकी सकल बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। कुछ घटनाओं और युद्धनिरत परिस्थितियों ने गांधीजी को धारण कर दिया कि वे विदेशी हुकूमत का विरोध करें। फरवरी 1920 में कश्मिर् के कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने सरकार के साथ असहयोग तथा मॉन्ट-चेर्च मुद्राओं के अन्तर्गत निर्मित व्यवस्थानिध सभाओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रख दिया।

असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव पर कश्मिर् की स्वीकृति (1920) : असहयोग-कार्यक्रम

महात्मा गांधी को यह दृढ़ विश्वास था कि वे हिन्दुओं तथा मुसलमानों को अपने असहयोग आन्दोलन की पदार्थ के नीचे एक कर सकते हैं। सितम्बर, 1920 को कोलकाता में कश्मिर् विशेष अधिवेशन में उन्होंने सरकार के प्रति 'अहिंसक असहयोग की नीति' अगवाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कश्मिर् अहिंसक असहयोग की नीति पर अब तक चलेंगे जब तक अन्याय दूर नहीं हो जायेंगे। प्रस्ताव के पद में 1886 और विनय में 884 मत पड़े। पण्डित मदनमोहन मालवीय, बिर्नमचन्द पाल, देशबन्धु चित्तरंजनदास, जिन्ना तथा श्रीमती एनी बेसन्त ने प्रस्ताव का विरोध किया। इन नेताओं के हठों में बौद्धि और अदृष्टता के बहिष्कार की योजना के प्रति सहानुभूति नहीं थी। तिलक की 3 जुलाई, 1920 को मृत्यु हो चुकी थी। उनके अनुयायियों ने फोर्ड के नेतृत्व में महात्मा गांधी की योजना का विरोध किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय गांधीजी के असहयोग-प्रस्ताव के विरुद्ध थे। कश्मिर् का निर्णय

ब्रिसिस का 'शान्तिमय तथा ठीक-ठाक तरीके से स्वयंज प्राप्त करना' घोषित किया गया। ब्रिसिस का प्रतियोगी सगठन प्रान्तों की भाषा के अनुसार किया गया। मुख्य परिवर्तन थे—विषय-समिति की बैठकों का ब्रिसिस के खुले अधिवेशन से दो-दो दिन पहले करना तथा उसकी सदस्यता महासमिति के सदस्यों तक सीमित रखना—विषय समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 350 कर दी गई, सभापति, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष समेत 15 सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना।

असहयोग आन्दोलन के कारण

(1) मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से असन्तोष—प्रथम महासुद के दौरान भारतीयों ने उन-मन-धन से ब्रिसिस की सहायता की थी, किन्तु भारतीयों के सन्तोष के लिए जो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार योजना प्रकाशित की गई, टांगमें भारतीयों को निराशा हो गई। 1919 के अधिनियम से भारतीय जनता के हित में कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल सके। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार योजना के उल्लंघन की शक्तों की स्थापना से स्वशासन को बढ़ावा नहीं मिला। ब्रिटिश भारतीयों ने इस सुधार योजना को अनुरोध तथा अपमानजनक माना, अतः असन्तोष उत्पन्न हुआ।

(2) आर्थिक दुर्दशा—1917 से 1920 तक की अवधि में भारतीयों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिससे उनमें असन्तोष फैला। मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, प्लेग और इन्फ्लूएंजा के प्रकोप ने उनकी आर्थिक कमाई तोड़ दी। महामरियों से बहुतों की जान से हाथ धोना पड़ा और इनके उत्पन्न एवं रोकथाम के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किए वे अपर्याप्त और असन्तोषजनक थे। भारत की जनता कई के बोझ से दब गई, किसानों तथा मजदूरों की दशा दर्दनाक हो गई। दम्पत्य में किसानों और अग्रजगण में मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा ने महात्मा गांधी को सत्याग्रह के प्रयोग का अवसर दिया।

(3) अकाल—1917 में अन्तर्द्वि के कारण देश में अकाल फैल गया और अनेक व्यक्ति भूख से मरने के शिकार हो गए। सरकार ने जनता के लिए विशेष प्रयास नहीं किए, जिससे जन-असन्तोष बढ़ता गया।

(4) सरकार का दमनक—जनता सुधार और सगठन के कार्यों का प्रचार करती थी, परन्तु सरकार ने दस 144 और 108 का दारुण प्रयोग कर दिया था। राष्ट्रीय आन्दोलन की वैधानिक धारा को कुचलने के लिए सरकार ने ब्रैम एक्ट, सैड्सन एक्ट, एक्सप्लोसिव सम्पत्ति एक्ट, क्रिमिनल अफेयर्स एक्ट आदि दमनकारी कानूनों का अग्रिम निष्ठा। ब्रिटिश लोगों की भाँति, कानून पाली और कठोर कानूनन की सजा दी गई। हिन्दुओं सभाओं पर रोक लगाई गई और राष्ट्रीय नेताओं को अनेक स्थानों पर जले से रोका गया।

(5) रोल्ट एक्ट—मुद्रकाल में ब्रिटिशकरणियों के दमन के लिए भारत सुखा अधिनियम पारित किया गया था, जिसकी अवधि मुद्रकाल तक थी, किन्तु मुद्रक के बाद भी सरकार ने दमनकारी कानूनों का निर्माण जारी रखा। न्यायपीठा सर मिहनी बल्लेंट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसका उद्देश्य यह मान्य करना था कि भारत में किस प्रकार और किस सीमा तक ब्रिटिशकारी आन्दोलन फैला हुआ था तथा किन कारणों द्वारा उसका अन्त किया जाना सम्भव था। सरकार का उद्देश्य ब्रिटिशकारी देशभक्तों को तथा राष्ट्रीय आन्दोलन की सम्पूर्ण शक्ति को कुचल देना था। अप्रैल 1918 में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसकी सिफारिश पर सरकार ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में फरवरी 1919 में दो विधेयक प्रस्तुत किए जिन्हें रोल्ट एक्ट कहा जाता है। देश भर में इन विधेयकों का विरोध 'काले विधेयक' (Black Act) कहकर किया गया, प्रदर्शन किए गए, हड़तालें की गयीं। सी. बी. पित्तनी के अनुसार, "इन दोनों विधेयकों का विरोध परिषद के गौर सकारण भारतीय सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों और मन्त्री-सदस्यों सबने समान रूप से किया, किन्तु सरकार अपना बाव धर अड़ी रही।" रोल्ट एक्ट द्वारा सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को जेलों में डाल देने का अधिकार प्राप्त हो गया। मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार मिला कि वे संदिग्ध ब्रिटिशकरणियों को मरुती जाँच-पड़ताल के उपरान्त नजरबन्दा के आदेश जारी कर सकें। हिन्दु एक्टों के अन्तर्गत एक ही उस धारा को सम्भव कर दिया गया जिसके अनुसार पुलिस अधिकारियों के सामने दो गवाहों की गवाही की गवाही नहीं मानी जा सकती थी। रोल्ट एक्ट को 'अवकाश और अपराध अधिनियम' (Anarchist and Revolution Crimes Act) की सजा दी गई। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 30 मार्च और ३ अप्रैल 1919 को 'रोक दिवस' तथा हड़ताल का आयोजन किया गया। विरोध में हिन्दुओं और मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया। देश भर में हिन्दु-मुसलमान हड़तालें हुई, ठपकाम किए गए। कहीं-कहीं आन्दोलन ने हिंसक रूप ग्रहण किया। दिल्ली में जनता और पुलिस में झगडा हुआ और पुलिस की गोली से अनेक व्यक्ति हताहत हुए। गाँधीजी की सिफारिशों के समाचार से जनता उत्तेजित हो गई। सरकार ने रात आन्दोलन को कठोरता और निर्ममता से दबाने की नीति अपनाई। पञ्च के गवर्नर द्वारा ने

जिसमें गरीब उस कपड़े को खरीद सके। विदेशी कपड़े मँगाने वालों से कहा गया कि वे विदेशी कपड़े न मगाए और अपने पास के फाल को हिन्दुस्थान के बाहर खपाने का ठगम करें।

असहयोग आन्दोलन को खिलाफत आन्दोलन ने समर्थन दिया। 8 जुलाई, 1921 को कराची में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में सेना की धर्ती का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया। मोरणा के खिलाफत आन्दोलन ने जोर पकड़ा। सरकार ने अली बन्धुओं को गिरफ्तार कर दो वर्ष की सजा दी। इससे देश में रोष बढ़ गया। जुलाई 1921 में गाँधीजी के आह्वान पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। दिल्ली में नवम्बर 1921 में सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाए, इसके निर्णय का भार प्रांतीय कमिटीयों पर छोड़ दिया गया। यह आश्चर्य था कि प्रत्येक सत्याग्रही ने असहयोग के कार्यक्रम के उस अंश को जो ठग पर लागू होना हो, पूर्ण कर ली हो, वह बरखा चलाना जानता हो, विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो, खदर पहनना हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो, खिलाफत और पञ्चम के अन्धकारों को दूर करने और स्वायत्त प्राप्त करने के लिए अहिंसा में विश्वास रखता हो और यदि हिन्दू हो तो असमर्थता को राष्ट्रीयता के लिए क्लृप्त समझता हो।

सरकार का दमनकर्म तेजी से चला और दफा 144 और 108 का दौर आम बात हो गई। राष्ट्रीय नेताओं को अनेक स्थानों पर जाने से रोका गया। मार्च 1921 में नवकाया कागड़ हुआ। मार्च के पहले मजराह में गुरुद्वारा में कुछ सिकड़ इकट्ठे हुए। वह शांतिमय सन्तुष्ट था। एकाएक उन पर गोलीबारी चलाई गई जिसमें जनता के कथनानुसार 195 और सरकार के अनुसार 70 मौतें हुईं। सरकार ने आन्दोलन को दबाने की चेष्टा की, परन्तु थक अधिक जोर पकड़ना गया। 17 नवम्बर, 1921 को ब्रिटिश युवाओं के भारत आगमन के विरोध में सर्वत्र प्रदर्शन किया गया। युवाओं की आगबानी से सम्बन्ध रखने वाले ठगसों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। युवाओं के मुर्खों पदार्थों में चार दिनों तक दंगे और खून-खराबे होने लगे। फलस्वरूप 53 आदमी मारे गए और 400 घायल हुए। ये दंगे सगेजिरी नाबद्ध और गाँधीजी के रोके न रुके। गाँधीजी ने जब तक शांति स्थापित न हो जाए, जनता को व्यादतियों का प्रायश्चित्त करने के निमित्त 5 दिन का उपवास किया। देश भर में स्वयंसेवकों के दल संगठित हुए। युवाओं 25 दिसम्बर को कोलकाता जाने लगे थे। बंगाल सरकार ने क्रिमिनल लान्सेमण्डल-एक्ट के अनुसार स्वयंसेवक धर्ती करना और कानूनी ऋार दे दिया था, बहुत से व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनमें देशबन्धु दाम, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पञ्जाब की भारी आई। अहमदाबाद जते हुए लाला जी पण्डित मोर्तालाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जेल में बन्द कर दिए गए।¹

काँग्रेस सरकार में सज्जनों की गतधीत चली जो असफल रही। 21 दिसम्बर, 1921 को पहिला मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक राष्ट्रमण्डल कांग्रेसवा से मिला। देशबन्धु कोलकाता की अलीपुर जेल में थे। ठाणे मध्यस्थों की टेलीफोन द्वारा बात हुई। शीघ्र ही गाँधी जी से अहमदाबाद में तार द्वारा सम्पर्क करना आवश्यक समझा गया। सरकार इस पर राजी हो गई कि सत्याग्रह के कैदियों को छोड़ दिया जाए और मार्च 1922 में गोलमेज परिषद बुलाई जाए, जिसमें ब्रिजिस की ओर से 22 प्रतिनिधि हों। इस परिषद में सुधार योजना पर विचार किया जाए। देशबन्धु दाम की माँग थी कि नए कानून के अनुसार सजा पाए हुए कैदियों को छोड़ दिया जाए। सज्जनों के निश्चय का फल यह हुआ कि लाला जी जैसे कैदी और पतवों के कैदी, जिनमें भीमना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, डॉ. किचनू और अन्य नेमा शामिल थे, जेल में रह गये, परन्तु गाँधी जी कठघी के कैदियों का छुटकारा चाहते थे। सरकार ने आर्थिक रूप में दूरे स्वयंसेवक लिये। उन्होंने माँग पेश की कि पतवों के कैदियों को छोड़ा जाए और रिजिस्ट्रार जाति रखने का अधिकार माना जाए। ये माँग नामावर कर दी गई। फलतः सज्जनों को बात असफल रही और युवाओं के आगमन के सम्बन्ध में बहिष्कार के कार्यक्रम का फलन भारत की जनता ने किया।

दिसम्बर 1921 के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद ब्रिजिस अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति हकीम अमजान खी थे। जो हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतिनिधि थे। उनके सभापतित्व में असहयोग और उसके प्रति देश के कर्तव्य के सम्बन्ध में मुख्य प्रभाव पाम हुए जिसमें कहा गया ब्रिजिस के पिछले अधिवेशन के समय से अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप भारतीय जनता ने निर्णयता, अन्ध-बलियन और अन्ध-सम्मान के मार्ग पर पर्याप्त प्रगति करने के साथ सरकार के सम्मान को बहुत धक्का पहुँचाया है और देश की प्रगति स्वायत्त की ओर तीव्र गति से हो रही है इसलिए ब्रिजिस, कोलकाता के विशेष अधिवेशन द्वारा स्वीकृत और नागपुर में दोहराए गए प्रस्ताव को स्वीकार बरती है और दृढ़ निश्चय प्रकट करती है कि जब तक स्वायत्त की स्थाना नहीं हो जाएगी तब तक अहिंसात्मक असहयोग का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस प्रस्ताव के अपने अर्थों में जनता की स्वयंसेवक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्वयंसेवकों के लिए कुछ प्रतिशत निश्चित की गयीं जो इस प्रकार हों—ईस्वर को माली करके मैं प्रविष्ट करता हूँ कि—(1) मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ का सदस्य होना चाहता हूँ। (2) जब तक मैं सभ का सदस्य रहूँगा तब तक वचन और कर्म में अहिंसात्मक

रहूँगा। (3) मुझे सामाजिक एकता पर विश्वास है और इसकी उन्नति के लिए मैं सदैव प्रयत्न कर रहा हूँ। (4) मेरा विश्वास है कि भारावर्ष के आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक उद्घाटन के लिए स्वदेशी का प्रयोग आवश्यक है और मैं दूसरी तरह के व्यर्थों को छोड़कर केवल हाथ के कते और बुने खदर का इस्तेमाल करूँगा। (5) हिन्दू होने की ईश्वरियता से मैं अभिमान का दूर करने की व्यापकता और आवश्यकता पर विश्वास करता हूँ। (6) मैं अपने धर्म और अपनी 'रा' के लिए बिना विरोध किये जेल जाने, आघात सहने और मरने के लिए तैयार हूँ। (7) अगर मैं जन जाग्रता को अपने कुटुम्बियों और शत्रुओं की सहायता के लिए कौन्सिल से कुछ नहीं माँगूँगा।

31 जनवरी, 1922 को कौन्सिल कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कर सरकार का चांगवनी दी गई कि वह नीतियों में परिवर्तन करे और उन असहयोगी कैदियों को मुक्त कर दे जो अहिंसात्मक कार्यों के लिए जेल गए हैं या बिना मायला विचारधारा है। सरकार से अनुरोध किया गया कि वह साक्षर शब्दों में देश का अहिंसात्मक हलालन में सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दे। अहिंसा की शक्ति सदा लागू रहे। गांधी जी ने वायसराय को फरवरी 1923 के अपने पत्र में लिखा कि यदि सात दिन के भीतर सरकार ने घोषणा कर दी और प्रस से कठोर प्रतिपत्ति हटा लिया तो मैं उस समय तक के लिए उग्र सत्याग्रह मुक्तवी करने की सलाह दूँगा जब तक सारे कैदी छूट कर नए सिरे से विचार न कर लें। यदि सरकार यह घोषणा कर दे तो मैं उसे सरकार की ओर से लोकता के अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सबूत समझूँगा। मैं सलाह दूँगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दबाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित भावों की पूर्ति के लिए ठोस लोकमत तैयार करे। उग्र सत्याग्रह तभी किया जाएगा जब सरकार तटस्थ रहने की नीति का पालन करेगी। अहिंसा जब वह जन-समुदाय की भावों को मानने से इनकार कर देगी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के वक्तव्य का जो उत्तर छपवाया उसमें दमन नीति का यह कह कर समर्थन किया गया कि यह नीति मुम्बई के दंगों और अन्य स्थानों पर दहननाक और गैर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वयंसेवक दलों द्वारा हिंसा, दंगे धमकाने और कामकाज में बाधा डालने के फलस्वरूप है। सरकार ने गांधी जी की चेतावनी की परवाह नहीं की कि यदि सात दिनों के अन्दर सरकारी नीति में कोई परिवर्तन न किया गया तो कर नहीं तो आन्दोलन (No Tax Campaign) आरम्भ कर दिया जाएगा।

धौरी घोरा खाण्ड और असहयोग आन्दोलन का स्थान

गांधीजी का सत्याग्रह और सत्याग्रह समिति की रिपोर्ट

असहयोग आन्दोलन से बड़ी आशाएँ थी लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। सात दिन बीते भी नहीं थे कि गारखपुर जिले की चौरी घोरा नामक स्थान पर दुर्घटना हो गई। 5 फरवरी को चौरी घोरा में कौन्सिल ने जुलूस निकाला जहाँ 21 सिपाही और एक धोतरा को भीड़ ने एक घने में खदेड़ दिया और आग लगा कर मार डाला। ऐसे ही इलाकाण्ड 13 जनवरी को चैन्नई में तथा 17 सितम्बर को मुम्बई में हो चुके थे। आन्दोलन में हिंसात्मक प्रवृत्ति के प्रवेश से गांधीजी दुःखित हुए, अतः उन्होंने आन्दोलन को 12 फरवरी, 1922 से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

गांधीजी की गिरफ्तारी और उनका सत्याग्रह

आन्दोलन के समाप्त होने के बाद 22 मार्च 1923 को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए। गांधीजी को राजद्रोह के अपराध में सेशन सुपुर्द कर दिया गया। यह ऐतिहासिक मुकदमा 18 मार्च को अवधदावाद में शुरू हुआ। सराजिनी-नाथ ने एक पुस्तक की प्रतिका में लिखा कि "जब गांधीजी की कुश, शान्त और अजैय देह ने अपने शिष्य और सहबन्दी शकरलाल बैकर के साथ अदालत में प्रवेश किया, कानून की दिगाह में उस अपराधी के सम्मान के लिए सभी उठ खड़े हुए।" कानूनी अवलकाओं ने तीन लेख छपे जिन्हें के लिए गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था—(1) राजद्रोह (2) सम्मान और शक्ति का हनन एवं (3) जन-वर्तन। जब अभियोग पढ़कर सुनाये गए, गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया। बैकर ने भी स्वयं को अपराधी कबूल किया। इसके बाद गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा।

जज ने गांधीजी को छ वर्ष की सजा सुना दी। अपने उत्तर में गांधीजी ने कहा कि डाकू लिए परम तीर्थाय की बात है कि उनका नाम तिलक के साथ जोड़ा गया है। गांधीजी की सजा के बाद कौन्सिल मरसमिति ने असहयोग सविनय धर और सत्याग्रह के सिद्धान्त तथा व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करने का प्रयत्न किया, 'मिन्स गांधी' की गिरफ्तारी के साथ असहयोग आन्दोलन समाप्त हो चुका था। देशभर्यु दास तथा विठ्ठलभाई पटेल ऐसा असहयोग चले। वे जिसका प्रवेश नौकरशाही के यंत्र में हो सके।

कौन्सिल समिति की रिपोर्ट—गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद कौन्सिल कार्यसमिति ने असहयोगी व्यक्तियों को चेतावनी दी कि वे मुकदमे हाथ में लें और असहयोगियों को अदेश दिया गया कि वे अपनी पैतृकी न करें। कौन्सिल महारमिति ने सत्याग्रह समिति नियुक्त की जिसे देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट देनी थी। सत्याग्रह समिति ने जो विशेष सिफारिशें प्रस्तुत की, उन्हें सशेष में डॉ. पट्टाभिसीतारमैया ने इस प्रकार प्रस्तुत किया—

(1) सत्याग्रह—देश सन्धिक सत्याग्रह के लिये तैयार नहीं है। हम सिद्धांत करते हैं कि प्रांतीय कार्यम कमिटियों को अधिकार दे दिया जाए कि यदि महासमितियों की सत्याग्रह सम्बन्धी शर्त पूरी हो तो वे अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सान्धिक सत्याग्रह की मजूरी दे सकते हैं।

(2) कॉमिन्स प्रवेश—कॉमिन्स प्रवेश के सम्बन्ध में डॉ एच. ए. अम्सारी, राजगोपालाचारी तथा एस. कस्तूरि राय आदिकों की सिद्धांतों की कि कॉमिन्स की नीति में हस्तक्षेप की किसी प्रकार की परिवर्तन न किया जाए। इसके विरुद्ध हकीम अब्दुल खौं ए मोहम्मद नेहरू और सादार वल्लभ भाई पटेल का मत था कि—(i) असहयोगियों का उम्मीदवारी के निरुपजाब और खिलौना की दादारी और लक्ष्यन स्वायत्त प्रणित के उद्देश्य से छाड़ा होना चाहिए और अधिकाधिक सख्ता में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिये। (ii) यदि असहयोगी अधिक सख्ता में पहुँच जायें कि उनके बाँध कोमल पूरा न हो सके तो उन्हें कॉमिन्स भवन में जबर बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। वे कॉमिन्स में केवल इसलिये जायें कि उनके विरुद्ध स्थान पूरा न हो सके। (iii) यदि असहयोगी इतनी सख्ता में पहुँचें कि अधिक होने पर उनके विरुद्ध कोमल पूरा हो सकता हो तो, उन्हें प्रत्येक साकारो कार्यवाही की जिम्मेदारी भरी रहित है, विशेष करना चाहिए और केवल पत्र लिखना और स्वायत्त सम्बन्धों प्रस्ताव पेश करने चाहिए। (iv) यदि असहयोगी अन्यसख्ता में पहुँचें तो इस कॉमिन्स के बन को पटायन चाहिए। (v) कॉमिन्सों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कॉमिन्स की नीति में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(3) स्थानीय संस्कार—हमारी सिद्धांत है कि असहयोगी राजनयिक कार्यक्रम के निरुद्धिनिर्दिष्टियों, बिना बेहो और लोकल बेहो की उम्मीदवारी के लिये छोड़े हैं, पानु असहयोगी सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में निषेध-उपनिषय न बन जायें।

(4) स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार—प्रकार बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने की सलाह नहीं देनी चाहिए।

(5) अदालतों का बहिष्कार—परचयों स्थिति लोक प्रवृत्ति जाग्रत करनी चाहिए। वकीलों पर लगे प्रतिबन्ध उठा लेना चाहिए।

(6) आन्तरिका अधिका—सबका मत था कि कानून आन्तरिका की स्वतन्त्रता सबका ही जरूर था इससे हिंसा की नीव न आ जाए। धर्म के मन्त्रों में सिद्धों की रक्षा करने में या पुराणों पर अनुचित आन्तरिक होने पर शक्तिगत बल का प्रयोग मत नहीं है। श्री पटेल का मत था कि असहयोगियों को कानून में आन्तरिका करने का अधिकार रहना चाहिए, पानु इससे सान्धिक हिंसा की नीव न आ जाए।¹

(7) गौरी माल का बहिष्कार—सत्याग्रह सन्धि की रिपोर्टों से स्पष्ट हो गया कि असहयोग के पुनः और नवीन दल समन रूप से विभाजित थे। डॉ. पटेलसिद्धांतों के शब्दों में, "दोनों असहयोग के दल थे और साकार से सहयोग करने की कोई तैयारी न था। अगर केवल इतना था कि नवीन दल असहयोग को कमान में एक दूसरी छोड़ें बहाकर उससे नैकराही के गड़ कॉमिन्स के बंदर से टूर छोड़ने का समर्थक था।" बहिष्कारियों और सहयोगियों ने स्युनिस्तिरिक्तियों और स्थानीय बेहो के निरुद्धि होना अग्रस्य कर दिया था। सख्त होने पर वे असहयोग के निरुद्धि और नीकियों के निरुद्धि की बहिष्कार के व्यवहार पर जोर देते थे। अन्तिमों पर राष्ट्रीय ज्ञाना बहने का अग्रह करते थे, स्युनिस्तिन स्कूलों में छात्रा और हिन्दी के प्रकार की सिद्धांत करते थे और गवर्नर एवं निरिक्तियों के आग्रस्य का बहिष्कार करने पर बल देते थे। गौरीजी ने दौरी-बाग कांड के बाद 12 फरवरी, 1922 को असहयोग आन्दोलन की अनिश्चित काल के निरुद्धि कर दिया था की गौरीजी की गिरफ्तारी के बाद निर्दिष्ट पद चुका था और अब कॉमिन्सों में प्रवेश करके साकार के काम में बाधा डालने या साकार से असहयोग करने की नीति बना फकने लगी। इस नीति के समर्थकों ने कॉमिन्स से अलग होकर स्वायत्त दल की स्थापना की (1 जनवरी, 1923)।

असहयोग आन्दोलन का मूल्यांकन

12 फरवरी 1922 को गौरीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन समन्वय करने से उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया अग्रस्य हुई। गौरीजी को मार्च 1922 को गिरफ्तार करके छ वर्ष का कारावास दिया गया था। स्वस्थ विरुद्ध होने के कारण उन्हें दो वर्ष बाद छोड़ दिया गया। अनेक दुर्घटनाओं के बावजूद असहयोग आन्दोलन महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। यद्य—1. यह पहला जन-आन्दोलन था जिसने भारत की राष्ट्रीयता में नूतन प्राण फूँके और देशवासियों में स्वतन्त्रता तथा निरिक्तता की भावना पैदा कर दी। 2. कॉमिन्स ने खड़ी बाधा काटकर राष्ट्रीय विद्या मार्ग पर चलने की स्वतन्त्रता अग्रि अग्रस्य निरुद्धि। इससे भारतवासियों में स्वतन्त्रता वस्तुओं के निरुद्धि प्रेम अग्रस्य हुआ तथा देश के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। 3. राष्ट्रीय विद्या सस्याओं से देशभक्त उत्पन्न होने लगे, जिसने कॉमिन्स की लम्बे स्वतन्त्रता सफल में कार्यकर्ताओं की कमी महसूस नहीं हुई।

स्वराज्य दल - उदय और अस्त

1922 में असहयोग आन्दोलन के स्थान से कांग्रेस के अधिकांश नेताओं और जनता में भारी क्षोभ फैला। पितरंजनदास, ए. मोतीलाल नेहरू, ए. टी. बल्लेकर सत्याग्रह समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में नया दल बन रहा था। 1922 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष पितरंजनदास ने अधिवेशन के समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कांग्रेस प्रवेश की नीति को पराजय मिली। असन्तुष्ट चित्तरंजनदास ने अध्यक्ष पद से और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से स्वीका दे दिया। तदन्तर मोतीलाल नेहरू ने 'स्वराज्य दल' की स्थापना की।

स्वराज्य दल का सिद्धान्त और कार्यक्रम

स्वराज्य दल का संस्था 'स्वराज्य' प्राप्त करना था। 'स्वराज्य' से उसका अधिप्राय सम्राज्य के अन्तर्गत 'औपनिवेशिक स्थिति' (Dominion Status) उपलब्ध करना था। स्वराज्यिस्ट चाहते थे कि निर्वाचनों में भाग लेकर व्यवस्थापक मण्डलों की सीटों पर कब्जा कर लिया जाए। इस प्रकार व्यवस्थापक मण्डलों में पहुँच जाने के उपरान्त बड़ी सरकार के प्रति असहयोग किया जाए और सरकारी नीति में रोड़ा अटकवाया जाए। ए. मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चित्तरंजन दास ने 'अडगा' शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा था, "हमने अपने कार्यक्रम में अडगा शब्द का व्यवहार किया है जो ब्रिटिश संसद के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं, मातहत और सीमित अधिकारों वाली कॉमिटी उस अर्थ में अडगा डालना असम्भव है, क्योंकि सुधार कानून के अन्तर्गत असेम्बली और कॉमिटी के अधिकार गिने-चुने हैं पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार अडगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही द्वारा डाली गई रकावटों का मुकाबला करना अधिक है।"¹

स्वराज्यिस्टों के अनुसार कॉमिटी प्रवेश का कार्यक्रम असहयोग सिद्धान्त के अनुकूल था। वह ठपित था कि नौकरशाही के गड़ (व्यवस्थापिका) में प्रवेश कर असहयोग का झण्डा फहराया जाए। कॉमिटी में प्रवेश करके वे बजटों को रद्द करने के पक्ष में थे और उन कानूनी प्रस्तावों को अस्वीकार करना चाहते थे जो नौकरशाही की स्थिति सुदृढ़ करने वाले हों। 'अडगा' स्वराज्य दल के कार्यक्रम का विधिसात्मक पक्ष था। रचनात्मक पक्ष में इसका कार्यक्रम उन प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को प्रस्तुत करना था जो राष्ट्रीय जीवन को प्राणवान बनाने वाले हों और अन्त में नौकरशाही को उखाड़ फेंकने में सहायक हों। कॉमिटी के बाहर स्वराज्यिस्टों ने महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्यों में सहयोग देने का वचन दिया।

स्वराज्य दल का मूलनीकन

मॉन्ट-फोर्ट सुधारों और दूध-शासन प्रणाली विनष्ट करने के अपने कार्यक्रम को सापने रखकर स्वराज्य दल ने नवम्बर, 1923 के निर्वाचनों में भाग लिया और कुछ स्थानों पर सफलता प्राप्त की। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में 145 सीटों में से 45 सीटें स्वराज्य दल के कब्जे में आ गईं। उदाहारणार्थ 1924-25 के बजट के पचासपेची भाग को अस्वीकार कर दिया गया और सरकार को उसकी पुनर्निष्ठ करने के लिए गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा। प्रान्तों में स्वराज्य दल ने बंगाल और मध्य प्रान्त में सफलता अर्जित की। इन प्रान्तों में दूध-शासन प्रणाली की क्रियावृत्ति को रोक दिया गया। स्वराज्य दल की सफलता के सम्बन्ध में एच. एन. बेल्सफोर्ड ने कहा—“मेरे विचार से अडगा संगाने की नीति सही थी, क्योंकि उसने ब्रिटिश मनुदर दल को नपसल कर दिया था कि दूध शासन प्रणाली अन्वयहार्य है।”

1925 में देशबन्धु पितरंजनदास की मृत्यु के पश्चात् स्वराज्य दल की शक्ति में ह्रास होने लगा और दल सरकार के साथ सहयोग करने की दिशा में झुकता गया। “व्यवस्थापक मण्डलों को छिन्न-विन्न कर देश की नीति का स्थान व्यवस्थापक-मण्डलों में भाग देने, उनका उपयोग करने और सरकार के साथ सहयोग तक करने की नीति सेने लगी।” बंगाल और मध्य प्रान्त में स्वराज्य दल का प्रभाव घट गया। 1926 के बाद इस दल में घूट पैदा हो गयी और वह दो दलों में विभाजित हो गया। एक दल शासन के साथ प्रतियोगी सहयोग करने की नीति का प्रतिपादक था दूसरा असहयोग करने की नीति का। 1926 के अन्त तक स्वराज्य दल अपनी शक्ति खो बैठा।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्राग्भ्य से पूर्व घटनाक्रम

कांग्रेस का लाहौर-अधिवेशन (1929)

1922 से 1927 तक का काल अशांति का रहा। एत अवधि में राष्ट्रीयता का अत्यधिक प्रसार हुआ। नवम्बर, 1927 में ब्रिटिश सरकार की ओर से 1919 के शासन विधान के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत भेजा गया। इस कमीशन के सतों सदस्य थे। एक ही भारतीय सदस्य नहीं रखे जाने से भारतीय जनता को असंतोष हुआ। कमीशन का भारत में पूर्ण बहिष्कार हुआ। उसे बाले झण्डे दिखाये गये।

‘साइमन वापस जाओ’ के नारे लगाए गए। सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया। प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ बरसाई गईं और घोड़े दौड़ाए गये। लाहौर में पुलिस की लाठियों से लात्ता सज्जित राय धायन हुए एवं चले गये। मन्तव्य में नेहरू और गोविन्द वल्लभ पंत पर लाठियाँ पड़ीं। विरोध के बावजूद साइमन कमिशन ने दो बार यात्रा की और अपना रिपोर्ट दी जो मई, 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमिशन की रिपोर्ट ने देश में व्याप्त असंतोष को तीव्र कर दिया। भारतीय लोकमत ने रिपोर्ट को दुःखा दिया जिसमें अधिराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) का विकल्प नहीं दिया गया। केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कुछ नहीं कहा गया था, प्रान्तों में रक्षा कवचों (Safeguards) के साथ उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कहकर महत्वपूर्ण मामलों में गवर्नरों को अपने अधिकारों के निर्णयों का उत्तरदायन करने की बात कही गई थी और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सभी में निम्न अन्तर्गत हुए उसे अनिवार्य ठहराया गया। एन्ड्रूज के अनुसार साइमन कमिशन की रिपोर्ट का दोष यह था कि इसमें अहिंसात्मक आन्दोलन आन्दोलन से सम्पूर्ण देश में सम्पन्न हुये परिवर्तन और जनता की अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं को ठगने का।¹

भारतीयों के विरोध ने ब्रिटिश शासन को दुःख कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने चुनौती दी कि भारतीय सम्मिलित रूप से अपना विधान नहीं बना सकते हैं। अंग्रेजों को विश्वास था कि हिन्दू मुसलमान एक नहीं हो सकेंगे, लेकिन रायबर की चुनौती मंजूर की गई। दिसम्बर 1928 में दिल्ली में एक सर्व-दलीय सम्मेलन बुलाया गया। पं. जवाहरलाल नेहरू इस समिति के मंत्री बने। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने भारत के प्रांतीय सविधान का ढाँचा प्रस्तुत किया गया। भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग रखी गई। 1928 में मन्तव्य सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई, लेकिन बाद में मन्तव्य उठ खड़े हुए। रिपोर्ट से सरकार बौद्धिमाना गई। उसने मुसलमानों को ठगने की नीति अपनाई। फलस्वरूप मुस्लिम समुदाय में मतभेद हो गया। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया, किन्तु पृथक्प्रायश्चित्त तत्वों ने इसका विरोध किया। दिसम्बर 1928 में यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया कि नेहरू रिपोर्ट में शासन विधान की जो योजना प्रस्तुत की गई है वह स्वागत-योग्य है और यदि ब्रिटिश समद इसे 31 दिसम्बर, 1929 तक या इससे पूर्व स्वीकार कर लेगी तो दिसम्बर इस विधान को अपना लेगी। प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि 31 दिसम्बर, 1929 को ब्रिटिश समद प्रस्तावित विधान को मंजूर नहीं करेगी या इससे पूर्व ही उसे नामजूर कर देगी तो दिसम्बर देश को कर बन्दी को सहाह देकर अहिंसात्मक आन्दोलन आन्दोलन चलावेगी। पृथक्प्रायश्चित्त मुस्लिम तत्वों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले चौदह शर्तीय योजना प्रस्तुत की। मुस्लिम हिंदी को अनुचित रूप से साहज्य देने वाली ब्रिटिश सरकार ने जिन्ना-योजना का विरोध नहीं किया और ये शर्तों मैकडोनाल्ड के ‘साम्प्रदायिक पंचाट’ (Communal Award) में सम्मिलित कर ली गई। जनता में रोष भड़क उठा और ‘सविनय अवज्ञा’ आन्दोलन के लिए वादवर्ण तैयार हो गया।

लाहौर-कॉमिशन (1929) का ‘पूर्ण स्वराज्य’ का प्रस्ताव और

26 जनवरी, 1930 का स्वाधीनता घोषणा-पत्र

सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट के दुःखा दिये जाने और पृथक्प्रायश्चित्त मुस्लिम तत्वों को प्रोत्साहन देने पर दिसम्बर 1929 में लाहौर अधिवेशन किया। पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में भारत के अन्तर्गत पर तीव्र क्रोध व्यक्त किया तथा भारत को स्वतन्त्र करने के अपने दृढ़ निश्चय को प्रकट किया। लाहौर दिसम्बर में 31 दिसम्बर, 1929 को मध्य-रात्रि को नेहरू की अध्यक्षता में ‘पूर्ण स्वराज्य’ सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया।

दिसम्बर के आदेश से 26 जनवरी, 1930 को देश में ‘स्वतन्त्रता दिवस’ के रूप में मनाया गया। दिसम्बर की नई कार्य समिति को बैठक 2 जनवरी, 1930 को हुई, उसने 26 जनवरी, 1930 के पूर्ण स्वराज्य दिवस के लिए एक घोषणा-पत्र तैयार करके जनता के सम्मुख पढ़कर सुनाया और उस पर हाथ ठाकर श्रोतार्यों की सम्मति लेना तय हुआ।² उस दिन सुनया जाने वाला घोषणा-पत्र संक्षेप में यह था—“हम भारतीय प्रजाजन अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना अन्तर्गत अधिकार मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होकर रहें, अपने अधिकार का फल स्वयं भोगें और जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों, जिससे हमें विकास का पूरा मौका मिले। अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की स्वतन्त्रता का अन्तर्गत कर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवासियों का शोषण किया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारतवासियों को अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए।”

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आरम्भ

स्वाधीनता-दिवस मनाने से स्पष्ट हो गया कि स्वदेश शक्ति और अन्तर्गत-वर्तमान की शक्त का विद्यमान है जिसे जाग्रत करने की आवश्यकता है। 25 जनवरी, 1930 को असेम्बली में दिया गया वादवर्ण का भाषण प्रकाशित हुआ

जिसमें भारत के आराधारी और धिक्काराशील राजनीतिज्ञों की आशाओं पर धनी फिर गया। गाँधीजी ने यह इंग्रहमा में लॉर्ड इर्विन के समक्ष ये शर्तें रखीं—1 सम्पूर्ण मंदिर निषेध। 2 विनियम की दर घटा कर एक। शान्तिग चार पस कर दी जाए। 3 जमीन का लगान आधा कर दिया जाए और उस पर कौंसिलों का नियन्त्रण रहे। 4 नमक-कर हटा दिया जाए। 5 सैनिक-व्यय में 50 पैसे की कमी कर दी जाए। 6 विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगा दिया जाये। 7 भारतीय समुद्र तट भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित रखने का प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाए। 8 इत्या या इत्या के प्रयत्नों में साधारण दृष्टान्तों द्वारा सजा पाए लोगों के सिवाय समस्त राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाए तथा समस्त राजनीतिक मुकदमों वषस से लिये जाएँ। 124 अ धारा और 1818 का तीसरा रेगुलेशन उठा दिया जाय। 9 खुदिया पुनित हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियन्त्रण कर दिया जाए। 10 आत्म-रक्षाई हथियार रखने हेतु लाइसेंस दिए जाएँ और उन पर जनता का नियन्त्रण रहे।

महात्मा गाँधी ने कहा—“अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता प्रप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों परन्तु भारतवर्ष के लिए अहिंसात्मक असहयोग के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा को, अप स्वराज्य के इस पत्र को सिर और प्रवृत्त करें और स्वाधीनता की जो लड़ाई निकट आ रही है उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का यह अपना मत और ताहस प्रदान करें।”

इसमें का असेम्बली और कौंसिलों से त्याग पत्र—कॉमिशन के आदेश पर कौंसिलों के 172 सदस्यों ने फरवरी 1930 तक त्याग-पत्र दे दिए। इनमें से 21 असेम्बली के और 9 राज्य परिषद के सदस्य थे। तत्कालीन शासक शासक के अनुकूल नहीं था और गाँधीजी के आन्दोलन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार थी। लॉर्ड इर्विन की घोषणा से स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारत को औपनिवेशिक स्थिति प्रदान नहीं करेगी।

सविनय अवज्ञा का श्रीगणेश और सरकार को अन्तिम चेतावनी

दिसम्बर 1929 में ‘पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास होने के बाद गाँधीजी गम्भीरता से विचार कर रहे थे कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन किस प्रकार प्रारम्भ किया जाए। 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित करके गाँधीजी को आन्दोलन शुरू करने के लिए अभिप्रेत कर दिया गया। कुछ समय बाद अहमदाबाद में महासमिति की बैठक हुई जिसमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाते का अधिकार उन्हें दे दिया गया। गाँधीजी ने 2 मार्च 1930 को लॉर्ड इर्विन को अन्तिम चेतावनी के रूप में एक पत्र लिखा जिसमें सविनय अवज्ञा का उद्देश्य स्पष्ट किया। इस पत्रों को रेजिनाल्ड नाटक अग्रेज मुकद दिल्ली ले गया जहाँ कुछ समय तक आग्रह में रह चुका था। गाँधीजी के इस पत्र को अन्तिम चेतावनी का नाम दिया गया। लॉर्ड इर्विन ने छत्र प्रकट किया कि गाँधी जी ऐसा काम करने वाले हैं जिससे कानून और सार्वजनिक शांति भंग होगी।

गाँधीजी का कृप अनिवार्य हो गया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ दण्डी यात्रा (Dandi March) की ऐतिहासिक घटना से हुआ। 12 मार्च 1930 को अपने 79 साथियों सहित महात्मा गाँधी ने साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दाण्डी नामक ग्राम के लिए प्रस्थान किया ताकि वहाँ नमक बनाकर सरकारी नमक कानून का उल्लंघन किया जाए। 200 मील की लम्बी यात्रा चंदल 24 दिनों में तय की गई। दण्डी पहुँच कर महात्मा गाँधी ने नमक कानून तोड़कर 6 अप्रैल 1930 को आन्दोलन का उद्घाटन किया और सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हो गया।

गाँधीजी द्वारा आरम्भ किए गये इस आन्दोलन को सख्त भन और प्रभाव का बल मिला। गाँधीजी को कृप यात्रा से सरकार विचलित हो गई एवं आकाश की कि लैंगोटी और टण्डपार गाँधीजी की पैदल यात्रा का मिनेमा चित्र न दिखाया जाए। गाँधीजी ने घोषित किया कि स्वराज्य नहीं मिला तो मैं रास्ते में मर जाऊंगा अथवा आश्रम के बाहर रहूंगा। नमक-कर न उठा सकर तो आश्रम लौटने का हवाला नहीं है। अंग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नाश कर दिया है। मैं इस राज्य को अधिशाय्य समझता हूँ और इसे नष्ट करने का प्रयत्न कर चुका हूँ। गाँधीजी ने मार्क्सवादी शब्दों में कहा—“मैंने स्वयं गांधी सेव दि किंग के भी गांधी और दूसरे से गंधी है। मुझे पिशा देहि की राजनीति में विरक्तता था, पर यह व्यर्थ हुआ। मैं जान गया कि इस सरकार को सीधा करने का यह उपाय नहीं है। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है, पर हमारी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई है। हम किंगों का भारता नहीं चाहते किन्तु इस शासन को खत्म कर देना हमारा परम कर्तव्य है। 6 अप्रैल को गाँधीजी ने अपनी यात्रा की समाप्ति पर अपने साथियों सहित समुद्र तट से नमक बान कर नमक कानून तोड़ा और गाँधीजी ने कहा नमक-कानून विधिवत भंग हो गया है। मेरी सलाह है कि सर्वत्र कार्यकर्ता नमक बनाएँ, जहाँ उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना आता हो वहाँ उसे काम में लाएँ और ग्रामवासियों को सिखा दें, परन्तु उन्हें यह अवश्य ज्ञात दें कि कानून छिप कर नहीं छुलकर भंग करना है।” सरकार हमारी बकिंगों से लड़ाई घोल नहीं लेगी और यदि सरकार सीमोल्सलधन करती है तो मित्रा जो खोलकर स्वाधीनता संग्राम में कूद सकती है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण

1. ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को ठुकरा कर भारतीयों के निर सपर के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं छोड़ा।
 2. देश को आर्थिक हानत निम्नतर शोचनीय होती जा रही थी और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने हानत और बिगाड़ दी थी। वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं और किसानों को हालत दयनीय थी वे कर संग्रान या कर्ब नहीं चुका सकते थे।

3. औद्योगिक संस्थाओं में हड़तालें अग बढ़ हो गयी थी। मेरठ बंदूक केश में गिरफ्तार 36 मजदूर नेतृओं को लम्बी कैद की सजा देने की धटना ने देश भर के मजदूरों में सनसनी फैला दी थी और वे संगठित होने लगे थे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, 'ब्रिटिश आन्दोलन सिद्धान्त एवं संगठन में वर्ग-चेतना खूबनाक हो रही थी।'¹

4. सरकार का हर कदम अंग्रेजों को घपसा पहुँचाने का होता था, हसनिर रुपये के मूल्य में परिवर्तन कर दिया गया था, अन्त आर्थिक और व्यावसायिक वर्ग सरकार के विरुद्ध बर्बिस हुए संचालित आन्दोलन में भाग लेना चाहता था।

5. वातावरण अराजक और डरा था। अन्त हिंसात्मक सपर की सम्पत्तिया अधिक हो गयी थी। बर्बिस के उचित निवेदन को ठुकराने की नीति सरकार ने अपना ली थी। अन्त मङ्गल गांधी ने समझ लिया कि अंग्रेज जाति शक्ति हुए ही दब सकती है।

आन्दोलन का कार्यक्रम, प्रगति और सरकार का दमन चक्र

सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने के पहले महात्मा गांधी ने अपनी 11 शर्तों अथवा माँगों की सूची बयामुय को भेजी थी, जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन का कार्यक्रम थी। इस आन्दोलन का कार्यक्रम था—सम्पूर्ण मंदिर निषेध, स्वतन्त्रतपूर्वक नमक बनाना, शाब् एव अर्धय तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, सरकारी नौकरियों तथा न्यायालयों तथा शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना, घरवा चमत्ता आदि। जनता ने उत्साह से भाग लिया। सरकार का दमनचक्र बड़ा गया। नेताओं को बंदी बना लिया गया, निहले सत्याग्रहियों पर सडियाँ बरसाई गयीं, प्रदर्शन करने वाली भीड़ों पर गोलीचार्ज चम्पू गई और ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गांधीजी ने बयामुय को निखे दूसरे पत्र में मृत बिने के धारसना और छरसा के नमक के कारखाने पर धरना करने का इत्ता जहिर किया। बिना ने कहा, "हम गांधीजी के साथ समित होने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका आन्दोलन भारत की स्वतन्त्रता के निर नहीं है अर्चि भारत के सब कण्ड मुसलमानों को हिन्दू महासभा के अत्रित बना देने के सिर है, किन्तु राष्ट्रवादी और देशभक्त मुसलमानों ने बर्बिस के पत्र के नीचे छडे होकर इस आन्दोलन में भाग लिया।

जून 1930 में देश में ब्रान्ति हिस्ती से रही थी और अनेक स्थानों पर ब्रिटिश शासन ठब टप हो गया था। मुम्बई शहर शासन सूत्र ब्रिटिश नौकरशही के हथ से खिलकर बर्बिस के साथ आ गया था। सरकार का दमनचक्र घुरे बेग पर था। लाठी-प्रहार दिन प्रतिदिन की धटना हो गयी और लोगों के शत्रुभूत अगों पर अघात किया जाने लगा। बर्बिस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। मङ्गलानों को रंडित किया गया। देश को अघादेश शासन के अन्तर्गत कर दिया और दमन कानून का सहारा लिया गया। करबन्दी आन्दोलन को कुचलने के सिर सरकार ने सम्पत् के बन्त प्रहण, डरा और नीलामी का महारा लिया। पुलिस के अत्याचारों से कई रंग ठब गर।

सनझाति के प्रयास : गोमनेज परिषद : गांधी-इंकिन समझौता, 1931

सरकार और सत्याग्रहियों के बीच समझाति के प्रयास असफल रहे। जेन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आन्दोलन को ठब तक जारी रखने का निश्चय प्रकट किया जब तक भारत को सूर रूप में स्वतन्त्रता प्रदान न कर दी जाए। सडमन कमरशन की जो रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित हुई थी उसने भारतीयों को निरा किया और सचे राज्यधिक दलों ने उसके मुझवों को अस्वीकार कर दिया। अन्त सरकार को गोमनेज परिषद (Round Table Conference) बुलानी पड़ी।

प्रथम गोमनेज परिषद, नवम्बर, 1930

12 नवम्बर, 1930 को सन्तन में प्रथम गोमनेज परिषद बर्बिस के अतिरिक्त सचे भारतीय प्रतिनिधि टर्चिषट दे, पर ठबक मनोनयन बयामुय ने किया था अन्त वे सरकार के निरु थे। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने परिषद के उद्घाटन भाषण में ठीन आधारभूत सिद्धान्तों की बर्च की। प्रथम, केन्द्रीय व्यवसायिक का निर्माण सप शासन के अघार पर होना तथा ब्रिटिश भारत के प्रान्त और देशी राज्य सप शासन की इकाई का रूप धारण करेंगे, द्वितीय केन्द्र में बटन उमरादी

शासन स्थापित किया जाएगा, लेकिन मुराहा तथा वैदेशिक विभाग गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे एवं तृतीय अतिरिक्त काल में कुछ शासक विधान (Statutory Safeguards) की व्यवस्था रहेगी।

राजसराय द्वारा मनोनीत और चुने हुए भारतीय प्रतिनिधि संघ शासन के उपरोक्त सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओरों ने ब्रिटिश सरकार के इशारे पर सच राज्य में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया, सुरक्षण (Safeguards) और उदारवादी मंत्रियों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रतिनिधियों में मतभेद पाया गया है। जयकर एवं सर तेज बहादुर सप्रू ने भारत के लिए "अपनिवेशिक स्वायत्त" की मांग की। जयकर के अनुसार, "यदि भारत को औपनिवेशिक स्वायत्त मिल जायेगा तो स्वतन्त्रता की मांग स्वतः समाप्त हो जायेगी।" सम्मेलन में साम्प्रदायिकता की समस्या विवादग्रस्त रही। मुसलमान पुरुष तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर अड़े रहे। जिन्ना ने अपनी चौदह सूची योजना स्वीकार करने को धक्कावत की। डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की हितों की दृष्टि से पुरुष निर्वाचक मण्डल का समर्थन किया। हिन्दू प्रतिनिधि संपुक्त निर्वाचन पद्धति और अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सराफा के पक्ष में थे। फलस्वरूप साम्प्रदायिकता की समस्या पर मतभेद नहीं हो पाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किसी घोषणा को स्वीकार नहीं किया। 9 फरवरी, 1931 को सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए बिना निर्वाचन निर्धारण पर चर्चें, स्थगित हो गया। सम्मेलन की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मैक्डोनाल्ड ने आशा व्यक्त की कि कांग्रेस प्रत्यक्ष में सम्मेलन में भाग लेगी और भारत के लिए सविधान निर्माण में मदद करेगी। सरकार समझ गई कि कांग्रेस को अनुपस्थिति में कोई निर्णय कल्पित नहीं हो सकता।

गौंधी-इर्विन समझौता, 1931 और आन्दोलन की समाप्ति

कांग्रेस के साथ समझौता करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उसे शामिल करने की दृष्टि से सरकार ने महात्मा गांधी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को 26 जनवरी, 1931 को मुक्त कर दिया। महात्मा गांधी एवं लॉर्ड इर्विन में पत्राचार हुआ। अन्ततः तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से 17 फरवरी 1931 को गांधीजी और लॉर्ड इर्विन की मुलाकात हुई। फलस्वरूप गौंधी इर्विन समझौता 5 मार्च को हुआ। इस समझौते की मुख्य बातें निम्नांकित थीं—

1. सरकार सभी अहिंसक कैदियों को मुक्त कर देगी।
2. समुद्र के समीप रहने वालों के लिए नमक एकत्र करने एवं नमक बनाने के लिए कानूनी दायित्व होगा।
3. सरकार सभी अभ्युद्देश एवं मुकदमों काफ़स से लेगी।
4. शांतिपूर्वक विदेशी सामान पर धाने देने की छूट होगी।
5. कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया जायेगा।
6. सरकार सत्याग्रहियों की जवाब सम्पत्ति सौदा देगी।
7. कांग्रेस का बहिष्कार कार्यक्रम बन्द हो जायेगा।
8. महात्मा गांधी पुलिस की ज्यादतियों की निन्दा जारी कर छोड़ देंगे।
9. कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और उदारवादी शासन को रक्षा कवचों सहित भारतीयों के हित में स्वीकार कर लेगी।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस एवं दक्षिण पक्ष के नेताओं ने समझौते को पसन्द नहीं किया। कांग्रेस के काम पक्ष ने समझौते को सरकार के समक्ष आत्म-समर्पण की सजा दी, जबकि दक्षिण पक्ष ने इस पर असंतोष प्रकट किया। इस समझौते के बाद संघर्ष तथा संग्राम समाप्त हो गया। कांग्रेस का झण्डा लहराने लगा।

द्वितीय गोलमेज परिषद, 1932

18 अप्रैल 1931 को लॉर्ड इर्विन ने भारत में प्रस्थान किया तथा 17 अप्रैल 1931 को नए वायसरॉय लॉर्ड विलिंगटन ने अपना कार्यभार संभाला। देश की स्थिति से वायसरॉय लॉर्ड विलिंगटन अपरिचित थे। प्रतिदिन कांग्रेस के दफ्तरों में उनमें समझौते की शर्तों का ठीक से पालन नहीं करने की शिक्कायत मिली। इस सम्बन्ध में गांधीजी ने कांग्रेसियों को जगजाह्नन शुरू करने की सलाह देताथी दी। फलस्वरूप सरकार की ओर से सहानुभूति दिखाई गई लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। गांधीजी ने सरकार से जो पत्र-व्यवहार किया उससे स्पष्ट हो गया कि समझौते में टप नहीं है अतः उन्होंने द्वितीय गोलमेज परिषद में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया, परन्तु अन्त में गांधीजी सहमत हो गये।

सन्धन में दूसरा गोलमेज परिषद 7 सितम्बर 1931 को शुरू हुआ। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। पण्डित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू व्यक्तिगत क्षमता से परिषद में सम्मिलित हुए। परिषद शुरू होने के पूर्व अहिंसक सरकार अपद्रव्य हो गई, राष्ट्रीय सरकार बनी और सर सैम्युअल होर भारत में नियुक्त हुए। द्वितीय गोलमेज परिषद अपने उद्देश्य में सफल न हो सकी। इसमें नये सविधान के ब्यौरे निश्चित कर लिए गए। सभी न्यायपालिका का ढांचा, राष्ट्रीय विधान मण्डल का संयोजन और भारतीय राज्यों के अखिल भारतीय सच में प्रवेश से सम्बन्ध

नीति निश्चित हो गई। महात्मा गांधी ने कृषि के राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतिपादन किया और सुरक्षा बलों एवं वैदेशिक मामलों में पूर्ण नियन्त्रण सहित औपनिवेशिक स्वतंत्र्य की माँग की, लेकिन विशेष प्रभाव नहीं हुआ। साम्प्रदायिक गतिरोध अनिर्णीत रहा। गांधीजी ने अन्यसंस्कार वर्गों के साथ समझौते की बातचीत की, लेकिन साम्प्रदायिक प्रश्न का हल नहीं निकल सका। सम्मेलन में महात्मा गांधी ने 30 नवम्बर 1931 को अपने भाषण में बताया कि अन्य दल साम्प्रदायिक हैं तथा कांग्रेस भारत में सबके हितों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है। यह साम्प्रदायिक सभ्यता नहीं है तथा उसको कट्टर शत्रु है। कांग्रेस नस्ल, रंग और धर्म का भेदभाव नहीं जानती। कांग्रेस ही सारे अल्पसंख्यकों (Minorities) का प्रतिनिधित्व करती है। गांधीजी के प्रयत्न करने पर गोलनेज सम्मेलन हो सका। प्रत्येक प्रतिनिधि ने सम्मेलन में अपनी जाति के लिए माँग की। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि ऐसे चुने थे जिनमें कोई समझौता न हो सके। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ गठबन्ध कर कांग्रेस के विरुद्ध उसे प्रयुक्त किया। फलस्वरूप सम्मेलन असफल होकर 1 दिसम्बर 1931 को विफल हो गया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन की पुनरावृत्ति और आन्दोलन की समाप्ति

महात्मा गांधी दिसम्बर 1931 को इंग्लैण्ड से खाली हाथ वापस लौट आए। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में ब्रिटिश सरकार ने अपना दमन चक्र तेज कर दिया और गांधी-विरोधी समझौते की शर्तों का उल्लंघन होने लगा। जब महात्मा गांधी लौटे तब तक पंजाब, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा मध्य प्रदेश में अध्यादेशों (Ordinances) द्वारा शासन चलाया जा रहा था। बंगाल में सैनिक शासन लागू कर दिया गया था।¹

28 दिसम्बर को मुम्बई में कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव में कहा गया कि देश की घटनाएँ और सरकार का रवैया यह असम्भव बना रहा है कि कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग करे। कांग्रेस का सहयोग तब तक असम्भव है जब तक सरकार की नीति में अमूल परिवर्तन नहीं हो जाता। प्रस्ताव में कहा गया कि नौकरगारी हटाना सौंपना नहीं चाहती। इससे यह प्रकट होता है कि सरकार कांग्रेस से सहयोग को उन्मील करती है तथा उस पर विश्वास करना चाहती है। प्रस्ताव में कहा गया कि पूर्ण स्वायत्तता से, जिसमें राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होने वाले तरक्षणों के साथ ऐसा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा आर्थिक मामलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित है, जरा भी कम हो कांग्रेस सतोषजनक नहीं मान सकती। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि आदिनेतों तथा कृषकों के सम्बन्ध में रहत दी जाए, भावी विचारों और परामर्श में कांग्रेस के लिये पूर्ण स्वतंत्रता का दावा पेश करने की आजादी रहे और स्वायत्तता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियों की सलाह से चलाया जाए तो कार्य-समिति सहयोग देने के लिए तैयार है। इन शर्तों के अन्धकार पर यदि सरकार की ओर से सतोषजनक उत्तर न मिले, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से दिल्ली के समझौते को रद्द किए जाने की सूचना समझेगी। सतोषजनक उत्तर न मिलने की दशा में कार्य-समिति राष्ट्र को निश्चित शर्तों पर सविनय अवज्ञा, जिसमें लगान-बन्दी सम्मिलित है, आरम्भ करने के लिए आह्वान करती है। वायसराय ने गांधीजी को सूचित किया कि "अपने उत्तरदायित्व का ख्याल रखने वालों सरकार राजनीतिक समस्या की गैर कानूनी कार्यवाही को धमकी युक्त शर्तों की स्वीकार नहीं कर सकती।" सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि दिल्ली समझौते पर सत्यधर्मी से अमल नहीं किया जा रहा है। सरकार का उत्तर 1 जनवरी, 1932 को तार द्वारा मिला और 3 जनवरी 1932 को गांधीजी ने अपना उत्तर दिया कि—“प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को धमकी समझना भूल है। क्या मैं सरकार को याद दिलाऊँ कि सत्याग्रह के घाटी रहते हुए दिल्ली की सन्धि चर्चा आरम्भ हुई और चलती रही। जब समझौता हुआ सत्याग्रह स्थगित किया गया था। मेरे लन्दन जाने से पहले, गत दिसम्बर में शिमला में इस बात पर दुयाय जोर दिया गया था। आपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया था। यद्यपि मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि सम्भव है कुछ हालातों में कांग्रेस को सत्याग्रह जारी करना पड़े, तो भी सरकार ने बातचीत बन्द नहीं की थी। यदि सरकार इस रवैये के विरुद्ध दो, दो बड़ मुझे लन्दन न भेजती, किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शुभकामना प्रदर्शित की थी। आपका यह कहना उचित नहीं है कि मैंने कभी दावा किया है कि सरकार की नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिए। समय बतायेगा कि किसने सच्ची स्थिति प्रकट की थी। मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह को सर्वदा द्वेष रहित तरीके से चलाने का प्रयत्न किया जाएगा।”

जब वायसराय परिस्थिति को सुलझाने को तैयार नहीं हुए, तो कांग्रेस कार्य-समिति ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय कर लिया। आन्दोलन का नेतृत्व पुनः गांधीजी के हाथ में आया, जिन्होंने 3 जनवरी 1932 को राष्ट्र का इस अभिपरीक्षा का सामना करने के लिए आह्वान किया। ब्रिटिश सरकार अपना दमन चक्र चलाने की तलारा में थी, अब आगे दिन 4 जनवरी को महात्मा गांधी एवं कांग्रेस को गैर-कानूनी सभ्य घोषित कर दिया गया। कार्यकर्ताओं को जेलों में डूँग दिया गया और पुलिस को शक्ति दे दी गई कि वह स्ट्रेट्स पर किसी को गिरफ्तार कर सके। कांग्रेसियों को सम्मति-जब्त कर ली गई।

सरकार ने आन्दोलन को कुत्तियों के लिए खतरा का टीका दिया। इसका पता इसे तब से चल जाता है कि नेताओं के अतिरिक्त सत्ता साध व्यक्तियों को जेलों में दूँस दिया गया था। यह आन्दोलन ढाई वर्ष तक 19 मई 1931 तक चलता रहा जब तक महात्मा गाँधी द्वारा 12 सप्ताह के लिए स्वयंसेवा न कर दिया गया। 14 जुलाई 1933 को महात्मा गाँधी ने जन-आन्दोलन रोक दिया, यद्यपि व्यक्तिगत सत्याग्रह एक वर्ष तक चलता रहा तथापि जनता का उत्साह आन्दोलन के प्रति कम हो गया था और नैतिक पतन के चिह्न दिखाई देने लग गये थे अतः 7 अप्रैल 1934 को महात्मा गाँधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को समाप्त कर दिया लेकिन ब्रिटिश सरकार जैसे-एक राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने में असमर्थ रही।

1932 से 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन से पूर्व की मुख्य घटनाएँ

नवम्बर-दिसम्बर 1932 में लन्दन में लॉग्स गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें भारत में बहिष्कार का प्रतिनिधि नहीं गया। ब्रिटेन क्रिश्चियन दल ने इस सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार नहीं किया। ब्रिट। में अनुदार दल की सरकार थी। मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री नहीं थे। नई सरकार ऐसा कोई सुझाव करने को तैयार नहीं थी जिसमें भारतीयों को अधिकार हिलें और भारत पर अंग्रेजों का राजनीतिक और आर्थिक अधिपत्य कमजोर पड़े। भारत के लिये नये सविधान के आरूप के बारे में निर्णय लिए गए। सम्मेलन के समापन पर भारत सचिव ने घोषणा की कि प्रस्तावित सविधान में जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार (i) संसदा और अदालतों से आये देशी राज्यों के राजा हैं मिलने के लिए तैयार हो जाने पर संप्रभुत्व का स्वरूप हो सकेगा (ii) केन्द्रीय विधान मण्डल में ब्रिटिश भारत के स्थानों में से 33½ प्रतिशत स्थान भारतीय मुसलमानों को मिलने एवं (iii) लिय और उद्घोषा के दो नये प्राव बन गए।

मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र-प्रशासित किया जिससे नये विधान के प्रस्तावों को लेखबद्ध किया गया। प्रस्तावों में संघात्मक व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। केन्द्रीय और प्रांतीय स्तरों पर विशेष उच्चशिक्षित और रक्षायाम् कार्यपालिका के हाथों में सुरक्षित रखे गये। गाँधी इर्विन समझौते में रक्षायाम् पार। के हित में होने थे, पालु स्वतंत्र-प्रशासित के अनुसार थे भारत और ब्रिटेन दोनों के सम्मान हित में होने थे। गये भारत सचिव संप्रभुत्व होर ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स में बोलते हुए 21 मार्च 1933 को कहा कि स्वतंत्र-प्रशासित की योजना भारत को प्रशासन देने की योजना नहीं है, यह भारत के सार्वभौमिक प्रगति की दिशा में नहीं किस्त है। इस परिदृश्य से सार्वभौमिक सुधारों की योजना का सन्दर्भ बदल गया।

इन प्रस्तावों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इनसे कोई सन्तुष्ट नहीं था इसलिए इन प्रस्तावों पर आगे विचार करने के लिए तथा पूरी योजना का परीक्षण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति बनाई। समिति में बहुमत अनुदार दल का था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड लिंत्थियरो थे। लॉर्ड लिंत्थियरो के सामने गयाह के रूप में ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थित होने का निमन्त्रण दिया गया। नवम्बर 1934 में इस समिति को रिपोर्ट में दोहराया गया कि संप्र की स्थापना तभी हो सकेगी जब कम से कम 50 प्रतिशत देशी राज्य उसमें शामिल होने को तैयार हो जाएँ। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विधान-मण्डल के लिए पक्ष निर्वाचन देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का नेतृत्व द्वारा नैपामक उच्च सदन समाप्त करने की शक्ति ब्रिटिश संसद के हाथों में रहने आदि के प्रावधान से जो स्वतंत्र-प्रशासित को नई योजना में खारिज थे। संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक का प्राव बन गया जो संसद में पास होने और संसद की अनुमति के बाद अगस्त 1935 में बानूत बन गया। 1935 का अधिनियम दोष पूर्ण था। ब्रिटेन ने इससे सहयोग करने का निश्चय किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत हुए चुनावों में बंगाल और पंजाब के अतिरिक्त अन्य सभी प्रांतों में बहिष्कार के बहुमत प्राप्त किया। सरकार से यह आश्वासन लेकर कि गवर्नर मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बहिष्कार ने जुलाई 1937 में 12 में से 8 प्रांतों में अपने मंत्रिमण्डल बनाये, लेकिन ५ जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस इन मंत्रिमण्डलों में शामिल नहीं हुए।

3 सितम्बर 1939 को द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटेन मंत्रिमण्डलों से बिना अनुमति लिए भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, अतः विरोध स्वरूप बहिष्कृत मंत्रिमण्डलों ने अक्टूबर 1939 में त्याग-पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग इस घटना से प्रसन्न हुई और उसने इस दिन को 'मुक्ति-दिवस' के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग अधिक सक्रिय हो गई। मार्च 1940 में जिन्ना ने 'हि-राष्ट्र सिद्धान्त' को प्रस्तुत करके पाकिस्तान की माँग रखी जो लोग के सहोदर अधिदेशन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई।

अंग्रेजी सरकार ने महसूस किया कि युद्ध काल में बहिष्कार का सहयोग जरूरी है अतः 3 अगस्त 1940 को एक घोषणा की गई कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को यथा शोध औद्योगिक पद दे दिया जायेगा तथा इसके नवीन सविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा कइया जायेगा लेकिन कमिशन ने इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गाँधी ने सांकेतिक विरोध के रूप में नवम्बर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया जो पूर्णतः शांतिमय था। इसका उद्देश्य सरकार के युद्ध कार्यों में बाधा डालना नहीं था। सरकार ने तीकड़ों व्यक्तियों को बन्दी बना लिया। युद्ध पूर्व में फैलने लगा। जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और दिसम्बर 1941 में जापान ने पिराहू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान भारत की सीमा पर आ डटा। इन परिस्थितियों ने अंग्रेजों को चिन्तित कर दिया। ब्रिटिश सरकार भारत का सहयोग देने की कोशिश करने लगी। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस गांधी होकर गुप्त रूप से विदेश

चले गये। उन्होंने जर्मनी और जापान के सहयोग से 'आजाद हिन्द फौज' का संगठन किया और 'दिल्ली चलो' का नारा लगाया। आजाद हिन्द फौज के वीर सैनिकों ने असम की पहाड़ियों और मैदानों में अंग्रेजी सैनिकों से लोहा लिया।

परिस्थितियों से बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख कॅबिनेट नेताओं को जेल से रिहा कर दिया और अप्रैल 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को कॅबिनेट से समझौता करने के लिए भारत भेजा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स 22 मार्च, 1942 को भारत पहुँचे। उन्होंने जो प्रस्ताव 30 मार्च को प्रकाशित किए, उन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) भविष्य से सम्बन्धित प्रस्ताव और (2) वर्तमान से सम्बन्धित प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव में भविष्य के सम्बन्ध में निम्न योजनाएँ दीं—(क) नए भारतीय सभा की स्थापना होगी जिसे स्वशासक उपनिवेश का पद प्राप्त होगा। वह किसी थोले या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा और यदि वह चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर सकेगा। (ख) युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद भारत में एक संविधान सभा की स्थापना होगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। (ग) इस प्रयोजन के लिए प्रांतीय विधान मण्डलों के निम्न सदस्यों के सभी सदस्य एक निर्वाचकमण्डल की स्थापना करेंगे और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा का चुनाव करेंगे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की सख्या निर्वाचकमण्डल के कुल सदस्यों की सख्या का दसवाँ भाग होगा। देशी राज्य अपनी जनसख्या के अनुपात से अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। (घ) ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा तैयार किये गये संविधान को तभी कार्यान्वित करेगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों—(i) यदि ब्रिटिश भारत के प्रान्त नए संविधान की स्वीकार करना न चाहें, तो उसे वर्तमान संविधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। यदि किसी प्रान्त की विधान सभा 60 प्रतिशत बहुमत से सभा में सम्मिलित होने का निराकरण न करे, तो उसके सभ प्रवेश का अन्तिम निर्णय जननिर्णय के द्वारा हो सकेगा। नई संविधानिक व्यवस्था में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तों को सम्राट की सरकार अलग से नया संविधान देगी। (ii) ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय संविधान सभा के बीच एक सन्धि की जायेगी। इस सन्धि में उन विषयों का समावेश होगा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंपने से उत्पन्न होंगे। सम्राट की सरकार ने प्रांतीय और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए जो बचन दिये हैं, सन्धि में उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था की जायेगी, लेकिन भारत सभ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्य राज्यों के साथ जो सम्बन्ध रखना चाहेगा, रख सकेगा। सन्धि में भारत सभ की शक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीय लोकमत के प्रत्येक वर्ग ने अस्वीकार किया। गाँधीजी ने कहा कि क्रिप्स योजना ऐसे जो कि फेल होने जा रहे बैंक के पोस्ट डेटेड अम्बवा आगे की तारीख पर बैंक के सपन की। नेहरू जी के अनुसार उनके पुत्रने मित्र क्रिप्स 'जीतान के वकील' बनकर आये थे और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनर्निमत विभाजनों की सम्भावना के दरवाजे खोल देना था। क्रिप्स योजना की मुस्लिम लीग ने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि इसमें साम्प्रदायिक आधार पर देश विभाजन की माँग नहीं मानी गयी थी। क्रिप्स प्रस्ताव भारतीय नेताओं—कॅबिनेट और मुस्लिम लीग दोनों को अस्वीकार्य थे, अतः उनमें परिकल्पित संविधान सभा की स्थापना नहीं हुई। दोनों दलों ने इस प्रस्तावों को भिन्न आधारों पर अस्वीकार किया था।

भारत छोड़ो आन्दोलन या अगस्त क्रान्ति, 1942

11 अप्रैल, 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिये गये और क्रिप्स एकरूप भारत छोड़ गए। यह स्पष्ट हो गया कि क्रिप्स मिशन का तमारा मित्र देशों की, जो भारत की माँग के प्रति सहानुभूति रखते थे तथा भारतीयों की आँखों में धूल झोंकने का प्रयास था। परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासकों और भारतीय नेताओं के बीच खाई और झीड़ी हो गयी और सरकार के विरुद्ध असंतोष की लहर जोर पकड़ गयी।

महायुद्ध छिड़ने के बाद सुभाषचन्द्र बोस ने युद्ध प्रयत्नों का विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्हें जेल में डाल दिया गया था और बाद में अवस्थता के कारण जेल से निकलकर नजरबन्द कर दिया गया था। जनवरी 1941 में वे पुलिस और सरकार को चुकमा देकर देश से बहर निकल गये। यह एक रोमांचकारी वीर गाथा है। मार्च 1942 में बर्लिन रेडियो से देश के नाम सुभाष बोस ने अपना पहला संदेश दिया। वे युद्ध की स्थिति से लज्ज उठाकर देश की स्वाधीनता को निकट लाने के पक्ष में थे। अप्रैल 1942 के बाद महात्मा गाँधी के विचारों में दृढ़ता आने लगी थी। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का तुरन्त समाप्त होना आवश्यक है।' 'भारत छोड़ो' विचार उनके मन में जन्मे लगा और उन्होंने 'हरिजन' में एक लेखमाता लिखकर उसे विकसित किया। द्वितीय महायुद्ध के आरम्भिक दिनों में गाँधीजी का विचार था कि ब्रिटिश सरकार को उसकी मुसीबत के समय और तब न किया जाए तथा मित्र देशों के युद्ध प्रयासों में नैतिक सहयोग दिया जाए। उस समय कॅबिनेट के बहुमतवीय तब पक्ष ने गाँधीजी की राय नहीं मानी। जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि नाज़ी और तमाराही शक्तियों को परास्त किया जाना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे मित्र देशों की शक्ति क्षीण हो और विश्व में लोकतन्त्र विरोधी शक्तियों को बल मिले। गाँधीजी का ब्रिटिश सरकार के वापसों से तथा देश की जापानी आक्रमण से रक्षा करने की क्षमता और तत्परता से विश्वास ठठ गया था। वे चाहते थे कि अग्रिम शासकों को तुरन्त भारत से चले जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए ताकि भारत

हजारों आदमी गोलीयों के शिकार हो गए। दस हजार लोगों को जेलों में डूँस गया। देश पर में आतंक का शासन पैदाकर सरकार ने नीज महोदय के भीतर आन्दोलन को दबा दिया, पर भूमिगत आन्दोलन चला रहा। जयप्रकाश नारायण, अरगा आसक अन्नी तथा राममनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने मण्डलवादी दृष्टिकोण द्वारा व्यक्त रूप से मार्गदर्शन किया।

भारतीय राष्ट्रीय सेना

(Indian National Army)

सुभाषचन्द्र बोस का विचार था कि द्वितीय विश्व युद्ध भारत के लिए बरदान सिद्ध हो सकता है, यदि ब्रिटेन के विरुद्ध सरसस्त्र युद्ध लड़ा जाए। अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में सुभाषचन्द्र बोस 26 जनवरी, 1941 को गुर्गे पठान का देश पारग करके पुलिस की कड़ी सुरक्षा से बचकर निकल भागे। 28 मार्च, 1941 को वह बर्लिन पहुँचे। जर्मनी में भारतीयों ने उन्हें 'नेताजी' कहा तथा 'जय हिन्द' के साथ अभिवादन किया।

1915 से रास बिहारी बोस जपान में थे। उन्होंने 28 से 30 मार्च, 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें राजा महेन्द्र प्रताप ने भाग लिया। 16-22 जून 1942 को बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कैप्टन मोहनसिंह के नेतृत्व में भारत के युद्धविहीनों की ओर से 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें रास बिहारी बोस की निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। इस सम्मेलन में 35 प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें से एक 'इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रोंट' द्वारा 'इंडियन नेशनल आर्मी' का गठन करने से सम्बन्धित था। 'इंडियन नेशनल आर्मी' का गठन भारतीयों में से करना था। 'इंडियन नेशनल आर्मी' का विचार मनाया में कैप्टन मोहनसिंह ने दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1 सितम्बर, 1942 को 17,000 सदस्यों के साथ हुआ। दिसम्बर, 1942 में मोहनसिंह तथा जापानियों में अड्डा एन ए के गठन तथा कार्य को लेकर मतभेद पैदा हो गए। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में आन्दोलन चलाया रहा। 5 जुलाई, 1943 को सुभाषचन्द्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रोंट का अध्यक्ष तथा 25 अगस्त, 1943 को आई एन ए का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। सुभाषचन्द्र बोस ने आई एन ए के दो मुख्यालय एक रंगून तथा दूसरा सिंगापुर में स्थापित किए।

21 अक्टूबर 1943 को सुभाषचन्द्र बोस ने मुक्त भारत की प्रोवोक्शनल सरकार का गठन किया। जापानियों ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ब्रिटेन से जीत कर इस सरकार की दे दिए। 30 दिसम्बर 1943 को सुभाषचन्द्र बोस ने यहाँ आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अण्डमान का नाम 'राहीद' तथा निकोबार का नाम 'स्वराज्य' रखा गया। 4 फरवरी, 1944 को इंडियन नेशनल आर्मी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्र से आक्रमण किया तथा कोहिमा पर कब्जा कर लिया। 4 जुलाई, 1944 को सुभाषचन्द्र बोस ने नारा दिया 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा'। आई एन ए की एक टुकड़ी राह नवाब खाँ के नेतृत्व में जापानियों के साथ इम्फाल में लड़ी। जापानियों की असहयोग एवं भेदभाव पूर्ण नीति के कारण यह अभियान सफल नहीं हो सका। सुभाषचन्द्र बोस की वायुसेना दुर्घटना में 18 अगस्त 1947 को धुलु होने की घोषणा कर दी गई। आई एन ए ने ब्रिटिश सेना के सामने आत्म समर्पण कर दिया। आई एन ए के नारे 'जयहिंद', 'नेताजी जिन्दाबाद' व 'छलो दिल्ली' थे। कर्मास के तीव्र विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने आई एन ए के मुख्य गिरफ्तार अधिकारियों—मेजर सक्कल, मेजर जनरल राजनवाब खाँ और कर्नल डिल्लो पर खुले आम दिस्ती के सान किल में मुकदमा चलाया। नवम्बर, 1945 में मुकदमा शुरू हुआ। भूमा आई देसाई ने इनकी ओर से बकलत की, लेकिन इनको सरकार ने मृत्यु दण्ड दिया। जनमत के तीव्र विरोध के कारण सरकार को इस दण्ड को स्थगित करना पड़ा।

भारतीय नौसैनिक विद्रोह

(Indian Naval Uprising)

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की गतिविधियाँ यद्यपि भारत से बाहर चल रही थी, किन्तु उनका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ रहा था। उनकी सैन्य गतिविधियों से प्रभावित होकर 1946 में अग्नि अधिकारियों एवं भारतीय अधिकारियों के समान वेतन के प्रश्न को उठाकर मुम्बई स्थित भारत की वायु सेना की टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। इनसे प्रेरित होकर अगले महीने में नौ सेना ने भी नौ सेना के 'तलवार' नामक जहाज पर विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने कई अग्नि अस्त्रों को मीत के भाट उतार दिया और भारतीय नौ सैनिक हड़ताल पर चले गए। मुम्बई की हड़ताल का प्रभाव अत्यन्त बढावाओं पर पड़ा और चेन्नई एवं कर्चों की स्थित नौ सेना के जहाजों पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के झुठे हवाक भारतीय राजनीतिक दलों के झुठे फहरा दिए। सैनिक इकनाब जिन्दाबाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुद्रावाद, हिन्दू-मुस्लिम एक ही आदि के नारे गगने लगे। जनता ने विद्रोहियों को समर्थन देना शुरू किया। ऐसी स्थिति में अग्नि सरकार ने विद्रोहियों को बुलाने के लिए सेना भेजी। भारतीय सैनिकों ने शस्त्र ठठने से मना कर दिया। इस पर अग्नि सैनिक भेजे गए। वे विद्रोह पर उठाकर सेना पर गोलीयों बरसाने लगे। इस पर जनता में तीव्र रोष फैला। 20 लाख से भी अधिक ग्रेडी मजदूरों ने हड़ताल की। अग्नि पुलिस और सैनिक गोलीयों बरसा कर मजदूरों एवं जनता का दमन करने लगे। सरदर

राष्ट्रवादी आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक आयाम (Socio-Economic Dimensions of the Nationalist Movement)

साम्प्रदायिक समस्या तथा विभाजन की माँग (Communal Question & Demand for Partition)

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में उदारवाद, उग्रवाद और अतृकवाद का प्रभाव विशेष रूप से प्रथम विश्वयुद्ध तक रहा। गंधी युग में यह प्रवृत्तियाँ प्रभावी नहीं रहीं, लेकिन साम्प्रदायिकता की लहर राष्ट्रीय आन्दोलन पर आई रही। इस विचलन ने अन्त में देश का विभाजन किया। भारत में साम्प्रदायिकता की बढ़ावा देने में अंग्रेजों ने कसर नहीं रखी। सर्वप्रथम मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय हुआ और प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू साम्प्रदायिक संगठन अस्तित्व में आए। मुस्लिम साम्प्रदायिकता को तावतन रूप में ठपते और अखण्ड भारत के दा टुकड़े करके 1947 में पकिस्तान का निर्माण करने में मुस्लिम लीग का निर्णायक हाथ रहा जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी तत्वों की दबदबा हुए मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया फलस्वरूप अगस्त 1932 में 'साम्प्रदायिक पंचाट' सम्मले आया। साम्प्रदायिक पंचाट जिसे साम्प्रदायिक परिनिर्णय अथवा मैकडोनाल्ड पंचाट भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने की सलाह चाल थी। पंचाट का राष्ट्रवादियों ने एक स्तर से विरोध किया गंधीजों ने इसके विरोध में आगरा अन्तराज प्रारम्भ कर दिया और फलस्वरूप सितम्बर 1932 को 'यूनान-सम्मले' सम्मले आया। मुहम्मद अली जिन्ना भारतीय राष्ट्रवाद पर घेरे कठे रहे उन्होंने ट्वो नेशन सिद्धान्त (Two Nation Theory) का विचार दिया और ऐसी परिस्थितियों पैदा कर दी कि भारत का विभाजन अनिवार्य हो गया और पकिस्तान अस्तित्व में आया।

मुस्लिम लीग की स्थापना से पूर्व मुस्लिम साम्प्रदायिकता

(Muslim Communalism before the Emergence of the League)

भारत में साम्प्रदायिकता का समस्या धार्मिक की अपेक्षा राजनैतिक रही। भारत की राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' का आश्रय लिया। हिन्दुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक-सामाजिक मतभेदों का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने इनका प्रयोग राष्ट्रीयता के प्रभव को कम करने में किया। प्रारम्भ में अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई, क्योंकि अंग्रेजों की प्रभुता का पूर्व मुसलमान इस देश के प्रायः विघात थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का विश्वास था कि इस घात में प्रमुख हाथ मुसलमानों का था। इसल पूर्व बहानी आन्दोलन के बारे में भी अंग्रेजों का इसी प्रकार का विचार रहा था। सर जॉन रे के अनुसार विद्रोह के प्रमुख प्रत्यक्षकारी मुसलमान थे और एच सी बाउन की दृष्टि में ये मुसलमान निश्चित रूप से बन्धी थे।¹

1871 तक ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के साथ विशेष और हिन्दुओं का साथ परस्पर की नीति पर अद्वान किया। शासन वर्गीय और उद्योगों में मुसलमानों का भाग था तो बहुत कम था अथवा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश नीति में निश्चित परिवर्तन आया। हिन्दुओं न अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति से लाभ उठाया और उनके हृदय में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार घर करने लगे, अतः अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, क्योंकि उन्हें डर लगा कि कहीं मुसलमानों पर राष्ट्रीयता का रग न चढ़ जाए। हिन्दू-मुस्लिम गठबन्धन ब्रिटिश हितों के लिए फलक हो सकता था। इस में सर्वोच्च सहयोग सर सैफद अहमद खाँ से मिला। अंग्रेज यह चैन गए कि मुसलमानों की ओर से ब्रिटिश साम्राज्य को कोई खतरा नहीं रह गया है। इस अनुभूति का परिणाम था कि अंग्रेजों ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित कर

अपनी ओर मिलाने की थी। डब्ल्यू एस ब्लायट ने मुसलमानों में अपना 'हक' माँगने की अपील की और कहा—“यदि मुसलमान केवल अपनी शक्ति पहचान लें तो उनकी अवहेलना नहीं होगी तथा सरकार उनसे बुरा व्यवहार नहीं करेगी। इंग्लैण्ड से हमें बराबर भारत में मुस्लिम विद्रोह का भय बना रहता है और यदि मुसलमान एक शब्द कह देता है तो उस पर 20 हिन्दुओं से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अतः यदि मुसलमान चुपचाप बैठे रहे तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश जनता को उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होगी।”¹ अहमदिया आन्दोलन मिर्जा गुलाम अहमद काश्गरी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आन्दोलन ने सभी धर्मों में सुधार का लक्ष्य बनाया। 1885 में अनुमन-ए-हिगायत-इस्लाम की स्थापना की जिसने मुसलमानों की सामाजिक नैतिकता में वृद्धि करने की और बौद्धिक उन्नति करने की चेष्टा की। फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों में राजनीतिक जागृति फैली, उनकी शिक्षा में सुधार हुआ और उनके दृष्टिकोण में व्यापकता आई लेकिन इन मुसलमानों ने साम्प्रदायिकता की भावना को आगे बढ़ाया, कम नहीं किया।

4 **हिन्दू धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव**—19वीं शताब्दी के हिन्दू धार्मिक आन्दोलनों से मुसलमानों में जागृति होने की भावना को प्रभाव मिला। हिन्दू नव-जागरण की प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों में धार्मिक जागृति की भावना को बल मिला। तिलक के शिवाजी समारोह और गणपति महोत्सवों को कट्टरतावादी मुसलमानों ने विपरीत अर्थों में लिया और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को कट्टर हिन्दू धार्मिकता के साथ सम्बन्ध कर दिया। हिन्दू धर्म-सुधार आन्दोलनों अस्वामी और कार्यक्रमों से मुसलमानों में शका के भावों को सबल मिला और साम्प्रदायिकता में उभार आया। पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप जिस धार्मिक उदासीनता का विस्तार हुआ था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों और अनुष्ठानों के प्रचार के लिए बहुत सक्रियता दिखाई पड़ी। यह आन्दोलन उध्वतर वर्षों तक सीमित नहीं था। यह बहुत-सी ऐसी जातियों पर असर डाल रहा था जो अब तक छोटी समझी जाती थीं। उन छोटी जातियों ने हिन्दू समाज के ऊपर उठने की कोशिश की तथा वे हिन्दू धर्म के अनुष्ठानों में और कट्टर होते गए। हिन्दू पुनरुज्जीवनवाद ने इनमें प्राचीन परम्पराओं के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न कर दी।

दोनों सम्प्रदायों में समानान्तर आन्दोलन चले, जिनके उद्देश्य और उपाय एक-से थे। इस सम्बन्ध में उनमें कोई सहयोग नहीं हुआ कि उनके अन्दर की उदारता तथा सहिष्णुता को बल पहुँचाया जाए। वे एक-दूसरे को सन्देश की दृष्टि से देखने लगे। वे आन्दोलन प्रतिवाद पर जोर देते थे और आक्रामक थे। दोनों आन्दोलनों में यह भावना थी कि हम सही हैं और दूसरे से श्रेष्ठता की ओर “मैं तुमसे अधिक पवित्र हूँ”। ये दोनों सम्प्रदाय सर्वोपरि स्वार्थ का कुछ ग्रहण कर रहे थे। यह सरकार के भेदभाव और पक्षपात से और बढ़ गया। धार्मिक पुनरुज्जीवनवाद के कारण साम्प्रदायिक भावनाएँ बढ़ीं, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए गुंजाइश नहीं थी।

इस स्थिति में दूरदर्श और समझ की आवश्यकता थी। दोनों सम्प्रदायों के स्थायी स्वार्थ एक थे और तात्कालिक प्रभाव उनकी सामान्य पराधीनता से उत्पन्न हुए थे। हर वर्ग अपनी उन्नति करने के लिए ऐसी नीतियों का अनुकरण करता रहा, जिससे उनके बीच की खाई और चौड़ी हो गई। परस्पर दोषारोपण के कारण वे तीसरे पक्ष के हाथ में पड़ गए जिसने इन घटनाओं का दोहरा लाभ उठाया। भारत पर अंग्रेजों की पकड़ और मजबूत हो गई।

विधिभ्रम कारणों से 1885 से पहले साम्प्रदायिक सन्देश और अनेक्य पैदा हो गया। इस समय मुसलमानों में उग्र पृथक्तावादी थे, जो यह कहते थे कि हिन्दुओं से बिल्कुल अलग हो जाए और अंग्रेज शासकों के साथ दोस्ती की जाए। इनमें सैयद अमीर अली प्रमुख थे, जिन्होंने 1877 में नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना इस उद्देश्य से की कि मुसलमान नौजवानों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाए। इंग्लैण्ड में पढ़ते समय वह इस विषय में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने तब यह कहा था कि यदि भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक प्रशिक्षण हिन्दुओं के साथ समानान्तर देखा में नहीं चलेगा, तो वे निश्चित रूप से नई राष्ट्रीयता के उठते हुए ज्वर में डूब जाएंगे। सैयद अहमद खाँ ने उस समय सैयद अमीर अली के इस कार्य का समर्थन करने से इनकार किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरम्भ हुआ, तो सैयद अमीर खाँ के सन्देश और भय सहज पर आ गए।

5. **ब्रिटिश नीति में परिवर्तन**—सर सैयद अहमद और बेक की धूमिका—ब्रिटिश शासन के प्राथमिक कारणों में अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई। उनका विचार था कि मुसलमान अंग्रेजी राज के राजु थे और हिन्दू मित्र लेकिन हिन्दू राष्ट्रवाद के उदय के साथ विदेशी शासकों की नीति में परिवर्तन आया। मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खाँ और प्रिंसिपल बेक ने अंग्रेजों और मुसलमानों के मेल की दिशा में प्रयास किया। सैयद अहमद को विश्वास हो गया कि जब तक अंग्रेजों से मुसलमानों का गठबन्धन नहीं होगा तब तक मुसलमानों की दशा में सुधार नहीं हो सकता, अतः उन्होंने प्रयास किया कि मुसलमानों से राजद्रोह के कर्त्तक को मिटा दिया जाए। 1857 के विद्रोह से अंग्रेज नाराज थे। विद्रोह

को विभक्तता हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों के लिए विपश्चिन्नक थी। सर सैयद ने 'भारत के वफादार मुसलमान' (Loyal Mohammadans of India) नामक पुस्तक का प्रकाशन कर अपने विचारों का प्रचार किया। 'प्रायोनियर' (Pioneer) नामक समाचार पत्र में उन्होंने ऐसे लेख प्रकाशित किए जिनसे अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच राष्ट्रप्रेमना उत्पन्न हुई। सर सैयद के विचारों और कार्यों के फलस्वरूप मुसलमानों की राजपक्षित पर सन्देश के बादल दूर हो गए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वह एक खतरा महसूस होने लगा। प्रतिरोध (Counter Poise) के सिद्धान्त पर आधारित करते हुए उस्तादों पराधीनकारियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रतिपार (Counter Weight) के रूप में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का संगठन करना प्रारम्भ कर दिया। 'फूट डालो और राज्य करो' के इस खेल में सफलता प्राप्त करने के लिए सर सैयद अहमद खाँ के सहयोग को प्राप्त करने में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। बम्बयवास के अनुसार सर सैयद को विश्वास दिला दिया कि अंग्रेजों और मुसलमानों या गठबन्धन मुसलमानों की दशा को उन्नत करने में सहायक होगा और उनका राष्ट्रवादियों से मिलन उन्हें छेद, श्रम और अभु में डुबा देगा। सर सैयद ने अपने मुसलमान साथियों को चेतावनी दी कि कांग्रेस ने भारतवर्ष में ब्रिटिश पद्धति के प्रतिनिध्यात्मक शासन की याँग की है उसमें मुसलमानों को सहयोग नहीं देना चाहिए। भारतवर्ष में प्रतिनिध्यात्मक शासन का अधिप्राय है बहुमत का शासन जिसका अधिप्राय है हिन्दुओं का शासन। सर सैयद अहमद खाँ का तर्क था कि यदि हिन्दुओं का देश के अधिकतर भाग में बहुमत है अतः वे ही सदैव सत्ताकाण्ड रहेंगे और मुसलमानों को उनकी अधीनता सहनी पड़ेगी।

साम्प्रदायिक भावधारण के निर्माण में प्रिंसिपल बेक की विशेष भूमिका रही। यह अलीगढ़ कॉलेज का यूरोपीय प्रिंसिपल था। सर सैयद के साम्प्रदायिक विचारों के पीछे विरोधी बेक ने प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया। "बेक ने विशेष रूप से प्रयास किया कि सर सैयद राष्ट्रवाद से अलग रहें और अंग्रेजों तथा मुसलमानों में निकटतम सम्पर्क स्थापित हो।" ¹ डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है ² बेक ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उत्कृष्टतम और भारत की दो महान् जातियों में फूट डालने, फूट पैदा करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान हिन्दुओं के बहुमत के अधीन हो जायें—इस स्थिति में मुसलमान कभी पुनरापत्नी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रिंसिपल बेक के प्रभाव से सर सैयद का प्रतिक्रियावादी-सम्प्रदायवादी स्वरूप अधिक उभर आया। बेक के प्रभाव से वे राष्ट्रीय आन्दोलन से विमुख हो गए और कांग्रेस से असहयोग करते हुए उन्होंने कांग्रेस के निर्णय में एक प्रतिक्रियावादी संगठन की स्थापना की। उनके प्रभाव के अन्तर्गत 'सेण्ट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन' तथा 'मोहम्मदन लिटरेरी सोसैट्टी' ने कांग्रेस से असहयोग किया। 1886 में सर सैयद ने 'मोहम्मदन एजुकेशन ब्रिग्स' की स्थापना की जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था। 1883 में उन्होंने 'मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इण्डिया' (Mohammadan Defence Association of Upper India) की स्थापना की जिसके सचिव वे और बेक थे। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे—(i) अंग्रेजों और सत्ता का मुस्लिम विचारधारा से परिचित कराना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। (ii) ऐसे उपायों पर बल देना जिनसे भारत में ब्रिटिश शासन सुदृढ़ बने। (iii) जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति राजपक्षित की भावना का प्रसार करना। (iv) मुसलमानों में राजनीतिक आन्दोलन को फैलाने से रोकना।

सर सैयद ने बेक के प्रभाव से विभिन्न राष्ट्र विरोधी कार्य किए जिनमें यथा 'संयुक्त भारतीय देशपक्षित सभ' (United Indian Patriotic Association) की स्थापना। इसका उद्देश्य था—अंग्रेजी राज्य को सुदृढ़ बनाना और भारतीय जनता के हृदय में कांग्रेस द्वारा प्रचारित भावनाओं के प्रति घृणा उत्पन्न करना ताकि जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असन्तोष की लहरें शान्त रहें।

ii 'फूट डालो और शासन करो' की नीति—अंग्रेजों ने 'फूट डालो और शासन करो' की नीति द्वारा मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद के उभरते हुए ज्वार को रोकना था। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने यह प्रयत्न किया कि हिन्दु और मुसलमानों में 'फूट डाल कर नकाशत राष्ट्रवाद का मार्ग अवरोध किया जा सकता है और अन्दर से विभाजित भारतीय उपनिवेश पर इच्छानुकूल शासन किया जा सकता है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में मुन्बई के गवर्नर एलफिन्स्टन ने कहा—'फूट डालो और शासन करो' पुनरा रोमन मंत्र है और यही हमारा होना चाहिए। अंग्रेज मेइता एवं मज्यु फ्लवर्डन ने लिखा कि—'अपने विपक्षित कौशल से जिसने हाल तक उनकी कूटनीति को विश्व में अधिक शक्तिशाली बना दिया था, ब्रिटिश शासकों ने इस मंत्र को हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच रखकर साम्प्रदायिकता त्रिकोण (Communal Triangle) निर्माण का निश्चय किया जिसका ये आधार हैं।' ³

1 Mehra and Patwardhan : The Communal Triangle, p 958

2 Rajendra Prasad India Divided p 96

3 Mehra and Patwardhan Op Cit, p 99

अंग्रेजों ने सबसे पहले मुसलमानों को सेवा में उच्च पदों से वंचित करके उनका स्थान हिन्दुओं को दे दिया। सरकारी सेवाओं में यही किया गया। कुछ अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम विरोधी और हिन्दू-पक्षी नीति अपनाई गई, लेकिन 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में ब्रिटिश शासकों के रुख में परिवर्तन आने लगा और यह नीति मुस्लिम पक्षी तथा हिन्दू विरोधी हो गई। अब अंग्रेज मुसलमानों से सौहार्द बढ़ाने लगे और उन्हें साम्प्रदायिक आधार पर विरोध राजनीतिक अधिकार देने की वकालत लगे। विधानसभाओं को पृथक् प्रतिनिधित्व देकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता की जड़ मजबूत बनाई गई।

7. **पृथक् शिक्षण सस्थाओं की स्थापना**—भारत में नवजागरण के फलस्वरूप विभिन्न सम्प्रदाय और जातियों अपनी पृथक् शिक्षण सस्थाएँ खोलने लगे। कुछ शिक्षण सस्थाओं की प्रकृति में साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्साहन मिला। मुसलमानों ने देवबन्द में दास्त-उलूम खोला, आर्य समाजियों ने गुरुकुल स्थापित किए और सनातनियों ने ऋषि कुलों की नींव डाली। धार्मिक आधार पर अनीति में मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय का मूकनाव हुआ। इन सस्थाओं ने विभिन्न सम्प्रदायों को निकट लाने की अनेका एक-दूसरे से पृथक् करने में सहयोग दिया।

8. **बंगाल का विभाजन**—लॉर्ड कर्जन की कुरिल नीति ने हिन्दू मुस्लिम भेदभाव को बढ़ाया। मुस्लिम साम्प्रदायिकता को ठेकी से ठपारने के लिए कर्जन ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। उसने पूर्वी बंगाल का दौरा किया और मुसलमानों ने यह प्रचार किया कि बंगाल के विभाजन की योजना की मुस्लिम समाज के लाभ के लिए लागू किया गया है। कर्जन की अपनी कूटनीति में सज्जता मिली और मुसलमानों को विश्वास हो चला कि ब्रिटिश सरकार का रुख सही है और मुसलमानों तथा हिन्दुओं के हित में कोई मैच नहीं है। डॉ. के. आर. बम्बवन् के अनुसार, 'बंगाल का विभाजन' देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सम्बन्ध (Counter Poise of Natives Against Natives) के कार्यक्रम में एक कदम था। कर्जन ने शासन सम्बन्धी सुविधाओं के आधार पर बंगाल-विभाजन का आश्रित सिद्ध करने की चेष्टा की, परन्तु माय पद है कि बंगाल-विभाजन के मूल में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच विषमता की खाई खोदने की प्रबल नीति थी।

इन कारणों से मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उदय और विकास को बन दिया। गैर सरकारी हस्तियों में सर सैयद अहमद, अमीर अली, मिस्सिन बेक आदि की प्रमुख भूमिका रही और सरकारी हस्तियों में लॉर्ड मिंटो एव लॉर्ड कर्जन का योग अन्वेषणीय रहा।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता (Muslim Communalism)

1906 से 1909 तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता

दिसम्बर, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के पूर्व 1 अक्टूबर 1906 को ब्रिटिश हुकूमत के संकेतानुसार मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल लॉर्ड मिंटो से मिला जिसके नेता सर आग़ा ख़ाँ थे। मुस्लिम शिष्टमण्डल ने भारत के वायसराय के समक्ष एक स्मृति-पत्र पेश करके निम्नलिखित माँगें पेश कीं—

1. मुसलमानों के लिए पृथक् चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था हो।
2. सुधार के बाद बने हुए विधानमण्डलों में मुसलमानों की उनकी आबादी से अधिक स्थान दिए जाएँ।
3. सरकारी नौकरियों मुसलमानों को अधिक दी जाएँ।
4. सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना में सरकारी सहयता दी जाए।
5. यदि गवर्नर जनरल की कौंसिल में किसी भारतीय को नियुक्त किया जाए तो मुसलमानों के हितों का ध्यान रखा जाए।

मुस्लिम शिष्टमण्डल ने वायसराय को यह विश्वास दिलाया कि सरकार मुसलमानों के हितों की वृद्धि करके, उनकी राजभक्ति को प्रोत्साहित बना सकेगी। लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम शिष्टमण्डल की साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँगों को सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार भारतीय इतिहास में पहली बार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को सरकारी स्तर पर स्वीकार कर साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया गया। लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम शिष्टमण्डल को बन्दूक देकर अस्त्रबल दिया कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों को अवश्य ध्यान रखा की जायेगी। लॉर्ड मिंटो कठिनाई की प्रतिक्रिया सत्ता चाहते थे और उनकी कूटनीति सफल हुई। ब्रिटिश सम्मेलन से प्रोत्साहित होकर 30 दिसम्बर, 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की नींव रखी गई। यह भारतीय मुसलमानों का प्रथम साम्प्रदायिक राजनीतिक संगठन था। मुस्लिम लीग की स्थापना के तुरन्त प्रभावित रहे गए—

1. भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य के प्रति शक्ति हस्तान्तरण करना और ब्रिटिश सरकार की नीति के हावभाव में कोई गलत धारणा हो, तो उसे दूर करना।

2. मुसलमानों की माँगों की ब्रिटिश सरकार के सामने रखना और उनके हितों की रक्षा करना।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों के विरुद्ध न जाते हुए मुसलमानों एवं अन्य जातियों में बंधासम्पन्न मेन-मिन्ताप पैदा करना।

मुस्लिम लीग के उद्देश्यों से भारत के राष्ट्रवादियों को यह विश्वास हो गया कि इसका दृष्टिकोण साम्प्रदायिकता और हठधर्मिता का दृष्टिकोण रहेगा। लीग का उद्देश्य विदेशी हुकूमत के प्रति राजपक्षित में वृद्धि करना और राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रवाह को रोकना था। कई मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थपना का विरोध किया। एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता ने कहा था—“मेरे सहपाथियों द्वारा भारत में अस्माधेय भाव पैदा करने का प्रयत्न प्रशंसनीय नहीं है। यह पन्देरा की पेटी सिद्ध होगी और भारत को ध्वंशर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।” 1908 में मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों को अबादी से अधिक स्थान विधान-मण्डलों में दिए जाने की माँग की। यह माँग की गई कि प्रिवी-कौंसिल में यदि एक हिन्दू नियुक्त किया जाए तो मुसलमान भी अवश्य नियुक्त किया जाए तथा सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1909 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पुनः इन्हीं माँगों को दोहराया और इंग्लैंड में अपने रिश्ते-मण्डल भेजे। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग के साम्प्रदायिक प्रयत्नों का घोर विरोध किया पर कोई परिणाम नहीं निकला। लॉर्ड रिप्टो के इस आग्रह पर कि भारतीय मुसलमानों को सन्तुष्ट करने के नाम पर पृथक् निर्वाचनों की माँग को मानना जरूरी है, भारत सगिव लॉर्ड मॉर्ले को अपनी इच्छा और विचारों के विपरीत यह प्रस्ताव पान लेना पड़ा और 1909 के मॉर्ले-रिप्टो सुधारों में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् चुनावों की व्याख्या का समावेश कर दिया गया। इसके बाद हिन्दू-मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ती चली गई और पृथक् चुनाव का परिणाम हुआ कि पृथक् राष्ट्रियता की विचारधारा और अन्य में देश का विभाजन तथा दो पृथक् राष्ट्रों की स्थापना।

1910 से 1929 तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता

1909 के अधिनियम के उपरान्त लीग की प्रतिक्रियावादी नीति कुछ लिपित पड़ गई। 12 दिसम्बर, 1911 को इंग्लैंड पर समाप्त कर दिया गया। दूसरी ओर 1912 में टर्की साम्राज्य के यूरोप स्थित बालकन प्रान्तों में राजाधीनता के लिए सफल आरम्भ कर दिया और अंग्रेजों ने उनकी सहायता की। टर्की में नवयुवक आन्दोलन आरम्भ हुआ जिसका उद्देश्य टर्की को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना था। अंग्रेजों ने इस आन्दोलन को दबाने में टर्की सम्राट की सहायता की। फलस्वरूप भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से खार खा बैठे और डॉ. अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयत्नों से कमिंस और लीग में सहयोग की सम्भावनाएँ प्रबल हो गईं। 1916 में लीग-कमिंस समझौता हो गया जो लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। आर्थिक रूप से इस समझौते तथा छिटाकत आन्दोलन को कमिंस समझौते के कारण 1920-22 के असहयोग आन्दोलन के दौरान दोनों सम्प्रदायों के बीच सहयोग चलता रहा। इस बीच अंग्रेजों की कुटिल नीति यही रही कि हिन्दू और मुसलमानों में सहयोग के सूत्रों को खल कर दिया जाए। 1919 के अधिनियम द्वारा साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति का विस्तार करते अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति का परिचय दिया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए प्रचलित साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति को बनाए रखा गया, पंजाब के सिक्खों के लिए साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति की व्यवस्था की गई, मुख्य के मराठों और चेन्नई के ब्राह्मणों के लिए बहु-सदस्यीय चुनाव-क्षेत्र में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई तथा अन्य हितों और वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष चुनाव-पद्धति जारी की गई। यह सब राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल कार्य था।

1922 से अगले 10 वर्षों तक भारत में साम्प्रदायिक दलों की स्थिति रही। 1916 के लखनऊ समझौते का महत्व नहीं रहा। ब्रिटिश नीकरशाही ने हिन्दू-मुस्लिम दलों को रोकने में आवश्यक सावधानी नहीं बरती तथा प्रच्छन्न रूप से इन्हें उत्तेजित और किया। 1927 में मुस्लिम लीग के दो दल हो गए—एक दल का अधिवेशन मोहम्मद शाफी के नेतृत्व में लाहौर में और दूसरा जिन्ना के सभापतित्व में कोलकाता में हुआ। इसी समय देश के सविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित सविधान में पृथक् निर्वाचन को कोई स्थान नहीं दिया गया, अतः मुस्लिम लीग के शाफी दल ने इसे स्वीकार नहीं किया। इधर जिन्ना ने इंग्लैंड से लौटकर शाफी दल से समझौता कर लिया और 1919 में लीग के दिव्तीय अधिवेशन में 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें यह आग्रह किया गया कि—

1. केन्द्रीय विधान-मण्डल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 हो।
2. साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन-पद्धति से हो, परन्तु कोई सम्प्रदाय जब चाहे तब सपुक्त निर्वाचन-पद्धति स्वीकार कर सके।
3. किसी प्रादेशिक पुनर्विभाजन द्वारा पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में मुसलमानों के बहुमत पर कोई प्रभाव न पड़े।
4. किसी विधान-सभा अथवा लोक प्रतिनिधि सभा में ऐसा कोई विधेयक या प्रस्ताव स्वीकृत न हो जितना किसी सम्प्रदाय के 3/4 सदस्य अपने समुदाय के हितों के विरुद्ध बताते हुए विरोध करें।

- 5 विधान में सभी नौकरियों में योग्यता की आवश्यकता के अनुरूप मुसलमानों को उचित भाग मिले।
- 6 मुस्लिम सभ्यता, शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानून और श्रमिक संस्थाओं की रक्षा एवं उन्नति के लिए सरक्षण एवं सरकारी सहायता मिले।
- 7 केन्द्रीय अथवा प्रांतीय मंत्रिमण्डल में कम से कम 1/3 मन्त्री मुसलमान रहें।

जिन्ना की इन शर्तों ने मुसलमानों की माँग का रूप धारण कर लिया। यद्यपि मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय दल ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, तथापि आगे मैकडोनाल्ड के साम्प्रदायिक पचाट में इन्हें पूर्ण स्थान दिया गया।

1930 से 1947 तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता और विभाजन की माँग

अंग्रेज हर प्रकार से साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देना चाहते थे अतः इस तर्क की आड़ में कि भारतीय स्वयं अपने में कोई समझौता नहीं कर पा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त, 1932 को विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व में एक पचाट प्रकाशित किया जो 'साम्प्रदायिक पचाट' (Communal Award) के नाम से जाना जाता है। इस पचाट में पृथक् निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों के ऊपर लागू कर दिया गया। मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्खों, आंग्ल-भारतीयों तथा महिलाओं तक के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई। श्रम, वाणिज्य, उद्योग, जमींदारों तथा विश्वविद्यालयों के लिए पृथक् चुनाव-क्षेत्र निर्धारित किए गए। निर्वाचकों को 17 विभिन्न भागों में बाँट दिया गया। स्पष्ट था कि यह साम्प्रदायिक पचाट भारतीय राष्ट्रवाद को निर्बल करने के लिए भारत के सम्प्रदायगत तथा वर्गगत मतभेदों को उग्र बनाने के लिए किया गया था। यह योजना प्रांतीय विधान-मण्डलों में ही लागू की जानी थी, केन्द्रीय विधान-मण्डल के निर्णय का प्रश्न अनिर्णीत छोड़ दिया गया था। इस पचाट में पुनः इस तथ्य की पुष्टि कर दी गई कि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यक वर्गों और विशेष रूप से मुसलमानों पर कृपात्त थी। सौभाग्यवश महात्मा गाँधी के अनुरोध के कारण सितम्बर, 1932 में पूना पैक्ट हो गया। फलस्वरूप हिन्दुओं के अन्दर हरिजनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्णय लिया गया और उनके पृथक् निर्वाचन बन्द कर दिया गया।

भारत में फूट डालकर हड़कृत करने की नीति पर चलते हुए अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत विनाशकारी साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति का हरिजनों के लिए विस्तार कर दिया। मुसलमानों को केन्द्रीय विधान-मण्डल में ब्रिटिश भारत के 33¹/₂ प्रतिशत स्थान दिए गए, जबकि उनकी जनसंख्या इस अनुपात में नहीं थी। विशेष रिपण्टों और ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों का उत्साहित हो उठना स्वाभाविक था। 1935 का अधिनियम लागू होने के बाद देश में मुस्लिम राजनीति ने नया मोड़ ले लिया। मुस्लिम लीग ने प्रतीक्षा की नीति अपनाई और कांग्रेस तथा अंग्रेज सरकार के बीच मतभेदों से लाभ उठाने की कोशिश की। अधिनियम के अन्तर्गत हुए निर्वाचनों के फलस्वरूप अनेक प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर मंत्रिमण्डल बनाना चाहा, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया और इस पर लीग ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि बहुसंख्यक सम्प्रदाय अपनी नीति से यह स्पष्ट करता जा रहा है कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए है। इसके साथ ही मुस्लिम लीग ने यह नारा भी बुलन्द किया कि इस्लाम छोड़ें मैं हूँ। यह वह समय था कि जब द्वितीय महायुद्ध के बादल अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति पर छाए जा रहे थे। मुहम्मद अली जिन्ना ने चालाकी से काम लेते हुए वायसराय के साथ सौदेबाजी की। युद्ध प्रयासों में सरकार की सहायता करने के लिए लीग की ओर से दो शर्तें रखी गईं—एक यह कि कांग्रेस बहुमत वाले प्रांतों में मुसलमानों के साथ न्याय हो और दूसरी यह कि भारत के लिए कोई भावी संविधान मुस्लिम लीग की अनुमति बिना न बनाया जाए।¹ अब एक मुस्लिम पृथक्तावादियों ने अपनी माँगों को पृथक् निर्वाचक-मण्डलों, गुरु-भार और आरक्षणों तक सीमित रखा था, लेकिन 1938 में हिन्दू और मुस्लिम दो राहों का सिद्धान्त सामने आया। मुस्लिम लीग ने यह दावा करना आरम्भ कर दिया कि भारतीय मुसलमान एक 'समुदाय' नहीं, प्रत्युत एक 'राष्ट्र' है इसलिए उन्हें 'राजनीतिक आत्म-निर्णय' का अधिकार है।²

अगस्त 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने साहसिक अधिवेशन में 'पाकिस्तान प्रस्ताव' पारित किया तथा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों का एक अलग पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न मुस्लिम राज्य स्थापित किए जाने की माँग पेश की जिसमें 'भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र' जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र सम्मिलित होंगे।³ उल्लेखनीय है कि भारत के मुसलमानों के लिए एक पृथक् राज्य का विचार सबसे पहले डॉ. मुहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के एक विशेष अधिवेशन में प्रकट किया था। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर-पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना की योजना प्रतिपादित की, लेकिन उस समय लोगों ने इसे दार्शनिक की कल्पना का एक चित्र समझा, अतः उनके संकेत पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, पर दूसरी ओर रहमत अली के प्रभाव में रहने वाले मुस्लिम कैम्ब्रिज विद्यार्थियों में यह विचार जोर पकड़ता गया। रहमत अली ने ब्रिटिश संसद के सदस्यों को अपनी पत्रिकार्य प्रस्तुत की जिन्में कहा गया था

1. 2. डॉ. मुहम्मद इकबाल, वही, पृ. 162.

3. डॉ. मुहम्मद इकबाल, वही, पृ. 163.

कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान का राज्य बना दिया जाए, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा-प्रान्त, काश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान के भाग मिलाए जाएँ। यूसुफ अली ने इस योजना को विद्यार्थियों की देन कहा तथा जफरुल्ला खाँ ने इसे स्वतन्त्रोन्मीय एवं अव्यवहार्य बताया। 1940 तक जिन्ना तक ने इस बात को नहीं माना। लन्दन से प्रकाशित पत्रिका 'टाइम एंड टाईड' (Time and Tide) में 19 जनवरी, 1940 को जिन्ना ने लिख—भारत में दो राष्ट्र हैं जिन्हें एक ही मातृभूमि के प्रशासन में भाग्यदेवर होना चाहिए, लेकिन चीन महीने बाद ही जिन्ना पूरी तरह पाकिस्तान की माँग का नेता बन गया।¹

जब 1942 में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध 'भारत छोड़ो आन्दोलन' चलाया गया तो मुस्लिम लीग ने आन्दोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं की, प्रत्युत प्रत्येक सम्भव तरीके से अंग्रेज सरकार की सहायता की। 1942 से 1944 तक कांग्रेस के सभी नेता जेल में थे, अतः उनकी अनुपस्थिति का मुस्लिम लीग ने फायदा उठाया। यह प्रचार किया गया कि कांग्रेस एक कट्टर विरक्त सत्ता है जो भारत में हिन्दू राज्य कायम करना चाहती है। लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए पुर्णोत्तरा प्रचार किया, 1946 के अन्तरिम चुनावों में मुस्लिम लीग को 1937 के चुनावों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त हुई। चुनावों से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और लीग दो ही बड़ी राजनीतिक सत्ताएँ भारत में हैं जो क्रमशः हिन्दुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चुनावों में अपनी सफलता से प्रेरित होकर लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए आन्दोलन छेड़ दिया। लीग ने अंग्रेजों की नीति अपनाते हुए अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया और 27-29 जुलाई को लीग की परिषद ने स्वतन्त्र पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए 'सीधी कार्यवाही' (Direct Action) की घोषणा की। 16 अगस्त सीधी कार्यवाही शुरू करने की तारीख निर्धारित हुई। 'सीधी कार्यवाही' का उद्देश्य था हिन्दुओं को मार-काट शुरू कर साम्प्रदायिक दंगों और आतंक का बतलावण फैलाकर, यह सिद्ध करना कि हिन्दू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते और देश के विभाजन के अतिरिक्त और कोई रास्ता है ही नहीं।² 16 अगस्त को देश के विभिन्न भागों में दंगे हुए और बगल तथा सिंध में जहाँ मुस्लिम लीग की सरकारें थीं, सार्वभौम छुट्टी की गई। कसकते में भीषण खूनपात हुआ। सार्वभौम अनुपस्थितों के अनुसार 500 हिन्दू मार डाले गए और 25-20 हजार के चोटें आईं। सम्पत्ति लूटने की तथा महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार और बलात्कार करने की असंख्य घटनाएँ हुईं।³ साम्प्रदायिक दंगों की यह आग सारे देश में फैल गई और एक वर्ष से अधिक समय तक यही स्थिति रही।

परिस्थितियों से विचारा होकर कांग्रेस ने देश का विभाजन करना स्वीकार कर लिया। गाँधीजी अन्त तक विभाजन के विरुद्ध रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि "यदि सारा भारत भी अंग को सपटों में फिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। भारत का विभाजन मेरे गले पर ही हो सकेगा।" 3 जून, 1947 को ब्रिटिश सरकार ने एक नीति सम्झौती स्वतन्त्र दिया जिसमें दो गई योजना (माउंट बैटन योजना) में भारत के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया गया। परिणामस्वरूप माउंट बैटन योजना के आधार पर ब्रिटिश ससद ने 18 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 को पास किया जिसके अनुसार 15 अगस्त, 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमोनियनों की स्थापना हो गई। टुकड़ों में विभक्त होकर भारत स्वतन्त्र हो गया।

हिन्दू साम्प्रदायिकता (Hindu Communalism)

मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने अनिवार्य रूप से हिन्दू साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया। डॉ. सुभाष कश्यप के अनुसार "इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता मुस्लिम साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया थी। उसने साम्प्रदायिक विद्वेष की ज्वाला दहन नहीं की, पर उसकी सपटों को अवश्य जँका रखा जिससे मुस्लिम-नीतियों को पाकिस्तान की दिशा में झोपने की प्रेरणा मिली। पृथक्तावाद की भावना को बढ़ाने में हिन्दू साम्प्रदायिक सत्ताओं से अधिक ब्रिटिश नौकरशाही ने काम किया।"

बंगाल-विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जब मुसलमानों ने साम्प्रदायिक दंगे शुरू कर दिए, हिन्दुओं की सम्पत्ति को लूटा और हिन्दू औरतों की इज्जत पर हाथ डाले तो हिन्दुओं ने विशेषकर बंगाल और पंजाब में, स्वयं को संगठित करना शुरू कर दिया। बंगाल में हिन्दुओं द्वारा अनुशीलन समितियाँ और पंजाब में हिन्दू-सभाएँ गठित की गईं। मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरोध रूप में अनेक हिन्दू बुद्धिजीवियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे हिन्दू महासभा स्थापित करके हिन्दू जाति को संगठित और शक्तिशाली बनाएँ। 1915 में हिन्दू महासभा की स्थापना हुई।

1 शमानन्द अग्रवाल, हथार राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सामाजिक विकास, पृ. 274-75
2-3 डॉ. सुभाष कश्यप, वही पृ. 218.

प्रारम्भिक अवस्था में महासभा का नेतृत्व पण्डित मदनमोहन मालवीय और सात्ता साजपव राय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ में रहा, लेकिन धीरे-धीरे कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने महासभा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हिन्दू महासभा मुस्लिम लोग की अपेक्षा अधिक संयुक्त और उदार समूह रही है। इसका मूल उद्देश्य था कि हिन्दुओं को एक जाति के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया जाए तथा मुस्लिम जाति को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर जनमत का निर्माण किया जाए। हिन्दू महासभा ने हिन्दुओं में एक राष्ट्र होने की भावना पैदा की। वीर सावरकर के प्रयत्नों से हिन्दू राष्ट्र का विचार हिन्दू महासभा का 'घोष शब्द' बन गया। यह कहा जाता है कि हिन्दू राष्ट्र के विचार की प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों के इस दावे को प्रोत्साहन मिला कि मुस्लिम सम्राट हिन्दुओं से भिन्न एक पृथक् राष्ट्र है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुस्लिम लोग ने अपने जन्म के तुल्य बाद ही पृथक्तावादी प्रवृत्ति का स्पष्ट संकेत दे दिया था। हिन्दू अपनी उदार मनोवृत्ति के कारण अपनी जड़-सी कमी अथवा छापी को तुल्य स्वीकार कर लेते हैं और बहुधा उसे अनावश्यक रूप से महत्वपूर्ण बना देते हैं। यह मनोवृत्ति इस विचार के विकसित होने में सहायक रही है कि हिन्दू महासभा जैसे संगठनों की कार्यवाहियों ने मुस्लिम-स्त्रीगियों को पाकिस्तान की दिशा में सोचने की प्रेरणा दी। यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण घटना-चक्र एक प्रतिक्रिया द्वारा दूसरी प्रतिक्रिया को और दूसरी प्रतिक्रिया द्वारा पुनः पहली प्रतिक्रिया को जन्म देने और बढ़ाने का था। यह एक विचित्र बात थी कि मुस्लिम संगठन बनने पर कोई तृप्तन खड़ा नहीं होता था, लेकिन हिन्दू संगठन बनने पर एक तृप्तन खड़ा कर दिया जाता था।

यह अभियान चलाया गया कि जिन हिन्दुओं को मुसलमान या ईसाई बना दिया गया था उन्हें और उनके वंशजों को पुनः हिन्दू बनाया जाए। हिन्दुओं के संगठन और शुद्धि आन्दोलन की प्रतिक्रिया यह हुई कि मुसलमानों ने तन्त्रिम और पन्थिक का अपना आन्दोलन चला दिया। अखिल इस्लामी आन्दोलन की प्रतिक्रिया हिन्दुओं पर हुई और 1936 में लाहौर के हिन्दू महासभाई अधिवेशन में जगत् गुरु राक्षसचरण के अध्यक्षीय भाषण में अखिल हिन्दूवाद का स्वर झकृत हुआ।

पिछड़ी जाति के आन्दोलन, ट्रेड यूनियन तथा किसान आन्दोलन, नागरिक अधिकार आन्दोलन

**(Backward Caste Movements, Trade Union and
Peasant Movements, Civil Right Movement)**

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन क्षेत्रीय दृष्टि से ही नहीं था। इसका विस्तृत सामाजिक आधार था। विभिन्न सामाजिक समूह इसमें सम्मिलित हुए। भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभिन्नताएँ रही हैं। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक समूह भी हैं। ब्रिटिश शासन में यह विभिन्नता अधिक थी। समाज हिंदू और मुसलमानों में बँटा हुआ था। मुसलमानों में सामाजिक विभाजन था। समाज में विभिन्न आर्थिक समूह थे, जिनमें बहुत विषमता थी। इन समूहों के सामाजिक और आर्थिक हित भिन्न थे। राष्ट्रीय आन्दोलन में अधिकांशिक समूह सम्मिलित होते गए।

बीसवीं शताब्दी एक क्रांति एक जन आन्दोलन का रूप ले चुकी थी। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन, इसका चरम बिन्दु था, जिसमें सामाजिक-आर्थिक विभिन्नता को भुलाकर सभी सामाजिक समूह सम्मिलित हुए। विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लक्ष्य ने विभिन्न समूहों को एक कर दिया। विभिन्न समूहों में गहव की एकता की भावना लाने में राष्ट्रीय आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आन्दोलन ने एक ऐसे लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि विभिन्न आर्थिक समूह एक मंच पर इकट्ठे हो गए। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत दिनों से असंतोष की भावना थी, जिसके कई कारण थे। भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की स्थापना से पहले जनता के विशेष के उदाहरण मिलते हैं। बंगाल के पावना जिले में 1873 में संगठित जमींदारों के खिलाफ भूमि सञ्चयी संगठन (Agrarian League), महाप्रभु के दक्षिण क्षेत्र में 1875 में साहूकारों के खिलाफ दण्ड आन्ध्र प्रदेश के 'रपा' क्षेत्र में 1879 में जनजातियों का विद्रोह, ऐसे कुछ उदाहरण हैं। किसानों और औद्योगिक श्रमिक वर्गों का अपना संगठन था। उनका विद्रोह अपने निरन्तर दमनकारी वर्गों—जमींदारों, साहूकारों और उद्योगपतियों के खिलाफ था। राष्ट्रीय आन्दोलन ने इनके समग्र 'ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने' का उच्च लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य के द्वारा किसान और जमींदार, श्रमिक और उद्योगपति सभी राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित हो गए। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का आपसी संपर्क ब्रिटिश सरकार के निरन्तर लाभकारी था, लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन ने इसके स्थान पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में एकता की भावना की स्थापना की। आने वाले वर्षों में यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ।

कोई भी आन्दोलन विशेष सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों की अपेक्षा नहीं कर सकता। किसान, श्रमिक, उद्योगपति, जमींदार—सभी वर्गों का महान भारतीय विचारक और नेता महात्मा गाँधी जिन्होंने 1920 में 'असहयोग आन्दोलन', 1930

में 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' और 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की शुरुआत की वे भारतीय स्वतन्त्रता के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। उन्होंने एक अहिंसा प्रधान समाज का स्वरूप दिया था। उन्होंने असम्यक्ता उन्मूलन के लिए विशेष रूप से कार्य किया। प्रसिद्ध पुस्तकें 'वीमेन एण्ड सोशल जस्टिस', 'सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका', 'इकॉनॉमिक्स ऑफ खादी' आदि पुस्तकों ने चेतना जागृत की। सभी वर्ग अपने अपने हितों को सुनिश्चित रखना चाहते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन ने इन वर्गों को संगठित करने के हितों का भी ध्यान रखा।

महात्मा गांधी ने 1917-18 में बिहार में गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए 'चंपारन सत्याग्रह' किया। इसका बाद 1919 में 'खेड़ा सत्याग्रह' हुआ। उन्ना प्रदेश के रायबरेली और फैजाबाद क्षेत्र में 1920 में किसान आन्दोलन अधिक व्यापक थे। 1921 में मालाबार क्षेत्र में 'मोपला विद्रोह' में जो कृषि श्रमिक और कृषक समाहित हुए वे अविभक्त मुसलमान थे। किसान सभाओं की स्थापना हुई जो बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश और बिहार क्षेत्रों में सक्रिय थी। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई। उद्योगों की स्थापना और व्यापारिक बैंकों के विस्तार के साथ ही भारतीय मध्यम वर्ग उभर आया, जिसका सम्बन्ध व्यापार और उद्योग से था। बंगाल के व्यापार संगठन—चेम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1887 में की और भारतीय व्यापारी सभ—इंडियन मेर्चेंट्स चैम्बर की स्थापना मुम्बई में 1907 में हुई। कोलकाता में 1900 में भारतीय व्यापार संगठन की स्थापना की गई। अन्ततः 1925 में एक भारतीय व्यापार सभ की स्थापना हुई। स्वदेशी आन्दोलन ने बिजनेस में बनी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया, जिसके द्वारा 'राष्ट्रीय उद्योगपति' विशेषकर कपड़ा उद्योग के उद्योगपति [१] और आकर्षित हुए। इसका असर यह हुआ कि भारत में निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन मिला, जिसका उद्योगपतियों ने स्वागत किया। बिहारी बजाज, अबालाल साराभाई, कस्तूर भाई जैसे उद्योगपतियों का कांग्रेस को समर्थन मिलने लगा। हितों की रक्षा के लिए संगठन जोर पकड़ रहे थे और राष्ट्रीय आन्दोलन के राय पर वे सम्मिलित हो रहे थे। विशेष समूहों से सम्बन्धित विषयों के साथ स्वतन्त्रता के व्यापक संरक्ष को साधने रखने से समूहों का समर्थन ज्यादा यथार्थवादी हो गया। आन्दोलन विशेष हितों की रक्षा और स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए प्रभावकारी था।

स्वतन्त्रता संग्राम के नेता समाज के विभिन्न वर्गों के समर्थन के प्रयास के साथ समाज सुधार और नागरिक अधिकारों में भी सजग थे। स्वतन्त्रता संग्राम के कई नेता सर्वमान्य समाज सुधारक थे। राजा राममोहन राय ने जिन्हें 'भारतीय राष्ट्रीयता का पिता' कहा जाता है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह आन्दोलन हिन्दू समाज की सती प्रथा और बाल विवाह जैसी बुराईयों के निषेध के लिए उत्तरदायी था। ब्रह्म समाज ने विद्वत्सत्ता की स्थापना तथा परिवारों और पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से शिक्षा के प्रसार का काम किया।

महादेव गोविन्द रानडे ने 1867 में मुम्बई में प्रार्थना सभा की स्थापना की। दवानन्द सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। 1886 में पहले दवानन्द एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना के बाद डी. ए. वी. स्कुल और बालेजों की गृहस्था प्रसिद्ध हो गई। ए. आर. देसाई के अनुसार, 'राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ में आर्य समाज ने एक प्रगतिशील भूमिका निभाई थी।' स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य था—'भारत को परिचयी सभ्यता के भौतिकवादी प्रभाव से बचाना।' श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी एक आध्यात्मिक आन्दोलन था। इसका पवित्र सम्बन्ध बाल विवाह, पर्दा प्रथा और निरक्षरता जैसी कुरीतियों को गिराने से था। कांग्रेस के कार्यक्रमों में विशेषतः होमरूल और स्वदेशी आन्दोलन में इसका योगदान था। मुस्लिम समुदाय में जिन सभाओं द्वारा सुधार लागू हुए वे अहमदिया आन्दोलन, अनुमन ए हिमायते इस्लाम, नवदख्तल उलेमा, अलीगढ़ आन्दोलन अब्दुल गफ्फर खान का युदाई छिदमतगार आन्दोलन और छाकसार आन्दोलन, सिक्खों द्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक सुधार आन्दोलन और सिंह सभाओं की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आन्दोलन के सभी नेता समाज सुधार और नागरिक अधिकारों के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे कुछ नेताओं के नाम हैं—राजा राममोहन राय गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक, अरविन्द घोष, लाला लाजपत राय, मुहम्मद इकबाल और महात्मा गांधी।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रगतिशील विचार सुधार के तीन कार्यक्रमों से स्पष्ट होते हैं—(1) वर्ग व्यवस्था (2) स्त्रियों की स्थिति एवं (3) असम्यक्ता।

ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज सन्ने समाज के विभिन्न वर्गों में बँटवारे का विरोध किया। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के 'सत्य शोधक समाज' और चेन्नई के 'स्व सम्मान आन्दोलन' (Self Respect Movement) ने उच्च वर्ण के प्रभुत्व के उल्लाप आवाज उठाई। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी और विधवाओं की दयनीय स्थिति, जैसी कुरीतियों का विरोध नारी मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। नेताओं ने नारी शिक्षा पर जोर दिया। 1919 के बाद राजनीति में अधिक महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया। महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाने में महात्मा गांधी की विशेष भूमिका रही। महिलाई किसान आन्दोलन में सक्रिय थीं।

सुआहृत वर्ग व्यवस्था की विकृति के रूप में प्रकट हुई। समाज सुधार और नागरिक अधिकार आन्दोलन और कांग्रेस ने सुआहृत दूर करने पर बल दिया। महात्मा गाँधी ने जिन्होंने इस समूह को 'हरिजन' की संज्ञा दी, इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। बी. आर. अम्बेडकर को इनका प्रवक्ता माना गया। अहर्तों के लिए आवाज उठाने में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का योगदान महत्वपूर्ण था। प्रान्तों में 1937 की कांग्रेस सरकारों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं द्वारा ये प्रश्न समानता और लोकतांत्रिक अधिकार के सिद्धान्तों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ये सिद्धान्त ब्रिटेन के शासन से स्वतन्त्रता की उनकी माँगों का आधार था। स्वतन्त्रता संग्राम के नेता उदार विचारधारा और कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मानते रहे। कुछ समूहों तक सीमित सकीर्ण विचारों का कोई स्थान नहीं था। नेताओं में मतभेदों की अभिव्यक्ति इस तरह हुई—नरम दल, उदारवादी और दक्षवादी, परिवर्तन न चाहने वाले, स्वराज्यवादी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी आदि। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के निर्माण के बाद आन्दोलन का समाजवाद की ओर स्पष्ट झुकाव हो गया। इस विचारधारा को जवाहरलाल नेहरू और मुभाषचन्द्र बोस जैसे प्रभावशाली नेताओं का समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस के नेता देश की गरीबी और पिछड़ेपन की समस्या के प्रति सजग थे और आर्थिक उत्थान तथा समानता पर अधिक बल देने के कारण समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। स्वतन्त्रता आन्दोलन के विस्तार के साथ धन की जनता के विभिन्न समूहों में राजनीतिक चेतना आती गई। इस चेतना में जीवन का सामाजिक आर्थिक पक्ष और समाज के विभिन्न स्तरों का हित निहित था। भारतीय राष्ट्रवाद के अन्तर्गत लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना आई। जनता लोकतन्त्र के नताओं और कार्य विधि से परिचित हो गई। नागरिकता को इस चेतना के साथ उसमें किसान, श्रमिक और उद्योगपति जैसे वर्गीय हितों के सम्बन्ध में चेतना आई।

साँवैधानिक विकास (ब्रिटिश शासन में महत्वपूर्ण घटनाएँ)

(Landmarks in Constitutional Development during British Rule)

भारत में संविधानवाद के विकास में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसका राष्ट्रीय आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन आवश्यक है। संविधान के विकास और राष्ट्रीय आन्दोलन में अन्तर्क्रिया रही है। इस सन्दर्भ में दृष्टव्य है कि 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम ने अंग्रेजों को 1858, 1861, 1892, 1919, 1935 और 1947 के महत्वपूर्ण अधिनियमों को पारित करने के लिए विवश किया। भारत शासन अधिनियम, 1858-1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम ने ईस्ट-इंडिया कम्पनी के प्रशासन को हटाने पर दृष्टि दिला दी। परिणामस्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत शासन अधिनियम 1858 पारित करना पड़ा।

इससे भारतीय शासन सीधे सम्राट के नियन्त्रण में आ गया। भारत का शासन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा 15 सदस्यीय भारत परिषद की सहायता से किया जाने लगा जिसमें 8 सदस्य सम्राट द्वारा नामांकित और शेष ईस्ट इंडिया कम्पनी के निदेशकों के प्रतिनिधि होते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सहायता से कार्य करता था। इस अधिनियम में भारतीय जनता के दृष्टिकोणों और सुझावों को कोई स्थान नहीं था।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861—इस अधिनियम में लोक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का नाममात्र का समावेश किया गया था। मुख्यतः यह अधिनियम भारत के साँवैधानिक विकास में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है—(i) कानून बनाने के कार्य में भारतीयों का सहयोग लेना प्रारम्भ किया गया। (ii) राष्ट्रीय विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय स्वायत्तता तथा गवर्नर जनरल को विधान सभा में भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी।

भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के मुख्य बिन्दु हैं—(i) भारतीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया, किन्तु गैर सरकारी सदस्य कुछ स्थानीय निकायों द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने लगे। ये स्थानीय निकाय थे—विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगरपालिका। (ii) परिषदों को बजट पर विचार विमर्श करने की और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। यद्यपि इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली तथा इसमें अनेक त्रुटियाँ थीं। निर्वाचन की पद्धति अन्यायपूर्ण थी, अतः वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे तथा सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाएँ निरन्तर विकसित हो रही थी, फलतः राष्ट्रवादी 1892 के अधिनियम से पूर्णतः असन्तुष्ट थे। विधान परिषदों में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के बहुमत और बजट पर मतदान करने के अधिकार की माँग कर रहे थे।

जॉन मार्टे मिण्टो सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम, 1909—नवम्बर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिण्टो भारत के वायसराय नियुक्त हुए और जॉन मार्टे भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाये गये। मार्टे उदारवादी थे और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। इनके द्वारा किये गये सुधारों को मार्टे मिण्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्टे मिण्टो के सुधारों द्वारा प्रतिनिधित्व और निर्वाचित तत्व का समावेश करने का प्रयत्न किया गया। केन्द्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी जिससे परिषद की कुल सदस्य संख्या 69 हो गयी। इनमें आठ 32 गैर सरकारी सदस्य तथा 37 सरकारी सदस्य थे जिनमें से 28 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और शेष 9 पदेन सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। 27 निर्वाचित सदस्यों को कर्जों, हितों और ब्रेजियों के आधार पर मनोनीत किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। अधिनियम ने सदस्यों को अवसर दिया कि वे बजट या लोकहित के किसी विषय पर सार्वजनिक प्रस्तावित करके प्रशासन

को नीति पर प्रभाव डाल सके। सरासरी बन् विदेश कार्य और देशों रिपब्लिकें अदि विषय इसके बहर था। 1909 के अधिनियम में निर्वाचन को जो पद्धति अपनाई गई उसमें एक बहुत बड़ा दोष था। इसमें प्रथम बार मुनिमन मसुदाय के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी थी। इसी से भारत में पृथक्तावाद का बीज बोणा हुआ जिसकी परिणति देश के दुखद विभाजन में हुई।

मॉन्टेग्यू स्टार भारतियों को उदारदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना की माँग पूर्ण नहीं कर सका। परिणामस्वरूप विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध आन्दोलन तेज गति से बढ़ने लगा। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीयों का महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया, अतः अब अंग्रेजों के लिए कमिशन की माँग के प्रति उदासीन रहना दुष्कर हो गया। परिणामस्वरूप 1917 में भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू ने भारत में अधिक सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की कि पश्चिम में प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा किन्ति ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में उदारदायित्वपूर्ण शासन का विकास होता रहे। इस घोषणा के बाद व भारत की राजनैतिक स्थिति की राई के लिए भारत आये, परिणामस्वरूप 1918 में एक रिपोर्ट प्रकटित की जा चम्पसार्ड कमेन्स कहलाई। रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सदन में एक विधेयक तैयार किया गया जो भारत सरकार अधिनियम 1919 कहलाया।

मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन और भारत शासन अधिनियम 1919—मॉन्टेग्यू घोषणा भारत में सविधानवाद के विकास की महत्वपूर्ण घटना है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे—

(i) प्रान्तों में द्वैध शासन अधिनियम द्वारा उदारदायी सरकार की स्थापना का प्रयत्न किया गया। प्रयत्न के विषयों को दो भागों में बाँटा गया—केंद्रीय विषय जो केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में तथा प्रान्तीय विषय प्रान्तों के लिए। प्रान्तों को तीन वर्ग विषयों में से अन्तर्गत-विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के उदारदायी मन्त्रियों की सहायता से किया जाता था। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बड़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया। दूसरी ओर आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। इनमें विधान मंडल के प्रति कोई उदारदायी नहीं था।

(ii) भारतीय विधान मंडल को अधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाया गया। केन्द्र में उदारदायित्व की स्थापना नहीं दिया गया। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश सदन का उदारदायी बन रहा। पहली बार विधान मंडल द्विसदनीय किया गया—उच्चतर सदन जिसे राज्य परिषद का नाम दिया गया 60 सदस्यों से मिलकर बनने की जिनमें 34 निर्वाचित थे। निचले सदन में जिसे विधान सभा का नाम दिया गया 144 सदस्य थे जिनमें 104 निर्वाचित थे, 40 नवांकित किये जाते थे। महाधिका और अधिकार अत्यन्त सीमित एवं सुकुचित थे। महाधिका की अर्हता सम्पत्ति के अधिका पर निर्धारित की जाती थी। सिखा को न महाधिका प्राप्त था और न वे परिषदों की सदस्य बन सकती थी।

केंद्रीय विधान मंडल के दोनों सदनों की समान अधिकार प्राप्त थे। वे केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकते थे। कुछ प्रान्तीय विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति से कानून बनने का अधिकार केंद्रीय विधान मंडल को प्राप्त था। केंद्रीय कानूनों की वीरता को न्यायमय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। केन्द्र और प्रान्तों में यदि कोई मतभेद उठता था तो गवर्नर जनरल निर्णय करता था कि अनुक विषय पर कानून बनने का अधिकार केन्द्र की है या प्रान्तों की। विरोध विषयों से सम्बन्धित विधेयक बिना उसकी अनुमति के विधानमंडल में नहीं लाये जा सकते थे। तथा अपने विरोधधिका के प्रयोग द्वारा वह किसी विधेयक को नमन कर सकता था और ऐसे किसी विधेयक को वह पस कर सकता था जिसे परिषद ने अस्वीकृत कर दिया हो। गवर्नर जनरल को आदेशपालन में आदेश देना जारी करन का अधिकार था। यह अधिनियम भारतीय नेताओं की उदारदायी सरकार की माँग को पूरा नहीं कर सका क्योंकि केंद्रीय सरकार का स्वरूप द्वायत्मक बना रहा। समूची रक्षा केन्द्र में (गवर्नर जनरल के हाथों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से जो कि ब्रिटिश सदन के प्रति उदारदायी की निर्दिष्ट थी। 1919 के अधिनियम को भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण में प्रतिनिध्यात्मक शासन के विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत बिंदु माना जाता है। इस अधिनियम ने देश में सार्वभौम शासन के स्वरूप को सार्थक और वास्तविक स्वरूप प्रदान किया।

1919 से 1935 के बीच राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रवृत्ति बढ़ती गई। राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धाराओं में कांग्रेस गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में अग्रदूत और उनके द्वारा असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन का नवीन धारा है। जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के कारण समूची देश में ब्रिटिश शासन विरोधी भावना, विद्रोह आन्दोलन, स्वतंत्र्य दन का अग्रदूत साइन कर्मास का भारत आगमन और भारतीयों द्वारा इस कर्मास के प्रतिवेदन को अस्वीकार करना, नेहरू रिपोर्ट और गेन्नेमेन सम्मेलनों की राजनीति को सन्निहित किया जा सकता है। इस घटनाक्रम का नतीजा कि ब्रिटिश सदन द्वारा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। 1919 से 1935 के बीच गांधीजी का राजनीति में अग्रदूत, जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड, विद्रोह आन्दोलन, स्वतंत्र्य दन का अग्रदूत अदि घटनाओं ने 1935 के अधिनियम की प्रवृत्ति स्पष्ट कर दी।

साइमन कमीशन (Simon Commission)

1919 के 'भारत शासन अधिनियम' की अन्तिम धारा में कहा गया था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की छानबीन के लिए ब्रिटिश संसद दस वर्ष बाद एक 'शाही आयोग' नियुक्ति होगी। इसके अनुसार नवम्बर, 1927 में ब्रिटिश संसद के द्वारा सन जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसे 'साइमन कमीशन' कहा जाता है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था इसलिए भारत में इसका बहिष्कार किया गया। 7 फरवरी, 1928 को आयोग के मुम्बई उतरने से लेकर जब तक आयोग भारत में रहा उसका सभी जगह हड़तालों, बाले झण्डों और साइमन वापस जाओ' के नारों से स्वागत हुआ। जब यह लाहौर पहुँच घाँसाला लाजपतराय ने एक विराल विरोध जुतूस निकाला। अंग्रेज पुलिस अधिकारी साइड्स ने लाठी चार्ज कराया। लाला लाजपतराय लाठी लागने से गम्भीर रूप से घायल हो गए परिणामस्वरूप उनका देहान्त हो गया।

साइमन रिपोर्ट

मिस विलकिन्सन के अनुसार, "जलियावाला बाग की दुखान्त घटना के परभाव सम्पूर्ण देश में जितनी इस कमीशन की निन्दा हुई, उतनी अंग्रेजों के और किसी काम की नहीं हुई।" इस व्यापक विरोध के होते हुए कमीशन ने दो बार भारत का दौरा किया। इस कमीशन की रिपोर्ट मई, 1930 में प्रकाशित हुई जिसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं—

(1) प्रान्तों में द्वैध शासन की समाप्ति—कमीशन की सिफारिश थी कि प्रान्तों में द्वैध शासन को समाप्त करके, वहाँ उदारवादी शासन स्थापित किया जाए।

(2) केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं—कमीशन ने केन्द्र के शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन न करने की सिफारिश की।

(3) संघ शासन की स्थापना—इस कमीशन ने यह सिफारिश की कि भारत में संघ शासन की स्थापना की जाए।

(4) अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की विशेष शक्ति—साइमन कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए गवर्नरों व गवर्नर जनरल के लिए विशेष शक्तियाँ दी जाएँ।

(5) मताधिकार का विस्तार—साइमन कमीशन की रिपोर्ट में मताधिकार के विस्तार की सिफारिश की गई। अब तक 2.8 प्रतिशत जनता को मताधिकार प्राप्त था। अब 10 से 15 प्रतिशत जनता को मताधिकार देने की सिफारिश की गई।

(6) बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना—साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संघ की स्थापना से पूर्व भारत में एक 'बृहत्तर भारतीय परिषद' की स्थापना की जाए, जिसमें भारत के प्रांतों और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। इस परिषद के माध्यम से प्रान्त एवं रियासतों को अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करने की सुविधा दी जाए।

(7) प्रान्तीय विधानमण्डलों की सदस्य संख्या में वृद्धि—कमीशन ने प्रान्तीय विधान मण्डलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की सिफारिश की तथा कहा गया कि सरकारी सदस्यों की व्यवस्था समाप्त की जाए।

(8) बर्मा भारत से पृथक्—इस कमीशन ने बर्मा को भारत से अलग करने का सुझाव दिया।

(9) कमीशन की नियुक्ति की समाप्ति—साइमन कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 1919 के अधिनियम की प्रति 10 वर्ष बाद जाँच-पड़ताल के लिए कमीशन की नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त की जाए तथा नया संविधान ऐसा मनोला बनाया जाए कि वह स्वयं ही विकसित होता रहे।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट का मूल्यांकन—भारतवासियों ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिसके प्रमुख कारण निम्नांकित थे—(1) भारतीयों की औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग पूरी नहीं हुई थी। (2) केन्द्र में पूर्ण की नीति ही अनुत्तरदायी शासन की सिफारिश की गई थी। (3) यद्यपि प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की सिफारिश की गई थी किन्तु गवर्नरों को विशेष शक्तियाँ देने की सिफारिश की गई थी।

फलस्वरूप भारतीयों ने साइमन कमीशन रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। सर शिवा स्वामी अय्यर के अनुसार, "आयोग की रिपोर्ट रही की टोकरी में फेंक देने योग्य थी।" एडवूज ने इस रिपोर्ट को निन्दा करते हुए कहा था कि "आयोग ने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन से समस्त देश में उत्पन्न हुए परिवर्तन और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ण उपेक्षा की। आयोग ने उस भारत को अपने समक्ष रखा जो राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भ होने से 30 वर्ष पहले था। राष्ट्रीय जागृति के फलस्वरूप उदीयमान युवक भारत का हममें परिचय नहीं मिलता।"

भारतीय शासन अधिनियम 1935—1935 के अधिनियम में मुसलमानों के अतिरिक्त सिक्खों यूरोपीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन लोगों के लिए भी धुक्क प्रतिनिधित्व था। इसके कारण राष्ट्रीय एकता के निर्माण में गम्भीर बाधाएं उपस्थित हुई। 1935 के अधिनियम के मुख्य संघर्ष निम्नांकित थे—

(1) संघात्मक व्यवस्था और प्रान्तीय स्वायत्तता—इस अधिनियम में संघात्मक शासन की स्थापना की गई जिसमें इकाइयों प्रान्त और देशी रियासतें थीं। देशी रियासतों के लिए परिभाषा में सम्मिलित होने का विकल्प था परन्तु देशी रियासतों के शासकों ने अपनी सहमति नहीं दी थी। 1935 के अधिनियम में जिस संघात्मक शासन की व्यवस्था थी वह

नहीं बन सकी। यद्यपि सप्ताम्यक शासन से सम्बन्धित भाग निष्पत्ती रहे, तथापि प्रान्तीय स्वायत्तता से सम्बन्धित भाग को भारत के लिए 1937 में प्रभावी किया गया। इस अधिनियम ने विधायी शक्तियों को प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान मण्डलों के बीच विभाजित किया। गवर्नर सम्राट की ओर से प्रान्त की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता था। वह गवर्नर जनरल के अधीन नहीं था। गवर्नर से यह अपेक्षा थी कि वह मन्त्रियों की सलाह से काम करेगा और मंत्री विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी थे, परन्तु कुछ विषयों में गवर्नर की स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति थी। ऐसे विषयों में गवर्नर मन्त्रिमण्डल की सलाह के बिना कार्य करता था।

(ii) केन्द्र में द्वैध शासन—केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी जिसके कार्यों को दो समूहों में बाँटा गया था—

(अ) प्रतिरक्षा, विदेश कार्य, चर्य और जनश्रमिक क्षेत्रों का प्रशासन गवर्नर जनरल की स्वविवेकानुसार और अपने द्वारा नियुक्त पदमार्शदाताओं की सहायता से करना था। ये पदमार्शदाता विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थे।

(ब) आरक्षित विषयों से भिन्न विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल को मन्त्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करना था। मन्त्रिपरिषद् विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थी, किन्तु इन विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष उत्तरदायित्व निहित था। गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नियन्त्रण और निर्देश के अधीन कार्य करता था।

विधायी शक्तियों का विभाजन—1935 के अधिनियम की विधायी शक्तियों को केन्द्र और प्रान्तीय विधान मण्डलों में निम्नांकित प्रकार से विभाजित किया गया था—

(I) सशोध सूची—सशोध सूची पर सशोध विधान मण्डल को विधान बनाने की शक्ति थी। जैसे—विदेश कार्य, कोरसी और मुद्रा, नौ सेना, दल सेना और वायु सेना, जनगणना आदि।

(II) प्रान्तीय सूची—जिस पर प्रान्तीय विधान मण्डलों की अधिकारिता थी। जैसे—गुनिस, प्रान्तीय नोकसेवा और शिक्षा।

(III) समवर्ती सूची—समवर्ती सूची पर प्रान्तीय और सशोध विधान मण्डलों को समान रूप से अधिकार था। जैसे—दण्ड और विधि एवं उसकी प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद।

गवर्नर जनरल द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसर विधानमण्डल को प्रान्तीय सूची में वर्णित विषयों पर विधान बनाने की शक्ति प्राप्त थी। सशोध विधान मण्डल उस परिस्थिति में प्रान्तीय सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति रखता था जब दो या अधिक विधान मण्डल अपने सामान्य हित में ऐसा किये जाने की इच्छा प्रकट करते थे। इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियों का आवंटन महत्वपूर्ण था। वह न सशोध विधान मण्डल में निहित था और न प्रान्तीय विधान मण्डल में। गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई थी कि वह परिसर या प्रान्तीय विधान मण्डल को किसी ऐसे विषय में विधि अधिनियम करने के लिए प्राधिकृत करे जो विधायी सूची में नहीं है। यह अधिनियम जिस प्रान्तीय स्वायत्तता की परिकल्पना पर आधारित था वह व्यवहार में क्रियन्वित किया गया। 1937 में प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचन सम्पन्न हुए। 11 प्रान्तों में हुए चुनाव में 6 प्रान्तों में कॉंग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। ये प्रान्त थे—मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, चेन्नई और मद्रास प्रान्त। आसाम, बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में कॉंग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में ठपर कर सामने आई। बंगाल, पंजाब और सिन्ध में मुस्लिम लीग के मन्त्रिमण्डल सत्तारूढ़ हुए। इन मन्त्रिमण्डलों ने उल्लेखनीय जन-कल्याणकारी कार्य किये। प्रान्तीय स्वायत्तता के इस व्यावहारिक परीक्षण के कारण कॉंग्रेस मन्त्रिमण्डलों को जनता में प्रतिष्ठा स्थापित हुई। भारतीय नेताओं की प्रशासनिक कार्यों के संवादन का अनुभव प्राप्त हुआ तथा यह प्रमाणित हो गया कि भारतीयों में वंछित प्रशासनिक क्षमता है। प्रान्तीय स्वायत्तता के इस परीक्षण ने भारत में सशानक व्यवस्था की बुनियाद को सशपागत और प्रक्रियागत स्वरूप प्रदान किया। परिणामस्वरूप प्रान्तीय स्वायत्तता से पूर्ण स्वायत्त तक भारत में सशैधानिक विकास के विभिन्न आयाम जुड़ते चले गये। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन से यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत को पण्डीन नहीं रखा जा सकता है फिर भी अन्तिम अन्तिम धन तक देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कृत शक्य है। इस परिदृश्य में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए विभिन्न सशैधानिक सुधारों की योजनाएँ प्रस्तुत की, उनमें मुख्य हैं—1. अगस्त योजना, 1940 (The August Offer, 1940); 2. क्रिप्स प्रस्ताव योजना, 1942 (The Cripps Proposals, 1942); 3. वेवल योजना, 1945 (Wavell Plan, 1945); 4. कैबिनेट मिशन योजना, 1946 (The Cabinet Mission's Plan, 1946); 5. माउन्टबेट्टन योजना, 1947 (The Mountbatten Plan, 1947)।

क्रिप्स मिशन

(Cripps Mission)

प्रधान विरयमुक्त में जापान की निरन्तर विजय ने और निर्य चट्टों की विगड़ती स्थिति ने पश्चिम की सरकार को भारत के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए विवश कर दिया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए 11 मार्च, 1942 को ब्रिटिश कॉमन लया में योजना की कि वे सर स्टेनोर्ड क्रिप्स को भारत भेज रहे हैं। इस योजना के अनुसार 22 मार्च, 1942 को क्रिप्स भारत आये।

अंग्रेज सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के निम्नांकित कारण थे—

- (1) अंग्रेजों को जापान से खतरा था। जापानी सेनाएँ फिलीपींस, मलयया, इण्डोनेशिया, इण्डोचाइना, सिंगापुर को विजय कर बर्मा को रौंदती हुई भारत की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी थी।
- (2) भारत की राजनीतिक गुल्मी को सुस्तवाने के लिए इम्पैण्ड या मित्र राष्टों का भारी दबाव था।
- (3) ब्रिटिश संसद एवं जनता भारत की स्वतन्त्रता का समर्थन कर रही थी।
- (4) महात्मा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह मत व्यक्त किया कि भारत मुद्र में उसी स्थिति में सहयोग करेगा जब उसे स्वतन्त्रता की घोषणा का आवासन मिले।
- (5) माइकेल बेयर के अनुसार क्रिप्स मिशन का भारत आने का कारण महात्मा गाँधी का सत्याग्रह आन्दोलन था।

क्रिप्स योजना के मुख्य बिन्दु

उन्होंने अपने 20 दिन के प्रवास के दौरान कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, उन्नावदी दलित वर्ग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से बैठ की। इसके पश्चात् उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे जिन्हें क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) मुद्र के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव एवं (2) तुरन्त लागू होने वाले प्रस्ताव।

(अ) मुद्र के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव—(1) उपनिवेश अथवा अधिपत्य की स्थापना, (2) संविधान सभा की स्थापना, (3) संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व, (4) संविधान सभा का गठन, (5) भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच कुछ विषयों पर संधि, (6) प्रान्तों एवं देशी रियासतों को पुष्क संविधान बनाने का अधिकार एवं (7) राष्ट्रमण्डल से पृथक् होने का अधिकार।

(ब) तुरन्त लागू होने वाले प्रस्ताव—(1) मुद्रकाल में भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा एवं (2) प्रस्तावों तन्त्र की कार्य भारतीयों के सहयोग से हो सकेंगे।

क्रिप्स प्रस्तावों का मूल्यांकन

क्रिप्स प्रस्ताव अगस्त, 1940 के प्रस्तावों से अच्छे थे, किन्तु वे भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सके। प्रस्तावों को लेकर जब क्रिप्स महात्मा गाँधी से मिले तो उनकी प्रतिक्रिया थी—“यदि आपके पास यही प्रस्ताव थे तो आपने आने का कष्ट क्यों उठाया। यदि भारत के सम्मन्ध में आपकी यही योजना है, तो मैं आपको परामर्श दूँगा कि आप अगले हवाई जहाज से इंग्लैण्ड सीट जाएँ।” कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया तथा 11 अप्रैल, 1942 को ब्रिटिश सरकार ने इन प्रस्तावों को वापस ले लिया।

अन्ततः ब्रिटिश संसद द्वारा माउण्टबेटन योजना के अनुसार जुलाई, 1947 में भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य देश का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना करना था। भारत में संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण करने के दायित्व का निर्वाह किया गया। संविधान सभा ने देश के लिए उदार लोकतांत्रिक प्रतिमान (Liberal Democratic Model) स्वीकार किया। इसके लिए देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश उत्तरदायी है। यह सांविधानिक विकास उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सूरपात करने में सहायक बना। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने जिरा उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया।

इसकी जड़ें इस विकास-क्रम में समाहित हैं।

भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति—लॉर्ड माउण्ट बेटन की योजना को स्वीकार कर लेने के बाद सन्दा सरकार ने 4 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक लोकसभा में पेश किया और 15 दिन के अन्दर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। इस भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 (The Indian Independence Act, 1947) में 15 धाराएँ थीं। यह अधिनियम एक नवीन युग के आरम्भ का सूचक था। इस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। लॉर्ड माउण्ट बेटन ने 13 अगस्त, 1947 को कराची जाकर पाकिस्तान संविधान सभा को सत्ता सौंपी और 14 अगस्त की मध्य रात्रि को सन्देशों के माध्यम से भारत को सत्ता हस्तान्तरण हुआ। डॉमिनियन मंत्रिमण्डल के प्रधानमन्त्री नेहरू के नेतृत्व में 14 मन्त्री नियुक्त हुए और लॉर्ड माउण्ट बेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।

भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947

(Indian Independence Act, 1947)

4 जुलाई, 1947 को ब्रिटेन की सरकार ने भारत को स्वतन्त्र करने के लिए एक विधेयक वहाँ के निजले सदन “हाउस ऑफ कॉमन्स” में रखा और पास कराया। 6 जुलाई, 1947 को यह विधेयक वहाँ के उच्च सदन “हाउस ऑफ लॉर्ड्स” में पास हुआ और यह विधेयक “भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947” बना।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम की प्रमुख धाराएँ—16 जुलाई, 1947 को पारित 'भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम' की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं—

1. 15 अगस्त, 1947 को भारत दो स्वतन्त्र अधिराज्यों—भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। उत्तरी पूर्वी सीमा प्रान्त असम का सिलहट जिला बलुचिस्तान, सिन्ध और पश्चिमी पंजाब का भाग पाकिस्तान अधिराज्य कहलाएगा और बाक़ों भारतीय भू-भाग भारत कहलाएगा।

2. 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतन्त्रता के लिए 'भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम' लागू होगा।

3. पन्द्रह अगस्त, 1947 के बाद ब्रिटेन की सरकार का दोनों राज्यों, उनके प्रान्तों के क्रिमी भाग पर कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा।

4. दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाएँ अपना संविधान बनाने के लिए स्वतन्त्र होगी। दोनों की यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि उनके देश राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना चाहते हैं अथवा नहीं।

5. नये संविधान की रचना तक दोनों अधिराज्यों में शासन का संचालन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार होगा, किन्तु आवश्यकतानुसार दोनों अधिराज्य उसमें संशोधन करने के लिए स्वतन्त्र होंगे तथा अपने राज्य के लिए कानून बनाने के मामले में स्वतन्त्र होंगे।

6. 15 अगस्त, 1947 से ब्रिटेन की सरकार का 'भारत सचिव' का पद समाप्त कर दिया जाएगा तथा 'इंडिया ऑफिस' को बन्द कर दिया जाएगा।

7. 15 अगस्त, 1947 से ब्रिटेन के सम्राट की 'भारत सम्राट' पदवी समाप्त हो जाएगी।

8. 15 अगस्त, 1947 से भारत के देशी राज्यों से ब्रिटेन के सम्राट की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाएगी तथा ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत के देशी राज्यों के साथ की गई सन्धिपत्रा स्वतन्त्र समाप्त हो जाएंगी। देशी राज्यों की भारत अथवा पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता होगी।

9. ब्रिटेन का सम्राट दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा जिसकी नियुक्ति उनके (अधिराज्यों के) मंत्रिमण्डलों के परामर्श से होगी।

भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 के अनुसार भारत के स्वाधीन होने के पश्चात् नवीन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी, 1950 से इस नवीन संविधान के अनुसार देश का शासन-संचालन होने लगा। भारत के विभाजन के कारण

1. **मुसलमानों में पृथक्ता की भावना का उदय**—कुछ मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में आकर मुसलमान हिन्दुओं से अलग ढंग से सोचने लगे। सैयद अहमद खाँ ने इस पृथक्तावादी प्रवृत्ति को बहुत प्रोत्साहित किया। देश के मुसलमानों में यह भावना घर दी गई कि उनके और हिन्दुओं के हित पृथक्-पृथक् हैं।

2. **बहुसंख्यक हिन्दुओं के हावी होने का घप पैदा होना**—मुस्लिम लीग और कट्टर एवं पृथक्तावादी मुस्लिम नेताओं के प्रभाव से मुसलमानों में यह विश्वास जन्म गया कि यदि भारत को उन्नतवादी शासन दिया गया ठां बहुसंख्यक हिन्दु अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हावी हो जाएंगे।

3. **मुसलमानों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का घप**—मुसलमानों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि शिक्षा की दृष्टि से मुस्लिम जनता पिछड़ी हुई है, अतः वह हिन्दुओं से स्पष्ट नहीं कर सकेगी। इस कारण मुसलमान हिन्दुओं से दूर होते चले गए।

4. **जिन्ना का द्विष्ट सिद्धान्त**—1940 में मुहम्मद अली जिन्ना ने द्विष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। अब मुसलमान इस पर अड़े हुए थे कि उनका अपना अलग देश होना चाहिए।

5. **ब्रिटिश सरकार की 'फूट डालो' नीति और मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन**—ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम धीति-नीति को प्रोत्साहन दिया। 'फूट डालो और शासन करो' की नीति का अनुसरण कर ब्रिटिश सरकार ने अन्य सम्प्रदायों को हानि पहुँचाकर मुसलमानों का पक्ष लिया। मुस्लिम जनता की प्रसन्नता के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। 1909 में मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया। विधान मण्डलों में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया और हिन्दुओं को कमिल एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए। इससे हिन्दुओं और मुसलमानों में मतभेदों की खाई भीड़ी होती गई। ब्रिटिश मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए रिश्वतें पेश करती रही। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न कर दीं कि भारत के मुसलमान अपनी प्रत्येक बात के लिए

ब्रिटिश सरकार पर निर्भर हो गए। उन्हें कांग्रेस अपना हिन्दुओं से सम्झौता करने में कोई हथि नहीं रही। 1946 और 1947 में मुस्लिम लीग के आन्दोलन में ब्रिटिश नौकरशाही ने सक्षिप्त सहायता दी। हिन्दुओं के प्रदर्शन पर उनका दमन किया गया जबकि मुस्लिम लीग बिना सरकारी दमन के अपने उग्र और हिंसक प्रदर्शन करती रही।

6. मुसलमानों के प्रति कांग्रेस की दृष्टिकोण की नीति—कांग्रेस ने मुसलमानों को दुरा करने का रीतिया अपनाया और उन्हें अपने अनुचित शोषों बढ़ाने को प्रोत्साहन दिया। मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की प्रबल भावना से कांग्रेस ने अनेक बार अपने सिद्धान्तों को तिलाजलि दे दी। साम्प्रदायिक रोग अत्यधिक बढ़ गया। अन्ततः भारत का विभाजन हो गया। कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक्तावादी और आक्रामक स्वरूप को समझने की चेष्टा नही की और यह साचा कि साम्प्रदायिक समस्या अचानक दूर हो जाएगी।

कांग्रेस ने स्वयं को धोखा देने की गतती की। कांग्रेस ने कई गतत कदम उठाए। पहली गतत 1916 में लखनऊ पैक्ट में सम्मिलित होने की की गई। इसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन की माँग स्वीकार कर ली। विधान-मण्डलों में मुसलमानों को एक निश्चित अनुपात में स्थान देने की बात स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दूसरी गतत 1932 के साम्प्रदायिक निर्णय के बारे में हुई। कांग्रेस की नीति से मुसलमानों की पृथक्तावादी प्रवृत्ति को बल मिला। एक गतत यह भी कि मुस्लिम लीग को सविधान-समझ में भाग लेने के लिए सहमत किए बिना अन्तरिम सरकार में सम्मिलित कर लिया गया। अन्तरिम सरकार के, सीपीएम सदस्यों ने अङ्गरेजानी की नीति अपनाई जिससे पाकिस्तान स्थापित किए जाने के कटावरण को बल मिला। अन्तरिम सरकार के सीपीएम सदस्यों ने अपने विभागों के महत्वपूर्ण पदों से हिन्दुओं और सिक्ख अधिकारियों को हटाकर ऐसे मुसलमानों को नियुक्त कर दिया जिन पर पाकिस्तान के पक्ष में चिलाने का प्रयत्न किया जा सकता था।

7. साम्प्रदायिक झगड़े—अन्तरिम सरकार के समय विशाल पैमाने पर साम्प्रदायिक उपद्रव हुए, अतः कांग्रेस कार्य-समिति विवश हो गई कि वह भारत-विभाजन की दृष्टि से बिचार करे। फरवरी, 1947 में ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा ने कि भारतीयों को शोध सत्ता सौंपने का निश्चय कर लिया गया है, देश की साम्प्रदायिक स्थिति को बिगाड़ दिया। इस घोषणा से पाकिस्तान निर्माण के आन्दोलन को सहायता मिली।

8. कांग्रेस की भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा—देश के साम्प्रदायिक और राजनीतिक कटावरण से बाध्य होकर मई 1947 में कांग्रेस ने अनुभव किया कि भारत का विभाजन होना आवश्यक है। सरदार पटेल के शब्दों में "मैंने यह अनुभव किया कि यदि हम विभाजन को स्वीकार न करते तो भारत अनेक टुकड़ों में बँट जाता और बर्बाद हो जाता। एक वर्ष पदारीन रहने पर मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय हो गया कि जिस मार्ग पर हम जा रहे थे वह विनाश की ओर ले जा रहा था। मैंने अनुभव किया कि हमारे देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे तथा प्रत्येक दफ्तर में पाकिस्तानी सैल होंगे। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि देश का विभाजन कर इन विदेशियों का यहाँ से शीघ्रतरी शोध चले जाना श्रेयस्कर है। मैंने यह अनुभव किया कि देश को सुपक्षित और समृद्ध बनाने का हल यही है कि शोध भारत को एक कर दिया जाए।"

9. अखण्ड भारत के लिए पाकिस्तान—अनेक नेत्रों का विचार था कि राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सैनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान एक कमजोर राष्ट्र सिद्ध होगा और विषय परिस्थितियों तथा आन्तरिक कमजोरियों के कारण नहीं टिक सकेगा। उन्हें भ्रम था कि अन्त में पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा और भारत एक हो जाएगा। आचार्य कृपलानी ने कहा था—“एक दृढ़ और सुखी प्रजातान्त्रिक भारत अलग होने वाले भाग को वापिस ले सकता है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता भारत की एकता के बिना पूर्ण नहीं हो सकती।” इस प्रकार की विचारापार ने तात्कालीन परिस्थितियों में भारत के विभाजन का प्रोत्साहित किया।

10. सत्ता हस्तान्तरण की शर्त—ब्रिटिश प्रधानमंत्री हटली द्वारा 20 फरवरी, 1947 को यह घोषणा की गई कि एक निश्चित तिथि तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। इस घोषणा से भारतीय नेताओं को भय हो गया कि यदि भारत विभाजन न हुआ तो सत्ता-हस्तान्तरण के समय गृह-युद्ध छिड़ सकता है और देश दो से अधिक टुकड़ों में बँट सकता है। यह आशंका थी कि यदि भारत-विभाजन के माउण्ट बैटन फार्मले को स्वीकार न किया गया तो ब्रिटिश सरकार अपना निर्णय भारतीयों पर लाद देगी जो अधिक हानिकारक सिद्ध होगा।

11. सत्ता का सारलच—माइकेल नेवर का विचार था कि कांग्रेसी नेता 1935 के सविधान के अन्तर्गत सत्ता अनुभव कर चुके थे और शीघ्रतरी सत्ता हथियाने के पक्ष में थे अब उन्होंने भारत के विभाजन को अधिक टाटला उचित नहीं समझा।

12. माउण्ट बैटन का प्रभाव—भारत के विभाजन को मनवाने में माउण्ट बैटन दम्पति का व्यक्तिगत प्रभाव सर्वाधिक रहा। माउण्ट बैटन का विचार था कि देश के विभाजन की कोमत पर भारतीयों को आजादी से लेनी चाहिए और यह अपेक्षा के लिए हितकारी होगा। उनकी व्यावहारिक राजनीतिक चतुराई, प्रशासनिक निपुणता और धिनय व्यवहार ने भारतीयों की प नेहरू आदि नेताओं के हृदय को जीत लिया। श्रीमती माउण्ट बैटन की बुद्धिमत्ता, चतुराई नेहरू और गाँधी के प्रति उनकी सम्पणशीलता और आकर्षक स्वभाव ने भारत विभाजन में मुख्य भूमिका निभाई।

उपयुक्त सभी भूतों, प्रभावों और विषय परिस्थितियों ने कर्म्मिस के सामने यह समस्या उत्पन्न हो दी कि तो युगद्वयों में से एक को चुन लिया जाए अर्थात् या तो सारे देश पर मुस्लिम आधिपत्य हो जाए या भारत-भूमि का विभाजन हो जाए। कर्म्मिस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया।

भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति में सहायक तत्त्व—भारत का विभाजन जब कर्म्मिस को मान्य हो गया तो इसे मूर्त रूप देने के लिए जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम (The Indian independence Act, 1947) पारित कर दिया गया जिसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश राज का अन्त हो गया और भारत तथा पाकिस्तान दो अधिराज्यों की स्थापना हो गई, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार दिया गया।

1. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति—भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन उपजाऊ, अग्निज्वाली और वैश्वनरूप लिए हुए था। सभी जातियों और वर्गों ने एक स्वर से स्वतन्त्र भारत का नारा लगाया था। 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ने की चुनौती थी। आज़ाद हिन्द फौज और मैनिफेस्ट विरोध ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ें हिला दी थीं। महापुरुष के बाद स्वतन्त्रता के बारे में भारतीयों का नारा हो गया था—'अभी नहीं हाँ बल्कि नहीं' (Now or Never)। इन परिस्थितियों में अंग्रेज यह समझ गए थे कि भारतीयों को स्वतन्त्रता देनी होगी।

2. महापुरुष के कारण ब्रिटेन का निर्बल हो जाना—द्वितीय महापुरुष के परिणामस्वरूप ब्रिटेन राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर हो गया था कि उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह भारतीय साम्राज्य का भार वहन करता तथा भारत को बनपूर्वक अपने अधीन रख सकता।

3. एशिया में जागरण—एशिया में जो स्वतन्त्रता आन्दोलन चल रहे थे, उनका भारत पर प्रभाव पड़ा था। राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत एशियाई राष्ट्रों में भारत अग्रणी था। एशिया के इस राष्ट्रीय जागरण ने ब्रिटेन को विवश कर दिया कि वह भारत को स्वतन्त्र कर दे।

4. ब्रिटेन में मजदूर हनीय सरकार का निर्माण—1945 के आम चुनावों में विजय प्राप्त कर मजदूर दल द्वारा सरकार का निर्माण महत्वपूर्ण घटना थी। मजदूर दल पहले ही घोषणा कर चुका था कि सनातन होने ही वह भारतीय सार्वजनिक गतिरोध को दूर कर, भारतीयों को स्वतन्त्रता प्रदान करेगा। मजदूर दल ने अपनी बात निभाई। मौलाना आज़ाद के शब्दों में भारत को तेज़ी से और सौम्यपूर्ण तरीक़ों से अंग्रेजों द्वारा छोड़ने के लिए मजदूर सरकार बर्माई की पात्र थी।

5. अन्तर्राष्ट्रीय दबाव—ब्रिटेन पर भारत को स्वतन्त्र करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दबाव सहायक सिद्ध हुए। 'ब्रिटेन और जर्मनी को सहन नहीं था कि पण्डित के बच्चे उनके उपनिवेश छीन लिए जाएँ और अंग्रेज अपने उपनिवेश कायम रखें। इसके अतिरिक्त अमेरिका भारत को स्वतन्त्रता देने के लिए आग्रह कर रहा था। नम अंग्रेजों के उपनिवेशवाद का घोर विरोध था। सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि "अमेरिका और नम जैसी अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ के दबाव के कारण भारत पर आधिपत्य कायम रखना असम्भव हो गया है।" चीन भी भारतीय स्वतन्त्रता का समर्थक था।

6. भारतीय शासन अनाप्तकारी—द्वितीय महापुरुष तक भारत औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर चुका था और युद्ध के बाद इंग्लैण्ड भारत को अधीन रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं था। इस समय तक इंग्लैण्ड से भारत में आयात घट गया था। अंग्रेजों ने आर्थिक लाभ के लिए भारत पर आधिपत्य स्थापित किया था और अब आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने भारत को छोड़ देना उपयुक्त समझा।

7. साम्यवाद का भय—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रगति करने और राष्ट्रवाद को बसाने का कार्य सम्पन्न किया गया। देश के सर्वोत्तम विचारों के लिए पञ्चवर्षीय योजनाओं का शुभारम्भ किया गया। साम्यवाद पर जनता का विश्वास नहीं था, पाल्मु स्वतन्त्रता प्राप्ति में कर्म्मिस की विफलता से जनता साम्यवाद की तरफ झुकने लगी थी। यह स्थिति लोकतन्त्र के लिए भारत की और अंग्रेजों के भय का बड़े पैमाने पर हस्तान्तरण स्रोत नहीं दिया तो भारत में साम्यवाद तेज़ी से फैलेगा। अंग्रेज जितने समय अधिराज्यत्व (Paramountacy) केन्द्रीय सरकार को नहीं दे पाए, अन्य देशों रियासतों ने स्वतन्त्र रहने की आकांक्षा को भारत की राजनैतिक एकता में गड़बड़ पैदा कर दिया, मैक्सवेल-तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ज़ोरूँ से उन्हें भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास के लिए राजी कर लिया। देशों रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया और देश की एकता को रक्षित किया गया।

8. ब्रिटिश राज्य और भारतीय राष्ट्रीय कर्म्मिस की देन—ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत जाने-अनजाने में ऐसे कार्य हुए जो भारत की स्वतन्त्रता के लिए ठोसतापी थे—जैसे प्रशासकीय एकता, सहायक और सहायक के सार्वजनिक विकास, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का विकास आदि। दूसरी ओर कर्म्मिस ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रतिकार और सक्रिय बना दिया था।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Indian Constitution)

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दार्शनिक मान्यताएँ (Philosophical Postulates of Indian Political System)

संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में भारत के उदारवादी दार्शनिक दृष्टिकोण और मान्यताओं को स्थान दिया है। संविधान में समहित मुख्य दार्शनिक मान्यताएँ निम्नांकित हैं—

1 यह निश्चय दिया गया कि भारतीय सभ एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता सम्बन्धी उपबन्ध धर्म-निरपेक्ष राज्य की आधारशिला है। धर्म-निरपेक्ष राज्य अधार्मिक या धर्म विरोधी न होकर विभिन्न धर्मों के मध्य तटस्थ होता है और उसकी किसी धर्म विशेष में आस्था नहीं होती। वह किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता और किसी भी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता।

2. संविधान ने जाँह, सम्प्रदाय, मूल वंश अथवा लिंग के भेदभाव के बिना सभी भारतीयों के लिए समता का प्रतिपादन किया है। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में समता अथवा 'समता—सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक नहीं केवल बल्कि स्थान और अवसर की समता पर बल दिया है।

3 संविधान-सभा ने राज्य रूपी सत्य की रचना करते समय सार्वभौम लोकतन्त्र का प्रतिपादन किया। देश में सार्वभौम राजनीतिक व्यवस्था ने अपनी सार्वभौमता और सफलता सिद्ध की है।

4 भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त हैं—बहुता और राष्ट्रीय एकता के मूल्य। भारत में विभिन्न जातों, भाषाओं, जातियों और रीति-रिवाजों के बावजूद एक युनिवर्सी एकता है और इस एकता को दृढ़ता प्रदान करना राष्ट्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। संविधान ने साम्प्रदायिक निर्वाचनों का और अस्पृश्यता का अन्त कर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एक-दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया और एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना कर देश को एकता पर बल दिया है।

5 भारतीय संविधान में फैलिबनवाद की छाप विशेष रूप से प्रस्तावना तथा नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में दिखाई देती है। प्रस्तावना नीति-निर्देशक सिद्धान्तों और सामाजिक सिद्धान्तों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है।

6 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गांधीवादी दर्शन की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। संविधान में पचासी राष्ट्र कुटीर उठाए-गये हैं जो प्रोसाहद, मन्द-विषेय और दुष्कार पशुओं की रक्षा आदि का उल्लेख है। यह गांधीवादी दर्शन की व्यवस्थापरक छाप है।

7 शांति-कल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता की स्थापना इसके मूलधार है।

(1) प्रस्तावना

(Preamble)

भारतीय संविधान की अपनी एक प्रस्तावना है जो संविधान-निर्माताओं के विचारों की कुंजी है।¹ प्रस्तावना में संविधान का सार एवं दर्शन है। प्रस्तावना में निरूपित तथ्यों, सिद्धान्तों और आदर्शों की छाप समूचे संविधान पर है और प्रस्तावना के आधार पर समूचे संविधान का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। प्रस्तावना की शब्दावली में अनेक शब्द और

पद ऐसे है जिसमें भारत की प्राचीन एवं पारंपार्य परम्पराओं के सर्वश्रेष्ठ तत्व समाहित है और जो प्रयोग की दृष्टि से सार्वभौम है। प्रस्तावना पर तीन महान् क्रान्तियों का प्रभाव पड़ा है—फ्रांसीसी, अमेरिकी, रूसी। फ्रांसीसी क्रान्ति में स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व पर, अमेरिकी क्रान्ति में राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति-स्वातंत्र्य पर और रूसी क्रान्ति में आर्थिक समानता पर बल दिया गया था। भारतीय क्रान्ति के सूत्रधारों ने इन तीनों में सम्मन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है।¹ हमारे संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है—

“हम भारत के लोग, भारत की एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक, धर्म-निरपेक्ष समाजवादी² गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता³ सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

संविधान के उपबन्धों के निर्वाचन में प्रस्तावना का महत्त्व

प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। बेहबारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ‘इन-ए-इन्टो-पाकिस्टान एग्रीमेन्ट’ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान का प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है, किन्तु उसे संविधान का आवश्यक अंग नहीं कहा जा सकता है। इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्य में अन्तर नहीं पड़ता है। यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है और न ही उस शक्ति को सन्तुष्ट करता है, किन्तु केरबानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेहबारी के मामले में द्वािर् गुरु निर्णय को बदल दिया है और यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।⁴ यदि संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो, तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की ‘अत्मा’ कहा जा सकता है।

प्रस्तावना की व्याख्या

‘हम भारत के लोग’—इन शब्दों में संविधान के निर्माताओं के अनुसार अन्तः शक्ति जनता में निहित है। सरकार की राज्यसत्ता के विभिन्न अंगों में जो शक्तिवाँटी है, वे सब जनता से मिलती हैं। संविधान जनता के अधिकार पर आधारित है। ‘हम भारत के लोग’ से तात्पर्य है संविधान का निर्माण राज्यों के लोगों ने नहीं किया बल्कि समूचे भारत के लोगों ने अपनी सामूहिक क्षमता से किया है इसलिये संविधानिक दृष्टि से न कोई राज्य अथवा राज्य-समूह हमारे संविधान का अन्त कर सकता है और न वह संविधान द्वारा निर्मित सत्ता से बाहर जा सकता है। प्रस्तावना में प्रयुक्त ‘हम’ शब्द के लोग इस संविधान की अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पदार्थनी से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात् जनता के जुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है।

‘सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न’—प्रस्तावना के ‘सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न’ पद से यह व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य है और कानूनी दृष्टि से इसके ऊपर किसी आन्तरिक शक्ति का प्रतिबन्ध नहीं है और न किसी बहरी शक्ति का। प्रस्तावना के अनुसार प्रभुत्व समूची भारतीय जनता में अथवा भारतीय गणराज्य में निहित है। आन्तरिक क्षेत्र में भारतीय सत्ता के क्षेत्राधिकार पर भारतीय जनता का प्रभुत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्रभुसत्ता का अधिप्राय है कि राज्य अन्य राज्यों के समदर्भ में पूर्ण स्वतन्त्र हैं और उसकी विदेश नीति पर कोई अंकुश नहीं है।

‘लोकतन्त्रात्मक’—भारतीय संविधान के दर्शन में लोकतन्त्र की जीवनयन्त्र की पूर्ण व्यवस्था के रूप में तथा जीवन के समस्त दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। लोकतन्त्र के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं। राजनीतिक पहलू में राजनीतिक समानता के आदर्श को माना गया है और राजनीतिक शक्ति पर किसी वर्ग-विरोध का दृष्टाधिकार स्वीकार नहीं किया है। सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतन्त्र मनुष्य में समानता का प्रतिपदन करता है। लोकतन्त्र में कोई सुविधा सम्पन्न वर्ग विशेष को नहीं हो सकती और जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, धन और निग के आधार पर व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लोकतन्त्र में आर्थिक पक्ष का अधिप्राय है कि समाज की आर्थिक शक्ति का ऐसा समानतायुक्त वितरण हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखी एवं समृद्ध हो सके, ठीके अन्विक्रम के समान अवसर मिल सकें और उसके व्यक्तिगत अधिकार एवं चुनाव में मतदान के अधिकार, उसका सम्मान और उसकी ध्वजवर्ण सुधित रह सकें। प्रस्तावना में ‘लोकतन्त्रात्मक’ शब्द ‘गणराज्य’ के विरोधा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो

1. डॉ. सुभाष काश्यप: वही, पृ. 319

2. 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा सम्शोधित।

3. बन्धुत्वपूर्ण शब्दों: वही, पृ. 36.

मरता है कि संविधान में न केवल राजनैतिक लोकतन्त्र का प्रवर्तन किया है, पर प्रस्तावना के आगे के शब्द 'न्याय', 'स्वतन्त्रता', 'समता', 'व्यक्ति की गरिमा', 'मनुष्यता' आदि इस के समूल है कि संविधान-निर्माताओं का लक्ष्य देश में राजनैतिक लोकतन्त्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र की नींव डालना था।

'धर्म-निरपेक्ष'—यह शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है। धर्म-निरपेक्षता की उपधारणा संविधान में प्रयुक्त 'विश्वास', धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता की प्रस्तावनी में पहले से अन्तर्निहित है। इस संशोधन द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया है। 'धर्म-निरपेक्ष' राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तथा उन्हें सम्मान, संरक्षण प्रदान करता है। धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने में प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र है।¹

'समाजवाद'—यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि 42वें संविधान अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त 'आर्थिक न्याय' प्रस्तावनी में समाजवाद की अवधारणा अन्तर्निहित है। संविधान-निर्माताओं ने इस 'आर्थिक न्याय' प्रस्तावनी की निश्चित परिभाषा नहीं दी है। यह संशोधन इस 'आर्थिक न्याय' को एक निश्चित दिशा देता है। भारतीय संविधान में एक मध्यम मार्ग अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द के साथ 'लोकतान्त्रिक' शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है। लोकतन्त्र और समाजवाद के इस अनेकौ सामंजस्य के प्रयास की परिकल्पना इस दिशा में एक नवीन कदम है।

'गणराज्य'—प्रस्तावना ने देश को एक 'गणराज्य' की सहा दी है इससे स्पष्ट है भारत में राज्य का प्रधान कोई आनुवंशिक नेरेश नहीं, बल्कि निर्वाचित राष्ट्रपति है। देश में विशेषाधिकार-सम्पन्न वर्ग नहीं है। राज्य के छोटे पद से लेकर राष्ट्रपति पद तक जाते, धर्म, प्रदेश या लिंग के बिना किसी भेद के सभी नागरिकों के लिए उन्मुक्त व्यवस्था है। हमारे गणराज्य में उच्चतम शक्ति सार्वभौम व्यवस्क प्रताधिकार से सम्पन्न भारतीय जन-समुदाय में निहित है।

'न्याय'—हमारे संविधान में बुनियादी और मौलिक धारणा 'न्याय' की है इसलिए प्रस्तावना में 'न्याय' को 'स्वतन्त्रता' और 'समता' से ऊपर रखा गया है। भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श है—'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'। संविधान के चौथे भाग, अनुच्छेद 38 में इस आदर्श का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे और लोक-कल्याण की दृष्टि का पथ प्रकाश करे। संविधान ने न्याय को आदर्श मानकर उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पक्षों पर बल दिया है।

'सामाजिक न्याय'—सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, किसी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक विपुल माना जाए, किसी पक्ष के लक्ष्य की सिद्धि का साधक-मात्र नहीं है। सामाजिक न्याय के इस मूलभूत मानवीय सिद्धान्त को संविधान में अनेक रूपों में मान्यता मिली है। संविधान के तीसरे और चौथे भाग में सामाजिक न्याय की सिद्धि के विविध उपायों का उल्लेख किया गया है।

'आर्थिक न्याय'—अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। इसमें राज्यों से कहा गया है कि वह अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करें कि सभी नगर-नगरियों को अजीविता के पर्याप्त भाषण प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वाधित्व और नियन्त्रण ऐसा हो जिससे अधिकाधिक सामूहिक हित सम्पन्न हो सके, आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत धन का और उत्पादन एवं वितरण के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अधिकार केन्द्रीकरण न हो, पुरुषों और स्त्रियों की समान कार्य के लिए समान वेतन मिले श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमारता का दुरुपयोग न हो आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर किसी ऐसे ध्ववसाय में न जाना पड़े जो उसकी आयु अथवा शक्ति के उपयुक्त न हो शैक्षणिक और किशोर अवस्था का शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो। 'समाजवादी दृष्टि के समाज', 'लोकहितकारी राज्य' और 'मिश्रित राज्य नीति' जैसे पदों में व्यक्त होता है कि भारतीय राज्य आर्थिक क्षेत्र में किन्हीं प्रतीकों की ओर न जाकर, राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहता है।

'राजनैतिक न्याय'—भारतीय संविधान सार्वभौम व्यवस्क प्रताधिकार की स्थापना, साम्प्रदायिक निर्वाचनों के अन्त और अनुच्छेद 19 से 22 तक के अन्तर्गत विधि स्वातन्त्र्य अधिकारों तथा अनुच्छेद 32 के अधीन सौधधार्मिक उपचारों द्वारा राजनैतिक न्याय के आदर्श को पूर्ण रूप प्रदान करता है।

'स्वतन्त्रता'—विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता को व्यक्तियों तथा राष्ट्र के आर्थिक उत्कर्ष के लिए आवश्यक माना है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अन्तर्गत स्वातन्त्र्य-अधिकारों का विस्तार

से प्रतिपादन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19-22 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त स्वतन्त्रताओं को सामूहिक रूप से 'स्वतन्त्र अधिकारों' की संज्ञा दी गई है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को ऐसी वैयक्तिक स्वतन्त्रताएं प्रदान की गई हैं जो उदारवादी लोकतन्त्र के लिए अनिवार्य हैं।

'समता'—प्रस्तावना में 'प्रतिष्ठा और अवसर की समता' की बात कही गयी है। समानता का सिद्धान्त की ध्यान में रखते हुए संविधान-निर्माताओं ने प्रस्तावना में 'समता' शब्द नहीं कहा और न ही 'समान-सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक' कहा है क्योंकि स्पष्ट 'प्रतिष्ठा और अवसर की समता' पर बल दिया है। प्रतिष्ठा और अवसर का समता के कई पहलू हैं—वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। वैयक्तिक रूप से विधि के समक्ष सब नागरिकों की समानता होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से धन, जाति, विद्युत और वर्ण के आधार पर मनुष्य में अन्तर नहीं होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में सभी नागरिकों—अल्पसंख्यकों तथा पागलों की छद्मता—देश के शासन में समान भाग मिश्रण चाहिए। सिंगल नस्ल अथवा धर्म के आधार पर राजनीतिक अधिकारों का विशेष राजनीतिक समता का अन्वयण करना है। आर्थिक समता में समता का अर्थ है कि योग्यता और समान क्रम के लिए बराबर समान हो। आर्थिक समता में एक वर्ग को दूसरे वर्ग का अधिकार नहीं है।

'व्यक्ति की गरिमा' और 'बन्धुता'—प्रस्तावना में अन्य दो अग्रगण्य सिद्धान्त एवं आदर्श हैं—व्यक्ति की गरिमा तथा बन्धुता। संविधान में समता के आदर्शों ने 'व्यक्ति की गरिमा' को प्रतिष्ठा दिया है। सारे देश के लिए एक प्रशासन, नागरिकता, धर्म, कानून व्यवस्था आदि की स्थापना करते देश को एकता के सूत्र में बाँधने और राष्ट्रीय बन्धुता को सुदृढ़ करते हुए अन्तराष्ट्रीय स्तर में विश्व बन्धुता की भावना के प्रचार प्रसार का निम्न प्रयत्न किया है।

'राष्ट्र की एकता और अखण्डता'—प्रस्तावना में इनका मन्व्य यह है कि विभिन्नताओं के बावजूद देश में एकता बुनियादी एकता है जिसे दृढ़ता प्रदान करना राष्ट्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। अखण्डता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे प्रस्तावना में समाविष्ट किया गया है।

प्रस्तावना में संशोधन

यह विवादस्पद प्रश्न है कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं? केवलानन्द भारती बनाम केन्द्र राज्य के मामले में यह प्रश्न सर्वप्रथम न्यायन्याय के समक्ष विचारार्थ उपस्थित हुआ था। सर्वोच्च पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि पूर्ण प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, अतएव अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत उसमें संशोधन किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों की ओर से कहा गया कि अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन की शक्ति सीमित है। प्रस्तावना में संविधान का आधारभूत ढाँचा संनिहित है जिसे संशोधन करने नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे संविधानिक स्थिति का चरम अंग निरिचय है। यद्यपि उच्चतम न्यायन्याय ने बहुमत से यह अधिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तथापि विद्वान् व्याख्यातकों में इस प्रश्न पर मतभेद नहीं था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। व्याख्यातकों के बहुमत का विचार इसी पक्ष में रहा कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, किन्तु जब तक केवलानन्द भारती का विनिर्णय उल्टा नहीं दिया जाता प्रस्तावना में किए गए संशोधन की कभी व्याख्या में पुनर्जाती दी जा सकती है कि वह उसमें निहित अग्रगण्यताओं में परिवर्तन है।

भारत का संविधान भारतीय शासक मूल्यों, मूल्यप्रणालियों एवं व्यवस्थाओं के समेकित दार्शनिक आधारों पर आधारित है जिसमें व्यक्ति की गरिमा, उसके प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को समन्वित किया गया है।

(2) मूल अधिकार और कर्तव्य

(Fundamental Rights and Duties)

विश्व के संविधानों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मेलन हुआ है, इसलिए भारतीय संविधान के अध्याय 3 की भारत का अधिकार-पत्र (Bill of Rights) कहा गया है। संविधान के पृष्ठ 3 (अनुच्छेद 12 से 35) में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। संविधान-निर्माताओं को विश्वास था कि भारत में पहली बार प्रजातन्त्र का प्रयोग हो रहा है अतः मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना व्यक्ति स्वतन्त्रता की आधारभूतता के समान है।

मौलिक अधिकारों के विशेष लक्षण

(Special Features of Fundamental Rights) -

1. मौलिक अधिकार सभी सरकार और राज्यें तथा प्रत्येक अधिकारी जिसे विधि-निर्माण की शक्ति हो सीमा (Limitations) अधीन होते हैं। ये उन सभी पर बन्धनकारी (Binding) हैं।

2. ये अधिकार भारत की आधारभूत एकता (Basic Unity of India) पर बल देते हैं। भारत विभिन्न इकाइयों में बँटा है और दृक्क अधिकारियों (Separate Authorities) की व्यवस्था है, किन्तु नागरिकों को अधिकार है कि वह सभी अधिकारियों से समान व्यवहार प्राप्त करें।

3. ये अधिकार पूर्णतः निषेध (Absolute) नहीं हैं। प्रत्येक मामले में संविधान में अपवादों, परिशेषों और अंशों को बताया गया है। संविधान ने राज्य को इन अधिकारों पर सीमाएँ लगाने का अधिकार दिया है।

4. इन अधिकारों के उपयोग में संविधान ने नागरिकों (Citizens) और विदेशियों (Aliens) में अन्तर किया है। कानून के समान समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता आदि अधिकार नागरिकों और विदेशियों के लिए समान हैं जबकि भाषण और सम्पत्ति की स्वतन्त्रता (Freedom of Speech & Conference) तथा मौखिक और शैक्षणिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। यह अन्तर संविधान में प्रयुक्त 'नागरिकों' (Citizens) और 'व्यक्तियों' (Persons) शब्दों से स्पष्ट है।

5. कोई व्यक्ति (Individual) मौलिक अधिकारों के बाहर राज्य के विरुद्ध किसी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। भारतीय न्यायालयों के लिए ऐसे मौलिक अधिकार की खोज करने का अधिकार नहीं है जो संविधान में न रखे गए हों। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन खेव पर यह प्रतिबन्ध (Restriction) है।

6. भारतीय मौलिक अधिकार प्रयोग में राज्य और उनके अधिकारणों को नहीं, निजी व्यक्तियों और संगठनों (Private Persons and Organisations) को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार व्यक्ति के लिए दण्डनीय अपराध है।

7. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उन्हें वास्तविक बनाने की दृष्टि से संविधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है। इन संविधानिक उपचारों के अधिकारों को मौलिक अधिकार मान लिया गया है।

8. संविधान में परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है जिनमें राज्य सम्पूर्ण देश के हित में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर सके या उनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा सके। प्रतिबन्धों का अन्तर्भाव निम्नांकित है—

(अ) प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के सम्बन्ध में (अनुच्छेद 33)—अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद को विधि द्वारा यह अधिकार है कि प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को इस सीमा तक प्रतिबन्धित किया जाये ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और उनमें अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 33 के प्रयोग में संसद ने अनेक अधिनियम पारित किए, जैसे—सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950, नौ सेना अधिनियम 1950।

(ब) जब मार्शल लॉ लागू हो (अनुच्छेद 33)—अनुच्छेद 34 के अन्तर्गत संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ (सैनिक विधि) के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। मार्शल लॉ के दौरान साधारण नागरिक हेतु न्यायालयों का स्थान हो जाता है और उनके स्थान पर सैनिक न्यायालय कार्य करने लगते हैं। संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के दायित्व से उन्हें विमुक्ति प्रदान कर सकती है।

(स) संविधान में सशोधन द्वारा (अनुच्छेद 368)—अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधानिक सशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के निलम्बन को संसद की शक्ति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 में संविधान सशोधन से सम्बन्धित कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया निश्चित है। वह संसद को मूल अधिकारों में सशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त 'विधि' शब्द के अन्तर्गत आती है और यदि वे भाग 3 में दिये गये उपबन्धों से असंगत हैं तो अवैध एवं असंवैधानिक घोषित किये जा सकते हैं, किन्तु संविधान के 24वें सशोधन अधिनियम, 1971 ने इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया। चौबीसवें सशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 13 में नया उपखण्ड 4 जोड़ा गया है और अनुच्छेद 368 में सशोधन किया गया है। इस सशोधन का उद्देश्य संसद के मूल अधिकारों में सशोधन करने की शक्ति को पुनः स्थापित (Restore) करना है। उपखण्ड 4 यह उपबन्धित करता है कि इस अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक सशोधन अनुच्छेद 13 के 'विधि' शब्द के अन्तर्गत नहीं आएँगे। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने चौबीसवें सशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित कर दिया, किन्तु संसद की संविधान-सशोधन शक्ति पर महत्वपूर्ण परीक्षा लगा दी। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि सशोधन शक्ति विस्तृत है, किन्तु असंमित नहीं है और संसद संविधान की शक्ति का प्रयोग इस तरह नहीं कर सकती जिससे संविधान का आधारभूत ढाँचा (Basic Structure) नष्ट हो जाये। केशवानन्द भारती की निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए 42वाँ संविधान सशोधन अधिनियम, 1976 पारित किया गया। इस सशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में नया खण्ड जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद की संविधान सशोधन शक्ति सर्वोच्च है और उस पर परीक्षा नहीं लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत किये गये सशोधनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(ख) आपातकालीन घोषणा के अन्तर्गत (अनुच्छेद 352)—अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकालीन स्थितियों में मौलिक अधिकारों के निलम्बन की व्यवस्था है। आपात-उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालयों की शक्ति में जाने के अधिकार को निलम्बित कर दे। 1962 के चीन के आक्रमण के अवसर पर अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात को उद्घोषणा की और अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत एक आदेश जारी कर अनुच्छेद 14, 21 एवं 22 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलम्बित कर दिया। सकट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम, 1962 (Defence of India Act, 1962) पारित किया गया। यह आपातकालीन स्थिति 10 जनवरी, 1968 तक चलती रही। पाकिस्तान के आक्रमण के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने 3 दिसम्बर, 1971 को आपात उद्घोषणा इस आधार पर की कि बाढ़ आक्रमण में देश की सुरक्षा को खतरा था। अनुच्छेद 359 के अधीन एक आदेश द्वारा अनुच्छेद 14, 21, एवं 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराने के अधिकारों को निलम्बित कर दिया गया। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के अधीन पुनः आपात उद्घोषणा की कि गम्भीर आन्तरिक आपातस्थिति विद्यमान है जिससे देश को खतरा है।

सविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 19(क) में प्रदत्त अधिकारों को देश पर 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण देश की सुरक्षा के लिए सकट उत्पन्न होने की दशा में निलम्बित किया जा सकता है, 'आन्तरिक अशांति' के आधार पर नहीं। दूसरे अनुच्छेद 358 केवल उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करेगा जो आपात-स्थिति से सम्बन्धित हैं, अन्य कानूनों को आपातकाल के दौरान न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकारों को निलम्बित करने की शक्ति नहीं होगी। ध्विज में अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलम्बित नहीं किया जा सकेगा जैसा कि 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान कॉमिंस सरकार द्वारा किया गया था। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है।¹ आपातकाल में मौलिक अधिकारों का अवाञ्छनीय रूप से हनन न हो, इस दृष्टि से विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाएँ की गई हैं।

9. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ऐसी की गई है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके। मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखा गया है, वहाँ दूसरी ओर समाज और राज्य-हित में उन पर राज्य द्वारा प्रतिबन्ध आरोपित किये जा सकते हैं।

10. मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। अगर राज्य इनका अपहरण करने का प्रयास करे तो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायपालिका राज्य के अतिक्रमण से इन अधिकारों की रक्षा करती है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की गई है।

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार

(Fundamental Rights under the Constitution)

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 तक निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है—

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), 2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), 3. शोषण से मुक्ति का अधिकार (अनुच्छेद 23-24), 4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28), 5. मौखिक एवं लिखित शिष्टा सम्बन्धी (अनुच्छेद 29-30) एवं 6. संविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

26 जनवरी, 1950 को मौलिक अधिकारों की जो स्थिति थी, तदनुसार 'सम्पत्ति के अधिकार' को अनुच्छेद 19(1) (घ) और अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार के रूप में अन्तर्निहित किया गया था किन्तु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा सम्पत्ति को मौलिक अधिकार समाप्त कर इसे अनुच्छेद 300 (अ) में सम्मिलित कर दिया गया है। सम्पत्ति का अधिकार साधारण विधिक अर्थात् कानूनी अधिकार रह गया है।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

(Right to Equality)

अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता)

इस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि "भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता" से अर्थात् विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।" यह वाक्यांश 'विधि अथवा कानून के समक्ष समानता' (Equality before Law) इंग्लिश सामान्य विधि (English Common Law) का प्रयोग है, किन्तु 'कानून का

(ख) ऐसे कुओं, तालाबों, स्नान-घरों, सड़कों तथा सावजनिक स्थानों के, जिनकी व्यवस्था पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राज्य की निधियों द्वारा की जाती है।

अनुच्छेद 15 की व्यवस्था राज्य की स्त्रियों, बच्चों, पिछड़ा जातियों के लिए विशेष प्रयत्न करने से नहीं राखता है। उदाहरणार्थ, यदि सरकार बच्चों एवं स्त्रियों के लिए पुस्तक पार्क बनाती है और उसमें पुरुषों के प्रवेश का निषिद्ध ठहराती है। सरकार के इस कदम को अनुचित भेदभाव पर आधारित नहीं समझा जाएगा और ऐसा विराध व्यवस्था अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा। राज्य को अधिकार है कि बाल-विवाह, बहु-विवाह जैसा सामाजिक क्रूरताओं का रोकने के लिए विशेष कानून बनाए। सुप्रीम अदालत अर्जुन कुमार मुखर्जी के वाद में भारतीय दण्ड विभाग का धारा 497 को संविधानिकता को चुनौती दी गई थी। प्रार्थी ने धारा 497 को संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विरुद्ध बताया और तर्क दिया कि अपराध के लिए पुरुष को दण्डनीय मानना और व्यक्तिगतता का गैर अभिप्राय (Abettor) के रूप में दण्डित न करना अनुचित है। यह विषेद लिंग के आधार पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 497 को रद्द माना, क्योंकि 'वर्गिकता' लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि समाज में स्त्रियों की विशेष स्थिति के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कानून को संशोधित कर दिया गया है पल्लवरूप अब स्त्री समान रूप से दण्डनीय है यदि वह अपराध को उकसाने में भाग लेती है।

अनुच्छेद 15 भेदभाव को खींच करता है इच्छारी नागरिकता को भेदना का प्राभाह्न देता है और सामाजिक समानता का सवाल बनाता है।¹ यह राज्य के न्यायोचित भेदभाव को निषेध नहीं करता, अनुचित भेदभाव की अज्ञा वस्तु है। एक नागरिक के नाते उसे जो अधिकार, सुविधाएँ और उन्मुक्तिपूर्ण (Immunities) प्राप्त हैं उनमें उसमें काइ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार देश में सामाजिक न्याय की स्थापना करने की दृष्टि से परमावश्यक है।

अनुच्छेद 16 (अमर की समानता)

यह अनुच्छेद पाँच भागों में विभक्त है। अनुच्छेद 16(1) में लिखा है कि "राज्याधीन नौकरियों" अथवा पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों के लिए अवसर को समानता होगी।" अनुच्छेद 16(2) में उल्लेख है कि "किसी धर्म, मूल ब्राह्मण, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी एक नागरिक के लिए राज्यधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपभ्रता होगी और न विषेद किया जाएगा।" अनुच्छेद 16 के अन्य तीन भागों में इसके अपवादों का उल्लेख है। अनुच्छेद 16(3) के अनुसार रासद चले विधि द्वारा किसी राज्य या स्थानीय पद को वहाँ के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार, जिन जातियों का सौकर-सम्बन्धों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, उनके लिए पदों तथा नौकरियों का राज्य आरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 16(5) में उपबन्धित है कि किसी धार्मिक या सम्प्रदायिक सभा के अन्तर्गत किसी पद का अधिकारी उस सम्प्रदाय या धर्म का सदस्य हो सकता है अतः अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत नागरिक को राज्य के अन्तर्गत नौकरियों में अवसर का समानता का अधिकार प्राप्त है व्यक्तिगत नौकरियों में नहीं।

अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अन्त)

इस अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत को पूर्णतः समाप्त कर इन्हें व्यवहार में लाना अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता को अवैध ठहराने वाला यह अनुच्छेद संविधान के अन्तर्गत दी जाने वाली समता का सभा अधिकारों से मूलस्थान है। अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति-भेद की देन है न कि शाब्दिक अस्पृश्यता की—देखिए देवराजी बनारस पटना² का विनिश्चय। पॉपुलर यूनिवर्सल डेमेक्रेटिक राइट्स बनारस भाठ सर्प के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रादेशिक व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है और यह राज्य का संविधानिक कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों का अतिरिक्त रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।³

अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अन्त)

इस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन की व्यवस्था है ताकि जनता में कृत्रिम भेदभाव फैलान की परिस्थितियाँ पर अकुरा रहे। यह अनुच्छेद चार भागों में बाँटा गया है—

18(1) के अनुसार, "सेना या सिखा सम्बन्धी उपाधि का सिपाय और कोई सिखाय राज्य प्रदान नहीं करेगा।"

1 ए. आई. आर. 1954 सुप्रीम कोर्ट 321

2 M. L. Pyle Constitutional Government in India, p. 207

3 जयन्तयन पाण्डेय वरिष्ठ, पृ. 133

4 ए. आई. आर. 1958, मैमूर 33

5 ए. आई. आर. 1982, सुप्रीम कोर्ट 1473

6 जयन्तयन पाण्डेय वरिष्ठ, पृ. 133

18(2) में लिखा है, "भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई छिताव स्वीकार नहीं करेगा।"

18(3) के अनुसार, "कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई छिताव राष्ट्रपति की सम्पत्ति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।"

18(4) में उल्लेख है, "राज्य के अधीन लाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्पत्ति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।"

भारत सरकार हर वर्ष गणतन्त्र दिवस पर नागरिकों को 'भारत-रत्न', 'पद्म-विभूषण', 'पद्मश्री' आदि उपधियों से अलंकृत करती है। सैनिक क्षेत्र में 'परमवीर चक्र', 'महावीर चक्र' और 'वीर चक्र' तथा अन्य उपधियाँ दी जाती हैं। ये उपधियाँ उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने पर प्रदान की जाती हैं। अनुच्छेद 18 निदेशात्मक है आदेशात्मक नहीं अर्थात् इस अनुच्छेद के उपबन्धों की अवहेलना करने वालों के लिए संविधान में किसी दण्ड-व्यवस्था का उपबन्ध नहीं है।

समता के अधिकार के सम्बन्ध में इन पाँच अनुच्छेदों से यह स्पष्ट है कि संविधान के अन्तर्गत देश में सामाजिक और राजनीतिक समानता को स्थापित करने का जितना प्रयासशाली प्रयत्न किया गया है उतना आर्थिक समानता लाने की दिशा में नहीं।

स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 14-24)

(Right to Freedom)

सामूहिक रूप से स्वतन्त्रता के ये पाँच अनुच्छेद व्यक्ति-स्वातन्त्रता के अधिकार पर हैं।¹ इसमें से 19वाँ अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जो नागरिकों को ये छः स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता है—(क) शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (ख) सभा बनने की स्वतन्त्रता, (ग) सच बोलने की स्वतन्त्रता, (घ) प्रमाण की स्वतन्त्रता, (ङ) आवास की स्वतन्त्रता, (च) पेशा, व्यापार, व्यवसाय एवं वाणिज्य की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं विदेशियों को नहीं। पूर्व में ये सात स्वतन्त्रताएँ थीं, किन्तु 44वें संविधान संशोधन से सम्पत्ति के 19(1) (च) अधिकार को 1978 में विलोपित कर दिया गया। वर्तमान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर निम्नलिखित सात प्रतिबन्ध लागू हैं—(1) राज्य की सुरक्षा और भारत में प्रभुसत्ता एवं अखण्डता, (2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, (3) सार्वजनिक व्यवस्था, (4) सार्वजनिक शांति और सन्तुलन, (5) न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) (6) मानहानि एवं (7) हिंसा को प्रोत्साहन। वर्तमान प्रतिबन्ध संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 एवं सोलहवें संशोधन अधिनियम, 1963 के अनुसार हैं। अनुच्छेद 19(2) से (6) तक में 'युक्तियुक्त निर्बन्धन' (Reasonable Restriction) की व्यवस्था की गई है अर्थात् यदि राज्य समाज के हित में आवश्यक समझे तो नागरिकों की स्वतन्त्रताओं पर निर्बन्धन लगा सकता है बशर्ते ये निर्बन्धन युक्तियुक्त हों।

'युक्तियुक्त निर्बन्धन' शब्द इस अनुच्छेद का महत्वपूर्ण शब्द तथा आत्मा और प्राण है। 'युक्तियुक्त' शब्द की व्याख्या करते हुए 'रोश धापर बनाम मद्रास राज्य' नामक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था—'युक्तियुक्त निर्बन्धन का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के अधिकार-उपयोग पर स्वेच्छापूर्ण एवं सार्वजनिक हित की आवश्यकता से अधिक प्रतिबन्ध न लगाये जाये, अतः जो विधि से स्वेच्छाचारी दण्ड से अथवा अत्यधिक मात्रा में एक अधिकार का अतिक्रमण को उसे 'युक्तियुक्त' नहीं कहा जा सकता। यदि एक विधि प्रत्याभूत स्वतन्त्रता तथा 19वें अनुच्छेद के अन्तर्गत निर्धारित सामाजिक नियन्त्रण में उचित सन्तुलन स्थापित नहीं करता तो उसे 'युक्तियुक्त' को सझा प्रदान नहीं की जा सकती।

अनुच्छेद 19(1) (क) शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अभिप्राय है शब्दों, लेखों, चित्रों, मुद्रण, अन्य प्रकार में अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में प्रेस की व्यवस्था सम्मिलित है। 'रोश धापर बनाम मद्रास राज्य' के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की थी कि "शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में विचारों के प्रसार की स्वतन्त्रता सम्मिलित है और यह स्वतन्त्रता विचारों के प्रसारण की स्वतन्त्रता द्वारा सुनिश्चित है। उस स्वतन्त्रता के लिए परिचालन की स्वतन्त्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी की प्रकाश की स्वतन्त्रता। निःसन्देह परिचालन के बिना प्रकाश का कोई महत्व नहीं होगा।"

'अभिव्यक्ति' शब्द वस्तुतः बहुत व्यापक है। "आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने अभिव्यक्ति के नये-नये साधनों का आविष्कार किया है और करती जा रही है, उदाहरण के लिए रेडियो, चर्चित्र, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाईल आदि अतः इन सब साधनों का संविधान में उल्लेख करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। 'अभिव्यक्ति' शब्द द्वारा इन सभी

साधनों की ओर संकेत हो जाता है।" सांख्य पेपर्स लि. बनाम भारत सभ में यह स्पष्ट न्यायिक व्याख्या की गयी थी कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में प्रेस की स्वतन्त्रता शामिल है। 'वृजभूषा बनाम दिल्ली राज्य' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि समाचार-पत्रों पर पूर्ण-अवरोध (Censorship) लगाना प्रेस की स्वतन्त्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध है। 'बोरिंद्र बनाम पंजाब राज्य' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी समाचार-पत्र को तत्कालीन महत्व के विषय पर अपने विचार प्रकाशित करने से रोकना वाक् तथा अभिव्यक्ति का अतिक्रमण है। प्रेस की स्वतन्त्रता अप्रतिबन्धित नहीं है, किन्तु राज्य को सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाना राज्य के लिए आवश्यक हो सकता है।

प्रमुदत बनाम भारत सभ के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रेस की स्वतन्त्रता में सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार (Right to Know) शामिल है। प्रेस को व्यक्तियों से सफाई के माध्यम से सूचनाएं जानने की स्वतन्त्रता है, किन्तु जानने की स्वतन्त्रता असम (Absolute) नहीं है उस पर दुष्प्रयुक्त निर्वन्धन अधिरोपित किये जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताओं को किसी भौगोलिक परिसीमा से बांधा नहीं जा सकता। नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग भारत की सीमा में तथा विश्व के किसी भी देश की भूमि पर कर सकता है। यदि राज्य किसी व्यक्ति द्वारा इन अधिकारों के प्रयोग पर देश की सीमा के आधार पर रोक लगाता है तो यह अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण होगा। उक्त सिद्धान्त मेनका गांधी बनाम भारत सभ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया है। इसमें वादी को विदेश जाने के लिए दिये गये पासपोर्ट को वापस करने का आदेश दिया गया था। वकील ने इस आदेश की विधि मान्यता को चुनौती दी। न्यायालय के निर्णय के अनुसार दक्षिण विदेश-भ्रमणा का अधिकार अनुच्छेद 19 के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, किन्तु यदि नागरिक के अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा तो उससे अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण हो सकता है। यह तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है।

अनुच्छेद 19(1) (ख) एवं 19 (3) : एकत्रित होने का अधिकार

सविधान का अनुच्छेद 19(1) (ख) नागरिकों को शान्तिपूर्वक तथा गिनत अथवा निरासन्न एकत्रित होने का मूल अधिकार प्रदान करता है। सभा एवं सम्मेलन की स्वतन्त्रता में सभाएं करने, सम्मेलन करने एवं जुलूस निकालने का अधिकार सम्मिलित है। जुलूस निकालने के अधिकार का स्पष्ट रूप में अनुच्छेद 19(1) (ख) में उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यह एकत्रित होने के अधिकार में सम्मिलित है। कुछ देशों के सविधानों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह अधिकार वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का आधार है। यह अधिकार अप्रतिबन्धित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था को रक्षा के लिए 'दुष्प्रयुक्त प्रतिबन्ध' लगा सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने 'इन्दुदेवसिंह विरुद्ध बिहार राज्य' के मामले में इस उपबन्ध की व्याख्या की थी। निम्नलिखित मर्दान्तों तथा सीमाओं में रहते हुए नागरिकों द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है—

1. सभा सम्मेलन, जुलूस शान्तिपूर्ण ढंग से संचालित किये जाने चाहिए। अराजक भीड़ हिंसक जुलूस इस अधिकार के अधीन बांध नहीं माने जायेंगे।

2. सभा, सम्मेलन, जुलूस निरासन्न होने चाहिए अर्थात् सभाएं सभा, सम्मेलन, जुलूस पर सविधान के अनुच्छेद 19 (ख) के अधीन प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं, किन्तु रक्त रंजित या अधिकार प्राप्त व्यक्तियों पर इस अनुच्छेद द्वारा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है, जैसे—सिन्धियों की धार्मिक सभा आदि।

3. अनुच्छेद 19(3) के अधीन लोकव्यवस्था तथा भारत की सम्प्रभुता एवं एकता के आधार पर विधि द्वारा दुष्प्रयुक्त निर्वन्धन लगाये जा सकते हैं।

भारतीय दण्ड विधान के अध्याय III के अनुभाग यदि किसी सभा से जब शान्ति भंग होने की आशंका हो तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुच्छेद 127 के अन्तर्गत उसे भंग करने का आदेश दिया जा सकता है। इस आदेश की अवश्या अनिवार्य है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुच्छेद 107 के अनुसार एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति जिससे शान्ति भंग किये जाने की आशंका हो शान्ति बरकरार रखने को जामिन ले। अनुच्छेद 144 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह हिंसा एवं संधि की आशंका में किसी सभा सम्मेलन तथा जुलूस को मनही कर दे। पुलिस एक्ट, 1861 के अधीन पुलिस अधिकारी सभाओं एवं जुलूसों को संचालित करने के ढंग, समय स्थान तथा उनके जाने के मार्गों के, लोकव्यवस्था के हित में, उचित निर्देश दे सकता है। इस एक्ट की धारा 30 की व्यवस्था के अनुसार जुलूस निकालने से पहले पुलिस अधिकारी से पूर्व-अनुज्ञ लेना आवश्यक है। राज्य सरकार को यह शक्ति

है कि यह किसी प्रान्त अथवा उसके किसी भाग को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दे। उपर्युक्त उस भाग में बिना जिलाधीश या पुलिस कमिश्नर को अनुमति से कोई सशस्त्र सन्मेलन या जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19 (1) (ग) एवं 19 (4) : सशस्त्र एवं सशस्त्र बनाने का अधिकार

अनुच्छेद 19(1) (ग) के अधीन भारत के सभी नागरिकों को विधि-सम्मत उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्पूर्ण एवं सशस्त्र बनाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यह सशस्त्रता या मध्य व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा भौतिक कार्य के लिए हो सकती है। इस अधिकार में सशस्त्रता या सशस्त्र बनाने के अधिकार के साथ ही उन्हें मर्यादित करने का अधिकार सम्मिलित है। अन्य स्वतन्त्रताओं की भाँति सशस्त्रता सशस्त्र बनाने का अधिकार निरपेक्ष (Absolute) नहीं है। अनुच्छेद 19(4) के अधीन राज्य नागरिकों की इस स्वतन्त्रता पर निम्नलिखित आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन स्थापित कर सकता है—1. भारत की सम्पूर्णता एवं एकता, 2. लोक व्यवस्था एवं 3. नैतिकता। किसी अथवा बहुसंख्यक उद्देश्य के लिए सशस्त्रता नहीं बनाया जा सकता। सशस्त्रता और सशस्त्र स्थापित करने के अधिकार नागरिकों को समान रूप से प्राप्त नहीं है। सरकारों कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमों से बंधे होते हैं, अतः इन नियमों के विरुद्ध जाकर सशस्त्रता या सशस्त्र स्थापित करने के अधिकार का अन्य नागरिकों के समान उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने 'बालकटिया बनाम भारत संघ' के विवाद में स्पष्ट कर दी थी।

प्रतिरक्षा सेना तथा सशस्त्र बनाने का अधिकार—उसके बाद सशस्त्रता सशस्त्र बनाने के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्त सेवक, जैसे—रसोइये, चौकीदार, लश्कर, नाई बर्तई मिस्त्री, जूता बनाने वाले, दवाई आदि प्रतिरक्षा सेना के सदस्य माने जा सकते हैं जिन्हें सशस्त्र बनाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उपर्युक्त व्यक्ति अनुच्छेद 33 के अधीन प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों में शामिल हैं अतः सेना अधिनियम की धारा 21 के अधीन केन्द्रीय सरकार उनके सशस्त्र बनाने का अधिकार का नियम बनाकर निर्बंधन कर सकती है। ऐसे सेवकों का कर्तव्य सेना के सदस्यों की सक्रिय सेवा पर अपने का अनुसरण करना या साथ रहना होता है। यद्यपि वे युद्ध में भाग नहीं लेते (Non Combatant), तथापि वे प्रतिरक्षा सेना के एफ आरएफए आग हैं।

अनुच्छेद 19(1) (घ) एवं खण्ड 19(5) : भ्रमण की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 19(1) (घ) के अनुसार भारत में नागरिकों को सारे देश में स्वतन्त्र रूप से भ्रमण या संचरण का बिना किसी प्रतिबंध के भारत संघ के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने तथा राज्य की सीमा के भीतर भ्रमण कराने का अधिकार है। सम्पूर्ण क्षेत्र नागरिकों के लिए एक इकाई के समान है। अनुच्छेद 19(5) के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक संचरण का यह अधिकार राज्य द्वारा दो परिस्थितियों में परिसीमित हो सकता है—(क) सार्वजनिक जनता के हित में (ख) अनुसूचित आदिवासी जातियों के हितों की रक्षा में। प्राकृतिक रोग से प्रसिद्ध व्यक्ति एवं वैर्या के संचरण के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह कदम सामान्य जनता के हित में होगा। अनुसूचित आदिवासी जातियों के हित में राज्य प्रतिबंध लगा सकता है ताकि उनकी अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक सम्बन्धी परम्पराओं की रक्षा हो सके। आदिवासी जातियों की सुरक्षा और हित की दृष्टि से सार्वजनिक नागरिकों द्वारा इनके क्षेत्रों में बसने अथवा सम्पत्ति क्रय करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अनुच्छेद 19(1) (ङ) एवं 19(5) : निवास की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 19(1) (ङ) द्वारा सभी नागरिकों को भारत में कहीं बसने या आवास की स्वतन्त्रता है। इसके लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है किन्तु अनुच्छेद 19(5) के अनुसार इस अधिकार पर सर्वसाधारण तथा अनुसूचित जनजातियों के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निवास और भ्रमण की स्वतन्त्रता एक-दूसरे को पूरक है क्योंकि दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना है। भ्रमण एवं निवास की स्वतन्त्रता को आपतकालीन स्थिति में कम अथवा निलम्बित किया जा सकता है। परिसर एक्ट 1864 तथा 1966 के अन्तर्गत किसी विदेशी व्यक्ति के भ्रमण एवं निवास के अधिकार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अथवा उसे भारत से चले जाने का आदेश दे सकता है।

अनुच्छेद 19(1) (छ) एवं 19(6) : व्यापार मुक्ति या उपजीविका की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 19(1) (छ) सभी नागरिकों को कोई पेशा व्यापार व्यवसाय या वाणिज्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता है, किन्तु इस अधिकार पर राज्य 'युक्तियुक्त प्रतिबंध अथवा निर्बंधन' लगा सकता है। खण्ड 19(6) के अधीन निम्नलिखित आधारों पर राज्य को प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है—

(क) साधारण जनता के हित में

(ख) विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित कर एवं

(ग) नागरिकों को पूर्ण एवं आर्थिक रूप में किसी व्यापार से बहिष्कृत करके।

वार्मपातिका के कृत्यों के विरुद्ध बन्धित विधानमण्डल के विरुद्ध सारण प्रदान करता है। विधान-मण्डल द्वारा पारित कानून सुनिश्चित तथा नैतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए अन्यथा उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है अतः भारतीय संविधान में व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) के अधीन रखा गया है। यह व्यवस्था अमेरिकन संविधान की व्यवस्था से मेल खाती है, लेकिन दोनों व्यवस्थाओं में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ भारतीय संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्दावली है वहीं अमेरिकन संविधान में 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। अमेरिकन न्यायालयों ने इस पदावली का विस्तृत अर्थ देते हुए इसकी तुलना नैतिक न्याय (Natural Justice) से की है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 'नैतिक न्याय' के सिद्धांत की अनुच्छेद 21 का आवश्यक तत्व मान लिया है। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'दैनिक स्वातंत्र्य' पदावली विस्तृत अर्थ लिए हुए है और उस रूप में इसके उद्देश्य दैनिक स्वतंत्रता के सभी आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक हैं। इस अर्थ में इस पदावली में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान स्वतंत्रता के सभी अधिकार आ जाते हैं।

अनुच्छेद 22 : धनोद्वेग तथा नजरबंदी से बचाव

संविधान के इस अनुच्छेद द्वारा बन्दी व्यक्तियों को कुछ संविधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 22 (1) और 22(2) द्वारा निर्धारित संविधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं—

(क) किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बराबरी अवगत करवाए बिना बन्दी बनाकर नहीं रखा जा सकता।

(ख) उसे अपनी रीति के बर्तन से परामर्श करने तथा अपने पक्ष की सफाई दितवाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

(ग) उसे गिरफ्तारी से 24 घण्टे के अन्दर नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

(घ) उसे न्यायालय की आज्ञा बिना 24 घण्टे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

अनुच्छेद 22 में बन्दी बनाए जाने की अवस्था में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 22 (3) में उल्लेख है कि अनुच्छेद 22(1) तथा अनुच्छेद 22(2) द्वारा बन्धियों को जो उपर्युक्त संविधानिक अधिकार दिए गए हैं वे दो प्रकार के बन्धियों को उपलब्ध नहीं होंगे—प्रथम जिन बन्धियों का विदेशी शत्रु राष्ट्र के साथ सम्बन्ध है। द्वितीय जिन व्यक्तियों को 'निवारक नजरबंदी' कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है और दोनों को एक-दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 स्वयं में पूर्ण नहीं है। यैवका गाँधी के मामले में यह स्पष्ट हो गया था कि अनुच्छेद 22 के अधीन पारित विधियों को अनुच्छेद 21 में विहित बुद्धिपुक्त और उचित प्रक्रिया की कसौटी पर जाँचा जाएगा।

निवारक निरोध—अनुच्छेद 22 (4) से 22(7) तक निवारक निरोध (Preventive Detention) की चर्चा की गई है। निवारक निरोध सकटकाल तथा साधारण काल में लागू रहता है। 'निवारक' (Preventive) शब्द दण्डात्मक (Punitive) या त्रितीय है। 'निवारक गिरफ्तारी' दण्डात्मक गिरफ्तारी से भिन्न है। दण्डात्मक गिरफ्तारी विरुद्ध व्यक्ति को दण्ड देने के उद्देश्य से की जाती है किन्तु निवारक बन्दीकरण का उद्देश्य दण्ड देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना या विरुद्ध व्यक्ति को किंवा किसी उद्देश्य को पूरा करने से रोकना है। इसमें विरुद्ध व्यक्ति अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है। यह एहतियारी कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए अपनाई जाती है। इसमें व्यक्ति को सन्देह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुच्छेद 22 (4-7) के अन्तर्गत निवारक निरोध कानून के उद्देश्य विरुद्ध किए गए व्यक्ति को ये राखण प्रदान किए गए हैं—(क) सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विचारन। (ख) गिरफ्तारी के कारण जानने एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। (ग) सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया।

अनुच्छेद 22(4) में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। धारा (4) (ख) में उपर्युक्त करता है कि निरोध अधिकतम अवधि से अधिक नहीं हो सकता है जो सार्व विधि द्वारा उन प्रकरण के मामलों में विरुद्ध व्यक्तियों के वर्गों के लिए विहित होगी। आ 44वें संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि 'निवारक नजरबंदी' सम्बंधी कोई कानून किसी देश में 2 महीने से ज्यादा के लिए नजरबन्द रहने का अधिकार नहीं दे सकता जब तक एक सलाहकार बोर्ड ने यह स्वीकृति न दी हो कि ऐसी नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण हैं। अनुच्छेद 22(5) के अनुसार यह आवश्यक है कि निवारक निरोध के अन्तर्गत बन्दी व्यक्ति को कारणों से अवगत कराया जाए और यह अवगत दिया जाए कि वह उन कारणों को प्रत्याख्यान में चुनौती दे सके। अनुच्छेद 22(6) में व्यवस्था है कि लोकहित के आधार पर निरोध के कारण बताने से इनकार किया जा सकता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 एष 24)

(The Right against Exploitation)

अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा जबरदस्ती किए जाने वाले श्रम को निषिद्ध किया गया है पर राज्यों को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बाध्य सेवा लागू करने में रुद्धवृत्त न होगी और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 24 के द्वारा चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरों में सलग्न नहीं किया जा सकता। बाल-श्रम का निषेध करने वाले अनुच्छेद 24 का राज्य के नागरिक निर्देशक सिद्धान्त से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है जिसने 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया गया है।

अनुच्छेद 23 में 'मानव दुर्व्यापार' विस्तृत शब्दशाली है जिसमें न केवल मनुष्यों या स्त्रियों का बन्धुओं की शक्ति द्वारा-विक्रय अथवा स्त्रियों और बच्चों के अनैतिक व्यापार को निषेध किया गया है और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उनका प्रयोग न करना शामिल है।¹ संविधान के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत ससद को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 23 द्वारा वर्जित कार्यों को करने पर कानून दण्ड की व्यवस्था करे। इस शक्ति के प्रयोग में ससद ने 'Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956' पारित किया है, जिसके अधीन 'मानव दुर्व्यापार' दण्डनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 का सरलता नागरिक और अनागरिकों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद में 'दास श्रम' का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किन्तु मानव दुर्व्यापार शब्दशाली में यह निश्चित रूप से शामिल है।² 'पॉपुलर यूनिफ़ॉर्म और डेमोक्रेटिक राइट्स बनान भारत सघ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 23 के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए यह निर्णय दिया कि 'बेगार' से तात्पर्य ऐसे करने से है जिन्हें किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बिना परिश्रमिक ली जाती हो। अनुच्छेद 23 के अनुसार 'बेगार' ही नहीं बल्कि किसी प्रकार के सभी 'जबरदस्ती' लिए जाने वाले कार्य वर्जित है, क्योंकि इसमें मानव प्रतिष्ठा और गरिमा पर आधारित पहुँचता है। अनुच्छेद 23 प्रत्येक प्रकार के 'बलात् श्रम' (Forced Labour) को वर्जित करता है और यह इन दोनों में कोई अन्तर नहीं करता कि बलात् श्रम के लिए परिश्रमिक दिया गया है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है चाहे उसे परिश्रमिक दिया गया हो, वह कार्य अनुच्छेद 23 के अधीन 'बलात् श्रम' माना जाएगा। 'बलात् श्रम' में शारीरिक दबाव, विधिक दबाव के अतिरिक्त आर्थिक अटिनाइयों से उत्पन्न दबाव शामिल है।

धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

(The Right of Freedom of Religion)

भारतीय संविधान के स्वातन्त्र्य अधिकारों में धर्म-स्वातन्त्र्य के अधिकार का विशेष महत्व है। अनुच्छेद 25 से 28 एष संविधान की प्रस्तावना में संविधान-निर्माताओं की इच्छा का अभ्यास हो जाता है। भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्षता सम्बन्धी निम्नलिखित चार आदर्श हैं³—

1. राज्य स्वयं को किसी धर्म-विशेष से सम्बद्ध नहीं करेगा, न किसी धर्म-विशेष के अधीन रहेगा।
2. राज्य जब किसी व्यक्ति को धार्मिक मान्यता, आचरण एवं प्रसार प्रसार सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्रदान करेगा तो वह किसी व्यक्ति विशेष को अपेक्षाकृत (Preferential) सुविधा नहीं देगा।
3. व्यक्ति-विशेष के विरुद्ध धर्म अथवा धार्मिक विश्वास के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा।
4. राज्य के अधीन किसी पक्ष को श्राव्य करने हेतु सभी धर्मावलम्बियों को समान अवसर प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 25(1) के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उद्देश्यों के अधीन रहते हुए सभी को अनुकरण की स्वतन्त्रता तथा धर्म के अन्वेषण रूप से मान्यता, आचरण एवं प्रसार करने का समान अधिकार है, लेकिन इस अनुच्छेद में ऐसे वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव डालकर नहीं डाल सकता जो (क) धार्मिक आचरण से सम्बन्ध किसी आर्थिक, विरोध, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक क्रियाओं को निबन्धन करती हों, (ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हों, हिन्दुओं की सार्वजनिक धर्म-संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विश्वों के लिए खोलती हों। संविधान में कृपाण धारण करना सिक्ख धर्म का अंग मान लिया है तथा हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्ख धर्म या बौद्ध धर्मावलम्बियों को निर्देश सम्मिलित कर लिया है।

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रवर्धन में स्वतन्त्रता

ऐसे व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुयायी को

1. एकराहुत बनान स्टैटस रिपोर्ट्स ए. आई. आर. 1953, बन्धन 523

2. दुबल स्टैटस बनान भारत सघ ए. आई. आर. 1952, कलकत्ता 476

3. गणसहाय शर्मा : यूटीकर, पृ. 170

(क) धार्मिक और पूर्ण प्रयोजन के लिए न्यायाओं की स्थापना और पोषण का (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबन्ध करने का (ग) जगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वाधिनत्व का और (घ) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अवसर प्रदान करता है।

अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर्तों के संदाय की स्वतन्त्रता

किसी व्यक्ति को ऐसे कर्तों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।

अनुच्छेद 28 : शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अपासना में उपस्थित होने के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता

(1) राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

(2) खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किन्तु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित व्यक्ति को दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या धार्मिक अपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने या अवसर होने पर उसके सरक्षक ने इसकी सहमति नहीं दी हो।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30)

(Culture and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

(1) 'भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के नागरिकों को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।'

(2) 'राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा-संस्थान में प्रवेश में किसी नागरिक को मात्र धर्म, मूल, वर्ग, जाति भाषा के आधार पर बहिष्कार न रखा जायेगा।'

अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार

(1) 'धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।'

(2) 'शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विरोध न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।'

अनुच्छेद 29 और 30 एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, क्योंकि शिक्षा-संस्थाओं के माध्यम से यह सम्भव है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि अथवा धर्म की रक्षा कर सकें। संविधान के तहत सशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर किया गया था। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी राज्य की भाषा को सरकारी स्वीकृति प्रदान करे। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह यह प्रयत्न करे कि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उनकी मातृ-भाषा में दी जाए। राष्ट्रपति को ऐसे निर्देश देने का अधिकार है। उसे यह अधिकार है कि भाषायी अल्पसंख्यक समूहों की समस्याओं के निराकरण के लिए वह विशेष अधिकारी नियुक्त करे।

संविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)

(Right to Constitutional Remedies)

संविधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण उपबन्ध है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था—“यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन-सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा तो मैं इसके (अनुच्छेद 32) सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है।”¹ ये शब्द संविधानिक उपचारों के अधिकारों के सम्पूर्ण महत्व को स्पष्ट कर देते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के अतिक्रमण पर उठे प्रवर्तित कराने के लिए संविधानिक उपचार उपलब्ध कराए गए हैं।² अनुच्छेद 32 जो संविधानिक उपचार का अधिकार देता है, संविधान के भाग 3 में होने के कारण स्वयं एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 32(1) नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाही द्वारा प्रवर्तित करने के लिए अधिकार की गारंटी करता है।

1. संविधान सभा की कार्यवाही। भाग 7, पृ. 833.

2. गंगासहाय शर्मा। पृथिवी, पृ. 189

अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित निर्देश या रिट, जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उद्देयण रिट सम्मिलित हैं, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 32(3) के अधीन ससद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपनी उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्ड (2) के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकेगी।

अनुच्छेद 32(4) यह उपबन्धित करता है कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा गारण्टी किए गए अधिकारों को निलम्बित किया जाएगा।¹ अनुच्छेद 32 को चार खण्डों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता संविधान का 'आधारभूत ढाँचा'² (Basic Structure) है, अतः इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित करके नहीं किया जा सकता है जब तक कि केशवानन्द भारतीय का निर्णय उलट नहीं दिया जाए।³ अनुच्छेद 32 के अधीन समुचित संविधानिक उपचार देने की शक्ति विवेकीय (Discretionary) नहीं है, अर्थात् यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल अधिकार के अतिक्रमण को दिखाने में सफल होता है तो वह उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अधीन एक अधिकार के रूप में समुचित उपचार देने का अधिकारी होगा।⁴ भारतीय उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामान्य अधिकार दिए जाने के साथ बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-warranto) तथा उद्देयण लेख (Certiorari) जारी करने जैसे विशेष उपचारों के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है जिसका विस्तृत विरलेषण निम्नांकित है—

(I) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)—'हैबियस कॉर्पस' का शाब्दिक अर्थ है 'शरीर प्रस्तुत करना।' इस रिट द्वारा न्यायालय उस व्यक्ति को संशयित अपने सामने उपस्थित करता है जिससे न्यायमय उसके कारागार के कारणों को जान सके और यदि बन्दी रखने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। यह रिट किसी व्यक्ति या अधिकारी को धम्कीपत्र हो सकती है जिसकी अभिरक्षा में कोई व्यक्ति है। रिट को अवहेलना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। यह स्मरणीय है कि किसी को निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है तो न्यायालय उक्त लेख जारी नहीं कर सकता है।

(II) परमादेश (Mandamus)—अंग्रेजी शब्द 'मैन्डमस' का अर्थ है 'हम आज्ञा देते हैं।' न्यायालय के द्वारा आदेश द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके कर्तव्य पालन की आज्ञा दी जाती है। यह आदेश उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय किसी सार्वजनिक संस्था या सार्वजनिक पदाधिकारी को अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए बिबहा करना चाहता है।

प्राप्त में, परमादेश उन अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिया जा सकता है जो किसी लोक कर्तव्य के लिए आवश्यक और सरकार के विरुद्ध, क्योंकि अनुच्छेद 226 और 361 में यह उपबन्ध है कि समुक्त सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाहियों की जा सकती है। यह रिट, अलग-अलग व्यक्तियों और अन्य व्यक्ति विभागों के विरुद्ध राज्य की जा सकती है। यदि वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। परमादेश निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए नहीं दिया जाएगा—

(क) राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने हेतु किए गए या किए जाने के लिए उत्तरदायी किसी कार्य के लिए।

(ख) परमादेश संविधान या अधिनियम कानूनी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिए निरी व्यक्ति या निग्रय के विरुद्ध नहीं किया जा सकता चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, चाहे राज्य की प्रादेश पञ्चवार के माघ दुराभिसंधि ही क्यों न हो।

(III) प्रतिषेध (Prohibition)—प्रतिषेध का अर्थ है 'मना करना'। यह लेख उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीन न्यायालय को जारी किया जाता है जिसका उद्देश्य अधीन न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना होता है। प्रतिषेध और परमादेश की रिटों में अन्तर यह है कि परमादेश कुछ कार्य करने

1. जननरपण पन्डेय; पृष्ठ 243

2. कर्टीलपुत्रा कॉरोरिशन कमण्ड एच बरनर बाल सच ए, आई और 1981, सुप्रीम कोर्ट 345

3. जननरपण पन्डेय; पृष्ठ 243

4. उपबन्दी बरन मद्रास एच ए, आई और 1975, सुप्रीम कोर्ट 623

5. दुर्गातल नमु; बाल का संविधान — एक परिचय पृष्ठ 127

का समावेश करती है जबकि प्रतिषेध निष्क्रिय बनाती है। परमादेश न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उपबन्ध है जबकि प्रतिषेध ऐसे लोक अधिकारों के विरुद्ध नहीं दी जाती जो न्यायिक कृत्य नहीं करता।

(iv) उद्योग लेख (Certiorari)—इस लेख का अर्थ है—'और अधिक सूचित होना'। यह लेख उच्च न्यायालयों द्वारा किसी अधीन न्यायालय के लिए भेजा जाता है जिसमें अधीन न्यायालय से उस मामले से सम्बन्धित कागजातों को माँगा जाता है जो अब तक उस अधीन न्यायालय में विचाराधीन थे। प्रतिषेध लेख और उद्देश्य लेख में अन्तर यह है कि प्रथम तो रोग के रूप में होता है जबकि दूसरा उपचार के रूप में होता है।

(iv) अधिकार-पत्रा (Quo-warranto)—इस लेख का अर्थ है कि किस आज्ञा से न्यायालय इस लेख के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकता है जिसके लिए वह कानून योग्य नहीं है।

भारतीय संविधान में इन लेखों को सम्मिलित करके व्यक्ति को स्वतन्त्रता सुनिश्चित कर दी गई है। संविधान लागू होने पर ये अधिकार मौलिक कानून का अंग बन गए और अब संविधान संशोधन किए बिना उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किन्तु संसद किसी न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार न्यायाधिकार सीमा में प्रयुक्त करने देती है। संवैधानिक उपारों का अधिकार किसी घोषित सफ़टकाल को छोड़कर स्थगित नहीं किया जा सकता, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह अधिकार सम्पूर्ण भारत में स्थगित हो जाए। इन्हें स्थगित करने का अधिकार अनिश्चित नहीं होता है। यद्यपि केन्द्र के कार्यपालक प्रधान को इन अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है, तथापि यह आदेश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संसद इसे अस्वीकार कर सकती है। सफ़टकाल समाप्त होते पर ये अधिकार पुनः लागू हो जाते हैं।

संवैधानिक उपचार के अधिकार का निलम्बन

अनुच्छेद 32(4) के अनुसार संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित परिस्थिति को छोड़कर संसदित अधिकारों को निलम्बित नहीं किया जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति आपातकालीन स्थिति से उत्पन्न होती है जबकि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलम्बित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन जब भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता का अधिकार स्वतः निलम्बित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सम्पूर्ण भारत में अथवा भारत के किसी भाग में आपातकाल में किसी निश्चित समय के लिए भाग 3 में उपबन्धित मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के संवैधानिक उपचार को निलम्बित कर सकता है। संवैधानिक उपचार के अधिकार के निलम्बन से नागरिक स्वतन्त्रताएँ प्रभावित होती हैं। इससे देश में निरंकुश शासन की आशंका उत्पन्न हो जाती है।

मौलिक अधिकार : एक समीक्षा

(A Critical Evaluation of Fundamental Rights)

एच. वी. पापली के अनुसार मौलिक अधिकारों के आलोचकों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—प्रथम वे जिनके अनुसार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार नाममात्र हैं क्योंकि जिन अधिकारों को मौलिक अधिकारों में स्थान पाना चाहिए उन्हें माना नहीं गया, जैसे काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि। दूसरे वे जिनके कथनानुसार निवारक निरोध (Preventive Detention) तथा संविधानिक अधिकारों के स्थान आदि असाधारण उपबन्धों से इस अध्याय का सार विलुप्त हो चुका है। इनका कहना है कि संविधान एक हाथ से देता है, वह दूसरे हाथ से छीन लेता है। तीसरे आलोचक वे हैं जो कहते हैं कि जिन अधिकारों को प्रत्याभूत करने का प्रयास किया गया है वे इतनी अर्द्धताओं, अपवादों में बँधे हैं कि यह सम्पन्ना कठिन है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकारों में क्या मिला। एक आलोचक ने धम्मपूर्वक यह कहा है कि मौलिक अधिकार अध्याय का नाम बदल कर 'मौलिक अधिकारों की परिसीमाएँ' अथवा 'मौलिक अधिकार एवं इनकी परिसीमाएँ' रख देना चाहिए।

मौलिक कर्तव्य

(Fundamental Duties)

चीन, इटली, जापान, नीदरलैंड्स आदि कुछ गैर साम्यवादी देशों के संविधानों में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। भारत के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया था लेकिन मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, इसी मध्यता के कारण कि अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग (4) के पश्चात् एक नया भाग (4-ब) जोड़कर संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट कर दिया गया है। इसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है—संविधान के अनुच्छेद 51-क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि—

1. संविधान का शालन करे और इसके आदर्शों, सपनाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे।

2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अशुण्य बनाए रखें।
4. देश की रक्षा करें और आझान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत में समरसता और समान प्रावृत्त की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश की रूढ़ि पर आधारित भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी मिश्रित (Composite) संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण (Environment) की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और धन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्द्धन करें तथा प्राणी के प्रति दया भाव रखें।
8. वैधानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जनार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रगल्भ और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू लें।

मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था के पक्ष में तर्क

भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्य सूचकत्व की व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले हैं, यदि उनका पालन किया जाए। राष्ट्रीय जीवन का उच्च-स्वरीय बनाने की दृष्टि से वैयक्तिक एवं सार्वजनिक रूप में योग्यता तथा श्रेष्ठता प्राप्त करने का कर्तव्य महत्वपूर्ण है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश करने से मौलिक अधिकारों की स्थिति सुदृढ़ होगी, देश के नागरिक उचित उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर कार्य करेंगे। फलस्वरूप देश की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा में मौलिक कर्तव्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो नागरिकों में अधिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर सक्रिय राष्ट्र की भावना साकार करती है।

मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था के विपक्ष में तर्क

डॉ. इकबाल नारायण के अनुसार¹—

1. मूल कर्तव्यों की व्यवस्था में जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उससे यह सम्भव है कि शासन उसकी आड़ में लोगों को अनावश्यक रूप से तंग कर सके। उदाहरणार्थ, संविधान के पालन के कर्तव्य के नाम पर लोगों को उसकी व्यवस्थाओं के प्रति मर्यादित व्यक्त करने से रोका जा सकता है। भारत की प्रभुता की मान्यता के नाम पर शासन द्वारा प्रभुता पर अनावश्यक बल दिया जा सकता है तथा इसके कार्यों की आलोचना एवं विरोध को संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है। 'धार्मिक, भाषायी क्षेत्रीय एवं वर्गीय विभिन्नता एवं सद्भावना, मिश्रित संस्कृति, जीवधारियों के प्रति सहानुभूति तथा सुधार की भावना' आदि ऐसे विचार हैं जिनका सर्वसम्मत अर्थ नहीं तथा इनके आधार पर शासन एवं व्यक्तियों तथा विविध समुदायों एवं वर्गों में अनावश्यक टकराव हो सकता है²। शासन की ओर से जनता के साथ कठोर व्यवहार किया जा सकता है।

2. अनेक मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें न समझा जा सकता है और न उनका पालन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, स्वतन्त्रता संग्राम के आदर्श विविध प्रकार के थे। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से समझ सकता है। मिश्रित संस्कृति ऐसी है। वैधानिक दृष्टिकोण, मानवता आदि से सम्बन्धित कर्तव्य ऐसे हैं जो साधारण व्यक्ति की बुद्धि से परे हैं।

3. अनेक मूल कर्तव्य व्यावहारिक न होकर आदर्शवादी हैं। उदाहरणार्थ, सौहार्द, भाईचारे की भावना, अहिंसा तथा मानवता के सम्बन्धों को ले सकते हैं, जो आदर्शों की वस्तुएँ हैं तथा जिन्हें व्यवहार में क्रियान्वित किया जाना सम्भव नहीं है।

4. राष्ट्रीय आन्दोलन के आदर्शों के पालन, वैधानिक तथा मानवीय दृष्टिकोण के विकास तथा सांस्कृतिक विभिन्नता के आदर सम्बन्धी ऐसे कर्तव्य हैं, जिनका पालन कराने के लिए कानूनी व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

संविधान में जिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख है उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो उनका महत्व और कम होता प्रतीत होता है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता एन. ए. पासकीन्सला के अनुसार, "संविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्य नागरिकों के अधिकार में निहित हैं अर्थात् जब कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उस पर यह कर्तव्य रोपित हो जाता है कि वह उस देश के राष्ट्रीय ध्वज, गान और संविधान का आदर तथा पालन करे तथा देश की प्रभुता, एकता और अखण्डता को बनाए रखे। इस दृष्टि से अनुच्छेद 51-ओ के कोष्ठक क, ख, ग, घ में उल्लिखित कर्तव्यों का संविधान

में वर्णन करना अनिवार्यक प्रतीत होता है।" शेष मूल कर्तव्यों में ऐसे कर्तव्य हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मूल अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। उदाहरणार्थ वर्ण भाषा तथा प्रदेश या वर्ग के आधार पर आपस में भेदभाव न करना, अनुच्छेद 14, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत अन्य जीव सम्मिलित हैं रक्षा करो का कर्तव्य अनुच्छेद 48 तथा ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करने का उल्लेखित अनुच्छेद 40 में पाया जाता है और यह आशा की जाती है कि सरकार नीति-निर्देशक अनुच्छेदों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण करेगी। उन कानूनों का पालन करना नागरिक का कर्तव्य होगा। नीति-निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन का स्वाभाविक परिणाम नागरिकों द्वारा उन कर्तव्यों का पालन करना होगा। मूल कर्तव्यों में एक व्यावहारिक कठिनाई यह है कि ये कर्तव्य अस्पष्ट अनिश्चित तथा काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

(3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त

(The Directive Principles of State Policy)

राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय सविधान की विशेषता है। इन सिद्धान्तों का वर्णन सविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इनका मूल लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के आदर्श तथा देश के शासन के आधारभूत सिद्धान्त भी हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार सविधान के भाग 4 में दिए गए उपबन्ध किसी न्यायमय द्वारा प्रवर्तनीय न होंगे किन्तु इनमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये निर्देशक तत्व अपनी रूपरेखा में सजीले एवं व्यापक हैं अतः देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल उन्हें ढाला जा सकता है। इन तत्वों में किसी दल-विशेष की विचारधारा को नहीं अपनाया गया है। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का उल्लेख है और देश में प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर इन्हें लागू करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में राज्य और समाज के धार्मिक स्वरूप की रूपरेखा पाई जाती है जिनका मूल लक्ष्य देश में शोषणमुक्त और संगतमुक्त लोकतांत्रिक समाजवादी और धर्म-निरपेक्ष गणराज्य की स्थापना पर लोक-कल्याणकारी राज्य की भावना को साकार करना है।

निर्देशक सिद्धान्त सवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 36 से 51)

सविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तदनुसार राज्य के अन्तर्गत भारत सरकार और समस्त तथा राज्य सरकार और विधान-मण्डल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

अनुच्छेद 37 के अनुसार निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होने पर देश के शासन में मूलभूत हैं।

अनुच्छेद 38 व्यवस्था देता है कि लोक-कल्याण की दृष्टि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 44वें सविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में एक नया खण्ड (2) जोड़कर एक नया निर्देशक तत्व जोड़ा गया है जो यह उपबन्धित करता है कि राज्य प्रयास करेगा कि विशेष रूप से व्यक्तियों को आय में असमानता कम हो पद सुविधाओं और अवसरों के सम्बन्ध में व्यक्तियों में नहीं, बरन् विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले या विभिन्न व्यापार में लगे सभी वर्गों में असमानता दूर हो।¹

अनुच्छेद 39 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व

राज्य द्वारा अनुसूचित जाति, जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मूलजन्म, क्षेत्र, धर्म—

- (क) नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो
- (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार विभाजित हो ताकि सामूहिक हित का साधन हो
- (ग) आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत धन और उत्पादन के साधनों का सर्व-साधारण के लिए अधिकारी कन्द्रीकरण न हो
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो
- (ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति बाधकों की सुकुम्हार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा अधिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो

(च) बालकों की स्वतंत्र और गतिमय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें दी जायें तथा शौर्य और किशोर अवस्था का शोषण से नैतिक और आर्थिक परिणाम से सशुद्ध हो।

अनुच्छेद 39 क - समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता—उत्पन्न यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र समान अवसर के अन्तर्गत पर न्याय सुलभ करके और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्धनता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान द्वारा या किसी उचित में निःशुल्क सहायता की व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 40 : प्रम पदावतों का संगठन—उत्पन्न प्रम पदावतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त गणम का इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाएँ।

अनुच्छेद 41 कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पाने का अधिकार - उत्पन्न अपनी आर्थिक सम्पत्ति और विकास की संभावनाओं के भीतर काम, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्ति तथा अन्य अपाव की दशाओं में सर्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्य ठगव्य करेगा।

अनुच्छेद 42 काम की न्याय रक्षा मानवोचित दशाओं तथा प्रभुत्व सहायता ठगव्य - उत्पन्न काम की यथेष्ट और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रभुत्व सहायता के लिए ठगव्य करेगा।

अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह-मजदूरी कार्य : उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा अथवा किसी दूसरे प्रकार से उत्पन्न कृषि उद्योग तथा अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवकाश का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा तथा प्रयोग में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी अन्तर्गत अन्तर्गत पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रत्येक में कार्यकर्तों का भाग लेना - उत्पन्न किसी उद्योग में नये हुए उद्योगों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रत्येक में कार्यकर्तों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य उचित से कदम उठाएगा।

अनुच्छेद 44 : श्रमिकों के लिए एक समान व्यवहार सहिता - प्रत्येक में समस्त उत्पन्न-क्षेत्र में नागरिकों के लिए उत्पन्न समान व्यवहार-सहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 45 : बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अवकाश : उत्पन्न संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कम आयु के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ठगव्य करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की रक्षा - उत्पन्न जनता के दुर्बलतम वर्गों के विशेषतः अनुसूचित आदिम-जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा का सामाजिक न्याय और रक्षण से उनका साधन करेगा।

अनुच्छेद 47 : आहार-पुष्टि और जीवन-स्तर ठीक करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का उत्पन्न का कर्तव्य - उत्पन्न लोगों के आहार-पुष्टि-जन और जीवन-स्तर को ठीक करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतः मदक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोगों से अतिरिक्त उपयोग का प्रतिरोध करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 48 : कृषि और पशुपालन का संरक्षण - उत्पन्न कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से सज्जित कर गन्दी, बड़ोई अन्य दुष्ट और बाधक पशुओं की नष्ट के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिरोध करने के लिए अग्रसर होगा।

अनुच्छेद 48 क - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा - उत्पन्न दत्त के पर्यावरण के साधन तथा संवर्धन का और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण - विधि के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारक या ऐतिहासिक अभिलेख वाले प्रत्येक स्मारक स्थान, वस्तु या पदार्थ, स्तूप, विमान, विमान, अमर, व्यक्त अथवा निर्मित से रक्षा करना उत्पन्न का अन्तर्गत होगा।

अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका से व्यापारपालिका का पृथक्करण : उत्पन्न की लोक सेवाओं में व्यवस्थित का कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए उत्पन्न अग्रसर होगा।

अनुच्छेद 51 : अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुशास की रक्षा : (क) राष्ट्रीय के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का (ख) संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि-व्यवस्था के प्रति अग्रसर बढ़ाने का (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रयत्न करने का प्रयास करेगा।

नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में अंतर

नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार हमारे संविधान की अन्तर्गता हैं जिनका सत्य देश में सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक गणराज्य की भावना को साकार करना है। दोनों भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता के प्रताक हैं तथापि दोनों के मध्य निम्नांकित अंतर है—

1 मूल अधिकार नकारात्मक हैं क्योंकि ये राज्य पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं क्योंकि ये राज्य को किसी निश्चित कार्य को करने का आदेश देते हैं।

2. मूल अधिकार वाद योग्य (Justiciable) हैं निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा वादयोग्य नहीं दी जा सकती। ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि-निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग राज्य का कर्तव्य है। दूसरी ओर मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं अर्थात् ये मूल अधिकार से असंगत किसी कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं लेकिन कोई विधि इस आधार पर अवैध घोषित नहीं की जा सकती कि यह निर्देशक तत्वों के विरोध में है और न ही न्यायालय सरकार के इन तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए आदेश दे सकते हैं।

3 मूल अधिकारों का विषय व्यक्ति है निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं। ये राज्य को नैतिक निर्देश देते हैं कि वह सार्वजनिक हित के लिए इन्हें लागू करे।

4 मूल अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए हैं जबकि निर्देशक तत्वों का उपयोग नागरिक तभी कर सकते हैं जब राज्य विधि इन्हें कार्यान्वित करे।

5 निर्देशक तत्वों का क्षेत्र मूल अधिकार के क्षेत्र से व्यापक है। मूल अधिकारों का क्षेत्र भारत-राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत है जबकि निर्देशक तत्वों में अन्तर्प्रद्वीप महात्त्व के सिद्धान्त तथा विश्व-व्युत्पन्न और विश्व शान्ति का संदेश अन्तर्निहित है। ग्लैडहिल (Gladhill) के अनुसार 'नैतिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध आशय (Negative Injunctions) हैं। राज्य के निर्देशक सिद्धान्त यह बतलाते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए।

न्यायालयों का दृष्टिकोण (Judicial View)

सन् 1971 में संविधान के 25वें संशोधन के पारित होने से पहला निर्देशक सिद्धान्तों के प्रति न्यायालयों के दृष्टिकोण को निम्नानुसार तीन वर्गों में रखा जा सकता है—

(क) मूल अधिकारों को निर्देशक तत्वों से उच्च मानने का न्यायिक निर्णय—न्यायाधीशों का तर्क यह है कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं अतः ये कम महत्वपूर्ण हैं मूल अधिकारों के अधीन हैं और उन्हें अधीन रहना चाहिए। न्यायालयों के निर्णय इस सम्बन्ध में निम्नांकित मुक्तियों में दिए गए थे—

1 खन्नाबम दोरायजन बनाम प्रदास राज्य का यह पहला मामला था जिसमें संविधान के लागू होने के बाद मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी गई। प्रदास राज्य ने एक आदेश जारी किया जिसमें राज्य के मेडिकल और इन्वीनिपेरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए विभिन्न समुदायों के लिए स्थानों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया गया। आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह वर्ण या जाति के आधार पर लोगों को कॉलेजों में प्रवेश का प्रवधान करता है और इसमें अनुच्छेद 15(1) तथा 29(2) में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन है। पिटीशनर को बाह्य होने के नाते कॉलेज में प्रवेश से इनकार कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदास राज्य के आदेश का अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध होने के कारण अवैध घोषित किया। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों वाले अध्याय के अनुकूल होना चाहिए और उससे सहायक के रूप में रहना चाहिए। न्यायमूर्ति एस. आर. दास के अनुसार, "राज्य-नीति के निर्देशक तत्व किन्हीं स्पष्ट अनुच्छेद 37 द्वारा न्यायालयों में वाद योग्य नहीं माना गया है संविधान के तीसरे भाग में दिए गए उपबन्धों का अतिक्रमण नहीं कर सकते।"

2 सी. सी. आर. श्रीनिवास बनाम प्रदास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उसी प्रकार के विचार प्रकट किए जो चम्पाकम के मामले में किए थे।

3 गोलकनाथ बनाम बंजारा राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की दलील कि यह बदलती हुई जन-आवृत्तियों के अनुसार निर्देशक तत्वों को लागू कर सकती है को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि "निर्देशक तत्वों को तीसरे भाग द्वारा व्यवस्थित स्वयं नियंत्रित करने वाले यंत्र (Self Regulating Machinery) के भीतर लागू किया जा सकता है।"

4 'मुहम्मद हमीद कुरेशी और अन्य बनाम बिहार राज्य' में बिहार पशु प्रारक्षण और मुगार अधिनियम 1955 के कुछ उपबन्धों की विधि-मान्यता पर विचार करते हुए न्यायाधीश एस. आर. दास ने चम्पाकम दोरायजन मामले में की

गई इस मुक्ति का आश्रय लिया कि संविधान के चौथे भाग में निर्धारित राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्तों को संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मूल अधिकार और उसके अधीन रहना होता है।

(ख) मूल अधिकारों तथा निर्देशक तत्वों को एक-दूसरे के पूरक मानने सम्बन्धी निर्णय—

1. 'बिहार राज्य बनाम कामेश्वरप्रसिंह के मामले' में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 39 पर बल देते हुए यह निर्णय दिया कि जमींदारी उन्मूलन 'लोक प्रयोजन' के लिए पारित किए गए हैं अतः संविधानिक हैं। न्यायाधीश महामन के अनुसार "संविधान के चौथे भाग में दिए गए उपबन्ध तीसरे भाग में दिए गए उपबन्धों का प्रतिपूरण करते हैं और ये दोनों मिलकर कल्याणकारी लोकतन्त्रात्मक राज्य के निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत करते हैं।"

2. 'सम्बन्धसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान' के मामले में न्यायाधीश मधोलकर ने कहा कि निर्देशक तत्व देश के शासन के आधारभूत सिद्धान्त हैं और संविधान के भाग 3 के उपबन्ध इन सिद्धान्तों के साथ समझे जाने चाहिए।

3. 'छन्द भवन बोर्डिंग एण्ड लोडिंग बगलौर बनाम मैसूर राज्य और अन्य' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मत रहा कि "यह सोचना मिथ्या धारणा है कि हमारे संविधान के अधीन अधिकारों की व्यवस्था है कर्तव्यों का नहीं, जबकि तीसरे भाग में प्रदान किए गए अधिकार मूल अधिकार हैं। चौथे भाग में दिए गए निर्देश देश के शासन में मूलभूत हैं। संविधान के तीसरे और चौथे भाग में दिए गए उपबन्धों में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है, ये एक-दूसरे के पूरक हैं। चौथे भाग के उपबन्ध विधान-मण्डल और सरकार को नागरिकों पर विभिन्न कर्तव्य अर्पित करने योग्य बनते हैं। संविधान का प्रदेश एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें हमारे राष्ट्रीय जीवन की समस्त समस्याओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुप्राणित करेगा। अगर हमारे नागरिकों के निम्नतम वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता तो संविधान में दी गई आशर्त और आकर्षण झूटी सिद्ध होंगी।"

(ग) ये न्यायिक निर्णय, जिनमें मूल अधिकारों पर प्रतिबन्धों को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक तत्वों का सहारा लिया गया—इस प्रकार के निर्णयों में न्यायालयों ने मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को महत्व दिया है। कुछ उल्लेखनीय मामले निम्नलिखित हैं—

1. 'एस. नायपज फन्सवी बनाम टी स्टेट ऑफ ट्रान्स्कार बोर्न' के मुकदमे में न्यायिक निर्णय में स्वीकार किया गया कि परानियम एक निर्देशक सिद्धान्त है जो अनुच्छेद 19(1) (छ) पर युक्तिपूर्ण निर्बन्धन अर्थात् प्रतिबन्ध लगाता है। मुकदमे में अनुच्छेद 19(1) छ के अनुसार कोई बुद्धि उपनिवेश व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर लागू होने वाले निर्बन्धों (प्रतिबन्धों) की वैधता का प्रश्न था।

2. 'बुगलकिशोर बनाम लेबर कमिशनर' के मुकदमे में अनुच्छेद 19(1) (छ) पर लागू होने वाले युक्तिपूर्ण निर्बन्धनों के क्षेत्र का प्रश्न था। न्यायिक निर्णयों में स्वीकार किया गया कि जनहित में इस अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने इन प्रतिबन्धों का जिक्र करते हुए अनुच्छेद 41, 43 तथा 46 में दिए गए निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया।

न्यायालय का दृष्टिकोण सम्पन्ननुसार बदलता रहा है अतः 25वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर अनुच्छेद 31-ग को जोड़ा गया। इसके दूसरे भाग में यह कहा गया कि यदि अनुच्छेद 39 (छ) और 39 (ग) में वर्णित निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए व्यवस्था की गई है (जिसमें यह धोखा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावित करने के लिए है) तथा उसके कारण मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक न्यायन्य की शरण में नहीं जा सकेंगे, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के 'केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य' वाले मामले के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31-ग के इस दूसरे भाग को अवैध ठहरा दिया। फलस्वरूप नागरिकों के लिए न्यायालय की शरण लेना सम्भव हो गया और न्यायालय यह जांच करने में सक्षम हो गया कि कोई कानून अनुच्छेद 39 (छ) एवं 39 (ग) में वर्णित निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 31-ग का पहला भाग वैध है जो कहता है कि 'अनुच्छेद 13 में किसी तत्व के न होते हुए भी कोई विधि जो अनुच्छेद 39 के खण्ड (छ) या खण्ड (ग) में उल्लिखित तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावित करने वाली हो इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है उसे संशय का न्यून करती है।' सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में 24वें, 25वें और 19वें संशोधन को वैध ठहराया (किन्तु अनुच्छेद 39-ग के दूसरे भाग को छोड़कर) इस मामले में अपना निर्णय देते हुए न्यायाधीशों हेगड़े और मुखर्जी ने कहा था—

"निर्देशक तत्वों के महत्व को कोई इनकार नहीं कर सकता है—संविधान का भाग 4 ठीक सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति को लाने के लिए बनाया गया था जिसकी पूर्ति स्वतन्त्रता के बाद होने की भाँति थी। संविधान का उद्देश्य कुछ स्वतन्त्रताओं की गारंटी देते से नागरिकों को ही नहीं, बल्कि सब नागरिकों को देना है। संविधान में हमारे समाज की कल्पना उसके सम्पूर्ण रूप में की गई और इसमें यह ध्यान रखा गया कि समाज का प्रत्येक सदस्य प्रत्यक्ष स्वतन्त्रताओं

में भाग ले। भाग 4 की उपेक्षा करने का अर्थ है संविधान में उपस्थित शक्ति राष्ट्र को दिखाई गई आशाओं तथा उन आदर्शों की उपेक्षा करना है जिन पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। निर्देशक तत्वों का निष्ठापूर्वक चालन किए बिना संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति असम्भव है।"

कुछ नवीनतम न्यायिक निर्णय

'रणधीर सिंह बनाम भारत सभ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिनियमित किया है कि यद्यपि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, वरन् केवल निर्देशक तत्व है, किन्तु यह एक सार्वजनिक तथ्य है और अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) है। रजन द्विवेदी बनाम भारत सभ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्देशक तत्व प्रथमतः विधान-मण्डल और कार्यपालिका के लिए निर्देश (Directives) हैं किन्तु न्यायालय भी इस निर्देश से बाध्य है। न्यायालयों का यह परम कर्तव्य है कि वे संविधान का इस तरह निर्वहन करें ताकि निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित किया जा सके और इनमें सामाजिक लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत अधिकारों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

निर्देशक तत्वों की आलोचना

प्रो. के. टी. राव के अनुसार "राज्य नीति के ये निर्देशक तत्व एक ऐसे चैक के समान हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।" कुछ आलोचकों ने निर्माताओं की पवित्र भावनाओं और आकांक्षाओं का समझ-भार कहा है उन्हें 'धोखे बजनों' की सज़ा दी है। नीति निर्देशक सिद्धान्तों की आलोचना में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

1. ये तत्व वाद योग्य नहीं हैं अतः इनके पीछे कोई बाध्यता नहीं है। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन्हें कहीं तक लागू करता है। ये राजनीतिक धोखेबाज़ी मात्र हैं।

2. इन तत्वों में वर्णित अनेक विषय अनिश्चित और अस्पष्ट हैं। उदाहरणार्थ, सम-जवादी सिद्धान्तों में श्रमिकों और मालिकों के पारस्परिक सम्बन्धों की निश्चित व्यवस्था नहीं है और न ही राष्ट्रीय योजनाओं का कोई विवरण दिया गया है।

3. कुछ ऐसे तत्व बताए गए हैं जिनका पालन व्यवहार में असम्भव है, जैसे—सद्यन्विषेध। इस प्रकार के तत्वों या सिद्धान्तों का अनुपालन न होने से अन्य सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा कम हो जाती है।

4. संविधान में कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाना था। उदाहरणार्थ, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी थी, किन्तु 53 वर्षों के बाद भी सभे राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया है। इसी प्रकार उत्पादन और वितरण के साधनों की न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकी है।

5. निर्देशक तत्वों का संविधान में समावेश कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण किया गया था। देश के कुछ राज्यों की यह भाँति थी कि संविधान में शिक्षा सम्बन्धी, विज्ञान सम्बन्धी और बेकारी सम्बन्धी अधिकारों को सम्मिलित कर दिया जाए तथा यथासम्भव उन्हें मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्थान दिया जाए। राजनीतिक सरोप एवं उनकी हथकड़ी के लिए निर्देशक सिद्धान्तों की व्यवस्था की गई है।

6. कुछ निर्देशक तत्वों की मूल अधिकारों के अभ्यास में रचना उचित या यथा—काम करने का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा आदि।

7. संविधान-सभा में कांग्रेस का प्रचण्ड बहुमत था, अतः निर्देशक तत्वों पर कांग्रेस की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

8. मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में द्वन्द्व की स्थिति है।

9. निर्देशक तत्वों के सम्बन्धों में दिए गए न्यायिक निर्णय बदलते रहे हैं और नौकरशाही तथा जनता के बीच तनाव के बिन्दु बनते रहे हैं।

10. निर्देशक तत्वों के अभ्यास में लक्ष्यों की चर्चा है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों की नहीं। जब तक साधन स्पष्ट नहीं होते हैं, तब तक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है।

11. आइब्रा जैनिस के अनुसार निर्देशक तत्व किसी निश्चित और संगतपूर्ण दर्शन पर आधारित नहीं हैं, ये समुचित रूप से क्रमबद्ध और वर्गीकृत नहीं हैं।

12. निर्देशक तत्वों की कार्यान्विति की प्रगति धीमी है, अतः संविधान में इन्हें स्थान देने की उपयोगिता संदेहास्पद हो जाती है। संविधान के लागू होने के 53 वर्षों के पश्चात् आज देश में व्याप्त गरीबी और विपन्नता की स्थिति सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न तथा आर्थिक विषमता की स्थिति नीति निर्देशक सिद्धान्तों के महत्व के आगे प्रश्न विह्वल करता है।

13 अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि संप्रति देश में एक सामान्य व्यवहार स्थापित होना चाहिए जिस मुसलमान अल्प धर्म के विपरीत मान्य है तथा उसका प्रचलन विरोध कर रहे हैं।

निर्देशक तत्वों की उपलब्धियाँ

निर्देशक तत्वों की उपयोगिता सावधानिक महत्ता और पवित्रता निर्विवाद है जिसके लिए निम्नलिखित तत्व दिए जा सकते हैं—

(क) ये तत्व देश में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लाने के लिए राज्य के माध्यमिक हैं। संघर्ष का गुलाम और शोषण के बाद देश आज़ाद हुआ अतः आर्थिक और सामाजिक समुदाय सामान्य में कुछ दशकों की योजना स्थापनिक है।

(ख) निर्देशक तत्वों का कार्यनिर्वाह के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किए गए जन-हितकारी कार्य ऐसे प्रमाण हैं।

(ग) संविधान के पञ्चासवें संशोधन के बाद मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धान्तों में द्वन्द्व समाप्त हो गया है।

(घ) निर्देशक तत्व देश के कल्याण की भावना को दृष्टिगत रखकर संविधान में रख गए हैं। ये तत्व प्रतिशतानुसार के घोषित हैं। इन पर ध्यान में पूर्ण राष्ट्रीय महत्त्व का स्थिति है। देश के सभी राजनयिक तत्व एक ही राजनीतिक अस्तित्व इनकी उपयोगिता पर एकमत हैं।

(ङ) काम करने का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा आदि के निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों में गिनना भ्रम इच्छित नहीं था कि भारत की आर्थिक स्थिति इसके लिए उपयुक्त नहीं है, अतः सामाजिक निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में सम संविधान में रखा जाना उपयुक्त है।

(च) नव निर्देशक तत्वों के महत्त्व को उपलब्धियों के रूप में नहीं मानना चाहिए। उनका प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम और माध्यमिक प्रकाश-प्रमाण के रूप में है।

(छ) भारतीय जनता का बहुमत इनका साथ एकजुट हो चुका है। वह इनका प्रति विश्वस्त तत्व मानता है।

(ज) निर्देशक सिद्धान्त सार्वभौमिक दल सार्वभौमिक दल के लिए व्यवहार की नियमन (Code of Conduct) है जो विश्वस्त मिलते हैं कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल सार्वभौमिक दल न हो वह जनता के कल्याण के लिए इन सिद्धान्तों के अनुसरण अपनी नीति का निर्धारण करेगा। यदि कोई सरकार अपने शासन में इन सिद्धान्तों का अभाव करता है तो उस पर कठोर विधान-मंडलों में बन्ने सम्पूर्ण देश में प्रचलन विरोध का सामना करना पड़ेगा और उनके लिए सार्वभौमिक बन रहना कठिन हो जाएगा। हमें जो पदार्थ के अनुसार "इन निर्देशक सिद्धान्तों से दूर होकर कोई सार्वभौमिक दल निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेख नहीं कर सकता, ये उनके व्यवहार की नियमन हैं।"¹

(झ) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त इस दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं कि ये भारत में वास्तविक लोकतंत्र के विकास का विश्वास मिलते हैं। इनका मूल उद्देश्य भारत में आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना है कि जिसके माध्यम से लोकतंत्र स्थिर बन सके।

(ञ) कानूनी ऋण के अभाव के बावजूद इनके पीछे भारतीय जनमत की शक्ति है।

(ट) निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रत्येक आर्थिक के अनुसार, "भारतीय संविधान प्रणाली और संवैधानिक रूप में एक सामाजिक दस्तावेज़ है। इसके अधिष्ठाता उपस्थापना या तो प्रत्यक्ष सामाजिक क्रान्ति के उद्देश्य की पूर्ण करने के लिए आवश्यक दशाओं का स्वयंसेवक बन कर सामाजिक क्रान्ति के तत्त्वों का अंग बनने के लिए या साथे उपस्थित है या सम्पूर्ण संविधान में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का संस्थापक तत्व है। यह सामाजिक क्रान्ति के लिए संचालन का भाग है वह भाग 3 और 8 के मूल अधिकारों तथा राज्य का तत्त्व के निर्देशक तत्वों में है। ये संविधान का भाग है।"

(ठ) 25वें तथा 42वें संशोधन संशोधनों ने नव निर्देशक सिद्धान्तों के महत्त्व का असंगत रूप से कमिष्ठ कर दिया है।

उपरोक्त विवरण स्पष्ट है कि दृष्टि नव निर्देशक तत्व व्यवस्थापकों द्वारा प्रवर्तन नहीं है, किन्तु उनकी सामाजिक महत्ता एवं पवित्रता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है।

(4) भारतीय संघवाद : संघ और उसका राज्य-क्षेत्र (Indian Federalism : The Union and its Territory)

संविधान के भाग-1 के प्रथम तीन अनुच्छेदों में संघ और उसके राज्य-क्षेत्रों का उल्लेख है। तदनुसार—

संघ का नाम और राज्य क्षेत्र—भारत (India) राज्यों का एक संघ है। इसके राज्य और राज्य-क्षेत्र प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किए गए हैं। भारत के भू-भाग में राज्यों के राज्य-क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र, जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किए गए हैं तथा दूसरे राज्य-क्षेत्र जो अंकित किए जाएं, समाविष्ट होंगे।¹

नए राज्यों का प्रवेश—संसद विधि द्वारा ऐसे निर्णयों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।²

नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना—संसद विधि द्वारा—(क) किसी राज्य से उसका प्रवेश अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्य³ या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नवीन राज्य बना सकेगी, (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, (घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी, (ङ) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी। इस प्रयोजन के लिए कोई विशेषक संसद के किसी सदन में तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति की सिफारिश न हो। यदि विशेषक किसी राज्य के रकबे, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस विशेषक को उन प्रभावित राज्यों के विधान-मण्डल को निर्दिष्ट की ताकि वे उस पर अपने विचार प्रकट करने में समर्थ हो सकें।⁴ किसी नए राज्य को सम्मिलित करने अथवा वर्तमान राज्य की सीमाओं को बदलने के बाद संसद साधारण बहुमत से और विधान के सामान्य क्रम में, संविधान में सभी अनुवर्गिक परिवर्तन कर सकती है।⁵ पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए संसद का अधिनियम संविधान का सशोधन समझा जाएगा।⁶ चन्द्रनगर 9 जून 1952 की एक संधि के आधार पर फ्रांस द्वारा भारत को अर्पित किया गया और यह भारत का अंग बन गया। आन्ध्र राज्य अधिनियम, 1953 द्वारा मद्रास राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया।

अपने राष्ट्र का कोई भाग किसी विदेशी राष्ट्र को अर्पित करना—भारत और पाकिस्तान के बीच मेरुवारी युनिन न. 12 के विभाजन और पुराने कृष्ण-बिहार क्षेत्र के विनियम के सम्बन्ध में करार हुआ। इसको लागू करने में यह सन्देह डठा कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार एक संसदीय कानून द्वारा वैधानिक कार्यवाही उपेक्षित है अथवा संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान सशोधन अपेक्षित है। उच्चतम न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि मामला सीमा-निर्धारण का नहीं बल्कि एक भारतीय भू-भाग के अर्पण या हस्तान्तरण का है अतः संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 को सशोधित करने वाला कानून पारित करना चाहिए ताकि किसी विदेशी राज्य के पक्ष में भारत के किसी भू-भाग के अर्पण के मामले उसमें शामिल हो जाएं। इस पर संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 1960 के द्वारा सीमा-विवाद सम्बन्धी 10 सितम्बर, 1958, 23 अक्टूबर, 1959 और 11 जनवरी, 1960 को हुए भारत-पाकिस्तान संघर्षों की शर्तों को कार्यान्वित करने और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तान्तरण करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में सशोधन किया गया।⁶

भारतीय संघ के राज्य—भारत संघ के क्रमिक विकास के साथ राज्यों की संख्या बढ़ी है। इसका प्रारम्भ 1 नवम्बर, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन से हुआ। वर्तमान में भारत 28 राज्यों और 7 केन्द्र शासित क्षेत्रों का एक संघ है।

भारतीय संघवाद की प्रकृति : सिद्धान्त और व्यवहार क्या भारत एक संघ है?

(The Nature of Indian Federalism : Theory & Practice
Is India a Federation?)

भारतीय संघ की प्रकृति के सम्बन्ध में विभिन्न सविधानवेत्ताओं राजनीतिक टीकाकारों समीक्षकों तथा शोधकर्ताओं ने अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। संविधान में भारत 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है किन्तु भारतीय संघवाद विद्वानों के लिए एक प्रश्न-चिह्न बना हुआ है। इसका कारण यह है कि भारतीय संघवाद अपनी

1 भारत का संविधान (संघर्ष जवन्दी सत्सन्ध्या अनुच्छेद 1, पृ. 1

2 पूर्वोक्त अनुच्छेद 2 पृ. 1

3 पूर्वोक्त अनुच्छेद 3 पृ. 1 एवं 2

4 भारत का संविधान (संघर्ष जवन्दी सत्सन्ध्या अनुच्छेद 4(1), पृ. 2

5 पूर्वोक्त अनुच्छेद 4(2) पृ. 3

6 सुभाष काश्यप पूर्वोक्त, पृ. 335

प्रकृति में अनेका है। इसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। समय और आवश्यकता के अनुमत यह अपने स्वयं में शिथिल और कठोर हो जाता है, शक्तिशालि में सघन प्रभावी रहता है आपसव्यक्त में एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। सविधाननिर्माताओं ने देश के अतीत को ध्यान में रखकर एक विशिष्ट प्रकार के सघनवाद को जन्म दिया जो ससरीय प्रणाली के प्रमुख तथ्यों को और एकात्मक शासनव्यवस्था के गुणों को अपनाए हुए है। एच बी पाटमकर के अनुसार "हमने सघन ढाँचे को बनाए रखा है, लेकिन उसकी अन्तर्वर्धु में परिवर्तन कर दिया है।" सविधान-गणना में देश की शासनव्यवस्था के स्वरूप पर खुलकर बहस हुई और एक ऐसा सविधान अपनाया गया जो 'स्वयं में सघन, किन्तु आत्मा में एकात्मक' है। सविधान-गणना में दो देशमुख को टिप्पणी दी कि "भारतीय सघन न तो सघनक है न एकात्मक।" कुछ सदस्यों का मत था कि सविधान में सघनक सिद्धान्त को हटा कर दी गई है। कुछ के द्वारा यह तर्क दिया गया कि भारत का सविधान 75 प्रतिशत एकात्मक और 25 प्रतिशत सघनक है।

भारतीय सविधान में सघनक और एकात्मकता का सम्बन्ध—भारतीय सविधान स्वरूप में सघनवाद के प्रमुख तथ्य ग्रहण किए गए हैं, किन्तु एकात्मकता की ओर उसका झुकाव है। भारतीय सघन की विशेषताओं को निम्नानुसार रखा जा सकता है—

1. लिखित और सर्वोपरि प्रमेय के रूप में—संघीय सिद्धान्त के अनुरूप भारतीय सविधान 'लिखित का सबसे बड़ा और लिखित सविधान' है। यह देश की सर्वोपरि विधि है और सविधान के उपबन्ध जो संघीय व्यवस्था में व्यवस्था रखते हैं, कम से कम अपने राज्य सरकारों को सहमित के बिना परिवर्तित या संशोधित नहीं किए जा सकते। इसीलिए सविधान अमेरिका के सविधान की भाँति न कठोर है और न ब्रिटिश सविधान की भाँति लचीला है। सविधान की प्रथम प्रक्रिया (संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करने वाली) सविधान की सुपरिर्वर्तनीयता का द्योतक है और शेष दोनों प्रक्रियाएँ (संसद के विरोध बहुमत वाली तथा संसद के विरोध बहुमत के साथ अपने राज्यों की स्वीकृति वाली) सविधान की सुपरिर्वर्तनीयता को प्रकट करती हैं। इस प्रकार सर्वोत्तम और कठोरता के आदर्श का सम्बन्ध दिया गया है।

2. दोहरी शासन प्रणाली—सघनक शासनव्यवस्था के अनुरूप भारतीय सविधान में दो प्रकार की सरकारें और दोहरी शासन-तंत्र की व्यवस्था है। सघन का शासन केन्द्र तथा राज्यों से चलाया जाता है और दोनों सरकारों का शासन तंत्र अलग है, लेकिन यह विशेषता पूरी तरह सघनक नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा एकात्मकता का लक्षण उपस्थित करती है।

3. शक्तियों का विभाजन—संघीय सिद्धान्त के अनुरूप केन्द्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तीन सूचियों—संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्धन सूची का निर्माण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को सौंपी गई हैं। सिद्धान्त रूप में यही लगता है कि प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि है और एक-दूसरे की सहयोगी है। संघ-सूची के विषय पर संसद का और राज्य-सूची के विषय पर राज्य विधान-मण्डलों का अनन्य क्षेत्राधिकार है। संवर्धन सूची के विषय पर संसद और राज्य विधान-मण्डल दोनों कायून बना सकते हैं, लेकिन बान्धविकता यह है कि शक्तियों के इस विभाजन में केन्द्र को शक्तिशाली बनाकर एकात्मकता की प्रवृत्ति अपेक्षित की गई है। संघीय सिद्धान्त के अनुकूल शक्ति-विभाजन इस तरह किया जाता चाहिए कि केन्द्र की शक्तियों को गिना दिया जाए और अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों में निहित की जाएँ, केन्द्र को इतनी अधिक शक्तियाँ भी न दी जाएँ कि राज्यों के पास कुछ नहीं रहे जैसा कि संयुक्त संविधान सभ में किया गया था। भारत में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति-विभाजन के इन मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। इनमें महत्वपूर्ण शक्तियाँ संघ सूची में हैं तथा विरोध परिमितियों में केन्द्रीय संसद को राज्यों के अनन्य क्षेत्र में भी कायून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद राज्यों के अनुपप पर राज्य सूची के किसी विषय पर कायून बना सकती है तथा जो विषय दोनों में से किसी सूची में नहीं आते उन पर संसद की शक्ति प्राप्त है। संघीय स्तरों के सम्बन्ध में किसी सूची के किसी विषय पर चर्चे वह राज्य-सूची में ही संसद कायून बना सकती है। विधान बनाने में हर प्रकार से संसद की सर्वोच्चता पर धन दिया गया है। राज्य का कायून ठाँकी सीमाओं से बाहर लागू नहीं हो सकता जबकि संसद का कायून न केवल सारे भारत में बल्कि उसके बाहर भी प्रभावी हो सकता है।¹ यदि संसद किसी ऐसे विषय पर कायून बनाती है जिसकी उसे शक्ति प्राप्त है और उसी विषय पर किसी राज्य द्वारा कोई कायून बनाया जाता है और वह संसद के कायून के प्रतिकूल है तो संसद का कायून ही प्रभावी होगा, जिस सीमा तक राज्य का कायून ससरीय कायून के प्रतिकूल है, तब तक वह प्रभावहीन हो जाएगा।² इस निष्पत्ति का एक अपवाद है कि "यदि संवर्धन सूची के किसी विषय पर किसी राज्य का कायून संसद के किसी पहले कायून के प्रतिकूल हो, तो वही प्रभावी होता है, बशर्ते कि वह राष्ट्रपति के विचार के निरूपण

1 अनुच्छेद 245, चौत एच एचथर: पूर्वक, पृ. 2

2 अनुच्छेद 245(1); चौत एच एचथर: पूर्वक, पृ. 4

रखा गया है और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई हो परन्तु इस विषय में संसद चाहे तो राज्य विधान-मण्डल द्वारा वापस किए गए कानून में संशोधन कर सकती है और चाहे तो उसका निरसन (Repeal) कर सकती है।¹ पुनरप, जब आपात-उद्घोषणा लागू हो तो संसद की विधायी क्षमता इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह राज्य-सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। शक्ति-विभाजन अपने ढाँचे में सभात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति लिए हुए है और संविधान की सफलता एकात्मकता का प्रतीक है।

4 स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका—सभात्मक व्यवस्था की भाँष के अनुरूप भारतीय संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो संविधान की संरक्षक है। देश का उच्चतम न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षक, केन्द्र और राज्यों के विवादों का निराकरण करने वाला और संविधान का व्याख्याकर्ता है किन्तु यहाँ संविधान का एकात्मक संरक्षण बना रहता है क्योंकि आपात-उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक नहीं रहता, जबकि अमेरिका में संसदकालीन परिस्थिति के दौरान वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक बना रहता है। हमारा संविधान न्याय की दोहरी व्यवस्था स्थापित नहीं करता अर्थात् ऐसा नहीं है कि केन्द्र और राज्य न्यायालयों के अपने उच्चतम न्यायालय हों और संवैधानिक मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों की अपील केन्द्र के उच्चतम न्यायालय में नहीं की जा सके। भारत का संविधान एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है जिसमें संवैधानिक मामलों के अतिरिक्त दोहरी और पौजदारो मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध (विशेष शर्तों को पूरा करने के उपरान्त) अपील की जा सकती है। संविधान की एकत्मक प्रवृत्ति इससे स्पष्ट होती है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सारे देश के लिए एक ही दण्ड-महिता और प्रक्रिया महिता है।

5. राज्यपालों की नियुक्ति—राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है (अनुच्छेद 155, 156) और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमण्डल के प्रति नहीं परन्तु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता है। कुछ विषयों से सम्बन्धित विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है² और अन्य में वह अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है।³ ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान की उक्त व्यवस्था संघीय सिद्धान्त के प्रतिवृत्त है और इससे राज्यों की स्वायत्तता पर आपात पहुँचता है लेकिन यह आरोप उचित नहीं है क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है जो सर्वदा मंत्रिमण्डल के परामर्श से कार्य करता है। व्यवहार में ऐसे उदाहरण नगण्य हैं जबकि राष्ट्रपति ने राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कानूनों पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया हो। केरल एजुकेशन बिल में केन्द्र ने पहले उच्चतम न्यायालय का परामर्श प्राप्त किया था उसके पश्चात् ही उसमें संशोधन के लिए राज्य विधान मण्डल को पुनः विचारार्थ भेजा था।⁴ राज्यपाल 'केन्द्रीय एजेंट' या अधिकारों के रूप में अपनी भूमिका का मुखरित रूप से निर्वाह करता है।

6. आपातकालीन स्थिति—आपातकाल में केन्द्र की शक्तियों में भारी वृद्धि हो जाती है। केन्द्र आपातकाल में राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता है। युद्ध और राष्ट्रीय आपात काल में केन्द्र की शक्ति में वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर राज्यों की स्वायत्तता को स्थगित किया जा सकता है और इस दिशा में राष्ट्रपति राज्य का सारा कार्य अपने प्रतिनिधि राज्यपाल के माध्यम से चला सकता है।⁵ राष्ट्रपति वितीय आपात की घोषणा करके राज्यों के वित्तीय क्षेत्र में संसद का नियन्त्रण स्थापित कर सकता है और सभी पदाधिकारियों के वेतनों में कटौती कर सकता है। आपातकाल में जब आवश्यक हो राष्ट्रपति सघ तथा राज्यों में शक्ति-विभाजन को परिवर्तित कर सकता है।

7. नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने की संसद की शक्ति—संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नवीन राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं तथा नामों को बदलने की शक्ति देता है। इस प्रकार राज्यों का अस्तित्व केन्द्र की इच्छा पर निर्भर है। यह व्यवस्था संघीय सिद्धान्तों पर आपात पहुँचाती है।

8. इकाइयों (राज्यों) के शुद्ध संविधान का अभाव—अमेरिकन और स्विस संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारत की संघीय व्यवस्थाओं में राज्यों के लिए शुद्ध संविधान नहीं है। यद्यपि जम्मू और कश्मीर की स्थिति अनुच्छेद 371(2) के कारण अपवाद है, तथापि इसका संविधान भारतीय संविधान के मुख्य ढाँचे के विपरीत नहीं हो सकता है। यह संविधान

1 अनुच्छेद 254(2) और एवं राष्ट्रपति; एनोकर, पृ. 2

2 अनुच्छेद 281(3) 288(2) और (31)

3 अनुच्छेद 163

4 जयन्तराजण राज्य एनोकर, पृ. 348

5 शुभाष काश्यप; एनोकर, पृ. 348

देश की समूची शासन-व्यवस्था का प्रबन्ध करता है। संविधान का भाग 6 (अनुच्छेद 152 से 237) राज्यों के प्रशासनिक ढाँचे की व्यवस्था करता है।

9. **इकहूरी नागरिकता और एक राष्ट्रध्वज**—संविधान देश भर में एक नागरिकता और एक राष्ट्रध्वज की व्यवस्था करता है। अमेरिका की भाँति संघ की इकाइयों (राज्यों) की कोई पृथक् नागरिकता नहीं है। 'भारतीय नागरिकता' का यह तत्व 'एक देश एक लोग' (One Country One People) के आदर्श की पूर्ति करता है और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बल प्रदान कर क्षेत्रीय भावना को निर्मूल बनाता है।

10. **द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं**—भारत में संघीय व्यवस्था की परम्परागत विशेषता को नहीं अपनाया गया कि द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। भारत में राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में है, अतः बड़े राज्यों से अधिक और छोटे राज्यों से कम प्रतिनिधित्व निरूपित किए गए हैं।

11. **संविधान की एकात्मकता बढ़ाने वाले कुछ अन्य सौविधानिक तत्व**—(i) देश में संघीय भू-भागों अथवा केन्द्र-शासित प्रदेशों की स्थिति ऐसी है जैसे एकात्मक राज्यों में उनके प्रदेशों की होती है। संघीय भू-भागों का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। वह इन क्षेत्रों के प्रशासकों को नियुक्ति अपने ऐजेण्ट के रूप में करता है। सदन को अधिकार है कि वह किसी भू-भाग के लिए उचित व्यवस्था करे। अग्नमान-निरोधक, लक्षद्वीप, मिनिक्म और अर्मानदीय द्वीपों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति को विनियमों (Regulations) के निर्माण का अधिकार है जिन्हें ससदीय कानून जैसी मान्यता प्राप्त होती है।

(ii) अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों का क्याण राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। उन्में विशेष अयोग नियुक्त करने का अधिकार है जो अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करके अपने सुझावों सहित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इन जातियों और वर्गों के क्याण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे।

(iii) सम्पूर्ण भारत के लिए एक चुनाव आयोग की व्यवस्था एकात्मकता के तत्व को सम्बल प्रदान करती है।

(iv) एकात्मक व्यवस्था वाले देशों की भाँति सारे देश की वित्तीय शासन व्यवस्था को भारत में निष्पक्ष महानिष्ठा परीक्षक के अधीन रखा गया है।

(v) राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत वित्त आयोग की नियुक्ति करता है जो केन्द्र और राज्यों के राजस्व वितरण के सुझाव देता है।

(vi) एकात्मक शासन-व्यवस्था के अनुरूप भारत में राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को समन्वयकारी शक्ति प्राप्त है। इसी उद्देश्य से केन्द्र को अन्तर्राष्ट्रिक परिवह को स्थापना का अधिकार दिया गया है।

(vii) संविधान में संशोधन के फलस्वरूप एकात्मकता के तत्व जुड़ते रहे हैं।

(viii) क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था—क्षेत्रीय परिषदों और प्रादेशिक समितियों के माध्यम से केन्द्र राज्य सरकारों की शक्तियों और कार्यप्रणाली पर ध्येय नियन्त्रण रखा है। देश में राज्य और संघीय क्षेत्र (उन्में छोड़कर जो कि पूर्वोत्तर प्रदेश में हैं) कई क्षेत्रों में बाँट दिए गए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय सलाहकार सभा होती है जिसे 'क्षेत्रीय परिषद' कहा जाता है। क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के राज्यों और संघीय क्षेत्रों के समान हितों पर विचार-विमर्श का अवसर मिलता है। उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चण्डीगढ़ और दिल्ली संघीय क्षेत्र शामिल हैं। मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्य शामिल हैं। गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोआ राज्य, दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली संघीय क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में हैं। दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और पाण्डिचेरी संघीय क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्रीय परिषद की दृष्टि एक समस्या है जो असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिज़ोरम जैसे राज्यों के समान हित के मामलों पर विचार करती है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केन्द्रीय मन्त्री की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 371 को संशोधित करके आन्ध्र प्रदेश और पंजाब के विधान-मण्डलों में प्रादेशिक समितियों की व्यवस्था की गई है, जिनके गठन, कार्य आदि के सम्बन्ध में आदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

12. **वादा सौविधानिक तत्व**—भारत में सघवाद और एकात्मकता के सम्बन्ध को दर्शाने वाले तीन बड़ा सौविधानिक तत्व हैं—

(i) भारत की एक संघीय राज्य व्यवस्था का केन्द्रवाद की ओर हटान योजना आयोग से प्रकट है जो कि एक संविधानोत्तर समस्या है। अनेक चर्चा के अनुसार "योजना न भारत में लोकतन्त्र और संघवाद दोनों को भाग दे दी है।" योजना आयोग ने केन्द्र की शक्तियों में भारी वृद्धि की है।

(ii) राष्ट्रीय विकास-परिषद् का स्थापना योजना आयोग की प्रति एक प्रशासकीय आदेश द्वारा हुई है तथापि इसके पैसलों का प्रभाव भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों पर पड़ता है। दोनों सरकारों इसके पैसलों को भागती है। यह अंतर स्पष्ट करता है कि इस परिषद् का उपयोग राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव डालने के लिए किया जाता है।

भारत का संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक और न विशुद्ध एकात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है।¹ यह अपने ढंग का अनाच्छा स्तंभ है जो इस भिन्नता को प्रतिप्रेषित करता है कि संघवाद के बावजूद देश का हित सर्वोपरि है। यह अमेरिकी संघीय संविधान की अपेक्षा कनाडा के संविधान के समीप है। भारत में केन्द्र राज्य सम्बन्धों को इस प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है—(क) संविधान की व्यवस्थाएँ—(i) विधायी सम्बन्ध (ii) प्रशासनिक सम्बन्ध (iii) वित्तीय सम्बन्ध (iv) न्यायिक सम्बन्ध (ख) जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्था (ग) आयोगों में केन्द्र राज्य सम्बन्ध (घ) केन्द्र राज्य सम्बन्धों का मूल्यांकन (ङ) क्या राज्यों का स्थिति नगरपालिकाओं जैसा है? (च) केन्द्र राज्य विभाग के मुख्य कर्ण और (छ) केन्द्र राज्य मतभेदों को दूर करने के लिए सुझाव।

(क) संविधान की व्यवस्थाएँ

(i) विधायी सम्बन्ध (Legislative Relations)

संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक भारतीय संविधान में केन्द्र राज्य सम्बन्धों का उल्लेख करते हुए विधायी शक्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—1 विधान-विस्तार की दृष्टि से 2 विधान-विषय की दृष्टि से।

विधान विस्तार की दृष्टि से—राज्य-क्षेत्र के समर्थ में अनुच्छेद 245 यह उपबन्धित करता है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उनके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधान-मण्डल उस सम्पूर्ण राज्य के भाग के लिए विधि बना सकेगी। खण्ड (2) यह उपबन्धित करता है कि संसद द्वारा निर्मित कोई विधि इस कारण से अमान्य नहीं समझी जायेगी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर लागू होती है। ए. आई. वॉटिंग ब्रान्स इन्वन्स टैंक्स कमिशनर बम्बई के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रभुसत्ता सम्बन्ध विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि को देश के न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह भारत राज्य-क्षेत्र के बाहर लागू होती है। ऐसा विषय जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उत्पत्ति कर सकता है विदेशी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता था। उन्हें लागू करने में व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है लेकिन ये सब नीति के प्रश्न हैं जिन पर देश के न्यायालयों में विचार नहीं किया जा सकता है।² संसद की विधायी शक्ति एक परिपूर्ण (Plenary) शक्ति है। संविधान में उपबन्धित परिसीमाओं के अधीन विधान-मण्डल को भूतलक्षी और भविष्यतः स्थानीय प्रकार की विधियों को बनाने की शक्ति प्राप्त होती है।³ भारतीय संविधान में शक्तियों के वितरण की योजना और वितरण के सिद्धान्त 1935 के भारत सरकार अधिनियम के समान ही हैं। 1935 के अधिनियम में तीन मूचियाँ का समावेश किया गया था—संघ सूची, राज्य सूची और सम्मिश्र सूची।

(1) संघ सूची (Union List)—इस सूची में साधारणतः वे विषय रखे जा गए हैं, जिनका महत्व अखिल भारतीय है या जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पर संघीय सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं जिनमें प्रमुख हैं—भारत की सुरक्षा, देशीयकरण, रेल्वे, अंतर-राज्य तथा गैलत-बाकूट परमाणु शक्ति, नैदेशिक सम्बन्ध, राजनयिक सन्धिपत्रों से देशी वस्तु-मार्गों पर जहाजगामी तथा नौ परिवहन, वायुमार्गों डाक एवं तार, टेलीफोन एवं तेल, मुद्रा निर्माण, लाक ऋण, विदेशी ऋण, भारत का रिजर्व बैंक, विदेशी व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य नियमन तथा उनका विनियमन, आयात-निर्यात, तन्वाक एवं अफीम आदि पर महसूल, बैकिंग, कोयला, शोषण, तेल तथा अन्य मार्गों के प्रतिमानों को निर्धारित करना, उद्योग-नियन्त्रण, खातों खनिज पदार्थों तथा रेल ससोपनों का विनियमन तथा विकास, राष्ट्रीय संप्रदायों का आरक्षण, ऐतिहासिक स्मारक, भारत का सर्वेक्षण, संघीय लोक सेवाएँ, संसद एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, जजगणना, शान्ति निकतन, सोमा शुल्क तथा निर्वात शुल्क, निगम बर, उत्पादन शुल्क, सम्पदा

1 भारतीय सरकार एवं उन्नीस खण्ड 1 पृ 130

2 Jennings Some Characteristics of Indian Constitution p 63

3 ए. आई. आर 1925 फेडरल कोर्ट 1825

4 जनसंख्या परीक्षण : भारत का संविधान 1985 पृ 394

5 वही पृ 394 राधिका गांधी बनाम राजनारायण ए. आई. आर 1975 सुप्रीम कोर्ट 2229 आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम हिन्दुस्तान

मशीन टून्स ए. आई. आर 1957 सुप्रीम कोर्ट 2037

शुल्क, समाचार-पत्रों के द्रव्य-विक्रय पर कर, अलीगढ़, बनारस एवं उस्मानिया विश्वविद्यालय आदि। राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है।

(2) **राज्य सूची (State List)**—राज्य सूची में 66 विषय हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। राज्यों की विषयी शक्ति के क्षेत्र में प्रमुख विषय हैं—सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल तथा सुधारालय, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, मादक पेय, शिक्षा, पुस्तकालय, अनाथालय, कृषि, सिंचाई, पर्यटन, मछली व्यवसाय, अस्पताल एवं औषधालय, जंगली पशुओं की रक्षा, ग्राम सुधार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, गैस एवं गैस-निर्माण मण्डलों और भेत्ते, साहूकार, राज्यगत व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि आग कर, भूमि कर, मनोरंजन कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, स्थानीय क्षेत्र के माल पर प्रवेश कर, समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर बिजली कर, विज्ञान पर कर, व्यापार-कर, वस्तुओं की उत्पत्ति और उनका वितरण, नाटकपर आदि।

(3) **समवर्ती सूची (Concurrent List)**—इस सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों महत्व के 47 विषय सम्मिलित हैं। इस सूची में प्रमुख मदें हैं—फौजदारी कानून एवं प्राप्ति, व्यवहार प्रणाली निवारक निरोध, किडनी और विवाह-विच्छेद, दिवालियापन तथा ऋण रोकथाम समितियाँ, पागलपन, ठेके और सामेदागी, मजदूर सभ, आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन, सामाजिक सुरक्षा और बीमा, शरणार्थियों की सहायता, पुनर्वास, खाद्य पदार्थों में मिलावट, राजगार और बेरोजगारी, विधि, औषधियाँ, जन्म-मरण के आँकड़े, श्रम-कल्याण, मूल्य-नियंत्रण, कारखाने, बिजली, समाचार पत्र, पुस्तकें तथा मद्रासालय आदि। संविधान का तृतीय संशोधन (1954) द्वारा समवर्ती सूची के तृतीयसर्वे विषय 'व्यापार-वाणिज्य' का अर्थ निश्चित और व्यापक करके हुए उसमें स्पष्ट रूप से आवश्यक वस्तुओं के व्यापार-वाणिज्य का समावेश कर दिया गया है। समवर्ती सूची में ये विषय हैं जिन पर समस्त देश के सामान्य कानून को होना चाहनीय है, किन्तु अनिवार्य नहीं, इसलिए इन विषयों को केन्द्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सातवीं अनुसूची को संशोधित किया गया है। तदनुसार 'सभ सूची में सभ और संसद बन पर सभ का नियंत्रण' विषय जोड़ा गया है और राज्य से 'शिक्षा' को निकालकर समवर्ती सूची में समाविष्ट कर दिया गया है ताकि शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जा सके।

(4) **अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers)**—जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है वे अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार को संविधान के अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत प्रदान की गई हैं। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों की शक्ति हैं। भारत में इस व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र ऐसे कर लगा सकता है जिनका राज्य और समवर्ती सूचियों में उल्लेख नहीं है। सभ सूची के विषयों पर निर्मित विधि के उपयुक्त प्रशासन की दृष्टि से संसद नये न्यायालय स्थापित कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह किसी देश अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सभा से की गई संधि, करार अथवा उपसन्धि को क्रियान्वित के लिए आवश्यक विधि-निर्माण कार्य कर सकती है।

विषयी शक्तियों का समीक्षणत्मक अध्ययन : संघीय सर्वोच्चतम—शक्ति-विभाजन की उपर्युक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि भारत में कनाडा के संविधान में समाविष्ट सबसे केन्द्र की प्रणाली का अनुसरण किया गया है। यह निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध है—

1. साधारणतया जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं वे केन्द्र को तथा स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को सौंपे गए हैं। समवर्ती सूची के विषय केन्द्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखे गये हैं, किन्तु दोनों सरकारों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति (Conflict) की स्थिति में केन्द्रीय विधि मान्य होती है। नियम का एक अपवाद है और वह यह है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर किसी राज्य का कानून संसद के किसी पहले कानून के प्रतिद्वन्द्व हो तो वह प्रभावहीन होता है, बशर्ते कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए अर्पित रखा गया हो और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिली हो, परन्तु इस विषय में संशय चाहे तो राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कानून में संशोधन कर सकती है और चाहे तो उसका परिवर्तन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। [अनुच्छेद 245(2)]

2. संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून इस कारण अमान्य नहीं हो सकता है कि वह भारत राज्य-क्षेत्र से बाहर लागू होता है। कोई राज्य अपने-आप क्षेत्रीय (उस राज्य-क्षेत्र से बाहर) विधि नहीं बना सकता। राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य-क्षेत्र तक सीमित है।

3. कुछ अपवादों को छोड़कर संसद निर्मित विधियों और राज्य विधानमण्डलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति की स्थिति में संसद निर्मित विधि प्रभावी होती है।

4. कुछ विशेष परिस्थितियों में संविधान के अन्तर्गत संसद को राज्यों के अन्य क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। उदाहरणार्थ, जब राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत विशेष बहुमत से संकल्प प्राप्त करने पर राज्यसभा को दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विशिष्ट विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक या अनिवार्य है।

तो शासक उस विषय पर कानून बना सकती है। अपात उद्घोषणा के दौरान संसद की विधायी शक्ति है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है।

5 शक्ति-सूचियों की व्याख्या में छत्र विधायन के सिद्धान्त (Doctrine of Colourable) का महत्व है। यदि संविधान केन्द्र और राज्यों में विधायन शक्ति का विभाजन करता है और मूल अधिकार रूप में उन पर अवश्यतः सीमाएँ निर्धारित करता है जैसे हमारे संविधान के अन्तर्गत है तो ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं कि क्या विधायिका ने इस शक्ति के प्रयोग में संविधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है या अपनी शक्ति से बाहर कार्य किया है? इस प्रश्न का अतिक्रमण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। यद्यपि विधायिका किसी कानून में अपनी शक्तियों के भीतर कार्य करती है तथापि यथापि में वह साविधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करती है। ऐसे प्रारम्भ विधायन को छत्र विधायन कहते हैं। ऐसे मामलों में अधिनियम का सार (Substance) महत्वपूर्ण होता है उसका वास्तव रूप या आवृत्ति (Form) नहीं। यदि किसी विधान की 'वैषम्य-यस्तु' सारतः उस विधान-मण्डल को शक्ति के बाहर है तो उसके बाह्य रूप उसे व्यापकता द्वारा अमान्य घोषित करने से नहीं बचा सकेगा। विधानमण्डल अप्रत्यक्ष या पराक्ष तरीका अपनाकर सांविधानिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। कामेश्वरसिंह बनाम बिहार के मामले में इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय है जिसमें छत्र विधायन के सिद्धान्त पर किसी अधिनियम को अवैध घोषित किया गया है। इससे बिहार लेण्ड्स एक्ट, 1950 को वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी।

6 सभ सूची में कुछ प्रविष्टियाँ ऐसी हैं जिनमें संसद को अधिकार है कि वह कानून द्वारा आवश्यक घोषणा करने के बाद राज्यों के क्षेत्र के कार्य या विषय अपने हाथ में ले ले। केन्द्रीय सरकार की नियन्त्रण शक्ति को बढ़ाकर सभ्य सन्वीकृत स्थापित की गई है। सभ सूची में ऐसे विषयों का उल्लेख है जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर नियन्त्रण रख सकती है। इनमें उल्लेखनीय हैं—राज्य विधानसभाओं के चुनाव संसद के नियन्त्रण में हैं और राज्यों के संतों की जाँच केन्द्र का विषय है।

7 संसद किसी देश के साथ की गई सन्धि करार या अधिसूचना किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या सभा में किए गए निर्णय को लागू करने के लिए कानून बना सकती है चाहे उसका विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता हो। जब अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य विरोध के शासन को अपने हाथ में ले लेता है तो राज्य विधान मण्डल के अधिकार संसद को प्राप्त हो जाते हैं।

8 सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों से स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के संसद के राज्य की सम्पत्ति के अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तुत विषयों पर दावे को अमान्य करते हुए संसद की शक्ति को वैध ठहराया है।

9 संविधान के कुछ सरोक्षणों ने संसद की विधायी शक्तियों को बढ़ाया है। उदाहरणार्थ 24वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों को दूर नहीं किया वरन् संसद की संशोधन शक्ति को और विस्तृत करने के लिये ये शब्द जोड़ दिये कि संशोधन की शक्ति में किसी उपबन्ध के जोड़ने परिवर्तित करने और निमित्त करने की शक्ति सम्मिलित है।

(ii) प्रशासनिक सम्बन्ध (Administrative Relations)

संविधान के भाग 11 के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से 263 तक केन्द्र राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों की चर्चा की गई है। केन्द्र को राज्यों की तुलना में कर्तव्य और दायित्व सौंपे गये हैं। संविधान की धारा 73 के अनुसार केन्द्र की कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानमण्डल को कानून बनाने का अधिकार है। यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन विषयों पर राज्य विधान मण्डल और संसद को विधि-निर्माण की शक्ति है उनमें राज्य को कार्यपालिका शक्तियाँ सभ को उन कार्यपालिका शक्तियों से परिशिष्टित रहेगी जो संविधान द्वारा अथवा किसी संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त हैं। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं है।

भारत में प्रशासन के लिए केन्द्र और राज्य-स्तरीय पर अलग-अलग सम्पूर्ण अधिकारों की स्थापना नहीं की गई है। एक ओर राज्यों का यह उदात्तदायित्व है कि वे सभ्य कानूनों को लागू करें और दूसरी ओर सभ्य सरकार को अधिकार है कि राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश के घट्बुद्धि विकास में सभ और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाकर तथा दोनों सरकारों को एक होकर कार्य करने की प्रेरणा देना है। केन्द्र राज्य प्रशासन सम्बन्धों को अमललिखित भागों में बाँट सकते हैं—

(1) सभ द्वारा राज्यों को निर्देश—सभ सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था सभाय सिद्धान्त के विरुद्ध है और भारतीय संविधान को छोड़कर अन्य सभाय संविधान में नहीं पाई जाती है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम के अनुच्छेद 126 से इस विचार को ग्रहण किया है। अपातजन्य की उद्देश्यता के दौरान केन्द्र राज्य सरकारों को आदेश दे सकता है, शक्तिवस्तु में यह अनेकित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो कि वह ससद निर्मित विधियों के अनुकूल हो। ऐसा करने के लिए केन्द्र राज्यों को वांछित निर्देश दे सकता है।

(क) अनुच्छेद 256 में यह व्यवस्था है कि "प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा जिससे ससद द्वारा विधियों तथा राज्य विधियों का पालन सुनिश्चित रहे तथा सभ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे।" राष्ट्रीय सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि केन्द्रीय विधान के प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(ख) अनुच्छेद 257(1) में केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने के अधिकार का उल्लेख किया गया है—“प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा जिससे सभ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़थक या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा सभ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे।” इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि राज्य की कार्यपालिका सत्ता का सभ की कार्यपालिका सत्ता से सर्वत्र न होने पाये।

(ग) अनुच्छेद 257 (2), (3), (4) द्वारा कुछ अवस्थारें निर्धारित की गई हैं जिनमें राज्यों पर सभ का नियंत्रण प्रयुक्त होता है। संपरिक महत्व की सड़कों तथा संपर साधनों की देखभाल, मामूली निर्माण आदि के लिए केन्द्र राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। ससद राज्य-पदों या जन्म-पदों को, बड़ी सड़कों या नहरों को, नौकागम्य नदियों का राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। सभाय कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत रेल-पथ की रक्षा के लिए उस राज्य को आवश्यक निर्देश दे। इनको सुरक्षित, मरम्मत या निर्माण पर जो अतिरिक्त व्यय होगा वह सभ सरकार द्वारा व्यय किये जाने का प्रावधान है।

अनुच्छेद 256 और 257 का समुक्त रूप में लागू करने पर भारत सरकार की शक्तिपूर्ण व्यवस्था हो जाती है और राज्यों का अधिकार क्षेत्र में प्रवेश बंद जगह है। ये अनुच्छेद राज्यों की कार्यपालिका सत्ताओं पर विरोधात्मक (Positive) और निषेधात्मक (Negative) प्रतिकूल लागू हैं। ये भारत सरकार को विस्तृत अधिकार प्रदान करते हैं कि वे राज्यों में किसी प्रकार के प्रशासनिक कृत्य निर्बाध रूप से कर सकें। राज्यों द्वारा केन्द्र के निर्देशों को अवहेलना न कर जा सकें, इसके लिए संविधान में उपबन्ध हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य इन निर्देशों का पालन करने में विवश हो जाते हैं तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुसार संचालित नहीं की जा सकती है वह राज्य की समस्त शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है।

अनुच्छेद 339(2) में उल्लेख किया गया है कि “सभ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य का उस प्रकार के निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुमोदित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने में सम्बन्ध रखते हों।”

(2) सभाय कृत्यों को राज्यों की सैन्य-केन्द्र राज्यों को दो प्रकार कार्य सैन्य सत्ता है—प्रथम राज्य सरकार को सत्ता है और द्वितीय ससद के माध्यम से। अनुच्छेद 258(1) के अनुसार, “ससद किसी राज्य सरकार की सहमति से सभाय कार्यपालिका शक्ति से सम्बन्धित किसी विषय को उस सरकार को अथवा उसके पराधिकारियों को सौंप सकती है।” अनुच्छेद 258(2) के अनुसार ससद को सभाय विधानों के संचालन के लिए राज्य के प्रशासनिक या प्रयोग करने का शक्ति प्रयुक्त है और उस प्रयोजन के लिए राज्य अथवा उसके पराधिकारियों को ऐसी शक्ति सौंप सकता है जिससे सभाय कानूनों को उस राज्य में समुचित रूप से लागू किया जा सके। इस अनुच्छेद के खण्ड 1 और खण्ड 2 में मुख्य अन्तर है कि खण्ड 1 के अन्तर्गत राज्यों की शक्तिपूर्ण राज्य सरकारों की सहमति से सौंपी जाती है वहीं खण्ड 2 के अन्तर्गत राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है।

राज्य सरकार अपने कृत्यों को सभ सरकार को सौंप सकती है। अनुच्छेद 258 (क) यह उल्लेखित करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सम्मति से ऐसे किसी विषय सम्बन्धी कृत्य जिस पर राज्य का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है मरतब या बिना शर्त के ठहरे सौंप सकता है। यह स्पष्ट है कि जहाँ किसी सरकार के लिए अपने प्रशासनिक कार्यों के साथे सम्बन्ध में अनुविधान होता हो तो वह दूसरी सरकार द्वारा उसे संचालित करवा सकता है, किन्तु राज्य केन्द्र की अपने कार्य केन्द्र का सहमति से दे सकते हैं जबकि केन्द्र अपने कार्यों को राज्यों की उनकी सहमति के बिना सौंप सकता है। संविधान ने प्रशासकीय सम्बन्धों में केन्द्र की प्रमुखता स्वीकार की है।¹

क्षेत्रीय स्तर पर सम्मेलन बुलाए जाने की परम्परा महत्वपूर्ण है। ये सम्मेलन राजनीतिक, प्रशासकीय और व्यावसायिक स्तरों पर आमंत्रित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सम्मेलन उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक केन्द्र राज्य सम्बन्धों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। निम्न सूची में इन सम्मेलनों को प्रस्तुत किया गया है—

1 सैट्रल कांसिल ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट (स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद) 2 दि सैट्रल कांसिल ऑफ हेल्थ (केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद) 3 दि फूड मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस (खाद्य मन्त्री सम्मेलन) 4 दि वाटर ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर्स (राज्यीय गृहमन्त्री सम्मेलन) 5 दि वॉर्कर्स ऑफ स्टेट फ़ाइनेंस मिनिस्टर्स (राज्यीय वित्तमन्त्री सम्मेलन) 6 दि कांफ्रेंस ऑफ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स (राज्यीय शिक्षामन्त्री सम्मेलन) 7 दि कांफ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर (कृषि मन्त्री सम्मेलन) 8 दि कांफ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ को-ऑपरेशंस (राज्यीय सहकारिता मन्त्री सम्मेलन) 9 दि स्टेट लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस (राज्यीय श्रममन्त्री सम्मेलन) 10 दि कांफ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट (राज्यीय समुदाय विकास मन्त्री सम्मेलन) 11 दि कांफ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ सोशियल वेल्फेयर एण्ड वेल्फेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज (समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्ग सम्बन्धी मन्त्री सम्मेलन) 12 दि स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस (राज्यीय गृह निर्माण मन्त्री सम्मेलन) 13 दि कांफ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ इरिगेशन एण्ड पावर (राज्यीय सिंचाई तथा बिजली मन्त्री सम्मेलन) 14 दि कांफ्रेंस ऑफ स्टेट इन्फ्रामेसन्स मिनिस्टर्स (राज्यीय मृत्तम मन्त्री सम्मेलन) 15 दि कांफ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग (राज्यीय प्रादेशिक योजना, देशीय योजना मन्त्री सम्मेलन) 16 दि कांफ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ कल्चरल अफेयर्स (राज्यीय सांस्कृतिक मन्त्री सम्मेलन) आदि।

(6) योजना आयोग तथा सघ राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध—भारतीय सघ में योजना आयोग के सघ केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है। हानियों की तुलना में इस व्यवस्था से लाभ कहीं अधिक हुआ है और राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजनाबद्ध रूप से लागू किए जा सके हैं। यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों की तुलना में केन्द्र की स्थिति प्रभावी और शक्तिशाली है। केन्द्र आपातकाल तथा शांतिकाल में राज्यों पर वर्चस्व स्थापित कर सकता है। इस स्थिति के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों में अविश्वास और शक की मनस्थिति के वातावरण का विकास होता है। अगर केन्द्र और राज्यों में भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें सत्तारूढ़ हों तब यह स्थिति और विकट बन जाती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से वर्तमान तक के इतिहास को देखने से पता चलता है कि कुछ मतभेदों के बावजूद भारतीय सघ की दोनों सरकारों ने पारस्परिक सहयोग और समन्वय की भावना से कार्य करते राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा है तथा सघात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिरता और परिपक्वता प्राप्त हुई है। केन्द्र राज्य सम्बन्धों से साझादारी की भावना विकसित हुई है।

(iii) वित्तीय सम्बन्ध (Financial Relations)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 291 केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों का वर्णन करता है। केन्द्र और राज्य में राजस्व वितरण की व्यवस्था भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण मात्र है। संविधान निर्माताओं द्वारा वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य संविधान में रखा गया है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल वित्तीय स्थिति पर पुनर्विचार कर संशोधन एवं परिवर्तन के सुझाव देता है। यह व्यवस्था भारत का अपना मौलिक योगदान है जिसने केन्द्र और राज्यों के जटिल वित्तीय सम्बन्धों का सरलीकरण कर दिया है।¹ सघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व सांभलाने के विभाजन के वित्तीय आधार तीन सिद्धान्तों पर अपनाए गए हैं—कार्यक्षमता पर्याप्तता और उपयुक्तता। इन उद्देश्यों की एक साथ प्राप्ति कठिन कार्य है अतः हमारे संविधान में समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाई गई है। तदनुसार विनियम को दो भागों में विभक्त किया गया—प्रथम सघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन द्वितीय सहायक अनुदान का वितरण। सघ एवं राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों का विवेकानुसृत निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

(1) विधि के प्राधिकार के बिना करारोपण का निषेध—अनुच्छेद 265 में स्पष्ट लिखा गया है—“विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त कोई कर न तो आरोपित और न एकत्र किया जाएगा।” इसका अर्थ है कि कोई वर वध विधि द्वारा आरोपित और एकत्र किया जा सकता है किसी कार्यपालिका आदेश द्वारा नहीं। यदि संविधान के उपबंध द्वारा करारोपण का निषेध है वह कर विधि अवैध होगी। उदाहरणार्थ वह कर विधि नहीं मानी जाएगी जो संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समता के मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो। यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 265 में निहित व्यवस्था करों के सम्बन्ध में लागू होती है शुल्क के सम्बन्ध में नहीं।

(2) सघ और राज्यों में राजस्व वितरण—अनुच्छेद 268 सघ और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था करता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को और सघ सूची के विषयों पर केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में कुछ करों का उल्लेख है। सघ सरकार के राजस्व स्रोत निम्नलिखित हैं—कु-आय को छोड़कर अन्य

2 अनुच्छेद 273 में पटसन अथवा पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर निर्वात शुल्क स आने वाली कुल राशि के किसी भाग को असम उड़ीसा पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों को सहायक अनुदान के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है। केन्द्रीय अनुदान की राशि राष्ट्रपति वित्त आयोग के परामर्श से नियत करता है।

3 यदि राज्य केन्द्र की स्वीकृति से अनुसूचित जाति एवं आदिम जातियों के कल्याण के लिए कोई योजना प्रारम्भ करे, उसकी पूर्ति के लिए केन्द्र वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

4 केन्द्र ऐसे विषय में अनुदान दे सकता है जिस पर विधिनिर्माण का अधिकार संसद के पास नहीं है। ऐसे विधेयकीन अनुदानों का अनुपात दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और राज्यों के बजटीय घाटों की पूर्ति के लिए केन्द्र से अनुदान दिये जा रहे हैं। वित्तीय अनुदान महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में नियन्त्रण करने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा केन्द्र राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में राज्यों से सहयोग प्राप्त करने में समर्थ होता है।

(4) केन्द्र एवं राज्य सरकारों का उधार लेने की शक्ति—सविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार केंद्रीय सरकार संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं में भारत की संचित निधि की गारण्टी पर धन उधार ले सकती है और इन सीमाओं तक ऋण की गारण्टी दे सकती है। अनुच्छेद 292 के अनुसार कोई राज्य भारत की सीमाओं के अन्दर राज्य विधानमण्डल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर रहते हुए राज्य की संचित निधि की गारण्टी पर धन उधार ले सकता है और इन्हीं सीमाओं के भीतर किसी ऋण की गारण्टी दे सकता है लेकिन राज्यों की धन उधार लेने की शक्ति पर यह प्रावधान है कि (i) कोई राज्य भारत से बाहर के कर्ज नहीं ले सकता, (ii) किसी ऐसे राज्य को केन्द्रीय सरकार तब तक उधार देने से इनकार कर सकती है जब तक राज्य ने पिछला उधार लौटा नहीं दिया है (iii) यदि पिछला कर्ज शेष रहते हुए राज्य धन उधार लेने का आग्रह करे तो केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वह उन शर्तों के साथ धन उधार दे जिन्हें लगाना वह उचित समझे। भारत में राज्य सरकारों सच सरकार के ऋण भार से दबी हैं अतः उन्हें सच सरकार की शर्तों को मानना पड़ता है लेकिन यह सत्य है कि सच सरकार अवाञ्छनीय शर्तें लागू करने से हमेशा बचती रही है।

(5) वित्त आयोग—सविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सविधान लागू होने के दो वर्ष बाद और तत्पश्चात् प्रति पाँचवें वर्ष अथवा जरूरत पड़ने पर इससे पूर्व वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था है। आयोग में एक सभापति और चार अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नियत समयोपरान्त पदाधिकारियों की नियुक्ति होने से आयोग के कार्य में अविच्छिन्नता आ जाती है। प्रत्येक आयोग पूर्ववर्ती आयोग के कार्य से लाभ उठाता है।¹ अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है—

(क) सच और राज्यों के उन कर्तों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण के सम्बन्ध में जो सच एवं राज्यों में विभाजित होते हैं। (ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के लिए सहायक अनुदान देने में किन सिद्धान्तों पर चला जाए। (ग) अन्य विषय राष्ट्रपति, सुव्यवस्थित वित्त-व्यवस्था के हितों में आयोग को सौंपे उनके सम्बन्ध में। वित्त आयोग यद्यपि वित्तीय प्रावधानों में परिवर्तन की सिफारिश नहीं कर सकता, तथापि केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्धों के क्षेत्र में आयोग का प्रभाव अधिक है क्योंकि सविधान यह बताता है कि उनको किस प्रकार वितरित किया जाएगा और वितरण सिफारिश वित्त आयोग द्वारा ही की जाती है। साधारणतया वित्त आयोग की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं। केन्द्र राज्य सरकारों के बीच जटिल वित्तीय समस्याओं को सुलझाने वाले एक सौवैधानिक उपकरण के रूप में वित्त आयोग की भूमिका प्रमुख रही है। वित्त वितरण-व्यवस्था वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग के कार्य का मुख्य महत्व इसमें है कि वह सप्तात्यक शासन पद्धति की वित्त-व्यवस्था को स्थिर बनाने में निष्पक्ष तथा तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है। वित्त-वितरण के प्रश्न को सच तथा राज्यों के मध्य अन्य राजनीतिक विवादों से दूर रखने का श्रेय इसी को प्राप्त है। वित्त आयोग राज्यों तथा सच के मध्य एक प्रत्याबरोध का कार्य करता है जो एक ओर निरन्तर अधिक वित्त की माँग करने वाले राज्यों में राजनीतिक दबाव से सच को रक्षा करता है दूसरी ओर आवश्यकताप्राप्त राज्यों को यथासम्भव सहायता प्रदान करने के लिए सच को विवश करता है।

(6) अन्य वित्तीय व्यवस्थाएँ—सविधान के अन्तर्गत ऐसे विशिष्ट उपबन्ध हैं जिनके अनुसार सच और राज्य एक-दूसरे की सम्पत्ति तथा आय पर कर नहीं लगा सकते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकालीन शक्तियाँ केन्द्र की निर्णायक शक्ति की परिचायक हैं। भारत में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (The Comptroller and Auditor General

of India) द्वारा केन्द्रीय सरकार अपना नियन्त्रण रखने में समर्थ है। यह अधिकारी भारत सरकार और राज्य सरकारों के लेखा रखने के दग और हिसाब-किताब की जाँच करता है। इन अधिकारों के माध्यम से सराद राज्यों की आय पर नियन्त्रण रखती है।

(b) न्यायिक सम्बन्ध (Judicial Relations)

भारतीय संविधान ने अनेक सभ्य शासन-प्रणालियों की न्यायिक व्यवस्था के विपरीत देश में एक न्यायिक व्यवस्था (A Single Judicial System) की स्थापना की है। एकल न्यायिक व्यवस्था में भारत में न्यायिक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी एकता स्थापित कर समूचे देश के लिए एकल न्यायिक सर्व (Cadre) की स्थापना कर दी है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह राज्य के उच्च न्यायालयों को निर्देश दे; उच्चतम न्यायालय के निर्णय नज़रों के रूप में राजकीय न्यायालयों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू करना राजकीय अधिकारियों का सार्वधानिक बर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया लेख समूचे देश में और विधि के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है।

(ख) जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्था

यद्यपि जम्मू-कश्मीर राज्य साधारणतया भारतीय संघ के अन्य राज्यों की तरह है पर उसके विषय में हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं—

1. जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में विधि-निर्माण के विषय में संसद की शक्ति सीमित है। इस राज्य के सम्बन्ध में सभ्य संसद उसी प्रकार विधि-निर्माण नहीं कर सकती जिस प्रकार वह भारतीय संघ के अन्य राज्यों—राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि के विषय में कर सकती है। जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में संसद सभ्य सूची और सचवाती सूची में उन विषयों पर कानून बना सकती है जिनमें उस राज्य से शासन के प्रश्नवर्ग में राष्ट्रपति। उन विषयों के अनुसार घोषित कर दे, जिनका उल्लेख राज्य द्वारा भारतीय उपनिवेश में प्रविष्ट होने के समय प्रवेश पत्र में भारतीय उपनिवेश के संसद की विधि-निर्मात्री शक्ति के अधीन विषयों के रूप में किया गया था। इसके अतिरिक्त संसद उन विषयों पर विधि-निर्माण कर सकती है जिनके विषय में राज्य के शासन की स्वीकृति से राष्ट्रपति अपने आदेश में ऐसा निश्चय कर दे।¹

2. संविधान के अन्य उपबन्धों की व्यवस्था अपवादों संग्रहनों सहित राज्य के शासन की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए हुए आदेश के अनुसार लागू होती है।

(ग) आयोजना में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

भारतीय संघवाद पर नियोजन के प्रभाव के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। अशोक चन्दा के अनुसार योजना आयोग ने संघवाद का स्थान ले लिया है। मोरिस जेम्स का मत है कि योजना आयोग ने संघवाद का स्थान न लेकर केन्द्रीकरण को बढ़ाया है। नियोजन ने व्यवहार में केन्द्र राज्य सम्बन्धों को प्रभावित किया है।² व. सन्धानम् का विचार है कि आयोजना ने संघवाद को स्थानान्तरित न करके केन्द्रीकरण को बढ़ा दिया है और नीति तथा वित्त-विषयक मामलों में राज्यों की स्वायत्तता को छाय का रूप प्रदान किया है।³ कुछ आलोचक कहते हैं कि योजना आयोग समानान्तर सरकार (Parallel Government) है सुपर कैबिनेट (Super Cabinet) है गाड़ी का पाँचवाँ पहिया (The Fifth Wheel of the Coach) है आदि।

भारत में नियोजन इस प्रकार का है जिससे राष्ट्रीय योजना और राज्तीय योजनाएँ कार्यान्वित होती हैं। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है और प्रांतीय एवं स्थानीय हितों की भी। मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि दोनों एक-दूसरे के विरोधी होने के स्थान पर एक-दूसरे के पूरक बनें। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति में केन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और केन्द्र तथा राज्य सम्बन्ध एकात्मकता के तत्क्षणों से प्रभावित होते हैं तो इसमें अशुभ या अनुचित जैसा कोई तत्व नहीं है। सामान्य हितों की पूर्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों को खेदजनक नहीं कहा जा सकता है। योजना आयोग परामर्शात्मक विकास है जो केन्द्र और राज्यों के विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय पर पहुँचता है।

नियोजन की विषय-वस्तु की प्रकृति, योजना-निर्माण का स्वरूप, वित्तीय पहलु, राष्ट्रीय नीति, विदेशी सहायता योजना का कार्यान्वयन, योजना आयोग की सदस्यता आदि ऐसे पक्ष हैं जिनमें केन्द्र राज्य सहयोग और समन्वय का बीच केन्द्र की

1 डॉ. इब्राहिम नारायण पुरोहित, पृ. 312-13

2 Morris Jones Op Cit p 115

3 K Santhanam Democratic Planning, Problems and Pitfalls p 20

प्रधानता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद् केन्द्र एवं राज्यों के मध्य समायोजन के लिए स्थापित की गई है, ये प्रधानमंत्री, केन्द्रीय सरकार के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित होते हैं। कोई मुख्यमंत्री परिषद् की बैठक में उपस्थित न हो सके तो उसे अपने प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार होता है। परिषद् में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सदस्यता और योजना आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर उनकी स्वायत्तता के कारण योजना को राज्यों की ओर से पूर्व-स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। योजना निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद् में परामर्श दिया जाता है। योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों एवं राज्य सरकारों से परामर्श के बाद योजना का जो प्रारूप तैयार किया जाता है, वह केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की स्वीकृति बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष, जो सहकारी सघनवाद (Co-operative Federalism) के सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करती है, आवश्यक सुझाव हेतु प्रस्तुत किया जाता है। परिषद् की सिफारिशों के आधार पर योजनाओं तथा कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार किया जाता है और उन्हें केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के पास प्रारम्भिक निर्देशों सहित भेज दिया जाता है। योजना-निर्माण को अन्तिम रूप देने से पूर्व परिषद् की सिफारिशें ली जाती हैं और योजना अन्तिम स्वरूप और आधार प्रहण करती है जिसे ससद द्वारा स्वीकृति मिलने पर प्रकाशित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की योजना-निर्माण के सम्बन्ध में निर्गोपक भूमिका होती है इसलिए उसे 'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet) कहा जाता है। इसके उच्च स्वरूप के कारण इसके परामर्श को केन्द्रीय और राज्य सरकारें सर्वाधिक महत्व प्रदान करती हैं। परिषद् के सदस्य सरकारी नीति के निर्माता होते हैं अतः योजना आयोग व कैबिनेट द्वारा परिषद् के दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं की जाती है, लेकिन अनेक अवसरों पर असहमति के मामले उपस्थित हुए हैं जिन्हें आपसी सहयोग से सुलझाया जाता है।

योजना क्षेत्र की प्रमुखता और एकात्मकता की प्रवृत्ति इस विचार से प्रेरित है कि योजना को राष्ट्रीय दृष्टि की दृष्टि से संचालित करने उसे राष्ट्रीय स्वरूप देने और सम्पूर्ण देश में नियोजन को समान रंग में चलाने के लिए माध्यम-सामान केन्द्र का निर्देशन और नियन्त्रण उपयुक्त है। स्थानीय योजनाओं और राष्ट्रीय योजनाओं का प्रारम्भिक उल्लेखित राज्यों पर है, लेकिन केन्द्र को राज्यों के कार्य में सहायता, समायोजन, और निर्देशन करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन और विकास समीक्षणक ढंग से हो सके। यह आरोप व्यक्तित्वित है कि योजना क्षेत्र में राज्य सरकारों की स्थिति केन्द्र के हाथ में कठपुतलियों जैसी हो गई है। इसके विपरीत पल एतद्विजे जैसे विद्वानों का मत है कि विक्रम के सम्पूर्ण क्षेत्र में केन्द्र वास्तविक शक्तियों का उपयोग नहीं करता। उसका कार्य 'स्टाफ फंक्शन्स' (Staff Functions) का है न कि 'लाइन फंक्शन्स' (Line Functions) का। समय की माँग है कि हम केन्द्र की प्रमुखता या राज्यों की प्रमुखता के विवादों में पड़ने के बजाय यह मानकर चलें कि योजना एक राष्ट्रीय दृष्टि है जिसे राजनीतिक संदेबादी और दबावों से दूर रखा जाना चाहिए। केन्द्र और राज्यों के सहयोग पर ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और राष्ट्र की समृद्धि निर्भर है।

(घ) केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों का मूल्यांकन

(इ) क्या राज्यों की स्थिति 'नगरपालिकाओं' जैसी है?

संविधान में केन्द्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं और योजना आयोग जैसी शक्तिशाली संविधानेन सभा केन्द्र-राज्यों पर अपना प्रभाव जमाव रखती है, तथापि यह आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण है कि "राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं के समान हो गई है।" सभात्मक शासन-व्यवस्था में शक्तियों का केन्द्रीकरण होता अथवा केन्द्र की राज्य सरकारों की अपेक्षा सशक्त होना कोई महत्व नहीं रखती है। संविधान सभा में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अत्यधिक केन्द्रवाद सम्बन्धी आलोचना का उत्तर देते हुए कहा था—“राज्यों की नगरपालिकाओं का स्तर देख कर संविधान ने केन्द्र को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं यह गर्भाशय शिकयत है। यह दृष्टिकोण अत्युक्तिपूर्ण है, तथा संविधान के उद्देश्यों के सम्बन्ध में भ्रान्त धारणा पर आधारित है।” “केन्द्र तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करने समय इन अपभारभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए कि सफलक शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वितरण स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है, केन्द्र-निर्मित विधि द्वारा नहीं। हनरा संविधान दत्त कार्य करता है इसलिए राज्य अपनी विधायी तथा कार्यपालिकाओं की शक्तियों के लिए किसी प्रकार केन्द्र पर आश्रित नहीं हैं। राज्य तथा केन्द्र एक स्तर पर हैं।”

“सभात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी तथा कार्यपालिका की सत्ता का केन्द्र और एकता में वितरण करना है। इस सिद्धान्त का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है, अतः यह कथन असत्य है कि राज्यों को केन्द्र के अधीन रखा गया है। केन्द्र अपनी इच्छा से विभाजन रखा बदल नहीं सकता। इसमें कोई म्यापलन परिवर्तन नहीं ला सकते। वे संशोधन कर सकते हैं किन्तु इस विचार को बदल नहीं सकते हैं। नई शक्तियों तथा दृष्टिकोण की प्रस्तुत कर व्यापक इन उपबन्धों की व्याख्या में अन्तर ला सकता है। उपबन्ध मामलों (Marginal Cases) में

सोमनेखा को इधर उधर कर सकता है किन्तु विपरीत सत्ता द्वारा ऐसी सोमनेखा बन जाती है जिसे वह लौंच नहीं सकता शक्ति का पुनर्विभाजन नहीं कर सकता है। सत्ता-वितरण की वर्तमान व्यवस्था को व्यापक रूप में न्यायलयाँ डाढ़ दिया जा सकता है किन्तु एक अधिकारी को दो गई शक्तियाँ वे दूसरे अधिकारी को नहीं सौंप सकते हैं।¹

हॉ. अवेडकर के उपर्युक्त विचारों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों की संस्थागत स्थिति को स्वीकार किया है। वे अपने अस्तित्व के लिए केन्द्र की कृपा के मोहताज नहीं हैं। संविधान निर्माताओं ने उन्हें व्यापक अधिकार प्रदान किये हैं। राज्य-सूची में उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए हैं। राज्यों द्वारा समवर्ती सूची पर कानून बनाया जा सकता है और शक्ति-विभाजन में केन्द्र को सर्वोच्चता दी गई है किन्तु राज्य पूर्णतया शक्ति-हीन नहीं है। वे अपने अधिकारों का शक्तियों का प्रयोग करके लोक-कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रीय केन्द्र की तुलना में राज्यों के आर्थिक संसाधन बहुत कम हैं अगर राज्य पितृव्यवाद से कार्य करें और अपने संसाधन जुटाने का प्रयास करें तो केन्द्र पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है। प्रशासनिक क्षेत्र में केन्द्र राज्यों को निर्देश दे सकता है और आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग कर राज्यों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सकता है। उरी राज्यों ने लोकतांत्रिक सरकार अनिवार्य रूप से बढ़ाल करनी ही पड़ती है। एक निश्चित समावाधि पूरी होने के बाद राज्य विधानसभाओं के चुनाव अनिवार्य रूप से कराने पड़ते हैं। केन्द्र राज्यों के सम्प्राप्ति स्वरूप को न तो समाप्त कर सकता है और न ही लोकतांत्रिक सरकार के सिद्धान्त को समर्थन दे सकता है। निकर्षित राज्यों का स्थिति नगरपालिकाओं जैसी नहीं है। यह एक अतिरिक्त तथा अतिशयोक्तिपूर्ण दावेक्षण है।

(च) केन्द्र-राज्य विवाद के मुख्य कारण

तनाव के सांविधानिक कारण

1. भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण केन्द्र के पक्ष में अधिक है। सच-सूची और समवर्ती सूची में केन्द्रीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि राज्यों की स्वायत्तता पर आंच आ सकता है। 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रा समिति ने सिफारिश की थी कि—(i) सच-सूची और समवर्ती सूची में से कुछ शक्तियाँ निकाल कर राज्य-सूची में डाल देनी चाहिए, (ii) वित्त आयोग को एक स्थायी अधिकार बना देना चाहिए, (iii) केन्द्रीय राजस्व स्त्रोतों को घटा कर राज्यों को हस्तान्तरित कर देना चाहिए ताकि केन्द्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता कम हो।

2. राज्य यह अनुभव करते हैं कि उनकी विधायी और प्रशासनिक शक्तियाँ इतनी सीमित हैं। उन्हें अपने निर्णयों के कार्यान्वयन में केन्द्र का मुँह ताकना पड़ता है। जब केन्द्र और राज्यों में एक दल की सरकार रहती है तब समस्या नहीं होती, लेकिन विपरीत स्थिति में तनाव प्रायः बढ़ जाता है।

3. राज्यपाल केन्द्र द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो राज्यों में केन्द्र का वर्चस्व बनाने रखने में सहयोग देते हैं। संविधान उन्हें अधिकार देता है कि समवर्ती सूची से सम्बद्ध विधेयकों को वे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लें और केन्द्रीय सरकार को यह अवसर प्रदान करें कि वह राष्ट्रपति द्वारा विधेयक या विधेयकों को अस्वीकृत करा दें। केन्द्र के राज्यपाल ने ई. एस. एस. नम्बूद्रीपाद के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकार को प्रगतिशील भूमि सुधार विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लिया था। बाद में केन्द्रीय सरकार ने इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत करा दिया। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव ने उन्हें केन्द्रीय जामूस की सजा दी थी। अनेक अवसरों पर राज्य सरकारों द्वारा राज्यपाल पद को समाप्त करने की प्रार्थना की गई है। राज्यपाल पद ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों में यथोचित तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की है।

4. आपातकालीन उपबन्धों ने संविधान को एकलपक्ष स्वरूप प्रदान कर दिया है और आपातकाल के दौरान राज्य सम्पूर्णतः केन्द्र निर्देशित इकाइयों बन जाते हैं। यह स्थिति कुछ राज्य सरकारों के लिए अग्रिम रही है। तनाव के सांविधानिक कारणों का अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि राज्य चाहते हैं कि उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाये तथा उन पर केन्द्र का अकुश न रहे।

तनाव के व्यावहारिक कारण

केन्द्र राज्य सम्बन्धों में तनाव के लिए व्यावहारिक कारण उत्तरदायी रहे हैं जिनका उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है—

1. केन्द्र और राज्यों में यह तनाव पैदा हो जाता है कि राज्य द्वारा आर्थिक अनुदान या आर्थिक सहायता माँगने पर केन्द्रीय सरकार एक ओर उदार स्वैय्य न अपनाकर यह आरोप लगाती है कि राज्य सरकारें स्वयं के राजस्व स्त्रोतों का

समुचित विरोध नहीं करती। केन्द्र का यह आरोप रहा है कि कुछ राज्य सरकारों उपलब्ध राशि का विक्रय याजनाश्र पर उचित समय पर व्यय नहीं करती।

2. ओवर-इन्फ्लेक्शन को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच सघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती है।

3. अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की निष्पक्षता को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाय जाते रहे हैं।

तनाव के राजनीतिक कारण

1. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एक-दूसरे पर सघर्ष दलबन्दी की भावना के आरोप लगाए जाते हैं। केन्द्र में किसी शासन के समय जब कभी किसी राज्य में गैर-कॉन्ग्रेसी सरकार बनी तो उसका आरोप रहा है कि केन्द्र राज्य सरकार को गिराने या नीचा दिखाने की प्रयत्नशील है। दूसरी ओर केन्द्र का आरोप रहा है कि राज्य सरकार केन्द्र के साथ असहयोग की राजनीति खेल रही है। इस तरह के आरोप-प्रत्यारोपों से पारस्परिक सम्बन्धों में तनाव पैदा होता है।

2. कुछ विपक्षी दल क्षेत्रीय सामुदायिक भावनाओं की मदद से जनता में लोकप्रिय होना चाहते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य के बीच तनाव पैदा करते हैं। धामपदी दल, जिनकी लोकप्रियता कुछ क्षेत्रों तक सीमित है निर्वाचन नीति के रूप में केन्द्र के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार करते रहते हैं।

(छ) केन्द्र-राज्य मतभेदों को दूर करने के सुझाव

1. भारतीय संविधान स्वरूप में सघातक, किन्तु अन्ध्रा से एकात्मक है, अतः इसे आत्मा से सघातक बनवा जाय, इस हेतु समस्त सूची के विषयों का पुनर्विभाजन इस प्रकार हो कि शक्ति-विभाजन का सन्तुलन राज्यों के पक्ष में हो जाय।

2. राज्यों को लचीले वित्तीय श्रोत प्रदान किए जाएँ ताकि उनकी आय बढ़ सके। राज्यों को अपने वित्तीय सघर्षों में वृद्धि तथा अपने प्रशासनिक व्यय में निरव्ययता के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

3. केन्द्र के पास राज्यों को विवेकानुसार अनुदान देने की शक्ति न रहे।

4. वित्त आयोग को स्थायी सभा के रूप में परिवर्तित किया जाए और इस आयोग का परामर्श केन्द्र के लिए बन्धनकारी होना चाहिए।

5. योजना आयोग को स्वायत्त सार्वजनिक स्टार प्रदान किया जाए।

6. राज्यों की आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए स्थायी, किन्तु गैर-राजनीतिक समिति गठित की जाए जो केन्द्र एवं राज्यों के मध्य आर्थिक सम्बन्ध का कार्य करे।

7. अनुच्छेद 263 के अनुसार अन्तर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) स्थापित की जाए तो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करे।

8. राष्ट्रपति एवं राज्यपाल सम्बन्धी सार्वजनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके उनकी शक्तियों में वृद्धि की जाए ताकि वे किसी विवशता से हटकर स्वविवेक से काम कर सकें।

9. किसी व्यक्ति को एक बार राज्यपाल नियुक्त किया जाए, मेल-मुका होने पर न तो उसे लम्बे का पद दिया जाए और न उसे राजनीति में भाग लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यपाल पद पर राजनीतिक आधार पर नियुक्ति नहीं की जाकर, योग्यता के आधार पर उचित नागरिक को नियुक्त किया जाना चाहिए।

10. राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक समिति बनाई जाए जिसके परामर्श पर राज्यपाल, न्यायाधीश, योजना आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति हो। इससे इन पदों पर औसत दर्जे के नागरिकों के स्थान पर योग्यतम नागरिक प्रतिष्ठित हो सकेंगे।

11. केन्द्र राज्य सूची के विषयों में हस्तक्षेप न करे। राज्य-सूची के विषयों सम्बन्धी कार्यक्रम लागू करने उन पर धन व्यय करने आदि का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर रहे। अपवाद रूप में राष्ट्रीय हितों की भाग पर राज्य सूची पर केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए।

12. प्रशासन, वित्त और विधायी सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय निदब्रण की व्यवस्थाएँ सिद्धि की जाएँ। इससे राज्यों को अपना विकास करने का समुचित अवसर प्राप्त होगा।

13. अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकार राज्य-सेवा में हैं, उन्हें उन पर पूरा निदब्रण राज्य सरकार का हो।

14. अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए सार्वजनिक सम्बन्ध समिति की स्थापना हो, यह समिति सघर्ष प्रश्नों पर राज्य को परामर्श दे।

15 संविधान के अनुच्छेद 249 पर पुनर्विचार किया जाए।

16 सम्बन्धी मूवी के ऐसे विषय राज्य-मूवी में रख दिए जाएँ जिनसे राज्यों के अधिकारों में वृद्धि होती हो लेकिन केन्द्र की शक्ति पर कोई आपत्ति न आती हो। इन विषयों को सशर्त राज्यों को सौंपा जाए।

17 राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श के लिए एक उच्च-स्तरीय सौविधानिक सलाहकार समिति स्थापित की जाए जो राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, निरन्तर एवं महालेखापाल, योजना आयोग के सदस्य आदि को नियुक्ति, न भविष्यक निर्माण के समय अनुपालनीय अभिप्रायों में व्यवस्थापिका को भग करने और विशेषकों को राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु आर्शित करने के सम्बन्ध में और अन्य राष्ट्रीय विषयों पर सलाह दे। इस समिति में उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों, भूतपूर्व राष्ट्रपतियों, देश के सौविधानिक बौली को अवश्य स्थान दिया जाए। प्रधानमंत्री की सिफारिशों के महत्व को किसी रूप में कम न करते हुए सौविधानिक सलाहकार समिति की नियुक्ति को व्यवस्था विपरीतीय हो सकती है। व्यावहारिक राजनीति की आवश्यकता है कि समिति को सनाइ प्रधानमंत्री अथवा मन्त्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित हो।

सरकारिया आयोग की सिफारिशें—9 जून 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अणु एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था जिसे 'सरकारिया आयोग' के नाम से जाना जाता है। श्री शिवरामन् और एम आर सेन की इस आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति की गई। आयोग ने देश के सभी राजनीतिक दलों और संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने आयोग के सम्मुख प्रतिवेदन देते हुए अपना मत प्रकट किया। 30 जनवरी 1984 को आयोग के प्रतिवेदन को मुख्य सिफारिशों का प्रकाशन किया गया जिनमें उल्लेखनीय ये हैं—

1. आयोग के प्रतिवेदन में सुदृढ़ केन्द्र की अवधारणा पर बल दिया गया है।
2. आयोग का यह मत है कि केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की जो व्यवस्थाएँ संविधान में की गई हैं उनमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. आयोग ने राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में केन्द्र और राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए 'सहकारी सघवाद की अवधारणा' का समर्थन किया है।
4. आयोग ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण करने के पक्ष में अपना अभिमत प्रकट किया है।
5. आयोग ने यह सिफारिश की है कि किसी राज्य को उपद्रव-ग्रस्त घोषित करने और किसी राज्य में केन्द्र द्वारा सुरक्षा बलों को भेजने से पूर्व राज्य सरकार से सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि आयोग का यह स्पष्ट मत है कि केन्द्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है।
6. आयोग ने राष्ट्रीय विवास परिषद के नाम में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। आयोग के मत में इसका नाम 'राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद' कर देना चाहिए।
7. आयोग ने केन्द्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने हेतु एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना के पक्ष में विचार व्यक्त किया है।
8. आयोग का यह सुझाव है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी का नेता राज्यपाल न बने और राज्यपाल पद से निवृत्त होने के बाद उसे लाभ का पद नहीं दिया जाना चाहिए।
9. आयोग का मानना है कि अनुच्छेद 356 का सहारा सोच विचार कर लिया जाना चाहिए।
10. आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की वकालत की है।
11. आयोग ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर केन्द्र के अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा है कि इन्हें प्रतिदिन के मासलों का संचालन करने के लिए उचित सोपा तक 'विकेन्द्रीकरण' की स्थिति प्रदान करनी चाहिए।
12. राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाने वाले विधेयकों की समय सीमा निश्चित करने में आयोग ने कहा है कि इस में अग्रवश्यक बिलम्ब को रोकना जाना चाहिए।

सरकारिया आयोग ने 'सुदृढ़ केन्द्र' की अवधारणा पर बल दिया है। भारत की एकता और अखण्डता को सुरक्षा के लिए केन्द्र का सुदृढ़ होना परम आवश्यक है, अतः सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू कर केन्द्र राज्य सम्बन्धों में नये युग का सूत्रपात किया जा सकता है।

राज्य स्वायत्तता की उठती माँग (Demand for State Autonomy)

राज्य-स्वायत्तता का प्रश्न भारतीय सघवाद का मुख्य प्रश्न बिन्दु है। 1967 के पूर्व केन्द्र तथा राज्यों में एक दल की सरकारों के सत्तारूढ़ होने के कारण यह समस्या कभी नहीं उठी, लेकिन 1967 के बाद केन्द्र राज्य सम्बन्धों के स्वरूप

में परिवर्तन हुए। अनेक राज्यों में गैर-कॉंग्रेसी सरकारों के सत्तारूढ़ होने के कारण केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। केन्द्र और राज्यों में तनाव का मुख्य बिन्दु यही है कि राज्य चाहते हैं कि उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, उन पर केन्द्र का अकुश न रहे। चौथे आम चुनावों के बाद चेन्नई में तत्कालीन द्रमुक-मन्त्री अन्नादुराई ने कहा था—“हमें संविधान-निर्माताओं द्वारा निर्धारित राज्यों की स्वायत्तता के सिद्धान्त को अपनाया चाहिए। सग्राहक संविधान में केन्द्र द्वारा उतनी शक्तियाँ व्यवहार में लाई जानी चाहिए, जिससे कि देश की सम्प्रभुता और एकता की रक्षा हो सके। राज्यों को संविधान की ओर से स्वायत्तता प्राप्त है और उनके साथ नगरपालिकाओं जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।” इस मौग को परिष्कृत बंगाल में अजय मुखर्जी के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार और पंजाब में सरदार गुरनामसिंह के नेतृत्व वाली अवाली सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ। मार्च, 1977 में कांग्रेस शासन के पतन के बाद स्वायत्तता की माँग जोर-शोर से उठी। परिष्कृत बंगाल के वामपंथी मोर्चे की सरकार के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने एक धाँपत्र तैयार कर सभी राज्यों को भेजा जिसमें निम्नलिखित माँगें रखी गई—

(1) केन्द्र के पास प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, व्यापार, मुद्रा संचार तथा आर्थिक समन्वय जैसे विषय रहे। शेष सभी विषय राज्यों को सौंप दिए जाएँ। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दे दी जाएँ। (2) संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को समाप्त कर दिया जाए और राज्यपाल के पद को पूर्ण सार्वभौमिक बनाया जाए। (3) संविधान की प्रस्तावना में ‘यूनिफन’ (Union) शब्द के स्थान पर ‘फेडरेशन’ (Federation) शब्द रखा जाए। (4) राज्य विधान-मण्डल जो कानून पारित करे उसे किसी स्थिति में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुप्रीम न रखा जाए। (5) योजना आयोग का स्वरूप और गठन का नियंत्रण राष्ट्रीय विकास परिषद करे। (6) केन्द्रीय सरकार की आय का 75 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाए। (7) राज्य-सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाए। इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो। (8) संसद के दोनों सदनों के अधिकार समान हों।

जम्मू-कश्मीर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला तथा अन्य द्वारा ज्योति बसु की माँगों का समर्थन किया गया। जम्मू-कश्मीर राज्य को देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। जनता पार्टी द्वारा शासन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दबे स्वर में इस प्रकार का विचार व्यक्त किया कि राज्यों को अधिक वित्तीय साधन प्रदान किए जाने चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देना आवश्यक नहीं है। यद्यपि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के स्वरूपों पर विचार किया जा सकता है। सरकारिया आयोग ने इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सुदृढ़ केन्द्र की अवधारणा पर बल दिया है। इस प्रसंग में नया अध्याम तब जुड़ गया जब जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने 26 जून, 2000 को राज्य की स्वायत्तता प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूर कर केन्द्र के सामने एक सफट खड़ा कर दिया। इस प्रस्ताव को केन्द्र ने नमजूर कर दिया है किन्तु ध्यान में रखते योग्य यह है कि जम्मू-कश्मीर में सत्तापंथी दल की तत्कालीन केन्द्र सरकार में सङ्केतशील थी।

व्यवहार में सहकारी संघवाद

(Co-operative Federalism in Practice)

भारत में संघवाद के सैद्धांतिक और कार्यकण सम्बन्धी सार्ग विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान को ‘सहकारी संघवाद’¹ (Co-operative Federalism) को कहा जा सकता है। सहकारी संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली होती है, किन्तु राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में बमबोर नहीं होती हैं। सहकारी संघवाद का यह मुख्य लक्षण है कि दोनों सरकारें एक-दूसरे की पूरक तथा निर्भर होती हैं। राष्ट्रीय और राज्य सरकार शासन की एक व्यवस्था के सर्वाधिक परिपूरक अंग (As Mutually Complementary Part of a Single System of Government) समझी जाती हैं जिनकी शक्तियों का प्रयोग सार्ग राज्य के सामान्य उद्देश्यों (Common Objectives) को प्राप्त करना होता है।² सहकारी संघवाद में केन्द्र और राज्य कानूनी रूप से एक-दूसरे से संपर्क में न उलझकर स्वयं को जनता की सेवा करने वाली संस्थाएँ मानते हैं।

ग्रेनविन आस्टिन के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर सहकारी संघवाद के उपरोक्त लक्षण भारत पर लागू होते हैं।³ परिस्थितियों, सांविधानिक प्रावधानों, संविधान-बद्ध संस्थानों (Extra-Constitutional Institutions) और स्वाधीनता-संग्राम के साधनों द्वारा प्रशासनिक उन्नयन के कारण व्यवहार में भारत में सहकारी संघवाद का

1 A. H. Brich, *Federalism, Finance and Social Legislation in Canada, Australia and United States* p. 305

2 M. V. Payley, *Constitutional Government in India*, p. 601

3 Granville Austin, *Op. Cit.*, p. 187

विकास हुआ है। इसके व्यवहृत करने में जिन व्यवस्थाओं का योग है वे हैं—1 योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद 2 वित्त आयोग और वित्तीय सहायता 3 नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक 4 क्षेत्रीय परिषदें 5 राष्ट्रपति की आपत्त शक्तियों का सभ्य के रक्षार्थ व्यवहारिक प्रयोग एवं 6 अन्य व्यवस्थाएँ सामुदायिक विकास योजना, अखिल भारतीय शोषण, एकल न्यायिक व्यवस्था आदि।

1. योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद—योजना आयोग की रचना संविधानेतर सभा (An Extra Constitutional Body) के रूप में हुई है। यह देश में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में गतिविधियों का विनियमन और निर्देशन करती है। इसी दृष्टि पर केन्द्र के नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन कहा जाता है परन्तु यह संवैधानिक स्थिति नहीं है। यदि कोई राज्य कहे कि योजना आयोग को संवैधानिक स्थिति नहीं है अतः वह निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है तो भारत सरकार उसे संवैधानिक प्रावधान से निवृत्त नहीं कर सकती।¹ सम्पूर्ण नियोजन व्यवस्था ऐसी है कि भारत सरकार पञ्चवर्षीय योजना स्वीकार करने में राज्यों की सहमति और सहयोग का पूर्ण आदर कर, योजनाओं का पूर्ति के निम्न उद्देश्य आश्रयक आर्थिक सहायता देती है। नियोजन राज्यों के हित में है और इस कल्याण कार्य में जनता का विमुक्त होना किसी रूप में सम्भव नहीं है अतः राज्य केन्द्र को भारी वित्तीय सहायता प्रणप्त करने हेतु आयोग के निर्देशों को स्वीकार करते हैं।

निर्देशों को स्वीकार करते हैं। योजना आयोग राज्यों पर अपना निर्देश लागू करने का प्रयत्न नहीं करता है। राज्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) की स्थापना की गई है जिसका गठन प्रधानमंत्री केन्द्रीय मंत्रियों, योजना आयोग के सदस्यों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया गया है। योजना आयोग के निर्णयों का अनुसरण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। परिषद के सभी निर्णयों की केन्द्र और राज्य सरकारों गतनी हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थिति सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र के [ए एच सर्वोपरि कैबिनेट (Super Cabinet) को है—बम कस आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में यह ऐसी कैबिनेट है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए कार्य करती है। योजनाओं को कार्यरूप देने का उत्तरदायित्व राज्य वहन करते हैं किन्तु सभ्य सरकार के मन्त्रालय राज्य सरकारों के समानान्तर मन्त्रालयों की विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। केन्द्रीय मन्त्रालय राज्यों के सम्मेलन आयोजित करके उनसे कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। योजना के निर्माण में केन्द्र अथवा योजना आयोग राज्यों के विचारों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। नियोजन कार्य में सहयोग और समायोजन के लिए राज्यों के मंत्रियों विभागाध्यक्षों के होने चाहिए। सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और जितने लिए गए निर्णय एक पक्षीय नहीं होते। इससे सहकारी सचवाद केन्द्र और राज्यों में तारतम्य की भावना विकसित होती है।

2 वित्त आयोग और वित्तीय सहायता—सम और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों के निर्धारण में वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम् के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध ज्ञान असम्भव है। वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य सरकारों को कर आय और अनुदान के रूप में भारी धनराशि केन्द्र से प्राप्त होती रही है। वित्त आयोग की भूमिका 'सरकारी सम्वाद को आगे बढ़ाने वाली है।

3 निपत्रक एवं महलेखा परीक्षक—भारत का निपत्रक एवं महलेखा परीक्षक, केन्द्र और राज्य सरकारों के सहयोग को रखने तथा मन्त्र के आवश्यक निपत्रक सहित सहकारी सभवाद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभ 4 राज्यों के हिसाब वरी प्रकार रहे जाते हैं जैसा पदधिकारी राष्ट्रपति की स्वीकृति से निर्धारित करता है। सभ 4 राज्यों के हिसाब वरी प्रकार रहे जाते हैं जैसा पदधिकारी राष्ट्रपति की स्वीकृति से निर्धारित करता है। इसके प्रतिवेदन को राष्ट्रपति सभद व प्रत्येक सदन में रखवाता है और राज्य के हिसाब एवं जांच की रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा राज्य विधान-मण्डल क सभने रखी जाती है। सम्पूर्ण देश के हिसाब की जांच आदि के लिए सभ द्वारा संगठित ध्यवस्था है। फलस्वरूप केन्द्र और राज्य सरकारों वित्तीय सहयोग के सूत्र में बंधी है। भारत में एकहरी नागरिकता है और करताता के हित को सुरक्षा की दृष्टि से इस पदधिकारी का कार्य महत्वपूर्ण है।

4 क्षेत्रीय परिषदे—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय परिषदे (Zonal Councils) तीन दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं—प्रथम, ये राज्यों और संघीय क्षेत्रों के बीच तथा केन्द्र और राज्यों के बीच सामान्य समस्याओं में धनियुक्त सहयोग के लिए मिलन-भूमि तैयार करती हैं। इस दृष्टि से सघ सरकार के स्वायत्त मन्त्री को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। द्वितीय, प्रत्येक क्षेत्र (Zone) में आने वाले राज्यों और संघीय क्षेत्रों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं प्रशासनिक समन्वय को इनसे प्रोत्साहन मिलता है। ये परिषदे विकास कार्यक्रमों के उचित एकीकरण में सहायक होती हैं। तृतीय, ये परिषदे पृथक्तावादी प्रवृत्तियों और असहस्य प्रतिद्वन्द्वताओं पर रोक का कार्य करती हैं। ये परिषदे सहकारी सपना (Co operative Federalism) की भावना का प्रतीक हैं।

राज्यसभा के उप-सभापति का पद धारण करने वाला व्यक्ति यदि सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। यह अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे उसके पद से हटा सकती है।¹ इसी प्रक्रिया द्वारा राज्यसभा अपने सभापति (उप-राष्ट्रपति) को हटा सकती है। राज्यसभा को किंगडोम बैठक में उप-राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचारणीय हो तब उप-राष्ट्रपति उस सभा का अध्यक्षता नहीं करेगा।²

राज्यसभा का स्थाई और निरन्तर चलने वाला सभा बनाकर हमारे संविधान-निर्माताओं ने दृढ़ता का परिचय दिया है। सदस्यों के अन्वर्तन (Rotation) की प्रणाली के कारण न केवल सदन की निरन्तरता बनी रहती है बल्कि हर राज्य की विधानसभा को यह अवसर मिल जाता है कि वह इस सदन में कुछ नए सदस्यों का निर्वाचन करता रहे। राज्यसभा में वर्तमान दलीय शक्ति और प्रत्येक राज्य में व्यापक समकालीन दृष्टिकोण और मनोवृत्ति परिलक्षित होता रहती है। परिणामस्वरूप राज्यसभा में राष्ट्रीय नीतिगत व्यापक रहती है। फलतः राज्यसभा में अनुभव और योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व समष्टि हो पाता है।

लोकसभा की रचना एवं अवधि—लोकसभा (House of the People) एक लोकप्रिय सदन है जिसका निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क मतधारक के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को दिए गए स्थानों और उसकी जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए जहाँ तक व्यवहार्य हो एक जैसा बना रहे परन्तु यदि किसी राज्य की संख्या 60 लाख से कम है तो उपर्युक्त विधि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुरूप प्रत्येक जनगणना के पश्चात् विधान राज्यों में लोकसभा के स्थानों का आवंटन करने सम्बन्धी राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करने के लिए संसद को अधिकृत किया गया है। यह इस विषय पर विधि की संरचना को तथा समुचित निर्देशन प्रदान करे, परन्तु 2020 तक ऐसे किसी पुनः समायोजन की आवश्यकता नहीं है। 2020 तक 1971 की जनगणना के आधार पर प्रतिस्थापित व्यवस्था ही प्रभावी बनी रहेगी।³

लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए जनसंख्या से छव्वे 1971 में की गई जनगणना पर आधारित जनसंख्या है और वह 2020 तक वैसा बनी रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण 2020 तक 1971 की जनगणना के आधार पर बना रहेगा।

अवधि (Period)—लोकसभा यदि पहले विघटित न कर दी जाए तो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से पाँच वर्ष तक चलेगी। राष्ट्रपति इस अवधि से पहले उसे विघटित कर सकता है।⁴ संसदकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल में एक समय में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है परन्तु घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के बाद यह अवधि सात के लिए बढ़ाई जा सकती है। 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था 1977 के प्रारम्भ में कार्यकाल को एक बार बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। 1971, 1980, 1991, 1996 और 1998, 2004 में ऐसा किया गया था, अतः इस सदन की अवधि निश्चित नहीं हुए भी अनिश्चित है।

लोकसभा की अर्हताएँ—लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में ये शर्तें होनी चाहिए—(1) वह भारत का नागरिक हो (2) 25 वर्ष से कम का न हो (3) वे तब अन्य अर्हताएँ हानी चाहिए जो संसद निश्चित करे। उसे भारत की प्रभुता तथा अखण्डता के प्रति शपथ लेनी होती है। जो व्यक्ति (1) भारत में किसी सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर हो जिस पर होना संसद के कानून द्वारा अनर्हता ठहराई गई हो (2) विद्रोह गतिविधि का हो (3) उन्मुख दिकाल्पिता हो (4) स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक बन गया हो एवं (5) संसद द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। सदस्यों की अनर्हता सम्बन्धी प्रत्येक प्रश्न, निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंप जाएगा, किन्तु इन मामलों में उसे निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार ही कार्य करना होगा।

1 अनुच्छेद 53

2 अनुच्छेद 53

3 महासभाय शर्मा पूर्वोक्त पृ 239

4 अनुच्छेद 83(2)

एक साथ दोनों सदनों की सदस्यता वर्जित

कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदनों (एकसभा एवं राज्यसभा) का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो सदन विधि द्वारा यह व्यवस्था करेगा कि उसका रिक्त सदन का स्थान रिक्त माना जाए।

समस्त सदस्यों के विशेषाधिकार

भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं और सदन के स्थानीय आदेशों तथा नियमों के अनुसार सदन सदस्यों के लिए वास्तु स्वतंत्रता निश्चित की गई है। फलतः उनके द्वारा दिए गए किसी भाषण अथवा मत के सम्बन्ध में देश की किसी न्यायपालिका में कोई आपर्याही नहीं की जा सकती है। यह सरल सदन के नियमन में प्रदर्शित भेदन का कार्यप्रणाली के लिए साधु होता है। सदन सत्र के प्रारम्भ होने के 40 दिन पूर्व और पर्याप्त किसी सदस्य को जीजायी विधियों के लिए साधु होता है। सदन सत्र के प्रारम्भ होने के 40 दिन पूर्व और पर्याप्त किसी सदस्य को जीजायी विधियों के लिए साधु होता है। सदन सत्र के प्रारम्भ होने के 40 दिन पूर्व और पर्याप्त किसी सदस्य को जीजायी विधियों के लिए साधु होता है। सदन सत्र के प्रारम्भ होने के 40 दिन पूर्व और पर्याप्त किसी सदस्य को जीजायी विधियों के लिए साधु होता है।

समस्त सदस्यों के दैनिक भत्ते

सदन सदस्यों के वेतन-भत्तों के निर्धारण करने का अधिकार सदन को है। सदन द्वारा उसमें परिवर्तन किया जाता रहा है। सदन सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन (सरोपन) अधिनियम, 1993 (1998 का 28) के द्वारा सदन सदस्यों का वेतन एक हजार पाँच सौ रु से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रतिमास, दैनिक भत्ते को दो सौ रुपये से बढ़ाकर चार सौ रुपये, एक वर्ष में एक बार हाट की जाने वाली एकल यात्राओं की सख्या को 28 से बढ़ाकर 32 करने, जिसके साथ यह उपबन्ध है कि वायुमार्ग द्वारा वर्ष में जितनी यात्राएँ नहीं की जाएंगी उन्हें परचयवर्ती वर्ष में अनर्गल कर दिया जाएगा। इसी के साथ सड़क एवं रेल द्वारा यात्रा की सुविधा उपलब्ध है, न्यूनतम पेंशन को एक हजार चार सौ रुपये से बढ़ाकर दो हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमास ऐसे सदस्य के रूप में सेवा के चौथे वर्ष से अधिक प्रति वर्ष के लिए दो सौ पचास रुपये की अतिरिक्त पेंशन को बढ़ाकर पाँच सौ रुपये, किसी ऐसे सदन सदस्य की निमयी मृत्यु ऐसे सदस्य के 75 में उसकी पदावधि के दौरान हो जाती है, पत्नी या पति की या ऐसे सदस्य के अश्वि की पेंशन की राशि को पांच सौ रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर एक हजार रु कर दिया गया है।

प्रतिवर्ष सामग्री को दो करोड़ रुपये के विकास कार्य के मुझव देने का अधिहार

23 दिसम्बर, 1993 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने सदन में घोषणा की कि स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपने क्षेत्रों में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की विकास योजनाएँ कार्यन्वित करा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन अपने राज्य के चुनीदा क्षेत्र में अपनी पसन्द की विकास परक योजनाएँ मुझ सकते हैं। कोई परियोजना दस लाख रुपये से ज्यादा की नहीं होगी तथा एक सदन में अधिकतम एक करोड़ रुपये तक की योजनाएँ मुझाई जा सकेंगी। प्रधानमंत्री ने उन कार्यों की सूची जारी की, जिन्हें इस योजना के तहत लाया जा सकता है। इसमें आवागमन एवं स्कूल भवनों का निर्माण, नलकूप जैसे पेयजन स्रोत उपलब्ध कराना, गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें बनाना, वृद्ध लोगों के लिए आश्रयस्थल तथा ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, सामाजिक चरित्रों, तालों की सफाई, नदी तालावों की सफाई और नहरें बनाना आदि शामिल हैं। इनके अलावा गोबर गैस सयनों एवं छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, गन्दी कस्बियों में शौचालय, श्मशान स्थल, बस स्टैण्ड और छोड़ा स्थल बनाने का काम इस योजना के तहत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सूची में परिवर्तन किया जा सकता है। इस योजना को व्यवहार में कार्यरूप दिया जा चुका है। इससे सदन सदस्यों की शक्ति में वृद्धि हुई है। इस योजना के अन्तर्गत जो कार्य हथ में लिये जाते हैं, उनका निष्पदन प्रारम्भ करता है। वर्तमान में यह राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रु कर दी गई है।

समस्त के दोनों सदनों के पर्याधिकार

एकसभा—पारत का उप-एकसभा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एकरा का अस्तन प्रश्न करते सदन वर राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता और न ही इस पद में सम्बन्धित वेतन अथवा अन्य पत्रों ले सकता है।

सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापतित्व उप-सभापति करता है जो सदन का सदस्य होता है और सदन के सत्रों को द्वारा नियोजित किया जाता है। राज्यसभा का सचिवसच्य होता है जिसका प्रथम एक सचिव होता है। राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति का वेतन भारत की सचिव निधि से दिया जाता है। उनको वे अधिकार प्राप्त हैं जो सामान्यतया विधान-सदस्यों के अधिकारों को प्राप्त करते हैं। यथा—सदस्यों को भाषण की अनुपति प्रदान करना, कार्य प्रणाली सम्बन्धी प्रश्नों को तय करना, बंद विवाद को अनुशसित और सुसंगत बनाए रखना, विचारार्थ प्रश्नों पर मतदान करना और मतदान का परिणाम घोषित करना आदि। सभापति का कार्यकाल पाँच वर्ष है किन्तु उप-सभापति को छ वर्ष के लिए चुना जाता है। सदन के सत्रों के बीच बचकर रहने पर सभापति अपने निर्णायक मत (Lasting Vote) का प्रयोग करता है किन्तु अपने मतधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

लोकसभा—लोकसभा अपने सत्रों में स एक अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का निर्वाचन करती है। सदन के प्रत्येक सदन को अपना सचिविक कर्मचारीबृन्द (Secretarial Staff) रखने का अधिकार है। लोकसभा के सचिवसच्य का प्रमुख एक सचिव (Secretary) होता है जो स्थायी पदाधिकारी होता है और अध्यक्ष की ओर से सदन के कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक तथा कार्यपालक (Executive) कर्तव्यों का पालन करता है। कई मामलों में वह सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा साधारण सदस्यों का परामर्शदाता है। सभापति की सहाय्य प्रणाली में सदन में प्रत्येक दल का संगठन होता है। उसके कई अधिकारी होते हैं जिन्हें सचेतक (Whips) कहा जाता है। ये दल के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ससनीय लोकसभा का मुखाल रूप और बिना किसी बाधा के का रचना सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों के सचेतकों पर निर्भर करता है।¹ लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचिव ससदीय-कार्यबन्धा होता है।

लोकसभा का अध्यक्ष

(Speaker of the House of the People)

भारत के लोकसभाध्यक्ष का पद प्रतिष्ठ गौरव और गरिमा का है। लोकसभा के सभी अध्यक्षों ने अभी तक अपना निष्पत्ता और शक्ति को बनाए रखा है। अध्यक्ष राजनैतिक दल से चुना होता है परन्तु अध्यक्ष चुने जाने के बाद दल की सत्स्यता से त्याग पत्र दिये जाने के उदाहरण हैं। भारत में अध्यक्ष शासक दल से और उपाध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। लोकसभा में बनाये जाने की परम्परा विकसित हो जा रही है। इसका उद्देश्य अध्यक्ष की निष्पत्ता को बनाये रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों और प्रभाव में ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा अध्यक्ष सभा की रक्षितियों का प्रतीक है। लोकसभा का अध्यक्ष-पद जिसे 1947 से पहले सभापति कहा जाता था 1921 में पद का रहा है। जब मॉन्टेग्यू-चैम्बरलेन सुधारों के अन्तर्गत पहली केंद्रीय विधानसभा बनी थी, उससे पहले विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता गवर्नर जनरल किया करते थे।² स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था है।

अध्यक्ष का निर्वाचन (Election of the Speaker)—निश्चित विधि पर अध्यक्ष का निर्वाचन राष्ट्रपति के आदेश पर लोकसभा के सदस्य करते हैं। इसके पूर्व प्रस्तावक, अनुमोदक तथा प्रत्याशों की सहमति के साथ नामांकन किया जाता है और निर्वाचन बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत दल अर्थात् शासक दल की ओर से प्रधानमंत्री प्रस्तावक होते हैं। बहुमत का समर्थन प्राप्त व्यक्ति निर्वाचित घोषित हो जाता है। इस सन्दर्भ में यह स्मरणीय तथ्य है कि यदि प्रत्याशी एक ही हो, प्रस्ताव विधिवत पारित होता है और निर्वाचन की घोषणा की जाती है। निर्वाचन का उपरान्त प्रथमपक्ष और मुख्य विरोधी दल के नेता प्रणेनीय अध्यक्ष के पास जाते हैं उसका अधिवादन करते हैं तथा उसे अध्यक्ष के आसन तक ले जाते हैं।

अध्यक्ष का कार्यकाल, उसकी पदभक्ति, वेतन एवं घरे

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य रहने तक पद पर बने रहते हैं तत्पश्चात् उन्हें अपना पद रिक्त करना होता है किन्तु लोकसभा के विघटित हो जाने के बावजूद अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं। वे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पदों से हटाए जा सकते हैं। प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक उसे प्रस्तावित करने के अधिप्राय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना न दी गई हो। लोकसभा

1. कौल एवं शकधर पूर्वोक्त, पृ 128-129

2. कौल एवं शकधर पूर्वोक्त, पृ 72

को किसी बैठक में जब अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव विचारणीय हो, तब अध्यक्ष और जब वह उपाध्यक्ष के विरुद्ध हो तो उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में वह भाग ले कर अपना मत दे सकता है, किन्तु मत संपादन होने की दृष्टि में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जिसे संसद विधि द्वारा नियंत्रित करे। जब तक कोई विधि पारित नहीं की जाती है, तब तक उसे वही वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित हैं।¹

अध्यक्ष पद की गरिमा

लोकसभा का औपचारिक प्रधान लोकसभा का अध्यक्ष है। अध्यक्ष निष्पक्षता का प्रतीक है और उस अपने प्राधिकार का प्रयोग निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह उचितता से करना चाहिए। निष्पक्ष रहने की जिम्मेदारी सचिवालय ने उम पर डाली है। मत-साम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अध्यक्ष के कठिन कर्तव्यों के निर्वहन में उसे न्याय तथा औचित्य की भावना से प्रेरित होकर सभा को यह विश्वास दिलाना होता है कि वह स्वयं को सभा की अन्तर्गतता और रक्षक समझता है। सभा का प्रमुख बचना होने के नाते वह उसकी सामूहिक अग्रगण्य है और बाहर की दुनियाँ के लिए सभा का एकमात्र प्रतिनिधि। राष्ट्रपति से लोकसभा के नाम जो सन्देश आते हैं वे अध्यक्ष के माध्यम से आते हैं। वह उसे सभा को पढ़कर सुनाता है और उस सन्देश में उल्लिखित विषयों पर विचार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश देता है। राष्ट्रपति को जो सन्देश भेजे जाते हैं वे अध्यक्ष के माध्यम से भेजे जाते हैं। राज्यसभा के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधि होता है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम लोकसभाध्यक्ष जी. बी. भावलकर थे। उनको इस पद पर रहते हुए असाधारण रूप से सम्मान प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य

1. अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके संचालन का नियन्त्रण करता है। सभा के सदस्य उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और जब वह बोलने के लिए उठता होता है तो उसे सभी खामोशी से सुनते हैं। उस समय सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सदन से उठकर नहीं जाएँ। अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अध्यक्ष के निर्णयों को भविष्य में मार्गदर्शन के लिए एकत्र कर लिया जाता है।

2. लोकसभा का अध्यक्ष अन्तिम निर्णय देता है कि कोई विधेयक वित्त-विधेयक है अथवा नहीं। वित्त-विधेयक जब राज्यसभा को भेजा जाता है तो उसके साथ अध्यक्ष का प्रमाण पत्र होता है कि वह वित्त-विधेयक है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाने वाले वित्त-विधेयक के साथ यही प्रमाण पत्र होता है।

3. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बैठक के सम्बन्ध में प्रक्रिया-नियम उसके निर्देशों तथा आदेशों के अन्तर्गत लागू होते हैं, किन्तु लोकसभा की बैठक यदि अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के किसी सकल्प पर विचार कर रही हो तो वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ऐसे विकल्प पर वह पहला मत दे सकता है, पर निर्णायक मत देने का उसे अधिकार नहीं रहता है।

4. लोकसभा की बैठक स्थगित करने या मणपूर्ति (कोरम) पूरा न होने की स्थिति में बैठक निर्यामित करने की शक्ति उसे प्राप्त है। वह किसी सदस्य को जो हिन्दी या अंग्रेजी भली-भाँति नहीं बोल सकता अपनी मातृ-भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।

5. अध्यक्ष सभा की बैठक के प्रारम्भ और समाप्त होने का समय तथा दिन नियंत्रित करता है। वह सभा स्थगित करने के निश्चित समय से पहले उसे बुला सकता है और अनिश्चित काल के लिए सभा को स्थगित करने के बाद परन्तु सत्रावसान से पहले उसे बुला सकता है।

6. वह शासक पक्ष के नेता से परामर्श करके सरकारी कार्यों का क्रम निर्धारित करता है। निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन के निश्चित एवं ठोस आधार ज्ञात होने पर वह उसमें संशोधन कर सकता है।

7. किसी विषय पर पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर हों तो वह निर्णायक मत देता है।

8. वह सदन में दलों तथा समूहों की मान्यता प्रदान करता है।

9. लोकसभा की गुप्त बैठकों की कार्यवाही का विवरण इस प्रकार किया जाए तब ऐसे अवसरों पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसके निर्णय का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है।

1. ब्रह्मरायण पाण्डेय : पूर्वोक्त, पृ. 302-303

2. कौल एवं रावथर : पूर्वोक्त, पृ. 103-105.

3. कौल एवं रावथर : पूर्वोक्त, पृ. 105-114.

10 वह लोकसभा में विचारार्थ प्रश्न प्रस्तावित कर उस प्रश्न को सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है तथा निर्णय के परिणाम की पोषणा करता है। सदस्य जो व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं उन पर अंतिम निर्णय देता है।

11 वह अपने विवेक से निर्णय लेता है कि प्रस्तावित विषय सदन में विचार करने योग्य है अथवा नहीं? मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आते हैं उनके विषय में वह यह सुनिश्चित करता है कि वे नियमानुसूल हैं अथवा नहीं? अनुदानों के प्रश्न पर जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं उनके विषय में वह निर्णय देता है कि प्रस्ताव नियमानुसार है अथवा नहीं?

12 उसे अधिकार है कि वह विधेयको तथा सक्त्यों के सम्बन्ध में जो संशोधन रखे हुए हैं उनमें से किसी को सदन के विचारार्थ रखे अथवा नहीं।

13 वह याचिकाएँ प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता है। वह सदन के नेता से परामर्श करके बजट आदि विधेयको पर विचारार्थ तिथि एवं समय निर्धारित करता है। उसकी अध्यक्ष के बिना विशेषाधिकार भंग के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

14 वह सदन की समितियों के अध्यक्षों को मनोनीत कर उन्हें परामर्श देता है उनका मार्गदर्शन करता है तथा समितियों की कार्य-प्रणाली निर्धारित करता है। वह 'कार्य-प्रणाली समिति', 'सामान्य प्रयोजनार्थ समिति' तथा 'नियम समिति' का पदेन स्थापित होता है जो उसके प्रत्यक्ष रूप से निर्देशन में कार्य करती हैं।

15 वह संविधान तथा नियमों की व्याख्या करता है। जो विचार वह अध्यक्ष पद से व्यक्त करता है। 'ले' विषय में वह सार्वजनिक रूप से किसी विवाद में नहीं पड़ता। वह पारित विधेयक की प्रत्यक्ष अशुद्धियों को दूर कर, स्वीकृत संशोधनों के अनुसार उसमें परिवर्तन करने का अधिकार रखता है।

16 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए पेन्सिल के पुर्य किसी पारित प्रस्ताव को वह प्रमाणित करता है।

17 अध्यक्ष का सचिवालय होता है जो उसके निर्देशन एवं नियन्त्रण में कार्य करता है। लोकसभा के कर्मचारियों उसके परिसर तथा सुरक्षा विषयक अधिकार उसे प्राप्त हैं। लोकसभा परिसर में सभी उसके आदेशों का पालन करने को बाध्य है।

18 लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करता है। उसकी अनुमति के बिना लोकसभा परिसर में किसी सदस्य को बन्दी नहीं बनाया जा सकता है। पौजदारी अथवा दीवानी कानूनों के अनुसार कोई आदेशिका सदस्य को उस समय तक नहीं दी जा सकती जब तक अध्यक्ष अनुमति न दे।

19 सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह उनकी शाहवा क प्र निर्णय करता है। मन्त्री द्वारा उत्तर न देने की स्थिति में अध्यक्ष उसे उत्तर देने का आदेश दे सकता है।

20 अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति है जो कि भारत में अन्तर्सदनीय संघ के राष्ट्रीय समूह के रूप में और राष्ट्रमण्डल संसदीय संस्था की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। वह राज्यसभा के सभापति से परामर्श करके विदेशों को जाने वाले विभिन्न प्रतिनिधि-मण्डलों के लिए सदस्यों का नाम निर्देशित करता है। वह स्वयं इन प्रतिनिधि-मण्डलों का नेतृत्व करता है। अध्यक्ष भारत की विधायिनी संस्थाओं की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों के सम्मेलन का सभापति है। वह लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय घटनाओं के औपचारिक अवसरों पर भाषण देता है। नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष पारित विधेयक में व्यापक प्रत्यक्ष गलतियों को शुद्ध कर सकता है तथा उसमें अन्य ऐसे परिवर्तन कर सकता है जो सदन द्वारा स्वीकृत संशोधनों के अनुपपन्निक हों। विधेयक सदन द्वारा पास कर अध्यक्ष उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए उस पर हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करता है।

21 52वीं दल-बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका को शक्तिशाली बना दिया है। दल-बदल सम्बन्धी विवाद में वह वह व्यवस्था देता है। दल का विधिवत रूप से विभाजन हुआ है अथवा नहीं? वह दल-बदल कानून के अन्तर्गत सदस्यों को सदन की सदस्यता के अयोग्य करार दे सकता है। दल-बदल विधेयक ने लोकसभाध्यक्ष की शक्तियों में विस्तार कर उसकी भूमिका को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यहाँ अध्यक्ष की निष्पक्षता पर उसकी साख और प्रतिष्ठा निर्भर करती है। अध्यक्ष को न्यायिक शक्तियों प्रदान की गयी हैं। हाउस ऑफ कामन्स के अध्यक्ष से तुलना

इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ कामन्स का अध्यक्ष एक बार अपने पद पर निर्वाचित होने के बाद दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। वह सदन में और सदन के बाहर पूर्णरूपेण निर्दलीय रूप में व्यवहार करता है। एक बार अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वह बहुत सम्बन्धी अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। वह निर्विरोध रूप से निर्वाचित होता है। विपक्षी दल उसके विरुद्ध अपना प्रस्ताव नहीं रखता है बल्कि उसके निर्वाचन क्षेत्र में वर्यों का सम्पादन करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सदन में सत्ताकण्ड और विपक्षी दल और उसके गौरव और प्रतिष्ठा को बचाये रखने

निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ—संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान-मण्डलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन-मण्डल की रचना करते हैं। इस सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपअध्यक्ष का निर्वाचन करती है। राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है।

प्रशासकीय शक्तियाँ—संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा का देश की कार्यपालिका पर वास्तविक नियन्त्रण नहीं है। उत्तरदायित्व का अभिप्राय है कि लोकसभा की विश्वासपात्र बने रहने तक सत्तारूढ़ रहेगी। लोकसभा का दायित्व है कि यह शासन के विभिन्न क्रिया-कलापों पर दृष्टि रखे। लोकसभा के पास नियन्त्रण के कई उपाय हैं, जैसे शासन के विभिन्न कार्यों की सूचना माँगना, शासन कार्यों की आन्वेषणा करना, मन्त्रियों से प्रश्न पूछना, सार्वजनिक महत्व के विषय में आकड़े माँगना, सरकारी सदसितियों के माध्यम से कार्यपालिका से विभिन्न सूचनाएँ प्राप्त करना आदि। यद्यपि राज्यसभा कार्यपालिका से प्रश्नों के उत्तर माँगती है कार्यपालिका की आलोचना करती है और लोकसभा के समान स्थान प्रस्ताव का अधिकार रखती है तथा ऐसा प्रस्ताव पास कर सकती है कि जिसमें आग्रह किया हो कि शासन को विशेष प्रकार की नीति पर चलना चाहिए।

सौध्यानििक शक्तियाँ—संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति से संविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन विधेयक किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है पर यह आवश्यक है कि संसद के प्रत्येक सदन में सम्पूर्ण सदस्य सभा के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 (दो-तिहाई) मतदान से यह संशोधन विधेयक पारित हो तथा राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे। संविधान में कुछ ऐसे विषय रखे गये हैं जिनमें संशोधन करने से पूर्व राज्य विधान-मण्डलों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है और अकेले संसद संशोधित कर सकती है। संविधान (सौबीसवें संशोधन) अधिनियम, 1971 के द्वारा कैलाशचन्द्र भारती वाले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन यह संविधान के मूलभूत या आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

दोनों सदनों के परस्पर सम्बन्ध

(Mutual Relations of Both the Houses)

विधायी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का मिल-जुलकर कार्य करना आवश्यक है किन्तु निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा को श्रेष्ठता प्रदान की गई है—

1 प्रत्येक मंत्री अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से और मन्त्रि-परिषद के निर्णय के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है जो यथार्थ में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद में उठाए गए शासन सम्बन्धी प्रश्नों के विषय में पूर्ण विवरण प्राप्त करने का राज्यसभा को अधिकार है परन्तु तत्कालीन सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव (Censure Motion) पारित करने का अधिकार राज्य सभा की नहीं है। संसद के विश्वास का हाथपर्य लोकसभा के विश्वास से है कार्यपालिका का उत्तरदायित्व इस प्रकार लोकसभा के प्रति है। इस सिद्धान्त का आधार लोकसभा का भारतीय जनता पर आधारित होना है।¹ लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरकार को त्याग-पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

2 वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में राज्यसभा की सत्ता नगण्य है। प्रत्येक वित्त विधेयक की पुनर्स्थापना (Introduction) लोकसभा में हो सकती है किन्तु संविधान द्वारा वित्त विधेयक के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसमें राज्यसभा को जीय करने की रोक नहीं लगाई गई उसे परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है। इसे प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर राज्यसभा उसके सम्बन्ध में उचित निर्णय कर सकती है। यदि वह उसे पारित कर दे तो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि इस विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत करे अथवा संशोधित कर दे तो वह लोकसभा के पास वापस भेज दिया जाता है जहाँ उस पर पुनः विचार किया जाता है और साधारण बहुमत द्वारा पारित कर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा का कार्य परामर्श देने तक सीमित है तथा अन्तिम निर्णय लोकसभा लेती है।

3 अन्य विधायी कार्यों में जिनमें सौध्यानििक संशोधन सम्मिलित है राज्यसभा की सत्ता लोकसभा के बराबर है। विधेयक की पुनर्स्थापना लोकसभा या राज्यसभा में हो सकती है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा द्वारा रद्द या संशोधित किया जा सकता है। यदि दोनों सदनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाये तो इसका निर्णय दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बहुमत द्वारा किया जाता है।

4. आवश्यकानुसार सदन के दोनों सदनों को एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है जिसके अन्तर्गत एक सदन लिखित सन्देश दूसरे सदन को भेजता है। सम्पर्क के अन्य तरीके हैं सदनों की संयुक्त समितियों की बैठकों और दोनों सदनों की बैठकें।¹

5. भारतीय राज्यसभा न अपेक्षा की सीनेट के समान निम्न सदन से श्रेष्ठ है, न आस्ट्रेलिया की सीनेट के समान शक्तियाँ रखती है, परन्तु यह कनाडा की सीनेट से शक्तिशाली है। कुछ मामलों में संविधान लोकसभा को राज्यसभा को अपेक्षा वरीयता प्रदान करता है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में नहीं। संविधान के संशोधन के लिए राज्यसभा को समानाधिकार प्राप्त है। यह विशेष महत्व का विषय है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा की सम्मति के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस उपबन्ध से स्पष्ट है कि संविधान-निर्माता राज्यसभा को महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहते थे। उदाहरणार्थ जनता सरकार ने संविधान का जो 44वाँ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया उसमें मूलरूप में 34 खण्ड थे। लोकसभा ने जिस मूल संशोधन विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेजा वहाँ कॅमिंस पार्टी के बहुमत ने पाँच खण्डों को स्वीकार नहीं किया और फलस्वरूप 44वाँ संशोधन विधेयक 49 खण्डों का ही पारित हुआ। संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं में संशोधन करने के सम्बन्ध में अनुच्छेद 368 में जनमत-संग्रह की व्यवस्था करने, दूसरे विषयों के लिए उच्च न्यायालय के स्थान पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण से सम्बन्धित भाग 14-ए को निकालने, मूलाधिकारों को राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के ऊपर रखने के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्ण की स्थिति को बहाल करने के लिए अनुच्छेद 31-सी में संशोधन करने, प्रस्तावना में उल्लिखित 'धर्मनिरपेक्ष' और समाजवादी शब्दों के महत्व को व्याख्या के लिए अनुच्छेद 366 में संशोधन करने तथा शांति को पुनः राज्य सूची में शामिल कर देने सम्बन्धी प्रस्तावों को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तथा राज्यसभा द्वारा अनुमोदित विधेयक को लोकसभा ने फिर स्वीकृति प्रदान की। इससे राज्यसभा की शक्तिशाली भूमिका प्रकट हुई।

6. राज्यों की प्रतिनिधि सभा होने के नाते राज्यसभा को संविधान के अन्तर्गत ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत यह सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दौड़-हाई बहुमत तथा कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत द्वारा यह घोषित कर सकता है कि राष्ट्र के हित में यह आवश्यक है कि मसदा राज्य सूची (State List) में दिए गये किसी विषय पर जो कि उक्त प्रस्ताव (Resolution) में बताया गया है, 'विधि निर्माण करे। उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर संसद के लिए उस विषय पर भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए एक वर्ष तक की अवधि के लिए विधि निर्माण किया जा सकता है।

7. राज्यसभा का दूसरा अधिकार राष्ट्रहित के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) स्थापित करने से सम्बद्ध है। इस प्रस्ताव को उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दौड़-हाई बहुमत तथा कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत से पारित किया जा सकता है। लोकसभा दोनों स्थितियों में तभी कार्य कर सकती है जब पहले राज्यसभा सम्मेलन द्वारा उसे कार्य करने की शक्ति प्रदान करे। यह शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है।

8. सरकारों कार्य के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ संविधान ने संसद के दोनों सदनों को समानता का दर्जा दिया है यथा—(i) राष्ट्रपति के निर्वाचन और उस पर महाभियोग के सम्बन्ध में दोनों सदनों के समान अधिकार (ii) उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में समान अधिकार (iii) संसदीय विशेषाधिकार की परिभाषित करने और अपमान के लिए दण्ड देने के मामलों में समान अधिकार (iv) आपातकाल की उद्घोषणा (अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत) और राज्यों में सांविधानिक तन्त्र के विफल होने पर (अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत) उद्घोषणाओं का अनुमोदन करने के मामलों में लोकसभा के समान अधिकार एवं कुछ मामलों में एकाधिकार एवं (v) विभिन्न सांविधानिक अधिकारियों से प्रतिवेदन और पत्र प्राप्त करने का लोकसभा के समान अधिकार यथा—(क) वार्षिक वित्तीय विवरण (ख) भारत के निधनकर्मचालेखा परीक्षक से लेखा प्रतिवेदन (ग) सप्त लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विशेष पदाधिकारियों के प्रतिवेदन (ङ) पिछड़े वर्गों के आयोग का प्रतिवेदन की जाँच एवं (च) भारतीय अल्पसंख्यकों के विशेष पदाधिकारियों का प्रतिवेदन।²

9. संविधान के अन्तर्गत मंत्रियों के चयन में दोनों सदनों में कोई भेद नहीं किया गया है और कुछ मंत्री राज्यसभा के लिए जाते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी सर्वप्रथम प्रधानमंत्री राज्यसभा से थीं। संसदीय लोकतन्त्र के अन्तर्गत संसद का कोई सदन जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं से अप्रभावित नहीं रह सकता और राज्यसभा के प्रतिवेदनों से यह प्रतीत होता है कि इसने लोकमत के प्रति पर्याप्त जागरूकता प्रदर्शित की है। राज्यसभा में उच्च-कोटि के सासनों ने अपनी प्रेरणास्पद उपस्थिति से इस सदन को गरिमा प्रदान कर अपने आचरण से भारतीय जनमानस को प्रभावित किया है।

1. कोल एवं शम्बर : पूर्वोक्त पृ. 38.

2. पवनन्द्र बनर्जी : भारतीय संविधान में राज्यसभा का स्थान, संसदीय पत्रिका, जनवरी-मार्च, 1967, पृ. 9-10.

राज्यसभा की तुलना अमेरिकी सीनेट या ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से की जा सकती है, किन्तु अपनी शक्तियों और अपने स्थान की दृष्टि से यह इन दोनों से भिन्न है। व्यवहार में राज्यसभा न अमेरिकी सीनेट जितनी शक्तिशाली है और न ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स जितनी प्रभावशाली। ठाढ़ारणार्थ राज्यसभा को वित्त विधेयक के सम्बन्ध में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं जबकि अन्य मामलों में इसकी विधायी शक्तियाँ उच्च सदन के समान हैं। वितीय मामलों के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों पर राज्यसभा में विधेयक तैयार जा सकते हैं और दोनों सदनों के मतभेद हो जाने पर किसी प्रश्न विशेष पर निर्णय करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त सभा की व्यवस्था है। लोकसभा राज्यसभा की उपेक्षा नहीं कर सकती। संवैधानिक ढाँचबन्ध के अन्तर्गत राज्यसभा महत्वपूर्ण प्रामाण्य देती है। यह ठोस सन्ध्या है जो स्थायी होने के कारण विचार एवं कार्यों में स्थिरता तथा निरन्तरता ला सकती है।

भारतीय संसद की सर्वोच्चता

(Supremacy of the Indian Parliament)

संविधान निर्माताओं के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न था कि संसद की स्थिति के विषय में ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाते हुए उसे पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सन्ध्या बनाए जाए या अमेरिका की व्यवस्था को अपनाते हुए एक सीमित शक्तियों वाली सन्ध्या बनाए जाए। वे ब्रिटेन में प्रचलित संसद की सर्वोच्चता के आदर्श को अपनाया चाहते थे, किन्तु सभी व्यवस्था, लिखित संविधान तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था आदि के कारण संसद की शक्ति को ब्रिटेन की तरह सर्वोच्च नहीं बनाया जा सकता था तथा इन विषयों से सम्बन्धित संसद की विधियों के लिए न्यायिक पुनर्विस्तोकन (Judicial Review) की व्यवस्था का रखा जाना अत्यावश्यक था अतः भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्यों के विधान-मण्डलों की तुलना में संसद को अधिक शक्तियाँ प्रदान करके उसे एक शक्ति-सम्पन्न सन्ध्या के रूप में प्रतिष्ठित अवश्य किया, परन्तु इसकी विधि-निर्माण की शक्ति पर न्यायिक पुनर्विस्तोकन का अकुश रख। यद्यपि न्यायिक पुनर्विस्तोकन की व्यवस्था उस प्रकार असीमित नहीं रखी जिस प्रकार यह अमेरिकी की संवैधानिक व्यवस्था में है। दुर्गादास के अनुसार भारतीय संविधान में अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता की व्यवस्था एवं संसदीय सम्प्रदाय ने इंग्लैण्ड के सिद्धान्तों के मध्य मार्ग को अपनाया गया है।

भारतीय संसद की सर्वोच्चता के पक्ष में तर्क

- 1 संसद सभ सूची एवं सम्पत्ती सूची पर कानून बना सकती है। किसी राज्य की प्रार्थना पर उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने में यह सक्षम है। राज्यसभा 2/3 के बहुमत से ऐसे विषय को जो राज्य सूची में है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तत्पश्चात् संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
2. भारत की संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतन्त्र में जनता सर्वोपरि है।
3. भारत के राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। आपातकाल की स्थिति में देश में शासन का सम्पूर्ण एकात्मक हो जाता है और उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर सकता है। इन अधिकारों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल करता है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिमण्डल तब तक पदासीन रह सकता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त है अतः संसद का कार्यपालिका, 'पर' पूर्ण, नियन्त्रण, है।
4. संविधान में संशोधन करने में संसद पूर्णतः सक्षम है।
5. संसद संविधान के 9वें परिशिष्ट में उल्लिखित किसी विषय को सम्मिलित करके उसे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से घुटका करने में सक्षम है।

संसद की सर्वोच्चता पर सीमाएँ

- 1 जिस देश में लिखित संविधान होता है वहाँ शासन के अंगों की रचना, उसका कार्य एवं शक्तियाँ संविधान के अनुसार सम्भव होती हैं और संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का उल्लंघन संसद नहीं कर सकती है।
2. भारतीय संसद सहायक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करती है। वह राज्य के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आपातकाल में स्थिति भिन्न हो सकती है, किन्तु राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन सामान्य स्थिति के आधार पर किया जाता है।
3. भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं जिसकी प्रकृति निषेधात्मक है अतः राज्य नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इन अधिकारों में संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था है। संसद हुए अपने अधिकारों को सीमित किये जाने पर नागरिक न्यायपालिका की राह में जा सकते हैं।

संसदीय समितियाँ

(Parliamentary Committees)

भारतीय संसद विशेषकर लोकसभा अपना कार्य-संचालन करने के लिए समितियों का प्रयोग करती है। विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने वाली समितियाँ विधेयकों पर विस्तृत वाद-विवाद करती हैं। वे सभी प्रकार के रिकार्डों एवं गवाहों को गौण भक्तों हैं और आवश्यक जानकारी करती हैं। उनमें बैठकों की कार्यवाही गुप्त रहती है। वे अपने विचारों पर अपनी रिपोर्ट निश्चित अवधि के भीतर तैयार करती हैं जिस पर बाद में सदन द्वारा विचार किया जाता है।

भारतीय लोकसभा में समितियों के सदस्य सदन द्वारा निर्वाचित होते हैं या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। किसी सदस्य का नाम किसी समिति में प्रस्तुत करने से पूर्व उस सदस्य की स्वीकृति ली जाती है। किसी समिति की कार्यवाही के लिए एक तिहाई सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। समस्त प्रश्नों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिये जाते हैं। बराबर मत आने पर समिति के अध्यक्ष को निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार होता है। समिति की बैठकें संसद-भवन की सीमा के अन्तर्गत होती हैं। लोकसभाध्यक्ष या स्पीकर किसी समिति को उसकी प्रक्रिया में निर्देश दे सकता है। संसद अपने विधेयकों पर रिपोर्टें प्रवर समितियों (Select Committees) अथवा संयुक्त प्रवर समितियों द्वारा प्राप्त करती है। प्रवर समिति विशेष विधेयक हेतु बनाई जाती है और रिपोर्ट देने के बाद उसका अन्त हो जाता है। ऐसी समिति के निर्माण का प्रस्ताव उसके सदस्यों की संख्या और उनकी सदस्यता का निर्णय प्रस्तावक पर सदन करता है। विधेयक के प्रस्तावक (Mover) और कमन्स-मन्त्री ऐसी समिति के सदस्य अवश्य होते हैं। प्रवर समितियों के गठनपरिचयों की नियुक्ति सदन का अध्यक्ष करता है।

लोकसभा समितियाँ

लोकसभा में समितियों की संगठित व्यवस्था है। समितियों की नियुक्ति, कार्यकाल, कृत्य तथा समिति का कार्य चलाने के लिए प्रक्रिया की मुख्य दिशाओं का विनियमन नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत और उन नियमों के उद्देश्य अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है। संसदीय समितियों के तीन नियम हैं—'सामान्य नियम' जो समितियों पर लागू होते हैं, 'विशिष्ट नियम' जिनमें विशेष समितियों के लिए विशेष उपबन्ध दिए गए हैं और 'आन्तरिक नियम' जिनके माध्यम से प्रत्येक संसदीय समिति की आन्तरिक प्रक्रिया का विनियमन किया जाता है। पहले दो प्रकार के नियम प्रक्रिया नियमों तथा अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों में दिए गए हैं। 'आन्तरिक नियम' सम्बद्ध समितियों द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से बनाए जाते हैं और वे कार्य करने की विस्तृत प्रक्रिया से सम्बन्धित होते हैं। इन्हें नियमों द्वारा 'निर्देशों' के उपबन्धों के अनुसार बनाया जाता है।¹

मुख्य वर्गीकरण—लोकसभा की समितियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है²—
(अ) स्थायी समितियाँ (ब) तदर्थ समितियाँ (स) नवीन विधायीय स्थायी समितियाँ।

(अ) स्थायी समितियों को निम्नलिखित शीर्षकों में बाँटा जा सकता है—

- (i) जाँच करने वाली समितियाँ (उदाहरणार्थ, वाणिज्य समिति और विशेषकर समिति)
- (ii) सवीक्षा करने वाली समितियाँ (उदाहरणार्थ सरकारी आवासनों सम्बन्धी समिति और अधीनस्थ विधान समिति)
- (iii) सभा के दिन-प्रतिदिन के कार्य सम्बन्धी समितियाँ (उदाहरण के लिए सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति समिति, कार्य-सूचना समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकलपत्र सम्बन्धी समिति और नियम समिति)
- (iv) सदस्यों को सुविधाएँ दिलाने वाली समितियाँ (उदाहरण के लिए सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति और पुस्तकालय समिति)
- (v) सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों पर नियन्त्रण करने वाली समितियाँ (उदाहरण के लिए प्राक्कलन समिति, लोक सेवा समिति और सरकारी उपक्रम समिति)।

इन समितियों का गठन नियमों के अनुसार किया जाता है और प्रत्येक समिति के निर्धारित कार्यकाल के अनुसार दशास्थिति, प्रतिवर्ष या कालान्तर में पुनर्गठित की जाती है।

(ब) तदर्थ समितियों को दो शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वे तदर्थ समितियाँ हैं, जो लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पास कर या अध्यक्ष द्वारा बनाई जाती हैं जिससे कि वे विशेष विषयों की जाँच करके अपनी रिपोर्ट दे सकें।

समिति के सदस्यों के रूप में अपने सदस्यों का नाम निर्देशित करते समय यह ध्यान रखें कि जहाँ तक सम्भव हो प्रकृतिपूर्व सदस्य प्रतिवर्ष नियुक्त हो जाएँ और दो-तिहाई समिति के सदस्य फिर चुने जाएँ, पानु जो सदस्य नियुक्त हो जाते हैं, उनका एक वर्ष बाद फिर नाम निर्देशित किया जा सकता है। किसी मन्त्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जाता। इसके अतिरिक्त, यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य चुने जाने के बाद मन्त्री नियुक्त हो जाए तो वह मन्त्री नियुक्त होने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता।¹

सभापति—समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है। वह ससदीय समितियों के सभापतियों के साथ-साथ दूसरे काम करता है, जिनका सम्बन्ध समिति के काम से है। इस बात का निर्णय सभापति करता है कि कोई विशेष दस्तावेज या जनसहारी सरकार से माँगी जानी चाहिए या नहीं और ऐसी जानकारी या दस्तावेज समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए या नहीं। सभापति यह निर्णय करता है कि कबट में 'भारित' मतों के क्षणोत्तर से सम्बन्धित मामलों की समिति द्वारा जाँच की ज़रूरी आवश्यक है या नहीं। यदि आवश्यक हो तो वह विशेष मामलों के सम्बन्ध में मन्त्रियों या मन्त्रालय के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करता है।

शक्तियाँ एवं कार्य—समिति ऐसे प्राक्कलनों की जाँच करती है जो सभा या प्रध्मस्य द्वारा विशेष जाँच के लिए भेजे गए हों, जिससे कि

- (i) यह रिपोर्ट दी जा सके कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप काम बचत की जा सकती है तथा सगठन कार्यकुशलता या प्रशासनिक व्यवस्था में और क्या सुधार किए जा सकते हैं।
- (ii) प्रशासन में कार्यकुशलता तथा बचत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दिया जा सके।
- (iii) यह पता लगाया जा सके कि प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं में रहते हुए सारी धनराशियों का उपयोग ठीक ढंग से किया गया है या नहीं और
- (iv) यह सुझाव दिया जा सके कि प्राक्कलनों को किस रूप में संसद के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

समिति प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकाल के प्रारम्भ में किसी मन्त्रालय या सरकारी उपक्रमों के प्राक्कलनों के किसी अंश से सम्बन्धित विषय अगले वर्ष जाँच के लिए चुन लेती है जो सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को उस वर्ष न भेजे गए हों। जाँच के लिए प्राक्कलनों का चुनाव इस सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है कि सभी मन्त्रालयों के महत्वपूर्ण प्राक्कलन, प्रत्येक श्लोकसभा की अवधि में कम से कम एक बार समिति के सामने आ जाएँ। समिति चाहे तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय का ख़रीद माँग सकती है और इसकी जाँच कर सकती है कि 'भारित' और 'मजूर' को जाने वाली खर्च की मदों का वर्गीकरण संविधान तथा संसद के अधिनियमों के उपबन्ध के अनुसार किया गया है या नहीं। वित्त मन्त्रालय समिति को उन निर्णयों की सूचना देता है जो सरकार समक्ष-समय पर खर्च की किसी 'भारित मद' को पहली बार बजट में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में करे या जब तक खर्च की किसी मद को 'भारित' की श्रेणी से निष्काट कर 'मजूर' खर्च की श्रेणी में डाले या किसी 'मजूर' होने वाले खर्च को 'भारित' मदों की श्रेणी में डाल दे।

विशेष रूप के उन मामलों की समिति जाँच करती है जिनका सम्बन्ध यद्यपि विशेष प्राक्कलनों से नहीं होता, पानु समिति यह समझती है कि उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए। जब समिति विषयों का चुनाव कर लेती है तो सम्बद्ध मन्त्रालय से कह जाता है कि वह अपने सगठन व्यवस्था कार्यकुशलता प्राक्कलनों सम्बन्धी स्पष्ट निर्दिष्ट प्रपत्र में जानकारी दे। इस प्रकार प्राप्त सामग्री का अध्ययन करने के बाद सदस्य अपने सुझाव भेजते हैं, जिनके सम्बन्ध में कोई और जानकारी चाहिए। ये सुझाव एक प्रश्नावली के रूप में संक्षेपित कर दिए जाते हैं और उन पर समिति, उप-समिति या अध्ययन दल विचार करता है। सभापति द्वारा उसका अनुमोदन होने के बाद उसे उत्तर हेतु मन्त्रालय के पास भेजा जाता है। समिति की जाँच का मूल उद्देश्य यह है कि प्रशासन में मितव्ययिता और कार्यकुशलता व्याप्त हो तथा प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं में रहते हुए धनराशियों का उचित ढंग से उपयोग किया जा सके। समिति संसद द्वारा अनुमोदित नीति की जाँच नहीं करती, किन्तु किसी अवाञ्छनीय नीति पर धन व्यय होने की स्थिति में समिति का यह कर्तव्य है कि वह सभा का ध्यान इस ओर दिलाए कि नीति में परिवर्तन करना वाञ्छनीय होगा। समिति को इसका अधिकार प्राप्त है कि वह संसद द्वारा अनुमोदित नीतियों से अलग कोई निर्धारित नीतियाँ नहीं हो। समिति ने कई बार प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दिया है।

महत्त्व—प्राक्कलन समिति की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह सरकार को अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। समिति स्वेच्छा से सरकार के किसी विभाग को परीक्षा के लिए चुन लेती है। इस समिति के निर्माण में कुछ त्रुटियाँ होने के कारण वह अपने कार्य को अधिक सुन्दरता से नहीं कर पाती है। समिति को सौंपा जाने वाला कार्य विशेषज्ञों का कार्य (Expert's Job) होता है, लेकिन इस समिति के

सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते और अपने कार्य में विशेष अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होता है। इस समिति को किसी विशेषज्ञ जैसे कम्पट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल की सहायता नहीं मिलती। यदि इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो समिति की कार्यक्षमता में निश्चित ही और अधिक वृद्धि हो सकती है।

6. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)—लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के भाई के समान है। प्राक्कलन समिति प्राक्कलन (Estimates) का परीक्षण करती है तो लोक लेखा समिति सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करती है। इस समिति के महत्व के सम्बन्ध में विल एच शकषर ने लिखा है—“लोक लेखा समिति करदाताओं की राशि के खर्च की मजूरी देने के बाद करदाताओं के हित में आशा करता है कि उचित समय पर ब्यौचर हिसाब कर दिया जाए कि वह धन किस प्रकार खर्च किया गया है। लोकसभा की अपना समाधान करना पड़ता है कि उसने जिन धनराशियों के खर्च की मजूरी दी थी, वे उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च हुई है और मिश्रितता तथा विवेकशून्यता से खर्च हुई या नहीं, जिनके लिए मजूरी दी गई थी। नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक सरकार के वार्षिक लेखों का पड़ताल करता है और पड़ताल के बाद लेखों का प्रमाणपत्र देता है। वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उन्हें संसद के सामने रखवा देते हैं। लोकसभा के लिए इन लेखों की जाँच करना असम्भव नहीं तो कठिन अवसर है, क्योंकि ये बड़े जटिल और तकनीकी ढंग के होते हैं और विस्तृत जाँच के लिए समय नहीं है इसलिए लोकसभा ने यह समिति बनाई है, जिसे लोक लेखा समिति कहा जाता है। इन लेखों की ब्यौचर जाँच का काम लोक लेखा समिति को सौंपा गया है।”

संरचना—समिति में संसद के अधिकतम 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं चुना जाता है और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य निर्वाचित होने के बाद मंत्री हो जाता है तो उस नियुक्ति की तिथि से वह समिति का सदस्य नहीं रहता है। सामान्यतया समिति प्रत्येक वर्ष मई में बनाई जाती है और उसका कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति सम्बन्धित सभा में प्रस्ताव पास करके की जाती है। लोकसभा में यह प्रस्ताव समिति के सभापति द्वारा रखा जाता है और राज्यसभा में उसके किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो समिति का सदस्य हो। आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करने के लिए चुने हुए सदस्य समिति के बाकी कार्यकाल में कार्य करते हैं। जब समिति का कोई राज्यसभा का सदस्य सद्विधान के उपबन्धों के अन्तर्गत, राज्यसभा की सेवा से निवृत्त होता है तो उस सेवानिवृत्ति के कारण समिति में हुई रिक्तता की पूर्ति उस सभा के किसी अन्य सदस्य का नाम निर्देशित करके की जाती है। ऐसे मामलों में लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमें राज्यसभा से सिफारिश की जाती है कि वह राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य का नाम निर्देशित करना प्रोत्साहित कर ले, जिसे समिति के शेष कार्यकाल में समिति में सम्मिलित किया जाए। उस सभा द्वारा नियुक्त सदस्य के नाम की सूचना लोकसभा को दी जाती है। राज्यसभा की सेवा से निवृत्त होने के बाद चुन लिए जाने पर वह पुनः समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। उसके पद का कार्यकाल समिति की तरह एक ही वर्ष का होता है।

शक्तियाँ एवं कृत्य (Powers and Functions)—लोकसभा की प्रक्रिया नियम 24(1) के अनुसार “यह समिति भारत सरकार के व्यय के लिए लोकसभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखों और लोकसभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखों की जाँच करती है।” भारत सरकार के विनियोग लेख और इनमें नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय लोक लेखा समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर दे कि—(क) लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उन सेवा प्रयोजनों के लिए विधिवत उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था जिनमें वह लगाया गया है या धारित किया गया है। (ख) व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है। (ग) पुनर्वित्त सहाय अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत एवं किए गए उपबन्धों के अनुसार किया गया है। (घ) राज्य निगमों, व्यापार तथा निर्माण-योजनाओं और परियोजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेख-विवरणों की तथ्यानुसृत पत्रों (Balance Sheets) अर्थात् लाभ-हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जाँच करना, जिन्हें तैयार करने की राष्ट्रपति ने अपेक्षा की हो जो किसी खास निगम, व्यापार संस्था परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था निर्धारित करने वाले सर्वविध नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किए गए हों और उन पर नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच करना। (ङ) स्वयंसेवक और अर्द्ध-स्वयंसेवक निकायों की आय तथा व्यय दिखाने वाले विवरणों की जाँच करना जिसकी लेखा-परीक्षा, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों के अन्तर्गत या संसद की किसी सविधि के अनुसार की जा सके। (च) उन मामलों में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना, जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उससे किसी प्राप्ति को लेखा-परीक्षा करने की या मन्दात के और रक्षक के लेखों की परीक्षा की अपेक्षा की हो।

यदि किसी विधायी वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस प्रयोजन के लिए ससद द्वारा अनुमत राशि से अधिक धन व्यय किया गया हो तो समिति प्रत्येक मामले में जिस कारण अधिक व्यय हुआ हो के तथ्यों के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों को जाँच कर आवश्यकानुसार सिफारिशें करता है। यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति अतिरिक्त खर्चों के सम्बन्ध में अलग रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में विभिन्न अतिरिक्त खर्चों के सम्बन्ध में कारण बताए जाते हैं और यदि इनकी मजूरा पर अनर्जत हो तो यह बर्खास्त जाती है। यदि समिति ने यह सिफारिश की हो कि अतिरिक्त खर्चों को नियमित रूप दिया जाए तो अतिरिक्त अनुदानों की सीमा सभा के सामने पेश की जाती है और वित्त मन्त्रा द्वाारा से प्रार्थना करता है कि अतिरिक्त खर्चों को पूरा कराने के लिए अनुदान/निधियों को आवंटित कर दिया जाए। समिति का महत्वपूर्ण कार्य वित्त पर अनुदान और सदन पर विचार करता है।

व्यापक अर्थों में नागरिक प्रश्नों से समिति का कोई सम्बन्ध नहीं है सामान्य नीति पर कोई विचार प्रकट नहीं करता परन्तु यह जाना समिति के अधिकार क्षेत्र में है कि उस नागरिकों का कार्य निम्नलिखित है। यह नतीजा कि समिति का एक काम यह है कि खर्च के अतिरिक्त खर्चों को नियंत्रण रखा जाए इसलिए उसे इस बात की चेतावनी है कि यदि यह आवश्यक समझा तो प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप कर उन व्ययों को जाँच करे कि अनर्जत मात्रा में व्यय करते हैं लेकिन हस्तक्षेप के मामले बहुत कम हैं। समिति सामान्यतया भाष्ययुक्त होने के लिए सामान्य नियंत्रण पर हस्तक्षेप करती है और आन्तरिक प्रशासन के प्रश्न सम्बद्ध मात्रा में के लिए छोड़ देता है परन्तु यह प्रशासन की कार्यविधियों को और ध्यान आकृष्ट कर सकती है और मात्रा में सहायता दे सकती है कि यह उनका उपकार करे। समिति सेन्सिटिविटी रिपोर्ट के सम्बन्ध में पेश किए जाने से पहले उसकी जाँच करती है परन्तु उसके सम्बन्ध में तब तक सभा कोई रिपोर्ट नहीं दे सकती जब तक कि तत्सम्बन्धी सख्त और लक्ष्य परीक्षा रिपोर्ट औपचारिक रूप से सभा के सामने पेश नहीं कर दी गई हो। समिति भारत सरकार द्वारा विभिन्न गैर सरकारी कंपनियों के अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के साथ किए गए सार के वार्षिक रिपोर्टों की जाँच प्रारम्भ करती है तथा आवश्यकानुसार वह अपनी या वार्षिक रिपोर्टों में भारतीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अवसर दे सकती है कि वे उनके सामने पेश किए गए वार्षिक रिपोर्टों से सम्बन्धित सार में जिसके सम्बन्ध में समिति और आगे जानकारी चाहती हो या प्रतिनिधि स्वयं कुछ और स्पष्टीकरण देना चाहते हों।

जहाँ तक इस समिति की उपलब्धियों का प्रश्न है इसी महाकाव्य कहा जायेगा। अपने गठन से लेकर आज तक समिति ने अपनी ओर से बहुत-सी अनिवार्यताओं को जाँच की है। समिति ने विभिन्न उपकरणों की कार्यविधि की परीक्षा की है। यदि समिति यह अनुभव करे कि न्यायालय के निर्णायक मामलों की जाँच से उस मामले पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, समिति उस मामले पर विचार स्वीकार कर देती है। वास्तव में ससद की लोक लेखा समिति एक विशेषज्ञ संस्था है जिसके सदस्य आवश्यक महत्त्वपूर्ण मामलों से निकट सम्पर्क बनाए रखते हैं। यह समिति अपनी कार्यकारी एक न्यायालय के समान है। यह अपने काम, जो दलील विचारों से पुष्टि बनाए रखती है। सारांश में लोक लेखा समिति ससद के आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है।

7 विशेषाधिकार समिति (The Privilege Committee) — 15 सदस्यीय इस समिति की नियुक्ति सदन में लोकसभा के स्पाकर की जाती है। इस समिति का कार्य सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges) का निरीक्षण करना है। सदस्यों के विशेषाधिकारों को ठेस पहुँचाने वाले मामलों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और उन पर यह अपना निर्णय देती है।

8. सब ऑर्डिनेट लैजिस्लेशन समिति (The Committee of Sub ordinate Legislation) — इस समिति का उद्देश्य मंत्रियों के प्रदत्त व्यवस्थापन (Delegated Legislation) सम्बन्धी अधिकारों का निरीक्षण करना और उसके सम्बन्ध में सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। 15 सदस्यीय इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए स्पाकर द्वारा की जाती है। भर्त्ता इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते।

9. सरकारी वारंटाण्टा सम्बन्धी समिति (The Committee on Government Assurances) — मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सदन को दिए गए आश्वासनों, वचनों अथवा प्रतिज्ञाओं की जाँच करने और इन पर प्रतिवेदन देने के लिए 15 सदस्यीय इस समिति की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए स्पाकर द्वारा की जाती है। इस समिति के प्रमुख कार्य ये हैं—(क) मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि का कहीं तक परिपालन किया गया है एवं (ख) जहाँ परिपालन किया गया है वह उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समय के भीतर हुआ है या नहीं।

10 सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों हेतु समिति (The Committee on Absence of Members from Sitting of the House) — इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनमें 1 वर्ष के लिए स्पाकर मनोनीत करता है। यह समिति अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की छुट्टी के प्रार्थना पत्रों पर विचार करती है और 60 दिन या इससे अधिक दिनों तक सदन की पूर्ण स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को रिपोर्ट पर विचार करके सदन को सूचित करती है कि उसकी अनुपस्थिति को क्षमा कर दिया जाए अथवा उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाए।

11 नियम समिति (The Rules Committee)—इस समिति के 15 सदस्यों का नियुक्ति स्वरूप द्वारा होता है। स्वरूप अपने पक्ष के द्वारा इस समिति का पञ्चम अध्यक्ष (Ex officio Chairman) होता है। समिति का प्रमुख कार्य सदन का प्रक्रिया और कार्य-संचालन सम्बन्धी विषयों पर विचार करना और उनसे सम्बन्धित नियमों में आवश्यक संशोधन आदि का सुझाव देना है।

12 लोक उपक्रम समिति (Public Enterprises Committee)—इस समिति का गठन दृष्टान्त 1963 के अनुशासक 1963 में किया गया था। समिति के गठन लाकसभा एवं राज्यसभा के सम्मेलन में किया जाता है। समिति में लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं जो एक-दूसरे सम्मेलन में द्वारा अन्य लोक पदों पर चुने जाते हैं। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है तथा 1/3 सदस्य वाय-वाय से प्रतिवर्ष सभा निर्गुण होते हैं। समिति के कार्यालय में दो सभा उपक्रम जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित हैं तथा सरकार द्वारा उद्घाटित किये गये कम्पनी अधिनियम 1956 का धारा 619 का उपपत्र (1) के अन्तर्गत गठित एक समान के समक्ष रखा जाता है।

(म) नम्रान भारत में स्थापित समितियाँ—समिति की स्थापना का अधिक कारण वाय तथा कार्य-संचालन का विषयों का प्रति अधिक जवाबदाय बनने के लिए 1989 में अठारवीं लोकसभा के कार्यकाल में तीन विभागों (1) कृषि (2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा (3) पर्यावरण एवं वन के प्रत्येक विषय से सम्बन्धित समितियों का गठन करके शुभचिन्तन का गठन था। इन प्रक्रियाओं के राजनीतिक कार्यों का देखते हुए 21 मार्च, 1993 का दरम लोकसभा द्वारा पारित नियमबद्ध समिति के द्वारा प्रतिवर्ष न सम्बद्ध स्थायी समितियों के लिए 17 विभागों की स्थापना का भाग प्राप्त किया जायेगा अथवा कम्पनी सरकार के सभा संचालन/विभाग आ जाते हैं। पिछले तीन समितियों का स्थान 11 इन स्थायी समितियों में ली जायेगा है। इनके नाम निम्नलिखित हैं—(1) वाणिज्य समिति, (2) गृह मामलों की समिति, (3) मानव संसाधन विकास समिति (4) उद्योग समिति (5) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन समिति (6) परिवहन एवं पर्यटन समिति (7) कृषि समिति (8) संचार समिति (9) रक्षा समिति (10) ऊर्जा समिति (11) विदेश मामलों से सम्बन्धित समिति (12) वित्त समिति (13) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक विपणन समिति (14) ग्राम एवं कल्याण समिति (15) पैदायन एवं रसायन समिति (16) नगर एवं विकास समिति एवं (17) खेल समिति।¹

नई समिति गठना का उपपत्र 31 मार्च, 1993 को उपपत्र के अन्तर्गत द्वारा किया गया। समितियों ने गठन होने के बाद कार्य करने प्रारम्भ कर लिया।

स्थायी समितियों का गठन—प्रत्येक समिति में अधिकतम 45 सदस्य नियत किये जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से 30 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और 15 सदस्य राज्यसभा द्वारा नियत किये जाते हैं। किसी सभा की समिति का सदस्य नम्रान नहीं किया जाता है और यदि कोई समिति सदस्य मंत्री नियुक्ति हो जाता है तो वह नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता है। लोकसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों का पक्ष अनुसूचा के भाग प्रथम में आकर 6 समितियों के सम्पत्ति राज्यसभा के सम्पत्ति द्वारा नियत होते हैं और जब 11 समितियों के सम्पत्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। समितियों का कार्यकाल एक वर्ष होता है। राज्यसभा के सम्पत्ति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समितियों के सदस्यों का नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा नामित व्यक्तियों में से का जाता है। सम्मेलन समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिनिधित्व सदन में उनके प्रतिनिधित्व के अनुसार न होता है।² समितियों के कार्य

- (अ) सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग की अनुमति का भागों पर विचार करना और सभा का अपना राय देना। समिति अपने प्रत्येक सदन में कठिनी प्रस्ताव का भाग के सुझाव नहीं दे सकता।
- (अ) राज्यसभा सम्पत्ति अथवा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सारे गये सम्बन्धित विभाग के विषयों का परामर्श का प्रतिवेदन करना।
- (अ) मन्त्रालय/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और सभा का अपना राय देना।
- (अ) सदन में प्रस्तुत उन नतिगत विषयों पर विचार करना जो कि सम्पत्ति अथवा अध्यक्ष द्वारा समिति का संपी जये।

मन्त्रालय/विभागों के निम्नलिखित के प्रारम्भ से जुड़े मामलों की समितियों के स्थापित स मुक्त रखा गया है। इन स्थायी समितियों का उपपत्र यह होगा कि सरकार के मन्त्रालय/विभागों का अनुमति भागों पर सभा के कम से

¹ नम्रान गदत (अध्यक्ष, लिखित विवरण) का लेख सम्बन्ध प्रक्रिया में सभा समितियों के स्थापित स मुक्त रखा गया

अथ 45 सदस्यों द्वारा छानबीन की जाएगी तथा नीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रयोजनार्थ सिद्धान्तों तथा सरकार द्वारा उनके कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करने में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। अब बजट पर सामान्य चर्चा के समाप्त होने के बाद लोकसभा निर्वाचन अधिनियम के लिए समितियाँ हो जाएंगी और समितियों इस मध्यवर्ती चरण के दौरान अनुदान माँगों पर विचार करेगी। तत्पश्चात् इन समितियों के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखी हुई लोकसभा द्वारा अनुदान माँगों पर विचार विमर्श किया जायेगा। आखिर में कार्यपालिका को आम व्यक्ति के प्रति जवाबदेर बनाने के लिए निरन्तर विकासशील संसदीय निगमनी पद्धति की नवीनतम उपलब्धि स्थायी समिति प्रणाली है। अतः समिति प्रणाली प्रशासन पर संसदीय निगरानी रखने का महत्वपूर्ण प्रयत्न है।

(6) संशोधन प्रक्रिया

(Amending Procedure)

संघीय संविधान एक कठोर संविधान होता है। इसके संशोधन की प्रक्रिया प्रायः जटिल होती है किन्तु भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाई गई है। भारत के संविधान के अध्याय 20 का शीर्षक है—“संविधान संशोधन और इसमें एक ही अनुच्छेद 368 है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है।” डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा था—“जो संविधान तो असन्तुष्ट है उन्हें केवल दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे सफल मत के आधार पर निर्वाचित संसद में दो तिहाई मत भी नही पा सकते तो यह सर्वज्ञात बात चाहिए कि संविधान के प्रति असन्तोष में जनता उनके साथ नहीं है।”¹

संशोधन का प्रारम्भ

संशोधन पद से मूल दस्तावेज की रूपरेखा में ऐसा परिवर्धन या परिवर्तन विवक्षित है जो उसमें सुधार करेगा या उस प्रयोजन की जिसके लिए वह बनाया गया था अधिक अच्छी तरह से कार्यान्वित करेगा।² उच्चतम न्यायालय ने संविधान में परिकल्पित संशोधन के तीन प्रकार बनाए हैं जिनके द्वारा उसके उपबन्धों में संशोधन किया जा सकता है—

पहला वे जिन्हें बहुमत द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है जो साधारण विधि से पारित किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 4, 169 और 240 के अन्तर्गत वर्णित विषयों के संशोधन इस वर्ग में आते हैं और वे विनिर्दिष्ट रूप से अनुच्छेद 368 की परिधि से निरस्त दिए गए हैं।³

दूसरा वे जो विशेष बहुमत से कार्यान्वित किए जा सकते हैं जैसा कि अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है।

तीसरा वे जो अनुच्छेद 368 में उल्लिखित विशेष बहुमत के अतिरिक्त अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट कम से कम आधे राज्यों द्वारा पारित व सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हैं लेकिन संसद संविधान की आधारित संरचना में कोई संशोधन नहीं कर सकती।

संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया

(क) संसद की शक्ति—अनुच्छेद 368(1) के अनुसार, इस संविधान में किसी संशोधन के होते हुए भी संसद अपनी संविधानी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबन्ध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरक्षण के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।

(ख) विशेष बहुमत—अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान के सभी संशोधन संसद के प्रत्येक सदन का कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा।

(ग) विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन (By Special Majority and Ratification by the States)—इस श्रेणी में संविधान के वे उपबन्ध आते हैं जो संपात्क ढंग से सम्बन्धित हैं और जिनमें संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के दो तिहाई बहुमत तथा 50 प्रतिशत राज्यों के विधायी मण्डलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। निर्मातृविधि उपबन्धों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है—

(1) राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54-55), (2) सभ एवं राज्यों की कार्यपालिका (अनुच्छेद 73-162) (3) सभ एवं राज्य कार्यपालिका (अनुच्छेद 124-147, 214-231, 241) (4) सभ और राज्यों के मध्य विधायी शक्ति का विभाजन (अनुच्छेद 245-255) (5) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (अनुसूची 4) एवं (6) अनुच्छेद 368 के उपबन्धों में।

1 सी ए डी दिन 25 11 1949 पृ 225-226.

2 शकरी प्रसाद बनाम भारत सभ ए आई आर 1951 एच सी 458

3 डॉ. जय राम उपाध्याय भारत का संविधान पृ 560

4 जयन्ताराम पाण्डेय भारत का संविधान पृ 425

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिना किसी वजहों के सम्पन्न हो गये। एलेक्जेंडर वॉक के अनुसार, भारतीय संविधान को दुर्भाग्यवश निराला करना ठीक रहा है।"

(2) भारत एक संघीय राज्य है फिर भी राज्यों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करार का अधिकार नहीं दिया जाया। राज्य भवन के सिद्धांत है अतः राज्यों का संविधान संशोधन प्रस्तावित किया जाने का अधिकार दिया जाया चाहिए लेकिन इस मामले में इस पहलू का ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संविधान और राज्य सरकार व्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य-विधानमण्डलों की स्वीकृति का प्रावधान रखा गया है अतः राज्यों को संविधान संशोधन का महत्व है।

(3) संशोधन प्रणाली में अनेक राज्यों का अर्थ पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्यों की जानकारी में ले पहलू को सम्यक ध्यान नहीं दिया गया है। यह हो सकता है कि फिर संविधान संशोधन की तार प्रदर्श आध प्रदेश, राज्य, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राज्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात के विधानमण्डलों से पुष्टि प्राप्त होगी जहाँ जहाँ देश के गैर-गोवाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या छूट है? राज्यों के विधानमण्डलों के अनुसमर्थन से पुष्टि किये गये संविधान संशोधन की वैधता और औचित्य पर प्रश्न-चिह्नक उत्पन्न नहीं होता। संविधान विधानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था होना ही चाहिए कि जिस संविधान संशोधन का अनुसमर्थन करने वाले राज्य विधानमण्डल देश की आधी जगह का प्रतिनिधित्व करे इससे यह काम हो जायेगा।

(4) संविधान संशोधन में सम्बन्ध में राज्यों की स्वीकृति की अनिवार्यता के प्रवधान की यह आवश्यकता नहीं है कि जहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद और राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति के बाद संशोधन को पास किया जाय। संसद और राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। वहीं संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रावधान नहीं है अतः भारत में राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रावधान संसद आवश्यक नहीं होना चाहिए।

(5) संशोधन के परामर्श दश में किये गये संविधान संशोधन के अध्यापक क्रम में संशोधन प्रदर्श की असफलता का उल्लेख कर दिया है। आलोचकों के अनुसार इस व्यापक संविधान संशोधन के कारण गुल संविधान प्रण संशोधन हो गया है बल्कि संशोधन बाकी रह गया है।

सिद्धान्त तथा व्यवहार में कार्यपालिका प्रणाली (The Executive System in Theory and Practice)

भारत सभ की कार्यपालिका एक राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल से मिलकर बनती है। मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत में शासन का स्वतंत्र सलाहकार प्रणाली का है, क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति राज्य का और सरकार का प्रारंभिक अध्यक्ष है। सभ सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।

राष्ट्रपति

(The President)

संविधान ने भारत में सलाहकार सरकार की स्थापना की है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार सभ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है और वही इस शक्ति का केंद्र है। अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार राष्ट्रपति धनदायक में सार्वजनिक अध्यक्ष है और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से करेगा वही अनुच्छेद 75 यह व्यवस्था देता है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।

राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ (Qualifications for Election of President)—अनुच्छेद 58 के अनुसार वही व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र है जो—

- (1) भारत का नागरिक हो,
- (2) 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो,
- (3) लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो,

(4) भारत सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी या इन दोनों में से किसी से नियुक्ति किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करे। लेकिन अनुच्छेद 58(2) में उल्लेखित व्यक्तियों के अनुसार भारत सभ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति राज्य का राज्यपाल सभ एवं राज्यों के राज्यपालों के पदों को लाभ का पद न मानते हुए उन्हें राष्ट्रपति के उपाध्यक्ष के रूप में योग्य मानेगा है।

अनुच्छेद 58 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति न तो सदन के किसी सदन और न किसी राज्य के विधान मंडल के सदन का सदस्य होगा। यदि ऐसे सदन का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अलग स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद धारण की दृष्टि से रिक्त कर दिया है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया (Election Process of the President)—भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष (Indirect) निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। अर्थात् अनुसूचित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक संवैधानिक पद के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा।

निर्वाचक मंडल—अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित की शामिल किया गया है—

- (क) सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा
- (ख) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अर्थात् सदन अथवा राज्यों की विधानसभाओं में यदि कोई सदन राष्ट्रपति के चुनाव के समय रिक्त हो तो इससे निर्वाचक मंडल अपूर्ण नहीं माना जाता है तथा रिक्तता के अभाव पर राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में आशंका नहीं की जा सकती।

नामांकन—राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार होगा उसे 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा कराये होंगे तथा उसका नामांकन पत्र कम से कम 10-10 निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जागा आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया है कि केवल वे ही चुनाव लड़ सकें जिनका सामाजिक ज्यादातर है तथा ऐसे लोग निर्वाचन में भाग न ले सकें जो केवल अपना नाम सभाचार पत्रों में देखने हेतु चुनाव में भाग लेते हैं। यदि किसी प्रत्याशी को कुल मतों के छोटे भाग के बराबर मत नहीं मिलेंगे तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

निर्वाचन-पद्धति एवं मतों के मूल्यांकन—राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक-गणदल प्रणाली नीति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को 'न्यूनतम वोट' (Quota) प्राप्त करना होता है। इस न्यूनतम वोट को निर्धारित करने का सूत्र इस प्रकार है—

$$\text{न्यूनतम वोट} = \frac{\text{दिए गए मतों की संख्या} + 1}{\text{निर्वाचन होने वाले प्रत्याशियों की संख्या}}$$

न्यूनतम वोट की व्यवस्था ऐसी है जिससे मतदाताओं के स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद प्राप्त कर सके तथा वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सके। राष्ट्रपति के निर्वाचन में परम्परा राज्यों के सदस्यों के मतों में एकरूपता लाने के लिए तथा एकरूप रूप से राज्यों तथा सभ के मतदाताओं के मतों में समानता लाने के लिए प्रत्येक संसद-सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों के मूल्यांकन की एक विधि व्यवस्था है। इसका सूत्र इस प्रकार है—

1. विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य—

$$\text{राज्य की संख्या} = \frac{\text{राज्य की संख्या}}{\text{राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} + 1000 = \text{उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचन के मतों की संख्या}$$

एक हजार के उक्त गुणितों को मिलाने के बाद यदि शेष 500 से कम न हों तो प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा।

इस प्रकार सब राज्यों के मतों की संख्या प्राप्त हो जाए तो उन सब के योग की संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संसद के प्रत्येक सदस्य की मतसंख्या होगी। अपूर्ण संख्या जो आधे से अधिक है, एक मानी जायेगी और आधे से कम संख्या छोड़ दी जायेगी।

2. संसद सदस्य के मत का मूल्य—

$$\frac{\text{सब राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों से प्राप्त मतों की संख्या}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} = \text{संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या}$$

इस प्रकार से निर्धारित मतों के मूल्यांकन के आधार पर दिए गए मतों की गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता (First Preference) के मतों की गणना में प्रत्याशी को निर्वाचित होने के लिए आवश्यक पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं होते तो द्वितीय वरीयता (Second Preference) के मतों की गणना की जाती है, जिसमें प्रथम मतगणना में सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी के मतों का हस्तान्तरण किया जाता है तथा यह क्रम इसी प्रकार चलता जाता है।

निर्वाचन पद्धति का मूल्यांकन—संसदतन्त्र शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सौवैधानिक अंग होता है, अतः भारत में अमेरिका की नीति सभी निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन (कास्ताविक प्रणाली) की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई, पर यह ध्यान दिया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जहाँ तक हो सके जाता पर हो आधारित रहे। भारत में राष्ट्रपति की वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था से ये दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक गणदल में लिये जाने का विशेष महत्व है। यदि राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों भाग लेते हैं तो संसद में बहुमत प्राप्त दल द्वारा अपने प्रत्याशी का सफलता से निर्वाचन सम्भव रहता किन्तु राज्य विधान सभाओं द्वारा निर्वाचन में भाग लेने से स्थिति में आधारभूत अन्तर आ गया है। यह सम्भव है कि संसद में जो बहुसंख्यक दल है उसे अधिकतर राज्यों में बहुमत न मिलता हो। ऐसी स्थिति में संसद में बहुमत रखने वाला दल राज्य विधानसभाओं के समर्थन के बिना अकेला ही अपने प्रत्याशी को राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं करवा सकता अर्थात् राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के जन-प्रतिनिधित्व को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा अन्त्यस रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में देश की जनता ही भाग लेती है।

(छ) उस सदस्य की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित न किया गया हो।

जब आरोप समझ के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या वरणा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा।

यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है आरोप का अन्वेषण करने या करने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किये जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। [अनुच्छेद 61(4)]

भारतीय और अमेरिकन संविधानों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग सविधान के उल्लंघन या अन्याय के लिए लगाया जा सकता है वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग 'राजद्रोह, धूम लेना तथा अन्य अपराध' करने के अपराध पर लगाया जा सकता है।

महाभियोग प्रणाली का मूल्योक्तन—इस प्रणाली में अनेक कमियाँ हैं। सर्वप्रथम यह याच का स्थापित सिद्धान्त है कि जो नियुक्त करता है वही पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में समझ के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं परन्तु उसके महाभियोग में निर्वाचित सासद ही भाग ले सकते हैं जो व्यापक नहीं है। द्वितीय निर्वाचन में केवल निर्वाचित सासद एवं विधायक भाग लेते हैं परन्तु महाभियोग में यतोन्नीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं जो वृद्धिपुक्त है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार—संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रदान करता है—

1 राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए आवश्यक कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, किन्तु अनुच्छेद 61 के अधीन महाभियोग के आरोप की जाँच के लिए समझ के सदन द्वारा नियुक्त या निर्दिष्ट न्यायालय न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विचार किया जा सकेगा।

2 राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि में किसी प्रकार की दण्डनीय कार्यवाही न्यायालय में स्मिथ (Impleaded) नहीं की जाएगी और न जालू रची जाएगी।

3 राष्ट्रपति की पदावधि में उसे बन्दी या कारावास के लिए न्यायालय से कोई आदेशिका (Warrant) अर्थात् राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बन्दी नहीं बनाया जा सकता है।

4 राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने के पूर्व या पश्चात् अपने वैयक्तिक रूप में किए गए अथवा कर्मि अधिप्रा किसी कार्य में राष्ट्रपति के विरुद्ध अनुलोष (Relief) वाली कोई योजना कार्यवाही उसके कार्यकाल में स्मिथ (Instituted) नहीं की जाएगी जब तक कि (क) इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को न दे दी गई हो (ख) ऐसी सूचना के बाद दो माह भीत न गए हों एवं (ग) इस सूचना में उस कार्यवाही की प्रकृति, बाद कारण पक्षपात का नाम स्थान, निवासस्थान तथा माँग किए जाने वाली अनुलोष का विवरण न दिया गया हो।

राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ लेना—अनुच्छेद 60 में लिखा है "प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है अपने पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्राथम अग्रतम न्यायाधीश के सामने निम्न रूप में शपथ का प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।"

"मैं अपुन ईश्वर की शपथ लेता हूँ/तत्पश्चात् से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अद्याप्य भारत का राष्ट्रपति पद का कार्यपालन (अथवा) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिपालन, संरक्षण और प्रतिक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा।"

पूर्व में ईश्वर की शपथ का प्रावधान था, परन्तु बाद में संविधान निर्माता समझ ने स्वयंनिष्ठा शब्द यह शोध कर जोड़ दिया कि यदि सदस्य नास्तिक हुआ तो वह ईश्वर की शपथ कैसे लेगा।

राष्ट्रपति के पद में स्थिति

- (i) पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर
- (ii) मृत्यु से
- (iii) पद त्याग से
- (iv) महाभियोग द्वारा हटाने जाने पर
- (v) उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से [अनुच्छेद 65(1)]

राष्ट्रपति के पद में रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों के सम्बन्ध में व्यवस्थाएँ

(क) जब रिक्ति राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले कर लिया जायेगा। [अनुच्छेद 62(1)]¹ यदि उसे पूरा करने में विलम्ब हो जाता है तो 'रज अन्धाल' न होने पाए, इसलिए यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। [अनुच्छेद 56(1)]। ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।²

(ख) पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न परिस्थिति में नवीन राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के परवान् यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में छह माह पूर्व कर लिया जाएगा। ऐसी रिक्ति होने पर यथा राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा [अनुच्छेद 65(1)], लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से पुरे पाँच वर्ष की पदावधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

(ग) स्थायी रिक्ति के अतिरिक्त सम्भव है कि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। यह भारत से बाहर अनुपस्थिति बीमारी या अन्य कारण से हो सकता है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का उस तारीख तक निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कृत्यों को फिर से पुनः सम्भालता है। [अनुच्छेद 65(3)]³

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

(Powers of the President)

उद्घाटन के रूप में राष्ट्रपति की सविधान-प्रदत्त विस्तृत और प्रभावशाली शक्तियों को चार शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है—(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ, (ब) विधायी शक्तियाँ, (स) वित्तीय शक्तियाँ एवं (द) मकदमालीन शक्तियाँ।

राष्ट्रपति की शक्तियों पर सौबैधानिक मर्यादा—राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण करने से पूर्व हमें उन सौबैधानिक मर्यादाओं को देखना होगा जिसके अधीन वह कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है।

राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग सविधान के अनुसार करना चाहिए [अनुच्छेद 53(1)]। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति से यह अपेक्षा है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करेगा। यदि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सलाह प्रधानमंत्री ने नहीं दी है तो यह सविधान का उल्लंघन होगा।

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार किया जा सकेगा। [अनुच्छेद 74(1)]। 42वें सविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था है कि 'राष्ट्रपति को अपनी सलाह और सलाह देने के लिए मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।' 'कार्य करेगा' शब्द के प्रयोग से राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परन्तु जोड़ा गया जो इस प्रकार है—'परन्तु राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्निर्धार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्निर्धार के परचात की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।'⁴

अतः राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने से इनकार करने पर उस पर सविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकेगा, लेकिन राष्ट्रपति को वह अधिकार दिया गया है कि वह किसी विषय को पुनर्निर्धार के लिए मन्त्रिपरिषद् के पास भेज सकता है। यदि मन्त्रिपरिषद् अपनी पूर्व सलाह पर टिकी रहती है तो राष्ट्रपति के पास उसके अनुसार कार्य करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता है। भारतीय सविधान उपर्युक्त मर्यादाओं के अधीन राष्ट्रपति को निम्नांकित शक्तियाँ प्रदान करता है—

(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ—सविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार सभ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है जिसका प्रयोग वह सविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है फिर भी सभ के सभी अधिकारी उसके 'अधीनस्थ' होंगे। [अनुच्छेद 53(1)] और उसे सभ के कार्यकलाप को जानकारी देने का अधिकार होगा। [अनुच्छेद 78 (ख)]।⁵

1. भारत का सविधान 1996, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, पृ. 18.

2. वही, पृष्ठ 17 एवं दुर्गादास नयू, भारत का सविधान : एक परिचय, 1994, पृ. 163.

3. वही, पृ. 163.

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में प्रशासकीय, राजनीतिक, सैनिक और न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक शक्तियाँ शामिल हैं। सशेष अधिकारियों को नियुक्त करने की उसे व्यापक शक्तियाँ हैं। जिन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है उनमें से मुख्य हैं—प्रधानमंत्री तथा अन्य सचीय मंत्री, महाधिवक्ता, निपन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, राजदूत एवं अन्य राजनयिक अधिकारी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, अनुसूचित वर्गों के लिए विशेष अधिकारी आदि। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करता है जैसे—वित्त आयोग, योजना आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग एवं भाषा आयोग आदि। राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों, राज्यपालों, महाधिवक्ता, उच्च सैनिक अधिकारियों आदि को पदच्युत करने का अधिकार है। यह प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है और राज्य का अध्यक्ष होने के नाते सभी राजनयिक विशेषाधिकारों का उपयोग करता है। देश के राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है और विदेशी राजदूत अपने पद के प्रमाण-पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या सम्मेलनों उसी के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति विविध नागरिकों को भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, पद्मश्री आदि उपाधियों के द्वारा सम्मानित एवं अलंकृत करता है। कुछ नियुक्तियों करने में सविधान में यह उपदेश है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों से भिन्न व्यक्तियों से परामर्श करेगा जैसे—उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से तथा सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो वह आवश्यक समझे [अनुच्छेद 124] (2)। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की राष्ट्रपति शक्ति सांविधानिक औपचारिकता मात्र है यह औपचारिक शक्ति जब व्यावहारिक बन जाती है जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति को अपने विवेक को प्रयोग में लाने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं।

(ब) विधायी शक्तियाँ—सविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। सब को विधायी शक्तियों को इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों में निहित माना गया है। राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि उसकी स्वीकृति के बिना विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित अथवा बग करने तथा गतिरोध हो जाने पर संसद के दोनों सदनों की समुक्त बैठक आहूत करने की उसे शक्ति प्राप्त है। उसमें भाग देने और संदेश भेजने का अधिकार है। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में से किसी क्षेत्र का विशिष्ट व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि इस सम्प्रदाय को संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। सविधान में एंग्लो-इंडियन को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी के माता-पिता में से कोई योरोपीय नस्ल का हो, वह एंग्लो-इंडियन कहलायेगा। एंग्लो-इंडियन वही व्यक्ति है जिसका पिता अंग्रेज तथा माता भारतीय मूल की हो।

संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे अभिनियम का रूप दे सकता है। सविधाने संशोधन विधेयक के अतिरिक्त विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है अथवा विधेयक को अपने संदेश या संशोधन सहित पुनर्विचार के लिए लाया सकता है। ऐसा विधेयक संसद द्वारा पुनः पारित होकर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समुक्त प्रस्तुत हो जाए तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी पड़ती है। इस प्रकार राष्ट्रपति को विलम्बन विशेषाधिकार है पूर्ण विशेषाधिकार नहीं है। विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण आज्ञा के बिना संसद में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, जैसे—वित्त विधेयक, राज्य की सीमा अथवा नाम को बदलने से सम्बन्धित विधेयक, व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित विधेयक। सविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत संसद के विप्रातिपालक में राष्ट्रपति को अग्रप्रादेश जारी करने का अधिकार है। इन अप्पादेशों का वही चल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, किन्तु ऐसे अप्पादेश को संसद के सब प्रारूप होने से 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना पड़ता है और ऐसा न करने पर अथवा संसद द्वारा उसे 6 सप्ताह के भीतर अस्वीकृत कर देने पर अप्पादेश अवैध हो जाता है। राष्ट्रपति अपने अप्पादेश को अपनी इच्छानुसार वापस ले सकता है। राष्ट्रपति को अग्रद्वार और निजीवार द्वीप समूह, संसदीय, मिनिक्वा और अग्रोन्दीव द्वीप समूह आदि सशेष क्षेत्रों को शान्ति, विकास और अनुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार है।

(क) वित्तीय शक्तियाँ—सविधान में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। वित्त विधेयक संसद के समक्ष केवल उनकी सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उसे आकस्मिक निधि पर नियन्त्रण प्राप्त है क्योंकि वह ऐसे व्यय के लिए इस निधि से धनराशि निकालने का अधिकार दे सकता है जिसके सम्बन्ध में संसद की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त न हुई हो, इस पर कालान्तर में संसद की स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। राष्ट्रपति वित्त आयोग नियुक्त करता है जिसकी सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष का राज्यों में वित्तव्यय किया जाता है। राष्ट्रपति यह निश्चित करता है कि पटसन के निर्यात कर की माफ में से कुछ राज्यों को बदले में क्या भनारति मिलनी चाहिए।

(15) न्यायिक शक्तियाँ—संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियों की प्रदान की गई है। वह उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह अनुदान करने की शक्ति के अन्तर्गत अपराधियों को दण्ड को कम करने, स्थगित करने या दण्ड करने का अधिकार रखता है। वह माफ़ की स्वीकृति स देश में आम माफ़ी (General Amnesty) की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति के सम्मानकालीन कार्यों और अधिकारों का सूचीकरण—सामान्यतः हमें राष्ट्रपति गवितारिका का मतानुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति के वरदान पर मन्त्रि परिषद् मतानुसार पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। तथापि राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद मन्त्रिपरिषद् द्वारा दी गई मन्त्रों का मनाने के लिए बाध्य है।¹ और राष्ट्रपति के संवैधानिक शक्तियों के रूप में संनिधित भूमिका है। वह प्रपन्नशी क नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् की सहायता और मतानुसार क अनुमति का लिए बाध्य है। वह देश का औपचारिक शासक है।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers of the President)

जर्मनी के कानून संविधान की धृति भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को तीन आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की हैं जो इस प्रकार हैं—

(1) युद्ध या आक्रमण अध्या 'सशस्त्र विद्रोह' से उत्पन्न भयन (अनुच्छेद 352)—

1. अनुच्छेद 352, यह उल्लिखित करता है कि यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि सशस्त्र भयन स्थिति विद्यमान है, जिससे युद्ध, बला आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या भारत के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है या ऐसा संकट संनिहित है। वह उद्घोषणा द्वारा इस तथ्य की घोषणा, 'सम्पूर्ण' भारत के सम्बन्ध में या उस ऐसे भाग के सम्बन्ध में कर सकेगा जो उद्घोषणा में उल्लिखित किया जाए।¹ ऐसी घोषणा की राष्ट्रपति तत्कालीन उद्घोषणा द्वारा बराम (Revoked) ले सकता है या परिवर्तित (Varied) कर सकता है, लेकिन मार्च 1988 में पारित 59वाँ संविधान संशोधन ने तिसरी व्यवस्था दो वर्षों के लिए पञ्च पर लागू होती है। आन्तरिक उपद्रव की शब्दावली को पुनः अनुच्छेद 352 में जोड़ दिया गया है। प्रस्तावित संविधान संशोधन के माध्यम से नये अनुच्छेद 359 (क) में यह व्यवस्था निर्दिष्ट की गई है कि भारतभर सभ्य या राष्ट्रपति देश में आन्तरिक उपद्रव होने की स्थिति में देश का एकत्र और अङ्गठन कर सकने की धन में रखकर सारे देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर सकता है। ऐसा पञ्च म आपातकाल लागू करने हेतु किया गया था।

2. राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करागा जब उसे प्रतिमांडल का विनिश्चय लिखित रूप में समुचित विचार करण अर्थात् पूरे प्रतिमांडल के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श पर नही जैसा 1975 में हुआ था। (खंड 3)

3. ऐसी उद्घोषणा ससद के प्रत्येक सदन के सभ्य हकी जारणी और 1 मस (44वें संशोधन के पूर्व 2 मस) का समर्थन पर प्रवर्तन में नही रहेगी यदि ठा का मतानुषि की समर्थि के पहले ससद क दोनों सदनों के सभ्य द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हो। यदि ऐसी उद्घोषणा उस समय की गई है जब लोकसभा का विघटन हो चुका है या तमस विघटन खंड (2) के अन्तर्गत बिना कोई सभ्य परित किए 1 मस की अवधि के भीतर हो जाता है जबकि राज्यसभा ने सभ्य का अनुमोदन कर दिया है ठे वह उद्घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक या तत्पश्चात् में 30 दिन की समर्थि पर प्रवर्तन में न रहेगी, जब तक उपर्युक्त 30 दिन की समर्थि के पूर्व उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला सभ्य परित न कर दिया गया हो। उद्घोषणा का अनुमोदन वाला सभ्य सदन के विशेष बहुमत स परित किया जाता है। यदि अर्थात् कुल सदस्यों के बहुमत से उल्लिखित तथ्य मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत स परित होना चाहिए। 44वें संशोधन के पूर्व ऐसा सभ्य सदन के सभ्य बहुमत स परित किया जा सकता था। (खंड 6)

4. ससद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर आपात-उद्घोषणा दूसरे सभ्य के परित होने की निधि में 6 मस की अवधि तक प्रवर्तन में रहेगी, यदि इससे पहले प्रतिमांडल (Revoke) न कर दी गई हो। ठा मत की आरंभ से अन्तिम रखने के लिए प्रत्येक छ मस पर ससद का अनुमोदन आवश्यक होगा। यदि छ मस की अवधि के भीतर आपात-उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उद्घोषणा पुनः के परामर्श नई लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन की समर्थि पर प्रवर्तन में नही रहेगी यदि इस अवधि के पूर्व उद्घोषणा का रदन द्वारा अनुमोदन न कर दिया गया हो। यदि उद्घोषणा के अनुमोदन का सभ्य बहुमत से परित किया जाता है। (खंड 5)

5. खंड (7) उल्लिखित करता है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा को प्रतिमांडल (Revoke) करना परामर्श यदि लोकसभा सभ्य बहुमत से इस मतानुषि करने के विशेष में सभ्य परित कर देती है। खंड (8) व्यवस्था करता है

कि यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस उद्घोषणा की समाप्ति के आशय का शक्तिसूचक (क) स्पीकर को, यदि सदन का सत्र चल रहा है या (ख) राष्ट्रपति को यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा है दिया गया है तो उस पर विचार करने के लिये राष्ट्रपति या स्पीकर को 14 दिनों में सदन का विशेष सत्र बुलाना होगा। खतरे की आशंका से आपात की घोषणा का जा सकता है। अतः आपातस्थिति के अस्तित्व में राष्ट्रपति का समाधान (Satisfaction) पर्याप्त है। यह कि भाषा-उद्घोषणा के लिए पर्याप्त परिस्थितियों विद्यमान हैं या नहीं अथवा संसद की आशंका सही है या नहीं विचार करने की शक्ति खतरे में है राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है। न्यायालय राष्ट्रपति के समाधान का अपील कर सकते हैं।

6 खण्ड (9) साह करता है कि अनुच्छेद 352(1) के अधीन विभिन्न आपातों पर आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति शक्तिमत्त है किन्तु भले ही इसके अन्तर्गत घोषणा करने की जा चुकी हो और वह प्रवर्तन में हो।

7 42वें संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करते यह स्पष्ट किया गया है कि आपात-उद्घोषणा देश के किसी भाग में परिस्थिति की जा सकती है या सम्पूर्ण भारत में लागू है तो उसे एक भाग से हटाया जा सकता है जहाँ स्थिति सामान्य हो गई है। इस प्रयोजन से प्रस्तुत संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शब्दावली—“सम्पूर्ण भारत के सम्बन्ध में या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में” जोड़ी गई है तथा छान्द (क) में परिवर्तित (Varied) शब्द जोड़ा गया है। इस संशोधन के पूर्व आपात का उद्घोषणा भारत के सम्बन्ध में की जा सकती थी।

8 44वें संशोधन, 1978 के द्वारा संसद के अनुमोदन के बाद आसन्न उद्घोषणा 6 माह के लिए प्रवर्तन में रहेगी। इस अवधि का बढ़ाने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा।

आपात उद्घोषणा का प्रभाव—अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपात-उद्घोषणा के निम्नलिखित परिणाम होते हैं—

1 सभ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को निर्देश देने तक विस्तृत हो जाती है कि वे कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति में करें। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केन्द्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है।

2 संसद की राज्य-सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह ऐसे विषय पर कानून बना सकती है जो सभ या उसके पदाधिकारियों को कार्यक्षम प्रोत्साहित हो, भले ही वह विषय सभ-सूची में वर्णित न हो। आपातकालीन स्थितियों में केन्द्र तथा राज्यों के बीच विधान-शक्ति का विभाजन सामान्य का रहता है। आपातकाल के दौरान राज्य विधानमण्डल की कानून बनाने की शक्ति निलम्बित कर दी जाती है। राज्य विधानमण्डल राज्य-सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं तो संसद द्वारा पारित विधियों के अधीन होते हैं।

3 राष्ट्रपति उचित समझे तो आदेश द्वारा अनुच्छेद 268 से 279 में उपबन्धित केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों में परिवर्तन कर सकता है। ऐसे प्रत्येक आदेश को राष्ट्रपति के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4 संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती और आपात-उद्घोषणा का समाप्त हो जाने के पश्चात् 6 माह बाद स्वयं समाप्त हो जाएगी।

5 इस प्रकार के प्रभाव अन्तर्गत सभ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया कि आपात-उद्घोषणा के प्रभाव से अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलम्बित नहीं होते हैं बल्कि उनका प्रवर्तन करने का अधिकार निलम्बित होता है। अतः विधिक दावे आपात-उद्घोषणा से रह नहीं हो जाते हैं। उनको केवल 358 और 359 (1) के प्रवर्तन काल में विधि बनाकर निलम्बित किया जा सकता है।

6 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार राष्ट्रपति प्राण एवं दीर्घकाल स्वतन्त्रता अधिकार को गौरीमान्य नहीं कर सकता तथा आपात के दौरान उन्हीं विधियों को न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से संरक्षण प्राप्त होगा जो आपात उद्घोषणा से सम्बन्धित है। अन्य विधियों की विधि-मान्यता को आपात के दौरान चुनौती दी जा सकती है।

अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को काफी व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। विश्व के किसी संघात्मक सविधान में आपात उपबंध को समावेश नहीं किया गया है। सविधान सभा में कुछ सदस्यों द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी कि राष्ट्रपति इस व्यापक शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है किन्तु डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस आशंका को निर्मूल बताते हुए कहा था कि सविधान में निर्धारित उपबन्ध राष्ट्रपति की शक्ति पर पर्याप्त अंकुश रखते हैं—

राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमण्डल की सहायता और परामर्श से करता है। लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बनी रहती है अतः वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल में निहित होती है।

(2) राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल होने में उत्पन्न आपात (अनुच्छेद 356) — सच सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार सविधान के उपबन्धों के अनुसार चलती रहे (अनुच्छेद 355)। इसलिए यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन सविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है या राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता है जब सच की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में राज्य असमर्थ रहता है (अनुच्छेद 365)। राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा द्वारा—

- (क) उस राज्य की कार्यपालिका के या अन्य प्राधिकारी के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले लेगा।
- (ख) यह घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग ससद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जा सकेगा परन्तु ऐसी घोषणा द्वारा उच्च न्यायालय के कृत्य नहीं लिए जा सकेंगे। जब उद्घोषणा द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निष्क्रिय किया जाता है तब—
- (i) ससद उस राज्य के लिए विधान बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन राष्ट्रपति को या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कर सकती है।
- (ii) जब लोकसभा सत्र में न हो तब राष्ट्रपति ससद द्वारा ऐसे व्यय की मजूरी दिए जाने तक राज्य की सचिव निधि से व्यय प्रधिकृत कर सकेगा।
- (iii) जब ससद सत्र में न हो तब राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन के लिए अध्यादेश प्रस्तापित कर सकेगा (अनुच्छेद 357)।

ऐसी उद्घोषणा की अवधि दो मास की होगी, किन्तु यदि जब उद्घोषणा की गई थी तब लोकसभा का विघटन हो गया था या उपर्युक्त दो मास की अवधि के भीतर विघटन हो गया है तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठित होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त नहीं रहेगी जब तक कि ससद ने उद्घोषणा का अनुमोदन न कर दिया हो। ऐसी उद्घोषणा की दो मास की अवधि का ससद के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प द्वारा विस्तार किया जा सकता है। यह विस्तार एक बार में छह मास की अवधि के लिए होगा और अधिकतम तीन वर्ष होगी। [अनुच्छेद 356 (3) (4)], किन्तु तीन वर्ष की अवधि तभी बढ़ाई जा सकती है जब—

- (क) ऐसे संकल्प के पारित करने के समय सम्पूर्ण भारत में या सम्पूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त में है।
- (ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खण्ड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा की प्रवृत्त बनाये रखना सम्बन्धित राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाई के कारण आवश्यक है।

उद्घोषणा दुर्भाव से भी की जा सकती है या उद्घोषणा में प्रकट किये गये कारणों का राष्ट्रपति के समाधान से कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं अर्थात् इस सम्बन्ध में न्यायालयों को एक एगमोक्न का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 352 और 356 में अन्तर—

(1) अनुच्छेद 352 राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यथावत कार्य करती रहती है। केवल केन्द्र को राज्य-सूची के विषयों पर विधान और प्रशासन की समवर्ती शक्ति मिल जाती है जबकि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल को निष्क्रिय अथवा विघटित कर दिया जाता है और राज्य की प्रशासकीय एवं विधायी शक्तियाँ केन्द्र सरकार में निहित हो जाती हैं।

(2) अनुच्छेद 352 की व्यवस्थाएं समान रूप से सभी राज्यों पर लागू होती हैं, जबकि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केन्द्र और केवल एक राज्य (जिसमें सांविधानिक तंत्र विफल हो गया हो) के सम्बन्धों में परिवर्तन होता है।

(3) अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 356 में मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(3) वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360) — अनुच्छेद 360 उपबन्ध करता है कि यदि राष्ट्रपति को 'समाधान' हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साध (Stability or Credit) संकट में है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है। वह राज्य के सेवारत कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कमी करने और धन-विषेयक तथा वित्तीय विषेयक स्वायत्तता के लिए अपने पास भेजने के निर्देश दे सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों व केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कमी करने का आदेश दे सकता है।

अनुच्छेद 360 की उपयोगिता की कारावधि 2 महीने की होगी। यदि उक्त दो महीने की समाप्ति के पहले सप्तरात्र पारित संकल्प से अनुमोदित नहीं की जाती है तो 2 महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी।

यद्यपि राष्ट्रपति को ये सभी बाधाएँ अधिकार प्राप्त हैं तथापि वह उनका मनमाना उपयोग नहीं कर सकता। वह अपने पद के ही कारण गणराज्य का प्रधान है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है तथा मंत्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका है।

भारतवर्ष में इस प्रकार के वित्तीय संकट की घोषणा अद्यतन नहीं की गई है।

राष्ट्रपति का आपात शक्तियाँ का व्यवहार में प्रयोग

(1) राष्ट्रीय संकटकाल—अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत बाह्य आक्रमण की स्थिति में इस शक्ति का प्रयोग अक्टूबर, 1962 और दिसम्बर, 1971 में हुआ तथा आन्तरिक अशांति की स्थिति में इसका प्रयोग जून, 1975 में किया गया। सितम्बर, 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण होने पर 26 अक्टूबर, 1962 को राष्ट्रपति डा. राजाकृष्णन ने जो आपात-उद्घोषणा की वह 10 जनवरी, 1968 तक चली। राष्ट्रपति की उद्घोषणा में कहा गया कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे बाह्य आक्रमण से भारत की सुरक्षा संकट में है। 3 नवम्बर, 1962 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बन्धित अनुच्छेद 11 एवं 22 स्थगित किए गए और इसी दिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मर्यादा के लिए व्यापारों की शरण लेने के अधिकार को भी स्थगित किया गया और 14 नवम्बर, 1962 को अनुच्छेद 14 भी स्थगित किया गया। 26 अक्टूबर, 1962 को ही भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश जारी किया गया। भारत प्रतिरक्षा नियम, नागरिक प्रतिरक्षा सेवा नियम, भारतीय प्रतिरक्षा (सम्पूर्ण अर्जन एवं अधिग्रहण) नियम आदि भी इसी अधिनियम के आधार पर बनाए गए। विधेयक को बाद में भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

इसी प्रकार दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने पर 3 दिसम्बर को आपात-स्थिति की घोषणा पुनः की गई। 1971 में पारित आपातकाल से लागू या इसके साथ ही आन्तरिक अशांति की स्थिति में 25 जून, 1975 से आपात-स्थिति लागू की गई वह 21 मार्च, 1977 तक चली। 25 जून, 1975 को भारत में तीसरी बार आपात-स्थिति लागू करने के पश्चात् संविधान की सभी व्यवस्थाओं का प्रयोग किया गया। 27 जून को राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया जिसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 में दिए गए अधिकारों को लागू करने के सिलसिले में किसी नागरिक जिनमें विदेशी नागरिक शामिल हैं, द्वारा अदालत में याचिका दायर करने के अधिकार को निलम्बित किया गया। इस सिलसिले में अदालतों में विचारणीय मामलों को आपात-स्थिति की अवधि तक स्थगित किया गया। यह आदेश जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत सच पर लागू हो गया। इन 19 महीनों के दौरान श्रीमती इन्दिरा गान्धी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए जिनसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था। इस अवधि में राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा नागरिक अधिकारों का निलम्बन किया गया, अदालतों और अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भविष्य में संशोधन के द्वारा सीमित किया गया।

मार्च, 1977 में जनता सरकार बनी और लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया आरम्भ हो गई। 25 जून, 1975 और 3 दिसम्बर, 1971 की राष्ट्रपति की आपात-उद्घोषणाएँ क्रमशः 21 और 27 मार्च, 1977 को रद्द किए जाने से देश में आपात-स्थिति औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। तदनुसार भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियाँ 26 दिसम्बर, 1977 तक उपलब्ध रही, पर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाए और केन्द्र सरकार से पहले सलाह-मशवरे के बाद। आन्तरिक सुरक्षा अनुसंधान अधिनियम, 1971 कानूनों में बना रहा, परन्तु राज्य सरकारों को नजरबन्दियों को कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियों के सदस्यों को छोड़कर रिहा करने की सलाह दी गई। बाद में इस कानून के स्थान पर निवारक नजरबन्दियों के सम्बन्ध में कानून बनाए गए जिसका निरसन करने के लिए निर्णय किया गया। राजनीतिक सम्बद्धता अथवा विश्वास के लिए दंडितता में रहे गए व्यक्तियों को रिहा करवाने के लिए प्रबल किए गए और तथाकथित नवसन्नाहियों के लिए नई नीति तैयार की गई। महत्वपूर्ण नीतियों तथा प्रशासकीय आदेशों को वर्तमान सरकार का नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनकी समीक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई।

नागरिक स्वतंत्रताओं को बहाल करने की 1977 में आरम्भ की गई प्रक्रिया का अन्तिम चरण 1978-79 में सम्पन्न हुआ। आन्तरिक सुरक्षा कानून 3 अगस्त, 1978 से रद्द किया गया और आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन सभी नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा किया गया।

(2) राज्य में संकटकाल—राज्यों में सार्वजनिक तब की विफलता को स्थिति में अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में राज्य प्रशासन का संचालन करता है। राज्य प्रशासन पर संसद का नियन्त्रण स्थापित हो जाता है।

(3) वित्तीय संकटकाल—अभी तक देश में वित्तीय संकटकाल की घोषणा नहीं की गई है।

आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन (Evaluation of Emergency Powers)—राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियों की सविधान-सभा में कड़ी आलोचना की गई थी। कुछ सदस्यों ने यह मत प्रकट किया था कि इन विधान शक्तियों का आश्रय लेकर भारत का राष्ट्रपति भविष्य में तानाशाही स्थापित कर सकेगा जैसे की हिटलर ने जर्मनी में सविधान की धारा 48 का लाभ उठाते हुए की थी। बी. दास (B. Das) के अनुसार “ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को दक्षिण अफ्रीका के टन प्रणाली की तरह बना देंगी जो वित्तीय शक्तियों सहित समस्त शक्तियों को हड़प सकने दे और प्रान्तों को वित्तीय संकट में डाल सकने दे।” आलोचकों के अनुसार भारत में आपातकालीन शक्तियों के प्रवर्तन और प्रयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में नहीं जा सकता—

1. राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संकटकालीन घोषणा पर दो मास तक (44वें सविधान संशोधन के बाद एक मास) कोई प्रतिबन्ध नहीं है और प्रतिबन्धहीन अवस्था में राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों को निराश्रय रूप में दुरुपयोग कर सकता है।

2. राष्ट्रपति को संकटकालीन परिस्थितियों में निर्णय करने का अधिकार है जिसको न्यायानुसंग में चुनौती नहीं दी जा सकती। (44वें सविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई निम्नलिखित सलाह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी)।

3. ‘युद्ध के कारण आपात’ और ‘राष्ट्रकालीन आपात’ तथा ‘अन्तर्राष्ट्रिक अशांति के कारण आपात’ में भारतीय संविधान में भेद नहीं किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक हड़ताल होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है और इस घोषणा के परिणाम वही हो सकते हैं जो युद्ध सम्बन्धी आपात घोषणा के हो सकते हैं (जून 1975 की आपात-घोषणा के बाद ऐसा हुआ था। अब 44वें संशोधन द्वारा निरिपक्ष किया गया है कि सरासरी विद्रोह के अन्तर्गत अन्य प्रकार के अन्तर्राष्ट्रिक उपद्रवों पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जायेगी)।

4. राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा के दौरान संपात्तिक सगटन में भी इच्छाओं की सरकारें स्थापित कर दी गईं।

5. केन्द्र में सत्तारूढ़ शासन यदि चाहे तो किसी राज्य में जहाँ मन्त्रिमण्डल की स्थिति बहुत सुदृढ़ है दलीय स्वयं को या पूर्वग्रहों के आधार पर सांविधानिक तन्त्र के असम्पन्न होने की घोषणा कर उस राज्य सरकार को अपदक्ष्य कर सकता है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग स्पष्ट प्रमाण है।

6. यदि राज्य केन्द्रीय सरकार के निर्देशन का पालन न करे तो इस पर राष्ट्रपति राज्य में सांविधानिक तन्त्र के असम्पन्न होने की घोषणा कर सकता है। किसी इच्छाई राज्य में शासनतन्त्र को विफलता की घोषणा की जा सकती है जब वहाँ राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाए। सन् 1994 में एम. अर. बोम्बाई बनाम भारत सरकार नामक बंद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति को सीमित कर इसके दुरुपयोग की कठिनी कर दिया है।

जून 1975 की आपात-उद्घोषणा के अनुभवों के परिचय में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आपातकाल के विरुद्ध कुछ और सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गयी है। अब यह सुनिश्चित किया गया है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई निम्नलिखित सलाह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी तबकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह घोषणा उन्मुख और प्रदीप्त विचार-विमर्श के बाद की गई है। 44वें संशोधन द्वारा सुरक्षात्मक व्यवस्था की दी गई कि आपात-उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा उन्मी बहुमत से स्वीकार किया जाना होगा जिसका बहुमत सविधान में संशोधन के लिए आवश्यक होता है और यह स्वीकृति एक महीने की अवधि के पक्षर दो जानी होगी। अतः नवीन परिस्थिति में यह विचार उपयुक्त नहीं है कि आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए। राष्ट्र की सुरक्षा का अन्तिम उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है, अतः संकटकाल में राज्य की समस्त शक्तियों को अपने नियंत्रण में लाने का अधिकार उसे होना चाहिए। समर और जनपद की सशक्त राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग की संभावनाओं को समाप्त कर सकती है। भारत के राष्ट्रपतियों की आपातकाल की कार्य-शैली इस तथ्य की पुष्टि करती है कि वे सांविधानिक शासक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। उनमें तानाशाही शासक के रूप में आचरण करने की मानसिकता दृष्टिगत भी नहीं है। उन्होंने यह माना कि वे औपचारिक सांविधानिक अध्यक्ष हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल में निहित है, अतः भारत में कभी राष्ट्रपतीय तानाशाही की सम्भावना किसी दृष्टि में भी नजर नहीं आती है।

राष्ट्रपति की सांविधानिक स्थिति

(Constitutional Position of the President)

राष्ट्रपति की शक्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि कुछ अवसरों पर राष्ट्रपति को स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ता है, तबकि वह एक सांविधानिक उपाध्यक्ष (Constitutional Head) है जो अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल को सन्तुष्ट से बरत है अर्थात् कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, बल्कि मन्त्रिमण्डल में निहित है जिसका नया प्रथममन्त्री

होता है। राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में सविधान-सभा में अनेक बार वाद-विवाद हुआ और प्रत्येक वाद-विवाद में राज्याध्यक्ष के सविधानिक गुणों पर बल दिया गया। राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्यीकरण करने के लिए और यह देखने के लिए कि सविधान द्वारा उसे संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है अथवा वास्तविक अध्यक्ष, राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद् के पारम्परिक सम्बन्धों की समीक्षा आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 74, 75 और 78 विशेष महत्व रखते हैं जिनके अनुसार यह निर्धारित किया गया है—

- 1 राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता एवं सल्लाह देने के लिए मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा।
- 2 राष्ट्रपति अपने कृत्यों के निर्वहन में मन्त्रिपरिषद् की सल्लाह के अनुसार चमकेगा।
- 3 राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् से उसकी सल्लाह पर पुनर्विचार की माँग कर सकते हैं। ऐसी पुनर्विचार के बाद जो सल्लाह राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है उसे वह उसी रूप में स्वीकार करेंगे।
- 4 क्या मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को सल्लाह दी? और यदि दूँ तो क्या दूँ? इस प्रश्न की व्यापारिक में जाँच नहीं की जाएगी।
- 5 प्रधानमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करेगा और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सल्लाह पर करेगा।
- 6 राष्ट्रपति के अनुसूच-पर्यन्त मन्त्री पद धारण करेंगे।
- 7 मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में (Collectively) उत्तरदायी होगी।
- 8 प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह—

- (क) मन्त्रिपरिषद् के द्वारा सच कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी समस्त विनिश्चयों तथा प्रस्तावित विधान सम्बन्धी सभी सूचार्ण राष्ट्रपति को दे।
- (ख) सच कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान-विषयक प्रस्तावनाओं सम्बन्धी जिन जानकारीयों को राष्ट्रपति माँगाए, वह प्रदान करे।
- (ग) ऐसे विषयों को जिसे मन्त्री ने विनिश्चय किया हो, किन्तु इस पर मन्त्रिपरिषद् ने विचार न किया हो राष्ट्रपति की इच्छा पर मन्त्रिपरिषद् के सामूहिक विचारार्थ प्रस्तुत करे।

इन उपबन्धों के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय सविधान निर्माता भारत में राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष बनाती है। राष्ट्रपति की शक्ति और अधिकारों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति 'राष्ट्र का प्रत्येक' है, राष्ट्र का शासक नहीं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मन्त्रिपरिषद् के प्रसाद पर्यन्त अपने पदों पर रहते हैं लेकिन राष्ट्रपति का 'प्रसाद' वास्तव में प्रसाद का ही प्रसाद है और प्रसाद के ही प्रसाद पर्यन्त मन्त्रिपरिषद् पदासीन रहते हैं। मन्त्रिपरिषद् को यदि स्वीकृति या विरक्तता प्राप्त है तो कोई राष्ट्रपति उसे अपदस्थ करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि यह कार्य असंवैधानिक होगा और इस दुस्साहस का परिणाम यह हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने पद को खो बैठे। प्रसाद के लिये यह असह्य होगा कि राष्ट्रपति प्रसाद की विरक्ततापर मन्त्रिपरिषद् को अपदस्थ करके प्रसाद की राजनीतिक और सार्वजनिक सत्ता को चुनौती दे दे। अर्थात् भारत का राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों का आलोचक है, परामर्शदाता है और मित्र है। परामर्शदाता के रूप में वह अपने विचारों को मन्त्रिपरिषद् के समक्ष रख सकता है। आलोचक के रूप में वह उस सल्लाह पर आपत्ति कर सकता है जो मन्त्री ने उसे किसी विषय पर दी हो, किन्तु उसे ज़िद या हठ नहीं करने चाहिए और आदेश उपचार के रूप में यदि मन्त्री राष्ट्रपति की बात को 'मानना' चाहे तो उसे मान लेना चाहिए। मन्त्रिपरिषद् के मित्र के रूप में राष्ट्रपति को सल्लाहानी बतानी चाहिए कि वह अपनी ज़िद पर व्यर्थ में अड़ा रहे जिसके फलस्वरूप शासन का शक्तिहीन हो खतरे में पड़ जाए। जब तक राष्ट्रपति ऐसी मन्त्रिपरिषद् की सल्लाह पर चलता है जिसने लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, वह कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं कर सकता है।

भारतीय न्यायपालिका ने 'राम जवाहा बन्साल भारत सच'¹, 'यू.ए.ए. बन्साल इन्डिया मीडिया'², 'शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब'³ आदि मामलों में जो निर्णय दिए हैं उनसे इसी मत की पुष्टि होती है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिपरिषद् में निहित होती है।

42वें और 44वें संशोधन के पश्चात् यह सोचना की राष्ट्रपति एक कठपुतली मात्र है अतार्थ है। यद्यपि उसके विशेषाधिकार (Prerogatives) का क्षेत्र अत्यन्त सीमित हो गया है तथापि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ राष्ट्रपति की शक्ति

1 ए.आई.आर. 1955, सुप्रीम कोर्ट, 549

2 ए.आई.आर. 1971, सुप्रीम कोर्ट, 1002

3 ए.आई.आर. 1974, सुप्रीम कोर्ट, 2192

पर उपर्युक्त सशोधनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और वह इन मामलों में मॉनिटरिंग के परामर्श से कार्य कर के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है। वे इस प्रकार हैं—

(1) **प्रधानमंत्री की नियुक्ति—अनुच्छेद 75(1)** यह उपबन्धित करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर कर सकता है तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सहायक पर होगा। भारत में यह रुढ़ि स्थापित हो चुकी है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सम्मुख रूप में उत्तरदायी होगी। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता चाहिए जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत दल का नेता या अन्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, वरतें उसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो और वे उसे अपना नेता चुनें। 1966 में श्रीमती इन्दिरा गांधी जब पहले-पहले प्रधानमंत्री नियुक्त की गईं तो वे लोकसभा की सदस्य थीं, शायद यह उचित एक लोकतांत्रिक प्रणाली का अनुरूप माना जाता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। साधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति का कोई संदेह नहीं होता कि जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, वह केवल विशेष परिस्थिति में जबकि किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, अपने विवेकानुसार का प्रयोग कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो उसके अनुसार लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो और एक स्वयं सारक बना सके। ऐसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न होती है किन्तु संविधानविदों के अनुसार ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को स्वविवेक के प्रयोग का कम अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि ठम पारम्पर्य के अनुसार कार्य करना होगा। संविधान में इसके लिए अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं हैं। इम्पैड की रुढ़ियाँ भारतीय परिस्थिति में लागू नहीं की जा सकती हैं। विभिन्न राज्यों में जो मन्त्र्यें उत्पन्न हुए वे उनके आधार पर निर्वाचित सिद्धांत हमारे समक्ष आए हैं—

1. सदन के सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए।

2. चुनाव के पहले बने सविद (Coalition) के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए।

संवैधानिक विशेषता के अनुसार यदि लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति का सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए। इस परम्परा के अनुसार कार्य करने से राष्ट्रपति का कार्य सरल हो जाएगा और वह अनोचना का पात्र नहीं होगा। यदि चुनाव के पूर्व कई दल मिलकर मयुक्त दल (Coalition) बनाते हैं तो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए। इसके परवर्तु चुनाव के बाद बन्य गये मयुक्त दल (Coalition) के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता चाहिए। सबसे बड़े दल के नेता और चुनाव के परवर्तु बने मयुक्त दल के बीच में यदि अंतर कम हो तो सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यह निर्णय करना राष्ट्रपति का कार्य होगा कि दोनों में से किसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यह विवेकपूर्ण तथ्य समझाया जा सकता है ज. साकार अविश्वास के प्रस्ताव में पारित हो जगती है और उपर्युक्त दोनों विवेकपूर्ण उपाय नहीं हैं। यह रुढ़ि ब्रिटेन में सुस्थापित है। ब्रिटेन में केवल दो राजनीतिक दल हैं, एक सरकार बनाना है दूसरा विरोधी पक्ष होता है। ऐसी दल में विरोधी पक्ष के नेता को आमंत्रित देना उचित है, किन्तु भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं, अतः इस रुढ़ि को लागू नहीं किया जा सकता है।

(2) **लोकसभा का विघटन—अनुच्छेद 85** लोकसभा के विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस हेतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सहायता से लोकसभा का विघटन करता है। राष्ट्रपति स्वविवेक से लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है राष्ट्रपति उसके पदमर्त से लोकसभा का विघटन करने के लिए बाध्य है।

क्या राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा का विघटन करने के लिए बाध्य है जो लोकसभा का बहुमत को चुका है (दल-बदल के कारण अथवा अन्य कारण से) अथवा लोकसभा में पारित हो गया है? इस प्रश्न पर संविधान विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। एक मत है कि राष्ट्रपति प्रत्येक दल में प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। यह मत ब्रिटेन की एक सुस्थापित रुढ़ि (Convention) पर आधारित है। ब्रिटेन में स्वच्छ स्वयं प्रधानमंत्री की सहायता पर राज्य ऑफ बॉन्स का विघटन किया है कि यदि वह सदन में बहुमत को चुका है अथवा उसके विश्वास अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो चुका हो। दूसरा मत है कि राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा के विघटन करने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है। अधिकांश संवैधानिक देशों के अनुसार दूसरा मत अधिक उपयुक्त है। राज्यों में इसके अनेक उदाहरण हैं जब राजनय ने ऐसे मुख्यमंत्रियों के परामर्श को मानने से इनकार कर दिया था जो सदन में अल्पमत हो गए थे अथवा विश्वास मत प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। अतः संवैधानिक परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है—

(1) जब वह सदन में अपना बहुमत छो देता है या (2) जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है या (3) जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, या (4) जब वह लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देता है और राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत है कि सरकार का बहुमत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति को वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि संविधान-सभा में डॉ. अम्बेदेकर ने यह विचार व्यक्त किया था कि लोकसभा को भंग करने का निर्णय सबसे अन्तिम विकल्प होना चाहिए। भारत एक बड़ा देश है, बार-बार चुनाव करना इस देश के लिए अहितकर है। जहाँ तक भारत में लोकसभा भंग करने सम्बन्धी प्रश्न का आचरणगत प्रश्न है अभी तक सभी राष्ट्रपतियों ने प्रधानमन्त्रियों की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करने का निर्णय लिया है। आशा है कि आने वाले वर्षों में भारत में इस सम्बन्ध में स्वस्थ परम्परा विकसित होगी।

राष्ट्रपतियों का आचरणगत पक्ष

स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक भारत में अनेक राष्ट्रपति सत्कार्ण हो चुके हैं। इन राष्ट्रपतियों की कार्य-शैली और भूमिका का विश्लेषण करने पर कतिपय निष्कर्ष सामने आते हैं—

(1) भारत का राष्ट्रपति पद देश के संविधान की सुरक्षा का प्रतीक बन गया है जिसकी लोकतान्त्रिक-गणराज्य के स्वरूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका रही है। सभी राष्ट्रपतियों ने संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण किया है। उन्होंने अपनी ओर से संविधान का अनादर करने अथवा उसका अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया है।

(2) राष्ट्रपतियों ने अपने आपको औपचारिक-संवैधानिक अण्डर के रूप में मानते हुए कार्य किया है, अर्थात् स्पष्ट है कि वह मात्र संविधानिक अध्यक्ष हैं और धार्मिक शक्तियों प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् में निहित हैं। इससे देश के समद्रीय लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हुई हैं।

(3) राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों ने इस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बार-बार सजाया है। प्रथम तीन राष्ट्रपति सर्वश्री डॉ. राजेन्द्रप्रसाद, डॉ. राजाज्यन्त और डॉ. जवाहर लाल नेहरू जी यहाँ विभूतियों द्वारा इस पद को धारण करने के कारण इस पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। ये तीनों ही विभूतियों भारतीय जनता में अत्यन्त आदर की पात्र रही हैं। बाद में सत्कार्ण हुए राष्ट्रपति भी इन महान विभूतियों सदृश सिद्ध हुए हैं।

(4) राष्ट्रपतियों ने अपनी भूमिका से इस देश की राजनैतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की है। उन्होंने अपनी कार्य-शैली से देश में संविधानिक गत्यावरोध और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। यह देश के समद्रीय लोकतन्त्र के हित में रहा है।

(5) समय-समय पर राष्ट्रपतियों और प्रधानमन्त्रियों के बीच मतभेदों की स्थिति उत्पन्न हुई है जो कि अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति ने इस स्थिति को इतना विस्फोटक नहीं बनने दिया कि वहाँ से लौटना ही संभव नहीं हो सके।

(6) राष्ट्रपतियों ने मन्त्रिपरिषद् के सलाहकार, मार्गदर्शक और दार्शनिक की भूमिका का निर्वाह किया है और अपने उपयोगी सुझावों से उनकी सहायता किया है।

(7) शक्तिशाली पद पर होते हुए राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री के मतभेदों का सामना करना पड़ा है और सुदृढ़ सरकार के अभाव में उसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, किन्तु उसने अपनी भूमिका का सम्यक्पालन किया है अतः उसे कभी महामहोदय का सामना नहीं करना पड़ा।

(8) राष्ट्रपति की शक्तिवैक्य वी शक्तियों महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। लोकसभा को किसी दौन अथवा दार्शनिक गठबन्धन के स्पष्ट बहुमत के अभाव में प्रधानमन्त्री से विश्वास मत प्राप्त करने की परम्परा विकसित हो रही है।

उपराष्ट्रपति

(The Vice President)

भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा (अनुच्छेद 63)। यद्यपि भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति का पद प्रत्यक्ष महत्त्व का अधिक नहीं है। उपराष्ट्रपति पद भारत का सम्मानित एवं गरिमापूर्ण पद है जिसमें अग्र्य भावी राष्ट्रपति की सम्भावनाये छिपी रहती हैं।

उपराष्ट्रपति की योग्यतायें—संविधान के अनुच्छेद 66(3) के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है।

(ख) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

भी सदन के सदस्य नहीं थे। मई, 1996 में जब राष्ट्रपति शंकरदास शर्मा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. देगोटा को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया तो वे भी संसद के सदस्य नहीं थे। यद्यपि ब्रिटिश परम्पराओं के अनुसार अपेक्षा की जाती है कि उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वह नियुक्ति के समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अन्तर्गत संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए। यदि वह वांछित समय में संसद में स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। साथ ही उसे लोकसभा के बहुमत दल का विकास और समर्थन प्राप्त होना चाहिये, क्योंकि वह संवैधानिक दृष्टि से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इंग्लैण्ड में परम्परा है कि प्रधानमंत्री को साधारण बर्तमान सभा का सदस्य होना चाहिए। भारत में ऐसी कोई परम्परा स्थापित नहीं हुई है। केन्द्र और राज्य दोनों ही स्थानों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति उच्च सदन से सम्बन्धित व्यक्तियों में से हुई है।¹

यदि लोकसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो एवं वह दल अपना सर्वमान्य नेता रखता या निर्वाचित कर सकता हो तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कोई स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त नहीं है। यद्यपि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। वह किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, परन्तु व्यावहारिक राजनीति में ब्रिटिश सम्राट की तरह उसे बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमन्त्रित करना पड़ता है। असाधारण परिस्थितियों में इंग्लैण्ड के राजा की भाँति भारतीय राष्ट्रपति भी स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, या बहुमत प्राप्त दल अपना कोई सर्वमान्य नेता न रखता हो अथवा नेता पद का दावा एक से अधिक व्यक्ति करते हों तो उसे स्वविवेक के अधिकार के प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकता है।²

प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति—संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के सम्पादन में सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था है। 44वें संविधान संशोधन के उपरान्त इस अनुच्छेद का पाठ इस प्रकार है—“राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और परामर्श देने के लिए मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों के निर्वहन में उसके परामर्श के अनुसार चलेंगे। राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् से उसकी मंत्रणा पर पुनर्विचार की माँग कर सकते हैं। ऐसे पुनर्विचार के बाद जो भी परामर्श या मंत्रणा राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, उसे वह उसी के अनुसार स्वीकार करेंगे।” इस नवीन व्यवस्था ने यह अनिवार्य कर दिया है कि राष्ट्रपति किसी परामर्श या मंत्रणा को मन्त्रिपरिषद् के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार में यदि मन्त्रिपरिषद् मूल मंत्रणा में कोई परिवर्तन नहीं करती तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार कर लेना पड़ता है। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि मन्त्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई मंत्रणा के सम्बन्ध में किसी विषय पर न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी।

संविधान के 42वें संशोधन से पहले मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति के अधीन एक परामर्शदात्री समिति जो तभी तक अपने पद पर रह सकती जब तक राष्ट्रपति चाहें। उसका कार्य केवल राष्ट्रपति की मंत्रणा प्रदान करना था और राष्ट्रपति उसके लिए स्वतन्त्र है कि वह मंत्रणा को माने या न माने। 42वें संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के सम्पादन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मन्त्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार चलेंगे। 44वें संशोधन में यह शर्त लगा दी गई है कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् से अपने परामर्श पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है, किन्तु इस पुनर्विचार के पश्चात् दिए हुए परामर्श के अनुसार उसे कार्य करना होगा।

प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि भारत सभ के कार्यों के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों से तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी से राष्ट्रपति को अवगत कराए तथा अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया हो, परन्तु जिस पर मन्त्रिपरिषद् द्वारा विचार नहीं किया गया हो, मन्त्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करें।

व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की स्थिति तब अधिक मजबूत होती है जब राष्ट्रपति भवन में मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व विराजमान हो। एक मैत्रीवहीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। अतः आवश्यक है कि प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति एक दूसरे को सहयोग देते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करें। संविधानिक व्यवस्था की माँग है कि राष्ट्रपति बही करे जो प्रधानमंत्री परामर्श दे। प्रधानमंत्री का शक्तिशाली व्यक्तित्व और व्यापक प्रभाव किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर आसीन करने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है, पद पर आसीन होने के बाद वह व्यक्ति राजनीतिक तटस्थता रखते हुए उत्तरदायित्वों को निभाता है। भारत के राष्ट्रपतियों ने इस व्यवस्था और परम्परा से महमति प्रकट की है कि राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् की मंत्रणा के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। राम जवाया बनाम भारत सभ, यू. एन. राव बनाम इन्दिरा गाँधी, रामशेर सिंह बनाम स्टेट आफ़ पंजाब के सदस्यों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से भी उपरोक्त मत की पुष्टि होती है। संविधान राष्ट्रपति की गरिमा प्रस्थापित करता है।

संविधान राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है जबकि कोई दली नीति के किसी प्राप पर मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखे बिना स्वयं निर्णय से लेता है। राष्ट्रपति ऐसे निर्णय को मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ रखने को अपेक्षा कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को सफलता से कार्यान्वित करना इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है। 42वें और 44वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति के विरोधाधीनकार का क्षेत्र सीमित हो गया है मगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ राष्ट्रपति की शक्ति पर इन संशोधनों का प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति तथा लोकसभा के विघटन के मामले में मन्त्रिमण्डल के परामर्श से कार्य करने के लिए राष्ट्रपति विधिक रूप से बाध्य नहीं है।

प्रधानमन्त्री : अधिकार और उत्तरदायित्व

(The Prime Minister : Powers and Responsibilities)

भारतीय प्रधानमन्त्री के अधिकार व्यापक हैं, क्योंकि मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति के व्यापक अधिकारों का प्रयोग करता है। आपात-स्थिति में मन्त्रिमण्डल के अधिकार और व्यापक हो जाते हैं। प्रधानमन्त्री इसमें सर्वोपरि होता है।

प्रधानमन्त्री को असाधारण शक्तियों पर दिग्गम्य करते हुए संविधान सभा में प्रो. के. टी. ताम्र ने कहा था—“उसकी विशाल शक्तियों के देखते हुए यह भय लगता है कि यदि वह चाहे तो किसी भी समय देश का अधिनायक बन सकता है।” प्रधानमन्त्री की वास्तविक शक्ति उसके व्यक्तित्व, चरित्र और उसकी नेतृत्व क्षमता में निहित है। यह इस बात पर निर्भर है कि उसका चयन किस प्रकार हुआ है? यदि प्रधानमन्त्री का चयन उसके व्यक्तित्व तथा दल में सुदृढ़ स्थिति के कारण हुआ है तो प्रधानमन्त्री की स्थिति निश्चय ही मजबूत होती है। यदि प्रधानमन्त्री के चयन में दलीय नेताओं, मुख्यमन्त्रियों आदि का विशेष हाथ है तो वे एक कमजोर प्रधानमन्त्री का चयन करने को तालाबित हो सकते हैं। जब लालबहादुर शास्त्री को प्रधानमन्त्री बनाया गया तब कॉम्रेस अध्यक्ष कामराज ने कहा था कि प्रधानमन्त्री ‘समकक्षों में प्रथम’ से अधिक नहीं होगा।¹

1996 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के चयन में कॉम्रेस के ‘सिण्डीकेट गुट’ की प्रमुख भूमिका होने के कारण उनकी स्थिति कमजोर रही, लेकिन 1971 ई. के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में लोकसभा में दो तिहाई बहुमत मिलने से उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। सन् 1977 में जनता पार्टी के ‘बटकवाद’ के कारण प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई की स्थिति सुदृढ़ रही। अल्पमतীয় प्रधानमन्त्रियों—जैशरी चरणसिंह, पी. पी. सिंह, चन्द्रशेखर, पी. वी. जयसिंहाय्य (अल्पमतिय स्थिति में), एच. डी. देवेगौडा, आई. के. गुजराल तथा अटलबिहारी वाजपेयी की स्थिति सुदृढ़ नहीं रही है।

(क) निर्वाचन का स्वरूप और उसका प्रधानमन्त्री की भूमिका पर प्रभाव—प्रधानमन्त्री की शक्ति के निर्धारण में उसकी चयन-प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। भारतीय प्रधानमन्त्रियों की चयन-प्रक्रिया का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

पं जवाहरलाल नेहरू का चयन—15 अगस्त, 1947 से 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने तक पं. नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री थे, परन्तु सरदार पटेल के दल में शक्तिशाली प्रभाव एवं नियन्त्रणकारी स्थिति के कारण उनका नेतृत्व विवादों एवं चुनौतियों युक्त था। दिसम्बर, 1950 में पटेल के चयन के पश्चात् वे ससदीय दल और संगठन के निर्विवाद नेता हो जाने के कारण 1952, 1957 और 1962 के आम निर्वाचनों में कॉम्रेस ससदीय दल के निर्विरोध नेता चुने जाते रहे। उनका सम्प्रान्तीय पारिवारिक परिवेश शैक्षणिक योग्यता, स्वतन्त्रता-संघर्ष में निस्वार्थ त्याग, अपार लोकप्रियता, चरमकारिक व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रीय छात्राधि, वार्षिक ईमानदारी एवं नियन्त्रणकारी नेतृत्व उन्हें प्रधानमन्त्री पद पर निरन्तर 18 वर्षों तक अधिकार बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुआ। उनके मार्गदर्शन में प्रधानमन्त्री पद का प्रारम्भ, विकास एवं ससदीय प्रजातन्त्र की परम्पराओं की सुस्थापना हुई।² वे भारत के सर्वोधिक शक्तिशाली और करिश्माई प्रधानमन्त्री हुए हैं।

प्रधानमन्त्री पद की अन्तर्गम व्यवस्था—27 मई, 1964 को पं. नेहरू की मृत्यु के कुछ घण्टों के अन्दर ही कैबिनेट की आपातकालीन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति डॉ. राजकृष्ण द्वारा कैबिनेट के चरिष्ठम सदस्य गुलजारीलाल नन्दा को कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया। माइकेल बेयर के अनुसार कृष्णमनन ने इस अस्थायी व्यवस्था को असौविधाजनिक मानते हुए कहा था “व्यवस्था द्वारा सिद्धान्ततः इन असामान्य परिस्थितियों में विरोध शक्तियों का प्रयोग करना असौविधाजनिक था।” एच. एम. जैन इसे सौविधाजनिक मानते हैं। राष्ट्रपति ने गुलजारीलाल नन्दा को अन्तर्गम कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त कर देश को नेतृत्वहीनता के संकट से बचाकर एक स्वस्थ परम्परा की स्थापना की। जनवरी 1966 में प्रधानमन्त्री शास्त्री की मृत्यु के उपरान्त पुनः ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति ने पूर्व परम्परा का अनुसरण

1 C. S. Bhargava 'New Leader', The Times of India, June 3, 1964

2 डॉ. जिल्ता शुक्ला पूर्वोक्त, पृ. 49

का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए 20 अगस्त 1979 को लोकसभा का विस्थापन मत प्राप्त किए बिना ही उन्हें अपनी सरकार का स्थापना दे देना पड़ा। यह मध्यावधि चुनाव होने तक के लिए उन्हें कामचलाक सरकार का प्रधानमंत्री बने रहने दिया गया।

श्रीमती इंदिरा गांधी का पुनः चयन—जनवरी 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए और श्रीमती गांधी पन प्रगल्भ बहुमूल के साथ जीतकर प्रधानमंत्री बनीं। इस अवधि में मार्च 1971 की भांति प्रधानमंत्री के चयन में कोई समस्या नहीं थी।

राजीव गांधी—31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। यश की यात्रा को बीच में ही स्थगित करके राष्ट्रपति श्रीमो जैलसिंह स्वदेश लौटे। उसी दिन ज्ञान को राष्ट्रपति श्रीमो जैलसिंह ने राजीव गांधी का प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। पहले की तरह कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया। कांग्रेस (इ) समर्थित कार्यपालिका ने राजीव गांधी को अपना नेता चुना और वे प्रधानमंत्री बन दिए गए। 1 नवम्बर, 1984 का कांग्रेस (इ) कार्यपालिका को एक आपात बैठक में राजीव गांधी को भारतीय दल का नेता घोषित करने सम्मेलन भारतीय संसदीय बोर्ड के निर्णय के आधार पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में नियुक्त करने के निर्णय की दिशा में लोगों ने बड़ी आलोचना की। अनेक सर्वप्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के निर्णय को 'संविधान सम्मत' बताया। निःसन्देह, तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना सही था, क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण भारतीय दल में भारी समर्थन प्राप्त था।

विश्वनाथ प्रतापसिंह—सन् 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय मोर्चे के नेता के निर्वाचन के पहले जनता दल में नरसिंह का प्रवेश जटिल बन गया। जनता दल में विश्वनाथ प्रतापसिंह, चन्द्रशेखर और चौधरी देवीलाल नेता पद के दावेदार थे। विश्वनाथ प्रतापसिंह और चन्द्रशेखर के बीच चौधरी देवीलाल के नाम पर सहपति हुई। जनता समर्थित दल को बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री और सामान्य चौधरी देवीलाल को सर्वप्रधानमंत्री से नेता निर्वाचित किया गया। यह निर्वाचित नेता चौधरी देवीलाल ने विश्वनाथ प्रतापसिंह का नाम नेता पद के लिए प्रस्तावित किया, जिसका सर्वप्रधानमंत्री ने अनुमोदन किया गया। इससे चौधरी देवीलाल की 'किंग मेकर' की भूमिका उभर कर सामने आई। चौधरी देवीलाल के निर्णय से जनता दल के वरिष्ठ नेता चन्द्रशेखर हतप्रभ हुए। राष्ट्रीय मोर्चे ने भी विश्वनाथ प्रतापसिंह को अपना नेता निर्वाचित कर लिया। विश्वनाथ प्रतापसिंह के चयन में उनकी स्वच्छ एवं अखिल भारतीय छवि, राष्ट्रीय मोर्चे के घटक दलों को स्वीकार्य व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी तथा कामगार दलों जैसे समर्थक दलों की सहानुभूति तथा समर्थन की मुख्य भूमिका रही। राष्ट्रपति आर वैकटरमण ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया।

चन्द्रशेखर—नवम्बर, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के पतन के बाद जनता दल का विभाजन हुआ। चन्द्रशेखर व चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जनता दल (समाजवादी) की स्थापना हुई। चन्द्रशेखर को सर्वप्रधानमंत्री से जनता दल (समाजवादी) का नेता निर्वाचित करने तथा कांग्रेस (इ) द्वारा उन्हें समर्थन देने की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति आर वैकटरमण ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया।

पी वी नरसिम्हा राव—मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पी वी. नरसिम्हा राव को कांग्रेस (इ) का कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जून में लोकसभा के चुनाव के द्वितीय चरण में कांग्रेस (इ) सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। कांग्रेस (इ) समर्थित दल के नेता पद के लिए तीन मुख्य दावेदार उभर कर सामने आए—कार्यवाहक अध्यक्ष पी वी नरसिम्हा राव मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी का राज की तरफ झुकना, कांग्रेस (इ) में दक्षिण भारत के सांसदों की अधिक संख्या, शरद पवार की गैर कांग्रेसी पृष्ठभूमि, अर्जुनसिंह द्वारा उम्मीदवादी को धापस लेने नरसिम्हा राव के दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव और गुटवादिता से दूर रहने की मनोवृत्ति तथा उनकी विवाद रहित छवि से राज कांग्रेस (इ) समर्थित दल के नेता के रूप में निर्वाचित हुए। देश में पहला अवसर था जबकि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी मंसूर का सदस्य नहीं था। तत्कालीन राष्ट्रपति आर वैकटरमण ने पी वी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस (इ) का भविष्य उज्ज्वल सातारूढ़ हुआ।

अटल बिहारी वाजपेयी—सन् 1996 के लोकसभा के चुनाव के पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया। लोकसभा चुनाव में यह पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने उन्हें लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन उनकी सरकार लोकसभा में विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीत सकी।

एच डी देवेगौड़ा—13 दलीय समुक्त मोर्चे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी देवेगौड़ा को अपना नेता निर्वाचित किया। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने देवेगौड़ा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। देवेगौड़ा 16 96 को प्रधानमंत्री बने तथा 16 4 97 को कांग्रेस के समर्थन वापस लेने पर लोकसभा में विश्वास मत हासिल से उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

इन्द्रकुमार गुजराल—कॉंग्रेस ने अपना निराशा देवगौड़ा को बनाया। उनके हटने पर उन्होंने नई सरकार को पुनः समर्पण दे दिया जिससे 21.4.97 को गुजराल नये प्रधानमंत्री बने, परन्तु उनका कार्यकाल 19.3.98 को समाप्त हो गया। जैन आयोग के विवरण को लेकर कॉंग्रेस ने माँग की कि डी. एम. के मंत्रियों को मन्त्रिमण्डल से निकाल दिया जाय। इसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए कॉंग्रेस ने अपना समर्थन पुनः वापस ले लिया तथा गुजराल सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। पुनः चुनाव 1998 में कराये गये।

अटलबिहारी वाजपेयी—19.3.98 को दूसरी बार एक 19 दलीय मिनी-जुली सरकार के प्रधानमंत्री बनाये गये। भाजपा सरकार के एक घटक अन्नामुक को नेता जयललिता के द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद राष्ट्रपति ने सरकार से विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया। सदन में सरकार अपने घटक नेशनल कॉंग्रेस के सातद सैन्ट्रीन सोन के एक मत से पराजित हो गई। परिणामस्वरूप सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा।

अटलबिहारी वाजपेयी—13 अक्टूबर, 1999 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

डॉ. मनमोहन सिंह—14वीं लोकसभा के चुनावों में सफुल प्रगतिशील गठबन्धन को जीत हुई और 22 मई, 2004 को कॉंग्रेस के डॉ. मनमोहनसिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्—प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करता है और मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है। संवैधानिक रूप में इस क्षेत्र में जितनी स्वतन्त्रता प्राप्त है, उतनी व्यवहारिक रूप में नहीं। मंत्रियों की नियुक्ति करते समय दलीय आवश्यकताओं, विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय सन्तुलन आदि का ध्यान रखना पड़ता है। संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है जिससे अपने सदस्यों के चयन में प्रधानमंत्री की छूट मर्यादित हो।

प्रधानमंत्री को मन्त्रिपरिषद् में मनचाहे परिवर्तन करने तथा किसी मंत्री को अग्रदत्त करने का अधिकार प्राप्त है जो वह राष्ट्रपति को सिफारिश करके करता है। उनकी सिफारिश को दुर्कृपा नहीं जा सकता है। यदि कोई प्रधानमंत्री की इच्छा के प्रतिकूल चले तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र की माँग कर सकता है, उसे बर्खास्त कर सकता है अथवा अपना त्यागपत्र देकर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को भग कर सकता है। वह बहुमत दल का नेता होता है, अतः राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त करता है। यदि उसकी दलीय स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो उसका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। प्रधानमंत्री प्रायः विशेष स्थिति में ही किसी मंत्री को अग्रदत्त करने की सिफारिश करता है। मन्त्रिपरिषद् में कोई अन्वयन-दोषक का पद बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री को स्वतन्त्र अपने विवेक के प्रयोग में बाधा पहुँचती है। ऐसी स्थिति प्रथम प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के बीच तथा जनता हारमन काल में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और उप-प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह एवं प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर एवं उप-प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बीच बनी रही।

प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का स्थान ब्रिटिश परम्परा के अनुरूप सुदृढ़ रहा जिस में कहा गया है कि कैबिनेट का हर मंत्री प्रधानमंत्री का सहायक होता है। प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च सत्ता—संसद के प्रति सीधे रूप से उत्तरदायी है। एकदलीय प्रधानमंत्री का अपनी मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों पर प्रभावशाली नियन्त्रण और वर्चस्व होता है, लेकिन अल्पमतीय और सविद सरकारों का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्रियों की स्थिति इस सम्बन्ध में सुदृढ़ नहीं होती, क्योंकि उसे अपने समर्थक और घटक दलों की इच्छाओं के अनुरूप मन्त्रिमण्डल का निर्माण करना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण करते समय उसके सम्मुख राजनीतिक बाध्यातर् आती है।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सम्बन्धः आचरणगत अख्ययन—राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत की संसदीय व्यवस्था के मुख्य आधार हैं। भारत में डॉ. राजेन्द्रप्रसाद से अन्तुल कसाम तक राष्ट्रपतियों की एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू से डॉ. मनमोहन सिंह तक प्रधानमंत्रियों की एक परम्परा रही है। स्वतन्त्रता से लेकर अब तक राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के आचरणगत पक्ष के परिदृश्य में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते जा सकते हैं—

(1) राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बीच अनेक अवसरों पर तनाव के बिन्दु उत्पन्न कर सामने आये हैं, लेकिन ये 'खुले सपथ' का रूप धारण नहीं कर सके। पंडित नेहरू के कार्यकाल में 'हिन्दू कोड बिल' को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद के बीच व्याप्त मतभेद की के वृष्णेन्स को केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् से हटाने के प्रश्न को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बीच मतभेद सन् 1966 में गाँवत दिवस पर राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्र को दिये गये अपने सम्बोधन में की गई टिप्पणियों से प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की कथित नाराजगी, 1974 में रेल इद्दालत के प्रकरण को लेकर बी. बी. गिरी और श्रीमती इन्दिरा गाँधी के बीच मतभेद आरावकल में सरकार की कारगुजारी के प्रति राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद की नाराजगी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार द्वारा नौ राज्यों की बंदिरी सरकार को बर्खास्त करने सम्बन्धी उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने में तन्मूर्तन राष्ट्रपति

की ही ज़मीन को आना-काजी और वित्तमय से किए गए इस्ताखर का प्रकरण, मोरारजी देसाई और नीलम संजोय रेड्डी के बीच कथित कटु सम्बन्ध और देसाई सरकार के पतन तथा चरणसिंह के नेतृत्व में जनता (एन) की सरकार को प्रतिष्ठित करने में श्री रेड्डी की भूमिका ज्ञानी जैलसिंह और राजीव गांधी के बीच कटु सम्बन्ध चर्चाओं तथा धर्म की राजनीति से अलग करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति डॉ. शंकरदत्त शर्मा और जयसिंहाबाब के नेतृत्व वाली सरकार के दृष्टिकोण में कथित अंतर के संदर्भ में इस तथ्य को देखा जा सकता है, लेकिन कानूनन में सभी प्रकरण शान्त हो गये। प्रधानमंत्रियों ने भी राष्ट्रपतियों की भावनाओं को समझकर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए निर्णय लिये हैं। दोनों ने लचीले दृष्टिकोण का परिचय दिया है। इससे देश का लोकतान्त्रिक ढाँचा अभ्युन्नत बना रहा है।

(2) प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सम्बन्धों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपतियों ने स्वयं को औपचारिक सार्वधानिक अध्यक्ष की भूमिका के रूप में सीमित कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका शक्तिशाली हो गई।

(3) राष्ट्रपतियों की सार्वधानिक अध्यक्ष की भूमिका तक ही स्वयं को सीमित कर लेने के कारण 'प्रधानमंत्री' पद का राष्ट्रपतीयकरण हो गया।

(4) भारतीय संसदीय व्यवस्था को 'प्रधानमन्त्री व्यवस्था' (Prime Ministerial Form of Government) के रूप में उन्मुख करने की दिशा में राष्ट्रपतियों की सीमित भूमिका उत्तरदायी रही है। फलस्वरूप प्रधानमंत्री के आगे भारी सत्कार गौण हो गई तथा प्रधानमंत्री पद की स्थिति शक्तिशाली बन गई।

प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि के कारण—विगत वर्षों में प्रधानमंत्री की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री की स्थिति उनके अन्य कैबिनेट सहयोगियों की अपेक्षा उनके पद में निहित सार्वधानिक एवं परम्परागत विशेषाधिकारों के कारण सर्वोच्च है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—(1) अपने सहयोगियों की नियुक्ति-बर्खास्तगी के अधिकारों द्वारा वह उन्हें नियमित कर सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुशासन में बाँधे रख सकता है। (2) राष्ट्रपति के सतत और प्रत्यक्ष सम्बन्धों के कारण वह कैबिनेट और राष्ट्रपति के मध्य सम्पर्क की एकमात्र सर्वोच्च कड़ी के रूप में सम्पूर्ण कैबिनेट का प्रतिनिधि एवं प्रवक्ता होता है। (3) अपने पद त्याग की धमकी द्वारा सम्पूर्ण कैबिनेट के राजनीतिक जीवन को समन्वित करने की क्षमता रखने के कारण वह अपने विरोधी-सहयोगियों की आलोचनाओं को अवहट्ट कर सकता है। (4) वह दल का नेतृत्व करता है। वह शक्ति उसके अन्य सहयोगियों को प्राप्त नहीं है। (5) संसद के विघटन की अपनी शक्ति द्वारा वह अन्य मंत्रियों को कैबिनेट से ही नहीं, बल्कि संसद सदनका से भी बर्चित कर मुक्त निर्वाचन के बख़्तर, यद्यपि कठिनाईपूर्ण स्थिति में भेज सकता है। (6) आधुनिक युग में समाजवादी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, युद्ध के उत्पन्न समस्याओं, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन, प्रशासन की जटिलताओं एवं प्रधानमंत्री के विशेष उत्तरदायित्वों ने इसकी शक्ति एवं भूमिका को अन्य सहयोगियों की अपेक्षा व्यापक एवं अत्यन्त प्रभावपूर्ण बना दिया है।

(ए) शक्ति के विस्तारक तत्व—शक्तिशाली प्रधानमंत्री की भूमिका के परिपालन के लिए प्रधानमंत्री का प्रभावपूर्ण घनत्वपूर्ण व्यक्तित्व, नियन्त्रणकारी स्वभाव एवं कार्यशीली, परिस्थितियों और उचित अवसर पर उचित निर्णय लेने की क्षमता, व्यावहारिक मुद्दे-बुद्दे, राजनीतिक व्यूह-कौशल-चातुर्य तथा अपने सहयोगियों में सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करने की क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनके अभाव में उसकी भूमिका सामान्य रूप से अक्षयजलस्थ 'समकक्षों में प्रथम' मात्र ही होगी। वह अपने सहयोगियों की इच्छाओं, दबावों, प्रभाव एवं नियन्त्रण के अधीन होकर कार्य करेगा। इन सब गुणों और क्षमताओं से सम्पन्न प्रधानमंत्री भी राजनीतिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता, अपने अस्तित्व की असुरक्षा, विभिन्न कठिनाइयों और समस्याओं के दबाव के फलस्वरूप कुछ समय के लिए अक्षयजलस्थ भूमिका सम्पन्न करने को बाध्य हो सकता है।

विशेष राजनीतिक घटनाएँ, युद्ध सन्धि इत्यादि प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रभाव और सत्ता को घटाने-बढ़ाने में सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ 1962 के भारत-चीन युद्ध की असफलता ने नेहरू की प्रतिष्ठित को अपात पहुँचाकर उनके साथियों तथा देशवासियों की प्रत्यक्ष आलोचनाओं को मुखरित कर दिया था। 1965 के भारत-पाक युद्ध एवं 1971 के भारत-पाक बांग्लादेश युद्ध के कुशल नेतृत्व एवं सफल संचालन के कारण कमराज लालनहासुर शास्त्री और इन्दिरा गांधी की शक्ति, प्रभाव एवं प्रतिष्ठित में अभूतपूर्व अभिवृद्धि हुई थी।

(ग) लोकसभा का नेतृत्व—प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होने के कारण संसद का नेतृत्व और मन्त्रिमण्डल की नीति निर्धारण करता है। विधेयक किस प्रकार के हों तथा कब सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाएँ यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वह सदन में शासन का प्रमुख वक्ता होता है तथा प्रतिपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देता है। राज्यसभा के 12 नामजद किये जाने वाले सदस्य उसकी इच्छानुसार मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का कार्यक्रम निश्चित करने उसे स्थिति अथवा रंग करने के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका होती है। इंग्लैण्ड में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है।

सकटवालीन पारित्यक्तियों में प्रधानमंत्री की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के सहायक अथवा अधिकारों का उपयोग व्यवहार में नहीं करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसे अंकुश लगा दिए गए हैं जिनसे सकटवालीन शक्तियों का उपयोग नहीं हो सके, पर यदि सकटवालीन की घोषणा हो जाए तो संविधान प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग व्यवहार में प्रधानमंत्री करता आया है। लोकसभा की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को न्यून करने का दावा उसी का है। लोकसभा के सदन सत्रांत में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक होती है।

(घ) **प्रमुख प्रशासनिक एवं संरक्षण प्रदानकर्ता**—प्रधानमंत्री प्रमुख शासक है। देश में अधिकांश राज्य पदों पर नियुक्ति सप लाक सेवा आयोग करता है, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण पद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। इन पर नियुक्ति करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, राज्यपालों का मनोनायक, कम्प्लेक्स एण्ड ऑडिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, सच लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, आयोगों के अध्यक्ष, सार्वजनिक निर्माणों के प्रबन्धकों आदि पदों पर नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। प्रशासकीय पदों का सूजन एवं इन पर नियुक्ति का अधिकार भी उसे है। वह सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष एवं नौ सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करने में भी सम्मिलित है। भारत सरकार के अनेक अलकरण (भारतखल, पद्मविभूषण, पद्मभूषण एवं पद्मश्री) आदि देने का क्षेत्र में भी उसका प्रभुत्व स्पष्ट रूप में दिखायी पड़ता है।

(ङ) **प्रधानमंत्री, विदेश नीति तथा सुरक्षा नीति**—प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विदेश नीति निर्धारित की जाती है। यथा विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, शान्ति, ध्यानार्थक एवं सांस्कृतिक सम्पर्क करना आदि प्रधानमंत्री विदेश मन्त्रालय को चाहे अपने अधीन रख अथवा किसी दूसरे मंत्री को सौंपे, लेकिन वह विदेश मन्त्रालय में लगभग सम्पूर्ण में रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में देश का वास्तविक प्रवक्ता बन जाता है। विदेश नीति के सभी महत्वपूर्ण मामलों का अन्तिम निर्णय वही करता है। प्रधानमंत्री प. नेहरू ने विदेश नीति के निर्माण में इतना योगदान दिया है कि भारतीय विदेश नीति का नेहरू की नीति कहा जाने लगा।

सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों पर प्रधानमंत्री का निर्णय होता है। रक्षा मंत्री का प्रधानमंत्री के निकट सम्पर्क और पूर्ण नियंत्रण में रहकर कार्य करता होता है। युद्ध में देश की इतर-जीव का श्रेय प्रधानमंत्री को मिलता है। जिस गृहशक्ति में क्या सहायता लेनी है? किस तरह के प्रति क्या नीति अपनानी है? किस प्रकार शान्ति-मार्गप्रति करने है? संयुक्त राष्ट्र सभ में क्या कूटनीतिक पंक्ति दिखाने है? सभी निर्णय अन्तिम रूप से प्रधानमंत्री के होते हैं। समस्त सैनिक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार किया जाता है। 1962 में चीन के साथ पराजय का कलंक नेहरू जी के ऊपर लगा था जबकि 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान को जिंककर देने का श्रेय क्रमशः शहरी जी एवं श्रीमती इन्दिरा गाँधी को मिला।

(च) **प्रधानमंत्री और अर्थनीति**—वित्तीय नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। वह कार्यक्रम निर्धारित करता है और क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होने के कारण वित्तीय विकास उसके मार्गदर्शन में होता है। देश की औद्योगिक नीति उसकी इच्छाओं का प्रतिबिम्ब है। जनहित की दृष्टि से वह शासन-प्रशासन का मार्ग-प्रदर्शन करता है। देश के अर्थतन्त्र की सञ्चालन-असञ्चालता का ठहराव-निर्णय प्रधानमंत्री पर होता है। वित्त मंत्री कोई राष्ट्रीय महत्व का फैसला स्वयं नहीं कर सकता। बजट निर्माण का कार्य तथा राज्यों की वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी अन्तिम निर्णयों के पीछे प्रधानमंत्री का परामर्श होता है। योजनाओं के सफल मन्त्रालय का भार उसे डढ़ाना पड़ता है।

(छ) **प्रधानमंत्री और विधि-निर्माण**—विधि-निर्माण समस्त का अधिकार और कृत्य है, लेकिन व्यवहार में इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की वय निर्णायक भूमिका होती है जब वह बहुमत का विश्वास अर्जित किए हुए हो। सामद में बहुमत दल के नेता होने के कारण कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर जाता है और बहुमत के बल पर वह समस्त से मन्त्रिपरिषद् बनाने बना सकता है, संविधान में संशोधन करवा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री यह सब करते समय जनता और विरोधी दलों के हक का ध्यान रखता है। अपना उद्देश्याधिक्य समझने वाला कोई प्रधानमंत्री निरंकुशता के मार्ग पर नहीं चलता। भारत में अब तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने लोकतांत्रिक आदर्शों और परम्पराओं के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

(ज) **राज्य सरकारें और प्रधानमंत्री**—केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के प्रमुख प्रेरण-प्रेरक, प्रवक्ता एवं सूत्रधारकर्ता प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री हैं, तथापि सैद्धान्तिक दृष्टि में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एवं उनके माध्यम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र और राज्यों के प्रमुख वास्तविक अधिकारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। उनके सौवैधानिक सम्बन्ध स्थायी होते हैं। व्यवहार में दोनों वास्तविक प्रमुख अधिकारियों के सम्बन्ध अन्त्यधिक प्रत्यक्ष हो गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर की जाती है। वास्तुतः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू

कानून में प्रधानमन्त्री की मुख्य भूमिका होती है। सार्वजनिक दृष्टि से प्रधानमन्त्री को न तो मुख्यमन्त्रियों की नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है और न ही मुख्यमन्त्रियों का प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में कोई भूमिका निभाने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु व्यावहारिक राजनीति में दोनों परस्पर नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने होते हैं।

राज्यपाल की अनेक व्यवस्थाएँ राज्य व्यवस्थापन के क्षेत्र में प्रधानमन्त्री की प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप का अधिकार देती हैं। उदाहरणार्थ समस्त मन्त्री पर केन्द्रीय और प्रांतीय कानून में मतभेद पैदा होने पर केन्द्रीय कानून को मान्यता प्राप्त होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्रीय हित में लोकसभा के सत्र के अन्त्य होने पर राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के परिणामों बहुमत से किसी विषय को राज्य-सूची से केन्द्र सूची में एक वर्ष के लिए ले आती है और आवश्यकतापूर्वक इस अधिकार को बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार संकटकाल में केन्द्रीय सत्तर राष्ट्रीय राज्य के समर्थन में बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संकटकाल में केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत राज्यों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुझाव कर सकता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य पार्षदों की समिति का केन्द्र को राज्य-सूची पर कानून बनाने का अधिकार स्वयं दे सकते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के प्रमुख प्रधानमन्त्री की राज्य व्यवस्थापन के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने तथा राष्ट्रीय नीतियों सिद्धान्तों एवं कानूनों की व्याख्या के लिए निर्देश प्रदान करने के अनेक साधन प्राप्त अधिकार प्राप्त हैं।

(इ) प्रधानमन्त्री और दल—प्रधानमन्त्री पद प्राप्त करने में उसका दल सहयोग प्रदान करता है, किन्तु सार्वजनिकता यह है कि वह अपने दल का घोषित अपना गठित नेता होता है। सामान्य निर्वाचन प्रधानमन्त्री का निर्वाचन है। प्रत्याशियों के पक्ष में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दल के सदस्य प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं।

दल की शक्ति, भूमिका एवं प्रधानमन्त्री से उसके सम्बन्धों को सर्वप्रथम के अन्तर्गत बारी पर सुपरिभाषित करिए एवं सुनिश्चित नहीं किया गया है। इन्हें सार्वजनिक चरित्र के रूप में परम्पराओं, परिस्थितियों और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित एवं परिभाषित किया जाता रहा है। बड़ी से विवाद सरकार और दल के दोनों प्रमुखों प्रधानमन्त्री बनाम दल के अध्यक्ष के मध्य और कभी सत्तीय बनाम संगठनात्मक पक्ष के मध्य चर्चित रहे हैं। पक्ष नेहरू के समय शक्ति दल से सरकार के हाथों में हस्तान्तरित की गई, किन्तु उनकी पुनः के बाद स्थिति बदल गई है। अब तक व्यावहारिक रूप से दलीय अध्यक्ष का पद प्रधानमन्त्री करता था, परन्तु अब प्रधानमन्त्री के पद में दल के अध्यक्ष की आवश्यकता हुई है। 1971 के बाद से प्रधानमन्त्री के पद पर दलीय अध्यक्ष के पद की आकांक्षित वर दिया गया और 'औपचारिक शक्ति' नहीं छोड़े हुए भी प्रधानमन्त्री वास्तविक रूप से दल और सरकार का नेता बन गया। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमन्त्री और दल के अध्यक्षों के सम्बन्धों में स्पष्ट स्थिति नहीं रही, पर ऐसा लगा कि दल का अध्यक्ष अपनी सार्वजनिक शक्तियों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा। जनता सरकार अल्पकालिक रही और जनता, 1980 में श्रीमती गान्धी विधान बहुमत के साथ प्रधानमन्त्री बनी तथा दल अध्यक्ष का पद प्रधानमन्त्री के द्वारा उसी प्रकार आकांक्षित हो गया है जिस प्रकार 1971 के बाद हुआ था। 31 अक्टूबर, 1984 को उनकी हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री बने। वे तब से प्रधानमन्त्री और दल के अध्यक्ष दोनों ही पदों को धारण किए रहे और दल और सरकार पर उनका सर्वोपरि प्रभाव बना रहा। विश्वनाथ प्रतापसिंह के समय राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष एन. टी. रामाराव थे। प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के अध्यक्ष थे जबकि अन्तर्द्विहारी चान्सेली के प्रधानमन्त्रित्व काल में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुशाभाऊ ठाकरे, बंगाल सरकार जनार्दन और नाथू के पास रहा है।

(ज) प्रधानमन्त्री और जनमत—डॉ. विमला शुक्ला के अनुसार, "प्रधानमन्त्री और जनता दोनों परस्पर अन्तर्सम्बन्धित और अनोखे-अपेक्षित हैं। प्रधानमन्त्री की भूमिका उनके कार्यों एवं नीति का प्रभाव जनता पर पड़ता है और जनमत के समर्थन एवं विरोध का प्रभाव प्रधानमन्त्री पर पड़ता है। प्रधानमन्त्री सत्तारूढ़ दल का ही नहीं, सम्पूर्ण दल का नेता होता है। अतः जनमत के विश्वास, बहुमत एवं लोकप्रियता को अपने पक्ष में कर, वह शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीय भूमिका सम्पादित कर सकता है।" जिस दल को ऐसे व्यक्तित्व एवं नेतृत्व वाला व्यक्ति मिल जाता है, जिसे जनता की प्रशंसा एवं विश्वास प्राप्त हो, उसे लम्बे समय तक सत्ता में बने रहने का स्वाम्य तथा कामाकाश बनने तक की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसी शक्ति जनता अपने निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, सम्प्रदायों, प्रभावक और हिताश्रित गुटों, अल्पसंख्यकों, आन्दोलनों, प्रदर्शनों एवं हड़तालों इत्यादि के द्वारा अपनी भाँगी, शिकायतों, इच्छाओं एवं असन्तोष को सरकार तक पहुँचा सकती है। अन्तिम रूप से जनता मतपत्रों द्वारा प्रधानमन्त्रियों की नीतियों को समर्थित या असमर्थित कर, सत्तारूढ़ या

अपदस्थ करने का अपना निर्णय देती है अतः प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह ऐसे कार्य सम्पादित करे जिससे जनमत उसके विरुद्ध समर्थित न हो, अपितु उसकी कार्य शैली से प्रभावित हो सके।

(ड) प्रधानमंत्री और राजनीतिक स्थिति—भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति उसकी राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करती है। 1989 के लोकसभा के निर्वाचन के उपरान्त किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत न आने से प्रधानमंत्री के प्रभाव में कुछ कमी आयी है। 1989 में गठित जन मोर्चा सरकार का नेतृत्व वी. पी. सिंह कर रहे थे। यह सरकार बाहर से समर्थन पर आश्रित थी तथा कई दलों की सरकार होने से आन्तरिक दबावों से प्रसिद्ध थी। प्रधानमंत्री का प्रतिकार और शक्ति सदन में उसके दल के बहुमत पर निर्भर करता है। बहुमत का अभाव सरकार के जीवन को कम कर देता है। 1991 में कॉंग्रेस की अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हाएव अपने कार्यकाल में सरकार को बचाये रखने के लिए जोड़घोड़ का सहारा लेते रहे, परिणामस्वरूप सांसदों के खरीद से सम्बन्धित प्रकरणों में न्यायलय में डमरू गए।

1996 में अटलबिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वे लोकसभा में विश्वासमन नहीं जीत सके परिणामस्वरूप दोरह दिन में ही सरकार से बाहर होना पड़ा। इस सरकार के बिकल्प के रूप में समुक्त मोर्चा के एच. डी. देवेगौड़ा 31 मई, 1996 को प्रधानमंत्री बनाए गए। यह सरकार कॉंग्रेस के बाह्य समर्थन पर टिकी हुई थी, देवेगौड़ा राष्ट्रीय नेताओं में से नहीं थे जिससे तालुमसाद यादव, राउद यादव आदि नेता उनमें विशेष रखते थे जिसके कारण जनता दल अन्तर्ग्रह से लगातार जुझता रहा। परिणामतः कॉंग्रेस ने मोर्चे पर दबाव बनाकर एच. डी. देवेगौड़ा को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर दिया। कॉंग्रेस के सरकार बनाने में असफल हो जाने के बाद समुक्त मोर्चा ने इन्द्रकुमार गुजराल को अपना नेता चुना। मोर्चे के नेताओं के निजी अहम् और विवादों के कारण समुक्ती के रूप में गुजराल को यह पद प्राप्त हो गया। 21 अप्रैल, 1997 को गुजराल को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह सरकार अल्पजीवी रही। जैन आयोग की रिपोर्ट के नाम पर कॉंग्रेस ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस रिपोर्ट में राजीव गांधी की हत्या में डी. एम. के की भूमिका पर सन्देह किया गया था। अतः गुजराल ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। किसी अन्य दल द्वारा सरकार बनाने की पेशकश न किये जाने पर राष्ट्रपति महोदय ने 17 मई 19 दिन में लोकसभा को भंग कर दिया।

12वीं लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, उसके नेतृत्व में दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने सविद सरकार को मजबूरियों को समझते हुए अपने गठबन्धन में सम्मिलित सभी दलों को सरकार में सम्मिलित करने तथा अन्य सभी प्रकार से समुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन अन्तर्ग्रह की नेता जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय ने सरकार से सदन में विश्वास मत बनाने का आदेश दिया, परिणामस्वरूप सरकार सदन में एक मत से पराजित हो गई। अन्य किसी भी दल द्वारा बिकल्प के रूप में सरकार नहीं बताई जा सकी। तत्पश्चात् लोकसभा को भंग कर दिया गया।

13वीं लोकसभा के चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के पश्चात् मोर्चे के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार 13 अक्टूबर, 1999 को देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार सभाला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन में भाजपा को छोड़कर 17 अन्य दलों तथा क्रॉसने मेनका गांधी को निर्दलीय डम्पीदवार के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिला है। इसा सरकार का भविष्य भाजपा की मौलिक नीतियों की विस्तारजलि तथा क्षेत्रीय दल की आकर्षणों और उनकी राजनीतिक मजबूरियों में समन्वय और प्रबन्ध पर निर्भर रही है। अतः 1989 से 1999 के दशक में प्रधानमंत्री की राजनीतिक स्थिति कमजोर रही है। इसका प्रमुख कारण किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न होना तथा अल्पमत या सविद सरकारों का गठन है परिणामस्वरूप सरकारों का भविष्य क्षेत्रीय दलों के हाथ में सिमट गया है तथा प्रधानमंत्री की स्थिति राजनीतिक मजबूरों बनकर रह गयी है।

भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान अथवा शासनाध्यक्ष लोकसभा में अपने दल का नेता राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रवक्ता आदि सभी पद एक साथ समुक्त रूप से अपने व्यक्तित्व में समन्वित करता है। सप सरकार एवं इकई राज्यों की सरकारों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता उसी का उत्तरदायित्व है। इन सभी पदों का एक व्यक्ति में समाहित हो जाने के कारण प्रधानमंत्री का पद शक्ति, प्रतिष्ठा, गौरव एवं गरिमा का पद होता है।

प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति

(Actual Position of the Prime Minister)

भारत का प्रधानमंत्री किसी भी शक्तिशाली व्यक्तित्व का हो, संवैधानिक व्यवस्थाएँ और अधिसमय प्रधानमंत्री पद को जो शक्ति प्रदान करते हैं, उससे प्रधानमंत्री निरकुश नहीं बन सकता है। देश में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अप्रतिष्ठित अकुश बने रहते हैं—

1. लोकसभा का निष्पन्न—कोई भी प्रधानमंत्री लोकसभा को डुकरा नहीं सकता। प. नेहरू जनमत के समर्थन पर निर्विवाद नेता बने रहे।
2. लोकसभा में बहुमत का प्रतिबन्ध—प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत के बल पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाता है। निरंकुश आचरण करने पर प्रधानमंत्री बहुमत का विश्वास खो सकता है और अपनी स्थिति को खतरे में डाल सकता है।
3. सारी शक्तियों का अंकुर—प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाले साधियों की हवा के रिक्त कार्य करने से बचता है ताकि उसकी स्थिति में दुर्बलता उत्पन्न न हो।
4. दलीय प्रतिबन्ध—अपने दल के बारे में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठता है, अतः उसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने सारोपी दल का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
5. राज्यों में विरोधी दलों की साकारता—राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें प्रधानमंत्री की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुर लगा सकती हैं। यदि केन्द्र और सभी राज्यों में एक दल सत्तारूढ़ हो तो भी राज्य सरकारों की हवा का सम्मान प्रधानमंत्री को करना पड़ता है।
6. मुख्यमंत्रियों का दबाव—प्रधानमंत्री को अपनी नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों की साथ लेकर चलना पड़ता है। उनके युक्तिसंगत दबाव को वह सहन करता है। उदात्तशैल्य के प्रति राजग मुख्मन्त्री अपने सत्परापूर् से प्रधानमन्त्री को निरकुशता की ओर नहीं जाने देते।
7. राष्ट्रपति का परामर्श—यद्यपि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की मन्त्रणानुसार अपनी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करता है लेकिन वह अपने सत्परापूर् अपनी सामयिक चेतावनी आदि के माध्यम से प्रधानमन्त्री के ऐसे कदमों पर प्रभाव डाल सकता है जो निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हों। प्रधानमन्त्री को एक पैडीपूर्ण राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है।
8. विरोधी दल—विरोधी दलों की रचनात्मक आलोचना प्रधानमंत्री को निरंकुशता की ओर जान से रोकती है।
9. बहुदलीय व्यवस्था—यदि केन्द्र में एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या जो बहुमत मिले वह बहुमत कम सदस्यों का हो तो यह स्थिति प्रधानमंत्री को नियन्त्रित रखती है।
10. न्यायपालिका—सविधान-विरोधी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका को होती है वह प्रधानमंत्री को बड़ी सीमा तक नियन्त्रित रखती है।
11. निम्न निर्वाचन आयोग—सविधान में एक निम्न निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है जो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूपों में चुनाव सम्बन्धी मामलों में प्रधानमंत्री की निरंकुशता पर प्रतिबन्ध लगाती है अतः प्रधानमंत्री 'तानाशाह नहीं बन सकता। वह सार्वजनिक सीमाओं के भीतर रह कर अपनी शक्तियों का कुशलपूर्वक प्रयोग करता है।

अतः भारत की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की बहु-आयामी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। 'उत्ते राह या नेता या नायक' माना जा सकता है। प्रधानमंत्री की शक्तिशाली भूमिका उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है अतः उसके व्यक्तित्व में धैर्य, साहस, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, अच्छी वक्तव्य कला, मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों से काम लेने एवं उन्हें नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, नीतिरक्षा पर नियन्त्रण करने की योग्यता, आकर्षक व्यक्तित्व तथा संसद एवं संसद के बाहर विपक्षी दलों से निपटने की क्षमता का होना परम आवश्यक है।

मन्त्रिपरिषद्

(The Council of Ministers)

भारतीय मन्त्रिमण्डल शासन पद्धति (The Indian Cabinet System)

1. राष्ट्रपति, राज्य का संवैधानिक प्रधान है जो मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर शासन करता है अर्थात् वह वास्तविक कार्यपालिका है। सविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 उल्लेखी शासन के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। मन्त्रिमण्डलीय शासन-पद्धति के त्रिपक्षधन में रुढ़ियों और परम्पराओं के लिए स्थान है।
2. मन्त्री आवश्यक रूप से संसद के सदस्य होते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति के मन्त्री बनने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जो संसद का सदस्य न हो, तथापि सविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मन्त्री जो निरन्तर छ मास तक संसद के किसी सदन का सदस्य न रहे, वह उस अवधि की समाप्ति पर मन्त्री पद पर नहीं रह सकता।
3. प्रधानमंत्री की स्थिति अन्य सभी मन्त्रियों से शीर्षस्थ और अधिकारपूर्ण होती है। उसकी स्थिति 'समकक्षों में प्रथम' (First Among Equals) यानी जाती है लेकिन व्यवस्था में डाकू की स्थिति सर्वोच्च होती है। उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रियों में विभागों का वितरण किया जाता है, प्रधानमंत्री ही मन्त्रियों का नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है तथा उनमें समन्वय स्थापित करता है। वह अपने

मंत्रियों से त्यागपत्र माँग सकता है और इनकार करने पर वह राष्ट्रपति से उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। वह संसद में और संसद के बाहर अपने मंत्रियों का बचाव करके उनमें आत्म-विश्वास की भावना का विकास करता है। उसका त्यागपत्र समस्त मन्त्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है।

4. मन्त्रिमण्डलीय शासन-पद्धति का सार मन्त्री का उत्तरदायित्व है। इसके दो अर्थ हैं—पैरिक्वेट स्तर का मंत्री, प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है और विभाग के क्रियाकलापों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

5. सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को प्रभावशाली रूप से प्रवर्तित करने के लिए भारतीय मन्त्रिमण्डल में गोपनीयता के सिद्धान्त को पूर्ण मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 74(4) में उल्लेख है कि 'हिमी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उससे पद तथा गोपनीयता की शपथ करवाएगा।' मनप्रेम की अवस्था में किसी मन्त्री द्वारा त्याग-पत्र देने पर स्पष्टीकरण के लिए सदन में कोई अतिवृत्त वक्तव्य स्पीकर की सहमति से दिया जा सकता है। भारतीय संसद को कार्य-प्रणाली के नियमों में ब्रिटिश अभिसमयों (रूटिन्स) का सरल प्रयोग हो रहा है।

6. राष्ट्रपति भौषाणिक प्रधान के रूप में दलीय राजनीति से ऊपर है, वह देश की व्यावहारिक राजनीति से दूर रहता है, वह मन्त्रिमण्डलीय बैठकों में भाग नहीं लेता, यहाँ तक की उन बैठकों में भी उपस्थित नहीं होता जिनमें मन्त्री यह निर्णय करते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति को क्या सलाह देनी है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल के निर्णयों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सूचना देता है।

6. मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यह संसद के 'विश्वासपर्यन्त' अथवा संसद के विद्रवाम तक अपने पद पर बनी रहती है। यदि लोकसभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।

8. मन्त्रिपरिषद् पर संसदीय नियन्त्रण की व्यवस्था है। संसद प्रत्येक काम उसके प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव और कटीती प्रस्ताव के माध्यम से मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण रखती है। विविध संसदीय समितियों मन्त्रिपरिषद् की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखती हैं। यह संसदीय नियन्त्रण मन्त्रिपरिषद् को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

मन्त्रिपरिषद् का निर्माण (Formation of the Council of Ministers)—संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद् होगी। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उसके परामर्श से होगी जो राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यन्त' अपने पदों पर बने रहेंगे। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ अनिश्चित नहीं हैं। यह लोकसभा में बहुमत दल के नेता की अनिवार्य प्रधानमन्त्री के रूप में नियुक्ति करता है, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में यह स्वविवेक के आधार पर ही निर्णय ले सकता है—

(क) जब लोकसभा में किसी दल या गठबन्धन की स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, (ख) जब लोकसभा में सबसे बड़ा दल राष्ट्रपति के सम्मुख सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करे, (ग) जब दो या दो से अधिक, या अनेक दलों का गठबन्धन मिलकर राष्ट्रपति के सम्मुख सरकार बनाने का दावा करे, (घ) जब दलीय विरोध के बावजूद, कुछ दलों का दावा हो कि कोई दल या एक या कुछ दल, गठबन्धन सरकार में शामिल हुए बिना बाहर रहकर उसे सरकार निर्माण करने में सहायता करे, (ङ) यदि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल में नेतृत्व के प्रश्न पर कुछ दल जाये तो दो प्रतिद्वन्द्वी नेता दल में अपने बहुमत का दावा राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करें, (च) यदि कोई प्रधानमन्त्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पारित हो जाये और वैकल्पिक सरकार के गठन के सम्बन्ध में बहिर्गति उपस्थित हो।

उपरोक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमन्त्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ऐसी स्थिति में वह लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर सकता है। वह अल्पसंख्यक दल के नेता को प्रधानमन्त्री के रूप में नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है। वह ऐसे प्रधानमन्त्री को एक निश्चित अवधि में लोकसभा का 'विश्वासपत्र' प्राप्त करने का 'निर्देश' दे सकता है।

मन्त्रिपरिषद् का गठन करना प्रधानमन्त्री का अपना विशेषाधिकार माना जाता है। वह अपनी पद्धति के लोगों को मन्त्रिपरिषद् में शामिल कर सकता है। इसके बावजूद वह मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करने में पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होता है। उस पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया होती है—

(क) प्रधानमन्त्री को अपने दल के प्रभावशाली सहयोगियों को मन्त्रिपरिषद् में स्थान देना पड़ता है, वह इनके उद्देश्य नहीं कर सकता, (ख) उसे मन्त्रिपरिषद् का गठन करते समय देश के सभी भागों के दलित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना पड़ता है, (ग) अगर वह संविद सरकार का नेतृत्व करने वाला हो तो अपने साझेदार पक्ष और पक्षों को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, (घ) वह अपनी मन्त्रिपरिषद् में देश के सभी स्मृदायी, वर्गों और हिन्दू-समुदायों को भी प्रतिनिधित्व देता है एवं (ङ) वह अपनी मन्त्रिपरिषद् में प्रशासनिक दृष्टि से कुशल और विशेषज्ञ लोगों को स्थान देता है।

मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रि मण्डल में अन्तर

(Difference between the Council of Ministers and the Cabinet)

अनेक बार मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रिमण्डल का समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया जाता है लेकिन मन्त्रि परिषद् और मन्त्रिमण्डल में अन्तर है। मन्त्रिपरिषद् में मन्त्रियों की सभी श्रेणियाँ आ जाती हैं जबकि मन्त्रिमण्डल में केवल मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री होते हैं। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् एक बृहत्तर संस्था होती है जबकि मन्त्रिमण्डल की संख्या उससे तुलना में सीमित होती है। मन्त्रिमण्डल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल होते हैं जो मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागीय मामलों का संचालन करते हैं। राज्यमंत्री, राज्यमंत्री और संसदीय सचिव, मन्त्रिमण्डल स्तर के मन्त्रियों की सहायता करते हैं। मन्त्रिमण्डल स्तर के सभी मन्त्रिपरिषद् की भूरी होती है।

मन्त्रिपरिषद् के कार्य और शक्तियाँ (Function and Powers of the Council of Ministers)—भारतीय संविधान में मन्त्रिपरिषद् का देश की कार्यपालिका शासन माना जाता है। भारत में मन्त्रिपरिषद् के कार्य ब्रिटिश मन्त्रिपरिषद् के समान निम्नलिखित हैं—

(1) मन्त्रिपरिषद् का प्रमुख कार्य देश के लिए नीति-निर्धारण करने का है। वह देश की गृह, वितीय, औद्योगिक, सैनिक, विदेश नीति आदि का निर्धारण करती है।

(2) व्यवहार में राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों और शक्तियों का उपयोग मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् वास्तविक शक्तियों का उपयोग करने वाली संस्था है।

(3) मन्त्रिपरिषद् द्वारा कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसके द्वारा सैनिक और असीमित दोनों शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तथा संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को लागू किया जाता है।

(4) मन्त्रिपरिषद् द्वारा देश के लिए जितने सम्बंधी कार्यों का सम्पादन किया जाता है। इसके द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। देश की औद्योगिक और व्यापारिक नीति का निर्धारण करता और उसको क्रियान्वित करने का दायित्व मन्त्रिपरिषद् का होता है।

(5) मन्त्रिपरिषद् द्वारा व्यवस्थापन सम्बंधी कार्यों का निर्वाह किया जाता है। यद्यपि कानून निर्माण करने का कार्य संसद का माना जाता है, लेकिन व्यवहार में मन्त्रिपरिषद् द्वारा कानून बनाये जाते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन प्रक्रिया में इस क्षेत्र में मन्त्रिपरिषद् की शक्तियों को अधिक विस्तृत कर दिया है।

(6) मन्त्रिपरिषद् संसद में प्रश्नोत्तर, सूचनात्मक सप्ताहिक वादविवाद में प्रभावशाली रूप से कार्य करता है। अविस्मर्य प्रस्ताव एवं वाग दोहे प्रस्ताव के समय इसकी निर्णायक भूमिका होती है।

मन्त्रिपरिषद् द्वारा अपने कार्यों का संचालन करने के लिए विविध प्रकार की समितियों का सहारा लिया जाता है। इन समितियों में 'राजनीतिक मामलों की समिति' (Political Affairs Committee) सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मन्त्रिमण्डलीय समितियों का दो भागों में विभाजित किया जाता है—स्थायी (स्टैंडिंग) तथा अस्थायी (एडहॉक)। स्थायी समितियों में प्रतिक्षेप, वितीय प्रशासनिक संगठन, संसदीय एवं विभिन्न विभागीय समितियों की गणना होती है। अस्थायी समितियों का निर्माण समानानुसार तब किया जाता है जब आवश्यक और उचित समझाएँ उपस्थित हो जाती है।

मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि के कारण (Reasons for the Growth of Powers of the Cabinet)—स्वातंत्र्य के पश्चात् भारत में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। आज स्थिति यह है कि संसद मन्त्रिमण्डल की विधिवित नही करती, अपितु मन्त्रिमण्डल संसद की नियंत्रित करता है। मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में होने वाली वृद्धि में निम्नलिखित कारणों का योगदान है—

(1) संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति तो औपचारिक-संवैधानिक अध्यक्ष मात्र है, मन्त्रिमण्डल वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है।

(2) दलीय अनुशासन के कारण मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में भारी वृद्धि हो गई है। संसद दलीय अनुशासन में बंध रहते हैं, अतः वे अपनी 'अन्तराल' को मारकर मन्त्रिमण्डल के निर्णयों का समर्थन करते हैं। दलीय सचेतन (डिपेंडेंसी) की अवहेलना करने को अनुशासनहीनता समझा जाता है। दल बदल विरोधी संविधान संशोधन 1985 के पारित होने के बाद दलीय अनुशासन का शिकंशा कड़ा हो गया है। अब दल से प्रसक्त होकर नया दल गठन करने के लिए एक-तिहाई सदस्यों का दल से विद्रोह करना आवश्यक है अन्यथा विद्रोह करने वाले सदस्यों को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है अतः अब दल से विद्रोह करना संभव नार्थ नहीं है।

(3) प्रधानमंत्रियों का 'ब्रिटिशवादी नेतृत्व' मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहा है। पं. जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गाँधी और राजीव गाँधी के प्रधानमन्त्रीत्व काल में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में असीम वृद्धि हुई है।

(4) भारतीय निर्वाचन को प्रभावित करने में प्रधानमन्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निर्वाचनों में दल को विजयी बनाने में प्रधानमन्त्री के व्यक्तित्व की अहम भूमिका रहती है। साथ ही समसदीय निर्वाचा में यह तथ्य होता है कि देश का अगला प्रधानमन्त्री कौन होगा? प्रधानमन्त्रियों की इस भूमिका के कारण मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि हुई है।

(5) मन्त्रिमण्डल के पास 'साध और अनुग्रह पहुँचाने' की व्यापक शक्तियाँ हैं, फलतः वह अपने समर्थकों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, स्थानान्तरणों, कोटा, नाइलैंड, परमिट और विविध प्रकार से साध पहुँचा सकता है। इससे मन्त्रिमण्डल की भूमिका शक्तिशाली हो गई है।

(6) प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ससद के निम्न सदन (लोकसभा) को भंग करा की शक्ति ने मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि की है। इस शक्ति के माध्यम से मन्त्रिमण्डल सासदों को इस दृष्टि से भयभीत रखता है कि अगर उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह करने का हस्ताक्षर किया तो वह लोकसभा को भंग करने का निर्णय लेकर उनके सासदों के रूप में अस्तित्व को संकट में डाल देगा। इससे सासद असामान्य परिस्थितियों में मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध निर्णय लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। जब भारत में मन्त्रिमण्डलों के विरुद्ध विद्रोह हुआ तो उसकी परिणति लोकसभा का विघटन और मध्यावधि चुनाव के रूप में हुई है।

(7) वर्तमान में निर्वाचन खोजें हो गये हैं, अतः समयवधि के पूर्व सासद निर्वाचन से बचने का प्रयास करते हैं अतः यह स्थिति मन्त्रिमण्डल की शक्तियों को बढ़ाने में सहायक बनी है।

(8) ससद के सत्र अन्त्यावधि के लिए होते हैं। इसमें उसे व्यापक कार्य निपटाने पड़ते हैं। ससद तो कपरेछा पर विचार करती है और वास्तविक कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा सम्पन्न दिये जाते हैं।

(9) प्रदत्त व्यवस्थापन प्रक्रिया ने मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में उतरोत्तर वृद्धि की है और व्यवस्थापन की निर्णायक शक्ति मन्त्रिमण्डल के पास केन्द्रित हो गई है।

(10) राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति ने मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में अपार वृद्धि की है।

(11) राष्ट्रीय वित्त पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण होने से इसकी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इससे वार्षिक शक्ति मन्त्रिमण्डल के पास केन्द्रित हो गई है।

(12) वर्तमान में शासन कार्यों का संचालन करना जटिल बन गया है। सामान्य सासद प्रशासन की बाटीकियों को सम्झने में अक्षम होते हैं। परिणामस्वरूप वे मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण नहीं कर पाते हैं।

धन्या भारतीय मन्त्रिमण्डल तानाशाह बन सकता है?

जब मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और ससद की शक्तियों में ह्रास हो रहा है तो क्या ऐसी परिस्थितियों में मन्त्रिमण्डल तानाशाह या अधिनायक बन सकता है। भारतीय मन्त्रिमण्डल पर निम्नांकित प्रतिक्रिया है, जिसके कारण वह अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करने को बाध्य है—

(1) भारतीय संविधान मन्त्रिमण्डल की तानाशाही को रोकने में सक्षम है। साँझान निर्माताओं ने भारत को 'सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य' का दर्जा प्रदान किया है, फलतः कोई सरकार या मन्त्रिमण्डल देश के इस बुनियादी स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संविधान निर्माताओं की भावनाओं और अपेक्षाओं को नकारने की क्षमता किसी मन्त्रिमण्डल में नहीं है। यद्यपि मन्त्रिमण्डल ससद में अपने बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन तो कर सकता है, तथापि इसके 'आधारभूत' या 'बुनियादी स्वरूप' में परिवर्तन नहीं कर सकता है।

(2) विपक्षी दलों का मन्त्रिमण्डल पर प्रभावशाली नियन्त्रण रहता है। वे ससद में प्रश्नोत्तर, काम रोकें प्रस्ताव, ध्यानार्जक प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, अविराम प्रस्ताव और कटीवर्त प्रस्तावों के माध्यम से मन्त्रिमण्डल को नियन्त्रित करते हैं। ससदीय समितियों के द्वारा विपक्षी दल मन्त्रिमण्डल पर अकुश स्थापित करते हैं। ससद के बाहर शिपिंगे दलों द्वारा प्रदर्शनों, धरनों, रैलियों और सभाओं के माध्यम से मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण स्थापित किया जाता है। विपक्षी दल जनमत प्राप्त करने का कार्य करते हैं।

(3) राष्ट्रीय निर्वाचन मन्त्रिमण्डल की शक्तियों पर अकुश लगाते हैं। पाँच वर्ष की समिति के बट मन्त्रिमण्डल को मतदाताओं का सामना करने के कारण वह अमर्यादित या तानाशाही व्याकरण करने से स्वयं को बचाता है। वह जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए कार्य करता है। उसकी कार्य-शैली लोकतांत्रिक बनी रहती है। जिस किसी मन्त्रिमण्डल ने अमर्यादित आचरण किया जनता ने उसे सत्तायुक्त कर दिया है।

(4) स्वतन्त्रता के पश्चात् देश की जनता की राजनीतिक चेतना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। एक के बाद एक ससदीय और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों में उसने भाग राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है, अतः प्रधानमन्त्री और

मन्त्रिमण्डल के सदस्य जनता की अपेक्षाओं और सवेदनाओं के प्रति चौकने रहते हैं और उसकी शक्ति से वाकिफ रहते हैं। यह स्थिति मन्त्रिमण्डल को सदैव नियंत्रित करती रहती है।

(5) सभापार पत्रों के निष्पक्ष एवं जागरक प्रकाश न के कारण तानाशाही प्रवृत्तियों पर अकुश लगता है।

(6) भारत में न्यायिक पुनर्रचलेकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षा का सिद्धान्त प्रचलित है जिसका तात्पर्य है मन्त्रिमण्डल और संसद द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जा सकती है। यदि न्यायपालिका को यह प्रतीत हो कि मन्त्रिमण्डल और संसद के किये कार्य से सविधान का अन्विक्षण हुआ है तो वह उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसके अलावा 'केरलानन्द भारती' विवाद में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा कि संसद सविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसके मौलिक या आधारभूत स्वरूप (Basic Structure) में परिवर्तन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय मन्त्रिमण्डलीय अधिनियमवाद पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करता है। हाल ही में 'न्यायपालिका की सत्प्रिया' ने मन्त्रिमण्डल की शक्ति को नियंत्रित किया है।

(7) संसदीय समितियाँ—लोकसभा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और अनुमान समिति और अन्य समितियाँ मन्त्रिमण्डल पर निरीक्षण स्थापित कर उन पर अकुश स्थापित करती हैं।

(8) लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) मन्त्रिमण्डल की भूमिका पर अकुश लगते हैं। प्रधानमंत्री और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को इन पौठासी अधिकारियों की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कृत-सक्त रहन पड़ता है। ये अधिकारी संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। ये मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को आचार्यक 'निर्देश' देते हैं जिनकी उनके द्वारा अनुपालना की जाती है।

राज्यपाल

(The Governor)

सविधान सभा में इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि राज्यपालों की प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाए या राज्यपालों की जनता द्वारा वयस्क मतधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए? गहन विचार विमर्श के बाद सविधान निर्माताओं ने निर्वाचित राज्यपाल के विचार को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर दिया—

- 1 निर्वाचित राज्यपाल की अवकाशा संसदीय शासन व्यवस्था से मेल नहीं खाने की है। यह सम्भव है कि राज्यपाल सार्वजनिक राज्याध्यक्ष के रूप में कार्य न कर राज्य सरकार का प्रमुख बन जाए।
- 2 एक निर्वाचित राज्यपाल में और राज्य के मुख्यमंत्री में संघर्ष की सम्भावनाएँ उत्पन्न हो जाएँगी क्योंकि मुख्यमंत्री और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है।
- 3 एक निर्वाचित राज्यपाल राजनीतिक दलबन्दी के कलावण के दलदल में फँस जायेगा और निरपेक्ष रूप से सार्वजनिक कार्यपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
- 4 राज्यपाल के निर्वाचन की व्यवस्था भारत की केन्द्रीभूत सदीय व्यवस्था के अनुकूल सिद्ध नहीं होगी। सभ और राज्य में विवाद की स्थिति में राज्यपाल केन्द्र सरकार का हित-साधक नहीं होगा और न सभ सरकार का कार्य करने के लिए विश्वसनीय उपकरण सिद्ध होगा।

राज्यपालों की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं—

- 1 यह पद्धति कम खर्चीली है। राज्यपाल के निर्वाचन कराये जाने पर भारी धन राशि व्यय करनी पड़ेगी। 2 इस पद्धति से अल्पसंख्यक समुदाय को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सकता है। 3 इसमें राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अतः ऐसा राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऐसे राज्यपाल पर केन्द्र का प्रभुत्व बना रहता है। 4 इस व्यवस्था में राज्य के अन्य दाय्य व्यक्तियों और सार्वजनिक जीवन के योग्यतम एवं प्रतिभावान व्यक्तियों को राज्यपाल पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। 5 नागरिक व्यक्ति को राज्यपाल पद से हटाया जाना सरल होता है। राष्ट्रपति उसे बिना कारण बताये अपने पद से अलग कर सकता है। 6 ऐसा राज्यपाल मात्र सार्वजनिक अध्यक्ष के रूप में आचरण करेगा। उसमें और राज्य मन्त्रिमण्डल में संघर्ष की सम्भावना अपवाद रूप में रहती है। 7 राज्यपाल का दूसरे राज्य में स्थानान्तरण सम्भव है। 8 ऐसी स्थिति में एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में परम्पराएँ

(Traditions Regarding Appointment of the Governor)

1 राज्यपाल पद पर अधिकारशक्त ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो अनुभवी हों राजनीति के क्षेत्र में जिनका प्रभाव हो और उन्हें राजनीति तथा प्रशासन की नीरक्षियों का ज्ञान हो, अतः राज्यपाल पद पर कुशल राजनीतिज्ञों और कुशल प्रशासकों को नियुक्त किया जाता रहा है।

के विपरीत अथवा केन्द्र द्वारा सुझाये गये नाम पर राज्य सरकार की सुची आपत्ति के बन्दूक उसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति केन्द्र राज्य सम्बन्धों तथा राज्यपाल-मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्धों की दृष्टि से कदापि उचित नहीं रहेगा। इससे सभी पक्षों में जहाँ 'रीतियुद्ध' या 'तनाव' की स्थिति का विकास होगा वहाँ राज्यपाल के प्रति सम्मान में निरिक्त कमी आयेगी।

(4) किसी राज्य में बहरी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

(5) राज्यपाल पद पर नियुक्ति को और अधिक अविवादसाध्य बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसा समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित हों। इस समिति द्वारा सुझाये गये व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किये जा सकेंगे और उनकी नियुक्ति के बारे में अनिवार्यक विवाद भी उत्पन्न नहीं होंगे।

(6) राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में सार्वजनिक आयोग की सिफारिशों को व्यवहार में अनुसरण करना चाहिए। इससे विवादों से मुक्ति मिल सके।

राज्यपाल की शक्तियाँ

(Powers of the Governor)

संविधान में राज्यपाल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य में राज्यपाल की बड़ी स्थिति है जो केन्द्र में राष्ट्रपति की है। संविधान के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गादास के अनुसार 'राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संवैधानिक अधिकारों को छोड़कर।' राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है और कार्यपालिका सम्बन्धी सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। संवैधानिक रूप से उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता है। वह अपने कार्य के प्रति राष्ट्रपति के मित्राण अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल को उसके बार्नों में सहायता और समर्थन देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होती है और व्यवहारिक रूप से राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से कार्य करता है। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों को निम्नानुसार रखा जा सकता है—

1 कार्यकारी शक्तियाँ—राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं जिन्हें वह स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सम्पादित करता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के नेता को अथवा विधानसभा में सर्वाधिक सङ्ख्या का समर्थन करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनमें विभागों का वितरण करता है। अगर निर्वाचन में राज्य विधानसभा में किसी दल की स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय लेने का अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है।

राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मन्त्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राज्य सूची में उल्लिखित विषयों तक है। समस्त सूची के विषयों पर वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्य सेवाओं में की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। उच्च न्यायालय के प्रधान और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल आत्म-भारतीय (ईन्डो इंडियन) समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है यदि उसका राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व न हो। राज्यपाल शासनों के विषय में मन्त्रिपरिषद् से किसी रूप में और किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों से अवगत कराए। राज्य में केन्द्र सरकार की आज्ञाओं के पालन कराने का दायित्व राज्यपाल का है अतः उसका यह दायित्व बन जागा है कि वह राज्य-प्रशासन को जानकारी से केन्द्र सरकार को अवगत कराता रहे।

राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने अथवा राजनीतिक अस्थिरता या अन्य किसी कारण से संवैधानिक तंत्र की अस्थिरता पर वह राज्य की स्थिति के विषय में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रेषित करता है। सामान्यतः उसके प्रतिवेदन के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल की भूमिका शक्तिशाली बन जाती है और वह वास्तविक शासक की भूमिका का निर्वहण करता है। राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् का मार्गदर्शक और अधिपति होता है अतः वह अपनी मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों को चेतावनी, सलाह और प्रोत्साहन देने की शक्ति रखता है।

राज्यपाल, की स्व-विवेकीय शक्तियाँ

(Discretionary Powers of the Governor)

सविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनके दो रूप हैं—(1) सविधान-प्रदत्त स्व-विवेकीय शक्तियाँ, (2) परिस्थितिक्रम स्व-विवेकीय शक्तियाँ। सविधान के कुछ विशेष मामलों में विशेष रूप से असम के राज्यपाल को स्व-विवेकीय अधिकार दिए गए हैं। असम के राज्यपाल को यह विशेषाधिकार है कि वह प्रजातीय क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ प्रशासनिक मामलों तथा असम सरकार एवं स्वायत्त जिला परिषद के बीच खनिज सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों के बारे में निर्णय करे। नागालैण्ड के राज्यपाल को विद्रोही नागाओं से निपटने के लिए स्व-विवेकाधिकारों के प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है। सिक्किम के राज्यपाल को वहाँ के सभी क्षेत्रों के लिए लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए स्मृतिप्रद प्रबन्ध करने की दृष्टि से विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं। सविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति ऐसे उपन्यासों का निर्माण कर सकता है जिनमें राज्यपालों को स्व-विवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अधिक अवसर मिल सकें। राज्यपाल को स्व-विवेक से निर्णय लेने का अधिकार सविधान के अनुच्छेद 163(1) की भाषा से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि "जिन बातों में सविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्देशन में सहायता और सलाह के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।" राज्यपाल को कुछ स्व-विवेकीय शक्तियाँ निम्नांकित विशेष परिस्थितियों में प्राप्त होती हैं—

- (1) किसी एक दल को राज्य विधान सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
- (2) संयुक्त सरकार का गठन और आपसी फूट के कारण शासन का सुचारु रूप से संचालन करना कठिन हो रहा है।
- (3) दलबदल के कारण सरकार के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया जाये।
- (4) राज्य में शान्ति और व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया हो या उसकी सम्भावना हो।
- (5) मन्त्रिमण्डल में विधानसभा के अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई हो।
- (6) दलीय विद्रोह के कारण मन्त्रिमण्डल अल्पमत में आ गया हो और विपक्षी दल वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दे।

राज्यपाल को स्व-विवेकीय शक्तियों को डॉ. एन. बी. पायली ने निम्नानुसार गिनाया है—

(1) मन्त्रिपरिषद् की स्थापना से पूर्व मुख्यमंत्री का चुनाव, (2) मन्त्रिमण्डल को पदच्युत करना, (3) विधानसभा का विघटन करना, (4) मुख्यमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों के सम्बन्ध में सूचना माँगना, (5) किसी मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय (जिस पर मन्त्रिपरिषद् ने विचार न किया हो) को मन्त्रिपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री को आदेश देना, (6) विधानमण्डल द्वारा पारित किए विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना, (7) राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, (8) किसी अध्यादेश को प्रख्यात करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश (Instructions) की माँग करना, (9) राष्ट्रपति को आपात परामर्श देना तथा घोषणा करना, (10) असम तथा पूर्ववर्ती राज्यों के राज्यपालों के लिए आदिम-जाति क्षेत्रों को कुछ प्रशासनिक समस्याओं की हल करना एवं (11) असम राज्य तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों को जिला परिषदों के खनिज सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों का निर्णय करना।

राज्यपालों की स्व-विवेकीय शक्तियों का क्षेत्राधिकार विस्तृत है। राज्यपाल को स्व-विवेकीय शक्तियों के प्रयोग करने में मन्त्रिपरिषद् की सहायता या उसके किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। अपने कार्यों के इस क्षेत्र में राज्यपाल वस्तुतः सशक्त सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश दे सकता है। राज्यपाल के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उनके आदेश का पालन करे फिर चाहे इसमें उसे राज्य की मन्त्रिपरिषद् के परामर्श की अवहेतना ही क्यों न करनी पड़े। राज्यपाल की ये स्व-विवेकीय शक्तियाँ उनकी भूमिका को उग्र विवाद या आलोचना का विषय बना देती हैं।

केन्द्रीय अधिकर्ता के रूप में भूमिका

(Role as an Agent of the Centre)

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः उसे राज्यों में केन्द्र का अधिकर्ता या एजेंट कहा जाता है। केन्द्र के अधिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को जो कार्य करने पड़ते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार) ही राज्यपालों को निर्देश-आदेश देता है। यदि राज्य का मन्त्रिमण्डल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशन के

विह्वल कार्य करने की सलाह दे तो वह ऐसी किसी सलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति का आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि राज्य मन्त्रिमण्डल केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता है तो राज्यपाल इसे सविधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक सक्ति घोषित करने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रेषित कर सकता है और तत्पश्चात् सक्ति की उद्घोषणा के परन्तु राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों को संचालित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि में केन्द्र के अधिकारों के रूप में राज्यपाल प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करता है और वह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका का संचालन करता है। इस भूमिका में वह पूर्व की लोकप्रिय सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को बदलने या उनके क्रियान्वयन को रोकने की कार्यवाही कर सकता है। वह प्रशासन में फेर-बदल कर सकता है। इस काल में नीकरशाह उसके मुख सलाहकार बन जाते हैं।

राज्यपाल केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में एक 'सम्पर्क कड़ी' (Connecting Link) का कार्य करता है। उसका सञ्चालन भूमिका से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में उठने वाले विवादों का समाधान कर सम्भावनापूर्ण वातचरण का जिम्मा ज्ञात करता है। वह राज्य में केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को लागू करने में मददगार भूमिका का निर्वाह करता है। उस पर यह दायित्व आ जाता है कि वह देखे की राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने में कहीं तक रुक नहीं रही है तथा असन्तुष्ट होने पर वह सरकार को चेतावनी अथवा आवश्यक निर्देश दे सकता है। अगर राज्य सरकार का व्यवहार प्रतिकूल हो तो वह केन्द्र सरकार को चेतावनी देने वाली अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन में वस्तुस्थिति से अवगत कर सकता है। केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राष्ट्रपति को सुझाव सहित रिपोर्ट भेजता है। राज्यपाल पर प्रहार करते समय सविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है और यदि वह राष्ट्रपति की संवैधानिक-कल्प की विरुद्धता की सूचना देता है तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्य विधान-मण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक की राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किन्तु कुछ मामलों में वह राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति अर्थात् केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह दखन है कि राज्य सरकार सचिवों आदेशों के अन्तर्गत कार्य करे न अपना कर समस्त सच के कर्तव्य का ध्यान रखे। केन्द्रीय अधिकारों के रूप में सैनिकीय शक्तों के राज्यपालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आतंकवादी, पृथकवादी, राष्ट्र-विरोधी, तस्करी तथा विदेशी घुसपैठियों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को सतर्क रूप से अवगत कराते रहें। केन्द्रीय अधिकारों के रूप में राज्यपालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्यमंत्री, मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के क्रिया-कलापों से केन्द्र को निरन्तर अवगत कराते रहें। केन्द्रीय अधिकारों के रूप में उसका गृह मन्त्रालय से प्रत्यक्ष और सीधा सम्पर्क होता है।

सविधान की उपर्युक्त व्यवस्थाओं पर दृष्टिपथ करने से यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की प्रमुख भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की है तथा उसकी गौण भूमिका केन्द्रीय सरकार के 'अधिकारों या एजेंट' की है। लेकिन स्वतन्त्रता के परन्तु राज्यपालों के आचरण या भूमिका से मुखरित होता है कि उन्होंने राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की तुलना में 'केन्द्रीय अधिकारों' की भूमिका को अधिक महत्व दिया है।

राज्यपाल की भूमिका : गिरती छवि

सन् 1967 के पूर्व केन्द्र और सभी राज्यों (कुछ अपवादों को छोड़कर) में कॉन्ग्रेस दल की सरकारों के सतत होने के कारण राज्यपालों की भूमिका औपचारिक मात्र थी। उनके सम्मुख विशेष चुनौतियाँ उपस्थित नहीं हुईं। वे राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष और केन्द्र के अधिकारों की औपचारिक भूमिका का सम्पन्नपूर्वक निर्वाह करते रहे। उनकी भूमिका के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं हुआ।

सन् 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद देश के राजनीतिक परिवर्तन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में केन्द्र में कॉन्ग्रेस का बहुमत कम हो गया और अनेक राज्यों में यथा पराजित विपक्ष दल सत्ता परिलब्ध बंगाल, केरल और तमिलनाडु में प्रमुख की एकदलीय सरकार को छोड़कर सभी गैर-कॉन्ग्रेसी सरकारें सविधान में निर्दिष्ट राज्यों की अल्पसंख्यक के लिए कृत-संकल्प थी। कॉन्ग्रेस के केन्द्रिय नेतृत्व की अनेक प्रेरित नृत्य का इस कार्य में शक्य था। केन्द्र के प्रतिनिधि या अधिकारों के रूप में राज्यपालों की निष्पक्षता पर शक्यों की जड़ें लगीं। दूसरा और दलबदल के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की कॉन्ग्रेसी सरकारों का पतन हुआ। इनके पतन पर दलबदलियों के नेतृत्व में सविधान सचिवों गठित हुईं। राज्यों में सरकारों के बनने, मिटने के क्रम में राज्यपालों द्वारा अल्पसंख्यक-मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा राज्य में मन्त्रिमण्डलों की बर्तावशाली, अल्पसंख्यक और सदिग्ध बहुमत का समर्थन रखने वाले मुख्यमंत्रियों की सलाह पर विधानसभाओं के विपक्षी राज्यपालों द्वारा मन्त्रिपरिषद् द्वारा तैयार किये गये अधिनियमों के अन्तिममन्त्र अशों के पढ़ने से इनकार करके संवैधानिक विवाद को जन्म देना राज्यपालों द्वारा बहुमत प्राप्त नेताओं को मुख्यमंत्री पद को

राज्य दिलाने के स्थान पर अल्पमतवादी नेताओं को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के निर्णय दलीय विद्रोह की स्थिति में मुख्यमंत्री के राज्य विधानसभा में बहुमत का निर्धारण करने के स्थान पर 'राज्यधर्म' में करने की प्रवृत्ति, प्राप्ताचार, अनैतिक आचरण, शान्ति और व्यवस्था तथा दलीय विद्रोह के नाम पर मुख्यमंत्रियों की नरसंहारी, राजधर्म में बैठकर सक्रिय राजनीति में भाग लेना, राज्यपाल रहते हुए दलीय कार्यक्रमों में भाग लेना, राष्ट्रपति शासन के समय अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग तथा राज्य में निर्वाचन की समयावधि में ही विवादोत्पत्ति निमित्तपूर्ण करने, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निरस्त करने, राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा अपने पुत्र के कथित चुनाव प्रचार को लेकर दिये गये त्यागपत्र जैसे घटनाचक्रों ने राज्यपालों की 'जनता में एवि' को गिरा दिया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति शासन के लिए की गई अभिलाषाओं ने इस पद पर गंभीर आपत्तिजनक आरोप लगाने के लिए जन मतस को उद्देक्षित किया है। उनकी भूमिका विवादोत्पत्ति हो गई। ससद राज्य विधानसभाओं और सार्वजनिक सभाओं में राज्यपालों के आचरण की निन्दा की गई। उन्हें 'केन्द्रीय जासूस' कहकर इस पद को समाप्त करने की माँग की गई।

राज्यपाल सभा की अविवादोत्पत्ति बनाने के लिए विभिन्न आयोगों ने सार्वक सुझाव दिये हैं। इस विरा में तमिलनाडु की एम. करुणानिधि वाली द्रमुक सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल समिति राष्ट्रपति की श्री गिरी द्वारा राज्यपाल प्रणवन सहाय के नेतृत्व में गठित 'सहाय समिति या राज्यपाल समिति' एवं सरकारी आयोग प्रमुख रहे हैं। इनमें सरकारी आयोग ने अनेक सुझाव दिये हैं जैसे राज्यपाल को इतने से पूर्व उसे अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपना पक्ष अपनी बर्खास्तगी के विरुद्ध प्रस्तुत कर सके तथा उसे ससद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि यह सुझाव मान लिया जाये तो राज्यपाल एक स्वतन्त्र प्रभारी के रूप में कार्य कर सकेंगा।

मुख्यमंत्री तथा राज्य मंत्रिपरिषद्

(Chief Minister and the State Council of Ministers)

राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् में निहित होती है जो राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार "उन बातों की छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे पहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।"

राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन

(1) मुख्य मंत्री की नियुक्ति—मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद् के गठन का प्रथम चरण है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधान सभा में बहुमत दल के नेता को मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है लेकिन यदि राज्य की विधान सभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या विभिन्न दलों के संयुक्त मोर्चे का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में विवेक का प्रयोग कर सकता है।

(2) अन्य मंत्रियों की नियुक्ति—अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। अन्य मंत्रियों का अपने मंत्रिमण्डल के लिए चयन करते समय मुख्य मंत्री क्षेत्र, दल, प्रभाव, विश्वास, योग्यता आदि कई बातों को ध्यान में रखता है।

(3) मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ और कार्य—राज्य मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं—(1) शासन की नीति निर्धारित करना, (2) उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना, (3) विधान मण्डल में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, (4) कानून निर्माण की व्यवस्था करना एवं (5) बजट तैयार करना।

मुख्यमंत्री की स्थिति—मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन की 'पुत्री' कहा जाता है। वह राज्य के सभी कार्यों का संचालन करता है। उसकी भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य विधानसभा में उसके दल को कितनी बहुमत का समर्थन प्राप्त है? राज्यपाल के साथ उसके सम्बन्ध कैसे हैं? केन्द्र में उसके दल की सरकार है या नहीं? प्रधानमंत्री के साथ उसके सम्बन्धों का स्वरूप कैसा है? दल के उच्च-कमान के साथ उसके सम्बन्ध कैसे हैं? आदि के आधार पर मुख्य मंत्रियों की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है—प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में पश्चिमोत्तर बंगाल के विपिनचन्द्र राय और ज्योति बसु, उत्तर प्रदेश के पंडित गोविन्द वल्लभ पंत और चन्द्रभानू गुप्त, महाराष्ट्र के पद्मवन्तराव चव्हाण, बसन्तराव नाईक और शरद पवार, गुजरात के जलवन्तराव मेहता, राजस्थान के मोहनलाल सुखलिया और भीमसिंह शेखावत, बिहार के श्रीकृष्ण सिन्हा और लालू प्रसाद यादव, मध्य प्रदेश के पंडित रजिन्द्रकर शुक्ल तथा हरिकृष्णप्रसाद मिश्र, तमिलनाडु के अन्नादुराई एम. जी. रामचन्द्रन और कु. जयललिता, कर्नाटक के निजलिङ्गप्पा, आंध्र प्रदेश के एन. टी. रामाराव, चन्द्रबाबु नायडू, उड़ीसा के बीजू पटनायक, पंजाब के सरदार प्रतापसिंह कैतों और प्रकाशसिंह बादल, जम्मू-कश्मीर के मोहम्मद शेख, अन्तुल्ला, हिमाचल प्रदेश के यशवन्तराव धारम, केरल के ई. एम. ए. नम्बूद्रीपद, त्रिचिङ्गम में नरबहादुर गुण्डारी तथा असम के विमलप्रसाद चलिहा के नाम गिनाये जा सकते हैं। यह सब अपने-अपने राज्यों के प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता रहे हैं—

और इनकी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में अहम् भूमिका रही है। केन्द्र द्वारा इनकी आवाज और राय को महत्व दिया गया है।

दुर्बल मुख्यमंत्रियों में उन मुख्यमंत्रियों को रखा जा सकता है, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री या दल के उच्चकमान की कृपा के आधार पर हुई तथा जिन्हें अपने राज्यों में विधानमण्डलीय दल का समर्थन प्राप्त नहीं था। ये मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने में दल के उच्चकमान की तरफ देखते रहे हैं। पंडित नेहरू से लेकर वाजपेयी तक के कार्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर, जिनका उल्लेख (शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों के रूप में) किया जा चुका है, ऐसे ही मुख्यमंत्रियों का अस्तित्व रहा है। इन दुर्बल मुख्यमंत्रियों की सत्त्यागत और आचरणगत स्थिति पर प्रधानमंत्री तथा दल के उच्चकमान का पूर्ण वर्चस्व रहा और उन्हें जब चाहे अपने पदों से हटा दिया गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो उनके पद की गरिमा और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल क्या जा सकता है। इस स्थिति के कारण मुख्यमंत्रियों की सत्त्यागत स्थिति प्रभावित हुई और वे 'मुख्यमंत्री' के स्थान पर 'मुख्य सन्देशवाहक' (Chief Messengers) में परिवर्तित हो गये। सन् 1967 के बाद दलबदल भारतीय राजनीति की एक आसदी बन गया। इस प्रक्रिया में ऐसे अल्पमतीय मुख्यमंत्रियों की परम्परा को जन्म दिया, जिनको किसी एक प्रमुख दल तथा दलों के गटबन्धन ने मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए, बिना बाहर से समर्थन दिया। ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूर्णरूपेण 'दलबदलजुओं' के मन्त्रिमण्डल सत्तामण्डल हुए। ऐसे 'परिभ्रत' मुख्यमंत्री शक्तिहीन, अल्पमतीय या कमजोर थे। ऐसे मुख्यमंत्रियों में आन्ध्र प्रदेश में नन्देला भास्करराव, बिहार में विधेयशर्मा प्रसाद मण्डल, पश्चिमी बंगाल में डॉ. प्रफुल्लचन्द्र घोष, पंजाब में डॉ. लक्ष्मणसिंह गिल, जम्मू-कश्मीर में गुलाम मोहम्मद शाह, केरल में मोहम्मद एन कोया तथा तमिलनाडु में डॉ. गुरुगु, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरणसिंह मध्य प्रदेश में भोविन्दारायण सिंह, हरियाणा में एब चौधरीसिंह और भजनलाल, उत्तर प्रदेश में मुख्य माधवशर्मा को गिनाया जा सकता है। ये अल्पमतीय मुख्यमंत्री दीर्घजीवी नहीं हुए और उनका समय रहते ही पतन हो गया।

छोटी दलों के मुख्यमंत्रियों की भूमिका शक्तिशाली बनी रही, क्योंकि ये अपने दलों की शक्ति का मुज्रा आधार रहे। ऐसे मुख्यमंत्रियों में जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्ग्रेस के मोहम्मद शौक अहमदल्ला और पश्चिम अहमदल्ला, आन्ध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम के एन टी रामाराव चन्द्रबाबू नायडू, तमिलनाडु में तमिलनाडु समाज पार्टी के एम एन जयललिता, पंजाब में अकाली दल के प्रकाशसिंह बादल, अकाली दल (लोगीवाल) के सुरजीतसिंह बल्लाना तथा गोवा में महापुरुषादी गोमन्तक पार्टी के दयानन्द बान्दोडकर तथा झारखण्ड की भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चन्द्र बोस को गिनाया जा सकता है। ये मुख्यमंत्रियों की तुलना में शक्तिशाली रही है।

मुख्यमंत्री के कार्य तथा शक्तियाँ—मुख्यमंत्री की शक्तियों की प्रकृति बहुत व्यापक है। यह राज्यपाल से राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति कावाता है और उनमें विभागों का वितरण करता है, मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है और राज्य प्रशासन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेता है, मंत्रियों को बहिष्कृत करने और निर्देश देता है तथा मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के कामकाज की समीक्षा कर मन्त्रिमण्डल को एक संगठित टीम के रूप में कार्य करवाने की अहम् भूमिका निभाता है। यह मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन कर सकता है तथा अयोग्य और अक्षम मंत्रियों को अपने पद से हटा सकता है।

मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन के संचालन में अहम् भूमिका होती है। उसके द्वारा ही राज्य प्रशासन के लिए वांछित नीतियाँ और दिशा-निर्देश दिये जाते हैं। राज्य सचिवबन्धन पर उसका नियन्त्रण होता है और मुख्य सचिव सचिव सभी विभागीय शासन सचिव राज्य मन्त्रिमण्डल द्वारा ली गई नीतियों तथा निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए तयार रहते हैं। राज्य में की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में मुख्यमंत्री की निर्णायक भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की नीतियों का प्रवक्ता माना जाता है। यह विधानसभा में और उसके बाहर राज्य सरकार के निर्णयों को घोषणा करता है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानमण्डल का नेता माना जाता है। सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को कायम रखने का दायित्व उसी का है। मुख्यमंत्री राज्य विधानमण्डल के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उत्सुकियों को रक्षा करने के दायित्व का निर्वाह करता है। मुख्यमंत्री पर राज्य में शक्ति और व्यवस्था को बनाये रखने तथा प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास और आस्था को बनाये रखने का उत्तरदायित्व होता है। राज्य में साम्प्रदायिक अलगाववादी, पृथक्तावादी और अल्पवादी शक्तियों को नियंत्रित करने का दायित्व मुख्यमंत्री का है।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों की दृष्टि से मुख्यमंत्री को महत्वपूर्ण भूमिका है। वह केन्द्र के सम्मुख राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री सम्मेलन में वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा विवादों तथा जल विवादों के समाधान खोजने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जो सम्मेलन बुलाये जाते हैं उनमें वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री राज्य की योजना को योजना आयोग से स्वीकृत करने का कार्य करता है। यह मुख्यमंत्री की कुरलता पर निर्भर

करता है कि वह राज्य के सम्मुख राज्य का पक्ष कितनी प्रबलता के साथ प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग के सम्मुख राज्य के पक्ष को प्रस्तुत करने का दायित्व मुख्यमंत्री का है। इससे यह राज्य के लिए अधिक सहायन जुटाने में सक्षम बन सकता है। मुख्यमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) तथा राष्ट्रीय एकाता परिषद (National Integration Council) की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अन्तर्-राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री की भूमिका सर्वोपरि तथा निर्णायक होती है। मुख्यमंत्री की जन-नायक भाषा जाता है। वह राज्य की जनता की आशाओं एवं अपेक्षाओं का प्रतीक होता है।

मन्त्रिपरिषद्

(Council of Ministers)

सविधान के अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् के सदस्य विधानसभा में बहुमत दल के सदस्य होते हैं। अगर सरकार का स्वरूप सविधान सरकार का है तो दा या दो से अधिक राजनीतिक दलों के सदस्य तथा सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय सदस्य हो सकते हैं। मन्त्रिपरिषद् के सदस्य अनिवार्य रूप से राज्य विधानमण्डल के सदस्य होते हैं। वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। अगर कोई सदस्य मन्त्रिपरिषद् में शामिल करते समय राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं होता तो उसे सदस्य बनने से 6 महीने की समाप्ति तक में राज्य विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। इसमें असफल रहने पर उसे मन्त्रिपरिषद् से त्यागपत्र देना पड़ता है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व और निर्देशन में मन्त्रिपरिषद् कार्य करती है। वह जब चाहे मन्त्रिपरिषद् में फेर बदल कर सकती है। वह मंत्रियों को हटा कर नये मंत्रियों को शपथ दिला सकता है उनके विभागों में परिवर्तन कर सकता है मंत्रियों को पदच्युत कर सकता है इनसे त्यागपत्र माँग सकता है और ऐसा करने से इनकार करने वाले मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर सकता है। वह मन्त्रिपरिषद् के पुनर्गठन के लिए एक साथ सारी मन्त्रिपरिषद् का त्यागपत्र माँग सकता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है।

मन्त्रिपरिषद् के सदस्य राज्य विधानमण्डल के प्रति ध्येयवृत्ति और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तीन सम्बन्धी प्रश्नों पर सामूहिक उत्तरदायित्व की धारणा लागू होती है। यदि मन्त्रिपरिषद् किसी नीति सम्बन्धी प्रश्न पर राज्य विधानसभा में पराजित हो जाती है तो मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् के सदस्य एक साथ तैरत और डूबते हैं। मन्त्रिपरिषद् पर विपक्षी और न्यायिक नियन्त्रण है। राज्य विधानमण्डल के विश्वास-पर्यन्त मन्त्रिपरिषद् अपने पद पर बने रह सकती है। यदि राज्य विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अधिश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमण्डल प्रश्नोत्तर, कामगोचर प्रस्ताव निम्न प्रस्ताव, ध्यानार्पण प्रस्ताव तथा कटौती प्रस्ताव में मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण रखती है।

मन्त्रिमण्डल की बैठकों में मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री भाग लेते हैं। सामान्यतः मन्त्रिमण्डलाध्यक्ष स्तर के मंत्री अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अपने विभाग के संचालन का दायित्व मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री करते हैं। राज्य मंत्रियों का भी मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्र कार्यभार सौंपा जाता है तथा उन्हें मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है। सामान्यतः राज्यमंत्री उपमंत्री और ससदीय सचिव अपने मन्त्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों को कार्य सम्पादन में सहयोग देते हैं।

मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल पाँच वर्ष का होने के बावजूद अनिश्चित होता है। यदि वह विधानसभा का विश्वास खो दे तो अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यदि केन्द्र सरकार अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् को बर्खास्त करने का निर्णय ले तो मन्त्रिपरिषद् का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

मुख्यमंत्री को राज्य मन्त्रिमण्डल के निचले सदन अर्थात् राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन रखने वाले मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया जाता है लेकिन राज्य विधानसभा में पराजित सदस्य बहुमत और अल्पमतों के मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। मन्त्रिपरिषद् को गोपनीयता के सिद्धान्त का पालन करना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् द्वारा निम्ने गये निर्णयों को जब तक सार्वजनिक नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें गुप्त रखना पड़ता है। अगर मन्त्रिपरिषद् के सदस्य उनका रहस्योद्घाटन कर देते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् के सदस्य सविधान की सराहा की शपथ लेते हैं अतः वे अपने कृत्यों से सविधान का सारक्षण करने के लिए बचनबद्ध होते हैं। मन्त्रिपरिषद् के सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं अतः विभागों का संचालन करना उनका आधिकारिक कार्य माना जाता है। वे अपने विभागों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

भारतीय सविधान मन्त्रिपरिषद् को कार्यपालिका विधायी और वित्तीय क्षेत्र में आने वाली सभी शक्तियाँ प्रदान करता है। मन्त्रिपरिषद् राज्य प्रशासन का संचालन करती है और सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करती है। मन्त्रिपरिषद् द्वारा सभी विधेयकों का प्रारूप तैयार किया जाता है और उन्हें विधानमण्डल से पारित कराया जाता है। मन्त्रिपरिषद् द्वारा ही बजट का निर्माण करके उसे पारित कराया जाता है। राज्य के विकास सम्बन्धी और अन्य सभी नागरिक निर्माण मन्त्रिपरिषद् द्वारा लिये जाते हैं। इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के सदर्भ में निर्णय लिये जाते हैं। मन्त्रिपरिषद् राज्य में केन्द्रीय निर्णयों को लागू करती है। मन्त्रिपरिषद् को शासन का 'संचालनकर्ता' माना जा सकता है।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्ध

(The Relationship between the Governor, the Chief Minister and the Council of Ministers)

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सम्बन्धों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे अनेक बिन्दुओं के लिए राज्यपाल को सूचित करने का सवैधानिक दायित्व है। इन दायित्वों को निम्नानुसार रख जा सकता है—

1. मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य-कार्यों के प्रशासन के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद् द्वारा लिए गए समस्त विनिरूपणों तथा विधान बनाने सम्बन्धी समस्त प्रस्थपनाएँ राज्यपाल को प्रदान करे।

2. वह राज्यपाल को समस्त जानकारी प्रेषित करे जो उसने राज्य-प्रशासन के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद् के तत्सम्बन्धी विनिरूपणों तथा विधान-निर्माण सम्बन्धी प्रस्थपनाओं के सदर्भ में चही है।

3. ऐसे किसी विषय पर जिस मंत्री ने अपना विनिरूपण पदान कर दिया है लेकिन उस मन्त्रिपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है उसके सम्बन्ध में मुख्यमंत्री पर यह दायित्व अधिरोपित किया है कि ऐसे विनिरूपणों को राज्यपाल की अपेक्षा करने पर मन्त्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करे।

4. अनुच्छेद 167 में सम्बिष्ट किये गये मुख्यमंत्री के सवैधानिक कर्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

5. राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद् के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। दोनों राज्य की कार्यपालिका के अभिन्न अंग होते हैं। जैसा कि सविधान में उल्लेख किया गया है—“राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह अप्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से तथा सविधान के अनुसार करेगा।”

नौकरशाही

(Bureaucracy)

भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही भारतीय प्रशासन नौकरशाही प्रधान रहा है। अंग्रेजों ने आई सी एस अफसरों का ऐसा दृढ़ानु तैयार किया जो शक्ति और दण्ड के बल पर देश के शासन को चलाता रहा। स्वाधीनता के बाद आई सी एस के स्थान पर आई ए एस वर्ग के अफसरों की पृष्ठभूमि जगह तैयार हो गई जिसे कुरान और सघन प्रशासन का प्रतिरूप मान लिया गया।

भारतीय नौकरशाही की विशेषताएँ—(1) भारत की नौकरशाही में स्वयंसेवक है। (2) वहाँ की नौकरशाही राजनीतिक रूप से उदात्त रहती है। (3) वहाँ लोकसेवा एक वेरा है। (4) भारत में लोक सेवाओं का संगठन पद सोपान के सिद्धान्त पर होता है।

भारत की नौकरशाही में ये विशेषताएँ भी व्यवहारिक जानकारी से दृष्टिगत होती हैं—(1) भारत की नौकरशाही में प्रतापपूर्ण व्यक्त है। (2) भारत के नौकरशाह परोक्ष रूप से राजनीति में सलतन रहते हैं। (3) लोकसेवा में सदान्तराष्ट्रीय है। (4) नौकरशाही में शासन का अङ्ग रहता है। (5) लोकसेवा में विरोधों की उपेक्षा है। (6) भारत में केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर अलग-अलग सेवाओं की व्यवस्था है। (7) लोक सेवाओं में अभिजनवर्गी प्रजिबद्धता है। (8) सेवा सरचना ऐसी है जो उत्तरदायित्वहीन करी जा सकती है।

लोक सेवाओं के कार्य—(1) नति निर्माण करना (2) राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देना (3) सरकार की नीतिवर्ती को क्रियान्वित करना (4) विधि निर्माण कार्य करना (5) अर्द्ध न्यायिक कार्य करना एवं (6) विकास कार्यों को संपादित करना।

संसद तथा संसदीय समितियों की भूमिका तथा कार्य

(Role and Function of the Parliament and Parliamentary Committee)

भारत में लोकतन्त्रिक व्यवस्था को अग्रोकार दिया गया है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका अर्थात् संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका संसद के विश्वासपर्यन्त अपने पद पर बनी रह सकती है अतः कार्यपालिका द्वारा बनाई जाने वाला नातिथी तथा लोकसेवकों द्वारा उन नीतियों को क्रियान्वित करने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया पर संसद का नियन्त्रण होता है। भारतीय संसद प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखती है।

पारस्परिक सम्बन्ध के आधार

(The Basis of Correlatenship)

(1) **संसदीय बहस**—संसद में लोकप्रशासकों के कार्यों पर बहस की जाती है ताकि यह जाना जा सके कि अनुमोदित नीतियों को किस मापा तक सम्पन्न किया गया है। बहस के दौरान यह अधिकारियों को आवश्यक निर्देश, आदेश तथा चेतावनी दे सकती है। संसद द्वारा प्रशासकों पर 'ऐस' पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण रखा जाता है ताकि वे कार्यों को कुशलता पूर्वक संचालित कर सकें।

(2) **संसदीय व्यवस्थापन**—संसद द्वारा पारित कानून लोक-सेवकों के व्यवहार का स्वरूप एवं मापदण्ड निश्चित करते हैं। लोक-सेवकों के कर्तव्य और अधिकारों का निर्धारण संसदीय कानूनों द्वारा किया जाता है।

(3) **संसद वित्तीय शक्ति का स्रोत है**—प्रशासनिक विभागों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद यदि धन की स्वीकृति न दे तथा आवश्यकता से कम की स्वीकृति दे तो लोक-सेवक अपने कार्य सन्तोषजनक रूप में सम्पन्न नहीं कर सकते। यह वित्तीय नियन्त्रण द्वारा लोक-सेवकों को जन-कल्याण के कार्यों की ओर प्रवृत्त रखती है।

(4) **व्यवस्थापिका शक्तियों का हस्तान्तरण**—संसद अपनी कानून बनाने की शक्ति को कार्यालयों के लिए हस्तान्तरित करती है और यह लोक-सेवकों को न्याय दायित्व सौंपती है। प्रदत्त-व्यवस्थापन प्रक्रिया इसी बात का परिणाम होती है किन्तु इस दायित्व के निर्वाह के लिए वे सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते बल्कि मंत्रियों के माध्यम से उत्तरदायी होते हैं। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन अथवा हस्तान्तरित व्यवस्थापन कहा जाता है।

संसदीय नियन्त्रण

(Parliamentary Control)

संसद द्वारा लोक-सेवकों के कार्यों पर नियन्त्रण रखा जाता है ताकि जनहित विरोधी कार्यों को रोका जा सके। भारत के सन्दर्भ में लोक-सेवकों पर संसदीय नियन्त्रण का महत्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ गया है—

(1) **सांशानिक राजनीतिक परिवर्तन**—स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में हुए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण भारतीय जनता के रहन-सहन, जीवन-स्तर एवं विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन ने प्रशासन को प्रकृति और लक्ष्य के प्रति जनता के दृष्टिकोण को बदल दिया है। इन परिवर्तनों के कारण आज का लोक-सेवक स्वेच्छाजारी जन-हित-विरोधी प्रिकुश एवं सम्पन्न के मूल्यों तथा आदर्शों की अवहेलना करने वाला नहीं हो सकता है। जब कभी लोक-सेवक जनहित के कार्यों में अक्षम एवं उदासीनता दिखाते हैं तभी व्यापक जन-विरोध उठ खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में लोक-सेवाओं पर संसद का नियन्त्रण अनिवार्य बन जाता है। संसद में लोकसेवकों के आचरण पर बहस होती है और उन्हें अनुशासनहीन होने पर प्रताड़ित किया जा सकता है।

(2) सरकार के कार्यों का विस्तार—स्वतन्त्रता के बाद सरकार के कार्यों का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। यह पुनः राज के दायित्वों के साथ नागरिक कल्याण के कार्य सम्पन्न करती है। उसके कार्यों की प्रकृति बहुमुखी है। आज भारत सरकार नागरिकों की सरसक, धन और सहयोगी है। सरकार के कार्यों के क्षेत्र-विस्तार के बड़ने के साथ प्रशासन के दायित्व बढ़ गये हैं। इसके लिए प्रशासन को नए अधिकारों और शक्तियों से सुसज्जित किया गया है। इन शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए ससदीय नियन्त्रण की व्यवस्था की जाती है।

(3) प्रजातांत्रिक समाजवाद—भारत ने प्रजातांत्रिक समाजवाद के मार्ग को अपनाया है और आज सरकार के दायित्व हो जाता है कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे नागरिकों के अधिकार और स्वातन्त्र्य को नुकसान हो सके। समाजवाद का मार्ग अवरोध होना चाहिए। इसके लिए संसद द्वारा प्रशासन पर निरन्तर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखा जाता है।

(4) नवीन निरक्षरता के खतरे—प्रशासन पर संसद के प्रभावशाली नियन्त्रण के अभाव में लोक-भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, जनता में असन्तोष पैदा होता है, प्रशासन में अनियमितता बढ़ती है। भाई भणोजावर तथा भणार का प्रदर्शन पनपती है तथा मुख्य कार्यपालिका प्रशासनिक नीतियों का अन्वयन करने लग जाता है। परिणामस्वरूप प्रशासनिक लक्ष्य-निर्देशों का विकास होता है विकास-योजनाएँ स्वीकृत हो जाती हैं। प्रशासनिक अक्षमता से जनता का नैतिक चरित्र और तत्त्वज्ञान क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के कानून महत्वहीन बन जाते हैं। उनकी अवहेलना, उपेक्षा और विरसकार किया जाता है। इन सभी बुराइयों पर नियन्त्रण रखने के लिए प्रशासन पर संसद का नियन्त्रण रचना अत्यावश्यक बन जाता है।

संसदीय नियन्त्रण के साधन (Tools of Parliamentary Control)

(1) नीति का निर्धारण—संसद द्वारा प्रशासन को व्यापक नीति का निर्धारण किया जाता है। जब भवक जिन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, वे संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। संसद द्वारा उन्मत्त परिवर्तन, परिवर्तन या संशोधन किया जाता है।

(2) बजट पर चर्चा—बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है। उसकी अनुमति के बिना लोक-प्रशासनिक पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। बजट पर चर्चा के समय संसद के सदस्य प्रशासन की सम्पूर्ण गतिविधियों का मूल्यांकन करते हैं। लोक-सेवकों एवं उच्च पदाधिकारियों के कार्यों का पुनरावलोकन किया जाता है। इससे भ्रष्टाचार-विरोधी नीति-निर्धारण का पदोन्नति होता है और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है। अनुदान की माँग पर मतदान करी समय संसद सदस्य लोक-सेवकों के व्यवहार की विराट् चर्चा करते हैं। कठोरी प्रस्ताव के रूप में लोक-सेवकों के व्यवहार पर पूर्ण तरह टिप्पणी और समीक्षा की जाती है। वित्त विधेयक पर विचार के समय संसद सदस्य लोक-प्रशासन का अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं अन्य दोषों का उल्लेख करते हैं।

(3) राष्ट्रपति का अभिभाषण—संसदीय अधिवेशन के प्रारम्भ पर राष्ट्रपति जब अपना अभिभाषण देते हैं तो वे लोक-सेवकों के कार्यों एवं उपलब्धियों की प्रशंसा एवं अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करते हैं। जब संसद सदस्य इस बात पर विचार विमर्श करते हैं तो लोक-सेवकों के कार्यों की आलोचना का विषय बनाया जाता है। संसद में हुई बहस समाप्ति पर, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से उनकी गतिविधियाँ जन-सामान्य तक पहुँच जाती हैं। इस प्रकार संसदीय घट विवाद से प्रशासन के प्रति जनमत निर्माण करने में सहायता मिलती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी जनमत जाग्रत करने का प्रभावशाली साधन बन गये हैं।

(4) प्रश्न-काल—संसद की कार्यवाही का पहला ध्येय प्रश्न पूछने के लिए नियत है। इस काल में संसद सदस्य मंत्रियों से उनकी प्रशासनिक नीतियों एवं कार्यों के सम्बन्ध में विविध प्रश्न पूछते हैं। अनन्तर प्रशासन पर सन्तोष-नियन्त्रण दृष्टापूर्वक स्थापित होता है। पूछे जाने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रत्येक मंत्री सज्ज रहता है। गलत या गलत अधिकार है कि वह किसी प्रश्न का उत्तर न दे अथवा उत्तर दे किन्तु ऐसा करना उसकी लोक-प्रियता को नुकसान पहुँचाता है। प्रत्येक प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त करने की दृष्टि से मंत्री लोक-सेवकों के कार्यों पर नियन्त्रण रखता है। वह अपने विभागीय अधिकारियों में व्यक्तिगत रुचि नेता है। किसी अधिकारी द्वारा की गई गलतियों के प्रति गलत में जायज होने के कारण मंत्री स्वयं यह प्रयास करता है कि ऐसे अवसर पैदा न हों। स्वयं अधिकारी ससदीय प्रशासन अपनी बाजूओं की बजाकर कार्य करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के मतानुसार "संसद में खुले रूप में मन्त्रियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण नागरिक सेवा की चौकन्ना रहना पड़ता है।"

(5) बहस एवं विचार-विमर्श—प्रश्न-काल के अतिरिक्त समय में संसद सदस्य लोक-प्रशासन के कर्तव्यों पर लोक-टिप्पणियाँ करते रहते हैं। ऐसा मुख्यतः तीन अवसरों पर होता है—

(क) नया विधेयक प्रस्तावित होने पर—जब नया विधेयक संसद में प्रस्तावित किया जाता है तो उसी समय प्रशासन लोक-सेवकों के कार्यों की पुनरीक्षा अथवा पुनरावलोकन कर देते हैं। ऐसे वाद-विवाद के समय प्रशासनिक संगठन की सफलता, उपयुक्तता एवं कार्य-कुशलता सामने आती है।

(ख) आगे पष्टे के विचार-विमर्श के लिए समय मौजना—ऐसा प्रावधान है कि यदि प्रश्न-काल में कोई सदस्य सरकार के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हो पाते हैं अथवा उसके सम्बन्ध में उसे सन्देह रहता है तो उसके निवारणार्थ वह प्रश्न काल के तुरन्त बाद अम्पस से आगे पष्टे के विचार विमर्श की अनुमति माँग सकता है और इस विचार-विमर्श में लोक-सेवकों के कार्यों की कटु आलोचना होती है।

(ग) अल्पकालीन विचार-विमर्श के समय—अत्यवश्यक लोकहित के विषय पर विचार करते हुए संसद सदस्यों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को बाद-विवाद का विषय बनाया जा सकता है। यह बाद-विवाद अम्पस की अनुमति से अधिक से अधिक ढाई घण्टे का हो सकता है। उक्त अवसरों पर संसद में विचार-विमर्श एवं आलोचना के लिए प्रशासन उतरदायी रहता है।

(6) स्थगन प्रस्ताव—संसद सदस्य किसी विभाग के अधिकारियों के अत्याचार एवं ज्यादतियों के विरुद्ध सदन में स्थगन प्रस्ताव रख सकते हैं। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों की सदन में कटु आलोचना की जाती है जिससे जनता में इन अधिकारियों की बदनामी होती है।

(7) अविश्वास प्रस्ताव—इसे संसद का अनोप शस्त्र माना जाता है। यदि नागरिक सेवकों के कार्यों के प्रति गहरा असन्तोष है तो कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान लोक-सेवकों की कटु आलोचना की जाती है। प्रशासनिक कमजोरियों, असफलताओं एवं ज्यादतियों पर प्रकाश डाला जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर पराजित होने पर सरकार को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।

(8) संसदीय समितियाँ—संसद की समितियाँ लोक प्रशासन पर नियन्त्रण रखने का सबसे साधन हैं। कई संसदीय समितियों का मूल उद्देश्य विस्तृत अध्ययन के बाद यह जानकारी प्राप्त करना है कि कौन अनियमितता बरती जा रही है? कौन अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है? किन्हीं द्वारा जनहित विरोधी कार्य किए जा रहे हैं? तथा कौन जनता के धन का अपव्यय कर रहा है? संसद की इन नियन्त्रक समितियों के तीन नाम उल्लेखनीय हैं। आश्वासन समिति, जनलेखा समिति और प्राक्कसन समिति। आश्वासन समिति के नियन्त्रण के कारण मंत्री आश्वासन देते समय सजग रहते हैं।

(9) लेखा परीक्षण—पात का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) विभिन्न सरकारी विभागों के लेखों की जाँच करता है तथा अनियमितताओं का पता लगाता है। लोक मेवब लेखा परीक्षा के मध्य से आतंकित रहते हैं तथा जनता के धन का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं।

संसदीय नियन्त्रण की समस्याएँ एवं सीमाएँ
(Problems and Limitations of Parliamentary Control)

प्रो. एपलबी (Prof. Appleby) के मतानुसार प्रशासनिक कार्यों में संसद का हस्तक्षेप नियन्त्रण की परिधियों में सीमित न रहकर महात्वाकीर्षी बन जाता है, इससे लोक-सेवकों के कार्य प्रतिबन्धित हो जाते हैं। भारत में सामन्तवादी परम्पराएँ, जनता और अधिकारियों के मध्य दूरी तथा शिक्षा का निम्न स्तर होने के कारण संसदीय नियन्त्रण वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसकी प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) गैर-विशेषज्ञता—संसद के सदस्य गैर-विशेषज्ञ होने के कारण लोक-सेवकों की ठोस रचनात्मक आलोचना नहीं कर पाते हैं। लोक-सेवक स्वेच्छावारी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि वे सांसदों की पकड़ में नहीं आते हैं। परिणामस्वरूप संसदीय नियन्त्रण का क्षेत्र समुचित हो जाता है। अधिकारशाली संसद गैर अनुभवी होते हैं, फलतः संसदीय नियन्त्रण की उपयोगिता कम हो जाती है। इस प्रकार संसदीय नियन्त्रण प्रभावशाली एवं सार्थक नहीं हो पाता है।

(2) आलोचना के लिए आलोचना—सांसदों द्वारा प्रशासन की आलोचना उसमें सुधार करने या कार्य कुशलता लाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि दार्शनिक दृष्टि के स्तरों को प्रभावित करने, समाचार-पत्रों में फोटो सहित नाम प्रकाशित करवाने तथा जनता में सख्ती लोकप्रियता पाने के लिए की जाती है। उनकी आलोचना के पीछे पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत मनमुटाव उतरदायी रहते हैं। यह स्थिति लोक-सेवकों के मनोबल को गिराती है। आलोचना के लिए की गई आलोचना सार्थक नहीं होती है और लोक-सेवकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(3) उतरदायित्व का प्रश्न—संसदीय नियन्त्रण के कारण मन्त्रिण अपने कन्धे से लोक-सेवकों के कार्यों का दायित्व उतार देते हैं। जब प्रशासनिक अनियमितता का दोष मंत्री पर डाला जाता है तो मंत्री उसे लोक-सेवकों की गलती बताकर बच निकलता है अथवा बच निकलने का प्रयास करता है। सांसदों द्वारा की गई नीति की आलोचना के उतर में मंत्री कहते हैं कि नीति ठीक थी, मगर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सही रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया। इससे लोक-प्रशासन अकार्यकुशल तथा ग्रह बन जाता है।

(4) **एकपक्षीय आलोचना**—संसद में लोक-सेवकों की आलोचना एकपक्षीय होती है, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस भय से लोक-सेवक प्रभावशाली सासदों को खुश रखने की नीति अपनाते हुए जलजित और ईमानदारी को ताक पर रख देते हैं। उनकी राजनीतिक निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। सासदों का आश्रय एवं सारक्षण प्राप्त करने के लिए वे अवैध या अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाते हैं।

(5) **दलगत राजनीति**—मंत्रियों के अधीन होने के कारण लोक-सेवकों को बहुमत दल का अंग मान लिया जाता है और जिस प्रचुर सत्ताधारी दल की आलोचना करना विरोधी दलों का धर्म होता है उसी प्रकार लोक-सेवकों के प्रत्येक कार्य की आलोचना करना उनका वर्तव्य मान लिया जाता है। वे आनोचक निष्पक्ष नहीं होते हैं। वे दलीय पक्षपात के कारण लोक-सेवकों के चरित्र और व्यवहार पर लाइन लगाने हैं। लोक-सेवक प्रत्येक दल की सरकार का समर्थन देने के लिए बाध्य होते हैं।

(6) **सौंदर्यात्मिक स्थिति**—पारतीय संविधान के अनुसार विधायी कार्यों का उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है। विभाग में होने वाली प्रत्येक गड़बड़ी, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं ज्यादती के लिए मंत्री को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, लोक-सेवकों को नहीं। रासदीय बहस के समय मंत्री के विरुद्ध तर्क-वितर्क प्रस्तुत कर, वह किसी लोक-सेवक पर प्रत्यक्ष रूप से लाइन नहीं लगाए।

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन

(Changing Socio-Economic Profile)

संसदीय नियन्त्रण का प्रशासनिक जीवन पर प्रभाव (Effects of Parliamentary Control over Administrative Vitality)—सिद्धान्त रूप में संसदीय नियन्त्रण के अच्छे उद्देश्य हैं, लेकिन व्यवहार में अपनी अनेक सीमाओं एवं समस्याओं के कारण संसद प्रभावशाली नियन्त्रण रखने में समर्थ नहीं है। जो नियन्त्रण वर्तमान है उसका प्रभाव प्रशासन, प्रशासकों के व्यवहार, विचार एवं स्थिति तथा संगठन की रचना एवं कार्यकुशलता पर निम्नलिखित प्रकार से है—

(1) **प्रशासन में हस्तक्षेप**—नियन्त्रण की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए संसद प्रशासनिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। प्रशासनिक तकनीकों से अनभिज्ञ सासदों तक यह पक्षपातपूर्ण होता है। पूर्वाग्रहों, व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित होकर वे लोक-सेवकों को भ्रष्टाचारी बना देते हैं। कर्तव्य भावना, ईमानदारी तथा जनहित को भावना से कार्य करने वाला कर्मचारी निन्दा का पात्र बनता है और दुराचारी स्वार्थी और भ्रष्टाचारी चमचागिरी में सिद्धहस्त व्यक्ति प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त करता है, फलतः राजनीतिक हस्तक्षेप से गम्भीर प्रशासनिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

(2) **अनामता असम्भव बन जाती है**—लोक-सेवक प्रायः अनाम रहकर कार्य करता है। वह मंत्री द्वारा हस्तान्वित शक्तियों का उपयोग करता है। उसके निर्णय तथा कार्य पर सम्बन्धित मंत्रियों के हस्ताक्षर होते हैं। यदि उनकी कोई आलोचना या विरोध करे तो मंत्री उसका जवाब देता है और लोक-सेवक पदों के पीछे रहकर कार्य करना रहता है। संसदीय नियन्त्रण में उसकी यह अनामता समाप्त हो जाती है। संसद में उस पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाये जाते हैं, उसकी खुले रूप में आलोचना की जाती है। इससे अनामता के सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं और नई प्रशासनिक उलझने पैदा हो जाती हैं, परिणामस्वरूप प्रशासक भय अनुभव करते हैं।

(3) **जनता में बदनामी**—संसदीय नियन्त्रण लोक-सेवकों के व्यवहार की गनी-गनी की चर्चा का विषय बन देता है। संसद में जब मंत्री पर आरोप लगते हैं तो वह बचाव के लिए लोक-सेवकों पर सारे दोष मढ़ देता है। पद की मर्यादा और सेवा के नियमों का पालन करते हुए जब लोक-सेवकों पर इस प्रकार के दोषारोपण होते हैं तब वे एक गम्भीर उत्पन्न में पँस जाते हैं।

(4) **निष्पक्षता असम्भव हो जाती है**—संसदीय नियन्त्रण के कारण लोक-सेवक यह मानते हैं कि वहाँ यदि ईमानदारी से कार्य किया तो दण्ड मिलेगा, यदि निष्पक्षता बरती तो बदनाम होना पड़ेगा, यदि सम्पन्नतापूर्ण व्यवहार किया तो कमजोर माना जाएगा और राजनीतिक प्रभाव की अवहेलना की तो पद से हटाया होगा पड़ेगा, फलतः वह राजनीतिक हस्तक्षेप को सहर्ष स्वीकार करके स्वार्थ-सिद्धि का प्रयत्न करता है।

(5) **कार्य-कुशलता की क्षति**—संसदीय आलोचना के भय से लोक-सेवक व्यक्तिगत परामर्श कर निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। वे नींवियों, निर्णयों के लिए संसद की राय देखते रहते हैं, फलतः निर्णय उस समय लिए जाते हैं जबकि इनका महत्व एवं उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता घटती है और प्रशासन बन्धनमय नहीं रह पाता है।

(6) **लोकसेवकों में भ्रष्टाचार**—निर्णायक शक्ति के अभाव में लोक-सेवकों की प्रशासनिक कार्यों में व्यक्तिगत रुचि नहीं रहती है। उनमें असन्तोष और निराशा बढ़ती है तथा उत्साह और प्रेरणा तुल्य हो जाती है। अनेक कार्यों को बिना रुचि के ही हड़ोत्साहित हो जाता है। वह अपने जीवन में 'छानो और छाने दो' का सिद्धान्त अपना लेता है, संगठन का पतन हो जाता है।

वित्त पर संसदीय नियन्त्रण : लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति (Parliamentary Control over Finance : Public Accounts Committee and Estimates Committee)

वित्त पर संसदीय नियन्त्रण प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था की मूल्यपूर्ण विशेषता है। सरकारी व्यय पर प्रभावशाली संसदीय नियंत्रण आवश्यक है। अतः आवश्यक है कि संसद स्वयं इसे इस बात के प्रति अश्वस्त न करे कि विनियमनों का उपयोग अनुमानित प्रयोजनों के लिए अनुमानों की सीमा में किया जा रहा है और नह (संसद) सरकार के वार्षिक बजट अनुमानों का समुचित परीक्षण करती रहे ताकि वित्तीय नियन्त्रण बना रहे और बजट अनुमानों में निहित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के परिचालन में मितव्ययता सम्बन्धी सुझाव दिए जा सकें। प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाओं में संसद अथवा व्यवस्थापिका की रचना ऐसी होती है कि उसके पास इन कार्यों को पूरा करने के लिए न तो समय होता है और न आवश्यक शक्ति। इसलिए इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए संसदीय समितियों और संस्थाओं का विकास हुआ है।

सन् 1921 में केन्द्रीय व्यवस्था में निर्वाचित बहुमत का प्रावधान किया गया है और उसे पूर्ति पर मत देने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार के साथ लोक लेखा समिति का संगठन आवश्यक हो गया जिसमें निर्वाचित और सरकारी दोनों प्रकार के सदस्यों का स्थान दिया गया। प्राक्कलन समिति की रचना 1950 में हुई। इसका उद्देश्य वार्षिक बजट के अनुमानों का विस्तृत परीक्षण करना है ताकि वह नये निहित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मितव्ययता का सुझाव दे सकें। दोनों वित्तीय समितियाँ प्राण्य में ग्रेट ब्रिटेन के मॉडल पर निर्मित की गईं किन्तु बाद में इनकी रचना और कार्यों में कुछ परिवर्तन आ गए। इन समितियों के माध्यम से संसद के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व स्थापित किया जा सकता है।

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)

लोकसभा कारदाताओं के ऐसे ही बहुत बड़े धनराशि के खर्चों की स्वीकृति देने के बाद कारदानाओं के हित में इस बात की आशा करती है कि उचित समय पर व्ययवार हिसाब दिया जाए कि वह पैसा किस प्रकार खर्च किया गया है। लोकसभा को समझाने का पद्धत है कि उसने जिस धनराशि का खर्च की स्वीकृति दी थी, वे मन्जूरी दी गई प्रयोजनों के लिए खर्च हुई है और मितव्ययता से तथा विवेकशीलता से खर्च हुई है या नहीं। नियन्त्रण तथा महालेखा परीक्षक सरकार के वार्षिक लेखों की परीक्षण करता है और इसके बाद लेखों का प्रमाण-पत्र देता है और उस सम्बन्ध में जो राय उचित समझता है देता है। वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के सामने रख देता है। लोकसभा के लिए इन लेखों की जाँच करना बहिन कार्य है क्योंकि ये बड़े जटिल और तकनीकी होते हैं और उसके पास विस्तृत ज्ञान के लिए समय नहीं है। इसलिए लोकसभा ने लोक लेखा समिति बनाई है। इन लेखों की व्योवर जाँच का काम लोक लेखा समिति को सौंपा गया है।¹

संरचना—सन् 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही लोक लेखा समिति में से सरकारी तत्व हट गए हैं और यह एक सच्ची संसदीय समिति बन गई है। आरम्भ में इसमें 15 सदस्य थे जो लोकसभा के सदस्य होते थे किन्तु 1954-55 से राज्यसभा के 7 सदस्यों को भी समिति में लिया जा रहा है। अतः वर्तमान में समिति में कुल 22 सदस्य हैं। समिति में उच्च सदन के सदस्यों का लिया जाना ब्रिटिश परम्परा के विपरीत है, क्योंकि वहाँ लोक लेखा समिति में लॉर्ड्स सभा का कोई सदस्य नहीं होता। स्पष्टकर द्वारा एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है जो प्रायः सभापति रहता होता है। समिति में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व सदन में उनके अनुपात के अनुसार होता है। समिति दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करती है। समिति में राष्ट्रिय का कार्य संसदीय सचिवद्वारा किया जाता है। समिति की बैठकों में वित्त मन्त्रालय की ओर से एक पर्यवेक्षक उपस्थित होता है ताकि नए परिवर्तनों और विकास से मन्त्रालय को परिचित रख सकें।

समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता। समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, प्रत्येक वर्ष नई समिति का निर्वाचन किया जाता है। यह पुरानी समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही कार्य सम्भालती है। सामान्यतया समिति प्रत्येक वर्ष मई में बनाई जाती है और उसका कार्यकाल अगले साल 31 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष या सभापति का कार्यकाल भी एक वर्ष का होता है।

कार्य—संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार लोक लेखा एवं लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाते हैं। लोकसभा के सामान्य सभाओं को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोक लेखाओं के परीक्षण के लिए निजो लोक लेखा समिति गठित कर ले, परन्तु यदि एक ही क्षेत्र में एक-सी बातों के लिए दो समितियाँ

पहुँचने वस्तु निष्पत्ती की व्यवस्था के डिब्बों से है सम्बन्धित व्यक्तियों से नहीं। समिति के मुझों पर की गई कार्यवाही से विभाग समिति को अदम्य करता है और यह इसकी पर्याप्तता के सम्बन्ध में मत प्रकट करती है। इसे सिफारिशों निम्नित करने का शक्ति प्राप्त नहीं है जिससे इसकी प्रभावशालिता में कमी नहीं आती है। इसके द्वारा की गई अलोचना का नैतिक प्रभाव होता है।

दोष—जन-सेवा समिति के प्रारम्भ से संसद के वित्तीय नियन्त्रण में कुछ कठिनाइयाँ बरिसों और दोष आ जाते हैं। समिति का घण्टन एवं कार्य-प्रणाली को आलोचकों ने दोषपूर्ण माना है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

1 सी. एच. ए. जी. के प्रतिवेदन आने तक समिति निष्क्रिय रहती है, क्योंकि कार्य प्रतिवेदन आने के बाद प्रारम्भ होता है।

2 समिति केवल उन्नी प्रश्नों का परीक्षण कर सकती है जो सी. एच. ए. जी. के प्रतिवेदन में उठाए गए हैं।

3 समिति के सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते। वे मुख्यतः राजनीतिज्ञ होते हैं और हमेशा बहुरंग दबावों से घिरे रहते हैं इसलिए निष्पक्ष नहीं रह पाते। वे राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं। वे केवल अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर प्रस्ताव करते हैं। उन्हें ऐसे व्यक्तियों से प्रश्न पूछने होते हैं जो अपने विषय के पूरे जानकारी तथा विशेषज्ञ होते हैं।

4 समिति नियुक्त करने के बाद संसद वित्तीय नियन्त्रण के कार्य में कुछ उदासीन बच जाती है जिससे सरकार समिति की सिफारिशों को आगुना से भुल सकती है।

5 समिति का नियन्त्रण परवर्ती होता है। यह पार्लियामेंट अध्ययन करता है। जैसे सदन के बने जाने के बाद उसकी लकार को पोट्टा रहना। अर्थात् प्रशासनिक विभागों द्वारा अपव्यय, अनियमितता आदि की जा चुकी जाती है तब समिति उस पर विचार करती है।

6 समिति के कार्यों पर नैतिक-सम्बन्धी आपत्ति उल्लेखनीय है अर्थात् समिति प्रशासनिक अपव्यय को रोकने में लाभदायक हो सकती है किन्तु लोकसभा द्वारा प्रतिपादित अपव्ययपूर्ण नितियों के सामने यह असहाय बन जाती है।

महत्त्व—उपयुक्त अलोचनाओं के महत्वपूर्ण होने के बावजूद समिति का महत्व कम नहीं है। इसके सदस्य निरन्तर कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं। यह अनुभव तथ्यों एवं गवाहों की जाँच करते समय पर्याप्त महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यह विभागों का आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती। इसका व्यापार (पोस्टमार्टम) अध्ययन निरपराधी नहीं है। सिटनी बेर के कथनानुसार “पोस्टमार्टम अध्ययन यदि मृत को जिन्दा नहीं कर सकता तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इससे हत्याएँ नहीं हटती।” समिति की सिफारिशों पर सरकार को विचार करना होता है। कोई विभागीय सचिव यह नहीं चाहता कि उसका विभाग समिति की आलोचना का शिकार बने। व्यपकारी विभाग जन-सेवा समिति से अधिक भयभीत रहते हैं क्योंकि समिति की गहरी छाँबीन से कुछ भी बचने की सम्भावना नहीं रहती है।

स्वतंत्रता के बाद इस समिति के कार्य पर्याप्त सन्तोषजनक रहे हैं। प्रशासन द्वारा समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाता है। संसद में प्रश्न पूछते समय तथा सरकारी व्यय की अलोचना करते समय सासनों द्वारा समिति के प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों का पूरा लाभ उठाया जाता है। जन-सेवा समिति रचनात्मक भावना से कार्य करती है। इसके नियन्त्रण का प्रभाव प्रतिरोधात्मक है। मोरिस बोनस (Morris Bones) के मतानुसार जन-सेवा समिति तीन दशाओं में मुख्य रूप से सफल रही है—

1 यह प्रशासन के उन दोषों को जनता के सामने रखती है जिनके बारे में प्रशासन का जानकारी तो रहता है किन्तु वह उन्हें पूरी तरह दूर नहीं कर पाती है।

2 समिति और सी. एच. ए. जी. का अस्तित्व अधिकारियों की सदैव रखता है कि उनके कार्यों का शूश्य परीक्षण किया जाएगा। यद्यपि यह परीक्षण व्यय होने के बाद किया जाता है तथापि व्यय की प्रकृति में निरन्तरता रहने के कारण यह महत्वपूर्ण रहता है।

3 यह समिति अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों को एक-दूसरे के निकट लाती है। यह दोनों का मार्गदर्शन करता है। यह अधिकारियों की जनमत के अनुसार चलने का तथा राजनीतिज्ञों को रचनात्मक अलोचना करने का अवसर देती है। प्रायकलन समिति (Estimates Committee)

लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि बजट के किसी भाग को स्वीकृति प्रदान करे तथा स्वीकृति देने से इनकार कर दे या उसमें निश्चित रकम की कटौती सहित पास कर दे तथा भारत की सचिव निधि पर धार्मिक खर्च के सम्बन्ध में प्रायकलन पर विचार करे। यद्यपि लोकसभा प्रायकलनों पर कभी लम्बे समय तक विचार करती है, परन्तु शायद के पास न तो समय है और न ही इतनी गुंजाइश कि प्रायकलनों के ज़ोरे तथा उनके तकनीकी पहलुओं पर विचार कर सके।

के सक्रिय निरीक्षण से सरकारी यन्त्र में यह चेतावनी जाग्रत हो जाती है कि उसके प्रस्तावों की गहराई से छानबीन की जाएगी।" यह कार्यभारिणी एवं प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध है। इसकी अन्त तक की सिफारिशों को देख कर विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह पर्याप्त उपयोगी समस्याओं को अपने निवारण का विषय बनाती है।

दोष एवं कमियाँ—प्राक्कलन समिति की कार्य-प्रणाली एवं संगठन के बारे में आलोचकों ने मुख्यतः निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है—

(क) जन-सेवा समिति की भाँति यह समिति संसद द्वारा सम्पत्ति नीतियों की आलोचना नहीं कर सकती।

(ख) यह समिति सी. एवं ए. बी. के सहयोग तथा परामर्श से स्थापनित नहीं हो पाती। इसका कोई परामर्शदाता नहीं है।

(ग) यह समिति जिस विभाग का परीक्षण कर लेती है वह कई वर्षों तक के लिए निर्णित हो जाता है। फलतः उस विभाग में असावधानी और लापरवाही घनपने लगती है।

(घ) यह प्रशासन में केवल उन्हीं परिवर्तनों का परामर्श देती है, जो अनुमानों को प्रभावित करते हैं। सरकार इसकी सिफारिशों की अवहेलना कर सकती है।

(ङ) अशोक चन्दा के मतानुसार समिति के कार्यों का विस्तार एवं उनका कार्य करने का ढंग सर्वाप्त होपपूर्ण है।

विभिन्न कमियाँ और दोष होते हुए भी यह एक मान्य तथ्य है कि संसद की ये दोनों समितियाँ प्रशासन पर वित्तीय निगरान का प्रभावपूर्ण साधन हैं। इनके सदस्य अपने सम्यक् अनुभव के बाद कार्य में विरोधता प्राप्त कर लेते हैं। सरकार इसकी सिफारिशों की अवहेलना नहीं कर पाती और व्यवकारी विभागों के सिर पर ये 'डेमोक्रेसीज की तानवार' की भाँति लटकी रहती हैं। प्राक्कलन समिति भारत में प्रशासन की योग्यता तथा उसके स्तरों को उन्नत करने में महत्वपूर्ण योग दे रही है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय

(The Supreme Court & the High Courts)

उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधारों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधारा से पचास परामर्शों द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधारा की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ठन न्यायाधारों के साथ परामर्श करना आवश्यक समझा गया है जिनके साथ परामर्श करना वह अधिक समझे।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधारा नियुक्त किये जाने के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या किसी उच्च न्यायालय या दो अथवा दो से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगाचार वकालत रह चुका हो या वह राष्ट्रपति का राय में कानून का प्रबन्ध पठित हो। यह व्यवस्था देश के उच्चतम विधि-विशारदों का आकर्षित करने के लिए रखा गई है। न्यायाधारों का नियुक्ति करने का राष्ट्रपति का शक्ति व्यवहार में औपचारिक है क्योंकि वह प्रतिनिधित्व की सलाह से कार्य करता है।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उपस्थित होने वाले विवाद

मुख्य न्यायाधारा की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुच्छेद 124 में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधारा को ही मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया जा सकता है। संविधान में ऐसा वाद्यता न होने के बावजूद उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधिपति के पद पर नियुक्त करने की परम्परा रही। सन् 1956 में विधि आयोग ने यह सुझाव दिया था कि मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होना नहीं बल्कि न्यायाधारों के गुण और उपयुक्तता के आधार पर की जाना चाहिए। प्रथम बार 1964 में वरिष्ठता की परम्परा का पालन नहीं किया गया जब जकर इमान को मुख्य न्यायाधारा नहीं बनाया गया यद्यपि वे वरिष्ठता में सर्वोच्च थे। ऐसा उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों का दृष्टिगत रखकर किया गया था। इससे कोई एक-दो विवाद उपस्थित नहीं हुआ था। 1973 में इस प्रश्न पर सार्वजनिक विवाद उठ खड़ा हुआ। 25 अप्रैल, 1973 को हेमचन्द्र भारती के मामले पर दिए गए निर्णय के कुछ घंटों के पश्चात ही सरकार ने अग्रप्राप्त उम्र से वरिष्ठताक्रम की उपेक्षा करके न्यायाधारा अजितनाथ राय को भारत का मुख्य न्यायाधारा नियुक्त किया। उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधारों—जे. एम. सैलट, क. एम. इगडे तथा एस. एन. मोरार ने केन्द्र सरकार के निर्णय से क्षुब्ध होकर पदों से त्यागपत्र दे दिया। सरकार के इस रवैय की बढ़ी मात्र आलोचना हुई और उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन ने बहुमत से पारित कर एक प्रस्ताव में आरोप लगाया कि उपरोक्त नियुक्ति विरुद्ध राजनीतिक आधार पर की गई थी जिसका योग्यता तथा वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं था।

दुसरी ओर लोकसभा में सरकार के कर्म का समर्थन करते हुए तत्कालीन विधि मंत्री एच. आर. गोखले ने कहा कि राय की नियुक्ति पूरा रूप से सार्वजनिक था। इस हेतु निम्न तर्क प्रस्तुत किये गये—(1) सार्वजनिक उपबन्ध (Constitutional Provision) (2) विधि आयोग की सिफारिशें (Recommendations of Law Commission) (3) अन्य देशों का उदाहरण (Precedents of Other Countries) (4) न्यायाधारों का सामाजिक दर्शन (Social Philosophy of Judge), (5) न्यायाधिपति के कार्यकाल की अवधि (Time Period of Judges)। 1977 में न्यायाधारा अजितनाथ राय की सार्वजनिकता के बाद पुनः वरिष्ठता के सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया। वरिष्ठतम न्यायाधारा एच. आर. खन्ना के स्थान पर उनके कानून एच. एम. बेग का मुख्य न्यायाधारा बनाया गया। इसका विरोध में खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। 1978 में मुख्य न्यायाधिपति एच. एम. बेग का सेवा निवृत्त होने पर

यह प्रश्न फिर से उठा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश की नियुक्ति की कसौटी क्या 'नी चाहिए? जनता सरकार ने पुनः परिष्ठा की कसौटी के आधार पर न्यायाधिश चन्द्रचूड को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर इस विवाद को समाप्त कर दिया।

न्यायाधीश की क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन

न्यायाधीश पद पर वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रहते हैं।¹ कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति की लिखित सम्मति प्राप्त अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उसे दुर्लभता करने तथा कार्य में अक्षम होने के प्रमाणित आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। व्याख्या है कि "उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा प्रमाणित दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्राप्त इस आशय का प्रस्ताव न मिल जाए।"² सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामास्वामी के विरुद्ध लगाया गया महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ऐसा प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। पदच्युति की कठिन प्रक्रिया अपनाने का कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है।

न्यायाधीशों के वेतन और विशेषाधिकार

संविधान की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमास वेतन दिया जाना निश्चित किया है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश को 33,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 30,000 रुपये प्रतिमास वेतन और निराल्प शासकीय निवास दिया जाता है। न्यायाधीशों को यह वेतन भारत की संपत्ति निधि से देय होता है तथा उनके कार्यकाल में उनके वेतन-पत्रों को कम नहीं किया जा सकता है।

अनुक्ति (Immunities)

भारत में उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कार्यों और निर्णय के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है तथापि न्यायालय के किसी निर्णय अथवा किसी न्यायाधीश की किसी सम्पत्ति की शीर्षावधि दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। संसद महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं कर सकती है। न्यायालय को अधिकार है कि वह अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए और शत्रुतापूर्ण आलोचना से अपना रक्षा करने के लिए तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय अवमानना की कार्यवाही कर सके।

उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार

(Jurisdiction of the Supreme Court)

भारत के उच्चतम न्यायालय की विधि के सम्भवतः अन्य किसी भी न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं जिन्हें निम्नांकित चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

(क) अभिलेख क्षेत्राधिकार (Court of Records) अनुच्छेद 129

अभिलेख न्यायालय के सभी कृत्य एवं कार्यवाहियाँ सदैव के लिए यादगार एवं प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखा जाती हैं। इन अभिलेखों पर न अंगुली डलाई जा सकती है और न कोई न्यायालय इन अभिलेखों के विरुद्ध या प्रस्ताव है यापि अभिलेख न्यायालय अपने अभिलेखों की सति सम्बन्धी श्रृंखला में सुधार कर सकता है। अभिलेख न्यायालय का इस दृष्टि से भी महत्व है कि वह अपने अवमानना (Contempt of Court) के लिए दण्ड देने की शक्ति रखता है जो उसे संविधान द्वारा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त संसद ने "न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971" (Contempt of Court Act, 1971) पारित करके "न्यायालय अवमानना" की एक निश्चित परिभाषा कर दी है। न्यायालय-अवमानना के लिए 6 महीने की सजा या 2,000 रु का जुर्माना या दोनों विधे जा सकते हैं। न्यायाधीशों को भी अपने न्यायालय की अवमानना के लिए दण्डित किया जा सकता है।

44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार उच्चतम न्यायालय यदि चाहे तो उच्च न्यायालय से मामलों का अपने पास मंगा सकता है।³ संशोधन के पूर्व न्यायालय ऐसा केवल एटार्नी जनरल के आवेदन पर ही कर सकता था। अब यह ऐसा स्वयं कर सकता है।

1 अनुच्छेद 124(2)

2 अनुच्छेद 124 (1) (ख) एवं (4)

(ग) अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) अनुच्छेद 132¹ से 136

उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है अर्थात् उसे देश के राज्यों के उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (अ) सर्वोपनिषद मामले (अनुच्छेद 132) | (ब) दीवानी मामले (अनुच्छेद 133) |
| (स) फौजदारी मामले (अनुच्छेद 134) | (द) विविध पुनर्विचार (अनुच्छेद 136) |

(अ) संवैधानिक मामले (Constitutional Cases)—अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में सविधान की व्याख्या से सम्बन्धित प्रश्न अन्तर्निहित है तो उस निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर दिया है किन्तु उच्चतम न्यायालय को यह विश्वास हो कि विवाद में सविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो वह स्वयं अपील की अनुमति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय में अपील उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के विरुद्ध की जा सकती है। अन्तिम आदेश वह आदेश होता है जो पक्षकारों के अधिकारों का अन्तिम रूप से निपटारा करता है। यदि आदेश के बाद भी मुकदमा जीवित है अर्थात् जिसमें अधिकारों का अभी निपटारा किया जाना शेष है तो उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इलेक्शन कमोरान बनाम वीक्टराव के सार में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

(ब) दीवानी मामले (Civil Cases)—अनुच्छेद 133 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को दीवानी अपालीय अधिकार प्राप्त हैं। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय या अन्तिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे दे कि—(क) मामले में सार्वजनिक महत्व का कानूनी प्रश्न निहित है, (ख) उच्च न्यायालय के अनुसार इस प्रश्न का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना अधिक है। ये उपर्युक्त अनुच्छेद 133 में सविधान के 30वें संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा जोड़े गए हैं, परन्तु उच्च न्यायालय के प्रमाण-पत्र मिल जाने पर भी सर्वोच्च न्यायालय अपील सुनने को बाध्य नहीं है तथा वह ऐसे प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकता है।

(स) फौजदारी मामले (Criminal Cases)—अनुच्छेद 134 के अनुसार फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है जबकि

(क) उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की मुक्ति का आदेश रद्द करके उसे मृत्यु दण्ड सुना दिया हो या आजीवन कारावास का या कम से कम दस वर्ष के कारावास का दण्ड दिया हो।

(ख) उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय का मामला सुनवाई के लिए अपने पास मंगल कर अभियुक्त को मृत्यु दण्ड सुना दिया हो या आजीवन कारावास का या कम से कम दस वर्ष के कारावास का दण्ड दे दिया हो।

(ग) उच्च न्यायालय ने यह प्रमाण पत्र दे दिया हो कि मुकदमा इस लायक है कि उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

सबसे फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है। फौजदारी अथवा दण्डिक विषयों में अपील का प्रमाण-पत्र देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार है, किन्तु उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता है। इस विवेकाधिकार का प्रयोग सुविशेष एवं मन्व्य सिद्धान्तों के आधार पर, जो इन मामलों को विनियमित करते हैं, न्यायिक ढंग से किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय को केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रमाण-पत्र देना चाहिए। तथ्य के प्रश्नों पर अपील करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 134 में उच्चतम न्यायालय, आपराधिक मामलों में एक साधारण न्यायालय की भांति है। इसका आपराधिक अपीलीय अधिकारिता सीमित है और वह उसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही करता है अर्थात् जहाँ न्याय इसकी अपेक्षा करता है कि उसे हस्तक्षेप करना ही चाहिए। साधारणतया उच्चतम न्यायालय साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन नहीं करता है जब तक कि यह न सिद्ध हो जाए कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में अवैधता या अनिश्चितता का सम्भार लोप हुआ है। उच्च प्रदेश राज्य बनाम राजनाथ² के मामले में अभियुक्त को एक मात्र आधार पर विमुक्त कर दिया गया था कि उसके मतो में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य मानने लायक नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्त की विमुक्ति से घोर अन्याय हुआ था क्योंकि उच्च न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य को मंजूर माना किन्तु बिना ही उसे न्याय आधारहीन समझा है, अपना निर्णय दिया था। अतः मामले को पुनः निर्णय के लिए उच्च न्यायालय के पास वापस भेज दिया गया³।

¹ ए आई आर 1983 सुप्रीम कोर्ट, 187

² जयनारायण फण्डेय पूर्वोक्त २ 227

(द) विशिष्ट पुनर्विचार (Special Appeals)—अनुच्छेद 136, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों विशिष्ट या अवशिष्ट (Special or Residuary) शक्तियों की प्रकृति की हैं। संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 तक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था है। कुछ ऐसे मामले जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते उनमें उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। अनुच्छेद 136 यह व्यवस्था करता है कि उच्चतम न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी बात या विषय में दिए हुए किसी निर्णय, आदेश, निर्धारण, दण्डादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। इसमें अववाद केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।

अंग्रेजीय क्षेत्राधिकार की दृष्टि से भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय है।

न्यायाधिकरण (Tribunals)¹—अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय की अपील सुनने की शक्ति केवल न्यायालयों तक ही सीमित नहीं है। यह 'न्यायाधिकरणों' से भी अपील सुन सकता है। 'न्यायाधिकरण' शब्द के अन्तर्गत वे सभी निम्नलिखित हैं जिनमें न्यायिक शक्तियाँ निहित हैं और जिनके निर्णय नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत वे न्यायाधिकरण शामिल नहीं हैं जो विशुद्ध रूप से केवल प्रशासनिक और कार्यकारी के कृत्य करते हैं या जो केवल विपक्षी कृत्य करते हैं। उदाहरणार्थ, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल्स, लैबर अरीबेट ट्रिब्यूनल्स, चुनाव आयोग, रेलवे रेट ट्रिब्यूनल्स आदि न्यायाधिकरण हैं जो यद्यपि सही मामले में न्यायालय हैं, किन्तु उनमें न्यायालय के कुछ कृत्य निहित हैं। न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय या निर्धारणों में यह निम्नलिखित अपार्यों पर ही हस्तक्षेप करेगा—

(1) जहाँ न्यायाधिकरण उस क्षेत्राधिकार के बहरा कार्य करता है जो उसे सृजित करने वाले अधिनियम या विनियम के अधीन प्रदान किया जाता है या जहाँ वह किसी प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल हो जाता है, (2) जहाँ कि निर्णय में प्रत्यक्ष रूप से कोई भूल की गई हो, (3) जहाँ कि न्यायाधिकरण के निर्धारण (Awards) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध किया है जिससे पक्षकारों के साथ घोर अन्याय हुआ है, (4) जहाँ न्यायाधिकरण ने सुस्थापित प्राकृतिक सिद्धान्तों को गलत ढंग से लागू किया है, उदाहरणार्थ कमकता दाम्नेन बनाम कमकता दाम्नेन के लिए² का निर्णय।

(घ) परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) अनुच्छेद 143

उच्चतम न्यायालय के कतिपय महत्वपूर्ण परामर्श सम्बन्धी कार्य भी हैं। सार्वजनिक महत्व का कोई कानूनी प्रश्न अथवा तथ्य तथा वे बातें जिनका सम्बन्ध सन्धियों, करारों आदि की व्याख्या से होता है और जो न्यायालय के मूल न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते, सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है।

कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी परामर्शकारी शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 का निर्माण करते समय हमारे संविधान-निर्माताओं ने कनाडा के संविधान का अनुसरण किया। अनुच्छेद 143 के निर्वाचन पर उच्चतम न्यायालय का मत समान नहीं रहा। सर्वप्रथम इन री एड्मिनिस्ट्रेशन बिज (1957)³ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उस पर ऐसा कोई संविधानिक दायित्व अधिरोपित नहीं किया गया है कि आवश्यक रूप से राष्ट्रपति को अपना परामर्श भेजे। अनुच्छेद 143(1) में 'प्रयुक्त कर सकेगा' (May) शब्दवाची यह दर्शाती है कि उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह अपनी राय दे या न दे। उच्चतम न्यायालय को कौनसे प्रश्न सौंपे जाएँ इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के इस निर्णय पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय यद्यपि सम्मान के योग्य है, परन्तु वह न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। सन् 1993 में राष्ट्रपति ने 'अयोध्या विवाद' के मामले में उच्चतम न्यायालय का परामर्श माँगा था, किन्तु उपर्युक्त निर्णय के विपरीत इन री स्पेसियल बोर्डर बिज 1978⁴ में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व विनिश्चयों की बदलते हुए यह अधिनियमित किया कि अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है।⁵ न्यायालय ने यह सलाह दी कि राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि जिन प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय के

1 जयन्तशरण फर्ग्युसन: एडोक्, पृ. 227.

2 ए. आई. आर. 1947, सुप्रीम कोर्ट, 2192.

3 ए. आई. आर. 1958, सुप्रीम कोर्ट, 956.

4 ए. आई. आर. 1978, सुप्रीम कोर्ट, 956.

5 ए. आई. आर. 1979, सुप्रीम कोर्ट, 478.

परामर्श की आवश्यकता है उन्हें स्पष्ट एवं निर्दिष्ट रूप से संदर्भित किया जाए। न्यायालय ने अपनी अग्रगण्य ध्वज करते हुए कहा है कि यदि ऐसे प्रश्न अस्पष्ट हैं तो उच्चतम न्यायालय या अधिरोपित संवैधानिक बाधता का महत्व नहीं रह जाता। यह सर्वविदित है कि प्रस्तुत मामले में राष्ट्रपति ने विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु उच्चतम न्यायालय की राय माँगी थी। विशेष न्यायालयों की स्थापना से सम्बन्धित विषयों को सिद्धान्तक स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विधेयक में तीन अन्य शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक बताया था, जिसे राष्ट्रपति ने बर्खास्त स्वीकार कर लिया। अन्ततोगत्या विशेष न्यायालय विधेयक पारित कर दिया गया। सविधान्य स्वरूप होने के दिन से अभी तक निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय ने परामर्श दिया है—

(1) 1951 में 'द देवली सौज एक्ट अन्धेर मेराष्ट्रा से सम्बन्धित अधिनियम और फॉर्ट सी अधिनियम की वैधता के प्रश्न पर (2) 1957 में केरल शिक्षा विधेयक के प्रश्न पर (3) 1956 में एन.टी. वेरुवाती के प्रश्न पर (4) 1962 में एन.टी. दि.सी. कस्टम्स एक्ट के प्रश्न पर (5) 1965 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से सम्बन्धित सार्वभौम विरोधाभास के प्रश्न के संदर्भ में (6) 1974 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय पर (7) 1978 में विशेष न्यायालयों की स्थापना के सम्बन्ध में (8) 1993 में अयोध्या विवाद के सम्बन्ध में।

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के सम्बन्धकारी स्वरूप

इस सम्बन्ध में प्रख्यात विधिशास्त्री डॉ. पाण्डेय के अनुसार "अनुच्छेद 141 यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों में आवश्यकता होगी। प्रश्न यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व-निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 141 में प्रयुक्त सब न्यायालय पदावली से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें उच्चतम न्यायालय सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और उचित मामलों में वह अपने पूर्व-निर्णयों को बदल सकता है।"

भारत इन्फुन्टी कम्पनी बनाम बिहार राज्य के बाद में यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। सविधान के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को अपना दोषपूर्ण निर्णय बदलने का अधिकार प्राप्त है। "उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर पुनर्विचार नहीं करता है जब उसका यह समाधान हो जाता है कि उसने पूर्व विनिश्चयों में गलती की है अथवा यह कि ऐसा विनिश्चय सामान्य सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अथवा यह हमारे सविधान के विविध दर्शन के प्रतिकूल है और सविधान सम्बन्धी विषयों में उच्चतम न्यायालय ऐसे पूर्व विचार अधिक तत्परता से करेगा, किन्तु विधि की अन्य श्रृंखलाओं के सम्बन्ध में इतनी तत्परता नहीं बरती जाएगी। वस्तुओं के निर्णयानुसरण के सिद्धान्त की व्यापकता को प्रस्तुत मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है और कोई स्पष्ट विवशता के सामने आ जाए तो पूर्ववर्त विनिश्चयों को उलट दिया जाना चाहिए।" प्रस्तुत बाद उच्चतम न्यायालय ने यूनाइटेड मोटर्स बनाम बम्बई राज्य के बाद में दिए गए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार किया था और उसे बदल दिया था।

गोलकुन्दाय बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने दो महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती निर्णयों—शकोरी प्रसाद और सज्जनसिंह को उलट दिया था। उक्त दोनों विनिश्चयों में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि सविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 में निहित है और उसके अन्तर्गत पारित किए गए संविधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अन्तर्गत नहीं आते हैं किन्तु गोलकुन्दाय के बाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 में नहीं बल्कि संसद की अवशिष्ट शक्ति में निहित है अतः अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है। केशवानन्द भारतीय बनाम केरल राज्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने गोलकुन्दाय के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया है। न्यायालय ने कहा है कि संविधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा सविधान में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में निहित है।

अतः भारत में पूर्वोदाहरण (Precedents or Stare Decisions) के सिद्धान्त का बहुत सीमित रूप से अनुसरण किया जाता है। यह आधुनिक प्रवृत्ति के अनुकूल है। इलाहाबाद और बम्बई उच्चतम न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि उच्चतम न्यायालय की हस्तोक्ति (Obiter Dicta) अनुच्छेद 141 के अर्थात्तर्गत एक विधि है और इस

- 1 ए.आई.आर. 1955 सुप्रीम कोर्ट 661
- 2 ए.आई.आर. 1953 सुप्रीम कोर्ट, 252
- 3 ए.आई.आर. 1967 सुप्रीम कोर्ट, 1043
- 4 ए.आई.आर. 1951 सुप्रीम कोर्ट, 458
- 5 ए.आई.आर. 1955 सुप्रीम कोर्ट, 805
- 6 ए.आई.आर. 1973, सुप्रीम कोर्ट, 1461

पुनरावलोकन के क्षेत्र की धरती आ रही अस्पष्टता दूर हो गई। 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानन्द भारती विवाद के सम्बन्ध में दिए गये अपने निर्णय में इस संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार कर लिया गया।

(क) अनुच्छेद 246 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति—यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को प्रकट करता है। इसके अन्तर्गत सभ्य अथवा राज्य द्वारा विधायी सोमा का उत्पत्तन एवं असंवैधानिक कार्य है और उच्चतम न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तीनों मूचियों में शक्ति-वितरण की स्पष्ट व्यवस्था है और सभी परिस्थितियों का संविधान में ब्यासम्भव उल्लेख कर दिया गया है अतः उच्चतम न्यायालय को अपना 'क्विवेक' प्रयोग करने के अवसर बहुमन कम मिल पाते हैं। उसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी कार्य की वैधता की जाँच करनी होती है। दूसरे ओर अमेरिकन उच्चतम न्यायालय को 'स्व-क्विवेक' प्रयोग करने के अनेक अवसर प्राप्त हैं। परिणामस्वरूप अमेरिकन उच्चतम न्यायालय की भाँति भारतीय उच्चतम न्यायालय के लिए 'तृतीय सदन' के अवसर नहीं हैं।

(स) अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति—इस अनुच्छेद में नागरिकों के सौवैधानिक अधिकारों का उल्लेख है। तदनुसार कोई भी नागरिक अपने किसी मौलिक अधिकार के उत्पत्तन पर उच्चतम न्यायालय की शरण से सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह देखने का अधिकार होगा कि क्या राज्य के किसी कार्य या कानून से नागरिक के मौलिक अधिकार का उत्पत्तन हुआ है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश श्रवितेष उदोक्षण और अधिकार पृच्छा लेख निकालने का अधिकार है। ये लेख या आदेश 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के उत्पत्तन पर ही निकाले जाते हैं, अमेरिका की तरह 'शकृतिक अधिकारों के सिद्धान्तों' के अनुसार नहीं। इन रिटों (Writs) के रूप में न्याय प्रशासन की एक नई शाखा का विकास हुआ है। इस नई शाखा का जनता ने किस उत्साह के साथ उपयोग किया है, वह इससे प्रकट है कि अनेक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में सी से दो सी प्रतिशत तक (कहीं-कहीं उससे भी अधिक) वृद्धि करनी पड़ी है फिर भी विपक्षीय मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यायपालिका द्वारा रिट-अधिकारिता के प्रयोग से जन-साधारण के मन में यह विश्वास जाग गया है कि उस पर कानून का शासन है।

(श) अनुच्छेद 131 एवं 132 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति—अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार का और अनुच्छेद 132 में सौवैधानिक मामलों में उसके अपोलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है अर्थात् ये दोनों अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की सपीय और राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं।

38वें संविधान संशोधन से 43वें संविधान संशोधन तक की स्थिति

संविधान के 38वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के राष्ट्रपति के अधिकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन के बाद राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा उद्घोषित आपातकालीन स्थिति वाले अध्यादेशों को न्यायालय की सुनवाई के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया। 39वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मन्त्रि के अध्यक्ष के चुनावों पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार समाप्त कर दिए गए। 40वें संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा प्रयासमन्त्री को राष्ट्रपति और राज्यपालों की तरह दायित्व तथा दीवानी कार्यवाहियों से विमुक्ति प्रदान कर दी गई। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति को और सीमित कर दिया गया, लेकिन 43वें संवैधानिक संशोधन ने न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवधानों को समाप्त कर दिया और न्यायिक पुनरावलोकन के सम्बन्ध में बड़ी स्थिति हो गई जो 42वें संविधानिक संशोधन के पूर्व की। 43वें संविधान संशोधन ने भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और गरिमा को बहाल कर दिया।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की समीक्षा

संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया के विकास में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वह किया है। देश में संवैधानिक विवादों की दृष्टि से न्यायालयों ने सुचनात्मक भूमिका का निर्वह किया है। कई बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग से न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधानपालिका के बीच विवाद एवं तनाव उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए निजी सम्पत्ति के सम्बन्धों, विधायी विशेषाधिकारों एवं संवैधानिक संशोधन के क्षेत्रों में दिए गए कुछ निर्णयों के कारण विवाद उत्पन्न हुए हैं। परिणामस्वरूप संविधान में संशोधन कर उन न्यायिक व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया जिन्हें सरकार नहीं चाहती थीं। ऐसा करने का औचित्य यह कहकर सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इन निर्णयों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।

इन विचारों के अतिरिक्त भारत में न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया को संविधान का अनुमोदन प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास बनाम राव के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया है कि संविधान में कई धाराएँ न्यायालयों को यह शक्ति देती हैं कि वे यह कार्य विधानमण्डल पर प्रहार करने को इच्छा से न करें, किन्तु संविधान द्वारा सार्वजनिक प्रदत्त कर्तव्यों को निवाहने के लिए उसे यह करना पड़ता है। गोपालन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है: "भारत में संविधान सर्वोच्च है और किसी विधि के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि वह हर स्थिति में सौविधानिक अपेक्षाओं के समनुरूप हो और यह निर्णय करना न्यायालय का कार्य है कि अधिनियम सौविधानिक है अथवा नहीं।" यदि विधानसभा किसी सौविधानिक परीक्षा का उल्लंघन करती है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधि को असौविधानिक घोषित कर दे क्योंकि "अपनी शपथ के कारण न्यायन संविधान को रखा करने के लिए बाध्य है।" न्यायिक पुनरावलोकन संविधान द्वारा सौंपा गया है। न्यायालय इस कार्य को करने में स्वयं को उल्लंघन और असमर्थता की स्थिति में पाता है परन्तु वे अपने सौविधानिक उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकते।

असौविधानिक का प्रभाव—जब उच्चतम न्यायालय किसी विधि को असौविधानिक घोषित करता है तो अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत उसका निर्णय भारत के प्रत्येक न्यायालय पर लागू होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय हर व्यक्ति पर सर्वव्यापी निर्णय के रूप में लागू हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप किसी के लिए उस अधिनियम की असौविधानिकता स्थापित करना आवश्यक नहीं है। किसी असौविधानिक विधि का अवज्ञा करने में न्यायालय बाध्य है। जब किसी विधि का एक अंश अवैध ठहराया जाता है तो उसकी उपेक्षा की जाती है। असौविधानिक अंश निकाल देने पर शेष विधि सौविधानिक बनी रहती है, परन्तु यदि अलग न किया जा सके तो पूर्ण विधि असौविधानिक मानी जाती है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार

उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 137 के अन्तर्गत अपने निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। यह कहा जाता है कि निम्न न्यायालय का सम्बन्ध तथ्यों से है, उच्च न्यायालय का सम्बन्ध त्रुटियों (निम्न न्यायालय द्वारा निर्णय की त्रुटियों) से है तथा उच्चतम न्यायालय का सम्बन्ध विवेक बुद्धि (Wisdom) से है किन्तु उच्चतम न्यायालय गलती कर सकता है इसलिए आवश्यक है कि उस त्रुटि को ठीक करने की राह खुली रखी जाए।¹ ऐसा करके न्यायानुसंग कानूनों की अशुद्धियों और शक्तियों में सुधार के साथ वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों की समीक्षा करके उन्हें सामयिक तथा जीवन्त स्वरूप प्रदान कर सकता है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

(Independence of the Judiciary)

1. **प्रदायिका की सराहना**—एक बार निम्नलिखित किए जाने के उपरान्त न्यायाधीशों को उनके स्वैच्छिक त्याग-पत्र के अलावा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जो एक कठिन प्रक्रिया है। आज तक एक भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सका है।

2. **न्यायाधीशों के क्षेत्र, भत्ते आदि विधायिका के अधिकार से परे होना**—उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, संविधान द्वारा नियत और भारत के संप्रति विधि पर आधारित हैं जिन पर संसद में प्रस्ताव नहीं हो सकता है तथा कार्यकाल के दौरान परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति अपवाद है।

3. **कार्य-प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति**—उच्चतम न्यायालय को अपनी कार्य-प्रणाली के नियम बनाने का अधिकार है। ये नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अन्तर्गत निर्धारित होते हैं और इन पर राष्ट्रपति को अनुमति दी जाती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को मान्य होंगे।

4. **कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण**—उच्चतम न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण सौंपा गया है ताकि उनकी स्वतन्त्रता को अपात न पहुँचे। न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

5. **संसद क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती**—संसद को उच्चतम न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है, घटाने का नहीं। उच्चतम न्यायालय को संसदीय दबाव से मुक्त रखा गया है। उसने अधिकार क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है।

6. **अनुक्तिपूर्ण**—अपनी आधिकारिक क्षमता से कष्टग्रस्त न्यायालयों के निर्णय और कार्यों को अलोचना नहीं की जा सकती। संसद न्यायाधीशों के ऐसे कार्यों पर जिसे उन्होंने कर्तव्यपालन करते हुए किया हो, विचार विमर्श नहीं कर सकती है।

7. अवकाश प्राप्त करने के बाद बकायत करने पर प्रतिबन्ध—अवकाश प्राप्त के बाद न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायपालिका या अधिकारी के समक्ष बकायत नहीं कर सकते, किन्तु संविधान विशेष प्रकार के कार्य-सम्पादन के लिए उनकी नियुक्ति को अनुमति देता है, उदाहरणार्थ विशेष जोखिमदातल तथा अन्वेषण करना आदि।

इस तरह हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थिति मजबूत है और उसकी स्वतन्त्रता पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, किन्तु सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को आयोग एवं समितियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की वर्तमान प्रथा से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।¹ भारतीय विधि आयोग ने इस प्रथा के सफाई की ओर संकेत करते हुए इसे समाप्त करने की सरकार से सिफारिश की है। अभी तक सरकार ने विधि आयोग की इस सिफारिश को लागू नहीं किया है। इस पर अफस होना चाहिये।

उच्च न्यायालय (High Courts)

संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक राज्य न्यायपालिका से सम्बन्धित हैं। संविधान का पौचर्चा अध्याय राज्यों के उच्च न्यायालय और अध्याय छठा अधीनस्थ न्यायालयों से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था रखी गई है, किन्तु कानून द्वारा संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या दो से अधिक राज्यों तथा एक संघीय क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में देश में 17 उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं जिनमें से दो ऐसे हैं जिनका न्यायाधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा उन्ने अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनके की छहपति समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियुक्त करें। संविधान के सातवें संशोधन के अनुसार अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार छहपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल से और राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की दशा में उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के परमात् उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पदभरण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। इसके पूर्व निम्नांकित रीति से अपना पद त्याग कर सकेंगे—

- (क) कोई न्यायाधीश छहपति को संबोधित अपने इस्तीफा सहित लेख द्वारा
- (ख) साबित हताचार या असमर्पता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा (उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से समर्थित) समावेदन पर छहपति द्वारा हटाया जा सकेगा,
- (ग) छहपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर या किसी उच्च न्यायालय में अन्तर्गति किए जाने पर।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ—संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और

- (क) भारत के राज्य क्षेत्र में दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या
- (ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

न्यायाधीशों के वेतन आदि—संविधान के अनुच्छेद 221(1) में व्यवस्था है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का सदाय किया जाएगा जो हाइड्र विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस निर्मित इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का सदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 30,000/- रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 26,000/- रुपये प्रति माह वेतन 1 जनवरी 1996 से दिया जा रहा है।

उच्च न्यायालय के कार्य और अधिकार—

राज्य के उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विशेष प्रकार के मुकदमों सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ उच्च न्यायालय बसीयत, विवाह, कम्पनो वगैरह के मामलों पर विचार कर सकते हैं उच्च न्यायालयों में अपमान सम्बन्धी मुकदमों सुने जा सकते हैं, भूमि-कर तथा

उसकी वसूली से सम्बन्धित मामले उच्च न्यायालय में सीधे लाए जा सकते हैं। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वे इन अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों सम्बन्धी मुकदमों में उच्च न्यायालय अथवा सीधे उच्चतम न्यायालय में पैरा किये जा सकते हैं। अपीलीय अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय दीवानी, फौजदारी और मान सम्बन्धी मुकदमों को अपीलें सुनते हैं। कुछ न्यायालय दीवानी मामलों में प्रायः जिला न्यायालय के विरुद्ध फौजदारी मामलों में सब न्यायालयों के विरुद्ध और माल (एवम्) सम्बन्धी मामलों में राजस्व मण्डल के विरुद्ध अपीलें सुनते हैं।

प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करने का अधिकार है। ये ऐसे न्यायालयों से न्यूनतम माँग सकते हैं, उनकी कार्य-प्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए सामान्य नियम बना सकते हैं और आदेश जारी कर सकते हैं। किसी अधीन न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो जिसमें सविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमों को अपने पास मंगा सकता है। उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी मुकदमे को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय को स्थानान्तरित कर दे। उच्च न्यायालय एक अभिनेत्र न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। वह अपना किाई कायम रखता है। उसकी कार्यवाहियों और निर्णय छापे जाते हैं तथा अन्य मुकदमों में उनका हवाला दिया जा सकता है। सविधान द्वारा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। वे ऐसे संवैधानिक संशोधन, केन्द्रीय कानून या राज्य-कानून को अर्थव्यापक घोषित कर दें जो सविधान के प्रवधानों के विपरीत हों। 42वें सविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया गया था और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया था, किन्तु 43वें सविधान संशोधन 1977 द्वारा उच्च न्यायालयों को अब न्यायिक पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में बड़ी स्थिति और शक्ति प्राप्त हो गई है जो 42वें संशोधन से पूर्व की। इससे उच्च न्यायालय की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

अधीनस्थ न्यायालय भारत की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। कुछ विभिन्नताओं को छोड़कर सारे देश में अधीनस्थ न्यायालयों का सम्भाव्य स्वरूप तथा ढाँचा समान सा है। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बँटा होता है और हर जिला एक जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में चलता या रहे प्रमुख दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधीन रहता है। अगर जिला न्यायाधीश उसकी सहायता करते हैं। जिला न्यायाधीश के नीचे ढाँचनी न्यायालयों के विभिन्न पद क्रमों के बहुत से कार्यवाही होते हैं। मुकदमों की सुनवाई करने के अतिरिक्त दीवानी न्यायालय मध्यस्थ-निर्णय, अधिभावकता, विवाह-विच्छेद और प्रमाणित इच्छा-पत्र जैसे अनेक मामलों को अपने अधिकार-क्षेत्र के अधीन रखते हैं। अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण जो आम न्यायालयों से अलग हैं, कुछ दीवानी अधिकारों को निरपेक्ष करने के लिए अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए हैं। कुछ मामलों में इनके निर्णय के विरुद्ध अप न्यायालयों में अपील की जा सकती है। ऐसे अधिकार न होने पर सविधान के अनुसार वे उच्च न्यायालय के अधीन हैं।

फौजदारी अदालत का विधान और गठन दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 के अधीन किया जाता है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1968 के स्थान पर 1 अक्टूबर 1974 को लागू हुआ। संहिता में कार्यपालिका और न्यायपालिका से सम्बन्धित कार्यों के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेटों की व्यवस्था है। कार्यपालिका से सम्बद्ध मजिस्ट्रेट राज्य सरकारों के और न्यायपालिका के सम्बद्ध उच्च न्यायालय के अधीन हैं। कार्यपालिका में हर जिले के लिए एक मजिस्ट्रेट और उसके अधीन कई अधीनस्थ मजिस्ट्रेट होते हैं। ये मजिस्ट्रेट कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अग्रगण्य ठेकने की समस्याओं से निपटते हैं। न्यायपालिका में जिला स्तर पर सबसे ऊपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और फिर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। अन्त मजिस्ट्रेटों से सम्बन्धित वे कार्य जो प्रमुखतया न्यायिक प्रकृति के हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के जिम्मे हैं। दस लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों में महानगरीय मजिस्ट्रेट हैं, जिनके पास मुकदमों की रीति-नियतों के लिए इससे अधिक अधिकार होते हैं।

व्यवस्थापिका न्यायपालिका सम्बन्ध (Legislative Judiciary Relations)

भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की स्थिति का विस्तार करने की दृष्टि से व्यवस्थापिका न्यायपालिका के सम्बन्ध के स्वरूप के बारे में जानना अत्यन्त सामयिक और प्रासंगिक बन जाता है। अनेक बार 'व्यवस्थापिका बनाम न्यायपालिका' की संघर्षता का मुद्दा चर्चित हुआ है और व्यवस्थापिका के प्रवर्धित व्यवस्थापन की आद में न्यायपालिका को शक्तियों को सीमित करने और अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। व्यवस्थापिका द्वारा विभिन्न सविधान

संशोधन पारित करने का मुख्य सत्य था। दूसरी ओर न्यायपालिका ने संविधान के बुनियादी स्वरूप (Basic Structure of the Constitution) में परिवर्तन करने की व्यवस्थापिका को शक्ति प्रदान करने जैसी अपराधना या प्रतिपादन पर व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता को सीमित करने का प्रयत्न किया है। भारत में संवैधानिक उपबन्धों ने न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त बनाकर उसकी स्वतंत्र स्थिति को प्रतिष्ठापित किया है पर यह व्यवस्था यह है कि यदि कोई न्यायाधीश संविधान के प्रतिकूल आचरण करता है तो उससे विरुद्ध या कार्यवाही की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा करने व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है।

न्यायपालिका का संविधान के अनुसूचित संसद के किसी कानून में या उसके अंश को असंवैधानिक ठहराने का अधिकार है। यद्यपि न्यायपालिका ने इस अंकुश में भागीय संसद को बहुत कुछ नियंत्रित कर रखा है लेकिन समय में न्यायपालिका की निर्णयकारी शक्ति को अपनी धर्मों के अनुकूल प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः अर्पण हो जाती है जब उसके निर्णय को किसी कानून अथवा संविधान से निरस्त किया जा सकता है। भारत में न्यायपालिका के निर्णयों का विरुद्ध संसद ने दो तरह से किया है—

1. न्यायालय के किसी निर्णय द्वारा किसी विधि के सम्बन्ध में की गई आपति अथवा दोष का दूर कराने के लिए दुरुस्त अध्यादेश अथवा विधि का निर्माण करने,

2. न्यायपालिका द्वारा किसी कानून के असंवैधानिक घोषित किये जाने पर स्वयं संविधान में संशोधन करके।

भारतीय संविधान में किए जाने वाले संशोधनों का उद्देश्य उन कृत्रिमों को दूर करना था जिनके कारण न्यायपालिका ने सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति अथवा कानून को असंवैधानिक घोषित किया था। इसका व्यावहारिक अर्थ यह निकलता है कि न्यायपालिका सरकार को शक्तियों पर समुचित अंकुश लगाने में ज्यादा प्रभावी नहीं हो सका है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने वाले अनेक कानूनों को संसद ने संविधानिक संशोधनों द्वारा वैधानिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जैसा प्रयोग किया गया है उससे पाठ्य ग्राहक इन की नीतियों को कार्यन्वित करने की भावना विद्यमान रही है और जहाँ तक संविधान दम् के हिस्से अथवा विधियों में जरा भी बाधबुझ हुआ है उसने निरसकार रूप से संविधान को ही बदल दिया है। संविधान के 42वें संशोधन के संवैधानिक संशोधन को न्यायपालिका को परिधि से बाहर कर यह व्यवस्था कर दी है कि किसी संवैधानिक संशोधन को किसी न्यायमय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान के मूल स्वरूप को ही बदलने हुए संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर न्यायपालिका को पंगु बना दिया था किन्तु 43वें और 44वें संशोधन ने उस स्थिति को समाप्त करने न्यायपालिका की पुनरावलोकन की शक्ति को पुनः विस्तृत किया जिसमें विधानमण्डल पर न्यायपालिका का नियंत्रण और प्रभाव बहुत बढ़ गया है और न्यायपालिका की शक्ति को पुनः महत्ता पाया दृढ़ता मिली है।

न्यायिक सक्रियता का युग

विगत कुछ वर्षों से भारतीय उच्चतम न्यायमय ने अपनी सक्रियता से भारत के जनसाधारण में अपनी गर्जना बनाई है। जनसाधारण ने केवल संविधान की रक्षा करने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही न्यायपालिका की ओर निहारते हैं अपितु देश में कार्यपालिका के सदस्यों के अनियंत्रित तथा अपरिचित आचरण पर रोक लगाने तथा इसमें व्याप्त गृहाचार पर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका की ओर देखने लगे हैं। जाता जनही न्यायिका द्वारा बने न्यायपालिका से घोटालों को उजागर करने में सफल हुई है जिसकी पूर्ण में सम्पन्न नहीं की जा सकती था। अनेक राजनेताओं के राजनीतिक भविष्य के आगे प्रश्नचिह्न लगा दिया। इन घोटालों के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय की भूमिका ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को शक्ति प्रदान की है। चन्दन तस्कर विस्फोट के प्रकरण में दिखाई गई न्यायिक सक्रियता के कारण तो न्यायपालिका की पूरे देश में प्रशंसा हुई है। न्यायिक सक्रियता के इतिहास में दिनांक 29 सितम्बर, 2000 को एक नया अध्याय जुड़ गया जब केन्द्रीय जीएस ब्यूरो की विशेष अन्तस्तन ने बरोड़ों रुपये के झारखण्ड मुक्ति मोर्चा संसद रिश्वत मामले में निर्णय देते हुए पूर्ण प्रमाणमयी नरसिम्हाराव और उनके मनिंगण्डल के सहयोगी रहे घुमसिंह को अविरास प्रस्ताव के खिलाफ अल्पसंख्यक विधायक को बचाने के ह्रादे से सांसदों के घोट लुटने व लिए अपराधिक बहयत्र रचने और प्रहार कर दोषी करार दिया। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सदस्यों का अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगा है और वे बचपने लगे हैं। देश के लोकतांत्रिक के लिए यह सुखद स्थिति है। इस न्यायिक सक्रियता के आलोचक कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार की शक्तियों से मुक्त करने के खतरनाक परिणाम निकलेगे और व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका की भूमिका के आगे प्रश्नचिह्न चिह्न लग जायेगा।

न्यायिक सक्रियता और भारतीय राजनीति

न्यायपालिका राजनैतिक प्रक्रिया का अंग है जो सरकार के हाथों में राजनीतिक शक्तियों के अत्यधिक केन्द्रीकरण की उपशम और लोकतान्त्रिक शोषणियों से जनता का बचाव करने को प्रतिबद्ध है। इन्हीं कारण न्यायधीन और न्यायानुव समग्र राजनीतिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। नागरिकों को प्राप्त स्वतन्त्रता के अधिकार की सुरक्षा न्यायपालिका के अलावा अन्य संस्थागत संरचना द्वारा संभव नहीं होती। इस प्रकार जन सामान्य के लिए न्यायपालिका संरक्षक के रूप में है। जो कार्य विधायिका एवं कार्यपालिका का है उस कार्य को न्यायपालिका सम्पन्न कर रही है। न्यायपालिका इन दोनों शक्तियों को नियंत्रित करने में अपनी कर्त्तव्य लागू रही है जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए पात्रक है। प्रसिद्ध राजनैतिक चिंतक लॉर्ड ब्राइस के अनुसार "न्यायपालिका राज्य के लिए एक आवश्यकता ही नहीं है, अपितु उसकी समता से बढ़कर सरकार की ठोसता की कोई कसौटी ही नहीं है।" न्यायपालिका केवल नागरिकों के माध्यम से विवादों का ही निपटारा नहीं करती, अपितु वह उन क्विडों का भी निर्णय करती है जो नागरिक एवं राज्य के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। अनेक विचारक इसको राजनैतिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग से अधिक एवं आधारभूत स्तम्भ मानते हैं। भारतीय संविधान का जो सामाजिक दर्शन है उस सत्य की पूर्ति हेतु ही न्यायपालिका को सरकार के एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान निर्माता इस बात से भलीभाँति परिचित थे कि यदि न्यायपालिका का उचित स्थान प्राप्त नहीं होता है तो समाज से परतंत्रता के भावों का उन्मूलन नहीं किया जा सकेगा और जन साधारण के सम्मिश्र सत्ता की स्थिति उपस्थित हो सकती है। इसलिए संविधान में मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का प्रावधान करके जन सामान्य की पीड़ा एवं निराशा को दूर करने का प्रयास किया गया। अत्र जहाँ न्यायपालिका सार्वजनिक परिधि में रहकर जन साधारण को कष्टों एवं असुविधाओं को दूर करने का प्रयास कर रही है तो इसे न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जा रही है। इस दृष्टि से न्यायिक सक्रियता प्रभावजन्य में जन कल्याण की अपरिहार्यता है। एक स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं निर्पक्ष न्यायपालिका लोकतन्त्र का प्रतीक होती है। विश्व में जहाँ कहीं न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है वहाँ जनता को अपार कष्ट सहन करने पड़ते हैं।

भारत में न्यायिक सक्रियता घटती सन् 1980 के दशक की देन है, परन्तु इसका अकुरुण संविधान लागू होने के बाद से देखा जा सकता है यथा—(1) सन् 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री फजल अली ने 'गोपालन बनाम मद्रास राज्य' प्रकरण में न्यायिक सक्रियता की आधारशिला रखी जिसमें निवारण विधेय अधिनियम के खण्ड 14 को अवैध ठहराया गया। (2) मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं। 'नेशा बचर बनाम मद्रास राज्य' विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 32 उन्हें मौलिक अधिकारों के संरक्षण की स्थिति प्रदान करता है। (3) नूतनपूर्ण न्याय दिल्ली राज्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतन्त्रता का समर्थन किया और कहा कि सामान्य शान्तिस्थानीय स्थिति में प्रेस को नियंत्रित करना अनुचित है। (4) इन्हीं श्रेणी में महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं—(क) बम्बई राज्य बनाम बम्बई रिण्टा समाज, (ख) रसंद अहमद बनाम केन्द्रीय सरकार, (ग) रिचर्ड सान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (घ) गैलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967। इन चारों प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संभित या सरोपित नहीं किया जा सकता है। (5) कैसाबान्द भारतीय बनाम केरल राज्य (1973) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31-C के द्वितीय खण्ड को निरस्त कर दिया, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों पर आपात पहुँचता था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय को दोहराते हुए मिनर्वा फ़िक्स तथा अन्य बनाम भारत सरकार के प्रकरण में 9 मई, 1980 को निर्णय देते हुए 42वें सार्वजनिक सरोपण की धारा 4 और धारा 55 को निरस्त कर दिया।

न्यायिक सक्रियता का वास्तविक प्रारम्भ सन् 1980 में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती के द्वारा हुआ। इण्डियन एक्सप्रस में सम्पादक के नाम एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें बिहार के अधिवक्ताओं की आश की जेल में दुर्घटना एवं उनकी रहन-सहन की शोचनीय स्थिति का विवरण प्रकाशित हुआ। इसके आधार बनाकर विधि संचायक के दो प्राथम्यको ने संविधान की धारा 21 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। इसके बाद मध्य प्रदेश में महिलाओं की हो रही ध्वनित खण्ड फ़ोछा सम्पन्न करने के लिए पत्रकार अम्मा शैली कुमारी क्यूर तथा अखिली सतीन न सपुत्र रूप में याचिका दायर की। बिहार राज्य के भागलपुर काठमाण में बन्द कैदियों की आँखों में पुतिस ने तेजाब डाल कर आँसु पोहन का उपाय कृत्य किया, जिसे अखिलीका काण्ड के नाम से जाना जाता है।

संविधान की कोई धारा स्पष्टतः न्यायिक पुनर्निर्माण का अधिकार नहीं देती है। पर धारा 13, 32, 131, 132 एवं 246 में यह अधिकार अन्तर्निहित है। न्यायिक सक्रियता न केवल भारतीय संविधान को सत्य रूप में स्थिर करने का प्रयास कर रही है, बल्कि वह पूरी राजनैतिक व्यवस्था में अनेक गंभीर विवादों के निदान करने के लिए प्रयत्नरत है।

जनहित याचिका

(Public Interest Litigation : PIL)

न्यायाधीशों की स्थानान्तरण के बारे में अपने वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की सविधान पंथ ने निर्णय दिया कि जनता का कोई भी व्यक्ति, भले ही उसका वाद से सीधा सम्बन्ध न हो पर उसमें उसकी पर्याप्त रुचि हो, अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में न्याय के लिए प्रार्थन कर सकता है अथवा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उन व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिये जो "गरीबी, साक्षरता या असमर्थता या सामाजिक एवं आर्थिक विपन्नता" के कारण न्यायालय तक नहीं जा सकते, उच्चतम न्यायालय में प्रविष्ट कर सकता है।¹ ऐसे मामले में एक पत्र के द्वारा न्यायालय के द्वार तक पहुँचा जा सकता है। एस पी. गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति ए आई आर 1982, एस पी 149 के वाद में दिए निर्णय से लोक सेवा आयोग अथवा नगरिक को या समाज सेवा संगठनों को धुन मिल गई है कि वे आम जनता के हित में न्याय की माँग कर सकें।

बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सच ए आई आर 1984 ए सी 803 के वाद में बधुआ-मुक्ति के श्रेय क प्रति समर्थित संगठन ने एक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवस्थित पत्थर की खानों का सर्वे किया और पाया कि उन खानों में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर "अमान्य तथा असह्य परिस्थितियों" में काम कर रहे हैं जिनमें से बहुत से बधुआ मजदूर हैं। इन याचिकाकर्ताओं ने याचिका की कि सविधान के विभिन्न उपबन्धों तथा कानूनों के समुचित परिपालन के लिए एक रिट जारी की जाए, जिससे कि उन मजदूरों का दुख, कष्ट एवं लाचारी दूर हो सके। न्यायालय ने इस पत्र को रिट याचिका माना और एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में दो अधिकार थे। उनसे कहा गया कि वे इन पत्थर की खानों पर जाएँ और वहाँ जाँचकर न्यायालय को रिपोर्ट दें।

लक्ष्मीकान्त पाण्डे बनाम भारत सच में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। उसका आधार एक पत्र था। इराम शिकायत की गई थी कि विदेशियों को भारतीय बच्चों को देने के काम में सगी समाज सेवा संस्थाएँ और संगठन कलाचार कर रही हैं। पत्र में आरोप था कि सुकुमार दय के बच्चों को गोद लेने की आड़ में उन पर अत्याचार किया जाता है। उनका दूर देशों की लम्बी और भयावह यात्रा करनी ही पड़ती है तथा उनकी जान को भारी जोखिम रहता है। उनका आश्रय तथा भविष्य अंधार में लटक जाता है। मुख्य न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने बच्चों का कल्याण क्षुब्धचित्त करने के लिए कुछ सिद्धान्त तथा मापदण्ड निर्धारित किए। उन्होंने सरकार तथा मामले से सम्बद्ध एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे रिश्तानों का पालन करें। इस प्रकार वर्तमान में न्याय की दृष्टि से न्याय की दुनियाँ में जनहित मुकदमों का महत्वपूर्ण स्थान है।

□□□

सांविधानिक संस्थाएँ/आयोग

(Statutory Institutions/Commissions)

संघ लोक सेवा आयोग

(U. P. S. C.)

भारत में लोक सेवाओं की भर्ती करने वाले मुख्य अधिकरण ये हैं—संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, रेलवे सेवा आयोग तथा सांविधानिक नियमों के अन्तर्गत निजी भर्ती-मण्डल अथवा आयोग। ये आयोग गवर्नाटिव एवं अन्य प्रणालियों को भर्ती की प्रक्रिया से दूर रखते हैं तथा योग्य कार्यधारियों के चयन को सम्भव बनाते हैं। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया था।

लोकतन्त्रिक राज्यों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों की जाती है। इसके अनुसार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 के अन्तर्गत केंद्र तथा सभी राज्यों के लिए एक-एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, किन्तु इसमें दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी अनुमति दी गई है, बशर्ते कि राज्यों के विधान-मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया हो। इस मामले में संसद कानून द्वारा इन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त सेवा आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था कर सकती है। राज्य केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से भी कार्य करने का अनुबंध कर सकते हैं और केन्द्रीय लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति की स्वीकृति से ऐसा कर सकता है। संविधान में लोक सेवा आयोग के बारे में धारा 145 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 में दिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग का संगठन एवं फंक्शंस

संविधान के अनुच्छेद 313(1) में व्यवस्था है कि "लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य आयोग है तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी।"

यद्यपि संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, तथापि सदस्यों की संख्या तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। संघीय लोक सेवा आयोग की पद संख्या अध्यक्ष सहित कुल नौ है। वर्तमान में संघीय लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और आठ सदस्य हैं। इसका कार्यालय धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है।

संविधान के अन्तर्गत स्थानीय अध्यक्ष अथवा सदस्य लेने पर अथवा किसी भी कारण से कार्य न करने की स्थिति में रिक्त स्थान पर आयोग के अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है जिसे राष्ट्रपति (संघीय आयोग या संयुक्त आयोगों की विधिवतियों में) नियुक्त करें। राज्य आयोग की अवस्था में राज्यपाल ऐसे कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पद-भार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की स्थिति में 65 के स्थान पर 60 वर्ष की आयु का प्रावधान है। संघीय लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद-त्याग कर सकता है। कदाचित् के आधार पर भी आयोग के सदस्य को हटाने का या निम्नस्थित किए जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया का विवरण अनुच्छेद 317 के खण्ड (1), (2), (3), (4) में दिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है—(1) यदि वह व्यक्ति दिवानिया हो, (2) यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान पद से भ्रष्टाचार से हटाया जाय, (3) यदि राष्ट्रपति के विचार में वह मन अथवा शरीर की असमर्थता एवं अस्थिरता के कारण पद पर कार्य करने

के लिए असहम हो गया हो एवं (4) यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा इनकी ओर से किए गए किसी ठेके अथवा करार के साथ उसका (एक निर्दिष्ट) कम्पन के साधारण सदस्य को छोड़ अन्य कोई सम्बंध न अथवा उससे वह कोई लाभ प्राप्त करता है।

संघीय आयोग या समुक्त आयोग के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्य आयोग के संदर्भ में राज्यपाल द्वितीयमें द्वारा आयोग की संरचना उनकी सेवा-शर्तों आदि का निर्धारण करता है। आयोग के सदस्य की सेवा-शर्तों में ठामा नियुक्ति के बाद ऐसे परिवर्तन नहीं किए जाते जो उसके लिए अलापकरी हों।

अनुच्छेद 316(3) के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्य को, उसकी पदावधि की समाप्ति तक, उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।

लोक सेवा आयोग का सचिवालय

संघीय लोक सेवा आयोग का सचिवालय है जिसमें सचिव अनेक उप-सचिव और अवर सचिव तथा अनुभवाधिकार और सामान्य कार्याधी वर्ग हैं। आयोग की अनेक शाखाएँ हैं जिनका सम्बन्ध उसके प्रमुख सम्बाधी कार्यों से है। इनके अतिरिक्त संघीय लोक सेवा आयोग का कार्यकाल निम्नांकित शाखाओं से संगठित है—(1) परीक्षा शाखा, (2) भर्ती शाखा, (3) सेवा शाखा, (4) नियुक्ति शाखा एवं (5) गुप्त शाखा।

लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ, कार्य एवं बुद्धि

लोक सेवा आयोग के कार्य सचिवालय के अनुच्छेद 320 में दिए गए हैं, किन्तु अनुच्छेद 321 में भी यह व्यवस्था है कि संसद/राज्य विधान-मण्डल क्रमशः विधि द्वारा संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की सभाओं के पदों में तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी सार्वजनिक संस्था की सेवाओं के अतिरिक्त कार्य सौंप सकते हैं।

संघीय लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्यों का विवरण डॉ. भाभरी ने निम्नानुसार किया है—

1. भर्ती के तरीकें, सिविल व असेनिक सेवाओं तथा असेनिक पदों पर सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने में अपनाए जाने वाले सिद्धान्तों से सम्बन्धित सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देना।

2. नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण आदि के लिए प्रत्याशियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में परामर्श देना।

3. सेवाओं पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संपादन करना।

4. लोक सेवाओं को प्रभावित करने वाले अनुसामन्तत्यक मामलों के सम्बन्ध में परामर्श देना।

5. लोक सेवा के किसी व्यक्ति द्वारा कर्तव्य पालन के लिए किए गए कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध की गई किसी कार्यवाहियों में जो ठीक गते करना पड़ता है उसके दाये के सम्बन्ध में तथा किसी लोक सेवाक द्वारा नियुक्ति-वेतन अथवा पेंशन के लिए किए जाने वाले उस दाये के सम्बन्ध में परामर्श देना जो वह अपने उवरादापिता का पालन करते समय करता है।

6. अन्य कोई ऐसा मामला जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से उनको सौंपा जाए।

संसद द्वारा अथवा राज्य विधान-मण्डल द्वारा केवल सरकारी सेवाओं के ही सम्बन्ध में नहीं बल्कि उन सेवाओं के सम्बन्ध में जो कि स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities), निगमों (Corporations) अथवा सार्वजनिक संस्थाओं के अधीन हों, आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता।

आयोग के कार्यक्षेत्र में कुछ पदों को अलग करके उसका अधिकार क्षेत्र कम किया जा सकता है। निम्नलिखित नियुक्तियों के चुनाव के सम्बन्ध में आयोग से कोई परामर्श नहीं किया जाता—

(क) न्यायाधिकरण (Tribunals) अथवा आयोग की सदस्यता अथवा अध्यक्षता।

(ख) उच्च राजनयिक प्रवृत्ति के पद पर।

(ग) वृतीय एवं तृतीय ग्रेजी के अधिकारी, कर्मचारी, जिसकी संख्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या का 98 प्रतिशत है आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

निन्दा, पदोन्नति या वेतन-वृद्धि रोके, लापरवाही या आदेशों का उल्लंघन करने से सरकार को आर्थिक हानि होने से वास्तविक सेवा-निवृत्ति सेवा पदच्युति आदि कोई भी दण्ड देने की प्रवृत्ति में राष्ट्रपति द्वारा मूल आदेश जारी करने के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श किया जाता है। आयोग सरकार को अन्य जिन मामलों में सलाह देता है वे हैं—भर्ती के तरीके, नियुक्ति, पदोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले सिद्धान्त और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रत्याशियों की उपयुक्तता। आयोग निम्नांकित मामलों के सम्बन्ध में भी सरकार को परामर्श देता है—

वा कार्य प्रशासनिक प्रवर्ति का अधिक है अतः सविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) के रूप में एक ऐसे अधिकारी की व्यवस्था की है जो प्रशासनिक दृष्टि से मुक्त हो और निराले आदेशों का पालन अधीनस्थ अधिकारियों निष्ठा के साथ करे।

निर्वाचन तंत्र के प्रमुख कार्य—निर्वाचन तंत्र के अथवा निर्वाचन की व्यवस्था करन वाला प्रशासकीय तंत्र के जिसमें निर्वाचन आयोग और उनके अधिकारी राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग आदि सम्मिलित हैं प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—(1) निर्वाचन क्षेत्रों का परिमोचन, (2) मतदाताओं की सूचियाँ तैयार करन तथा उनका प्रकाशन करना, (3) चुनाव-चिह्नों की व्यवस्था करना, (4) निर्वाचन-समय की व्यवस्था करना जैसे—मतदान पेटी, स्वादी मोहर आदि की व्यवस्था, (5) निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करना, (6) नामनिर्देशनों की व्यवस्था करना, (7) अधिकतम व्यवस्था, (8) मतदान व्यवस्था, (9) गणना और परिणाम की उद्घाटन, (10) मतदान सामान जमा करना एवं उसका प्रत्यक्ष, (11) निर्वाचन व्यय पर सीमा एवं (12) धातिकाओं के लिए प्रत्यक्ष आदि।

निर्वाचन तंत्र का गठन—निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यों के सम्पादन के लिए जिस स्वतन्त्र प्रशासकीय तंत्र का गठन किया गया है वह इस प्रकार है—(क) निर्वाचन आयोग एवं (ख) राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग।

(क) निर्वाचन आयोग (Election Commission)

सविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है तथा सविधान सुनिश्चित करता है कि वह सर्वोच्च उच्च न्यायालयों की धार्मिक कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहकर स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सक।

निर्वाचन आयोग का संगठन—अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, "निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य ठगने निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनमें से राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करे।" इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा एक से अधिक निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति किया जाना अनिवार्य नहीं है और इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना राष्ट्रपति के अधिकार में है किन्तु यदि अब निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाए तो संविधान की व्यवस्था है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति राष्ट्रपति ससद द्वारा विलित कानून के अन्तर्गत करेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों (Regional Commissioners) को नियुक्ति कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

सेवा शर्तें, कार्यकाल तथा पदयुक्ति—अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदाधिकारी (कार्यकाल) ऐसी होंगी जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। स्पष्ट है कि उनका कार्यकाल सविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है तथा इसका निर्धारण राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों और शर्तियों से हटाया जाएगा जिन कारणों और शर्तियों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों तथा प्रादेशिक या क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। नियुक्ति के पश्चात् मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में अलापरकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार सविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों की पदाधिकार अथवा कार्यकाल को पूर्ण संरक्षण प्रदा करता है जिससे वे अपने कार्यों को निराला निष्पक्षता तथा बिना किसी हस्तक्षेप से कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और निर्वाचन आयुक्त की स्थिति में अन्तर केवल इतना है कि प्रथम को 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जबकि द्वितीय को केवल एक निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

संविधानसभ—चुनाव अथवा निर्वाचन आयोग का अपना सचिवालय होता है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपनिर्वाचन आयुक्त, सचिव, अन्य सचिव, अनुभागाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। निर्वाचन आयोग प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से अनेक शाखाओं में विभाजित है, यथा— निर्वाचन शाखा I, II, III, IV आदि परिसीमन शाखा प्रशासकीय शाखा I एवं II, टंकन एवं प्रेषण शाखा आदि।

निर्वाचन आयोग के कार्य एवं अधिकार—निर्वाचन तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान निर्वाचन आयोग को ही प्राप्त है। आयोग से अपेक्षा की जाती है कि समय-समय पर सरकार को कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन भेजता रहेगा और निर्वाचन-प्रक्रिया को व्यवस्थित तथा कुशल बनाने के लिए सुझाव देता रहेगा।

निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों की देखरेख, संचालन और नियन्त्रण से सम्बन्धित हर विषय का अधिकार दिया गया है। आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1 निर्वाचन क्षेत्रों का परिमोचन या सीमांकन करना।

2. मतदाताओं की सुविधों तैयार करवाने और उन्हें नवीनतम बनाए रखने हेतु निर्देशन करना।
3. संसद, राज्य विधानमण्डलों, राष्ट्रपति के चुनावों का असीछन, निर्देशन और नियंत्रण करना।
4. निर्वाचनों का संचालन करना।
5. संसद तथा राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचित न्यायाधिकरण को नियुक्ति करना।

6. संसद तथा राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की अर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना।

7. निर्वाचन आयोग को अधिकार है कि वह राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए मान्यता जिन आधारों पर प्रदान की जाए, इसका निर्णय निर्वाचन आयोग ही करता है। आम चुनाव के परचाय् दलों को मिले मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की सूची में संशोधित किया जाता है। उदाहरणार्थ, पहले आम चुनाव के बाद आयोग ने निरूपण किया था कि राष्ट्रीय दल के रूप में केवल उस दल को मान्यता दी जायेगी, जिसे लोकसभा चुनाव में कुल मतों के 13 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हों। उसी प्रकार राज्य-स्तरीय दल के रूप में केवल उन दलों को मान्यता देने का निरूपण किया था, जिनकी सम्बन्धित राज्य के विधान सभा चुनाव में दिए गए कुल मतों के कम से कम 3 प्रतिशत मत प्राप्त किए हों। अवश्यजन पड़ने पर चुनाव आयोग इसमें समय-समय पर परिवर्तन भी कर सकता है।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की दो श्रेणियाँ हैं—एक 'राष्ट्रीय दल', दूसरे 'राज्यीय दल'। यदि किसी दल को चार या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है तो उसे 'राष्ट्रीय दल' माना जाता है। यदि किसी दल का चार से कम राज्यों में मान्यता मिले तो उसे राज्य का या जिन राज्यों में मान्यता प्राप्त हों 'राज्यीय' दल माना जाता है।

8. राजनीतिक दलों को आरंभिक चुनाव-चिह्न प्रदान करना आयोग का कार्य है। यदि किसी दल को मान्यता मिलनी है तो उसे एक चुनाव चिह्न दिया जाता है। कुछ चिह्न सुरक्षित हैं और अन्य 'मुक्त', सुरक्षित चिह्न मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को दिए जाते हैं। 'मुक्त' चिह्न अन्य सब के लिए होते हैं। यदि चुनाव चिह्न के सम्बन्ध में किसी दो राजनीतिक दलों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाए तो आयोग निष्पक्षता के ढंग से विवाद का निश्चय करने का प्रयास करता है। समय-समय पर भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनाव चिह्न सम्बन्धी विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। सन् 1969 के बाद संगठन कमिशन तथा कमिशन (आई) के मध्य भी कमिशन के चुनाव चिह्न को लेकर ऐसा ही विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें निर्वाचन आयोग ने कमिशन का चिह्न 'दो बैलें की जोड़ी' कमिशन (आई) को दिये जाने का निर्णय किया था।

9. राजनीतिक दलों को आक्राशवाणी तथा दुरदर्शन द्वारा चुनाव-भाषणों के प्रसारण की सुविधाओं की व्यवस्था करना, आधार संहिता का निर्माण करना, प्रत्याशियों द्वारा कुछ व्यय की राशि का निर्धारण करना, निर्वाचन व्ययपत्रों के बारे में सरकार को आवश्यक परामर्श एवं सुझाव देना।

10. आयोग चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। चुनाव प्रक्रिया का प्रारम्भ जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 14वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिमूचना से होता है, जिसमें राष्ट्रपति मतदाताओं में विधायका के निर्वाचन का प्रावधान करते हैं।

11. निर्वाचन आयोग संसदीय और विधानमण्डली चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में व्यय की गई राशि का विवरण माँगता है तथा उस विवरण की जाँच करवा सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग ने जिना निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश दिये हैं कि वे प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में व्यय की गई राशि की जाँच-पड़ताल करें। इसमें प्रत्याशियों की सतर्क कार्य करना पड़ता है।

12. निर्वाचन आयोग चुनाव आचार संहिता को लागू करने के लिए विभिन्न कार्यवाहियाँ करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले राजनेताओं और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करता है।

13. निर्वाचन आयोग की अनुमति के परचाय् ही निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किये जाते हैं।

14. निर्वाचन आयोग द्वारा ही उपचुनावों को सम्पन्न किये जाने की व्यवस्था की जाती है।

15. निर्वाचन आयोग जल्दी मतदान की रोकने के लिए तथा मतदाताओं की पहचान को निश्चिन करने के लिए उनके 'फोटो' के सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर सकता है। इस मुद्दे ने केन्द्र और राज्य सरकारों को उद्बेजित कर रखा है। वे इस दिशा में गंभीरता से सोचने लगे हैं।

(ख) राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग

प्रशासनिक तंत्र में दूसरा स्थान राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग का है। संविधान में प्रावधान है कि 'विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व अथवा अन्य निर्वाचन से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके निर्वाचन आयोग का गठन गण-कार्यों में आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।' प्रादेशिक आयुक्त (Regional Commissioners) को सेवा-शर्तों और पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति समद के कानून के अन्तर्गत करेगा और उन्हें आयोग की सलाह पर ही हटाया जा सकेगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन आयोग प्रार्थना पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल निर्वाचन अथवा प्रादेशिक आयुक्त को आयोग के कार्यों को करने के लिए आवश्यक कर्मचारी देपलव्य करायेंगे।

राज्य स्तर पर जिस निर्वाचन विभाग का निर्माण किया गया है उसके अध्यक्ष को 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' कहा जाता है। उसकी नियुक्ति प्रशासनिक सेवाओं में से अथवा न्यायिक सेवाओं में से निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। उसका स्तर राज्य-सचिव के समान होता है और उसके मुख्य कार्य हैं—आयोग के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण में मतदाता सूचियों तैयार करवाना, उन्हें नवीनतम रखना और प्रकाशित करवाना। किसी राज्य में पूर्णकालिक निर्वाचन अधिकारी होगा है तो किसी में अंशकालिक। डॉ. एच. पी. राय ने लिखा है "अम चुनावों में प्रत्येक राज्य में निर्वाचन विभाग रूप लिए होता है। किसी राज्य में पूर्णकालिक (Whole Time) निर्वाचन अधिकारी होता है तो किसी में अंशकालिक। पूर्णकालिक अधिकारी के अधीन अन्य कर्मचारी होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करने के लिए तीन स्थाई उपकरणों की व्यवस्था है—(i) निर्वाचन आयोग, (ii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं (iii) निर्वाचन सम्बन्धी पंजीयन अधिकारी। विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक पंजीयन अधिकारी होता है जो प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम अंकित करता है और मृत लोगों के नाम निकाल देता है। प्रत्येक सप्ताह एवं विधानसभायी निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन पदाधिकारी (Returning Officer) नियुक्त होता है जिसके कार्यों में सहायता देने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। वास्तविक मतदान अनेक अधिकाधिक और अधिकाधिक के संचालन में सम्मिलित होता है। प्रत्येक मतदान क्षेत्र के लिए एक प्रसाहडिंग ऑफिसर और अनेक मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जिनकी सहायता के लिए पुलिस तथा अन्य कर्मचारी आवश्यकतानुसार दिए जाते हैं।"

अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी—अधीनस्थ अधिकारी दो प्रकार के होते हैं—प्रथम वे अधिकारी जो स्थाई रूप से निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त होते हैं और द्वितीय वे अधिकारी तथा कर्मचारी जो चुनाव के समय कार्य विशेष के लिए अस्थाई रूप से निर्वाचन पदों पर रखे जाते हैं। प्रथम प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(i) **जिला निर्वाचन अधिकारी**—प्रत्येक जिले में निर्वाचन अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। सामान्यतः यह पद जिलाधीश को ही दिया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले के निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यों में सम्मिलित करता है। उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करना होता है। जिले में चुनाव कर्मचारियों के लिए बाहनों के प्रबन्ध करने, चुनाव के लिए आवश्यक सामान इकट्ठा करवाने, मतदान केन्द्र दल की नियुक्ति करने, चुनाव एवं पंजीयन से सम्बन्धित कार्यों पर नियंत्रण रखने आदि का उत्तरदायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी पर ही होता है।

(ii) **उप-मण्डलीय निर्वाचन अधिकारी**—जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए उप-मण्डलीय निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वे अधिकारी अंशकालिक होते हैं। इनकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। एस. डी. ओ. अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को उप-मण्डलीय निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाता है। जहाँ पूर्णकालिक नियुक्तियाँ होती हैं वहाँ नीचे स्तर के अधिकारी भी रख दिए जाते हैं।

(iii) **निर्वाचन पंजीयन अधिकारी**—निर्वाचन आयोग द्वारा एस. डी. ओ. को ही निर्वाचन पंजीयन अधिकारी बनाया जाता है। वह जिला निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। मतदाता सूची को नवीनतम बनाए रखना, नए मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना, मृत्यु तथा अन्य किसी कारण से मतदाता सूची से नाम हटाना, नाम स्थानान्तरित करना आदि कार्य निर्वाचन पंजीयन अधिकारी की निम्नलिखित पड़ते हैं। पंजीयन का कार्य समय-समय पर सरोचित किया जाता रहता है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार इस प्रकार का सरोक्षण तीन अवसरों पर हो सकता है—लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन से पहले, किसी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्य के निर्वाचन से पहले एवं निर्वाचन आयोग के आदेश पर। पंजीयन कार्य में सहयोग के लिए निर्वाचन पंजीयन अधिकारी किसी भी कर्मचारी को रख सकता है।

(iv) सहायक निर्वाचन परीक्षण अधिकारी—यह अधिकारी भी निर्वाचन परीक्षण अधिकारी के कार्यों में सहायक करता है, पर विशेष रूप से इसे परीक्षण के विरुद्ध शिकायतें सुनने का दायित्व सौंपा जाता है अधिकारों तहमनदार को इस पद पर रखा जाता है।

(v) अन्य परीक्षण अधिकारी—परीक्षण के कार्य के लिए निर्वाचन परीक्षण अधिकारी आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को नियुक्ति कर सकता है। परिणाम के पद पर परीक्षण को नियुक्त किया जाता है।

दूसरे प्रकार के अर्थात् असाई रूप से निर्वाचन-परी पर रखे जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में प्रमुख ये हैं—

(i) चुनाव अधिकारी—निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव अधिका निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है और उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कभी-कभी एक अधिकारी के नीचे एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र भी रख दिए जाते हैं। संसदीय क्षेत्र के लिए सामान्यतः जिलाधीश को दो चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र के लिए अध्यादेश अधिकारी को चुनाव अधिकारी बना दिया जाता है। चुनाव अधिकारियों का मुख्य कार्य मतदान केंद्र के व्यवस्थापन, आवश्यक सुविधाएं तैयार करना, निर्वाचन कार्यक्रम और वितरित प्रश्नों की रूपरेखा तैयार करना, मतदान-पत्र वितरण करना, उनका परीक्षा करना, चुनाव सहने वाले उम्मीदवारों को अन्तिम सूची तैयार करना, अन्तिम क्षेत्र में चुनाव का पूर्ण प्रबन्ध करना और मतगणना तथा परिणाम की घोषणा करना आदि है।

(ii) मतदान केन्द्र दल के कर्मचारी—इन्हें नियुक्ति बिना निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। मतदान केंद्र दल में एक अधिकाधिक अधिकारी, एक मतदान अधिकारी और दो चयनित होते हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र दल के एक पुलिस की ओर से एक हवलदार और दो सिपाहियों रखे जाते हैं। मतदान अधिकारियों को, नियुक्ति बिना निर्वाचन अधिकारी, अधिकाधिक अधिकारी द्वारा की जाता है। किसी मतदान अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित न हो तब पर अधिकाधिक अधिकारी को उसके स्थान पर अन्य नियुक्ति का अधिकाधिक होता है। मतदान केन्द्र दल का कार्य मतदान केन्द्र पर मतदान का कार्य पूर्ण करना है। अधिकाधिक अधिकारियों के पद पर उपस्थित अधिकारी को रखे जाते हैं पर नीचे के स्तर के कर्मचारियों को भी रखा जा सकता है। मत-पत्रों को छपाने आदि के लिए कुछ सहायक निर्वाचन अधिकारी, कौटिल्य, चौक, नम्बरमैन, परिवहन, सहायक कर्मचारी आदि भी रखे जाते हैं। चुनाव कार्य के पर्यवेक्षण के लिए कुछ पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया जाता है। कानून और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कुछ मजिस्ट्रेटों की विशेष नियुक्ति की जाती है।

स्थानीय सभाओं का निर्वाचन

स्थानीय सभाओं के निर्वाचन व्यवस्था आदि का उदाहरणित राज्य सरकार का है, अतः इनके निर्वाचन प्रणाली का दृष्टिगत राज्य सरकारों पर है। इसीलिए राज्य के निर्वाचन विभाग को दो शाखाओं में विभक्त किया जाता है—प्रथम व्यवस्थापिकाओं के लिए और द्वितीय स्थानीय सभाओं के लिए। व्यवहार में दोनों शाखाओं का सम्पर्क स्पष्टित कर दिया जाता है। जिला स्तर पर भी निर्वाचन कार्यलय में ये दोनों शाखाएं होती हैं, तथापि ये निश्चित सभाओं में कार्य करती हैं। राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही सरकार के निर्वाचन विभाग का निदेशक होता है और स्थानीय सभाओं के निर्वाचन कार्य उन्हीं के अधीन होते हैं। स्थानीय सभाओं के लिए चुनाव अधिकारी तथा निर्वाचन परीक्षण अधिकारी जिम्माधार होता है।

निर्वाचन आयोग की अन्वेषणा

निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित आचारों पर अन्वेषणा की जाती है—

(1) एकल सदस्यीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था दोषपूर्ण है। वह मुख्य निर्वाचन आयोग को अर्थाधिकार शक्तिहीन बनाती है जिससे वह अमान्यित व्यवहार भी कर सकता है।

(2) बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की अपनी समस्या है। मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयोगों के बीच क्षेत्राधिकार और शक्तियों की लेकर भी अनेक विवाद खड़े हो सकते हैं। इससे निर्वाचन आयोग की प्रविष्टि को नुकसान पहुँचता है। अतः मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य आयोगों के बीच अपनी विस्तार और सम्बन्ध न होने की भी समस्या बनी रहती है।

(3) निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन सम्पन्न करने के लिए स्वयं की शक्तियों या शरणाग्र-कर नहीं है। अतः उसे इस हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे भी निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनेक बार केन्द्र तथा राज्य सरकारों निर्वाचन आयोग के प्रति उदासीनता का व्यवहार करती हैं।

(4) निर्वाचन आयोग की कार्य-शैली भी आत्मचरित्र का विषय है। विपक्षी दलों को यह सिखाया रहता है कि निर्वाचन आयोग की कार्य-शैली से सत्ताकण्ड दल को अनुचित लाभ पहुँचता है। दूसरी ओर, सत्ताकण्ड दल भी निर्वाचन आयोग की कार्य-शैली से असन्तुष्ट रहता है। अतः निर्वाचन आयोग को इस दुविधा का सामना करना पड़ता है।

(5) निर्वाचन आयोग के देश में निर्वाचनों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने की समस्या है। उसके सामने जाली मतदाता को रोकने, हिंसक घटनाओं को रोकने, कालेधन का बढ़ता विस्तार, मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा करने की घटनाएँ, मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा सभ और राज्यों में निर्वाचन तंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाये रखने जैसी समस्याएँ आती हैं जो निर्वाचन आयोग के सम्मुख अनेकानेक चुनौतियाँ उपस्थित कर रही हैं।

(6) मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सब व्यवस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान नहीं है। उसके लिए यह व्यवस्था नहीं है कि वह जज की तरह एक निश्चित छद्म तक अपने पद पर बना रहेगा। उसकी नियुक्ति केवल दो तीन वर्ष के लिए भी हो सकती है अतः इस सम्पालना से इनकार करते किष्क जा सकता कि नियुक्ति होने की आशा में वह सत्ताकण्ड साकार और दल का पक्षपात करे। सरकार को खुश करने पर उसे यह आशा रहती है कि रिटायर होने के बाद वह दूसरे अथवा पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस बात की भी सम्पालना रहती है कि मजिस्ट्रेट्स की सलाह पर हाइपरी किशो दलियो नेता को चुनाव आयुक्त बना दे।

निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने की दिशा में कतिपय सुझाव

निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने की दिशा में निम्नलिखित सुझाव, कारगर सिद्ध हो सकते हैं—

(1) निर्वाचन आयोग को शासन से पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया जाए तथा उसे अपना स्वतंत्र कार्यवाही वर्ग दिया जाए ताकि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यकारी वर्ग पर आयोग की निर्भरता न रहे।

(2) निर्वाचन आयोग को शक्ति-सम्पन्न बनाया जाए और आयोग में कुछ स्वतंत्र निरीक्षक रखे जाएँ जो निर्वाचन के समय आकस्मिक छपा मारकर अनियमितताओं का पता लगा सकें।

(3) निर्वाचन आयोग को वांछित शक्तियाँ दी जानी चाहिए जिससे कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सम्पादित कर सके तथा अनियमितताओं को रोक सके।

भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक

(Comptroller and Auditor General of India)

लोक-हित पर नियन्त्रण के लिए किष्कणीय व्यव के सेलों का परीक्षण कार्यपालिका के स्वात्र क्रिया द्वारा किया जाता है। भारत में यह कार्य नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया गया है। यहाँ लेखा-परीक्षण विभाग की रचना 1753 में हो चुकी थी, किन्तु स्वतंत्र निकाय के रूप में इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत की गई। सन् 1935 के अधिनियम द्वारा उसका स्तर बढ़ा दिया गया। सन् 1947 के स्वात्रता अधिनियम में उसको शक्तियाँ सौंपी गईं। जब देशी रियासतों भी भारत सभ में शामिल हो गईं तो लेखा-परीक्षा के क्षेत्र में सारा देश आ गया। सन् 1950 के नए संविधान में महालेखा परीक्षक के पद का नाम बदल कर नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए. जी.) कर दिया गया। उसे सर्वोच्च न्यायाधीशों की भीति एक संवैधानिक अधिकारी का पद दिया गया।

नियुक्ति एवं सेवा शर्तें (Appointment and Conditions of Service)—सी. एण्ड ए. जी. की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा युक्त अधिव्यत्र द्वारा करता है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की भीति अपने कार्य की शपथ लेता है। इसका वेतन तथा सेवा की शर्तें संसदीय कानून द्वारा निश्चित की जाती हैं किन्तु जब तक ऐसा न हो तब तक ये संविधान की द्वितीय अनुसूची के अनुसार रहेंगी। इसकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सन् 1953 में ससद ने इसके कार्यकाल तथा पेंशन सम्बन्धी अधिकारों का नियमित करने के लिए व्यवस्थापन किया और अन्ना शर्तों को पूर्ववत् करने दिया।

वर्तमान में इसका कार्यकाल छ वर्ष का है। इस पद पर ठा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितना वेतन पाता है उतरे सेवा-नियुक्ति की विशेष दर का इक्का होता है। यह पद से हटने के बाद संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य नहीं कर सकता। इसके न्यायलक्ष्य का प्रशासनिक व्यवहार की शक्ति निधि से दिया जाता है। उसके वेतन, शर्तें पेंशन आदि पर होने वाले व्यव के सम्बन्ध में ससद मतदान नहीं कर सकती। संविधान द्वारा इसकी सेवा-शर्तें कर्तव्य एवं अधिकार की प्रकार से स्पष्ट करने का कार्य ससद को दिया गया है। ससद ने उसके कार्यों की स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित नहीं की है फलतः इसके अधिकार तथा पद सम्बन्धी अस्पष्ट शक्ति कई बार सन्देह उत्पन्न कर देती है।

लिए गठन करेंगे। यह आयोग एक अध्यक्ष और छह सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा याचक और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से चयन किया जाएगा, परन्तु अध्यक्ष को मिलाकर पाँच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें—(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य या तीन सत्रों तक कार्य करेगा। तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) अध्यक्ष या सम्पूर्ण केंद्रीय सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित सचिव द्वारा या राज्य सरकारें प्रति अध्यक्ष या सम्पूर्ण राज्य सरकारें कर सकेंगी।

(3) केंद्रीय सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटाने का अधिकार नहीं देगी कि वह व्यक्ति—

(क) निर्वासित हो जाता है

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में निर्दोषता अथवा अनिर्दोषता है उसे पकड़ा और बरखास्त या दण्डादिष्ट किया जा रहा है।

(ग) विद्वान होने पर किसी सभ्य व्यापकता द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है

(घ) कार्य करने में असमर्थ अथवा इनकार करने

(ङ) स्थिति के बिना लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है।

(च) केंद्रीय सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का दुरुपयोग करता है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों का साक्षात्कार के लिए हानिकारक हो गया है।

परन्तु इस छूट के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं दे दिया जाता है।

(4) उपधारा (2) के अधीन होने वाली शक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा पूरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो राज्य की जाएगी।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी—(1) केंद्रीय सरकार आयोग के लिए एक सचिव और तीन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जिन्होंने इस अधिनियम के अधीन आयोग के कर्मचारियों का दायित्वपूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विधि की जाएगी।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाएगा—(1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या नियुक्त सचिव द्वारा प्रमाणित आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

आयोग के कृत्य—(1) आयोग निम्नलिखित सभी या शिष्ट कृत्यों का पालन करेगा—

(क) राष्ट्र और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विचारों का मूल्यकन करना।

(ख) संविधान में संसद तथा राज्य विधान-मण्डलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपस्थित त्रुटियों का कार्य को करना।

(ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सिफारिशें करना।

(घ) अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना और ऐसे मामलों को सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष ठठाना।

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विवेक के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना और उनका दूर करने के लिए सिफारिशें करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन अनुसंधान और विस्तार करना।

(छ) किसी अल्पसंख्यक के सम्बन्ध में ऐसे सम्बन्धित सुझाव देना जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने चाहिए।

(ज) अन्यसदस्यों से सम्बन्धित किसी विषय पर और विशिष्टता उनके सामने आने वाली बर्तनस्थितियों पर, केन्द्रीय सरकार को विरोध रिपोर्टें देना और

(क) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ठस निर्दिष्ट किया जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निहित सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक ड्रॉप के साथ रखवाणी जिसमें सभ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और किसी ऐसी सिफारिशों की यदि कोई हो, स्वीकार न किया जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण होगा।

(3) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निहित कोई सिफारिश या उसके कोई भाग, किसी राज्य सरकार से सम्बन्धित है वहां आयोग ऐसी सिफारिश या उसके भाग की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष एक ड्रॉप के साथ रखवाणी जिसमें राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और किसी ऐसी सिफारिशों या उनके भाग की यदि कोई हो, स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण होगा।

(4) आयोग को उपधारा (1) के उपखण्ड (क), (ख) और (घ) में वर्णित कार्यों में से किसी का पालन करते समय और विद्विष्टता निम्नलिखित विषयों की बाबत, किसी बात का विचार करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ हारी अवस्था—

(क) भारत की किसी भी भाग से व्यक्तियों को सम्म भेजना और हजर करना तथा शरण पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दम्पत्य का प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना,

(ग) शपथपत्रों पर माक्ष प्रमाण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी लोक अधिलेख या उसकी प्रतिनिधि की अपेक्षा करना,

(ङ) सश्रियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग

(National Commission for Women)

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन—(1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से निम्न का गठन करेगी जो 1990 के अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा।

(2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो,

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य सम्बन्धित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से पाँच सदस्य जिन्हें विशिष्ट, अवसरानुसंग आन्दोलन महिलाओं के निर्माण की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबन्ध स्वीच्छिक महिला संगठन (जिनके अन्तर्गत महिला कार्यकर्ता भी हैं) प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव।

परन्तु अनुमूर्धित जर्ज और अनुमूर्धित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सदस्य-सचिव जो—

(i) प्रबन्ध, संगठनात्मक सञ्चय या सामाजिक आन्दोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, या

(ii) ऐसा अधिकारी जो सच की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अपना सभ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें—(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य ऐसे सदस्य-सचिव से भिन्न जो सच की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा सभ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित लेख द्वारा किसी भी समय यथास्मिन्, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति—

(क) दिवानिया हो जाता है,

- (छ) किसी अपराध के लिए सिद्धोष उहराया और कारावास से दण्डादि किया गया हो तथा जिसमें केन्द्रीय सरकार के अनुसार नैतिक शयता अनार्यस्त है,
- (ग) विद्रुतिचिन का हो जाता है और न्यायनय की ऐसी घोषणा किलयन है,
- (घ) कार्य करने में असमर्थ इनकार करना
- (ङ) स्वीकृति लिए बिना आपोग के लगाता तीन अधिवेशनों से अनुपस्थित रहना
- (च) केन्द्रीय सरकार की राय में उसने अध्यास या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बना रहना लोकहित के लिए अहितकर है

यहनु इस खण्ड के अधीन बिस्ने ध्वनित को तब तक नहीं हटया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति का इस विषय मुआयई का डरिन अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपपारा (2) के अधीन होने वाली शक्ति नए नार्मनिदेशन द्वारा थरी जएगी।

(5) अध्यास और सदस्यों को धन एवं भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

आयोग के अधिकारों और अन्य कर्मचारियों—(1) केन्द्रीय सरकार आया 4 के लिए ऐसे अधिकारियों और अधिकारियों को ध्यनस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हैं।

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिए निपुण अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेना और भत्त और उनकी या के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

आयोग के कृत्य—(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किसी कृत्यों का पालन करेगा अर्थात्—

- (क) महिमाओं के लिए सविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबधित रक्षाणों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना
- (ख) उन रक्षाणों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना
- (ग) महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षाणों के लिए सिफारिशें करना
- (घ) सविधान और अन्य विधियों के महिमाओं को प्रभावित करने वाले विधायन उपबन्धों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके समोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधायन में किसी कर्म अपर्याप्तता या बृद्धियों को दूर करने के लिए विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके
- (ङ) सविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के महिमाओं से सम्बन्धित अतिव्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष ठठाना
- (च) निम्नलिखित से सम्बन्धित विषयों पर शिक्षावर्तों की जांच करना और स्वचरेणा से ध्यान देना—

- (i) महिमाओं के अधिकारों का बयन
- (ii) महिमाओं की सहाय्य ब्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का क्रियान्वयन
- (iii) महिमाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका बल्यण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुशील उपलब्ध करने के नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धान्तों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों का समुचित प्राधिकारियों के समक्ष ठठाना

(छ) महिमाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से सम्बन्धित समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन करना या करना और भाषाओं का पता लगाना जिससे उनको दूर करने की योजनाओं को सिफारिश की जा सके

(ज) सर्वजन और शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में धिष्य उत्तरे के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और नुनियारी सेवाओं की प्राप्ति में आने वाली उन्नाउपन और उपजोबिका स्थाय्य परिसंकोटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहाय्य सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता

(झ) महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना में भाग लेना और सहाय्य देना

(ञ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास का मूल्यांकन करना

- (2) किसी जेल, मुफार गृह महिलाओं की सहाय या अधिरा के अन्य स्थान की जहाँ महिलाओं की यन्त्रों के रूप में रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और औद्योगिक कार्यवाही के लिए, यदि आवश्यक हो, सम्बन्धित प्रविष्टियों से बाधित करना।
- (2) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित मुद्दों के लिए धन उपलब्ध करना।
- (3) महिलाओं में सम्बन्धित किसी बात के और विविधता उन विभिन्न परिस्थितियों के बारे में जिसके अर्थों महिलाएं कार्य करती हैं, सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना।
- (4) कोई अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को सप्ताह ५ प्रत्येक सदन के सत्र रखी जाएगी और उसके साथ साथ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तुत कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अन्वीकृत की गई हैं तो अन्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने काया प्रयास भी होगा।

(3) जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट या दस्तावेज कोई एक विषय से सम्बन्धित है जिसका विषय राज्य सरकार सहाय्य है वहाँ आयोग ऐसी रिपोर्ट या उसके भाग की एक प्रति उस राज्य सरकार को भेजगा जो उसे राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखनी होगी और उसके साथ राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तुत कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अन्वीकृत की गई हैं तो अन्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने काया प्रयास होगा।

(4) आयोग की उपधारा (1) के खण्ड (क), (घ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय और विविधता निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे सभी शक्तियाँ होंगी जो वचन का विचारण करने वाले निम्नलिखित शक्तियों की हैं, अर्थात्—

- (क) भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को मनन भेजना और हजरि करना तथा राज्य पर उसकी परीक्षा करना।
- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करना।
- (ग) राज्य परी पर साक्ष्य प्रदान करना।
- (घ) किसी न्यायलय या कार्यलय से किसी लेख अभिलेख या उनकी प्रतिलिपि को अर्जित करना।
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कर्मचारी निकालना और
- (च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

पिछड़ा वर्ग आयोग

(Backward Class Commission)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 340(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को सार्वजनिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की स्थिति तथा उनकी कठिनाइयों के सम्बंध में अनुसंधान के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति है। आयोग इन वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों के लिए या उनके लिए दिए जाने वाले अनुदान या अनुदान की शर्तों आदि के बारे में सच या राज्य सरकारों को अपनी सिफारिश भेजेगा।

आयोग दिए गए विषयों का अनुसंधान करेगा और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा तथा उसमें पाए गए तथ्यों का समावेश करेगा और ऐसी सिफारिशें करेगा जिसे आयोग उचित समझे। राष्ट्रपति आयोग द्वारा दिए गए प्रस्तावनों को उस पर की गई कार्यवाहियों सहित सदन के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवरेगा। आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् राष्ट्रपति आदेश द्वारा पिछड़े वर्गों को उल्लिखित करेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति आदिश शक्तियों के लिए नियुक्त विशेष पदाधिकारी पिछड़े वर्गों के लिए भी कार्य करेगा।

संविधान की इस व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक दो आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। एक 1953 में काका काबेलकर की अध्यक्षता में और दूसरा 1978 में बी.पी. मन्डस की अध्यक्षता में। पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के लिए सदन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 पारित किया जिसके अधीन आयोग की स्थापना अगस्त, 1993 में की गई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

(National Human Rights Commission)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत केन्द्र की सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की शक्ति प्रदान की गई है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं।

राजनीतिक दल व्यवस्था एवं दबाव समूह (Political Party System & Pressure Groups)

लेबरन्त्र के लिए राजनीतिक दल अविहार्य हैं।¹ वर्तमान में देश के आधारभूत सांस्कृतिक ढाँचे के राजनीतिक दल महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। दल-प्रणाली के बिना लोकतन्त्रात्मक शासन का कार्य ही नहीं उन सकारात्मक दलों का महत्व सर्वविदित है।

दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार

(Ideology and Social Basis of Parties)

समसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की विशिष्ट भूमिका है। भारत एक बहु-दलीय व्यवस्था वाला देश है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय स्तर के तथा अनेक क्षेत्रीय और पञ्जीकृत दलों का अस्तित्व है। देश की राजनीतिक व्यवस्था का मंचालन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वतन्त्र भारत में राजनीतिक दलों का विकास

(Development of Political Parties in Independent India)

देश में राष्ट्रीय स्तर के दो दल थे—भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा साम्यवादी दल। काँग्रेस ने राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। बर्षाब में काँग्रेस राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप में दल नहीं एक था था जबकि साम्यवादी दल का सीमित रूप में प्रभाव था। इनके अतिरिक्त दक्षिण में द्रविड़ कड़गम तथा उत्तर में हिन्दू महासभा जैसे दल विद्यमान थे। स्वतन्त्रता के बाद राजनीतिक दलों का विकास आरम्भ हुआ। सन् 1948 में रामजन्म परिषद की स्थापना हुई। 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का उदय हुआ जो द्रविड़ कड़गम से प्रेरित हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा गठित किया गया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने भारतीय समाजवादी दल की और आचार्य कृष्णानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। 1951 में डॉ. जयप्रकाश मुकुजी ने भारतीय जनसभा की स्थापना की।

1952 में भारतीय समाजवादी दल तथा किसान मजदूर पार्टी के विलय के फलस्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (प्रतोप) का जन्म हुआ। 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की नेत्रणा से स्वतन्त्र पार्टी अस्तित्व में आई। 1967 के चुनावों से पूर्व काँग्रेस से विद्रोह करके अनेक काँग्रेसियों ने क्षेत्रीय दलों की स्थापना की। इनमें जन काँग्रेस, बंगाल काँग्रेस, प्रमुख थे। इन असंतुष्ट काँग्रेसियों ने काँग्रेस को पराजित करने की दृष्टि से विपक्षी दलों के साथ चुनावी गठबन्धन किये जिससे देश में काँग्रेस विरोधी बालावाण बना।

1969 में काँग्रेस का दो भागों में विभाजन हुआ—नई काँग्रेस (श्रीमती गीरी के नेतृत्व वाली काँग्रेस) एवं सगठन काँग्रेस (जिस पुर्ण काँग्रेस कहा जाता था और जिसका नेतृत्व निजलिङ्गा कपूर, मोरारजी देसाई आदि के हाथों में था)। 1971 में श्रीमती गीरी को पराजित करने के लिए स्वतन्त्र पार्टी, जनसभा, सोशलिस्ट पार्टी और सगठन काँग्रेस ने 'महागठबन्धन' का निर्माण किया, लेकिन इन दलों को पराजय का सामना करना पड़ा। नई काँग्रेस को लोकप्रियता में दो-तिहाई स्थान प्राप्त हुए। 1972 में सोशलिस्ट पार्टी एवं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पुनः मिल गईं, फलस्वरूप सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के नाम से नया दल अस्तित्व में आया। कुछ समय पश्चात् इसमें भी फूट पड़ गई और रामजन्म और उनके समर्थकों ने 31 दिसम्बर 1972 को लखनऊ में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (समोप) को पुनर्जीवित किया तथा

1 Byer "Parties are inevitable. No free country has been without them. No one has shown how representative government could be worked without them."

एए एन पार्टी इसने अधस्त बने। जनमत से निर्धारित होने के बाद वरिष्ठ नेता कल्याण मधोक ने अर्धम् 1973 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा नामक नए दल का निर्माण किया। केंद्रित विभाजन के बाद अगस्त, 1974 में 'भारतीय लोकदल' का उदय हुआ जिसमें भारतीय कमिंस दल के अलावा स्वतंत्र पार्टी (पीयू मोदी गुरु), उच्छल कॉमिंस (बीजू पटनायक) क्रिसाना मजदूर पार्टी (चौदण्ण), समुदाय सोशलिस्ट पार्टी (राकेशरायण) और पत्राव खेतोबाड़ी जमींदारी कृषिजन तथा महेन्द्रासिंह जैसे दल मिल गए। चौथी वर्षासिंह इस दल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

अपनाग्रस्त में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा मार्च में चुनाव करवाने की घोषणा के दूसरे दिन चार गैर-साप्ताहिक दलों (संगठन कमिंस, जनता, भारतीय लोकदल और समाजवादी दल) ने 'जनता पार्टी' के नाम से नया दल बना। इस नए संगठित दल में विद्रोही कोयले शामिल होने लगे। 2 फरवरी, 1977 को भारतीय राजनीति में उस समय एक नया परिवर्तन हुआ जब जगजोहनराय ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल और केंद्रित से त्यागपत्र देकर 'लोकतांत्रिक कॉमिंस' नाम से नए दल की घोषणा की तथा इसके दूसरे प्रमुख सदस्य देववर्ता नन्दन बहुगुणा थे। लोकतन्त्री कॉमिंस ने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया। मार्च 1977 के चुनावों में भाजपाओं ने श्रेष्ठता गांधी और उनके दल की बुद्धि तह स पराजित करते हुए जनता पार्टी का सत्ताकूट होने का अवसर दिया। मई, 1977 में जनता पार्टी में शामिल प्रीति दत्त ने अपना विधिवत विनय कर लिया और चुनाव आयोग ने मान्यता देते हुए पार्टी के लिए 'चक्र-हल्कर' चुनाव-चिह्न प्रस्तावित कर दिया।

नवम्बर, 1979 में जनता पार्टी में विभाजन हुआ। राजसमूह की अण्डरग्रा में जनता (मिक्मूल) नामक एक नए दल का गठन हुआ और 15 नुपार् की मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया। 26 सितम्बर, 1979 को जनता (एस) अर्धार्थ सेक्यूलर, सोशलिस्ट पार्टी तथा उद्देश्य की जनता पार्टी को मिलाकर दिल्ली में एक नई पार्टी एनकेदल की घोषणा की। प्रधानमंत्री चरणसिंह लोकदल के प्रथम अध्यक्ष और जनता (एस) के अध्यक्ष राजनारायण उत्तम कार्यवाही अध्यक्ष चुन गये। कमिंस पार्टी अविभाजित नहीं रह सकी। इन्दिरा गांधी के समर्थकों और विरोधियों के बीच सत्ता-मार्ग के कारण 2 जनवरी, 1978 को कमिंस का पुनः विभाजन हुआ और दो कमिंस अखिल में आर्ज-इन्दिरा कॉमिंस एवं प्रह्लाद रेड्डी की अण्डरग्रा वाली कमिंस। श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाली कॉमिंस का प्रचार बढ़ा गया। सन् 1980 के लोकतांत्रिक चुनाव में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में कमिंस का को दो-तीस स्थान प्राप्त हुए और वह पुनः प्रधानमंत्री बनीं।

जनवरी, 1980 में आम चुनावों के बाद विपक्षी दलों में विपक्ष की प्रक्रिया चलती रही। जनता पार्टी के विधिल धरुं दल से अलग हो गए और उन्होंने अपना पुनर् अस्तित्व कायम कर लिया। फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी और जगजोहनराय के नेतृत्व में कमिंस (ज) नाम से नए दल अस्तित्व में आए। 1984 के लोकसभा के चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कमिंस (ज) ने लोकसभा में 401 स्थान प्राप्त करके सफलता प्राप्त की। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों—विशेषकर गैर साप्ताहिक दलों का अन्त हो गया। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि तेलंगदेशम जैसा क्षेत्रीय दल लोकसभा में दूसरे बड़े दल के रूप में उभरा।

1987 के बाद कमिंस (ज) का सराफा बिकल्प खड़ा करने के उद्देश्य से चौथी देवीलान ने गैर साप्ताहिक विपक्ष को संगठित करने के प्रयास किये। इसका परिणाम था—जनता पार्टी में लोकदल (अ) और श्रीमती मेनका गांधी के नेतृत्व वाले 'राष्ट्रीय जनय विचार मन्त्र' का विलय। इसी बीच विश्वनाथ प्रतापसिंह के समर्थकों ने कमिंस (ज) छोड़कर 'जन मोर्चे' की स्थापना की। चौथी देवीलान के प्रयत्नों से कमिंस (ज) विरोधी दलों के एकीकरण की दिशा में प्रयास चलते रहे। उनके प्रयासों का परिणाम था कि जनता पार्टी, लोकदल (ब), जनमोर्चा और कमिंस (एस) का विलय हुआ तथा 'जनता दल' नाम से नये दल का गठन। विश्वनाथ प्रतापसिंह को जनता दल का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जनता दल का अध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1989 के लोकसभा के चुनाव में इस दल के अध्यक्ष ने कमिंस (ज) के गमुख चुनौती उपस्थित की। इन गैर साप्ताहिक विपक्षी दलों ने 17 सितम्बर, 1988 को मद्रास में राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया। तेलंगदेशम के नेता और आंध्र प्रदेश के बकालीन मुखमरी एन टी रामराव को मोर्चे का अध्यक्ष तथा विश्वनाथ प्रतापसिंह को सयोजक बनाया गया। मोर्चे में शामिल प्रमुख दल थे—जनता दल, प्रमुख, असम गण परिषद, तेलंगदेशम और कमिंस (एस)। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और बाधपथी दलों के समर्थन से विश्वनाथ प्रतापसिंह के नेतृत्व में 'राष्ट्रीय मोर्चे' की सरकार सत्ताकूट हुई। 1990 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण इसका पतन हो गया।

नवम्बर 1990 में केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के पतन के बाद जनता दल का विभाजन हो गया। देवीलान और चन्द्रशेखर के समर्थकों ने जनता दल से अलग होकर जनता दल (समाजवादी) की स्थापना की। कमिंस (ज) ने चन्द्रशेखर की सरकार बनाने में सहायता दी। फरवरी, 1991 में कमिंस (ज) द्वारा इस सरकार से समर्थन वापस लेने

के कारण उसका पतन हो गया। 1991 के लोकसभा चुनावों में जनता दल (भाजपा) को पञ्चम या सातवां करना पड़ा। इसके बाद दल की शक्ति नग्न रह गई। जनता दल (बोम्बे) को शक्ति मिल गई। अजीतसिंह के नेतृत्व में अनेक समर्थन से जनता दल छोड़कर जनता दल (अ) का गठन किया। नवम्बर, 1992 के राज्य विधानसभा चुनावों से पूर्व जनता दल के पूर्व सदस्य—जनता दल (भाजपा) के सदस्यों, अजीतसिंह के नेतृत्व वाले जनता दल तथा जनता दल (बोम्बे) ने एकीकृत जनता दल के पुनर्गठित करने का निर्णय किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजीतसिंह के निर्णय के परभाव जनता दल (बोम्बे) के नेताओं और अजीतसिंह के समर्थकों के मध्य मतभेद बढ़ गये। अजीतसिंह ने पुनः जनता दल (अ) को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसके बाद दिसम्बर, 1993 को अजीतसिंह ने समर्थकों सहित कांग्रेस (अ) में शामिल होने का निर्णय लेकर सबको चौंका कर दिया। इससे जनता दल (अ) का कार्यात्मक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। 1996 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस (अ) को पञ्चम या सातवां करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में ठहर कर सामने आई। राष्ट्रीय मोर्चे और कामगार मोर्चे और कृषियोग सेनारो दलों को मिलाकर 'दोसरे मोर्चे' का गठन किया गया। बाद में 'तीसरे मोर्चे' की 'संयुक्त मोर्चे' का नाम दिया गया।

1985 के बाद क्षेत्रीय दल ठहर कर सामने आये हैं। उनमें बंगाली दल बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में मुलायमसिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, असम गण परिषद, अरुणाचल प्रदेश (लोगोवाल), अरुणाचल प्रदेश (मान), नरबहादुर सिंह धर्मदारी के नेतृत्व में सिक्किम समाज परिषद तथा मिजोरम में लालटेन के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट भी शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के रूप में उभर कर सामने आये हैं। 1994 के चुनाव में मद्रास में शिवसेना ने भाजपा से गठबन्धन कर सत्ता पर कब्जा हो गई। 1994 में आन्ध्रप्रदेश में एन टी रामा राव के नेतृत्व में तेलगुदेशम को दौलिसिंह समर्थन प्राप्त हुआ। रामा राव पुनः राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वे अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह सके। उनके दोमाद चन्द्रबाबु नायडू के नेतृत्व में तेलगुदेशम के अनेक विधायकों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस पर रामा राव को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। चन्द्रबाबु नायडू राज्य के नये मुख्यमंत्री बने। तेलगुदेशम की (नायडू गुट) की सत्ता हो गई। इसके रामा राव की पत्नी चन्द्रबाबु नायडू और कुछ ही समय बाद उनका दैहिकान्त हो गया। इसके बाद रामा राव की विधवा पत्नी लक्ष्मी पर्वती ने तेलगुदेशम (रामा राव) का नेतृत्व किया, लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में तेलगुदेशम (नायडू गुट) को हार का सामना करना पड़ा और लक्ष्मी पर्वती गुट का पूरी तरह से सन्ध्या हो गया। केन्द्र में एच. डी. देवेगौडा का प्रधानमंत्री बनने में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबु नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तमिलनाडु कांग्रेस (अ) का ईश्वर ने तमिलनाडु प्रधानमंत्री और कांग्रेस (अ) अध्यक्ष नरसिम्हा राव द्वारा अन्ना द्रमुक के साथ चुनाव गठबन्धन करने के निर्णय से 'बुद्धि' होकर विद्रोह कर दिया। जी. के. मुन्नाय तथा पी. रिदुवाम के नेतृत्व में एक नया क्षेत्रीय दल 'तमिल मनीसा कर्गिस' का गठन किया। इस दल ने एम. करुणाधिपति के नेतृत्व वाली द्रमुक के साथ चुनाव गठबन्धन करके सफल अभिजित किया। द्रमुक तथा 'तमिल मनीसा कर्गिस' की केन्द्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार को प्रतिष्ठित करने में भूमिका रही। पञ्जाब में अरुणाचल प्रदेश (बादल) एक शक्तिशाली राजनीतिक दल बनकर उभरा। हरियाणा में चौधरी बरिहाल की 'हरियाणा विकास पार्टी' एक प्रभावशाली क्षेत्रीय दल के रूप में उभरी। जर्ज फर्नांडीस के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। इनके अतिरिक्त पारवट्टे ब्राह्मण, आरएसपी, केजल, असम गण परिषद, मुस्लिम लीग, नाग नेशनल कर्गिस (नागलैण्ड), मिजो नेशनल फ्रंट (मिजोरम), अन्ना पीपुल्स दल लोहदी कॉलेज (मिजोरम) तथा सिक्किम गण परिषद (सिक्किम) आदि प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं।

भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ

भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का विश्लेषण विभिन्न क्रमों में विभाजित करके निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है—

मार्च, 1977 के पूर्व तक दलीय व्यवस्था

मार्च, 1977 को एक विभ्रान्तकेन्द्र माना जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के 30 वर्षों के बाद पहली बार केन्द्र में गैर कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ हुई। मराठी देशाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का सत्ता में आना एक घटना थी। 1952 से मार्च, 1977 के पूर्व की दलीय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ दृश्य हैं—

1. भारत में बहुदलीय व्यवस्था चलती रही और राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय स्तर पर 80 से ऊपर राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों का संचालन करते रहे।

2. बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद एकदलीय प्रभुत्व वाली दलीय व्यवस्था कार्य करती रही। कृषियोग राज्यों में 1967 से 1970 तक के समय को छोड़कर एकदलीय कांग्रेस दल की सत्ता में बनी रही।

3. 1967 के आम चुनाव ने जो स्थिति उत्पन्न की वह बहुदलीय व्यवस्था का परिणाम गैर-कॉंग्रेसी दलों ने गठबन्धन किये। चेन्नई (तमिलनाडु) केरल और उड़ीसा में चुनावों से पूर्व गठ इन राज्यों में गैर कॉंग्रेस सरकारें सत्ताकूट हुईं। पंजाब, बिहार और पश्चिमी बंगाल में कॉंग्रेस को रोक्ने के लिए गैर कॉंग्रेसी दलों ने समुक्त मोर्चे गठित किये। इसमें शामिल दलों की विचारधारा में भिन्नता थी। एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सरकारें गठित की गईं। वैचारिक विभिन्नता, सत्ता के लिए राजनीतिक दलों के दृष्ट और विपक्षी दलों के रूप में कॉंग्रेस की इन सरकारों को अपदरश करने की भूमिका के कारण इन सरकारों का पतन हुआ। अनेक राज्यों में सम्प्रदायिक चुनाव हुए और कॉंग्रेस पुनः सत्ताकूट हुई। इस संविद राजनीति ने भारतीय दलीय व्यवस्था की कमजोरियों और असमताओं को ही दर्शाया।

4. एकदलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था होने के बावजूद कॉंग्रेस की सैवधानिक तथा लोकतांत्रिक संस्थागत और परम्पराओं में आस्था और विश्वास बना रहा। उसकी इस कार्य-शैली से भारत में साम्प्रदायिक लोकतन्त्र को शक्ति और स्वायत्तता प्राप्त हुआ। यह एक सकारात्मक योगदान माना जा सकता है।

5. सत्ताकूट दल में अन्तर्दलीय गुटीय प्रतिवर्धिता बनी रही। 'विशुद्ध या असन्तुष्ट गुट' राज्यों में मुख्यमन्त्रियों के विरुद्ध अधिपान चलाते रहे। सन् 1967 के आम चुनावों के पूर्व असन्तुष्ट कमिसियों ने दल से प्रमुख हॉकर विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का गठन करते हुए विपक्षी दलों के साथ गठबन्धन किये। सत्ताकूट कॉंग्रेस के अलावा गैर-साम्यवादी विपक्षी दलों में गुटबद्धता और आन्तरिक छोटपटाई की स्थिति बनी रही। साम्यवादी दल का भारतीय साम्यवादी और मार्क्सवादी साम्यवादी दल के रूप में विभाजन होने के कारण इसकी शक्ति में हास हुआ तथा कॉंग्रेस के भी संगठनात्मक पक्ष में उत्तरोत्तर शिथिलता आती रही।

6. 26 जून 1975 को देश में आन्तरिक आपातकाल की घोषणा की गई। इस निर्णय ने देश में प्रतिस्पर्धी दलीय व्यवस्था का अन्त कर दिया। विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाये जेलों में डाल दिया गया। प्रेस सेंसरशिप लगाने के कारण समूह की कार्यवाही से विपक्षी दलों के नेताओं के भाषणों के ठन अर्थों का प्रकारानुसार संभव नहीं हो पाता था, जिनमें सत्ताकूट दल की आलोचना की जाती थी। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता पर छापे मारे गये। गुजरात और तमिलनाडु की विपक्षी दलों की सरकारों को अपदरश किया गया। जून 1975 से जनवरी, 1977 तक यह स्थिति बनी रही। लोकसभा के चुनावों की घोषणा के बाद ही इस स्थिति का अन्त हुआ।

7. 1977 के आम चुनावों के पूर्व विपक्षी दलों का स्वरूप दबल समूहों जैसा था।

8. अनेक राजनीतिक दल साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दलों के रूप में गठित रहे, यथा—अकाली दल, द्रविड मुनेत्र कड़गम्, हिन्दू महासभा, मजदित्त मुस्लिम, मुस्लिम लीग, परिगणित जाति सघ आदि।

9. अधिकांश राजनीतिक दलों में कार्यक्रम की अपेक्षा नेतृत्व की प्रमुखता दी जाती रही। इससे देश में राजनीतिक दलों की प्रतिवर्धिता व्यक्ति विशेषों पर केन्द्रित हो गई।

10. एक ही दल में विभिन्न क्षेत्रों में प्रायः अलग-अलग नीतियों का अनुसरण होता रहा अर्थात् दल में समरूप नीति न अपनाये की नीति प्रबल रही।

11. दल-बदल भारतीय राजनीति का अभिशाप बन गया। राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना।

12. लोकसभा और राज्य विधान-सभाओं में निर्दलीय सदस्यों की संख्या बहुत अधिक रही। निर्दलीय सदस्य अवसरवादिता का परिचय देते हुए राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाते रहे।

13. राजनीतिक दलों के विभाजन और धुवीकरण की प्रक्रिया चलती रही।

मार्च, 1977 से नवम्बर, 1979 तक दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ

मार्च, 1977 के आम चुनावों में सभी विरोधी दलों ने पहली बार सत्ताकूट कॉंग्रेस के विरुद्ध मोर्चा जमाया और द्वि-दलीय व्यवस्था जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और कॉंग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। इन ऐतिहासिक चुनावों के बाद 1978 के मध्य भारतीय दलीय व्यवस्था का जो चित्र उभर कर सामने आया उसके विशिष्ट बिन्दुओं को निम्नवत रखा जा सकता है—

1. भारतीय राजनीति में 30 वर्षों से कॉंग्रेस के एकछत्र प्रभुत्व का अन्त हो गया और जनता पार्टी का अभ्युदय हुआ।

2. पहली बार विपक्ष के रूप में कॉंग्रेस ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई।

3. मार्च, 1977 के चुनावों के बाद कॉंग्रेस के रूप में विरोधी दल के उदय की सम्भावना हो गई थी, किन्तु 2 जनवरी, 1978 को कॉंग्रेस के पुनर्विभाजन ने इस सम्भावना को धक्का पहुँचाया। इससे कॉंग्रेस की शक्ति कमजोर हो गई।

4. राजनीतिक धुवीकरण की दिशा में कुछ प्रयत्न किये गये। 1977 में लोकसभा के चुनावों की घोषणा के बाद कुछ दलों का जनता पार्टी में विलय हुआ। 1979 में भारतीय लोकदल का गठन हुआ। 1977 राजनीतिक धुवीकरण का वर्ष रहा, वहीं 1978 में पुनः इस दिशा में अग्रगति के वर्ष रहे।

2. गैर-भाष्यवादी विपक्षी दल असंगठित और फूट कर शिखर रहे।
3. जनता दल का गठन तथा 1990 के बाद इसका विघटन इस काल की प्रमुख घटना है।
4. गैर-भाष्यवादी विपक्षी दलों को 7 दलीय 'राष्ट्रीय मोर्चा' अस्तित्व में आया। इसके प्रमुख घटक रहे—जनता दल, लोकदल (न. भाष्यवादी कमिश्नर जनमोर्चा, वेलगुदेसम, असम गण परिषद और द्रमुक।
5. क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ और राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। 1996 में 13 दलीय संयुक्त मोर्चे का सत्ता में आना क्षेत्रीय दलों के प्रभाव और उत्कर्ष की परिणति रही है। आयोग के पास पञ्जीकृत क्षेत्रीय दलों की संख्या 37 है। वर्तमान में भारत की राजनीति पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव इंगित हो गया है।
6. मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेतृत्व में साम्यवादी शक्तिपूर्ण संगठित हुई है। साम्यवादी मोर्चा, 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 के चुनाव में अपनी स्थिति को बनाये हुए रहा तथा पश्चिमी बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा को अपना प्रभाव-क्षेत्र बनाये रखने में सफल रहा। मई, 2004 में हुए चौदहवें लोकसभा के चुनावों में 'नस मोर्चे' ने अपनी स्थिति में और भी सुधार किया।
7. भारतीय जनता पार्टी ने 'अनेका चलौ' की नीति को अस्वीकृत कर गठबन्धन में स्वयं को शामिल किया। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में इसकी शक्ति में सुधार हुआ और सत्ता पर वाजिब हुई किन्तु मई 2004 के लोकसभा के चुनावों के बाद इसे सत्ता से हटाया गया।

समग्र रूप से भारतीय दल प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ

1. बहुदलीय दल प्रणाली—स्वतंत्रता से पूर्वभारत में बहुदलीय शासन प्रणाली कार्य कर रही है। वर्तमान में छ सौ से अधिक राजनीतिक दल पंजीकृत हैं।

2. भारत में संविधान राजनीति के युग का श्रीगणेश—1996, 1998 तथा 1999 के लोकसभा चुनाव में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को न तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और न ही वे कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिनाकर सरकार बनाने की स्थिति में थे। ऐसी स्थिति में एक दलीय सरकार का युग समाप्त हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति राजनीति हो एकमात्र विकल्प दिखाई देता है।

3. राजनीतिक धुवीकरण का अभाव और विखण्डन की प्रवृत्ति—भारत में राजनीतिक दलों के धुवीकरण के प्रयास तो हुए लेकिन उन प्रयासों को दीर्घकाल तक स्थायी नहीं किया जा सका। 1977 में जनता पार्टी का गठन और उसमें विखराव 1988 में जनता दल का गठन और बिछराव के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों में धुवीकरण के स्थान पर विखण्डन की प्रवृत्ति है। वे 1977 के पश्चात् एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर संसद एवं राज्य विधानसभाओं और उसके बाहर संगठित होकर कार्य कर रहे हैं। इन दलों में बिछराव की प्रवृत्ति नदी के बराबर है। 1996 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्त करने के लिए 'धर्मनिरपेक्ष दलों' ने एकजुट होकर सरकार गिरा दी। संयुक्त मोर्चे की सरकार का गठन इसी क्रम परिणाम रहा है, परन्तु इसे धर्म निरपेक्ष दलों का धुवीकरण नहीं माना जा सकता है। 1998 में भाजपा गठबन्धन की सरकार का पतन गठबन्धन सरकार के लिए एक सबक था। 1999 के निर्वाचन में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन को सम्भाव्य रूप देने का प्रयास किया। मई, 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठ बन्धन ने कांग्रेस के डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई।

4. दल-बदल की प्रवृत्ति—दलीय-व्यवस्था सम्ये समय तक विकृत रही है। इसका स्तर सभी दलों ने उठाया है। यह केवल राज्यों तक सीमित थी, परन्तु अब यह केन्द्र की प्रभावित करने लगी है। केन्द्र में देसाई सरकार के पतन के लिए मुख्यतः दल-बदल ही उत्तरदायी रहा। दल-बदल की सीमित करने के लिए भारतीय संविधान का 32वाँ संशोधन विशेषक लोकसभा में 1973 में प्रस्तुत किया था, परन्तु वह धारित नहीं हो सका। 1977 के लोकसभा के चुनावों में भी दल-बदल हुआ। राजीव सरकार ने 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दल-बदल पर वैधानिक रोक लगाकर भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1985 के बाद नागालैण्ड, मणिपुर, हरियाणा में दलबदल की घटनाएँ घटित हुईं। 1991 में कांग्रेस (X) ने शिवसेना, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, जनता दल और वल्लभभट्टम को विभाजित करते हुए लोकसभा में अपना बहुमत प्राप्त किया था। 1995 में वेलगुदेसम का विभाजन हुआ। 1998 में भाजपा सरकार का गतन दल बदल की श्रेणी में आता है। सत्ता में दल-बदल या दल-विभाजन की प्रवृत्ति जलती रहेगी।

5. आन्तरिक गुटबन्दी—भारत की दल-प्रणाली में आन्तरिक गुटबन्दी है। समग्र सभी राजनीतिक दलों में छोटे-छोटे गुट हैं—वह एक गुट जो सत्ता में है और दूसरा गुट असन्तुष्ट गुट। इन गुटों में पारस्परिक मातृपद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी-कभी निर्वाचन में एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवारों को दूसरे गुट के सदस्य पराजित कराने का प्रयत्न करते रहते हैं। इससे सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता है। इस तरह सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में यह स्थिति बनी हुई है।

6. व्यक्तिवाद का महत्व और अवसरवादिता—भारतीय दलीय प्रणाली नीतियों एवं कार्यक्रमों की अपेक्षा व्यक्ति एवं व्यक्तिगत तत्वों को महत्व दिया जाता है तथा इसके कारण अवसरवादिता फैलती है। उदाहरणस्वरूप कांग्रेस में

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारत के राष्ट्रीय जीवन एवं स्वाधीनता संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। 1885 में स्थापित कांग्रेस ने देश को राजनैतिक स्वायत्त प्रदान करके लोकतांत्रिक पथ की ओर अग्रसर किया।

कांग्रेस का संगठन—भारतीय राजनैतिक व्यवस्था की विशेषता है कि जहाँ शासन का ढांचा सभात्मक है वहाँ राजनैतिक दलों का ढांचा एकात्मक। कांग्रेस की सभी इकाइयाँ, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय तक हाईकमान के नेतृत्व में आती हैं। ग्राम या मोहल्ला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस संगठन की आधारभूत इकाई (Basic Unit) है जिसके ऊपर तहसील या तालुका समितियाँ, जिला समितियाँ और उन पर प्रदेश या प्रांतीय कांग्रेस समितियाँ होती हैं। प्रदेश या प्रांतीय कांग्रेस समिति के अन्तर्गत प्रत्येक जिला में जिला और मध्यम समितियाँ होती हैं जिसका क्षेत्र प्रदेश कांग्रेस समिति। निर्धारित करती है। प्रांतीय कांग्रेस समितियों के ऊपर कांग्रेस का राष्ट्रीय अथवा अखिल भारतीय संगठन होता है जो अध्यापक कार्यकारिणी समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और कांग्रेस के सुले कार्यक आधिवेशन से गठित होता है। कार्यकारिणी समिति दल की सर्वोच्च कार्यपालिका अंग है। इनमें अध्यक्ष मुख्य हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (Congress Working Committee) में केवल कांग्रेस की कार्यकारिणी हैं बल्कि एक छाया मन्त्रिमण्डल (A Shadow Cabinet) है। कार्यकारिणी समिति में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है और वह पण्डित नेहरू इन्दिरा गांधी और नरसिंहाग्र क सम्बन्ध में रहा है।

कांग्रेस के संसदीय ढांचों के नियन्त्रण और समन्वय के लिए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति एक सभासद बोर्ड की स्थापना करती है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य रहते हैं। इसके अतिरिक्त संसदीय बोर्ड के सम्बन्ध और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा चुने गए सदस्यों को मिलाकर केन्द्रीय निर्वाचन समिति का गठन किया गया है जो देश में केन्द्र और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करने के लिए योग्य प्रत्याशियों की छंटनी में अग्रणी निर्णय देती है। दल में महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस की इकाइयाँ होती हैं जिसके अध्यक्ष और कार्यकारिणी होता है।

कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास अनेक उतार चढ़ाव का सन्धी कहना है। 1885 में डब्ल्यू. सी. बन्नर्जी (W. C. Banerjee) की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन गुवाँ में हुआ। कांग्रेस की स्थापना संगठन के रूप में हुई जिसका उद्देश्य भारतीयों का गैर सत्कारी सराद के रूप में काम करने के लिए तैयार करना था। स्थापना के वर्षों में इस संगठन को ब्रिटिश शासकों का सरक्षण तथा सहानुभूति प्राप्त थी लेकिन धीरे धीरे उनके हृत् में परिवर्तन हुआ क्योंकि कांग्रेस ने सामान्यवाद की आलोचना तथा स्वशासन की माँग शुरू कर दी थी। वास्तव में कांग्रेस एक राजनैतिक दल कम तथा राष्ट्रीय आन्दोलन अधिक था। कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश को रथान्वन प्राप्त हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प नेहरू कांग्रेस दल के नेता तथा भारत के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को निधन होने से पूर्व तक वह कांग्रेस दल का नेतृत्व करते रहे। नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल बहुत ही छोड़ा लगभग डेढ़ वर्ष का ही रहा। शास्त्री के बाद जवाहर 1966 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी कांग्रेस दल की नेता और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनीं। अनेक राजनैतिक घटनाओं तथा दल के विभाजनों के बावजूद अपनी मृत्यु तक उनका दल पर पूरा आधिपत्य रहा। 1969 में उनके नेतृत्व में पहली बार चुनौती का सामना करना पड़ा जो अपने सहयोगी कांग्रेसी नेताओं द्वारा दी गई थी लेकिन उनकी विजय हुई। दिसम्बर 1969 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई—संगठन कांग्रेस तथा कांग्रेस का इन्दिरा कांग्रेस। 1971 में मन्त्रिमन्त्रि लक्ष्मणपुरा चुनाव में श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में इन्दिरा कांग्रेस की विजय में उन्हें दल और सरकार का नेता बना दिया। 1977 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी (स्वयं) की तथा कांग्रेस दल को हार हुई और केन्द्र सत्ता तत्काल में जनता पार्टी की विजय हुई। आपसी फूट तथा कुछ अन्तर्गतों से अनेक राजनैतिक दलों का गठनपन अधिक समय नहीं टिक पाया। 1979 में इसका विघटन हो गया।

जब श्रीमती गाँधी सत्ता में नहीं थी तब जनवरी 1978 में कांग्रेस का एक और विभाजन हुआ। 2 मार्च 1978 को लगभग आठ वर्ष बाद कांग्रेस की दूसरी बार विभाजन श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में दिल्ली में बिड़लाभाई फोरेस भवन में इसी स्थान पर हुआ जहाँ पहले 1969 में हुआ था। अब दो कांग्रेस अस्तित्व में आ गई—ब्रह्मानन्द देवी। दो अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कांग्रेस और इन्दिरा कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस के अधिकांश नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही बने रहे। 1978 में दक्षिणी राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में इन्दिरा कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की और ब्रह्मानन्द देवी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस का सफाया हो गया। जनवरी 1980 के चुनावों में इन्दिरा कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की और उसे बार बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कांग्रेस (I) संसदीय दल ने श्रीमती गाँधी को नेता मान उस देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। वे 31 अक्टूबर 1984 तक कांग्रेस सरकार और दल का नेतृत्व कर रहे थे। 31 अक्टूबर

1984 को श्रीमती गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी कांग्रेस दल के नेता और भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में दिसम्बर, 1984 के आम चुनावों में लोकसभा में कांग्रेस ने विजय के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए और सन् 1985 में राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हुए उनमें कुछ अपवादों को छोड़कर रोष सभी राज्यों में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई। 1991 में कांग्रेसी नेता पी. वी. नरसिम्हायन ने 5 वर्षों तक अल्पमत सरकार चलाई।

कांग्रेस दल की चुनावी राजनीति का इतिहास—भारत में अब तक 14 संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं, उनमें से आठ में कांग्रेस की सफलता मिली। सन् 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (इ) बड़े दल के रूप में उभरी और सरकार बनाने में सफल रही। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी, 1989 में विश्वनाथ प्रतापसिंह, 1996 में सयुक्त मोर्चे के देवेगौड़ा एवं गुजरात तथा भाजपा के वाजपेयी के नेतृत्व में तथा 1998, 1999 में पुनः भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई, लेकिन ये सरकारें पूरे समय सना में नहीं रहीं। दलबदल या दल-विभाजन के कारण सरकारें का पटन हो गया। सन् 1999 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (इ) को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे मात्र 114 स्थान ही प्राप्त हुए। साथ ही कांग्रेस (इ) को लोकसभा में विपक्ष में बैठना पड़ा। अप्रैल-मई, 2004 में हुए लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को 145 स्थान मिले तथा उसके नेतृत्व में सयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में आया।

कांग्रेस की नीतियाँ और कार्यक्रम—पंडित नेहरू से लेकर नरसिम्हायन तक के कार्यकाल में कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों का विरलेषण किया जाए तो कहा जा सकता है कि लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद इस दल की नीतियों के तीन आधार स्तम्भ रहे हैं। 1952 से लेकर 1996 एवं 1999 तक के संसदीय चुनावों में जहाँ घोषणा-पत्र से कांग्रेस की नीतियाँ और कार्यक्रम स्पष्ट होते हैं। कांग्रेस की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव, अल्पसंख्यक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और गुटनिरपेक्षता को गिनया जा सकता है।

स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक कांग्रेस की उपलब्धियाँ रही हैं। देश में स्थिर, संसदीय लोकतन्त्र का क्रियन्वयन, धर्म-निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक समाजवाद का आदर्श, नियोजित आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, सामन्तवाद, जागीरदारी तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, देश में मतदाताओं को शिक्षित करने का प्रयास, नीकराश्री का लोकतान्त्रीकरण, देश में आधुनिकीकरण का सूत्रवाद, भारत में सभात्मक व्यवस्था, विश्व में सामान्यवाद, उपनिवेशवाद तथा रणभेद के विरुद्ध यातायात तैयार करने तथा विश्व शान्ति में योगदान जैसे अनेक ऐसे कार्य हैं जो इस दल के योगदान को दर्शाते हैं।

इन उपलब्धियों के साथ-साथ इस दल की असफलताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक बन जाता है। स्वतंत्रता के परचात्र मार्च 1977 से जनवरी, 1980 तथा नवम्बर, 1989 से जून 1991 एवं 1996-1998 के संमित काल के विपक्षी शासन को छोड़कर ग्यारहवीं लोकसभा के गठन के पूर्व तक यही दल सत्ता में रहा। इतने वर्षों में देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाये तो अनेक कमजोरियाँ स्पष्ट होती हैं। कांग्रेस ने जिन नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाया, उससे जनसाधारण के जीवन में कोई नया परिवर्तन नहीं आया। धनिक और निर्धन वर्ग के बीच अन्तर बढ़ा है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर होने वाले अत्याचार सामाजिक न्याय की भावना पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। कांग्रेस द्वारा दमनवाद का सहण लेकर विपक्षी दलों की शक्ति को सदैव कमजोर करने के प्रयास किये गये, जिसका परिणाम एक सरकृत विरोध का अभ्युदय नहीं हो सका। समाजवाद का नाउ ठो बुलन्द किया गया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक शक्तों का एकाधिकार तथा प्रभुत्व स्थापित होता चला गया। सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का विकास होता गया है। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों का संकट बढ़ा है। नीकराश्री का पूरा तरह से जनतान्त्रीकरण नहीं हो सका। जम्मु-कश्मीर तथा पंजाब, उत्तर-पूर्वी राज्यों की अशांति स्थिति के लिए इस दल को ही उत्तरदायी माना जाता है।

भारतीय जनता पार्टी

(Bhartiya Janta Party : BJP)

भारतीय जनता पार्टी 1980 के चुनावों से नया संस्करण है। भारतीय जनसभा की स्थापना प्रथम आनंद चुनावों के कुछ समय पूर्व 1951 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ जिसमें संस्थापक डॉ. रघुनाथप्रसाद मुकुर्जी को अध्यक्ष चुना गया। इसके कुछ समय पूर्व पंजाब, पेश्वा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रतिनिधि जालंधर में मिलकर एक और 'जनसभा' का सूत्रावत कर चुके थे। दोनों के बीच 1 अक्टूबर, 1951 को विलय सम्पन्न हो गया और मुकुर्जी अखिल भारतीय जनसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1952 के बाद के चुनावों में जनसभा ने सफलता अभिमत की। लोकसभा में 1957, 1962, 1967 और 1971 (स्थगित) में क्रमशः 4, 14, 35 और 22 सीटें प्राप्त कीं। जनसभा अगले एकता की बनाए नहीं रख सका। दल से निष्कासित होने के बाद वरिष्ठ नेता बनारस मणिक ने अगस्त, 1973 में राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक सभा नामक दल का निर्माण कर लिया जो भारतीय लोकदल में विलीन हो गया। 18 जनवरी, 1977 को छठी लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद जनसभा ने 'जनता पार्टी' में अपने विलय की घोषणा की। 1980 के

लोकाभा के चुनावों में जनता पार्टी की पराजय के बाद जनसंघ घटक के लोगों ने इस पार्टी से सम्बन्ध तोड़कर ॥ अप्रैल १९८० को नई दिल्ली में एक सम्मेलन में 'भारतीय जनता पार्टी' नाम से नये दल का गठन किया। अटलबिहारी वाजपेयी को दल का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में वाजपेयीजी ने निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जोर दिया—(१) भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। (२) भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता और गैर-मजहबी राज्य में विश्वास करती है। (३) आर्थिक नीति का मूलधार गांधीवादी अर्थव्यवस्था होगी। उनके मत में ए. दीनदयाल उपाध्याय ने पूर्व जनसंघ के लिए जो आर्थिक नीति तैयार की थी वह पूर्णतया गांधीवाद के अधिक निकट थी। (४) भारतीय जनता पार्टी ने पी. आन्दोलन और सम्पूर्ण क्रांति के उद्देश्यों की प्रेरणा का आधार मानकर चलेगी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता पार्टी की 'जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति का आदर्श और गांधीवादी अर्थदृष्टि' को विरासत के रूप में स्वीकार किया।

नीति एवं कार्यकल्प—26 से 29 दिसम्बर, 1980 को मुम्बई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में दल द्वारा नीति-समन्वय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस प्रस्ताव में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को स्वीकार करने, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में विरोध नहीं मानने निर्धनता दूर करने के लिए विरोध कोष की स्थापना करने, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायीकरण करने, निजी क्षेत्र पर कुछ न्यूनतम सामाजिक नियन्त्रण रखने, कृषकों को उत्पादन के सापेक्षारी मूल्य देने, पाँच वर्षों में सबको काम अथवा बेरोजगारी भत्ता दिलवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को योजना को लागू करने जैसे विषय पर बल दिया गया। पार्टी ने गाँधीवाद समाजवाद के प्रति आस्था व्यक्त की।

के प्रति आस्था ध्वस्त की।

1986 के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सत्यकुण अडवाणी के नेतृत्व में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुई। इससे गौधीवादी समाजवाद को कायम रखने का आधार कमजोर हो गया। 1989 में सम्पन्न होने वाले लोकसभा के चुनाव में दल के अध्यक्ष सत्यकुण अडवाणी ने चुनाव घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 370 की समाप्ति आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की स्वायत्तता को कायम करने के लिए एक स्वायत्तशासी निगम की स्थापना, एक समान नागरिक संहिता (Common Code) का निर्माण करने, 'रोजगार गारण्टी' की योजना का आरम्भ करने जैसे विषयों पर बल दिया गया।

[illegible]

मार्गश्री का प्रारम्भ तथा महिलाओं और युवकों के उत्थान के लिए अलग कार्यक्रम प्रारम्भ करने का उद्देश्य है। सन् 1991 से 1993 की अवधि के मध्य दल की नीति में कोई अन्तर नहीं हुआ। जयपुर में आयोजित अधिवेशन में डॉ. मुस्लीमनोहर जोशी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उत्तर प्रदेश में कल्याणसिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में डॉ. मुस्लीमनोहर जोशी को अध्यक्ष के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया। इसके बाद 'यात्राओं' की राजनीति का सहारा लेकर भाजपा दल के अध्यक्ष डॉ. मुस्लीमनोहर जोशी ने 'कल्याणकुमारी से कश्मीर' तक की यात्रा प्रारम्भ की जिसका मुख्य सत्य दल की नीतियों के प्रति दक्षिण से लेकर उत्तर तक जन-समर्पण जुटाना

था। वृत्तिपय स्थानों पर यात्रा के दौरान साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएँ भी घटित हुईं। अन्त में 26 जनवरी, 1992 को श्रीनगर के लाल चौक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डॉ. मुरलीमनोहर जोशी द्वारा 'तिरंगा झण्डा' फहराने के साथ ही इस यात्रा की समाप्ति हुई। इस यात्रा को ठटना जन-समर्पण प्राप्त नहीं हुआ, जितना की तालकृष्ण अडवाणी की रथ-यात्रा को। 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में कारसेवकों द्वारा 'बाबरी मस्जिद' को गिराये जाने की घटना से दल को अपात लगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की चारों भाजपा राज्य सरकारों को बर्खास्त कर तालकृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे भाजपा के सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित करते हुए इन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जनता में प्रभाव स्थापित करने की दृष्टि से 'जनदेश यात्राओं' का सहारा लिया। 11 सितम्बर, 1993 से मैसूर, पोरबन्दर, कोलकाता और जम्मू से रवाना होने वाली यात्राओं का नेतृत्व तालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, कल्याणसिंह तथा पैतृसिंह शेरवाहत ने किया। इन यात्राओं में लगभग 15 हजार किमी. की दूरी तय की गई और 25 सितम्बर, 1992 को गोपाल ने एक साथ रानापन हुआ।

ग्यारहवीं लोकसभा के चुनावों में जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में 'रामरज्य की स्थापना' को पार्टी का लक्ष्य माना गया। घोषणा पत्र में उतावखण्ड, वनारस, विदर्भ तथा छत्तीसगढ़ नये राज्य बनाने, अयोध्या में जन्मस्थान पर भव्य राममन्दिर का निर्माण करने, सविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने, एक समान नागरिक संहिता बनाने, कश्मीर घाटी छोड़कर आये लोगों को विस्थापितों का दर्जा प्रदान करने तथा उम्मीदी सम्पत्ति की रक्षा करने, चुनाव में बाले धन से दूषित हुई निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने, सरकारी खर्च पर चुनाव सड़ने तथा गोस्वामी समिति की सिफारिशों को लागू करने, राजनीतिक दलों की खुलेआम कथनियों से घन्टा लेने के लिए प्रोत्साहित करने, दलबदल कानून में संशोधन करने, मनदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का सहारा लेने, भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिए लोकपाल की स्थापना करने, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य रूप से अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने की, बी. बी. आई. का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से रोकने, सरकार मुक्त बाजार नीतियों को प्रोत्साहित करने, विदेशी पूँजी निवेश का स्वागत, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं में इसे प्रोत्साहन नहीं देने, कर ढाँचे तथा आपकर की सीमा को साठ हजार रुपये करने, लघु उद्योगों को पूर्ण प्रोत्साहन देने, भ्रष्टाचार तथा कालेपन के विरुद्ध सफ़र को दृढ़ता से जारी रखने, पाक-अधिकृत कश्मीर पर भारत की सम्मति के अतिरिक्त, सेनाओं का आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, पृथ्वी गुरुत्वा के प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण कार्य तेज करने, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सुरक्षा सेनाओं को घट्ट देने, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ससाधनों का 60 प्रतिशत खर्च, कृषि को उद्योग का दर्जा देने, सभी निर्वाचित निधियों में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं को प्रदान करने तथा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन को राष्ट्रीय एजेंडा में रखने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया।

दल का चुनावी इतिहास—भाजपा की स्थापना के बाद मई, 1980 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाग लिया, जिसमें उसे 2,242 स्थानों में से 147 स्थान प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में 60 और राजस्थान में 32 स्थानों पर विजय प्राप्त कर इस दल ने मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया। मई 1982 में सम्पन्न होने वाले लोकसभा के 7 उपचुनावों में से 2 पर विजय प्राप्त करके इस दल ने उपस्थिति दर्ज कराई। सन् 1983 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में देवीलाल के नेतृत्व वाले लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और लोकदल भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ सर्वाधिक स्थानों पर विजय प्राप्त करके बड़े गठबन्धन के रूप में उभरा। दिसम्बर, 1984 के लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए निराशाजनक रहे और इसे मात्र दो स्थान ही प्राप्त हुए। मार्च, 1985 में सम्पन्न 11 राज्य विधानसभाओं की कुल 2,534 सीटों में से भाजपा को 171 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस दल को सफलता प्राप्त हुई और इन राज्यों में उसे मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का स्थान प्राप्त हुआ। सन् 1987 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में लोकदल (ब) और भाजपा का गठबन्धन सफल रहा। देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल (ब) और भाजपा की मिली-जुली सरकार सत्तारूढ़ हुई। सन् 1989 के लोकसभा चुनाव में इस दल को सफलता प्राप्त हुई। लोकसभा में इसकी सदस्य संख्या 2 से बढ़कर 86 हो गई और चन्द्रशेखर के काल में भाजपा लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बन गया। तालकृष्ण अडवाणी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। जनवरी, 1990 में राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भाजपा को सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में यह बड़े दल के रूप में उभरा। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ हुए। गुजरात में चिमनभाई पटेल के नेतृत्व में जनता दल के साथ सविद सरकार में शामिल हुई। जब केन्द्र में भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तो राजस्थान में जयदल दल ने पैतृसिंह शेरवाहत मन्त्रिमण्डल से समर्थन वापस ले लिया। गुजरात में चिमनभाई मन्त्रिमण्डल से अलग हो गई। राजस्थान में पैतृसिंह शेरवाहत ने जनता दल की विपक्षित बग कर अपनी सरकार की बधाई ली। 1991 के लोकसभा

चुनाव में भाजपा ने शक्ति में वृद्धि करते हुए अपनी सदस्य संख्या 86 से बढ़ाकर 119 कर दी। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः सानुकूल अवस्थाओं और सिक्कर बल विपक्ष के नेता बने। उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव भी सम्पन्न हुए। उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कल्याणसिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार राज्य में सत्ताकब्जे हुई। 1991 में कर्नाटक और महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनावों में भाजपा विनाश विस्तृत करने में सफल रही। दिसम्बर, 1992 में चारों भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी इस दल के लिए एक आघात था। नवम्बर, 1993 में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली विधानसभाओं के चुनावों में भाजपा ने आत्म-विश्वास के साथ चुनाव सफल में उतारते हुए 'आज पीपल प्रदेश कल सार देश' का नारा लगाया था, लेकिन चुनावी परिणाम अपेक्षा के अनुकूल नहीं आए। हिमाचल प्रदेश में पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शान्तानुकार भी पराजित हो गये। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति रही। उत्तर प्रदेश में पहले से अधिक मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के बावजूद यह राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा। यद्यपि यह राज्य विधानसभा में बड़े दल के रूप में उभरी और 'जैद तोड़ दी राजनीति' के माध्यम से सरकार बनाने में सफल रही। दिल्ली विधानसभा में सफलता मिली। इस प्रकार से 1993 के राज्य विधानसभा चुनावों ने भाजपा को देश में लोकसभा मध्यस्थ चुनाव कक्षा की भाँति जोर दिया। साथ ही 'मन्दिर भूरे' शीतल पड़ जाना भी दल के लिए प्रमुख चिन्तनीय विषय बन गया।

1994 में सम्पन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। नवा भग विधान सभा में इसके मात्र 5 स्थान थे, वे बढ़कर 40 हो गये। 1995 में सम्पन्न हुए गुजरात विधानसभा के चुनाव में जनता पार्टी को विशाल जनश्रेष्ठ प्राप्त हुआ और यह दल राज्य में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में सफल रहा। महाराष्ट्र में दल की शक्ति में वृद्धि हुई और शिवसेना के साथ मिलकर इन्हीं मिली जुली सरकार बनाई। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सफलता महत्वपूर्ण इसलिए थी कि ये दोनों ही राज्य भारत के सम्पन्नतम राज्य हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 161 स्थान प्राप्त कर बड़े दल के रूप में उभरी। इससे नेता अटलबिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिवाई गई किन्तु उनकी सरकार अल्पमयी रही। 1996 में आम चुनावों के उपरान्त सबसे बड़े दल (गठबन्धन) के नेता के रूप में चुने जाने के परचात वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने। भाजपा सरकार के शुरुआती दिनों में जयललिता के इस समर्थन काफ़ी सेने के बाद राष्ट्रपति ने सरकार को विश्वास पत्र प्राप्त करने का आदेश दिया। सरकार एक मत से पराजित हो गई। परिणामस्वरूप सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। तेरहवीं लोक सभा के चुनाव हुए और राष्ट्रीय जनताधिक गठबन्धन के नेता के रूप में अटलबिहारी वाजपेयी का पुनः तीसरा बार 13 अक्टूबर, 1999 को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तेरहवीं लोक सभा के चुनावों में इस दल का 182 स्थान प्राप्त हुए। अप्रैल-मई, 2004 में हुए चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 139 स्थान मिले तथा उसके हाथ से सत्ता चली गई।

भारतीय साम्यवादी दल

(Communist Party of India : CPI)

भारतीय साम्यवादी दल देश का राष्ट्रीय दल है। इस दल के संस्थापक नेताओं में श्रीपद अमृत दाँगे भूपश गुप्त जे ए. अहमद और सी. राजेश्वरराव के अलावा इन्द्रीत गुप्ता और चतुरानन मिश्रा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस दल का संगठन पूर्व सोवियत संघ के साम्यवादी दल की तरह त्रिकोणात्मक रहा है। दल का आधार इकाई का समूह है। दल की सबसे छोटी इकाई सेल (Cell) कहलाती है, जिसकी स्थापना किसी कारखाने या अन्य स्थान में की जा सकती है। साम्यवादी दल में संगठन की सोझी में ग्राम, नगर, जिला और प्रांतीय समितियों एक के ऊपर एक होती हैं। प्रत्येक स्तर पर कार्यकारिणी समिति होती हैं। राष्ट्रीय संगठन के रूप में साम्यवादी दल की एक अधिकृत भारतीय आगम है जो अपने वार्षिक अधिवेशन में दल का महासम्मेलन निर्वाचित करता है जो दल का शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। दल के महासम्मेलन की दल की गतिविधियों के संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह दल की नीतियों का अधिकृत प्रवक्ता एवं समन्वयकर्ता माना जाता है जो संगठनात्मक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है। दल की अधिकृत भारतीय वरिष्ठ द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन किया जाता है। इस केन्द्रीय समिति का अनारग समूह होता है जिसे उसी परम्परा के अनुसार 'पोलिट ब्यूरो' (Polit Bureau) कहा जाता है जिससे दल में शीर्षस्थ भूमिका होती है। यह दल के लिए नीतियों का निर्धारण एवं सभी गतिविधियों का संचालन करता है। पोलिट ब्यूरो साम्यवादी नेतृत्व परम्परा का प्रतीक होता है। इससे महासम्मेलन के अतिरिक्त वरिष्ठ सदस्य होते हैं जिनकी दल में महत्वपूर्ण स्थिति होती है। दल में भर्ती के नियम कठोर हैं। अनुशासित लोग साम्यवादी दल के सदस्य बन सकते हैं। कोई 18 वर्ष का या इससे अधिक का व्यक्ति इस दल का सदस्य बन सकता है। जहाँ तक दल में शक्ति और स्थिति का प्रश्न है सारी शक्ति दल के 'पोलिट ब्यूरो' में केन्द्रित होती है। साम्यवादी दल का नेतृत्व अन्य दलों की अपेक्षा 'चतुर्थी' नेताओं के हाथ में रहा है। बहुत लम्बे समय तक श्रीपद अमृत दाँगे और सी. राजेश्वरराव का दल पर वर्चस्व रहा है।

साम्यवादी दल सगठनों और सदस्यों को दल द्वारा जारी पत्रिकाओं, पैम्फलेटों तथा पार्टी पत्रा क माध्यम से गठित करता रहता है। एक पार्टी पत्रिका (उदाहरणार्थ 'पार्टी लाइफ') भारतीय तथा जिला समितियों और महत्वपूर्ण सम्मेलनों को भेजी जाती है। विदेशी पत्र-पत्रिकाएँ केवल केन्द्रीय समिति के सदस्यों के लिए होता है। पार्टी की इस संपादक-व्यवस्था तथा सैद्धान्तिक शिक्षा का बंशेय सदस्यों में सेवा की तरह अनुशासन उत्पन्न करना है। इसमें रक्षा, आक्रमण, युद्ध (खा. लड़ाई, पिछली सेना, युद्ध विराम, सेनाएं, सैनिकों, छापागण युद्धकला, हथियारबन्द स्पर्ष आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साम्यवादी दल का अनुशासन सदस्यों के निजी तथा सर्वजनिक जीवन तक फैला हुआ है। दल विवाद या तनाव को आशा दे सकता है। दल सदस्यों से पूर्ण निष्ठा की माँग करते हुए समय-समय पर आदर्श तथा निरुद्ध दल के लिए पाठशालाओं का प्रबन्ध भी करता है।¹

भारतीय साम्यवादी दल की नीतियों और कार्यक्रम मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद से प्रेरित हैं। यह सन्नर्तित एवं आर्थिक व्यवस्था के स्तर पर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद पर आधारित हो। यह दल मजदूरों और किसानों के हितों के संरक्षण का पक्षधर है। समाज के कमजोर वर्ग के अध्यात्म जमीनदार और जागेरदारों के दबाव का ठगलून, धूमि सुधारों को लागू करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राज्यों के विशेषाधिकार और विशेषताओं को समाप्त करने, सम्पत्ति पर पूँजीपतियों के एकाधिकार को समाप्त करने, सम्पत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकारों में हटाने, किसानों को कृषि और सिंचाई की सुविधा तथा उत्पत्तियों का उचित मूल्य दिलाने, मूल्य सिद्धांत को बनाए रखने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान कर न्यूनतम मजदूरी का माँग का निधारण करने, श्रमिकों को अधिकार प्रदान करने, प्रमोशन विकास को महत्व देने, दलबदल पर रोक लगाने, ब्रह्मण परिवार नियंत्रण कार्यक्रम का अन्त करने, धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने, अल्पसंख्यकों का सुरक्षा करना, महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करने, साम्प्रदायिक शक्तिवादों का दमन करने, वामपंथी और लोकतन्त्रिक शक्तियों की प्रगतिशील, एमजन्मधूमि बावरी मौलिक विवाद का समाधान और अगर ऐसा नहीं हो सक तो न्यायनिका के निर्णय का साथ पक्षों को स्वीकार करने, उदारतापूर्ण के साथ पर निरीक्षण की प्रक्रिया का विरोध करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से स्वीकार करने, इत्यादि प्रमुख विषय पर बल देता है। नवम्बर, 1980 के लोकसभा चुनाव में 33-संघीय प्रार्थना में वामपंथी, लोकतन्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष एकजुटता का अड्डन किया गया था। 1991 के लोकसभा के चुनाव में दल द्वारा जारी किये गये घोषणापत्र में साम्प्रदायिकता पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा धर्म-स्थलों की स्थिति का बनाए रखने की वकालत की गई। 1998 एवं 1999 के आम चुनावों में जारी घोषणापत्र में पूर्व की नीतियों का मार्गदर्शन करने के साथ दल द्वारा वामपंथी, लोकतन्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों से एकजुट होकर साम्प्रदायिक शक्तियों का पराजित करने की अंगीकृत की गई।

भारतीय साम्यवादी दल का चुनावी इतिहास—देश में सम्मिलन होने वाले ससदीय और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल कठोर भाग लेता रहा। सन् 1952 के प्रथम आम चुनाव में भारत में 27 और राज्य विधानसभाओं में 187 स्थानों पर विजय प्राप्त करके केंद्र के बाद इसी दल को स्थान प्राप्त हुए। 1957 के द्वितीय आम चुनाव में दल को प्राप्त मतों और स्थानों की संख्या दुगुनी हो गई। इसे लोकसभा में 27 स्थान तथा केन्द्र विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। ई. एस्. बसु, मजदूरों के नेतृत्व में, राज्य में प्रथम गैर-कॉरेसिड सांसद, मजदूर हुए जिसे 1959 में बर्खास्त करके राज्य में उपरुपि रामन लागू कर दिया गया। सन् 1962 के तृतीय आम चुनाव में दल को जन-समर्थन प्राप्त हुआ और इसका मत 3.30 से बढ़कर 9.96 प्रतिशत हो गया।

1962 के चीनी आक्रमण के बाद इस दल में दरार होने लगी और मजदूरों की रणदिष्टे व्यवधि वस्तु, हथियारनिर्माण, मजदूरों के नेतृत्व में एक बड़ा वर्ग दल से अलग हो गया जिसने प्रचुक्ष से 1964 में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का गठन किया। इससे दल की स्थिति कमजोर हो गई। 1967 के आम चुनावों में 23 स्थान गिने और बिहार, कर्नाट तथा पश्चिमी बंगाल विधानसभाओं में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई। 1971 के लोकसभा चुनाव में विरोध पैदा होने नहीं हुआ और उसे 23 स्थान प्राप्त हुए जबकि पण लोकसभा में इसके 24 सदस्य थे। 1969 के कॉरेसिड विधानसभा के पश्चात् इस दल ने प्रथमपंथी के नेतृत्व वाली कॉरेसिड को समर्थन दिया। 1977 के चुनाव में श्रीमती गंधी के नेतृत्व में कॉरेसिड-भारतीय साम्यवादी दल के गठनोद्देश ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल का पक्ष का समर्थन करना पड़ा। उसे लोकसभा में मात्र 7 स्थान और केवल 2.87 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। इस पक्ष में साम्यवादी दल का कॉरेसिड के प्रति विश्वास कम हो गया तथा अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए मार्क्सवादी साम्यवादी दल और अन्य वामपंथी दलों के साथ संप्रकुल मोर्चे में अपने को शामिल कर लिया। पश्चिमी बंगाल और कर्नाट की राजनीति में साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेतृत्व वाले वामपंथी लोकतन्त्रिक मोर्चे की सरकारों में शामिल हुआ। 1980 के लोकसभा चुनाव में इस दल को 11 स्थान और 2.61% मत प्राप्त हुए। 1980 के राज्य विधानसभाओं

के चुनाव में इसे मात्र 57 स्थान प्राप्त हुए। 1984 के लोकसभा चुनाव में इसकी शक्ति पुनः घट गई तथा इसे 6 स्थान प्राप्त हुए। 1989 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल की स्थिति में सुधार हुआ और उसे 12 स्थान प्राप्त हुए। राष्ट्रीय मोर्चे तथा अन्य वामपंथी दलों के साथ चुनावी गठबन्धन करने के कारण ही इस दल की सफलता प्राप्त हो सकी। 1991 के लोकसभा चुनावों में इस दल को 13 स्थान प्राप्त हुए। मई 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल को 11 स्थान प्राप्त हुए जो 1991 के लोकसभा चुनाव की तुलना में दो स्थान कम है। 1996 के लोकसभा के साथ सम्पन्न हुए केरल विधानसभा के चुनावों में 18 स्थान प्राप्त हुए। पश्चिमी बंगाल विधान सभा में 6 स्थान प्राप्त हुए। दोनों ही राज्यो में यह दल मार्क्सवादी दल के नेतृत्व वाले वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार में शामिल है। इस दल को 1998 में बारहवीं लोक सभा में 9 तथा 1999 में तेरहवीं लोक सभा में 4 स्थान प्राप्त हुए। 2004 में हुए चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 9 स्थान मिले।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)

[Communist Party of India : CPI (M)]

1964 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल के एक बड़े वर्ग ने कम्युनिज्म के सैद्धांतिक मतपद के परिप्रेक्ष्य में एक नवीन दल का गठन किया जो सोवियत संघ के 'समोचनवाद' का विरोधी था। इस नवीन दल का नाम 'मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी' रखा गया और घोषणा की गई कि यह दल देश में समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना कराने के लिए उन भारतीय श्रमजीवियों का संगठन होगा जो कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद के प्रति आस्था रखते हैं तथा जो प्राथमिक कारण में इस देश में जनवादी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। मार्क्सवादी साम्यवादी दल दक्षिणपंथी साम्यवादी दल की तुलना में उग्र वामपंथी दल है। इसके संस्थापक नेताओं में प्रमोददाम गुप्ता, ज्योति बसु ई एम् एम् नम्बूदीपद, हरिकर्णसिंह सुरजीत ए के गोपाल, पी रामपति और टी. रणदिवे का नाम उल्लेखनीय है। हरिकर्णसिंह सुरजीत दल के महासचिव तथा मुख्य नीति निर्धारकों में से हैं। 1969 में राष्ट्रपति डॉ. जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन और केंद्रित के विभाजन की प्रक्रिया में मार्क्सवादी दल ने श्रीमती गांधी का समर्थन किया था, परन्तु बाद में 1970 के अन्त में दल में इस विचार ने जोर पकड़ा कि इससे मार्क्सवादी दल कांग्रेस से दब जाएगा और उसका व्रान्तिकारी स्वरूप सामाज्य हो सकता है। इस कारण दल ने कांग्रेस के सम्बन्ध में नीति बदल ली।

दल की चुनावी इतिहास

1964 में स्थापना के पश्चात् दल ने 1967 के जनार्ण आम चुनाव में भाग लिया। लोकसभा में इसने 19 स्थान प्राप्त किये। केरल और प. बंगाल में इस दल को सफलता मिली। केरल में नम्बूदीपद मुख्यमंत्री और पश्चिमी बंगाल में ज्योति बसु उपमुख्यमंत्री बने। इन दोनों ही राज्यो में वस्तुतः मार्क्सवादी साम्यवादी दल ही प्रभुत्ववादी दल था। 1971 के लोकसभा के चुनाव में इसे 25 स्थान प्राप्त हुए। मई 1972 के चुनाव में पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को पराजय का सामना करना पड़ा। 1977 के लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने जनता पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया, उसके फलस्वरूप उसे 22 स्थान प्राप्त हुए। जून 1977 में राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को पश्चिमी बंगाल में सफलता प्राप्त हुई। इसे विधानसभा में 178 स्थान प्राप्त हुए, जो स्पष्ट बहुमत का परिचायक था। दल के मुख्य स्तम्भ ज्योति बसु के नेतृत्व में सविद सरकार गठित हुई। ज्योति बसु के नेतृत्व में मार्क्सवादी नेतृत्व वाला वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा लगातार 1982, 1987, 1991 तथा 1996 में सम्पन्न राज्य विधानसभाओं के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने में सफल रहा। इन चारों चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। चारों ही अवसरों पर ज्योति बसु को वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे का नेता निर्वाचित किया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर संयुक्त मोर्चे के सभी घटक दलों में आग सहर्षीत थी। अगर ज्योति बसु द्वारा संयुक्त मोर्चे का नेता पद स्वीकार कर लिया जाता तो ये देश के पहले साम्यवादी प्रधानमंत्री बनते, लेकिन बसु ने नेता पद स्वीकार नहीं किया। इस दल को 1998 के बारहवीं लोकसभा के चुनाव में 32 तथा 1999 में तेरहवीं लोकसभा के चुनाव में 33 स्थान प्राप्त हुए। 2004 में चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 44 स्थान प्राप्त हुए।

जनता दल

(Janta Dal)

अक्टूबर, 1998 में जनता दल का गठन, भारतीय राजनीति की एक घटना थी। 1987 में हरियाणा में सत्तारूढ़ होने के बाद मुख्यमंत्री देवीलाल गैर साम्यवादी विपक्ष को संगठित करने के लिए प्रयास करते रहे। इस समय बोफोर्स लेप सौदे और अन्य रक्षा घोटालों में घिरि कमिश्नर (C) की 'जॉय' मूकित हो रही थी। ससद में और ससद के बाहर विपक्षी दल प्रहार कर रहा था। तत्कालीन रक्षामंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह के कमिश्नर (C) से त्यागपत्र देने के साथ देश के राजनीतिक पर्यावरण में परिवर्तन हुआ। उनके साथ सांसदों ने कमिश्नर (C) से अलग होकर 'जनमोर्चा' की स्थापना की।

जनता दल (समाजवादी) के लिए अत्यन्त निराशाजनक रहे। इसे लोकसभा में मात्र 5 स्थान ही प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर तो सफल रहे लेकिन उपप्रधानमन्त्री चौधरी देवीलाल सहित अनेक मन्त्री और सासद चुनाव में पराजित हो गए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा विधानसभाओं के चुनाव में भी दल को पराजय का सामना करना पड़ा। जबकि उत्तर प्रदेश में मुलायमसिंह यादव और गुजरात के चिमनभाई पटेल ने अपना सम्बन्ध तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी और गुजरात जनता दल का गठन किया। इससे जनता दल (समाजवादी) वस्तविक रूप से हरियाणा तक ही सीमित रह गया। मई 1996 के लोकसभा चुनाव में जार्ज फर्नांडीस के नेतृत्व वाली सपा पार्टी तथा चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाली जनता दल (समाजवादी) ने आपस में विलय कर सपा पार्टी का गठन किया, लेकिन चुनावों के बाद इस दल में फूट पड़ गई। जहाँ जार्ज फर्नांडीस और नीतिश कुमार के नेतृत्व वाले सपा पार्टी के गुट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबन्धन किया और वाजपेयी सरकार का समर्थन किया, वहीं चन्द्रशेखर और ओमप्रकाश चौटाना ने इसका समर्थन नहीं किया। इससे सपा पार्टी का विभाजन हो गया। 2004 के लोकसभा चुनावों में यह दल गृहत्वहीन रहा। इसे मात्र 1 स्थान प्राप्त हुआ।

विखण्डन तथा क्षेत्रीकरण

(Fragmentation and Regionalism)

भारत में तीन प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं—पहले वे क्षेत्रीय दल हैं जो वास्तव में जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण—तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रमुक, तमिल मनील कॉंग्रेस, पंजाब में अकाली दल, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉंग्रेस, महाराष्ट्र में शिव सेना, बिहार में झारखण्ड पार्टी आदि प्रदेशों में तेलुगुदेशम, असम में असम गण परिषद, मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी तथा हरियाणा में श्रिभाणा विरासत पार्टी हैं। दूसरे प्रकार के क्षेत्रीय दल वे हैं जो किसी समस्या विशेष को लेकर अथवा सदस्यों की क्षुब्धता के कारण राष्ट्रीय दलों से अलग हैं। इनमें से अधिकतर दल कुछ समय के लिए राष्ट्रीय रहे हैं। ऐसे दलों में भारतीय जनता दल, बंगाल काँग्रेस, उत्कल काँग्रेस, केरल काँग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति, विराटल हरियाणा तथा हरियाणा विकास पार्टी इत्यादि दल सम्मिलित किए जा सकते हैं। तीसरे वे दल हैं जो विचारधारा तथा लक्ष्यों के आधार पर तो राष्ट्रीय दल हैं परन्तु उनका समर्थन केवल कुछ लक्ष्यों तथा कुछ मामलों में कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। इस प्रकार के दल फारवर्ड ब्लाक, सोशलिस्ट यूनियो सेन्टर, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग, जनता पार्टी सांगलस्ट पार्टी इत्यादि हैं। प्रमुख क्षेत्रीय दलों को निम्नानुसार रखा जा सकता है—

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK).—तमिलनाडु का द्रविड़ मुनेत्र कड़गम क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय दलों में अपना प्रभाव रखता है। 1949 में सी. एन. अन्नादुराई ने द्रविड़ कड़गम से अलग होकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल की स्थापना की जिसका उद्देश्य द्रविड़ परम्परा और संस्कृति की रक्षा करना और तमिल समुदाय को राजनीतिक क्षेत्र में भागी स्थिति प्रदान करना है। 1965 में सम्पूर्ण मद्रास राज्य का नामकरण (वर्तमान में चेन्नई) हिन्दी विरोध के साथ ही 'राज्यों के लिए स्वायत्तता' इस दल की नीति एवं कार्यक्रम का आधार रहा है। द्रमुक औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन कर, लाइसेंस बाँटने का कार्य राज्यों को देना चाहता है। यह मिश्रित अर्थतन्त्र का समर्थक है और चाहता है कि देश की योजना में त्रिपक्षीय सहभागिता होनी चाहिए जिसमें सरकार, मालिक और श्रमिक सम्मिलित हों।

द्रमुक आरोप लगाता रहा है कि दक्षिण की निर्धनता का कारण औद्योगीकरण का सीमित विकास है और इसके लिए उत्तर भारतीय व्यापारियों द्वारा दक्षिण पर आर्थिक नियन्त्रण जिम्मेदार है। द्रमुक ने कई अवसरों पर उत्तर भारत की दक्षिण का शोषण करने वाली साम्राज्यवादी शक्ति की मञ्जूर दी और कहा कि केन्द्रीय सरकार दक्षिण के लोगों की आर्थिक स्थिरता के प्रति उदासीन है। इस प्रकार दक्षिण की आर्थिक स्वतन्त्रता का प्रश्न उत्तर के राजनीतिक प्रभुत्व से मुक्ति तथा द्रविड़ सन्नत की कार्य संस्कृति के नियन्त्रण से पृथक्ता के साथ जोड़ा गया। संतुष्टि एवं स्थानीय निर्धार का समर्थक होने के कारण दल को तमिलनाडु की जनता का समर्थन प्राप्त रहा है। 1967 में दल ने चलाई राज्य विधानसभा के चुनावों में विजय प्राप्त कर सी. एन. अन्नादुराई के नेतृत्व में द्रमुक मंत्रिमण्डल ने शपथ ली। इसके बाद द्रमुक ने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए पृथक् 'द्रविड़स्थान' की माँग को छोड़ दिया। 1967 में राज्य विधानसभा के 234 में से 138 स्थान और लोकसभा के 25 में से 25 स्थान प्राप्त किए। अन्नादुराई की मृत्यु के बाद के कर्णानिधि को मुख्यमंत्री निर्वाचित किया गया। जनवरी 1972 में दल का विभाजन हो गया और एम. जी. रामचन्द्रन ने अन्ना-द्रमुक की स्थापना की। 1967 से 1975 तक इस दल का राजनीति पर सर्वश्रेष्ठ बना रहा। 1975 में तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मार्च 1977 के छठे लोकसभाई चुनावों में द्रमुक का जनता पार्टी के साथ गठबन्धन होने के कारण सारी पूर्वी सफ़लापूर्व सफल हो गई और उसे केवल 1 ही स्थान प्राप्त हुआ। जून 1977 में तमिलनाडु विधान सभा के चुनाव हुए और 234 स्थानों में से द्रमुक को केवल 48 स्थान प्राप्त हुए। अन्ना द्रमुक ने द्रमुक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गौण स्थिति में ला दिया। 1980 में मध्यावधि लोकसभा चुनावों में द्रमुक

ने कांग्रेस (3) के साथ गठबंधन करके अपनी स्थिति में सुधार साकर 16 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस (3) को तमिलनाडु में 39 में से 20 स्थान मिले। इससे स्पष्ट हो गया कि तमिलनाडु में किसी राष्ट्रीय दल की अपेक्षा क्षेत्रीय दल का प्रभाव है। मई 1980 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में द्रमुक को पुनः पराजय हुई और दिसम्बर 1984 के लोकसभा चुनावों में द्रमुक केवल 1 सीट जीत सकी। लोकसभा के चुनावों के साथ ही तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा की 234 सीटों में से द्रमुक केवल 20 सीटें जीत सकी। करुणानिधि प्रभावी व्यक्तित्व के बावजूद पार्टी को जीता नहीं सके। उन्होंने केन्द्र राज्य सम्बंध एवं श्रीलंका में तयिती की दुरावस्था के मामले उठाए, लेकिन माद्रासा दोहरी पाबुबद्ध का साथ सातपणी दल से जुड़ा रहा। 1988 के बाद द्रमुक 7 दलीय राष्ट्रीय मोर्चे का घटक अंग बन गया। जनवरी, 1989 में तमिलनाडु विधान सभा के चुनाव में द्रमुक को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। एम. करुणानिधि मुख्यमंत्री बने। 1990 में इस दल को सरकार को बर्खास्त किया गया। 1991 में संसदीय और विधानसभा चुनाव में दल का सफाया हो गया। 1993 में विघटन हो गया।

1996 के लोकसभा के चुनाव के पूर्व द्रमुक की स्थिति कमजोर थी, लेकिन मुख्यमंत्री कु. जयललिता की नीतियों के फलस्वरूप एम. जी. रामचन्द्रन के नेतृत्व वाली तमिल मनीला कांग्रेस के साथ गठबंधन तथा फिल्म अभिनेता राजनीकाव के द्रमुक और तमिल मनीला कांग्रेस के गठबंधन को समर्थन देने के कारण राजनीतिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया। तमिलनाडु की जनता ने द्रमुक-तमिलनाडु मनीला कांग्रेस के गठबंधन को पूर्ण समर्थन दिया। द्रमुक को लोकसभा में 17 स्थान तथा राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 234 सदस्यीय राज्य विधानसभा में द्रमुक को अकेले ही 168 स्थान प्राप्त हुए। एम. करुणानिधि के नेतृत्व में राज्य में द्रमुक सरकार सत्ताह्वित हुई। द्रमुक 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में सहभागी रहा। इसे 1999 में लोकसभा के चुनावों में 12 स्थान प्राप्त हुए। 2004 में हुए चौदहवें लोकसभा के चुनावों में इस दल को 15 स्थान प्राप्त हुए।

अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम (A D M K.)—अविपक्षित द्रमुक (D M K.) के अध्यक्ष करुणानिधि और कोषाध्यक्ष एम. जी. रामचन्द्रन के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाने पर नवम्बर, 1972 में रामचन्द्रन ने पृथक् दल अन्ना द्रमुक (A D M K.) का निर्माण किया जिसका पूरा नाम अधिकृत भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम है। यह क्षेत्रीय दल है जिसका प्रभाव तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में है। इस दल की नीति राज्य में सत्ताह्वित होने और अपने हाथ में सत्ता सुरक्षित रखने की लिए आवश्यक है कि केन्द्र में शासक दल के साथ अच्छे सम्बंध बनाए रखे जाएं। अपातकाल के दौरान अन्ना द्रमुक श्रीमती गौधी का समर्थक रहा और जब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई तो दल ने समर्थन की घोषणा की। अन्ना द्रमुक ने बौद्ध चुनावी घोषणापत्र प्रकाशित नहीं किया, लेकिन प्रामाण्य महिलाओं और युवकों में दल और उसके नेता रामचन्द्रन की लोकप्रियता रही है। इस कारण तमिलनाडु की राजनीति को 'सिनेमाई राजनीति' कहा जाता है। अन्ना द्रमुक की नीति केन्द्र में सत्ताह्वित दल के साथ सहयोग करने की है। अपनी नीति के अनुसार जून 1975 से 1976 तक के अपातकाल में उस समय केन्द्र पर सत्ताह्वित कांग्रेस का तथा जनता पार्टी का तथा बाद में चरणसिंह की मिनी-जुली सरकार का समर्थन ही नहीं किया अपितु अन्ना द्रमुक के दो सदस्य के बाला पञ्जूर और श्रीमती सरावाणी मुमु मन्नी भी बने। दिसम्बर, 1984 के चुनाव में केन्द्र में सत्ताह्वित कांग्रेस और अन्ना द्रमुक के बीच सहयोग बना रहा।

मार्च 1977 के लोकसभा चुनावों में जहाँ द्रमुक ने केवल 1 स्थान प्राप्त किया, वहीं अन्ना द्रमुक ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 19 स्थान जीते। जून 1977 में तमिलनाडु विधानसभा के 234 स्थानों में से द्रमुक ने केवल 48 स्थान जीते, वहीं अन्ना द्रमुक ने 120 स्थान प्राप्त कर सरकार बनाई। पाण्डिचेरी विधानसभा में 30 में से 14 स्थान अन्ना द्रमुक ने जीते। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, अन्ना द्रमुक ने प्रतियोगिता को महत्व दिया, फलस्वरूप तमिलनाडु की जनता ने सभी नीतियों को अस्वीकृत कर प्रांतीय दल को ही स्वीकार किया। जनता पार्टी न विधानसभा की 234 सीटों के लिए 233 उम्मीदवार खड़े किए, पर उसे केवल 10 सीटों पर सफलता मिली। कांग्रेस के 198 प्रत्याशियों में से केवल 27 जीते। अन्ना द्रमुक के 200 प्रत्याशियों में से 129 ने विजय प्राप्त की। मत-प्रतिभाता को लें तो अन्ना द्रमुक को 37.5, द्रमुक को 21, कांग्रेस को 20 और जनता पार्टी को 10 प्रतिशत के लगभग मत मिले। जनवरी 1980 के आम चुनावों में लोकसभा में अन्ना द्रमुक ने जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। फलस्वरूप दल को पराजय का सामना करना पड़ा। अन्ना द्रमुक ने केवल 2 स्थानों पर विजय प्राप्त की। वह मार्च 1977 के साथ को खा बैठी। लोकप्रियता और विजय की दृष्टि में द्रमुक ने अन्ना द्रमुक को पछाड़ दिया, लेकिन मई, 1980 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक पुनः विजयी हुआ और सरकार बनाई। दिसम्बर, 1984 के आम चुनावों में लोकसभा में अन्ना द्रमुक ने 12 सीटें जीतकर द्रमुक की पुनः पराजय किया। द्रमुक को केवल एक सीट मिली। राज्य विधानसभा के चुनाव साथ ही हुए जिसमें बहुमत से विजय प्राप्त कर अन्ना द्रमुक ने सरकार बनाई।

अन्ना द्रमुक का विभाजन—दिसम्बर, 1987 में मुख्यमंत्री एम. जी. रामचन्द्रन के देशवासन के परचाऊ उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर अन्ना द्रमुक में फूट पड़ गई। बी. आर. नेदुन चैडियन को कार्यवाहक मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं करने दिया गया अतः श्रीमती जालाई रामचन्द्रन का मुख्यमंत्री के

के हाथ में चला गया और आनन्दपुर साहब प्रभाव एक बुनियादी मुद्दा बन गया। आनन्दपुर साहब के प्रभाव में जहाँ लिखा है कि अकाली दल सिखों के 'बोल बाला' के लिए सपर्य्य करेगा वहीं यह भी लिखा है कि इसके लिए टैक्स इत्यादि होना चाहिए। इसमें वर्तमान में पंजाब के साथ डलहौजी, चन्दीगढ़, पिंजौर, बालक, अम्बाला, ऊना, नरगढ़, जिला कराना के साहबपुर और गड़गा ब्लाक, सिरसा तहसील, रोहता तहसील, बिना हिंसा का गठित नार्क, राजस्थान के श्रीगंगानगर की 6 तहसील और इसके साथ सगने वाले अन्य पंजाबी भाषी इनके शामिल किए जाए।

धोरे-धोरे अकाली दल पर उपवादियों का शिकवा मजबूत होता गया और स्वर्ण मन्दिर सिखों का 'युद्ध मोर्चा' बन गया तथा यहाँ की अकाली गतिविधियों की चुनौती राष्ट्र की अखण्डता को खतरा पैदा हो गया अतः स्वर्ण मन्दिर में जून 1984 में सेना को प्रवेश करना पड़ा और भिड़टवाने सहित अनेक उपवादों का गये। इसे 'आनन्दपुर बन्द स्टार' कहा गया। पंजाब की समस्या अनसुलझी रही, हिंसा और अराजकता जारी थी और अकाली दल अपनी पुष्पनी धोरे के साथ-साथ नर-नर मसले उठाता रहा। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इन्दिरा गान्धी की हत्या उनके सिख अग्राहकों द्वारा की गई। उपवादी गतिविधियों तेजी बढ़ती गई और अकाली दल आतंकवादियों के सम्मेलन देवम हो गए। अकाली दल के उपवादी दल नाम तत्वों पर बुले ठहरे हावी हो गए। इन उपवादी तत्वों का आतंकवादियों से स्पष्ट गठजोड़ था। एजेंट सरकार ने पंजाब समस्या को प्राथमिकता दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अरुण सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया और अकाली दल के नेताओं की रिहाई के साथ-साथ एक के बाद एक बदम ठाढ़ गए जिनमें अकाली दल के नरम पंथ को प्रोत्साहन मिला और ठग पंथ उठता गया। अक्टूबर 24 जुलाई, 1985 को पंजाब समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री एजेंट गान्धी और अकाली नेता हरचन्द सिंह लोहोवाल के बीच एकमुरत हस्ताक्षर समझौता सम्पन्न हुआ। 26 जुलाई को अकाली दल ने समझौते पर मोहर लगा कर 'धर्म युद्ध' मोर्चा वापस लेने का घोषणा की, किन्तु 'समुद्र अकाली दल' और 'अखिल भारतीय सिख छात्र सभ' ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। दोनों समझौतों को 25 जुलाई, 1985 को अलग-अलग बैठकों में यह निर्णय लिये गये। समुद्र अकाली दल की बैठक की अध्यक्षता दिवंगत जर्नेल सिंह भिड़टवाल के पुत्र पिता तथा जोगेंद्र सिंह ने की। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद सन् हरचन्द सिंह लोहोवाल की उपवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। अकाली दल ने सुरजोत सिंह बलाना को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर समझौते पर चलने का निश्चय दोहोराया।

दिसम्बर, 1984 में पंजाब के 13 लोकसभा स्थानों के लिए चुनाव नहीं कराए गए थे। पंजाब विधानसभा का भी और राज्य में राष्ट्रपति शासन था। पंजाब समस्या पर ऐतिहासिक समझौते के बाद 25 सितम्बर, 1985 को लोकसभा की 13 सीटों तथा पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। लोकसभा की 13 सीटों में से अकाली दल को 7 एच डीएस (5) को 6 सीटें मिलीं। पंजाब विधान सभा की 117 सीटों में से 115 सीटों पर चुनाव में अकाली दल ने 72 सीटों पर विजय प्राप्त कर सुरजोत सिंह बलाना के मुख्यमन्त्रित्व में अकाली दल की सरकार का गठन किया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन का अन्त हो गया। सुरजोत सिंह बलाना और प्रकाश सिंह बादल के बीच चलने वाले सपर्य्य ने अकाली दल (लोहोवाल) का विघटन कर दिया। मई, 1987 में राज्यपाल द्वारा सुरजोत सिंह बलाना मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसी बीच अकाली दल के विभिन्न गुटों में एकता स्थापित कर एकिकृत अकाली दल की स्थापना की गई। 9 जुलाई, 1988 को पटियाला में अकाली दल के नरम-बन्द अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान के पिता और पंजाब विधान सभाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह मान की पार्टी का संघर्षक बनाया गया। इसके बाद पुनः अकाली दल में फूट पड़ गई। 1989 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल (मान गुट) को लोकसभा में 6 स्थान प्राप्त हुए। सिमरनजीत सिंह मान लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए लेकिन उन्हें अपने को लोकसभा में कृपा सहित नहीं जाने देने के प्रश्न पर त्यागपत्र दे दिया। 1990 से 1992 के बीच अकाली दल गुटों में विघटित हो गया। अकाली दल (मान गुट), अकाली दल (लोहोवाल गुट या बलाना गुट), अकाली दल (तलवटो गुट) और अकाली दल (कानुल गुट) जैसे प्रतिद्वन्द्वी गुट सामने आये। 1992 के राज्य विधानसभा चुनाव का अकाली दल (कानुल गुट) को छोड़कर सभी प्रमुख अकाली गुटों ने बहिष्कार किया। इस चुनाव में डीएस (5) को राज्य से होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त हुई। अकाली दल अनेक गुटों में विघटित हो गया। टाराचंद हन प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में संगठित हुए और उनके नेतृत्व वाला दल अकाली दल (बादल) कहलाया। दूसरी ओर उपवादी तत्वों का नेतृत्व सिमरनजीत सिंह मान के हाथ में आ गया जिसे अकाली दल (मान) की संज्ञा दी गई। 1996 के लोकसभा चुनाव में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबन्धन किया जिसका परिणाम था चुनाव में सफलता। 1998 के लोकसभा चुनाव में सिरोमणी अकाली दल (बादल) ने लोकसभा के 8 स्थानों पर विजय प्राप्त की। केन्द्र में यह भारतीय जनता पार्टी का समर्थक दल रहा, जिसने 'विशाल मर्दा' पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। तेरहवीं लोकसभा में वर्ष 1999 में इस दल को 2 स्थान प्राप्त हुए। वर्ष 2004 में हुए चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 8 स्थान प्राप्त हुए।

तेलगुदेशम—तेलगुदेशम आन्ध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल है। 1893 के राज्य विधानसभा के चुनावों में पूर्व स्थापित क्षेत्रीय दल ने राज्य में जहाँ जमा कर राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया। इस दल की सफलता का मूलाधार इसके संघायक नेता और तेलगु हिस्सों में लोकप्रिय कलाकार एन. टी. रामाराव के 'व्यक्तित्व' को जाता था। उन्होंने चुनाव प्रचार कर तेलगु भाषा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का नारा देकर तेलगु भाषी लोगों में लोकप्रियता प्राप्त की। 1984 के लोकसभा चुनाव में इस दल को कांग्रेस (I) के बाद सबसे बड़ा दल होने का गौरव प्राप्त हुआ। राज्य विधानसभा के चुनाव में इसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सत्ता के सूत्र वापस अपने हाथ में ले लिए। 1989 तक यह दल राज्य सत्ता में रहा। 1983 से 1989 तक का समय तेलगुदेशम के चरमोत्कर्ष का काल कहा जा सकता है। इस अवधि में यहाँ इस दल को राज्य के मतदाताओं का ठनरोता समर्थन प्राप्त होता गया, वहीं इसके नेता एन. टी. रामाराव का व्यक्तित्व ऊँचाइयों प्राप्ति करता गया और वे विपरीत राजनीति के मुख्य केन्द्र बिन्दु बन गये। 1984 में लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करके तेलगुदेशम ने सारे देश का ध्यान आकर्षित किया। इस बीच राज्यपाल गमलाल हाफ़ एन. टी. रामाराव को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करके, नान्देला भास्करराव को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के निर्णय का देश-व्यापी विरोध हुआ, फलतः रामलाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। डॉ. शंकरदास शर्मा ने एन. टी. रामाराव को पुनः मुख्यमंत्री बना दिया।

1989 के लोकसभा के चुनाव में राज्य के मतदाताओं ने तेलगुदेशम के इस सुदृढ़ गढ़ को भस्म कर दिया। इसे राज्य में मात्र 2 स्थान प्राप्त हुए। राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही सम्पन्न हुए। इसी तेलगुदेशम को पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस (I) पुनः सत्ता में आई। 1991 के लोकसभा चुनाव में तेलगुदेशम को 13 स्थान प्राप्त हुए, लेकिन इसके सदस्यों के दल-बदल कर कांग्रेस (I) में शामिल होने से इस दल की शक्ति में कमी आई। इसके आलावा एन. टी. रामाराव के 'विकास प्रकरण' से इस दल की प्रियछ में कमी आई। 1994 के राज्य विधानसभा चुनाव में संपर्कित एन. टी. रामाराव के नेतृत्व में तेलगुदेशम को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन उनकी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की भूमिका से रूढ़ होकर उनके दामाद एन. चन्द्रबाबू नायडू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने उनके प्रति विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप रामाराव सरकार अल्पमत में रह गई। रामाराव को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस सन्देह को वे सहन नहीं कर सके अन्ततः उनका देहावसान हो गया। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में अन्त हो गया। 1998 की लोकसभा में इसके 12 सदस्य निर्वाचित हुए। 1999 में तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल के 29 सदस्य चुने गये। 2004 में गठित चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 5 स्थान प्राप्त हुए।

तेलगुदेशम (नायडू)—1995 में चन्द्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आन्ध्र प्रदेश में तेलगुदेशम के अधिसंख्यक विधायकों ने एन. टी. रामाराव से विद्रोह करके उन्हें सत्ता से अपदराव कर दिया। एन. चन्द्रबाबू नायडू ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एन. टी. रामाराव के देहावसान के बाद तेलगुदेशम (नायडू) की वास्तविक शक्ति बचकर उभरी। यद्यपि रामाराव की विधवा पत्नी लक्ष्मी पार्वती ने चन्द्रबाबू नायडू का विरोध जारी रखा। सन् 1996 के लोकसभा चुनाव में चन्द्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलगुदेशम को 16 स्थान प्राप्त हुए। इसने ही इसे वास्तविक तेलगुदेशम दल सिद्ध कर दिया। इस विजय ने चन्द्रबाबू नायडू का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व अधिक बढ़ा दिया। केन्द्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार को सततकूट करने में चन्द्रबाबू नायडू की भूमिका रही है। बारहवीं लोकसभा में 1998 के चुनावों में तेलगुदेशम के 12 सदस्य थे। तेरहवीं लोकसभा में तेलगुदेशम को 29 स्थान मिले तथा उनमें से एक जी. एच. सी. बोसयोगी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। चौदहवीं लोकसभा के मई, 2004 में प्राप्त हुए परिणामों में इस दल की शिराशा जनक स्थिति रही।

समाजवादी पार्टी—अक्टूबर, 1992 में मुलायमसिंह यादव ने जनता दल (समाजवादी पार्टी) से अलग होकर 'समाजवादी पार्टी' नामक क्षेत्रीय दल का गठन किया। मुलायमसिंह ने मुलायमसिंह, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जाटों और नुर्जरी जैसी जातियों में जनधारा विस्तृत किया। अपने को चौधरी चरणसिंह का शासत्विक उत्तराधिकारी और 'मासपुत्र' बता कर जनता दल (अजीत) के समर्थक वर्ग को आकृष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देकर मुस्लिम मतों के आधार पर राजनीति करने वाले इमामों की फतवा राजनीति का विरोध किया। बारौराम के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबन्धन करके समाजवादी पार्टी राज्य की सबसे प्रज्ज्बुत 'राजनीतिक शक्ति' बनकर सामने आई। सन् 1993 के राज्य विधानसभा चुनाव के समय अपने दल का चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने, सत्ता में आते ही नक्सल विरोधी कानून को रद्द करने, अयोध्या प्रकरण का शान्तिपूर्ण समाधान करने तथा साम्प्रदायिक शोषण कायम रखने, विपक्षीय को समाज करने तथा साम्प्रदायिक दंगा होने की स्थिति में सम्बन्धित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को उत्तरदायी बनाने जैसे मुद्दों को दोहराया गया। चुनाव परिणाम में समाजवादी दल और बहुजन समाज पार्टी (सम-मतदाता) गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन 171 स्थान प्राप्त दूसरे स्थान पर रहा। कांग्रेस (I) जनता दल और निर्दलीय सदस्यों द्वारा फिना शर्त गठबन्धन का समर्थन करने की घोषणा के साथ ही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। दिसम्बर, 1993 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में सभा-बसपा की संविद सरकार सत्ताकूट हुई जो सन्धे समय तक वहीं चल सकी। बसपा द्वारा मुलायम सिंह सरकार का

समर्थन वापस लेने के कारण उनकी सरकार का पतन हो गया। इसके बावजूद मुलायमसिंह यादव राज्य में अपना जनाधार सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुनःआधार दीरे करते रहे। 1996 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की 17 स्थान प्राप्त हुए तथा 1998 में 20 स्थान प्राप्त हुए। जिससे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक शक्ति है। 1999 में हुए तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 26 स्थान प्राप्त हुए। चौदहवीं लोकसभा के गई, 2004 में प्राप्त हुए परिणामों में इस दल को 35 स्थान मिले।

बहुजन समाज पार्टी—14 अप्रैल, 1984 को कांशीराम झाप बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। इस दल का वर्तमान में न तो कोई संविधान हो है और न कोई औपचारिक संगठन ही है। कांशीराम को छोड़कर न तो दल में कोई प्रभावशाली नेता ही है और न ही कोई प्रादेशिक नेता ही। राष्ट्र दल कांशीराम के व्यक्तिगत पर आधारित है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की नीतियों और कार्यक्रम का सम्बन्ध है यह बनिया, राजपूत और ब्राह्मणवाद का विरोध, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण तथा 'मन्त्री' (धन), भाषिया और मीडिया के विरोध करने के कार्यक्रम पर आधारित है। इसके आलोचक बसपा पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब इसके प्रमुख प्रभाव क्षेत्र हैं।

1989 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 3 स्थान प्राप्त हुए, वहीं 1991 के लोकसभा चुनाव में इस दल को मात्र 11 स्थान प्राप्त हुए। इसके बाद 1993 के राज्य विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में 67 स्थानों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति में वृद्धि की। बसपा के सदस्यों ने मुलायमसिंह मन्त्रिमण्डल में भाग लिया, लेकिन दल की महासचिव सुखी मायावती और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता ने बसपा को बाद में के नेतृत्व वाले मन्त्रिमण्डल से समर्थन वापस लेने के लिए बाध्य किया। बाद में सुखी मायावती भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन जून 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती की कार्य-शैली तथा डटेजक बयानों से नाराज होकर इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस पर मायावती ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। राज्य में विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 11 स्थान प्राप्त हुए और दल के अध्यक्ष काशीराम विजयी हुए। कांशीराम के नेतृत्व में बसपा ने विरवास मत के समय अटलबिहारी वाजपेयी और एच. डी. देवेगौडा का विरोध किया। 1998 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने 5 स्थान प्राप्त किए। 1999 में तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 14 स्थान प्राप्त हुए हैं। मई, 2004 में प्राप्त चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल ने 20 स्थान किये।

नेशनल कॉंग्रेस—नेशनल कॉंग्रेस जम्मू-कश्मीर का मुख्य क्षेत्रीय दल है। इसकी स्थापना कश्मीर के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला द्वारा की गई थी। इसकी नीतियों और कार्यक्रमों में जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को बनाए रखने, भारतीय संघ में विलय को अन्तिम मानने और इसे भारत का अधिन अंग मानने, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं। इसके नेता शेख अब्दुल्ला का राजनीतिक इतिहास अनेक उतार-चढ़ावों में भरा हुआ है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गान्धी और उनके बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इसके आधार पर कश्मिर के मुख्यमंत्री सैयद नूर कासिम ने शेख अब्दुल्ला के लिए मुख्यमंत्री का पद खाली कर दिया। शेख अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कश्मिर और उनके सम्बन्ध विगड़ गये। कश्मिर ने समर्थन वापस ले लिया। 1977 में मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की सलाह पर राज्यपाल एल. के. झा ने राज्य विधानसभा को भंग कर पुनः निर्वाचन करवाया। राज्य में नेशनल कॉंग्रेस की एकदलीय सरकार सत्तावर्य हुई। इसके बाद राज्य में कश्मिर (इ) कभी अपनी एक दलीय सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। शेख अब्दुल्ला के देहावसान के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र डॉ. फारूख अब्दुल्ला को दल का नेता निर्वाचित किया गया। वे राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इससे नेशनल कॉंग्रेस में सत्ता संपर्क प्रारम्भ हो गया। डॉ. फारूख अब्दुल्ला और उनके बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह के बीच संपर्क चलता रहा। डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय राजनीति में कश्मिर (इ) के विरुद्ध विपक्षी दलों को समर्थन देने की नीति अपनाई। श्रीनगर में विपक्षी दलों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इससे कश्मिर (इ) का रुठ होना ही था। 1984 में कश्मिर (इ) की सह से राज्य में दलबन्धन कृत्य गया। गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व में विधायकों ने नेशनल कॉंग्रेस छोड़ते हुए नेशनल कॉंग्रेस (खालिद) के गठन की घोषणा की। इससे फारूख मन्त्रिमण्डल अल्पमत में आ गया। मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने राज्यपाल जगमोहन से राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने का अनुरोध किया, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा करने के स्थान पर फारूख अब्दुल्ला को बर्खास्त करके गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जिसकी देशव्यापी निन्दा हुई। साम्यवादी, गैर साम्यवादी, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने केन्द्र के इस कदम का विरोध किया। इसके बाद डॉ. फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉंग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली अल्पमतयी सरकार को हटाने का प्रयास किया। इस बीच राजीव गान्धी के नेतृत्व में कश्मिर (इ) और नेशनल कॉंग्रेस के बीच मतभेदों को कम करने का प्रयास किये जाते रहे। केन्द्रीय मन्त्री राजेश पायलट ने इसमें मुख्य भूमिका निर्वहण किया। इससे नेशनल कॉंग्रेस और कश्मिर (इ) में गठबन्धन बनने का आधार बना। इसके आधार पर ही 1986 में राज्यपाल जगमोहन द्वारा गुलाम

मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली अल्पमतीय सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा को भंग किया गया। इसके बाद राज्य विधानसभा के लिए हुए चुनाव में डॉ. फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्ग्रेस और काँग्रेस (इ) गठबन्धन ने तीन-चौपाई बहुमत प्राप्त किया। फलतः उनके नेतृत्व में नेशनल कॉन्ग्रेस और काँग्रेस (इ) की संविद सरकार सत्तारूढ़ हुई। इसके पूर्व जम्मू-कश्मीर में राजीव और डॉ. फारूख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ। 1989 में केन्द्र में सत्ता-परिवर्तन हुआ। विश्वनाथ प्रतापसिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ हुई। इस सरकार ने जागमोहन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की। इसके विरोध में डॉ. फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली संविद सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। सितम्बर, 1996 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। नेशनल कॉन्ग्रेस के नेता डॉ. फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार कार्यरत है। 1999 की तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 4 स्थान प्राप्त हुए। मई, 2004 में प्राप्त चौदहवीं लोकसभा के चुनाव परिणामों में इस दल ने 11 स्थान मिले।

असम गण परिषद (अगण)—असम गण परिषद असम का क्षेत्रीय दल है। असम से विदेशियों को निष्कासित करने के लिए अखिल असम छात्र सभ और असम गण सभाय परिषद के तत्वावधान में एक प्रबल जन-आन्दोलन चलाया गया। देश के गैर साम्यवादी विपक्षी दलों तथा जनता द्वारा आन्दोलन को समर्थन देने से आन्दोलन के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ। राज्य में बन्द का आयोजन करना इस आन्दोलन के प्रमुख अंग थे। अन्त में 1985 में राजीव गाँधी और असम के आन्दोलनकारियों के बीच 'असम समझौता' हुआ जिसके अन्तर्गत राज्य विधानसभा को भंग कर नये चुनाव कराये जाने की व्यवस्था थी। इस पर दिवेश्वर सैकिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस (इ) की सरकार द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। इसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अखिल असम छात्रसभ और अखिल असम गण परिषद ने अपना विषय करते हुए 'असम गण परिषद' (अगण) के रूप में संगठित किया। इस दल को राज्य विधानसभा में समर्थन प्राप्त हुआ। प्रफुल्लकुमार मदन को असम गण परिषद का नेता निर्वाचित किये जाने पर मुख्यमंत्री बनाया गया। वे देश में सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री बने, साथ ही दल के अध्यक्ष भी बने रहे। असम गण परिषद की नीतियों में असम की सांस्कृतिक विरासत और घोरछोर की सुरक्षा और राज्य में अवैध रूप से आये विदेशियों की पहचान करके उन्हें बाहर निकालने तथा राज्य का विकास करने जैसे गुरे शामिल थे। सत्तारूढ़ होने के बाद असम गण परिषद में अन्तर्कलह और गुटबन्दी की स्थिति चलती रही। यह मुख्यमंत्री प्रफुल्लकुमार मदन और गृहमंत्री भृगुकुमार फूकन के नेतृत्व में दो प्रतिद्वन्दी गुटों में विभाजित हो गई। इससे जहाँ दल में गुटबाजी और अनुरक्तसन्धीनता की गठनाई भ्रष्ट हुई, वहाँ सरकार की कार्य-शैली के कारण जनता में दल की छवि गिरी। राष्ट्रीय राजनीति में असम गण परिषद ने राष्ट्रीय मोर्चे के साथ अपने को सम्बद्ध कर लिया। विश्वनाथ प्रतापसिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में दिनेश गोस्वामी दल के मंत्री रहे। नवम्बर, 1990 में चन्द्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल (समाजवादी) की सरकार ने प्रफुल्लकुमार मदन के नेतृत्व वाले मन्त्रिमण्डल का बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इसके पश्चात् दल का विभाजन हो गया। भृगुकुमार फूकन के समर्थकों ने मदन के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए असम से नये दल का गठन किया। सन् 1991 के राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में असम गण परिषद की भारी पराजय हुई। इस चुनाव के बाद इस दल ने राष्ट्रीय मोर्चे में अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। असम गण परिषद ने राज्य में सशक्त विपक्ष की भूमिका को बनाये रखा। 1996 में लोकसभा के चुनाव के साथ ही राज्य विधानसभा के निर्वाचन सम्पन्न हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस (इ) नेता दिवेश्वर सैकिया के देहासन के कारण राज्य में कांग्रेस को आपात लगा। 126 सदस्यीय राज्य विधानसभा में असम गण परिषद को 59 स्थान प्राप्त हुए। प्रफुल्लकुमार मदन ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। असम गण परिषद केन्द्र में गठित संयुक्त मोर्चे का एक अभिन्न अंग रही। चौदहवीं लोकसभा में मई, २००४ को प्राप्त हुए परिणामों में इस दल को 3 स्थान प्राप्त हुए।

शिवसेना—शिवसेना महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय दल है। बाल ठाकरे इसके संस्थापक हैं। प्रारम्भ में शिवसेना ने 'महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए है' का नारा लगाकर गैर महाराष्ट्रियों में दहशत उत्पन्न कर दी थी। बाद में शिवसेना के नजरिये में परिवर्तन हुआ और इसने राष्ट्रीय प्रतिरोध में सोच विकसित करके इस नारे का व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। शिवसेना 'हिन्दुत्व विचारधारा' की कट्टर समर्थक है। सन् 1989 से इस दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी गठबन्धन है। 1995 के महाराष्ट्र के सम्पन्न हुए चुनाव में शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी के गठबन्धन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। शिवसेना के नेता मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्य में पहला अवसर था कि शिवसेना का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हो। इससे शिवसेना की शक्ति और प्रतिष्ठान में वृद्धि हुई। 1996 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने महाराष्ट्र में 15 स्थानों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति में वृद्धि की। इस दल को 1998 की बारहवीं लोकसभा के चुनावों में 6 तथा 1999 में तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में 15 स्थान प्राप्त हुए हैं। चौदहवीं लोकसभा के अप्रैल-मई, 2004 के चुनावों में इस दल को 12 स्थान प्राप्त हुए।

हरियाणा विकास पार्टी—हरियाणा विकास पार्टी हरियाणा का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। चौधरी बशीरतल इसका संस्थापक है। सन् 1996 में लोकसभा के साथ-साथ हरियाणा विधानसभा के निर्वाचन सम्पन्न हुए। इन चुनावों में हरियाणा विकास पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबन्धन किया। चौधरी बशीरतल के नेतृत्व में इस गठबन्धन ने 90 सदस्यीय सदन में 44 स्थान प्राप्त किये। बशीरतल को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिनाई गई। फरवरी 2000 के विधानसभा निर्वाचन में हरियाणा विकास पार्टी की पाठ्यप हुई तथा ओमप्रकाश चौटाना मुख्यमंत्री बने।

तमिल मनीला कॉंग्रेस—यह तमिलनाडु का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। 1996 के लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हाय द्वारा कॉंग्रेस (I) के अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक के साथ चुनावी गठबन्धन करने का निर्णय से यह होकर जी. के. मुन्नाय, पी. चिदम्बाम् द्वारा एम. अन्नादुरैयम् के नेतृत्व में राज्य के अनेक कॉंग्रेसजनों ने कॉंग्रेस (I) से त्यागपत्र देकर 'तमिल मनीला कॉंग्रेस' नाम से एक क्षेत्रीय दल का गठन किया। इस दल ने द्रमुक के साथ चुनावी गठबन्धन किया। इस दल को लोकसभा में 20 तथा राज्य विधानसभा में 37 स्थान प्राप्त हुए। केंद्र में सन्तुष्ट मोदी को सरकार को सलाह करने में इस दल की अग्रिम भूमिका रही थी। वर्तमान में इस दल की स्थिति अनेककृत कमजोर है।

अन्य क्षेत्रीय दल—अन्य मुख्य क्षेत्रीय दलों में बिहार में झारखण्ड पार्टी, मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रन्ट, नागालैण्ड में नागा नेशनल फ्रन्ट, असम में प्लेस टाइबल्स कडमिसिन्ट, सिक्किम में सिक्किम समाज परिषद्, त्रिपुरा में त्रिपुरा उपजाति सभा, महाराष्ट्र में पीपेन्ट एण्ड वर्कर्स पार्टी, गोवा दमन एवं दीव में महाराष्ट्रवादी गोपबन्धक पार्टी, केरल में केरल कॉंग्रेस (मणि गुट और मुस्लिम लीग) और मेघालय में आल पार्टी हिन्द लीडर्स कॉन्ग्रेस, हिल स्टेट यूनिन, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम गिनाये जा सकते हैं।

सात क्षेत्रीय दलों की साम्यता समझ—29 जून 2000 को चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करके हरियाणा विकास पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर को समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) समेत सात पार्टियों को क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता समझ कर दी थी।

भारत में विपक्ष की भूमिका

(Role of Opposition in India)

भारतीय लोकतन्त्र का दुर्भाग्य ही है कि देश में चौदह संसदीय निर्वाचनों के सम्पन्न होने के परावर् अन्ध भी सरासरी विपक्ष विकास के क्रम में है। सन् 1967 के आम चुनावों के बाद विभिन्न राज्यों में सत्ता में आई संकेत सरकारें केंद्र में जनता शासन के 1977-79 का काल 1989 से 1990 तथा 1996 से आज तक के काल को छोड़कर देश में कॉंग्रेस का शासन रहा। ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव के बाद कॉंग्रेस (I) का शासन समाप्त हुआ। समय-समय पर देश में कॉंग्रेस और कॉंग्रेस (I) को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के मोर्चे संगठित होते रहे हैं। ऐसे मोर्चों को साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी दोनों ही रूपों में रखा जा सकता है। साम्यवादी दलों के मोर्चों में मार्क्सवादी दल के नेतृत्व में गठित कम्युनिस्टी लोकतान्त्रिक मोर्चा प्रमुख है, जो पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और केरल में कार्य करता रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी साम्यवादी दल के नेतृत्व में भारतीय साम्यवादी दल आर. एस. पी. और फारवर्ड ब्लॉक का 'वामपंथी मोर्चा' अस्तित्व में है। यह सदन में और सदन के बाहर कार्य कर रहा है लेकिन इसका प्रभाव-रेख सामित है। यह पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल और त्रिपुरा में ही प्रभावशाली है। अप्रैल-मई 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाला राजग विपक्षी की भूमिका में आ गया।

गैर-साम्यवादी दलों के मोर्चे—गैर साम्यवादी दलों ने भी कॉंग्रेस को चुनौती देने के लिए अनेक मोर्चे बनाये। राष्ट्रीय स्तर पर 1971 में स्थापित संगठन कॉंग्रेस भारतीय जनसत्ता स्वतन्त्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का 'बौद्ध' (Grand Alliance), 1977 के चुनाव के समय स्थापित की गई जनता पार्टी, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का लोकतान्त्रिक गठबन्धन तथा राष्ट्रीय मोर्चे हैं। समय-समय पर राज्य स्तर पर अनेक मोर्चे गठित किये गये। इनमें परजल में अक्षयती दल और भारतीय जनसत्ता का सफुक्त मोर्चा, ठंडीसा में स्वतन्त्र पार्टी का सद्गुप्त मोर्चा, तमिलनाडु में द्रमुक एवं मनीला कॉंग्रेस, महाराष्ट्र में शिवसेना एवं भारतीय जनता पार्टी का गठबन्धन, असम में असम गण परिषद तथा कम्युनिस्ट दलों का गठबन्धन, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी के गठबन्धन को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।

भारत में आज तक स्वस्थ और शक्तिशाली विपक्ष का विकास नहीं हो सका है, इसके लिए निम्नलिखित कारणों को ठहरावारी ठहराया जा सकता है—

1. अग्रियों से सत्ता भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस को प्राप्त हुई थी और वह राजनीतिक दल के रूप में बनी रही। यद्यपि गाँधीजी ने कॉंग्रेस के राजनीतिक स्वरूप को समाप्त करना चाहा था तथापि स्वार्थ की राजनीति तथा सत्ता को

लेखपत्र ने भीषणी का मत नहीं माना। भारत की जनता काँग्रेस को स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आन्दोलन था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो राजनीतिक दल बना, उसके अन्तर को नहीं समझ सकी। चुनावों में काँग्रेस को इसका लाभ मिलता रहा है।

2. काँग्रेस ने शक्तिशाली राजनीतिक संगठन के रूप में, सत्ता के चक्कर से, विरोधी पक्ष को चुनौती देकर दिया और सत्ता के आकर्षण में विरोधी पक्ष के बहुत-से सदस्य काँग्रेस में आ गए। इस प्रकार स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद काँग्रेस की सरकार में प्रत्येक विचारधारा के लोग एकत्रित हुए। काँग्रेस के भीतर समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी थे और काँग्रेस की नीतियों सबके मन में ठहरी थीं। अतः जो कार्य विपक्ष को करना था, वह काँग्रेस के भीतर विद्यमान विरोध पुरा करता रहा है।

3. काँग्रेस के बाहर जो राजनीतिक दल थे, वे छोटे छोटे भागों में विभाजित रहे हैं जो स्वयं को एक-दूसरे का विरोध करते रहे हैं और एक सरकार में आने को भी तैयार नहीं होते हैं। विपक्ष की स्थिति का लाभ सत्ताका दल को मिलता रहा है।

4. विपक्ष का विकास भीषण एवं प्रभावहीन रहने के कारण विभिन्न दलों की समान प्रवृत्ति है। अधिकांश विभिन्न दलों का नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं जो कापी काँग्रेस में थे और शीर्षस्थ नेताओं में मतभेद के कारण वे विपक्ष में चले गए हैं। ऐसा विपक्ष लोकतन्त्र की ज़िम्मेदारी को निभाने की बजाय अपना समय झींटों की हेरफेर में व्यतीत कर देता है या जाति और उपजाति की 'अपेक्षा' की तलाश में समस्त विपक्ष को कैंक्रेस करता रहता है।

5. धन और प्रभाव की राजनीति सत्ताका दल को प्रभावशाली और विपक्ष को कमजोर बना रही है। चुनावों के समय जब भविष्य के साथ वरिष्ठ शासन अधिकारी घूमते हैं तो इसका प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है, विरोधकर तब जब राज्य में वही दल सत्ताका है जो केन्द्र में है। सत्ताका दल के सदस्य नियमों के बाहर अपने समर्थकों का कार्य करने में सफल हो जाते हैं जबकि विपक्ष के सभी कार्य में नित्य नई बाधा उपस्थित होती है।

6. स्वयं विपक्ष के मार्ग में आने वाली रुकावट 'धन की शक्ति' है जो सत्ताका दल के पास स्पष्टीकृत अधिकारी है। उसे विपक्ष की तुलना में खुले हाथ से चन्दा प्रदान कर बदले में अनिवारित पारित, लाइसेंस और ठेके आदि लिए जाते रहे हैं।

7. विपक्ष को प्रभावहीन बनाने में देश की वर्तमान चुनाव प्रणाली सहायक रही है, जिसके द्वारा काँग्रेस अल्पमतों पर सत्ताका होती रही।

8. इन सभी का यह अर्थ नहीं है कि विपक्ष दुर्बल एवं प्रभावहीन स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं है। विपक्ष के पास राजनीतिक विचारधारा एवं कार्यक्रम का अभाव रहा है। विपक्षी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सस्ती लोकप्रियता के साधनों को अपनाते हैं साथ ही सत्ता के भीतर एवं बाहर ही दमना करने, शोरगुल करने छींटकरी करने में ही अधिक दिलचस्पी लेते हैं।

स्वयं विपक्ष के विकास के लिए सुझाव

1. विपक्ष को देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक मामलों की जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे उन मामलों पर मार्ग निर्देशन का स्वयं एवं प्रबुद्ध जनमत तैयार कर सके। अमेरिका में 'वाटरगेट काण्ड' का भण्डाफोड प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही सम्भव हो सका था।

2. निर्वाचनों में धन का अधिक व्यय जनता को भ्रम में डालता है। चुनावों में लाखों रुपये खर्च करना फिर कई गुना अधिक कमजोर राजनीति का एक मात्र सिद्धान्त बन चुका है। निर्वाचन सम्बन्धी व्यय सरकार द्वारा ठेकाकर या राजनीतिक दलों को उनकी प्रतिनिधित्व शक्ति के आधार पर निर्वाचन व्यय के लिए आर्थिक भक्ष्यता देकर किया जा सकता है।

3. हिंदीय प्रणाली के विकास के लिए प्रयास किया जाए। समान विचारधारा वाले दलों का सुधीकरण होना चाहिए। राष्ट्रीय दल होने के लिए मापदण्ड में परिवर्तन करके दलों की संख्या कम की जा सकती है।

4. विपक्षी दलों को सुस्पष्ट कार्यक्रम और विचारधारा के आधार पर मिलकर एक हो जाना चाहिए।

5. दल-बदल का सहमा लेकर विपक्ष की शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहिये।

6. विपक्ष को अपने दृष्टिकोण एवं महत्वाकांक्षों में परिवर्तन लाना होगा। 'विरोध के लिए राजनीति को छोड़कर' उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाया जाय। सदन की कार्यवाही को रोककर अद्वितीय किया गया विरोध नहीं पातक और नकारात्मक है वही घोर प्रतिक्रियावादी विध्वंसक एवं लोकतन्त्र विरोधी भी है।

दबाव समूह**(Pressure Groups)**

राजनैतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आधुनिक काल में दबाव तथा दबाव समूहों की लोकतन्त्र का परचमक एवं सहयोगी भाग बनता है। वर्तमान में दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति राजनैतिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं और राजनैतिक शक्ति के स्वल्प को प्रभावित करते हैं। राजनैतिक दल न होते हुए भी वे दलों की भाँति राजस्व-संगठन हैं जिसकी सदस्यता खरेद, एकता, प्रतिष्ठा और साधन होते हैं। सामान्यतः द्वि-स्तरीय व्यवस्था में ये अधिक जगत्सक और राजस्व-सम्पन्न रहते हैं, बहुस्तरीय व्यवस्था में राजनैतिक दलों का अन्तर्गत इतना प्रभाव और स्थानों हो जाता है कि वे खुद दबाव समूहों से लगते हैं। आधुनिक दबाव समूह दम्पन आर्थिक युग की देन है। इनके मध्य विविध हित-सम्पन्न फर्मों, प्रान्तीय, संयुक्त कर्मियों, विविध उद्योगों आदि के ऐसे अङ्गभूत होते हैं जो विविध तर्कों अथवा विषयों को अपने पक्ष में करते हैं। इसी कारण वेग इन दबाव समूहों को प्रभावित का केन्द्र करते हैं। अमेरिका में दबाव-समूहों के प्रतिनिधियों को 'लॉबीस्ट्स' (Lobbyists) कहा जाता है। प्रत्येक व्यवस्थापक सदन के साथ सगो हूँ करने अथवा बहाने को 'लॉबी' (Lobby) अर्थात् 'प्रवोच' कहा जाता है जहाँ विधायक अवकाश के समय अन्तर बैठते हैं। वहाँ दबाव समूहों के प्रतिनिधि अपने सम्पर्क स्थापित करते हैं तथा उन्हें अपने पक्ष में प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। यह प्रभाव न केवल प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा वार्त्त जनमत और प्रचार द्वारा भी हासिल जाता है तथा पक्षधर व्यक्तियों की जाती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जगत्ता में सहायता प्राप्त करने के लिए तथा खरेद-प्रति में सहायक सिद्ध होने वाले लोगों के हितों को अपने अनुकूल करने के लिए दबाव समूह अथवा वार्त्त एवं आर्थिक हितों के प्रभावशाली संगठन, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक प्रकाश विरोधों की सेवाओं आदि का उपयोग करते हैं। वे अपना सहाय्य विस्तार करते हैं और अपने हितों से विशेष दावों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं।¹ संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पाश्चात्य देशों के दबाव समूह आधुनिक तकनीक के द्वारा ही प्रभावशाली तथा रक्षितराली बन गये हैं।

दबाव समूह और राजनीतिक कार्य-व्यवहार अथवा दबाव-समूहों की तकनीक**(Pressure Groups and Political Action or The Technique of Pressure Groups)**

दबाव अथवा दबाव समूह लगभग असंख्य विविधताओं (Almost Endless Varieties) के साथ व्यवहार में क्रियाशील रहते हैं।² दबाव समूहों की तकनीक को निम्नानुसार रखा जा सकता है—

दबाव समूह और चुनाव (Pressure Groups and Elections)

दबाव समूह निर्वाचनों के माध्यम से हितों के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करते हैं। यह सहायक अथवा अप्रत्यक्ष-रक्षित के रूप पर राजनैतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की 'अप्रत्यक्ष दबाव नीति' (Indirect Pressure Policy) है। दबाव समूह चुनाव के समय उन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करके उन्हें सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनके अर्थ होटी है कि वे विधान-सभा, कानून, सरकार में पहुँच कर उनके हितों का पोषण करेंगे। दबाव समूहों का प्रयत्न रहता है कि वे अपने अनुकूल राजनैतिक दल को पक्षधर से समर्थन प्रदान करें, उसके विरोध केवल सरकार में अपने अनुकूल दलकों (प्रतिपक्षी आदि) को भिद्यार्थे विधान सभा में अपने अनुकूल सदस्यों को बाँधत में सने का प्रयत्न करें तथा राजनैतिक सला उनके पक्ष में कुछी रहे या उनके हितों का रक्षण रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा भारत के दबाव समूह ऐसा ही करते हैं। आदर्श में छोटे दल जो सदा में अपने में असमर्थ होते हैं, दबाव समूह के साथ मिलकर कार्य करते हैं।

दबाव समूह और विचार-शक्ति तथा प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया—दबाव समूह अथवा प्रवोचक गुट एक 'गतिक शक्ति' (Dynamic Force) है। वे प्रवोचक के रूप में सत्ता स्थान बनाए रखने में सहयोग देते हैं। वे सरकारों के अन्तर्गत में तथा निर्वाचनों की प्रविधि में शक्ति को रोकेते हैं तथा जन-जीवन में राजनैतिक के प्रति शक्ति उत्पन्न करते हैं। निर्वाचनों के पराजित करने इन अनुकूल विरोधक तथा सार्वजनिक हितों को सहायता से प्रवोचक गुट विधान-सभा एवं सदनियों के वहाँ में प्रतिनिधियों को केन्द्रित करके व्यवस्थापन को अपने हित में प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। दबाव समूहों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में व्यक्ति इन्हीं गुटों के माध्यम से निम्न-निर्धारित शक्ति को प्रभावित करके अपने निजी हित रक्षित करते हैं। दबाव समूह प्रवोचकों के सम्बन्ध में विशेष योग देते हैं।

1. Stephen L. Wasby : Political Science : The Discipline and its Dimensions, p. 365

2. Charles R. Adams : The American Political Process, p. 221.

दबाव समूह और गोष्ठियाँ (Pressure Groups and Conference etc.)—विश्व में अनेक साधन-सम्पन्न दबाव समूह विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद के लिए समयानुसार गोष्ठियाँ, सेमीनार, व्याख्यान मालाओं और कार्याओं का आयोजन करते हैं जिनमें विधायकों और प्रशासकों को आमंत्रित किया जाता है। इन गोष्ठियों, कार्याओं आदि का उद्देश्य अपने मत को लोगों के सामने प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त करना तथा विधायकों को अपने पक्ष में प्रभावित करना होता है। इस कार्यकारी का प्रमुख रूप में काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आमंत्रित और भाग लेने वाले व्यक्तियों की प्रभावशाली सूची विपक्षी और कार्यकारी क्षेत्र दबाव समूह के प्रभाव से परिचित हो जाते हैं और ऐसे कदम उठाने से बचते हैं जिनसे उन दबाव समूहों से टकराने की स्थिति आए।

दबाव समूह और लॉबींग (Pressure Groups and Lobbying)—लॉबींग का आशय है कि दबाव एवं दान समूहों के कार्यकर्ता व्यवसायिक साधन-सम्पन्न के कक्षों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से विधायकों से सम्पर्क स्थापित कर उन पर विभिन्न उपायों से दबाव डालते हैं कि वे ऐसी विधि का निर्माण करें जिससे उनके (समूहों) हितों का साराण मिले। इन कार्य हेतु चतुर यंत्रणाएँ और विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है जो विधायकों पर तर्किक दबाव से प्रभाव डालकर उन्हें महसूस कराते हैं कि अमुक विधि या अमुक धारा अमुक दृष्टि से सार्वजनिक हित के अनुकूल या प्रतिकूल है। दबाव समूहों के कार्यकर्ता विधायकों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और हर सम्भव उपाय से प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। कनिश्टन में जहाँ सैकड़ों दान समूह कार्यरत हैं, सम्भवतः एक हजार से अधिक प्रक्रिया काँग्रेस के प्रत्येक सत्र में सक्रिय लाइबेरीस्ट (Active Lobbyists) के रूप में मौजूद रहते हैं।¹ यह तो केवल रजिस्टर्ड लाइबेरीस्ट की संख्या है और जो कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं हैं उन लाइबेरीस्टों की गतिविधियाँ भी कम नहीं रहती हैं।

मुख्य कार्यपालिका पर दबाव (Pressure on Chief Executive)—बहुत उच्च या महाकायदेशी उद्देश्य से प्रति राजनीतिक समूह सीधे मुख्य कार्यपालिका पर दबाव डालने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भारत में राजनीतिक औद्योगिक धारण, व्यावसायिक समूह जैसे—बिड़ला समूह, दलमिया समूह, अम्बानी समूह, रिलायन्स समूह, बाँबे इत्यादि समूह, द्रष्टा समूह किसी नीति-विशेष के पक्ष में प्रचारमन्त्री को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति को प्रभावित करने के प्रयास किये जाते हैं।² वास्तव में कार्यपालिका पर विभिन्न प्रकार के दबाव बने रहते हैं और दृढ़ निश्चयी तथा शक्तिशाली प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इन दबावों के साथ सन्तुलन बनाये रखता है। आखिर मुख्य कार्यपालिका राजनीतिक ही होते हैं, उन्हें चुनावों का सामना करना पड़ता है अतः वे दल के प्रभावशाली व्यक्तियों, देश के सम्पर्क गुरु, गतिगण्डल के अपने वरिष्ठ सचिवों से अप्रभावित नहीं रह पाते। अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव हाइट हाउस स्टाफ के माध्यम से डाला जाता है। दान समूह राष्ट्रपति की पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों तक पहुँच जाते हैं। क्लेक्लिन डी. रूजवेल्ट यहाँ अपने पति से उदार दबाव समूहों के हितों (Concerns of Liberal Groups) की चर्चा किया करती थीं और सक्रिय रूप से उनके हितों की वकालत करती थीं। इसी प्रकार की दबाव नीति भारतीय प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्रधानमंत्री का प्रारंभिक राष्ट्रपति पर लागू होती है।

जब दबाव समूह सम्पर्कों के माध्यम से कार्यपालिका को प्रभावित नहीं कर पाते हैं तो वे प्रचार, प्रदर्शन, हड़ताल, धेरा, विरोधी दलों का आश्रय आदि तकनीकी के माध्यम से कार्यपालिका पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। उनका उद्देश्य दबावकारी अज्ञानत कावचण पैदा कर देना होता है जिससे कार्यपालिका यह सोचने पर विवरा हो जाये कि कहीं घटनाएँ तुल न पकड़ जायें और उसका या उसके राजनीतिक दल का भविष्य अन्धकार में न पड़ जाये अथवा उसके राजनीतिक हितों का आपात न पहुँचे। कार्यपालिका को किसी कानून को लागू करने के लिए शक्ति को उपयोगितापूर्ण कर्मचारियों आदि के तापों की भाँगी के आगे झुकना पड़ता है। कई बार दबाव समूह जब अन्य दबावकारी तत्वों से संयोग कर लेते हैं तो कार्यपालिका के आगे कठिन परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं।

दबाव समूह और कर्मचारी-तन्त्र (Pressure Groups and Bureaucracy)—प्रत्येक व्यवस्था में सरकारी कार्य अधिकारिक जटिल होते जा रहे हैं। विस्तृत विधान अथवा प्रदत्त व्यवस्थापन (Detailed Legislation or Delegated Legislation) कम व्यावहारिक (Less Practicable) बन गया है अतः विधान मण्डल कानूनों में विस्तार के विस्तार क्षेत्र प्रशासकीय विवेक पर छोड़ देते हैं और दबाव समूहों के लिए सरकार को प्रभावित करने की प्रभावित का मन-गढ़ा आग्रहण दे डालते हैं। प्रदत्त विधान ने नैकरशाही को इतना समर्थन बना दिया है कि दबाव या दान समूह उसे अपने प्रभाव में लेकर अपने हितों का साराण करते हैं। भारत में और ब्रिटेन में दबाव समूह नैकरशाही को प्रभावित करने के लिए सभी नीतियों अपनाते हैं। समुक्त राज्य अमेरिका में स्वतन्त्र नियामकीय आयोग (Independent Regulatory Commissions) सत्ता सम्पन्न हैं और उनके निर्णयों में कानून जैसी शक्ति और प्रभाव होता है। इन आयोगों के सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव समूह सधन प्रयास करते हैं। विभिन्न कर्मचारी सधन भी एक प्रकार के दबाव समूह ही होते हैं।

राज्य तक पहुँचाने का मार्ग प्रदान करते हैं और शासन-व्यवस्था को जनता के प्रति प्रतिक्रियाशील (Responsive) बनाते हैं। दबाव समूह वास्तव में राजनीतिक क्रांतिकरण के यंत्र हैं जिनके आधार पर नीतिनिर्माता अपनी नीतियों का निर्माण और मूल्यांकन कर सकते हैं।

भारत में दबाव समूह : विकास और विशेषतायें

(Pressure Groups in India : Development and Characteristics)

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दबाव-समूह का विनिर्माण मजबूत रहा है। इनका निर्माण ऐसे स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले आरम्भ हो चुका था। 1885 में कांग्रेस को स्थापना ऐसी संस्था के रूप में हुई जो जिसका उद्देश्य राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार से अधिकृत सुविधाएँ प्राप्त करना था। स्वतन्त्रता में इण्डियन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से यह माँग करना था कि भारतीय लोक सेवा में भारतीयों के लिए अवसरों की संख्या बढ़ाई जाए तथा इस सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा को भी बढ़ाया जाए। 1920 में गौंधीजी ने भारत में राजनीति में प्रवेश कर कुर्क तथा क्रिश्चियन वर्ग को संगठित कर कांग्रेस के द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप दिया। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले कुछ श्रमिक संगठनों का निर्माण हो चुका था। उदाहरण के लिए 1880 में मुम्बई में एक ट्रेड यूनियन 'दि बम्बे मिल वर्कर्स एसोसिएशन' के नाम से संगठित हुई। 1918 से श्रमिक आन्दोलन तेजी से शुरू हुआ और केवल एक वर्ष में ही सात ट्रेड यूनियनों को 'बम्बे ट्रेड यूनियन कांग्रेस' निर्माण में गौंधीजी ने विशेष रुचि ली। 1920 में राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रेड यूनियन 'एन इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' के नाम से संगठित हुई जिसके अध्यक्ष कांग्रेस दल के तत्कालीन अध्यक्ष सान्ना सायबान की बनाया गया। 1936 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का संगठन 'एन इण्डिया किसान सभा' के नाम से स्थापित किया गया, जिसे कांग्रेस का निर्देशन तथा समर्थन प्राप्त था। इस संस्था की ओर से जयोंदारी उन्मुक्त तथा भूमि के पुनर्वितरण की माँग की गई।¹

स्वतन्त्रता के बाद भारत में दबाव समूहों की संख्या और उनके प्रभाव क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई। इसका कारण प्रत्यक्ष पदाधिकारी, राजनीतिक समानता, सरकार के कार्य क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता का अन्तिम स्रोत जनता को माना और सरकार के अधिकारों का दिया जाना है। भारतीय संविधान में राजनीतिक सत्ता का अन्तिम स्रोत जनता को माना और सरकार के निर्माण का अधिकार जन-साधारण को प्रदान किया। प्रतिनिधिक शासन-प्रणाली की स्थापना के परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों का अधिकार कमजोर हो गया और व्यावहारिक राजनीति में जन-साधारण के भाग लेने के कारण स्वयं राजनीतिक दलों दल अधिक क्रियाशील हो गए और व्यावहारिक राजनीति में जन-साधारण के भाग लेने के कारण स्वयं राजनीतिक दलों ने विभिन्न वर्गों की हितों के आधार पर संगठित करना आरम्भ कर दिया। फलस्वरूप भारत में व्यावसायिक, श्रमिक, व्यापारिक, जातीय तथा सम्प्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का निर्माण हुआ। रॉबर्ट हल हार्मिन्ग ने भारत में दबाव समूह की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं—

1. भारत में दबाव समूहों का विकास बहुत धीमी गति से हुआ है और जो दबाव समूह विद्यमान हैं वे बहुत कमजोर हैं।
2. कांग्रेस दल के भीतर पाए जाने वाले समूहों ने विभिन्न हितों के एजेंड के रूप में कार्य किया है।
3. अधिकतर भारतीयों में राजनीतिक समता निम्न स्तर की है। उनके मतानुसार सरकारी पदाधिकारी सामान्यतः अनुराधायी और भ्रष्ट हैं। दूसरी ओर सरकारी पदाधिकारियों में दबाव-समूहों की गतिविधियों के प्रति सदैव आशंका बनी रहती है।

भारत में दबाव समूहों के विभिन्न प्रकार और उनका प्रभाव

(Kinds of Pressure Groups in India and their Influence)

पारम्पर्य देतो की नीति स्वतन्त्र भारत में आर्थिक हितों के अनुसार दबाव समूहों के चार प्रकार हैं—

1. व्यावसायिक—जैसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल सभा। इस क्षेत्र में इनकी सबसे बड़ी संस्था है। इसके अतिरिक्त अलग-अलग व्यवसायों की विभिन्न राज्यों में सैकड़ों संस्थाएँ हैं जिनका अपने-अपने व्यवसाय से सम्बन्ध है।
2. श्रमिक—जैसे अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस आदि।
3. कृषि सम्बन्धी—जैसे भारत में कुर्क संगठन, किसान सभा, किसान पंचायत, समुक्त किसान सभा, किसान मजदूर यूनियन आदि।
4. राज्य कर्मचारी संघ—जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी आदि विभिन्न व्यवसायों और कार्यों से सम्बद्ध जैसे—मेट्रिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया, अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस, इण्डियन लॉ इन्स्टीट्यूट, अखिल भारतीय शिक्षा संस्था सभा, अखिल भारतीय यूनिवर्सिटीज एण्ड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, युवा कांग्रेस, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ, सिविल सर्विस एसोसिएशन आदि।

ये समूह प्रायः सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में दो और विशेष प्रकार के समूहों का संगठन हुआ है जो अन्यत्र नहीं हैं—1. धर्म, जाति अथवा सम्प्रदाय सम्बन्धीजैसे अकाली दल, परिगणित जाति सभ, वैश्य महासभा आदि। 2. गांधीवाद और सर्वोदयो विचारों से प्रेरित सम्पूर्ण जैसे—गांधी ज्ञानि प्रतिष्ठान, सर्वसेवा सभ, अखिल भारतीय हरिजन सेवक-सभ, गांधी स्मारक निधि अखिल भारतीय चर्खा सभ आदि। ये सम्पूर्ण साधारण दबाव समूहों से इस हद तक भिन्न हैं कि वे राजनीतिक जोड़-तोड़ में विश्वास नहीं रखती और दसगत राजनीति से अलग रहकर सामंशिक के साथ अपना कार्य करती हैं। इसीलिए इनके साधनों को देखते हुए इनका नैतिक प्रभाव दूसरे समूहों को अपेक्षा कहीं अधिक होता है। रॉबर्ट एल. हार्टवे ने हित-समूहों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया है—1. सामुदायिक सभ (Communal Association), 2. कृषि एवं ग्रामीण समूह (Agriculture and Rural Groups), 3. श्रमिक सभ (Labour Unions), 4. विद्यार्थी संगठन (Students Organisations) एवं 5. व्यावसायिक समूह (Business Groups)। इनके अतिरिक्त गांधीवादी जैसे कुछ विशिष्ट समूहों को अलग में लिया जा सकता है। एक अन्य दृष्टि से भारत में विद्यमान दबाव समूहों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) भारत में परम्परागत दबाव समूहों (Traditional Pressure Groups) में जाति एवं धर्म पर आधारित दबाव समूहों का उल्लेख किया गया है जो मूलतः सामाजिक-सांस्कृतिक सम्प्रदाय हैं। यद्यपि राजनीति में इनकी भूमिका नगण्य होनी चाहिए, तथापि भारत के सार्वजनिक जीवन में धर्म और जाति के तत्वों का विशिष्ट स्थान है और इन पर आधारित दबाव समूह अनेक अवसरों पर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक दबाव समूहों के रूप में विगत वर्षों में भारत-यौन मैत्री समाज, अखिल भारतीय ज्ञानि परिषद आदि सांस्कृतिक संगठन विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। जातीय एवं धार्मिक दबाव समूहों में उल्लेखनीय हैं—भारतीय ईसाइयों के अखिल भारतीय सम्मेलन, ऑक्स-भारतीय एसोसिएशन, सनातन धर्म दक्षिणी सभ, आर्य प्रतिनिधि सभ, भारतीय एंग्लोसिएशन, हरिजन सेवक सभ, जाट सभ, वैश्य महासभा, बंगाली समाज आदि। ये सभी दबाव एवं हित समूह अपनी जाति और सदस्यों के हितों की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा देश की राजनीति और चुनाव अभियानों में महत्त्व रखते हैं। कुछ राजनीतिक दलों तथा—अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कडगम, मुस्लिम मजलिस, जमीयत उलउलामा-ए-हिन्द, इस्लामिक दल, परिगणित जाति सभ आदि का उद्देश्य मुख्यतः दबाव समूह के रूप में ही हुआ था और आज अपने स्वरूप और कार्यों की दृष्टि से वे कमतरता में राजनीतिक दल और अधिक सीमा तक दबाव समूह माने जा सकते हैं। शिवसेना भी जातीयता पर आधारित एक दबाव-समूह ही है। अनुसूचित जातियों के समूह अपने हितों की रक्षा के लिए राजन पर निरन्तर दबाव डालते रहते हैं। उनका यह प्रयत्न रहता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकधिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पद प्राप्त हों। महाछत्र में एक शक्तिशाली दबाव समूह के रूप में 'दलित-सेवा' का उद्भव हुआ है।

(ख) भारत में आधुनिक दबाव समूहों (Modern Pressure Groups) में व्यावसायिक एवं औद्योगिक दबाव समूह, श्रमिक सभ, किसान संगठन, शिक्षित वर्ग के संगठन आदि तो हैं ही, गांधीवादी संगठन भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। भारत में ये दबाव समूह व्यवस्थान सनितियों को प्रभावित करते हैं। ये दबाव समूह मन्त्रिमण्डलों के निर्णय तक बढ़ल देने की क्षमता रखते हैं।

प्रमुख दबाव समूह—भारत में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दबाव समूह कार्यरत हैं—

(1) व्यापारिक दबाव समूह (Trade Pressure Group)

भारत में अनेक व्यावसायिक समूह दबाव समूह कार्यरत हैं, जिनमें देश के व्यापार और व्यवसाय को केन्द्रित कर रखा है। ये परिवार राजनीतिक दलों को बन्दा देकर, सार्वजनिक क्षेत्रों में दान देकर औद्योगिक तथा शिक्षण संस्थाओं में उचित वेतन देने पर देकर, समर्थक प्रत्याशियों को निर्वाचन में विजयी बनाकर सार्वजनिक नीति को बदलाने के रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन औद्योगिक समूहों अथवा धर्मों के अतिरिक्त विभिन्न व्यापारिक उद्देश्यों सार्वजनिक नीति को प्रभावित करती हैं, जैसे—भारवादी, जैन, पारसी, दक्षिण भारत में चेन्नैपा आदि। इसके अतिरिक्त अनेक व्यापारिक संगठन हैं जिनमें कुछ तो कर्षों के आधार पर संगठित हैं, जैसे—एम्पलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (Employers Federation of India), बीमा बिल ओनर्स एसोसिएशन (Insurance Bill Owners Association) आदि एवं कुछ धर्म अथवा जाति के आधार पर संगठित हैं जैसे—भारवादी चेम्बर ऑफ कॉमर्स। ये संगठन व्यापारिक दृष्टिकोण में एकरूपता लाने और व्यापार के स्तर की वृद्धि करने में कार्यरत रहते हैं। इन सभी व्यापारिक संगठनों के शीर्ष पर 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री' (Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry) है। इन व्यापारिक दबाव समूहों का सार्वजनिक नीति पर दबाव बना रहता है। सभी क्षेत्रों में निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं पर इन्हीं का नियन्त्रण है। इससे व्यापारिक दृष्टिकोण के प्रचार और प्रसार में कोई बाधा नहीं होती है।

1. जातिवाद अथवा जातिगत राजनीति—यद्यपि जातिवाद का तथ्य भारत के सभी राज्यों में प्रभावी है, तदपि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केरल में इसका प्रभाव सर्वाधिक है। मतदान व्यवहार में जातिवाद और जातिगत राजनीति का प्रभाव प्रायः उन जातियों से अधिक पाया जाता है जो किसी क्षेत्र में अनेकसंख्य बहुसंख्यक है और जो अपने मतों के बल पर किसी जाति के उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में होती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अल्पसंख्यक जातियों के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है।

2. आर्थिक स्थिति—लोगों की आर्थिक स्थिति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। एक सामान्य निष्कर्ष यह है कि यदि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो प्रायः मतदान शासक दल के पक्ष में होता है अन्यथा मतदान उसके विरुद्ध होता है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है और शासक दल की चेष्टा रहती है कि चुनाव 'अच्छी कृषि' के वर्ष में हो।

3. सत्तारूढ़ दल का आचरण—सत्तारूढ़ दल के आचरण और क्रियाकलापों का मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल यदि जनहित के कार्यों में अधिक रुचि लेता है, लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि व्यवस्था करता है और शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखता है तो मतदान सामान्यतः शासक दल के पक्ष में और विरोधी दलों के विपक्ष में होता है।

4. नेतृत्व—मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक प्रधान तत्व नेतृत्व है। भारत में इस तत्व के आधार पर देश के अब तक चुनाव परिणामों की व्याख्या की जा सकती है। प्रथम तीन आम चुनावों में मुख्यतः प. नेहरू के नेतृत्व के कारण कांग्रेस की मत मिलने, चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की आर्थिक पण्डित इस्मिराई हुई कि कांग्रेस के पास प. नेहरू जैसा कोई चमकदार नेतृत्व नहीं था। 1971, 1972, 1980 के चुनावों में श्रीमती इन्दिरा गांधी के बिलछा और आकर्षक नेतृत्व ने मतदान व्यवहार को कांग्रेस के पक्ष में किया तो 1977 में कांग्रेस इस्मिराई सभी कर्पणिक कुछ अश्विचर कार्यों के कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व की छवि धूमिल हो चुकी थी। सत्तारूढ़ दल जनता पार्टी का नेतृत्व आपसी लड़ाई का शिकार रहा और जनता में विश्वास खो बैठा। दिसम्बर, 1984 के चुनावों में राजीव गांधी के व्यक्तित्व का मतदाताओं पर प्रभाव पड़ा। 1996 एवं 1998 के चुनावों में कांग्रेस (I) की पण्डित में पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व की मुख्य भूमिका रही। उनके नेतृत्व में 'करिगना' के अभाव के कारण वे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सके।

5. राजनीतिक स्थिरता तथा सुदृढ़ सरकार की आवश्यकता—भारतीय मतदाताओं ने अपने मतदान व्यवहार में स्पष्ट कर दिया है कि वे केन्द्र में ऐसी सरकार चाहते हैं जो मजबूत और सक्षम हो, जो एक इकाई की भाँति काम कर सके और देश को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करे, इसके लिए अन्तर्द्वीपीय प्रतिष्ठित अन्वित कर सके। 1977 के पूर्व में चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में मतदान का यही एक प्रमुख कारण रहा है। देश के मतदाताओं की विश्वास रहा है कि देश में शासन सम्हालने योग्य दल केवल कांग्रेस है और इसके पास सुयोग्य नेतृत्व है, जबकि विरोधी दल अपनी फूट का शिकार हैं एवं सुयोग्य नेतृत्व कांग्रेस की तुलना में उनके पास बहुत कम है। जब मार्च, 1977 के चुनावों के समय कुछ प्रमुख विरोधी दल जनता पार्टी के रूप में संयुक्त हो गए तो मतदाताओं को आशा हुई कि अब कांग्रेस का शक्तिमान् विकल्प मौजूद है और इसे अमर देना चाहिए। जनता को विश्वास हो गया कि जनता पार्टी स्थायी और कुशल शासन दे सकेगी, अब कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी को सत्ता प्रदान की गई, लेकिन जब जनता पार्टी फूट के कारण देश के पतों की तरह बिखर गई और देश में राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता छा गई तो मतदाताओं ने पुनः कांग्रेस का और श्रीमती गांधी को सत्ता में स्थान दे दिया। 1984 में कांग्रेस (I) की विराट् विजय के पीछे यही तथ्य उत्तरदायी रहा। 1991 में कांग्रेस (I) की विजय में स्थिरता का तत्व प्रमुख था, लेकिन 1996 एवं 1998, 1999 तथा 2004 में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्रदान नहीं करने तथा उन्हें अपने बन्धुवों पर सरकार बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करके भारतीय मतदाताओं ने पूर्व की तुलना में विपरीत व्यवहार किया। उन्होंने 'सर्वोद राजनीति' के पक्ष में मतदान किया। मतदाताओं का व्यवहार पूर्व की तुलना में अलग ही दिखाई देता है।

6. मुद्र में सफलता-असफलता—मुद्र में सफलता-असफलता मतदान व्यवहार को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है। 1962 में चीन के द्वारा पण्डित को मतदाता भूले नहीं और 1967 में कांग्रेस पर इसका विनोद प्रभाव पड़ा। 1971 में कांग्रेस सरकार की यौद्धिक सफलता ने 1972 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सफलता को अतिरिक्त बना दिया।

7. श्रेष्ठवाद की प्रवृत्ति—भारतीय राजनीति के कुछ क्षेत्रों में श्रेष्ठवाद मतदान को बहुत कुछ प्रभावित करता रहा है। उदाहरणार्थ कई अवसरों पर पंजाब में अकाली दल ने, तमिलनाडु में डी. एम. के, अन्ना द्रमुक तथा तमिल मनीष कांग्रेस ने, बिहार में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, पश्चिमी बंगाल में माक्सवर्तियों ने श्रेष्ठवाद के आधार पर ही सफलता प्राप्त की है। आन्ध्र प्रदेश में तेलंगूदेशम् असम में असम गण परिषद मेघालय और नागालैण्ड में भी श्रेष्ठवाद दलों ने उन्मुखीय सफलता प्राप्त की है।

8. दलीय विचारधारा, कार्यक्रम और नीति—डॉ. इब्राल नरयण का यह निष्कर्ष ठीक ही है कि भारतीय मतदाताओं का सामान्य वर्ग कम तथा प्रबुद्ध वर्ग राजनीतिक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति से अधिक प्रभावित होता है। चुनाव से पूर्व विविध दलों के जो चुनावी घोषणापत्र प्रकाशित होते हैं वे प्रायः जनसंख्या के समझने की

बलु न होकर केवल पड़े निचे एवं प्रबुद्ध वर्ग के समझने की बातें होते हैं। उदाहरणार्थ, विविध दलों के कार्यक्रमों में सम्मिलित 'समाजवादी समाज की स्थापना', 'धर्म निरोधता', 'लोकतन्त्र एवं समाजवाद के प्रति आस्था', 'गौधीवादी सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता', 'अर्थतन्त्र एवं हासन का विकेन्द्रीकरण' तथा 'अन्योदय' आदि ऐसी सन्देशवाचक हैं, जिन्हें जनता नहीं, बल्कि प्रबुद्ध वर्ग के लोग ही समझ सकते हैं। इसका परिणाम होता है कि दलों की विचारधारा, नीति एवं उनके कार्यक्रम केवल प्रबुद्ध वर्ग के मतदान के व्यवहार को प्रभावित करते हैं तथा उनका प्रभाव जनसाधारण के मतदान व्यवहार पर नहीं पड़ता।

9. भाषाई प्रेम या लगाव—भारत में भाषा का तत्त्व मतदान व्यवहार को प्रभावित करता रहा है। उदाहरणार्थ 1967 और 1981 के चुनावों में तमिलनाडु में द्रमुक को जो भारी सफलता मिली उसके मूल में हिन्दी निरोध का हाथ था। 1977 में लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का मुख्य कारण यह रहा कि दक्षिण भारत के मतदाता जनता पार्टी की भाषा-नीति के सम्बन्ध में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और उन्हें आशंका थी कि वहाँ उन पर हिन्दी बोपने का प्रयत्न न किया जाये। बाद के संसदीय तथा राज्य विधानसभा के चुनावों में तमिलनाडु में भाषाई तत्त्व नगण्य हो रहा और अब यह कोई प्रमुख मुद्दा नहीं रहा है।

10. सामन्तशाही का प्रभाव—मतदान व्यवहार पर सामन्तशाही व्यवस्था अथवा राज-महाराजधर्म और जागीरदारी का प्रभाव रहा है किन्तु 1971 के संसदीय चुनाव के पश्चात् क्रमशः कम होया गया। अब सामन्तशाही का प्रभाव सन्तप्त हो गया है। मध्यप्रदेश के सिन्धिया राजघराने को इसका अन्त्यवाद माना जा सकता है जिसके किसी सदस्य को अब एक चुनावों में राजस्व का सामना नहीं करना पड़ा।

11. राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप—विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्दर के क्रियाकलाप मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, कांग्रेस को पहले तीन आम चुनावों में अधिक मत प्राप्ति के मूल में एक मुख्य कारण यह रहा है कि उसने स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

12. आर्थिक साधन—आर्थिक साधन मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जनवरी, 1980 के चुनावों में इन्दिरा गाँधी को अधिक लोकसत्ता प्राप्त होने का कारण यह रहा है कि दम विपक्ष की तुलना में बहुत अधिक साधन-सम्पन्न था तथा भुगतित और व्यापक स्तर पर अपना चुनाव अभियान चला सका, लेकिन 1977 के चुनावों में स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक साधन सम्पन्नता चुनावों को निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं कर पाती। दिसम्बर, 1984 के चुनावों में कांग्रेस (I) की अनुसूचित साधन-सम्पन्नता ने उसकी विजय को आसान बना दिया। सन् 1989 और 1991, 1998, 1999 में भाजपा की सफलता के पीछे उसके प्रभु साधन ही थे। 2004 के संसदीय चुनावों में अन्य दलों की तुलना में कांग्रेस (I) के पास सोनिया गांधी का प्रभावी नेतृत्व तथा भारतीय जनता पार्टी के पास साधनों की प्रचुरता थी।

13. दल अंगदा प्रथाशीली की जीत की सम्भावना—कौनसा राजनीतिक दल अपना कौनसा प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगा, इसकी सम्भावना मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। जिसके पक्ष में चुनाव-लहर बह रही हो उसे प्रायः लोग मत देते हैं ताकि उनका दल विजय न जाए। सन् 1971 के बाद के सभी संसदीय निर्वाचनों में इस तथ्य को देखा जा सकता है।

14. धर्म और साम्प्रदायिकता—धर्म और साम्प्रदायिकता दलों की सफलता का महत्वपूर्ण कारक रहा है। 1989, 1991, 1996, 1998 तथा 1999 में भाजपा की सफलता में धर्म और साम्प्रदायिकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन वर्षों ही आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 'हिन्दू कार्ड' का सफलता के साथ प्रयोग कर अपनी शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि की है।

वर्तमान राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसी धारणा व्याप्त है कि भारत की जनता अपने मतदाधिकार का प्रयोग औचित्य अथवा विवेक के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि वह अज्ञानता, गरीबी जातिगत द्वेष धर्मान्धता आदि की शिकार है लेकिन प्रथम आम चुनाव से लेकर अब तक भारतीय जनता का जो मतदान व्यवहार रहा है उससे इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि उपरोक्त भ्रामक मत केवल उन्हीं लोगों का है जो भारतीय जनता के मन-मस्तिष्क को नहीं समझते, जिन्हें भारत के मतदाताओं के चरित्र एवं चिन्तन का बोध नहीं है। अभी तक भारतीय मतदाताओं ने अपने मतदान में जिस विवेक, सूझबूझ और कुशलता का परिचय दिया है, और कतिपय अपवादों को छोड़कर अनुशासन-प्रियता प्रदर्शित की है और गलाधिकार को कोमत समझी है इससे भारत में संसदीय लोकतन्त्र का भविष्य सुरक्षित है।

राजनीतिक दल और नेता जातिवाद और जातीय राजनीति को हेम मानते हैं, किन्तु आन्तरिक रूप से सभी दल और नेता जातीय आधार पर अपने दल और दलीय प्रत्याशियों के लिए समर्पण माँगते हैं। यही नहीं दलीय प्रत्याशियों का चयन जातीय आधार पर ही किया जाता है, यही तक कि सरकार निर्माण प्रक्रिया भी जातीय-प्रभाव से मुक्त नहीं रहती।¹ भारत की राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि अशिक्षित और/या छत्र व्यक्ति जातिगत प्रभाव के कथों पर चढ़कर विधानसभाओं और संसद में प्रवेश करते हैं तथा जातिवादी राजनीति के बल पर मन्त्री-पद हाथिया लेते हैं। जातियों में प्रतिद्वन्द्विता रहती है और प्रशासन जातिवाद से प्रभावित रहता है।

जाति का राजनीतिक स्वरूप²—जाति व्यवस्था और राजनीति में अन्तःक्रिया (Interaction between Caste and Politics) के सन्दर्भ में डॉ. रजनी कोठारी ने जाति-प्रश्न के तीन रूप प्रस्तुत किए हैं—

(क) लौकिक पक्ष (The Secular Aspect)—जाति-प्रश्न के तथ्यों पर सबका ध्यान गया है, नीते—जाति के अन्दर विवाद, रीति-रिवाजों में जाति की पुष्कट इकाई को बनाये रखने का प्रयत्न, लेकिन इसकी उपेक्षा कर दी जाती है कि जातियों में आपस में प्रतिद्वन्द्विता रहती है और वे लगातार अपनी प्रतिष्ठा और पद बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। जाति के लौकिक संगठन के दो रूप हैं—एक शासकीय रूप यानी जाति और गाँव की पंचायत और चौधराहट, दूसरा रूप राजनीतिक या यानी जाति की आन्तरिक गुटबन्दी और अन्य जातियों से गठजोड़ और प्रतिद्वन्द्विता। इन संगठनों का बलवर्धन या बलहास इस बात पर निर्भर था कि स्थानीय नेताओं के समाज की केन्द्रस्थ सत्ता में कैसे सम्बन्ध दे। धर्म, व्यवसाय और प्रदेश के आधार पर जातियों की स्थिति बनती या बिगड़ती थी। अब भी इनका महत्व है, यद्यपि सन्दर्भ बदल गये हैं। जाति या सम्प्रदाय को किसी राजा से सम्बन्ध रखना पड़ता था और स्थानीय मामलों का प्रबन्ध जाति या गाँव की पंचायत स्वयं करती थी। अब राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार और जातीय पंचायतों की बजाय स्थानीय और प्रांतीय विधान सभाएँ हैं। यह परिवर्तन एक साथ नहीं बल्कि क्रमशः हुआ है।

(ख) एकीकरण पक्ष (The Integration Aspect)—जाति का दूसरा पहलू एकीकरण का अर्थात् व्यक्ति को समाज से अलग करने का है। जाति जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का लगाव पैदा हो जाता है और आपस में एक-दूसरे से बंधा रहता है। व्यक्ति का लगाव और निष्ठा अपने छोटे-से समूह, बिरादरी या जाति में रहता है, किन्तु इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि बड़ी या उच्चतर निष्ठानों की प्रेरणा व्यक्ति को जातिगत ढाँचे से ही प्राप्त होती है। एक लोकतन्त्रीय राष्ट्र के निर्माण में जाति-प्रश्न का यह प्रभाव नकाराज्य नहीं किया जाना चाहिए। लोकतन्त्र के अन्दर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्विता होती है, इससे विभिन्न समूहों या जातियों में एक-दूसरे से मिलने और गठबन्धन की प्रेरणा होती है। भारत की प्रवृत्ति हमेशा अनेकता में एकता को प्राप्त करने की रही है और आज लोकतन्त्रीय राजनीति में इस पर बहुत बल दिया जाता है।

(ग) चेतना पक्ष (The Consciousness Aspect)—जाति-प्रश्न का तीसरा तत्व चेतना बोध है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के परिवर्तन के परिणामस्वरूप जाति विशेष की स्थिति बदलती है। क्षेत्रीय वर्ग के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियों ने इस वर्ग का दावा किया है। कुछ जातियों ने इस प्रकार ब्राह्मण पद का दावा किया है। इसमें कम आकर्षण वैश्य वर्ग का है। एक ओर जाति किसी वर्ग से जुड़ी रहती है और दूसरी ओर किसी व्यवसाय मत या रीति-रिवाज से। सामाजिक व्यवहार में अलग-अलग स्तर पर विभिन्न रूप धारण करने के कारण जाति-व्यवस्था में होच और परिवर्तनशीलता आ जाती है।

समाज में उर्ध्वगमिता की इच्छा के अनेक रूप हैं। एक प्रवृत्ति ब्राह्मणीकरण या सन्स्कृतिकरण की है और दूसरी प्रवृत्ति पाश्चात्यीकरण और लौकिकीकरण की। आर्थिक उन्नति, राजनीतिक एकता और बुद्धिवाद की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से अक्सर ब्राह्मण जातियाँ ब्राह्मणों की नकल करने की प्रवृत्ति छोड़ देती हैं और अन्य अबाह्मण जातियों से मिलकर राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करने और अपनी स्थिति सुधारने की चेष्टा करती हैं। इसके अलावा कभी-कभी जाति अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए अपना सामान्य पौराणिक पुरुषों से जोड़ने का प्रयत्न करती है जैसे—गुजरात के पाटीदार, बंगाल के महिष्य और राजस्थान के जाट आदि। कुछ हलाकों में जहाँ ब्राह्मणों ने आपुनिकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व नहीं किया, वहाँ अधिकतर सीधे कुछ शक्तिशाली कृषक जातियों के हाथ में आए, इसलिए वहाँ ब्राह्मणीकरण या ब्राह्मणवाद की जरूरत नहीं पड़ी और यह जातियाँ सीधे आपुनिक राजनीति में भाग लेने लगी और इन्होंने समाज में उच्च स्थिति प्राप्त की। आन्ध्र प्रदेश और बिहार इसके उदाहरण हैं। यहाँ राजनीति जातियों की गुटबन्दी या गठजोड़ पर आधारित है। सम्मतिकरण की प्रवृत्ति कुछ सामाजिक तनाव और अस्थिरता उत्पन्न करती है, जैसे—बुद्धी

और नीचे गीरे या यूरोपीय लोगों की नकल करते हुए भी मन में उनके प्रति विरोध, ईर्ष्या या नफरत का भाव रखते हैं उसी प्रकार के भाव छोटी जातियों ब्राह्मणों के प्रति रखती हैं। नीची जातियों के आगे बढ़ने की क्रिया जारी रहती है और यह हिन्दू समाज की शक्ति का स्रोत है। आगे बढ़ने में सफलता, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र पर निर्भर होता है। वास्तव में हिन्दू समाज में लौकिक शक्ति के आधार पर जातियों की स्थिति ठठती और गिरती है इस प्रकार उनमें परिवर्तनशीलता रहती है।

जाति और राजनीति में अन्तर्क्रिया के तीन चरण—जाति का राजनीतिक रूप दर्शाने के बाद डॉ. राजनी काटा ने जाति और राजनीति में अन्तर्क्रिया के तीन चरणों (Three Stages) का वर्णन कर यह बताया है कि किस प्रकार पुराना समाज नई राजनीतिक व्यवस्था के कठोर आगा। इसके विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं—

प्रथम चरण—प्रथम शक्ति और प्रभाव की स्पर्धा एवं समाज की प्रतिष्ठा जमी हुई जातियों (Entrenched Castes) तक सीमित रही। शुरु में नई शिक्षा का लाभ थोड़ा-सो बुद्धिजीवी जातियों के लोगों ने उठाया। जहाँ नई शिक्षा और उससे प्राप्ति होने वाली पद प्रतिष्ठा केवल एक जाति या उपजाति तक सीमित रहा, वहाँ अन्य जातियों में जो पहले से समाज में अपना प्रभावपूर्ण स्थान रखती थी, उसके प्रति ईर्ष्या पैदा हुई और इन ऊँची जातियों ने अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन बना लिया। इससे दो उंची जातियों के मध्य प्रतिद्वन्द्विता प्रारम्भ हुई। चेन्नई और मद्रास में ब्राह्मण-अन्नद्वारा, राजस्थान में राजपूत-जाट, गुजरात में बनिवास-ब्राह्मण-पट्टादार, आन्ध्र में कम्मा-रेड्डो और केरल में एरवा-नमर इन्ड इसके उदाहरण हैं। इस क्रिया में अक्सर एक जाति की प्रधानता प्राप्त कर लेने पर दूसरे से उसके इन्ड खदे हो जाते हैं जैसे—गुजरात में पाटीदार क्षत्रिय और मराठवाड़े में मराठा-महार इन्ड। इन इन्डों के परिणामस्वरूप नए और पेशेदार गठबन्धन बन रहे हैं।

द्वितीय चरण—इस चरण में पद और लाभ के आकांक्षियों का सङ्घा बड़ जाती है और भिन्न जातियों में स्पर्धा के साथ-साथ जाति के मध्य प्रतिस्पर्धी गुट बन जाते हैं जिनमें विभिन्न जातियों का संग्राम आते हैं। अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की सहायता ली जाती है जो अब एक दायरे से बाहर थीं। जाति-व्यवस्था की शक्ति और पद का ढाँचा ज्यादा से ज्यादा जटिल हो जाता है। पारस्परिक आर्थिक सहायता, जैसे—अपने परिवारों को काम-धन्दा या नौकरी दिलाना या विविध में सहायता करना, आश्रय-आश्रित सम्बन्ध तथा जातियों के सप और महासपों का संगठन इस नई व्यवस्था के अंग बन जाते हैं।

जिन क्षेत्रों में जमीन या अन्य आर्थिक आधार पर जातियों में पहले से सम्बन्ध रहता है वहाँ राजनीति को नए जातीय संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। पहले से विद्यमान जाति-गुच्छनों को जो त्यों राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है। दूसरी जातियों के प्रभावशाली लोगों को दल या संगठन में लेने में असमर्थ होती है। नई राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना से जातियों की गुटबन्दी और प्रतिद्वन्द्विता नष्ट-नष्ट रूप से होती है। जिते और प्रान्त की राजनीति में प्रभावशाली जातियों में प्रतिद्वन्द्विता प्रकट होती है, जैसे—आन्ध्र में कम्मा और रेड्डी, गुजरात में पाटीदार और अनजिन, कर्नाटक में लिङ्गयत और चौकन्निगा और मद्रास तथा बिहार में विभिन्न जातियों में राजनीतिक गुटबन्दी। जाति या वर्ग सम्बन्धों के कारण नए संगठन जन्म लेते हैं जिनके कारण नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों तक का प्रभाव बढ़ता है। द्वितीय चरण में, प्रारम्भ में शक्ति और प्रभाव की होड़ थोड़ा-सो ऊँची जातियों तक ही सीमित रही किन्तु धीरे धीरे प्रतिस्पर्धी नेतृत्वों ने अपना गुट मजबूत करने के लिए नीची जातियों को भी राजनीति में खींच लिया। चुनाव में समर्थन प्रदान करने के लिए इन नीची जातियों के लोगों को छोटे राजनीतिक पदों और लाभ में कुछ हिस्सा दिया गया।

तृतीय चरण—इस चरण में जहाँ राजनीतिक गुच्छनों की प्रधानता हुई है तथा जाति-सीत स लगाव कम हुआ, वहाँ दूसरी ओर शिक्षा, नए शिल्प, प्रतिष्ठा के परिर्वर्तित पैमाने और शक्ति-क्षेत्र के कारण समाज में परिवर्तन आया है। जाति की भावना कम पड़ने लगी है। सामाजिक व्यवहार अपनी जाति तक सीमित नहीं रहा। राजनीति में व्यवस्था आई है। नई शिक्षा और नए सामाजिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली नई प्रवृत्तियाँ व्याप्त होने लगी हैं। आपुनिकता का एक आवश्यक तत्व है—विभिन्न क्षेत्रों और व्यक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण। पहले राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक संचार के बाद सामाजिक वर्ग या जाति के अन्दर ही होते थे, अब इन्ध अलग-अलग क्षेत्र बन गया है। राजनीति अभी प्रभावशाली तत्व है, परन्तु अब इसकी आपुनिकता के एक साधन के रूप में माना जाता है। इसे जाति को नष्ट करने या उसका स्थान लेने वाली शक्ति के बजाय नए समाज की स्थापना में सहायक माना जाता है। अब राजनीतिक संस्थाओं का ढाँचा व्यापक होता जा रहा है जिसमें जाति की भावना को नया रूप मिला है और उसका ऐसी-वैसी बन्ना आधार कमजोर हो गया है। दूसरी ओर राजनीतिक प्रवृत्तियों ने नए संगठन और नई निष्ठाओं को जन्म दिया है, जो पुरानी निष्ठाओं का समाप्त

करती है। जाति अब राजनीतिक समर्थन या शक्ति का एक मात्र आधार नहीं रही, यद्यपि राजनीति में इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जाति-प्रथा पर प्रचलित की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा बाद में जाति-भावना का सामंजस्य हुआ और इसने राजनीतिक संगठन में सहायता दी। आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ कि आज के युग में केवल जाति और सम्प्रदाय से काम नहीं चल सकता। जहाँ जाति बड़ी होती है, वहाँ इसमें एकता का अभाव होता है, उसमें जातियों के भेद होते हैं और जब सच्चा छोटी होती है तब तो वह अपने प्रभुत्व पर चुनाव जीत नहीं सकती। फिर भी यदि कोई उम्मीदवार अपनी ही जाति का पक्ष लेता है तो ऐसी स्थिति में दूसरी जातियाँ उसके खिलाफ हो जाती हैं। इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियों का गुट बनाना पड़ता है। इससे विभिन्न जातियों में एकता होती है। राजनीतिक दल की शक्ति तभी बनी रहती है जब समाज के सभी प्रमुख वर्ग अर्थात् सभी जातियों के लोग उसकी समर्थन दें। अस्तु राजनीति में आने के कारण जाति की भावना कमजोर पड़ जाती है और अनेक नई एकतावादी विचारों का उदय होता है।

राज्यों की राजनीति के संदर्भ में जातिवाद और राजनीति पर आलोचकों के विचार—राज्यों की राजनीति जातियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। यद्यपि भारत में जाति-व्यवस्था का प्रभाव एक लम्बे ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल है, तथापि आधुनिक भारतीय राजनीति में इसका प्रभाव बहुत उन्मुक्त रूप से पड़ रहा है। रजनी बोठारी के अनुसार, "राजनीति में जातिवाद और जाति का राजनीतिकरण दोनों प्रवृत्तियाँ एक साथ दिखाई पड़ती हैं।" एक अन्य लेखक के अनुसार जातिवाद भारतीय समाज में उतनी गहराई से बैठ रहा है जितना कि साम्प्रदायिकतावाद, स्थानीयवाद और भाषावाद। रजनी बोठारी के अनुसार जाति के तीन प्रमुख स्वरूप हैं—धर्म-निर्पेक्ष स्वरूप, एकीकरण स्वरूप और चेतनात्मक स्वरूप। तैद्धान्तिक दृष्टि से राजनीति और जाति के संगठनों की तीन स्तरों पर देखा जा सकता है—

(1) प्रजातांत्रिक राजनीति को संगठित करने के लिए जाति एक शक्तिशाली आधार प्रदान करती है। वास्तव में जाति सामाजिक व्यवस्था के संगठन एवं क्रियाकलापों का आधार मानी जाती है। ये जातिगत संगठन प्रभावशाली माध्यम का कार्य करते हैं जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था में निर्वाचन एवं राजनीतिक समर्थन संचालित होता है। रजनी बोठारी ने इसको व्यक्त करते हुए कहा है—“वह राजनीति नहीं है जो जाति पर सवार होती है, बल्कि जाति वह है जो राजनीति पर हावी रहती है।”

(2) जाति ग्रामीण क्षेत्र में रहती क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालती है। रहती क्षेत्रों में क्षेत्रीयता, भाषावाद, वर्ग और ध्वांसवादीक हित जाति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं, किन्तु जातिगत तत्व पूर्णतः शून्यविहीन भी नहीं होते।

(3) जातिगत सम्प्रदाय अन्तरिक रूप से सामाजिक-आर्थिक तत्वों के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में एक सर्वांगीण कटम उठाना उनके लिए असम्भव हो जाता है अतः इसका लाभ राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न जातिगत समूहों के हितों को उभारने के लिए किया जाता है।

चुनावों में जातिवाद का प्रभाव अत्यधिक स्वरूप में रहता है—उम्मीदवार का नामांकन, उसका चुनाव प्रसार और अन्त में मतदान जातिवादी भावनाओं से प्रेरित होता है। उदाहरणार्थ, प्रत्याशी निर्दिष्ट करते समय राजनीतिक दल उम्मीदवार की जाति एवं चुनाव क्षेत्र के लोगों की जाति के मध्य सादर सम्बन्ध स्थापित करने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार जातिगत भावनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाता है अतः क्षेत्र में अरचयजनक गुटबन्दीय बन जाती है। राज्यों के चुनाव प्रचार के समय सगोत्रक जातिवाद का पूरा ध्यान रखते हैं। सामान्य धारणा यह होती है कि जिस जाति या समुदाय का उम्मीदवार है वह उसकी सफलता को तप करेगा। उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को जाति के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं और तदनुसार चुनाव के विरुद्ध बात नहीं की जाती क्योंकि प्रत्याशी उनका भी मत प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आम सभाओं में दिए जाने वाले भाषण जातिवाद से पूरे और जातिगत एकता के समर्थक होते हैं, किन्तु घटने के पीछे वास्तविक चुनाव प्रचार अन्य प्रकार का होता है। मतदाताओं को जातिगत गठबन्धनों की प्रकृति समझाई जाती है और उनकी भावनाओं को इतना उधारा जाता है कि मतदान के समय जातिवादी तत्व अपना निर्णायक प्रभाव डाल सकें। एक सामाजिक अन्वेषणकर्ता ने चुनाव में जाति का अध्ययन करते हुए अपने परिणाम में बतलाया है कि प्रायः मतदान के लिए निम्न दृष्टिकोण सामान्य मतदाताओं द्वारा अपनाए जाते हैं—स्वयं का जाति के लिए मतदान, अपनी जाति के हितों की अधिकतम रक्षा करने वाले दल के लिए मतदान, उस दल के लिए मत जिसका नेता अपना जाति का व्यक्ति है, दूसरी जातियों के द्वारा बर्त्ताव मतदान, अपनी जाति के लिए व्यवस्थापिकाई संरक्षण एवं हित के लिए जाति के नेता की स्वीकृति पर विशेष दल के लिए मतदान। राज्यों की राजनीति में जाति की अग्रगण्य प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं—

(1) जातिवाद व्यक्ति के परोपकारात्मक कार्यों का दृष्टिकोण लिए रहता है। राज्यों के राजनीतिक रंगमंच पर ऐसे अनेक आन्दोलन हुए हैं जो जातिवाद के विरुद्ध प्रारम्भ हुए और अन्त में एक नवीन जाति के रूप में परिणित हो गए। उदाहरणार्थ, दक्षिण में लिगायत और कबीर पंथों और उत्तर में सिक्ख, जिन्होंने ब्राह्मण-हिन्दूवाद के विरुद्ध सिक्खवाद को अपनाया।

(2) राजनीति में ज्यों-ज्यों आपुनिकीकरण और सामाजिकरण होता जा रहा है उसके साथ-साथ जाति का प्रभाव कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न रही है। मोरिस जोन्स ने कहा है कि भारतीयों में ज्यों-ज्यों राष्ट्रोत्थान बढ़ रहा है वहाँ के लोग प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से जातिगत सामंजस्यों में अधिक बढ़ रहे हैं।

(3) राज्यों की राजनीति में जाति ने अपना पारम्परिक स्वरूप बदल दिया है। इसके पीछे शक्ति प्रभुत्वपूर्ण तत्व रही है। इसीलिए राजनीति कोटारो ने उचित ही कहा है, "वह राजनीति नहीं है जो जातिपरस्त हो गई है, बल्कि जाति है जो राजनीति हो गई है।"

(4) आज राज्यों की राजनीति में जातिवादो सिद्धान्त का प्रभुत्व हो गया है। यह प्रभुत्वशाली जातिवादो सिद्धान्त कई स्वरूपों में प्रकट हुआ है। कैरोलिन एम. इल्लियट ने अन्ध में रेडोन और कम्माज के सम्बन्ध में प्रभुत्व जाति राष्ट्र का प्रयोग किया है और सिरमोंकर ने प्राचीन नेतृत्व के सम्बन्ध में इसी सिद्धान्त को उद्धरित किया है। प्रभुत्व जाति आपुनिक भारत में ऐतिहासिक विद्यमान का परिणाम है, जिसमें बढती हुई सदस्यता, पूँजीगत स्रोत आदि ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(5) राजनीति में जाति समुदाय का प्रभाव राजनीतिक निर्णयों पर है। उदाहरणार्थ, 1952 में पदयात्री ने राजगोपालाचारी मन्त्रिमण्डल में उस समय तक सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया जब तक कि बनीदार जाति की माँगें सरकार ने कार्यान्वित करने का वादा नहीं किया।

(6) जाति समुदाय एक संगठन के रूप में राज्यों में सशक्त हो रही है। उदाहरण के लिए, नगर महाजन संगम ने 1956 में एक राजत जनता मन्त्रालय। इसी तरह के अन्य समूह हैं—बनीदार क्षेत्रीय संगम, गुजरात क्षेत्रीय सभा आदि।

(7) जाति को राजनीति में प्राथमिकता देने से नेतृत्व उन लोगों के हाथों में आने लगा है जो जाति की रक्षा कर सकें। इससे जातिगत नेतृत्व में आपुनिकीकरण होने लगा है।

(8) राजनीति में जाति समुदाय दो प्रकार से प्रभाव डालते हैं। कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जैसे—गुजरात एवं राजस्थान के बैरव एवं महाजन और कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो जाति की संख्या के आधार पर राजनीति को प्रभावित करती हैं, जैसे—पंजाब में सिक्ख।

(9) राज्य स्तर पर जातिगत भेद-भाव अनेक अधिकारणों के माध्यम से बनते और फलपते हैं। उदाहरण के लिए, शैक्षणिक संस्थाएँ जाति के होस्टल जाति पंचायतें और जाति-कोष आदि। जातिगत समुदाय या सभाएँ किसी न किसी रूप में राज्यों की राजनीति को निरन्तर प्रभावित करते रहते हैं।

भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव—राजनीति को प्रभावित करने में जातीयता की भूमिका को निम्नप्रमुख रूप से विश्लेषित किया जा सकता है—

1. भारत में सभी निर्वाचनों में जातीयता की भूमिका रही है साथ ही इसने निर्वाचन परिणामों को प्रभावित किया है। यद्यपि 1977, 1980 और 1984 के संसदीय निर्वाचनों में जातिवादी राजनीति को घटका लगा है और इसका प्रभाव नागण्य हो रहा है, तथापि 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के संसदीय चुनावों में इसका प्रभाव बढ़ा है।

2. सन् 1977 के पश्चात् चरणसिंह के नेतृत्व में देश की पिछड़ी जातियों उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में शक्ति-मुँज बनकर सामने आई। जय, अहिर, गुजर, यादव, तोषा और कुर्मी जातियों की राजनीति में पहचान हुई। रामनारायण यादव, मुलादमसिंह यादव, चौधरी देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर इन जातियों के प्रमुख प्रवक्ता बने। वर्तमान में कशीराम, मायावती, मुलादमसिंह यादव, सालूजसाद यादव, रामविलास पासवान, शारद यादव आदि पिछड़ी जातियों के मुख्य नेता हैं।

3. केन्द्र और राज्यों में मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है कि इसमें सभी प्रमुख जातियों का प्रतिनिधित्व हो जाए।

4. प्रशासनिक ढाँचे और उसकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में जातिवादी राजनीति की भूमिका रहती है। अनेक बार जातिगत हितों की पूर्ति करने के लिए प्रशासनिक निर्णय भी लिए जाते हैं।

5. जातीयता से हिंसात्मक घटनाएँ घटित हुई हैं। बिहार की राजनीति इसका ज्वनन्त उदाहरण है। बेन्जो और जरीनावाद की हिंसक घटनाएँ रोंटो खड़े कर देती हैं। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में ऐसी हिंसात्मक घटनाएँ प्रायः घटित होती रहती हैं।

6. आरक्षण की राजनीति ने जातिगत विरोध को बढ़ावा दिया है। गुजरात का आरक्षण विरोधी हिंसक आन्दोलन इसका उदाहरण है। 1990 में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद भी देश में जगह-जगह इससे विरोध में हिंसक घटनाएँ घटित हुई हैं।

7. देश में सभी राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को राजनीति का साधन बनाया है।

भारत की राजनीति में वर्ग
(Politics of Class in India)

भारतीय समाज के वर्गों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है—

2. उच्च वर्ग (Higher Classes)—अगढ़े वर्ग की उच्च वर्ग की राजा दी जाती है। इसमें वाहन, राजनृत, वैश्य, नगर, नदर और वायव्य वर्गों को शामिल किया जाता है। इन 'सर्वोच्च वर्ग' के रूप में जाना जाता है। सामन्तों, जमींदारों, पृथ्वीपति, उद्योगपतियों बड़े किसानों, मध्यम श्रेणी के व्यापारियों और व्यावसायिकों, धार्मिक महानों को इस वर्ग में रखा जाता है। इन वर्गों का अल्प संख्या में होने के बावजूद देश की राजनीति, व्यवसाय, प्रशासन तथा देश के हाताफतों पर इनका प्रभुत्व है। राजनीतिक दलों द्वारा इन वर्गों की पूर्ण - चेतना में कार्य किया जाता रहा है। जब पिछड़े और निम्न वर्गों ने इनके प्रभुत्व को चुनौती देने अपना इनके स्वार्थों पर, धीरे-धीरे करने का प्रयत्न किया तो इस 'अगढ़े वर्ग' ने उन्हें कथक्के हेतु उन पर निर्भर अत्याचारों का कहर बरसाया है।

2. पिछड़े वर्ग (Backward Classes)—ऐस में जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों का है। इन्हें सामान्यतः पिछड़े वर्ग की संज्ञा दी जाती है। यह वर्ग सदियों से उच्च वर्ग के अत्याचारों, उत्पीड़न और शोषण की प्रत्यूतना का शिकार होने के कारण 'पिछड़ा' रहा है। जो श्वेतजात के पर्याप्त भी जारी है। आधे दिन उच्च या तलवर्ग वर्गों के अत्याचारों की प्रत्यूतना की गुंज समस्त राज्य विधानसभाओं और समाचार पत्रों में सुनाई पड़ती है। पिछड़े वर्ग को आर्थिक विपन्नता, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक पिछड़ेपन के साथ ही गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, दलितता, आर्थिक विपन्नता तथा आर्थिक अपावों का सामना भी करना पड़ रहा है। यह वर्ग सामाजिक अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न तथा सामाजिक दलित से हीनता की भावना से ग्रस्त है।

राष्ट्रपति के निम्न अनुच्छेदों में इस वर्ग के उत्थान के लिए प्रावधान निश्चित किये गए हैं। इसी देश में 'सामाजिक और आर्थिक न्याय' की स्थापना की दिशा में आपार भूमि निश्चित हुई है। स्वतंत्रता के पंचपात्र पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं। देश में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। राज्यों द्वारा भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए अनेक अधिनियम प्रारम्भ किये हैं। इन वर्गों के आर्थिक उत्थान और कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। विभिन्न प्रकार के आरक्षणों के माध्यम से इन वर्गों का भागीदारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व और पदोन्नति व्यवस्था लागू करने के प्रयास किये गये हैं। देश की राजनीति में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो इसके लिए पंचपात्री राज सम्प्रदायों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इन वर्गों पर अत्याचारों को रोकने की दिशा में सार्वक कदम उठाये गये हैं जिससे इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और व्यवस्थापिका सभाओं और प्रशासन में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। इन वर्गों की राजनीतिक जागरूकता में अभिवृद्धि हुई है। कतिपय वर्गों में प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व का अभ्युदय हुआ है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर, बाबू जेजुरीबनराव चौधरी, भरणसिंह, कर्पूरी तानुकर जैसे नेताओं ने इन वर्गों को संगठित करने एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना दी है। अर्जुन ने कर्जरीराव मुलगावर्करों कादय सहस्रप्रसन्न कादय सम्प्रदाय पामसान, भाद कादय सुओ भावकादी इन वर्गों प्रमुख नेता हैं। विश्वनाथ प्रतापसिंह भी इस वर्ग के हितों के प्रवक्ता हैं। इन नेताओं ने पिछड़े वर्गों को संगठित करने में योगदान दिया है। इसीसे इन वर्गों में उच्च आत्म-विश्वास और गौरव की भावना का विकास हुआ है। इस वर्ग ने अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। सभी राजनीतिक दल पिछड़े वर्गों में अपना जनधार सार्वक करने के लिए इन वर्गों को अपने पक्ष में करने हेतु प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में डॉ. भीमराव अम्बेडकर को राष्ट्रीय नेता के रूप में सम्मान प्रदान करने और उनके विचारों का प्रचार करने की सोझ सगी हुई है।

साम्प्रदायिकता की राजनीति

(Politics of Communalism)

साम्प्रदायिकता भारतीय राजनीति को प्रमुख समस्या है। यद्यपि संविधान ने भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया है, इसके बावजूद देश में अभी तक धर्म-निरपेक्ष समाज की स्थापना नहीं की जा सकी है।

साम्प्रदायिकता की समस्या के कारण—प्रातः में साम्प्रदायिकता के विकास में तनाव, वोट की राजनीति, साम्प्रदायिक दलों और व्यक्तिगत की भूमिका, बहुसंख्यकों में अविश्वास और घय की मनोवृत्ति, मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन, हिन्दू और

4. धर्मनिरपेक्षता का प्रचार—धर्मनिरपेक्षता का प्रचार लोगों के विचारों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सुलभ संचार माध्यमों का इस्तेमाल धर्म-निरपेक्ष के आदर्शों का प्रचार करने तथा साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय शान्ति को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

5. शिक्षकों की भूमिका—छात्र-छात्राओं के विचारों को प्रभावित करने में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन व्यवसाय से सम्बद्ध रहने वाले को किसी धर्म-निरपेक्षता विरोध या समाज में वैमनस्य पैदा करने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए।

6. राष्ट्रीय एकता को बल देना—भारतीय संस्कृति अथवा इतिहास को परिभाषित करना सरल नहीं है। परस्पर विरोधी धारणाओं वाली ऐतिहासिक घटनाओं से देश में अनेक बार संघर्षों की स्थिति पैदा हुई है। पाठ्य-पुस्तकों में ऐतिहासिक घटनाओं को साम्प्रदायिक जाति पहनाकर देश हित में किया जा सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास की सभी पुस्तकों को पुनः समीक्षा की जाए ताकि उनमें से राष्ट्रीय एकता विरोधी सामग्री को निकाला जा सके।

7. नैतिक शिक्षा—बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें साम्प्रदायिक मान्यताओं और क्षेत्रीय तथा विदेशी निष्ठाओं से दूर रखा जाना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार किए जाएं ताकि बच्चे सभी धर्मों के महानुभावों की जीवनी पढ़ सकें और उनमें सहिष्णुता की भावना पैदा की जा सके।

8. आधार-संहिता—छात्रों के लिए आधार-संहिता तैयार करना सापेक्ष हो सकता है। इस आधार-संहिता को हिंसा और साम्प्रदायिक संघर्ष से दूर रहने के लिए दोसरा मार्ग निर्देशन का समावेश किया जाना चाहिए। छात्र संघों को इस दिशा में अग्रसर देना सर्वोत्तम नीति होगी।

9. राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम—राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकारें गोष्ठियाँ एवं वाद-विवाद समारोह आयोजित कर सकती हैं जिनमें भारत की सांस्कृतिक एकता पर बल दिया जाए।

10. नवयुवकों के लिए कार्यक्रम—नवयुवकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें सभी सम्प्रदायों के नवयुवक भाग लेकर आपसी सहभावना बढ़ा सकें।

11. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा—अल्पसंख्यकों को सरकारों नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और दूसरे। निष्ठाओं तथा संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए दोसरा प्रयासों की जरूरत है।

12. धार्मिक सहिष्णुता के लिए मेल-जोल—गाँवों और मोहल्ला स्तर पर विभिन्न सम्प्रदायों के लोग विशेषकर हिन्दुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे से मिलने-जुलने के लिए तथा उनमें एक-दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसी सम्प्रदाय विरोध के धार्मिक उत्सवों में दूसरे सभी सम्प्रदायों के लोगों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना सापेक्ष हो सकता है।

13. राजनीतिक दलों के लिए आधार संहिता—राजनीतिक दलों के लिए आधार संहिता तैयार कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके कार्यकर्ता विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के बीच वर्तमान मतभेदों को बढ़ाने या आपसी घृणा पैदा करने के लिए कोई काम न करें।

14. धार्मिक स्थलों की सुरक्षा—धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग रोकने के सख्त प्रयास किये जाने चाहिए।

15. अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों को लागू करना—जहाँ तक सम्भव हो अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

16. जिलाधिकारियों की उत्तरदायी बढावा—साम्प्रदायिक दंगे होने की स्थिति में जिलाधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

17. धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध—जबान धर्म-परिवर्तन पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

18. पिछड़ेपन को दूर करना—मुस्लिम लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दोसरा प्रयास किये जाने चाहिए। उनमें शिक्षा का प्रचार भी किया जाना चाहिए और उन्हें परिवार नियोजन के लाभों से अवगत कराते हुए 'मौलित परिवार सुख का आधार' को अपनाने पर बल देना चाहिए।

क्षेत्रवाद

(Regionalism)

क्षेत्रीयता भारतीय राजनीति का प्रमुख निर्धारक तत्व है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। फलस्वरूप लोग भारतीय संघ की अपेक्षा उस क्षेत्र एवं राज्य विशेष को अधिक महत्व देते हैं जिसमें वे रहते हैं। प्रांतीयता और क्षेत्रवाद की इस प्रवृत्ति को समझना करने और सभी को एक 'एक' के प्रति निष्ठावान बनाने की भावना से संविधान द्वारा एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में 'भारतीय नागरिक' होने की अपेक्षा बंगाली, बिहारी,

4 सविधान के 16वें संशोधन द्वारा संसद को ऐसे क़ानून के निर्माण का अधिकार दिया गया, जिसके द्वारा भारत का सम्पूर्ण और अछूत-छात को चुनौती देने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जा सके। साथ ही संसद अपना राज्य विधान-मण्डल के चुनौती में उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि सविधान के प्रति निष्ठा तथा देश की प्रभुमता और अछूत-छात की रक्षा को वे राखें। ऐश्वर्य सर्वोपरिता की धारक शक्ति पञ्चायत के सिद्धांतों के एक अन्य छोट्टे से बर्ग के नेता जयजीतसिंह चौहान के उन प्रयासों के रूप में दिखाई दी जिनके अन्तर्गत उन्होंने विश्व के अनेक देशों का द्रव्य करके स्वयं सिद्धिस्तान के पक्ष में विश्व लोकमत तैयार करने का अतृप्त प्रयास किया था। मुझे धर सोने ने छलितता की गौण प्रवृत्ति को, उत्तर-पूर्व की आदिम जातियों के क्षेत्र में रहने वाले मिजोरम और नागालैण्ड में भी की गई थी। नागालैण्ड में विद्रोही नागा नेता फिनो के नेतृत्व में पृथक्तावादी तत्व 1950 से ही सक्रिय थे, यद्यपि नागालैण्ड क्षेत्र के अधिकांश नागा स्वयं भारत से अलग होने के पक्ष में नहीं थे, फिर भी क्षेत्र की महत्वाकांक्षा 1960 में भारत सरकार और नागा जन-सम्मेलन के बीच हुए सम्झौता के अनुसार 1962 में सविधान के 13वें संशोधन द्वारा नागालैण्ड को भारतीय सभ के एक पूर्ण राज्य का स्तर प्रदान कर दिया गया है।

भारतीय सभ से पृथक्ता को ऐसी माँग लालटेंगा के नेतृत्व में 'मिजो नेशनल फ्रंट' द्वारा भी उठाई गई थी। सन् 1985 में मिजो नेता लालटेंगा और राजीव गांधी के बीच हुए सम्झौते ने मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। मिजोरम में पृथक्तावादी तत्वों ने भड़े पैमाने पर हथियार दत्त दिए। मिजोरम में हुए चुनाव में लालटेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने से इस दल की सरकार बनी। उसने राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कड़े कदम उठाये। इस सबके बावजूद इन क्षेत्रों में पृथक्तावादी तत्व पूर्णतया समाप्त नहीं हुए हैं और अब भी अनेक बार कानून और व्यवस्था को चुनौती देने रहते हैं।

2. अपने लिए पृथक् राज्य की माँग—कुछ क्षेत्रों द्वारा पृथक् राज्य की माँग के आन्दोलन भारतीय राजनीति को उल्लेखित करते रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और पञ्जाब राज्यों की स्थापना मुख्यतः ऐसे ही आन्दोलनों का परिणाम है। असम के कुछ कर्मागारी लोगों ने पृथक् राज्य के लिए आन्दोलन किया। 'असम पीपल' डिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस' के नेतृत्व में गाँव, छाती, जपानिया, मिजोर और उत्तरी कछार के क्षेत्रों में रहने वाले इन लोगों के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना हुई। समय-समय पर पृथक् विदर्भ राज्य और बिहार, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की निम्नलिखित पृथक् प्रान्तीय राज्य की स्थापना की माँग इसी क्षेत्रीयता की धारणा के प्रदर्शन के रूप में रही है। कछार की पहाड़ीयों में रहने वाले भगतिनों की शिकायत है कि असम सरकार के हाथों में उनके हित सुरक्षित नहीं हैं, इस कारण उनकी एक पृथक् राज्य की माँग है। झांखण्ड मुक्ति मोर्चा पृथक् झारखण्ड राज्य की माँग करता रहा है। उत्तराखण्ड की माँग और पञ्जाबी गई है। इसी के परिणाम स्वरूप में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा उत्तरांचल (उत्तराखण्ड) व झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो चुकी है।

3. क्षेत्रीय भाषायी विवाद—भारत में भाषायी दंगे होते रहे हैं। असम और मुम्बई में भी भाषायी आधार पर हुए तो कौलकाता में गैर-भगतिनों के प्रति द्वेष की भावना इसी आधार पर हुई है। क्षेत्रीय भाषायी दंगों में कुछ विचारकों का मत है कि 'क्षेत्रीय भाषा के सम्बन्ध' को इसका मुख्य आधार नहीं माना जा सकता। भाषा तो मात्र एक बहाना है। वास्तव में प्रदेश विरोध का शिष्टित भाग रोजगार पाने में मुश्किल से जमे हुए बाहर वालों से मात खाला है तो उसे बड़ी बेचैनी होती है। वह सोचता है कि वह अपने क्षेत्र में 'बेरोजगार' है जबकि 'बाहर वाले' वहाँ अच्छी नौकरियों पर जमे बैठे हैं। अतः वह 'बाहर वालों' के विरुद्ध संचालन शुरू करता है, जिसका आधार शैक्षिक या तकनीकी योग्यता न होकर भाषा का मानता है, जिसमें वह क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता को अपने साथ ले सकता है। क्षेत्र विरोध के निहित स्वार्थों और बाहर के निहित स्वार्थों के आपसी टकराव इस स्थिति को उत्तेजित करते रहते हैं।

4. अन्तर्राष्ट्रीय विवाद—क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व अन्तर्राष्ट्रीय विवाद है। इस सम्बन्ध में उदाहरण महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद का है। महाराष्ट्र की माँग है कि कर्नाटक राज्य में बेलगाँव शहर, कावा, हलिवान्त एवं सुपर तालुका के मराठी भाषा जिले में एक हजार से ऊपर गाँव और लगभग 10 हजार लोग रहते हैं, उन्हें महाराष्ट्र में मिला दिया जाए तो इसके बदले में कर्नाटक को लगभग सवा दोन लाख जनसंख्या के 260 गाँव महाराष्ट्र से दिलवाया जाए। कर्नाटक महाराष्ट्र की इस माँग से सहमत नहीं है। केन्द्र द्वारा नियुक्त 'महाज-माधोम' ने महाराष्ट्र की माँग के औचित्य को स्वीकार नहीं किया है। इसी कारण यह विवाद आन्दोलनात्मक राजनीति तथा तोड़ फोड़ एवं हिंसा का कारण रहा है जो आज भी अनिर्णित रहा है। दूसरा सीमा विवाद पञ्जाब और हरियाणा के बीच रहा है जो सम्मिलित पञ्जाब के समय से वहीं की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। इस विवाद के समर्थन के लिए 29 जनवरी, 1970 को यह घोषणा की गई थी कि चण्डीगढ़ को पञ्जाब में मिला दिया जाएगा तथा हरियाणा को इस नगर के बदले पाँजिल्ला तहसील के फाँजिल्ला सहित 114 हिन्दी भाषी गाँव तथा अनौहर एवं चण्डीगढ़ के सघोष क्षेत्र के 6 गाँव दे दिए जाएँगे। इस घोषणा में यह कहा गया था कि 5 वर्ष तक केन्द्र-शासित क्षेत्र रहने के बाद चण्डीगढ़ पञ्जाब में शामिल

पर छोड़कर का दुष्प्रभाव रहता रहा है। भाषाई विवाद जो लगने लगे हैं। कुछ राज्यों में भाषा अथवा अन्य आधार पर टुकड़े कर पृथक् राज्य बनाए जाने की माँग उठाई जा रही है। कई वक्तापत्ती और आदिवासी क्षेत्रों में निरक्षरों की शिक्षाओं का चर्चा जा रही है। उड़ीसा तथा बिहार में वहाँ के कुछ दिशा-प्रतिपक्ष तत्वों द्वारा उत्तर भारतीयों, विशेष रूप से पारलौकिकों के खिलाफ जनाया गया आन्दोलन क्षेत्रीयता का उदाहरण है। ऐसे आन्दोलनों को निन्दा करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें हर्षित से दबाना भी ज़रूरी चाहिए। क्षेत्रीयता की आड़ में हिंसा की स्थिति को बदलना सहन नहीं किया जा सकता है।

विगत वर्षों में क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक रूप में अभ्युदय और राष्ट्रीय राजनीति में उनके बढ़ते वर्चस्व ने क्षेत्रीयता को बढ़ावा दिया है। इससे राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों की भूमिका कमजोर हुई है, जैसे देश की समग्र व्यवस्था के लिए शुभ सल्लग नहीं माना जा सकता है। समुक्त मोर्चे के नेता देवेगौड़ा सरकार के गठन और संघर्ष में क्षेत्रीय दलों की निर्णायक भूमिका ने केन्द्र में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति को कमजोर बना दिया। अनवरत क्षेत्रीय दल इस कमीकाम राजनीतिक स्थिति में अपने को बड़ी तक उतारपासी दल से आचरण करने के लिए तैयार कर पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बतावेगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय लोकतन्त्र के लिए यह अत्यन्त सुन्दर स्थिति होगी।

क्षेत्रीयतावाद को रोकने के उपाय—देश में क्षेत्रीयतावाद को रोकने की दिशा में निम्नलिखित उपाय सार्थक बन सकते हैं—

1. सभी उप-सांस्कृतिक क्षेत्रों (Sub-Cultural Regions) में समुचित आर्थिक विकास की प्रभावी नीति पर अमल किया जाए।
2. सभी क्षेत्रों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान आर्थिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ ताकि उनमें असम्यक् ईर्ष्या और आन्दोलन न फैले।
3. नियोजन का साथ पिछड़े और गरीब तबके के साथ-साथ सामान्य जन को अधिकारधक मिले और कुछ ही हाथों तथा कुछ ही क्षेत्रों में धन का संचयन न हो।
4. भाषाई विवादों के समाधान हेतु सभी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी जाए।
5. हिन्दी भाषा प्रचार और विस्तार ऐसे किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे सम्पर्क भाषा (Link Language) के रूप में स्वीकार कर लें।
6. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व हो ताकि क्षेत्रीय घटपटपूर्ण नीतियों का संचयन हो सके।
7. अन्तर्राष्ट्रीय नदी विवादों का शीघ्रान्वेषण हल किया जाये। राष्ट्रीय जल-नीति का निर्माण हो।
8. देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो।
9. शिक्षा में भारतीयता का समावेश हो।
10. क्षेत्रीयतावाद तथा सम्प्रदायिकता से जुड़े राजनीतिक दलों का पूर्ण खंडित किया जाए। उनके ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिए जायें।

पिछड़ा वर्ग तथा दलित आन्दोलन (Backward and Dalit Movements)

जन्म के आधार पर श्रेणीबद्ध समाजमान्यता वर्णाश्रम समाज व्यवस्था का विशेष दलित चेतना का केन्द्र बिन्दु रहा है। दलित चेतना का निर्माण उस ऐतिहासिक परिस्थिति में होता है, जहाँ सामाजिक संरचना दलित समुदाय को एक नियमित स्थान पर स्थापित कर देती है तथा उस नियमित स्थान से मुक्ति की आकांक्षा हो-इस विशिष्ट सामाजिक श्रेणी को चेतना का निर्माण करती है। दलित चेतना जहाँ परम्परागत सामाजिक संरचना का विरोध करती है, वहीं विकल्प के रूप में एक मानवीय समतापरक तथा गतिशील सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखती है। दलितों के बौद्धिक प्रतिबिम्बन में 'मानवीय', 'समता परक', 'गतिशील' आदि उद्बोधन प्रयुक्तता से होते हैं। यानी दलित चेतना और दलितों के आन्दोलन बहुआयामी स्वरूप में यह स्पष्ट संदेश होता है कि परम्परागत वर्ण व्यवस्था वाला समाज आन्तरिक रूप से अमानवीय एवं अन्यायपरक है।

पिछड़े और दलितों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—वर्णाश्रम या जातुर्वर्ण व्यवस्था चार सामाजिक समूहों के एकीकृत संयोग से बनती है। ये चार समूह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जिस जातुर्वर्ण समाज की वर्णना की गई है, उनमें इन्हीं चार सामाजिक श्रेणियों का उल्लेख है जो एक दूसरे से अविभाज्य रूप से संबद्ध हैं तथा एक दूसरे की पूरक हैं। यद्यपि श्रेणी बद्धता जातुर्वर्ण समाज की मौलिक रूपरेखा है, ब्राह्मण सर्वोच्च तथा शूद्र सबसे नीचे, पर इनमें न कोई अछूत है और न ही कोई 'सखुत' है।

इससे स्पष्ट है कि वर्गों के भीतर गैर बराबरी तो है पर अशुद्धता, शुद्धता का प्रावधान नहीं है। अतः एव आदिवासी ही ऐसी दो सामाजिक श्रेणियाँ हैं जो चातुर्य वर्ण व्यवस्था के बाहर हैं। व्यवस्था के बाहर होने मात्र में ही इन दो सामाजिक श्रेणियों में स्वाभाविक एकता उत्पन्न नहीं होती है। हस्तनिष्ठ अतृप्त व्यवस्था से बाहर होने के बावजूद व्यवस्था में बंध रहे तथा आदिवासी हेमोस्टासिक रूप में व्यवस्था से दूर रहे पर इन दोनों में एक और समानता है कि ये दोनों ही सामाजिक श्रेणियों की व्यवस्था की भौतिक उपलब्धियों से वंचित रही है तथा आज भी ये जातियाँ उस पीड़ा को महन कर रही हैं।

दलित चेतना और आन्दोलन—दलित समाज जिन चमत्कारों का शिकार रहा है और जिस तरह हिंसा जन्म ममस्त ज्ञान रूपों का भोगी है। इसके बावजूद इनका अस्तित्व में धने रहना किसी अद्भुत मयोग से कम नहीं है। कुछ भौतिक कारण रहे हैं जिनमें आन्तरिक रूप से सराका होना दलित समाज की प्रवृत्ति रही है। दलित मन में मजबूत शोच से न्याय त्रिप तथा सामाजिक व्यवहार से विद्रोह रहा है और ये स्पष्ट विशेषताएँ दलित चेतना में परिलक्षित होती हैं।

इसके महामत रविदास अम्बेडकर पूर्व के दलित समाज में दलित चेतना के श्रेष्ठतम वाहक रहे हैं। इस महान् दलित विद्रोही को दलितकार करने की कोशिश उनके जीवन काल में की गई थी, उसी प्रकार सन्त रविदास के प्रभाव को कम करने के लिए कोशिश की गई थी। रविदास दलित चेतना के ध्वज वाहक थे। सन्त रविदास रविदास की भाँति ही महात्मा कबीर ने भी जाति-पंथ का विरोध करके दलित और पिछड़ों के रूपान्तरण का महान् कार्य किया था।

इसी प्रकार सन्त नामदेव, यन्त्र पोषा व अन्य सन्तों ने दलितों के उत्थान के लिए काम किया था। इन बहियों के बाद महात्मा ने ज्योति बाबा फूल ने दलितोत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। महात्मा गाँधी ने तो अतृप्तों के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम बनाया था तथा उन्होंने उनका नाम हरिजन रखा। 'हरिजन' का नाम से उन्होंने पत्र भी निकाला।

अम्बेडकर और दलित आन्दोलन—अधुनिक भारत में दलित चेतना का कार्य एव ध्वजान्तर अम्बेडकर के वर्गों में महत्वपूर्ण है। उनके प्रयत्नों से दलित समाज आज कार्यो अच्छी स्थिति में आ गया है। अम्बेडकर ने समाज के माध्यम से दलितों की उन्नति के लिए अनेकानेक मार्ग खोले। भारत का दलितोत्थान आन्दोलन महत्वपूर्ण रूप से सफल माना जा सकता है क्योंकि देश के उच्चतम पद राष्ट्रपति से लेकर पंचायतों में तथा राजकीय सेवाओं में दलितों का महत्वपूर्ण स्थान एवं भूमिका है।

लिंग न्याय हेतु संघर्ष

(Struggle for Gender Justice)

भारत तथा अन्य देशों में पुरुष-प्रधान समाज में स्त्रियों की एक बन्धु मानकर उनके साथ व्यवहार किया है, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विभेदों का सामान्य प्रतिमान नहीं है। भारत में दलित समाज चेतना की उत्पत्ति माध्यम वर्गों के प्रादुर्भाव और उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 57 वर्ष बाद भी अनेक महिला समूहों द्वारा चलता गर महिला उत्थान के बहुतेरे आन्दोलनों के बावजूद पुरुष प्रधान सुदृढ़ है। दलित महिलाओं का जाति और वर्ग-समूह पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है।

महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में आर. पण्डितों का विम्वान अध्ययन किया गया है— (1) उत्पन्न (2) प्रजनन (3) लैंगिकता और (4) बच्चों का सामाजिकरण। भारत के संदर्भ में माक्सवादी और समाजवादियों ने उत्पन्न पर ज़रूरत से ज्यादा बल दिया है। भारत में इन चारों पहलुओं में बहनों का शायद ही जबकि इन्हीं क्षेत्रों में स्त्रियों का मुख्य ठगदायित्व है। पुरुष की सर्वोच्चता जाति, वर्ग, पुरुष-तन्त्र और पुरुष कामुकता से उत्पन्न होती है।

परिवार में स्त्री अपने साम-भूमर बनीं तक कि अपने पति द्वारा दलित की तरह समझी जाती है। स्त्रियों की स्थिति उन सब जातियों और वर्गों के परिवारों की स्त्रियों के बारे में सही है जिन पर आज सामन्तवाद का प्रभाव है या जिनकी जीवन-प्रणाली और मूल्य सम्पन्नी है। गाँवों में नव-धन-हूय लोग ने स्त्रियों पर उच्च शिक्षा प्रदान करने, प्रवसन और नौकरी करने पर प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। सही बात तो यह है कि पुरुषों और उनके द्वारा निर्मित वर्णवर्ण ने स्त्रियों को पक्षीय बना दिया है। स्त्रियों की पुरुषों के साथ समता की खोज समझने की दृष्टि से पुरुष महिला समूहों की भूमिका विधान, सामाजिक आन्दोलन और स्त्री-पुरुष सम्बन्धों का विस्तार यहाँ किया जा रहा है।

समानता की खोज—स्त्री द्वारा पुरुष के साथ समानता की खोज एक सार्वभौमिकता बन चुकी है। ईश माँग के कारण महिला आन्दोलनों, नारीशक्त कार्यक्रमों और समूहों का जन्म हुआ है। नारोपद्र की उत्पत्ति सत्तार में सामाजिक सरचना के रूप में हुई है। पुरुष और स्त्री में असमानताएँ और स्त्रियों के प्रति भेदभाव आदि की कठिनाईयें मनुष्यों में सदा से रही हैं। समानता है। समानता तक स्त्रियों पर की चारदीवारी के भीतर रही है तथा पुरुषों पर वे पूर्ण रूप से निर्भर रही हैं। जब शिक्षित महिलाओं ने घर से बाहर रोजगार करने की आवश्यकता महसूस की तब विगत कुछ वर्षों से माध्यमवर्गीय महिलाओं ने घर से बाहर के कार्यों में अपना वर्षाव बढ़ाया है और महंगाई की मार से खाने में निम्न बर्तन को धन की उठाया है और भारत के विभिन्न रहस्यों में कीमत-वृद्धि विरोधी आन्दोलन शुरू किए हैं। घर के भीतर भी स्त्रियों ने पुरुषों के साथ समानता की माँग की है। जो वस्तु पुरुषों की शक्ति होती है उनकी माँग स्त्रियों ने भी की है जो पुरुषों के निकृष्ट आधिपत्य की अवधारणा का टोका है।

व्यक्ति के रूप में स्त्रियों की पहचान (Women As an Individual Identity)—परिवार में स्त्री की पहचान उसकी भूमिका से परिभाषित की जाती है। उसकी पहचान एक पुत्री, पुत्रवधू, माता, सास, पत्नी आदि के रूप में की जाती है न कि एक व्यक्ति के रूप में। परिवार के बाहर मित्र, सम्बन्धी और अन्य स्वतन्त्र सम्पर्क नहीं है। उसके अन्य मित्र, सम्बन्धी और अन्य सम्पर्क वही हैं जो परिवार के पुरुष सदस्यों के माध्यम से उसे मिले हैं। इन सम्बन्धों के लिए उसकी स्वतन्त्र पसन्द का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए परिवार में स्त्री की प्रस्थिति अधीनस्थ प्रस्थिति है। स्त्रियों की पहचान के कई अस हैं जो उसके परिवार की जातीय और वर्गीय पृष्ठभूमि पर निर्भर हैं।

क्या स्त्री एक व्यक्ति है? न चाहेत हुए भी स्त्री अपने पति की इच्छाओं के सामने हारती है। स्त्री को 'यौन न्याय' या पुरुष के साथ समानता प्राप्त नहीं है। जब स्त्री ने व्यक्ति के रूप में पहचान प्रकट की है, तबको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। "जबल यौन सम्बन्ध" या "वैवाहिक अधिकारों का पुनर्स्थापन" बहुत हद तक स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा है। देहेज उत्पीड़न और दुर्वहन जलाना स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा का रूप है। समुक्त परिवार और अनुलोम विवाह को पुनर्नियोजित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, समुक्त परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पुत्र-वधू को परिवार में "बाहरी" और "नैकर" माना जाता रहा है। परिवार में उसको प्रत्येक सदस्य डॉट-डपट और मर्दान्ता का पात्र समझता है। अनुलोम विवाह का अर्थ है कि अन्तर्जातीय और बहुगोत्र के सन्दर्भ में सड़की के साथ उच्च प्रस्थिति परिवार के सड़के के साथ विवाह किया जाता है। अनुलोम विवाह के कारण हिन्दुओं में सड़के का मूल्य बढ़ गया है और इसीलिए देहेज बड़ी समस्या बन गई है।

सविधान में समानता और धर्म, प्रजाति, जाति और यौन पर आधारित भेद-भाव के विरुद्ध जो भी कहा गया है उसके अतिरिक्त भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद विवाह, सम्पत्ति के उत्तराधिकार, उत्साह, देहेज और बलात्कार आदि के बारे में अनेक कानून पारित किए हैं। भारत में सामाजिक विधान अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। देहेज अधिनियम और बलात्कार कानून पिछले कुछ वर्षों से अदालतों और सार्वजनिक मंचों पर चर्चित रहे हैं। बलात्कार की घटनाएँ निरन्तर हो रही हैं। गरीब और दलित स्त्रियाँ विशेषकर इसका शिकार होती हैं। देहेज उत्पीड़न और यातनाएँ, घर-बर् को जलाना और यतनओं के कारण आत्म-हत्याएँ निरन्तर हो रही हैं। राहों और कस्बों में देहेज उत्पीड़न अधिक है तथा इस यातना की शिकार उच्च जातियों, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की महिलाएँ हैं। अनुलोम विवाह की प्रथा उच्च और उच्च मध्यम जातियों और वर्ग समूहों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अपनी पुत्री के लिए उच्चतर परिवार के सड़के ढूँढ़ने की एक अत्यन्त प्रतियोगिता अभिभावकों में उत्पन्न हो गई है। ऐसे सड़के की शैक्षणिक योग्यता और सफेद-पोश नैकरी के सन्दर्भ में प्रस्थिति उच्च होनी चाहिए।

यद्यपि महिलाएँ पुरुषों से किसी तरह के से कमजोर नहीं हैं। भारत के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया तथा बहुत से सामाजिक कार्य किये। राष्ट्रीय हित में स्त्रियों के योगदान के बावजूद उनका शोषण किया जाता है। स्त्रियों का दमन और शोषण इसलिए होता है क्योंकि वे प्रायः असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं। तकनीकी विकास का महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवार के ससाधनों और अपने रोजगार के अन्य भागों पर उनका अब नियन्त्रण कम है। कृषि, दुग्धशाला विकसित, मछली पालन और घरेलू प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रगति के परिणामस्वरूप महिलाओं की सामान्य प्रस्थिति और आर्थिक हानिता में कमी आई है। घरेलू कार्यों में पुरुष स्त्रियों पर कम निर्भर हो गए हैं। पुरुष और स्त्री के बीच अन्तर और अधिक बढ़ गया है। उदाहरण के लिए पुरुषों और स्त्रियों के बीच अन्तर के प्रमुख क्षेत्र साक्षरता, शिक्षा और प्रशिक्षण, रोजगार, स्त्री नस्लवाद, स्वास्थ्य रहा और चिकित्सा सेवाएँ आदि हैं। स्त्री नस्लवाद विरासत और पितृसत्तात्मकता और पुरुष प्रधान्य की दृढ़ परम्परा के कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई हैं।

समाज सुधार आन्दोलन (Social Reform Movements)—वैदिक काल की स्त्रियों की उत्तम अवस्था से लेकर निरन्तर होता जा रहा पतन जब स्वार्थ, अन्याय और शोषण की पराकृत्य पर पहुँच गया तब इनके विरुद्ध आवाज उठाना स्वाभाविक है। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतीय समाज परिवर्तन के दौर में आने लगा जिसमें अनेक प्रभुत्व सम्पन्न एवं चिन्तनशील लोग स्त्रियों की निम्न स्थिति से चिन्तित रहने लगे एवं उन्होंने उसे केंद्रा ठठाने के विरोध प्रयास किये। यद्यपि इस प्रयास में अंग्रेज सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ था। 1813 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह आदेश दिया था कि वह भारत में सभी वर्गों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करे तथापि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।

1. राजा राममोहन राय—सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। 1823 में उन्होंने ब्रह्म समाज (Brahm Samaj) की स्थापना की तथा इस समाज ने सबसे पहले सती-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार को 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर इसे रोकना पड़ा। राजा

राममोहन राय ने बाल-विवाहों के विरुद्ध एवं स्त्री-शिक्षण के प्रसार के कष्ट में भी आन्दोलन प्रारम्भ किया था और सुधार आन्दोलन की नींव रखी। उन्होंने जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि विधवा-पुनर्विवाह शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। वर्गा में भी दबजपूर्ण वैधव्य की उपस्थिति नहीं है। जब राती-प्रथा जैसे अमानवीय रिवाज के विरुद्ध आन्दोलन बना तो राजा राममोहन राय पूरी शक्ति के साथ साक्षर के साथ रहे और अन्त में राती प्रथा की समाप्ति हुई।

2. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर—राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किए गए कार्यों के ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अनुयायी थे। विधवा समाज को सम्बन्धित कार्यों को विद्यासागर ने प्राथमिकता दी। उन्होंने राजा राममोहन राय की कार्यप्रणाली अपनाई तथा विशिष्ट कार्य दिए। उनके कार्य का मूलोत्पत्ति उनके काम के परिणाम से जाँच जा सकती है। इनका विशिष्ट है कि सुधार का भोदा उठाते आते शैलियों के कार्यों का तत्काल कोई परिणाम दिखाई नहीं पड़ता। जनता में उनके कार्य से स्मृति जागृत हो गई तथा भावों कार्य-कार्यों ने कार्य को निष्ठा आगे बढ़ाया यही कर्माटी विशिष्ट कार्य के मुद्दा-विषय के निमित्त उपयोग में लाई जा सकती हैं। विद्या के क्षेत्र में विद्यासागर विशेष सक्रिय थे। स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ प्रचार उपाय स्पष्ट प्रमाण था। बसकता विद्यापीठालय की प्रथम स्त्री स्नातक धर्मशाला बंगु जैयुता महाविद्यालय की छात्रा थी।

विधवा-विवाह के समर्पण में दिए गए आवेदन-पत्र पर 21,000 हस्ताक्षर करवाए गए थे। विद्यासागर ने जो प्रथम विधवा का पुनर्विवाह करवाया तब अनेक पित्रों ने विवाह प्रसंग पर उपस्थित होकर उम्मेद साधना किया था। 'विधवा पुनर्विवाह में ठाढ़े पुत्रों को बाराही और गुजराती में अनुवाद हुआ था।

उनके अनेक प्रेरित करने की धर्माभिव्यक्तियों ने अपनाई। 1891 में राजीवरो नामक मासिक पत्रिका में एक से अधिक विवाह करने वाले पुत्रों की सूची प्रकाशित की थी तथा उसकी गणना के अनुसार प्रति पुरुष विधवा का औसत 4.5 प्रतिशत का था। विद्यासागर के काल में विवाह का औसत 5.5 था। गणना की श्रुति का स्वीकार करें तो जाना तो कहना ही पड़ता कि इस क्षेत्र में कोई सुधार अवश्य हुआ। अतः यह कहना अविश्वसनीय न होगा कि विधवा स्त्री समस्याओं में विद्यासागर का गन्दन अमूल्य था।

3. बहराम जी मल्लाबारी—बहराम जी मल्लाबारी का नाम बालविवाह की समाप्ति को हल करने से सम्बन्धित है। बाल विवाह के कारण प्रायः बाल-विधवाओं की समस्या पैदा होती है। इस प्रकार बाल-विवाह तथा बाल-शिक्षा के द्वारा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक विधवा द्वारा अपना बालक की हत्या की घटना ने मल्लाबारी के हृदय को झकझो दिया। बहराम जी मल्लाबारी का नाम बाल-विवाह विरोध-विवाह तथा समाजी आराम बालू एवं ऑफ कर्सेट ऑफ ग्लास के साथ जुड़ा हुआ है। उनके शक्ति प्रयासों का स्वीकृत-जागतिक प्रतीक मुम्बई की 'सेवा सदन' नामक संस्था है जो स्त्रियों की विविध समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है।

महादेव गोविन्द रानाडे—रानाडे के कार्यों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता है कि समाज-सुधार तथा स्त्रियों की प्रगति के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय था। भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रभाव से वह पूर्णतः परिचित थे। प्राथमिक काल में युवा बंगाल आन्दोलन अंग्रेजी राज्य का अधानुकरण कर रहा था, किन्तु रानाडे ने तो पश्चिमी सभ्यता के अर्थ अनुकरण के ही पक्ष में थे और न ही पुनरुत्थानवादियों की भीति भात के भूत काल के ही परभावों से। उन्होंने इन दोनों प्रवाहों का सामन्वय करके नई दृष्टि प्रदान की। समाज-सुधार आन्दोलन में उनकी दृढ़ भावना थी कि यदि समाज सुधार व्यवस्थित रूप से करता हो तो गतिशीलता स्वीकृत की तो राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का संगठन देश में बिछी हुई सामाजिक सुधार की गतिविधियों को एक भागे में बिरो संकेत। रानाडे के भावना में उनको स्त्री दृष्टि का दर्शन होता है। सामाजिक समस्याओं को हल करने का जो प्रयत्न अब तक स्थायी रूप से प्रारंभ था, उसे उन्होंने राष्ट्रव्यापी बनाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुधार आन्दोलन को असाधारणिक रूप दिया। रानाडे के समाज-सुधार भावों की समीक्षा करने समय शिवर उन्हीं द्वारा स्थापित कोई स्त्री शिक्षा संस्था दिखाई न भी पड़े या विनी जीवन में पुनर्विवाह करने समय विधवा-विवाह करने की निवृत्ति के दर्शन न हों किन्तु भी सामाजिक सुधार के हविर्मा में उनका नाम स्थायीतः लिखा जाएगा। समाज-सुधार आन्दोलन उस समय ऐसी अवस्था में था कि राजा ध्यापी संस्था की स्थापना आन्दोलन की प्रगति के लिए अनिवार्य थी। महादेव गोविन्द रानाडे ने इस ध्येय को पूरा करके समाज सेवा कार्य को आगे बढ़ाया।

महर्षि घोड़े केशव धर्मे—समाज-सुधारकों तथा स्त्री प्रगति आन्दोलन के अधिनियों में महर्षि धर्मे का विशिष्ट स्थान है। उनके वा कार्यकाल 19वीं शताब्दी से आरम्भ होकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक फैला हुआ है। अन्य सुधारकों के साथ उनका स्थान अद्वितीय है। भारतीय नारी के उत्कर्ष के विविध क्षेत्रों में घोड़े केशव धर्मे का स्थान अग्रणी है। यह कहना अविश्वसनीय न होगा कि विधवा स्त्री की ओर तत्कालीन समाज की विरक्तपूर्ण दृष्टि में परिवर्तन करने का श्रेय धर्मे को ही देना चाहिए। उस जमाने में बड़े बड़े नगरों में पुनर्विवाह का समर्पण सामाजिक धाप मरना जाता था। आज

तो छोटे-से-छोटे गाँव में भी दंड के भय से मुक्त वातावरण में विधवा-पुनर्विवाह का प्रचार किया जाता है। यह सामाजिक परिवर्तन लाने में कब्रें का योगदान अमूल्य है। प्रश्न चाहे स्त्रियों के कार्य क्षेत्र का हो या मतपेदों के बावजूद विराष्ट्र राष्ट्रवाद का, कब्रें ने स्त्रियों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और इस कार्य के लिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कब्रें अपना परिचय धनी व्यक्ति के रूप में देते हैं। उनके जीवन का प्रधान स्वर था—नारी की प्रगति। मानव मुक्ति और प्रगति के बदले हुए चरण को ऐसे कर्म्मनिष्ठ और धुनी व्यक्ति ही पंजिल की ओर ले जा सकते हैं। उनके निरक्षर ग्रामीणों के समग्र समाचार-पत्र पढ़ने से समाज-सुधार का श्रीगणेश हुआ। कर्त्तव्य की विनम्र शुरुआत को पूर्णहुति एक ऐसे महिला महाविद्यालय के रूप में हुई जिसने हजारों नारियों के अज्ञान को दूर किया।

स्वामी विवेकानन्द—पुनरुद्धारवादियों में स्वामी विवेकानन्द का स्थान विराष्ट्र है। विवेकानन्द परिचयी शिष्टा पद्धति के दृष्टि सम्पर्क में आए। एक समय तो ऐसा आया कि यह नास्तिक हो गए थे। इस अद्वितीय प्रतिभाशाली वैदानी ने समाज-सुधार एवं स्त्री-उत्थान के प्रति दैनिक भी उदासीनता नहीं बरती।

रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में स्वामी विवेकानन्द ही सबसे प्रभावशाली थे। विवेकानन्द ने अपने गुरु की स्मृति को बनाये रखने हेतु रामकृष्ण के नाम से अनेक संस्थाएँ स्थापित कीं। स्वामीजी को अपने गुरु से दो सिद्धान्तों की मोख मिली थी—एक तो विचारों और कार्यों की स्वतन्त्रता तथा दूसरी मानवता के प्रति सहानुभूति। विवेकानन्द ने सामाजिक सेवा पर विशेष बल दिया। एक स्थान पर उन्होंने कहा है, “जिन्होंने प्रजा के धन से शिक्षा प्राप्त की हो और लाखों व्यक्तियों को सुधा से मर्ते देखा हो फिर भी उनका हृदय प्रजा की व्यापा से द्रवित न हो, वे सब देशद्रोही हैं।”

विवेकानन्द की दृष्टि से भारत में दो युगद्वयी थीं—एक स्त्रियों का भारतीय समाज में पृथगीन स्थान तथा दूसरी हिन्दू समाज में असमानता को जन्म देने वाली तथा लोकतन्त्र के सिद्धान्तों की अवहेलना करने वाली जाति-व्यवस्था। नारी उद्धार के सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द के कार्यों का मूल्यांकन करते समय विवेकानन्द की नारी के प्रति सम्मान एवं आदर भावना की ओर सहज जाता है। उन्होंने स्त्रियों की पृथगीनता के ऐतिहासिक कारणों का अन्वेषण कर नारी के प्रति आदर भावना को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। समय राट्ट को ही नहीं, बल्कि विश्व के उत्थान में शिष्टि भारतीय नारी अपना निश्चित योगदान दे सकेगी, ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता थी। अन्य सुधारकों की तुलना में विवेकानन्द का स्थान इस दृष्टि से विराष्ट्र है कि अन्य सुधारक नारी उत्थान को एक विभाग की दृष्टि से देखते थे जबकि स्वामीजी ने इस कार्य को प्राथमिकता दी। उनकी ऐसी धारणा थी कि अन्य देशों की पंक्ति में अपना स्थान लेने के लिए स्त्रियों की उन्नति एवं सम्मान भी आवश्यक है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती—हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले दूसरे पुनरुद्धारवादी, जिनका स्मरण किया जा सकता है, वे हैं—स्वामी दयानन्द सरस्वती। स्वामी दयानन्द ने अपने निजी प्रयासों से तथा मुख्यतः आर्य समाज की विविध संस्थाओं के माध्यम से स्त्री-शिक्षा का प्रचार किया तथा विवाह की न्यूनतम आयु बढ़वाने का प्रयास किया। आर्य समाज ने पश्चिम के अंधे अनुकरण के प्रवाह को रोकने का प्रयास अवश्य किया, किन्तु उनकी राष्ट्रीयता में धर्म का सम्मिश्रण था। वेद धर्म अटल हैं इस मान्यता के आधार पर उन्होंने वर्गों को स्वीकार किया। विरुद्ध उदारवादियों की स्त्री-समानता की तुलना में दयानन्द और आर्य समाज द्वारा स्त्री स्वातन्त्र्य की माँग का आधार समानता नहीं, बल्कि वेदकालीन समाज में व्याप्त स्वतन्त्रता वर्तमान नारी की मिलनी चाहिए थी। उनका प्रयास सीमित होते हुए भी स्त्रियों के उत्थान में स्वामी दयानन्द का नाम स्मरण किया जाएगा।

श्रीमती एनी बीसेण्ट—भारतीय नारी की स्थिति सुधारने में धियोसेन्सिबल विचारधारा की सत्पानक श्रीमती एनी बीसेण्ट का योगदान प्रमुख है। 19वीं शताब्दी के सब सुधारक तथा कार्यकर्त्ता पुरुष थे। प्रथम स्त्री-सुधारक के रूप में श्रीमती एनी बीसेण्ट इतिहास के रंगमंच पर आईं। अभी तक अधिकांश विदेशी विचारक तथा कार्यकर्त्ता भारतीय समाज व्यवस्था को या तो कृपादृष्टि से देखते थे या आलोचनात्मक रूप अपनाते थे। श्रीमती एनी बीसेण्ट एक ऐसे महिला थीं जिन्होंने भारत के गौरवमय अतीत की प्रशंसा की और साथ ही साथ धोषणा की कि भारत के समान सभ्यता में समृद्ध दूसरा देश कोई नहीं है। राष्ट्रीय आत्मसम्मान की जापत करने में श्रीमती एनी बीसेण्ट का योगदान अमूर्त था। तत्कालीन भारत में होने वाली सभी समस्याओं पर एनी बीसेण्ट ने अपना ध्यान केन्द्रित किया। भारत के अतीत के संस्कारों को उन्होंने प्रशंसा की है। भारत के स्वतन्त्र तथा कल्याणकारी नवसर्जन में जिन अनेक विप्लवियों ने अपना बलिदान दिया है उनमें श्रीमती एनी बीसेण्ट का योगदान उल्लेखनीय है। “धियोसेन्सिबल सोसायटी” के माध्यम से श्रीमती एनी बीसेण्ट ने भौतिक तथा बौद्धिक अन्वेषणों को दूर करने का प्रयास किया। एक महिला होने के नाते स्त्रियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति का वातावरण पैदा करने में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। भारत के सामाजिक रिवाजों को भी प्रोत्साहन दिया। भारतीय प्रजा मनजने में ही पश्चिम का अंधानुकरण न करे। इस हेतु भारत के गौरवशाली अतीत की उन्होंने धीरे-धीरे प्रशंसा की।

• महिलाओं के लिए असमान दुनिया है। विकसारील देशों में 90 करोड़ व्यक्ति निराश्रित हैं, जिनमें दो-तिहाई महिलाएँ हैं। 13 करोड़ छात्र-छात्राएँ प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, उनमें 60 प्रतिशत तो केवल छात्राएँ हैं। भारत में इनका प्रतिशत और अधिक है। कई विकसारील देशों में प्रसूति-पूर्व और प्रसूति-बाद की पूरी सुविधाएँ नहीं हैं और प्रसूति के दौरान अधिकांश महिलाओं को मृत्यु हो जाती है। विकसारील देशों में भी प्रतिवर्ष 5 लाख महिलाओं की मृत्यु प्रसूति के दौरान हो जाती है।

आर्थिक क्षेत्र में बीबी प्रगति—शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार हुआ है, परन्तु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी है। विश्व में 130 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, जिनमें 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं। यह स्थिति उनकी मात्रा और परिवार में क्रम के कारण हुई है। यद्यपि महिला भ्रष्टाचार दर में दो-तिहाई वृद्धि हुई है, तथापि श्रमिकों में इनकी वृद्धि केवल 4 प्रतिशत हो गई है। बैंकों से भी उन्हें बहुत कम सहायता में भ्रम मिलता है, क्योंकि ऋणपात्र के लिए कोई सम्पत्ति उनके नाम नहीं होती। 55 देशों में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार महिलाओं को मजदूरी पुरुषों की तुलना में तीन-चौथाई प्रतिशत ही मिलती है। सभी स्थानों पर महिलाएँ अधिक सहायता में बेरोजगार होती हैं। इन 55 देशों में कोई महिला संयुक्त राष्ट्रमन्त्री है और के भी तो 5 प्रतिशत से कम। इन देशों में गरीब देश भी हैं, जैसे—भूटान और इथियोपिया और उच्च आय वाले देश भी हैं, जैसे—ग्रीस, कुवैत, कोरिया, गयाना और सिंगापुर।

मानव विकास सूचकांक के अन्तर्गत पहली बार महिला-शक्ति माप (जेन्डर एम्पावरमेंट मेजर) निर्धारित किया गया है। महिला विकास सूचकांक (जेन्डर डवलपमेंट इन्डेक्स) में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर का सम्मिलित किया गया है, वहीं महिला शक्ति-माप में महिलाओं की राजनीतिक जीवन में भागीदारी और व्यवसायों में उनके स्तर और आय को सम्मिलित कर मापा गया है।

महिलाओं की आय की गणना ही नहीं—महिलाओं की आय बहुत कम आँकी जाती है। अनुमान है कि महिलाओं की आय 11 लाख करोड़ डॉलर का कम अंकन होता है। कारण यह है कि एक तो पुरुषों में महिलाओं को अधिक समय काम करना पड़ता है। औद्योगिक देशों में पुरुष का 2/3 समय आय वाले घरों में लगता है एवं 1/3 समय बिना आय के घरों में, जबकि महिलाओं की स्थिति इससे विपरीत होती है। विकसारील देशों में पुरुष का 3/4 समय आय वाले घरों में लगता है, जबकि महिलाओं का सारा ही समय घर के घरों एवं बच्चों के शालन-पालन में ही व्यतीत होता है जिसका कोई मूल्य नहीं आँका जाता। यदि स्त्रियाँ मूल्य के कार्य को भी आय में परिवर्तित किया जाए, तो महिलाओं की आय पुरुषों से ज्यादा अथवा उनके समान तो होगी ही, साथ ही ऐसा करने से पारम्पर्य में पानी आ रही मान्यताओं को ढोहा धक्का तो लगेगा, परन्तु सम्पत्ति के अधिकार, वलाक के सम्झौते और बैंक के ऋणों के लिए साक्ष्य आदि क्षेत्रों में परिवर्तन आरम्भ। महिलाओं की अदृश्य आय को आँकड़ा में परिवर्तन किए जाने पर राष्ट्रीय नीतियाँ भी प्रभावित होंगी।

कानूनी भेदभाव एवं अत्याचार—समाज में महिलाओं का स्थान निम्न होने का एक कारण कानून में भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं हिंसा का है। महिलाओं के अधिकार एवं भेदभाव को समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1979 में कार्टर जारी किया था परन्तु अभी तक 41 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, 6 ने हस्ताक्षर तो किए हैं, परन्तु अनुमोदन नहीं किया है, 43 ने अनुमोदन कुछ शर्तों के साथ किया है। दूसरे शब्दों में 90 देशों में महिला समानता के सभी पहलुओं को स्वीकार नहीं किया गया है।

महिलाओं के प्रति सामाजिक एवं शारीरिक हिंसा जन्म से मृत्यु तक बरकरा होती रहती है। कुछ देशों में तो गर्भ में ही लिंग की जाँच कर ली जाती है और यदि स्त्रीलिंग है, तो गर्भपात कर दिया जाता है। मनुष्यित जागरूकता के कारण भारत में तो इसे अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। कनाडा, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एक-तिहाई बच्चों एवं छिद्रोदियों के साथ यौन-दुर्व्यवहार किया जाता है। एशिया में अनुमानतः 10 लाख बालिकाओं को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि चिनी, मेशिको, पापुआ, न्यूगिनी और कोरियाई गणराज्य में दो-तिहाई विवाहित युवतियों के साथ परिवार में हिंसक व्यवहार किया जाता है। जर्मनी में अनुमानतः पानीस लाख महिलाएँ इस हिंसा का शिकार होती हैं। कनाडा, न्यूजीलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 में से एक महिला के साथ जीवन में एक बार बलात्कार होता है। महिलाओं की विपत्ती हथारों होती है उनमें बोम्बेरा, नाबाल, केन्या, पापुआ, न्यूगिनी और थाइलैण्ड में आधी से अधिक महिलाओं की हत्या वर्तमान या भूतपूर्व पतियों द्वारा की जाती है। महिलाओं की आत्महत्या का अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा कारण वैवाहिक झगड़े एवं हिंसा का होना है।

कुछ प्रस्ताव—महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए रिपोर्ट में निम्नलिखित पाँच सूची प्रस्ताव दिए गए हैं—

1. कानूनी सम्यक्ता के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले दस वर्ष तक पूरे प्रयत्न किए जाएँ। महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए एवं विधिक ज्ञान प्रसार के कार्य किए जाएँ। राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग को सम्पन्न हो। महिलाओं के प्रति अत्याचार को मुक्त-अपराध की तरह मानकर अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय किए जाएँ।

2. महिलाओं की आर्थिक एवं सहायक सहायता में निरन्तर वृद्धि की जाए। इसमें महिला के प्रसूती अवकाश में वृद्धि की जाए साथ ही पुरुष को भी अवकाश दिया जाए। जापान ने 1992 से यह व्यवस्था की है। सयुक्त राज्य अमेरिका में यह व्यवस्था तो है परन्तु बिना बेतन पिता को अवकाश दिया जाता है। बाल्टिक सागर में कई देशों में छोटे बच्चों के लालन-पालन के लिए पुरुष के अवकाश की भी व्यवस्था है। सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार के कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

3. 1990 में महिलाओं के स्तर के लिए सयुक्त राष्ट्र सच के आयोग ने सिफारिश की थी कि राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का हिस्सा कम-से-कम 30 प्रतिशत होना चाहिए। अभी तक विश्व में बहुत ही कम देश इस लक्ष्य तक पहुँचे हैं। भूतान एवं मॉरिशस में इस लक्ष्य तक पहुँचने एवं पार करने वाले देश डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन और स्लोवेनिया हैं। प्रशासन के क्षेत्र में 15 देशों ने यह लक्ष्य प्राप्त किया है और नगरपालिका क्षेत्र में केवल 11 देशों ने। भारत में पचासवीं राज सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर इस ओर पहल की गई है जिससे महिलाएँ सशक्त एवं समानता की ओर अग्रसर रही हैं।

4. सार्वजनिक शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए ऋण सुविधा में वृद्धि की जाए ताकि महिलाओं के अवसरों में वृद्धि हो सके। इन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कई बाधक तत्व हैं जिनके लिए सरकारों को पूरे प्रयत्न करने चाहिए।

5. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों एवं विशेषकर महिलाओं के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। कोपनहेगन में सामाजिक शिक्षा सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि विकासशील देशों को मानव विकास कार्यक्रमों के लिए अपने बजट की 20 प्रतिशत राशि मानव ससाधन विकास, जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, परिवार कल्याण एवं पोषाहार आदि कार्यक्रमों के लिए चिन्हित कर देनी चाहिए। इसी प्रकार गरीब लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा मिलनी चाहिए। भारत में उदारीकरण की नीति के बाद सामाजिक क्षेत्रों में ध्वंस की राशि में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है।

विश्व इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुका है। नई विश्व-व्यवस्था में महिला और पुरुषों के समान अवसरों से उन्नति प्राप्त हो सकती है। जब तक विश्व में महिलाओं की आर्थी आबादी इस त्रासदी से मुक्त होकर पुरुषों के समान अवसर युक्त जीवन यापन नहीं कर सकेंगी, विश्व-विकास का सपना अधूरा ही रहेगा। अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार इन क्षेत्र में महिलाओं को जब समान अवसर उपलब्ध होंगे, तभी सही विकास होगा। यद्यपि विश्व में और खासकर भारत में पिछले वर्षों में काफी प्रयत्न हुए हैं पर अभी बहुत कुछ करार बाकी है।¹ भारत में संविधान, विभिन्न कानूनों, पंचवर्षीय योजनाओं एवं सरकारी कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए धरमक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

□□□

आयोजन तथा आर्थिक विकास (Planning & Economic Development)

स्वतन्त्रता पूर्व देश का नियोजित विकास करने पर विचार किया गया था। इजीनियर एम. विन्चेस्वरीया ने 1934 में अपनी पुस्तक 'Planned Economy for India' में नियोजित विकास पर बल दिया था। पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय योजना समिति' का गठन किया गया। सन् 1944 में भारत सरकार ने 'नियोजन एवं विकास' नामक विभाग का गठन किया। सन् 1946 में 'परामर्शदाता बोर्ड' एवं 'नियोजित समिति' स्थापित की गई। इससे स्पष्ट है कि योजना आयोग का निर्माण पूर्व प्रयत्नों एवं चिन्तन की परिणति मात्र था। 15 मार्च, 1950 को योजना आयोग का विधिवत गठन किया गया। संविधान सभा ने 'योजना आयोग' को वैधानिक संस्था का स्वरूप प्रदान नहीं किया, अतः यह आयोग एक राजस्वीय आदेश के द्वारा स्थापित किया गया है।

योजना आयोग (The Planning Commission)—योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक संस्था है। शक्ति एवं कार्य-क्षमता की दृष्टि से 1950 से लेकर आज तक योजना आयोग ने सभी क्षेत्रों में और विशेषतः राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में विभिन्न पराम्यदलों के माध्यम से अपने आपको विकसित किया है।

योजना आयोग का संगठन—मार्च 1950 में नियुक्त योजना आयोग के संगठन में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। जनवरी, 1985 में एजीय गौपी के नेतृत्व वाली सरकार ने योजना आयोग का पुनर्गठन किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. मनमोहनसिंह को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। अब तक योजना मंत्री ही आयोग का उपाध्यक्ष होता था। जून 1991 में केन्द्र में बहिस 10 सप्ताह हुए। प्रधानमंत्री रातिसिन्हाएव योजना आयोग के अध्यक्ष बने। प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। 17 अगस्त, 1991 को योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सात पूर्णकालीन सदस्य तथा मंत्रियों को शामिल किया गया। आयोग के सभी के संरक्षण के लिए आन्तरिक संगठन की दृष्टि से आयोग को चार भागों में विभाजित किया गया है—

1. **समन्वय विभाग (Co-ordination Department)**—इसके दो उप-विभाग हैं—योजना समन्वय विभाग (Plan Co-ordination Department) तथा कार्यक्रम प्रशासन विभाग (Programme Administration Department)। जब योजना आयोग को विभिन्न विभागों में सहयोग की आवश्यकता होती है तो समन्वय विभाग अपनी भूमिका निभाता है। प्रशासन विभाग के कार्य वारिक और पञ्चवर्षीय योजनाओं में समन्वय अविचलित क्षेत्रों का पता लगाना, प्रदेशों की केन्द्रीय सहायता के तरीकों तथा योजना की प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में परामर्श देना है।

2. **सहायक विभाग (General Department)**—योजना से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए अनेक साधारण विभाग हैं। प्रत्येक विभाग का अपना निदेशक होता है। मुख्य साधारण विभाग ये हैं—सौराष्ट्रकामी योजना विभाग, आर्थिक विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग, सांख्यिकीय तथा सर्वेक्षण विभाग, प्रबन्ध एवं प्रशासन विभाग।

3. **विषय विभाग (Subject Division)**—आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विषय विभाग हैं, जो विषय से सम्बन्धित योजना के लिए कार्य और शोध करते हैं।

4. **विशेष विकास कार्यक्रम विभाग (Special Development Programmed Division)**—कृषि विशेष कार्यक्रम पर जोर देने की दृष्टि से विशेष विभाग बनाए गए हैं। ये दो हैं—ग्रामीण विभाग एवं सहकारिता विभाग।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन—देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए 1952 में वह एक स्वतन्त्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसने अपने कार्यक्षेत्रों की विधिवत किया और कृषि, ग्रामीण

उद्योग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्राचीन योजना आदि से सम्बन्धित अन्य योजनागत कार्यक्रमों को अपने कार्य में शामिल किया। चतुर्थ वर्षों से इस संगठन ने (क) योजना-कर्ताओं को आवश्यक प्रतिपुष्टि देने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के 'त्वरित मूल्यांकन अध्ययन', (ख) केन्द्रीय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और राज्य मूल्यांकन संगठनों के बीच समुक्त मूल्यांकन अध्ययन और (ग) विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रारम्भ किया है।

योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं भूमिका—योजना आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1. देश के साधनों का अनुमान लगाना है। योजना आयोग देश के भौतिक, पूँजी सम्बन्धी और मानवीय साधनों का अनुमान लगाता है। यह ऐसे साधनों के विकास की सम्भावना का पता लगाता है, जिसका देश में अभाव होता है। साधनों का अनुमान और उनके अभिवृद्धि का प्रयत्न अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कोई नियोजन सम्भव नहीं है।

2. योजना आयोग का कार्य योजना-निर्माण करना है। योजना आयोग देश के संसाधनों के प्रभावशाली और समुचित उपयोग के लिए योजना का निर्माण करता है।

3. योजना आयोग के दो कार्य हैं—योजना को पूरा किए जाने की अवस्थाओं को परिभाषित करना तथा योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना।

4. योजना आयोग देश के साधनों का समुचित आवंटन करता है।

5. योजना आयोग योजना क्षेत्र का नियंत्रण करता है। आयोग योजना की प्रत्येक अवस्था के सभी पहलुओं की क्रियाविविधियों के लिए योजनात्मक की प्रवृत्ति निर्धारित करता है।

6. समय-समय पर योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन में की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के आधार पर यह नीतियों और प्रयत्नों में परिवर्तन या समायोजन की सिफारिश करता है।

7. योजना आयोग का कार्य सुलभ और दिशा-निर्देश देने से सम्बन्धित है। योजना आयोग आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाले पदकों को इंगित करता है और योजना की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्धारण करता है। योजना निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, विकास कार्यक्रमों आदि पर योजना आयोग सरकार को सुझाव देता है। यदि राज्य या केन्द्रीय सरकार किसी समस्या विशेष पर सुझाव चाहे तो आयोग उस समस्या विशेष के समाधान के लिए अपने सुझाव देता है।

8. अन्य—अपने कार्य के सफल सम्पादन की दृष्टि से योजना आयोग को कविवर्य निम्नलिखित कार्य हैं—

1. सामग्री और पूँजी साधनों का मूल्यांकन संरक्षण तथा उनमें वृद्धि की सम्भावनाओं का आँकड़ा तैयार करना। इस सम्बन्ध में योजना आयोग का कर्तव्य यह है कि वित्तीय साधनों, मूल्य-स्तर, उपयोग प्रविधान, आदि का निरन्तर अध्ययन करता रहे।

2. साधनों के समुचित प्रयोग की दिशा में योजना आयोग को ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे एक क्षेत्र को विकास की अधिकतम दर प्राप्त की जा सके तथा दूसरी ओर सामाजिक न्याय की स्थिति को सुधरे।

3. योजना आयोग योजनाओं की सफलता के लिए सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता रहता है।

4. योजना आयोग आर्थिक एवं अन्य नीतियों का सामाजिक मूल्यांकन करता है और यदि नीतियों में किसी तरह के परिवर्तनों की आवश्यकता हो तो इसके लिए मन्त्रिमण्डल को सिफारिश करता है।

5. नियोजन की तकनीक का आवश्यक अध्ययन करते हुए अपने सुझाव का प्रचलन करता है।

6. योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन-सहयोग प्राप्त करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना हाथीय मशमूस करते हुए योजना आयोग के कार्यों में भागीदार बन सके।

उपरोक्त कार्यों का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि योजना आयोग की योजना निर्माण प्रक्रिया में बहु-आवामी भूमिका है और इसे इस दिशा में विविध प्रकार के कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है।

योजना आयोग के प्रमुख सम्भाग और समितियाँ—योजना आयोग के तीन प्रमुख सम्भाग (Divisions) हैं—कार्यक्रम परामर्शदातागण (Programme Advisors), सामान्य सचिवालय (General Secretariat) तथा तकनीकी सचिवालय (Technical Secretariat)। इसकी तीन महत्वपूर्ण समितियाँ भी हैं—अनुसन्धान कार्यक्रम समिति (Research Programme Committee), कार्यक्रम मूल्यांकन समिति (Programme Evaluation Committee) तथा योजना उपक्रम समिति (Committee on Plan Project)। कार्यक्रम परामर्शदातागण क्षेत्र अध्ययन (Field Study) तथा विभिन्न गतिविधियों एवं प्रयोजनों के पर्यवेक्षण तथा उनके क्रियान्वयन की प्रगति के विषय में योजना आयोग को सहायता देते हैं। सामान्य सचिवालय तथा तकनीकी सचिवालय आयोग के आन्तरिक अनुभागों

(Sections) से सम्बन्धित है। अनुसूच्य कार्यक्रम समिति सामाजिक तथा आर्थिक विकास की समस्याओं पर शोध-कार्य संचालित करती है। कार्यक्रम मूल्यांकन समिति समुदायिक विकास आयोजना के अन्तर्गत कार्यों का मूल्यांकन करती है। योजना उपक्रम समिति महत्वपूर्ण योजना उपक्रमों के कार्य की जाँच करती है जिससे अधिकतम कार्यकुशलता एवं निरालस्यता की प्राप्ति की जा सके।¹

योजना आयोग के प्रभागों के कार्यकलाप—योजना आयोग के सभी 27 प्रभागों के मुख्य कार्य-कलाप निम्नलिखित हैं—

1. भावी योजना प्रभाग—यह पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में उक्तोक्त टिप्पणी की अंतिम रूप देता है। यह प्रभाग गरीबों और क्षेत्रीय असमानता की स्थिति से सम्बन्धित कार्यकारी दल के लिए विभिन्न अध्ययन करता है। विभिन्न क्षेत्रों की कीमतों पर आधारित कीमतों, निर्धारित कीमतों और बतों की दरों में परिवर्तन के प्रभाव तथा शीघ्र कीमतों के मूल्यांकन में वृद्धि के प्रभाव की जाँच करने के लिए आगन्त-निर्गत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी निर्देशन का अध्ययन इस प्रभाग द्वारा किया जाता है। यह प्रभाग निम्नी और अन्त्य वार्षिक योजना के लिए विभिन्न क्षेत्रों के निर्गत उत्पादन स्तरों का अनुमान लगाता है।

2. आर्थिक प्रभाग—यह कृषि और औद्योगिक उत्पादन अपार सार्वजनिक क्षेत्रों के निष्पादन, शीघ्र और उपभोक्ता कीमतों का प्रवृत्ति, मुद्रास्फीति और बैंक ऋण भुगतान नीति आदि के सम्बन्ध में आर्थिक स्थिति का विश्लेषण और समीक्षा करता है। इसके अलावा प्रभाग दूरस्थ और अग्रगण्य क्षेत्रों में उचित कीमतों पर वस्तुओं और कीमतों पर निगरानी से सम्बन्धित समिति, खाने के तेलों से सम्बन्धित मन्त्रियों की स्थायी समीक्षा समिति और केन्द्र, बैंक और सरकारी विदेशी सहायकों द्वारा निवेश के अन्तर्गत स्वरूप से सम्बन्धित कार्यकारी दल के कार्य से परिचित रूप से सम्बन्ध रखता है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग—यह प्रभाग देश के व्यापार और भुगतान शर के विभिन्न तत्वों की समीक्षा करत तथा जाँच से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार करने के कार्य में लगा रहता है। विकासशील और विकसित राष्ट्रों के साथ परिचित आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी सहयोग स्थापित करने के लिए अनेक टिप्पणीय दस्तावेज करता है। नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक अभिकरण तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार और कार्य करत है।

4. वित्तीय सहायन प्रभाग—यह प्रभाग केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजटों का विश्लेषण, वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सहायकों का आवधिक मूल्यांकन, साप्ताहिक अवधि तक अपेक्षित होने वाले राज्यों के सहायकों की माध्यम-वर्षिक समीक्षा और भावी वार्षिक योजना के वित्त व्यवस्था करने में बजट के बाद की घटनाओं और परिवर्तनों तथा घरेलू वित्त-व्यवस्था, निर्यात बैंक से अपेक्षित पर अन्तःराष्ट्र रूप से निर्धारित किए गए वार्षिक योजना की सहमति और स्वीकार करने के लिए आवश्यक प्रत्येक दस्तावेज करता है।

5. परियोजना का मूल्यांकन—यह प्रभाग उन केन्द्रीय सरकार के निवेश प्रस्तावों का विश्लेषण करता है जिन पर सरकार निवेश बोर्ड और धन वित्त समिति द्वारा विचार किया जाता है।

6. प्रयोग और सूचना प्रभाग—यह प्रभाग उद्योग और खनिज, ऊर्जा, परिवहन, सिंचाई, नौका विकास और शिक्षा आदि के विभिन्न उप-क्षेत्रों के योजनागत परियोजनाओं की प्रगति और तथ्यों की प्रगति के विश्लेषण करता है और विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जुने हुए क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्य, इस्पात, कोयला, विद्युत और रेलवे में उत्पादन, निष्पादन और परियोजना कार्य-व्यय के सम्बन्ध में विभिन्न रिपोर्ट तैयार करता है। परियोजनाओं के कार्य-व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण करता है, समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाता है और उनके सम्बन्ध में सुधार-उपक्रम उद्योग प्रारम्भ करने के लिए कार्य-वर्ष के दिशों की रूपरेखा तैयार करता है। यह प्रभाग सिंचाई परियोजनाओं के प्रयोग और विश्व बैंक की सहमति प्राप्त वन-उद्योग कार्य-क्रमों के प्रयोग सूचना व्यवस्था का विकास करने में सहायता करता है।

7. कृषि प्रभाग—यह प्रभाग कृषि के विकास के लिए उपयोगी सुझाव देता है।

8. ग्रामीण विकास और सहकारिता प्रभाग—यह प्रभाग ग्रामीण विकास और सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करता है।

9. सिंचाई और निपटारा क्षेत्र विकास प्रभाग—यह प्रभाग सिंचाई, बाढ़-निपटारा और बहु-उद्देश्य परियोजनाओं पर विचार करता है। छोटी सिंचाई और निपटारा विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। इस प्रभाग ने सहायक अनुमत तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है।

10. बहुस्तरीय योजना प्रभाग—यह प्रभाग बहुस्तरीय योजनाओं से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में यह विभिन्न समस्याओं के सहयोग से कार्य करता है और पाठ्यक्रम चलाता है।

11 **विद्युत और ऊर्जा प्रभाग**—यह प्रभाग विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की सतत समीक्षा करता है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कर्मियों के लिए उत्तरदायित्व क्षेत्रों, उत्पन्न होने वाली लागतों के लिए उपकरणों की वितरण, समय-अनुसूची और निर्माण कार्यक्रमों सहित बड़ी स्कोपों की स्वीकृति देने की गति बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

12 **टेलीग्राफ और खनिज प्रभाग**—इस प्रभाग द्वारा टेलीग्राफ और खनिज से सम्बन्धित सरकारी उद्यमों के साथ उनकी परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाता है। विशेष रूप से अन्तर-मन्त्रालय सम्बन्ध और दीर्घकालीन योजना के सम्बन्ध में होने वाली विभिन्न समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निष्पत्ति समाप्ति बैठकें आयोजित की जाती हैं।

13 **ग्राम और लघु उद्योग प्रभाग**—यह प्रभाग ग्राम और लघु उद्योगों के लिए अधिकतम की प्रगति की अपेक्षा के प्रश्न पर विचार करता है और सुधारणक उपाय सुझता है तथा एशियाई उद्यमिता संगठन अथवा अन्य संगठनों द्वारा प्राप्ति योग्य के लिए आयोजित सम्मेलनों में भाग लेता है।

14 **आवास, शहरी विकास और जन आर्थिक प्रभाग**—इस प्रभाग द्वारा शहरी विकास करने की जगहों और मकान निर्माण स्वीय राशियों की परीक्षा सुधार और ग्रामीण जल-आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष तैयार किए जाते हैं जिनमें उन समस्याओं और प्रश्नों को स्पष्ट किया जाता है जिनमें क्षेत्रीय स्तर पर तल करना आवश्यक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल-आपूर्ति स्कीमों के लिए मानक निर्धारित करने और उन स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर ध्यान दिया जाता है और उनके बारे में निर्माण और आवास मन्त्रालय को सुझाव दिया जाता है।

15 **परिवहन प्रभाग**—यह प्रभाग परिवहन सम्बन्धी परियोजनाओं के मूल्यांकन और उनको स्वीकृति से सम्बन्धित है। विस्तृत विचार विमर्श द्वारा परियोजनाओं के सम्बन्ध में बाधाओं का पता लगाकर, सुधारणक उपायों का सुझाव देना इसका कार्य है। परिवहन परियोजनाओं से सम्बन्धित अध्ययन दल भी यह गठित करता है।

16 **शिक्षा प्रभाग**—यह प्रभाग देश के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा परियोजनाओं विशेषकर प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा एवं सामुदायिक साक्षरता पर विशेष रूप से ध्यान देता है। शिक्षित बेरोजगारी से सम्बन्धित अधिकतम की समीक्षात्मक दल से मूल्यांकन करना, शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकारी दलों की रिपोर्टों पर विचार करना तथा शिक्षा और रोजगार के सम्बन्ध में सिफारिश करना आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं।

17 **विज्ञान और शिल्प-विज्ञान प्रभाग**—विभिन्न मन्त्रालयों विभागों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी तकनीकी सहायता के लिए जो परियोजनाएँ भेजी जाती हैं उनकी जाँच इस प्रभाग द्वारा की जाती है। मन्त्रालयी विभागों के विज्ञान और शिल्प विज्ञान योजनासर्गर्त कार्यक्रमों पर विचार करता है।

18 **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**—यह प्रभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित है। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में इस प्रभाग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया जाता है। कुष्ठ रोग निवारण तथा अन्वेषण की रोकथाम में विशिष्ट भूमिका होती है।

19 **समाज कल्याण प्रभाग**—यह प्रभाग समाज कल्याण परियोजनाओं पर विचार करता है। साथ ही पिछड़ी जातियों की महिलाओं और विधवाओं के उद्यान के लिए कार्य करता है।

20 **पिछड़ा प्रभाग**—यह प्रभाग पिछड़े वर्ग की परियोजनाओं से सम्बन्धित है। जनजातीय उद्योगों और अनुसूचित जातियों के लिए सफ्टक योजनाओं के अन्तर्गत शामिल स्वीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और तथ्य निर्धारित करना मुख्य कार्य है।

21 **ग्राम, रोजगार और जन शक्ति प्रभाग**—यह प्रभाग ग्रामीण असंगठित श्रमिकों बन्धुआ मजदूरों और बाल मजदूरों से सम्बन्धित कार्य और श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं, हस्तशिल्प कार्यों के सम्पादन, टण्डों/केन्द्र साहित्य प्रदेशों और केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा प्रस्तावित एवं विभिन्न योजनासर्गर्त कार्यक्रमों में रोजगार पदों की जाँच करने तथा जन-शक्ति से सम्बन्धित विविध पहलुओं की जाँच करने राज्य-स्तरीय जन-शक्ति की रूपरेखा तैयार करने सम्बन्धी दायित्वों का निर्वहण करता है।

22 **साक्षिकी और सर्वेक्षण प्रभाग**—यह प्रभाग साक्षिकी और सर्वेक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय साक्षिकी संगठन के माध्यम से आयोजित करता है। यह साक्षिकी और सर्वेक्षण प्रकाशन निरूपित करता है।

23 **संचार, सूचना तथा प्रसारण प्रभाग**—योजना प्रभाग के कार्य कलाओं की प्रगति को यह प्रभाग सूचना प्रसारण मन्त्रालय के माध्यम से एकत्रित से सम्पर्क बनाए रखता है। यह विभाग/प्रभाग योजना और सम्बन्ध विधियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज छपवाता है।

24 **भारत-जपान अध्ययन समिति**—इस समिति का कार्य भारत और जपान के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक विषयों से सम्बन्धित विविध पहलुओं का अध्ययन करना है ताकि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध प्रगाढ़ हो सकें।

25. सामाजिक-आर्थिक अनुसन्धान एका—यह एक विभिन्न नए अनुसंधान अध्ययन अनुमोदित करता है। विभिन्न अनुसन्धान अध्ययन के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए जाते हैं। अनेक अनुसन्धानों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

26. हिन्दी का प्रयोग—राजभाषा नीति और राजभाषा, 1976 के अनुसरण में योजना आयोग में साक्षरी कामकाज विशेष रूप से पत्र-व्यवहार, सामान्य आदेशों और द्विभाषक फार्मों में हिन्दी के प्रयोग में लगातार प्रगति होती रही है। योजना आयोग द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण कामकाज पर हिन्दी में निरूपित जाते हैं।

27. पुस्तकालय—योजना आयोग पुस्तकालय अन्य समन्वय, सभाओं तथा विश्वविद्यालय आदि के अनुसन्धानकर्ताओं, विद्वानों और अधिकारियों को परामर्श सुविधाएँ देने के अलावा योजना आयोग सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सन्दर्भ सेवा और पुस्तकें देने की सुविधाएँ देता है।

योजना आयोग का भारतीय संसदीय प्रणाली पर प्रभाव

(Impact of Planning Commission on Parliamentary System of India)

योजना प्रणाली तथा योजना आयोग ने भारत की संसदीय व्यवस्था के स्वरूप तथा कार्य-प्रणाली को प्रभावित किया है। इसका सारगर्भित विवेचन डॉ. पी. डी. शर्मा एवं अन्य ने इस प्रकार किया है—“योजना आयोग की व्यवस्था ने भारत की संसदीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। अनेक विचारकों ने इसी आधार पर योजना आयोग को अंगीकृत करने का आधार बनाया है। इस सम्बन्ध में अरुणो कान्ता द्वारा योजना आयोग को प्रभावप्रणाली रूप में अन्तर्निहित किया गया। उनकी दृष्टि में भारत में नियोजन के परिणामस्वरूप संसदीय प्रणाली समाप्त हो गई है। केन्द्रीय सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर योजना आयोग छाया रहता है तथा राज्य सरकारों को भी योजना आयोग के निर्देशों के अधीन पर ही चलना पड़ता है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को कोई निर्णय लेने की स्वतन्त्रता नहीं है, तथापि योजना आयोग अपना प्रत्येक निर्णय इन पर लादने में समर्थ होता है जबकि आयोग के सदस्य एवं कर्मचारी न तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और न ही राज्य की व्यवस्थापिका सभा के प्रति। संसदीय व्यवस्था का मूल मंत्र ही उत्तरदायित्व की व्यवस्था है जिसे योजना आयोग ने अपनी सार्वभौम स्थिति के कारण समाप्त कर दिया है।”

यद्यपि योजना आयोग केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के निर्णयों को प्रभावित करता है, किन्तु यह तथ्य पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं जा सकता कि योजना आयोग के अस्तित्व में आने से संसदीय व्यवस्था का आधार-विन्दु उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है, क्योंकि केन्द्र के स्तर पर योजना मंत्री तथा राज्य के स्तर पर नियोजन मंत्री राज्य की विधान सभा के प्रति उन सभी निर्णयों के लिए उत्तरदायी हैं जो उन्होंने स्वयं अथवा योजना आयोग के परामर्श से लिए हैं।

योजना आयोग के संसदीय व्यवस्था पर एक अन्य प्रभाव की ओर संकेत करते हुए यह कहा जाता है कि योजना आयोग के अस्तित्व में आने से एक समानान्तर सरकार की स्थापना हो गई है। योजना आयोग में लगभग वे सभी विभाग पाए जाते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के स्तर पर पाए जाते हैं अथवा राजकीय स्तरों पर पाए जाते हैं। योजना आयोग का अधिकार यह प्रयास रहता है कि वह इन विभागों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित कर अपन कार्य संचालित कर सके। वह यह आवश्यक नहीं समझता है कि इन विभागों से केन्द्र पर प्रधानमंत्री, राज्य पर मुख्यमंत्री अथवा सम्बन्धित मंत्रियों के माध्यम से इन विभागों से सम्पर्क स्थापित करे। इसलिये ‘साम्राज्य के अन्दर साम्राज्य’ का उन्मूलन हो गया है। योजना आयोग के इस अनुचित प्रभाव के विचार को अनेक विचारकों द्वारा खंडित किया गया है। यद्यपि यह ठीक है कि योजना आयोग में मुख्य रूप से विकास से सम्बन्धित सभी विभाग पाए जाते हैं जो केन्द्रीय या राज्य के स्तर पर उपलब्ध हैं, किन्तु जो व्यावहारिक अध्ययन हुए हैं उनसे यह सिद्ध नहीं होता है कि योजना आयोग द्वारा सम्बन्धित मंत्रियों को उपेक्षा कर विभागों से सम्पर्क स्थापित करना चाहता हो और उन पर प्रभाव जमाने की एक सामान्यवर्ती प्रवृत्ति निहित रही हो।

योजना व्यवस्था ने संसदीय व्यवस्था को प्रभावित किया है तथा नियोजन की प्रक्रिया का सम्बन्ध पर प्रभाव एक विवादप्रसूत प्रश्न बना हुआ है। इस सन्दर्भ में विभिन्न विचारकों के विभिन्न मत रहे हैं। अरुणो कान्ता की मान्यता है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में योजना आयोग की भूमिका सम्बन्ध के अनुकूल नहीं है, यद्यपि इसकी क्रियाओं के अनुचित प्रभाव के कारण सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था ही समाप्त हो गई है। इस विचारधारा के विरोधी एक अन्य विचारधारा यह है कि नियोजन व्यवस्था के होते हुए हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था बनी हुई है या सम्बन्ध का स्वरूप संसदीय सम्बन्ध के रूप में उभरा है। यद्यपि इससे भारतीय सम्बन्धी व्यवस्था में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है, किन्तु सम्बन्ध के आधारभूत तत्व इसमें विद्यमान हैं। एक अन्य विचारधारा के अनुसार यद्यपि सम्बन्ध नियोजन की व्यवस्था के कारण समाप्त नहीं हुआ कि भी केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज्यादा आ गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान में एकलपक्षता का पक्ष इससे अधिक मजबूत हुआ है। भारतीय संविधान द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता की स्थापना की गई, किन्तु योजना आयोग के अनुकूल अनुदान की प्रक्रिया ने ‘वर्तिकल सभ्य’ स्थापित कर दिया अर्थात् राज्यों के सम्बन्धों में

असमानता का प्रयोग किया जाने लगा तथा यह असमानता गैर-सौविधानिक सहाय योजना आयोग द्वारा आरम्भ की जाती है। इस स्थिति के होते हुए के सम्बन्ध में स्वीकारा है कि योजना व्यवस्था में होते हुए भी यह कहना गलत होगा कि राज्य पूर्णतः अनाहिज हो गए अथवा केन्द्र के अधीन हो गए क्योंकि योजना-निर्माण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को बनाने तथा वित्त की रूपरेखा तैयार करने में और विशेषकर योजनाओं को लागू करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए केन्द्र से सौदे के बाद सहयोग की स्थिति बनी रहती है।

नियोजन व्यवस्था से साथ एवं राज्य सरकारों पर जो प्रभाव पड़ता है इसी के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग के माध्यम से राज्यों पर सौविधानिक नहीं अपितु आर्थिक दबाव अधिक पड़ता है, क्योंकि सविधान में नियोजन के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया गया तथा नियोजन समझौते सूची में रखा गया, इसलिए योजना आयोग का निर्माण केन्द्रीय सरकार के एक प्रशासक के आधार पर किया गया। इस आधार पर योजना आयोग कानूनी दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। उसके किसी प्रभाव के पीछे सौविधानिक शक्ति नहीं हो सकती, किन्तु राज्यों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता के कारण आयोग के प्रभाव को स्वीकार करना पड़ता है। यदि कोई राज्य यह तर्क देता है कि वह योजना आयोग का आदेश मानने को बाध्य नहीं है, क्योंकि यह कोई कानूनी शक्ति नहीं रखता, सौविधानिक दृष्टि से उसका पक्ष सही कहा जा सकता है तथा केन्द्रीय सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है जिसके आधार पर वह राज्यों को आयोग का निर्णय मानने को बाध्य कर सके, किन्तु यहाँ राजनीतिक और आर्थिक कारण कानूनी दायरों की अपेक्षा अधिक प्रभाव रखता है। इसी दबाव शक्ति के कारण राज्य आयोग के निर्णयों का विरोध करने में समर्थ नहीं हो पाते। जहाँ तक योजनाओं के निर्णय का सम्बन्ध है, मुख्य रूप से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि नियोजन की दिशा राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। योजना का सत्य क्या होगा तथा प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी, इसके निर्धारण का कार्य योजना आयोग ही करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि योजनाओं के निर्माण में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। यदि योजना-निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया देखी जाए तो बिना किसी विरोध के यह नहीं स्वीकारा जा सकता है कि योजना-निर्माण में राज्यों का कोई सहयोग नहीं रहता। प्रत्येक योजना के निर्माण से पूर्व एक योजना सम्बन्धी आलेख तैयार किया जाता है। योजना का यह आलेख निर्मित कर राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है। कभी इससे पूर्व तथा कभी इसके पश्चात् दलील स्तर पर भी आलेख पर विचार किया जाता है। इसके बाद यह आलेख राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, योजना एवं वित्त मंत्री होते हैं। इस स्तर पर योजना-निर्माण में राज्यों का दृष्टिकोण जान लिया जाता है और इस दृष्टिकोण के आधार पर आलेख को सारोपन के साथ अथवा बिना सारोपन के स्वीकृति दे दी जाती है तथा इसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है।

संसद की स्वीकृति के पश्चात् यह आलेख योजना-निर्माण के लिए पुनः योजना आयोग के पास भेज दिया जाता है और इस आलेख के आधार पर विभिन्न राज्यों से योजना के निर्माण के लिए सुझाव माँगे जाते हैं। राज्य अपने स्तर पर जिलों से एवं जिला पंचायत समिति प्रायः पंचायतों से सुझाव माँगकर अपनी योजना की रिपोर्ट योजना आयोग को भेज देते हैं। इसके बाद योजना आयोग विभिन्न राज्यों के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए तथा उनसे निरन्तर बातचीत के माध्यम से एक नवीन प्रलेख तैयार करता है जो पुनः राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद एवं संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। योजना की इस प्रक्रिया का सम्बन्ध बहुत कुछ इन विषयों से होता है जो राज्य-सूची के होते हैं। इसलिए जब योजना आयोग द्वारा राज्य सूची के विषयों का नियोजन किया जाता है तथा जब राज्यों का परामर्श पूरी तरह नहीं स्वीकारा जाता है तो कुछ मात्रा में उनकी स्वातंत्र्य आवश्यकता सीमित की जाती है, किन्तु राज्यों के परामर्श अथवा उनकी भूमिका को गौण स्थान नहीं दिया जाता। योजना निर्माण में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी नियोजन की प्रक्रिया केन्द्र, राज्य तथा योजना आयोग की प्रतीक बड़ी जा सकती है।

नियोजन के संदर्भ में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण राज्यों की आर्थिक व्यवस्था असन्तुष्ट हो जाती है, क्योंकि राज्यों पर ऋण इतना बढ़ जाता है कि अपनी आय का अधिकांश भाग उन्हें ऋण के रूप में केन्द्र को देना पड़ता है। इसी असन्तुष्टि अर्थ-व्यवस्था के कारण राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता बढ़ती जाती है फलतः भारतीय सघीय व्यवस्था में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिलता है।

आर्थिक नियोजन की चुनौतियों के संदर्भ में प्रशासनिक सुधार

(Administrative Improvements in View of the Challenges of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन में प्रशासन को नए दायित्व सौंपे हैं। विकास कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए नई चुनौतियाँ उपस्थित हुई हैं। इनका सामना करने के लिए प्रशासन को तदनुकूल ढाला जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने नियोजन के संदर्भ में भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इनमें से अधिकांश का सम्बन्ध योजना आयोग से है।

चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें योजना आयोग का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष तथा योजना आयोग का उपाध्यक्ष सदस्य हों। औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों का चयन करते समय इण्डियन टैल्गर ऑफ कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज के अध्यक्ष की सहायता ली जानी चाहिए। जहाँ आवश्यक प्रतीत हो वहाँ समिति के पासपोर्ट के लिए विशेषज्ञों को भी सहजित किया जा सकता है।

10. प्रशासनिक सुधार आयोग ने ग्लोबल को रूनिशन्स बनने हेतु यह सुझाव दिया है कि प्रविर्ण योजना कार्यक्रमों को प्रगति प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तुत की जाए। ये प्रवेदन छ माह के अन्तर-अन्तर समस्त में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी राज्य नियोजन महत्त्व योजना कार्यक्रमों की प्रगति सम्बन्धी सूचना एकत्रित करें तथा एक प्रतिवेदन तैयार कर उसे राज्य विधान-मण्डल के सामने रखें। योजना आयोग में पुष्ट से एक मूल्यांकन द्वारा स्थानों की जानी चाहिए जिसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन रहना चाहिए। यह राज्य महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यों का अध्ययन करेगी जिससे राज्य में मूल्यांकन कार्य का पक्ष-प्रदर्शन हो सकेगा। योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाने वाला कार्यक्रम भारतीय संसद के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रशासनिक या योजना सम्बन्धी (सैल) अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों के मूल्यांकन का कार्य भी करेगा जहाँ वर्तमान में योजना आयोग द्वारा यह नहीं किया जा रहा है। राज्य नियोजन मण्डलों में मूल्यांकन इकाईयें होने चाहिए जो राज्य योजनाओं के कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सकेंगी और इनके प्रतिवेदन राज्यों को व्यवस्थापिकाओं के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे।

11. प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि लगभग 25 सदस्यों की एक विशेष समन्वय समिति गठित की जा सकती है जो योजना कार्यों की वार्षिक प्रगति की जाँच कर सकेंगी। राज्य स्तर पर ऐसी समिति उपयोगी होगी। प्रस्तावित समिति अवैधानिक परामर्शदात्री समिति का कार्य कर सकती है।

12. प्रशासनिक सुधार आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, उन्-प्रशासकी, केन्द्रीय वित्त मंत्री, स्वास्थ्य तथा कृषि-मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, वित्त-मंत्री, ग्राम तथा रोजगार मंत्री, गृह-मंत्री, सिविल एवं शक्ति मंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने चाहिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग की उक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर, 1967 में राष्ट्रीय विकास परिषद का पुनर्गठन कर दिया।

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव—

(1) सर्वप्रथम योजना आयोग के सगठन में परिवर्तन करना आवश्यक है। योजना आयोग पूर्णतः गैर राजनीतिक परामर्शदात्री संस्था होने चाहिए। आयोग में गति नहीं होने चाहिए। आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सभी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए। कभी-कभी यह कहा जा सकता है कि विशेषज्ञों को पुस्तक-ज्ञान होता है और व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में आयोग विशेष अन्य वैधानिक सहाय के अधिकारों का विकल्प नहीं हो सकता है। वह मात्र परामर्शदात्री संस्था ही होगी। इससे इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

(2) केन्द्रीय मंत्री मंत्री-अन्तरे विभागों की योजना बनाकर आयोग को प्रस्तुत करें।

(3) योजना का विवेकीकरण होना चाहिए। प्रत्येक राज्य विवेचित आधार पर योजनाएँ तैयार करें। ब्लॉक स्तर पर अथवा किसी अन्य निर्धारित स्तर पर योजनाएँ बनाई जायें। इन योजनाओं पर राज्य-मंत्रिमण्डल विचार करें और राज्य की समन्वित योजना तैयार करें। योजना आयोग प्रत्येक क्षेत्र एवं स्तर से प्राप्त योजनाओं का अध्ययन करे, समन्वित की योजना तैयार करे और फिर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल उस पर विचार करे और निर्णय ले। जिन राज्यों की योजना में कमीती की जाये उसके कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए। इसके विषय यह तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रकार की समन्वित की जाये उसके कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए। इसके विषय यह तर्क दिया जा सकता है कि योजना आयोग प्राथमिकताएँ व्यापक आधार पर योजना तैयार नहीं की जा सकती। इस सम्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि योजना आयोग प्राथमिकताएँ निर्धारित कर दे एवं समाजनों के विषयों में स्थिति स्पष्ट कर दे। तभी सभी वास्तविक आधार पर योजनाएँ प्रस्तुत करेंगे और स्वीकृत एवं साधन प्राप्त होने पर सही ढंग से उन्हें कार्यान्वित करेंगे।

(4) केन्द्र सरकार केन्द्रीय विषयों पर तथा राज्य सरकारें राज्य-विषयों पर योजनाएँ बनाये।

(5) जहाँ से सुझाव माँगे जायें। साधनों की पूर्ति के सुझाव जनता से माँगे जाने चाहिए।

यदि उपर्युक्त आधार पर योजना आयोग कार्य करे तो बहुत-सी समस्याओं का समाधान स्वतः हो सकेगा। राजनीतिक पक्षपात का अवसर समाप्त हो जायेगा और राज्यों को पूर्ण सहभागिता बढ़ेगी, उनका उत्तरदायित्व एवं महत्व बढ़ेगा और जनता भी रुचि ले सकेगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद

(National Development Council)

भारत में योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य लक्ष्य योजना के निर्माण में राष्ट्रीय सहमति का लक्ष्य प्राप्त करना रहा है।

राष्ट्रीय विकास योजना का संगठन

योजना सम्बन्धी मामलों में केन्द्र और राज्यों के मध्य समायोजन (Co-ordination) के लिए योजना आयोग की सिफारिश पर अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में प्रधानमंत्री, केन्द्रीय सरकार के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित होते हैं। यदि किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उपस्थित न हो सके तो उसे अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री की सदस्यता और योजना आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर उनकी स्वीकृति के कारण योजना को राज्यों की ओर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। योजना के निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद से अनिवार्यतः परामर्श लिया जाता है। योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों एवं राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करने के बाद योजना का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वह केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष जो कि सहयोगी सहवाद (Co-operative Federalism) के सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करती है, आवश्यक सुझाव देते प्रस्तुत किया जाता है। बाद में परिषद की सिफारिशों के आधार पर योजनाओं में तथा उनके कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार किया जाता है। इसके बाद मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों के पास शरम्भिक निर्देशों सहित भेज दिया जाता है और उनसे केन्द्रीय योजना निर्माण की वे सभी प्रक्रियाएँ पूरी करवाई जाती हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। योजना-निर्माण की अन्तिम रूप देने से पूर्व मन्त्र परिषद की सिफारिशें ली जाती हैं और तब योजना अपना स्वरूप और आकर्म ग्रहण कर लेती है जिसे बाद में संसद द्वारा स्वीकृति मिलने पर प्रकाशित कर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को योजना-निर्माण के सन्दर्भ में बहुत कुछ निर्णायक भूमिका होती है इसीलिए उसे 'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet) तक कहा जाता है। इसके उच्च स्वरूप के कारण ही इसके परामर्श की केन्द्रीय और राज्य सरकारों महत्व प्रदान करती हैं। परिषद के सदस्य शासकीय नीति के निर्माता होते हैं, अतः योजना आयोग एवं मंत्रिमण्डल द्वारा परिषद के इष्टिकोण की प्राप्ति अवहेलना नहीं की जाती। राष्ट्रीय विकास परिषद का इतना दबदबा होता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री उसके निर्णय की स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अनेक अवसरों पर असहमति के मुद्दे भी उठते हैं जिन्हें आपसी सहयोग से सुलझा लिया जाता रहा है।

राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य

राष्ट्रीय विकास परिषद योजना की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

- (i) समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य-संचालन का पर्यावलोकन करना।
- (ii) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीति-सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।
- (iii) राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपाय सुझाना।
- (iv) जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
- (v) प्रशासनिक सेवाओं की कुरालता में वृद्धि करना।
- (vi) समाज के अल्प-विकसित वर्गों और प्रदेशों के पूर्ण विकास के लिए सहायता का निर्माण करना।
- (vii) समस्त नागरिकों के समान त्याग के द्वारा राष्ट्रीय विकास के लिए सहायता का निर्माण करना।

योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद के पीछे सार्वधानिक या कानूनी सत्ता नहीं होती, किन्तु इसमें सिफारिशों का केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा पालन अवश्य किया जाता है। इसके कार्यों की प्रकृति का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह उन बहुमुखी कार्यों का निष्पादन करती है, जिन्हें योजनाओं के निर्माण तथा उनकी सफल क्रियान्विति के लिए आवश्यक समझा जाता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रकृति

राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रकृति का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं—

(1) राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में सभात्मक व्यवस्था की एक प्रतीक संस्था के रूप में उभर कर सामने आई है। इसमें केन्द्र और राज्यों के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व होता है। यह सभावादी अवधारणा को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करता है।

(2) राष्ट्रीय विकास परिषद 'सहकारी सफवाद' (Co-operative Federalism) की भावना को क्रियान्वित करती है। केन्द्र और राज्यों के बीच योजनाओं के प्रारूप के सम्बन्ध में खुलकर विचार-विमर्श होता है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय मन्त्र है जहाँ सभी पक्ष राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श करते हैं। योजना के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों में उठने वाले विवाद का समाधान हो जाता है। इससे 'सहकारी सफवाद' की भावना सुदृढ़ होती है।

(3) राष्ट्रीय विकास परिषद देश में नियोजन तंत्र की 'शोषण या सर्वोच्च संस्था' है।

(4) राष्ट्रीय विकास परिषद के संगठन का विनियोजन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका राष्ट्रीय स्तर है। इसमें प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इससे सम्पूर्ण राष्ट्र के परिवेश में योजनाओं का निर्माण होता है।

(5) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है और इस परिषद का वह नेतृत्व नियन्त्रण और निर्देशन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की कार्य-प्रणाली पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ रहा है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गान्धी तथा राजीव गान्धी जैसे व्यक्तिगत रूप से परिषद पर पूरा वर्चस्व रहा। यद्यपि इन्दिरा गान्धी के शासन के अन्तिम वर्षों में उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में गैर कठिनीय मुख्यमंत्रियों द्वारा चुनौती दी गई। फिर भी राष्ट्रीय विकास परिषद की गतिविधियों पर उनका वर्चस्व बना रहा। सर्वप्रकार तथा अन्यमतीय शासक का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री की स्थिति राष्ट्रीय विकास परिषद में उतनी सरल और सुदृढ़ नहीं होती है।

(6) राष्ट्रीय विकास परिषद में केन्द्र में सत्ताकण्ड राजनीतिक दल की सक्रिय भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्बन्ध सत्ताकण्ड दल से होता है, फलतः इस परिषद की कार्यवाही को प्रभावित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

(7) राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने-अपने राज्यों के लिए अधिक रिषावतें प्राप्त करने की दृष्टि से दबाव की राजनीति का सहारा लिया जाता है और इसमें शक्तिशाली और जवाबदार रहने वाले मुख्यमंत्री सफल भी रहते हैं।

(8) राष्ट्रीय विकास परिषद का सम्बन्ध देश के नियोजन से है, अतः सामाजिक और आर्थिक विकास करना इसका प्राथमिक तथा सर्वोपरि लक्ष्य है। यह परिषद देश का अधिक विकास करने, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने, क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने, देश में विकास की दूर को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इस तरह से इसकी सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है।

साधारण में, यही कहा जा सकता है कि भारत की संपादन और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रीय विकास परिषद उत्प्रेक्षणीय भूमिका का निर्वाह कर रही है।

उद्घाटन के युग में आयोजना एवं आर्थिक सुधारों के राजनीतिक आयाम

(Planning in the Era of Liberalisation and Political Dimensions of Economic Reforms)

नीचे से योजना का निर्माण—भारत में केन्द्र द्वारा योजना बनाने के साथ-साथ संगठन की निचली इकाइयों की आवश्यकताओं, उनके लक्ष्यों के मूल्यांकन तथा सुझावों के अनुसार सरकार इस योजना में परिवर्तन या समायोजन करती है। विभिन्न राज्यों, जिलों और विकास खण्डों द्वारा योजना के अंश में निर्धारित व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना-निर्माण में उसका समायोजन कर लिया जाता है। उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन काके समन्वित योजना में समायोजन कर लिया जाता है। योजना आयोग राज्यों, जिलों और पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं, प्रस्तावों और कार्यक्रमों की आर्थिक और तकनीकी से सावधानीपूर्वक जाँच करता है और उसके आधार पर समन्वित योजना का निर्माण करता है। इस प्रकार से योजना आयोग द्वारा सभी स्तरों पर योजना निर्माण का कार्य किया जाता है।

नियोजन की तकनीकी और योजना आयोग की भूमिका—भारत में योजना आयोग मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण में जिस तकनीकी का उपयोग करता है, वह निम्नानुसार है—

1. अर्थ-व्यवस्था की स्थिति का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के आधार पर भूतकालीन प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा मुख्य आर्थिक समस्याओं का अनुमान लगाया जाता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न सार्वजनिक और निजी संस्थान सहायता देते हैं। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आँकड़े तैयार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापक मौद्रिक और वित्तीय आँकड़े एकत्रित करता है। योजना आयोग को अनुसंधान कार्यक्रम समिति विभिन्न समस्याओं के बारे में अध्ययन-अनुसंधान करती है। आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन प्रांतीय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा कई अन्य विशिष्ट संस्थाएँ सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक होती हैं। प्रत्येक मन्त्रालय में सांख्यिकी कक्ष होते हैं जो अपने विषय पर सब प्रकार की सूचनाएँ एकत्रित करते हैं। योजना आयोग इन सब स्रोतों द्वारा प्राप्त सांख्यिकीय आधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करता है तथा योजना-निर्माण के कार्य में आगे बढ़ता है।

2. उपयुक्त विशेषण निर्देशन एवं अध्ययन के आधार पर आर्थिक विकास की सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जाता है तथा यह भी देखा जाता है कि विकास की वांछनीय गति क्या होनी चाहिए? नियोजन की माध्य-मोटी प्रारम्भिकताओं और नीतियों के सम्बन्ध में निर्णय किया जाता है। विकास की वांछनीय गति के आधार पर योजनावधि में बचत और विनियोग की आवश्यकताओं पर निर्णय लिया जाता है। यह सब कुछ करने के बाद वित्तीय साधनों की छानबीन की जाती है। निजी क्षेत्र के वित्तीय साधनों का अनुमान रिजर्व बैंक द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के साधनों का अनुमान योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है।

3. नियोजन तकनीक में मुख्य आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके निर्धारण में उपलब्ध समय तथा भौतिक और वित्तीय दोनों दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। इन दोनों ही उद्देश्यों में समायोजन किया जाता है।

4. मुख्य उद्देश्यों के निर्धारण के बाद विभिन्न क्षेत्रों, यथा—कृषि, उद्योग, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यह काम कार्यकारी दल (Working Groups) करते हैं। तत्पश्चात् योजना आयोग सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के इन लक्ष्यों को उपयुक्तता की जाँच करता है और देखता है कि इनमें परस्पर असंगति तो नहीं है।

5. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्यों के निर्धारण के बाद इन सबको समन्वित किया जाता है और उनकी तुलना मूल अनुमानों से की जाती है। उपलब्ध पूंजीगत साधनों और विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में लक्ष्यों का विचार किया जाता है। तदनुसार लक्ष्यों को अधिक गतिशील बनाने या लक्ष्यों को घटाने-बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है। योजना का सभी पहलुओं पर पूरा विचार विमर्श करके सरकार और योजना आयोग द्वारा योजना का नैतिक बाजना के अन्तर्गत योजना के क्षेत्र विनियोगों के आवश्यक प्रारम्भिकताओं के निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं और योजना का अन्तिम रूप दे दिया जाता है।

समवाद पर नियोजन का प्रभाव (Impact of Planning on Federalism)

भारतीय समवाद पर नियोजन के सम्बन्ध में विभिन्न मत पार् जते हैं। आर्येक चन्दा के अनुसार योजना आयोग ने समवाद का स्थान ले लिया (Suprecede) है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है और इसे प्रभावित करने में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में सम्पूर्ण नियोजन इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय योजना कर्षणीय होती है और राज्यीय योजनाएँ भी। इस प्रकार राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है और प्रत्येक स्वतन्त्रीय हितों की भी। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि दोनों एक-दूसरे को पूरा करें। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति से केन्द्रीकरण को कुछ बढ़ावा मिलता है और केन्द्र-राज्य सम्बन्ध एकात्मकता के लक्षणों से प्रभावित होते हैं। समवाद पर नियोजन के प्रभाव को अध्ययन की सुविधा से निम्नलिखित बिन्दुओं में विभाजित किया जा सकता है—

1. नियोजन की विषय-वस्तु की प्रकृति—भारत जैसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत शासन का विषय केन्द्र और राज्यों के मध्य विभक्त होते हैं, अतः किसी राष्ट्र-व्यापी नियोजन में राज्यों को 'केन्द्रीय निर्देशों' को ग्रहण प्रारम्भिकता देनी पड़ती है। शासन के सभी विषयों पर योजना आयोग योजना बनाता है अर्थात् राज्य-स्तर के विषयों पर उसका एक सीमा तक अधिकार होता है। इस प्रकार योजना आयोग के माध्यम से देश में एकात्मकता की प्रवृत्ति का विकास होना स्वाभाविक है।

2. योजना-निर्माण का स्वयम्—भारत में राज्यों की समस्याएँ अलग-अलग हैं और उनके निष्कर्षों के निर्माण होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुसंख्यी समस्याएँ केन्द्र और राज्यों में सांख्यिक समान प्रकृति की हैं अतः इस प्रकार की समस्याओं के निष्कर्षों में केन्द्र की अध्यक्षता अथवा अधिक महत्वपूर्ण रहनी है। योजना-प्रकार का अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सार्व के अधिकार में है। राज्यों के पास अपने प्रकृष्ट योजना-बोर्ड नहीं है, अतः केन्द्र द्वारा स्थापित और शक्तिशाली योजना आयोग का राज्य सरकारों पर प्रबल प्रभाव होता है। प्रारम्भिक सुधार आयोग ने राज्यों में योजना बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य इस आकांक्षा से सहमत नहीं हुए कि योजना बोर्ड की राज्य में 'समानता' सरकार जैसी शक्ति प्राप्त न कर ले। योजना-निर्माण प्रक्रिया से यह स्पष्ट स्पष्ट है कि राज्य-सरकार का प्रबल विचार विमर्श किया जाता है और इस बात में अन्तिम निर्णय लेते समय राज्य के मुख्यमन्त्रियों को सलाह का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार, राष्ट्रीय केन्द्र की प्रमुखता होती है, तथापि राज्यों की सलाह की उत्तरा भी नहीं की जाती। केन्द्र 'मिथुन' नहीं बनाता बल्कि 'अंगुली' अवश्य बना रहता है। वह नियम 'देने' की अपेक्षा 'कुरान' नेतृत्व करता है।

3. राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रभाव—राज्य सम्बन्धी मन्त्रियों में केन्द्र और राज्यों के मध्य समन्वयन अथवा समन्वय (Co-ordination) स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है। योजना का निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद से अनिवार्य परामर्श लिया जाता है। योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मन्त्रियों एवं राज्य-सरकारों

में परामर्श करने के बाद योजना का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वह केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष आयाज्यक सुझाव हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

4. योजना आयोग की सदस्यता—प्रधानमंत्री आयोग की अध्यक्षता करता है। इसका एक उपाध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा कतिपय विशेषज्ञ व्यक्तियों को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। आयोग की रचना भारतीय सप्ताह के केन्द्र के अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

5. वित्तीय पहलू—यद्यपि आयोग अपनी प्राथमिकताओं को राज्यों पर अपनी वित्तीय शक्ति के आधार पर थोपने में सक्षम है, तथापि सामान्य प्रवृत्ति 'सहयोग और सहमति' की रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है वह इतनी अधिक मात्रा में होती है कि प्रारम्भिक स्तर पर कोई राज्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता है। राज्य सरकारों किस स्तर तक केन्द्रीय अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। योजनाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं— प्रथम, राज्य योजनाएँ जिनके लिए केन्द्र कुछ आर्थिक सहायता देता है, द्वितीय केन्द्र निर्मित और अनुदानित योजनाएँ जिनमें राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में लागू करना पड़ता है और केन्द्र से श्रम धन-राशि का उपयोग उन योजनाओं को पूरा करने में करते हैं तथा जो धन प्रदान करता है उसकी नीति माननी पड़ती है। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आप भोत बढ़ाने की माँग करते हैं। समय-समय पर वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन केन्द्र का कष्ट सामान्यतः सहानुभूतिपूर्ण रहा है। दूसरी ओर राज्यों की एक बड़ी कमी यह रही है कि वे उपलब्ध वित्तीय साधनों का समुचित उपयोग नहीं कर सके हैं। राज्यों ने अपने प्रशासनिक व्यय में अनाप-रनाप वृद्धि की है, किन्तु केन्द्र की सहायता पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया है। राज्यों को वित्तीय शक्तों की दृष्टि से केन्द्र पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, अतः स्वायत्तता के लक्षणों का विकास हुआ है जिससे सप्ताह की वास्तविक प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

6. अन्य दृष्टियों से केन्द्र की साधन-सम्पत्तय—इन सब के अतिरिक्त परामर्श, तकनीकी विशेषज्ञता आदि विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की तुलना में केन्द्र बहुत अधिक सम्पन्न है, अतः योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के सन्दर्भ में राज्य केन्द्र पर निर्भर करते हैं।

7. राष्ट्रीय नीति—सविधान में निहित राज्य-नीति के निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। राष्ट्रीय नीति का अनुपालन करने से राज्य इनकार नहीं कर सकते हैं अतः केन्द्र निर्मित और केन्द्र निर्देशित योजनाओं को राज्यों को स्वीकार करना पड़ता है।

8. विदेशी सहायता सम्बन्धी पहलू—योजनाओं के कुछ पक्षों की पूर्ति के लिए जो विदेशी सहायता ली जाती है, उसके समुचित उपयोग का दायित्व केन्द्र सरकार पर हो है। विदेशी सहायता का कुशल उपयोग हो, इसके लिए केन्द्र के पास राज्यों को समुचित निर्देश देने का अधिकार रहता है।

9. योजना का कार्यान्वयन—राज्य केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने वाले अधिकरण हैं। राष्ट्रीय योजना की क्रियान्विति के लिए केन्द्र राज्यों को दिशा-निर्देशन देता है और राज्यों में देखभाल के लिए विभिन्न नियुक्तियाँ करता है, जैसे—विकास आयुक्त आदि। इसीलिए प्रायः राज्य किसी भी असफलता का दायित्व केन्द्र पर डालने का प्रयास करता है। योजना आयोग अपनी नीतियों में एकपक्षता लाने की कोशिश करता है, यद्यपि यह एक अति कठिन कार्य होता है, क्योंकि मलग-मलग समस्याएँ होती हैं। अपने कर्तव्यों के अनुपालन में योजना आयोग को एक परामर्शदात्री समझा के रूप में कार्य करने के साथ-साथ कुछ कार्यकारी कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। वास्तव में नियोजन द्वारा यह एक छोटी प्रशासकीय मशीनरी की स्थापना हुई है।

योजना का क्रियान्वयन तथा आर्थिक नियोजन के प्रशासकीय परिणाम

योजना के क्रियान्वयन तथा आर्थिक नियोजन के प्रशासकीय परिणामों का सार रूप में संकेत करते हुए डॉ. सी. पी. भाम्नी लिखते हैं—“योजना के निर्माण के बाद उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रशासकीय विभागों पर आती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योजना भी निर्णयक है, यदि उसे उचित रूप से क्रियान्वित न किया जा सके। योजना में सर्वाधिक बल क्रियान्वयन, व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने में गति एवं पूर्णता तथा अधिकतम उत्पादन, रोजगार एवं मानवीय श्रोतों के विकास के लिए पारंगत परिस्थितियों पैदा करने पर होना चाहिए।”

आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप भारतीय प्रशासनिक दृष्टि को शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण चुनौती मिली है। भारत में लोक प्रशासन की गतिविधियों का क्षेत्र तथा उनके दायित्वों का क्षेत्राधिकार निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में प्रशासन को उसके समस्त उपस्थित होने वाली चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

यद्यपि योजना के सम्बन्ध में भारत में सन्तोष व्यक्त किया गया है, तथापि योजना के क्रियान्वयन के दौरान उपस्थित होने वाली कठिनाइयों के लिए प्रशासनिक अक्षमता, विसंगत अक्षर्यकुशलता तथा दोषपूर्ण कार्य-प्रणाली, इत्यादि उत्पत्तायी

कारण है। जिनमें मुख्य दोष निम्नलिखित हैं—(अ) क्रियाबन्धन की मन्द गति (ब) समय-संज्ञा का ठन्ढापन एवं खर्च में कटि (स) उचित स्तर तथा अनुपब बतने प्ररिस्थित कर्मचारी वर्ग का अपभ्य (द) अर्थव्यवस्था के परस्पर सम्बन्ध क्षेत्रों में विस्तृत समायोजन का अपभ्य (ए) समाज के व्यपक समर्पन एवं सहयोग प्ररि में असम्पन्नता। इन दोषों को समाय करने के लिए नई कार्य-प्रणालियों बननी आवश्यक है जिसमें कि देश प्ररासनिक यन्त्र एवं आर्थिक नियोजन की पुर्नरी का सम्मना कर सके। इसके लिए निम्नलिखित प्ररासनिक सुधार आवश्यक प्रतीय हेतु हैं—(क) कार्य-प्रणालियों का सरलीकरण (ख) विनय की प्रवृत्ति का ठन्ढापन (ग) व्यक्तिगत दायित्व का उचित स्पष्टीकरण (घ) काम के खर्च में कमी (ङ) प्ररासनिक अनुसंधान तथा मूल्यांकन पर उचित बन् (च) वित्त मन्त्रालय को कार्य-प्रणालियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन (छ) मन्त्रालय की वित्तीय शक्तियों का अधिक हस्तान्तरण (ज) बजट पूर्व निर्णयों पर बन् (झ) मन्त्रालयों का पुर्नगठन (ञ) भारत सरकार के मन्त्रालयों तथा विभागों में श्रेष्ठतर समायोजन (ट) जन-सम्पर्क का विकास (ण) निर्णय लेन का प्रक्रिया में गतिशीलता (द) सिविल अधिकारियों का उचित प्ररिस्था (इ) लोक प्ररासन में नेतृत्व के योगदान पर उचित बन् (ण) प्रत्येक स्तर पर कार्य को उचित तथा प्रभावरानी देखरेख (त) प्ररासन में रणनीति की भावना पर बन् (थ) प्ररासन में स्पष्ट व्यवस्था के महत्व की अनुपुति (द) सार्वजनिकजीवी को बल करने के साधनों का विकास इत्यादि। य एवं प्ररासनिक सुधार योजना के क्रियाबन्धन को सफल बनने में सहायता देंगे।

नियोजन प्रणाली की अन्वेषणा

भारत में नियोजन प्रणाली की अनेक अपारों पर अन्वेषणा की जाती है। नियोजन स लोकायुक्त की प्रतिकूल दृष्टि से प्रभावित होता है। योजना के निर्माण में जनता का कोई सहयोग नहीं है। समद निष्पत्ति है तथा मन्त्रिपरिषद् के नियम भी प्रभावित होते हैं। मन्त्रालय स्वेच्छा से कार्य करने में असमर्थ हैं यदि दृष्टि लोकायुक्त का दिव्यता मात्र बना देते हैं। इस लक्ष्य की अतिम स्वीकृति समद ही प्रदान करती है, पानु स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं करती। योजना अपाग का कोई ठसरदायित्व नहीं है। प्रयत्न का अपार विकेन्द्रिकरण है केन्द्रोपकरण नहीं। आर्थिक नियोजन से वित्त अपाग के निर्णय प्रभावित होते हैं इससे इस अपाग का महत्व कम हो जाता है।

आर्थिक नियोजन ने राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रतिकूल दृष्टि से प्रभावित किया है। यद्यपि सहाय्य विकेन्द्रिकरण का पर्यायवाची है, यद्यपि केन्द्रोपकृत नियोजन ने राज्य सरकारों की स्थिति को नगण्यनिष्ठ के सदृश्य बना दिया है। भारतीय सभ में शक्ति विभाजन केन्द्र के पक्ष में है। राज्य पहल से ही असहाय हैं, शक्ति और सभन रूचि है और उनका महत्व नगण्य है। योजना अपाग ने उन्हें पूर्णतः निष्पन्न बना दिया है। योजना के निर्माण में वह सहभागी नहीं है फिर अपने क्षेत्र में वह क्या करके दिखा सकते हैं? यदि राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं तो केन्द्र राज्य सम्बन्ध विषयों का रूप धारण कर लेते हैं। केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण स्वभाविक रूप से पक्षनपूर्ण हो जाता है और वह प्रत्यक्ष सम्भव उपाय से राज्य सरकार की अनुपलब्ध सिद्ध करने का प्रयत्न करती है। इस काम को दूर करने के लिए 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की स्थापना की गई है। यह परिषद् ही योजना को स्वीकृति प्रदान करती है।

योजना अपाग के कारण केन्द्रोपकरण की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि हुई है जिसके कारण जनसहभागिता का प्रदान समाप्त हो जाता है। वास्तविकता यह है कि कई योजनाएँ तो बनती हैं, किन्तु जो सभ जनता को प्राप्त होने चाहिए वे प्राप्त नहीं हुए। आर्थिक विपन्नता में कमी नहीं आई किन्तु वृद्धि हुई है। ऐश्वर्य असन्तुलन एवं विपन्नता बढ़ी है। गणराज्य का रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रविष्ट अँकड़ों की दृष्टि से घटा है किन्तु व्यवहार में वह देखने का नहीं मिलता। बेरोजगारी की सख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय सभ में वृद्धि हुई है किन्तु मूल्यों में वृद्धि का कारण उसका मुख साधारण जनता को नहीं मिला है। व्यक्तिगत आय की स्थिति भी कुछ भिन्न नहीं है अतः वह नहीं क्या कर सकता है कि योजनाएँ अपने उद्देश्य में सफल हुई हैं, किन्तु यह कहना असत्य ही होगा कि योजनाएँ पूर्णतः विफल हुई हैं। जनता के कुछ क्षेत्रों में निरक्षरता घटित हुई है औद्योगिकता हुआ है उत्पादन में वृद्धि हुई है खेती में उत्पन्न-निर्माण घटा हुआ है। फिर भी अनेक समस्याएँ परिलक्षित होती हैं।

भारत में नियोजन की समस्याएँ—व्यवहार में भारत में नियोजन सन्धियों निम्नलिखित समस्याएँ उभर कर सामने आई हैं—

1. यद्यपि भारत में योजनाओं का निर्माण लोक-समन्वयक और बड़े विरोधों द्वारा किया जाता है तथापि इनके बावजूद भी ये योजनाएँ जनता के असहयोग एवं उदात्तता के कारण सफल नहीं हो पाती। सामान्य जनता का कार्य के प्रति बहुत अधिक उदात्तता है।
2. सरकारी अधिकारियों द्वारा जनता को सार्वजनिक समस्याओं से अवगत कराने का प्रयत्न नहीं किया जाता है।
3. भारतीय जनता के नैतिक चरित्र में बहुत अधिक निष्पक्षता आ रही है। जन प्रतिक्रियाओं में व्यक्तिगत भेदभाव एवं शक्ति का दुरुपयोग यदि अनेक कारणों से योजनाओं के विकास में आ रहा है।

4 योजना आयोग के समय तथ्य और आँकड़े तो होते हैं, वे काफी हद तक मिथ्या होते हैं। इन आँकड़ों के कारण सारी योजनाएँ असफल हो जाती हैं तथा योजना के वास्तविक लक्ष्य धूमिल हो जाते हैं।

5 भारत में सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर पाया जाता है। योजना-निर्माताओं के सामने विदेशी कल्पनाएँ और उच्च आदर्श होते हैं जो कि भारतीय यथार्थ से कहीं अधिक दूर होते हैं। योजना के क्रियान्वयन के समय सारी कठिनाइयाँ सामने आने लगती हैं।

6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हर वर्ष सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा होता है। इनकी हानि को कम करने के लिए दौरे बढ़ाई जाती हैं जिसका कुप्रभाव अन्य उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ता है। फलतः ये उपक्रम 'सफेद हानी' सिद्ध हो रहे हैं।

7 विकास कार्यों हेतु योजनाओं में निर्धारित राशि का शहरों पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है। गाँवों में बहुत कम विकास किए जाने के कारण ग्रामीण लोगों को पर्याप्त लाभ नहीं पहुँचता। चूंकि ग्रामीण लोग उपेक्षित हैं, फलतः ग्रामीण साग देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं।

8 उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाओं में निर्धारित धन का 40 से 50 प्रतिशत धन ही वास्तव में खर्च हो पाता है। शेष धन नेता, इन्जिनियर, टेक्निकल कर्मचारियों आदि को जेबों में चला जाता है। इससे जनसाधारण को योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है और अन्तर ही अन्तर भ्रष्टाचार फैलता रहता है।

9 उत्पादन का 50 से 60 प्रतिशत तक पाग उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

10 प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ों, सूखे, अकाल और महामारियों के कारण उत्पादन ठप्प हो जाता है।

निम्न अवस्था समस्या निवारण के उपाय

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है अतः कुछ ऐसे कदम उठाए जाने आवश्यक हैं जिनसे योजनाओं के लक्ष्यों को साकार किया जा सके। इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम अपेक्षित रहेंगे—

1 योजना की कार्य प्रणाली को सरल बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में वित्तसम्बन्धी प्रवृत्ति को दूर किया जाना चाहिए।

2 नियोजन में विभिन्न उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, जिससे कि उत्तरदायी व्यक्ति या संस्था का आसानी से पता लगाया जा सके।

3 प्रशासन में आवश्यकता से अधिक व्यय किया जाता है अतः प्रशासन में अनावश्यक व्यय पर कठोरता से नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए।

4 प्रशासन में द्रुत-गति से अनुसंधान किया जाना चाहिए। अनुसंधान के परिणाम तबिल मूल्यीकृत किया जाना चाहिए।

5 जनसम्पर्क का कार्य प्रभावशाली ढंग से सम्पादित किया जाना चाहिए। इससे जनता का योजनाओं की सफलताओं में सहयोग मिल सकेगा और उनकी योजनाओं में रुचि पैदा हो सकेगी।

6 नीकराशी में अनुशासन और ईमानदारी की भावना का विकास करना चाहिए, क्योंकि उस पर ही योजना को सफलता निर्भर करती है।

7 योजना कार्यों का प्रभावशाली सम्पादन तथा निरीक्षण किया जाना चाहिए।

8 प्राकृतिक साधनों के विदोहन पर पूरा ध्यान देना चाहिए और ऐसे कुशल प्रबन्धक वर्ग का विकास करना आवश्यक है जो योजनाओं के धन से इन साधनों का देश के विकास हेतु समुचित प्रयोग कर सकें।

9 सार्वजनिक उपक्रम यदि लाभ और कुशलता से चलते जाएँ तो इनसे प्राप्त स्थापों से देश को विकास-न्दर को बढ़ाया जा सकता है।

10. योजनाओं में व्यय हेतु रखा गया धन यदि यथासमय व्यय किया जाए तो उत्पादन की वृद्धि दर 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित धन के सदुपयोग हेतु भ्रष्टाचार का अमूलन आवश्यक है जो सर्वप्रथम ऊपर अर्थात् जन प्रतिनिधि स्तर से ही प्रारम्भ होना चाहिए।

11 भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है अतः जनसंख्या नियन्त्रण अत्यावश्यक है।

12 बिजली, कच्चा माल, औद्योगिक शक्ति आदि को प्रभावो सुविधाएँ प्रदान की जाएँ कि उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

13 देश में बहने वाली नदियों के पानी की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि बाढ़ या सूखे का प्रभाव अर्धव्यवस्था पर न पड़े तथा देश के सभी राज्यों की जनता को उसका लाभ मिले। किसी का एकाधिकार न रहे।

14. विकसित उत्पादक तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके।
15. मूल्य-वृद्धि पर सख्त तथा प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रण किया जाना चाहिए।
16. गैर विकास व्यय को मात्रा घटाकर विकास व्यय को बढ़ाया जाना चाहिए।
17. वित्तासिता को जगह आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि पर जोर देना चाहिए और योजनाओं में परिचयी देशों का अन्धानुकरण पूरी तरह त्यागना चाहिए।

18. विदेशी सहायता पर निर्भरता कम की जानी चाहिए।

19. सभी स्तरों पर व्यापक प्रशासनिक ढंग से समाव किया जाना चाहिए।

बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में उदात्तकरण के कारण घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर आए परिवर्तनों को छाँव में भारत के वित्तीय क्षेत्र में प्रारम्भ किए गए सुधारों का उद्देश्य भारत के वित्तीय क्षेत्र में पिछले दशकों में आई कमगैरियों का पता लगाकर बैंकों एवं विकास वित्त संस्थानों की लाभ प्रदत्तता को बढ़ाते हुए उनकी वित्तीय स्थिति तथा परिचालनात्मक पारदर्शिता और कार्यकारी दक्षता साबित करने औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र के विकास तथा परिमाण में उत्सर्जित कारोबार परिमाण को उत्तरता के साथ संभाल लेने लायक बनाते हुए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में प्रतिस्थापित करना था। इस दिशा में विशेषज्ञों के विचार जानने के लिए निम्नांकित समितियाँ गठित की गई—

(1) वित्तीय क्षेत्र हेतु सुधारों पर नरसिंहम समिति, 1991

(2) बैंकिंग क्षेत्र में सेवा सुधारों पर गोहोपेरिया समिति, 1992

(3) बैंकों एवं विकास संस्थानों की एकरूपता तथा एकीकरण पर खान समिति, 1998

(4) गैर निष्पादनीय आस्तियों पर सेल्चय समिति, 1998

(5) कमजोर बैंकों की पुनर्गठना पर वर्मा समिति, 1999

इन समितियों की सिफारिशों को कड़ी पूर्णरूपेण तो यहाँ आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार लागू किए गए हैं, उनके परिणामस्वरूप काफी सुधार हुआ है। फिर भी अभी तक ये चुनौतियाँ देश में विद्यमान हैं—

(1) बैंकों के पास उपलब्ध उच्च तरलता तथा बड़ी मात्रा में अल्प साख मॉग के बीच परस्पर विरोधाभास।

(2) उपार देने से उत्पन्न व्यवधान।

(3) राजनीतिक हस्तक्षेप।

(4) नौकरशाही की मजबूत पकड़।

(5) औद्योगिक सम्बन्धों की जटिलता।

(6) नियन्त्रक और मालिक की दोहरी भूमिका में रिजर्व बैंक।

(7) निरपेक्ष रूप से गैर निष्पादनीय आस्तियों का उच्च स्तर।

(8) ऋण देने के प्रति बैंक अधिकारियों का उदासीन व्यवहार।

(9) वेजी से विकास वाली सूचना प्रौद्योगिकी, पचासवीं राज्यावली राज संस्थाओं आदि को साख मुहैया करने में उदासीनता।

इन चुनौतियों का सामना किए बिना वित्तीय क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का भला नहीं कर सकता है। जहाँ तक राष्ट्रीय आय का प्रश्न है वर्ष 2003-2004 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 1999-2000 में 209.8 मिलियन टन, 2000-2001 में 195.9 मिलियन टन एवं वर्ष 2001-02 में 209.2 मिलियन टन रहा तथा वर्ष 2003-04 में भी यह लगभग 210.0 मिलियन टन ही रहा। वर्ष 2003-04 में देश में मूल्यों की स्थिति निम्नलिखित रही। भारत पर कुल विदेशी ऋण सितम्बर, 2004 में 5,11,861 करोड़ रुपये था। भारत को कम ऋणदात राज्यों की सूची में विश्व बैंक ने अनुसूचित किया है।

आधार स्तर पर प्रजातन्त्र (Democracy of Grassroots)

भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की संैदानिक अवधारणा को व्यवहार में 'पंचायती राज' व्यवस्था एवं जनसहभागिता के द्वारा साकार किया गया है।

पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System)

भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पंचायती राज की परिकल्पना केवल स्वतंत्र भारत की ही उपज है बल्कि इसकी जड़े इतिहास में निहित हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के अनुसार वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। उस जमाने में राजा पंचायतों के माध्यम से राज करता था। ग्राम के प्रमुख को उस समय ग्रामिणी कहा जाता था तथा ग्रामिणी ही पंचायत का प्रमुख कार्यकर्ता होता था। बौद्धकाल में भी ग्राम परिषद होने का उल्लेख मिलता है। बौद्धकालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि ग्राम परिषदों का प्रमुख कार्य ग्राम भूमि की व्यवस्था करना, शान्ति एवं सुरक्षा में सहयोग करना था। स्मृति ग्रन्थों में भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इस तरह वैदिक एवं बौद्धकाल में पंचायतें प्राचीन जनहित के कार्यों में सलग थीं। रामायण एवं महाभारत काल में इनका विस्तार एवं विकास हो चुका था। पंचायतें गाँव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हुआ करती थीं, लेकिन इतना अवश्य है कि वर्तमान पंचायती राज की कल्पना स्वाधीनता सपनों के दौरान रहो गई थी। महात्मा गाँधी के स्वराज्य की अवधारणा में पंचायती राज व्यवस्था को परिकल्पना निहित थी।

भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज की धारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा गया है—“राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।”

पंचायती राज व्यवस्था के सिद्धान्त—भारत में पंचायती राज व्यवस्था के सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(1) भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। सत्ता को दिल्ली की लोकसभा अथवा राज्यों के विधान मण्डलों तक ही यदि सीमित रखा जाए तो देश समृद्ध नहीं हो सकता, अतः यह आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर गाँव से जिला और स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढाँचा बनाया जाए। इस व्यवस्था से देश का हर गाँव और गाँव का हर परिवार दिल्ली की लोकसभा से जुड़ जाएगा।

(2) पंचायती राज की संस्थाएँ सामुदायिक विकास की एजेंसी बनें सहकारिता को प्रोत्साहन दें, स्वयं की कोई नीति न बनाकर सरकारी नीति को काम में लाएँ।

(3) सरकार अपने कुछ कार्यों का दायित्व ऐसी संस्थाओं को दे जो अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए स्व-प्रेरणा से काम लें। इसके लिए उन्हें समुचित अधिकार प्रदान किए जाएँ।

(4) संस्थाओं को काम करने के लिए साधन और नियंत्रण के इतने अधिकार दिए जाएँ कि वे सौंपे गए कार्यों को समुचित रूप से कर सकें।

(5) इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि भविष्य में अधिकार सौंपने में सुविधा हो।

स्वातंत्र्यता के पश्चात् पंचायती राज के स्वरूप के विकास में बलवन्तराय मेहता समिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी सिफारिशों के आधार पर देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था—जिला परिषद, पंचायत समिति

और ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया। इस तरह से देश में पंचायती राज व्यवस्था का जो सम्पादन हो चुका है, वह बलवत्तरूप में ही समिति के अनुरूप है। 1957 में बलवत्तरूप में ही समिति ने अपना प्रतिवेदन पारित सरकार के समुचित प्रस्तुत किया और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस पर स्वीकृति प्रदान की। लोकार्गनिक विकेन्द्रीकरण को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। राजस्थान पहला राज्य था, जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू ने नगौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया।

1. 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज का मूल्यांकन करने के लिए अरोक्त मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में बिहारी पण्डित तथा टर्मिनाद के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य तथा सत्तद सदस्य शामिल थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रो. इन्द्रबल गहलोत को इस समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। इस समिति ने सारे देश में घूमकर पंचायती राज के सम्बन्ध में बीजक के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ विचार-विमर्श किया। इसके अलावा समिति ने एक प्रस्तावनी भी की, जिसे पंचायती राज में शीघ्र रखने वाले लोगों के पास भेजी। समिति को एक हप्ता से अधिक उम्र प्राप्त हुई। इस समिति ने 21 अगस्त 1978 को अपनी रिपोर्ट उल्लेखनीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को प्रस्तुत की। समिति ने पंचायती राज के विविध पक्षों पर विस्तार में अपनी 132 सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इनमें मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं—

(1) समिति ने 'महान पंचायती' के निर्माण को सिफारिश की जिसमें 15,000 से 20,000 की अवधि और 10-15 गाँव शामिल हों।

(2) जिन्हा स्तर पर 'योजना सेल' हों, जिसमें एक अध्यक्ष, सचिव, वित्त, धन, मानविकी, कृषि, शाली, इन्फ्रा और कम योजना अधिकारी हों।

(3) यह इकाई जिन्हा परिषद के अन्तर्गत होगी और इसका प्रबन्धन मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा।

(4) विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की योजना तैयार करना जिन्हा परिषदों की जिम्मेदारी होगी और उनका कार्यान्वयन महान पंचायती की जिम्मेदारी होगी।

(5) पंचायती राज निधियों का चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

अरोक्त मेहता समिति की ये सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण थीं लेकिन व्यवहार में इनको लागू नहीं किया गया, अतः इनका केवल 'अभ्युक्ति महत्व' ही रह गया।

2. बी. के. राज की अध्यक्षता में गठित समिति का भी पंचायती राज व्यवस्था की दृष्टि से महत्व है। इसकी सिफारिशें ये थीं—

(1) राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होनी चाहिए, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री हों। जिन्हा स्तर पर मंडला विस्तार परीक्षा करी रहे। राज्य सरकार के सभी मंत्री और जिन्हा परिषद के अध्यक्ष राज्य विकास परिषद के सदस्य होंगे और विकास आयुक्त इसके सचिव हो सकते हैं।

(2) जिला स्तर पर जिन्हा परिषद के समस्त कार्य का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। जिन्हा स्तर पर सभी विकास विभाग उनके अधिकार क्षेत्रों में ही जिन्हा परिषद के अधीन स्तर पर रहेंगे। जिला स्तर का बजट बनाने के लिए इन विभागों में समुचित बजट प्रवर्धन का हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

(3) एक समूह में, खास स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निष्पक्ष अर्थात् पंचायत समिति हनी चाहिए, जो जिन्हा परिषद के मार्ग-निर्देशन में विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हो। क्षेत्रीय विभाग खास स्तर पर पंचायत समिति के अधीन कार्य करेंगे। योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायत समिति के कार्यकारी कार्य रहने चाहिए।

(4) दूसरा समूह वर्तमान ग्राम पंचायतों के बढ़ने 15,000 से 20,000 तक की अवधि के गाँवों के समूह के लिए महान पंचायत का गठन है। यह एक कार्यकारी निष्पक्ष होगी, जिसे इस स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की सूची होगी। राज्य इस समूह के अन्तर्गत सहायक और सम्बन्धित निष्पक्ष के रूप में खास स्तर पर पंचायत समिति भी बना सकता है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए अलग की व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) प्रत्येक गाँव के लिए एक ग्राम सभा होनी चाहिए, जिसमें उस गाँव के सभी सदस्य मतदाता हों। गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों जैसे—एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा की बैठकों में होनी चाहिए।

(6) ग्राम पंचायत समिति और ग्राम मण्डल की उप-समिति होनी चाहिए जिसमें महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों और योजनाओं पर विचार करने एवं उनका कार्यान्वयन करने के लिए मुख्य रूप से महिला सदस्य हों।

राज-समिति की ठकठ शिकायतों परापूर्व राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं, लेकिन इनका भी व्यवहार में क्रियान्वयन नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री रास्ट्रेय गौथी हाउस देश में पंचायती राज को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए 1989 में संविधान में संशोधन करने का एक विशेषक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जो पारित नहीं किया जा सका। 1991 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस (छ) ने चुनावी घोषणापत्र में पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य के अनुरूप नरसिम्ह राव की कांग्रेस (छ) सरकार ने सितम्बर 1991 में संविधान का बहतरवाँ संशोधन विशेषक 1991 लोकसभा में पेश किया, जिसे विचारार्थ संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा ने 22 दिसम्बर, 1992 को इसे स्वीकृति दी। 23 दिसम्बर, 1992 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद 17 राज्यों की विधानसभाओं ने इस विशेषक का अनुमोदन कर दिया। फलतः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर इसे 24 अक्टूबर, 1993 से अधिनियमित कर दिया गया और इसे संविधान के 73वाँ संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। 25 अक्टूबर 1993 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इस संविधान का मूल पाठ निम्नानुसार है—

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

संक्षिप्त नाम और शीर्षक—भारतीय गणराज्य के तैत्तलीसवें वर्ष में संसद द्वारा निर्मित लिखित रूप में यह अधिनियम हो—

- (क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान वेदताली संशोधन अधिनियम, 1992 है।
- (ख) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- संविधान के भाग 8 के पञ्चाद निम्नलिखित भाग अदस्तापित किया जाएगा अर्थात्—

'भाग 9' पंचायतों

243 इस भाग में जब तक कि सदर्थ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- 'जिला' से किसी राज्य का जिस है,
- 'ग्राम सभा' से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में राजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है,
- 'मध्यवर्ती स्तर' से ग्राम और जिला स्तरों के मध्य का ऐसा स्तर है जो किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर विनिर्दिष्ट किया जाए,
- 'पंचायत' से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243-ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (पहले वह किसी भी नाम से ज्ञात हो), अधिप्रेत है,
- 'पञ्चायत क्षेत्र' से पञ्चायत का प्रादेशिक क्षेत्र अधिप्रेत है,
- 'जनसंख्या' से ऐसी अतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अनिश्चित की गई जनसंख्या है जिसके आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं,
- 'ग्राम' से राज्य द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम है और इसके अन्तर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।

243 क ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे मूल्यों का निर्वहन कर सकेगी, जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा उपबन्धित किए जावें।

पंचायतों का गठन

243 ख(1) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबन्धों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अल्पसंख्यकों के पदों की कुल संख्या एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी;

परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगी।

(5) खण्ड (1) और खण्ड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अल्पसंख्यकों के पदों के लिए आरक्षण (जो महिलाओं के आरक्षण से भिन्न) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मण्डल को किसी स्तर पर किसी पंचायत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में स्थानों के या पंचायतों के अल्पसंख्यकों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

पंचायतों का कार्यकाल

243 ड (1) प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ठहरे पहले से ही विघटित नहीं कर दिया जाता है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन किसी स्तर पर ऐसी प्रजापत का जो ऐसे संशोधन के पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटित नहीं करेगा, जब तक खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाता।

(3) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन—

(क) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व,

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा किया जाएगा;

परन्तु जहाँ वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कठिन आवश्यक नहीं होगा।

(4) पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पंचायत के विघटन पर गठित की गई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित पंचायत खण्ड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

सदस्यता के लिए निर्वाह

243 य (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के लिए निर्हित होगा—

(क) यदि वह सम्बन्धित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है, परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्हित नहीं होगा कि ठमकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि पंचायत का कोई सदस्य खण्ड (1) में वर्णित किन्हीं निर्वाहों से प्रस्ता हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जैसा राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबन्धित करे, विनिराज्य के लिए निर्देशित किया जाएगा।

पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

246 छ सविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्थायित शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर देखे सार्वों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे—

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना,

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएँ, जिसके अन्तर्गत वे स्कीमों भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं क्रियान्वित करना।

पचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पचायतों की नियियाँ

243 अ राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा—

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे कर, शुल्क, पदकर और घाँस उदगृहीत, मगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पचायत को प्राधिकृत कर सकेगा,

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा उदगृहीत और मगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पदकर और घाँसों किसी पचायत को दे सकेगा,

(ग) पचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबन्ध कर सकेगा और

(घ) पचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनो के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा, जो विधि में निर्दिष्ट किए जाएँ या की जाएँ।
जिनियम स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए विन आयोग का गठन

243 इ (1) राज्य का राज्यपाल, सचिवन का टेहतरवाँ सचिवन अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर पचायतों को और उसके पचायत प्रदेक पाँचवें वर्ष के उपरान्त पर, पचायतों की विनियम स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और—

(क) उन सिद्धान्तों को जो निम्नलिखित को शक्ति करेंगे, अर्थात्—

(i) राज्य द्वारा उदगृहीत ऐसे करों, शुल्कों, पदकरों और घाँसों के गृह आगमनों का राज्य और पचायतों के बीच बँटवारा जो इस भाग के अधीन उनके बीच वितरित किए जा सकेंगे और पचायतों के बीच सभी स्तरों पर अपने-अपने अपने का आवंटन,

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पदकरों और घाँसों की अवधानता जो पचायतों को निर्दिष्ट किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे,

(iii) राज्य की संचित निधि में से पचायतों को सहायता अनुदान,

(ख) पचायतों की विनियम स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अनुदान,

(ग) किसी अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा पचायतों के दोम विनियोजन के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए, इस बात पर राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

(2) राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा, आयोगों की सारचना, अर्हता, जो आयोगों के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता होगी और ऐति, जिससे उनका चयन किया जाएगा या उपबन्ध कर सकेगा।

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा उसे प्रदान करे।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का सहीकरण-शान्त राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा।

पचायतों के सेवाओं की भरीक्षा

243 अ राज्य का विधानमण्डल, पचायतों द्वारा सेवा बनाए रखने और ऐसे सेवाओं की सन्निधा करने की बात, विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगा।

पचायतों के लिए निर्वाचन

243 ड (1) पचायतों के लिए करार करने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक जनताओं के तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अर्हता, निर्देशन और निद्वारा एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा।

(2) राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा की शर्तों और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल निम्नो द्वारा अवधारित होगी। पालु राज्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से उसी रीति से और उसी आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर राज्य स्वयंसेवक के न्यायार्थ का हटाया जाता है अन्वय नहीं और राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के परचा उसके लिए अन्वयार्थ परीक्षा नहीं किया जाएगा।

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उसके कार्यवाही के उपबन्ध करेगा जिसने खण्ड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे संपी भर कृत्य के निर्देश के लिए अवसर्य हो।

(4) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा पचायतों के निर्वाचनों से सम्बन्धित सभी विषयों बाबत उपबन्ध कर सकेगा।

राज्य क्षेत्रों को लागू होना

243 ड इस भाग के उपबन्ध संघ राज्य-क्षेत्रों पर लागू होंगे और किसी एक राज्य-क्षेत्र को ठाँके लागू होने में उनका यह प्रभाव होगा याने राज्य के धन्यता के प्रतिनिदेश 239 के अधीन नियुक्त किए गए एक राज्य-क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश है और राज्य के विधानमण्डल या विधानसभा के प्रति निर्देश, उस संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिनमें विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रति निर्देश है।

परन्तु राष्ट्रपति लोक अभिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग में उपबन्ध किसी एक राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और उपातों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अभिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू न होना

243 ड (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खण्ड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

(2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित में लागू नहीं होगी—

(क) नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम राज्य

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं।

(3) इस भाग की—

(क) जिला स्तर पर पंचायतों के सम्बन्ध में, पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जिनके लिए तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषदें विद्यमान हैं।

(ख) किसी प्रावधान का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

(4) इस संविधान में किसी प्रावधान के होते हुए भी—

(क) खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा इस भाग का विस्तार, खण्ड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों, यदि कोई है, के सिवाय, उस राज्य पर कर सकेगा, यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प वा सदन की कुछ सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है।

(ख) समस्त विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपातों के अधीन रहते हुए कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

243 ड इस भाग में किसी प्रावधान के होते हुए, संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से सम्बन्धित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, तब तक जब तक कि सक्षम विधानमण्डल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त बना रहेगा।

परन्तु ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी यदि उन्हें उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान-परिषद है उस राज्य के विधानमण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा, पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता।

निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

243 ए इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) अनुच्छेद 243 ड के अधीन बनाई गई या बनाए जाने के लिए किसी ऐसी विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिशिष्ट या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से सम्बन्धित है, विधि मान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपलब्ध है अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 280 द्वा मशोफन

3. सविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) के तहत (ख) के तहत निर्धारित दरदम और स्थिति किता जाराम अर्थात्—

“(छठ) राज्य के विरुद्ध अपराध द्वारा की गई सिद्धियों के आधार पर राज्य में पदाधिकारियों के व्यक्तियों की अनुपस्थिति के निरवधि राज्य की संपत्ति निधि के सर्वपक्ष के निरवधि अपराध।”

ग्यारहवीं अनुसूची का बोझ बना

4. माँवपप को दसवों अमृतचो के पखत् निर्मलखित अमृतचो जोहो जराहो अदाह—

ग्राह्यो अनुमो (अनुच्छेद 246-छ)

1. कृषि एवं कृषि-विस्तार।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यक्रम, एककरी और भूमि सारण।
3. लघु सिंचन, जल प्रबंध और जल-आवृत्ति विकास।
4. पर्यावरण, दुग्ध-उद्योग और कुक्कुट-पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक कनेक्शन और धर्म कनेक्शन।
7. लघु बजट बनाना।
8. लघु उद्योग, बिजली, अनाज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
9. खेती, मूल और कुटीर उद्योग।
10. प्रशिक्षण कार्यक्रम।
11. रोजगार।
12. ईंधन और बजट।
13. मछली, पुष्प, फल, सब्जी, जलवायु, उद्योग, मूल के अन्य माल।
14. प्रशिक्षण, विद्युत्-उद्योग, बिजली, अनाज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
15. गैर-परम्परागत उद्योग क्षेत्र।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, बिजली, अनाज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मूल के अन्य माल।
18. उद्योग, बिजली, अनाज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
19. प्रशिक्षण और अनाज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
20. पुस्तकालय।
21. मौसमिक कार्यक्रम।
22. बाजार और मूल।
23. स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, बिजली, अनाज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मूल के अन्य माल।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल विकास।
26. स्वास्थ्य, बिजली, अनाज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मूल के अन्य माल।
27. दुर्गम क्षेत्रों का और विशेषज्ञ अनुसंधान और अनुसंधान कार्यक्रम।
28. सामाजिक विकास कार्यक्रम।
29. सामाजिक कनेक्शन का कार्यक्रम।

सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक अधिकार 1992 के अधिनियम पर सभी राज्य में दायर कर रहे हैं। इनके मुकदमे विचारित नहीं किए गए हैं—

(क) पदार्थ क्षेत्र में रहने वाले किसी भी वस्तु के क्षेत्र का वह सतह क्षेत्र में तब ही है जब वह सतह क्षेत्र सतह हो।

(ख) पचासों का एक विस्तार होना होगा—सब सचिवों और जिल्ले मग पर। जिन एजेंसियों का जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें यह विकल्प होगा कि नए एजेंसियों को न रखें।

(10) सभी तैनों सतों की पदधतों की सतों सौसे सुरव दुर धी नरुंग। इनने कर्तितक गंव पदधतों के कपध, पदधतों सत की पदधतों के सतय कदर ग सतों है और पदधतों सत की पदधतों के कपध गिया सत

की पंचायतों के सदस्य बनाए जा सकते हैं। सदर सदस्य विधान मण्डल और विधान परिषद सदस्य भी मध्यवर्ती या जिला स्तर की पंचायतों के सदस्य बनाए जा सकते हैं।

(ए) सभी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें सुरक्षित होंगी। कुल एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी।

(इ) सभी स्तरों की पंचायतों के अध्यक्षों के पद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में उनकी आबादी के अनुपात में सुरक्षित रहेंगे। सभी स्तरों की पंचायतों के अध्यक्ष पदों में भी एक-तिहाई महिलाओं के लिए सुरक्षा होगी।

(ए) राज्य के विधान-मण्डल को यह अधिकार होगा कि पंचायतों की सीटों में और अध्यक्ष पदों में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे।

(उ) हर पंचायत की अवधि एक-सौ अर्थात् पाँच वर्ष की होगी और नई पंचायतों के लिए चुनाव पुरानी पंचायतों की अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरे हो जाएंगे। पंचायत भंग किए जाने की स्थिति में छ महीने के भीतर निरिचित रूप से चुनाव कराए जाएंगे। नई पंचायत पाँच वर्ष की अवधि के शेष समय के लिए काम करेगी।

(ज) किसी अधिनियम में संशोधन करके अपनी अवधि पूरी होने से पहले किसी पंचायत को भंग नहीं किया जा सकेगा।

(स) यदि कोई व्यक्ति किसी कानून के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है या राज्य के किसी कानून के अन्तर्गत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह पंचायत का सदस्य बनने का अधिकारी नहीं होगा।

(य) हर राज्य में चुनाव प्रक्रिया के सजान्, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए मजदूत सुविधाएँ तैयार करने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग स्थापित किए जाएंगे।

(इ) पंचायतों को वह विरिष्ट जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि ग्राहकों अनुसूची में वर्णित विषयों के क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करें। विकास योजनाएँ कार्यान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी जाएगी।

(इ) पंचायतों को अपने कार्य पूरे करने के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाएगी। राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान पंचायतों के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा, परन्तु राज्य सरकारों से यह आशा की जाएगी कि वे कुछ कठों का राजस्व पंचायतों को सौंप देंगी। कुछ मामलों में पंचायतों को वह भी अनुमति होगी कि अपने द्वारा लगाया गया राजस्व इकट्ठा कर सकें और उसे अपने पास रख सकें।

(इ) हर राज्य में एक वर्ष के अन्दर-अन्दर एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा और उसके बाद फिर हर पाँचवें वर्ष गठित किया जाएगा जिसका काम ऐसे सिद्धान्त तय करना होगा जिनके आधार पर पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन सुनिश्चित किए जाएँ।

(इ) जो पंचायत 24 अप्रैल, 1993 को काम कर रही थी, उन्हें अपनी पूरी अवधि के लिए काम करने दिया जाएगा बशर्ते कि सदन अपने किसी प्रस्ताव द्वारा उन्हें भंग न कर दे।

उपर्युक्त सविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की स्थिति बहुत सुदृढ़ होकर उन्हें नई शक्ति प्राप्त हुई। इस सविधान संशोधन के लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों ने वर्गों से सम्बन्धित इन समस्याओं के निर्वहन सम्पन्न कराये हैं। अब राज्य सरकारें इनकी ओर अधिक ध्यान दे रही हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की वित्त व्यवस्था—पंचायती राज संस्थाओं को स्वयं कर लगाने का अधिकार होता है। वे घरों पर तथा कुछ प्रकार की जमीनों पर मेलों और ठकसों तथा घात की किस्में पर कर लगाती हैं और जुगो वसूल करती हैं। वे आर्थिक लाभ वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण भी करती हैं। पंचायतों राज संस्थाओं को अधिकार और दायित्व न केवल अपने-अपने राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों से प्राप्त होते हैं, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं से भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इन संस्थाओं को बहुत व्यापक दायरे के कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकारों द्वारा उन्हें आर्थिक अनुदान भी प्रदा किया जाता है।

पंचायती राज का संगठन—पंचायत राज संगठन में सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके ऊपर खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद होती है।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का मुख्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है जिसमें एक गाँव या छोटे-छोटे कई गाँवों के सब वयस्क निवासी एकत्र होकर मतदान करते हैं और यदि गाँव सभा का क्षेत्र अल्पसंख्यक चुनकर क्षेत्रों में विभक्त है तो अपने-अपने क्षेत्र में मतदान करते हैं। यह सभा वार्षिक बैठक या विचार करती है और यह तय करती है कि अनेक बजट सत्र में छोटी-छोटी टपक का क्या नक्शे रखा जाए। पंचायत के सभी सदस्यों का निर्वाचन जाता द्वारा किया जाता है। सारण का मुख्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

पंचायत समिति

पंचायत समिति का संगठन सभी राज्यों में एकसा नहीं है। विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य सम्मिलित सब पंचायतों के सारणों के अधीनस्थ सहकारी समितियों और छोटी नगरपालिकाओं एवं नोटिफाइड क्षेत्रों के प्रतिनिधि, छात्र से निर्वाचित या छात्र में रहने वाले, पाली विधानपरिषद और राज्यसभा के सदस्य, छात्र से चुने हुए जिला परिषद के सब सदस्य विकास एवं अन्योद्यम में रुचि रखने वाले दो सहयोगी सदस्य और महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों के कुछ महयोगी प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। विकास अधिकारी इसका सचिव होता है। अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित प्रधान होता है और इसी सहायक के तिर उपप्रधान भी चुने जाते हैं। इस सारी योजना में पंचायत समिति सरतः अधिक महत्व की सभा है। छात्र की सब ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय रखना और समस्त विकास कार्यों को सुचारु रूप से चलाना इसी का काम है। राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है वह इसी के द्वारा ग्राम पंचायतों को बाँटा जाता है। जिला परिषद

जिला परिषद का संगठन भी पंचायत समिति के अनुसार ही रखा गया है। इसके सदस्य भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इसके अधीनस्थ जिनके सब विपक्ष, समस्त सदस्य राज्य विधान परिषद के सदस्य और कुछ महिलाओं और अनुसूचित जातियों के सहयोगी सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद में एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है जिसे जिला प्रमुख कहते हैं और एक उपप्रमुख होता है जो उपनिष्ठा प्रमुख होता है।

पंचायती राज समझौते के कार्य—पंचायत राज समझौते के कार्यों को निम्नानुसार विस्तारित किया जा सकता है—

जिला परिषद के कार्य—जिला परिषद ग्रामीण स्तर पर जलन की सर्वोच्च इकाई है, अतः उसका प्रमुख कार्य समन्वयकता और पंचायतों द्वारा विकास का है। साथ ही उसने यह अंश की जाती है कि वह राज्य सरकार या निम्नस्तरीय पंचायतों के बीच की भूमिका निभाए। यदि प्रचलन दृष्टि से कार्य किया जाए तो जिला परिषद पंचायती राज समझौते की व्यवस्था पर प्रभाव डालकर बड़ी परिवर्तन ला सकती है।

पंचायती समिति के कार्य—पंचायती राज की वर्तमान योजना के अर्धन पंचायत समिति वह धुरी है जिसके चारों ओर पंचायती राज की सभी प्रवृत्तियाँ केन्द्रित हैं। जिला परिषद केवल एक समूह देने वाली और निरासरी रखने वाली सभा है। कार्यपालिका के सभी दायित्व अधिकार और कार्य पंचायत समितियों में ही निहित हैं। पंचायत समितियों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1. सामुदायिक विकास कार्य—पंचायत समिति अधिक रोडगार, उपवन और सुख-सुविधाएँ प्रत्यक्ष करने के लिए ग्राम समूहों का संगठन करती है। ग्राम समूहों में स्वावलम्ब्य की प्रेरणा देने तथा लोक कल्याणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।

2. कृषि सम्बन्धी कार्य—पंचायत समिति को कृषि से सम्बन्धित अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे—अधिक कृषि उपवन के लिए योग्यता करना और विकसित करना, धूमि एवं जनसंख्याओं का प्रयोग करना, नवीनतम रीति पर अधीनस्थ कृषि को सुधरी हुई सिंचि का प्रसार करना, पालु सिंचाई कार्यों का निर्माण करना, सिंचाई के कुँओं तथा बाँधों का निर्माण और मंटे रखने में सहायता देना, धूमि की कृषि योग्यता तथा कृषि धूमियों पर पुनर्वासन करना, उर्वर बोन विवर्धित करना, स्वयंसेवक छात्र सम्बन्धी सफाई का विकास करना, सुधरी हुई कृषि उपकरणों के प्रयोग और निर्माण को प्रोत्साहन देना, पशु-प्राशन करना, राज्य अन्योद्यम में बर्बाद हुई नीति के अनुसार व्यापारिक फसलों का विकास करना, सिंचाई तथा कृषि के विकास के लिए कर्षा और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करना आदि।

3. पशुपालन—पशुपालन के क्षेत्र में कृषि गहन क्षेत्र स्थानित करना, स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधार, सुधरी हुआ पशु-उत्पाद उपलब्ध करना, भूत की बीमारियों को रोकना, पशु-चिकित्सकों की स्थापना करना, दुग्ध-उत्पादों की स्थापना और दुग्ध देने का प्रबन्ध करना, तन की प्रेरित करना, छात्रों की समस्या को सुलझाना एवं पंचायतों के अर्धन दलजों में प्रत्यक्ष पालन का विकास करना इत्यादि पंचायत समिति के कार्य हैं।

इतनी विकसित नहीं हुई हैं जितनी शक्ति एवं सत्ता हासिलाने के रूप में। नेतृत्व में सत्ता के लिए दौड़ पंचायती राज संस्थाओं के परिधि के लिए अहितकर है।

सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों का पारम्परिक सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। जिला-स्तरीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मित्र दारोन्नतिक एवं सहायक के रूप में ग्रामवासियों के साथ कार्य करेंगे, किन्तु वास्तविकता यह है कि वे अधिकारीगण ग्रामवासियों पर अपनी राय घोषित कर प्रयास करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में दलगत राज्यों का प्रवेश चुनचों पर होने वाले भय एवं कटुता का वातावरण तथा पंचायतों की घनता के दुष्परिणाम इन समस्याओं की उत्पत्ति का बमजोर किया है। राज्य सरकारों द्वारा इनके चुनाव निर्मित सम्बन्ध पर नहीं करने तथा राजनीतिक धारणा से इन समस्याओं को पंग करने के निर्णय भी पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर बनाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा घटिया निर्माण कार्य तथा सार्वजनिक धन का दुष्परयोग भी इनकी स्थिति को कमजोर बनाते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सुझाव

पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने की दिशा में निम्नलिखित सुझाव सिद्ध हो सकते हैं—

1 पंचायती राज संस्थाओं को प्राणवत् बनाने और शोभाहीन करने के लिए उन्हें अधिक कार्यकारी अधिकार दिए जाने चाहिए।

2 वे परियोजनाएँ और कार्य जो जिला परिषद को सौंपे जा सकते हैं राज्य स्तर से जिला परिषद को सौंप दिए जाने चाहिए। पंचायत समितियों में वे परियोजनाएँ वापस ली जानी चाहिए जो जिला परिषद स्तर पर अधिक कुशलता के साथ कार्यान्वित की जा सकती हैं।

3 जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कर्मचारियों में अनुशासन स्थापित करने और उनसे काम लेने के लिए प्रभावपूर्ण शक्तियाँ दी जानी चाहिए। कार्यारियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसके ठीक ऊपर के उस अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिए जिसके अधीन वे कर्मजारी कार्य कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4 जिला स्तर के अधिकारियों को समूह भाव में काम करना चाहिए। उनका प्रमुख दायित्व जिला परिषद पंचायत समितियों, छपट विकास अधिकारियों तथा विस्तार अधिकारियों को सरकारी नीतियों और निर्देशों के अनुसार तकनीकी दृष्टि से योजनाएँ बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता देना है।

5 लोगों की आम समस्याओं को हल करने के लिए पंचायतों को अधिकार और सौधन प्रदान किये जाएँ। लोगों को अधिक से अधिक समस्याएँ पंचायत के क्षेत्राधिकार में लाई जाएँ ताकि लोग अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें तथा समस्याओं का समाधान पा सकें।

6 नियम और कार्यवाही सुगम बनाई जाए। नियम ऐसे होने चाहिए जिनको आम आदमी भली-भाँति समझ सके।

7 राजस्व और पुलिस सेवाओं का सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

8 ग्राम सभा की कार्यवाही जनता की भावनाओं के अनुसार चलाई जानी चाहिए। ग्राम जीवन को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्राम सभा में विचार विपरीत होने चाहिए। ग्राम सभा के विचारणीय विषयों में पंचायत का बजट, पंचायत के काम का विवरण, योजनाओं की प्रगति, ऋण और अनुदानों का उपयोग, स्कूल और सहकारी समितियों की व्यवस्था, लेखा परीक्षण की रिपोर्ट आदि शामिल की जानी चाहिए।

9 पंचायती राज में संस्थाओं के मार्ग-निर्देशन, देख-रेख और नियन्त्रण का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकारें, उनके तकनीकी अधिकारियों और जिला अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं की समुचित एवं उदर दग से मार्ग-निर्देशन कर उन्हें शोभाहित करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्रीय संस्थाओं के मित्र, दारोन्नतिक तथा पथ-प्रदर्शक के रूप में आगे जाना चाहिए। उनका कार्य सही ढंग से सकारात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए।

10 राजनीतिक दलों को पंचायती राज के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा इन संस्थाओं के चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर हो।

11 पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के पास स्वयं के साधन विकसित किए जाने चाहिए ताकि वे अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि कर अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यों का पालन कर सकें। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदानों में वृद्धि करनी चाहिए। राज्य सरकार को पंचायत राज संस्थाओं को व्याप्त रहित ऋण देकर अपने खुद के लाभकारी व्यवसाय चलाने के लिए अभिवेक्षित करना चाहिए। कर वसूल करने वाली मशीनरी को प्रभावशाली बनाना जाना चाहिए।

12 प्रशासनिक व्यय में हर स्तर पर पितव्यविता होनी चाहिए।

13 पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन नियत समय पर कराये जाने चाहिए।

14 राज्य सरकारों द्वारा अकारण पंचायती राज संस्थाओं को समयावधि के पूर्व ही भंग करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।

पंचायती राज की उपलब्धियाँ

नैतिक-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार पंचायती राज को अस्तित्व दिया गया देश में इस व्यवस्था का सफल परिणाम भी हुआ है। यद्यपि पंचायती राज अपनी कमियों और दुर्बलताओं के बावजूद प्रभावशाली की जीवन पद्धति बनता जा रहा है, तथापि अस्तिष्ठित जनता में जतिगत और धर्मगत अन्धविश्वास, परम्परागत अनेकानैतिक सामाजिक और पारिवारिक ढाँचे, परिपक्व राजनैतिक प्रवृत्तियों की कमी के कारण सचराज जनता में पंचायती राज की उपलब्धियों का मूल्य कम करने अथवा पंचायती राज की अल्पज्ञान करने की एक सामान्य प्रवृत्ति विकसित हो गई है अतः हम बात में इनका नहीं किया जा सकता कि पंचायती राज व्यवस्था ने देश के राजनैतिक तथा आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायत चुनावों और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्षेत्रों ने प्रजनन में एक नया जगह पैदा किया है। अब गाँव वालों का उस प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता जिस प्रकार पहले मजदूर और जमींदार वर्ग करण था। वोट की कीमत समझी जाने लगी है। ग्रामीण जनता की राजनैतिक हिस्सेदारी बढ़ी है। लोकतन्त्रिक विकेंद्रीकृत मन्दिर स्वतन्त्रता की इच्छाओं के रूप में विकसित हो रही है। ग्राम नेतृत्व बनता जा रहा है। गाँव की स्थितियों में राजनैतिक कार्यक्षेत्रों में भाग लेने लगे हैं। राजनैतिक जागरूक के साथ सामाजिक चेला बढ़ा है। लुआलुआ अस्पृश्यता और भेदभाव की दीवारों को पंचायती राज ने जबरदस्त धक्का पहुँचाया है। मजदूर और नौकर का जाने वाला व्यक्ति अब पंचायत या पंचायत समिति की अध्यक्षता करता है और बड़े-बड़े राजनैतिक नेताओं के साथ बैठता है तो क्या इसे गाँव में सामाजिक और राजनैतिक स्थिति नहीं कहेंगे? गाँवों की जागरूकता राज्य स्तर की राजनीति पर दबाव डालने में सक्षम है। जागरूक धर्मगत और अन्य प्रकार के हित स्थानीय दबाव-समूह के रूप में प्रकट होने लगे हैं। दबाव-समूह की राजनीति अब गाँवों की बनती नहीं रह गई है। ग्रामीण जनता की अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में नई जानकारी मिली है। पंचायती राज नये विकास सौंपनों को जन्म देकर गाँवों को आगे बढ़ा रहा है जिससे गाँव वालों में आत्मविश्वास की भावना जाग्रत हो रही है साथ ही उनकी स्थिति सुधारने के लिए पाय-पथों ने नई ठोकरें, कुठ कर मारने की प्रवृत्ति बन रही है। पंचायती राज ने गाँवों में यद्यपि कुछ सीमा तक सामाजिकता, प्रजापार, अस्पृश्यता, स्त्रीवाद, मजदूरवाद और को बढ़ावा दिया है, लेकिन इनकी तुलना में पंचायती राज के लाभ बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। गाँवों में आराओं भए उत्पन्न पैदा हुआ है जिसे दबाया नहीं जा सकता है।

ग्रामीण स्थानीय समस्याओं पर राज्य नियन्त्रण

(State Control over Rural Local Bodies)

ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले स्थानीय निकायों पर राज्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करके इन्हें कुशल एवं प्रभावशाली बनाया जा सके। पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्र में नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था का अनेककृत अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि ग्राम्य स्तर पर स्थानीय जनता को जो शक्ति दी गई है उसका प्रयोग करने वाले लोग अस्तिष्ठित एवं पर्याप्त योग्य नहीं हैं और उनके द्वारा सत्य का दुरुपयोग की सम्भावनाएँ प्रायः अधिक रहती हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासकीय संस्थाओं की शक्ति हस्तान्तरित करने के बाद सरकार जनता के विकास एवं कल्याण के उत्तरदायित्वों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। यह राज्य का एक स्वाभाविक अधिकार एवं सक्रिय उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार को यह देखना पड़ता है कि ये स्थानीय संस्थानें एक निरंतर रूप के अनुसार कार्य करती रहें। पंचायती राज प्रशासन के एककृत रूप के रूप में विकसित होनी है तथा य राष्ट्रीय स्तरियों एवं राज्य के संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम देखें हैं। जब इन संस्थाओं पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की एक विकसित व्यवस्था लागू की जाती है तो वे स्वयं लाभान्वित होंगे हैं और नागरिकों को अधिकतम लाभ प्रदान होंगे हैं।

नियंत्रण की विधियाँ—ग्रामीण स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है—

1. राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारी वहाँ पंचायती राज संस्थाओं के निर्देश का कार्य करते हैं। यदि कोई संस्था ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तो निर्देशक का दायित्व है कि वह उसे दक्षिण प्रकार से कार्य करना सिखाए। निर्देशक स्थानीय निकायों की सम्पत्ति, निर्माण कार्य, कार्यन्वयन स्तर आदि का निर्देश करते हैं। इन्हें अधिकार है कि रिपोर्ट, लेख-पत्रों आदि की संश्लेषण करें। निर्देशक अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रकार में अपने विभाग का देते हैं।

राज्य स्तर पर पचायती राज सभाओं के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए कहीं तो स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग है और कहीं पचायती राज विभाग है। कहीं-कहीं पर इसे पचायती राज निदेशालय कहा जाता है। निदेशालय की सहायता के लिए स्थान-स्थान पर परामर्शदात्री बोर्ड हैं जो पचायती की समीक्षा करते हैं। राज्य सरकार को पचायती से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर परामर्श देते हैं एवं पचायती को उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर सलाह देते हैं आदि।

2. राज्य सरकार पचायती राज सभाओं से रिपोर्टें माँगी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अनेक प्रकार के विवरण-पत्र और प्रतिश्ठ-पत्र माँगे जाते हैं और इन संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि वे निर्धारित प्रश्नों में लेख प्रस्तुत करें। विभाग आवश्यक अध्ययन के बाद ब्रिटिशों की ओर स्थायीत विकासों का ध्यान आकर्षित करता है और उन ब्रिटिशों को ठीक करने के लिए समुचित निर्देश भेजता है। कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं जो नियमानुसार समय-समय पर भेजी जाती रहती हैं किन्तु विभाग को अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार अन्य रिपोर्टें और सूचना की माँग करे।

3. ऐसे मामलों में जहाँ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को स्वीकृति, सहमति या अनुमोदन आवश्यक हो, राज्य सरकार उचित जीव का आदेश दे सकती है। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह आवश्यक समझे जाने पर अन्य किसी मामले में जीव का आदेश दे तथा जीव अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह आवश्यक समझने पर किसी व्यक्ति को अपने सामने पेश होकर बयान देने का आदेश दे। जीव अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करके निर्णय देना सरकार का काम है।

4. राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह पचायत समितियों के निर्णयों, प्रस्तावों या आज्ञाओं को अनुचित समझने पर रद्द कर दे, लेकिन ऐसा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि राज्य सरकार पचायत समिति को उतर में अपनी सफाई देने का उचित अवसर दे। राज्य सरकार की ओर से अधिकार का प्रयोग जिला-कलेक्टर भी कर सकता है यदि वह आवश्यक समझे कि जनहित और शांति की दृष्टि से अविलम्ब कार्यवाही अनिवार्य है। जिला-कलेक्टर को अपने कार्य की रिपोर्टें सीधे ही राज्य सरकार को भेजनी होती है और राज्य सरकार का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होता है।

5. राज्य सरकार जिला परिषद एवं पचायत समितियों के निर्णय में परिवर्तन कर सकती है। यह पचायत समिति या जिला परिषद के किसी निर्णय या आदेश सम्बन्धी कारणों को पेशकर देख सकती है और अपना निर्णय दे सकती है। निर्णय देने से पूर्व जिला परिषद या पचायत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के अवसर दिए जाते हैं।

6. जिला-कलेक्टर को अधिकार होता है कि वह पचायत समिति की अवल सम्पत्ति और उसके कार्यों आदि का निरीक्षण करे। पचायत समिति के नियन्त्रण में चलने वाली किसी सभा के कार्यवाजा आदि के निरीक्षण करने का उसे अधिकार है।

7. कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पचायत या पचायत समिति राज्य सरकार की स्वीकृति से ही कर सकती है। राज्य सरकार की सहमति के अभाव में किए गए ऐसे कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्य सरकार को अधिकार होता है कि वह प्रशासकीय आदेशों द्वारा ऐसे कार्यों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दे।

8. महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिकार है कि यदि पचायत राज सभाएँ अपना कार्य न करें तो राज्य सरकारें अपने अधिकारियों से कार्य करवा लें। राज्य सरकार कार्य-व्यय इन सभाओं से वसूल कर सकती है। प्रायः इस प्रकार का कदम तभी उठाया जाता है जबकि पचायती राज सभाएँ निरन्तर गलती करती रहें और राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद कार्य पूरा न करें अथवा निर्धारित समय के भीतर अपनी गलती न सुधरे।

9. यदि राज्य सरकार समझे कि कोई समिति या परिषद अपने कार्य सुचारु ढंग से नहीं कर रही है तो वह उसे भंग करके प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। चेन्नई, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के अधिनियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह समिति या परिषद को भंग करने के बजाय उसे तुल्य नए चुनाव की आज्ञा दे।

10. यदि पचायत राज सभाएँ अधिनियमों नियमों और उपनियमों का समुचित रूप से पालन न करें तो राज्य सरकार को अपीलें सुनने का अधिकार है। ऐसी अपीलें पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होता है। ये निर्णय न्यायालयों की अधिकार सामग्री से परे होते हैं।

11. पचायत राज सभाओं पर राज्य सरकार का पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण रहता है। इन संस्थाओं की आय का अधिकांश भाग राज्य सरकारें अनुदान के रूप में उपलब्ध कराती हैं अतः सभाओं का कर्तव्य है कि वे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आचरण करें। राजस्थान राज को रें तो राज्य सरकार के निरीक्षक प्रतिवर्ष उनके हिसाब-किताब की जाँच करते हैं। पचायत को अपने वार्षिक बजट पर मन्त्री लेनी पड़ती है। बजट के अलावा कोई धन राशि पचायत समिति की पूर्व अनुमति के बिना व्यय नहीं की जा सकती। राज्य सरकार के

नियमों का पालन न करने या राज्य सरकार द्वारा समुह न होने की स्थिति में सरकारी अनुदान रोका जा सकता है। सरकारी अनुदान के बिना पंचायत राज संस्थाओं का कार्य सम्पन्न नहीं चला सकता अतः वितीय नियंत्रण व्यवस्था में प्रभावी होता है। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं के बजट निर्माण, कर्पोरेण, ऋण सम्बन्धी शक्तियों आदि पर नियंत्रण रखा जाता है। कठो बंधन और उनकी वसूली के नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं।

12. जहाँ मुख्य पंचायत अधिकारी की शक्तियाँ हैं वहीं वह पंचायत के किसी आदेश या प्रस्ताव को रोक सकता है। इस अधिकारी को आज्ञा में आवश्यक सरोधान या परिवर्तन राज्य सरकार कर सकती है।

13. राजस्वान्, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अधिनियमों में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे निर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों को हटा दे जो पंचायत राज व्यवस्था के कानून और नियमों का उल्लंघन करते हों। मद्रास के लिए यदि राजस्वान् राज्य की व्यवस्था को लिया जाए तो राज्य सरकार को पंच, मण्डल पंचायत समिति के सदस्य, न्याय पंचायतों के सदस्यों और अध्यक्ष तथा पंचायत समिति के प्रधान को कर्तव्य परिस्थितियों में हटाने का अधिकार है। राज्य सरकार ऐसा कदम ग्रहण करने उठाती है जब शक्तियों के दुरुपयोग, अधिकार-संभा का उल्लंघन, कदाचार आदि के स्पष्ट आरोप हों।

नगर शासन

(Municipal Government)

नगरीकरण और औद्योगीकरण के विकास के साथ नगरीय शासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। भारत में वर्तमान नगरीय शासन में नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिकाएँ, नगर-क्षेत्र समितियाँ, अधिमूर्धित क्षेत्र-समितियाँ, छावनी-बोर्ड आदि सम्मिलित हैं।

महानगर

(Metropolitan City)

एक महानगर क्षेत्र केवल बड़े आकार के नगर का ही छोटा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अधिक है। महानगर क्षेत्र को अपनी विशेषताएँ होती हैं, जैसे—अत्यधिक गाड़गाड़, अत्यधिक निवास, व्यापक दृष्टिकोण आदि जहाँ के निवासियों में धन, जमीन, विश्वास, रंग, रसि, व्यवसाय आदि के आधार पर अनेक विभिन्नताएँ होती हैं। यही कारण है कि ऐसे क्षेत्रों में प्रशासनिक समस्याएँ अत्यन्त जटिल होती हैं। अत्यधिक समस्याएँ होने के कारण सरकार के संचालन का प्रत्यक्षित व्यय भी अधिक होता है। इस क्षेत्र में प्रशासनिक निष्ठाओं के बीच समन्वय की समस्या भी उत्पन्न होती है।

भारत में भी बड़े-बड़े नगरों में इसी प्रणाली को अपनाया जा रहा है। वैसे तो भारत में प्रशासन नगर निगमों द्वारा चलाया जाता है, किन्तु इनमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई का विशेष स्थान है। इन चारों को महानगर क्षेत्र कहा जाता है। इन महानगरों का प्रशासकीय ढाँचा उनके अपने अधिनियमों पर आधारित है। देहली नगर निगम अधिनियम 1957 में बना था। कोलकाता नगरपालिका अधिनियम 1952 में, चेन्नई नगरपालिका अधिनियम 1919 में (1951 में संशोधित) तथा मुम्बई नगरपालिका अधिनियम 1888 में (यह 1955 में परिवर्तित किया गया) पास किए गए। इन अधिनियमों में चेन्नई तथा मुम्बई के अधिनियम अनेकानु अनेक अधिक पुण्डे हैं और इनमें समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। देहली नगर निगम का अधिनियम भारतीय संसद द्वारा प्रशंसित होता है, जबकि अन्य दोनों ही अधिनियम अपनी-अपनी व्यवस्थापिका सभा द्वारा प्रशंसित होते हैं।

नगर निगम

(Municipal Corporation)

नगर निगम शहरी क्षेत्र में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। उसके सर्वोच्च होने का आशय है कि वह अन्य प्रकार के नगर शासनों पर अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। नगर निगमों की स्थापना राज्यों में राज्य सरकार के तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्र सरकार के विशेष नियम के अन्तर्गत की जाती है, इनका अस्तित्व एवं अधिकार राज्य या केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है।

नगर निगम की स्थापना का आधार—नगर निगम बनाने से पूर्व प्रायः उस स्थान से प्राप्त वार्षिक आय स्थानीय जनता को अधिक सुविधाएँ देने की क्षमता आदि का आकलन किया जाता है। नगर निगम स्थापित करने के निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित किए जा सकते हैं—

1. पना बसा हुआ क्षेत्र
2. नगरपालिका का वर्तमान विकास और उसके भावी विकास की सम्भावनाएँ
3. नगरपालिका की वर्तमान और सम्भावित वित्तीय स्थिति

4 बड़े हुए करो को खत्म करने की जनता की क्षमता और आकांक्षा

5 निगम के पग में जनमत एवं

6 क्षेत्र विशेष की महत्वपूर्ण परिस्थितियों का आकस्मिक।

डॉ. श्रीराम माहेश्वरी ने लिखा है—ये सिद्धान्त वास्तु में सुनिश्चित नहीं हैं। इन्हें तो केवल किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का नगरीय शासन स्थापित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है तथा इस बात की शक्यता निर्णायक राज्य सरकार ही है कि किस नगर को नगर निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए। सामान्यतः जो नगर बड़ा होता है और जहाँ लोकमत निरन्तर नगर निगम की माँग करता है उसे राज्य-सरकार नगर निगम का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाती है। जनसंख्या तथा राज्य की बसोटी वास्तव में समय-समय होती है इसलिए समय के परिवर्तन के साथ-साथ इनकी सार्थकता कम होती रहती है।

भारत में मुख्य नगर निगम—जनसंख्या, जनघनत्व तथा वित्तीय अवस्था की दृष्टि से नगर निगमों में अन्तर किया जा सकता है। पन्नी मुम्बई और कोलकाता देश के सबसे पुराने नगर निगम हैं। हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुरते, विवेन्द्र, कालोक्ट कोजीर, मद्रास, पुना, नागपुर, सोलापुर, बंगलौर, कानपुर, आग्रा, इलाहाबाद, बाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर तथा बोटा अन्य बड़े नगर निगम हैं।

नगर निगम का संगठन—भारत में नगर निगम में ये सत्तार्य या घटक सम्मिलित हैं—1 परिषद, 2 मेयर या महापौर, 3 समिति एवं 4 नगर आयुक्त।

1 परिषद (Council)—यद्यपि परिषद नगर निगम का एक अंग होता है तथापि इसकी शक्तियाँ इतनी व्यापक होती हैं कि प्रायः इसको ही नगर निगम के नाम से जाना जाता है। परिषद एक प्रकार से स्थानीय विधानसभा है जो स्थानीय शासन के सम्बन्ध में जनता की इच्छा को प्रकट करती है। परिषद में नगर के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है। वे वयस्क मतधिकार के आधार पर तीन से पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। चुनाव के लिए नगर को जतने ही क्षेत्रों में विभजित किया जाता है जितने स्थान परिषद में होते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का बहुत छोटा होता है अतः उचित यही है कि परिषद का कार्यकाल पाँच वर्ष का हो। परिषद में निर्वाचित सदस्य तो होते ही हैं उनके अतिरिक्त कुछ सदस्य निर्वाचित पार्षदों द्वारा नगर के वयोवृद्ध अनुभवशील व्यक्तियों, महिलाओं और अन्य वर्गों में से चयनित किए जाते हैं जिन्हें एल्कमैन कहा जाता है। पार्षदों द्वारा इन नगर वृद्धों का चयन लोकायुक्तिक दृष्टिकोण से होता है। इस प्रकार नगर निगम की परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं—(क) वे पार्षद जो सीधे जनता द्वारा विभिन्न नगरीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं एवं (ख) वे सदस्य जो निर्वाचित पार्षदों द्वारा नगरवृद्ध के नाम से परिषद में लिए जाते हैं। प्रत्येक निगम में दोनों प्रकार के सदस्यों का होना अनिवार्य नहीं है। मुम्बई जैसे कुछ निगमों की परिषदों में केवल निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं किन्तु अन्य निगमों में नगरवृद्धों को भी परिषद में स्थान प्राप्त होता है। नगरवृद्धों को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो निर्वाचित पार्षदों को होते हैं। निगम की परिषदों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा महिलाओं के लिए अब 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।

देश के नगर निगमों के परिषदों के आकार में कोई एकरूपता नहीं है। परिषद का आकार यदि छोटा होता है तो सुसंगठित और व्यवहार कुशल होती है। आकार बड़ा होने से प्रभावकारण ढग से काम नहीं हो पाता है और पार्षदों की कार्यव्यवसायिता प्रायः अपेक्षित स्तर की नहीं रह पाती। नगर निगम के आकार के बारे में कहा जाता है कि स्थानीय क्षेत्र के अनुरूप चालीस से सौ सदस्यों वाली परिषद उपयुक्त होती है।

2 महापौर या मेयर (Mayor)—नगर निगम में कार्यपालिका शक्तियाँ महापौर अथवा मेयर को दी जाती हैं जो नगर का प्रथम नागरिक होता है। मेयर या महापौर नगर की प्रतिष्ठा और गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। मेयर का चुनाव निगम के निर्वाचित पार्षदों और नगरवृद्धों द्वारा उन्हीं में से एक वर्ष के लिए किया जाता है। यदि निगम के सदस्य चाहें तो अगले वर्ष उसी व्यक्ति को पुनः मेयर चुन सकते हैं। मेयर के चुनाव की स्थिति सभी निगमों में एक जैसी नहीं है।

मेयर परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसका परिषद के कार्यालय पर प्रशासनिक नियन्त्रण होता है। दिल्ली आदि कुछ नगरों में मेयर को निगम के सभी अधिकारों को देखने का अधिकार है। मेयर नगर के नागरिक प्रशासन के बारे में किसी भी नगरपाल से जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ संविधियों के अनुसार मेयर को अधिकार दिया गया है कि संकटकाल में वह किसी काम को करने या रोकने का आदेश दे सकता है। आवश्यकता पड़ने पर मेयर परिषद की विशेष बैठकें आमन्त्रित कर सकता है। यदि एक निश्चित संख्या में सदस्य माँग करें तो मेयर को विशेष बैठक बुलानी पड़ती है। चेन्नई, बंगलौर, विवेन्द्र तथा कालोक्ट के नगर निगमों में यह व्यवस्था है कि निगम और राज्य

सत्कार के बाध सभी पत्र-व्यवहार मेयर के माध्यम से होगा, लेकिन मेयर किसी पत्र को रुक कर नहीं रख सकता। मेयर पत्र-व्यवहार के समय अपना टिप्पणी लिख सकता है। मध्यप्रदेश में यद्यपि मेयर को आपातकालीन मामलों में क्रियान्वयन करने या क्रियान्वयन को रोकने के लिए निर्देश देने का अधिकार है लेकिन यह निर्देश उसे निगम परिषद की अगला बैठक में कारण सहित रखने होते हैं जिसमें परिषद का निर्णय हा मान्य समझा जाता है। उत्तर प्रदेश में मेयर को वारंठ अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी शक्तियाँ सौंपी गई हैं किन्तु ये सभी नियुक्तियाँ राज्य लाक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती हैं। यद्यपि मेयर निगम का अध्यक्ष होता है और निगम में कार्यपालिका शक्तियाँ उसे सौंपी जग है तथापि अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण मगर वास्तविक कार्यपालिका नहीं है। मगर निगम का प्रभाव नता न हाकर औपचारिक अध्यक्ष ही रह जाता है।

निगमों में मेयर या महापौर के नीचे टपमहापौर (Deputy Mayor) होता है। उसके लिए परिषद का सम्मन होना अनिवार्य है और उसका निर्वाचन पाच वर्ष के लिए किया जाता है। टपमहापौर, महापौर के व्योमों और उतरागण्यों का पूर्ति में सहायता करता है।

3 समितियों (Committees)—निन कारणों से केन्द्रीय एव राज्य व्यापस्यिक को विभिन्न कारणों का देखभाल के लिए अपन सदस्यों की समितियाँ बनान पड़नी हैं वे कारण स्थानीय स्तर पर भी विद्यमान रहते हैं। नगर निगम परिषद की बैठकें महने में प्रायः एक या दो बार से अधिक नहीं हो पती, अतः निगम के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह स्वयं अपने सभी काय सम्पन्न करे। निगम परिषद अपने बड़े आकार के कारण अपने उतरदायित्वों की भरसतापूर्वक करने में प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में परिषद सोचनाय पद्धति क अनुरूप अपनी शक्तियों क सफन संचालन, क्रियान्वयन एव पर्यवेक्षण के लिए कुछ समितियों का गठन करती है। समितियों के निमाण स व्यक्तिगत शक्ति दृश्यभाग का सम्मन्धन कम हो जाती है। निगम परिषद द्वारा नियुक्त समितियाँ दो प्रकार की होती हैं—(1) सौविधिक समितियाँ (ii) गैर सौविधिक समितियाँ।

(i) **सौविधिक समिति**—सौविधिक समिति वह है जिसका रचना उस सविधि द्वारा की जाता है जिसका द्वारा निगम का निमाण होता है। सौविधिक समितियाँ प्रत्येक नगर निगम में बनाया जाना आवश्यक है क्योंकि इनका उल्लेख अधिनियम के अन्तर्गत होता है। ये समितियाँ साथे गैर-निगम सावधि या अधिनियम स सत्ता प्राप्त करती हैं। इनके गठन, शक्तियों व्योमों और अधिकतों की रूपरेखा अधिनियम में दी जाती है।

शक्तियों और व्योमों की व्यापकता की दृष्टि से परिषद का स्टाई समिति महत्वपूर्ण होती है। स्टाई समिति एक मार्गदर्शक समिति के रूप में कार्य करता है जिसके हाथों में कार्यकारी पर्यवेक्षण विवरण एव कर्मचारी वर्ग स सम्बन्धित शक्तियाँ हाता हैं। वास्तव में स्टाई समिति निगम की कार्यकारण समिति के रूप में कार्य करता है। इस समिति का काय सम्पूर्ण नगर प्रशासन पर निगड रहना है। स्थाया समिति उन सभी शक्तियों का प्रदाय करती है जो अधिनियम द्वारा उसे सौंपे गए हैं। स्थानीय समिति परिषद और नगरपाल के मध्य की कड़ी है। वह दानों का प्रभावकारिता को निपन्नित और प्रभावित करता है। यद्यपि स्टाई समिति अनेक मामलों में अपने निगदों के लिए परिषद की स्वीकृति लेता है, लेकिन यह स्वीकृति सामान्यतः औपचारिकता मात्र होती है।

(ii) **गैर सौविधिक समिति**—इन समितियों का गठन परिषद द्वारा अपने उतरनियों के अन्तर्गत किया जाता है। परिषद अपने व्योमों के सुचारु एव सफन क्रियान्वयन के लिए इन समितियों का निमाण करती है। ये समितियाँ भिन्न-भिन्न विषयों और व्योमों में परिषद की सहायता करती हैं। सभी नगर निगमों में समितियों का गठन किया गया है, लेकिन उनका संख्या, संगठन और व्योमों में एकसूत्रता नहीं है। पृथक्-पृथक् निगमों में उनका स्वरूप या पृथक्-पृथक् ही देखने को मिलता है। इन प्रमुख समितियों में 1. वित्त एव स्थाना समिति 2. शिक्षा समिति 3. स्वास्थ्य एव बस्ती विकास समिति 4. जल-पूर्ति एव सफाई समिति एव 5. निमाण एव कस्बा समिति को शामिल किया जाता है।

सौविधिक एव स्टाई समितियों क अतिरिक्त निगमों में सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत विरहित समितियों तथा अस्थाई समितियों का भी गठन किया जाता है। अस्थाई समितियाँ उद्देश्य-विशेष के लिए बनाई जाती हैं और निगम द्वारा प्रदत्त कार्य का सम्पदन करती हैं। कुछ निगम अपने काय का सतत और सुमन बनने के लिए शरीय समितियों का गठन करते हैं। कर्मचारी समितियों में श्रेणीय समितियों का गठन किया जाता है। कुछ नगर निगमों ने अपन सम्पूर्ण क्षेत्र को अनेक छोटे-छोटे उपक्षेत्रों में विभाजित कर दिया है तकि जनता को सुविधार्थ आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय शासन के लिए एक क्षेत्रीय समिति गठित की जाती है जो उस क्षेत्र के निवासियों को समस्याओं का समाधान करती है।

4 नगर आयुक्त (Municipal Commissioner)—नगर आयुक्त अथवा नगरपाल निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वास्तव में उसे निगम का प्रमुख प्रशासनिक कार्यकर्ता समझना चाहिए। नगर आयुक्त उन कर्मियों

का निर्वाह करता है जो अधिनियम द्वारा उसे सौंपे गए हैं। सफ्टकाल में वह कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझता हो। नगर परिषद की नीतियों को और सविधि के प्रावधानों को कार्यान्वित करना नगर आयुक्त का उत्तरदायित्व है।

नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वह प्रायः उच्च स्तर पर पेशेवर प्रशासक होता है जिसे राज्य सरकार नगर का प्रशासन करने के लिए नियुक्त करती है। वह अपना वेतन निगम से प्राप्त करता है। नगर आयुक्त का कार्यकाल धिन्-धिन् नगर निगमों में धिन्-धिन् है। चेन्नई और मुम्बई नगर निगमों में उसका कार्यकाल छह वर्ष का है तो ब्योन्नात और दिल्ली नगर निगमों में पाँच वर्ष का है। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह उसके कार्यकाल में वृद्धि कर दे। निगम के पार्षदों की शिफारश अथवा उसके अधीनस्थ सिद्ध होने पर राज्य सरकार नगर आयुक्त को अपने पद से हटा सकती है। यद्यपि नगर-सरकारी व्यक्ति को नगर आयुक्त पद पर नियुक्त करने पर कोई कानूनी प्रतिबाध नहीं है तथापि सरकार प्रायः सेवारत लोक सेवक को ही इस पद पर नियुक्त करती आई है। नगर आयुक्त की नियुक्ति की अवधि का प्रायः सविधि या अधिनियम में उल्लेख रहता है। नगर आयुक्त की शक्तियों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

(i) वे शक्तियाँ जो उसे नगर निगम अधिनियम द्वारा प्राप्त होती हैं एवं

(ii) वे शक्तियाँ जो उसे नगर निगम परिषद अथवा उसके स्थाई समिति द्वारा प्रदान की जाती हैं।

कार्य—नगर आयुक्त को विविध प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। प्रशासनिक, वित्तीय और निर्वाचन सम्बन्धी क्षेत्रों में उसके विभिन्न उत्तरदायित्व हैं। निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उसे निगम परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों में बोलने का अधिकार है, किन्तु वह मतदान नहीं कर सकता। निगम के सभी कर्मचारी नगर आयुक्त के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं, तथापि नियुक्ति, पदोन्नति एवं अनुशासन के मामलों में परिषद तथा उसके समिति भी नगर आयुक्त की शक्ति में भागोदार होती है। यह स्थिति निगम कर्मचारियों के सम्बन्ध में नगर आयुक्त की स्थिति को कमजोर करने वाली है। नगर परिषद कर्मचारियों पर हान् प्रकार का दोहरा नियन्त्रण अनुरासन की क्षीण करता है। नगर आयुक्त निगम और स्थाई समितियों के निर्णय के लिए नीति-प्राकृष्ट तैयार करता है। कुछ नगर निगम अधिनियमों में नगर आयुक्त को अन्तिम अधिकार दिए गए हैं।

नगर आयुक्त को पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि विधि के अनुसार यद्यपि निगम का बजट पहले स्थाई समिति द्वारा स्वीकृत एवं बाद में परिषद द्वारा पारित किया जाता है, तथापि बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व नगर आयुक्त का ही है। व्यवहार में नये करों के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अभिक्रम नहीं करता है। परिषद द्वारा बजट पारित कर देने के पश्चात् नगर आयुक्त स्थाई समिति के पास यह अधिकार प्राप्त करने के लिए जा सकता है कि वह बजट अनुदानों के अन्तर्गत किसी राशि को एक छोटी मद में से दूसरी में अन्तर्गत कर सके। कुछ छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति का भी उसे अधिकार है। वह निगम के सभी दस्तावेजों और कागजातों का प्रभारी अधिकारी होता है। आपसतकाल में नगर आयुक्त को अधिनियम की विशिष्ट और असामान्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

नगर आयुक्त नगर परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह परिषद की बैठकों में भाग लेता है और पार्षदों के प्रश्नों के जवाब देता है। वह परिषद के प्रस्तावों का क्रियान्वयन करता है। नगरीय सेवाओं के अधिनियमों, नियमों, उपनियमों के प्रावधानों के निष्पादन का उत्तरदायित्व नगर आयुक्त का है। परिषद और नगर आयुक्त के मध्य सम्बन्ध कुछ इस प्रकार के हैं जैसे कि एक प्रमुख तथा उसके अधिकारों के बीच हुआ करते हैं। परिषद का उस पर नियन्त्रण रहता है। परिषद यह निर्धारित करती है कि नगर आयुक्त अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करेगा। वह प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार से उसे वापस बुलाने की माँग भी कर सकता है।

नगर निगम के कार्य (Functions)—स्थानीय नागरिकों को समझाओं को दूर करने और उन्हें अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए नगर निगम को अनेक कार्य करने होते हैं—

अनिवार्य कार्य (Obligatory Functions)

1. पीने योग्य जल की व्यवस्था और उसका वितरण करना।
2. नालियाँ एवं ऐसी ही अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण तथा सफाई व्यवस्था करना।
3. बिजली का वितरण करना।
4. सड़क परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करना।
5. कोयले तथा मल को इकट्ठा करना और हटाना।
6. गन्दी बस्तियों की सफाई करना।
7. रम्यता प्रमोद का नियन्त्रण एवं देखभाल करना।

- 8 जन दत्त मृत्यु की पंजीकृत करना।
- 9 बेमरिदों की ऐक्यन के लिए टीका लगवना।
- 10 छतरनाक बीमारियों की ऐक्यन।
- 11 अस्पताल डिस्पेनरी तथा मनार्थों के लिए कन्या केन्द्र खोलना।
- 12 अति-रक्षण सेवा की व्यवस्था करना।
- 13 छतरनाक एवं पतक व्यापारों पर नियंत्रण रखना।
- 14 छतरनाक भवनों को हटा देना।
- 15 सार्वजनिक सड़कों, गलियों एवं पुलिया बनवाना।
- 16 खाद्य पदार्थों तथा भोजनान्तरों का नियमन तथा नियंत्रण करना।
- 17 सार्वजनिक गलियों में प्रकाश एवं सफाई का प्रबन्ध करना।
- 18 गलियों एवं पुलियाओं पर से बचकर चारों को हटाना।
- 19 गलियों एवं सड़कों का नम्बर लगाना तथा गलियों एवं रास्तों का नक्का रखना।
- 20 प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्कूल खोलना।
- 21 विज्ञान विस्तार, गृहक दालपत्र एवं जन-विस्तार सभाओं के लिए ठगनों की रचना, स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
- 22 नगरपालिका कार्यालय एवं निगम की अन्य सम्पत्ति का रचना एवं प्रबन्धन।
- 23 गृह कर एकत्रित करना।
- 24 सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करना।
- 25 सड़कों एवं फुटपाथों से अतिक्रमण हटाना।

ऐच्छिक कार्य (Discretionary Functions)

- 1 अन्य सभनों द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ाना देना।
- 2 पुस्तकालयों, अग्रपथों, कला-प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।
- 3 सार्वजनिक पार्क, बगीचे, अखाड़े तथा मनोरंजन-गृह बनाना।
- 4 धर्मों का निर्माण करना।
- 5 भवनों एवं भूमि का सर्वेक्षण करना।
- 6 शान्तिपूर्ण व्यवस्था करना।
- 7 अपन-गृह, गरीब-गृह, बालक-गृह, बुढ़ गृह, रैन बसेरा आदि का प्रबन्ध करना।
- 8 अन्धों पर धर्मों को पकड़ना।

नगर निगम की आय के सधन (Income Resources)—नगर निगम का आय के प्रमुख सधनों में राज्य सरकारों द्वारा प्रत्य अनुदान, व्यापारिक प्रगतिधनों से प्रत्य आय, घरेलू द्वारा प्रत्य आय, करों द्वारा प्रत्य आय तथा ऋण हैं।

नगर निगम पर नियन्त्रण—केन्द्र शासित प्रदेशों कानून नगर निगमों पर केन्द्र सरकार तथा राज्य में विद्यमान नगर निगमों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण रहता है। निगमों की ठगनों कायों की सम्पत्ति करने का स्वतन्त्रता हटो है किन्तु केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित अधिनियमों के अन्वयत ठगने अधिकृत किया गया है। नगर निगमों के कार्य-कलापों की न्यायपरिनिष्ठा में पुनर्ती दो जा सकती है।

74वीं संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

नगरीय स्थानीय स्वराज्यन के विद्वांस में उस समय एक महत्वपूर्ण पृष्ठ बुढ़ गया जबकि भारतीय संसद ने 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर स्थानीय या नगरीय क्षेत्र की स्वराज्यन की सभाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संविधान संशोधन के मुख्य प्रवर्धनों में—सभी सभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किये जाने, मुख्य निर्वाचन अधिकारों के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में प्रति 5 वर्ष बाद इन सभाओं के निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने, स्थानीय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इन सभाओं में स्थानों की आरक्षण किये जाने तथा जनसंख्या के अनुसार में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन करने जैसे महत्वपूर्ण नियमों का सक्ते हैं।¹ निम्नलिखित नगरीय क्षेत्र की स्वराज्यन की सभाओं की संवैधानिक दर्जा

1. डॉ. अरुण एस. मिश्रा एवं डॉ. एस. वी. राव, भारतीय सरकार एवं प्रबन्धन, पृ. 204

प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण घटना है। इससे जहाँ तक समस्याओं को एक नई शक्ति प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर सारे देश में एकता की स्थिति बनेगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं की इन समस्याओं में प्रभावशाली साझेदारी होगी। इस समीक्षण सरोचन के प्रति हमारे देश के वरिष्ठ राज्यों ने इसका अनुसरण किया है। इससे देश में एकता की स्थिति बनी है।

नगरपालिका

(Municipality)

भारत के नगरों में नगरपालिकाओं का उदय किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासकाल के दौरान में ही हुआ था। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ ऐसा नियम न हो। राजस्थान के मुख्य शहरों में नगरपालिका को नगर परिषद कहा जाता है जबकि साधारण छोटे शहरों के पास कार्यों में इसे नगरपालिका या म्युनिसिपल बोर्ड कहा जाता है। नगर परिषद और नगरपालिका के संगठन, कार्यों तथा अधिकारों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं पाया जाता है। नगरीय स्थानीय शासन को इन समस्याओं का नामकरण नगर के जनसंख्या पर निर्भर करता है।

नगरपालिकाओं की स्थापना—नगरपालिकाओं का गठन ऐसे नगरों में किया जाता है जहाँ शाह में रहने वाले लोगों के लिए जन-सुविधाओं की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है और भी "नगर" के गठन के लिए जनसंख्या की एक निश्चित सीमा का होना आवश्यक है। कुछ राज्यों ने नगरपालिका को शहरी क्षेत्रों के लिए जनसंख्या एवं आय दोनों ही कर्षणार्थी निर्धारित की है। आय को शर्त को अनुचित नहीं कहा जा सकता। नगरपालिका से अपेक्षा है कि वे नगरपालिका की स्थापना तथा रख-रखाव के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था करें। नगरपालिका की स्थापना सभी की जानी चाहिए जब वहाँ की जनता उसके लिए समुचित साधन जुटाने के योग्य और इच्छुक हो। आय की कमी ही महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है जबकि कम जनसंख्या वाले स्थान में नगरपालिका बना दी जाती है। ऐसी स्थिति में नगरपालिका की आय के स्रोतों का बड़ा भाग राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है।

राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि वह नगरपालिका को अधिकार क्षेत्र को परिभाषित कर सके। शान्त द्वारा राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वह नगरपालिकाओं को अधिनियम के उन उपबन्धों से मुक्ति प्रदान कर दे जो उसके लिए अनपेक्षक हैं। कुछ नगरपालिकाएँ अवर्गीकृत भी हैं। सरकार कभी भी आदेश निकाल कर उन्हें किसी श्रेणी की नगरपालिका घोषित कर सकती है। किसी भी क्षेत्र में नगरपालिका बनाने या किसी क्षेत्र में नगरपालिका समाप्त कर देने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। राजस्थान प्रान्त में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञापित निकाल कर—

- (i) किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है।
- (ii) किसी भी नगरपालिका की सीमाएँ निर्धारित कर सकती है।
- (iii) किसी भी नगरपालिका में कोई भी क्षेत्र शामिल कर सकती है या उससे पूर्णतः अलग कर सकती है।
- (iv) किसी भी नगरपालिका की सीमाओं में अन्य प्रकार से परिवर्तन कर सकती है।
- (v) यह घोषित कर सकती है कि किसी भी विधिविधि से किसी स्थानीय क्षेत्र में नगरपालिका नहीं रहेगी।

नगरपालिकाओं का संगठन (Organisation)—नगरपालिका जनता की सभा है जो नगरपालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नगर शासन के लिए नियमो-उपनियमों का निर्माण करती है। प्रत्येक नगरपालिका में एक परिषद होती है जिसमें वयस्क मतदाताओं के आधार पर निर्वाचित सदस्य (मैमबर्स) सम्मिलित होते हैं। परिषद वह सर्वोच्च सत्ता है जो उन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है जो नगरपालिका को सौंपे गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों में नगरपालिकाओं के संगठन, कार्यकाल आदि में भिन्नता मिलती है तथापि सामान्य रूपरेखा मिलती-जुलती है।

1 नगरपालिकाओं का निर्वाचन—राजस्थान में नगर परिषद या नगरपालिका मण्डल के सदस्यों की संख्या का नियमन सरकार द्वारा किया जाता है। चुनाव वयस्क मतदाताओं के आधार पर प्रति जैसे वर्ष किए जाते हैं। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होते हैं। चुनाव के लिए कक्ष या नगर को विभिन्न क्षेत्रों अथवा सार्कों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक सार्क से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। सीटों तथा सार्कों के निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट जारी होती रहती है। नगर परिषद या नगरपालिका-मण्डल में शिखर और पिछड़े जातियों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जिस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या जनजातियों का बहुमत होता है उस क्षेत्र को प्रायः इन जातियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है अर्थात् ऐसे क्षेत्रों में केवल इन जातियों के प्रतिनिधि ही चुनाव सार्क सकते हैं। यदि कोई स्त्री चुनाव जीत कर नहीं आई हो तो शिखरों के प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य अपने बहुमत से दो स्त्री सदस्यों को मनोनीत करते हैं।

2. सदस्यों के लिए योग्यताएँ—राजस्थान में नगरपालिका के सदस्य होने के लिए निम्नांकित योग्यताओं का होना आवश्यक है—

- (i) यह व्यक्ति उस पालिका के क्षेत्र में भवदाता हो।
- (ii) यह पौजदारी अदालतों में एक वर्ष से अधिक सजा पाया हुआ न हो। (ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष समाप्त होने के बाद चुनाव लड़ सकता है।)
- (iii) यह व्यक्ति राज्य या स्थानीय सत्ता की नौकरी में न हो अथवा कदाचार के आरोप में निकाला न गया हो। (पदभूत व्यक्ति तीन वर्ष बाद चुनाव लड़ सकता है।)
- (iv) वह दिवालिया अथवा पागल न हो।
- (v) वह नगरपालिका की ओर से या उसके विरुद्ध किसी मामले में वकील न हो अथवा नगरपालिका से किसी भी रूप में ठेके या व्यापार आदि से सम्बन्धित न हो।

सदस्य चुन लिए जाने के बाद किसी प्रकार की अयोग्यताएँ पाई जाएँ तो निर्वाचित सदस्य को अपना पद त्याग करना पड़ता है।

3. पदावधि—नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है। यद्यपि सरकार को अधिकार है कि वह नगरपालिका को अवधि से पूर्व ही भंग करके प्रशासक नियुक्त कर दे।

4. एक वार्ड से अधिक के लिए निर्वाचन में खड़े होने पर प्रतिप्रत्यक्ष—राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 25 में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उसने अपना नामांकन पत्र एक से अधिक वार्डों के लिए प्रस्तुत किया है तो उसे निर्वाचन के लिए निश्चित लिखित से पूर्व विवाध एर वार्ड के अन्य समस्त वार्डों से अपना नामांकन पत्र वापस लेना आवश्यक होता है।

5. पद की शपथ और त्यागपत्र—अधिनियम के अनुसार नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्यों का पालन करने से पूर्व जिलाधीश अथवा सरकार द्वारा मनोनित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रश्न में शपथ लेनी होती है और उस पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। यह व्यवस्था भी है कि कोई सदस्य नगरपालिका की प्रथम बैठक की तिथि से तीन मास की अवधि में शपथ ग्रहण नहीं कर पाता तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। अधिनियम के अनुसार, कोई भी सदस्य लिखित रूप में अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र का नोटिस अध्यक्ष को दे सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र नोटिस के 15 दिन बाद प्रभावशाली होगा। यह आवश्यक है कि नोटिस प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा उचित रूप में प्रमाणित हो। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार ऐसा त्याग-पत्र उसके प्रभावशाली होने से पूर्व वापस लिया जा सकता है। अधिनियम में दिए गए कुछ प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार समुचित आधारों पर किसी सदस्य को हटा भी सकती है।

6. पदाधिकारी—अधिनियम की धारा 65 में व्यवस्था है कि प्रत्येक नगरपालिका मण्डल के लिए एक अध्यक्ष और उपअध्यक्ष होगा जिनका चुनाव नियम के अनुसार मण्डल के सदस्यों द्वारा अपने स्वयं में से ही किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक नगर परिषद के लिए एक सभापति और एक उप-सभापति होगा जिनका चुनाव नियम के अनुसार परिषद के पार्षदों द्वारा स्वयं में से ही किया जाएगा। ये पदाधिकारी नगरपालिका के कार्यकाल और अपनी सदस्यता-पर्यन्त अपने पद पर काम करते हैं। दौ-तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सदस्य उन्हें हटा सकते हैं। वे स्वयं भी त्याग-पत्र दे सकते हैं और सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने कार्य की लापरवाही के लिए उन्हें हटा सकती है। बड़ी नगरपालिकाओं में एक कर्मचारी ऑफिसर अथवा सचिव भी होता है। इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। नगरपालिका की आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, इन्वीनिस्ड, ओवरसिपर, स्वास्थ्य अधिकारी, सैनेटरी इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। इनकी नियुक्ति बोर्ड करता है।

7. समितिपूर्व—कार्य की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक नगरपालिका में विभिन्न समितियों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक समिति को अलग-अलग कार्य सौंपा जाता है। सभी समितियाँ बोर्ड अथवा कौन्सिल के नियन्त्रण में और उसके आदेशानुसार अपना कार्य करती हैं। बोर्ड अथवा कौन्सिल को यह पूरा अधिकार होता है कि वह उनके निर्णयों में परिवर्तन या संशोधन कर दे।

अधिनियम की धारा 73 में व्यवस्था है कि प्रत्येक कौन्सिल अर्थात् नगर परिषद की कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें ये सदस्य सम्मिलित होंगे—(i) परिषद का सभापति, (ii) परिषद का उप-सभापति, (iii) परिषद द्वारा निर्वाचित परिषद के 7 सदस्य (पार्षद) तथा परिषद द्वारा निर्मित समितियों के अध्यक्ष। परिषद का नगरपालिका आयुक्त कार्यकारिणी समिति का पदेन सचिव होता है।

कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक परिषद धारा 73(3) के अनुसार निम्नलिखित समितियों का निर्माण भी करती है—(i) वित्त समिति, (ii) स्वास्थ्य और सफाई समिति, (iii) भवन तथा निर्माण समिति, (iv) नियम तथा उप-नियम

समिति (v) सार्वजनिक वाहन समिति। कार्यकारिणी समिति और अन्य समितियाँ ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों को प्रयोग में ला सकेंगी तथा उनका चालन और निष्पादन कर सकेंगी जो परिषद द्वारा उन्हें प्रदान किए गये हैं। उल्लेखनीय है कि कार्यकारिणी समिति का गठन केवल शहरी नगरपालिकाओं अर्थात् नगर परिषदों में ही अनिवार्य है, नगरपालिका मण्डलों में नहीं। उपर्युक्त चौथी समितियों का शहरी नगरपालिकाओं अर्थात् नगर परिषदों में होना अनिवार्य है। साथ ही अन्य समितियों नगर परिषदों की सुविधानुसार गठित की जा सकती हैं।

8 नगरपालिका की बैठकें—अधिनियम की धारा 70 के अनुसार, कार्य निपटाने के लिए प्रत्येक माह में नगरपालिका की कम से कम एक साधारण बैठक होने जरूरत है। अध्यक्ष का दायित्व है कि वह इन सामान्य बैठकों के लिए तिथियाँ नियत करे। अध्यक्ष जब भी उचित समझे, एक विशेष सामान्य बैठक सम्पन्न कर सकता है। ऐसी विशेष सामान्य बैठक अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को कृत सभा के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर की जाती है। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस समय उपस्थित सदस्यों में से किसी एक ऐसे सदस्य द्वारा की जाती है जिसे बैठक में उठा अवसर पर अध्यक्ष चुन लिया जाए। समस्त प्रश्नों का निर्णय ठरस्थित या मत देने वाले 75% (अध्यक्ष सहित) के बहुमत से किया जाता है। बराबर मत देने की स्थिति में अध्यक्ष की द्वितीय मत देने का अधिकार होता है। बैठक की गणपूर्ति के लिए सदस्यों की सम्पूर्ण सभा के एक-तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है।

नगरपालिका की शक्तियाँ (Powers)—सभी राज्यों में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ और अधिकार एक जैसे हैं। राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

1. नियम बनाने की शक्ति—प्रत्येक नगरपालिका को ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धारा 297 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के विरुद्ध नहीं होंगे। नगरपालिका को कार्य संचालन के बारे में तथा अपनी शक्तियों या कर्तव्यों को सौंपने के सम्बन्ध में, समितियों की नियुक्तियों एवं निर्माण के सम्बन्ध में भी अनेक अधिकार होते हैं। नगरपालिका सामान्यतः अपने पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के पद-प्रदर्शन के लिए नगरपालिका के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त विषयों पर नियम बना सकती है। किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी, जिससे प्रतिभूति (सिम्बोलिटि) लेना उचित समझा जाए, प्रतिभूति की राशि तथा आकृति का निश्चय भी नगरपालिका द्वारा किया जाता है। किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को नियुक्त करने, हटाने या विमुक्त करने के तरीकों और शर्तों का निश्चय किया जाता है। वे सभी शक्तियाँ नगरपालिका (याहें म्युनिसिपल बोर्ड हो या म्युनिसिपल कांसिल हो) को अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, लेकिन इस धारा के अन्तर्गत किसी नगरपालिका द्वारा बनाया गया नियम तब तक प्रभाव में नहीं आएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो जाए।

प्रत्येक नगरपालिका को समय-समय पर ऐसी उपविधियाँ बनाने का अधिकार है जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रतिकूल नहीं हों। अधिनियम की धारा 90 में उन विषयों की व्यवस्था है जिनके सम्बन्ध में नगरपालिका को सामान्यतः उपविधियाँ बनाने की शक्ति प्राप्त है, परन्तु नगरपालिका द्वारा बनाई गई कोई भी उपविधि तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं कर दी जाए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 91 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि उपर्युक्त नियम और उपविधियाँ मुद्रित होंगे तथा सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए नगरपालिका कार्यालय में भुत्ते रखे जाएँगे और उनकी मुद्रित प्रतियाँ लागत मूल्य पर विक्रय के लिए रखी जाएँगी।

2. सम्पत्ति को अगल और धारण करने की शक्ति—अधिनियम की धारा 92 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका पल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति को गाण कर सकती है, फिर चाहे वह नगरपालिका की सोमाओं के अन्दर हो या बाहर।

नगरपालिका को प्राप्त अथवा नगरपालिका के द्वारा निर्मित की गई समस्त धनराशियाँ नगरपालिका कोष का अंग होंगी अर्थात् राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए अथवा लगाए गए समस्त कर, मार्ग कर तथा अन्य कर, जुर्माने, शुल्क, नगरपालिका द्वारा बेची गई भूमि या अन्य सम्पत्ति से प्राप्त करों तथा उससे प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण किराया आदि नगरपालिका निधि का अंग होते हैं परन्तु शर्त यह है कि कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा तय की गई किसी योजना द्वारा स्वीकृत या आरोपित किसी दायित्व पर किसी प्रकार से प्रभाव न डाले। नगरपालिका अपनी निधि तथा सम्पत्ति का प्रयोग राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे काम में ला सकती है जो सार्वजनिक हित में हों, तथापि इस सम्बन्ध में कुछ शर्तें धारा 94 में निर्धारित की गई हैं। धारा 96 के अन्तर्गत नगरपालिका को अतिरिक्त कोषों को जमा करने अथवा उनका विनियोग करने की शक्ति दी गई है और धारा 97 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नगरपालिका को शकम उधार लेने की शक्ति भी प्राप्त है।

नगरपालिकाओं के कार्य (Functions)

(क) प्राथमिक एवं अनिवार्य कार्य—अधिनियम की धारा 98 के अनुसार ५ दैनिक कार्य निम्नानुसार हैं—

1. सार्वजनिक स्थानों और भवनों में प्रवेश की व्यवस्था करना तथा सड़कें का प्रबन्ध करना तथा गन्दगी हटाना।
2. सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर जम छिड़कना।
3. हानिकारक वनस्पति को हटाना और स्थान सार्वजनिक बाधाओं को कम करना।
4. आग बुझाना और आग से जागरूकों को जानकारी का रक्षण करना।
5. उद्देगकारी अथवा खतरनाक व्यक्तियों या वृत्तियों का नियन्त्रण करना।
6. सार्वजनिक गतिधरो बाजारों, नावियों, सामान-घर, बूढ़ेछानों, तालाबों, कुँओं, कण्डे पाने के स्थान आदि का निर्माण और उनकी व्यवस्था करना एवं सफाई करना।
7. सार्वजनिक शौचालयों और भूखण्डों का प्रबन्ध करना।
8. सार्वजनिक मार्गों अथवा स्थानों और ऐसे स्थानों से जो निज सम्पत्ति नहीं है जो जनता के उपयोग के लिए मुक्त है, स्वयंसेवकों और आगे निकल हुए भागों को हटाना।
9. खतरनाक भवनों को सुरक्षित करना या हटाना तथा असुरक्षित वस्तुओं या स्थानों का उद्धार करना।
10. मूर्तों को जमाने या गड़ने के स्थानों का प्रबन्ध करना।
11. जन्म और मरण का हिसाब रखना।
12. अन्धों और अमानवों के निवास का प्रबन्ध करना।
13. सार्वजनिक आरक्षणों को स्थानों और व्यवस्था करना और जनसङ्घरण को विविधता सम्बन्धी महत्वा देना।
14. सार्वजनिक टीकों का प्रबन्ध करना।
15. पगल कुत्तों को पकड़ने और ऐसे कुत्तों द्वारा काट गए लोगों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना।
16. पन और कूड़े-कचरे में मिश्रित खाद तैयार करने के लिए प्रबन्ध करना।
17. सार्वजनिक वाहनस्थलों की स्थाना आदि।

विशेष ध्यान—प्रत्येक नागरिक को दो विशेष दायित्व निभान होते हैं—

(क) भयवर् बँपाई जी अवस्था में विशेष विज्ञप्ति की व्यवस्था करन और बँपाई की संकल्पन के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(ख) अकाल या अतिवृष्टि के समय अनायास लोगों की सहायता करना।

(ख) गौण या ऐच्छिक कार्य—प्रत्येक नगरपालिका के मुख्यतया ऐच्छिक या गौण कार्य निर्धारित है—

1. नई सड़कों एवं गलियों का निर्माण करना तथा सड़कों पर वृक्ष लगवाना।
2. सार्वजनिक पार्कों, बगीचों, पुस्तकालयों, अस्पतालों, कर्मालयों, विद्यालयों आदि का निर्माण एवं प्रबन्ध करना।
3. गन्दी बस्तियों को सभ्य बनाना तथा ऐसे कार्य करना जो जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा या सुविधा के लिए आवश्यक हों।
4. प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना करना और उनकी व्यवस्था करना।
5. पशु घरों की स्थापना करना।
6. नौका और प्रदर्शनियों को लागू करना।
7. सार्वजनिक स्वच्छता समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का प्रबन्ध करना।
8. स्थानीय कला और उद्योग-धंधों के लिए कर्ष देना आदि।

एक सरकार अप्रतिमता को पाप 100 के अनुसार, किमी भी नागरिकों को प्रत्यक्ष और विशेष कार्य सम्बन्धी श्रवणों से मुक्त कर सकती है कि अमुक प्रत्यक्ष या विशेष कार्य नागरिकों के विवेकानुसार किया जाने वाला कार्य समझा जाएगा।

अपेक्षित साधन-निरूपितकर्मों को विभिन्न प्रकार के कर लागू कर अधिकार है, जैसे—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पर कर, संपत्ति टैंगि, न्याय टैंगि, सहायक कर आदि पर कर, सीमा में आने वाली वस्तुओं और पशुओं पर टैंगि कर, सार्वजनिक सड़कें कर, सार्वजनिक रोस्तों कर, सार्वजनिक जल-व्यवस्था कर, व्यापार एवं पेशा कर, आन्दोलन कर, टैंगि और व्यापारिक संपत्तियों पर कर आदि लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि नगरपालिका वस्तुतः सभी करों को

संगत। आवास कर सामान के आवागमन पर कर व्यवसाय एवं पशु कर आदि करों को लगाना तो आवश्यक है, यद्यपि कुछ कर ऐसे हैं कि जिन्हें लगाना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, नगरपालिका चाहे तो मोटरों पर कर, नगरी पर कर एवं आवागमन के अन्य सधनों पर कर लगा सकती है। घर लगाने से पूर्व वोटों को उसके सम्बन्ध में आवश्यक नियम आदि बनाने पड़ते हैं और सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। नगरपालिकाओं को कुछ खाद्य सामग्रियों के विप्रेषण का साधन देना भी अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समय-समय पर सहायता दी जाती है। नगरपालिकाएँ सरकार की पञ्चुरी से ऋण ले सकती हैं। साइरोस फीस, जुर्माना आदि से भी नगरपालिकाओं को आय होती है।

नगरपालिकाओं पर नियन्त्रण—यद्यपि नगरपालिकाएँ बहुत कुछ स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करती हैं तथापि इन पर राज्य सरकार का नियन्त्रण रहता है। सरकार इन्हें सहायता अनुदान और ऋण आदि देती है अतः सरकार के सेवा परीक्षक इन सम्पत्तियों के हिसाब-किताब की जाँच-पड़ताल करते हैं। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि नगरपालिका द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने पर या अपना कार्य ढग से न करने पर वह उसे बन्द कर दे और उसकी जगह प्रशासक नियुक्त कर दे। राज्य सरकार नगरपालिका के पदमधिकारियों को हटा सकती है, यदि वे अपने पदों का दुरुपयोग करें अथवा नगरपालिकाओं के कार्य में गड़बड़ी करें।

अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ एवं नगर क्षेत्र समितियाँ

(Notified Area Committees & Town Area Committees)

महानगर स्थानीय स्वशासन में जहाँ नगरपालिकाओं की व्यवस्था नहीं हो पाती है वहाँ 'अधिसूचित क्षेत्र समिति' एवं 'नगर क्षेत्र समिति' बनाई जाती है।

अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ

कुछ बड़े कस्बों और उन नगरों में जहाँ नगरपालिकाएँ स्थापित नहीं की जा सकती, अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ स्थानीय प्रबंध का कार्य करती हैं तथा इन समितियों का निर्माण नए विकासशील नगर के लिए किया जाता है। समिति के निर्माण की सूचना राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित कर दी जाती है, इसलिए इसको 'अधिसूचित क्षेत्र समिति' कहते हैं। यह समिति राज्य नगरपालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित दायों के अन्तर्गत कार्य करती है, किन्तु इन पर अधिनियम के केवल वे प्रावधान ही लागू होते हैं जो गजट में अधिसूचित कर दिये जाते हैं। सरकार की अधिकार है कि वह समिति को ऐसी शक्तियाँ सौंपे जिनका प्रयोग किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत न किया जा सकता हो। अधिसूचित क्षेत्र समितियों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के होते हैं। प्रायः राज्य सरकार ही उसके सदस्यों तथा अध्यक्ष को मनोनीत करती है। इस प्रकार यह पूर्णतः राज्य सत्ता होती है। इन समितियों के कार्य, अधिकार, आय स्रोत आदि लगभग ठाढ़ा प्रजा के होते हैं जैसे नगर पालिकाओं के होते हैं। बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ विद्यमान हैं। प्रायः इनकी संख्या घंटौ-घण्टौ रहती है।

नगर-क्षेत्र समितियाँ

छोटी जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों अर्थात् छोटे कस्बों में नगर क्षेत्र समितियाँ स्थापित की जाती हैं। भारत में असम, केरल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल-प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों में नगर क्षेत्र समितियाँ हैं। नगर क्षेत्र समितियों का सबसे अधिक प्रचलन उत्तर प्रदेश में है। इन समितियों का शासन राज्य सरकार द्वारा पारित पृथक् अधिनियमों के अन्तर्गत चलता है। जिलाधीश को नगर क्षेत्र समिति के सम्बन्ध में विप्रेषण की पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इनके सदस्यों की संख्या प्रायः कम होती है। इन समितियों के कार्य-क्षेत्र और आय स्रोत नगरपालिकाओं की तुलना में सीमित होते हैं। इन्हें छोटी नगरपालिका कहा जा सकता है।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट एवं छावनी बोर्ड

(Improvement Trust, Port Trust and Cantonment Boards)

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

बड़े नगरों की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के लिए नगरपालिका के साथ-साथ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किए जाते हैं। इनके कार्य नगरपालिकाओं के कार्यों से कुछ भिन्न होते हैं। ये ट्रस्ट इमारतों की अव्यवस्थित रूप से बनने से रोककर, नगर का व्यवस्थित रूप से विकास करते हैं। नगरों में खुले स्थानों, पार्कों, चौड़ी सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक शौचालयों आदि की व्यवस्था करना इस ट्रस्ट का कार्य है। इन ट्रस्टों में कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ मनोनीत होते हैं। जिन नगरों में ये ट्रस्ट नहीं होते, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य नगरपालिकाएँ ही करती हैं।

पोर्ट ट्रस्ट

बड़े-बड़े बंदरगाहों तथा कोलछाव, मुम्बई, चेन्नई, विशाखपट्टनम, कोलकाता आदि स्थानों पर स्थानीय समस्याओं के रूप में पोर्ट ट्रस्ट है। इसके सदस्य वाणिज्य और व्यापार मस्याओं द्वारा चुने जाते हैं तथा सरकार भी मनोनीत करती है। इनका सविधान भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पर आधारित होता है। इनका सभापति सरकारी व्यक्ति द्वारा होता है। इनका मुख्य कार्य है—बंदरगाह से सम्बद्ध मायनों का प्रबन्ध, बंदरगाह की रक्षा, माल का प्रबन्ध, सामान उठाना एवं चढ़ाना, यात्रियों को सुविधाएँ प्रदान करना आदि।

छावनी बोर्ड

छावनी क्षेत्रों में छावनी बोर्ड स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य इन क्षेत्रों के निवासियों का नगरिक सुविधाएँ और कल्याण सेवारत प्रदान करना है। सम्बद्ध कमान के जनरल आफिसर कमान्डिंग इन्-चार्ज और केन्द्र सरकार के नियंत्रण में ये बोर्ड स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि इन बोर्डों में निर्वाचित और नामांकित सदस्यों का संख्या जा 1 से लेकर 7 सम्मिलित होती है तथापि कानूनी प्रावधानों के अनुसार नामांकित सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों का संख्या से एक से अधिक हो सकती है। इन बोर्डों को कर लगाने का अधिकार है जो इनके उद्देश्य का मुख्य स्रोत है। बोर्डों का द्वारा पैसा बिक्रि एवं बजट अनुमानों की जाँच-पड़ताल और उनकी स्वाकृति जनरल आफिसर कमान्डिंग-इन्-चार्ज द्वारा होती है। छावनी बोर्ड छान क्षेत्रों में संगठित है—

- 1 प्रथम श्रेणी की छावनियाँ—इनकी औसतिक जनसंख्या 10,000 से अधिक है। ये संख्या में 30 हैं।
- 2 द्वितीय श्रेणी की छावनियाँ—इनकी औसतिक जनसंख्या 2500 और 10,000 के बीच में है। ये संख्या में 19 हैं।

3 तृतीय श्रेणी की छावनियाँ—इनकी औसतिक जनसंख्या 2500 से कम है। ये संख्या में 13 हैं।
कार्य—छावनी बोर्डों की दृष्टि से छावनी बोर्ड नगरपालिका जैसा ही होता है किन्तु इन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं। छावनी क्षेत्र में सड़कें एवं दीन दुराचार के दमन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छावनी बोर्ड के कार्य अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों प्रकार के हैं। इनमें प्रमुख अनिवार्य कार्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है—

- 1 मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था।
- 2 मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छिड़काव।
- 3 मार्गों, नालियों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सफाई।
- 4 धार्मिक तथा खतरनाक व्यवसायों, उद्यमों एवं परिपटियों का नियमन।
- 5 लोक-सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधा के आधार पर मार्गों तथा अन्य स्थानों से अवरोधकों का हटाना।
- 6 खतरनाक इमारतों एवं स्थानों को सुरक्षित बनाया जायें।
- 7 मृतक-क्रिया के स्थल का आँकड़ा एवं नियमन।
- 8 मार्गों, पुलियों, झरोखों, गेटों, गलियों, जल निकास व्यवस्था, गालियाँ का निर्माण तथा मल निष्काशन की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।
- 9 सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना एवं उनकी अनुरक्षण करना।
- 10 शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।
- 11 जन्म एवं मरण का पंजीकरण।
- 12 सार्वजनिक टोकियों की व्यवस्था तथा सार्वजनिक चिकित्सालयों की स्थापना।
- 13 प्राथमिक पठशालाओं की स्थापना।
- 14 अग्नि से बचाव।

छावनी बोर्ड के ऐच्छिक कार्य इस प्रकार हैं—1 सार्वजनिक उद्देश्यों की चीजों, वस्तुओं तथा कुंओं का निर्माण।
2 अस्वास्थ्यकर स्थानों की निजसंयोग बनाना। 3 जनगणना करना। 4 सर्वेक्षण करना। 5 बिजली का प्रबन्ध करना।
6 सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का प्रबन्ध।

छावनी बोर्डों के प्रशासन का रूप यद्यपि सैनिक ही बना हुआ है किन्तु भी निर्वाचित हलों को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक परिवर्तन किए गए हैं जैसे—(i) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के छावनी बोर्डों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की संख्या बराबर कर दी गई है (ii) तृतीय श्रेणी के छावनी बोर्डों में प्रायः एक निर्वाचित और एक मनोनीत सदस्य होता है (iii) प्रबन्धन निर्माण समिति में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया है, (iv) इमारतों और सीमा दीवारों पर नियन्त्रण रखने एवं सड़कें के सम्बन्ध में औसतिक क्षेत्र समिति के अधिकारों में वृद्धि की गई है।

विरोध—नगरीय शासन व्यवस्था में छावनी बलों की उपस्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। इसे केवल एक लोकतांत्रिक देश में स्थानीय स्तर पर सैनिक शासन का ही प्रचलन रूप कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिभूत छावनिर्दी बड़े नगरों के निकट स्थित हैं और इतने निकट स्थानीय शासन के दो रूपों का चलना लोकतांत्रिक स्थिति में उचित नहीं होता है।

भारत में नगरीय स्वशासन की प्रमुख समस्याएँ

भारत में नगरीय स्वशासन की समस्याओं को विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. बी. एम. सिन्हा ने भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं की प्रमुख समस्याओं को निम्नांकित प्रकार से बताया है—

1. जनसाधारण की उदासीनता—इन समस्याओं को जनसाधारण से जो सम्बन्ध मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाता जिसके कारण हमें असमर्थता, अकार्यकुशलता तथा ईमानदारी की कमी बनी रहती है।

2. पेशेवर राजनीतिज्ञों की मनमानी—बड़े शहरों में जनता की उदासीनता तथा पेशेवर राजनीतिज्ञों की मनमानी का एक कारण यह है कि इन शहरों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बाहर से आए हैं, जिनका स्थानीय जनता तथा शहर से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। शहर को अच्छा बनाने की भावना इनके मस्तिष्क में आती ही नहीं है।

3. अशिक्षा—जनसाधारण का काफी बड़ा भाग अशिक्षित है। अपने अधिकार तथा कर्तव्यों के विषय में जागरूक नहीं है। पढा-लिखा वर्ग अपनी ही समस्याओं में उलझे रहने के कारण नगर प्रशासन की समस्याओं के प्रति उदासीन रहता है। फलतः वहाँ ऐसा कोई प्रभावशाली वर्ग नहीं होता जो नगर प्रशासन में सुधार के लिए सक्रिय प्रयत्न करे।

4. व्यक्तिगत तथा दलगत लाभ—निर्वाचित पदाधिकारी अपना अधिकांश समय अपने व्यक्तिगत तथा दलगत लाभ के लिए दाक-पेचों तथा अखाड़ेबाजों में व्यतीत करते हैं। इससे नगर प्रशासन का हित तथा जनता का हित गौण हो जाता है।

5. दलगत राजनीति—इन समस्याओं का प्रशासन दलगत राजनीति का शिकार हो गया है। व्यक्तिगत, दलगत तथा राजनीतिक कारणों से विकास कार्यक्रमों की अवहेलना की जाती है। दिन-भरिदिन के प्रशासन पर जैसे—क्यों की बमूली, साइनीस जारी करना, संस्था के उपनिषदों की लागू करना आदि पर राजनीति हथौड़ी रहती है।

6. ईमानदारी का अभाव—जनसाधारण की उदासीनता तथा पेशेवर राजनीतिज्ञों के कारण अच्छे ईमानदार व्यक्ति इन समस्याओं की ओर आकर्षित नहीं होते। परिणामस्वरूप इन समस्याओं की बागडोर क्षेत्र के अच्छे ईमानदार व्यक्तियों के हाथों में न होकर, पेशेवर राजनीतिज्ञों के हाथों में होती है।

7. अस्तोत्रजनक वित्तीय स्थिति—इन समस्याओं की वित्तीय स्थिति असन्तोषजनक है जिसके मुख्य कारण हैं—(क) मुद्रा-स्फीति तथा इसके फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि। (ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सम्पत्ति एवं ऋणन कर से छूट। (ग) सम्पत्ति कर का आधार वार्षिक किराया है। किराया नियन्त्रण वाले क्षेत्रों में किराया नहीं बढ़ाया जा सकता अतः इन समस्याओं को कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना होता है। (घ) कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि। (ङ) प्रशासकीय व्यय का विस्तार। (च) कर बढ़ाने सम्बन्धी आय के साधन न होना। (छ) करों की बमूली में झील तथा बढ़ती हुई बकाया राशि। (ज) इन समस्याओं द्वारा धन का अपव्यय।

8. वित्तीय स्थिति में सुधार के प्रयासों का अभाव—इन समस्याओं ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की दिशा में कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। नए कर लगाने अथवा चालू करों में बड़ोत्तरी करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया गया है। निर्वाचित सदस्यों को यह आशय रहता है कि इससे उनकी लोकप्रियता पर भौतिक प्रभाव पड़ेगा। फलतः इन समस्याओं का सतत प्रयास यह रहता है कि राज्य सरकारों से अनुदान अथवा ऋण के रूप में अधिक से अधिक सहायता प्राप्त कर ली जाए।

9. करों के प्रति जनता का दृष्टिकोण—करों के विषय में स्थानीय जनता के विचार मलत है। यदि नगर प्रशासन में सुधार लाना है नयी सेवाएँ उपलब्ध करवानी हैं तो इनका व्यय-भार नगर निवासियों को उठाना ही होगा। नगर निवासी नयी सेवाओं की तथा चालू सेवाओं में सुधार की माँग करते हैं, पर इससे व्यय के लिए करावैपण अथवा करों की दर में वृद्धि का विरोध करते हैं।

10. सुविधाओं का दुरुप्रयोग—सार्वजनिक सम्पत्ति, सेवाओं एवं सुविधाओं के दुरुप्रयोग के कारण इनका उपयोग अत्यधिक हो रहा है। उदाहरण के लिए सड़क पर कुड़ा-कचरा फेंक देना, जहाँ-तहाँ धुक देना, नल के उपयोग के बाद बन्द न करना, सड़क के किनारे बच्चों को मलमूत्र त्याग के लिए बैठना आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इससे एक ओर तो गन्दगी फैलती है तथा दूसरी ओर इन सेवाओं पर इन संस्थाओं का व्यय-भार बढ़ता है।

11. **ग्रामीण क्षेत्रों का दबाव**—बड़े शहरों में आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का दबाव रहता है। ये लोग नगरपालिका की आय में कोई योगदान नहीं करते, पर नगरपालिका की सेवाओं तथा यातायात, बाजार, अस्पताल तथा शिक्षण संस्थाओं आदि का लाभ अवश्य उठाते हैं।

12. **राजनीतिक आधार पर नियन्त्रण**—राज्य सरकारों द्वारा नियन्त्रण के अधिकारों का उपयोग कई बार राजनीतिक आधारों पर किया जाता है। विरोधी दलों द्वारा प्रशासित संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाता है। विरोधी दल के चेयरमैन को पद से हटा दिया जाता है अथवा उसे अधिकार विहीन बना दिया जाता है। अनेक बार न्यायालयों ने इस प्रकार के आदेशों को अवैध ठहराया है।

13. **राज्य सरकारों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग**—राज्य सरकारें अनेक बार अपने नियन्त्रण के अधिकारों का समय रहते उचित रूप से उपयोग नहीं करती हैं। यदि समय पर उचित मार्गदर्शन हो जाए तो कई अवसरों पर संस्था को अधिकृत अथवा भंग करने की स्थिति उत्पन्न ही न हो।

14. **चिंतनीय प्रशासन में त्रुटियाँ**—सेवा-परीक्षण के फलस्वरूप इन संस्थाओं के चिंतनीय प्रशासन में प्रायः कई त्रुटियाँ पाई गई हैं, जैसे—(क) समय पर करों का वसूल न होना तथा बकया कर की राशि एकत्रित न होना। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में प्रयास काफी कम हो गये हैं तथा बकया राशि की मात्रा में वृद्धि हुई है। (ख) बजट की निर्धारित राशि से अधिक व्यय की प्रवृत्ति। (ग) आय के स्रोतों के अनुमान से कम आय की प्राप्ति। (घ) भुगतान में अनियमितताएँ यथा दुबारा भुगतान बिना यथेष्ट जाँच-पड़ताल के भुगतान, झूठे यात्रा विलों के भुगतान आदि। (ङ) स्टॉक रजिस्टर में अनियमितताएँ। (च) अनुदानों का दुरुपयोग - जिस उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त किए गए हों उस पर व्यय न करके अन्य मदों पर व्यय करना। (ज) टेण्डर स्वीकार करने के नियमों का उल्लंघन तथा कम दर वाले टेण्डरों को बिना उचित कारण के रद्द कर देना। (झ) निर्वाचित अधिकारियों द्वारा बिना किसी प्रशासकीय औचित्य के हारि करना। (झ) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के वर्षों में इन संस्थाओं ने अधिक से अधिक राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है, योजनाबद्ध विकास के लिए उपलब्ध धनराशि में से इन संस्थाओं को अनुदान आदि दिए गए, फलतः इन संस्थाओं ने धीरे-धीरे स्वावलम्बन की भावना को एकदम मुला दिया है और अपने सभी कार्यक्रमों के व्यय के लिए वे राज्य सरकार से सहायता की अपेक्षा करती रहती हैं।

15. **निम्नकोटि की कुशलता**—इन संस्थाओं में प्रशासकीय कुशलता का स्तर निम्न कोटि का रहा है। इन संस्थाओं में अच्छे कर्मचारियों का अभाव है। वैसे ही प्रत्येकी इन संस्थाओं की ओर आकर्षित होते हैं, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के अच्छे प्रतिष्ठानों द्वारा हाईट दिए गए हैं।

16. **कर्मचारियों में कर्तव्य पालन का अभाव**—कर्मचारियों में ईमानदारी तथा कर्तव्यपालन की भावना को प्रायः कमी पाई जाती है। अधिकतर कर्मचारी किसी तरह राजनीतिज्ञों के सम्पर्क में आकर अपना स्वार्थ साधने के प्रयास में लगे रहते हैं। उन्हें कार्यपालय में आकर ईमानदारी से काम करने का न तो अवसर मिलता है और न इसमें उनकी रुचि ही होती है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतनमान बहुत कम होता है अतः रिश्वत, दस्तूरी आदि का बड़ा जोर रहता है।

भारत में नगरीय स्थानीय प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव

डॉ. सिन्हा ने नगरीय स्थानीय प्रशासन में सुधार के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं—

1. **ईमानदार नेता एवं कर्मचारी**—इन संस्थाओं को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि उचित एवं ईमानदार नेता तथा कर्मचारी इन संस्थाओं की ओर आकर्षित हों और यह तभी सम्भव है जब इन संस्थाओं के प्रति जनता की सम्मान भावना बड़े तथा सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण न हो। यदि अच्छे लोग इन संस्थाओं की ओर आकर्षित होंगे तो निम्न श्रेणी के राजनीतिक नेता अपनी घमण्डी नहीं कर सकेंगे।

2. **सेवा शर्तों राज्य सरकार के संपादन**—इन संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतनमान तथा सेवा शर्तें राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समकक्ष होनी चाहिए। यदि राजकीय स्तर पर इनकी सभी सेवाओं को एकीकृत करने की अथवा सेवाओं की व्यवस्था हो जाए तो इस दिशा में अच्छी प्रगति हो सकती है।

3. **नेतृत्व तथा कार्मिक व्यवस्था में सुधार**—कोई भी संस्था बिना उचित प्रकार के नेतृत्व तथा अच्छे कार्मिकों के सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। वर्तमान स्थिति अत्यन्त ही असन्तोषजनक है। इस दिशा में सुधार के बिना इन संस्थाओं का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता।

4. **दलगत राजनीति से दूरी रखना**—इन संस्थाओं के निर्वाचनों में यदि दलगत राजनीति से पोर रखने का प्रयत्न किया जाए तो अच्छा हो। स्थानीय संस्थाओं के प्रशासन में दलगत राजनीति का स्थान नहीं होना चाहिए। इन संस्थाओं का निर्वाचन निर्दलीय आधार पर किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों में यह समझौता किया जा सकता है कि वे स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचनों में दलरूप नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में स्थानीय जनता प्रयत्नशिलों को चुनाव उनकी योग्यता

के आधार पर कर सकेंगी तथा इन संस्थाओं को उचित प्रकार का नेतृत्व प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही इन संस्थाओं के निर्वाचन व्यवस्था को सीमित करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि योग्य प्रत्याशी धनाभाव के कारण चुनाव में भाग लेने से वंचित न रह जाएँ।

5. आचरण संहिता—यह आवश्यक है कि निर्वाचित नेताओं तथा अन्य राजनीतिज्ञों के लिए एक आचरण संहिता बनार् तथा कठोरता के साथ उसका पालन किया जाना चाहिए।

6. आय वृद्धि के प्रयास—इन संस्थाओं की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

7. मास्टर प्लान—यह निम्नलिखित प्रयास किया जाना चाहिए कि नगर सुन्दर एवं योजनाबद्ध रूप से विकसित हो। नगरीय के बहुमुखी विकास के लिए मास्टर प्लान का निर्माण किया जाना चाहिए और भूमि का उपयोग उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। शहरों के पुराने भागों में यद्यपि अब मूलभूत सुधार सम्भव न हों, पर नगर के नए भागों को पूर्णतया नियन्त्रित किया जाना चाहिए।

8. नगरीय समस्याओं के समाधान के प्रयास—नगर निगम तथा नगरपालिका प्रशासनों को औद्योगीकरण तथा उसमें उत्पन्न शहरीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किया जाना चाहिए। शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि यह शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के द्वारा उत्पन्न समस्याओं का मुकाबला कर सके।

9. सामुदायिक विकास—देशीय स्तरों की भाँति शहरी स्तरों में भी शहरी सामुदायिक विकास योजनाएँ लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार की योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय जनता के सहयोग से शहर में रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाना होना चाहिए। ऐसी योजनाओं से लोगों का नगर-प्रशासन से निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा तथा वे प्रशासन के कार्यक्रमों में रुचि से सकेंगे। उस स्थिति में प्रशासन द्वारा संचालित कार्यक्रम उनके कार्यक्रम होंगे।

10. प्रशासन का विकेन्द्रण—जनता से निकट सम्पर्क के लिए आवश्यक है कि बड़े निगमों एवं नगरपालिकाओं के प्रशासन को क्षेत्रीय स्तर पर विकेन्द्रित किया जाए।

11. जनता का सहयोग—इन संस्थाओं के प्रशासन के प्रति जनता बड़ी उदासीन है, अतः जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचित प्रतिनिधि वादों में जाकर लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को समझें तथा उनके निराकरण का प्रयास करें, जिससे लोगों को विश्वास हो कि नगर प्रशासन मात्र कर वसूल करने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि उनके सुख-दुख के साथ काम आने वाली संस्था है। यदि ऐसी सभाओं का गठन हो सके जिनमें नगर प्रशासन तथा निर्वाचित सदस्य जनसाधारण से मिल सकें तो इस दिशा में प्रगति हो सकती है।

12. उचित समन्वय—कई बार नगर प्रशासन में असुविधा तथा समन्वय सम्बन्धी कठिनाइयाँ इस कारण उत्पन्न हो जाती हैं कि शहर का प्रशासकीय उत्तरदायित्व अनेक संस्थाओं के मध्य विभाजित रहता है। नगरपालिका नगर का प्रशासन सम्भालती है। नगर विकास न्याम शहर के आसपास अविकसित क्षेत्रों को विकसित करता है। अतएव इनमें प्रशासकीय समन्वय होना चाहिए, अतः यह उचित होगा कि शहर का मध्य प्रशासकीय उत्तरदायित्व एक ही संस्था के हाथ में हो।

13. वर्गीकरण का वस्तुनिष्ठ मापदण्ड—नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों की स्थापना एवं वर्गीकरण अधिक वस्तुनिष्ठ मापदण्ड से किया जाना चाहिए। सारे देश में इस सम्बन्ध में एक ही मापदण्ड की स्थापना होनी चाहिए। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद कुछ राज्यों में नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं की स्थापना की हो-ही लग गई है। नगरपालिका या नगर निगम शहर की सम्पदा का मापदण्ड बन गया है, यह अनुचित है।

14. समन्वय की उचित व्यवस्था—अनेक शहरों में नगर प्रशासन का उत्तरदायित्व अनेक संस्थाओं के बीच विभाजित है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उनमें पारस्परिक समन्वय तथा उनके सन्तुलित विकास के लिए प्रयास किए जाएँ। इसके अतिरिक्त इस बात की आवश्यकता है कि नगर प्रशासन से सम्बन्धित राज्य की सभी संस्थाओं में समन्वय हो, अतः राज्य स्तर पर एक उच्च शक्ति प्राप्त शहरी विकास बोर्ड अधिकरण की स्थापना की जाए जो विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर सके।

15. राज्य सरकार के निष्पक्ष नियन्त्रण—राज्य सरकारों को अपने नियन्त्रण के अधिकार को निष्पक्ष रूप से उपयोग में लाना चाहिए। प्रजातन्त्र में निर्वाचित सदस्यों को बिना उचित कारण के केवल दलगत आधार पर हटा देना या पदच्युत कर देना उचित नहीं कहा जा सकता।

16. जनता का उत्तरदायित्व—नगर प्रशासन के लिए जनता को अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। यदि नगर प्रशासन अकार्यकुशल भ्रष्ट और अक्षम है तो यह जनता का उत्तरदायित्व है कि वह उसे सुधारे। यह कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है—एक ओर जनता स्वयं नियमानुसार ईमानदारी से काम करे, अपने लिए किसी ऐसे लाभ के लिए

प्रवास न करे जो नियमानुसार उसे नहीं मिलना चाहिए, दूसरी ओर जहाँ कहीं निर्वाचित सदस्य प्रशासक, राजनीतिक दल अथवा अन्य कोई व्यक्ति निम्नो के विरुद्ध अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कार्य करे तो उसे चुनौती दी जानी चाहिए लेकिन जनता जागरूक नहीं है, अतः स्वार्थी तत्व सक्रिय हो जाते हैं। यदि स्वार्थी तत्वों को यह आपास हो जाए कि जनता जागरूक हो गई है तथा उनकी अपनी सफलता की सम्भावनाएँ घट रही हैं तो वे स्वयं ऐसा करना बन्द कर देंगे। अन्ततः नगर प्रशासन का वही रूप होगा जो जनता उसे देगी।

17. जनसम्पर्क—इन सभाओं की बिगड़ी स्थिति का एक कारण यह भी है कि निर्वाचन के बाद सदस्यों से जनता का न कोई सम्पर्क रहता है और न उस पर कोई नियंत्रण ही रहता है। जनता के सदस्यों द्वारा निम्नतर सम्पर्क बनाए रखने के लिए दो प्रकार के मुद्दाएँ दिए जा सकते हैं। पहला यह कि सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्षों के लिए हो तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष किया जाए। इस प्रकार की पद्धति से यह लाभ होगा कि बदलते हुए लोकमत को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। नगरपालिका क्षेत्र को तीन सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिवर्ष एक सदस्य निर्वाचित किया जाना चाहिए। दूसरा विकल्प इस दिशा में यह हो सकता है कि निर्वाचित सदस्यों को वापस चुनने की व्यवस्था होनी चाहिए (जैसा कि 1999 में मध्य प्रदेश सरकार ने किया)। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के 1/10 मतदाता प्राद्वत-पत्र प्रस्तुत करें कि सम्बन्धित सदस्य का 'रिचयन' होना चाहिए तो इस सम्बन्ध में मतदान किया जाना चाहिए। यदि मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत उस निर्वाचित सदस्य के विरुद्ध हो तो उसे सदस्यता से हटा दिया जाना चाहिए।

18. समिति पद्धति को शक्ति देना—इन सभाओं को समिति-पद्धति को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए।

19. अन्य—कुछ सेवाओं के लिए स्थानित कौंसिल, बोर्ड अथवा निगम का क्षेत्र शापट छोटा रहे। उदाहरण के लिए बस सेवा, होटल, विन्यास आदि। अतः यह किया जा सकता है कि एक क्षेत्र की सभी समस्याएँ निम्नतर अथवा क्षेत्रीय सभा बनाने वाली इन सेवाओं की व्यवस्था क्षेत्रीय स्तर पर की जा सके। इससे दो लाभ होंगे—प्रथम यह कि इससे क्षेत्र की समस्याओं के कार्यक्रमों में व्यापकता नहीं होगी तथा उनमें पारस्परिक होड़ के स्थान पर एक-दूसरे से मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास होगा। द्वितीय, यदि बड़ी समस्याएँ निम्नतर काम करेंगी तो कुछ इतक दूरगोचर बन की समस्या हल हो सकती है। ऐसी स्थिति में दो या तीन समस्याएँ निर्धारित अनुपात में दूरी सभाकर औद्योगिक प्रविष्टि, बाजार आदि की स्थापना कर सकती है।

20. नीति और उद्देश्य में सीमा रेखा—इन सभाओं में नीति-निर्धारण तथा कार्यकारी उद्देश्यों के बीच सीमा रेखा खींची जानी चाहिए।

21. सर्वसाधारण का हित—इन सभाओं के शासन-संयोजन से सम्बन्धित सभी लोग यदा निर्वाचित सदस्य, इन सभाओं के कार्यकारी, राज्य सरकार तथा राजनीतिक दल सभी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनका प्रशासन सर्वसाधारण के हित में चलाया जाना है, अतः इन्हें इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे जनसाधारण के हितों का उल्लंघन हो।

नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियन्त्रण

(State Control over Urban Local Bodies)

भारत में विभिन्न राज्यों के नगरीय स्थानीय निकायों का राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखा जाता है। इस नियंत्रण की मात्रा एवं प्रकृति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है, तथापि जिन क्षेत्रों में और जिन तरीकों से यह नियंत्रण रखा जाता है उसमें बहुत कुछ एकस्यता परिलक्षित होती है।

नियंत्रण की विधियाँ—राज्य सरकार नगरीय स्थानीय निकायों पर प्रायः निम्नलिखित विधियों से नियंत्रण रखती है—

1. सूरक्षण प्रदान करना—स्थानीय सभाएँ राज्य सरकार का एक अधिपत्य अंग हैं तथा उसके द्वारा हस्तक्षेपित शक्तियों का प्रयोग स्थानीय सभाएँ करती हैं, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जब कोई स्थानीय निकाय प्रशासन की मूलिकता की अवहेलना करे या जनता के हितों का दुरुपयोग करे तो कोई उच्च सत्ता निम्नलिखितपूर्वक उसमें हस्तक्षेप करे। पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की सामान्य शक्तियाँ राज्य कार्यपालिका में निहित रहती हैं। कार्यपालिका स्थानीय शक्तियों की क्रियाशक्ति के लिए उत्तरदायी सभाओं के भिन्न निर्देशक, दारोक्तिक, उत्तराह्वारक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। वह तुलनात्मक अध्ययन, आलोचना एवं समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, सामान्य एवं विशेष स्मृति-पत्र आदि के माध्यम से विभिन्न नगरपालिका परिषदों को विशेषज्ञपूर्ण परामर्श प्रदान करती है। विभिन्न आयोगों, समितियों एवं जॉइंट के माध्यम से नवीन व्यवस्थापन के अपावों का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार कार्यो एवं शक्तियों के सम्बन्ध में

नई नीतियों सुझाने में समर्थ होती है। नगरपालिका प्रशासन के सभी पहलुओं की कार्यपालिका के पास सुचना रहती है इसलिए नगरपालिका परिषदों को व्यक्तित्व एवं सामूहिक रूप से कभी भी निर्देशित कर सकती है। स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ये शक्तियाँ सरक्षण शक्तियाँ कहलाती हैं।

2. कानून को लागू करना—अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त होता है कि वह अधिनियम लागू करने के सम्बन्ध में आदेश सभी नगरपालिकाओं अथवा कुछ विशेष नगरपालिकाओं के लिए जारी किए जा सकते हैं। नियम और आदेश राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं और प्रकाशन-विधि के उपरान्त एक निश्चित अवधि के बाद लागू कर दिए जाते हैं। राज्य सरकार स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए उपनियम आदि तभी लागू समझे जाते हैं जब राज्य सरकार द्वारा उनका अनुमोदन कर दिया जाए। किसी उपनियम में कोई परिवर्तन राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है।

राज्य सरकार को विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। नगरपालिका या नगर परिषद द्वारा सम्पत्ति प्रदात एवं स्थान-सन्तति किए जाने की शर्तों में शक्ति-निधि की क्रियान्विति में कर लागू, वित्त एवं अनुमोदन से सम्बन्धित विषयों में राज्य एवं नगरपालिका सत्ताओं के मध्य सम्पर्क रखने वाला कार्यालय के सम्बन्ध में परिषद द्वारा तैयार की गई योजनाओं एवं अनुमानों में, नगरपालिका परिषदों द्वारा रखे जाने वाले लेखों में, जिस ढंग से राज्य सरकार के अधिकारी नगरपालिका परिषद को अधिनियम के दायरे के सम्बन्ध में सहायता, परामर्श एवं सहयोग प्रदान करेंगे तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से विषयों में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। ये विभिन्न विषय स्पष्ट रूप से अधिनियम में दिए होते हैं किन्तु राज्य सरकार चुनाव, पार्षद के चयन एवं नामजदगी, अध्यक्ष एवं उप-अध्यक्ष छाने होने वाले उम्मीदवारों द्वारा जमा किए जाने वाले धन आदि ऐसे विषयों पर नियम बना सकती है जो अधिनियम में नहीं दिए गए हैं।

सरकार को नियम बनाने की शक्ति नगरीय स्थानीय प्रशासन में एकरूपता लाती है। यह लोक सेवकों को, इनके उदात्तमूल्यों का निर्वाह करने में सहयोग देती है। अकेलकों को लेखों की परीक्षा करने में मदद करती है और स्थानीय स्वायत्त सरकार विभाग को उसके प्रतिवेदन तैयार करने तथा नगर परिषद कार्यों में पुनरीक्षा करने में सहायता करती है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं उपनियम प्रत्येक राज्य के स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रसारित किए जाते हैं।

3. निरीक्षण करना—राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारी नगरीय स्थानीय शासन निकायों का निरीक्षण करते हैं तथा इन निकायों या साधारणों की सम्पत्ति, निर्माण कार्य, रिकार्ड आदि का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण ब्रिटिशों की ओर स्थानीय शासन अधिकारियों का ध्यान केन्द्रित करते हैं और ब्रिटिशों को दूर करने के उपाय सुझाते जाते हैं। निरीक्षण का अधिकार मुख्य रूप से जिलाधीश एवं सभागीय अधिकारी को प्राप्त होता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी नगरपालिका या अन्य स्थानीय शासन निकाय के कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है और रिकार्ड आदि को अपने समस्त पैदा किए जाने का आदेश दे सकता है। जिलाधीश की शक्तियाँ व्यापक होती हैं। यदि उसका अभिमत होता है कि नगरपालिका या परिषद की किसी आज्ञा, प्रस्ताव या कार्य की क्रियान्विति से जिले की शान्ति को खतरा है तो वह उस पर रोक लगा सकता है। नगरपालिका द्वारा संचालित विद्यालयों के पाठ्यक्रम एवं शिक्षा सम्बन्धी साधारण नीति पर शिक्षा विभाग का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण रहता है। सफाई से सम्बन्धित विषयों का निरीक्षण करने के लिए जिले का सिविल सर्जन होता है और जन-स्वास्थ्य विभाग का सप्ताहिक वार्षिक निरीक्षण करता है।

4. सूचना प्राप्त करना—राज्य सरकार को नगरीय स्थानीय शासन निकायों से सुचना प्राप्त करने का अधिकार है। अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत आवश्यक विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन और विवरण राज्य सरकार को नियमित रूप से भेजना स्थानीय संस्थाओं का कार्य है। राज्य सरकार को, सूचना, आवश्यक समझे, वह, श्रमजन्म, जन्म, का, आदेश किसी स्थानीय निकाय को दे सकती है। जब अधिकारी किसी व्यक्ति को, जो उसकी दाय में आवश्यक हो, अपने समस्त उपस्थित होने, बयान देने तथा दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।

5. स्वीकृति देने का अधिकार—अनेक ऐसे कार्य हैं जो स्थानीय निकाय राज्य सरकार की स्वीकृति से ही वैध रूप से कर सकते हैं। उदाहरणार्थ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐच्छिक कर राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जा सकता। स्थानीय निकायों के उपनियम तभी लागू हो सकते हैं जब राज्य सरकार स्वीकृति प्रदान कर देती है।

6. वित्तीय नियन्त्रण—राज्य सरकार स्थानीय शासन निकायों पर वित्तीय नियन्त्रण रखती है। सभी नगरपालिकाओं से अपेक्षित है कि वे अपने आय-व्यय का वार्षिक बजट प्रस्तुत करें। राज्य सरकार नगरपालिका के बोर्ड को लागू और नियमित करने सम्बन्धी नियम बनाती है। नियमों के आधार पर वह तय करती है कि कितनी लागत वाले अनुमान एवं योजनाएँ किसके द्वारा तय होंगे, नगरपालिका के खर्च एवं भुगतान की आज्ञाओं पर किसके हस्ताक्षर होंगे तथा वह भुगतान किस प्रकार किए जाएंगे आदि। नगरपालिका द्वारा किसी भी रूप में सरकार की स्वीकृति के बिना कोई धन व्यय नहीं

किया जा सकता। नगरपालिका के कोष को किसी ऐसे बैंक में नहीं रखा जा सकता जो राज्य सरकार द्वारा मान्य नहीं है। नगरपालिका अपनी सीमाओं से बाहर खर्चों केवल तभी कर सकती है जबकि राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ले। उसकी सीमाओं के खर्च पर राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा नगरपालिका के कर निर्धारित किए जाते हैं। राज्य सरकार कर लगाने तथा उसकी अधिक से अधिक मात्रा निश्चित करने के नियम बना सकती है। कर लगाने समय राज्य सरकारों की स्वीकृति लेनी होती है। कई बार अनिवार्य करों की दरें वसूली की डिग्री आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वसूली के नियम भी राज्य सरकार ही बनाती है। राज्य सरकार स्थानीय निकायों को ऋण देती है। ऋण राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कुछ निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही दिये जा सकते हैं। ऋण से सम्बन्धित कार्यों एवं लेखाओं का परीक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार को है। जब ऋण के रूप में कोई धन नगरपालिका को दिया जाता है तो राज्य सरकार उससे सम्बन्धित कार्य पर पर्यवेक्षण रखती है। यदि कार्य पूरा हो जाने के बाद ऋण में से कोई धन वापस जाता है तो उसे राज्य सरकार को लौटा दिया जाता है। गैर-सरकारी ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार यह निर्देशित कर सकती है कि खर्च न किए गए धन को ऋण कम करने के काम में लाया जाए।

118286
 राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के लेखों का अंकेक्षण करने के लिए अधिकृत नियुक्त किए जाते हैं। राज्य सरकार लेखों को उचित रूप से रखने के नियम बना सकती है और परिषद द्वारा रजे जाने वाले विभिन्न रजिस्ट्रों के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत कर सकती है।

7. **राज्य सरकार द्वारा कार्य अपने स्तर पर करवाना**—यदि नगरपालिका या अन्य नगरीय स्थानीय निकाय अपना कार्य न करें तो राज्य सरकारों को अधिकार होता है कि अपने अधिकारियों से यह कार्य करावा से और कार्य-व्यय स्थानीय निकायों से वसूल कर ले। जब वसूल करना या न करना राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ अधिनियमों के द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय निकायों को जनहित में कुछ कार्य करने के लिए निर्देश दे। ऐसे निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होता है।

8. **अपील करना**—अनेक अवसरों पर नगरपालिका के अधिकारियों के निर्णय एवं आदेश विरोध का कारण बन जाते हैं। इनके विरुद्ध की गई अपीलें राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। यदि कानून का संचालन सही ढंग से न किया जाए और नगरपालिका परिषद उनकी अवहेलना करें तो राज्य सरकार से इसकी अपील की जा सकती है। विभिन्न राज्यों में ऐसे अनेक विषयों का उल्लेख कर दिया गया है कि जिन पर दी गई आशय अपील का विषय बन सकती है। सामान्य रूप से परिषद की आकांक्षों के विरुद्ध की गई अपील तथ्य के विषयों से सम्बन्ध रखती है न कि कानून के विषयों से। अपील सुनने वाली सभा का निर्णय प्रत्येक स्थिति में अन्तिम माना जाता है तथा कोई न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता तथा विषय को पुनरीक्षा या पुनरावलोकन के लिए नहीं भेजा सकता है। साधारणतः लाइसेंस देने या न देने या रद्द करने, भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियमों को लागू करने में एवं कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुरासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध राज्य सरकार से अपील की जा सकती है।

9. **परिषदों को भंग कर नये चुनाव करवाना**—अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नगरपालिका अथवा नगर परिषद को भंग कर दे या उसका अधिक्रमण कर दे। यदि परिषद अपने कर्तव्यों की पूरी तरह अवहेलना करती है या मतभेद के कारण प्रशासनिक कार्य अवकट हो जाता है या परिषद अपनी शक्तियों का उल्लंघन या दुरुपयोग करने लगती है तो राज्य सरकार को अधिकार है कि परिषद को भंग करके, नए निर्वाचन की आज्ञा दे। इस प्रकार की आज्ञा देने से पहले साधारणतः सभा को आरोप पत्र दिया जाता है, जाँच समिति द्वारा आरोप की जाँच कराई जाती है और संस्था को अवसर दिया जाता है कि वह जाँच समिति के समक्ष अपनी सच्चाई पेश करे। कुछ अधिनियमों के अन्तर्गत जाँच समिति की राय मानना अनिवार्य होता है। उदाहरणार्थ राजस्थान में जाँच समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। अतिक्रमण या भंग किये जाने का आदेश अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाना चाहिए अन्यथा सम्बन्धित साक्षान ऐसे आदेश को न्यायालय में चुनौती दे सकती है। न्यायापालिका राज्यदेश को आवश्यक मुक्तियों के बाद वैध या अवैध घोषित कर सकती है।

10. **सेवीयार्थ पर शक्तिपूर्व**—नगरपालिका स्तर पर अधिकारी एवं गैर-अधिकारी दोनों प्रकार के सदस्य कार्य करते हैं। जहाँ तक गैर-अधिकारी सदस्यों का प्रश्न है राज्य सरकार पार्षदों की संख्या निश्चित करती है, परिषद में निर्वाचित चयन किए हुए एवं मनोनीत सदस्यों का अनुपात निश्चित करती है और उनके चुनाव का नियमन करने के लिए नियम बनाती है। जहाँ सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान होता है वहाँ पार्षदों की कुल संख्या का सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। पंजाब में सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी निर्वाचित सदस्य का पद रिक्त होने पर उस पद को रिक्त रखने या नियुक्ति द्वारा भरने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। वह निर्वाचित या नियुक्त किसी विशेष सदस्य

की सौट को झाली करा सकती है। राज्य सरकार को यद्यपि यह शक्ति है कि वह परिषद के किसी सदस्य को हटा सके, किन्तु इस शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित पार्षद को स्पष्टीकरण का अवसर न दे दिया जाए। यदि किसी नगरपालिका के सदस्य को बायोलेट से बिना किसी कारण के हटा दिया जाए तो वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हटाने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि वह उचित कारणों से ही हटाया गया है। वेन्यू आन्ध्र प्रदेश और केरल राज्य में सरकार अध्याय की शक्ति के दुरुपयोग या कर्तव्यों के पालन में स्वभावगत असफलता के लिए हटा सकती है। राज्य सरकार शिक्षा, जन कार्य मेडिकल, स्वास्थ्य एवं अन्य तकनीकी विभागों के लोगों को समर्पित की बैठकों में भाग लेने के लिए तथा उनके विभागों को प्रभावित करने वाले विषयों पर बोलने के लिए आमन्त्रित कर सकती है। नगरपालिका के लोक सेवकों की दृष्टि से राज्य सरकार की विभिन्न शक्तियाँ सौंपी गई हैं। उसे अधिकार होता है कि सार्व्व अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, सफाई निरीक्षण, लेखाधिकार, भोवरासीय, नर्स आदि की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम बना सके।

11. **न्यायिक नियन्त्रण**—राज्य सरकार का प्रमुख अंग न्यायपालिका है जो स्थानीय निकायों पर न्यायिक नियन्त्रण की भूमिका निभाता है। न्यायिक नियन्त्रण प्रशासनिक नियन्त्रण से भिन्न होता है। कोई न्यायालय तब तक स्थानीय निकायों की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि उनके द्वारा अपनी शक्तियों को धातक रूप में अधिनियम के प्रतिफल और नुरे विरुद्ध के साथ न अपनाया गया हो। न्यायाधीश स्वयं अपनी तरफ से पहल करके कदम नहीं उठा सकता, पहल अन्य पक्षों द्वारा होनी चाहिए। न्यायिक नियन्त्रण स्थानीय सत्ताओं को सीमा में रखा है इसलिए नगरिकों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। नगरपालिकाओं पर न्यायपालिका का नियन्त्रण तीन प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम, न्यायालय अधिनियम और कानूनों की व्याख्या करता है और उन्हें कानून का स्तर देता है। द्वितीय, न्यायालय नगरपालिका की सत्ताओं को गैर-कानूनी कार्य करने से मना करता है। तृतीय, अधिनियम के अधीन न्यायपालिका को नगरपालिका के कार्यों एवं प्रशासन पर अपील सुनने का अधिकार होता है।

नियन्त्रण व्यवस्था के दोष—उपरोक्त विवेचन से यह प्रकट होता है कि नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार की नियन्त्रणकारी शक्तियाँ विस्तृत और व्यापक हैं पर व्यवहार में वर्तमान नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार का नियन्त्रण कुल मिलाकर स्थानीय शासन निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सफल नहीं हुआ है। इस नियन्त्रण व्यवस्था के मुख्य दोष निम्नानुसार हैं—

1. नियन्त्रण के साधन नकारात्मक हैं। नियन्त्रण का उद्देश्य समुचित मार्गदर्शन न होकर दण्डात्मक होता है। राज्य सरकार को नगरपालिका एवं नगरपरिषद को भग करके नए निर्वाचन का आदेश देने का अधिकार होता है, लेकिन इसे सुधारात्मक उपाय नहीं बना जा सकता है। उचित तो यह होता है कि सरकारी विभाग की देख-रेख में प्रभावों निदेश देकर, स्थानीय सत्ता को अपने को सुधारा का अवसर दिया जाए।

2. स्थानीय शासन सत्ताओं को बार बार भग करने अधिकरण करने सदस्यों एवं चेयरमैन को निष्कासित करने से न केवल सार्वजनिक धन और शक्ति का अपव्यय होता है, बल्कि स्थानीय सत्ताओं से जनता का विश्वास उठने लगता है।

3. ऐसे अनेक अधिकरण हैं जिनके द्वारा परिवर्तों पर राज्य का नियन्त्रण किया जाता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सफाई, पशु चिकित्सास्य आदि पर विभिन्न सरकारी, तकनीकी विभाग अपने कार्यालयों द्वारा प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखते हैं। सामान्य प्रशासन एवं विवाद के क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त सत्ताओं पर सरकार मंत्रालय, आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों के माध्यम से नियन्त्रण रखती है किन्तु ये आधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं और इनको स्थानीय प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिलता है। वे अन्य कार्यों में अत्यन्त व्यस्त रहने के कारण स्थानीय निकायों में अधिक समय नहीं दे पते फलतः स्थानीय निकायों पर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण अत्यन्त अपर्याप्त रहता है। उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वायत्त सरकार समिति ने बताया था कि जिला अधिकारियों एवं आयुक्तों द्वारा सरकार की ओर से स्थानीय निकायों पर जो नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण रखा जाता है उसमें वे पर्याप्त हवि नहीं लेते, क्योंकि उन पर उनके अपने ही कार्यों का काफी भार रहता है।

4. कई बार नियन्त्रण की कठोरता से स्थानीय पहल को ठेस पहुँचती है। राजस्थान में वित्तीय सहायता और ऋण प्राप्ति के नियम कठोर और जटिल हैं।

5. ऐसी शिकायतें प्रायः सुनने में आती हैं कि नियन्त्रण-शक्तियों का प्रयोग दलान्तर राजनीति के व्यक्तिगत लाभ अथवा बदले की भावना से किया जाता है। एक ही आधार की परिस्थितियों में कुछ नगरपालिकाएँ भग कर दी जाती हैं जबकि अन्य को कुछ नहीं कहा जाता है।

6. कई बार स्थानीय शासन सत्ताओं का अधिकरण वर्षों तक चलता रहता है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। यह आवश्यक है कि अधिनियम के अन्तर्गत अधिकरण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाए।